संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमियाका

जिल्द ६१

सोमवार, ६ जनवरो, सन् १६४० से शनिवार, १४ जनवरी, सन् १६४० ई० तक



सुद्रक मधीक्षक, राजकीय मुद्रगास्त्रय एवं लेखन-मामग्री, उत्तर प्रदेश, इस्राह्मबाद १६५०

विषय-सूची

सोमवार, ६ जनवरी सन् १६५० ई०

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों को सूची		₹3
प्रश्नोत्तर		३ २७
श्री अजोज अहमद खां तथा श्री बलभद्र शिह की मृत्यु पर	शोक संवाद	२७ २८
श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक संवाद		₹९३०
जालीन डिस्ट्रियट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उपचुनाव के	सम्बन्ध में काम	,
रोको प्रस्तांच (अवैघ घोषित)	• •	₹१३२
भूमिघरी अधिकार तथा जमींदारी उन्मूलन कीष	एकत्र करने के	
विषय में कामरोको प्रस्ताव (अवैध घोषित)	• •	₹ ?
देवरिया जिले मेरबी की फसल, किसान सत्याग्रह बंदियों के दिषय में काम रोको प्रस्ताव (अवैध घोषि	तथा सत्याग्रहा	
•	-	३२
प्रान्तमे चंनी के मूल्य नियत्रण के संबंध में । (अवैध घोषित)	कामराका प्रस्ताव	
सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्राःतं य काइतकार (विशे		३ ३
विधेयक (बिल) पर महामान्य ग्वर्नाः कं स्वं कृति	षाधकार ६ पाजनः) कः गोषणः	מ מ
सन १९४९ ई० के संयुक्त प्राप्त य मेरिनेस अफ पहिल		¥ ₹
और कार्यवाधियों को वैध करने के) बिल पर सहाम	क आडर (सशाधन अस्य क्रमर्जन स्थान	
की स्वाकृति की घोषणा	त्त्व भवतर जनरल	3 3
सन् १९४९ ई० के रुड़की जिञ्चितिद्यालय (यूनीर	वसिनी (संकोधका	77
बिल पर महामान्य गवर्नर की सर्व कृति को घोषण	(((4))	\$ 3
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय औषधि (नि	यन्त्रण) आर्डिनेंस	**
(मेज पर रखा गया)	•••	38
सन् १९४९ ई० का इंडियन बार काउन्सिल (य०पी० असेजसेट	•
ए ज वालडशन आफ प्राप्त डिग्स) आडिनेस (मेज	पर रखा गया)	३४
सन् १९४९ ई० का युनाइटेड प्राविमेज रिक्वीजीशन आ	फ मोटर बेबिकिस्य	•
(एमजन्सः पादसं) (अभडमट एन्ड प्रोसोडिंग्स वै	लिडेशन) आहिनेस	
(मज पर रखा गया)		₹%
सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रांसपोर्ट	कंट्रोल (अमेंडमेट)	
(आजनसम्जपर रखागया)		38
हरिद्वार कुम्भ में अ के निपम (में अ पर रखे गए)	• •	38
इलाहाबाद माघ मेला के नियम का संशोधन (देज पर रख	ागया। .	३४
पू०पो० मो टर वेहिकिल्स रूल्स (नियमों) का संझोधन (मेज पर रखा गया)	₹8

विपन		મૃત્
मन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्तीय जमीदारं विनाश व्यवस्था बिल (विशिष्ट समिति की रिपोर्ट प्ररतुत)	• •	₹ ४−− ₹/
सन् १९४८ ई० का सयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खद्य बिरु (थिशिष्ट समिति को रिपोर्ट प्र ^र तुन)		্ব ৬
मन् १९५९ ई० का को आपरेटिव मोमाइटीज (संयुक्त प्रान्ती बिल (स्यक्ति)	• •	३७
मन् १९४९ ई० का मंयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने (भ्भिप्राप्त करने का) (सशोधन) बिल (स्वोक्टत)	• •	₹ ८ ४०
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूरि बिल जारी)	भ-व्यदस्था ••	४० ६९
नित्ययां	. •	७० − −३०२
मंगलवार, १० जनवरी सन् १६५०	इ	
उपस्थित सदस्यों की सूची		३०३३०५
प्रश्तोत्तर		३०५३२८
सन् १९४९ ई॰ के संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वर नुओं के नियंत्र आर्डिनेंस (सेंस पर रखा गया)	ण का	३२८
सन् १९४९ ई॰ के संयुक्त प्रान्तीय कोर्टफीस [छूट (रेभिशन)] (सेज पर रखा गया)	आर्डिनेस • •	३२८
सन् १९४९ ई० के यूनाइटेंड प्राविसेज इन्टर मीडिएट एजू केशन (आर्डिनेस (भेज पर रखा गया)	(अमेडमेंट)	३२८
आरकोल्गाजिकले स्यूजियम्, मथुरा की प्रबन्धकारिणी समिति है सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताध (सर्व कृत हुआ)	ह लियेएक 	३२८
प्रान्तीय म्यूजियस्, लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक निर्वाचन का प्रस्ताच (स्वीकृत हुआ)	सदस्य के	३२८
संयुक्त प्रान्तः य स्यूजियम ऐडवाइजरा बोर्ड में काम करने के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्त स (स्व कृत हुआ)	लिये दे।	35/
्रकृषि तयः पञ्चपालन स्थायः सभिति में स्थर्गीय श्रीः बलभद्र सिह द्वा	रा रिक्त	३२८
हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (सर्वे कृ -यूनाइटेड प्राचिनेज नर्सेज एंड मिडवाइफ कौसिल में काम करने के वि		३२९
सदस्यों है निर्वाचन का प्रस्ताश (स्वीकृत हुआ) बुन्दे चुन्न अत्युर्वे दिक कालेज, झासा की प्रबन्धकारिणी समिति ।	• •	३२९
शिवराभ वैद्य द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के नि	म अ≀ ।विचिन	
कः अस्ताच (स्वोकृत हुआ) सन् १९४९ ई० के नमुक्त अस्तोय जमीदारी विनाश और भूमि-स्यक्ष	 स्या बिल	३२९
(चारा) ••		३२९ ३७१
लखनऊ में सदस्यों के लिये इ पर्यू के परिभट	• •	३७२
नित्ययां		8955e8

विषय			ূ ৽ ড
बुधवार	, ११ जनवरी सन् १	९५० ई०	
उपस्थित सदस्यों की सूची	• •		३९५ ३९७
प्रश्नोत्तर	• •	• •	₹ ९७ —-४२ १
सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्र आर्डिनेस (भेज पर रखा गय		क्वोजीशन • •	8
सन् १९४९ ई० कायूनाइटेड प्रार् ऐड एशिक्झन आर्डिनेस (वसेज (टेम्पोरेरं) कंट्रोल मेज पर रखा गया)	आफ रेम्ट	४२१
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय व्यचस्था बिल (जारी)	ा जमींदारो विभाश और भ् · •	<u>(</u> [∓;∸ · ·	४२१४३०
कतिपय सिमतियों के लिये सदस्य	। वे चुनाव का कार्यक्रम		830838
सन् १९४९ ई० का संयुवत प्रान्ती	य जमींदारी धिनाश अ	गैर भूमि	
ंग्यवस्था विल (जारी)	•	• •	8389.45
नत्थियां	• •	• •	४५९४६३
बृहरपतिवः	ार, १२ जनवरी सन् १	१ ९४ ० ई ०	
उपस्थित सदस्यों की सूची	•		४६५४६७
प्रश्नोत्तर	• •		850864
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्ताय	जिमोंदारी यिनाश औ	र भूमि	-
व्यदस्था बिल (जारी)			^७ ८५५०६
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों	•	-	405400
भारतोय पालियामेट के पद्चीस रि मे घोषणा	वत (थ.नीं के लिये चुन.च	के सम्बन्ध	F
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रस्तीय	स्वयोधानी दिल्लाका की		५०७ ५०८
व्यवस्थाः बिलः (जारी)	रामायारा विमास आ	र भू।म	406-476
कतिपय समितियों के लिये सदस्यों	के चनावंं। के सम्बन्ध में घो	লি গ া	4-6
नित्थयां			479439
शुक्रवार,	१३ जनवरी सन् १६	४० ई०	113
उपस्थित सदस्यं। की सूची			५४५५४३
प्रश्नोत्तर .			483447
हजकमेडों के लिये सदस्यों के चुनाय	। के सम्बन्ध मे घोषणा	• •	५६२
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्ताय		र भूमि	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
व्यवस्था बिल (जारो)	•	• •	५६२५७३
भारतीय पालियामेट के पच्चीस रिक में घोषणा	तस्यानं के चुनाच के	सम्दन्ध	
			५७३
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्राप्तीय व्यवस्था बिल (जारी)	पानादारा विनादा अस्	भू।भ-	۸۱ = تا ۲ م ر ن
हज कमेडा के लिये सदस्यों के चुनाय	के सम्बन्ध में घोषणा	• •	403400
नित्थयां .	* *	* *	2003 2003 2003

विषय			पृष्ठ
	, १४ जनवरी सन १ ९	५० ई०	-
उपस्थित सदस्यों की सूची	••	• •	६१३—–६१५
त्रश्नोत्तर		• •	६१५—–६३१
मन् १९४९ ई० का रामपुर (अप्ल	िकेशन आफ लाज) आर्डिनेर	त (सन्	
१९४९ ई० की संख्या १३)	(क्षेज पर रवला गया।)	• •	६३१
सन् १९४८-४९ ई० का यूनाइटेड	प्राविसेज मर्ज्ड स्टेट्स (अप्ल	.केशन	
आफ लाज) आर्डिनेंस (सन्	१९३५ ई० की संख्या १) (मे	'ज' पर	
रक्ला गया।)	• •	• •	६३१
सन् १९३५ ई० के संयुक्त प्रान्त के	मोटर गाड़ियों के आय	हर के	
नियम १२ में संशोधन (मेज पर	रक्लागया)	• •	६३२
सन् १९४९ ई० क् प्रयुक्त प्रान्त	रिय जमीदारी विनाश और	: भूकि-	
व्यवस्था बिल (जारी)	•	• •	६३२६७९
नित्यया	•		६८० ६९६

शासन

गवन र

महामान्य श्री हारमस जी पेरोशा मोदी।

सचिव-परिषद्

मातनीय श्री गोविन्द वत्लभ ान, बी० ए०, एल-ए ४० बी०, प्रथान मिलव तथा अर्थ, न्याय, सूचना और सामान्य-प्रशासन सिलव । माननीय श्री मुहम्मद इब्राहीम, बो० ए०, एल -एल० बी०, निर्माण सिल्प । माननीय श्री सम्पूर्णानन्द, बी० एस-पी०, शिक्षा तथा श्रम सिल्व । माननीय श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल एल० बी०, वन तथा माल सिल्व।

माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी, बी० ए०, एल-एल० बी०, कृषि तथा पशु-पालन

माननीय श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, रिजम्हेशन, स्टाम्य, जेल तथा मादक-कर सिवव। माननीय श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०, स्वप्नासन गिवव। माननीय श्री चन्द्रभानु गु'त, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वास्थ्य तथा अ व सिवव। माननीय श्री लालबहादुर, गृह (पुलिस) तथा परिवहन सिवव। माननीय श्री केशवदेव मालवीय, एम० एम-सी०, उद्योग तथा विकास सिवव।

सभा-मन्त्री

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री -

१--श्री चरग सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

२--भो जगनप्रसाद रावन, बी० एस-मी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०।

३--श्री गोविन्द सहाय, एन० एल० ए०। माननीय निर्माण सचिव के सभा-मंत्री--

१—-श्री लताफत हुसैन, एम० एल० ए०। माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री—-

१—-श्री महक्जुर्रहमान, एम० एल० ए०। माराीय उद्योग सन्धिः हे सभ;—रंत्री——

१--श्री वहीद अहमा, एम० एल० सी०। माननीय मात्र सचिव तथा कृषि सचिव के सभा-मंत्री---

१--श्रो हरगोविन्द सिंह, एम० एल० सी०।

सदम्यो की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अचल मिह		आगरा नगर।
२—अजिनप्रनाप मिह		अवध का विटिश इंडियन एसोमियेशन।
३ अब्दुल गर्ना अंमारी		जिला आजनगढ़ (पश्चिम) ।
४—-अब्दुल वाकी		जिला आजमगढ़ (पूर्व) ।
५—-अब्दुल मर्जीद		मुरादाबाद–अमरोहा–चन्दौमी नगर ।
६अब्दुल मजीव रवाजा		अलीगढ–हाथरस–मथुरा नगर ।
э—अब्दुच्च वाजिद, श्रोमनी		मुरादाब द जिला (उत्तर-पूर्व) ।
८—अब्दुच्च हमीद	. ,	जिला देहरादून ओर सहारनपुर (पूर्व) ।
९जम्म [ा] र अह्नद खां		जिनाबुलन्दशहर (पूर्व) ।
१०अर्बेस्ट झइके र फिलिप्स		मयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईसाई ।
११—अलग्राय बास्त्री		जिला आजमगढ़ (उत्तर - पूर्व) ।
१२अची जरीर जाफरी		जिला गोंडा (उत्तर−पूर्व) ।
१३अन्प्रोड वर्मदास		मयुक्त प्रान्तीय भारतीय ईमाई।
१४—–असगर अली खा		जिलामुजक्फरनगर (पदिचम)।
१५—-अक्षयवर सिंह		जिला गोरवपुर (पश्चिम) ।
१६आन्मानाम गोविन्द खेर,		फर्रुलाबाद-इटावा-झांमी नगर ।
माननीय श्री		
१७—-अर्धिवाल्ड जेम्स फैन्थम		मंपुनत प्रान्तीय ऐग्लो इंडियन ।
१८—इन्द्रदेव त्रिपाठी		जिला गाजीपुर (पहिचम)।
१९—-इनाम हर्बोबुल्ला, बेगम		लवनऊ नगर।
२०उदयवीर सिह		जिलाबस्ती (दक्षिण)।
२१——ऍजाज रसूल	• •	जिला हरदोई ।
२२—कमलापति तिवारी		जिला बनारस ।
२३—करोमुर्रजा खां		बदायूं –शाहजहांपुर–सम्भल नगर ।
२४कालीचरण टंडन	• •	जिला फर्रुलाबाद (दक्षिण) ।
२५——िकशनचन्द पुरी	•	संयुक्त प्रान्तीय चेम्बर आफ कासर्स तथा
		संयुक्त प्रान्तीय मर्चेन्ट्स चेम्बर।
२६—कुंजबिहारीलाल शिवानी		जिला झांसी (उत्तर) ।
२७—ङ्ग्रानान्द गैरोला 🤝		जिजा गढ़वाल (उत्तर-पश्चिम) ।
२८—कृपाशंकर		जिलाबस्ती (दक्षिण)।
२९—कृष्णचन्द्र	• •	जिला मथुरा (पश्चिम) ।
३०कृष्णचन्द्र गुप्त	• •	जिला मीतापुर (दक्षिण)।
३१केशव गुप्त		जिला मुजपफरनगर (पूर्व)।
३२—केञबदेव मालवीय, माननीय श्री		जिला मिर्जापुर (दक्षिण) ।
२२बानचन्द गौतम	• •	जिला बुलन्दशहर (पूर्व) ।
		- ' ' ' ' '

```
जिला खीरी (उत्तर-पूर्व) ।
  ३४--- खुशववत राय
                                          जिला अल्मोड़ा।
  ३५--खुशीराम
                                          जिला बिजनोर (पूर्व)।
  ३६-- ज्ब सिंह
                                          जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)।
  ३७--गंगाधर
                                         जिला गोंडा (उत्तर-पूर्व)।
  ३८--गंगाप्रसाद
                                          जिला कानपुर (पश्चिम)।
  ३९--गंगासहाय चौबे
                                         जिला आजमगढ़ (पिवचम)।
  ४०--गजाधरप्रसाद
                                         जिला सुल्तानपुर।
 ४१--गगयति सहाय
                                         जिला फैजाबाद (पूर्व)।
 ४२--गणेशकृष्ण जैतली
                                         जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
 ४३--गिरधारीलाल, माननीय श्री
                                         जिला मीतापुर (उत्तर-पश्चिम) ।
 ४४--गोपालनारायण सक्सेना
 ४५--गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री
                                         बरेली-पीलीभीत-शाहजहांपुर-बदायुं नगर ।
                                         जिला बिजनौर (पश्चिम)।
 ४६--गोविन्दसहाय
 ४७--चतुर्भुज शर्मा
                                         जिला जालौन ।
 ४८--चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री
                                         लवनऊ नगर।
 ४९--चन्द्रभानु शरण सिह
                                         जिलागोंटा (दक्षिण)।
                                         जिला मेरठ (दक्षिग-पश्चिम)।
 ५०--चरण सिंह
 ५१--- चेतराम
                                         जिला बाराबंकी (उत्तर)।
 ५२—-छेशलाल गुप्त
                                         जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिम)।
                                        जिला सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)।
 ५३--जगन्नायदास
                                         जिला गीतापुर (पूर्व) ।
५४--जगन्नायप्रसाद अप्रवाल
५५--जगन्नाय बर्ज्ञा सिह
                                        अवय क। ब्रिटिश इंडियन एसोमियेशन।
५६--जगन्नाथ सिंह
                                        जिला वलिया (उत्तर)।
                                        जिला आगरा (दक्षिण-पश्चिम)।
५७--जगनप्रसाद रावत
५८--जगमोहन सिंह नेगी
                                        जिला गढ़वाल (दक्षिण-पूर्व) ।
५९--जयकृरण श्रीवास्तव
                                        अवर इंडिया नेम्बर आफ कामर्स ।
६०--जयपाल सिंह
                                        जिला फैजाबाद (पूर्व) ।
६१--जयराम वर्मा
                                        जिला बाराबंकी (उत्तर)।
६२—-जवाहरलाल रोहतगी
                                        कानपुर नगर।
६३--जहीरल हसनैन लारी
                                        जिला गोरखपुर (पूर्व )।
६४--जहर अहमद
                                        इलाहाबाद-झांमा नगर।
६५--जाकिर अली
                                        आगरा-फर्हताबाद-इटावा नगर।
६६--जाहिट हसन
                                       जिला सहारनपुर (दक्षिण-पश्चिम) ।
६७-- जुगुलकिशोर
                                        मथुरा-अलीगढ़-हाथरस नगर।
६८--त्रिलोकी सिंह
                                       जिला लखनऊ।
६९--दयालदास
                                       जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व)।
७०--- इाऊरवाल खन्ना
                                       मुरादाबाद (पूर्व)।
```

```
जिला जोनपुर (पूर्व)।
    ७१--द्वारिकाप्रमाद मोर्य
                                           जिला इटावा (पश्चिम)।
    ७२—दोनदयानु अवस्थी
                                           महारनपुर-हरिद्वार-टेहरादून-मुजपफरनगर
    ७३—-दीनदयालु हास्त्री
                                            नगर।
                                           जोनपुर-मिर्जापुर-गाजीपुर-गोरखपुर नगर ।
    ३४—-दोयनारायण वर्मा
                                          जिला इटाना और कानपुर ।
   ७५—चर्मे मुल हमन
                                          फैजाबार-योनापुर-बहराइच नगर।
   ७६—नवाजिश अली खां
                                          जिना अनोगड (पूर्व)।
   ७७--नवाब मिट चोहान
   ७८—नाजिम अन्रो
                                          जिला सुन्तानपुर ।
   ७२--नाराषगदास
                                          लवनऊ नगर।
                                          जिला मैनपुरी और एटा।
   ८०-- निमार अहमद शेरवानी, माननीय श्री..
                                          जिला बदायूं (पूर्व) ।
   ८१--निहालुद्दीन
                                          जिला सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)।
   ८२---परागोनाल
   ८३—पुरुषोत्तनदान टडन, माननीय श्री
                                          इलाहाबाद नगर।
  ८४--पूर्ममम्बो
                                          जिला गोरवपुर (उत्तर)।
                                          जिना फर्रुबाबाद (उत्तर)।
  ८५--पूर्णि स बनर्जी, श्रीमनी
                                          जिला मेरठ (उत्तर)।
  ८६-प्रकाशवर्ना मूद, श्रीमनी
                                          अवध का निटिश इंडियन एसोसियेशन।
   ८७---प्रयागनारायण
   ८८—प्रेमिकशन खन्ना
                                          जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।
   ८९—फवरल इम्लाम
                                          जिला जौनपुर और इलाहाबाद (उत्तर-पूर्व)।
   ९०-फजलुर्रह्मान त्या
                                         जिला शाहजहांपुर।
  ९१--फनेइसिंह राणा
                                         जिना मुजक्फरनगर (पश्चिम)।
  ९२—फूलसिंह
                                         जिला सहारनपुर (दक्षिण-पूर्व)।
  ९३--बदन मिह
                                         जिला बदायं (पश्चिम)।
  ९४---बनारमीदास
                                         जिला बुचन्दशहर (उत्तर)।
  ९५--वलदेवप्रनाद
                                         जिला गोटा (उत्तर-पूर्व)।
  ९६—वशीर अहमद हकीम
                                         जिला मीतापुर।
  ९७-वक्षीर अहमद असारी
                                         जिला बिजनोर (दक्षिण पूर्व)।
  ९८--बादशाह गुप्त
                                         जिला मैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
  ९९-- बाबूराम वर्षा
                                         जिलाएटा (उत्तर)।
१००--बृजमोहनचाल शादत्री
                                         जिला बरेली (दक्षिण-पश्चिम) ।
१०१--भगवती प्रसाद दुबे
                                         जिला गोरखपुर (दक्षिण-पश्चिम् )।
१०२--भगवती प्रसाद शुक्ल
                                         जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम)।
१०३--भगवानर्दान
                                         कानपुर नगर।
१०४--- भगवानदीन मिश्र
                                         जिला बहराइच (दक्षिण)।
१०५--भगवान सिंह
                                         जिला पोलीभीत (दक्षिण)।
१०६--भाग्न सिंह
                                         जिला मैनपुरी (दक्षिण-पश्चिम) ।
```

```
जिञा बुलन्दशहर (दक्षिण-पश्चिम)।
 १०७--भोनसेन
                                          जिला रायखरेली (दक्षिण-पश्चिम)।
 १०८--मंग राप्रसाद
 १०९--मसुरियादीन
                                          इलाहाबाद नगर।
                                          जिला बहराइव (दक्षिण)।
 ११०--महफू नुरहिमान
                                          देहराद्गन-हरद्वार-सहारनपुर-मुजयफरनगर
 १११--महपूद अली वां
                                          जिला जैनपुरी (उत्तर-पूर्व)।
 ११२—- मिजाजीलाल
                                          जिला पोलीमोत (उसर) ।
 ११३—— मकुन्दलाल अग्रनाल,
 ११४--- मुजफ्फर हुसैन
                                          लखनऊ नगर।
 ११५-- मुनकैत अलो
                                          जिला सहारनपुर (उत्तर) ।
                                          जिला बस्तः (पविवम् ) ।
११६-- मुहम्भद अदील अब्बासी
                                          जिला बदायूं (पश्चिम) ।
 ११७--मुहम्मद अंतरार अहमद
                                          जिला गढ़काल और बिजनीर (उत्तर-एडिच्म )।
११८-- मुहम्मद इब्राहीस, माननीय श्री
११९--न्हम्मद इस्पाईल
                                          जिला जुरादाबाद (दक्षिण पूर्व) ।
१२०--- मुहम्मद अबैदुर्रहमान खां शेरवानी . .
                                          जिला जल गढ़।
१२१-- मुहम्भद जमकोद अली खां
                                          जिला ग्रेरठ (पश्चिम्)।
१२२--- मुहम्मद नबी, सैयद
                                         जिञामुजफ्फरनगर (पूर्व) ।
१२३-- पृहम्मद नजोर
                                          जिना बनारस और मिर्जापुर।
                                         जिला गोरखपुर (पश्चिम्)।
१२४--भुहम्भद फारूक
                                          जिला गाजापुर और पलिया।
१२५--म्हम्भद याक्व
                                          जिला इलाहाबाद (तक्षण-विन्तः)।
१२६--मुहम्मद युसुफ
                                         जिला बरेलें (पूर्व, दक्षिण ओर पश्चिम)
१२७--मुहम्यद रजा खां
                                         बनारस-मिर्जापुर नगर।
१२८--मुहम्मद शक्र्र
१२९--मुहम्मद शमीम
                                         जिला रायबरेली।
१३०--मुहम्बद शाहिद फालरी
                                         लखनऊ नगर।
१३१-- मुहम्मद शौकत अला खां
                                         जिला बुलन्दशहर (पश्चिम)।
१३२--मुहम्पद सजादत अली खां
                                         जिला बहराइच (उत्तर)।
१३३-- पुहम्बद सुलेमान अवमी
                                         जिलाबस्ती (उत्तर-पूर्व) ।
१३४-- यज्ञनारायण उपाध्याय
                                         जिला बनारस (पश्चिक्ष)।
१३५⊸-रघुनाथ विनायक धुलेकर
                                         जिला झांसं/ (दक्षिण)ः
१३६→-रबुवंशनारायण सिंह
                                         जिला में रठ (पूर्व)।
१३७--रघुवं र सहाय
                                         जिला बदायूं (पूर्व) ।
१३८--राघदवास
                                         फैजाबाद-दहराइच-सेतापुर नगर।
१३९-- राजकुंवार सिंह
                                         आगरा प्रान्त जमोंदार एस। सियेशन।
१४०--राजाराम निश्र
                                         जिला फैआबाद (पश्चिम) ।
'१४१—-राजाराम शास्त्रो
                                         कानपुर औद्योगिक श्रम ।
१४२--राधाकृष्ण अग्रत्रास
                                         जिला हरवोई (भध्य)।
```

(ङा)

जिना बलिया (दक्षिण)। १४३-- राघ(मोहन मिह जिला बस्ती (पश्चिम)। १४४--राघेश्याम शर्मा जिलाबस्ती (उत्तर-पूर्व)। १४५५-र भकुमार वास्त्री बुलस्दशहर-मेरठ-हापृड़-खुर्जा-नर्गाना नगर। १४६--राम्ह्याल मिह जिला आगरा (उत्तर-पूर्व)। १४७--रामचन्द्र पालीवाल आगरा नगर। १४८--राह्यवन्त्र मेहरा जिला गोरखपुर (मध्य) । १४२,--रामजी महाय इलाहाबाद, लखनऊ तथा आगरा विश्व– १५०-- एमबर मिश्र विद्यालय १ जिलागोरखपुर (उत्तर-पूर्व)। १५१--राजवारी गंडे अवर इंडिया चेम्बर आफ का सर्स । १५२-- रामन रापण जिलासुल्तानपुर (पूर्व)। १५३-- रामवर्ग १५४--रामम्ति जिला बरेली (उत्तर-पूर्व) । जिला वर्स्तः (दक्षिण-पूर्व) । १५५--र'मशंकरलाज मुरादाबाद-अमरोहा-सम्भल-चन्दौर्सः नगर ६ १५६-- रामशरण जिलाकानपुर (दक्षिण) । १५७--रामस्बह्य गुप्त जिला हरदोई (दक्षिण-पूर्व)। १५८--र भेश्वर महाय सिंह १५९--रुक्तुद्दीन खां जिला प्रतापशह । जिला गोंडा (दक्षिण-पश्चिम)। १६०--रोशनजनां खां १६१--चर्मीदेवी, श्रीमती जिला फैजाबाद (पश्चिम) । जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम)। १६२--चताफत हुसैन जिलाबदायूं (पूर्व)। १६३--लाखनदास जाटव १६४--जालबहादुर, माननीयश्री जिला इलाहाबाद (गंगापार) । १६५--लालविहारी टंडन जिलागोंडा (पश्चिम) । १६६--ले! गधर अब्डाना जिला उन्नाच (पूर्व)। जिला मेरठ (पूर्व)। १६७--लुत्फ अली खां १६८--लोटनराम जिला जालीन। १६९--वंशगोपाल जिला फतेहपुर (पूर्व) । १७०-- वज्ञीघर मिश्र जिला खोरी (दक्षिण-पश्चिम)। जिला मिर्जापुर (उत्तर) । १७१-- विजयानस्य मिश्र १७२--विद्यावर वाजरेई जिला सुल्तानपुर (पश्चिम) । १७३-- विद्यावनो राठोर, श्रीमती जिलाएटा (दक्षिण)। १७४--विनय कुमार मुकर्जी लखनऊ–अगरा–अलं,गढ़–इलाहाबाद औद्योगिक मिल श्रम । १७५--विश्वनायप्रसाद जिला मिर्जापुर (उत्तर)। १७६--विश्वनाथ राय जिला गाजीपुर (पूर्व) । १७७-- विश्वम्भरदयाल त्रिपार्ठी जिला उन्नाव (पश्चिम)।

१७८——त्रिष्णु शरण दुब्लिश

१७९-- वीरबल सिंह

१८०-- बीरेन्द्र शाह

१८१--वेकडेश नारायण तिवारी

१८२--शंकरदत्त शर्मा

१८३--ज्ञान्ति प्रयन्न शर्मा

१८४--कािबकुमार पांडेय

१८५--शिवकुमार मिश्र

१८६--शिवदयाल उपाध्याय

१८७--शिवदान सिंह

१८८--शिवमंगल सिंह

१८९--शिवमंगल सिंह कपूर

१९०--स्वामलाल वर्मा

१९१-- स्थामसुन्दर शुक्ल

१९२--भोचन्द सिघल

१९३--श्रीपति सहाय

१९४--सज्जन देवी सहनोत

१९५--सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री

१९६--सरवत हुसैन

१९७--सलोम हामिद खां

१९८-- साजिद हु मैन

१९९--सालिग्राम जायसवाल

२००--सिहासन सिह

२०१--सिराज हुसैन

२०२--सोताराम अव्छाना

२०३--सुदामाप्रसाद

२०४——सुवेता कृपलानी

२०५--सुरेन्द्र बहादुर सिंह

२०६--मुस्तान आलम खां

२०७--सूर्यप्रसाद अवस्थी

२०८--सईद अहञद

२०९--हबीबुरहमान अंसारी

२१०--हबोबुर्रहमान खां

२११--हरगोविंद गंत

२१२--हरप्रसाद सत्यप्रेमी

२१३--हरप्रसाद सिंह

.. जिलामेरठ (उत्तर)।

.. जिला जौनपुर (पश्चिम)।

.. अणरा प्रान्त जमीदार एसोसियेशन।

.. जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व)।

.. जिला मुरादाबाद (पश्चिम)।

.. जिला देहरादुन।

.. जिला इलाहाबाद (द्वापा) ।

.. जिला शाहजहांपुर (पश्चिम)।

. . जिला फतेहपुर (पश्चिम) ।

.. जिला अर्लोगढ़ (पश्चिम)।

.. जिला मथुरा (पूर्व) और जिला एटा (पश्चिम)।

.. जिला आजभगढ़ (दक्षिण)।

.. जिला नैनीताल ।

.. जिला प्रतापगढ़ (पूर्व)।

.. जिला अर्लागढ़ (मध्य)।

.. जिला हमं।रपुर।

.. जनारसनगर।।

.. बनारसनगर।

.. जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)।

. . जिला झांसी, जालीन और हर्मारपुर ।

. . अवध का ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन।

.. जिला इलाहाबाद (यमुनापार)।

.. जिला गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)।

.. जिला पीलं भात ।

.. जिला आजमभढ़ (पश्चिम)।

.. जिला गोरखपुर (उत्तर)।

• जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व) [१० जनवरी, १९५० से स्थान रिक्त हो गया]।

. . जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व) ।

. . जिला फर्रखाबाद।

.. जिला अन्नाव (दक्षिण)।

🕟 जिला नैनीताल, अहमोड़ा और बरेली (छत्तर)

.. जिला लखनऊ तथा उभाव।

.. जिला खीरी।

.. जिला अत्मोड़ा।

•• जिला बाराबंकी (दक्षिण)।

.. जिलाबांदा (दक्षिण)।

२१६-हिरहरनाय शास्त्री

२१५--ह्मन अहमद शाह

^{२१६}--हमरत मोहाती

२१७-- नुकुम मिह, माननीय श्री:

२१८--होनी:लाल अग्रवाल

₹१२--हैदर बढश

२२०—(क्विन)

२२१--(रिक्स)

२२२--(जिक्त)

२२३ -- :रे३=)

२२४—(रिक्न)

२२५--। रिक्त)

२२६--(रिक्त)

·· ट्रेड यूनियन निर्वाचन–क्षेत्र [१० जन०री १९५० से स्थान रिक्त हो गया]।

.. जिला फतेहपुर और बांदा।

. . कानपुर नकर।

.. जिला बहराइच (उत्तर)।

.. जिला इटावा (पूर्व)।

.. जिला मथुरा तथा आगरा।

·· मेरठ-हापड़-बुलन्दशहर-खुरजा-नगीना नगर, मुस्लिम नगर।

. . जिला बस्तो (दक्षिण-पूर्व), मृस्लिम ग्रामीण ।

. . जिला बुलन्दशहर (.क्षिण पश्चिम), साक्षा-न्य ग्रामीण।

. . जिला बाराबंकी, मुस्लिम प्रामीण ।

• • वरेली–पीलीभीत नगर, सृस्लिय नागर ।

· जिला बांदा (उत्तर) सामान्य ग्रामीण ।

.. जिला फैजाबाद, मुस्लिम प्रामीण ।

संयुक्त प्रान्तीय ले जिस्लेटिव स्रमेम्बली

के

पदाधिकारी

स्पोकर

१--माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०।

डिप्टी स्पीकर

२--श्रा नफीसुल हसन,एम० ए०, एल-एल० बी०।

सेकेंटरी

३--श्रो कैलास चन्द्र भटनागर, एम० ए०।

अमिस्टेंट सेक टरी

४--श्री कृष्ण बहादुर सके ना, बी० ए०।

मुण्रिंटेंडेंट

५--श्रो राघे रमण सक्सेना, एभ० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०। ६--श्रोसी० जे० एडम्स, बी० ए०।

संयुक्त शन्तीय ले।जस्ले ंटव असेम्बली

न (बार, ६ जनम्), सन् ११४० ६०

नम्ब े की प्रव प्रसंदात। नवा, लबनक में, ११ वर्जे दिन में प्रारम्न हुई

[म्पी,कर--माननीय श्रो पुररातम दास थ्रडन]

उपस्थित गदस्यों की सूची (१८६)

अवल िह अजिल बनाय शिह अब्दुल वाकी अञ्चल वनीद अब्दुल पजीद एनाचा अब्दुच रागिं, भीमती अद्भुल उतीन ऑर्र गईनेल फिल्मि अलगुरा। तस्त्री अल्फ्रेड नगंगान अक्षावर सिउ आाराय गोजिन्द खर, आनतीय श्री इन्द्रदेव त्रियाठी इनाय उबीयुरला, श्रीगती उदयबीर शित एजाज रशूल कमलापति निवारी करी नुर्रजा लां काली चरण टंडन किरानचन्द पुरी कुंजविहारीलाल भित्रानी क्ञलानन्द गैरोला कृपाशंकर कृष्ण चन्द्र कृष्णचन्द्र गुप्त केशव गुप्त खशवक्त राय खुशीराम

खुबसिह गगाधर गंगात्रसाद गंगा सहाय वोष ननागर प्रशाद गणपति पहाप गणेत कृष्ण च ली गोपाल नारायण वसेना गोविन्य बल्लभ धन्त, माननीय श्री गोविन्त सहाय चतुर्भुज यमी चन्द्रभानु गृष्त, पाननीय श्री चन्द्रभान् शरण सिंह चरण गिह चेतराग छेरालाल गुण्य जगन्नाथ दःस नगताय पताद अग्रयाल जनप्राथ उटा सिंह जनगढ्नां हा नेगी नगाल सिंह जाराम यर्मा तवाहरलाल रोउलगी चरीवल हसनैन लारी चहर अहसब जाकिर अली ं जाहिद ह नन । जगल हिशोर

त्रिलोकी रिन दरालदाम भगन दाकदयाल खन्ना द्वारिका प्रशाद मोर्घ दीन ज्यान् अवस्यी दोनन्शल रास्त्री दीरतराज्य वर्ष नकी ल हात नवाँ र इसी दो तहर निव स-जिल पर्नी नागावर या-निनार परन्य शेरवानी, माननीय श्री निह चहुरेन यगारील ज जुर्ज्ञासी पूर्णि र जनती, श्रीमती प्रकार बनी एउ, भीनती बागना राज्य प्रेन किः न वज्ञा फ़नेहिं नह राणा फूर्लीक वदनसिंह बनारमी डाच बलदेव प्रभाव बशीर अहमद बशीर अहमद अन्सारी बादशाह गुप्त बाबु राम वर्मा वृजमी नलाल शास्त्री भगवनी प्रमाद दुवे भगव नदीन भगवानदीन मिश्र भारत निहु यादवाद्यार्थ भीम मेन मंगला प्रनाद ममुरिया दीन महकूजुर्दनान महमूद अली खां **मिजाजीला**न् मुकुन्डलाल अग्रवाल मुज**प**क रहु नैन मुहम्मद अदील अब्बासी मुहम्मद असरार अहमद मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री महम्मद इस्माईल

मुहम्मद जनशेर जली खां मुहम्भद नबी महम्मद नजीर म्हम्मद यूसुफ म्हरपद रजावा महस्मद शक्र महस्मद शमीम मुहम्बद शाहिद ऋखरी मुहम्मद सुलेपान अदहमी यज्ञनारायण उपाध्याय रघुनाय विनायत धुलेकर रजुवंशनार ग निह रधुवीर हार राबद दाम राजाराभ भिश्र राजाराज दात्री राधाकुञ्ण अग्रवाल रात्रामोहन जिट रापेक्या- भर्मा रामकुमार शास्त्री रावकृपाल सिंह रामचन्द्र पालीवाल रामचन्द्र सेहरा रानधारी पांडे राभ नारायण राम बलो मिश्र राम मुति राम शकर लाल राभ शरण राम, स्वरूप गुप्त रुवतुद्दीन खां रोशन जमांखां लक्ष्मी देवी, श्रीमती लताफ़त हुसैन लाखन दास जाटव लालबहादुर, जाननीय श्री लाल बिहारी टण्डन लीलाघ र अष्ठाना लुफ्त अली ख़ां लोटन राम वंश गोपाल बंशीघार मिश्र विजयानन्द मिश्र विद्याधर बाजपेयी विद्यावती राठौर, श्रीमती विनय कुमार मुकर्जी

उपस्थित सदस्यों की सची

विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ राय विश्वम्भ र दयाल त्रिपाठी विष्णुगरण दुब्लिश वीरबल सिंह वीरेन्द्र शाह वेंकेटे नारायण निवारी शंकरदत्त शर्मा शान्ति प्रपन्न शर्मा शिव कुपार पांडे शिवकुमार मिश्र शिवदराल उपाध्याय शिवदान सिंह शिवमंगल सिंह शिवपंगल सिंह कपूर इयाम लाल वर्मा **र्याम सुन्दर शु**रल श्रीचन्द्र मिघल श्रीपति सहाय सज्जन देवी महनोत, श्रीमती सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री

मरबत हुसैन सञीम हामिद खां माजिद हु सैन सालिग्रान : 11 पवाल **पिहासन** सिह सिराज उसैन सोताराम अध्यान। सुरामा प्रभाव मुरेन्द्र बहाद्रर सिंह सूर्वे प्रताद अवस्थी प्वोज्रहमान अन्धारी हवीबुरहसान खां हरगोविन्द पस हरप्रनाद तत्यप्रमो हरप्र सादिनिह हरिहर नाथ शास्त्री हसरत मोहानी हुकुम िह, माननीय श्री होतीलाल अग्रवाल हैंदर बख्रा

प्रनोत्तर

स मवार, ९ जनवरा सन् १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

मार्के टिंग सेक्शन के काम ग्रोर उप पर खर्जा

*१--श्रो द्व रि का प्रमाद मोर्ज -- (क) क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्केटिए सेक्शन के नाम से कोई सरकारी विभाग काम कर रहा है ?

(ल) यदि हां, तो इस विभाग पर सन् १९४८-४९ ई० में कितना सर्च

हुआ ?

(ग) इस विभाग द्वारा अब तक कौन-कौन से काम हुए? माननीय अस सचिव (श्री चन्दभानु गुप्त)-- (क) जी हां।

(ख) १७,८९,००० ।

(ग) अन्न और रसद विभाग का मार्केटिंग सेक्शन उस अन्न को खरीवने, लाने, ले जाने और इकट्ठा करने का काम करता है जितकी राशिनंग के लिये जरूरत पड़ती ह। जब गुड़, तेल और तिलहन पर कन्ट्रोल था तब यह सेक्शन उनके भी खरीदने, इकट्ठा करने और एक जगह से दूसरी जगह भेजने का भी कार्य करता था।

श्री द्वारिका प्रसाद मार्य--जो जवाब की नक़ल मुझे मिली है उसमें 'ख' मे १७ लाख ८९ हजार लिखा हुआ है परन्तु माननीय सचिव ने १७ लाख ७९ हजार कहा है, इस

में कौन सी संख्या ठीक है?

माननीय श्रम सचिव --आप जो कह रहे हैं वह सही है।

मन ६ ८-६८ ई० की प्रपेक्षा सन १६४८-४६ ई० में गहन्छे की उपज २--शे द्वारिका प्रमाद माय --स्या नरकार कृत्या बतायेगी कि सन् १९४८-४८ ई० की अपेक्षा प्रान्त में तन् १९४८-४९ ई० में किसना अधिक ग्रहण पैदा हमा?

सन्तरीय प्रियम् चव (भ्रातिमार ग्रहमद् होरवानी)-- नन् १९४७-४८ ई० के

मुक्क बिने में नन् १९४८-४९ ई० में अधिक गल्ना पैदा नहीं हुआ।

े प्राप्ति के प्रमाद स्पेर्य-प्रयासिननीय अधिव कृषा गरेके यह बतलावेगे कि अधिक एहं तुमा में पान नगरन हुआ। या कम हुआ ?

सार्य क्रिज निचा--जावन नेहूं ओर दशा पहने से ज्यादा हुआ ओर बाक़ी खरीप ना हो उत्ता है नह कम हुना आर कुन निकास पहने पाल से और उपसे भी पहने बात ने पतने का पहाबार से करी रही।

भी द्वारिक क्षेत्र क्षेत्र मेर्न-निका इत्या जारणभी नाहर बतलावेगी कि लरीफ़ की वैदाबार क्यों कन हुई ओर विख्ला पैदाबार क्यों अधिक हुई ?

ान तीय कृषि स्वित --इन ताक शारिश को कमरत की बजह से खरीक की वैदायन कारी गई यानी बहुत कम वैदाबार हुई।

आ: व्यारिका प्रमाद मार्थ — क्या तरकार यह बतलावेगी कि सन् १९४७-४८ ई० की जोक्ष नन् १९४८-४९ ई० में अधिक जमीन पर काइत की गई, तो इत अधिक काइत में पैदाबार में कुछ अन्तर हुआ या नहीं और जो गेहूं वगैरा ज्यादा पदा हुआ, क्या वह अधिक जमीन काइत में आने के कारण ते पैदा हुआ ?

माननीय कृषि निचय --इस सबाल का जबाब देना मुश्किल है लेकिन जहां तक गर द्याल है जनोन काइत में तो जहर बढ़ी लेकिन जो जमीन काइत से आई उसके उनक्ष बिन कन यो और चूंकि ग्रन्ले का निर्व गिरां रहा इसलिये लोग उस जमीन को काइन में ले अप् लेकिन पैदाबार में कोई खाप इजाका नहीं हुआ।

ा मुहम्मद असर र जामद्र-- क्या यह सही है कि सन् १९४७-४८ ई० के मुकाबले में पन् १९४८-४९ ई० में की बीधा पैदावार कम हुई?

म नर्नाय ऋषि सिचिय--चावल और चने की ज्यादा हुई और बाकी ग्रन्ले की कम हुई।

वृक्क सरकारी विमागीं का डाइरेक्ट (सीधे) सामान खरीदना

*३--श्री मुहम्मद् अमरार ग्रह्मद--क्या यह सही है कि सरकार के हर मोहकमें के किये नामान इन्डस्ट्रांज स्टोर्स परवेज आफ़िसर के द्वारा खरीदा जाता है।

मानर्नाय पुल्सि सचिव (श्री लाल वहादुर)—हां, यह सही है।

ं - प्री मृहम्तद् ग्रस्र ग्रहण्द--क्या यह सही है कि सन् १९४७-४८ ई० ओर १९४८-४९ ई० में बहुत से किभागों ने बहुत सा सामान डायरेक्ट खरीदा?

माननीय पुलिस सचिव--हां, यह भी लही है।

*५--श्री मृहामद असराग् छा मद--न्या सरकार बतलायेगी कि किन-किन विभागों ने क्या-क्या सामान किन-किन दामों पर और कब-कब डाइरेक्ट खरीदा ?

मारनः य पुर्तिम सिचिव—डाइरेक्ट खरीदों की ऐसी तालिका तैयार करना कठिन है। इनने बहुत समय लगेगा। बड़ी-बड़ी खरीदों की एक संक्षिप्त तालिका† पेश है।

त्रा सहम्मद प्रनरार ग्रह्मद—क्या तरकार वतलाएगी कि डायरेक्ट पर्चेज का क्या कोई हिपाव नहीं रखा जाता है?

मानना उपित्रस सचि ।--हिलाब तो रखा जाता है।

श्री मुहम्मद् ग्रसरार ग्रहमद्—न्या सरकार बतलाएगी कि जब इस सवाल का नोटित ५-६ महीने पहले दिया गया था तो सरकार ने इसका जवाब मालूब करन की कोशिश क्यों नहीं की?

माननीय पुलिस सिचिय—मालूम करने की कोशिश इसलिये नहीं की गई जैसा कि जवाब में लिखा हुआ है कि एक लम्बी लिस्ट तैयार करनी पड़ती और ज्यादा वक्त लगता, इसलिये माननीय सदस्य यह जुनासिब समझेंगे कि इसनी महनत वेकार थी।

श्री मुहामद् श्रस्रार श्रह्मद्—नया अरकार बतलायेगी कि इंजीनियरिंग विभाग ने करीब १ करोड़ का नाल डायरेक्ट खरोड़ किया, उसके लिये ऐ ती कीन सी जरूरत पेश आई कि उसने यह डायरेक्ट पर्नेंज किया और वह स्टोर पर्नेंज डियार्टमेन्ट से नहीं खरीदा गया?

माननीय पुलिस सिचिव—-गालिबन पूरा नक्ष्मा माननीय सदस्य के पास है उसमें बतलाया गया है और वजूहात दिय गए हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ा और यह भी बतलाया गया है कि बहुत से ऐसे मौके आए कि जिसम डायरेक्ट पर्चेज करना पड़ा बजाय इसके कि स्टोर पर्चेज विभाग के द्वारा यह काम किया जाता और मजबूरी की बात हो गई।

श्री पृहम्मद् ग्रसरार ग्रहमद्—न्या सरकार बतलायेगी कि जितनी चीजें नक्कों में दी गई है उनके अलावा और कुल कितनी खरीदारी हुई होगी?

माननाय पुत्तिस सचित्र--यह इस समय नहीं बतलाया जा सकता है।

श्री मुहम्मद असरार ग्रहमद--क्या सरकार यह बतलायेगी कि पहले से महकमों को यह क्यों नहीं लिखा गया कि डायरेक्ट पर्चेज न की जाय ?

माननीय पुलिस सिचिय—इन तरह से कन्ड्रोल रहता है कि एक डिपार्टसेन्ट इस काम के लिये मुकर्रर है बजाय इस के तेजो में कान कर लिया जाय। हिदायन देने को अब जहरन इसिलये हुई कि पहले हर डिनार्टमेंट इस बात का फैसला कर ले और आइन्दा डायरेक पर्नेज न करे।

श्री मुहम्मद अस्तार ग्रहमद्--क्या यह सही है कि महकतों ने गलत तरी के से सामान खरोदा और इसा वजह से सरकार को यह हुका जारो करना पड़ा?

मानमीय पुछिस सिचा — गलत तरोके पर नहीं, जैया कि वैने कहा कि कन्दोल रजने के लिये अगर एक ही जगह से सारी खरीदारी की कार्यवाही होती हैं तो खर्व सुनासिय तरीके से हो सकता है और इसीलिये यह हिदायत की गई।

*६--श्रो मुहम्मद ग्रसरार ग्रहमद--इस तरह खरीवने के क्या कारण है और यह खरीवारी किसके हुक्म से की गई?

माननोय पुलिस सचिव-कारण नीचे दिवे हुये हैं-

- (१) स्टोर पर्चेज कत्त्र के अन्दर अवस्था विशेष म ऐसी खरीद करने के अधिकार हैं।
 - (२) डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज आवश्यक होते पर ऐसी खरीद की आज्ञा दे देते हैं।
- (२) कभी-कभी शीख़ ही खरीदने की आवश्यकता होने पर सरकार स्वयं ही ऐसी आज्ञा दे देती है।
- (४) अवसर अफ़सर लोग स्वयं ही बिना आज्ञा लिये ऐसी खरीद कर लेते हैं।
 *७--श्रो पृहम्मद् श्रसरार श्रहमद्--क्या यह सही ह कि सरकार ने दुबारा
 हिदायत की रू, आगे डाइरेक्ट सामान न खरीदा जाय?

माननोय पुलिस सचिव-हां, पह सही है।

गडवान ऊन-योज राष्ट्रों के मन्द्रन्य में पूक्त-त (क्

ं ८-- भ्रास वान मेह (अनुपत्थित) -- क्या सरकार यह बतलाने की छना करेगी कि मोजूर पहत्र के अन-योजनाओं ने कर्याग्य योजना की अपेक्षा कितना असिक खर्वा हो रहा है ?

मान नाय उद्योग मिचव (श्र केशवदेव नालबीय)—ाड़बाल में कार्रीय ना की अपेक्षा वर्षयान देवच्यारेंट योजना में कोई खाम अधिक खर्च नहीं हो रहा है जैसा कि निम्नोनित प्रांत्रहों के विदित्त हैं —

-	१९ <i>४</i> ६− <i>४७</i>	3629-28	१९४८-४९	
	ন্ ১	そ 0	₹ ०	
	55.630	91000	८२,०००	

डबरानेट योजना चरु,ने के लिये बुनाई व कताई इत्यादिका सामान १९४७-४८ ई० में खरीदा गया।

*९-- श्री भगवानासह (अनुपस्यित)--(क)क्या यह बात सही है कि सरकार वर्नेनान डेवलामेंट योजना में परिवर्तन कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो वे परिवर्तन क्या हैं?

मानतीय उद्योग मिन्यव (अनुरियन) -- (क) वर्तमान डवलगर्मेंट ऊन-योजना में सरकार अभी कोई परिवर्तन नहीं कर रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

*१०--श्रे: भगान चिंह (अनुपस्यित)—(क) क्या यह बात सत्य है कि गढ़वाल अन-रोजना में कराई व गुनाई का कार्य दिन-दिन घटता गया है और इस समय समूची योजना में कताई का कार्य बहुत ही कम है?

(ख) क्या यह सहीह कि कर्माज्ञयल योजना के अन्दर सन् १९४५-४६ ई० में सालाना उत्पत्ति ६० मन के क़रीब थी?

माननीय उद्योग सचित्र (अनुपस्थित)--(क) नहीं।

(ख) हां।

*११--श्री भगवान सिंह(अनुपश्यत)--(क)क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि गुरु कर नोजन: के बोत्रा कराई के द्र केवच अन बेचने का कार्य कर रहे हैं?

(ख) यि वे कनाई भी कर रहे हैं, तो क्या सरकार कृपा करके प्रत्येक केन्द्र के सन् १९४८-४९ ई० के उत्नादन के आंकड़ देगी ?

माननीय उद्योग सचित्र (अनुपहियन)—(क) गड़वाल योजना के अन्तर्गत कताई केन्द्र केवल अन विकास काड़ी कार्यनहीं कर रहे हैं बल्कि कताइयों को शिक्षा देना, कताई व रंगाई का प्रवार करना व रंग मशीन और चर्बे आदि की विकी का कार्य भी करते हैं।

(ख) जैता कि प्रश्न १० (क) के उत्तर में प्रकट किया गया है कि सरकार का ध्येय वर्तमान ऊन-पोजना के अनुसार खुद कताई व बुनाई कराने का नहीं है, इसिलये केवल नमूना तथा अन्य प्रयोगों के लिये १९४८-४९ ई० में केवल १२ मन तागा कतवाया गया है।

* २२ - - त्रें भावान सिंह (अरुास्थिर) - - (क) क्या नियमानुकूल सब कताई व बुनाई केन्द्र सहयोग समितियों के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं ?

(स) यदि उपर्युक्त नियम का उल्लंघन किया गया है, तो क्यों और कितनों के द्वारा?

अइनोत्तर

माननीय उद्याग सिचित्र (अनुपस्थित)—कताई केन्द्रो मे योजनानुकूल कार्यहो रहाह। बुनाई केन्द्रो का कार्य अभी सहयोग समितियों ने नहीं लिया है, परन्तु यह कार्य तीन केन्द्रा में विभाग अपनी देखभाल में करा रहा है और जब तक कि समितिया इस कार्य को अपने हाथ से न ले सकेगी विभाग कराता रहेगा।

(ख) नियम का कोई उल्लबन नही हुआ।

*१३--श्रो भगवान सिह (अनुपस्तित)--क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि गढवाल अन-पोजना के मुख्य कार्यालय पोड़ी में उतना बड़ा स्टाफ क्यो रखा गया है जिसका सालाना खर्वा करीब २०,००० हपया है जबिक उत्पादन केवल १,००० रुपये के क़रीब हैं?

माननीय उद्य ग सिच्य--पोडी इस योजना का केन्द्र है। यहा पर दिवीजनल सुगरिन्टेडेट इन्डस्ट्रीज का दफ्तर है ओर बुनाई तथा रंगाई का कार्याल है। इसमें लाभा १२,००० ६० सालाना पर्व होना है। मुख्य कार्यालय में एक डी० एन० आई०, ६ क्लर्क, नीन चारासी ओर एक वोकीदार काम करते हैं।

'१४--श्राभगवान सिह (अनुपस्थित)—(क)क्पायह बात सत्य है कि तर से गढ गल कर-पोजना कार्य कर रही हैं (अर्थात् सन् १९४४ ई० से) कोई भी उद्योग शिभाग का आफिसर निरीक्षण करने को नहीं गया ?

(ख) यदि हा, तो क्यो [?]

माननीय उद्याग मिच र -- १३ तात सर गही है योजना का निरीक्षण निम्नाकित अकसरो द्वारा हुआ--

> १--श्री एम॰ के॰ िर्ध्य , गृ॰ डी॰ आई॰ सी॰ ता॰ ४-१०-४४ २--श्री रब ,, ता॰ १८-५-४६ ३--श्री सी॰ बी॰ दुबे ,, ता॰ २४-४-४७ ४--श्री एच॰ बी॰ शराफ डी॰ डी॰ जाई॰ सी॰ ता॰ २७-५-४८

(ख) यह प्रश्न नही उठता।

*१५--श्राभगरान सिंह (अनुपिस्थत)--(क) क्या यह बात रात्य है कि जो दो अहमी गड़बल अन-पोजना के अन्तर्गत सरकारी खर्चे पर ट्रेनिंग के लिये हाइमीर भेजें गये थ अब इस योजना में कार्य नहीं कर रहे हैं ?

्र (ख) यदि ऐपा है, तो क्या सरकार कृया करके यतलायेगी कि क्यो उन दो श्राद्मियो को इस योजना के अन्दर कार्य में नहीं रखा गया जहा के लिए वें रारकारी खर्चें पर ट्रॉनिंग पाने को भेजें गये थे ?

माननीय उद्याग सचिव--(क) व (ख) इनमें से दोनो आदमी उद्योग विभाग में ही काम कर रहे हैं। एक सरकारी पोलीटिक्नीक इन्स्टीटघूट श्रीनगर गढ़वाल में बुनाई विभाग में काम कर रहे हैं और दूपरे रिष्यूजी स्कीम में थोडे समय के लिये मेज दिये गये थे, परन्तु इस समय उनकी नियुक्ति इसी योजना में असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट के पद पर हो गई हैं। उनकी योग्या। व अनुभव का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा रहा है।

काइमीर में छोटे रेशे की ऊन का प्रयोग होता है। गढ़वाल में लम्बे रेशे की अन काम में लाई जाती है। इन कारण से शिक्षार्थी दूपरी योजना में अधिक लाभदायक साबित हो रहे हैं।

*१६--श्रा भगवान सिह (अनुपस्थिन)--क्या यह बात सत्य है कि जो रूप-रेखा गढ़वाल ऊन-योजना की सन् १९४८-४९ के बजर में मंजूर हुई थी, अब तक वह चाल नहीं की गयी है, किन्तु उसके अनुसार आदिमियों की नियुक्ति होती जा रही है ? मान्तीय उद्य ग मिचव-नंजूर की गई योजना के अनुसार कार्य हो रहा है, आवश्यक्यातृमार आविमयों की नियुक्ति की जा रही है।

विलापत को अमेरिकः के विश्वविद्यालयों में प्रान्त के विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालयों के मान्यता

'१५--अ'मन पृष्णिमा वनजां--क्या यह उच है कि विलायत व अनेरिका के विश्वविद्यालयों से यह के विश्वविद्यालयों की एउ० ए० और बी० ए० डिग्री पंजूर नहीं की अपनी है ?

सानिय दिस्य सचिव के स्मानिशे (श्रामन्फूज़रेहमान)--जहां तक हम जानने ने यह यात जीक नहीं है।

श्रीमर्न परिचा बनर्जी—द्या तरकार निश्चित रूप से जानती है कि हमारे प्रान्त् की बनीर्जीयदोन की डिमियां अभरीका शंर विलायन में रेकग्नाइज होती है और हमारे लड़कों को किर ने बहां कोई इम्नहान नहीं दिलाया जाता है ?

भी महरू जुर्रहमान—जहां तक नालून है, ऐसा ही है कि जो लड़के हिन्दुस्तान की यूनी— वीनिटिशों ने बना जाते हैं वे उन्हीं डिडियों की बिना पर ले लिये जाते हैं, लेकिन अगर कोई खान मजनून वहां ऐसा होता है जिसकी बाबत वह नहीं साझते है तो उस सब्जेक्ट में उनकी नैशरी कराने के बाद फिर इम्तहान लिया जाता है।

*१८--श्रीमती पूर्णिमा वनर्जी---यहां से बी० ए० पास करके जाने वाला विद्यार्थी क्या वहां जाकर एम० ए० पढ़ने के योग्य माना जाता है या उसे कोई और इम्तहान देना पड़ना है?

श्री महफू दुर हमान-जी हां। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१९—श्रीमती पूर्णिमा वनर्जी—क्या हां के विश्वविद्यालयों का कोई एम० ए० पास विद्यार्थी विजायत में पी० एच० डी० के रिसर्च कोर्स में दाखिल किया जा सकता है या दाखिल होने के पहिले उसे वहां कोई और इस्तहान देना पड़ता है?

श्री महरू जुर हमान-जी हां, प्रश्न का भाग नहीं उठता।

*२०—श्रीम ी पूर्णि मा वनजीं—क्या विलायत में हमारे प्रान्त के बनारस, अलीगढ़, इलाहा गढ़, लखनऊ और आगरा यूनीविसटी की डिग्नियां समान तरीक़े से मानी जाती हैं या रेजिडेंशियल यूनीविसटी के डिग्नी वालों को ही माना जाता ह ?

श्रा मह्फू हर्र हमान-जी हां। जिन यूनिवासिटियों के नाम दिये गये हैं उनमें से समी की डिग्नियां मान्य होती हैं।

*२१—श्रीनती पृष्णिमा वनजीं—जो विद्यार्थी यहां से स्कालरिशप (छात्रवृत्ति) लेकर बाहर जाते हैं, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत गवर्नमेंट से की है ?

श्रो महफूजुर हमान—जी नहीं।

श्री द्वारिका प्रसाद मोय — नया सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अमरीका और विलायत के बी० ए० अथ वा एम० ए० पास विद्यार्थि यों को भारत के बी० ए० अथ वा रु म० ए० पास विद्यार्थियों से अधिक महत्व दिया जाता है ?

श्रा महफूजुर हमान--ऐसी तो कोई बात नहीं हैं।

भिकारोपुर जिला पीलीभीत से पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत

*२२— श्री मगवान सिंह (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार के पास कोई शिकायत पंचायत के चुनाव के विषय में भिकारीपुर, जिला पीलीभीत से प्राप्त हुई है ?

- (ख) यदि हां, तो उस पर क्या विचार हुआ ?
- माननीय विशासन सचिए (शि आंत्माराम गोविन्ट सेंग्रान्न (त) जी हा। (ब) ति परीपुरगाँव नमाव प्यानी अवान्त में पुनः गुनाय करा ेवा निर्णय हुआ।

रक्षक-दता रिपुरिस मे प्रान्द

१२३--श्री कृपा शंहरम--वा सरकार छवा जरके वहारी कि रहतक-दल और पुलिस से क्या प्रस्क है ? यह सरकार रहा कर के हाला हा। विकास आहि रहा ही नियमों की एक प्रति भवन के पानने उपरित्त हरे हैं ?

माननीय पुलिस स्वित--त्र ता विकासिश कर्य रचने विवासकतानुसार रक्षण दल के सदस्य पुलिस की सहायता करते हैं, रक्ष -- के वार्ति तथा अधिकार आदि सम्बन्धी नियम १९ जून सन् १९४८ ई० के विवास विकास क्षेत्र है।

*२४--श्री कृपा शंकर-- क्या सरकार शा सालून, कि २५१०-६ जोर पुलिस में देहाती क्षेत्रो में अकसर कशमकश रहती है ? यदि हा तो इनके मिटाने के लि रे रस्कार क्या उपाय कर रही है ?

माननीय पुलिस सचिव--नही। प्रश्न नही उठता।

कानपुर म्यनिसिर्यालटी के चेयरमेन ना त्यारका

*२५--श्री गन्शीध्यर मिश्र (अनुपस्थित)--वया सरकार के पार म्युनिसिपल बोर्ड कानपुर के कुछ सदस्यों ने चेगरमैन के हटाने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की क्रपा करेगी कि--

(क) वे आवेत्न-पत्र सरकार को किन तारीखों को मिले थे?

- (ल) क्या वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कानपुर के पास जान ओर रिपोर्ट के लिये भेजे गये थे? यदि हा तो क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कानपुर की रिपोर्ट सरकार की प्राप्त हो गई है?
 - (ग) उप रियोर्ट पर नरकार ते द्या किया?
 - (घ) का। सरकार उप रिपोर्ट को भाव दे गायने अवाद न ?

माननीय विद्यासन सन्तिव-विविध्य के जानपुर के तार व्यस्त (श्री मन्ना लाल, श्री राम लाल तथा श्री गंगा नारायण विद्या विवेश विद्या के व्यवस्थ में केवल एक संयुक्त बिना तारीख का आवेदन-पत्र कमिन्स के वाल भेजा गा

- (क) वह सधुवत आवेदन-पन्न कमिन्नर को २८ अस्ट्रा, १९४८ ई० का मिला और उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा कमिन्नर की रिगोर्ट तरकार का १४ फरवरी १९४९ ई० को प्राप्त हुई।
- (ख) यह सयुक्त जानेदन- । जिह्नर ने जिल्लियट मिलिएट्ट रे पास जाच और रिपोर्ट के लिये भेजा था। डिल्डियट मिलिस्ट्रेट की रिपोर्ट तर का का पास्त हो गई है।
 - (ग) सरकार ने चेपरमंन के रिएइ कोई कार्धवाही करना कित गहा समझा।
- (घ) जन-हित की दृष्टि से प्रकार उस रिपोर्ट में नवर के नायने उपारियत करना उचित नहीं समझती।

२६--श्री वन्शीधर मिश्र (अन्गस्थित)--क्या यह गय है कि म्युनिसिगल बोर्ड कानपुर के वेपरमैन ने अपने पद से त्याम-पत्र अ कार को दे दिया है ? यदि हा तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि--

(क) त्याग-पत्र किम तारीख को दिया गया?

(ख) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट के पास वह त्याग-पत्र किस तारीख से किंग तारीख तक रहा ?

- इक्षित्मर में बाद बहु त्यारा-यह किस नारीख ने क्षिण तारीख निक रहा ? चारान क्षणान्यम चास्त्रिय-म्युनि ज्यित होई कानपुर ने सेयरतैन से गामे यह नादो हार ग्यान-गह दिया।
 - च व्यक्त स्वाप-व्यव ३० विन्यार १९४८ ६० को ओर ह्यारा १० लगावर, े० को देवा प्रा
 - च विनिन्द किन्द्रेड ने प्राप्त न्या न्यासानाम ३० दिन्स्बर, १९४८ देव ने १५ चन्द्रने प्रश्चित्रक रहा आर द्वारा न्यासान्यक १७ वहान्यर, १९४९ ईविसे २६ मारमा १ ४ के तक रहा
 - निवासन के प्रवास कार क्यास रह का कार है। १९४९ ई० की पहुच जेन एम निवासन के प्रवास १९४९ ई० सी बायर के जिया। दूररा ध्यास - पह निवास के प्रवास कर सम्बद्ध १९४९ ई० के ३० स्वस्थर, १९४९ ई० कहा गृहा १
- २७--श्राह्मीयर विश्व अन्य स्थित '-- (क ' व्यापह सत्य है ति । रागर से इस्तीतिता बाह ते सेप्रकेंसी के इक्तीनों से सब्द सकते का अधिकार जुन ते । ४० वित्त में दिसीका तीरमा को पे शिया था ?
- ा पेह्नोहासरा र प्रदेशको ह्या करे। ते हाराप्-द्रपात सरापा के प्रस्ता के पर हु-1 हार प्रप्तिक के छात्रप्

यानिय करवान जिल्ला, नामिति न्युनिनि न बोर्डो के पेरमैने देर गाण्य ने स्वीकार पाने ना अदार किन्द्रने को तो यूव थीं क न्युनिश्यिक हैं उहा, श्र है वे जन्मन प्रमान को है। निटोक्युनिनियल घोडों के चे रखेनों के त्यागथत्र तर्ज कार परने जा प्रिका को उन्न है उन मरवार को निया है उने जून, १९४१ ईव में का दिन्तरों ने दिना गाण था. बन्नु पर कि नियान ने अपने पर चई, १९४९ ईव में द्रापस के निज

व परण स्थापन जिनके नदीक, च े अधिवार कि शिवस का। जा चेत्राचा ने विमाण ने पश्चित्रेक १९४१ - कि नो वाप किया। दूसरा त्याण—१, कि को नर्नाणा माने का पीना परनार को शानह परकार १९४२ दिंग्या १९०० द्विकी पहुंच अप उसे पाणार ने १३ दिनागर १९४२ ई० की पीन के ए किया उत् स्वाप्ति कोई के १० दिनम्बर १९४९ ई० क विर्वा

वरान के बना मालवा गाँर विधवाद्रने। की पुलिस द्वारा जा ब

२८—श्री रजनागय ग्राट याण्य—स्या सरकार कृषा करके बतायेगी कि दगारस गहा न हुए जनायाच्य ओर विधनाध्यम खुले आम लडिनियो की जिल्ली करते हैं ? स्या होता में बनारम पुनिष्ठ द्वारा उना जाच हुई है ?

धारिकुन् हन। न-वनार परारो कुछ अनाथानको के धारे ने सुनने में आता ही वेलडिकियों की बिकी करने हैं। इस विषय में अभी जाव ही रही है।

अपूर प्रिचा वन परि—अभी सरकार ने पताथा है कि कुछ अनामालयों के बारे ने बार्म हो होने हा रही है, क्यातक हमें इन कार्यवाही की सूचना थिल स्वती है?

यान प्रिताल विश्वित प्रियो नम्पूर्णान न्य) — मने यह नहीं कहा कि किसी एक या अधिन जनायान ये कि किसी एक या अधिन जनायान ये कि कि किसी एक यो अधिन जनायान ये कि कि एक जमेटी बैठाई गई थी और उमकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट के मंजूर होने के बात की भी अनाथालय है उन मभी के मुनाहित होगी। एक ही के विशेष नहीं होगी। हां, एक अनाथालय के खिलाफ हुए जिल्ला प्रकार के भी और जैमा माननीय सदस्यों ने अखबारों में भी देखा होगा, उमके बारे में युन्तिन द्वारा अस्त हुई और हो रही है।

श्र रचना^र्णा उपारण यान्या २०१४ हारायन आलयो । तसी निरीक्षण मी होता ह[े]

शाननाय तिस्त राजिए--कोई राज्ये । निरीक्षण तो तोता नहीं है लेकिन जैसा कि हाउम को पार्व है एक भीटी दो नजाई गई या जाने क मिरारिकों की हा उन सिफारिका का प्रवन्त है। दान के पर्वा के सिफारिका का प्रवन्त है। दान के पर्वा के सिफारिका प्रवन्त है। दाना ।

श्र अस्तार्यमा उपाध्या -- गार्यकाणा को कार की जोर के को व्याप्ति रहायता दी जाती है ?

सामनीय दिशा व्यक्तिय -- पश्चित्रा हिन्दे ने ती िसी को दी जानी हो। के जिन किनी चार की याज्य रहा दाणा जा मारा गिकि प्रेश्नर भे ऐसी सेकटः मन्थ्ये हा

:सि-शुपार-या साके प्रतर्गत असी का उपर

, ३८—ा भारत ति : भान्यासाय — (क) वर्ण मनार यह दलावे वे ला क्रोगी कि जबसे उसने ग्राम सुधार योजना आ। अ वे तता नवा तता का का कि वे लिस—ि व गावों का किस—िक्स दिशा वे सुधार हुँथा ?

(ख) उनसुषारो में जाजातक हुक तिकारका गुआर ⁷

जो बर्च हुआ है उपका ्त्र अनुवान देना विश्व का कि कार्ति पान विभाग होरा जो बर्च किया जाता है यह उसी दिशाण के रजट में उचित जाता है।

सदस्या को जिकारिक पर हर, कारा तथा एकं। क लाज ने

'३९-- में। भारत निर्याद्वाचा । -- का रजार यह बताने की जुण करणी सन् कि १९४७ ई० से एम० एल० ए० तथा एम० ए०० कि कि कि कि कि कि कार्य कार, लारी और दूक के लाइसेस कितने लोगों को थे रुप्य उनकी दिने गर्थे ?

साननीय प्रतिस्न नांच्य —— किसी २ ट्यास्त को नेया दर्शा के उसकी दरख्वास्त पर किसी एस > एल० ए० जा एस० ९०० सी ने क्लिंग्सिस की थी पर्शमट नहीं दिये गये।

एम० एल० एज तथा एत० ए०० तीज को तीर पविचा करियर तथा तीन प्राइवेट कैरियर के परमिट दिये गये।

श्री भा त सिहय द्वाच र्य--जिन लोगो को परिषट दिये गरे उत्मान सी दरस्वास्त पर दिये गये है या निकारित पर ?

मानरीय पुलिस सचिव-- उनकी वरस्वास्तों पर।

भी भारत सिंह याद्वाचार्य --क्या जिन सरस्यास्तों के बुलाबिक पहले परिमट नहीं विधे गर्ये थे, उनमें और बाद में जिनके जुलाबिक परिश्ठ विधे गर्ये, उनमें कोई फर्क था ?

ना निर्माय प्रश्तिस स**िय--जिन** वरस्वास्तों पर जब परिमाट नहीं दिले गये थे उस सम्ब दिवक केरियर देने पर रकायड थी, तेकिन जब परिमाट दिये गये और किन्हीं दरस्यातों पर, सब वे स्कावटें हट गई थीं। यह इंशके पहले थी भार है।

जिलेबार ऋषि के श्रीजारों का कोटा

*४०--धी जते हिन्द राखा--न्या तरकार क्रवा करके बतायेगी कि कृषि के अंजारों (इस्ट्राच्ड इस्कीनेंट्स तथा मायूली धीजार) के लिये प्रति वर्ष प्रति जिले के लिये कोई कोटा निश्चित है। अगर है, तो किस जिले के लिये कितना-कितना ?

माननीय हारि सचित्र--जिन जिलों को छुवि के औजारों के लिये कोटा दिया गया है उनका नाम और कोटा नत्थी को हुई सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क्र' आगे वृष्ठ ७० पर)

श्री कतेह सिंह राखा--क्या सरकार कृया करके बतायेगी कि फेब्बोकेटर्स को क्या कोटा कंट्रोल के दामों पर दिया जाता है।

माननीय अन्न सचिव-- जी हां।

श्री फतेह सिंह राखा--क्या यह सच है कि कंट्रोल के दामों पर कोटा दिये जाने पर जो औजार बनते हैं उनकी कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं है ?

माननीय इस सचिव--अब तक ऐसा ही रहा है।

श्री फतेह सिंह ाणा--वया सरकार को यह जात है कि यह औजार किसानों को कंट्रोल के दामों पर नहीं थिलते?

माननीय ग्रन्न सचिव--तरकार को यह बात ज्ञात हुई। इसीलिये सरकार ने एक नई योजना बनाई ह जिसके अन्तर्गत यह संभव हो सकेगा कि बंबी हुई की मत पर किसानों को आजार जिल सकें।

श्री कुन्य विहासी लाल शिवानी—न्या तरकार प्रत्येक जिले में कोटा देते समय इस बात को ध्यान में रजती है कि इस जिले में किसने औजार यनते हैं और उनमें कोई फर्क नहीं होता ?

जाननीय ग्रस सि वय--अभी तक तो ऐसा ही रहा है कि फेब्रोकेटर्स दो तीन जगहों पर ही ज्यादा संख्या में थे। उन्हीं जिलों को कोटा देते थे। लेकिस अब नई घोजना के अन्तर्गत हर जिलों को कोटा बांध दिया गया है। जिन जिलों में इनकी संख्या ज्यादा है वहां ज्यादा कोटा दिया गया है।

*४१—ओ फतेह सिंह रागा—स्या पासूली ओजार किसी सरकारी कर्मचारी हारा तैयार करावे जाते हैं। यदि हां, तो किस अफसर के द्वारा और तैयार करता है?

माननः य कृषि सचिव--प्रामूली आंजार किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा नहीं तैयार कराये जाते हैं। विजलों के प्राप्त होने पर कृषि के आंजारों को अधिक संख्या में तैयार करने का कान क्षेन्ट्रल वर्कशाय, बरेली, में शीघ ही शुरू किया जायेगा।

जिला वं डॉ के अध्यापकों के वेतन का वकाया

*४२--आ वादशाह गुप्त--क्या तरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बोर्ड कानपुर के अध्यापक मंडल का वेतन कितने मास का देना बकाया है ?

श्रो महफूजुर हमान-कोई बकाया नहीं है।

*४३—-श्राबादशाह गुण्त--स्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ता०३१ मार्च सन् १९४९ ई० को किन-किन जिला बोर्डी में अध्यापक मंडल का बेतन पृथक-पृथक मार्च के बेतन के अतिरिक्त कितने-कितने यात का बेतन देना शेष है ?

श्री अहफूजुर हमान--३१ नार्च सन् १९४९ ई० की समस्त बोडों में सार्च के वेतन के अतिरिक्त अध्यापकों का किसी भी माह का वेतन बाकी नहीं था ।

*४४—श्रो बादशाह गुर:—-जिला बोर्डो के अध्यापकों को प्रतिपास उनका वेतन मिलता रहे और जिल जिला बोर्डो मेंदे तन देना बकाया है यह तुरास देहें, इसके लिये सरकार क्या क़दम उठा रही है ?

श्रो महफूजुः हिलान- यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रांत के को सापरेटिय डिपार्ट मेंट के कर्ष सारियों के वारे में ब्यारा

*४५--भ्रो निहालुशन-क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि युक्त प्रांत के कोआपरेटिव डिपार्टसेंट से कितने इन्स्येक्टर और कितने आडीटर हैं ?

माननीय पुरित्स सचिद--इन अधिकारियों की संख्या निम्नलिखित है --

इन्सरेक्टर--३२०।

आडीटर--२८०।

*४६—-श्री निहालुह्गीन—क्या गवर्नमेंट मेहरवानी करके इन ओहदेवारों की एक लिस्ट देगी और यह बतलायेगी कि इन लोगों की कितनी सिवस है और इनमें कितने मुस्तकिल हैं ?

माननीय पुछिछ क्रिका—इन अधिकारियों की सूची अधिक लम्बी हो जाने के भय से नहीं दी जा रही है। इन्सपेक्टरों में से २०२ पद स्थायी हैं और ६ पद शोघ ही स्थायी होने वाले हैं।

*४७—-भ्रों निह्य हिन्द--एया गवर्नमेंट मेहरवानी करके उन ओहदेवारों की एक किस्ट देगी, जो अभी तक मुस्तकिल नहीं हैं ?

माननीय पुलित सचित--अस्थायी अधिकारियों की लंख्या निम्नलिखित है:--

इन्सपेवडर--११८।

आडीहर--३८।

सूची जम्बी हो जाने के कारण नहीं दी जा रही है।

*४८--थ्रो निह् खुर्न--व्या धवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि वह ओहदेवार जो तीन साल या उत्तरे ज्यादा काम कर चुके हैं, क्यों मुस्तकिल नहीं किये गये हैं ?

माननीय पुिस्प सचिव—इन्सपेक्टरों में से सिवाय उनके, जिनका स्थायोकरण विचारा— धीन हैं तीन साल से अधिक सेवा बाले सभी इन्सपेक्टर स्थायों हैं। उसी प्रकार आडिटरों में से वह सभी आडीटर स्थायों हैं जिनकी सेवाएं तीन वर्ष से अधिक की हैं, सिवाय कुछ सुपरवाइ जरों के जो कि स्थानापन्न आडीटर हैं और जो कमीशन द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, तथापि एक और आडीटर जिसका काम संतोषजनक नहीं हैं।

*४९--श्री निहालुद्दीन--क्या गवर्नमेंट वेहरवानी करके यह बतलायेगी कि इस महक्तमे में कुल कितनी मुस्तकिल जगह इन्स्पेक्टरों और आडीटरों की हैं ?

माननीय पुलिस खिचव--इस प्रक्त का उत्तर प्रक्त संख्या ११६ में दिया जा जुका है।

*५०--श्री निहालुद्देन--क्या यह वाक्या है कि इस मुहकले में कुछ ओहदेवार ऐसे हैं जो लगातार १० लाल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुस्तकिल नहीं हैं ? यदि ऐता है, तो क्यों ?

माननीय पुनिस सचिव--नहीं, प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता।

ग्रोद्यागिक तथा न्यापारिक ग्रन्वेषण के लिये किसी संस्था की स्थापना

*५१—श्रो चतुमु न दार्मा—क्या सरकार ने अभी तक कोई इन्डस्ट्रियल (औद्योगिक) एवं कर्माज्ञयल (व्यापारिक) रिसर्च (अन्वेषण) संस्था के लिये कोई इन्स्टीट्यूट आर व्यूरो (संस्था) कायम की हैं?

माननीय पुलिस मचिव — हां स्थापित है। हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इन्स्टीटचूट कानपुर की एडवाइचरी कमेटी औद्योगिक अन्वेषण के विषय में सलाह देती है। हारकोर्ट बटलर इन्स्टीटचूट कानपुर में इन विषयों पर रिसर्च होती है।

*५२-श्री चतुर्भु ज शर्मी-यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पृळिस सचिव-उपरोक्त संस्था सन् १९२१ में संस्थापित हुई।

*५३—श्रो च्रनुमु ज रामी—क्या उक्त विषय में यू० पी० के विश्वविद्यालय से कोई जांच की गई है या नहीं ?

माननीय पुलिस मचिव--उपरोक्त संस्था में संयुक्त प्रांत के कुछ विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व है।

श्रो चतुर्भेज शर्मा—प्रश्न ५३ का जवाब नहीं दिया गया है। मैने यह पूछा था कि विश्व-विद्यालय से कोई बांच की गयी है या नहीं ?

माननीय पुलिस सिचित्र—पदि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व इसमें है तो इसका मतलब यह है कि पुनिर्वासटी के प्रतिनिधि वहां मौजूद है और उनकी देख—रेख म यह काम होता है। अगर कोई खास बात बुराई या गलती की होगी तो वह बतलायेंगे।

*५४—भ्रा चतुर्भुत शर्मा—क्या सरकार विश्वविद्यालयों के इस कार्य के लिये कोई बान्ट देती हैं?

माननीय पुलिस सचिव-जी हां।

श्री चतुर्मुज शर्मा—सरकार प्रतिवर्ष कितनी प्रांट देती है ?

माननीय पुछिस सचिव—इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री चतुर्भूज शर्मा — क्या सरकार कृपा करके बताएगी कि सन् १९२१ से अब इस संस्था न कोई नया अन्वेषण किया है ?

माननीय पुलिस सचिव-यदि माननीय सदस्य देखना चाहेंगे तो उनको नोट दियाः बा सकेगा।

बदायूं में पडल्ट प्जुकेशन के लिये रुपये का वितरस

*५५—श्री मुहम्मद् अस्नार अहमद्—(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एडल्ट एजुकेशन के लिए जो प्रान्ट दी जाती है, उसके अन्तर्गत बदायूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए जो रुपया रक्का गया है वह रुपया उन लोगों के पास जिनकों कि प्रतिमास मिलना चाहिए था, नहीं मिला है ?

(स) उपरोक्त रुपये के वितरण का क्या नियम है ?

श्री महफूजुर हमान -- (क) जी नहीं।

(स) सरकारो प्रौढ़ पाठशालाओं के अध्यापकों का बेतन, महंगाई और कन्टिन्जेन्सी जिले के डिप्टी इन्स्पेक्टर के द्वारा खबाने से निकाला जाता है और उसे या तो मनीआईर से या स्वयं व्यक्तिगत रूप से वितरण कर दिया जाता है। पुस्तकालयों और वाचनालयों के एलाउन्स और कन्टिन्जेन्से का रुपया भी इसी तरह बरामद करके वितरण किया जाता है। सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सहायता की स्वीकृति जिला के प्रौढ़ शिक्षा समिति अथवा जिला के स्कूलों के इन्स्पेक्टर की सिफारिश पर शिक्षा प्रसार के अध्यक्ष देते हैं और उसका वितरण डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल के द्वारा होता है।

इसी तरह प्रौढ़ पाठशालाओं की सहायता की स्वीकृति भी जिला प्रौड़ शिक्षा सिमिति या डिप्टी इन्स्पेक्टर स्कूल की शिकारिश पर शिक्षा प्रसार के अध्यक्ष ही करते हैं। सहायता का रुपया डिप्टी इन्स्पेक्टर स्थानीय खजाने से निकाल कर सम्बधित स्कूलों को वितरण करते हैं।

*५६--भ्रो मृहस्मद ग्रसरार ग्रहमद--सन् १९४८--४९ ई० के लिए कितना रुपया उपरोक्त मद में रक्खा गया था, कितना बांटा गया और कितना नहीं ?

श्रो महफूजुर्रहमान-सन् १९४८ में १४, १०० रु० इस कार्य के लिए रक्खा गया था। उसमें से १३,४१७ रु० ३ आ० खर्च हुआ था और ६८२ रु० १३ आना शेष रह गया था।

*५७--श्रो मुहम्द ग्रस्रार ग्रहमद्--(क)क्या यह सही है कि जिन लोगों को रुपया मिलना चाहिए था, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स तथा डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को सुचित किया कि यह रुपया उन्हें नहीं मिला?

(ख) यह कितने रुपये का मामला है और अफ सरान ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है और क्या कर रहे हैं?

श्री ग्रहफूजुर हमान—जी नहीं, केवल एक अध्यापक ने अगस्त १९४८ का वितन न मिलने की शिकायत की थी। वह भी उसे मार्च १९४९ में दे दिया गया था। इसमें देर होने का कारण यह था कि यह रुपया गलतो से एक अध्यापक को दुबारा दे दिया गया था।

यह केवल एक अध्यापक के अगस्त १९४८ के बेतन लगभग ३७ रुपए का प्रश्न था। वह भी उसे सन् १९४९ में अथवा १९४८-१९४९ वष के भीतर ही दे दिया गया था।

श्री मुद्दम्मद श्रसरार ग्रहमद्—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि अडल्ट एजूकेशन की और दूसरी तरह की रकमें जिन-जिन लोगों को मिलनी चाहिये थीं, उनको तारीखवार मिलती रहीं या सिर्फ गबन करने के बाद आहिस्ता—आहिस्ता अदा की गयीं?

श्रो महफूजुरीहमान-गवर्नभेंट को इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री मृहम्मद् ग्रसरार ग्रहमद्—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि एक शख्स को, जो बुबारा नौ महीने के बाद, रुपया दिया गया उसका क्या कारण है ?

माननी र शिक्षा सिच्च य—माननीय सदस्य खुद फाइनेंस कमेटी के मेम्बर हैं। वह जानते हैं कि हम को पिंडलक के रुपये का कितना ख्याल रखना पड़ता है। फिर यह पता लगाना कि किस के पास रुपया चला गया है और उसको बरामद कराना इन सब बातों में देर लगती है। बहरहाल उसको अगस्त की तनख्वाह नहीं मिली। सितम्बर में दरख्वास्त आयी होगी तो नौ महीने में सात आढ़ महीने तो यों ही चले गये।

*५८--श्री मुहम्मद् ग्रसरार श्रहमद्-िस्थिगत किया गया]।

श्री मूहम्मद् ग्रम्गार ग्रह्मद्— पझे, जनाब की तवज्जह सवाल नं० ५८ की तरफ दिलानी है। इसकी नोटिस दिये हुए एक साल हो गया। एक दफा मुल्तवी हो गया था और आज फिर दिया गया है कि मुल्तवी हो जया है ?

माननीय स्पीकर—में सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाता हूं कि यह सवाल २७ अप्रैल, सन् १९४९ ई० को सरकार के पास भेजा गया और अब भी स्थागित किया गया है। तुनासिब होगा कि इसका जवाब जल्दी देन की चेण्टा की जाय।

प्रांत में पेट्रोल का ग्रायात तथा वितरण

*५९--श्चा मुहम्मद ग्रस्रार ग्रह्मद्--क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रान्त में भिन्न-भिन्न पेट्रोल कम्पनियों द्वारा कितना पेट्रोल १ अक्तूबर सन् १९४८ ई० से प्रति मास अब तक आया ?

मान रोय पुलिस सिचव-इस प्रांत में तेल को कम्पनियों द्वारा प्रतिमास प्राप्त किये हुए पेट्रोल की मात्रा का विवरण नत्थी है।

(देखिये नत्यी 'ख' आगे पृष्ठ ७१ पर)

*६०—श्री मुहम्मद् नस्रार श्रहमद्—इस प्रांत के लिए कितना पेट्रोल कोटा केन्द्रीय सरकारद्वारा अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर सन् १९४८ ई०, जनवरी, फरवरी, मार्च, सन् १९४९ ई० और चालु क्वार्टर में एलाट किया गया है ?

माननीय पुन्निस सिंचव — केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्तूबर १९४८ से जून, १९४९ तक तीन तिमाहियों में दिये गये पेट्रोल कूपन के कोटे का विवरण इस प्रकार है—

क्वार्टर	गैलन	
अक्तूबर—दिसम्बर, १९४८	३२,८४,०००	
जनवरीमार्च, १९४९	३६,१०,०००	
अत्रैल जून, १९४९	३८,३०,०००	

*६१— श्री नहम्मद म्मरार अःमद—न्या नरकार को मालूम है कि इस प्रान्त में १ अक्तूबर सन् १९४८ ई० से अब तक बहुत से पेट्रोल कूपन पेट्रोल न मिलने के कारण लैंग्स हो स्यो है ?

माननाय पृत्तिस सिचित्र--इस संबंध में हमें सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं मिली है लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस प्रान्त के पिछली तथा पूर्वी जिलों में पट्रोल की कुछ कमी सहसूस की गई थी। अब स्थित ठीक ह।

श्री मृहम्मद् सम्रार् सहमद्—निया गवर्नमें वतलायेगी कि जब एक करोड़ गैलन से ज्यादा पेट्रोल इस प्रान्त में आया और उससे कम के लिये कूपन जारी हुआ तो किर क्यों पेट्रोल के कूपन्स लैप्स हुये और ब्लैंक मार्केटिंग हुई ?

माननाय पृल्लिस सीं बच--यह तो हर जिले में पेट्रोल के पहुंच सकने की बात है। पेट्रोल तो बाया लेकिन हर जिले के लिये ट्रांसपोर्ट मिलने और वहां पेट्रोल पहुंच जाने की सहल्यित पर ही हर जिले में पेट्रोल मिल जाता है। जहां नहीं पहुंच पाता वहां स्टाक की कुछ कमी हो जाती है और वहां कूपन्स लैप्स हो जाते हैं।

श्री मृहम्मद् श्रस्रार ग्रह्मद्—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि रेलवे बोर्ड ने भी और इस हाउस के दो मेम्बरान ने भी गवर्नमेंट को इत्तिला दी कि पेट्रोल के बहुत वैगन्स रेलवे बोर्ड के पास खड़े हैं और मांग से ज्यादा मौजूद हैं?

माननीय पुलिस सचि ।—जी हां, मौजूद तो रहते है लेकिन वे पहुंच नहीं पाते। श्रो सहम्मद ससरार श्रा मद्—व्या गवर्नमेंट को मालूम है कि पेट्रोल होते हुये भी पेट्रोल इन्स्टालेशन्स डिपो और डीलर्स मिल कर ऑटिफिशल शार्टेज पैदा करते है ?

माननीय पुलिस सचिव मुमिकन है ऐसा हो लेकिन गवर्नमेंट के पास इस मामले में कोई रिपोर्ट इस वक्त तक नहीं है।

*६२--श्री मृहम्मद् श्रस्तार ग्रह प्रद्—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रान्तीय सरकार ते केन्द्रीय सरकार की पेट्रोल के कम आने के सिलसिले में कोई तवज्जह विलायी है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस मचिव--जी हां, प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे बोर्ड से इसके बारे में लिखा पढ़ी की जिसके फलस्वरूप अब स्थिति ठीक है।

*६३—श्रो मुहम्मद् असरार ग्रहमद्—क्या सरकार बतलायेगी कि प्रान्तीय सरकार १ वेन्तुबर, सन् १९४८ ई० से अब तक जिलेवार हर केटेगरी का पेट्रोल क्या क्या मुकरेर किया बा, जिसके कि कृपन जारी हुए ? माननीय पुलिस सिचिय —इस सवाल का जवाब देने मे काफ़ी श्रम करना होगा और इसमें समय भी लगेगा। माननीय सदस्य मानेंगे कि इसकी जरूरत नहीं है।

*६४--श्री महम्मद्र ग्रसरार ग्रहमद--क्या सरकार बतलायेगी कि इस प्रांत में किस-किस पेट्रोल कम्पनी का पेट्रोल आता है और इन कम्पनियों के इस प्रांत में किस-किस रेलवे साइडिंग पर (स्टेशन जिला, रेल का नाम दिया जाय) पेट्रोल डिपो इन्स्टालेशन्स है और उन के अलग-अलग क्या स्टोरेज कैपिसिटीज है ?

माननीय पुलिस सचिव—इस प्रांत में बर्मा शेल आयल कम्पनी, बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, कैल्टेक्स इंडिया लिमिटेड कम्पनी तथा स्टैंडर्ड वैकूम आयल कम्पनी से पेट्रोल आता है।

शेष सूचना हिफाजत के ख्याल से बताना मुनासिब न होगा।

*६५--श्रो मुहम्मद असरार श्रंभद-क्या सरकार बतावेगी कि इन हर एक इन्स्टालेशन से किस-किस जिले को कितना-कितना पेट्रोल दिया जाता है ?

माननीय पुलिम्न सचिव--अपर जो कारण दिया गया है उससे इस सवाल का भी जवाब देना उचित न होगा।

श्री महम्मद ग्रस्रार ग्रह्मद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जो मूबना मागी गई है उसका कोई इल्म गवर्नमेंट को है या नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, इल्म पूरा है।

*६६--७०--श्री बलभद्र सिह--[तबसे माननीय सदस्य की मृत्यु हो गई।]

प्रांत में सब-डिप्टी इन्सपेश्टर ग्राफ स्कूल्स ग्रीर डिप्टी इन्साकरर ग्राफ स्कूल्स को नियुक्ति

*७१-- प्रा बाटद्वाद गुष्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार श्वाया बतायेगो कि सब-डिप्टो इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स तथा डिप्टो इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की नियुक्ति के यथा नियम है ?

म'ननीय शिक्षा अचित्र—तत्सम्बन्धी नियमावली की एक प्रति गाननीय सरस्य के मेज पर रखी हुई हा

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२ पर)

*७२--श्रा बादशाह गुष्त (ग्रनुपिस्थत)--गत वर्ष सरकार ने कितने सब-डिप्टो इन्स्पेक्टरों की नियुक्ति की और अब इस वर्ष कितनों की नियुक्ति करने का विचार है ?

माननीय शिक्षा सिचिव—गत वर्ष (१९४८—४९) में ५० अतिरिक्त सब-डिप्टी इंस्पेक्टर्स भरती किये गये और इस वर्ष (१९४९—५०) में भी ५० इन्स्पेक्टर भरती किये जावेंगे।

*७३--श्री बादशाह गुप्त (श्रमुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रांत में कुल कितने सब-बिप्टी इन्स्पेक्टर है और पहाड़ी जिलों, अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल में प्रथक-प्थक कितने है ?

माननीय शिक्षा मचिव-सब-डिप्टी इन्स्पेक्टरों की कुल वर्तमान संख्या ३१८ है जिनमें से पहाड़ी जिलों के लिये १९ स्थान नियत है—

अलमोडा--७।

गढवाल--८।

नैनीताल--४।

इसमें नये ५० सब—डिप्टो जो इस वर्ष भरती होने को हैं सम्मिलित नहीं है। उनमें से भो एक—एक सब—डिप्टी प्रत्येक पहाडी जिलों में नियुक्त किये जावेंगे।

ज़िला बर्स्ता में लारियों का कुप्रबन्ध

*७४—श्री मृहम्मद् ग्रदोल श्रब्शासी—क्या रोडवेज के स्टेशनों परगाड़ियों के छूटने के समय लिखे हुए होते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला वस्ती के रोडवेज में समय की पाबन्दी नहीं होती है और गाड़ियां वक्त से नहीं छुटतीं?

नाननीय पुलिस्स सचिव—जी हां। जिला बस्ती में सड़कों की हालत खराब होने के कारण खासकर बरसात में रोडवेज की गाड़ियों के छूटने और पहुंचने के सनय में कभी—कभी ठीक पाबन्दी नहीं हो सकी। गाड़ियों को बहुत धीरे—धीरे और सावधानी से चलाना आवश्यक था जिसके कारण उनके पहुंचने में देरी हो जाती थी। बरसात खत्म हो गई है और सड़कों की हालत भी बहुत कुछ सुधर गई है, इपियों अब आशा है कि गाड़ियों के छूटने और पहुंचने के समय में ठीक—ठीक पाबन्दी हो सकेगी।

*७५—श्रो सुरम्भद् स्रदोल सन्वासी—क्या सरकार कृषी कर यह बतायेगी कि १५ अप्रल, ४९ ई० को दुमरियागंज, जिला बस्ती से आखिरी लारी के छूटने का समय क्या था? क्या वह लारी छूटी? अगर नहीं, तो क्यों?

माननीय पुल्लिस सचिव--डुमरियागंज से आखिरी लारी छूटने का समय ५-३० बजे शाम का था । वह साढ़े सात बजे रात को छूटी थी। लारी का नं० ३६१८ था।

*७६—श्री मृहम्मद् घदोल ग्रन्बासी—क्या जिला बस्ती के रोडवेज में कोई शिकायत की किताब है ? उस पर लिखी हुई शिकायतें किसके पास जाती हैं और उन पर क्या कोई कार्रवाई होती है ?

माननीय पुलिस सचिव—जी हां। लिखी हुई शिकायतों का विवरण तथा उन पर जो कार्रवाई की जाती है वह एक नक्शे के रूप में प्रति मास सरकार को भी भेजी जाती है। जेनरल मैनेजर शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करते हैं।

*७७--श्रो मुहम्मद श्रदील ग्रब्बासी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती खिले में गुजिश्ता एक साल के अन्दर किस-किस एम० एल० ए० ने शिकायत की किताब में झिकायतें लिखीं और इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय पुलिस सिचव—पिछले एक साल में जिन एम० एल० ए० ने शिकायत की किताब में जिकायतें लिखीं और उन पर जो कार्रवाई की गई, उसकी सूचना मेज पर रख

(देखिए नत्यी 'घ' आगे पृष्ठ ७४ पर)

श्री महम्मद ग्रदील ग्रब्बासी—क्या गवनंमेंट को यह मालूम हैं कि इन गाड़ियों में जो बहुत गर्द आती है उसमें अभी कोई कमी वाक्य नहीं हुई है ?

माननीय पुलिस सचिव — जी हां। यह सही है कि ये गाड़ियां कुछ ऐसी है कि जिनका फ्लोर ऐसा नहीं बनाया गया है कि जिससे इनमें गर्ब न आए और इसिलये जब ये बाहर से आती हैं तो इनमें गर्ब बहुत भरती हैं। लेकिन हम सेन्द्रल वर्कशाप में इस बात का इन्तजाम कर रहे हैं कि उनके फ्लोर वगैरः ठीक करके और स्टील वगैरः लगा करके उसे इस तरह से बन्द करें कि गर्ब का आना बन्द हो जाय। बहुत सी गाड़ियों में इसका इन्तजाम हो गया है। अब दूसरी गाड़ियों में भी हम इसका इन्तजाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

*७८---श्रो मुहम्मद ग्रदील ग्रब्बामी--क्या ऐसा भी हुआ है कि कई मरतबा गाड़ी के अन्दर यह किताब मौजूद नहीं मिली?

माननीय पुलिससचिय—रजिस्टर रखने की सख्त ताकीव की गई है। फिर भी अगर

प्रश्नोत्तर

*७९--श्रा मुहम्मद् अदील अब्बासी--क्या सरकार को यह मालूम है कि बांसी, डुमिरयागंज, बस्ती तथा गोरखपुर के रोडवेज के स्टेशनों पर जनता को तीसरे दर्जे के टिकट खरीदने में बड़ी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय किया है ?

माननोय पुलिस सिचिव — जी हां। ऐसा होता था। अब एक नया टिकटघर बस्ती में स्त्रियों की सुविधा के लिये बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त बस्ती से विभिन्न दिवाओं को जाने वाली गाड़ियों के टिकट अलग—अलग खिड़कियों से मिलते है। इसी तरह के टिकटघर बांसी और डुमरियागंज में भी बनाये जा रहे है। इससे कठिनाइयां दूर हो जायंगी।

नई शिक्षा संस्थाओं का स्थायीकरण तथा उनका उन्नित

*८०—श्री कुरालानन्द गैरोला—क्या सरकार यह जानती है कि कुछ दिनों से शिक्षा संस्थाओं की स्थापना बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो इन स्कूलों को स्थायी रूप देने तथा उन्नत करने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री महफ्रूजुरेहमान—जी हां। स्थायी रूप देने से माननीय सदस्य का क्या अर्थ है यह स्पष्ट नहीं है। सरकार इस बात का बराबर प्रयत्न करती रहती है कि इन संस्थाओं को जहां तक अधिक आधिक सहायता सम्भव हो दी जाय और शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको उचित परामशं देते रहते हैं। इस बात पर भी दृष्टि रखी जाती है कि उनमें योग्य अध्यापक काम करें और उनका प्रबन्ध ठीक हो। आशा की जाती है कि इस प्रकार वह उन्नत होंगे।

श्री कुरा ठानन्द गैरोला—स्थायी रूप से मेरा मतलब स्थायी रूप से रिकगनीशन का था। माननीय शिक्षा सिचय—रिकगनीशन के लिये म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों की एक कमेटी है उसके सामने उनकी दरस्वास्तें जाती है और यदि वह मुनासिब समझती है तो सरकार को उसके लिये परामर्श देती है।

श्री जगमोहन सिंह नेगो—क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां के गरीबों ने कई उच्च माध्यमिक पाठशालायें बनाई और सरकार द्वारा प्रमाणित हुई, किंदु उनमें से अधि—कांश को कोई आर्थिक सहायता सरकार की ओर से नहीं दी जाती है ?

माननीय शिक्षः सचिव—इस सवाल का जवाब देना कठिन है, क्योंकि जो असल सवाल है वह सूबे भर का है। सरकार को किसी खास संस्था का नाम नहीं बताया गया है। बात यह है कि अधिकांश संस्थाओं को सरकारी सहायता नहीं दो जाती है और नदी जा सकती है कारण यह है कि जो संस्था चलाई जाती है उसके चलने के एक साल बाद सहायता वी जाती है। पहिले साल २०:२५ या ५०६० की प्रिलिमिनरी ग्रान्ट दी जाती है किर अगले साल उसके दरख्वास्त देने पर स्थायी रूप से ग्रान्ट देने के सवाल पर विचार किया जाता है। इसलिये में नहीं कह सकता कि किस जिले की ओर आपका इशारा है, लेकिन आम तौर से उसूल यह है।

श्री जगमोदन मिह नेगी—में यह जानना चाहता हूं कि जहां पर सरकार द्वारा संस्थायें प्रमाणित हो जाती है वहां पर उनको सरकार कुछ न कुछ आधिक सहायता प्रदान किया करती है या नहीं?

माननीय शिक्षा सिचिव—महज प्रमाणित हो जाने से ही किसी संस्था को ग्रान्ट मिल जाय यह जरूरी नहीं है। जब कोई संस्था प्रमाणित हो जाती है तब उसकी दरख्वास्त -आती है दरख्वास्त आने पर सब बातों को देखकर जब यह विभाग मुनासिब समझता है तो उसको प्रिलिमिनरी ग्रान्ट दी जाती है। आम तौर से कुछ न कुछ प्रिलिमिनरी

मान्ट मिल ही जाती है जिलकी रकम २५ या ५० २० होती है किर दैसके र साल बाद दरस्वास्त आने पर रेग्युलर ग्रान्ट दी जाती है।

श्री कुरालानन्द गैरोला-क्या में सरकार से दरियाक्त कर सकता हूं कि श्री रघुनाथ

देव कीर्ति पाठज्ञाला के बारे में सरकार की क्या कैफ़ियत हैं ?

माननीय शिक्षा सचिव-इसके लिये नोटिस की जरूरत है। इस सवाल का जवाब देना गैर-मूमकिन है।

ग्रपर गढ्वाल के हरिजनों को सहायता

*=१-श्रो कुशलानन्द गैरीला-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अपर गढ़वाल प्रदेश के हरिजनों की आधिक दशा सुधारने के लिये वह क्या क़दम उठा रही है ? सरकार उन्हें कल सम्बन्धी शिक्षा देने का तथा इस सम्बन्ध में शिक्षा देने तथा इस प्रदेश में छोटे-छोटे औद्योगिक घन्धों की स्थापना करने का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-भंत्री (श्रो गोविन्द सहाय)-उत्तर गढ़वाल के प्रदेश हरिजनों के लिये विशेषतः कोई बात करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई, परन्तु निस्संदेह इसमें विभिन्न स्थानों पर जो कल-सम्बन्धी शिक्षा देने की तथा छोटे-छोटे अपैद्योगिक घंचों की योजनायें सुचालित हैं, उनके द्वारा हरिजनों के लिये भी खुले हैं।

श्री जगमीहन सिंह नेगी-क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि हरिजनों के

बारे में कुछ जानने की विशेष आवश्यकता उसे क्यों नहीं पड़ी?

श्री गोदिन्द सहाय--जानने का सवाल नहीं है विशेष सुविधा देने का प्रश्न है। दस आघार पर उन्हें कोई विशेष मुविधायें नहीं दो जा सकतीं।

श्रो जगमोहन सिंह नेगा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि श्रोनगर में चमड़े का काम विशेष इप से होता है और वहां के हरिजनों को इसके लिये सरकार द्वारा अभी तक कोई सहायता नहीं प्रदान की जा रही है?

श्री मोविन्द सहाय हो सकता है कि श्रीनगर में ऐसा होता हो और सरकार को

उसकी जानकारी न हो।

बिख्या के ज़िलाधीश के क़ार्यालय के पेड अपरेन्टिसों के विषय में पूछताक *८२—भ्रो खुरावक्त राय (अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार यह बसलाने की कृपा करेगी कि जिलावीओं के कार्यालयों में जो वेतन भोगी कर्मचारिताभिलाषी (पेड अपरेन्टिस) कार्य करते हैं, उनके लिये कोई न्यूनतम योग्यता नियत है?

(ख) यदि हाँ, तो वह न्यूनतम योग्यता क्या है?

(ग) क्या सरकार ने यह अधिकार अपने लिये सुरक्षित रक्ला है कि वह न्यनतम योग्यता के नियम से मुक्त कर सके ?

(घ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सुविधा सरकार किन

कारणों अथवा परिस्थितियों में देती है ?

(ङ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया के जिलाघीश के कार्यालय में कितने वेतनभोगी कर्मचारिताभिलाषी काम कर रहे हैं और उनमें से कितने को सरकार ने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी मुक्ति दी है?

(च) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन सज्जमीं के नाम क्या

हें और उनको वास्तव्यक योग्यतः क्या है?

(छ) क्या इनमें से कोई सज्जन अध्यक्ष डिस्ट्बट बोर्ड, बलिया के निकट सम्बन्धी हैं.?

(ज) क्या यह सच है कि इनका पहिला प्रार्थना-पन्न अस्वीकृत हो गया था, पुरुत्तु दुबारा प्रार्थनापत्र देने पर इन्हें नियम से मुक्ति प्राप्त हो गयी थी ? 📈 🚾 🗷 वया सरकार इसका कारण बतलाने की कुपा करेगी?

माननीय माल सचिव (श्री हुजूम सिंह)-- (क) जो हां।

(स) पैरा ३३२ एम० जी० ओ० के अनुसार हाई स्कूल या उसके समान की भरीक्षा आवश्यक है।

(ग) जी हां।

(घ) आधुनिक विशेष परिस्थितियां निम्नलिखित है—

(१) यदि प्रार्थी ने कई वर्ष तक संतोषजनक किसी पद पर काम किया हो और अंग्रेजी की योग्यता हाई स्कूल तक हो तो पैरा ३३२ एम० जी० ओ० के अनुसार,

(२) यदि प्रार्थी बन्दोबस्त मे ५ वर्ष तक काम कर चुका हो और ३५ वर्ष

से कम अवस्था हो,

(३) प्रार्थी यदि योग्य शरणार्थी हो,

- (४) प्रार्थी ने यदि राजनीतिक आन्दोलन में भाग लिया हो और उसके कारण उसको हानि पहुंची हो।
- (ङ) बलिया के जिलाधीश के कार्यालय में ९ वेतनभोगी कर्मचारिताभिलाधी काम कर रहे हैं इनमें १ को न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी मुक्ति प्रदान की गई है।
- (च) जिस सज्जन को न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी मुक्ति प्रदान की गई है उसका नाम राम प्रवीण पांडेय है और उन्होंने अध्ठम कक्षा की परीक्षा पास की है।
- (छ) जी हां। श्री राम प्रवीण पांडेय, श्री तारकेश्वर पांडेय, अध्यक्ष, जिला बोर्ड बलिया के भतीजे हैं।

(ज) जी हां।

(झ) राजनैतिक पीड़ित होने के कारण।

सन् १६४८--४९ में जिला इलाहाबाद में राजनैतिक पोड़ितों को पन्तिक कैरियस वे पश्मिट

*८३—-श्री खुदावक्तराय (अनुपस्थित)—-(क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में आधिक वर्ष १९४८-४९ ई० में कितने पब्लिक केरि-यर्स के परमिट राजनैतिक पीड़ितों को दिये गए?

- (ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि राजनैतिक पीड़ितों की क्या परिभाषा है और उसके लिये किन-किन प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है ?
- (ग) क्या सरकार यह बतलाने की क्रुपा करेगी कि जिला इलाहाबाद में जिनको आर्थिक वर्ष १९४८-४९ ई० में परिमट मिले उनके नाम, पते व राजनैतिक पीड़ित होने की योग्यता क्या है ?
- (घ) क्या यह सच है कि इनको जो परिमट दिये गए हैं उनके साथ कुछ शतें भी लगायी गयी हैं ?

(क्र) यदि हां, तो यह शर्ते क्या है ?

- (च) क्या यह इातें सब परिमट पाने वालों पर लागू है या इनमे से किसी के साथ रियायत भी कर दी गयी हैं?
- (छ) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय इलाहाबाद— कोहडार घाट पर कितनी गाड़ियों को चलने का परिमट मिला हुआ है और उन गाड़ियों के नम्बर तथा मालिकों के नाम क्या है तथा क्या वह गैस प्लान्ट पर चलती है या पेट्रोल से ?
- (ज) क्या यह सच हैं कि पहिले इस सड़क पर एक और गाड़ी को चलने का परमिट मिला हुआ था, परन्तु किसी विशेष कारण से यह परमिट रद्द कर दिया गया नै १

माननोय पुल्लिस सचित्र--(क)आधिक वर्ष, १९४८-४९ ई० मे आर० टो० ओ० इलाहादाद ने तीन पब्लिक कैरियर के परमिट राजनैतिक पौड़ित व्यक्तियों को दिये

- (ख) सन् १९४८ ई० की पुरानी घोजना के अन्तर्गत उन्हीं व्यक्तियों को रोट प्रमिट पाने के लिये राजनैतिक पीड़ित माना जाता था--
 - (१) जो सन् १९४२ ई० के आन्दोलन में ६ नास या इसरो अधिक समय के लिये जेल जा चुके हों।
 - (२) या जिनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई हो।
 - (३) या जिनका व्यापार नब्ट कर दिया गया था।

सन् १९४९ ई० की नवीन योजना में वेसब लोग रोड परिमट पाने के ठिये राज-नैतिक पीड़ित माने गए है जो--

- (१) सन् १९३० ई० के बाद कम से कम ६ माह के लिये जेल जा चुके हों।
- (२) या जिनके पालन-पोषण करने वाले या तो जेल में मर गए हो अथवा गोली में मारे गए हों।

पुरानी योजना में कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस, सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल, टिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी वा एम० एल० ए० के प्रमाण-पत्र पर्याप्त समझे जाते थे। आवश्यकतानुसार अधिकारियों द्वारा और भी जांच कर ली जाती थी।

नई योजना में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का सिंटिपि केट पर्यान्त माना गया है।

(ग) आर्थिक वर्ष, १९४८-४९ ई० में इलाहाबाद जिले में जिन व्यक्तियों को स्टेंज कैरेज या पहिलक कैरियर के परिभट दिये गए उनके नाम, पते तथा राजनैतिक पीड़ित होने की योग्यता कृपया नत्थी किये गए स्टेटमेंट में देखी जाय।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ७६ पर)

(घ) जी हां।

(इ) यह शत १९४८ की स्कीम में इस प्रकार थीं--

- (१) परिमट कच्ची सड़कों पर जिनकी लम्बाई १०० मील से अधिक नहीं है दिया जाएगा। सुविधा के लिये अधिक से अधिक २० प्रतिशत पनकी गएक भी दी जा सकती है।
- (२) यदि इनकी स्वीकृत सड़कों सरकारी रोडवेज ने छे ली तो यह पर्रामट रद्द कर दिये जायेंगे तथा इन लोगों को किसी प्रकार का मुआविजा नटो दिया जायगा।
- (३) पहले इनकी गाड़ियों को चलाने के लिये गैरा प्लांट लगवाने की शर्त थीं परन्तु अब वह हटा ली गई है और इनको पेट्रोल दिया जा रहा है।
- (च) यह झर्ते सब के लिये लागू है और किसी के साथ रियायत नहीं की गर्द है। (छ) इलाहाबाद—कोहडार बाट पर २ गाड़ियों के परिमट दिये गए थे। गाज़ियों

के नम्बर तथा मालिकों के नाम नीचे दिये हुए हैं--

- (१) श्री कौशलेश सिंह, बरांव की कोठी, इलाहाबाद, यू० पी० सी० २९४७। (२) श्रीमती गिरीश कुमारी, बरांव की कोठी, इलाहाबाद, यू० पी० सी० २९६६। दोनों गाड़ियां पेट्रोल पर चलती हैं।
- (ज) जैसा कि उत्पर कहा जा चुका है पहले इस सड़क पर गाड़ी नं० यू० पी० सी० २९६६ को भी चलने का परिमट मिला था। चूंकि इस सड़क पर चलने वाले मुसाफिरों के लिये केवल एक गाड़ी ही पर्याप्त थी, इसलिये गाड़ी नं० यू० पी० सी० २९६६ को दूसरी लाइन दे दी गई है।

जिला बाजमगढ़ में महाराजगंज स्कूल के कात्र श्री वीरवल सिंह पर जुर्माना

*८४--श्री गजाधर प्रसाद--महाराजगंग हायर सेकेंडरी स्कूल, जिला आजमगढ़ में न्यू १९४८ ई० के नुलाई पाह में श्री भीरगल सिंह छात्र कक्षा ९ से जो १५ ६० जुर्माना इसिलए बसूल किया गया था कि उसने गत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में सोशलिस्ट पाटी का साथ दिया था क्या सरकार ने जस जुर्माने को बापस कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महणूजुर्वनान—विद्यार्थी वीरबल सिंह पर जुर्माना किया गया, लेकिन वसूल नहीं किया गया। अतः उसके वापस कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रो गानागाम गास्ती--नया सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुर्माना वयों किया गया?

माननी प्रशिक्षा सचित्र--इसलिये कि स्कूल के अधिकारियों ने यह मसन्ना कि लड़के ने गलत काम किया।

श्रो राजाराम तास्त्री—-जुर्माना वसूल हुआ या नहीं इसके बारे मे आपको किस तरीके पर मालूम हुआ ?

माप्तनाम जिल्ला निचन-जिलातरोके से गवर्नमेट को तीचे की और तब बातों का पता लगा करता है।

प्रान्तोय सिविल सर्विस (एकजोक्यूटिव) प्रतियागिता में परिगणित जातियों के लिये सुविधागें

*८५--भ्रो गंगाचर--क्या सरकार जानती है कि इस वर्ष प्रान्तीय सिविल सीयस (एक्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता में पूर्णार पब्लिक सीवस कमीवन ने ४८ स्थानों में से ५ स्थान परिगणित जातियों के लिए सुरक्षित घोषित किये थे?

श्री गो।बन्द सहाय--जी हां।

*८६--श्री गंगाधा--क्या सरकार यह जानती है कि इस प्रतियोगिता में परि-गणित जाति के २५ उम्मीदवारों में से ।सर्फ तीन ही भेंट (इन्टरब्यू) के लिये बुलाये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोिन्द सहाय—जी हो, परिगणित जाति के २८ उम्मीदवारों में से (२५ नहीं) जो इम्तिहान में बैठे सिर्फ़ ३ उम्मीदवारों का भेट (इन्टरब्यु) के लिये बुजाया गया था, क्योंकि कमीशन की राय में केवल इन्हीं तीनों के लिखित पर्चा में इतने नम्बर आये थे कि उन्हें भेंट के लिये बुलाया जा सकता था।

*८७—श्रो गंगा धर — व्या यह सत्य है कि इस वर्ष प्रान्तोय निविल सिवस (एक्जी ग्यूटिव के ४८ स्थानों में सिर्फ एक स्थान परिगणित जाति के उम्मीदवार को मिला है?

श्रा गोविन्द् महा ५--जी नहीं। इस्त प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव-व्रान्च) से ग्यिक्त के लिये २ उम्मीदवार डाक्टरी परीक्षा में पास होने की धर्त पर मंजूर किये गये थे।

*८८--श्री गंगाधर--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि परिगणित जाति के लिये इस प्रतियोगिता में सवर्ण हिन्दुओं के मुकाबिले में कोई विशेष सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्रो गोविन्द् सहाय--जी हां, परिगणित जाति के उम्मीदवारों को भीचे लिखी रियायतें दी जाती है।

२— १० प्रतिशत जगहें परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लि े सुरक्षित रक्खी जाती है। २-- उनके जिये उमर की मियाद ३ साल बढ़ा दी गई है।

३-- उनकी योग्यता की जांच का म्यार कुछ साल रक्या गया है।

८९—— अन् गगाचर— क्या सरकार कृषा करके बतलायेगी कि इस प्रतियोगिता में पिनागित जानि के उम्मीत्वारों के लिए इस वर्ष पहले से स्टैन्डर्ड (स्तर) बढ़ा दिया गया है ? यदि हा, तो कार्रे ?

थ्रा ग विन्द् सहार -- जी नहीं। इस प्रान का दूसरा भाग नहीं एठता।

घरेलू उद्याग-अन्धें के। सर नारा सहाजना

'१०-- प्रा नामचन्द्र पालाव ल--घेलू उथोग-धंत्रों को सहापना देने के सरकाय में मरकार की क्या नीति हैं ?

स'ननीय पुनित सचिव-कृडीर उद्योग-धंत्रों के सम्भन्ध पे तरकार की नीरि उनको महाप्र दरे ही है। परकार ने मवालक उद्योग तथा वावमाय का पुनः नाजकरण सवालक कुटीर उद्योग दिया है। जिसमें कि सवालक कुटीर उद्योग की और अधित ध्यान दे नके। मरकार ने कुटीर उबीगों के लिखाने का समुचित प्रबन्ध कि । है। इस गोडना के अन्तर्गत रु राजकीय शिक्षालय हे और ऐसे ही ५१ विकालयों की राज्य आर्थि : महायता देना है। टच्यून क्लात को स्कीय भी गांव-गांव से कुटीर टखोग-र्फे रिंग पे गारका कार्य करनी है। इग प्रकार के ११८ क्लाप है। बरेलू उलीगो पंचों को आर्थिक महायना देने के लिये सरकार ने एक कमेटी जनाई है जिनने मन् १९४७-४८ में २६,६५० हपये अनुदान और ८७,५०० हपये ऋण तथा १९४,-४९ चे ६९,३७० रुपये अनुदान और २,२४,१०० रुपये ऋण स्वरूप दिया। घरेलु एक्षेग्र-प्रधा द्वारा निर्मित वस्तुओं को विकी के लिये सरकार ने एक यु० यो० हैण्डी काष्ट्रस नात्क लोला है जहां राथ को बनो हुई वस्तुओं का विकय होता है। इसके अतिरिक्त हाथके बने हुये कपड़ो को उनित, खादो. ऊन, रेशन के कीड़े पालने की व्यवस्था और नेलघनी, मिट्टी के वर्तन बनाना कांच, मोनी, हाय का बना हुआ काग़ज, रेशों का व्यवसाय, इत्र पोजना. जिकन योजना, चरता निकाय योजना, ताड़ गुड़ और गुड़ विकास योजनाय तालू की गई है। विशेष जानकारी के लिये उद्योग विभाग से मना-संत्रप पर, प्रकाशित† पत्रिकाओं हा अब-लोकन करिये।

फ़िरो आवाद के घरेलू उद्योग-धन्धों को सरकारा महायता

*९१--श्री गमचन्द्र पानीव (ल--(क) क्या सरकार किरोजः वाद की काटेज इण्डस्ट्री को कोई सहायता देती हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या ?

(ग) बिद नहीं, तो क्यों ?

माननीय पुलिम सचिय-(क) हां।

(ल) सरकार किरोजाबाद की कार्टज इन्डस्ट्री तथा उन बड़े कारखानों को भी, जोकि वड़ां पर चन्न रहे हैं, आवश्यक रा मैटीरियल सामान्य परिस्थित की सीमा के अन्तर्गत उच कभी भी बढ़रत होती है, संस्लाई करने में सहायता देती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से लिक्विड गोल्ड (हिल्ल) के आयात पर नियं रा

*९२—श्री रामचन्द्र पालीवाः — (क) क्या सर हार को मालून है कि फ़िरोज का के इन घरें ने उद्योग—अंबे में विदेशों में बना हुआ लिक्ष्विड गोल्ड (हिल्ल) एक प्रधान रा मैटोरियल है ?

(ख) येदि हां, तो क्रिरोजाबाद के इस उद्योग में इस हिल्ल की समय-समय ार जो कभी आया करती हैं उसके बारे में क्या सरकार को जानकारो हैं ?

[ं] यहां पर छापी नहीं गयीं।

(ग) क्या यह सब है कि पूर्णीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह लिखा है कि वह हिल्ल के आव पर नियंत्रण नहीं चाहती? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस सचिय— (क) विदेशों में बना हुआ हिल्ल लिक्विड गोल्ड जूड़ी बनाने के घरेलू उद्योग धंबे का रामैशिरियल नहीं है बिल्क थह तो एक क्रोमती रसायन है जिसे कि सीदागर कारलानों से खरीदी हुई चूड़ियों को अपने यहां सजाने के काम में लाते हैं। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाय तो इसका प्रयोग एक लक्जरी है क्योंकि कई पाँड सोना इस प्रकार प्रतिदिन वितरित होता है। जिससे देश को सदा के लिये नुकसान होता है।

(ख) हिल्ल का आयात हमारे देश में पर्याप्त संख्या में होते के कारण, अल्पकालिक कमी स्पैकुलेशन के कारण हो जाना सम्भव हैं। कारीगर पेन्टर तो औदागरों से वेतन भात्र ही पाते हैं और चूंकि हिल्ल सदेव बाजार में मिलती है कम या अधिक रेट पर हिल्ल के भाव में परिवर्तन होने का असर कारीगरों पर नहीं पड़ता बल्कि केवल सौदागरों पर ही पड़ता है।

हिल्ल लिनियड गोल्ड सोने से जनती है जिसे कि बैंक आफ इंगलैंग्ड ब्रिटिश कंट्रोल रेट पर देतीं हैं जोकि हमारे देश की बाजारी भाव से तीन गुना सस्ता है। फिरोजाबाद में हिल्ल के उपभोक्ताओं ने देखा कि इस रसायन से सोना निकाल कर बेचना कहीं अधिक लाभकारी हैं बजाय इसके कि उससे चूड़ियों को सजा कर बेचा जाय। एक समय था जबकि यह साइड बिजनेस लिक्विड गोल्ड को कमी का मुख्य कारण था और यह तब ही बन्द हुआ। जब कि लिक्विड गोल्ड को क्रोमत बढ़ गई।

(ग) यह सत्य है कि यू०पी० सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सलाह दी थी कि बैलिक्वड गोल्ड के भाव पर नियंत्रण न रखा जाय क्योंकि इस रसायन के आयात के लिये ओपेन जनरल लाइ सेंस था तथा कोई भी इसे मंगा सकता था। ऐसी दशा में सरकार अनावश्यक पदार्थी पर एक अनिश्चित काल तक नियंत्रण कायम रखना आवश्यक नहीं समझती ह।

*९३--श्री रामचन्द्र पाली वाल--(क) क्या सरकार को मालूब है कि सन् १९४८ ई० ो पहिली छमाही में जब कि हिल्ल को इंगलैंग्ड से आयात करने पर भारत सरकार क आयात नियंत्रण कानून लागू रहा इसके भाव बाजार में स्थिर रहे ?

- (ख) क्या सरकार को नालूम है कि जब से भारत सरकार द्वारा यह आयात नियंत्रण क़ानून हिल्ल के आयात पर से उठा लिया गया तभी से इसके दाम एकदम ऊंचे हो गये?
- (ग) क्या यह सब है कि हिस्त के आयात पर दुवारा नियंत्रण लागू करने के लिये फिरोजाबाद की संस्थाओं ने प्रार्थना की थी ९
 - (घ) यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्य किया गया ?

माननीय पुलिस सचित्र-(क)हिल्ल का भाव सन् १९४८ ई० की पहली छनाही में स्थिर था जबकि उसका वितरण ग्लास टेक्नालाजिस्ट की देखरेख में होता था।

- (ख) यह सत्य हैं है कि नियंत्रण उठ जाने पर भाव ऊंचे हो गये। नियंत्रण उठ जाने पर प्रायः चीजों के दाम बढ़ जाते हैं'।
- (ग) यह सत्य है कि हिल्ल के आयात पर दुवारा नियंत्रण कायम करने के लिये हिल्ल के उपभोक्ताओं की संस्था ने सरकार से प्रार्थना की थी।
 - (घ) उन्हें सरकार ने उचित सलाह तथा चेतावनी दी थी।

*९४ — श्रीरामचम्द्र पालीवाल-(क)क्या लरकार को सालून है कि फिरोजाबाद को दसवरेलू उद्योग की पतिनिधि संस्था (जो रिजस्टर्ड भी है) बैंगिल्स एसोसियेशन ने हिल्ल

को वनमान किंदिनाइयों से प्रान्त के इस उद्योग को मुरक्षित रखने के लिये सम्बन्धित विभागों नथा पदायिकारिों से जिनमें ग्लास टेक्नोलाजिस्ट भी शामिल हैं, वार बार अनुरोध किया कि हिल्ल के भाव व बटवारे में कोई मुनिश्चित सरकारी नीति के बारे बरती जावे ?

(ख) यदि हां, तो क्या तरकार यह बनायेगी कि उन सम्बन्धित विभागों ने तथा

ग्लास देश्नोलाजिस्ट ने उन्नके लिये क्या-क्या कार्यवाही की?

(ग) यदि कर्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

H

उद्योग की प्रतिनिधि सस्या नहा हु। यह ता कवल पूछा च कार्या है इस मंस्या ने ग्लास टेक्नोलाजिस्ट से दुबारा नियंत्रण क्र यम करने के लिये अनुरोध किया था।

(ख) ग्लास टैक्नोलः जिस्ट ने उन्हें सलाह दी थी कि वे कम से कम एक महीने के लिये ही चोर बाजारी करने वालों का वहिष्कार कर दें और उनसे हिल्ल न खरी दें। ऐसा करने मात्र से ही लिक्विड गोल्ड के भाव में काफी कमी आ जाती।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

*९५-श्री रामचन्द्र पालीवा उ-क्या सरकार को मालून है कि इंगलैंड से हिल्ल

का आना दिन पर दिन कम होता जा रहा है?

माननोय पुलिस सचिव — इंगलैण्ड से लिक्विड गोल्ड का आयात दिन पर दिन कम नहीं हो रहा है, बल्कि वह पहले से कहीं अधिक तथा पर्याप्त है और नियमित रूप से होता है।

१ ग्र≄तुवर सन् १६४८ ई० से २८ मई सन १९४९ ई० तक भूख−हड़ताल करने वाले कैहियों के बारे में ब्यौरा

*६६--श्री मुहम्मद् असरार अहमद--(क) क्या सरकार यह बतायेगी कि एक अक्तूबर सन् १९४८ ई० से २८ मई सन् १९४९ ई० तक प्रांत में जेलवार जिलेवार किस-किस राजनीतिक या अराजितक कैंदियों ने भूख हड़ताल की ?

(ल) भूत हड़ताल करने का क्या कारण या तथा उनकी क्या-क्या मांगें थीं और

सरकार ने, उनकी कौन-कौन सी मांगें पूरी कीं?

(ग) इन हड़ताल करने वालों ने किस-किस जेल में अपनी मांगें पूरी करने के लिये या जेल का क्रायदा तोड़ने के लिए बल प्रयोग किया और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

(घ) सरकार ने किस-किस जेल में ऐसे क़ैदियों पर बल प्रयोग किया?

श्री गोदिन्द सहाय—(क) भूल-हड़ताल करने वाले कैंदियों के नाम देना तो संभव नहीं है। एक तालिका कि जिसमें भिन्न-भिन्न जेलों में भूल-हड़तालियों की संख्या दी हुई है मेज पर रखी गई है।

(ब) एक इसरी तालिका †ख मेज पर रखी है जिसमें भूख हड़ताल के कारण तथा भूख – हड़ेतालियों की मांगें और जो-जो मांगें सरकार द्वारा पूरी की गई हैं दी गई हैं।

(ग) किसी तूल-हड़ताली ने बल प्रयोग नहीं किया।

(घ) सरकार ने भी किसी भूख-हड़ताली पर बल प्रयोग नहीं किया।
गहला वसूला योजना के सिर्लासिले में माननीय सिंचवीं तथा सभा
मंत्रियों के दौरे

*९७—श्रो मुहम्मद् सस्रार ग्रहमद्—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष त्रोक्योरमेंट के सिलसिले में माननीय सचिव व पालियामेंटरी सेन्नेटरियों ने कुल कितने मील का सफर किया—कितना रेल से, कितना हवाई जहाज से, कितना मोटर से और

[†]तालिकायें छापी नहीं गई हैं।

प्रशोत्तर २७

कितना अन्य साधनो द्वारा—कितनी स्पीधे दी ओर तहा—कहा १ हर एउ साननी सिवव व गालि गामेटरी मेकेटरी के सम्बन्ध में सूचना सूची के रूप में दी जाय ?

श्री गोदिन्ट स्वाय—िसर्फ गल्ला वसूली के लिये कोई दौरे नही किये गये, लेकिन कुछ सभाओं से जो भाषण दिये गये उनमे गल्ला वसूली के बारे रे भी कहा गया। ऐसी हालनते इस प्रदन का उत्तरदोना कठिन है। अगर प्राननीय सदस्य उन जगहो की कोई सूची चाहते हैं जिनका दौरा मामनीय सचिवो और सभग्सचिवो ने विशेष जालि विभिन्न के किया हो उसे वे स्पष्ट करे।

श्रा मुहःगढ पसर,र ग्रहमद्—क्या गर्वामेंट बतलायेगी कि आने-जाने के स्लिसिले में मिनिस्टर्स और पालियामेटरी सेन्नेटरीज के सफर खर्च के सिलसिले में कोई रिकार्ड रखा जाता है या नहीं?

श्री गोविन्द सहाय--जी हा?

श्रा मुहम्मद श्रमरार ग्रहमद--क्या गवर्नभेट बतलात्रेगी कि रेकार्ड्स मौजूद होने की हालत में यह सूचना किस गरज में नहीं दी जा रही है जो कि मागी गयी है !

श्री गाविन्द सनाय-- १व के आने - गाने के खर्व का रेकार्ड तो रखा जाता है, लेकिन इसका रेकार्ड नही रखा जाता कि कीन कहा - कहा गथा और कब कब गया। (प्रश्नों का समय समाप्त हो जाने पर शेष प्रश्न अगले िन के कार्यक मे रल दिये गये।)

श्री ग्रजीज ग्रहमद खा तथा श्रा बलभद्रा सह ा मृत्यु एर शाक-सवाद

माननीय प्रधान मचिव (भ्री गाविन्द वर्ण्स पन्त)—म ननीण स्पीकर साहब, हम लोगों के आखिरों सेनन के जाने के बाद हमारे कुछ साधिया का विछोह हो गया। मौलबी अजीज अहमद खा, इस हाउस के ओर असेम् ों के एक काबिल पुरानी मेम्बर थे और वह खामा हिस्सा पिल्ल कामों में लिया करते थे। = बेखौक ओर आजादाना तरीके में अपना काम करते थे ओर जिस मसले की ह लेते थे उसमें काफी दिलचस्पी उनकी रहती थी। वह काफी अपें तक बीमार रहे और आखि में उनकी जिन्दगों को बचाने में और लोग कामयाब नहीं हो पाये। उनकी इस वकात से हमारे हाउस को एक नुकसान पहुंचा और एक कमी हुई। में यह तजबीज करता हं कि स्पीकर साहब मेहरबानी करके उनके खानदान वालों तक हाउस की तरक पे इज्जहारे अफसोस भेज दे।

इसी दरिययान में ठाकुर बलभद्र सिंह जी, जो हमारे इस हाउस के एक बहुत अच्छें काम करने वाले थे, हमारी पार्टी में ओर कांग्रेस में जिनकी एक खास जगह थी, जिनकी अपने जिले में जनता की खिदमत करने की वजह से काफी लोगों में शोहरत थीं और जनता की श्रद्धा भी उनके लिये थीं और जिन्होंने अपनी सारी उम्म जनसेवा में ही बिताई, उनका भी इस बीच में स्वर्गवास हो गया।

वह भी कम उमर के थे और वह मुल्क से आगे खिदमत बहुत अच्छी तरह से करते और उनके जिरये हम सब की और मुल्क को बहुत फायदा पहुंचता। मुझे अफसोस है कि यकायक उनकी मौत हो गई और वह अब हमारे बीच में नहीं है। उनके बारे में ज्यादा कहने के लिये मुक्किल हैं, क्योंकि वह हमारी पार्टी के मेम्बर भी थे और बहुत दिनों से वह देश के सिर्फ पोलीटिकल हो नहीं, बिल्क सोशल, कंस्ट्रक्टिव और दूसरे क्षेत्रों में सेवा करने थे। में आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उनके लड़के और उनके खानदान वालों को आप हमारी तरफ से महानुभृति भेजने की कृपा करें।

श्री उहीर न हमनेन लारी—— मुहतरम रपीकर साहब आनरेबिल वजीर आजम ने जो तजवीजे ताजियत पेश की है, में उसकी ताईद करता हूं। मौलवी अजीज अहमद साहब हमारे साथी और एक बहुत बड़े पुराने कारकुन थे और विलाफत की तहरीर के जमाने में उन्होंने पब्लिक मामलों में काफी दिलचस्पी ली और उसके बाद वह मुस्लिम ं श्रो जड़ीवल हसरेर ज'री]

लींग पारटी के एक उहुत ही नुसाया सेम्बर थे। हम लींग हसेजा उनकी राथ पर काको सरोमा किया एरते थे और कीन सानिये कि वह धड़ी संजीवगी और वसीउल नजरी से तार प्रमामलों पर अपने प्यालात का इजहार किया करते थे। अफसोस है कि एक तूल तबील बीकारी के बाद उनकी उफात हो गयी। इम ऐगान को यह भी मालूम होगा कि वह दरदूरसारा असेम्दली ले भी यू० मी० की तरफ से सेम्बर खुने गये थे और उस है लियत में उपहोंते विधान के धनाने में काकी दिलचस्मी ली थी।

हसारे दूररे माथी ठाकुर दलभड़ मिह की भी इशी जमाने में बफात हुई। अड़ उनके नाथ बदिक स्तती ने काम करने का मौका तो नहीं मिला भगर इस ऐवान में हमेशा जो मानले आते में उनमें बह काकी विज्वस्पी लिया करते थे और जहां तक भुझे इत्म है वह अपने जिले में भी नमात दिवक कामों में काफी मेहनन से हिस्सा लिया करते थे। इन दोनों साहबान की वफात पर मुझे और मेरी पार्टी को बहुत सदया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जनाब स्पीकर सान्व हुगरे इन जजबाते हमदर्बी को उनके पत्मान्दगान तक पहुंचा देगे। मैं इन अस्काब के साथ इस तहरीक की तार्दि करता हूं।

श्री नगन्नाथ पहन सिंह—माननीय स्पोकर महोदय, किसी भी स्पासद दे देहाबासन पर प्रत्येक सनुत्य को दुख होना स्वाभाविक है, परन्तु जब हम यहां अपने किसी मायों के दियांग के दुख का अयान करते हैं उसमें कुछ अपने भावों से अधिक देश के भावों का भी विचार आता है। श्री पलभद्र तिह और अजीज अहमद साहद दोनों की ऐसी उमर नहीं यो कि वह इस संसार से चले जाते। एक तो भवन के सभासद जिन्होंने इन दिनों तक मेहनत और दिलजोई को यहां के कान को अंजाम दिया हो वह इस तरह से यकायक उठ जायं इसके केवल उनके घर वालों और मित्रों को ही नहीं दुख होता चिन्क देश की बड़ी क्षित होती है और देश की क्षति ऐसी होती है कि जो पूरी नहीं हो सकती है। मुझको भी हार्दिक दुल हुआ है और इन विचारों को में अपकी ओर से और उनकी ओर से जिनकी ओर ने में यहा हूं प्रकट करता हूं। में साननीय स्पीकर साहब से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारी महानुभूति उनके सम्बन्धियों और कुटुम्बियों तक पहुंचा दें।

माननीय स्पीकर—माननीय सदस्यगण, मौलवी अजीज अहमद और श्री बलभद्र भिह से हम में से ज्यादा इन दोनों से अच्छी तरह से वाकिफ रहे हैं। यौलवी अजीज अहमद साहब के बोलने के वक्त उनकी जवान की फसाहत तो आज भी मुझको याद आती है। ऐसी अच्छी तरह से और इस खुश बयानी से वह अपनी बातों को पेश करते थे कि उनकी सुनने को जी चाहता था। हम सब को कुदरतन बहुत अफसोस है कि वह हमारे बीच में नहीं हैं और बीमारी के बाद चले गये।

श्री बलभइ सिंह तो हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले और काम करने वाले थे। उनके इस दुनिया से चले जाने के करीब एक महीना पहले में उनके और उनके साथियों के निमंत्रण पर बुलन्दशहर गया था। मेरी उनसे कुछ बातें जिले के काम के बारे में हुई थीं, उस वक्त भी वह लखनऊ से बोमारी के इलाज के बाद गये थे और हमें उम्मीद थी कि वह बिल्कुल अच्छे हो जायेंगे, लेकिन कुछ ही रोज बाद वह चले गये। "मेरे मन कछ और है कर्ता के कछ और।" हम लोगों ने समझा या कि वह अपने दूसरे भाइयों के साथ बुलन्दशहर के जिले में हमारे देश के दाम की देखमाल अच्छी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि वह हम लोगों के भरोसे के आदमी थे और हमने हमेशा उनको वड़ी ईमानदारी से काम करते हुये पाया। कुदरती तौर पर हमें बड़ा घलका लगा जब हमने उनकी मृत्यु का हाल मुना। में अपने इन दोनों साथियों के कुटु निचयों को इस भवन की हमदर्दी के बारे में लिखवाऊंगा। आप सब से अब मेरी दरस्वास्तं है कि कुछ देर खड़े होकर अपने रंज का इचहार करें।

(थोड़ी देर के लियें सब सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

श्री गोपी नाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक-संवाद

मानतीय प्रधान सचिव-- श्रीमान जी, हमारे आखिर सेशन के बाद गीपी नाथ श्रीवास्तव जी का स्वर्गवास हो गया। वह पहले हमारी असेम्बली के सेम्बर थे हमारे पालिया-मेंटरी लेकेटी भी थे। उस जमाने में जबकि वह असेम्बली के भेम्बर थे तो उन्होंने बहुत हो खबी के साथ अपने काम को और असेम्बली की जिम्मेदारियों को पूरा किया। उन्होंने जेल के जहक में में बास तौर पर दिलचस्पी ली और जितनी भी बातें ऐसी हो सकती थीं जिनसे सुवार और बेहतरी हो, उनको अमल भें लाने की कोशिश की। इसके अलावा सबही मसले पर जो बहुत ही अहमियत रखते थे या बहुत उलझे हुये होते थे, उनकी सलाह और उनका सश्विरा बहुत कारआमद और गुफीद होता था। वह अपनी काबिलियत से अपनी इल्मियत से, अपने उम्दा तर्जें अमल से, अच्छे ढंग से, हर मसले को देखते थे वह अपनी खास जगह रखते थे असेम्बली के अलावा बाहर भी उन्होंने बहुत से कास किये उनका ताल्लुक बहुत से पिल्लिक इन्स्टीच्युवन्स से रहा। गरीब और पिछडे हुये लोग जो इख की हालत में होते थे उनको जो भरद देने के काम होते थे उनमें वह हर यक्त और हर तौर पर मदद देने के लिये तैयार रहते थे। वह बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले हमारे बीच में एक पब्लिक मैन थे। वह हर मसले को गहरे ढंग से देखते थे और उनका ऐप्रोच कांस्ट्रियंव हुआ करता था। हर मलले को सुलझाने का ढंग है उससे वह काम किया करते थे। वह पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर रहे। वहां भी उन्होंने काफी मेहनत की। अपने जमाने में उन्होंने वहां बहुत सी तब्दीलियां करने का अपना इरादा रक्खा। वह उसमें बहुत हद तक कामधाब हुए। वह एक अच्छे जनरिलस्ट थे अखवार लिखा करते थे ; वह प्रेस कन्सल्टेटिव कमेटी के प्रेशिडट भी रहे। वह अखबार नवीसों के बीच में एक खास ऊंची जगह रखते थे। हम लोगों से उनका ताल्लुक़ और सरोकार बहुत अर्से तक रहा हमारे उनके जाती ताल्लुकात भी थे। उनका हमारे बीच से उठ जाना तकलीफदेह चीज है। मुझे अफलोस है कि जह बहुत कम उम्ध में चले गये। अगर वह जिन्दा रहते तो मुझे पूरा यक्तीन है कि हमारे सुबे को और हमको उनके जरिये काफी फायदा होता। यह मसँल है कि जो बहुत अच्छे होते हैं बहुत दिन जिन्दा नहीं रहते। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप इस हाउस की तरफ से उनके खानदान को हमारी हमदर्दी का इजहार भेज दीजिये।

श्री जहीरल हमनेन लारी—जनाब स्पीकर साहब में गोपी नाथ जो ले उस वक्त वाकिफ हुआ जबिक वे पिछली असेम्बलों के मेम्बर थे। वह गवर्नमेंट के पालियामेंटरी लेकेट्री भी थे। मेरा ख्याल है कि इस सूबे के चोटी के आदिलयों में से थे। उनकी शिख्सयत इस किस्म की थीं कि उनकी बफात से हक़ीक़तन सूबे में एक खला पैदा हो गयी। अब मुश्किल से उनकी जगह पूरी हो सकती है।

सब से बड़ी बात जो मैंने गोपी नाथ जी में देखी थी वह उनकी वसीउलस्याली थी उनमें किसी किस्म के जजवात, किसी किस्म का कोई खिचाव, किसी तरफ से भी चाहे वह शरकी ही या फिरके के हों या सूबे के हों, बिल्कुल नहीं पाये जाते थे। वह बहुत से खूबियों के मालिक थे। अगर वह एक तरफ सुलझी हुई तक़रीर कर सकते थे तो दूसरी तरफ निहायत ही मुअस्सर मजमून लिखा करते थे। जब वह पब्लिक सिवस कभीशन के चेयरमैन हुये तो उन्होंने जिस शान और जिस आला हौसलगी से उसके फरायज अंजाम दिये, मेरे ख्याल में मुक्किल से उसको भुलाया जा सकता है। मुझे तो उस वक्त अफसोस हुआ था जब मुझे यह मालूम हुआ था कि वह पब्लिक सिवस कमीशन की चेयरमैनी से अलाहदा हो गये। लेकिन खुवा को यह मंजूर न था और पब्लिक सिवस कमीशन की चेयरमैनी तो अलग रही वह खुव भी हमसे जुवा हो गये। यकीनन उनकी मौत से इस सूबे के बाशिन्दों को बहुत ही नुक़सान पहुंचा है। वह गवनं मेंट की तनकीद भी किया करते थे, लेकिन मैंने उनकी तनकीदों को हमेशा ही तामीरी पाया और उनमें मुक्त और बतन का एक ऐसा दर्द था जो दर्व बहुत कम हजरात में सही मानों में पाया जाता है। इसलिये

ृश्रे तर्ीहल हमतेन लारी]

में ममझता हूं कि न मिर्फ इस ऐवान को बल्कि इस सूबे की जनता को काफी धनका पहुचा है। ले किन इसका कोई चारा नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जजबात हमारे स्पीकर माहब उनके घर वालों तक पहुंचा देगे।

श्री जगन्नाथ वरुग मिह--सभापित महोदय, श्री गोपी नाथ श्रीवास्तव के निधन में बड़ी ही क्षित इस प्रान्त को और देश को हुई ज़ैसा कि उन दो महापुरुषों के विषय में मेंने अभी कहा था। गोपीनाथ जी साहिन्य के मर्मन्न थे, उल्लेखक थे और अच्छे वक्ता थे। तीसरो बान, युक्तिपूवक ओर स्वतंत्रता से अपने विचार रखने का गुण उनमे विशेषतापूर्वक वर्तमान था। मुझको बहुत काफी असें से उनका परिचय रहा है और वह जब अखबार में पहले से ज्यादा ममय देने लगे उस नमय मेरा परिचय कुछ और अधिक बढ़ा। में अधिक समय उनके गुणों का वर्णन करके, इस भवन के सभासदों को वास्तव में और दुखी नहीं करना चाहता, परन्तु में जानता हं कि इस भवन के अन्दर ही नहीं बल्कि इस भवन के बाहर भी उनके मित्रों की तादाद बहुत बड़ी थी। ऐसे मिलनसार आदमी का निधन जिनसे जायद कोई मी दुखी न रहा हो और ऐसे असमय पर बहुत ही असहय है। भेरा निवेदन है कि हमारी सहानुभूति उनके परिवार तक पहुंचा दी जाय।

प्राननाय स्वाकर—माननीय सदस्यगण, श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव से हम सब कांग्रेस वालों का इतना घनिष्ट और इतने त्यार का सम्बन्ध था कि उनके उठ जाने में हम लोगों को वहीं कब्ट हुआ जो अपने कुटुम्ब के किसी प्यारे भाई के जाने से होता है। उनकी योग्यता से सूबे के पढ़े—लिखे लोग परिचित थे। हिम लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वह कांग्रेस वालों के बीच एक हीरा थे।

उन्होंने इस भवन में इसकी पहली असेम्बली में अपने काम से हम लोगों को अपनी खोर खींचा था। उन्होंने जेल के प्रबन्ध का काम बड़ी सुन्दरता से किया था। उनमें विशेष बात यह थी कि वह महज रोज का ही काम नहीं किया करते थे बल्कि जिस काम की जिम्मेदारी वह लेते थे उसके भीतर घुस जाते थे उसके सिद्धान्तों की ओर उनका ध्यान जाता था। मैंने उनमें ऐसी बात जेल के प्रबन्ध में देखी। जब वह पब्लिक सर्विस कमीशन में गये, तब भी यह बात सामने आयी। उन्होंने कुछ नोट चेयरमैंन पब्लिक सर्विस कमीशन की है सियत से लिखे थे। वे नोट आज भी जो कमीशन में काम करने आदें, उनके पढ़ने और ध्यान देने की वस्तु है।

श्री गोपीनाथ ने अपनी कल्पनाशक्ति को केवल शासन के कामों तक ही सीमित नहीं रक्ला था। उनके हृदय के कुछ अनुमान उनके हृदय में कितनी करणा थी, इसका कुछ अनुमान मेंने उस समय किया था जब उन्होंने सूबे के दिर्द्रो का भिष्तमंगों का, प्रश्न अपना प्रश्न बनाया था। अभाग्यवश इस प्रश्न की ओर अभी देश भर में घ्यान बहुत ही कम गया है। हमारे मुल्क की जो समस्यायें है, उनमें यह समस्या अभी तक बिना किसी काम के पड़ी रही है। श्री गोपीनाथ श्रीवास्तव का उधर ध्यान गया। उन्होंने इस तरफ कुछ काम भी किया, लेकिन अभी तो वह काम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है। वह एक कड़ा काम है। श्री गोपी नाथ ने इस काम को उठाया। यह काम उनकी सच्चाई, इन्सान की तरफ उनके हृदय की खींच का नमूना थी। मुझे तो वह पहले से प्यारे थे, लेकिन जब उन्होंने यह काम उठाया तो उनकी ओर मेरा हृदय और भी खिच गया और वह बहुत अधिक प्यारे लगने लगे।

मै शब्दों में नहीं बता सकता कि उनके उठ जाने से कितनी वेदना हुई। मै आप सब की ओर से उनके कुटुम्ब की ओर अपने इस कर्त्तव्य का पालन करूंगा कि एक सहानुभृति का पत्र भेजा जाय। आप कृपा करके खड़े होकर अपने खेद का इजहार करें।

(थोड़ी देर लिये सब सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेमीडेंट के उम्चुनाव के सम्बन्ध में हा बरोको प्रस्ताव माननीय व्यक्तिर—श्री रोशन जमा खां साहब ने एक कामरोको प्रस्ताव की मुचना दी है। वह इस तरह है—

"मै प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा रार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विवाद करने के लिये सभा की कार्यवाही स्थिगित की जाय अर्थात् जालीन टिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उप-चुनाव को एकाएक अवैध और अनुचित रीति से स्थिगित किया जाना जिसके कारण जनता में घोर असंतोष हुआ है।"

श्रा र द्वान जाना खां—जनाब स्पीकर साहब, गवनमेट की तरफ से जालीन के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्रेसीडेट के बाईइलेक्शन का हुक्म सादिर किया गया था। इस हुक्म के वसूजिब दो उम्मीदवारान मैदान में आये। एक काग्रेस पार्टी की तरफ से ओर दूसरा सोशिलस्ट पार्टी की तरफ से आया। दोनो की नामजदगी हुई। नामजदगी के बाद नामिनेशन पेपर्स की स्कूटनी (जाच) हुई। यहां तक कि बैलट पेपर्स तक छप गये। इलेक्शन की तारीख १० जनवरी मुकर्रर थी और यह समझा जाता था कि अब बहुत ही थोड़े दिनो मे इलेक्शन हो जायगा। एकाएक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जालीन ने फरीकैन को मेरा मतलब दोनों उम्मीदवारान से हैं, इलेक्शन के मुलत्वी होने का नोटिस दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटने अपने नोटिस में कोई वजह नहीं बतलाई। हा यह जरूर है कि हुक्म की तरफ से ५ जनवरी को एक कम्यूनिक निकला है जिसमें कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो नये नियम बने हैं उसमें कही उसका प्रावीजन नहीं है लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। लेकिन में नियत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो ऐक्ट इस हाउस ने पास किया है उसकी दफा ३५ और ३५—बी इन दोनो को रू से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेमीडेट का इलेक्शन यानी चुनाव हो सकता था।

माननीय प्रधान मचिय--यह तो मेरिट्स की बात हो रही है। जब यह हो जाये तब आप करे। जिससे हाउस का वक्त किसी ओर खास काम में आ सके।

श्री राज्ञान जमा खां——जिसका हवाला गवर्नमेट ने दिया है वह गलत है और इस हाउस के बनाये हुये ऐक्ट की दफा को तोड़ने के लिये गवर्नसेट तैयार है। जाहिर है कि एक इलेक्शन को इस तरह से बिला किसी माकूल वजह के मुल्तवी कर देने से जनता में असंतोष पैदा कर देना है। यह तो डेमोक्रेसी के बजाय डिक्टेंटरशिप कायम करना है। लिहाजा में दरख्वास्त करूंगा कि इस मोशन पर हमको बहस करने की इजाजत दी जाये और गवर्नमेट से भी में कहूंगा कि उनको अपनी पोजीशन साफ करने का मौका मिलेगा लिहाजा वह इसकी मुखालफत न करे। हमें इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हम २८ मेम्बर्स खड़ा न कर सकेगे। लिहाजा गवर्नमेट से दरख्वारत है कि वह अपनी पोजीशन साफ करने के लिये और पोजीशन को अपने ख्यालात का इजहार करने देने के लिये इसकी मुखालफत न करे।

*माननीय प्रधान सिचिय — यह मोशन जो रोशन जमां खां साहब ने पेश किया है उससे मालूम होता है कि आपको बहुत ज्यादा धक्का लगा कि ऐसी कार्यवाही की गई और सारे सूबे में एक तहलका मचा हुआ है। जनता के ऊपर एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। उनके लिये यह बात हो सकती है लेकिन किसी और के देखने में यह बात नहीं आई। जहां तक मोशन का ताल्लुक है यह एडजर्नमेंट मोशन के अन्दर नहीं आ सकता। इसके मुताल्लिक जो कार्यवाही होनी थी वह हो चुकी है। इलेक्शन पोस्टपोन (स्थिगत) हो चुके है और इले—क्शन की प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करना या न करना गवर्नमेंट के अख्तियार की बात है।

मान्तीय स्पीका —कामरोकी प्रस्ताव पर बहस करने का मीमूली निध्य गार् है कि वह बहुत आवश्यक विषय पर हो। यह प्रस्ताव मुझे ऐसा नहीं रूपता उस्तिर में इस प्रस्ताव की अवैय भावता हूं और इसके पैश करने की अनुमति नहीं देता।

भृभिचरी अधिकार तथा अमींदारी-उन्मृहन-कोष एकत्र करने कं विषय

प्राननीय स्पीकर-श्री रोजन जमां खां का दूसरा काम रोकने का प्रस्ताय इस प्रकार हैं-

"मैं प्रस्ताव करता हं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा सार्वेद्धित का का प्राप्त का प्रमान का प्रमान के लिये सभा की कार्यवाही स्थानित की जाय अपनित कि किया है। किया के लिये दश्युने लगान की वसूली में अनुचित दबाय अ र अविधान अधिकार प्राप्ति के लिये दश्युने लगान की वसूली में अनुचित दबाय अ र अविधान अधिकार प्राप्त के लिये दश्युने लगान की वसूली में अनुचित दबाय अ र अविधान के उत्पादन के विधान के

्र रेचा किए में रवा का फसल, जिसान सत्याग्रह तथा भत्यात्र ति वन्दियों के ियय में कामगोको प्रताव

ग्या नाय स्योक्तर—श्रो रोज्ञन जमां खां के दो और प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव इस प्रकार है—

"से प्रनत् व करता हूँ कि निम्निलिसि आवायक तथा सार्वणिया गत्यपूर्ण प्रदेन पर विद्याः करने के किये सभ की कार्यवाही स्थिति की जाय अर्थात् देवरिया जिले में रबी की करल बादाद होने पर लगान में छूः न देने का सरकारी किया, किसान सरवाग्रत् के किछ नरकार के दरनात्मय कार्यवाही और जेल में सरवाग्रही बंदियों के साथ अमान्याय व्यवहार।"

यह प्रस्ताव भो न आक्ष्यक है और न सिवियत। यह स्मरण रखना धाहिये कि कोई निश्चित वस्तु होनी चाहिये, सभी उसके ऊपर ऐसा प्रस्ताव आ सकता है। यह प्रस्ताव बहुत फैला हुआ और गोल है। भ इसको उपस्थित करने की अनुमति नटा देना । प्रान्त में चीनी के मूल्य-नियंत्रण के सरबन्ध में कामरोकी अन्ताव

माननीय स्पी कर--श्री रोशन जहा खा का चोथा प्रस्ताव इस प्रकार है — 'में प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित आवश्यक तथा सार्वजनिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर

विवाद करने के लिये सभा की कार्यवाही स्थिगत की आय अर्थात्-

प्रान्त में चीनी के मूल्य-नियत्रण में सरकार की भयंकर प्रसफलता ओर नीनी की

गड़बड़ी, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कष्ट उठाना पड़ा।"

यह एक निश्चित विषय है और इस विषय में मेरी सहानुभूति श्री रोशन जमा लां के साथ है, लेकिन मुझको यह नहीं लगता कि में इसको एक ऐडजर्नमेट मोशन (कामरोको प्रस्ताव) का विषय मानकर इस पर बहस करने की इजाजत दूं। यह कोई ऐसा आवश्यक विषय नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी मुसीबत या विकत हो और जितपर गवर्नमेंट को कोई काम फोरन करने की जरूरत हो। इसमें संदेह नहीं कि उचित है कि सदस्यगण इस विषय पर गोर करे, गवर्नमेंट भी गोर करे, लेकिन कामरोको प्रस्ताव का यह विषय बने, ऐसा मुझको उचित मालूम नहीं होता। में इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की भी इजाजत नहीं देता।

सन् १६४६ ई० के संयुक्त पान्तीय काइत भार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधेय म (बिल) पर महामान्य गवनर की स्वीकृति की सोषणा

मान गिर्जा निर्मातिमा—में घोषणा करता त कि सन् १९४९ ई० के सयुदत प्र तीय काइतकार (विश्वषाधिकार उपार्जन) विध्येक (बिल) पर, जिसे सयुवत प्रातीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १६ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा स्युदत प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कोसिल ने अपनी २३ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति १०अगस्त सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का प्राप्त हो गयी

मन् १६५९ ई० के संयुक्त प्रान्तोय मेन्टिनेन्स आफ पिन्तक आईर (संशोधन ग्रीर कार्यवाहियों का वैद्य काने के) बिल गर महामान्य गर्जन र आ रहा की स्वीकृति की गोषणा

माननीय स्वाक्ता—में घोषणा करता हू कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय मेन्टिनेंस आफ पब्लिक आर्डर (सशोधन और कार्यवाही को वैध करने के) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिरलेटिव असेम्बली ने अपनी २१ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिसलेटिव कौतिल ने अपनी ३ अगस्त सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर जनरल की स्वीकृति १२ अगस्त सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का ग्यारहवा ऐक्ट बन गया।

सन् १६४६ ई० के रुड़कां विश्वविद्यालय (युनियसिंटी) (मंशोधन) बिल पर महामान्य गर्वनर की स्थाकृति की बाषणा

माननात्र म्पाकर—में घोषणा करता हूं. कि सन् १९४९ ई० के चड़की विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) (संशोधन) बिल पर, जिसे संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौसिल ने अपनी १४ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में तथा संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी २१ जुलाई सन् १९४९ ई० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्य गवर्नर की स्वीकृति ७ सितम्बर सन् १९४९ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त का बारहवां ऐक्ट बन गया।

सन् १६४६ ई॰ का संग्रुक्त प्रान्तोय ग्रौषधि (नियंत्रण) ग्रार्डिनेम्स माननीय श्रन्न सचिव—अध्यक्ष महोदय, में सन् १९४९ ई॰ के संयुक्त प्रान्तीय औषधि (नियंत्रण) आर्डिनेंस (सन् १९४९ ई॰ की संख्या ६) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १६४६ ई० का इंडियन बार कौन्सिल(यू० पी० ग्रमेन्डमेंट पेन्ड वैछिडेशन ग्राफ प्रोसीडिंग्स)ग्रार्डिनेन्स

माननीय प्रधान सन्तिव--मैं सन् १९४९ ई० के इंडियन वार कौंसिल (यू० पी० अमेन्ड-मेंट एन्ड वेलिडेशन आफ प्रोसीडिंग्स) आडिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ८) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १२७६ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज रिक्यू जीशन ग्राफ़ मोटर वेहि किस्स (इमजन्सी पावस) (अमेंडमेंट ऐन्ड प्रोसोडिंग्स वेलिडेशन) ग्राडिनेन्स

माननीय पुल्तिस सचिव--में सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविन्सेज रिक्वीजीशन आफ्रमोटर वेहिकित्स (एमर्जेन्सो पावर्स) (अमेन्डमेंट ऐन्ड प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन) आडिनेंस (सन् १९४९ ई० को संख्या १०) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १६४९ ई० का क्रमायुं एनिमन ट्रान्सपेटि कन्द्राल (यमेंडमेंट) यार्डिनेंस

मानेनीय यत्र सचिव--में सन् १९४९ ई० का कुमायूं एनिमल ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल (अमेंड्रनेंट) आडिनेंस (सन् १९४९ ई० की संख्या ११) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

हरिद्वार कुम्भ मेला के नियम

माननीय स्वदाःसन मिचव--में यू॰ पी॰ मेलाज ऐक्ट सन् १९३८ई० की धारा ९ (१) के अन्तर्गत बनाये गये सन् १९५०ई० के हरिद्वार कुम्भ मेला के नियम की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

इलाहाबाद माघ मेला के नियम का संशोधन

माननीय स्वशासन संचिव--म यू०पी० मेलाज ऐक्ट, सन् १९३८ ई० की धारा ९ की उपवारा (१) के अन्तर्गत बनाए गए सन् १९४० ई० के इलाहाबाद माघ मेला के नियम ४ (१) में किए गए संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

यू० पी० माटर वेहिकिल्स रूल्स (नियमेां)का संशोधन

माननीय पुलिस सचिव--में सन् १९३९ ई० के मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा १३३(३) के अनुसार यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स के नियम १३१ (ए) में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १९४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश बीर भूमि-व्यवस्था बिल*

†माननीय माल सचिव--माननीय अध्यक्ष महोदय, में सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर संयुक्त विशिष्ट समिति की रिपोर्ट उपस्थित करता हूं।

आपकी आज्ञा से इस सम्बन्ध में में चन्द शब्द इस ऐवान के सामने कहना चाहता हूं। इसमें दो रायें नहीं कि जमींदारी-उन्मूलन की मांग किसानों की बड़ी पुरानी और बहुत ही आवश्यक है। कांग्रेस ने हमेशा अपना यह घ्येय रखा है कि किसानों की इस मांग को पूरा किया जाय क्योंकि कांग्रेस हमेशा इस बात को महसूस करती रही कि जब तक

^{*}देखिये नत्यो 'च' आगे पृष्ठ ७७ पर। †माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मौजूदा जमींदारी का दस्तूर रायज रहेगा, हमारे किसानों का उद्घार किसी तरह से हो नहीं सकता। विदेशी हुकूमत के आने पर हमारा देश गुलाम हुआ लेकिन साथ ही साथ इस जमींदारी प्रथा के रायज होने पर किसानों की गुलामी में भी किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। किसान हमारे सूबे की एक खास जमाअत है। करीब अस्सी—पचासी फीसदी लोग खेती पर जिन्दगी बसर करते है और इन्हों के परिश्रम का यह नतीजा है कि बिकया तबके के लोग अपनी जिन्दगी आराम से बसर करते हैं। लिहाजा हमेशा यह बात मानी गई कि अगर अधिकांश लोगों की जो खेती करते हैं माली हालत खराब रही, अगर वे परेशान हाल रहे और अगर उनको अपने काम मे पूरा फायदा उठाने का मौका न रहा तो हमारा सूबा किसी तरह से खुशहाल नहीं बन सकता।

इसके ताय-ताथ जो दस्त्र इस वक्त हे उतकी वजह से जो फठिनाइयां कितानों के रास्ते में है उनकी दुहराने की में ज्यादा आवश्यकता नहीं समझता। में समझता हूं कि जब यह बिल हाउस के सामने पेश हुआ था तो काफी वादिववाद इन बातों पर हुआ था। इसके साथ-साथ हमेशा पब्लिक प्लेटफार्म से इनका इजहार वक्तन फवक्तन होता रहा लिहाजाइस सम्बन्ध में इस ऐवान का वक्त लेना में मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक बात में यह कहना चाहता हूं

श्रा तही हत हस्तेन लारी--जनाब सदर, रिपोर्ट पेश की गई है तकरीर करने का मौका नहीं है। यह तकरीर कैसे हो रही है ?

माननीय रुपीकर--अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। कायदे के मृताबिक उनको अख्तियार हैं कि रिपोर्ट पेश करने के साथ-साथ जो मुख्य-मुख्य बाते हों उनको थोड़े शब्दों में कहें।

माननीय माल सिचिय--मेने अध्यक्ष महोदय की इजाजत लेकर चन्द बाते कहनी हुइ की थीं। मेरे लाय हा योहत जह रत से ज्यादा परेशान हो गये। लारी साहब उस वक्त थे नहीं, लिहाजा, गालिबन उन्होंने न सुना हो कि मैने स्पीकर महोदय की इजाजत से बाते शुरू की थीं। खैर में लारी साहब की भी दिलाजारी नहीं करना चाहता अभी उनसे बहुत काम लेने हुं, इसलिये में महन तरन अपनी बातें कहता हूं ताकि मैं अपनी बात भी कह दूं और लारी साहब को भी परेशानी नहीं।

म यह कह रहा था कि इस जमीं द्वारी उत्मूलत की मांग बहुत पुरानी थी और जरूरी थी लिहाजा यह बिल बन कर तैयार हुआ ओर इस एवान में पेश हुआ। इस ऐवान ने उसे विशिष्ट समिति के सुर्दे किया। बिल को विशिष्ट समिति के सुर्दे करने के बाद यह तय है कि इस हाउम ने इस उसूल को माना है कि जमीं दारी खत्म होनी चाहिये। विशिष्ट समिति के पास यह बिल पहुंचा, उसने विचार किया और गीर किया। लारी साहब के साथी लोग भी मौजूद थे। में उन सब साहबान को बन्यवाद देता हूं जो इसमे थे और उनके सहयोग से बिल पर विचार करके यह रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में दो—चार जो नई बातें आई हैं, जो नई तब्दीलियां हुई हैं, यह में जरूरी समझता हूं कि उनका जिक कर दूं और गालिबन लारी साहब को उनके सुनने में कुछ कब्ट न होगा।

श्री जहीरळ हमनेन लारी—दूसरा मोशन आप पेश नहीं करना चाहते? माननीय प्रधान सचिव—जी नहीं।

मानतीय माल स्चिव—-बिल में यह था कि जो २५० रु० से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदार ये उनकी सीर और लदकाइत की डिमार्केशन हो जाने के बाद मुआवजा तशालीस किया जाय। कमेटी ने यह सोचा और यह मुनासिब समझा कि यह डिमार्केशन की प्रोसीडिंग्स की जायगी तो बहुत वक्त मुआवजा तशालीस करने में लगेगा जिससे हमारे

[माननीय माल सचिव]
जमीं बार भाइयों की कट होगा, उनकी मुआवजा मिलने में देरी होगी, लिहाजा डिमार्केंगन की प्रोसीडिंग्स को खत्म कर दिया गया और और इस तरह से जो देरी होने वाली थी तश्खीस मक्षवजे में, वह न होगी। इसके साथ-शाथ पहिले बिल में यह रखा गया था कि अगर कोई ठेकेदार की तीर या खुदकारन की जमीन जोतता है तो और अगर वह ५० एकड़ तक है तो वह भी उस कारतकार को किल गयगी लेकिन अगर सीर के अलावा दूसरी जमीन है और वह ५० एकड़ तक है तो उसके कब्जे में रहेगी। इसके बजाय कमेटी ने खुदकारत की सीमा को घटा कर २० एकड़ कर दिया ने और इस तरह पर इसमें २० एकड़ की कमी हो गई है। एक सवाल यह भी कमेटी के सामने आया था कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको जमीन दी गई और वाकई में जमीन कारत के लिये दी गई लेकिन ठेका कह कर दी गई। मौजूदा कानून की ह से ठेकेदार उसका मौख्सी हो गया। इस दिक्कत को मिटाने के लिये यह भी प्राविजन रख दिया गया। कि अगर इस बात का सबूत हो कि वाकई वह जमीन कारत के लिये दी गया। कारत के लिये दी गया कारत के लिये दी गया। कारत कारत कारत कारत कारत के लिये दी गया। कारत कारत के लिये दी गया। कारत के लिये दी गया। कारत कारत कारत कारत कारत कारत के लिये दी गया।

इसके अलावा एक तब्बीली और की गई है और वह अजला में इस्तमरारी वन्वोवस्त के बारे में ह। हमारे नवाब साहब भी इस बात से बलूबी वाकिफ़ होंगे कि जौनपुर ओर बिल्या में ऐसे काश्तकार ह। इनके लिये बिना १० गुना दिये ही भूमिधरी हक उनको देने का इसमें प्राविजन (व्यवस्था) किया गया है। कुछ रेट प्राीया प्रान्ट की भूमि को जोतने वाले लोग भी ह उनको बिला किसी अदायगी के भूमिधरी हक्ष दिये गये है। इस तरह के काश्तकारों की जो शरह मअय्यन काश्तकार है, बहुत सी ताबाद है, यह छोटे तबके के लोग हैं लिहाजा उनके भी हकक बराबर ख्याल करके उनके लिये भी सेलेबट कमंटी ने प्राविजन किया ह।

गई थी, ठेके के लिये नहीं तो चाहे उसे ठेका कहा गया हो या और कुछ, वह काइत के लिये

ही समझी जायगी और उसी को कानुनी हक्क हासिल होंगे।

इसके साथ-साथ सेलेक्ट कमेट्री न एक तब्बीली और की है वह यह है कि १ जलाई सन् १९४८ के बाद जितने ट्रांसफर्स (तबादिले) हुये हैं स्वाह वे बैमामे के जित्य से हुये हों या हिबा के जित्ये से, वह कानूनन जायज करार नहीं दिये गय हैं क्योंकि कमेट्री के स्थाल म यह बात आई कि जब से इस बात की कोशिश चली लोगों ने बहुत से फर्जी ट्रान्सफर्स किये ताकि वे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट पुनर्वासन अनदान के मुस्तहक हो जायं। जहां तक रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का ताल्लुक है ऐसे ट्रान्सफर्स जायज करार नहीं दिये गये हैं।

कमेटी न एक एसा प्राविजन किया है कि अगर ४ काइतकार हैं और वे मुइतरका है तो अब तक उनके जिय कायदा यह या कि एक भी काइतकार यदि चाहे तो भूरा मतालबा बमा कर सकता या यानी अपन हिस्सेदारों की तरफ से भी जमा कर सकता था लेकिन इसम काइतकारों को बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लिहाजा कमेटी ने इस पर भी विचार किया और हर एक को अपना हिस्सा देने का हक दे दिया। अब यह प्रावीजन भी हो गया है कि अगर वह सबकी तरफ से भी जमा करता है तो दूसरे के हिस्सों के मतालबे को बतौर लैन्ड रेवेन्यू के वसूल कर सकता है ताकि उसको जमा करने और उसको वसूल करने में कोई दिक्कत न हो।

एक बात बिल में यह भी है कि औरतों नाबालिंग और डिसऐबिल्ड परसन्स को राइट्स दिये गये हैं तथा इसके साथ ऐसे लोगों को भी, जो बीमार हैं या जो कालेज वगरह में बढ़ते हैं उनको भी सबलैटिंग करने के राइट्स दिये गये हैं है इस तरह से उसका भी स्कोप सेलेक्ट कमेटी ने कर दिया है। उसके साथ-साथ जहां तक कि बटवारे का ताल्लुक है उसके लिये भी सेलेक्ट कमेटी ने कुछ मैदान वसी कर दिया है। सवा छः एकड बेसिक होल्डिंग मान करके बटवारे में पहले दिक्कतें थीं लेकिन अब एसा कर दिया गया है कि मान लीजिये कहीं से एक से ज्यादा काइतकार है और उनमें कोई डिसएबिल है या कोई लेडी है या कोई लड़का है जो कालेज में पढ़ता है तो ऐसे लोगों को सबलेटिंग की इजाजत दी गई है और अपने हिस्से के बटवारे की इजाजत दी गई है, ख्वाह वह सवा छः एकड़ से कम प उता हो। इस तरह से कमेटी ने इसमें भी संशोधन किया है।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर श्री नफीसुल हसन डिप्टी स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

माननी प्रमाल माच्चय—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में इस सम्बन्ध में यह कह रहा था कि सेलेक्ट कमेटी ने प्रा २ खास—खास तब्बीलिया की। सेलेक्ट कमेटी ने सब— दिनेंट्स के लिये भी यह किया हैं कि अपने लंडहोल्डस की इजाजत से इस वक्त भी दसगुना जमा करके भूमियर हो सकते ह और जो रेलिजस और चैरिटबिल इंस्टीट्यूशंस ह, जिनके पास सीर और वृदकाश्त है वे अविवासी भी अपना दस गुना जमा करके भूमियर का हक हासिल कर सकते हैं। उनके साथ ही साथ मेलेक्ट कमेटी ने इसमें दावे और दरख्वास्तों के बारे से जो तरीका मुकर्रर किया हे यह भी शेड्यूल की शकल में इस बिल में लिखा गया है जिससे यह पता चलेगा कि किस किस्म के दावे, किस किस्म की दरख्वास्तें किस इजलास में होनी चाहिये। एक तब्दीली इसमें और भी की गई है, वह यह है कि अभी तक तीन अपीलें हुआ करती थी लेकिन अब सिर्फ दो अपीलें होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण तब्दीली हैं। इसके अलावा और भी कुछ चेजेज किये गये है जो कि बहुत साधारण है और जिनका जिक आगे किसी मोके पर किया जावेगा। इन शब्दों के साथ में इस रिपोर्ट को उपस्थित करता है।

मन १६४८ ई० का मंयुक्त प्रान्तीय अुद्ध खार्रा विठ (ब्रालेख)

भाननीय प्रश्न मिचित्र—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मं सन् १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य बिल (आलेख) पर विशिष्ट समिति को रिपोर्ट उपस्थित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ... पर)

सन् १६४९ ६० का काम्रापरेटिव मासाउरीन (पंयुक्त प्रान्तीय संशोत्रक) बिल

माननीय प्रधान मचिय--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल, उपस्थित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मं यह प्रस्ताव करता हू कि सन् १९४९ ई० के कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल पर विचार किया जाय। यह एक बहुत साधारण संशोधन हैं। इस बिल में एक क्लाज सन् १९४४ में रक्खा गया या जिससे कि जो अनिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज के मेम्बर हैं वह अगर कर्जी लें तो वह कर्जी उनकी कोआपरेटिव सोसाइटी का, उनकी तनख्वाह में से उनके इम्पलायर (मालिक) किस्तों में काट लें। उस क्लाज में रेलवेज के मुलाजिम एक्सक्लूड (अलग) किये गये थे परन्तु उस एक्सक्लूजन (अपवाद) से अब वे अलाहदा किये जाते हैं ताकि रेलवेज के मुलाजिम भी या सेंट्रल सरविसेज के मुलाजिम भी अगर सोसाइटी से कर्जा लें तो उनके इम्पलायर (मालिक) उनसे कर्जा बसूल करें। यही उसमें संशोधन हैं जो कि बिलकुल एक नानकंट्रोवर्सियल (निर्विवादास्पद) चीज है।

हिट्टी स्पीकर — सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० के कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

घारा २

आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ की वारा २८-ए की उपधारा (४) को जाय।

घारा १

) यह ऐक्ट कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) ऐक्ट, १९४९ Derative Societies (U. P. Amendment) Act, 1949]

यह समस्त संयुक्त प्रान्त मे लागू होगा। यह तुरन्त लागू होगा।

प्रस्तावना

भावरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ (Co-operative Societies Act, रं तक इसका सम्बन्ध संयुक्त प्रान्त से हैं, संशोधन करना उचित ओर आवश्यक हैं नीचे लिखा कानून बनाया जाता हैं।

हिट्टी स्पीकर—सवाल यह है कि बिल की भारा २, भारा १ और प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय।

(प्रक्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रधान सचिव—मै यह प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल स्वीकार किया जाय, जैक्षा कि इससे मेने पहुछे कहा था कि पहले ऐक्ट में यह था—

Nothing contained in this section shall affect Foderal Railways or other departments directly under the control of the Central Government

(इस घारा में दो हुई किसी चीज का प्रभाव फेडरल रेलवेज या अन्य विभागों पर जो सीचे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है, नहीं होगा।)

यह क्लाज इसमें से निकाल दिया जाय ताकि सेन्द्रल गवर्नमेंट के जो नौकर है उनकों भी इसका फायदा पहुंच सके।

डिप्टी स्पीकर--प्रश्न यह है कि सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (संयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों की बसाने के लियं (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल

माननीय प्रयान सचिव-- में सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल उपस्थित करता हूं। (कुछ ठहर कर)

मं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने के) (संशोधन) बिल पर.विचार किया जाय।

यह बिल भी बहुत मामूली हैं। पहले जो इसके अन्दर लफ्ज थे उसकी परिभाषा यह थी कि शरणार्थी वही होगा जो कि ३१ मार्च सन् १९४८ ई० तक रजिस्टर्ड हो चुका हो। इसके मुताबिक ३१ मार्च सन् १९४८ तक जो लोग यहां पर रजिस्टर्ड हो चुके थे वही शरणार्थी माने जा सकते थे इससे कई दिक्कतें हुईं और कुछ शरणार्थी जो उस तारील के पहले आ गये हों या उसके बाद भी आये हों मगर जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई उनको यह ऐक्ट लागू मही हो सकता था। इसलिये उस अड़चन को दूर करने के लिये शरणार्थी की यह दूसरी इंफिनिशन (परिभाषा) की गई ह, जिसके मुताबिक जो कोई भी पाकिस्तान से यहां आया हो वह भी शरणार्थी माना जा सकता है। अंग्रेजी मे जो शरणार्थी की परिभाषा अभी तक थी वह यह थी कि ३१ मार्च सन् १९४८ ई० के पहले जो यहां रजिस्टर्ड हो चुका हो अब जो यह अमेडमेट किया है उससे यह हो जायगा कि:——

Refugee means any person who was resident in any place which now forms part of Pakistan and who on account of partition or civil disturbances or fear of such disturbances has on or after 1st. March 1947 migrated to my place in the United Provinces and had been residing here

(शरणार्थी में तात्पर्य ऐमें व्यक्ति से हं जो उन प्रदेशों का निवासी रहा हो जो अब पाकिस्तान का भाग है और जो देश के विभाजन के कारण अथवा नागरिक दंगों के कारण अथवा ऐसे वंगों के भय से उन प्रदेशों ने १ मार्च, १९४७ ई० को अथवा उसके बाद संयुक्त प्रान्त के किसी भी भाग में चला आया हो और तब से वहीं रह रहा हो।)

डिप्टो रूपी हर-- सवाल यह हे कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणाियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।)

धारा र

२—संयुक्त प्रान्त के शरणाधियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का ऐक्ट, १९४८ ई० की बारा २ के खंड (७) में दी गई "शरणार्थी" शब्द की परिभाषा के स्थान पर निम्न-लिखित परिभाषा रखी जायगी:—

"शरणार्थी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से हैं जो उन प्रदेशों का निवासी रहा हो जो अब पाकिस्तान का भाग है और जो देश के विभाजन के कारण अथवा नागरिक दंगों के कारण अथवा ऐसे दंगों के भय से उन प्रदेशों से १ मार्च, १९४७ ई० को अथवा उसके बाद संयुक्त प्रान्त के किसी भी भाग में चला आया हो और तब से वहीं रह रहा हो।"

संपृक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० २६ की धारा २ की उपवारा (७) में संशोधन

धारा १

१—(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय शरणाथियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने का (संशोधन) ऐक्ट, १९४९ ई० कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त लागू होगा।

संक्षिप्त जीर्षं क और प्रारम्भ

प्रस्तावना

क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्त के शरणाथियों को बसाने के लिये भूमि प्राप्त करने के ऐक्ट १९४८ ई० में ऐसे प्रयोजनों के लिये जो आगे मालूम होंगे, कुछ संशोधन किया जाय।

इसलिये नीचे लिखा ऐक्ट बनाया जाता है :---

संयुक्त प्रान्तीय **ऐक्**ट सं० २६,

8685 €0

हिप्टी न्पी कर—सवाल यह है कि घारा २, धारा १ और प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

माननीय प्रयान मिवव--में प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के करणांथियों को बनाने के लिए (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) बिल पास किया जाय।

हिण्डी स्पीकर-सवाल यह है कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को वसाने के लिए (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन) दिल पास किया जाय।

(प्रक्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्या बिल

*माननीय मान्न सिचव—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि—व्यवस्था बिल पर, जसा कि वह संयुक्त विशिब्ध समिति द्वारा संशोधित हुआ ह, विचार किया जाय।

इस सम्बन्ध में आपकी इजाजत से मं चन्द बातें इस ऐवान के सामने अर्ज करना चाहता जैसा कि इस भवन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है और अवाम को भी भली-भांति मालूम है कि मौजूदा दस्तूरे जमींदारी के खात्में का रावाल असे से हमारे देश और सूबे में वेश ह। किनानों की यह मांग हमेशा से थी कि इस जमींदारी के दस्तुर का खात्मा किया जाय और उनकी गुलामी को दूर किया जाय ताकि वह भी आजाद होकर अपनी जिन्दगी चैन से बसर कर सकें, देश को फ़ायदा पहुँचा सके और सूबे का फ़ायदों कर सकें। कांग्रेस ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि इस प्रश्न पर किसानों यो फ़ायदा पहुँचावें और उनकी यह मांग पूरी करें, लेकिन कांग्रेस के रास्ते में अड़चनें थीं और वह अड़चनें खास तौर से अंग्रेजी हुकूमत की वजह से थीं। अंग्रेजी हुकूमत न जमोंदारों को अच्छी तरह से मजबूत कर रखा था ताकि उनका काम चलता रहे और हमेशा देश पर उनकी हुकूमत क्रायम है और देश के तमाम काश्तकारों की असली कमाई का फायदा नाजायज तरीक़े से वह उठाते रहें और किसानों को सर उठाने तक की जुरत न हो और वह सहूलियत के माथ हुकमत करते रहें। लेकिन पूज्य महात्मा गांधी के इक़बाल से हमारे आपके रास्त से अड़चनें दूर हुई, विदेशी हुकूमत दूर हुई और हम अपन देश के मालिक हुए। अब हम जिस तरह से चाहें अपन देश का प्रबन्ध कर राकत हैं और अब हम ऐसे क़ानून भी बना सकत है कि जिससे हमारे देश के अधिकांश रहन वालों का फायदा हो। लिहाजा अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये जब से कांग्रस हक्मत कायम हुई हर तरह का उद्योग किया गया और एक कमेटी क्रायम की गई थी। इस कमेटी न हरतरह से, हर पहलू से, जितने भी सवाल पैदा हो सकत थ, उन पर गौर किया ह। काम आसाव नहीं या जैसा कि हमारे चन्द भाइयों का स्थाल है। खास कर हमारे सुबे में वसे तो कई सूबों में इस सवाल को हल करन की कोशिश की गई और की जा रही ह। लेकिन हमारा सूबा इतना लम्बा-चौड़ा है कि इतने सवालात को हल करना और इतनी कारत का इन्तजाम करना बहुत मुश्किल काम ह। यह कहना कि इसमें देरी हई, कितना ठीक ह या गुलत ह इसकी बाक़या साबित करेंग और बताएंग । में यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रस सरकार ने किसी क्रिस्म की कोई कोताही इस सवाल के हल करन में नहीं की। कोई बेजा बात सर्फ करने की कोशिश नहीं की। कमेटी ने विचार करके अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर विचार करके मसविदा क़ानून इस एवान के सामने पक्ष हुआ और विशिष्ट कमेटी दोनों हाउसेज के मेम्बरान की क़ायम की गई। यह काम

माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मुद्रतका उसके सिपुर्द हुआ। कमेटी ने काफी जाच की। जितने प्राविजन्स रक्खे गए उन पर खूब विचार किया गया। विचार करने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी, जिस रिपोर्ट को मैने अभी एंवान के मामने पेश किया है। जहा तक इस बिल का ताल्लुक है में तो यह कह सकता हूँ कि इसमें काफी इन्तजाम किया गया है कि हमारे किसानों का भला हो। मौजूदा स्थित और मौजूदा हालात में जो कुछ मुमकिन था उसको इस बिल में लाने की कोशिश की गई है। असली मंशातो यह पाकि जो किसान ह और जिनकी तादाद हमारे सूबे में ८०-८५ फीसदी है बहुत बड़ी तादाद है और जिनकी माली हालत भी अच्छी नहीं है, मौजूदा दस्तूर की वजह से उनको अपनी कमाई का पूरा फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता था। कमाते वे थे ओर फायदा दूसरे लोग उठाते थे जिससे कि जैसी उनकी माली हालत होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। इसके साथ २ किसानों की तबियत अपनी खेनी में लगती नहीं थी। उनके दिल में हर वक्त इस बात का स्थाल रहता था कि जमीन के मालिक वे नहीं, दूसरे लोग मालिक है। ऐमे मौके और जांसेज हो सकते है जब कि ये जमीन से बेदखल हो सकते है। जब तक किसान को इस बात का इसीनान नहीं होता कि यह अपनी जमीन का मालिक है।

श्री जहीरत हस्तन लारी--यह तो आप ओरिजनल बिल पर तरुरीर फरमा रहे हैं।

माननीय माल मचिव-मे यह कह रहा था कि किसान को इस बात का इस्मीनान हो जाता है कि जमीन मेरी ह, में उसका मालिक हूँ जिस तरह से चाहूँ उसका इतजाम कर सकता हूँ तब ही वह पूरी कोशिश से, पूरी दिलचस्पी से खेती-बाडी के काम मे लगता है, काफी रुपया भी सर्फ करता है। लिहाजा यह जरूरी समझा गण कि इस इन्तर्जाम ओर इस दस्तर को हटाकर हर काक्तकार को जो अपनी जमीन को जोतता है उस जमीन का मालिक बना देना चाहिए। असली दृष्टिकोण इस् अल या यही है। साधारण तात नही, महत्वपूर्ण बात है। हर नाइनकार को जमीदार बनाने की चेट्या की गई। अब तक हमारे यहां जहां तक मौजूदा कानून का नाल्लुक है नहीं मालूम भिराने किरम के इटरस्ट है, जिनकी फेहरिक्त लेखो-चोड़ी हो जहती है, जिस के फलस्वरूप हमारे सूबे का रेशार्ड इतना पेचीदा है कि जिसके मुनाहिलक दो राये नही हो सकती। हमारे लारी साहब खूब वाकिफ है ओर गोरखपुर जिले के रहने वाल है। इस बिल में यह रक्खा गया कि जितने हुकूर थे, उनको एक कलम खत्म कर दिया जाय। क्लामेज कन कर दिगे जामे जिसको फेट्टिस्त बहुत लम्बी न हो, जैसीकि मौजूदा तरीके के मातहत है। तो अब सारे हुकूक ओर गारे क्लासेज को खत्म किया गया औरतीन क्लासेज भूनिवर, मीरदार, असामी और चौथे अधिवासी जो महज टेम्पोरेरी है यह आगे बल कर खत्म हो जापगा। लावारिस हो कर निर्फ तीन शाखे रहेगी। इस तरह से हमने इसको बहुत सीधासादा बनाया है ताकि हमारे किसानों को समझने में दिक्क़त न हो और इसके फलस्वरूप हमारा जो विलेज रेकार्ड है सीधा-सादा हो जाय इसके माय-प्राथ इसमें जमींदारो की गुजर-औकात का भी ठीक-ठीक लिहाज रखा गया है और में समझता हूँ कि इससे हमारे लायक दोस्त रोशन जमां साहब भी मझसे खुश रहेंगे और मृतमइयन रहेगे क्योंकि उनकी भी दिलवस्पी आजकल उन लोगों में काफी है। तो इस बिल में यह रखा गया है कि जमींदारो की जितनी सीर और खुदकाइत है, जो अपने हल बैल से वे जोतते है वह बदम्तूर उनके पास कायम रहे और जो बागात उनके है वह भी बदस्रूर उनके पास क्रायम रहें। यह भी इस बिल में ठीक तौर से प्राविजन कर दिया गया है।

जहां तक इस बात का सवाल है कि जमीं दारी खत्म होने के बाद जमींदार भाइयो की किस तरह से अपने रहन-सहन का इन्तजाम करना होगा, उसका भी माकूल इन्तजाम इस बिल में हैं। भले ही लोग कहें कि मआविजा जमींदारों को न दिया जाय, लेकिन यह बात अनुचित सीप्रनीत हुई और नामुनामिब सी मालूम हुई कि मुआविजा न दिया जाय और जमींदारी

माननीय माल सचिव ज्ञान कर ली जाय। अव्वल तो क़ानूनी अड़चनें हैं जिससे उनको मुआविजा देना जरूरी है और इसके अलावा एक तादाद जमींदारों की है और अगर उनकी जायदाद जिस पर वह चाहे मही तरीक़े से या ग्रलत तरीक़े से उनकी मिल्कियत है और जिससे उनकी गुजर-औकात होती है, अगर आज हम एकबारगी उससे उनको महरूम कर दें और उनको छोड़ दें और उनकी जीविका का कोई माकूल इन्तजाम तक न रहे तो क्या हुछ होगा, उनका और उनके बालवच्चों का और उसके क्या असरात होंगे हमारे सूबे पर, हमारे

सूब के रहनेवालों पर, यह भी बात देखने के क़ाबिल थी और इसका भी लिहाज रखा

यया है ।

इसके साय-साथ हमने इस बिल में जमींदारों को दो तबकों में तक़सीम किया है। एक बड़ा तबका जो पांच हजार रुपये या उससे ज्यादा मालगुजारी देता है और दूसरे वह लोग जो पांच हजार से कम मालगुजारी देते हैं। जहाँ तक छोटे जमींदारों का ताल्लुक है, उनकी तादाद तो बहुत काफी है, वह १८ लाख से कम न होंगे। उनकी , बमींदार केहना कहां तक ठीक होंगा, में तो कुछ कह नहीं सकता, मुमिकन है वह बुरा मान जायं, अगर में जमींदारन कहूँ, लेकिन जहां तक उनकी माली हालत का ताल्लुक है वह अच्छी नहीं है। लिहाजा इस बिल में हमने यह रखा है कि जो बड़े जमींदार है उनको ८ गुना मुआविज्ञा दिया जायगा और जो छोटे हैं उनेकी यह मुआविजा तो मिलेगा ही लेकिन उसके माय-साथ उनके लिये पुनर्वास का भी इन्तजाम किया गया है कि उनको २० गुने से लेकर ३ गुने तक और मुआविजा दिया जा सकता है। इस तरह से छोटों के लियें भी काफी प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि वे अपनी आइन्दा आने वाली जिन्दगी को ठीक तरह से बसर कर सकें और अपने को नये समाज के निर्माण में ठीक तौर से बैठा सकें। इंसलिये ये सब बन्दिशें और इन्तजामात उनके लिये भी किये गये हैं। जहां तक बड़े जमींदारों का सवाल है, उनकी जरूरियात के लिये और मौजुदा हालाते को देखते हुये, किसानों की माली हालत को देखते हुये, हम उनको भी एक माकल रक्तम दे रहे हैं जिससे वे अगर चाहें तो अपना ठीक तौर से इन्तजाम. कर सकते हैं और अपनी जिन्दगी चैन से गुजार सकते हैं। हां, इस मौजूदा हालत में जो उनके इस समय अखराजात है उनके लिये हमारा मुआविजा भले ही पूरा न होसके लेकिन अगर वे एक अच्छे नागरिक की हैसियत से उद्योग-धंधेमें लग करके अपने जीवन का इन्तजाम करगे तो में समझता हूं कि जो रकम उनको मिलेगी वह वहुत मुनासिब और काफी होगी और उससे वे ठीक तौर से अपना इन्तजाम और प्रबन्ध कर सकते हैं।

इसके साथ-साथ हमने इस बिल में यह भी इन्तजाम किया है कि गांव-समाज परती जमीनों का मालिक होगा। वहां के तालाब, कुएं, फिशरीज, घाट, वर्गरह का इन्तजाम सब गांव-समाज के अधीन होगा और आबाबी, चरागाह, जंगलात इत्यादि सब गांव-समाज की मिल्कियत होंगे। इनका गांव-पंचायतें प्रबन्ध करेंगी और इस तरह से हुम तो यह चाहते हैं कि हमारे गांवों के रहने वाले और वाक़ई जिनका खेती से ताल्लुक है और जमीन से ताल्लुंक है वे लोग खुद गांव का प्रबन्ध करें और गांव में जितनी चौजों की जरूरत हो उनके मुताल्लिक वे इन्तजाम करे और अपने गांवों की जरूरियात को पूरा करें। असल में तो मिल्कियत गांव-समाज की होगी। यह हमारे देश का पुराना दस्तूर चला आया है, जिसको विदेशी हुक्मत के जमाने में बहुत ही क्षति पहुँची थी और क्षति ही नहीं बल्कि वह नेस्तोनाबूद ही कर दिया गया था कि हमारे गांव का समाज खुद ही सब अपने इन्तजामात करता था। इसको हम फिर से जीवित करना चाहते हैं ताकि हमारे गांव की एक रिपब्लिक हो और वह फिर से क़ायम हो करके अपने गांव का प्रबन्ध करे। इस तरह से इस बिल में सब बातों का इन्तजाम किया गया है।

इस बिल में हंमने कोआपरिटव फार्मिंग का भी इन्तजाम किया है जिसकी वजह से कोआपरेटिव फार्मिग जल्दी शुरू करने में काफी मदद मिले।

हमने कंसोलिडेशन (चकवन्दी) का भी इन्तजाम रलाह ताकि होल्डिंग्ज के कंसोलि-डेशन का भी प्रबन्ध ठीक और माकूल तरीक़े से हो सके।

इस तरह से संक्षेप में में यह कहना चाहता हूँ कि अगर ग़ौर से इस बिल को देखा जाय तो इससे बेहतर बिल इस मौजूदा हालत में नामुमिकन था। हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां भी रह गई हों। यदि आइन्दा इस भवन के सदस्य कृषा करके कुछ ऐसी बातें बतावेंगे तो उनको रफा करने की कोशिश की जावेगी। लेकिन जहां तक मौजूदा शक्ल इस बिल की है वह इस क़ाबिल है कि उसकी हर तरह से दाद दी जानी चाहिये। में प्राथना करता हूँ कि यह ऐवान इस पर विचार करके इसे स्वीकार करेगा।

इन चन्द शब्दों के साथ में चाहता हूँ कि इस बिल पर विचार किया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा जमाने में जो जमीन का क़ानून चल रहा है। उसके मुताबिक तो जमीन में काश्त करने वालो, जमीन में खेती करके ग़ल्ला पैदा करने वाला जमीन का मालिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा वर्ग मालिक है जो जमीदार के नाम से कहा जाता है और वह जमींदार तबका सरकार और किसान के दरिमयान का . . है। किसान जो अपनी मेहनत और मशक्कत से जमीन को हमवार बनाता है, जमीन को जरखेज बनाता है और गल्ला पैदा करता है तो सबसे बड़ी बात जो मौजुदा बिल हमारे माननीय माल सचिव ने उपस्थित किया है और में कांग्रेस गवर्नमेंट की बधाई देता है कि उसमें इस वसूल को मान लिया गया है कि जो जमीन जोतता है वही जमीन का मालिक ह यानी जो जमीन की काश्त करता है वह ही जमीन का मालिक है। इससे दो बड़ी बातें होती हैं। पहली बात तो यह है कि जिसकी जमीन होती है, वह जो पैदा करता है उसकी पूरे अख्तियारात होते हैं। इसलिये वह जमीन की क़ीमत बढ़ाता है, उसके जरखेजपन को बढ़ाता है। उसको भी फायदा होता है और मुल्क को भी फायदा होता है, क्योंकि उसके पास भी ज्यादा ग़ल्ला आता है और मुल्क को भी ज्यादा गल्ला मिलता है। अगर किसान समझता है कि जमीन तो दूसरे की है वह तो सिर्फ मेहनत तथा मशक्कत करके गल्ला पैदा करनेवाला है तो ऐसी सूरत में न तो उसको जमीन से उन्सियत होती है और न मुहब्बत होती ह क्योंकि उसे खतरा बना रहता है कि उसके हाथ से जमीन निकल जा सकती हैं। सब से बड़े उसूल की बात जो सामने हैं वह यह है कि जमीन का वही मालिक होगा जो जमीन जोतता है और गल्ला पैदा करता है और यह इंसाफ की भी बात है। जमीन किसी एक शख्स की बनाई हुई नहीं है और न किसी एक शख्स ने जमीन की एक इंच भी पैदा करने में कोई क्राबलियत दिखाई है। वह तो एक चीज है ईश्वर की हवा-पानी की तरह है, जो जमीन की काइत नहीं करता, उसकी किसी किस्म का हक मालिकाना गलत उसूल था। वह कैसे इतने दिनों तक कायम रहा, यही आक्वर्य की बात है। आज जो हमारे जमींदार साहबान है वह ग़लत उसूल की बुनियाद पर अपने आपको जमीन का मालिक समझते चले आये.थे, असल में वह जमीन के किसी भी सूरत में मालिक नहीं थे। हमने इस बिल में इस चीज को भी देखा है कि कोई मुलालिफत जमींदार साहबान की नही। जमींदार जो खेत जोतता है वह भी मालिक होगा, लेकिन सरकार और किसान के बीच वाली बात जो गलत उसूल पर मबनी थी उसके बारे में खुशी के साथ कहना पड़ता है कि आज हम सैकड़ों वर्ष के गन्दे तरीक़े को खत्म करने जा रहे हैं और आज वही जमीन का मालिक है जो उस जमीन को मेहनत तथा मशक्कत से जोतता है और उसकी पैदावार बढ़ाता है।

दूसरी बात जो इस बिल के अन्दर खास है वह यह है कि हालांकि जमींदार तबका यों तो जमीन का किसी सूरत से भी मालिक नहीं है, लेकिन क़ानून ने उसको एक अख्तियार दिया था। क़ानन की वर्जह से वह अपने आपको जमीन का मालिक समझता था और मैं उनको किसी तरीक़े से गुनहगार नहीं ठहराता। क्योंकि एक चीज चली आती है आदतन, और क़ानून इजाजत देता है, इसलिये वह भी अपने को मालिक समझने लगे। ्थी द्वारिका प्रमाद मौर्य]

चुनांचे हम देखने हं कि उनकी गुजर-आकात का भी मुनासिब तरीक़े पर इन्तजाम किया गया है क्योंकि उनकी मृगसिब तरीक़े पर मुआविजा दिया जा रहा है और जो छोटे तबक़े के जमींदार है उनकी भी सुन्दर व्यवस्था की गई है, उनका भी गुजर औकात का जरिया रखा गया है। इसलिए कि क़ानूनन उनको एक हक मिला था और आज क़ानून के ही उरिये ने हम उम हक को उनसे ले रहे हैं। साथ ही हम उनको क़ानूनी तरीक़े पर कुछ देना भी चाहते हैं। इसके अलावा क़ानूनी तरीक़े पर किसानों के हुकूक को भी मंजबूत बनाये देते हैं, जो क़ानूनी हक मिला था उसे क़ानूनी तरीक़े पर लिया गया और क्रानूनी तरीक़े पर ही उन चर्मीदारों की कुछ दिया भी गया, तो ऐसी सूरत में जो एक क्यवस्था इस बिल के अन्दर है, आज जो जमींदारी खत्म करने का सिलसिला दिया जा रहा है, उसमें पुनर्वासन और मुआविजा भी है। यह इस बिल की एक खास अहमियत है और जिस पर मुमकिन है कुछ साहबान इस्तिलाफात पेश करें, लेकिन एक उसूल की चीज है और इस उसूल से कोई इन्कार नहीं कर सकता। साथ ही जमींदारों का भी ख्याल रखा गया है, उनके साथ सरकार की पूरी हमददी है, पूरे तौर पर वह इस मुल्क के बाशिन्दे हैं और उनका भी हर एक के समीन रहने का अधिकार है। गांव-समाज बनेगा, उसमें चाहे जमींदार हों, चाहे किसान हों, हर एक के बराबरी के हुकूक रहेंगे और किसी क्रिस्म का तफकी नहीं रह जायेगा और न किसी क़िस्म का भेद-भाव ही रहेगा। यह भी इस बिल की एक खाम अहमियत है। हर एक जो जमीन जोतता है वह भूमिधर होगा और हर एक की बराबरी के दर्जे की हैसियत हो जायेगी। में तो इसे बखूबी समझता है कि किसानों और जमींदारों के बीच एक खाई बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अब बराबर की हैसियत होने में उनमें मोह बत होगी, उनमें इखलाक होगा और गांव की व्यवस्था सन्दर होगी।

एक खास अहमियत और जो इस बिल में है वह यह कि उनको मुआविजा देने के लिये अर्थात् पुनर्वासनं अनुदान देने के लिये हमने इसमें जो व्यवस्था रखी है इस देश की तवारीख में उस व्यवस्था का कोई सानी नहीं है; उसके मुक्राबिल की कोई स्कीम आज तक नहीं सोची गयी है। अपनी जगह पर वह एक गैर मिसाल चीज है। आज हम किनानों से कहते हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी अदा करो, सरकार का साथ दो और उसके लिये आगे बढ़ो। इस जमींदारी को अपनी चीज समझ लो कि यह हमारी मिल्कियत है, गांव-समाज की मिल्कियत है। जैसे भी हो इसके लिये तुम कुछ वो। ऐसा भी नहीं है कि वह अलग से देंगे बल्कि वह तो उस लगान का जिसकी वह आज तक बराबर अदा करते चले आ रहे हैं उसका एक जुज है जिसको उन्हें पहले अदा करना है। पहिले अदा करने के बदले में उन किसानों को ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा पहुँचता है। सबसे बड़ा फायदा यह पहुँचता है कि उनका लगान ४० साल के लिए आधा हो जाता है और दूसरा फायदा यह है कि वह अपनी जमीन के मालिक हो जाते हैं। साथ ही जमींदारों को कैश पैमेंट (नक़द अदायगी) करने से जो एक सवाल मुआविजा देने का है वह हल हो जाता ह। अगर आज वह १० गुना लगान नहीं देते हैं और जमींदारों को मुआविजा बांड की सकल में दिया जाता है तो उसका यह मतलब होता है कि काश्तकार लगान पूरा देते चलें और उस लगान में से जमींदार साहबान को थोड़ा–थोड़ा करके किस्त की शक्ल में वह मुआविजा अदा किया जाए। किसानों को कोई जाहिरा फायदा इससे नहीं होता। यदि बांड की शक्ल में लगान से मुआविजा दिया जाय तो जो भूमिघरी का अधिकार दिया जा रहा है, उनका यह हक हासिल करने का सवाल एक अलग सी चीज हो जाती है। जमींदारों को मुआविजा भी मिलना चाहिये और नक़द मिलना चाहिये और जमींदारों और काश्तकारों का सम्बन्ध भी हमेशा के लिये खत्म हो जाय, साथ ही साथ इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में की गयी है। किसान यह समझे कि हमने अपनी कमाई से जमींदारी खत्म करने के लिये रुपया दिया और जमींदारी खत्म करने में हमने

भी हिस्सा लिया। गवर्नमेट का जो हिस्सा रहा वह तो अलग सी चीज है। किसानों को एक बल मिले कि हमने जमीं दारी जत्म की और उनके बाल—बच्चे भी कहें कि हमारे बाप—दादा ने जमीं दारी को खत्म किया था। यह एक बहुत बड़े उसूल की बात है। इसमें काश्तकार को बल मिलता है। मैं तो यह कहूँगा कि इस तरह से जो दिया जा रहा है और जिस स्कीम के साथ दिया जा रहा है इसमें अच्छा तरीक़ा मौजूदा हालत में कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ किसानों को लगान में सहू लियत भी दी जा रही है। इस उसूल की हिफाजत के साथ, और किसानों के हक़ को देखते हुंए मुआविजा अदा करने का इससे अच्छा तरीक़ा नहीं हो सकता।

इसके अतिरिक्त इस बिल में जो खास व्यवस्था है वह कोआपरेटिव फार्मिंग की है। कोआपरेटिव फार्मिंग (सहकारों खेती) के बारे में भूमि और खेती के बड़े—बड़े जानकारों का विचार है कि इससे पैदावार बढ़ती है। इसके लिये भी काफी सहूलियतें इस बिल के अन्दर दी गयो है। कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये इसमें काफी प्रोत्साहन दिया गया है, जिसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में किसी को इनकार नहीं हो सकता।

दूसरे इन्तजाम किया जाय । वे तमाम जिन्दगी ऐसी खेती में लगे रहें जहां से उनका गुजर न हो सकता हो और उनके लिये अगर दूसरा कोई जरिया भी न हो तो वह चीज तो ज्यादा दिन नहीं चल सकती। खेती के इतेने ज्यादा दुकड़े होना मनासिब भी नहीं है। अगर हिसाब लगाया जाय कि जितनी खेती है और जितने किसान है उन सबमें बांट दिया जाय तो फिर फी किसान पर बहुत कम जमीन पड़ती है और अगर हम इस पर भीर

करें तो पता चलेगा कि यह होत्डिंग को बांट-बांट करके जो खेती करने का तरीक़ा है इससे किसानों की हालत बहुत खराब है।

हरे वरः

एक चीज जो खासतौर पर तवज्जह करने की है वह यह है कि जमीनों के बहुत छोटे-छोटे टुकड़े जो है वे बहुत फासले पर है और दूर—दूर पर टुकड़े होने की वजह से न तो उनकी आबपाशो ठीक होती है, न ठीक से रखवाली हो सकती है और न वे उतनी पदावार कर सकते हैं जितनी टुकड़े न होकर सब खेती, सब जमीन एक जगह होने से हो सकती थी। तो ऐसी सूरत में मझे इस तरफ खास तवज्जह आप लोगों को दिलानी है। मैं अपनी जानकारी से गांवों में देखता हूँ कि किसानों के ट्कड़े दूर—दूर होने की वजह से एक विन एक खेत में आवपाशी करता है तो दूसरे दिन दूसरे खेत में जाकर हल बैल ले जाता है। हमारे यहां कुएं से आबपाशी होती है। में देखता हूँ कि किसान को यहां से यहां करने में सारा समय लगा देना पड़ता है। इसलिये इस चीज

[श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य] की तरफ वहुन तवज्जह की जहरत है। जिस सूरत से भी हो सब चीजें एक जगह हों और जल्दी मे जल्दी हों तो मुझे पुरा यकीन है कि गहले की पैदाबार में काफी बढ़ती हो जाय।

में जो दाम तौर पर इस बिल की एक चीज की तरफ इस भवन की तवज्जह दिलाना चाहता हूँ वह एक क्लास जो लंडलेंस लेडरर्स का है उसकी तरफ लंडलेन लेबरर्स वह क्लास है जो खेती में ही अपनी मशक्कत को लगाता है, लेकिन उसके लिये जो व्यवस्था इस बिल में की गई है वह मेरी निगाह में मुनासिब नहीं है। इस क़ानन की व्यवस्था में कोई भी शिकमी पर खेत किसी को उठा नहीं सकता। अब तक जो रिवोज या आम तरीक़े पर लोग शिकमी को उठा दिया करते थे, लेकिन अब तो यह चीज नहीं रही और इस चीज के खत्म हो जाने के बाद ऐसे बहुत से लैडलेस लेबरर बलास के हैं जिनको जमीन शिकमी पर मिलती थी और काश्तकारी करते थे लेकिन अब उनको कोई क्रिकमी नहीं देगा तो वे जिनके पास जमीन रहेगी उससे महरूम हो जायेगे। कोई यह चीज प्रान्द नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में जब जमीन को न काश्नकार उठा सकता है किसी शिकमी को और न लंडलेस लेडरर के लिये कोई व्यवस्था है मुझे उनकी किस्मत पर जरूर एतराज पैदा होता ह। जो जमीन खाली हो और बहुत सी जमीन ऐसी है भी, इस क़ानून के मुताबिक ऐसी बहुत सी है भी, जो लोग खुद कारत नहीं करेंगे उनकी जमीन भी खाली होगी तो किसी न किसी सूरत से जो जमीन खाली हो उनकी व्यवस्था का हक गांव-सभा को सुपूर्व होना चाहिये कि वह किसी दूसरे को कोआपरेटिव फार्मिंग वालों को दिया जायं या जिनके पास जमीन उनके गुजर-औकात के लिये कम है उनकी जमीन को पूरा करने के लिये दी जाय और आख़िर ' में लैडलेस लेबरर को दी जाय तो भेरा ऐसा अंदाजा है कि लैडलेस लेबरर को एक इंच जमीन बच कर आने वाली नहीं है क्यों कि जो बेकेट (खाली) लैंड (जमीन) होशी वह तो होल्डिंग को पूरा करने भर को नहीं होगी। जो मौजूदा होल्डिंग द। एकड से कम है उनको पूरा करने में वह सब खम हो जायगी, इसिलये लैंडलैस लेबरर को रखें या न रक्लें, सब बेकार है। मेरे विचार से लंडलेस लेबरर या जो लंडलेस काइतवार है, उसका यह हक है कि जो खाली जमीन है वह उनको दी जाय। यह तो मानी हुई षात है कि जमीन को वही तोड़ेगा, वही उसको ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिये इस कार्बिल बनायेंगा कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। में फिर कहता हूँ कि इतना जरूर किया जाय कि जो वेकेन्ट लैंड है वह लेंडलस लेंबरर को दी जाय।

दूसरी बात यह है कि मूलतः इस बिँल में एक प्राविजन, दफा २२४, यह रक्खा गया या कि ६। एकड़ जमीन एकोनामिक होल्डिंग हैं। अगर वह ६। एकड़ जमीन किसी काइतकार के पास अपने क॰ जो में नहीं है और उसने ज्ञिकमी में उठा रक्खी है तो वह बेदखली द्वारा ६। एकड़ पूरा कर सकता है। अब जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें वह ६। एकड़ के बजाय ८ एकड़ कर दिया गया है। में मुनासिब समझता हूँ कि वह ८ एकड़ किसी भी सूरत से नहों। जब हमने ६। एकड़ का मियार क्रायम कर लिया है तो फिर ८ एकड़ के रखने के कोई मानी नहीं है। ६। एकड़ एक ऐसा है जो एकोनामिक होल्डिंग मानी गई है। यह दूसरी बात है कि बुंदेलखंड या दूसरे स्थानों के लिये और तरीक़े पर गौर कर लिया जाय। यह एक्सेपशनल केस हैं, लेकिन आम तरीक़े पर ६। एकड़ के बजाय ८ एकड़ का करना में मुनासिब नहीं समझता। में समझता हूँ कि जो ६। एकड़ पहले था वही मुनासिब है और इसीलिये मैंने इससे अपनी रायका इत्तिफाक भी किया है।

एक चीज और क़ाबिले ग़ौर है कि आज बहुत से किसान ऐसे है जो कि काइत कर रहे है लेकिन उनके नाम काग्रज शिकमी पर दर्ज नहीं है और लोग भी इसकी जानकारी रखते हे और मैं भी अपनी जानकारी से जनता हूँ कि जमीदारों ने शिकसी दिया है, किसानों ने शिकमी दिया है लेकिन कागजात में शिकमी दर्ज नहीं है। अब फैसला यह करना है कि कौन काबिज है और कौन नहीं है। अदालतों में यह होता है कि पटवारी के कागजात को बहुन ज्यादा अहिमयत दी जाती है। में मानता हूँ कि अदालत के कोर्टस् के लिमीटेशंस है, कोर्ट डाक् मेंटरी एवीडेस को मानता है। उनके मामने और दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसिलये पटवारी के काग्रजात को ही एक डिसाइ— डिंग फैक्टर बना लिया जाता है। लेकिन इंसाफ तो यह है कि वाकयात को टेखे। यह न हो कि वाकया कुछ और हो लेकिन जो पटवारी ने दर्ज कर लिया है उसी को माना जाय।

इस दिक्कत का हल निकलना चाहिये। इस दिक्कत का ऐसा कोई हल सोचना है कि जो सही काबिज है उनको वह जमीन मिल जाये। इसके लिये कोई लैंड रिकार्ड आफितर या कोई जिलेवार आफिसर या कोई एक कमेटी हो जिसमें नान-आफीशियल मेम्बर हों उसमे चाहे एम० एल० एज० हों या और कोई हों, उन लोगों की सोचकर कोई कमेटी बनाई जाय जो इस चीज को तय करें। इसकी वजह से काफी दिक्कत काश्तकारों को हो रही है। बहुत से काश्तकार जमीनों से महरूम किये जा रहे है, बहुत सी जमीनें छीनी जा चुकी है और छीनी जा रही हैं और वे फोजदारी मुक्रदेमा भी नहीं चला सकते। दफा १४५ में भी हार जाते हैं। सबत जिस तरह से देखा जाता हैं उसकी बुनियाद पर १४५ में भी किसाँग मुकदमा हार जाता है लेकिन मौके पर वही काबिज चला आता है ओर बीस बरस से फाविज है। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेट पर है कि मोक्रे पर जो किसान काबिज है उनको सही हक वह दिलाये। गैवर्नमेंट के मुलाजिमीन जो पटवारी है उन्होंने सही तौर पर, इंसाफन वहां दर्ज नहीं किया है और जिसकी वजह से ग़लत फैसले हो जाते हैं, उसके लिये गवर्नमेंट को कोई इन्तजाम जरूर करना चाहिये कि वह किसानों के हाथों मे से ऐसी जमीन न जाने दें। मैं यह नहीं कह रहा है कि ऐसा किसी जोर-जुल्म और किसी अंदालत के गलत फैसले की वजह से हो रहा है। लेकिन बात यह है कि अदालत लिखे सबूत पर जाती है और ग़रीब किसान उसके खिलाफ अदालत में किसी भी तरह से सब्ते नहीं दे सकता है। न तो वह काग़जात की बिना पर ही जीत सकता है और न पैसे की वजह से ही जीत सकता है। इसलिये ऐसी हालत में किसान को सिर्फ जमीन छोड़कर भाग जाने के सियाय और कोई चारानहीं है। मेरा कहना यह है कि इस कान्न से सही मानों में किसानों को लाभ पहुँचना चाहिये। और किसी न किसी तरीक़े से उसके बारे में हमें सोचना चाहिये। उसको सही तौर से कब्जा मिलना चाहिये क्योंकि आज तक उसका कब्जा उस पर मौजूद है और वही जमीन का सही मालिक भी है।

एक खास बात की तरफ में श्रीमान् जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूँ कि एक उसूल इस बिल में यह भी रखा गया है, कि जो शिकमी काश्तकार हैं और जमीत के मालिक दोनों है, तो उनका नाम अधिवासी देनेन्द रखा गया है जो ५ साल बाद १५ गुना देने के बाद उसके मालिक हो सकेंगे। इस उसूल को जब हमने मान लिया है कि जमीन का जोतने वाला ही जमीन का मालिक होगा तो फिर ऐसा क्यों कि कुछ को १० गुना अभी देने पर भूमिभारी हक मिल जावे और कुछ को ५ साल तक इन्तजार करना पड़े। जब हमने उसकी मालिक मान लिया तो इस सवाल को कितने दिनों के लिये क्यों टाला जा रहा है ? अगर वे मालिक हैं तो आज ही उनको भी भूमिभारी बनने का मौका दिया जाना चाड़िये। उनको ५ बरस तक रोके रखना उसूलन ठीक नहीं हैं। आज तो किसानों के पास थोड़ा सा रुपया है और उसका सबूत भी है। अब जबिक उनके पास फसल भी है, ईख की फसल हुई है आलू की फसल हुई है और जबिक उन्होंने जोश के साथ रुपया जमा करना शुरू किया है, तब क्यों नहीं उनको यह हक दिया जा रहा है। किसी भी

[श्री द्वारिका प्रनाद मौर्य]

चीज का एक वक्न हुआ करता है। आज जो शिकमी काश्तकार है जिनके पास गपया है कीन जानता है कि उनके पास ५ वरस बाद पैसा न हो। मान लिया जाय कि बच्चों के खाने भर को भी न हो तब कौन आपका रापया जमा करेगा। मुझे उम्मीद है और होना चाहिये हरएक इंसान को कि आज जो हमारी गल्ले की हालत हैं वह बहुत जल्द मुंबरेगी और गल्ले की पैदाबार बढ़ेगी और गल्ले का भाव लाजिमी तौर पर घटेगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि ५ वर्ष में मुल्क की हालत बदल जानेगी और उन वक्त किमान के लिय १५ गुना लगान जमा करना ' ५० गुना के बराबर हो नकना है। इसलिये मैं गुजारिश कंख्गा कि उस अधिवासी को जो शिकमी काइत करना है उनको भी फौरन १५ गुना लगान जमा करने का मौक़ा मिलना चाहिये ताकि वह भी अपनी जगह पर मुस्तिकल काश्तकार हो जाय और वह यह न सोच सके कि ५ वर्ष के बाद हमारा नम्बर आयेगा और उस वक्त पता नहीं कि हम रहेगे या नहीं रहेंगे। आज हन यह चाहते हैं कि जो लोग जमीन जोतते हैं चाहे वह असली काक्त कार हों चाहे जिकमी काक्तकार हों भाई-चारे की तरह से भूमिधर होकर गांव में समाज बनायें। अब बीच में कोई तबका एक मिनट के लिये नहीं रहना चाहिये। क्रान्न जिस दिन बने और लैंड रिफार्म जिस दिन अमल में आवे उसी दिन वह मुकम्मल तोर से अमल में आवे और हर इंसान जो काश्त करता है अपनी जमीन का भूमिधर हो जाय। यह हमारा नुक्ते-निगाह होना चाहिये और इसीलिये में इस ऐवान का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता है।

इस बात के लिये कि इस क्रांतन के जिरये से जो हमदर्शी किसानों के माथ दिखाई गई हैं जिसने किसानों की हैं सियत ऊंची हो रही हैं में उसके लिये सरकार को बधाई देता है। आज किसान सोचने लगा है कि हम भी एक इंसान है और हमारा भी एक दर्जा है। आज तक जमींदारों के नीचे वह गुलामी की जिन्दगी गुजार रहा था लेकिन अब उसकी उससे छुटकारा मिल रहा है। आज उसके दिल में बात पैदा हो गई है। आज देहात में एक जीवन आ गया है। जो पपया जमा करने की बात है उस संबंध में भी आज किसानों में एक उमंग है। वह इस बात को समझ रहा है कि बहुत जल्द उसको नजात मिलेगी और वह भी फछा के साथ बराबर दर्जे पर भूमिधर बन कर जिन्दगी बसर करेगा। इसिलये में किसानों की तरफ से सरकार को बधाई देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह ऐवान इस बिल का पूर्ण रूप से स्वागत करेगा और किसानों के आशीर्वाद का भागी होगा जो उसल हम बहुत दिनों से कहते आये हैं आज वह उसल नुमायां हो रहे हैं। इन उसूलों को लेकर हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमने एक ऐसा क़दम रक्खा है इस सुशा में, जिसका मुझाबिला कहीं नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि ऐवान का हर एक मेम्बर इस बिल का स्वागत करेगा और हमें आशा है कि किसानों के और अच्छे दिन आयेंगे।

*श्री निहालुद्दीन—हुजूरवाला, जमींवारी के मुताल्लिक अभी तक जितनी गुफ्तग् हुई और जो लिखा जा चुका है वह मेरे नजदीक मसला करीब—करीब ऐसा है कि जिसमें किसी मुल्क के हिस्से में कोई इस्तलाफ का मौक़ा नहीं ह। उम्मीद यह की जाती भी कि सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बिल जाने के बाद वह सब खामियां और कमजोरियां जी कि इब्तबाई बिल में थीं, दूर हो जायंगी। बिल दो हिस्पे में था— अध्वल यह हिस्सा जो कि जमींवारी खत्म करन के मुताल्लिक है, दूसरा वह हिस्सा जो आइन्दा शक्ल व सूरत काक्त तारों को भूभिधर व असामी व उन हक्क, फरायज और जिम्मेदारी के मुताल्लिक है। बिल में हक़ीक़तन दो हिस्से थे—एक तो यह कि जो आज भी है, एक वह जो कि मस्तिकल और दवामी ह। वह लोग जो कानन बनाने के माहिरहैं

वह इसको बहुत अच्छो तरह के जानच कि वह नानून वे जिनके मियार बुटतिलफ है वह कुछ हैसे हं कि कुछ मुद्दा ने बाद बहु में कार, लाजमल हो जाने हे और कुछ हिस्से कानून के दवामी होते हैं। इनको जलग—अलग होना चाहिने था। गुरतसरन यह कि बिल को स्रत गन भिन्ते की तरह हो गमी हा। मगर होते को अलग—अलग होना चाहिने था ए तो बहु जो जमोदारी वो सत्म कर ते के सिलिसिल में हैं और दूसरा वह जो मुस्तिक हे तूक त्या कर ने के मुतालिल है है अर हमें उम्मीद मि चे के स्तान की मुस्तिक है है जिन होते जो वे हि के स्तान की नित्ति से इन कमी को महस्स करके बिल को दो दुक्ता में से एं जान के सामने कि करेगे। यह हिस्सा जो बिल वा है वह मेरे नक्षिण मानूकत बिल , भार इससे यह मानूम होगा है दि उन लोगो को जिन्हों। इस पर इनचा बक्न बाया किया और इतनी महनत की इब्नदायन लेजिस्लेजन के बारे में नावाक कियत है या अगर नावाक कियत की वो जन्हों अपनी जानकारी को ठीक तोर में इस्तेगाल कर ने की की की का की का लोगों को जाती थी।

माही रस इप्ल हे प्रानित कि नभागरी बत्य करने पर मुआविजा लिया जाय तो कि पर से पिन गा लोग पन परो पता को जान, इसके मुल्लिक मुख्नलिफ रापे नहा हो कता। गुर किए उपल भी निनाधर देला भागनी जगीदारी की अभी ही लए हो नाना चाहि।, इसने जिन्ही जल्दो की आप वह ठीक ही है। सास तोर पर ये इन्या जा गर्हि [अधियों की गरूरत गर्भा ५३ एक उस्लें अंश्सही उसल । अर अगर इस ८म्७ को नाभा जाथ भेष सबसे पण्या आरमी होऊगा कि दिसकी ताईद करणा कि बिटा किसी पुजावित्र के जमीदारी सारा की जाय। मगर अगर आप इा और पुनाचिता देता तो इसमें कोई सवाल नहीं तीना उमार पर जा ५ न । नारों वाहिये कि बरे आदमी को मुड़ी भर क्या. । जान, उससे लोटे की मुद्ठी भर णायद दिया जाय और उससे छोड़ भी उससे भी पुड्ठो भर जाएट दिया जाय। यह फोर्ड उसूल नहीं रा लड एक्बीजियन के पुराहित्के मुशाबिया देना कवायद की ह से जाँदन माना जाता ै। अगर आप जमादारी को छो न तो उमके मृताबिक आगको पुरातिजा देना नादिये। नामल अब यह रहा कि मुआविजा कहा से दिया जारोगा। या जो ए। पुकार । कि दल गुना रपया जमा किया जे, , इसकी कोई जरूत नहीं । गुन्द की लाग अब इननी है लिहाी कैविस्त हमारे यहा इतना है कि कर्ज लेकर जमादा को दिया जा सकता है। म िसी को गाविजा देने की ताईद के लिने नर्राया पुत्राती। जेगा कि भेगे अपनी उब्दायन तकरीर में कहाथा। अगर गुल्ककी हुतूमा को जाम गकाद के लिये यह जरूरी है कि बिश मुणविजे जमीदारी खत्म की जाय तो ल्लारी आप कर सकते ।। अगर जाग नुआविजा देते हु तो आपको बाइतकरो की जेने ट्टोजने की जरूरत नहीं,। यह बार तभी वह आदमी भहसूस कर सकता है जो जो ना ै कि उसकी आर जिला मुआविजा है तक दे दे। परना यह रारमा दिशी एक किस्म दी ।रपररती दें कि उन्हीं जीगों को हक्क मिले जो १० गुना अवना लगान सरकार के यहा तमा कर में; जो लोग इसी लरह से मुक्त की दोजत में इजाका करते हैं जैसा कि सरमागेदार करता है। अगर जाके पास १० गुना लगान देने की नहीं है तो आप क्यों उसको हमूक से महरूम करते ह ? आप अगर जिला किसी बनियादी उसूल के उनको हक्क देते हैं ती तमाम काइतकारों को यह हकूक दिये जापं जो १० गुना लगान दे सकता है या नहीं दे पकता है। आप कर्ज ले सकते हैं और उस कर्जों की अनामगी बडी आयानी के भाग उस आमदनी से की जा सकती है जो कि जागीरदारों के पास से आपके पान आर्रेगो। इन अन्हाज के साथ में इस स्पिटि पर जो आज हमारे सामने रखी गई है अपनी रापका उजहार करना हं ओर उन जोगो की खिदमन के िन हमदर्दी जाहिर करता है जिन्होने इस रिपोर्न तो लिखा। मुप्ते उम्मीव है कि मुस्तरकी गौर के बाद वह लाभिया दूर हो जागगी जिनकी तरफ मैंने इशारा किया है।

श्री साजिद् हुसै ।--जनाब डिप्टी स्वीकर साहब! सेलेक्ट कपेटी की अंग्रेजी की कापी मुझे अभी लंब के बाद मिली। मगर जो कुछ भी मुझे अन्दाजा हुआ उससे यह मालूम हुआ कि जिस बात की उम्मेद की जाती थी, जिस बाद पर दावा किया जाता था वह सब जबानी ही रह गथा। मतलब यह था कि जनींदारी खत्म करके हम एक ऐसी सूरत पेश करें, एक ऐ ने सूरत पैदा करें कि मुल्क के अन्दर ज्यादा गल्ला पैदा हो। मुल्क के काश्तकार ओर मुल्क की जनता मालदार हो जाय। उनका रहन-सहन का जो स्टैंडर्ड है वह बढ़ जाय। जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है अगर ऐसा होता तो में कम से कम एक ऐसा शहस था जो कि बावजूद किसी जाती नुकसान के इसकी ताईद करता अगर महत्र मक्त सद वोटों से या तो इसके मुताल्ठिक में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता। कहा यह गर्या कि पैदावार इससे बढ़ेगी। अब आप दे बें कि पैदावार कैसे बढ़ जायगी। को हक दिया गया है कि वह अपनी होल्डिंग जिस तरह से चाहे इस्तेमाल कर ले। वह चाहे तो उसको लाली मैदान कर दे, उस जगह पर चाहे तो वह कारलाने बना लेबे या कुछ भी करे या न करे। इससे मन्क की पैदाबार कैसे बढ़ जायगी। यह बात समझ में नहीं आई यह भी कहा गया कि हम सवा छः एकड़ या आठ एकड़ जो भी एक भियार है, जो भी इ कोनामिक होल्डिंग कही जाती है उसके लिये भूमिषर को यह भी हक है कि वह उसने कन भी कर तकता है तो इनसे पैदाबार कैसे बढ़ जायगी ओर उन लोगों के मुता-हिलक जहां तक कि छोटे जमींदारों का ताल्लुक है उनकी तादाद इतनी है कि जैसा अभी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने कहा कि उनको भी काइतकार ही समझना चाहिए। हैं तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है ? करीब-करीब आठ लाख एकड़ जो उन को सीर की जमीन उठी हुई है उससे भी उनको हाथ घोना पड़ेगा। शिकमी पर दिए हैं वह भी उनको वापिस न होगी। इसके अलावा आप देखें कि आप उनकी हालन को मुआविजा देकर किस तरह से दुरुस्त कर सकते है। जब आप उनका शुमार भी जनता और अवाम में ही करते हैं तो फिर तो उनके साथ भी कोई खास रिआयत का बर्ताव क्यों नहीं करते या इन्साफ क्यों नहीं करते ? इसको तरजीह दी गई है कि शिकमी खुदकाश्त करें। आप यह देखें कि यह ज्यादा बेहतर समझा गया है कि वह लन्डलेस लेबरर को एम्पलाय करें और उनसे काम लें बहैसियत मजदूर के उन को एम्पलाय करें, आप देखें कि उसको क्या मुनाफा होता है और सबटोनेन्ट (शिकनो काश्तकार) को क्या होता है। आप देखें कि आजकल मजदूर को कितनी रकम कम मिलती है और उसकी नकद लगान से उस सूरत में कितना फ़ायदा होता है। आपने इस बात का कोई लिहाज नहीं किया है और जल्दी में यह तमाम काम आप कर रहे हैं। बड़े जमींदारों की यह हालत है कि वह लोग काफी तादाद में मककज है एग्रीकल्च-रल इन्कम-दैक्स देने के बाद आज उन को अपनी जायदाद फरोख्त करने की जरूरत हो रही ह।

एक साहब ने मिल्कियत की बात कही कि यह कोई अच्छी चीज नहीं है और यह न रहनी चाहिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, यह बात उसके मुंह से तो नहीं निलक्षनी चाहिए क्योंकि आज उनकी गवर्नमेंट तो कैपटिलिस्टों (पूंजीपितयों) के कदमों पर गिर रही है कि आप अपना रुपया मुक्क की इन्डस्ट्री में लगाइए। किसी दूसरी पार्टी के लोग अगर ऐसा कहें तो किसी कदर मुनासिब होता लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले मिल्कियत के बारे में ऐसा कहें यह जरा समझ में नहीं आता।

जहां तक सोशलाइ जेशन और नेशनेलाइ जेशन का ताल्लु क है मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि एक तरफ तो आप नेशनेलाइ जेशन करते हैं और दूसरी तरफ बहुत ही सख्त किस्म की सर—माएदारी के आप हामी है। यह चीज हमारी समझ में नहीं आती। मैं यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका की तारीफ करता हूं कि उन्होंनें साफ कह दिया है कि हमारा सरमाएदार मुल्क है और हम कैपिटलिज्म को ही अच्छा समझते हैं और वह अच्छा है या गलत लेकिन वह लोग उसी पर कायम है। मगर हमारे मुल्क की इ होनामी क्या है यह समझ में नहीं आता। एक तरफ

आप सोशलाइजेशन के तरी के से काम लेते हैं और दूसरी तरफ आप के सामने यह सवाल है कि कैंपिटलिज्म को कैंसे बचावें। यह चीज आप की हमारी समझ में नहीं आती कि आप चाहते क्या है? एक अजीब कनफ्यूजन (गडबड़) है और कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इस मुल्क का बेडा पार होगा और हमारी सरकार जल्दी में इस तरह के काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं और बाद में भी उसे कोई कामयाबी दिखाई नहीं देती।

हमको इंतहाई खुशी है और इस तजवीज से खुश होना चाहिए कि यहां की जनता मालदार हो जाय । यहां के लोग अच्छी हालत में हो मगर हम तो देखते हैं कि माल तो चन्द आदिमयों के ह्रार्थें में जमा होता चला जा रहा है ।आम तरो हे से ख्वाह काश्तकार हो जमींदार हो उन लोगों के पास से रुपया रोजबरोज खींचता चला जाता है। यह रुपया कहां जा रहा है यह राज की बात नहीं है। यह हमारी आंखों के सामने की बातें हैं कि किथर जा रहा ह। जब तक इसका इंतजाम न हो या कोई गवर्नमेंट इसका इंतजाम न करे या उसमें इतनी ताकत न हो कि वह जिन लोगों को डिसप्लेस करें जिन की रोजी निकाल लें उसका भी कोई इंतजाम करें। मेरे ख्याल में तो मेरे सामने कोई बात नहीं आई । मुनासिब नहीं है सरकार के लिये इस तरीक से वह करे । क्या उनके प्रकृक काइतकारों को दे दिये। किस तरह का अमल किया गया। वह लगान आज देते हैं लगान कल भी देंगे । क्या वह लगान से बच गए यह बात समझ में नहीं आई । हां कुछ रुपया दे दिया सभि झिये उसके सूद से उनका लगान दे दिया। दूसरी जगह उसी रुपये का उसी देहात में कितना ज्यादा सुद मिलेगा। फिर असल कहीं नहीं जायगा। यहां असल का पता भी नहीं चलेगा। अब बजाय जमींदार के वह आप के अमलेवालों को लगान देंगे। रिश्वत का बाजार यों ही क्या कम है ? फिर पूरी बेईमानी हो जायगी। रिश्वत का बाजार खुब ज्यादा हो जायगा। यही आप चाहते हैं। खर कोई मुजायका नहीं ह। करण्यन और ब्राइबरी घटी नहीं हैं । अाप का यह दावा कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं गलत है । ब्राइबरी और करप्शन को हटाने के यह तरी*ने* नहीं हैं। आज भी लोगों को शिकायतें हैं। इससे मुल्क में शिकायतें और बढ़ेंगी और मुल्क में एक कन्पयुजन पैदा कर देंगे। जहां तक कपिटलिज्म का ताल्लक है मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से और किस किस्म का स्टेप आप ले सकते हैं ? किस तरी के से उस की खत्म कर सकते हैं। हां, यह दूसरी बात ह कि कम्युनिज्म का रास्ता खुल जाय । जैसा कि सर जगदोश प्रसाद ने कहा कि सैपर्स और माइनर्स का काम सरकार करेगी। इसमें शक नहीं ह। इससे मुल्क की हालत न अच्छी हो सकती हैं और न दुरुस्त होती हैं। न मुल्क की तरक्की की कोई सूरत दिखाई देती है। जो बेसिक सवाल है उसकी तरफ सवज्जह नहीं है। सरकार की तवज्जह नहीं है। सरकार की दिलचस्पी नहीं है। आबाबी बढ रही है उस के लिये कहां से गल्ला आएगा। बर्थ कन्ट्रोल का इंतजाम करें। आप की चाहिये था कि ज्यादा आबादी को आस्टलिया भें बसवाते आप ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि अंग्रेज आगे कदम बढायें तो उनके पीछे चलने लगें। फायदा की चीज है वह करें। जहां तक जनता की जरूरत है यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वह क्योंकर पूरी होगी। क्या आप लोग समझते हैं कि जमीन रबड़ हो जायगी? यह बात तो ठोक नहीं है। जहां तक जंगलात का ताल्लुक है साइनटिस्ट के ख्यालात के मुताबिक २५ होना चाहिए । जहां तक मैंने सुना है इस सुबे में १२ फी सदी रकबा जंगलात में शामिल है। मतलब यह है कि जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है। जमीन कहां से लायेंगे। अगर आप बारिश बढ़ाने का इन्तजाम करना चाहते हैं तो कम से कम कुछ जंगलात और तो यह सब कन्फ्यूजन है मुल्क के सामने। आपने जल्दी में आकर के कि फलां पार्टी न आजाय, ऐसा किया कि भुमिधरी के सिलसिले में शायद कुछ और हमारे वोटर्स बन लेकिन जहां तक मुल्क की हमदर्दी और दोस्ती का ताल्लुक है, इसके कुछ माने नहीं है। में तो महात्मा गांधी की तारीफ करूंगा कि इस शख्स ने इतना काम किया लेकिन कोई आफिस, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेना पसन्द नहीं किया और यही सच्ची हमदर्दी है। इसमें तो यह है कि एक पार्टी की मानोपली है, एक पार्टी गैंग है जो कब्जा किये हुये है। क्या हम हिन्दुस्तानी नहीं हैं, क्या और लोग हिन्दुस्तानी नहीं हैं ? क्या उनको हक नहीं है, क्या उनको दर्द नहीं है ? इसके यह माने नहीं कि आप मुल्क का सत्यानाश करें।

श्री सारत निह यादवाचाय --श्रोमान् डिप्टो स्पोकर साहब! में इस बिल का तमर्थन करने के जिये खड़ा हुआ इं लेकिन कुछ अपने विवार रखते हुये। हमारी सरकार जो इस समय किमानों के माथ हमड़दीं अर रही है कि वह अपना क्मगुना लगान जमा करदे तो जमीन के मालिक हो जाये. यानी जिननी काइन उनके हाय में है उसके वह भूमिधर बन जायं, ती जिनके पाल पैसा है बह नो जमाकर रहे हैं, लेिन जो गरोब है और जिनके पास खाने-पीने से नहीं फुरसत भिलती है उनकी कोई रकम बहुती तो है नहीं और न देहात में उनके कोई कारखाने या कलें चलती है उनके लिये नरकार क्या इन्तेजामे कर रही है? उनके लिये तो रफ्तार धीरे २ है। जैसे कि तीन महीने की रक्की और उसकी अले किर थोड़ा बढ़ा दिया। तो यह हगददी तो अलकी सह है. के किन जब सरकार से क्या गया कि एक, दो मही ना इधर छोड़ विया जाय और नवस्वर, दिनम्बर ने बुह किया जाय ताकि मार्च, अप्रैल तक दस गुना लगान पूरा जक्षा हो जाय तो उस वक्त हम रे भाई काँग विवह कट्ने ये कि नहीं सरकार, रुपया तो किसान देने को तैयार है। लेकिन बेम्न का हाल तो नचे मोल महुआ जब घर में रंग ही नहीं है। और मुझे प्या फहना है। मुझे दी यह पहना है कि जो आदमी पद्टेदार है वह तो अपना लगान जमा कर देगे, छिकिन को २०, २१ वर्र में बर इर जोनने चुले आसे है और आज भी जोत रहे है लेकिन पडवारी के खाते में उत्तरा नाम नहीं, वह क्या घरे ? हाकिमी से अहा जाता है जो इस वक्त मौजूद है जिलों के अन्दर नो बर जहते हैं कि हम फैनला वही देंगे जिसका नाम पडवारी जिखता है । तो इसके जिये हमारी जरजार बया प्रयन्ध कर रही हैं ? पटदारी को सौजूदगी में किसान और जमींदार दोनां परेजान हे जैर में नहीं जानता कि हजारी काग्रेम सरकार किमके कहने से इस बात को नमझेची जा इनके ऊपर कोई अपर जादमी नैनात करेगी कि पह दोरा करे और दौरा कर के ठीक जांच-पर्माल करे और वहां कोई ऐसा हाकिस तैनात परे और अही बात का पता लगावे को इमोर को परती से मजरूका बनाये । ऐसा किसान आज अपना ६स गुना लगान किस तरह से दाखिल करे । होई इसकी बातचीत नहीं है। न कोई उसका शिरपैर है। वह अवालत में भी जाता है. दारा-मारा फिरता है ओर अगर वह अपने खेत को जीतता है तो वह जमीनवाला उस पर जाकर क़टजा कर लेता है जिसके नान खेत है। फिर यह भी होता है कि जमींदार उसके ऊपर दाना करता है या वह जिन्के पान ज्यादा जमीन है, नालदार है या ठेकेदार है वह दावा करता है । पंनता कि रान के खिलाल होना है। किसान के अपर दक्षा १०७ चलाई आती है और वह वेबात परेशान होता है।

हिमान हे पान जो हुछ हो है या जो कुछ बहु अपनी मेहनत से पैसा भी हर लेला है वह तो उनके उन्हें को है नहीं, रिहन के हैं नहीं और बहु बे बारा १०० में लदका—लउका यूनता है। आप जानते हैं कि आवकर बकीलों की फ़ीसे कितनी पड़ गई हैं। कि आव उनकों भी मही दे नका। पड़ बे बारा पैवल या लारों या मोटर पर चढ़ कर आता है। कभी उस पर भी विचार किया कि जहां पर बमें चलती हैं या लारियां चलती है, उन पर लिखा हुआ होता है कि २२ तवारी, ३३ सवारी, ३८ सवारी। लेकिन जरा उनका चे किंग किया जाय तो उनमें मालूम होगा कि कितनो सवारियां है। जहां से वे चलती है और जहां स्टेशन पर उनको पहुंचना है वहां तक रास्ते में भी बैठाते चले जाते है। सवारी पर सवारी और लारी पर सवारी। मगर कोई देखने वाला नहीं है।

तो नेरी प्रार्थना है कि सरकार तो ग्रारीब किसानों के लिये खूब करती है। लेकिन काग़ ज में या जवानी सरकार इन्तजाम करें और उसके साथ गांव—गांव जाकर उसके आदमी देखें कि दरअसल बनीन कीन जोतता हैं ओर पटवारी जमीन किसके नाम लिखता है। इसके लिये आजनक आपने कितने पटवारियों को सजा दी है ? पांच सो दरख्वास्तों, मेरे पास हैं और तीन सो मैंने प्रधान जी को दी थों। उन्होंने उनको कलेक्टर के पास भेज दिया जो उसकी मेज पर रखी हुई एक बंडल की सूरत नें मौजूद है। मगर देखभाल कुछ नहीं। कलेक्टर तो कहता है कि में बुड्ढा हूं ओर पेंजन पर जानेयाला हूं। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो नव—युवक कालिजों से निकलते हें, हमारे कालिजों से निकल रहे हैं, उनको इधर उधर टकरांबें नहीं। आम

५३

बुड्ढों को पेन्सन देकर के अलग करवे ओर उन तदानों को तीन—तीन पहीने की ट्रेनिंग दे करके उनको जिले में भेजे ताकि वे न्याय के तथ, इन्मफ के लाथ, ओर सच्चाई के साथ यह फैसला करें कि दरअनल जमीन हैं कि को जोर जीतता जीन है। पगर हवारी रारकार को तो बहुत की मुक्षेबते हैं, और कपड़ा, शक्कर, तेल, नमय । ओर भी बहुत सी चीजे है। इन सबके लाइसेंस ह। जिन ने पाल आइने महिर्दे के लो न आर सरकार इनके लिए आदमी भी ऐसे मुन्तैं करती हैं कि एक आउमी जोते जित को बीच दिन अर बेचता रहे लेकिन पिंडलक को कुछ भी नहीं पिंडना। तो कोई फैमला नहां हा। जगर आप गलत समझते हैं कि तो मैं आपको दर बीम जिला का बौरा करा के दिखा सलता है कि ऐ हैं या नहीं। सगर इस पर विचार कोन करें। जिननी रिआन हैं, जिननी देगत को रिआया आर किमान हैं, वे सब सरपार के उनर है। सरकार को खिया चार्चे कि रिश्वत जिल्कुल नहीं होनी चाहिये और इलैक— मार्केट भी पहीं होना अन्हिये। पार को कोन और इप पर विचार कान करें? जैसे हम किमान लोग टकट की लगाते हैं कि आकान से पर्या हो उती तरह से सरकार के हाकिम ध्यटकी लगाने हैं। हमारी सरकार ऐसा इन्प जा। करें कि कोई कि को दिशत न हो या गुलामों न हो या ठेकेदारी न हो।

डिट्टी स्था कर——माननीय रादस्य की तबज्जह मैं इम तरफ दिलाता हू कि यह जमीदारी विनाश बिन है। इनमें शहर पर्गरा का कोई मवान नहीं जाना है। आप कृपा करके इनी बहुस पर अपनी पातचीत को रमें।

श्री भारत सिंह यादवाचार्य — मैं डिग्टी रमेकर मान्ब से प्रार्थना जरता हू कि जो दो चार हाथ में भागे पलागवा हू तो म देशन का रन्नेवाका नु ।

श्रोनान् जो, हनारी तरकार इतका जल्द से जन्द प्रवय करे और कोई अफमर स्थायी या स्यानिक या कहों से भी चाहे वह अस्याई हो मुकर्रर करे कि जो काइतकार जमीन को बनाता है और जोनता है वही उसका मालिक रहे। उसके पात आप को ऐना हुश्म मिले कि वह इस हिमाब से अनना दन गुना लगान जना करे या आप तरकार हे, मालिक हं, सबको आइवासन देते है कि किनी को कर्ड नहीं होगा लेकिन काइनकार के कब्दो का वारापार नही है उसकी कोई जाव-गूंछ गही होनो, देख भारतही हो से और यह कहा जाता है कि कितान सब से अच्छा है.——

खुद खाना नही खि जाता है, देखो रिन रात कमाता है। उसकी रोहनत पर करो ध्यान, गव करते हैं जिसको किसान।। खेती के रिवाय कुठ काम नहीं, यकने ता लेता राम नहीं। ति उठता है होते बिहान, गव कहते हैं जिसको किसान।। भेजा ठेश और नीर्थ वाम, पैदल चलता है मुबह शाम। रखना नहां वाने सुख का पान, गव कहते ह जिनको किसान।। कुछ नेड बबू कर आम नरी, खाना में किसान का राव गहीं। धा करता है। वहना है बहना ने बेई गा, गव कहते ह जिसको किसान।।

इत अबबों के साथ में इन बिल का समर्थन करता हूं। हमारी सरकार इस ओर ध्यान दे। अपने हाकिमों को हबत दे कि पह अपने-अपने जिले के सर्वंध में रिपोर्ट दे। जहां तक मेरा संबंध है मैं इस बीन जिलों की निगोर्ट दंगा कि जमीन किसकी है और कौन जोतता है।

श्री मु म्मट रजा खा--जनाववाला! मैं तो यह अर्ज करता हूं कि जहा तक जमीदारी का ताल्लुक है जमींदारी का खात्मा लाजिमी और जरूरी था और वह हो रहा है। मेरा ख्याल है [श्री मुहम्मद रजा खां]
कि इस बिल में सेलेक्ट कमेटी ने बमुकाबिले पहिले के कुछ तरक्क़ी की है और छोटे जमींदारों की इस बिल में सेलेक्ट कमेटी ने बमुकाबिले पहिले के कुछ तरक्क़ी की है और छोटे जमींदारों को कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश की है लेकिन वह बहुत ही कम है। में यह ख्याल करता हूं कि किसानों में भूमिधर बनने का जोश बहुत ही कम है यानी ज्यादा नहीं है। इस वजह से कि इस बिल में काश्तकार को यह हक़ तो दिया गया है कि वह अपनी जमीन बेच सकता है लेकिन उनको शिकमी कर देने का हक़ नहीं दिया गया है। काश्तकार ज्यादातर गरीब है, मालदार उनको शिकमी कर देने का हक़ नहीं दिया गया है। काश्तकार ज्यादातर गरीब है, मालदार काश्तकार बहुत हो कम है। अक्सर उनको कर्ज वगैरा की जरूरत होती है। उह यह महसूस करते है कि अगर एक मर्तबा अपनी जमीन बेच डाली तो वह हमेशा के लिये चली जायेगी। शिकमी पर देने का हक़ जैसे पहिले था पांच साल, कि कीन साल वह खुद काश्त करे बाद को शिकमी पर दे दे। काश्तकार इसको बहुत ज्यादा पसन्द करता है।

मेरा स्थाल यह है कि यह उसूल कि जमीन को जो काश्त करेगा वही उसका मालिक होगा, में तो यह समझता हूं कि जो शब्स कावत को खुद अपने हाथ से करता है या किसी को शरीक कर लेता है वह भी जमीन का मालिक है, मगर यह कहना कि वह आदयी जो अपने हाथ से काश्त नहीं करता वह मालिक नहीं है जमीन को, यह उसूल तो खत का है। हिन्दुस्तान को उत उसूल को कर्ज नहीं लेना चोहिये। मेरे ख्याल में यह बात किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हमें हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुए दूसरे मुल्कों के नजरिये से फायदा उठाने की कोशिश ने करना चाहिए। हमे तो अपने मुल्क के लिए जो यहां के काश्तकारों के लिए मुफ़ीद हो, यहां के जमींदारों के लिए मुफीद हो, वही सब काम करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हुकूमत को कम्यूनिज्म के उसूलों को नहीं अपनाना चाहिए। इसमे शक नहीं कि हिन्दुस्तान के काश्तकार का जहां तक सवाल है उनका एक बड़ा हिस्सा गरीब है और यह कहना कि काश्तकार अपनी जमीनों से इसलिए मेहनत नहीं करता कि वह जमीन का मालिक नहीं है, ग़लत है। मै तो समझता हूं कि वह इस वक्त भी मालिक है और वह महसूस करता है कि मै जमीन का मालिक हूं। जिमींदारी का लात्मा होने से यह यक्तीन कर लेना कि पैदावार में इजाफ़ा हो जायगा, मेरे ख्याल में यह चीज ग्रलत है। इस वजह से कि बहुत से छोटे-छोटे जमींदार है जो अपने हाथ से खेती करते है। क्या उन्होंने अपनी कारत बढ़ाने में कोई कोताही की. नहीं की। काफ़ी मेहनत से काम किया मगर पैदावार नहीं बढ़ा सके। यह काम तो हुक़ुमत का है कि वह उनको छाद सप्लाई करे, और और आसानियां दे क्योंकि आराजी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गयी है, पेइतर की तरह नहीं ह। उसमे काश्तकार पूरी जमीन में खाद नहीं डाल सकता। यह काम हुक पत का है कि वह उसको इमदाद दे।

में यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत से मुक़द्दमात काश्तकार के अब भी १७१ के तथ नहीं हुए हैं। हुआ यह कि काश्तकार ने दरख्वास्त वापसी की दी मगर अदालत से वह आरिज हो गयी। किमश्नरी से किंलग लेना है। कोर्ट में मुक़द्दमात भेजे गये हैं। बरेली गे ऐसे मुक़द्दमात बहुत हैं। दाश्तकार उस यक्त तक रुपया होंगज देने को तैयार नहीं हो सकता जब तक कि उसको यह यक्तीन न हो जाय कि वह जमीन का भूमिधर सही तरीक़े से बन सकता है। कोर्ट में एक साल से वह मुकद्दमे पड़े हुए है। जहां तक कि मुआबिज का सवाल है में समझता हूं कि सरकार को कर्ज लेना चाहिए और कर्जा ले कर जमींदारों को मुआबिजा देना चाहिए और काश्तकारों की आइंदा की आमदनी जो गवर्नमेंट के पास जायगी उससे वह अदा हो सकता है। बड़े और छोटे जमींदारों का सवाल रखना मेरे ख्याल में ज्यादा मुनासिब नहीं है। छोटे जमींदारों को भी जिन्दा रहने का हक़ होना चाहिए। बड़ों के पास बड़ा रुपया है और सामान भी काफ़ी है लेकिन छोटे र जमींदार जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको जिन्दा रखना हुक़्मत का फ़र्ज हो जाता है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है मुझे उसकी बहुत सी बातों से इत्तिफ़ाक़ नहीं है। उनके मुताल्लिक़ में आइंदा वक्त आने पर अर्ज करूंगा। आम तौर से जहां तक जमींदारी के खात्मे का सवाल है इसको खत्म होना था और इसको होना चाहिए।

श्री ग्रब्दल बार्को -- जनाबवाला ! इस बिल के कसीड़ेशन (विचार) के मुताल्लिक मिनिस्टर आफ रेबेन्यू ने चन्द चीजो का जिक्र किया है और उसी पर बुनियाद गयी है इस बिल के कंसीड़ेशन की और इस बिल की ताईद की। म अपनी तकरीर में तकरीबन अपने पेशेनजर उन्ही उम्र को रख्गा। मेरी जाती राय इस बिल के मुताल्लिक यह है कि अभी गवर्नमेट की यह कोशिश है ओर यह कोशिश नातमाम नाकि न और नाम कम्मिल है। न इससे गवर्नमेंट का वह मंज्ञा पूरा होता है जिसका वह बढागे दोहल ऐलान कर रही है ओर न काश्तकारों को फायदा पहुंच संकेगा जिसका स्लोगन के बरिये से ढिढोरा पीटा जा रहा है, और न मुल्क को फायदा पहुंचेगा, जिस फायदे की उम्मीद दिलायी जा रही है। बुनियादी चीज यह बताई जा रही है कि जमीदार का बड़ा इक्तदार था इस सबे में और उसने काश्तकारों पर बड़ा सितम किया। एक हद तक यह चीज सही है कोइतकारों ने तकलीफ उठाई और जमीदारों ने अपनी जिन्दगी राहत से बसर की और जमीदारी का नाजायज फायदा भी उठाया। मगर हम को देखना यह है कि जो बिल हमारे सामने है जो आइन्हा कागून बनने वाला है उससे क्या हम जमीदारों की मुल्क का मुआजिज बाशिन्दा रख सकते हे और किसानो की हैंसियत को बुलंद कर सकते ह या नहीं। मेरे ख्याल में किसी मल्क का यह नजरिया नहीं हो सकता कि जिन की हालत पहिले से अच्छी हो उनको ओर पस्त किया जाय । जिनकी हालत खराब है उनको तो बुलन्द करना ही है, मगर जिनकी हालत ब्लंद है उनको पस्न करना हरगिज अच्छा नहीं । देखना यह है कि इस बिल से जमीदार किस सतह पर पहुचता है। हम अगर गोर करेगे तो हमको यह मालूम होगा कि अगर किसी के म्बाशियत के जरिये को ले लिया जाय और उसका माकूल इन्तजाम ने किया जाय तो उसकी जि-न्दगी बरराद हो जायगी। में समझता हू कि गवर्नमेंट इस मामले में न तमाम जमीदारों को बरबाद करना चाहती है जिनका जरिये माज जमीदारी है। और मेरी समझ मे बिल्कुल नही आता कि क्या गवर्नभेट यहा तक नही समझ रखती कि वह एक ऐसी चीज ला रही है जिसकी वजह से एक तबका खराब होगा और आइन्दा खुद गवर्नमेंट की परेशानी का बायस होगा। मैं समझता हैं कि यह बिल बिल्कुल अनप्लांड है। में तमसिले के तोर पर एक चीज कहे दूं। में रेल पर क्षा रहा था। अब गवर्नमेट ने सेकेड के दो हिस्से कर दिये हैं आडिनरी और स्पेशल। पहिले तीसरा, इटर, सेंकेंड और फर्स्ट के दर्जे थे। लेकिन गवर्नमेट ने इन्टर का दर्जा तोड दिया मगर उजलत में तोड़ा। फिर बादिले नाखास्ता वैसाही करना पड़ा। मगर इटर कर देते तो सब समझते कि बड़ी अहमक थी गवर्नमेट, इसलिये बादिले नाख्वास्ता आपने इटर तो उसका नाम नहीं रखा सेकन्ड स्पेशल रख दिया । मैं समझता हूं कि गवर्नमेट इस वक्त जो बिल ला रही है यही घोखा फिर गवर्नमेट को उठागा पडेगा और बादिले नाख्वास्ता गवर्नमेंट पछतायेगी लेकिन पछताने के लिये वबत नहीं होगा, आप अफसोस करेगे मगर अफसोस करने के लिये आपके पास दिन नहीं होगे। आप नदामत करेगे मगर आपकी नदासत बेकार जायगी इसलिये में कहता ह कि गवर्नमेट इस बिल को बनाते वक्त फिर एक मर्तबा नहीं हजार मर्तबा गौर कर ले कि उसके क्या नतायज होगे, मुत्क में इसके क्या असरात होगे ? जमीदारो का दया हाल होगा, इसको इस दुख दर्द को सुनाने के लिये तो जमीदार पार्टी आपके सादने कहेगी मेरे पास न तो एक धूर जमीन है और न काश्तकारी है मगर मैं इतनी समझ रराता हूं कि कानून का क्या अन्जाम होगा। उजलत में आप जो कानून बना रहे है उसके क्या अन्जाम होगे इस पर आपको गौर कर लेना चाहिये। आज गवर्नमेट जो कहती है कि हम किसानो की हालत बुलन्द कर रहे हे तो यह समझना चाहिये कि जो काश्तकार युलन्द होना चाहता है उसमें क्या हिम्मत है। अध्या यह भी इस बिल इस्तकबाल कर रहा है या नहीं। अगर जिल में दरहकीकत उसकी दिलचस्पी होती और अगर वह इसको दिलोजान से चाहता होता तो मेरे ख्याल में आपको जुलाई के बाद से आपने जो दोरे किये है उसकी जरूरत न पड़ी होती। आपने इस सूबे में तमाम रारते को पार किया है, कितनी धूल फाक डाली, कितना पेट्रोल सर्फ किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटो ने, हुक्कामान ने और खुद कै बिनेट के मेम्बरान दौरा कर रहे हैं उनको मालूम हो ही गया होगा कि क्या कर लिया आपने ? अगर दरहकीक़त काइतकार के दिल में इसकों एहतराम होता कि आपने भलाई की है तो आपके दौड़ने की जरूरत नहीं होती। काश्तकार खुद आपके क़दमों में लाकर वह रक़म रख

[अंध अञ्चल ब जी]

'ব' जिपर्र' आपको अवार्ल, तन (विनाश) के लिये जरूरत है। जरा देखिये कि मुल्क में आपदे[।] देखेगे मु तिल्क जे में व्या क्याल है। जहां आप जायेगे तो आप कुछ ओरही समा अपने ि जाक देवेगे। पड़ी हिरफावाजियां हो रहीं हा कोई काइनकार से कहता है कि १० गुना जमा कि वो ारा घर दिकल जायता, अरेवाड़ा विकल लायगा, पछवाड़ा निकल जायगा और इस तरी है से १० पुटा जारा किया जा रहा है। जाइत र र इम िक की अहिरियत समझ रहा है, आहे, यह रिजोन्यूरान सन् १९४६ मे वैश किया था, एक छोटा बच्चा भी जानता है, जो काइतवार सर्दि है वे भा जोनते है कि यह बिल क्या है ? जमीदार तो आज उजनत कर रहा है कि उराकी जमीदारी जन्द खन्म हो। आपने इधर नुमका लगान दन्द कर दिया, उसका लगान वसूल नहीं होता, मालग्-इ। नी आप मीने पर चढ़कर ले लेने हें मैं कहना हूं कि आप जुल्म कर रहे हैं। दीजियें सबको बरा-वर कः मोका । लेकिन आप कहने हे कि हम जमान लेसे वृं तो कम्पन्से ।न (पितकर) दे हि है । मदाल या नहीं है कि आप दे रहे हैं। सबाल यह है कि जब अप की जेब से पेसा नहीं है तो जाप वेकार के निये क्यों गजब ढा रहे हे उन पर जिनके पान पैना नहीं है। अगर गदर्न में ट दरहक कत जनोंदारी अबाजित करना चाहनी है तो अबालिश करने के जिये कर्ज ले। उन लोगों दे चैना ने जिनके पाम पै पा है उनमे ले कर मुंआविजा दिया जाय । यह क्या है कि अप है रहे है जमीदार को और गना टीन रहे है उस वेबारे का इतकार का जिनके पान कुछ गहा है। फेनरप्ले और जिस्टन तो यह होनी कि आन काश्नकारों की हालत का जायजा लेते कि ने प्रदा करने को नाकत को रबने भी है। मार आज आप इम वक्त जो वसूल कर रहे है, जानते है, उ (हे बारे से काश्नकार क्यां ख्याच कर रहा है ? वह समझता है कि आप इन्सोलप्रेन्ट (दीवालिये) और आपके पास पूजी और सरमाया नहीं है। आ। काइनकार की जेब को तला न करते हैं। कभो यह मंशा नहीं होना चाहिये कि आप कानून ऐपा लाये जिससे कि वे जिनको कि हातन से फायदा है और जिनके लिये कान्न बनाया गया है वे हो समझे कि कान्नमाज हमारे गृहनाज है और हमारे ताथ साजिश की जा रही है, चाल चली जा रही है। अभी एक मेरे लायक दोस्त न कहा कि हम इस राय के ह कि बिला मुआबिजों के जमीं दारी तोड़ दी जाय। यह तो खला डाका है। वन्त यू गिव दो गवर्नमेट दिस पावर, अगर एक सर्वबा आपने गवर्नमेट को यह हक दे दिया कि कोई चीज वह बिला मुआदिजे के ले ले तो कल वह हमारी अचकन उतार लेगी, हमारा गैजामा घमीट लेगी, घर और जायदाद तो ले ही लेगी । मैं समझता हूं कि यह तो डाकेजनी है। मै इस राय का नहीं हूं कि गवर्न रेंट कोई प्रापर्टी बिला मुआविजा के ले। अब तक जो गवर्नमेट रही है उनको जब कोई जहरत पड़ी तो उसने जो भी बीजे ली उतक। सही माकल दाम दिया। में इस गवर्नमेट को कंडेम्न करता हूं। मेरी जबान में जितनी भी ताकत है, उस ताकत से में इसको कंडे व्न करता हं। यह जो क़ानून है वह निहायत खराब है, बेमार है। यह कहीं नहीं हुआ कि एक नेजन र की कोई चोज गवर्तमें ह ले ले और मअ विजा न दे। वैर आप तो यह कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आए भी ऐसा करते ता आप भी एक हद दर्जे की गलती करते। इट उड हैव बीन रांग बाई टी कांस्टोटगूशन (संविधान के अन्तर्गत यह चीन गलत होती)। आपने कांस्टीटचूशन में तय कर लिया है कि जब किसी की मिल्कियत को लेंगे तो कम्पेन्सेशन अदा करेगे। आपको कम्पेन्सेशन अदा करना है। अत्र सवाल यह है कि आप किस तरह से कम्पेन्सेशन अदा करते है। मै तो समझता हं कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज आर बास्ट, रिसोर्सेज आर ग्रेट (सरकार के जरिये यहुन वसीह और बड़े है)। बात जो समझने की है वह यह है कि वह रिसोर्स त्रया है ? आप सनझते हैं कि वह रिसोर्सेज ये है कि गरीबों की जेवें टटोली रारीबों को जेवे न पकड़िये, कास्तकार से मुआविजान लीजिये। एक तो यह शिसोर्न है कि गवर्नमेट शुड टेक लोन (स कार ऋँग ले)। आप जो यह कहते हैं कि आठ गुना दिया जाय, यांच गुना दिया जाय ओर जो गाय इसी वजह से बिल की लेलेक्ट कमेटी या इवर ने उघर से धूमाते हैं, वर गिर्फ इसिन्ये कि आव समझते है कि आपकी जेब में कुछ नहीं है और यह सोचते हैं कि मुआ वेजा दिया जाय तो कैसे दिया जाय। यू शुड टेक लोन (आपको ऋण लेना चाहिये)। सब प्रापटीं का (जायदाद) वैन्युयेशन (तशासीश) करे। पेदी

करेकट बैल्युपेशन आफ दी प्रायटी (जायदाद की सही रकम तशाखीस हो यह दीजिये)। हर ज्ञानींदार की जमींदारी लेली जाय बट यू सस्ट पे दी फुल कम्पे सेशन (लेकिन आपको पूरा मुआविजा देना चाहिये)। जो उसका करेक्ट बैल्युपेशन है उसको आप दें। दी कम्पे सेशन शुंड दी आन करेक्ट बैल्युपेशन, आम यूनीफार्म बेसिस (मुआवजा सही तशाखीस और एकसा बुनियाद पर मननी होना चाहिये।) और अगर आप यह चाहते हैं कि हम जो चाहिंगे वह देंगे तो यह रांग है, टोटली रांग कम्पोलीटिली एवसर्ड (बिलकुल ग़लत और बेहदा चीज है।) बाजार में एक किस्म के कपड़े का एक ही भाव होता है और जो दो निर्द्ध से बेचता है तो वह ब्लैक मार्केंटिंग है। जैसा कि आपने चीनी में किया है। बाजार में दो दो रपये सेर बेची और अपनी दूकानों में १३ आने सेर। आई डिनाउन्स इट, आई डिनाउन्स इट बिद फुल पाचर। (सेंइस की निन्दा करता करता हं, में पूरी शक्ति से इसकी निन्दा करता हं)।

माननीय माल सचिव-निरे लायक दोस्त हिन्दी में बोला करें तो ज्यादा अच्छा है। डिट्टा स्पीकर-पाननीय सदस्य महोदय उस प्रस्ताव का जकर ख्याल रक्खेंगे जो इस भवन ने संजूर किया है। पालूम होता है वे गुस्ते में बोल गये।

श्री चा दुल बाको-न्यें अपने आप को उसप्रस्ताव तक महदूद कहना जो आनरेबिल वजीर रेवेन्यू ने हाउस के सामने रखा है। जैसा कि।

डिण्टी स्पीकर—मैंने यह नहीं कहा था कि आप गुस्ते में बिल से बाहर चले गये लेकिन यह कहा था कि आप शायद गुस्से को वजह से अंग्रेजी बोलने लगे। जहां तक जवान का ताल्लुक है भवन की सब कार्यवाही सूबे की जबान में ही होनी चाहिये।

श्री ग्राब्दुत बाकी -- बह गुस्ते की अंग्रेजी नहीं थी बल्कि प्यार की अंग्रेजी थी। डिप्टी स्पीकर--अब आप उस प्यार की अंग्रेजी को छोड़ दीजिये।

श्री ग्रब्दुल बाकी—अब में प्यार करना छोड़ दूंगा। में यह जिक्र कर रहा था कि हर चीज का निर्ल और शरह एक ही होना चाहिये लेकिन गवनंमेंट का निर्ल का निर्मार मुख्तलिफ करना मेरे ख्याल में उसकी सूझ—बूझ की खराबी की वजह से हैं। आसान तरीका तो यह है कि आप मुआविज को तो एकसां दीजिये इस पर तफसील के वक्त तो उस वक्त बोलूंगा जब कि दफात आयेंगी लेकिन इस वक्त तो इतना ही कहूंगा कि आप ने जो यह उसूल बनाया है वह उसूल गलत है। आपने एक चीज की शरह और निर्ल को मुख्तलिफ करार दिया है। इस विल में जो सब से खराब बात है वह यही है कि इसमें निर्ल में इख्तलाफ़ रखा गया है, मालुम होता है आपने उसको सोचा नहीं है। आप उसे सोचें, दुबारा सोचें, खेबारा सोचें। दरअसल आप को अगर सुआविजा देना है तो आप यूनीकार्म, एकसां मुआविजा दीजिये और हर छोटे—बज़े के लिये एकसां मुआविजा रिखये।

दूसरी गलत बात यह है कि अगर आप कम मुआविजा देंगे तो सबसे बड़ी तक लीफ इस मुल्क के उन लोगों को होगी कि जो आप ही के हिस्से हैं, आप ही के पार्ट ऐंड पालिल हैं यानी जमींदार लोग बड़ी ऊंची बुलंदी से पस्ती में गिरेंगे और शायद सदियों तक अपने को ऊंचा और बुलंद नहीं कर सकेंगे। यह कितने बड़े दुल की बात है कि मुल्क का एक तबका पस्ती में डाल दिया जाता है। अगर ऐसा होगा तो बहु आप के साथ नया हमदर्शी रखेंगे? मरीज की तर् से जमींदार इस बक्त तो यहसूस ही क्या करेंगे अभी तो वह जमींदारी लेकर बैठे हुये हैं, अभी तो वह इन्तजाम करते हैं। अभी तो वह उस मरीज की विस्ल हैं जिसके इदं—गिर्द तबीज और घर के लोग बैठे हुये हैं। उसे तब महसूस होगा जब कि तबीब उठ जायगा, घर वाले चल देंगे और वह बिल्कुल मर जायगा। उनके लिये आप ने इस बिल में कोई इन्तजाम नहीं किया है। इसलिये में अर्ज करंगा कि यह बिल नाकिस है, नातसाम है इसमें बड़े अमेन्डमेन्टों (संशोधनों) की जरूरत है। जमींदारों को जमीन का सही मुआविजा दीजिये, उनको वह जगह दीजिये जिसके वह मुस्तहक है, जो

श्री अदल बाजी] उनके शायानेशान है। मेरे लायक दोस्त ने यह बात कही कि वे बन्दोबस्त कर रहें है। कोआपरेटिय सोसाइटियों के जरिये से अनाज और गल्ला बढ़ाने की। यह तो आप की एक स्कीम है, आप का एक ख्याल है, आप का एक नजरिया है, सही है या गलत यह तो मालूम होगा जब इस पर आप अमल करेंगे। जमाना आप को बतायेगा कि आप की राय कहाँ तक दुरुस्त है और आप का नजरिया कहां तक काविले असल है। आप यह समझते हैं कि आप छोटी-छोटी होल्डिंग खत्म करेंगे और कोआपरेटिव बना कर के प्रोडक्शन (उपज) बढ़ायेंगे लेकिन में बहुत बड़े तजुर्वे के बाद आप से बताता हूं कि जब एक मर्तवा आव कोआपरेटिव सोसायटीज बना देंगे और उसके मेम्बरान यह महसूस करेंगे कि हमारा मखनूत हिस्ता जो था वह बाक़ी नहीं रहा तो होगा यह कि वह मेहनत कम करेंगे। और लेबर से जी चुरायेंगे मुझे ऐसा अन्देशा मालूम होता है कि इस तरह वह चीज मुनाकिस हो जायगी। आप समझते हैं कि अच्छा नतीजा होगा लेकिन मुझे डर मालूम होता हैं कि कहीं इसका ननीजा खराब न निकले। इसलिये में तो यह समझता हूं कि अगर आप दरहक़ीक़त मुल्क की पैदावार बढ़ाना चाहते थे तो आप को किसानों से यह कह देना चाहिये था कि हम तुमसे कोई ताल्लक नहीं रखेंगे। तुम्हारे मामले में हम जरा भी दस्तन्दाजी नहीं करेंगे अगर तुम ज्यादा से ज्यादा पैदा करोगे तो वह तुम्हारा ही होगा लेकिन इस विल के अन्दर मुझे कोई ऐसा प्राविजन या सेक्शन नजर नहीं आ रहा हैं। क़ानून ऐसा बनाना चाहिये कि क़ानून की दफात की वजह से काश्तकार यह समझे कि उते अच्छा हक दिया गया है क्योंकि इससे वह दिलवस्पी से काम करेगा और पैदावार ज्यादा बडायेगा।

तीतरी वात जो में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मैं यह कहना चाहता था जैसा कि आनरेबिल मिनिस्टर ने फरमाया है कि काश्तकारी का कानून बड़ा पेंच दरपेंच कानून था ओर उसमें इन्दराजात बहुत पेचीदा थे लेकिन अब हम उसको सिग्पलीफाई (आसान) करना चाहते हैं। मैं यह समझता था कि जब जमींदारी का एवालिशन हो जायगा और जमींदारी खत्म हो जायगी तो मामला बहुत सादा हो जायगा। सिर्फ एक क्लास काश्तकारों का रह जायेगा, मगर आप ने भूमिधर रख दिया, सीरदार रख दिया और असामीदार रख दिया। अगर एक किस्म के काश्तकार होते तो मामला ज्यादा सिम्पलीफाई हो जाता मगर ऐसा आपने नहीं किया है। यह बहुत बड़ी खराबी है इस बिल की। आप ने यह कहा कि हम पेचीदिगियां रका कर रहे हैं मगर आप यह नहीं समझे कि अभी इसके अन्दर बहुत सी पेचीदिगियां हैं।

चौथी वात जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे एक लायक मुर्कारर ने यह कहा है कि गवर्नमेंट जिल को तैयार कर चुकी है और उसका प्रचार भी उसने किया है मगर अभी गवर्नमेंट को यह पता नहीं है कि एक्चुअल कल्टीवेटर (वास्तविक किसान) है कौन। एक बड़ी ताबाद ऐसे लोगों की है जो जोतते हैं खुद और कागज़ में नाम चला आता है दूसरों का। गवर्नमेंट की सब से ज्यादा तवज्जह इस बात पर होना चाहिये थी कि जब वह जमींदारी को तोड़ रही है तो कम से कम इस बात का बन्दोबस्त कर लेती और इन बिल में कोई ऐसा प्राविजन रखती जिससे यह मालूम हो जाता कि वह इन्दराज पर एतमाद करेगी यह दरहक़ीकत जो असली काइतकार हैं जिनकी जोत में वाकई जमीन है उनका लिहाज करेगी।

मुझे तो इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है। और जैसा कि मेरे लायक दोस्त ने जो कहा है वह चीज बिल्कुल सही है। मैं भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर आप काश्तकारान का भला करना चाहते हैं तो आप के लिये यह जरूरत है कि आप सबसे पहिले इस बात की कोशिश करें कि जमीन पर कब्जा है कितका, इसको ठीक तौर से पता लगावें। आपने

मुन्क में जो एक खिल्फिशार फैला रखा है कोई काबिज है, तो कोई इन्दराज है ओर पटवारी को लांग लेटिच्यूड दे रखा है, कम से कम मेहरबानी करके उसकी रस्ती को काट डालिये। यह तो न हो कि उससे कस दीजिये। इसकी तरफ आप को कोरन तवज्जह करने की जरूरत है। पांचवी बात इस सिलसिले में मैयह अर्ज करना चाहता हू और गालिबन इस मौके पर इसी पर अपनी तकरीर भी खत्म कर दूंगा अर आगे चल कर अगर मौका मिला तो अपने ख्यालात को जरा बजाहत के साथ अर्ज करूंगा । दरहकीकत यह बिल बड़ा मुन्तिशर बिल है। आपने तमाम चीजों को उलट-पलट कर एक जगह उठा कर रख दिया है । एक मुफीद और गैरमुफीद सब चीजों को आपने एकजा रख दिया है जैसा कि मेरे लायक दौस्त निहालुद्दीन साहब ने कहा कि दोनों चीजों को अलग-अलग होना चाहिये था। जमीदारी तोडने का अलग ओर जमीदारी निजाम का अलग। दोनो अलग-अलग चीज है और दोनो के दो डिपार्ट-में न्द्रस है। मगर आप सबको एक में मिला कर मरगूबा तैयार कर रहे है। में कहता हं नि एक हिस्सा तो दयामी का है और दूसरा हिस्सा जमीदारी को खत्म करने का है। कोर इन दोनों को अलग–अलग होना चाहिये था। मै उम्मीद करता हूं कि इस पर गौर किया जायगा । आप को चाहिये था कि दोनो के लिये अलग-अलग कानून बनाते। एक में तो जमीदारी खत्म करने को बात होती और दूसरे में यह होता कि आगे उसका इन्तजाम क्या होगा ? आगे जो आप जमीदारी को बन्दोबस्त रखना चाहते है वह किम तरह से रखेंगे। दोनों दो चोच्चे हैं इसलिये दोनों के लिये अलग–अलग कानून बनाना चोहिये था। इप वक्त में सिर्फ इतना ही कह कर अपनी तकरीर खत्म करता हं और एक बार फिर आनरेबिल मिनिस्टर नाहब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह बिल बेड़ी नाकिस हालत में है ओर इनको फिर पाये तकमील तक पहुंचावे।

श्री हर प्रसाद सिह--श्रीमान डिप्टी स्पोकर महोदय । में कोई बड़ी लाबी तकरीर करने के न तो काबिल हूं और न करना चाहता हूं। में तो दो एक सजेशंस (सुझाव) माननीय माल सिवव की सेवा मे पेश करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि वह उनपर गोर करके अपने इस बिल में कुछ संशोधन कर लेंगे। में बुन्देलखेंड से आया हूं। बुन्देलखंड की अवस्था सूबे के तमाम और जिलों से बिल्कुल ही अलग है। की भूमि बहुत ही कमजोर है और प्राधन भी बुन्देलखंड में बहुत कम है। यहां पर न तो काफी नहरें हैं और न काफी सड़कें हैं। कहने का मतलब यह है कि बुन्देलखंड सब तरह में गिरा हुआ है। तो इकोनामिक होल्डिंग देने की जो बात है उसके लिये मैं यह कहुगा कि वहां के लोगों को कम से कम बीस एकड़ भूमि दी जाय। बात यह है कि वहां की जमीन साधारण है और जितने काश्तकार है वे ज्यादातर बड़े बड़ेही हैं। और अगर उनको आप छोटी होत्डिंग देगे तो मेरा ख्यालयह है कि उसमें उनका गुजर नहीं हो सकेगा और न कामयाबी ही हो सकेगी। बाज जगहों पर एक फसल होती हु और बाज जगहो पर दो फसलें होती है मगर पैदावार बहुत कम है । ऐसी हालत में मै चाहता हूं कि बुन्देलखंड का लिहाज हमारे माननीय माल मंत्री महोदय करें।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हं। बाज जमीदार ऐसे है कि जिन्होने अपनी कुल सीरे शिक मियो को उठा रखी है, उनको सिर्फ ८ एकड़ जमीन मिलेगी । अब आप ख्याल फरमार्थे कि एक तरफ तो वह जमीदार है जिनके पास सैकडों बीघा सीर होगी जो कि उनको मिलेगी और दूसरी तरफ वह जमीदार है जैसे कि औरते जमींदार है, उन औरतों से उनकी सीरें ठेके पर लोगों ने ली हुई ह या औरतो के जमीदार होने से किसी ट्रेसपासर ने उस पर कब्जा कर लिया है तो ज्यादातर उनकी सीरें शिकमियो के पाम है। जो उनको ८ एकड़ मिलेगी उससे कैसे उनका गुजारा होगा। उन स्त्रियो के लिये २० एकड़ कम से कम शिकमियो से निकाल कर उनको देना चाहिये। २० एकड जमीन उनको मिल जाना चाहिये ताकि वह भी अपनी गुजर बसर अच्छी तरह से कर

श्री हर प्रनाद मिही

परें। इस तरह के केमेज बहुत कम है, इनको कंसीडर करने एक प्राविजन इस तरह का जहा का दिया जाने कि रिनकी कुल सीरें शिकामियों के पास है उनको कम से कम २० एकड़ तो जहर फिल कार्य और बाकी जो शिकमी काश्तकारों के पास है उसको भूतियर करार दे दिया जार !

में पहुकहुना बाहुना हूं कि जोख्याल अपन लोगों का है ओर जो लोगों की शिकायत है के इत्र १० गुना लान के इकट्ठा करने में ज्यादनी हुई है, मै समझता हूं यह बात बिन्कुर गरन है। जहां तरु भेरे जिने का ताल्लुक है मैने देखा है कि लोगों से बहुत न स्मा क साथ वेदेण करने के जिये कहा गया है और लोगों ने अपनी राजी से वालि-न्दीयरी नरीके ते इत्येका वेतेन्ट किया है। एक बात यह कही गई है कि गवर्नभेग्ट इन्सा-लबेन्ट (दोवालिया) हो गई है। शायद उन्होंने इस उसूल को नहीं समझा कि अगर क उनकर ही पेनेन्ट करना है तो इसमें कोन सो बड़ी बात है जब कि काइतकार को भ निवर बनावाजः रहा है और उसकी पूरी तरह से हकूक दिये जा रहे हैं। क्या मेरे भाईको यह नहां मालून है। के इसकी खबर सुनकर बहुत से जमींदारों ने खेतवार यानी एक-एक खेन करके तमान बेत उन्हीं काइनकारों के हाथ बेच दिये थे कि जिनकी काइन के अन्दर वह खेत थे। तो ऐसी हालत में १० गुना लगान उनसे बसूल करके अगर ज रीं दारों को मुअविजा गवर्नमेंट दे रही है तो वह कोई गुनाह नहीं कर रही है बेल्कि इंसा क कर रही है। कं ग्रेत गत्रनेमेंट एक तरह से काइतकारों के साथ रिआयत कर रही है। ऐसी नूरन में यह कहना कि जनों दारी बिला मुआविजा खतम कर दी जाय यह ठीक नहीं है और यह उसूल गनत है। मैं भी एक छोटा सा जमींदार हूं मैं तो इससे स-नुष्य हूँ कि जो मुआविजा मिलेगा वह ठीक है और उससे सन्तोष है। वहुत जर्नी दार अन्तो लागरवाही की वजह से सीर शिकमी को दिये हुए हैं तो उनके ऊर्वर इननी रिआयन कर दी जाय कि जो शिकमी हैं उनके पास से बड़ा हिस्सा निकाल कर उन जमीं दारों को देदिया जाय ताकि वह भी अच्छी तरह से अपना गुजारा इन इनिया में कर सकें।

भा भगवान दोन मिश्र --भोमान् आज जमीं हारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था बिल पर जिन माननीय सदस्यों ने अपनी सम्मिति प्रकट की है उनमें से केवल बाकी साहब को छो कर वाकी सब लोगों ने जमींदारी को खत्म करने का समर्थन किया है। एक बान तो में अवश्य कहना चाहता हूं कि वह समर्थन कई रूप में हुआ है और उसमें कई प्रकार के सुसाव भी रखे गए हैं, किन्तु प्रायः सभी ने जिमींदारी को खत्म करने की बात अपनी सम्मति में जाहिर की हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना आवश्यक है कि जो कुछ सुझाव लोगों ने रखे है जिनमें बतलाया है, किसी साहब ने जमीदारों के साथ हमदर्दी र्दिखलाकर कर्द सुझाव रखे हैं, किसी साहब ने किसानों के सम्बन्ध में कुछ अलग २ अव-स्यायें दिखलाकर सुझाव रखे हैं लेकिन जो बिल आया है वह कुछ सिद्धान्तों पर रखा गया है। उसके सिद्धान्तों को मानते हुए अगर आप सिद्धान्त के साथ विचार करे तो में समझता हूं कि जिस स्वरूप में और जिस तरह से यह बिल लाया गया है वह सर्वोच्च उचित तथा मान्य भी है। आप यह देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार के खत्म होने के बाद ओर देश में जनतन्त्र राज्य कायम होने पर और देश में पूर्ण स्वतन्त्रता होने के बाद भा देश के अधिक से अधिक रहने वाले किसानों को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई और किसान का गला आज भी उसी जमोंदारी प्रथा के नीवे दबा हुआ है जब कि देश दो वर्ष पहिले स्वतन्त्र हो चुका है। इसलिये यह देलकर कि देश में पूर्ण स्वतन्त्रता तभी हो सकेगी कि जब देश के ८५ फी सदी किसानों को परतन्त्रता और जो जमींदारी का बोस उन पर है, जो जमोंदारी प्रया को देन है, उसे जल्द से जन्द दूर किया जाय। इस तरह से यह प्रयादूर करने के लिये हमारी सरकार ने बहुत पहिले से जो वादा किया था ओर

समय-नमय पर जिस की धोषणा भी की है उसी आधार को लेकर रूरतार यह। पर सन् ४६ में यह प्रस्ताय अवन के सामने लाई थी कि वह जमीदारी के जत्म करेगी।

हवारे याकी साह्य ने कहा ह कि इसमें बहुत उजलत की गई य तमाना ह कि बहुन से साननीय थेन्छ पन गह भी कहा। कि इसने बहुत देर की गर्, लेकिन स समजना ह कि अगा पिचार किया जाय तो उसने उजलत तो कर्तर गरी की गई है । यह एक बड़ अहम आर महत्वपूर्ण प्रस्तान ना कि जिस पर इतना कभी विचार करने के बार जिस शक्ल में यह बिल अब पेश किया गण है उससे जाहिर होता ह कि उस में इतना समय लाना आवश्तक ही था। न समजना हूं कि इस पर हमारी प्रवर समिति न जिन तरह से विचार किया है ओन कि । तरह से बहुन सो चीजा। को हल करने को वोशिश भो गई ह इस पात को देखते हुन कि प्रारा को किस तरह से समुचित से समुचित सुविधा पहुंचाई जा सलतो है दा जित से कोई प्रधिक समय नहीं लगा है। म जानता ह कि बहुन से लेन इन जियार पुर कि जिन का यह कहना है कि जमीवारी प्रथा अवश्य खत्म होनी जाहित, ऐमा कि सो दल या पार्टी नहीं है पता नक कि सम्भवार जमीवार या राजा पहारा भा यह बान कहने के किये तैनार ह कि अब यह प्रथा दूर होने चाहिते।

जुळ को नो कि । राह कि समोदारी वार करन ने किये सुप्राधियों नो जो राद कही गीत, यह गाउत है। यमाद थे जिल स्नातिना रत्म हो । विचित्र अमर इस पर पूर्व बहस और पिचार विया जान तो म समजना ह कि नार वि में र स्म मार में यह नियम है कि जो जिल्ही जानतर ओर नरपत्ति न, २५ जानशर जोर सम्पत्ति को यिका पूर्य ।दये हुए तेना किसी तरह न्याप सगत नहा है। यह आप कह सकते हैं कि वह सराति करें आई? जाप यह कह सकते है कि वह सम्पति जनाि । सम्पत्ति है, लेकिन फिर भी यह आप की भागना भेगा कि सकड़ों वर्षों से ११० मे-वारी को भी जर्भारार का सप्पत्ति मान ना राष्ट्रितो अवस्था में यह जो उनकी स्थाति ह, उसके एवज ओर न ले में उचित से उि। मुअायिजा देन न्यायसगत नी हा जान वो ज्ञायद गृह श्री भालून ुकि विधान परिषद् ने यह गिथम बनाया ह कि जा ि। को मम्पत्ति है उसका मुआतिजा देना चाहिये। जो लोग यह कहते ह कि मुआदिणा न ने प्रर जमीवारी केना पाहिंगे ता वह जान न्यायसगत नहीं मालूम होती है। दूसरी ओर यगर आप ऐसा नियम तमेवे नन या रिवाज जारी करेंगे. जमें बारी पथा को राम कर। के िने मरनार द्वारा िया हो निमासि हो यह प्रश्नरती लेली जाय तो इससे देश मे अन्यवस्था कायम हो जानगो। फिर का जनावार, क्या किसान जिसी को कोई सम्पति नहीं सपत्नी जाएगी। ए किसन दूसरे किसान की एवर्गात की बिजा िसी मुआबिजे या जिना जिली (अक के अधने जीर में और अपने बल से जबरदस्ती से ले लेगा चाहेगा। इम प्रकार पेदेन के एक कोने से एमर कीन तक अज्ञाति और अप्यवस्था हो जायगी। दूसरी या। पर आप विधार करे कि इस स्वराज्य और जनतन्त्र युग मे यह जनादार तबका जो हमारे यहा अच्छी परिन्धिति में ट उसको भी देखना है, उसके निये भी गोर करना ह, उसके लिये भी रासा। निकालना है कि वह अपने परो पर अधा हो पर देश में एक स्वतन्त्र भाग्तीय गी हैसियत से गर्व से बसर कर राके, निर्वाह कर सके। आपको यह भी विचार करना है कि ऐसी अवस्था में यदि आप यह न सोचे या ऐसा विचार न करे कि चू कि जमोदारों ने कुछ ज्यादितया की है, उनका शोषण किया है, इसलिये उसके बदले में मानवीय भावना से उनके निर्वाट की शक्ल न निकाले ओर जबरदस्ती जगीदारी खत्म कर दे तो देश में शान्ति खत्म हो जायगी। दूसरी बात यह होगी कि आपके सूबे में १८ लाख खाते हैं या २० लाख खाते है। अगर एक घर में चार आदमी या पाच आदमी गिने जाये तो एक करोड आदमी होगे जो बेकार हो जायगे। अगर आप उनको सवर्ष का मोका दे तो सूबे मे एक कोने से दूसरे कोने [श्री भावान दोन निश्र]

तक रक्तपात हो और खन की निदयां बहें। आप यह जानते है कि कांग्रेस महात्मा गांधी की अनुयायी संस्था ै। महात्मा गांधी ने विदेशियों से देश को स्वतन्त्र करने में रक्तपात की कभी भी तलाह नहीं दी। शान्ति और अहिन्सा से लड़ाई लड़कर देश को आजाद किया। ऐसी अवस्था में आज हमारी सरकार उचित नहीं समझती कि जमींदारी को इस तरीके पर खत्म किया जाय जिसमें रक्तयात सम्भव हो, जिससे देश में अशांति सम्भव हो, देश में अव्यवस्था हो। जमींदारी खत्म करने के लिये तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि जमोंदार राजी होकर जमीन किसानों के हाथ में दे दें। यह चीज जापान को छोड कर किसी दूसरे मुल्क में नहीं पाई गई है या दूसरा तरीका यह है कि आप उनको कुछ उचित से उचित मुआविजा दें या जैसा कि लोगों का नुझाव है और संभव है इस भवन के सामने भी वही सुझाव आवे कि লুন্ত भी न देकर जनोंदारी ले लेना चाहिये। ऐसे जनींदारी ले लेने की बात जो है और उसके साथ शंका होगी वह तो सामने है। रूस में जनींदारी इसी तरह से खत्म की गई लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि चार वर्ष तक वहां घोर संवर्ष हुआ और उससे बहुत कुछ जन और धन की हानि हुई। ऐसी सूरत में हमारी सरकार उस ब्यवस्था को किसी तरह से पसन्द नहीं करती। इसल्यि हमारे यहां मुआविजा की तजवीज की गई। वह मुआविजा कहां तक उचित है। इस पर अगर आप विचार करें तो जमींदार की दृष्टि से उसको अपने पुरुषार्थ पर खडे होने की पूरी सुविया दी गई है। अगर वह चाहेगा तो उस मुआविजे को लेकर वह पुरुषार्य से देश में एक स्वतंत्र भारतीय की हैसियत से अच्छी तरह से रह सकता है। लेकिन जो बेकार और निकम्मा वन कर इस जमींदारी प्रथा के आधार पर जीवित रहा है, जिन्होंने अधिक से अधिक सुख उठाया है उनका कायम रखना देश के लिये किसी तरह से उचित नहीं है। इसलिये जमींदारी प्रया को खत्म करके और उनको भी ऐसा अवसर दे करके जिससे वह अपने पुरुषार्थ से खड़े हो सके, इस बिल के द्वारा आपके सामने यह सम-चित योजना रखी गई है।

हमारे एक साहब ने एक बात यह भी कही, और वह भी हमारे बाकी साहब ने कही कि साहब दस गुना लगान के सिलिसले में लोगों को घर से निकालने की बात कही जाती है या उनको घमकी दी जाती है कि तुम्हारे घर नहीं रह जायंगे। में समझता हूं कि आज यह एक नयी बात कही गई है। सब तरफ से टीका—टिप्पणी सुनते हुए और विरोधियों की भी जो टीका—टिप्पणी हैं उसको देखते हुए आज भवन के सामने एक नयी बात बाकी साहब के मुंह से निकली और वह यह है धमिकयां दी जाती हैं। में यह कह सकता हूं कि इस योजना के सफल बनाने में जिस तरह से समझाने से और जिस तरह से किसानों के लाभ के लिये यह योजना है इस बात को जिस सफलता के साथ हमारे सरकारी कर्मचारियों और देश के कार्यकर्ताओं ने इस योजना को सफल बनाने में जिस प्रकार चेष्टा की है मैं कह सकता हूं कि उसमें कहीं धमकी की गंध भी नहीं आई है और न आयेगी। ऐसी सूरत में यह कहना उचित नहीं है।

अब दूतरी बात एक और है कि कितानों के पास धन की कमी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसानों के पास धन की कमी है, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि किसानों के पास धन की कमी बाद करने का ही यह साधन है और यही उपाय है। और यह उपाय हम लोग इस तरह से उनके सामने नहीं रखना चाहते कि जिससे आगे चलकर वे भी निकम्मे बनें और जमींदारी प्रथा की तरह उनके सामने भी यह अवसर आये कि वे भी इससे हटा दिये जाये। अगर आप यह कहते हैं कि गवर्नमेंट कर्जा लेकर उनको भूमिधर बना दे तो गवर्नमेंट जो कर्जा लिया करती है या अगर गवर्नमेंट कोई योजना चलाती तो वह कर्जा किसके ऊपर होता है, जरा ग़ौर करने की बात है। भवन के जिम्मे—दार माननीय सदस्य यह कहीं कि कर्जा लेलिया जाय और किसानों से कहा जाय कि

लुव जमीन के मालिक हो तो आपको घोखा दिया जाता है, इसके माने यह हुए। कांग्रेस सरकार आपके सामने यह बात साफ़ कहना चाहती है कि अगर हम कर्जा लेंगे तो किसके बल पर लगे। हुकूमत वहां की जनता के बल पर हुआ करती है। चाहे सालबेंट गवर्नमेंट हो वह भी वहां की जनता की हुआ करती हैं। ऐसी सूरत में यह सझाव भी किसी तरह से उचित नहीं मालूम होता है। हां, यह बात अवश्य है कि अगर किसान अपने लगान का दस गुना जमा करके अपनी जमीन का मालिक बनना चाहता है तो वह भी यह समझेगा और उसके कुल के जो बच्चे होंगे उनको भी इस बात का गर्व होगा कि हमारे बुजुर्शों ने जिस जमीन का आधिपत्य हासिल किया है उसका मुआविजा दिया है और इस तरह का मुआविजा दिया है जो कांग्रेस सरकार, (जो जनता की सरकार है) उसके द्वारा जो उचित से उचित मुओविजा निश्चित किया गया है। अगर आप गौर करें तो आपको पता लगेगा कि इस सूत्रे में साढ़े चार करोड़ ए कड़ जमीन है जिसमें से करीब २८० लाख एकड़ जमीन तो बंजर और परती की शक्ल में है ऐसी कुल जमीन जो भी है उसका मुआविजा रक्खा गया है। अगर आप गौर करें तो मालूम होगा कि शायद हमारे जमींदार साहबान को जो दो रुपया इस फ़सल में और दो पया उस फ़सल में जिलेशरों को नजराना देना पड़ता है उससे भी कम है। ऐसी सूरत में इस मुआविजों के बारे में में तो सबझता हूं कि प्रत्येक भारतीय का और सुबे के रहने वाले का यह कर्तव्य है कि वह इस ीजना की सफल बनाने में पूरा-पूरा सहयोग दे क्योंकि में समझता हूं कि इससे अच्छा अवसर किसानों के अपनी जमीन का मालिक बनने का दूसरा नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र में यह बात पहिले भी थी कि किसान जो खती करता है वही पृथ्वी का मालिक है। लेकिन बटिश साम्राज्य ने इसे उलट दिया और जमींदार को जमीन का मालिक बना दिया । इसिलिये इस जनतन्त्र राज्य में सब से पहले इस बात की आवश्यकता थी कि किसान को जमीन का मालिक बना दिया जाय। इस हेतु इस जमींदारी उन्मूलन बिल को लाकर हमारी सरकार ने सूत्रे को रहते वाली जनता का उपकार किया है। उसके लिये में उनको हार्दिक बधाई देता है।

एक सज्जन ने इस बिल के बारे में यह भी कहा है कि ये दोतों कानून अर्थात् जमीं-दारी उन्मूलन और भूमिव्यवस्था एक साथ लाना उचित नहीं है। हमारे माननीय मेम्बर ने यह कहा है कि ये चीजें अलग-अलग हैं। वास्तव में दोनों अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन में तो यह समझता हूं कि यदि किसी चीज को कोई मिटाना चाहता है, किसी प्रथा को अगर कोई मिटाना चाहता है, तो उस प्रथा को मिटाने के बाद हमारी क्या प्रथा होगी, हम किस तरह से उसे चलायेंगे, यह बात भी आवश्यक हो जाती है। अगर कोई सरकार इस तरह से दूरर्दाशता से काम नहीं लेती है तो वह बहुत बड़ी गल्ती करती है। वह तो हमारे लोहिया साहब की योजना के अनुसार होगी (कि जमींदारी २४ घंटे में खत्म हो सकती है)। लेकिन २४ घंटे में जमींदारी खत्म होने में खतरा है जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा। में समझता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के साथ ही साथ भूमि-व्यवस्था हमारी आगे चल कर क्या होगी, यह बात भी हमारी सरकार के लिये बहुते आवश्यक है। अतएव हमारी सरकार ने जो भूमिव्यवस्था की बात रखी है वह भी सर्वथा उचित है और इसी समय रखनी चाहिये। इस सम्बन्ध में बहुत सी दफायें है और उनमें कई प्रकार की बातें रखी गई हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि यह बिल जो है उसमें समाज को वर्गों में बांटा गया है और इसमें कितने ही वर्ग मुक़र्रर किये हैं, जैसे भूमिघर, सीरदार, अधिवासी और असामी। उनका कहना है कि इस तरह से वर्गविहीन समाज बनाने का जो नारा है कि वर्गविहीन समाज बन जाय, यह जो आदर्श या यह चीज इस बिल से पूरी नहीं होती है। लेकिन में नम्म निवेदन करना चाहता हूं कि जरा ग़ौर के साथ विचार करें जहां पर अवध क़ानून लगान अलग हो और आगरा कानून लगान अलग हो उन दोनों को एक में मिलाया गया। इसके अलावा जितने सूबे में काश्तकार हैं, अगर आप विचार

[श्री भगवाद ीन निश्र]

करें नो आपको साजूम होगा कि उस सब बीज को खत्म करके एक ऐसी चीज लाई गई है जिसके आयार पर जल्द से जल्द योड़े समय में एक वर्ग मिहीन समाज बन जायगा। जान जो नू तिवर और वीरदार ने दो चीजे रबी है ये क्यों रखी है ? हमारे कुछ भाइयों ने जिलायन की है कि किसानों के पात पैता नहीं है और इस बजह से वे कैसे भूमियर जन सकते .हैं। यहत से लोगों ने ग़लत प्रोवेगेन्डा भी किया है कि जो पुनिघर नहीं यन सकेंगे उन की भूनि भी गई। यह गलन बात है। हमने यह प्रोजना रेखी है कि जो अपने उद्योग से पूरी प्रश्तन अरके बतग्ता लगान जमा करके जमीन का नालिक वनेगा, वह भूभिधर कहजारेगा। याको लोग जो अत्रोतरह से नहीं बन मकते हैं, उनके रास्ते में भी कोई रुजाबट या रोड़ा नहीं है। वे नौकती कारतकार जैसे आज हैं वैसे रहेंगे। अधिवाकियों के लिने यह दौका दिया गया है कि ५ वर्ष के बाद उनको १५ गुना लगान जमा करके मुमिशर बनने का हक होगा। इसके दारे में कुछ सज्जनों ने अलग-अलग राये प्रजद की हुं अर मैं समझता है कि इसमें अलग-अलग रायें हो सकती हैं। इपले कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने एक पुझे व दिया कि जर आप यह कहते हैं कि सरकार और किसान के बीच ने कोई मध्यवर्ती जमाअत उपूलन नहीं होती चाहिये, तब कोई बजह नहीं साल्य होनी कि ५ वर्ष का इन्तज र उन शिक्सी काश्तकारों के लिये क्यों रखा जाते जबिक आप कहते हैं कि हर समीन का जोतने वाला विभिन्न वन सकता है। लेकिन अगर आप इस पर भी गौर करेकि आपकी सरकार ने जो कानून ये उसमें हमेशा इस बात को रखा था कि हर मौरूसी कार कार अपनी जमीन शिकमी पर उठा सकता है। कभी तीन साल और कभी यांच साल के लिये। आज भी यह कालन मौजूद है। ऐसी अवस्था मे इप व्यवस्था के बनने के बाद, जबकि हमारी व्यवस्था बदल रहो है। मैं यह कह सफता हूं कि ग्राम पंचायतें और इस बिल के पाग होने के बाद हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसमे अगर कोई ऋंशिकारी तब्दीली कही जा सकती दै तो इससे ज्यादा शांतिमय तरीके से वह तब्दीली नहीं हो सकती। इसलिये इं तके अन्दर इस बात को नोका दिया गया है कि जिनको कानून के लिरिये हक देरखाया कि वह जिक्रमी पर जसी देस कते हैं। उनके लिये हक दिया गया है कि वह पांच साल तक इसका फायदा उठ। हैं। बाद को १५ गुना देकर भूमिधरी बन राधाते हैं। अगर कोई समय की कमी करने का मौका दे सकें तो अच्छा होगा। इस पर भी पुनः विचार किया जा सकता है।

इत जिल के तिकतिले में एक बात मैंने प्रवर समिति के सामने रखी थी के किन मुझे दुःख है कि वह बोग प्रचार-समिति की रिपोर्ट में न आ सकी। उस बात को मैं इस हाउस के अपने भी रखना चाहना हूं। आप कांतिकारी परिवर्तन कर रहे हैं और वह शराह-नीय है तो हमें फिर भी जो आप सब की अवस्था है उसे कानून बनाते समय भूलना नहीं चाहिथे। इसको भी अपने मस्तिक में रख कर कानूनी व्यवस्थी करनी चाहिये। अच्छे से अच्छा वही कानून कहा जा सकता है जिसे देश के साथ ठीक तरह क्षे संचालित कर सके । वह केवल कागज परही न रह जाए और जनता उसका दुरुपयोग न करना शुरू कर दे। इसिलघे ऐसे कानून को ज्यादा मुनासिब नहीं कहा जा सकता। इसीलिये मैंने यह निवेदन किया था और हाउस के सामनें भी कह देना आवश्यक समझता हूं आज भी यह दशा है कि बिना सहायक या मजदूर के कोई भी किसान खेती नहीं कर सकता। .जो लोग ड्रैक्टर पर भरोसा करते हैं उनसे भी पूछिए कि क्या केवल द्रैक्टर से ही खेती हो सकती है। इसमें भी मजदूरों की आवश्यकता होती है। आज तक हमारे यही प्रथा चली आई हैं। जो सहायक रहते हैं वह बहुत सी जगह तो हिस्से पर रहते हैं जैसे छः हिस्सों में एक हिस्सा या पांच हिस्सों में एक हिस्सा। लेकिन अब तो मजदूरी प्रथा शुरू हो गई है। मेरा सुझाव यह है कि इस चीज को आप खत्म न करें। इससे आपकी अधिक अन्न उपजाओ योजना को ध^{क्}का पहुंचेगा । जब आप कास्तकार को इतनी सुविधा भी

नहीं देते कि वह मजदूर से या हरवाहे से अरनी जमीन में भदद ले सके। आप कानन वाहें कड़ें ते कड़ें बना है लेकिन अगर वह समय ओर परिस्थित के अनुसार नहीं होता तो जो। उनका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। वह ऐसा करने के लिये मजबूर हो जाने हैं, विवश हो जाते हैं। इसलिये में इस भवन के सामने और माननीय माल सचिव से प्रार्थना करूगा कि वह इस प्रश्न पर फिर से विचार कर ले। इसमें सदेह नहीं है कि आदर्श तो आदर्श हुआ जरते हैं। लेि न सामियक व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ता है। इसकी उपेक्षा करना बुद्धिमानी की बान नहीं होती। एक सज्जन ने यह कहा था कि सवा छः एकड जमीन की व्यवस्था रखीं गई थीं। किंतु हमारी प्रवर—समिति ने ८ एकड़ रखीं है। अभी—अभी हमारे एक मित्र ने बुदेलखण्ड के बारे में कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि कम से कम २० एकड़ रखीं जाए।

लेकिन में यह कहना चाहता हू कि योड़। सा आपविचार करें। जो व्यवस्था चल रही थी, जित्र दावस्था में हर आदमी अपनी परिस्थिति के अनुकूल शिकमी देकर अपनी जीविका भला सकता था, उतमे आप इतना परिवर्तन करें दे कि सव। ६ एकड़ से अधिक वह किसानी नहीं कर सकता तो जेरे ख्याल में यह उतके वाथ ज्याननी होगी, अन्याय होगा। ये सनझा ह कि हर वर्ग के रहन-हिन का एक तरी का होता है, सब का रहन-सहन बराबर नहीं होता, यह द्वारी बात है कि हम इस दात का स्वप्न करे और ईश्वर करे कि वह दिन आये जब हम तब लोग सुली हो, परावर अवस्था मे हो, लेकिन अभी हा में भेद ह, अवस्थाओं में भेद हा पहिचसी जिलों में जहा माधन हैं वहा पर सबाद एकड़ से एक परिवार निर्वाह कर सकता ने, लेकिन पूर्वी जिलो के लिये में माफ कह देना चाहता हू कि वह। सड़को के नाम पर गर्द उड़ती है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तालाबो पर हमारे जर्मादारों और ताल्लुकेदारों के पट्टे हैं जिसके कारण कि नान उन तालाबों से पानी भी नहीं ले सकता। वहा के लिये वही ब्यवस्था रखना कि सवा६ एक द से ज्यादा कोई खेती कर रेके लिये भी नहीं ले सकता। मेरे ख्याल में यह उतके साथ जादती होगी। मैंने तो यह सुझाव दिया था कि १० एकड़ होना चाहिए लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने उसे ८ एकड़ ही रखा। यह भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे कम करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा।

कुछ सज्जनों ने एक बात – बार बार दुहराई है। यह कहा गया है कि जो मुआविजा है उसमें भेद नहीं होना चान्यि। मैं नहीं समझ सहा कि ऐसे लोग जमीदारों के हमदर्द हैं या उनके वास्तव में घातक हैं। यह कहना कि मुआविजे में भेद नहीं रखा जाना चाहिये, साबारण नियम यह है कि हमारी रोज की विनचर्या में भेद हैं, भेद रखा जाना स्वा-माविक सी बात है। किसी के लिये कम खूराक पर्याप्त है और किसी के लिए ज्यादा। ऐसी सूरन में हनारी सरकार ने उन छोटे जमींबारों को भी, जिनकी तादाद १८ लाख के लगभग है, जिनके पास जमीन बहुन कम है उनको भी ८ गुना मुआविजा देती तो वह नहीं के बराबर होगा। हम जो कहते हैं कि हम उनको अपने बल पर खड़े होने का साधन देते हैं गलत त्रोता। इसलिये उन जमींदारों का जो कम से कम जमीदारी रखते है, उनके पास कुछ कारत भी है, जमींदारी से वह निर्वाह नही कर पाते, उनको भी बड़े जमींदारों की तरह ८ या १० गुना मुआविजा देना उचित नही है। हमने अपनी योजना में २० गुने से लेकर २ गुने तक पुनर्वासन अनुदान देने की व्यवस्था रखी है। इसके मानी यह है कि छोटे से छोटा जमींदार २८ गुने तक मुआविजा पा सकेगा। यह बात दूसरी है कि एक पार्टी इस योजना को सामने लाई है, अंतएव उसके बारे में कुछ न कुछ कहना जरूरी है, लेकिन ठंडे दिल से हमारे माननीय सदस्य अगर इस पर विचार करे तो मे समझता हूं कि उनको भी इस बात पर विश्वास होगा कि यह योजना हर प्रकार से उपयोगी है और देश को आगे बढ़ाने वाली है। कुछ लोगों का यह कहना है कि नहीं साहब, इसमें क्या फर्क हो जायगा। में समझता हूं बड़ी भ्रमात्मक बात है, भूल की बात है। एक सीधी सी और मोटी सी बात

[श्री भगवानदीन मिश्र]

है कि अगर कोई आदमी किसी मकान में किरायेदार की हैसियत से रहता है तो वह उस मकान की कितनी परवाह करता है। अगर माननीय सदस्य गौर करेंगे तो उनको यता चलेगा कि किरायेदार और मालिक मकान की हैसियत में कितना फर्क हैं। आज भी जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने कानून के जिरये से सब तरह की सुविधायें देकर किसान की जमीन को काफी सुरक्षित कर दिया है, तब भी दफा ६१ और ७३ के मातहत चार आने की बकाया पर बेदखलियां की गयीं और फिर नजराना बसूल किया गया। ऐसी सूस्त में यह कहना कि साहब, नहीं, उनमें फर्क क्या होगा यह बात गलत है। मालिक बन जाने के बाद उनकी प्रवृत्ति बदलेगी, वे ज्यादा उन्नति कर सकेंगे और सरकार उन की ज्यादा सहायता कर सकेगी, कृषि की उन्नति करने में।

अन्त में एक बात और कहूंगा। यह जो जमींदारी खत्म करने की बात हें, इसमें यह सोचना कि वास्तव में आज स्वतन्त्र भारत में भी जमींदार ही जमीन का मालिक हैं जिसको कि किसान नहीं हटा सकता। सरकार को तो हटा सकता है। किसान को पूरा अधिकार है कि हर तीसरे या पांचवें वर्ष जिस गवनंमेन्ट को उचित नहीं समझता जिस व्यक्ति को उचित नहीं समझता उसको वह अपना अगुवा और मेम्बर नहीं बनायेगा। लेकिन जमींदार को हटाने का कोई हक किसान को नहीं है, क्योंकि जमींदार किसान का बनाया नहीं है। इसलिये वहुत आवश्यक यह बात थी कि स्वतन्त्र भारत में वह प्रथा जो सैकड़ों वर्षों से चली आती थी और किसान और सरकार के बीच में मध्यवर्ती जमाअत थी जो आज भी किसानों का षोषण कर रही है जिससे किसान पनप नहीं सका उसको खत्म करना और भूमि का प्रवन्ध और उसकी व्यवस्था करना यह हमारी सरकार के लिये परमावश्यक चीज थी और सरकार ने इसको बना कर और भवन के सामने लाकर एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है। इसके लिये में सरकार को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। भी

श्री रोशन जमां खां — जनाब डिप्टो स्पीकर साहब! हुकूमत की तरफ से इस ऐवान के सामने आज जमींदारी मिटाने का कानून पेश किया गया है। ऐसे कानूनों पर गौर करने से पहिले एक बड़ा ही अहम सवाल मौजूदा हिन्दुस्तान की हर सियासी पार्टी के सामने आना चाहिये। वह अहम सवाल यह है कि आया जो मौजूदा समाज हमारे मुल्क और सूबे का है उसको हन उसी तरह से कायम रखना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं। अगर आपका फैसला यह है कि हम स्टेट्स को मौजूदा समाज को जैसा कि वह कायम है आयन्दा भी कायम रखेंगे जो मुमिकन है कि आपका इस कानून से कुछ इस्मीनान, संतोष और खुशी हो। लेकिन वह लोग जो कि मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था की, सरमायादारी निजाम को एक सिरे से खत्म करके इस मुल्क के समाज को बराबरी के बुनियाद पर कायम करना चाहते हैं उनके लिये इस कानून में खुशी के बजाय रंज और अफसोत के लिये ज्यादा मुकाभ है।

आज हमारे देश के देहातों में बसने वालों में बहुत से लोग हैं। एक बड़ी लम्बी तादाद उन लोगों की है जो खेतिहर मजदूर कहलाते हैं और उन खेतिहर मजदूरों में तो बड़ी अच्छी खासी तादाद उन लोगों की है जो दिन भर खेतों में वालियां बीनते हैं, दाने चुनते हैं और दिन भर के बाद कहीं जाकर कुछ दाने उनको मिल पाते हैं जिनमें बड़ी मुक्तिल से उनकी बसर होती है। खेतिहर मजदूर दिन भर मजदूरों करता है, लेकिन उसको पूरी मजदूरी नहीं मिलती। छोटे—छोटे किसान हैं जिनके पास छोटे—छोटे रकबे हैं जो उनका ही पेट पालने को काफी नहीं हैं, बाल—बच्चों की कौन कहे। एक जिले की बाबत तो मुझे काफी तौर से मालूस है कि कटहल की दाल उनके हमेशा खाने की चीज रही हैं। छोटे काश्तकारों को छोड़ने के बाद बहुत मामूली सी तादाद उन बड़े काश्तकारों या किसानों की है कि जिनको आप कह सकते हैं कि वे खुशहाल

है। खुद हुकूमत की जमीदारी अबालीशन रिपोर्ट में यह चीज निहायत वजाहत के साथ बयान कर दी गई है कि इस वक्त हमारे सूबे मे ४० फीसदी किसान ऐसे है जिनके वास खाने भर के लिये गल्ला पैदा नहीं होता और न उनके पास और कोई काम को जरिया है। सिर्फ ३३ फीसदी किमान ऐसे है जो मेहनत करते है, काश्तकारी करते है और उनके पास ख।-पीकर सब बराबर हो जाता है। सिर्फ २७ फीसदी किसान ऐसे है कि जिनके पास खाने-पहनने ओर कर्ज अदा करने के बाद कुछ थोड़ा सा बच रहता है। जहा तक जमीदारों का पवाल है छोटे जमींवार मे ५,००० रुपया माल-गजारी तक के जमींदार को नहीं गिनता, बल्कि ढाई सौ रुपया तक मालगुजारी अदा करने बाले को छोटा जमीदार समझता हूं और उनके ऊपर जितने जमीदार है वे बंदे जमीदार है-छोटे जमीदारों की हालत किसानों से अच्छी नहीं है, जो बड़े जमीदार है उनकी हालत जरूर अच्छी है। इस निजाम को इस हालत को, बदलने के लिये अगर हम तैयार है तो हमे एक-दूसरे ही नुक्तेनिगाह से इस सारे कानून पर गौर करना पड़ेगा। हमे ऐसा कानून बनाने से पहिले एक प्लान तैपार करना हागा, एक नकशा नैयार करना होगा, एक लाका बनाना होगा जिसकी बुनियाद पर हम नये-नये इस्लाहात करेगे। लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की पार्टी दोनों ग पिर्फ स्टेट्स कुओ की पार्टी बन कर रह गई है बल्कि साथ ही साथ वह बिला किसो प्लान के हर काम करने के लिये तैयार रहती है। आज हमारे वैजोर माल स(हब ने निहायत फख के साथ फरमाया कि इस कानन के लाने में, कोई देर नहीं हुई है। उन्हां के जिले के दूसरे मुजिजज मेम्बर साहन ने कहा कि न इस कानून के लाने में देर हुई और न जल्यो ही हुई है। ठीक है, यह आपके बमूजिय देर न हो लेकिन मवाल यह है कि जब आपने मन् १९४६ ई० में, बल्कि सन् १९४६ से भी पहले सन् १९४५ में कांग्रेस के मैनिफैरटो में यह लिख दिया था कि हम जमीदारी खत्म करेंगे तो क्या आप जमींदारी को मिटाने में इतनी देर करने के मुस्तहक थे?

डाक्टर राम मनोहर लोहिया की उस स्पीच का हवाला दिया गया है जिसमे उन्होंने कहा था कि २४ घंटे के अन्दर जमोदारी खत्म हो सकतो है और उसका मजाक सा उड़ाया गया है, लेकिन आज क्या काग्रेस के दोस्त इस सवाल का जवाब दे सकते है कि उनके माथी शेख अबदुल्ला वजीरे आजग काशमीर ने किस तरह से एक नोटिफिकेशन के जरिये वहां जमींदारी को खत्म कर दिया और अगर आप हमारे कांग्रेसी दोस्त इस पर बोलते हैं तो में फह दूं, अदब के साथ , कि उन्हें पता नहीं है कि आपकी मरक़जी सरकार और सरदार पटेल ने अबद्दल्ला के इस इरांदे में रकावट डालने की पूरी कोशिश की। २४ घंटे की बात है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर एतराज हो सके। २४ घंटे की चीज का मतलब यह है कि जिस तरह से आप इस कानून के जरिये से आप सरकार को इस बात का अख्तियार देते हैं कि वह एक नोटिफिकेशन जारी करे कि आज से सारी जमीदारी, सारी जायदाद , सारे खेत, सारे हक्क, हुकूमत के पास आ गए, उसी तरह से जब २४ घंटे की बात कही जाती है तो उसका मतलब यह होता है कि अगर आप एक चीज को करना चाहते हैं तो उसके लिये एक ऐलान जारी कीजिए कि आज से जमींदारी खत्म हुई और उसके बाद किसान यह लगान सरकार को अदा करें। दूसरी और जो चीजें है वे बाद को तय होंगी कि मुआविजा दिया जाय या नही।

एक सटस्य--और भी लम्बी स्पीच दें।

श्री रोशन जभां खां--जो, लम्बो स्पीच नहीं है। आप समझ लें ५-६ मिनट और है, कल तकरीर होगी। बहरहाल आप घबराये नहीं, कल और मजेदार तकरीर सुनेंगे और मुमिकिन है कि इस ऐवान में गर्मी भी पैदा हो। मैं आज तो चाहता नहीं कि इस ठंडक में ज्यादा गर्मी पैदा करें क्योंकि आप लोगों को शायद ज्यादा तकलीफ मससूस होगी।

एक सदस्य-न्या जमींदारी एक नोटिफिकेशन के जिर्ये से खत्म हो सकती है।

श्री रोशन जमां खां—हमारे करीब में बैठे हुए कांग्रेसी दोस्त फरमाते है कि क्या जमींदारी एक नोटिफिकेशन के जित्ये खत्म हो सकती है। अफसोस है, शायद उन्होंने मौजूदा बिल को पढ़ा नहीं। उसमें खुद ही लिखा है कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे कि जमींदारी खत्म कर दी गई और फिर सारे हुकूक हिज मैजेस्टी या गवर्नमेंट मे बेस्ट हो जायेंगे। फिर कैसे कांग्रेस बेंचेज पर बैठे हुए लोग ऐसी बात कर सकते हैं! हां! अगर वह किसी चीज को पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते तो बात और है।

जहां तक डिले (देरी) की बात है उसके लिये तो हमारे वजीरे माल साहब बहुत ज्यादा मुजरिन हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव आया, हमारे वजीरे माल साहब ने सूबे का दोरा किया, हर जगह कहा कि अब के आइन्दा जून तक, हमारी रिपोर्ट शाया हो जाएगी। अप्रैल, १९४८ ई० में एलेक्शन हो रहा था।

माननीय मान सचिव—मं अपने लायक दोस्त को याद दिलाना चाहता हूं कि बजट सेशन के सिलिसले में मुझसे जब सवाल किया गया कि पहिली जून तक क्या जमींदारी खत्म हो जायगी तो मैंने जवाब दिया था कि यह पहिली जून तक कैसे हो सकता है, जो आप फरमाते हैं मैने नहीं कहा।

श्ची रोशन जमां खां—हमारे माल सचिव ने सुनने की कोशिश नहीं की। मैने बजट स्पीव का हवाला नहीं दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन का जो अप्रैल १९४८ ई० मे हुआ या और उसके सिलसिले में आयने जो दौरा किया था उसका हवाला दे रहा हूं। उसमें आपने कहा था कि जून १९४८ ई० तक हमारी रिपोर्ट शाया हो जायगी और गोरखपुर पहुंच कर वहां वह तकरीर की जो सर जगदीश प्रसाद को ही जेबा देती है, वहां उन्होंने कहा कि हमें जमींदारी का बहुत ज्यादा इन्तजाम करना है इसलिये ऐसे मामले में देरी होना जरूरी है। बजट का सेशन जब आया और उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जमींदारी मिटाने का सवाल सिर्फ चन्द महीनों का है। जनाब वाला चन्द महीना क्या साल भर हो गया, मैं अर्ज करूंगा कि इस कानून के लाने में और इस कानून के बनाने में सरकार की तरफ से बहुत काफी देरी हुई है।

एक सदस्य-यह आपकी हौसला अफ़जाई के लिये।

श्री रोदान जमां खां—जो प्लान कि अब तैयार किया गया है उसी से साबित है कि सरकार ने जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में जो बातें कहीं, जब बिल इस ऐवान में आया तो उसमें पूरे तौर पर उन उमूलों को जो जमींदारी अबालीशन कमेटी ने बनाये थे, खत्म किया गया। इसके बाद जो उमूल उन्होंने इस बिल में रखे थे उनको इस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में खत्म करने की कोशिश की गई है और जनाब वाला एक चीज और में इस ऐवान की तवज्जह के लिये कहे देता है और यह हक़ीकत है कि इस ऐवान के बाहर इस वक्त कांग्रेस के मुकाबले में एक ही विरोधी दल है और वह सोशिलस्ट पार्टी है। इस सोशिलस्ट पार्टी के मेम्बर जो इस ऐवान में सिर्फ तीन हैं उन्होंने इस बात को अपनी तौहीनी समझा कि वे यह कहते कि हम लोगों को भी सेलेक्ट कमेटी में जगह दी जाय। लेकिन क्या आपका यह फर्ज नहीं था और आप जबिक एक डेमोकेटिक पार्टी की हैसियत से काम करना चाहते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि एक सही विरोधी दल को राय सेलेक्ट कमेटी में शामिल हो, तो आपका यह फर्ज था कि सेलेक्ट कमेटी में उनमें से यानी सोशिलस्ट पार्टी में से लेते। लेकिन आपने सोशिलस्ट पार्टी, जो कि एक प्रोग्नेसिव प्रगतिवादी प्रतिक्रियावादी संस्था है, उसके बजाय रिऐक्शनरी, प्रतिक्रियावादी रज—अत पसन्द लोगों को सेलेक्ट कमेटी में भरने की कोशिश की। उसका नतीजा यह हुआ

कि नोट आफ डीसेन्ट जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में देखने को मिलता है वह प्रतिक्रिया— बादी और रजअत पसन्द लोगो का तैयार किया हुआ है, जो तरक्की पसन्द जमाअत का नुक्तेनिगाह हो सकता है, उसकी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में झलक नहीं है।

डिप्टी स्पीकर—अब हम उठते हैं। आप अपनी तकरीर कल जारी रिखए। (इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

> कॅलासचन्द्र भटनागर, मन्त्रो, लेजिस्लेटिव असेम्बली, संयुक्त प्रान्त ।

लखनऊ, ९ जनवरी, सन् १९५० ई०।

नत्थी 'कं (देखिये नारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

विवरण-पत्र लोहा १--मुजफ्फरनगर १२टन ५--मेरड ३३ " ३——अलीगढ ₹0 ,, ८--आगरा 26 ,, ≺—मैनपुरी ₹ ,, इ--बरेली ₹ " ७---बिजनौर ₹ " ८--मुराहाबाद ξ,, ९—इटावा ₹ " २०--कानपुर १८ ,, ११--जौनपुर 28 " १२--देवरिया १२ ,, १३--आजमगढ ξ,, १४--नैनीनाल Ę " १५--लखनऊ १२ " १६--फैजाबाद 84 ,, १ ७-- प्रतापगढ ४२ ,,

नत्थी 'ख'
(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)
युक्त प्रान्तीय तेल की कम्पनियों द्वारा अलग-अलग प्रतिमास प्राप्त किये हुए पेट्रोल की
मात्रा का विवरण

(१) अक्तूबर सन् १९४८ ई० से जून सन् १९४९ ई० तक

ऋम- संस्या	महीनों के नाम		बर्मा शेल आयल कं०	इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कं०	कैल्टेक्स इंडिया कं०	स्टेंडर्ड वैकुअम आयल कं०
			गैलन	गैलन	गैलन	गैलन
8	अक्तूबर, १९४८	- •	५,१२,४९६	१,१४,६८७	१,६१,३०२	१,६२,९५५
2	नवम्बर, १९४८		५,०१,७४९	१,४२,१३९	१,६२,५६७	२,२२,२०४
7	दिसम्बर, १९४८	• •	६,५२,८८४	१,७८,३८०	२,२०,४८९	°? २,७१,१७७ {
. ४	जनवरो, १९४९ 🖟 🎉	• •	६,७१,०८० }}	१,०५,२१०	१,३२,६८२	*
ધ	फरवरी, १९४९	• •	६,००,०३१	१,१०,१२६	१,७३,९६४	२,०४,८२८
Ę	मार्च, १९४९	• •	७,८०,३६७	१,५१,७१७	२,०४,८०९	३,३८,०७३
و	अप्रैल, १९४९	••	८,३८,०००	१,११,४६०	१,६१,९४०	२,३९,९००
2	मई, १९४९	Great	८,०७,३११	१,३६,९७०	१,९९,९६०	२,६३,६९८
8	जून, १९४९	• •	८,१९,१८४	१,१६,२७२	१,६५,५६०	१,६८,८२२

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर) विद्यालयां के महायक निरीक्षका (डिप्टी इन्सपेक्टरें) के लिये नौकरों के नियम

- ५—(१) भर्ती के साधन—(अ) इन नियमों के पांचवे भाग में निर्धारित प्रत्यक्ष रीति के अनुसार तथा
- (आ) इन नियमों के छठवे भाग में निर्घारित रीति के अनुसार उप-सहायक निरीक्षकों (सब-डिप्टी इन्सपेक्टरों) की पदोन्नित द्वारा.....नौकरी में भर्ती की जायगी।

किन्तु प्रत्येक तीन स्थायी रिक्त स्थानों में से दो की पूर्ति प्रत्यक्ष द्वारा तथा तृतीय की पूर्ति किमी उप-सहायक निरीक्षक (सब-डिप्टी इन्सपेक्टर) की पदोन्नति द्वारा की जायगी।

- (२) किन्तु प्रत्यक्ष भर्ती से संबंधित नियमों की अभीष्ट दशाओं की पूर्ति करने की अवस्था में उप-महायक निरीक्षकरण (सब-डिप्टी इंसपेक्टरों) भी सहायक निरीक्षण (सब-डिप्टी इन्सपेक्टर) स्वरूप प्रत्यक्ष भर्ती के लिये समर्थ हो सकेंगे।
- ८-व--(अ) नियम ५ (१) (अ) के अन्तर्गत भर्ती किये जाने वाले पदार्थी का वय भर्ती-वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को निश्चित रूप से पूरे २८ वर्ष का होना चाहिये और पूरे ३३ वर्ष से कम होना चाहिये।
- (आ) ५ (१) (अ) के अन्तर्गत भर्ती किये जाने वाले पदार्थी का वय भर्ती-वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को पूरे ५० वर्ष से कम होना चाहिये।
- ९—ि शिक्षा संबंधी योग्यताये—िनयम ५ (१)(अ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष भर्ती के लिये तब तक समर्थन होगा जब तक कि—
- (१) उसने संयुक्त प्रान्त में विधिपूर्वक संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा गवर्नर द्वारा इस हेतु मान्य अन्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि तथा शिक्षा की ऐसी उपाधि के अभाव में गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज अथवा गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज, प्रयाग के एल० टी० का उपाधि—पत्र अथवा लखनऊ या आगरा के गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेजों में से किसी का प्रमाण—पत्र अथवा इस हेतु युक्त प्रान्त में विधिपूर्वक संस्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा गवर्नर द्वारा मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की शिक्षा का उपाधि—पत्र न प्राप्त कर लिया हो, तथा
- (२) बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमोडियेट एजूकेशन, युक्त प्रान्त द्वारा संचालित हाई स्कूल की अथवा युक्त प्रान्त की विभागीय परीक्षा के रिजस्ट्रार द्वारा संचालित वर्तमान भारतीय भाषाओं की विभागीय विशिष्ट परीक्षा (डिपार्टमेटल स्वेशल इक्जामिनेशन) जैसीकोई सार्वजनिक परीक्षाओं द्वारा परीक्षित प्रान्त की किसी एक भाषा (उर्दू अथवा हिंदी) का पर्याप्त ज्ञान न रखता हो, तथा
- (३) किसी मान्य पाठशाला में शिक्षक स्वरूप अथवा उप-सहायक निरीक्षक (सब-डिप्टो इसपेक्टर) स्वरूप कम से कम ३ वर्षों की अनुमोदित सेवा न की हो।

विद्यालयों के उप-सहायक निरोक्षकों (सब-डिस्टी इम्सपेक्टरों) के लिये नौकरी के नियम

तृतीय भाग-भर्ती

५--भर्ती--नौकरी में भर्ती प्रत्यक्ष रूप से तथा-

(१) इन नियमों के पांचवें भाग में निर्धारित रीति के अनुसार प्रधानाध्यापकों के अनिरिक्त अन्य व्यक्तियों में से क्यार

(२) इन नियमो के छठवे भाग में निर्धारित रीति के अनुसार प्रधानाध्यापकों में से की जावेगी

किन्तु स्थायी रिक्त स्थानो में भर्ती इस प्रकार से की जावेगी कि इस श्रेणी के १० प्रतिशत स्थानो पर सदैव प्रधानाध्यापक नियुक्त रहेगे।

- ६--माम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व--(१)पाचवे नियम के अतर्गत नौकरी में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्तिया करते समय विभिन्न सम्प्रदायो को उचित प्रतिनिधित्व देने तथा किसी एक वर्ग अथवा सम्प्रदाय के वाहुत्य को रोकने के लिये उचित ध्यान रखा जायगा।
- (२) शिक्षा विभाग में सचालक किसी विशिष्ट सम्प्रदाय अथवा वर्ग के लिये सुरक्षित रखे जाने वाले स्थानों की संस्था का निणय करेंगे तथा निर्णय की सूचना कमीशन को देंगे।
- ८—वय जिस वर्ष में भर्ती की जाने को है, उमकी जनवरी के प्रथम दिन की भर्ती किये जाने वाले पदार्थी का वय।
- (१) नियस ५ (१) के अन्तर्गत निश्चित रूप से पूरे २२ वर्ष का होना चाहिये और पूरे ३० वर्ष से कम होना चाहिये।
- (२) नियम ५ (२) के अतर्गत निश्चित रूप से पूरे ३० वर्ष का होना चाहिये और पूरे ४५ वर्ष से कम होना चाहिये।
- ९--शिक्षा सबधी योग्यताये नियम ५ (१) के अतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष भर्ती के लिये नब तक समर्थ न होगा जब तक कि --
- (१) उसने सयुक्त प्रान्त में विधिपूर्वक सस्थापित किसी विश्वविद्यालय की अथवा गवर्नर द्वारा इस हेतु मान्य अन्य किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि तथा शिक्षा की ऐसी उपाधि के अभाव में गवर्नमेट ट्रेनिंग कालेज अथवा गवर्नमेट बेसिक ट्रेनिंग कालेज प्रयाग के एल ० टी० का उपाधि—पत्र अथवा युक्त प्रान्त की विभागीय परीक्षाओं के रिजस्ट्रार द्वारा प्रदत्त आगल—हिन्दुस्तानी परीक्षक का प्रभाण-पत्र अथवा युक्त प्रान्त में विधिपूर्वक संस्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा गवर्गर द्वारा मान्य किसी अन्य विश्वविद्यालय की शिक्षा का उपाधि—पत्र न प्राप्त कर लिया हो तथा—
- (२) बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इटरमीडिएट एजूकेशन युक्त प्रान्त द्वारा सर्वालित हाई स्कूलों की अथव। युक्त प्रान्त की विभागीय परीक्षाओं के रिजस्ट्रार द्वारा सर्वालित विभागीय विशिष्ट हिन्दुस्तानी परीक्षा (डिपार्टमेटल स्पेशल वर्नाक्युलर इक्जामिनेशन) जैसी कोई सार्वजिनक परीक्षाओं द्वारा परीक्षित प्रान्त की किसी एक भाषा (उर्दू अथवा हिन्दी) का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। किन्तु उपर्युक्त परिच्छेद (१) में निर्धारित योग्यताओं के प्रति परिगणित जाति के पर्वाथयों के लिये युक्त प्रान्त के विभागीय परीक्षाओं के रिजस्ट्रार द्वारा प्रवत्त आगल-हिन्दुस्तानी शिक्षक का प्रमाण-पत्र न्यूनतम योग्यता होगी।
- (३) नियम ५ (२) के अतर्गत भर्ती किये जाने वाले प्रधानाध्यापको की दशा में जिन्होने हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन युक्त प्रान्तीय द्वारा सचालित हाई स्कूल परीक्षा अथवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हे वरीयता दी जायगी।

नत्थी 'घ' (देखिये तारांकित प्रक्त ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ .पर) शिकायतों की सूची

तिथि नाम ए २० छ०	० । ज्ञिकायत का सारांश	शिकायत पर कार्रवाई
२४-१-४९ श्री अदील अन्वाम	पर न पहुंचने के विषय में	दी गई है।
	(ब) गाड़ी की रफ्तार २० मील से अधिक होने के विषय में	गाडी के अन्दर लगा हुआ स्पीड कंट्रोलर गैस्केट फिर से चेक किया गया।
	(म) गाड़ी के अन्दर धूल अधिकता से आने के विषय में,	गाड़ी के अन्दर फर्झ की दराजे लोहे की पत्तियों से और दरवाजे के पास की दराजें लकड़ी तथा रबड़ लगाकर बन्द की गई और कानपुर सेंट्रल वर्कशाप को भी गाड़ियों में इस शिकायत को दूर करने की सूचना दी गई।
	(ड) स्टेशन पर यात्रियों का सामान रखने के लिये कृलियों के विषय में	कुलियों का पर्याप्त प्रबन्ध स्टेशन पर किया गया है ।
	(क) ३६१८नं० की गाड़ी में शिकायत की किताब न मिलने के विषय में	कन्डक्टरको आगाहकर दिया गया है ।
	(ख) ३९१८ नं० की गाड़ी पुरानी होने के विषय में	गाड़ी की मरम्भत कर दी गई
	(ग) गाड़ी में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की असुविधा के विषय में	गाड़ी में खड़े हुए यात्री मोटर गाड़ी विघान १४० (अ) के अनुसार ले जाये जाते हैं। खड़े होने का टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को दिया जाता हैं, जिन्हें बहुत थोड़ी दूर जाना होता है।
२६–१–४९ श्रो मी० सुलेमान	अन्दर से टिकट न मिलने के विषय में	यात्रो खिड़की पर लाइन में खड़े होकर बाहर से टिकट ले सकते हैं। अन्दर से टिकट बांटने की प्रथा ठीक न होने से किसी को अन्दर टिकट नहीं दिया जाता।
२६-५-४९ श्री रामेश्वर लाल	(अ) लकड़मंडी स्टेशन पर कुलीन होने के विषय में	उचित प्रबन्ध कर दिया गया है।

নিখি	नाम एम० एल०	ए० शि	हायत का सारा श	शिकायत पर कार्रवाई
		ं का ग	इमंडी स्टेशन पर पा ल होने की आवश्य- के विषय में	नी प्रबन्ध किया जा रहा है। -
		(स) लकड के उ		फ प्रबन्ध कियाजारहाहै। त
		टीन व	तरखाने की छत के बजाय फूस का ∶होने के विषय मे	मुसाफिरखाने की छते छप्पर की नहीं बनाई जा सकती है क्योंकि उनमें आग लगने की अधिक संभावना है। टीन की छतो के नीचे लकड़ी के तख्ते इत्यादि लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।
		(क) लकड़ गाड़िय	मडी स्टेशन से ाबढ़ाने के विषय में	यात्रियोकी अधिकता होने परया और कोई खास वजह माल्महोतोगाड़ियांबढ़ाई जातो है।

नत्थी 'ङ' (देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

जिला इलाहावाद

प्रश्न- संख्या	नाम और पता	सिफारिश करने वाला	जेल जाने की अवधि
१	श्री काझीनाथ जैसवाल, क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद	एस० पी० स	न् १९४२ के आंदोलन मे तीन साल की सजा
ą	श्री छोटेलाल गुप्ता, शंकरगढ़, इलाहाबाद	सुपरिन्टेंडेंट पुलिस स	ान् १९४२ के आंदोलन में १साल की सजा
rin.	श्री रामेश्वर त्रसाद, खुल्दाबाद, इलाहाबाद	सभापति, जिला कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद	n
ሄ	श्री भगवान दोन, निहालपुर, इलाहाबाद	डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट स	न् १९४२ के आंदोलन मे ८ माह की सज्जा
ų	श्रोमती गिरीश कुमारी, बरांव कोठी, इलाहाबाद	सरकार को आज्ञासे ए	क राजनीतिक पीड़ित की आश्रिता
Ę	श्री अल्लाबस्स, अटाला, इलाहा— बाद		न् १९४२ के आंदोलन ों संपत्ति लूट ली गई
હ	श्रो यदुनाथ सिंह, शहरारा वाग़, इलाहाबाद	सालिगराम जैसवाल एम० एल० ए०	कई आन्दोलनों में जेल गये तथा एक साल तक फरार रहे

नत्थिया ७७

१६४६ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ज़र्मीदारी-विनाश ख्रीर भूमि-व्यवस्था बिल पर संयुक्त विशिष्ट समिति (ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी) की रिपोर्ट

१——जमीदारी—विनाश और भूमि—व्यवस्था बिल विचार करने के लिये संयुक्त विशिष्ट समिति को सौपा गयाथा। हम लोगों ने, जो इस समिति के मेम्बर हे, इस बिल पर विचार किया है और अपनी रिपोर्ट के साथ नत्थी करके संशोधित बिल प्रस्तुत करते हैं।

२—सिमिति ने २, ३, ५, ६, ७, ८ सितम्बर को और २४ से २९ अक्नूबर तक और ११, १३ और १४ नवम्बर तथा ४, ५, ६, १९ और २१ दिसम्बर, १९४९ ई० को अपनी बैठकें कौसिल हाउस में की।

३—हमने बिल की प्रत्येक धारा पर वाद—विवाद किया है और उसमें बहुत से संशोधन किये है, जिनमें से सब संशोधन समान महत्व के नहीं है। हमने बहुत से ऐसे परिवर्तन किये हैं जिनसे महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर प्रभाव पड़ता है। अन्य संशोधन या तो केवल वाक्य—रचना (आलेखन) सम्बन्धी है या दूसरे संशोधनों के परिणामस्वरूप करने पड़े हैं इस रिपोर्ट में केवल उन्हीं संशोधनों की चर्चा की गई है जिनका प्रभाव महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर पड़ता है। अन्य संशोधन हमारे दोहराये हुये बिल के आलेख से मालूम हो जायेंगे।

अध्याय १

प्रारम्भिक

४—इस बिल की घारा १ (२) में उन क्षेत्रों का विवरण दिया है जहां पर यह बिल लगा न होगा। इस घारा के उपखंड (ग) मे यह निदेश है कि यह बिल ऐसे आस्थानों पर लगा न होगा जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये अधिकार में रखे गये हों या प्राप्त किये गये हों। "सार्वजनिक प्रयोजन" पद विवादास्पद है। अतएव हमने यह काम सरकार के लिये छोड़ दिया है कि वह इस बात की घोषणा करे कि सार्वजनिक प्रयोजन क्या है। इस सम्बन्ध में हमने उपधारा (२-क) बढ़ा दी है, जिसमें यह निदेश रखा गया है कि इस विषय में प्रान्तीय सरकार की घोषणा निश्चायक होगी। इस सम्बन्ध में एक अपवाद यह रखा गया है कि ऐसी भूमि जो ७ जुलाई, १९४९ ई० से पहले गृह-निर्माण की किसी योजना के लिये प्राप्त की गई हो, सार्वजनिक उपयोगिता के किसी निर्माण-कार्य के लिये प्राप्त की गई समझी जायगी। हमारी राय में यह बात आवश्यक थी, ताकि विकास की योजनाओं को घक्का न पहुँचे।

हाल ही में संयुक्त प्रान्त में विलीन हुये बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल राज्यों के प्रदेशों को मिम्मिलित करने के प्रयोजन से हमने एक नये खंड (घ) का भी समावेश कया है।

्यारा २ में यह व्यवस्था की गई है कि यह बिल ऐसे किसी क्षेत्र पर लागू को या तो म्युनिसिपेलिटी, नोटीफाइड एरिया, कंट्नमेंट या टाउन एरिया घोषित किया गया हो या इसके बाद घोषित किया जाय या उसमें सिम्मिलित हो। यदि कोई ऐसा क्षेत्र, जिसमें इस बिल के निदेशों के अवीन नये अधिकार उत्पन्न होते हों, बाद में किसी म्युनिसिपेलिटी में मिला लिया जाय. तो यह बात स्पष्ट नहीं होती है कि इसका नये प्राप्त किये ये अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस असंगति (anomaly) को दूर करने के लिये हमारी यह राय है कि इस बिल के निदेशों में ऐसे म्युनिसिपल क्षेत्र ही सिम्मिलित किये जाने चाहिये जो ७ जुलाई, १९४९ ई० को विद्यमान थे अर्थात् उस दिनांक को विद्यमान थे जब यह बिल व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किया गया था। नये म्युनिसिपल क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था होगी यह बात एक पृथक् विधान का विषय होगा, जिसका प्रस्ताव उद्देश्यों और कारणों के विद्यरण में किया गया है।

—हमने "पट्टा" और "बान" शब्दों की दो अतिरिक्त परिभाषाओं श किया। ये परिभाषाये अध्याय ६ के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हैं जिसमें बानों और बनिज पदार्थों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। हमने पट्टे की परिभाषा में शिकमी पट्टा (sub-lease), भावी पट्टा (prospecting lease) या पट्टे पर या शिकमी पट्टो (sub-lease), भावी पट्टा (prospecting lease or sub-let) भी सम्मिलित किया है। हमने "बान" की परिभाषा यों एख दो है कि इसमें ऐसा खोदा हुआ गर्त सम्मिलित है जहां पर बनिज पदार्थों को बोजने या प्राप्त करने के लिये कोई काम किया गया हो या किया जा रहा हो, किन्तु उसमें तत्सम्बन्धी कोई निर्माण कार्य, मशीनें, टामचे " साइडिंग (siding) सम्मिलित न होंगे। हमने यह बात भी कह दो है कि केवल इसी दशा में चालू समझी जायगी जबकि उसमें काम प्रारम्भ होने की थारा १ डियन माइंस ऐक्ट, १९२३ की घारा १४ के अधीन दी गई हो।

ाने "गांव" शब्द की परिभाषा विस्तृत कर दी है, जिससे कि उसमें ऐसी हा भी समावेश हो जायगा जबकि सम्पूर्ण गांव एक ही जगह पर न हो या गांव के भिन्न-भिन्न भाग भिन्न-भिन्न जिलों में पड़ते हों।

७—हमने पहले अध्याय की धारा ४ निकाल दो है, जिसमें यूनाइटेड प्राविसेज बेन्यू ऐक्ट, १९०१ ई० और यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ ई० के उन क्षेत्रों में रह किये जाने का वर्णन है जो धारा ६ के अधीन जारी की गई विज्ञाप्ति में दिए गये हैं। हमने अध्याय १२ में, जिनमें विविध विषयों का वर्णन किया गया है, निवर्तन (repeal) के सम्बन्ध में व्यापक शब्दावली में एक नई धारा का समावेश किया है।

अध्याय २

मध्यवतियों के रतत्वों का हरतगत किया जाना और उसके परिणा

घारा १ और १४

८—घारा ५ में इस आज्ञय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित करने की व्यवस् गई है कि प्रान्तीय सरकार ने संयुक्त प्रान्त में स्थित सभी आस्थानों को हस्तगत का निश्चय किया है। हम इंग् प्रकार की घोषणा को अनावश्यक समझ् विज्ञेषतः संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विज्ञेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९ के प्रवर्तित हो जाने के बाद। अतएय हमने इस घारा को निकाल दिया तदनुसार घारा ६ तथा ७ में परिवर्तन कर दिये हैं।

९—धारा ८ के विषय के सम्बन्ध में बहुत कुछ बहस हुई। हमन यह किया कि कुओं को स्वत्वाधिकार में लाने की बात को छोड़ कर इस धारा न काई और परिवर्तन न किया जाए। अतएव हमने यह व्यवस्था की ह कि ऐसे निजी कुओं के अतिरिक्त जो आबादियों, खातों अथवा बागों में स्थित है, सभी कुयें महामहिम (Flis Majesty) को हस्तान्तरित हो जायेंगे और उनके स्वत्वाधिकार में आ जायेंगे।

अभिप्राय को और अधिक रपष्ट करने के लिये हमने इस बिल में प्रयुक्त शब्द "हाटों" और "बाजारों" के बाद शब्द "मेलों" बड़ा दिया है।

हमने घारा ८ में एक पृथक् खं (ज्ञ) बढ़ाया है, जिसका अभिप्राय यह है कि स्वत्वाधिकार में आने के दिनांक पर सब वर्तमान महाल और उनके सब उप-विभाग और मालगजारी की अदायगी के सब अनुबन्ध समाप्त हो जायेगे। स्वत्वाधिकार में आने का यह अनिवार्य परिणाम है और हमारी राय में इस बात का स्पष्ट निरूपण कर देना शरा १५

१०—हमने धारा ९ के खंड (ख) में से शब्द "नियत किये जाने वाले" विये हैं जिससे कि ऐसे सब देय (dues) जो स्वत्वाधिकार के दिनांक वसूल किये जाने योग्य हो गये हों, अब भी उसी तरह से वसूल किये जा सकेंगे अब तक किये जाते थे।

रा १७

११—धारा १० और ११ में यह व्यवस्था की गई है कि निजी जंग मीनाशयों के सम्बन्ध में जो संविदें (मुआहिदें) ८ अगस्त, १९४६ ई० के बाद हों, वे स्वत्वाधिकार के दिनांक से व्यर्थ (void) हो जायंगे, किन् दिनांक से पहिले के संविदों (मुआहिदों) पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिप्राय के सम्बन्ध में सम्भव सन्देहों को मिटाने के लिये हमने घारा ११ दिया है और उसके निदेशों को घारा १० की एक उपधारा के रूप मे भाषा व रख दिया है।

त १८

१२—धारा ८ (क) में कुओं के स्वत्वाधिकार में आने के सम्बन्ध में परिवर्तन के अनुरूप ही हमने घारा १२ में आवश्यक परिवर्तन किया है। इससे पह बात

स्पष्ट हो जाती है कि आबादियों, खातों अथवा बागों में स्थित केवल निजी कुओं को ही उनके वर्नमान स्वामी अपने अधिकार में रखेगे। अन्य सब कुएं महामहिम (H.s Malesty) के म्बत्वाधिकार में आ जायंगे।

१३-- उन सीरदारों की सीर की हदबंदी की व्यवस्था धारा १३ में की गई है, जो यूनाइटेड प्राविसेज टेनेसी ऐक्ट की धारा १६ के निदेशों के अनुसार २५० ६० के ऊपर मालगुजारी देते हो, ताकि ऐसे खेत जिनमें काइतकारों ने मौरूसी अधिकार प्राप्त कर लिये हों, अन्य खेतों से पृथक किये जा सकें। इस घारा के सम्बन्ध में **दो वातों पर वाद-विवाद हुआ:--**

- (१) मीर की हदबन्दी की जो व्यवस्था इस घारा में की गई है क्या उसे छोड दिया जाय, और
- (२) यदि हदबन्दी (demarcation) की व्यवस्था न की जाय, तो दया सीर के सब काश्तकार धारा २१ (क) के अधीन अधिवासी हो जायं या उन सबको मौह्सी काश्तकार घोषित कर दिया जाय, ताकि वे धारा २० के अधीन सीरदार हो जायं।

हम सब लोग इस बात से सहमत थे कि हदबन्दी सम्बन्धी कार्रवाइयों के कारण अध्याय ३ के अधीन प्रतिकर निर्धारित करने में बहुत विलम्ब होगा और इसलिये इसे छोड़ दिया जाय। हम लोगों ने बहुमत से यह भी तय किया कि २५० र० से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों की सीर के सब काव्तकारों को मौकसी काव्तकार बना दिया जाय। तदनुसार हमने इस धारा की वाक्य-रचना फिर से की है और घारा १४ में आवश्यक परिणामी परिवर्तन कर दिया है।

१४-मध्यवर्तियों के अधिकारों को हस्तगत करने के कारण किसी ठेकेदार की निजी जोत पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन घारा १५ में किया गया है। यदि किसी ठेकेदार की निजी जोत की भूमि किसी मध्यवर्ती की सीर या खुदकाइत हो तो वह घारा १९ के अघीन उक्त मध्यवर्ती की भूमिघरी हो जायगी और ठेकेदार उसका असामी हो जायगा जो ठेके की अविध समाप्त होने पर या स्वत्दाधिकार में जाने के दिनांक से ५ वर्ष व्यतीत होने पर, जो भी अवधि कम हो, बेदखल हो सकेगा। यदि ठेकेदार की निजी जोत की भूमि सीर या खुदकाश्त से भिन्न हो और उसका क्षेत्रफल ५० एकड़ से अधिक न हो, तो ठेकेदार उसका मौरूसी काश्तकार समझा जायगा और वह घारा २० के अवीन सीरदार हो जायगा। यदि क्षेत्रफल ५० एकड़ से अधिक हो, तो वह ५० एकड़ का मौरूसी काश्तकार हो जायगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि किसी कृषि-फार्म का भाग न हो और उस फार्म को कुशलता और सफलता से चलाने के लिये और अधिक क्षेत्र आवश्यक नही। ऐसी दशा में कलेक्टर उसको मौरूसी काश्तकार के रूप में अपने पास ५० एकड़ से अधिक भूमि रखने का अधिकार दे सकता है और इसके लिये उसको मौरूसी दरों से लगाये ाये लगान से पांच गुनी धनराशि देनी होगी। हमने इन निदेशों पर काफी सोच-

विचार किया है और हमारी यह राय है कि ५० एकड़ की सीमा को घटा कर ३० एकड़ कर दिया जाय। बिल में अधिक मे अधिक ३० एकड़ भ्नि की जोत रखी गर है। हमें इस बान का कोई स ल कारण नहीं पालून होता कि स्वत्वाधिकार येजाने के दिनाक के बाद किसी ठेकेदार को उसी ३० एक ३ भूमि से अधिक भूमि रखने की अनुमति दी जाय, क्योंकि उसको उसके ठेकेदारों के अधिकारों की हानि के बदल में, प्रतिकर देने की ध्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त हमे यह भी मालूम होता है कि किसी ठेकेदार को अपने कब्जे में स्थायीरूप से ३० एक ड' से अधिक भूमि रखने की अनुभित नहीं दी जानी चाहिये, चाहे वह किसी कृषि-फार्म के प्रयोजन के लिए ही क्यों न अभे क्षित हो। प्योंकि यदि उसने ठेके पर ली हुई भिम पर फार्म का काम शुरू किया है तो उसने यह काम इस बात की पूरी जानकारी के साथ किया है कि ठेका अपनी अप्रिय के समाप्त होने पर जत्म हो सकता है। अतएव हवारा यह मत है कि उसको ३० ए र से ऊपर की उस भूमि मे केवल असामी के अधिकार दिये जायं जिपे क केन्टर किसी कृषि-फार्म के सुवार ओर सफल संचालन के लिये आव-श्यक समझे ।

हमने इस या। को भो ध्यान भे रखा है कि ठुछ स्थान में बहुत वडी संख्या में धारा १४-क इस अभित्राय से ठेके दिये गये है कि ठेहेदार, ठेके में दी गई भूबि के चड़े भाग में स्वयं खेती करे। ऐसी दशाओं में काश्त कारी के पट्टे दिये जाने चाहिये थे, किन्तु ठेकों का निष्पादन इस प्रयोजन से किया गया कि उन्त भूमि से मोरूपी अधिकार उत्पन्न न होसकें। इसलिये हमने ऐसे ठेकेदारो को धारा १५ के प्रतिबन्धो से अलग रखा है और इसके लिये एक नई घारा १४ (क) का समावेश किया है, जिसमे यह निदेश किया गया है कि यदि ठेके के सम्बन्ध में यह बात मालूम हो कि वह ठेकेदार द्वारा स्वयं खेती करने के प्रयोजन से दिया गया है तो ठेकेदार मौक्ति काश्तकार समझा जायगा।

१५--धारा १७ में ऐसी संपुत्रन सीर या अन्य भूमियों की हदबन्दी की व्यवस्था की गई है जो संयुक्त रूप से सहभागियों के रुक्जे मे हो। वाक्य-रचना की दृष्टि से ठेकेदार की निजी जोत की भूतियां भी इस धारा के अन्तर्गत आ जातो है जो कि स्पष्टतः इस भारा का अभिप्राय नहीं है। अतएव हमने पंक्ति २ मे आये हुये ज्ञब्द "मध्यवर्ती" के बाद शब्द "जो ठेकेदार न हो" यदा दिये है।

१६---वारा १८ में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी भूमियो पर, जो उन भूमियों से भिन्न हों, जिनमें धारा २१ (ग) के अयोन अधिवासी अधिकार उत्पन्न होते हो, कब्जा रलने वाले व्यक्ति जो १ जनवरी सन् १९३८ ई० को किसी ऐसे अभिलेख (record) में काबिज के रूप में दर्ज हों, जो यू० पी० लेंड रेवेन्यू ऐक्ट के अध्याय ४ के अधीन पुनरीक्षित (revised) हो या जो विशेष कार्रवाइयों (special operations) द्वारा सशोधित किया गया हो, मौहसी काश्तकार समझे जायेंगे। काबिज (occupant) की परिभाषा के लिये (अंग्रेजी बिल गे) इस बारा की ा। । इटेंड प्राविसेज टेनेंसी (एमेंडमेट) ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा २७ की उपयारा

घारा १७

थारा १८

(१) के खंड (ग) से ली गई है, किन्तु हमें १ जनवरी, १९३८ ई० के दिनांक में कोई विशेष महत्व की बान नहीं माठूम होती और इमीलिये हमने उसे छोड़ दिया है। हमने इस धारा में परिवर्तन भी किये हैं जो धारा १३ के उपर्युक्त परिवर्तन और धारा १९ तथा २० के बाद विशन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप किये गये हैं।

घारा १८-क, १९ तया २०

१७--धारा १९ में यत्र मध्यवितयों को ऐसी भूमियों में भूमिथरी अधिकार देने की व्यवस्था की गई है जो उनके पास या अब्जे में सीर, खुदकारत, बाग या उनकी निजी जोत के रूप में हो और बारा २० हारा अवव के स्थारी पट्टेबारों (per ma nent lessee in Oudh) और दवामी काश्तकारों (permanent tenure holders) के अतिरिक्त जो मध्यवितयों के वर्ग में रखे गये हैं, सब काश्तकारों, अतीयादारों और बागदारों को सीरदारी के अधिकार दिये गये हैं। हमारे नत में सब शरह म् अइयन काश्तकारों और माकी शरों को भी भूमिवरी अधिकार दिये जाने चाहिए। शरह मुअइयन ठाश्तकारों को पहिले ने ही हम्नान्तरण अधिकार प्राप्त है और यह बात डायुक्त नहीं मालुम होनी हैं कि उनने भनिश्वर पद प्राप्त करने के लिथे अपने लगान को दन पुनी पाराधि देने के तिरे कहा जाय। यही बात माफीदारों के सम्बन्ध ने भी हु। उन्हें कोई अवत्न नहीं देना पड़ता और इसलिये उन्हें अपने आप ही इस प्रतिबन्ध के साथ मृतिधरी अधिकार मिल जाने चाहिये कि स्वत्वाधि-कार के दिनांक में उन पर उपयुज्य मालगुजारी लगाई जाय। हमारा यह भी विचार ह कि सीर की भूभियों के एसे काश्तकारों को, जिनके पास किसी ऐसे पटटे के आधार पर भूनि हों, चाहे वह दवामी पटटा हो या इसामरारी, जिसके अधीन उन्होंने सीर के सावारण काश्तकारों की अपेक्षा अधिक अच्छे अधिकार प्राप्त किये हों, धारा २१ के अधीन अधिवासियों को दिए गये अधिकारों की अपेक्षा अधिक ऊंचे अधिकार दिये जाने चाहिये। अतएव हमने यह प्रस्ताव किया है कि उनको धारा २० के अधीन सीरदार बना दिया जाय।

बारा २१

१८—वारा २१ सीर के ऐसे काश्तकारों को अधिवासी अधिकार देती है जो उन काश्तकारों से भिन्न हों, जिन्हें मौक्सी काश्तकार, जिक्रमी असामी, और कडजेदार (ocsupants) नहीं समझा जाता है और जिनको धारा १८ के अधीन मौक्सी काश्तकारों के अधिकार नहीं दिये गये हैं। हमारां यह विचार है कि यनाइटेड प्राविसेज टेनसी (एमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ ई० की धारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्ध में अभिदिष्ट (referred to) शिक्मी असामियों को अधिवासी अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये, किन्तु उन्हें ऐसे असामियों के रूप में ही रहने दिया जाय, जिन्हें उनकी नियत अवधि के समाप्त होने पर बेदल किया जा सके। हमने इस धारा में जो और परिवर्तन किये हैं वे धारा १८ और २० में किय गये संशोधनों के परिणाम—स्वरूप हैं। सीर की भूमियों के किसानों को अधिवासी अधिकार देने के सम्बन्ध में बहुत रूमवा वाद-विवाद चलता रहा, किन्तु अस्त में हम होग धारा २१ के सिद्धान्त को हां पालन करने के लिये सहसत हुये।

बारा २३

१९——घारा २३ किसी न्यायालय की डिग्री या आज्ञा के अनुसार की गई लगान की कसी के अतिरिक्त किसी और प्रकार से १ जुलाई, १९४८ ई० के बाद की गई रा की कमियों को निरर्थक करती है। हमारा यह मत है कि ऐसी कपटपर्ण डिक्री पर भी विचार नहीं किया जाना चाहिये जिसमें लगान सर्किल रेट से भी कम रखा गया हो और तबनुसार हमने इस आशय का एक प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है।

ारा २४

२०--१ जुलाई, १९४८ ई० के बाद किये गये किसी स्थान के अन्तरण को, चाहे वह विकी द्वारा किया गया हो या दान द्वारा, भारा २४ अमान्य टहराती ह। अभिप्राय यह है कि ऐसे अन्तरणों पर ध्यान न दिया जाय जो जमींदारी-उन्मूलन के पूर्वानुमान के आधार पर इस प्रयोजन से किये गये हों कि अध्याय ५ के अधीन प्राप्त अपेक्षाकृत अधिक धनराशि का पुनर्दासन अनुदान प्राप्त किया जाय। हमारा यह विचार है कि जो अन्तरण १ जलाई. १९४८ ई० और ७ जुलाई, १९४९ ई० के बीच में किये गये हों जब कि उक्त बिल लेजिस्लेटिब असेम्बली में प्रस्तुत किया गया था, उनको केवल पुनर्वासन अनुदान की घनराशि निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये अमान्य ठहराया जाय। ऐसी दशाओं में पुनर्वासन अनुदान इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये मानो अन्तरण किया हो न गया हो, किन्तु अनुदान की धनराशि अन्तरण-ग्रहीता (transferee) को दी जाय। ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद किये गये अन्तरणों की दशा में यह समझा जाना चाहिये कि अन्तरण-ग्रहीता (transferee) को कोई आगम (title) नहीं दिया गया है और वह किसी भी पुनर्वासन अनुदान के पाने का अधिकारी न होगा। यदि किसी व्यक्ति ने ७ जलाई. १९४९ ई० के बाद अपने पक्ष में कोई अन्तरण कराया है । उसने यह बात इस बिल के निदेशों की पूरी जानकारी के साथ की है और उसे कोई भी सुविधा नहीं दी जानी चाहिये। हमारी यह भी राय है कि इस धारा के अधीन लगाये गये निरोध दो प्रकार के अन्तरणों पर लागु न किये जायं। यदि कोई अन्तरण किसी न्यायालय की आज्ञा के अधीन किसी डिक्तीं के निष्पादन या रुपयें के भुगतान के सम्बन्ध में किया गया हो, तो हमारे विचार से ऐसा अन्तरण सच्चा है और मान लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार हमारा यह मत है कि किसी पूर्णतः पुण्यार्थ स्थापित किये गये वक्फ, ट्रस्ट, इन्डाउमेंट या समिति के पक्ष में किये गये अन्तरणों पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय जब तक कि प्रांतीय सरकार किसी विशेष दशा में इसके विपरीत आदेश न दे। बारा २४ में जो संशोधन किये हैं, उन्हें दुष्टि में रखते हुये धारा ४० अनावश्यक है और निकाल दी गई है।

२१—वारा २६ में यह व्यवस्था की गई है कि धारा ६ के अधीन विज्ञाण्त प्रकाशित होने पर, कलेक्टर सभी आस्थानों को अपने अवधान (oharge) में लेले।
खंड (ख) द्वारा कलेक्टर को यह शक्ति (power) दी गई है कि वह
किसी स्थान के अंगभूत किसी भूमि, इमारत या अन्य स्थान में प्रवेश करे और उसकी
तलाशी लें। हमने तलाशी लेने की शक्ति हटा दी है, क्योंकि हमारे मत में यह बात
बिल के प्रयोजनों के लिये अनावश्यक थी।

धारा २६

अध्याय ३

प्रतिकर का निर्वारण

२२—हमने इस अध्याय की सामान्य योजना सुरक्षित रखी है, किन्तु धारा ४३ और ४८ में कुछ परिष्कार किये हैं, जिनका सम्बन्ध किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी (net assets) के अवधारण (determination) से है। धारा ४३ में किसी महाल या गांव के सम्बन्ध में कच्ची निकासी अवधारित करने का विषय है। उसके खंड (क) में यह व्यवस्था की गई है कि उन करने के

धारा ४३ तथा ४८

लगान देय हो, किन्यु अवदारित न किया गया हो, तो वह मौरूसी दरों के अनुसार अवधारित किया जाय। मब वजाओं में मौह्नमी अने के अनुसार लगान की गणना करने से राज्य पर अनुचिन भार आ पड़ेगा। अनएव इस निर्देश की बदल दिया है और यह ब्यवस्था की है कि मानहनदारों और साकिनूल मिल्कियत काश्तकारों की दशा में जगान साकिन्त मिल्जियत दरों के अनुवार और बाग के अतिरिक्त अन्य सद त्याओं में मौडमी हरो के अनुमार लगान अवशास्त्रि किया जायगा। खंड (ग) क जथीन मायर भन्दन्यी अण्य को निमाद नान्ह वर्ष की आब के ओसत के आधार पर लगाना जाना है। हमारी यह राय है नि विद्वत्वे दन दक्षों की आय को आवार मानना पर्याप्त होता है जी जी अब न नगरंथ से जिसके लिये खंड (घ) से व्यवस्था का गई है, हुआ पह राप्र है कि बीस से चाजीन बदों की अवधि के भीतर जैसा भी प्रत्यक दशा में उचित ननक्षा जाय, होने वादो जार के आधार पर हिसाब लगाया जान चाहिये। हमने यह भी व्यवस्था कर दी है कि दर्शीदक आय का निर्धारण करते समय जंगल की वास्तविक अवस्था का ध्यान रक्खा जाय। धारा ४८ में यह व्यवस्था की गई है कि किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी निकालने के लिये उसकी कच्ची निकामी में में न्या-त्रया बटाया जाय। हमने उस बारा की उपधारा (घ) में इसलियें परिवर्तन रूर दिया है कि इस उपखंड में उल्लिखित आय के कारण करेची निकासी मे में कोई धनराशि घटाने से पहिले कृषि-आय कर, सालगजारी, अववाब और खंड (ग) में अभिदिष्ट प्रवन्थ-व्यय की समानपानी धनराशियां निकाल ली जायं।

घारा ५९, ६१ और ६१-क

TI'

8 6

२३—— घारा ५९ के अधीन ठेकेदार को देय प्रतिकर के सम्बन्ध में हमने ल्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करनी अज़दरक नमर्झ, कि प्रतिकर अधिकारी को यह बात तिक्षेष रूप में ध्यान में रखनी आहिए कि मध्यवर्ती के समस्य अधिकार हस्तगत किये जा रहे हैं। उनन अधिकार नित्यता के आधार पर है और यह कि ठेकेदार के अधिकार परिमित प्रकार (limited haracter) के हैं। हमने यह भी व्यवस्था की हैं कि घारा ६१ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दो गई अपील की ऐसी डिक्री के विकद्ध, जिसमें मध्यवर्ती और उसके ठेकेदार के प्रतिकर सम्बन्धी पारस्परिक भागों का विभाजन किया गया हो, हाई कोर्ट में अपील ऐसे आधारों पर की जानी दाहिये जिनका उल्लेख कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ ई० की धारा १०० में किया गया हो।

अध्याय ४

धनिकर ना भुगतान

थारा ७२

२४—जारा ७२ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि प्रतिकर पाने का अधिकारी वक्फ, ट्रस्ट या इन्डाउमेट हो या अवयस्क या किसी व्यावहारिक अक्षमता (legal d sability) के अधीन हो या परिमित स्वामी (limited owner) हो तो प्रतिकर ऐसे अधिकारिक या बैंक के पास, जो नियत किया जाय, जन्मा कर दिया जाय।

हमने इस बात को स्पष्ट करने के लिये एक उपधारा बढ़ाई है कि ऐसे व्यक्ति की, जिसके लिये उक्त प्रतिकर जमा किया गया हो, जमा की गई धनराजि को, उस विधि के अनुसार काम में लाने के अधिकारों पर, जिससे उसके अधिकार अनुज्ञासित होते हों, किसी प्रकार था प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने किसी ऐसी सम्भव शंका को निवारण करने के लिये कि व्यवस्थित आस्थानों (settled estates) के मालिक परिमित स्वामी (limited owner) नहीं हैं, एक स्पष्टीकरण भी बढ़ा दिया है।

श्रध्याय ५

पुनर्वासन ग्रनुदान

२५--हमने इस अध्याय की सामान्य रचना और योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया है। घारा ७५ के अधीन पुनर्वासन अनुदान केवल उन्हीं मध्यवितयों को दिये और १०४-व जायंगे, जिनकी कुल देय मालगुजारी पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होती है। सम्भव शंकाओं को निवारण करने के लिये कि ऐसे मध्यवितयों पर भी, जो, मालगुजारी न देते हों, किन्त जो केवल लगान या अंशतः मालगुजारी और अंशतः लगान देते हों, यह प्रतिबन्ध लाग होता है, हमने एक नई धारा १०४ (क) बढ़ा दी है।

धारा ७५

अध्याय ६

खान ग्रीर खनिज पदार्थ

२६--हमने इस अध्याय में सिवाय एक छोटे से परिवर्तन के, जो धारा १०८ में किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया है। उसमें यह बात स्पष्ट की गई है कि स्वत्वाधिकार के दिनांक पर मध्यवर्ती को किसी ऐसी खान, जिसे वह स्वयं चलाता हो, के पट्टे को छोड़ देने का विकल्प (option) प्राप्त होगा।

घारा १०८

अध्याय ७

गांव-समाज और गांव-सभा

२७--गांव-समाज के संगठन की जैसी व्यवस्था धारा ११५ में की गई है, हम उससे सहमत है, किन्तु हमारा यह विचार है कि असामियों के साथ अधिवासियों को भी सिम्मिलित कर लिया जाय। इसके अतिरिक्त यह व्योरा अनावश्यक है, जैसा कि खंड (ग) में किया गया है कि किसी सहकारी खेती संस्था (co-operative farm) के सदस्य गांव-समाज के भी सदस्य होंगे, क्योंकि ऐसे सदस्य या तो खंड (क) या (ख) के अन्तर्गत आ जायंगे।

घारा ११५

२८-- थारा ११७ के अधीन किसी ऐसी भूमि के, जो जीत की भूमि या बाग की भूमि से भिन्न हो, गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने की व्यवस्था करने वाले निदेश पर यह प्रतिबन्घ लगाया गया है कि यदि किसी गांव में कृषिगत क्षेत्र की अपेक्षा कृषिहीन क्षेत्र बहुत अधिक हो तो कृषिहीन क्षेत्र का कोई भाग सरकार के विवेक से गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में न जाने दिया जाय। हमारा विचार है कि इस बात का निश्चय करने के लिये कि कृषि-हीन क्षेत्र का कोई भाग स्वत्वाधिकार में जाने से अलंग रखा जाय या नहीं, यह कसौटी नहीं होनी चाहिये कि कृषिगत क्षेत्र की तुलना में उसका आकार बहुत बड़ा है। किन्तु यह बात गांव-समाज की आवश्यकताओं की दृष्टि से तय की जानी चाहिये।

घारा ११७

अध्याय =

वावेदारों के वर्ग

च धारा १३३

२९—धारा १३३ के अनुसार कतिपय वर्गों की भूमियों में मीरदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे, किन्तु यह बात सम्भव है कि ऐसी भूमि में यूनाइटेड प्राविसेज देनेनी ऐक्ट के अधीन पड़के में ही मोक्सी अधिकार उत्पन्न हो गये हों। ऐसी दशाओं के सम्बन्ध में ध्यवस्था करनों के लिये हमने इस धारा में इस आशयं का एक खंड ओड़ दिया है कि धारा २० के निदेशों पर कोई प्रतिकृत्व प्रभाव नहीं पड़ सकेगा, जिसके अधीन उमी धारा में उन्तिवित काश्नकारों को सीरदारी अधिकार मिछते हैं।

म मेथरी अधिकारों का उपार्जन

घारा १३५--१३९ ३०—धारा १३५—-१३९ में इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने से पहले ही भूमिधरी अधिकार उपार्जन करने के लिये काश्तकार द्वारा अपने वार्षिक लगान से दसगुनी धनराशि जमा करने के तम्बन्ध में निदेश रखें गये हैं।

संपुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० के प्रवितित होने के परिणामस्वरूप उक्त निर्देश अनावश्यक हो गये हैं। किन्तु हमने पुरानी घारा १३५ के स्थान पर एक नई धारा १३५ रखी है, जिससे कि संयुक्त प्रान्तीय काश्नकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० के सम्बन्ध में कुछ अभिवांछनीय परिवर्ननों को लागू किया जा सके। इनके आधार पर कोई सह—कृषक किसी जोत के केवल अपने भाग के सम्बन्ध में रुपया जमा कर सकता है और यदि वह कुल जोत के वार्षिक लगान का दम गुना रुपया जमा कर द तो वह दूसरे सह—काश्तकारों के कारण दी हुई धनरािश को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है।

हमने इन बातों के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की है कि सीर के काश्तकारों को भी, जिन्हें हमने धारा १३ के अधीन मौरूसी काश्तकार प्रख्यापित किया है और नूमि के कब्जेदारों को भी, जिन्हें हमने धारा १८ के अवीन मौक्सी काश्तकार प्रख्यापित किया है या जिन्होंने यूनाइटेड प्राविसेन टेनेसी ऐक्ट के अधीन मौरूसी अधिकार प्राप्त कर लिये है, प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई० के अधीन रुपया जमा करने की सुविधार्ये दी जानी चाहिये और यह कि उस दशा में जब जोत का कोई भाग शिकमी कारतकार के अधिकार में हो तो असल काश्तकार उस भूमि के न उठाये हुये भाग • के सम्बन्ध में ही रुपया जमा कर सकता है और यह कि उस दशा में जब देय लगान मौख्सी दरों पर लगाये जाने पर उस धनराज्ञि के दुगने से भी अधिक हो तो उस धनराशि को घटा देना चाहिये जिससे कि वह दस गुना भुगतान करने के प्रयोजन के लिये उक्त घनराशि के दुगने से अधिक न रहे। किसी ऐसी जोत की दशा में, जो शिकमी काश्तकार के कढ़नें में हो, शिकमी काश्तकार भूमिधरी अधिकारों को अर्जन करने के लिये घारा २२२ के अधीन पांच वर्ष की अवधि तक बिना प्रतीक्षा किये हुये ही अपेक्षित रुपया जमा कर सकता है यदि असल काश्तकार इस बात से महमत हो। इसके अतिरिक्त हमारा यह मत है कि किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसने संयुक्त प्रान्तीय कास्तकार (विशेषाधिकार उगर्ज) विशान (ऐक्ट), १९४९ ई० के अवीन प्रख्यापन प्राप्त कर लिया हो, यह समझा जाना चाहिये कि प्रख्यापन के दिनांक से इस बिल के अधीन भूमिधर को दिये गये अधिकार उसे प्राप्त है और वह उस पर आरोपित दायित्व के अधीन है।

३१--हमने माफीदारों का वर्गीकरण उनसे किसी धनराशि के भुगतान के लिये धारा१४२-३ बिना ही भूमिधरों के रूप में किया है और इस कारण हमने धारा १४२ निकाल दी है। उसके स्थान पर हमने यह प्रतिबन्ध रखा है कि उस दशा में जब मौरूसी काश्तकार द्वारा देय लगान सर्किल रेट पर लगाये गये लगान के दुगने से अधिक होता हो तो उसे अपने लगान का दस गुना देने के लिये बाध्य नहीं किया जायगा, किन्तू उससे कछ कम धनराशि ली जायगी जो सिकल रेट के दुगने के हिसाब से लगाई जायगी। हमारा यह मत है कि जो काश्तकार अत्यधिक लगान देते हैं उनको यह सुविधा दी जानी चाहिये और हमारा यह भी विचार है कि भविष्य में ऐसे काइतकार की मालगुजारी किसी दशा में भी सर्किल रेट के दुगने से अधिक नियत नहीं की जाय।

३२—हत्रने इस बात के लिये भी व्यवस्था करना आवश्यक समझा है कि उस दशा में जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जोत के अपने ही भाग के सम्बन्ध में भूमिधर बन गया है, जिस पर उसका और ऐसे लोगों के साथ-साथ जो सीरदार हों, संयुक्त अधिकार होतो भूमिधर उक्त जोत में से अपने भाग के विभाजन के सम्बन्ध में नालिज्ञ कर सकता है। यह निदेश विभाजन सम्बन्धी सामान्य निदेशों के एक अपवाद के रूप में है, जिनके सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में आगे चर्चा की गई है।

भूमि का उपयोग और उसकी उन्नित

३३—हमने यह व्यवस्था करने के लिये घारा १४६ और १४७ की रचना फिर से की है कि जब भूमिधर अपनी जोत में सम्मिलित किन्हीं भूमि-खंडों को औद्योगिक या रावन-निर्माण के प्रयोजनों के लिये काल में लाये तो वह उस सम्बन्ध में कलेक्टर से एक प्रख्यापन पाने का स्वत्याधिकारी होगा और ऐसा प्रख्यापन (Declaration) होजाने पर इस अध्याय में अन्तरणों और पट्टों के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्ध लाग न हो सकेंगे और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में भूमिधर अपने निजी धर्म शास्त्रीय विधान (Personal law) से अनुशासित होगा। यदि किसी भूमिघर की ऐसी भिम जो इषि-फलोत्पादन या पश्-पालन के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त न होती हो, किसी समय उपरोक्त प्रयोजनों के लिये काम में लाई जाने लगे, तो कलेक्टर इस सम्बन्ध में एक प्रख्यापन जारी करेगा और ऐसे प्रख्यापन के हो जाने पर उक्त भूमिधर फिर से इस अध्याय के निदेशों से अनुशासित होने लगेगा। उपरोक्त दोनों दशाओं में से प्रत्येक दशा में भूमिधर भूमिधर ही बना रहेगा। इस बात को त्पष्ट करने के लिये हमने धारा १९० का खंडे (घ) निकाल दिया है।

३४--धारा १४८ के बाद, जिसमें सीरदार या असामी को अपनी जोत की उन्नति करने का अधिकार दिया गया है, हमने दो और धारायें १४८-क, और १४८-व बढ़ायों हैं। धारा १४८ में हमने यह व्यवस्था की है कि यदि उन्नति किसी ऐसी भूमि में की जाय या किसी ऐसी भूमि के लिये हानिकारक हो, जो उस खातेदार की जोत या खाते में सम्मिलित न हो जिसमें उक्त उन्नति की हो तो ऐसी भूमि के खातेबार की या गांव-सभा की जैसी भी दशा हो, लिखित अनुज्ञा प्राप्त की जानी चाहिये। घारा १४८ (ख) में हमने यह व्यवस्था की है कि यदि उस जीत से, जिस पर कोई उन्नतिमुलक काम बनवाया गया हो, अंशतः बेदखली हो भी जाय, तो भी कुल जोत को उस उन्नतिमूलक काम से लाभ पहुँचता रहेगा यद्यपि जोत के उस भाग पर, जिस पर उन्नति मुलक काम बनवाया गया हो, दूसरे व्यक्ति का कब्जा हो जाय। यह निदेश [,] यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट के प्रचलित निदेशों के अनुसार ही हैं।

३५-- धारा १५० के बाद हमने एक और बारा १५०-क बढ़ायी ह, जिसके अधीन धारा१५०-क किसी असामी की बेदखली की आज्ञा देने वाले न्यायालय के लिये यह अनिवार्य रखा गया है कि वह उन्नतिमुलक काय के सम्बन्ध म, यदि कोई हो, प्रतिकर अवधारित करे और डिग्री या बेदललो की आज्ञा के साथ प्रतिकर के भुगतान करने का प्रतिबग्ध लगा व ।

धारा १४३

भारः १४६, १४७ और १९०

घारा १४८-क और १४८-ख

ग्रन्तर्ख

शाया १५ 🗲

३६--भूमिश को दिये गए अन्तरण के अधिकार पर यारा १५३ में प्रति ग्व लगाया गया है। उन बारा में यह नियत किया गर है जि कोई केता अपनी जोतः या खाते को २० एकड़ से अधिक नहीं बड़ा नकता। बाड्य-हिन्यान के अनुसर धारा १५३ की यह भी ब्याख्या की जा सकती है कि यह प्रनिवन्ध के नन उनी खेता पर चामू होता है जिसके नास पहले से भी बाड़ भूमि हो। किन्तु इस जिल का बहु अभिक्राय नंहीं है। इसने भविष्य की जोनों या खातों की मीमा अधिक से अधिक ३० एउड़ त- रमबी गर्द है। इसने अपने अलेख में इस दोष को दूर कर दिया ह। इसने पुष्य व स्थापित मंह्याओं के यस में एक अपबाद भी रखा है और वे हमारी राय में ३० एकड़ ने अधिक भूमि प्राप्त कर सकती हैं।

जाग १५६

३०—धारा १५६ में किसी अक्षमता-प्रस्त भूमिशर या सीरदार को अपनी जीन उठा देने की अनुजा दी गई है। हसने से कुछ लोगों का यह विचार हुआ है कि लगान पर भूमि उठाने का यह निदेज बहुत ही संकुचित है, किंदु फिर भी हम लोग पीमित प्रनिदन्थों (re-tricted condition) के अधीन भी लगान पर भूमि उठाने के किसी तामान्य अधिकार के देने के विरद्ध थे। क्योंकि यह बात इम बिल के मूल विद्धांतों के विपरीत होगी! किंतु हमने असमर्थता-प्रस्त व्यक्तियों की सूची में बृद्धि की ह और उपमें गृते व्यक्ति को, जो किसी गम्भीर व्याघ ने पीड़िन होने के कारण खेती न कर तकता हा और २५ वर्ष तक की अवस्था के विद्यार्थों को मम्मिलित किया है, जो कियी स्वीकृत संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। इसने यह भी व्यवस्था की है कि किभी संयुक्त खाने की दशा में, जिसमें सब खातेदार किसी असमर्थता से प्रस्त न हों, असमर्थता-प्रस्त सहभागी (co-sharer) उस खाते के अपने भाग या खंड को लगान पर उठा तकता है। भूमि को इस प्रकार से खंडाः लगान पर उठाने की दशा में हमने असपर्थता-प्रस्त सहभागी या उसके पट्टे दार को खाते का बटवारा कराने का अधिकार खाते के रकबे पर विचार न करते हुए दिया है.

धारा १६०

३८—धारा १६० में भूमि को अरला—बदची के अधिकार से हम सहमत है, कि वु हमने असमे इस आशय का एक प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है कि इस अधिकार का प्रयोग घारा १५३ के निदेशों को विफल करने के लिये नहीं किया जाना चाहिए।

घारा १६२, १६६ ३९—— घारा १६२ से १६६ तक में विभिन्न खातेदारों द्वारा अवैध अन्तरणों के परिणामों का वर्णन किया गया है। उन घाराओं की वाक्य-रचना समीवीन नहीं थी। हमने तीन पृथक् घाराओं १६२, १६३ और १६३— क में भूमिधरों द्वारा किए जान वाले अवैध अन्तरणों के सम्बन्ध म व्यवस्था की है और एक परिणामी संशोधन धारा १६४ में और सम्बन्धित घाराओं १६५ और १६६ में किया है जिनमें सीरदारों और असामियों द्वारा जैसी कि आजकल उनकी विधक स्थित है, किये जाने वाले अवैध अन्तरणों का वर्णन किया गया है। हमने भूमिधरों द्वारा अवैध अन्तरणों के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की है कि:—

- (क) यदि घारा १५३ के निदेशों के प्रतिकृत कोई विकय या दान किया जायगा, तो वह अन्तरण व्यथं होगा और अन्तरिणी गांव—सभा द्वारा बेदखल किया जा सकेगा। एसी बेदखली के फलस्वरूप वह भूमि खाली हो जायगी और गांव—सभा द्वारा उसकी व्यवस्था की जाएगी। अन्तरणकर्ता को विकय का प्रतिफल अपने पास रखने या अन्तरिणी से वसूल करने का अधिकार इस आधार पर प्राप्त होगा कि अन्तरिणी को इस बात का अवश्यमेव ज्ञान होना चाहिये कि उसको कोई भूमि मोल लेने का अधिकार भी है या नहीं।
- (स) यदि कोई बन्धक धारा १५४ के निदेशों के प्रतिकूल किया जायगा, तो उस बन्धक को विऋय समझा जायगा और यदि वह विऋय धारा १५३ के अर्थों में अर्वेष होगा, तो अर्वेष विऋय के परिणाम लागू होंगे।

- (ग) अवैध रूप से लगान पर भूमि उठाने की दशा मे--
- (१) यदि पट्टेरार के पास कुल क्षेत्र, जिसमे उसके द्वारा लगान पर उठाया हुआ क्षेत्र भी सम्मिलित है, ३० एकड़ से अधिक न हो, तो पट्टेरार सीरदार हो जायगा, और
- (२) यदि उपर्युक्त कुल क्षेत्र ३० एकड़ से अधिक हो, तो पट्टेदार क्षेता हो जायगा और घारा १५३ और १६२ के निदेश लागू होगे।

उत्तराधिकार

४०--हमने घारा १६७ के अधीन भूमिघरों को दिया गया वसीयत करने का अधिकार स्त्रियों से हटा लिया है, क्योंकि इनको आजीवन स्वत्य का ही उत्तराधिकार मिलता है और यह भी व्यवस्था कर दी है कि वसीयत लिएित ओर विधिवत् प्रमा- णित होनी चाहिए।

धारा १६७

४१—हमने धारा १६९ में दिये गए उत्तराधिकार के फ्रम में कुछ परिवर्तन कर दिये हैं। हमारी समझ में विधवा, सौतेली माता को इतना ऊंचा स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और तदनुसार हगने उसको पुरुष जातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तित में से किसी की विधवा (Widow of a male sine al descendant) आर अविवाहिता पुत्री के बीच में रख दिया है। हमने भाई के पौत्र को भी पितामह के पुत्र के बाद सिमालित कर लिया है।

घारा १६९

४२—घारा १७० का उसकी वाक्य-रचना के अनुसार यह अर्थ लगाया जा सकता है कि विवाहिता पुत्रियां, जिनको अविवाहित दशा में स्वत्वाधिकार के दिनाक से पहले पूर्ण उत्तराधिकार मिला था, अब अगने अधिकारों से विचत हो जायंगी। स्पष्टतः यह बात वांछनीय नहीं हैं। अतएव हमने उन दशाओं के सम्बन्ध में, जिनमें उत्तरा— विकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले मिला था और उन दशाओं के सम्बन्ध में, जिनमें उत्तराधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद मिलेगा, पृथक्-पृथक् व्यवस्था की है।

घारा १७०

४३—हम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है कि किसो खाते में किसी भी व्यक्ति का स्वत्व केवल इस कारण से नहीं निम्ना जायगा कि वह किसी आस्थान में किसी खातेदार के साथ संयुक्त ह। हमें यह मालूम है कि यूनाइटेड प्राविमेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में इस प्रकार का एक निदेश है, कितु इसके कारण सयुक्त परिचार के छोटे सदस्यों को बहुत कठिनाइयां हुई है और उन्हें उनके अधिकारों से केवल ऐसे कारणों के आधार पर वंचित रखा गया है, जैसे कि किसी खाते के क्षेत्रफल या लगान में परिवर्तन होना, जिसके कारण विधि के अनुसार उसका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। हमारा यह विचार है कि संयुक्त परिवारों के सम्बन्ध में अब तक जो धारणा (prosumption) रही है वही बनी रहनी चाहिये।

धारा १७३

बटवारा

ठ४—इस बिल में मूल खाते का क्षेत्रफल ६ एकड़ रखा गया है और इससे कम क्षेत्रफल के खातों को छोटे-छोटे दुकड़ों में बांटने का निषेध किया गया है। इसमें ध्यवस्था की गई है कि यदि किसी ऐसे खाते का बटवारा कराने का बिचार हो तो उसका विकय (sale) और बिकी की धनराशि का जितरण (ditin bution) किया जाना चाहिये। यही विचार ऐसे बटवारे के सम्बन्ध में हैं जिसके कारण मूल खाते के क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खाते बनते है। हमने इस सामान्य नियम के दो अपवाद रखे हैं। सयुक्त खाते की दशा में यदि खातेदारों में से

घारा १७४, १७९ ओर १८१ कोई एक खानेदार भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर ले और दू गरे ऐसा न करें, तो हमारा प्रह सत है कि इस बात का विचार किये बिना ही उन खाते का क्षेत्रफ कितना है, उक्त भूमिधर का भाग अलग कर दिया जार्ग चाहियें। और यह कि यदि संयुक्त खाते— बारों (joint la lders) में से कोई एक व्यक्ति धारा १५६ में विणात किमी असमर्थता से प्रस्त हो और अपने भाग को लगान पर उठा दे, तो उस भाग भी बाते से अलग करने की अनुमित दी जानी चाहिये। हमने यह भी व्यवस्था की

बटवारे के सब वादों में गांव-मभा फ़रीक (party) बनाई जायगी और अदालत अपने विवेक ने उपर्युक्त शिक्ष्य के परिणामस्वरूप भूमि से इंचिन हुए व्यक्ति के लिये गांव-पभा के अधिकार में रहने वाली रिक्त भूमियों से उपर्युक्त भाग नियत कर सकती है। हमने अदालत को उपर्युक्त दशाओं में अपने विवेक से बटवारे को मना कर देने का भी अधिकार दिया है।

समर्पेख (surrender) होर परित्याग (abandonment)

घारा १८६

४५— यदि कोई सीरदार अपने खाते को समर्पण करना चाहे तो हम समझते हैं कि उसे न केवल गांव-सभा को ही, किंनु तहमीलदार को भी इमकी सूचना देनी चाहिए। इससे बाद के अनावश्यक झगड़े दूर हो जायंगे।

धारा १८९, १८९-क ओर १८९-ख ४६—यदि कोई सीरदार या असामी अपने खाने को कृषि, फलोत्पादन या पशु— पालन से सम्बन्धित किमी प्रयोजन के लिये लगातार दो वर्षों तक काम में न लाए, तो उसके सम्बन्ध म यह समझा जायगा कि उसन खाने का परित्याग (abandon ment) कर दिया है। असमर्थता—प्रस्त सीरदार को सम्भव किनाई (harlship) से बचाने के लिये हमने यह विशेष बात बढ़ा दी है कि ऐसी दशाओं में गांव—सभा को असमर्थता—प्रस्त व्यक्ति की ओर से उसका खाता असमर्थता की बची हुई अवधि के लिये लगान पर उठा देना चाहिये।

यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट के इसी प्रकार के एक निदेश के अनुरूप हमने यह बात भी बढ़ा दी हैं कि क्षेत्रपति (land-holder) किसी ऐसे खाते पर, जो परित्यक्त समझा जाता हो, कढ़जा करने से पहले अपने अभिप्राम की सूचना तहसीलदार को देगा और तब तहसीलदार सम्बन्धित सीरदार या असामी को उस पर आपत्ति करने का अवसर देगा। यदि एसा नहीं किया जायगा तो यह समझा जायगा कि सीरदार या असामी की अवैध बेदखली हुई हैं।

घारा १९२–क और १९२–ख ४७—धारा १९२ के वाद, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भूमिशर या सीरवार का अधिकार समाप्त होने पर उसके अधीनस्थ (holding under him) अमामी का भी स्वत्व समाप्त हो जायगा, हमने दो नई धाराये १९२-क और १९२-व बढ़ाई । पहली धारा का सम्बन्ध यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी ऐक्ट की पद्धति के अनुसार स्वत्वों के विलीन होने (merger) से हैं और दूसरी धारा में यह व्यवस्था की गई है कि सीरवार या असामी के स्वत्व के समाप्त हो जाने पर भी खेनों में लगी हुई फ़सल के सम्बन्ध में उसका अधिकार बना रहेगा जैसा कि बेदखली की दशा मे होता है।

धारा १९४–क ४८—घारा १९४ द्वारा गांव-सभा को अधिकार दिया गया है कि किसी को खाली भूमि में (उस भूमि को छोड़ कर, जिसमें घारा १३३ के कारण सीरदारी का अधि-कार नहीं उत्पन्न हो सकता) सीरदारी के अधिकार दे दे। हमारी सम्मित में यदि भूमि घारा १५ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) में खाली हुई है तो ठेका देने दाले को भूमि लेने का प्रथम अधिकार निल्ना चाहिये, यदि उसकी कोई सीर इस कारण से नष्ट हो गई हो कि इस विधान में हमने धारा १३ में कुछ मध्यर्वीतयों के सीर के काश्तकारों को मौकसी अधिकार दे दिये हैं। ऐसे मध्यवर्ती अपने खातों को इस साधन का लाभ उठाते हुए ५० एकड़ से अधिक न बढ़ावें, इसलिये हमने प्रतिबन्ध भी लगा दिया है।

धारा १९६

४९——धारा १९६ में गांव-समा को यह आजा दी गई है कि वह किसी ब्यित की रिक्त भूभि देने के सन्बन्ध में किस प्रकार के तारतम्य के क्रम (order of pracedental) का अनुसरग करे। हमारा प्रस्ताव है कि खातेदारों में उन ब्यिक्तयों को तरजीह देना चाहिये, जिन्होंने यू० पी० टेनेन्सी एक्वीजिशन आफ प्रिविल्जिस ऐक्ट में अपना अधिकार पमाणित कर लिया है या घारा १४३ में सनद पा ही है।

हमने इस धारा के अधीन गांव-सभा द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध सब-डिबी-जनल अफसर के यहां अपील करने की भी टपवस्था कर दी है। हमने गांप-सभा को निल्पक्ष ट्यवहार म लगाये रखने के लिये यह बान आवश्यक गमश्री।

बे : खली

५०--धारा २०० के खंड (च) में पह ज्यवस्था की गई है कि किमी असमर्थता- धारा २०० ग्रस्त खानेदार का असामी जिन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है, उनमें से एक यह है कि क्षेत्रपति (land-holder) भूमि को अपनी निजी जोत में लेना चाहता है। हमारी यह राय है कि यदि असामी के पास भूमि किसी नियत अवधि के पट्टें के आधार पर हो, नो असमर्थ वाक्ति के स्वयं भूमि जीतने के अपने अधिकार को काम में लाने से पहले उस अबिध को अबस्थ समाध्त हो जागे दिशा जाय।

५१--हमने उन दशाओं के सम्बन्ध में भी व्यवस्था की है, जिनमे निर्णीत ऋणी (judgement deliter) की बिना कटी कसच या पड़ उस भूमि पर स्थित हों, जिससे वह बेदखल किया जा रहा है। हमो गह व्यास्था यूनाइटेड प्राविमेन हेनेंसी ऐक्ट की धारा १६० के आधार पर की है।

भारा २००**-**क

५२—धारा २०१ में यह व्यवस्था की गई है कि यदि अमनर्थ खातेदार का अमामी बाद प्रस्तुत करने की नियत अवधि (period of limitalion) के भीतर ही येदखल न किया गया, तो वह उक्त अवधि के समाप्त होने पर अपनी अप्रिक्त भूमि का भूमिधर या सीरदार, जेसी भी दशा हो, बन जायगा। हमने इस निदेश को परिष्कृत कर दिया है जिसमे कि उना असामी को सीरदार के पद से ऊंचा पद न मिल जाय।

धारा २३१

५३—यदि असमर्थता—ग्रान खालेदार किशी असामी को इस आधार पर बेदखल कर दे कि वह भूमि को स्त्रयं जोतना चाहता है, तो उसको तीन वष के भीतर नये पट्टे पर भूमि देने का निषेध किया गया है। सम्भव किठनाई को दूर करने के लिये हमने इस अविध को घटा कर दो वर्ष कर दिया है।

बाग २०२

५४—धारा २०७ के अधीन यदि कोई अतिक्रमी (tresspasser) वाद प्रस्तुत करने की अविध के भीतर बेदखल न किया जायगा तो वह सुम्बन्धित खाते के अनुसार भूमिधर, सीरदार या असामी हो जायगा। हमने इस निदेश को परिष्कृत कर दिया है, जिससे कि अतिक्रमी (tresspasser) को सीरदार के अधिकार से ऊंचा अधिकार प्राप्त न हो सके।

धारा १९७, २०७ और २०८

५५— घारा २०९ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक पशुचर भूमि, इमशान या किन्न स्तान, तालाब, रास्ता या खिलहान की भूमि को कोई काश्तकार गांव—सभा के बाद प्रस्तुत करने पर उस दशा गे बेदखल किया जा सकेगा, जब उसको ८ अगस्त, १९४६ ई० को, जब जमींदारी—विनाश प्रातात असेम्बली मे स्वीकार किया गया था या उसके बाद काश्तकार के रूप में भूमि उठाई गई हो। अनाज की आजकल की बढ़ी—चढ़ी कीमतों के कारण लोगों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि वे गांव की सार्वजनिक उपयोग

घारा २०९

की भूमियों को भी जीतनें-बोने लगे है। यह वान स्पट्टतः अवांछनीय ह। उपधारा (१) के निदेश नो एएथारा (२) से बहुत कुछ रद हो जाते हैं जिसमें यह दक्किरथा की गई है कि यदि काइनकार ने भूमियरी अधिकारों को प्राप्त करने के लिये अपने 'लगान का दम गुना कपया जमा कर दिया हो. तो वह बेदलल न किया जा सकेगा। हमने उपधारा (२) निकाल दी है और उपधारा (१) के निदेशों का विस्तार कर दिया ह जिससे कि उममें उन जमीदारों के लिये व्यवस्था हो जाय, जिन्होंने उक्त भूमियों में कृषि करना प्रारम्भ कर दिया ह।

लगान

धारा २११-क ५६—घारा २११ द्वारा हमने 'असामियों' के लगान नियत करने के लिये वादों (cuits) की व्यवस्था की है और यह नियम बनाया ह कि उनका लगान मोजली वरों का १३३ है प्रतितन नियत किया जाएगा । हमारी समझ से असामियों के लगान के सम्बन्ध में यह उच्चनम मीपा उचित है।

धारा २१३

५ अ-हमने घारा २१३ निकाल दी है, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मब लगार नक्द त्यये में अदा किये नायं। हमारे प्रान्त में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर खेती-बारी इननी गिरी हुई दशा में हे कि काश्नकार नकद रुपए में लगान देना पसन्द न करेंगे।

धारा २१२-क, २१३-ख- और २१३-ग ५८-- हनने तीन नई पाराएं, २१३-क, २१३-ख और २१३-म बढ़ायी हैं, जिसमें असामी द्वारा पोस्टल मनीआईर से लगान का रुपया भेजा जाना वध घोषित किया गया है और रुपया पाने वाले की रसीद (payees receipt) को एविडेन्स ऐक्ट के अन्तर्गत पाद्य (admissible) माना है। उसमें जिन्सी लगान के नकदी बदलने (commutation) की भी व्यवस्था की गई है और यह निदेश रखा है कि लगान दो समान अनराशियों की किस्तों में देय होगा।

धारा २१४, २१४-क, २१४-ख, २१४-ग, २१४-घ और २१४-इ ५९—हमने घारा २१४ उसके वर्तमान स्वरूप में निकाल दी है और उसके स्यान पर लगान वसूल करने और लगान न दे सकने पर एक प्रार्थना—पत्र के आधार पर वेदलल किये जाने के सम्बन्ध में व्यौरेवार निदेश रखे हैं। यदि उक्त प्रार्थना—पत्र का विरोध किया जायगा तो वह बाद के रूप में परिवर्तित हो जायगा और यदि उस वाद (suit) में कोई बात आगम (title) सम्बन्धी उठेगी तो वह बाद दीवानी की अहा— लत के सुपूर्व कर दिया जायगा। उसमें इस अपवाद की भी व्यवस्था की गई है कि ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जो या तो केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार के स्वामित्व में हों या उनके प्रवन्ध में हों, बक्राया लगान मालगुजारी के बक्राया की तरह वसूल किया जाय।

घारा २१५–क

६०—हमने नार्दनं इंडिया केनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ ई० की घारा ४७ के अधीन नहर का महसूल वसूल करने के लिये वाद उपस्थित करने के सम्बन्ध में एक निदेश बढ़ा दिया है।

घारा २१६ और २१७

६१—धारा २१६ और २१७ में प्रान्तीय सरकार को बहुत व्यापक अधिकार विये गए हैं जिनके अनुसार वह इस अध्याय के निदेशों को प्रवर्तित करने के लिए टेनेंसी ऐक्ट और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में परिष्कार (modification), अनुकलन (adaptation) और संशोधन कर सकती हैं। उनकी पैवता सन्देहास्पद हैं। अतएव हमने उन्हें निकाल देने का निश्चय किया है। हमने इस अध्याय में और अध्याय १० में, जिसमे मालगुजारों के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है, जो नई धारायें बहुई हैं, उनसे हमें आशा है कि काम चल जायगा।

बारा२१६-क

६२—हमने ऐसे निदेश रख दिये हैं जिनके अनुसार गांव—सभा अपनी सिंकल में स्थित किसी भूमि ने किसी व्यक्ति के अधिकार की घोषणा कराने के लिये बाद प्रस्तुत कर सकती है। हमारी राय में इससे गांव—सभा को भूमि प्रवन्ध सम्बन्धी अपने कर्साव्यों के पालन करने में सहायता मिलेगी।

अध्याय ह

प्रधिवासी

८३--ह्निने एक यह निदेश रख दिगा है कि किसी अधिवासी के मरने पर उत्तराधिकार के सम्बन्ध में टाके खातेगत रवत्व की व्ययम्था धारा १६९ से १७३ तक के नित्शों के अनुसार की जायगी। इसके सम्यन्ध में किसी स्पष्ट निदेश के न होने के कारण यह बात सन्देहास्पद थी कि अधिवासी के गरने पर उसका खासा क्षेत्रपति (Land-holder) को तो न लौट जायगा।

घारा २१९

६४—धारा २२२ में हमने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है ओर यह निदेश रखा है कि अधिवासों मूमिपरी अधिकारों को प्रान्त करने के ित्रये किसी समय भी इस धारा म उन्लिखन पाव वर्षों को अविध से पहले भी, अपने क्षत्रपति की तिखित महमति प्राप्त करके भ्ष्या जमा कर सकता है। हमने तुरत्त रुपया भुगतान करने का यह अधिकार उन अधिवासियों को भी दिया है, जिनके क्षेत्रपति धार्मिक तथा पुण्यार्थ स्थापित सस्थाये है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे अित्रासियों को ५ वर्ष तक प्रतीक्षा करने के लिये वाध्य

धारा २२२

६५—धारा २२३ में उस दशा में अधिवासी के क्षेत्रपति को प्रतिकर देने की बात कही गई है जब वह भूमिधरी अधिकार प्रप्त करले। इस पारा के सिद्धान्त का पालन करते हुए हमने शरह मुअइयन काश्तकारों और माफीदारों को भी शामिल कर लिया है, जिनको हाने भूमिधरों के वर्ग में रखा है और यह व्यवस्था की है कि अधिवासी हारा जमा की हुई कुल धन्राशि उनको प्रतिकर के रूप में दे दी जाय।

किया जाय।

धारा २२३

थारा २२४

६६—धारा २२४ में उन परिस्थितियो का वर्णन किया गया है, जिनमें भूमिधर या सीरदार किसी अधिवासी को बेदखल करना वाहे। एसी बेदखली उम देशा में की जा सकती है जब क्षेत्रपति के पाप उस सिकल में उसकी निजी जीत की भूमि ६ १/४ एकड से कम हो । किन्तु बेदखली करने से पहले असिस्टेट कलेक्टर के लिये यह आवश्यक होगा कि वह यदि सम्भव हो, तो क्षेत्रपति की निजी जोत के क्षेत्र की खाली भेमियों में से भूमि लेकर पूरे ६ १/४ एक ड कर दे। जब यह बात पूरी नहीं की जा सकेगी तभी अधिवासी बेदखल किया जायगा। हमने दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किये है। एक तो हम यह समझते है कि ६ १/४ एकड़ की सीमा बहुत कम है और यह कि खाते के क्षेत्रफल की सीमा की यह संख्या लाभप्रद खातो की स्थिति के अनुसार नियत की जानी चाहिये। तदनुसार हमने उसको बढ़ाकर ८ एकड कर दिया है। किन्तु यह व्यवस्था भी कर दी है कि प्रान्त भर मे क्षेत्रपति की निजी जोत की कुल भूमि के क्षेत्र का भी विचार किया । जाना चाहिये। दूसरे यह कि हमने उपधारा (४) में दिये हुये क्रम को उलट दिया है और यह व्यवस्था की है कि बेदलल किये गये अधिवासी को ही खाली भूमियो मे से भूमि दी जानी चाहिये न कि क्षेत्रपति को, जिसको हमारी राय मे निजी भूमि को फिर से प्राप्त कर लेगे का अधिकार है। इसका एक परिणाम यह होगा कि यदि अधिवासी को नई भूमि दी जायगी तो यह उसका सीरदार हो जायगा।

ऋध्याय १०

मालगुजारी

६७—महाल के हिस्सेदारों पर मालगुजारी देने का जो संयुक्त तथा व्यक्तिगत भार था उसको अब धारा २३० से गांव के सब मालगुजारी देने वालों पर लगा

घारा२३०

दिया गया है। कियान समुदाय अब तक केंच्य अपना ही लगान देने के लियें बाध्य था। इस निदेश के कारण उन पर प्रभाव पड़ेगा और शायद इसके कारण उनको कठिनाई पड़े। इस कठिनता को दूर करने के लिये हम लोगों ने यह रखा है कि मालगुआरी देने का संयुक्त भार उन्हीं क्षेत्रों मे लगाया जाय, जिनका गवनिमेट समय—समय पर प्रस्थापन करे। इस मंद्रोधन का यह असर होगा कि यदि कलेक्टर को प्रतीत होगा कि इस गांव में मालगुजारी जिना संयुक्त भार के सिद्धान्त के लागू किये हुए नहीं उगाही जा सकती तो वह अपने कारगों के सहित नरकार को रियोर्ट भेजेगा।

६८—मीरदार जो स्वन्बाधिकार के पहले गल्कई लगान दे रहे थे उनके नकदी लगान करने के निर्देश भी इस विवान में दिये गए है।

घारा २४०-क,ख,ग धारा २४१-क,ख ५० -- नये दन्दोत्रम्न, जिनका विवरण घारा २४० मे दिया हुआ है, के सम्बन्ध में हमने कई उई धाराउँ और जोड़ी है। ये लैन्ड रवेन्यू एक्ट के निदेशों के अनुरूप है।

धारा २४२-क,ख

धारा २४५

७०--धारा २४५.में सरकार को अधिकार प्राप्त है कि व्यवस्थापिका सभा की

महमति मे भूमि की उपज का मूल्य यहते, यह वे उर उनके अनुरूप मालगुजारी भी घटाबढ़ा हैं। यह निदेश ४० साल तक व्यवहार ये न आवेगा और बूंकि उस सम्म की
अवस्था का ठीक-ठीक जान लेना इन नम्म किठन है, इसलिये हमने इस धारा को छोड़
दिया है।

घारा २४६

७१—हम लेगों ने बारा २४६ को भी छोड़ दिवा है, क्योंकि हमारी सम्मित में यदि किसी न अपने खेन पर कोई उन्निमूलक कार्य किया है तो उसे ८० वर्ष तक मालगुजारी म रिआयत देने की आवश्यकता नहीं है।

घारा २५०-

७२—बारा २५० के निदेशों के अनुमार हम लोगों ने बारा २५०-क, ख और जोड़ दी हैं।

क, ख घारा २५०-ग, घ, ड

७३--हमने यू० पी० लैंग्ड रेवेन्यू ऐक्ट के निदेशों के अनुरूप बन्दोबस्त की निग-रानी के निदेश इस विशान में सम्मिलित कर दिशे हैं।

घारा २४६

७४—यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के वर्तमान निदेशों के उदाहरण पर हमने भी इस निदेश को इस विधान में सम्मिलित कर दिया है कि तहसीलदार की दी हुई सनद इस बात का निश्चियात्मक प्रमाण होगी कि मालयुत्रारो बाकी है और व्यक्तिगत नादेहन्दों के बारे में गांव—सभा सनद जारी कर सकेगी।

धारा २५५–२५९ ७५--धारा २५५ जिलाधीश को अधिकृत करती है कि मालगुजारी उगाहने के लिये खेत से उपज उठाना रोक दे। धारा २५६ के अधीन जिलाधीश उपज को काटने तथा एकत्रित करने से रोक सकता है। धारा २५६ के अधीन मालगुजारी उगाहने के प्रकार धारा २५७ और २५८ में दि रे हुए हैं। हमारी सम्मति में जिलाधीशों को ऐसे असा- धारण अधिकार देने उचित नहीं हैं। अतएव हमने इन धाराओं को छोड़ दिया है।

धारा २६०

७६—शारा २६० में मालगुजारी के उगाहने के प्रसारों (processes) का वर्णन दिया हुआ है। अधिकारियों को केवल स्वयं बाकीदार को ही गिरफ्तार तथा रोक रखने का अधिकार हमने दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त भार के सिद्धान्त पर कोई भी व्यक्ति दूसरे की मालगुजारी के लिये पकड़ कर गिरफ्तार नहीं किया जा मकता ह। धारा २६०-क, ख और ग में हमने भिन्न-भिन्न प्रमारों (processes) की प्रक्रिया (procedure) दी है।

७७--धारा २६२ में क, ख,ग तथा घ में हम लोगों ने नादेहन्दों की अचल सम्पत्ति से मालगुजारी उगाहने की प्रक्रिया दी है।

धारा-२६२ क, ख, ग और घ धारा २६३ और २६३-क, ख, ग

७८—धारा २६३ कलेक्टर को अधिकृत करती है कि मालगुजारी की उगाही के लिये गांव को कुर्क कर ले। हम लोगों ने कुर्की में रखने की अवधि ५ साल से घटा कर ३ साल कर दी है और यदि बकाया शीच वसूल हो जाय तो कुर्की खंडित कर दी जायगी। हम लोगों ने यह भी प्रबन्ध कर रक्खा है कि इस अधिकार का व्यवहार गांव के किसी विशेष क्षेत्र में भी हो सकता है। इस कुर्की के परिणामों का दिग्दर्शन धारा २६३—क, ख, ग और घ में दिया है।

हमने यह भी रक्खा है कि इस बारा के अधीन प्रार्थना-पत्र तथा प्रिक्तियाओं (proceedings) में लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अध्याय ९ और १० (इस विज्ञान से संशोधित होने के बाद) लागू हो जायंगे।

२६३–घ

अध्याय ११

सहकारी फाम

७९--हम लोगों ने घारा २६५ में ५० एकड़ से घटा कर ३० एकड़ की सीमा कर दी है। इस घटाने के कारण सहकारी फार्मों को प्रारंभ में विश्वष प्रोत्साहन मिलेगा।

घारा २६५

८०--२७८ एवं २८२ धाराओं को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इन विषयों का समावेश विशेष औचित्य के साथ नियमों में किया जा सकता है।

घारा २७८ और २८२

८१--फार्मी के नये सदस्यों के बनाने के नियमों के निरूपण करने का अधिकार हमारी सम्मति से फार्म ही को होना चाहिये।

धारा २८४

अध्याय १२

विविध

८२—-२९९ (ङ) तथा ३०१ घाराओं को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि हमने उन्हें अनावश्यक समझा। हमने घारा ३०५ की उपधारा (१) को भी छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी सम्मित में घारा ३०६ की उपधारा (२) और (३) में क्यि हुए साधन प्रांतीय सरकार एवं सरकारी कमचारियों की रक्षा के लिये पर्याप्त थे और अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है कि और किसी दूसरे को भी इस रक्षा के साधन प्राप्त हों।

धारा २९९,३०१ और ३०५

८३--हम लोगों ने इस विधान की अनुसूची ३ में वादों, प्रार्थना-पत्रों एवं प्रिक्षयाओं को सुननेवाले न्यायालयों का विवरण दिया है। इस अनुसूची में दी हुई प्रिक्षयायें
इसी अनुसूची म दिये हुए माल के न्यायालयों द्वारा ही सुनी जा सकेंगी। इस विधान के
अन्तर्गत अन्य प्रिक्षयायें, जो उसमें विणित नहीं हैं, समर्थ दीवानी न्यायालय के सामने
प्रस्तुत होंगी। तहसीलदार, असिस्टेंट कलेक्टर और कलेक्टर या प्रितकर अफसर को
(जिसे हमने आवश्यकतानुसार उचित समझा है) मूल न्यायालय बना दिया है। छोटेछोटे मामलों को छोड़कर, जहां कमिश्नर के यहां केवल एक अपील होने की आज्ञा दी
गई हैं, अन्य मामलों में हमने बोर्ड को दूसरी अपील सुनने का भी अधिकार दिया है।
मने ऐसा प्रशन्य रक्खा है कि यदि किसी प्रक्रिया में किसी स्वाधित्व के आग्रम का प्रश्न

धारा ३०४-क, ग डठ खड़ा हो तो फ़रीक को उचित समर्थ न्यापालय में बाद प्रस्तुत करना चाहिये। हर हालत में हम रे विधि $(l_{\rm TW})$ और सामर्थ्य $(j_{\rm H}rlsGlobio_2)$ के विधि ं पर माल-परिषद् को निगरानी का भी अधिकार दिया है।

्धारा ३०६–क ८४—हम लोगों ने नए विषय का जमाबेश किया है और अवल सम्पत्ति के विषय में शका का हक उड़ा दिया है। हरारी सम्मति में हक-१५० का ग्रीवन समाप्त हो चुका है आर उसको बना रे रखार िर्फ झगड़े की जड़ होगी।

धारा ३०६–ख ८५—यू० पो० देनेन्सी ऐक्ट मे यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि थोड़ी जन— मंह्या वाले क्षेत्रफलों म अर्थात् बुन्देलखंड श्रेयमुना के दक्षिण भाग में इलाहाबाद में इटावा, आगरा आंर मयुग में दो एकड़ के खेत्रफ श्रेष्ट एक इसान लेना चाहिये। अतः हम लोगों ने मामान्यतः यह मान लिया है कि इस दिथान में क्षेत्रफल लगाने के सम्बन्ध में उपरोक्त स्थानों म दो एकड़ एक एकड़ के बरावर भानना चाहिये।

धारा ३०७-क े ८६-ह । भारा ४ त्याग दी है और उसके स्थान पर घारा ३०७ (क) बना दी ह, जिममें अनुसूर्य। ४ की सूची १ में विणत ऐक्टों के निवर्तन (repeal) का वर्णन है और माथ हो साथ सूची २ म यू० पी० लन्ड रेवेन्यू ऐक्ट के व्यापक संशो- घनों का वर्णन है। इन संशोधनों में बटबारा, मालगुजारी की उगाही तथा बन्दोबस्न के अध्याय विशेष रूप से छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि इन विषयों का समावेश इस विधान म हो चुता है। लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट में तीन अपीलों का निरंश है, अब केवल २ ही अपीलों की अनुजा दी गई है और विधि के विषय में (on a point of law) निगरानी का भी अधिकार दिया है। दाखिल खारिज तथा अविवादग्रस्त उत्तराधिकार के मामले अब पंचायती अदालत द्वारा निर्णीत होंगे। दूसरे मामले तहसीलदार के पास भेज जायंगे जो यदि विवादग्रस्त है या जिनम हस्तान्तरण अवैध प्रतीत होता है, नो तहसीलदार उनको हाकिम परगना के पास भेज देगा।

८७—यह बिल १० जून, १९४९ ई० के विशेष गजट में प्रकाशित हुआ था और हमारी सम्मति है कि अब संशोधित बिल किर से प्रकाशित कर दिया जाय ।

गोविद वल्लभ पन्त
हुकुम सिंह विश्वेन
चरण मिंह
विश्वमभरदयाल त्रिपाठी
‡द्वारका प्रसाद मौय
चतुर्भुज शर्मा
अलगुराय शास्त्री
*त्रिलोकी मिंह
शिवदान सिंह
मुजफ्कर हसन
*जयपाल सिंह
*रामशंकर लाल
बलदेव प्रसाद सैलानी
†फूलसिंह
भगवानदीन सिश्र

*एस० ऐजाज रसूल
*मुहम्मद जमशेद अली खां
*मुहम्मद जमशेद अली खां
*सुल्तान आलम खां
†जगन्नाथ बस्श सिंह
विरोग्द्र शाह
हर गोविन्द सिंह
राघवेन्द्र प्रताप सिंह
बेजनाथ
राप्रचन्द्र गुप्ता
अस्तर हुसैन
सुमत प्रसाद जैन
*रामनारायण गर्ग
*फूल कुंबरि
*के० ऐजाज रसूल (वेगम)
*सुरेश प्रकाश सिंह

‡अपने संतोधन के अधिकार को रखते र्कमतभेद की टिप्पणी पर उगिश्रत। †टिप्पणी सहित। नस्थिया

मतभेद लेखे

सवश्रो माहम्मद जमशद यलो खां, एजाज रसूल, सुल्तान श्रालम खां ग्रोर श्रीमती के० एजाज रसूल के मतभेद का नाट

१—विक अलल औलाद धमार्थ प्रयोजनों के लिये कानून (statute) (१९१३ हैं के विक ऐक्ट नं ०६) द्वारा पूष्यार्थ इन्डाउमेंट (endemment) घोषित किया गया है। जब तक यह ऐक्ट (कानून) रहता है तब तक इसके आदेश मान्य होगे। इस विचार से सभी उलल औलाद विकां को जमीदारी विनाश बिल के पैरा ७८ के बाक्य खंड (क) में रखना चाहिये।

२—यदि यह मत स्वीकार नहीं किया जाता, तो वक्क अललओलाद को ऐसा वक्क समझना चाहिये, जिसगे वक्क निया के विश्व को (descendant), उत्तराधिकारी (heirs)या सम्बन्धियों के लिये हैं एक वक्फ हैं और प्रत्येक फलभागी (benefi lary) और उसकी आखा उत्तराधिकार (nheri-tance) के साराण्य निय्मों के बजाय वक्फ के हप में वास्तविक लाभों का एक भाग प्राप्त करेगे। यदि दिसी वदण्यक्ति उत्तराधिकार के सामान्य कानून को हो चलने दिया, तो प्रत्येक वक्फ वर्षों के व्यक्तियत कानून के अनुसार प्रत्येक हिस्सा पाने वाले का लाभों में से कोई भाग (शेयर) प्राप्त होता है। ऐसे कानून से पृथक बात वे वल वितरण सम्बन्धी है, जो व्यक्तिगत कानून वे अनुसार नहीं किन्तु वक्फ कर्ता की इच्छा के अनुसार है। कोई कारण नहीं कि प्रत्येक पलभागी (line ficialy) को लाभों की उस सीमा तक उसमें साझीदार क्यों न समझा जाय जहां तक यह वक्फ के अधीन भाग प्राप्त करने का अधिकारी है। इसका यह मतलब होता है कि यदि वक्फ की उपेक्षा की जाय, तो उच्चित यह होगा कि उवत दक्फ के अधीन प्रत्येक फलभागी (beneficiary) लाभों की उस सीमा तक, जो वह अपने उपयोग वे तिये प्राप्त करने का अधिकारी हो और फल की उस सीमा तक, जो वह अपने उपयोग वे तिये प्राप्त करने का अधिकारी हो और फल की उस सीमा तक जो दवपद क्तां वाले की योजना वे अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को मिलेगा, गध्यवतीं (intermediaty) समझा जायगा।

किसी वक्फ अलल औलाद (वहाजों के प्रति) के अधीन ऊपर बताये गये अधिकारों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुये पैरा ३ (१) में मध्यवर्ती (111t (111 (1121y) की परिभाषा में शब्द "किसी वक्फ, टस्ट या धर्मादाय के अधीन कोई फलभागी, जो दास्तविक लाभों का एक भाग ऐसे भाग को सीमा तक अपने ताभ के लिये प्राप्त करने का अधिकारी है" सम्मिलित होने चाहिये। इस शब्दों को मध्यवर्ती (11 tc1111cd121y) की परिभाषा सम्बन्धी वाक्यखंड १ में जोड़ा जाना चाहिये।

इससे किसी फलभागी (heneficiary) को वबफ अललऔलाद (वंशको के प्रति) के अधीन प्राप्त होने वाले पुनर्वासन अनुदान (relabilitation giant) की धनराशि पर असर पडेगा, जो किसी आस्थान में साझीदार की तरह एक यूनिट समझा जायगा।

३--प्रत्येक फलभागी (beneficialy) के देय प्रतिवर और पुनर्वासन अनुदान (rebabilitation giant) को इस ढग से सुरक्षित रखना चाहिये जैसा उवत बिल के पैरा ७१ और ७२ में व्यवस्था की गई है। जमीदारी विनाश ऐदट के प्रयोजनी के सिवाय वक्फ अललऔलाद वैध हैं और लागू करने योग्य है। किसा भी फलभागी (beneficiary) की पूजी विशेष कार्य में लगाने और व्यय करने का अधिकार व होगा, जिससे उसके उत्तराधिकारियों को हानि पहुंचे, जैसा कि उक्त वक्फ की योजना में दिया हुआ है।

४--प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान (rchalilitation grant) किसी भी बता में विसी मृतवल्ली (Musawalli) की नहीं दिया जाना चाहिये। कानन में बान मृतवल्ली क्वेंबल एक मनेजर हैं। वह एक फलभागी (lentfolary) के हो नकता है आर उस हेसियत से उसको वैसा ही समझा जायगा, जसा कोई दूनरा कलभागी (bal floiard), लेकिन इसके अतिरियर उपको रोई विधिक है नयन नहीं है। त्रियी कोसिल ने इन शब्दों में उसकी स्थिति गा वर्गन किया है--

श्री अमीर अर्गी ने निर्मय देते हुये कहां — "जय एक बार प्रख्यापित कर दिया जाता है कि कोई विशेष संपति वक्क हैं या किनी ऐसे पद का प्रयोग किया जाता है, जिसने वक्क या अभिगाय प्रगट होता हो, तो ववशासी के अधिकार समाप्त हो जाते हैं ओर उसकी निश्चियत भाषान की हो जाती है। एक्क का मनेजर मुतवहली, एवर्नर मुपरिटेटेट या अपूरेटर हैं। खानताह की दशा में अध्यक्ष सम्जादानशीन कहलाता है। किन् तो सम्जादानशीन को ओर न मुतवहली को वक्क की संगत्ति में कोई अधिकार प्राप्त हैं। उक्त मंदित में उमे अधिकार प्राप्त हीं है और पारिभाष्टिक अर्थ में वह एव इन्हीं नहीं है। वक्ष नामें में संपत्ति दृश्टियों को इस्तांतरित नहीं को जाती इस्लाम मानून के अधीन जिमका कोई वक्ष कायब दिया जाता है उसी क्षण वक्ष के सम्पत्ति संबंध सभी अधिनार दवक के नहीं रह जाने और अग्रवात के हो जाते हैं।"

क्यूरेटर चाहे वह मुतवल्ली या सज्जाहानकीन या किसी दूतरे नाम से पुकारा नाए केवल एक भैनेजर ह। १९२०, ३ पी० मी०, पष्ठ ४४ पृष्ठ ४६ पर स्तम्भ २ के अनुसार जिसूका उद्धरण एक पहिले के मुकदमें से दिया गया है, कु दला १९२२, पी० सी० पृष्ठ १२३ पृष्ठ १२७ स्तम्भ १।

ज्योंही जमींदारी का विनाश हो जायगा प्रत्येक जुतवल्ली ज्यावहारिक रूप में कार्यरहित अधिकारी (Fulc-tous onicio) हो जायगा। उत्तके लिये प्रवन्य करने को कुछ नहीं रह जायगा। बहुत सी दशाओं में एक जुतवल्ली की हैसियत किसी येतन भोगी मनेजर से अधिक नहीं है। अनेक दशाओं म मैनेजरों की एक कमेटी मुलदल्ली के कर्तांचों को करा। हा इन कारणों से प्रतिफल और पुनर्वासन अनुदान पाने वाला ज्यक्ति कोई मृतवल्ली नहीं, विन्य उपर बताई गई विधि से अपने अपने फलभागी स्वत्य के अन्सार प्रत्येक फलभागी होना जाहिये।

- (१) मोहम्मद जमशेद अली खां।
- (२) एजाज रसूल।
- (३) के० एजाज रसूल वेजम ।
- (४) सुल्तान आलम सां।

ता० २१ दिसम्बर, १९४९ ई०

श्री रामशङ्कर छाछ के मतमेद का नाट

प्रान्त को संयम्न बनाने के बिषय में होने वाली प्रगति के सम्बन्ध में जमीं बारी उन्मूलन और मूमि-ध्यवस्था (लैंड रिफार्म) में बहुत विलम्ब हो चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता ह कि वतमान बिल के आदेशों में इन दोनों समस्याओं को सन्तोषजनक रूप से हल किया गया ह। इस बिल के आदेशों का सामान्य रूप से समर्थन करते हुए मुझे इस बात का खेद ह कि उनत बिल के आदेशों में निम्नलिखित संशोधनों की आवश्य-

१—बारा २१ उस भूमि के सम्बन्ध में है, जो भूल से जमींदारों की सीर और खुदकाइत लिखी गई थी, यद्यपि वह वास्तव में काइतकारों के कटजे में है। दुर्भाग्यका मेरे जिले अर्थात बस्ती में एँसे हजारों किसान है। कांग्रेस सरकार ने इत लेखों का संशोधन करने के लिये दो बार विशिष्ट अधिकारी नियुक्त किये, किन्त अब भी कुछ ऐसे किसान हैं कि जिन्होंने अपनी काइत की भूमि पर दावाँ नहीं किया और इसलिय उनके नाम नहीं लिखे जा सके। चंकि पिछली विशेष कार्यवाही में परिस्थितिवश लैंड रेबेन्य ऐक्ट की धारा ५४ के अधीन क्रान्नी कार्यवाही नहीं की जा सकी अधिप इसका बिस्तृत और पूर्ण प्रबन्ध किया गया था कि रिकार्ड अफसर के निर्णय (findings) ठीक उतरें । उपर्युक्त त्रुटियों के कारण कुछ अहालतों ने रेकर्ड अफतरों के निर्णयों को उन मुक़दनों में नहीं माना है, जो जमीदारों ने यक्त प्रान्तीय कब्जा आराजी ऐक्ट की धारा ६३ के अधीन या किनिनल प्रोसीडचोर कोंड की धारा १४५ के अवीन दायर किये । परिणाम यह हुआ कि अधिकांश काश्तकार अपने जीविकायालन के केवल एकमात्र साधन से वंधित कर दिये जायेंगे। बहस के समय यह एक भावना थी कि इस बारा को इस प्रकार बनाया जायगा, जिससे उन सब दखीलकारों की अधिवासी संबंधी अविकार प्राप्त हो जायं, जो १३५६ फस्ली में रिकार्ड सम्बन्धी कार्यवाही में दर्ज किये गये थे। किन्तु घारा की वर्तमान शब्दावली उपर्युक्त भावना के अनुसार नहीं है। इसलिये या तो यह धारा इस प्रकार बनाई जाय, जिसते, उपर्युस्त भावना प्रगट हो या वर्तमान रूप में ऐसे दखीलकारों को फिर से कब्जा दिलाने के आदेश बनावें जायं जो उपर्युक्त निर्णयों के फलस्वरूप बेदखल हो गये हों। घारा २२४ उक्त बिल के मूल आदेशों में से एक है। भूमि के पुनः वितरण करने के प्रश्न का यह एक इसरा हल है। हममें से कुछ लोग, जो कुछ सीमा तक उक्त भूमि को फिर से बांटने के लिये उच्छक थे, इस घाराके पक्ष में थे, क्योंकि इसने हमको सीला निर्फारण (demareation) संबंधी कठिनाई नहीं पड़ती और फिर भी भमिहीन असामियों या शिकमी काश्तकारों को दिये जाने के लिये वहत कम रक्तवा बचता है।

भूमि को फिर से वितरण करने की अपेक्षा इस घारा से बहुत से काइतकारों को अधिक सुरक्षा और अधिकार प्राप्त होते हैं। कमेटी ने घारा १८२ में मूल खाते के रूप में ६ के एकड़ स्वीकार किया, किन्तु इस घारा में इसने इस सीमा को ८ एकड़ तक बढ़ा दिया है। परिणाय यह होगा कि शिक्षमी काइतकारों की अधिकांश संख्या, जिन्होंने भूमिचरी अधिकारों को उन्ते बिल के मूल आदेशों द्वारा प्राप्त कर लिया है, अब पांच वर्ष बाद बेदखल कर दिये जायेंगे। में समझता हूँ कि इन सीमाओं को घटा कर ६ की एकड़ कर देना चाहिये।

उपर्युक्त विशेष विवरण के साथ में कमेटी की सिफारिशों से सहसित प्रगट करता हूँ और उस पर अपने हस्ताक्षर शर्त के अधीन करता हूँ कि हाउस में यदि अवस्यक होगा तो संशोधनों को प्रस्तुत करने का मुत्रे अधिकार होगा।

रामशंकर लाल।

श्री जयपाल सिंह और श्री द्वारका प्रसाद मौर्य के मतभेद की टिप्पणी

धारा १३ के चनुसार जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-व्यवस्था विल में २४० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींटारों की सीर के शिकमी कास्तकारों की वंशानुनानी अधिकार दिये गये हैं, जिन्तु २४० ह० स कम माछगुजारी देने व ले जमींद रों के शिकमी काश्तकारी और काश्तकारी के शिकितियों के। अथवा अधिवासियों की, जिनके कब्जे में जमीन है और जिसे वे जातते रहे हैं, वंशानुगामी अधिकारों से वंचित ख्या गया है। इनक संख्या साहे ६३ लाख के लगभग है। इस प्रकार इतने काश्तकारों के भाग्य का कैसला ४ वर्ष के लिये वड़े काश्तकारों पर ही नहीं, विलक कोटे-कोटे जमींदारों के रहम पर कोड़ दिया गया है। जब हम लगभग सवा करोड़ काश्नकारों के फ़ायदे के लिये, जिनमें ६३ छाख शिकमी काश्तकार मी हैं, जमादारी का उन्मूलन कर भूमि-सुधारकर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं कि अधि के लगभग छोटे किसान उसी जमींदारी दलदल में फंसे रहें मौर वे वड़े-बड़े कारतकारों मथवा छोटे जमींदारी के पंत में फंस कर बेदखळी के ळाखों मुकदमें। में ग्रापस की वैमनस्य रूपी चक्की के पाटों में पिसते रहें। देवने में आया है कि छटे जमींदार व बड़े काश्तकार एक नहीं, दे। नहीं, बिक्कि पांच-पांच ग्रौर दस-दस मूठे मुकदमेां में उन्हें फंसिये रहते हैं। उनका यही उद्देश्य रहता है कि काश्तकार गरीबी से तक्ष है। कर, बार-बार भदालतें। में भाने-जाने से ऊव कर, काफी भपव्यय और गवाहों को छाने तथा उन पर व्यय करने से लाचार होकर जमीनों के। छोड़ दें। दूसरी श्रोर वकील भी उनसे रुपया ही चूसते हैं। वास्तव में कवीलवर्ग से भी उनके। कोई कानुनी सहायता नहीं मिलती। कारण यह है कि पध्यवर्ष के जमींदार लोग हो लगभग वकील है।ते हैं ग्रौर न्यायाधीश भी इसी वर्ग के होते हैं।

जब हमने यह सिद्धांत एक बार नहीं, धनेक बार स्वीकार किया और भूमि-सुधार निमित्त प्रस्ताव रखते हुये अबिज भारतीय कांग्र स कमेटी ने बार-वार स्वीकार किया कि भूमि उन जोतने वाले लोगों के पास जानी चाहिये अथवा वही लोग काइतकार हैं, जो जमान को अपने हाथ से बोते-जोतते और इसमें मेहनत तथा परिश्रम कर के फसल पैदा करते हैं, तो अब कें ई कारण नहीं दिखाई देता कि हम काशतकारों में यह भेद रक्खें कि एक वे काशतकार हैं, जो स्वयं हल नहीं जोतते और खेत में मेहनत तथा परिश्रम नहीं काते और दूसरे वह, जो स्वयं हल चलाने हैं। इस प्रकार हम अपने बुनियादो सिद्धांत केंग हो समाप्त कर रहे हैं। शिक्रमी तथा दूसरे प्रकार के काशतकार भी तो असलो काशतकार ही हैं। वे पांच साल तक और भी घिसटते रहें, इसका कोई कारण सुभे तो दिखाई नहीं देता। इससे स्पष्ट

है कि इस बिल द्वारा मध्यवर्ग का एक प्रिविटेज़ क्लास (privilege class) बन जायगा, जो बिल के उद्देश्य के बिलकुल विपरीत होगा।

धारा २१ में दर्ज काश्तकार अधिकतर हरिजन अथवा भूमिहीन मजदूरों में से हैं। दूसरे उन कोटी-कोटी जातियों में से हैं, जो पिकड़ी हुई हैं। इसलिये इस मेद के कारण ऊचे दर्ज के लोग यथवा मध्यवर्ग के कौरतकार, जिसमें सभी छोटे-छोटे जमींदार समितित हैं, अपने हिनें। की रक्षा करने में ही केवल सफल नहीं होंगे, बल्कि अपने से कोटे काश्तकारी की, जी कुल काश्तकारों में लगभग बाधे हैं, पांच साल तक और यहीं तक नहीं इससे भी ग्रधिक समय तक सामाजिक ग्रीर शार्थिक गुलाम वनाने ग्रीर भविष्य के तिये ग्रपने राजनीतिक अधिकारें को इस ग्राधार पर कि वे लेग जमींदार, सरमायेदार और हर प्रकार से समर्थ हैं, बचा सकने में समर्थ होंगे। ग्रामतौर से जमींदार लेग चाहे वह कोटे हों अथवा बड़े, कोटी-कोटी जाति के लोगों की, जिनकी हमेशा से सामाजिक तथा गार्थिक दशा शोचनीय रहा है, ग्रधिक लगान ग्रौर ग्रविक नजराना द्वारा उनका ग्रधिक शोषण करने के निमित्त अपनी जमोन लगान पर उठाते रहे हैं। दूसरे बड़े काश्तकार भी अपनी कारत से ग्रधिक भूमि उन शिकमी काइतकारों के। उठाते रहे हैं, अधिक से अधिक शोषण किया जा सकता रहा है। ये छाग बहुत दिनें। से अपनी भालगुजारी अथवा लगान का दुगुना, चारगुना ही नहीं, बल्कि दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह गुना तक वसूल करते रहे हैं और वड़ी बड़ी रकमें नजराने के रूप में लेते रहे हैं। फलतः ऐस किमाने। के काटे। ग्रीर दुखों तथा उनके इस शोषण के कारण ही कांग्रेस ने जमोंदारी प्रया का उनमूलन करने का निश्चय किया था। यदि हम इस प्रकार की कमी इस कानून में छोड़ जायेंगे, तो इसका यह परिगाम होगा कि वाच के लोग ही जमीन को सदा अपने हाथों में रख सकेंगे और इस मध्यवगींय काश्तकार ग्रौर जमींदार, जो श्रवनेग्राप तो जोतना-बोना जानते नहीं ग्रौर जो सदैव कम मजदूरी पर जुतवाते और बुगाते हैं भौर उन करोड़ां खेतिहर मजदूरों की गाढ़े पसाने का, कमाई का, जिस उन्होंने मेहनत तथा परिश्रम करकं अपने. हाथ से हला जोत कर पैदा की है, मुक्त में दुरुपयांग करते रहेंगे और सदा मजदूरीं का खून चूसते रहेंगे। परिणामस्वरूप बड़े-बड़े काश्तकारों तथा छोटे-छोटे जमींदारों के पंजों में जमीन सदा रहेगी ग्रीर उसके बोने ग्रीर जीतने वालें के हाथ में कभो अधिगी ही नहीं। जिन जमींदारों के पास जमीदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि का कुछ भी भाग उनके पास काश्त के लिये नहीं रहेगा उन को गांव-ंसमाज के अधिकृत भूमि में से काश्त के छिये देने की स्वीकृति की गई है, जो सिद्धान्त गलत है। ऐन जमींदारों ने कभी स्वयं खेती नहीं की है ग्रौर यदि वह किसी भी प्रकार खेती करते होते ते। उनके पास अवश्य ही काश्त में भूमि होती। यही कारण है कि ऐसे जमादारों के पास

खुडकारन की मृति नहीं रही है, क्येंगिक न तो वे स्वयं खेती करते थे कीर न उन्हेंनि वेईमानो अथवा चाळवाजी से प्रपने कन्ते में भूमि को बनाये रक्का वरत उन्होंने उसे लगान पर उठा रक्खा। इस प्रकार जमींदारीं की जमीन देना न्याय-संगान नहीं है।

इन बानें: का ध्यान में रखकर हमें अपने निजी लाभ की छोड़ देना होगा। किनानों हार, किये जाने वाले शोपण की भी रोकना है। गा। इस बिल में आमूल परिवर्तन करन चाहिये, क्योंकि इस विल में ऐसे किमानी के। भी मान लिया ग्या है, जा इसरा का शायण करते रहे हैं। जहां हम लाखीं किसानें की उन्नत करना हे वर्न हमें करे। हों खेतिहर मजदूरी और उन गरीव किसानी का भी उन्नत करन होग, जिनक सारा जीवन हो खेती पर निभर है। उनके साथ न्याय करने के तिये यह आवश्यक है कि उन सभी काश्तकारी की एक ही श्रेणों में माना जावे क्रोग काइ-कारी में अभी ने कोई भेद-भाव न रक्षा जावे। इस काइनकार कार्यकार के भेद-भाव की अभी से समात किया जावे। यदि हम देना नहीं करते ते। इससे अमि-मुधार विळ का उद्देश्य स्वयं हो समाप्त हो जाता है। सब के भृमिधर हो। जाने के समान अधिकार मिल जाने चाहिए। यदि यह भी नहीं है। सकता ते! सभी शिकमी काइतकारों की अपने लगान का पन्द्रह गुना धन जमा कर भृमिधर ग्रधिकार सुरक्षित करने के छिये ग्रवसर देना बहुत ही सावश्यक है और उन्हें सपने गाढ़े पसीने की कमाई के दुरुपयाग होने से बचाना चाहिये। उन्हें यह सहलियत होनी चाहिये कि वे भी अपना रुपया इसो समय जमा कर भूमिधर के ग्रधिकार प्राप्त कर सकें। गांच साल के बाट यदि अनाज और दूसरी चीजों के भाव गिर गये, तो के ाई भी शिकमी यथवा यधिवासी काशतकार पपना रुपया जमींदारी-उन्मूलन कोष में जमा नहां कर सकेगा ग्रार भूमिधर बनने के वंचित रह जायगा। इस तरह से हम करीब साढ़े ६३ लाख शिकमी अधिवासी काश्तकारी की, जो खेतिहार मजदूरों और विशेष कर पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों में से हैं, हमेशा के छिये भूमियर के ग्रधिकार से बंचित कर देंगे। इस समय जिस काश्तकार के। वंशानुगामी अधिकार प्राप्त है, यदि उसके द्वारा पैदा की हुई चीजों के दाम गिर जायं ता वह अपना दस गुना लगान जमा करने में कभी भी ममर्थ नहीं है। सकता ग्रौर भूमिधर नहीं वन सकता । जब व शानुगामी कारतकार हो समते समय में भूमिधर नहीं बन सकते ता बेचारे शिकमी और मधिवासी काश्तकारों के लिये तो सस्ते समय में लगान का १४ गुना जमा करना और भो कठिन है। जायेगा। ग्रतः सभी शिकभी काश्तकारों की सीरदार के अधिकार तुरन्त मिल जाने बहुत हो यावश्यक है अन्यथा वे कभा भी भूमिधर नहीं वन सके गे।

खेतिहर मजदूर, जो खेतें। पर काम करते हैं, जिनके पास अपने जीवन-निर्वाह के लिये खतन्त्र रूप से कोई जमोन नहीं है, उनके। भी कांग्रेस तथा इसः

ावल के सिद्धांतात्रसार सबसे पहिले रिहै ब्लिटेट (rehabilitate) करना ग्रावश्यक है; किन्तु इस बिल में उनके रिहै ब्लिटेट करने की कोई भी धारा नहीं है, उनके लिये केाई न केाई ज्यवस्था करनी आवश्यक है। (१) याम-समाज के पास जो भी जमीन खेत के लिये ग्रायेगी उसमें सबसे पहले खेतिहर मजदरों को देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। (२) मिमलित खेती (cooperative farming) में खेतिहर मजद्रों को सभी दूसरे काइतकारों की मांति मिमिलित करना चाहिये। कारण यह है कि यह वर्ग सदैव जमीन पर ही जीवन निर्वाह करता रहा है। वह मेइनती तथा परिश्रमी है और इसरे की अपेक्षा अधिक परिश्रम कर अधिक गल्ला पैदा कर सकता है, जिसकी इस समय देश का बहुत ही ग्रावश्यकता है। (३) इस समय लाखी एकड मि खाली पडी हुई है, उसको एकटम प्राप्त करके खेतिहर मजदरीं में बांट देनी चाहिये और नई ते। ड की भूमि खेतिहर मजदूरों का देने की •यवस्था (provision) की जाय। (४) बहुत से जमीदारों ने हजारों बीधे फर्जी कारत अपने नाम करा कर चपने अधिकार में कर रक्खो है, उसमें अच्छी पैटावार बढ़ाने के हेतु जमींदारों के पास जीत में रखने के लिये इतनी जमीन क्रोड देनी चाहिये, जी कि उनके परिवार के गुजारे के लिये तो काफी हो, पर उनका दुरुपयाग और उससे गरीबों का शाषण न हो सके। यतः यह ग्रावश्यक है कि जिन जमादारों ने जमींदारो-उन्मूलन प्रस्ताव के पास होने से पूर्व (ग्रथांत ८ ग्रगस्त, १९४६ ई०) ग्रपने फार्म बना लिये थे ग्रथवा बड़े पैमाने पर खेती कर रहे थे, उनका छोडकर बाकी जमीनें का प्राप्त करके खेतिहर मजदरों में बाट देना चाहिये। इस निमित्त किसी जमींदार के पास ३० एकड से प्रधिक भूमि न रहनी चाहिये। न्याय ते। यही है कि देश भौर समाज की उन्नति के लिये उन्हें ऐसी जमीनों की स्वयं ही छोड़ देना चाहिये, जिन पर वे स्वयं काइत नहीं करते और फसल पैटा नहीं करते। उनको कोई यन्य व्यवसाय करना चाहिये।

देश में यद्यपि सिंचाई और खाद को सह लियत सरकर की भीर से होते हुए भी जमीन की पैदाबार में दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है, उसका यही एक कारण है कि अधिकतर किसान स्वयं खेती नहीं करते हैं, बल्कि वे कागजी काश्तकार रहे हैं। हमें इस प्रकार के कागजी काश्तकारी तरीके की खतम करना है। भूमि उसी को मिलनी चाहिये, जी उसे जोतता है न कि दूसरे से ज़ुतवाता है। इस सिद्धांत की कियातमक रूप देने के लिये निम्नलिखित दो तरीके काम में लाने चाहिये:—

१—यदि कोई भूमिचर और सीरदार अपनी भूमि को अथवा उसके मांग की किसी अन्य व्यक्ति की जीतने के जिये उठावेगा अथवा जुतावेगा ती वह भूमि अथवा वह भाग ऐसे भूमिघर अथवा सीरदार के अधि कार में न रह कर बाली पड़ी हुई जमीन अर्थात वेकेन्ट लैंड (vacant land) घोषित की जाय और वह गांव-समाज के अधिकार में आ जाय।

२-- प्राम-समाज के। यह प्रिविकार है। कि वह इस खाछी पड़ी हुई जमीन और अन्य प्रकार की प्रिधिक जमीन के। ऐसे छोगें का ही दे, जो स्वयं बेती जातकर पैटाबार करते हैं ग्रीर जिन्होंने दूसरों के यहां मजदूरी पर खेत जीता है। विनाहज जीतने वाले के। भूमि किसी प्रकार भी नहीं दी जायगी।

यभी तक बहुत सी भूमि ऐसा है, जिसका सही इन्द्राज रेबेन्यू कागजात में नहीं है। पाया। जरोंदारी-उन्मूलन है।ते ही ऐसे काश्तकारों की समस्या, जो खेत पर काबिज रहे है, उसे जोतते जाये, किन्तु उनकी काश्त का इन्द्राज रेबेन्यू कागजें: में नहीं है. हमारे जामने एक भयानक क्ष्य घारण करेगी। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी काश्त के इन्द्राज के लिये हर जिले में सरकारो, गैर-सरकारों और घारा समाग्रों के सदस्यों की एडहा क कमेटी द्वारा ऐसी व्यवस्था को जाय कि जिससे सही-सहा इन्द्राज है। सके ।

वृतमान ऐक्ट की घारा १८० के सभी काश्तकार ऐसे हैं, जो भूमि की वर्षों से जीतते माये हैं, किन्तु जमाँदार और बड़े काश्तकारों के स्वार्धवश उनकी काश्त रेवेन्यू कागजों में दर्ज नहीं हो पाई है और इस घारा के अनुसार सभी केसों की वर्षों से स्टे (stay) किया हुमा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे ही भूमि के असजो जीतने वाले हैं। अतः भूमि के असली जीतने बाले सिद्धांत निमित्त उनकी अधिकार देने के लिये यह मावश्यक है कि उनकी सीर-दारों के अधिकार दिये जायं भीर उनकी लगान का दस गुना रुपया जमा कर भूमियरी अधिकार देने का प्राविजो (proviso) इस बिल में किया जाय।

शिक्रमी कारतकारी की टेनेन्ट इन चीफ की लिखित रजामन्दी से अपने लगान का दसगुना रुपया देकर भूमियरों अधिकार प्राप्त करने की धारा इस बिल में आई है, उससे एक प्रतिशत भी लाभ होने की आशा नहीं है। वमतीन परिस्थिति में हर जमींदार अथवा काश्तकार यह चाहता है कि अपने पास से एक इंच मी जमीन ने जाकर दूसरों की जमीन को प्रपन्न रच कर अपने अधिकार में लिया जाय। जिस किसी भी जमींदार अथवा काश्तकार से इस अधिकार के। दूसरों की देने की चर्चा की जाता है ते। वह इसका विरोध हा करता है। इस प्रकार की धारा लाने से कीई लाभ नहीं है। अतः असली काश्तकार के। सीधे (direct) तरों के से ही अधिकार देने की व्यवस्था को जाय।

इस विल की धारा २२६ के अनुसार पांच साल के बाद अविवासी असामी है। जायंगे, जो किसी समय भी धारा २२४ के अनुसार भूमिधर और सीरदार द्वारा बंदखल किये जा सकते हैं। यह भी भूमि के असली जोतने वाले सिद्धांत की अबहेलना करना है। भूमि जोतने वाले के यास रहती चाहिये। इसित्वये अधिवासि गों के। बेदखल न करने की बारा इस बल में लाई जानी चाहिये।

लामकर खेती (economic holding) ६ एकड़ हो होती चाहिये और ८ एकड़ लामकर खेती नहीं हो। शकती, क्योंकि एक हल की खेती दो बैलें से ठीक ढड़ से जीती जाय, ते। ६ एकड़ भूमि ही उसकी उसके लिये पर्याप्त है। एक साधारण परिवार के लिये भी ६ एकड़ भूमि पर्याप्त है। इससे अधिक भूमि दो बैलें से जुतवाना बहुत ही कठिन है।

हमें समाज में इस तरह के परिवर्तन लाने है, ताकि सब लेग बराबर हों ग्रौर जो जैसा काम करता है उसके। वैसा हो फठ मिल सके। यदि वह खेती करता है तो उसके। ग्रपनो फसल का पूरा हक मि उना चाहिये ग्रौर याद वह खेती नहीं करता ते। सुपत में उसे उस फल के। हड़पने से उसे रोकन प्राहिये।

र्दशावास्यमिदं सर्वं यंकिञ्चजगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जोथाः मा गृयः कस्यचिद्धनम् ॥१॥ ईशोपनिपद्।

हम यह सहन नहीं कर सकते कि हम अपने निजी लाभ के कारण दूसरें का शोषण करते रहें। किसानों और काश्तकारों द्वारा शोषण का भी हमें रोकना होगा और ऐसे किसानें।, जमींदारे। और काश्तकारे। को भूमि का अधिकार न दिया जाने, जो दूसरों का शोपण करते हैं।

२१ दिसम्बर, १६४६ ई०

जयपात सिंह, द्वारका प्रसाद मीय।

नोट—संयुक्त प्रान्तीय सरकारी जमींदारी-उनमूलन समिति रिवोर्ट खरड २ के श्रवुसार शिकमी काश्तकारों को संख्या—गृष्ठ ७ खतौनी भाग नम्बर १ (११) के श्रवुसार २४,२४,३८१।

पृष्ठ ८ खती पृष्ठ ,,	या २ (२) २ (४)		११,८६,०७४ । १४, ८३ ,७१८ ।
पृष्ठ ,,	ર (ફ)		११,५४,६०४।
	कुल योग	••••	६३,५६,०७८

जयपाल सिंह, द्वारका प्रसाद मार्थ।

राजा जगन्नाथ बख्दा सिंह का नाट

न इम रिपोर्ड पर अपने हस्ताक्षर इस बर्न के अधीन करता हूं कि नुझे हाउस में संदोधनों की प्रमृत काले का अधिकार रहेगा। में इस बिल में सिम्मिलित किये गये अनेक आदेशों और मिद्धान्तों में केवल असहमन ही नहीं हूं किन्तु उनसे भेरा घोर मतभेद भी है, फिर भी में मतभेद का नोट नत्थी नहीं करता हूं क्योंकि में ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की अधिकां दें दें कों में भाग नहीं ले सका था।

२३ दिसम्बर, १९४९ ई०

जगन्नाथ बल्जा सिंह

श्री मुख्तान गालम या. एम० एल० ए० के मतभेद का नेहि

मुझे खेद है कि में अपने साथियों से उन कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सहनत नहीं हूँ, जिनके बारे में निर्णय दिया जा चुका है और जिनका बिल में समावश किया गया है। में मानता हूँ कि यह अबसर जमीदारी विनाश के प्रश्न के गुण और दोषों पर विवेचन करने के लिये नहीं है। जैसा कि में कई बार कह चुका हूं कि पिछल कुछ दर्शों में एसी स्थिति और परिस्थितियां पैदा की गई है, जिनके कारण केवल देश और नारे प्रान्त के ही हित में नहीं बिल्क जमीदारवर्ग की रक्षा और मलाई के लिये भी जमीदारों का विनाश आवश्यक है। यह इतिहास का एक मुबिख्यात तथ्य हैं कि क्याँदार अपने गांव का एक मुख्य अंग और वहीं सम्पूर्ण देहाती समाज का म्छ विन्दु हुआ करता था। इसमें कोई मन्देह नहीं कि कुछ दिनों से इस प्राचीन व्यवस्था में भी भारता या। इसमें कोई मन्देह नहीं कि कुछ दिनों से इस प्राचीन व्यवस्था में भी भारता वा गया है जैसा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हैं, लेकिन इस चीज को उचिन ना ने कानून कब्बा आराजी में संशोधन करके अब्छी तरह दूर किया जा सकता था व्यक्ति इस कानून ने जिस ढंग में वह आजकल लागू है शोषण की तनिक भी गृंजान नहीं रक्षी है। इन लोगों को उपयोगी स्थानीय नेता बनाया जा सकता था और नहीं लोगों में प्रामीण-क्षेत्रों में विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम लिया जा मकता था।

म कार और संयुक्त प्रान्त के जमीदारों के बीच उसी प्रकार एक अन्तरिम समझौता हो मन्ता था, जिस तरह कि भारत-सरकार ने उद्योगपितयों को यह आइवासन देकर समझौता कर लिया है कि आगामी दस वर्षों तक उद्योग-अंधों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। यदि ऐसा करना ही आवश्यक था तो यह सरकार हल्के-हल्के जमींहापी-दिनाश योजना का अनुकरण कर सकती थी जैसा कि इस सम्बन्ध में पड़ोमी बिहार प्रान्त ने किया, यह योजना हर पहलू से अधिक व्यावहारिक है।

विमी भी प्रकार हो यदि जमींदारी-विनाश वास्तव मे हो जाय तो सरकार का कर्त्तच्य ह कि वह जमीदारो, उनके कुटुम्बियों और उनके आश्रितों के लिये यदि उदालक प से न हो सके तो एक उचित गुजारे की तथा समाज में अच्छा और उम्दा जीवन बितान के लिये आश्वासन देने की व्यवस्था करे। यह इस विवार से और भी जरूरी है. क्योंकि भारत-संघ के नये संविधान में यह व्यवस्था रक्खी गयी है कि मुआवज के सम्बन्ध में कोई मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है। यह स्मरण रहे के जमीदार इसी भूमि की संतित है और उनकी संख्या किसी भी प्रकार नगण्य नहीं है। प्रान्त में लगभग २३ लाख जमींदार है और लगभग ७ लाख कास्तकार शरह मोअइयन (Fixed tale tenints) और माफीदार (rent free grantees) है, जो आवहारिक रूप में सब प्रकार से जमींदार है । मान लीजिये कि प्रत्येक जमींदार के पांच आश्रित है, जिनमे उनके कुट्रम्बी और नौकर भी सम्मिनित हैं (जिनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण विचार होना चाहिये और जिनकी बिल ने अभाग्यवज्ञ अवहेलना की गई है), तो जमीदारी की आय से जीवन-निर्वाह करने वाले प्राणियों की संख्या डेढ़ करोड़ यानी भारत के इस सबसे बड़े प्रान्त की जन-संख्या के चौथे भाग तक पहुँचती है। उनको बेकार और निर्धन बना देना कभी राज्य के लिये लाभप्रद न होगा। यह बुद्धिमानी की नीति नहीं हो सकती । विशेषकर ऐसे समय में जबकि साम्यवाद भारत का द्वार खटखटा रहा है। यदि जमींदार राज्य पर भारस्वरूप थे, जैसे कि वे अब होके रहेंगे, तो ग्रामीण-क्षेत्रों में एक वर्गरिहत समाज स्थापित करने का विचार स्वप्नमात्र होगा। इस प्रकार जान-बूझ कर या अनजाने में हम एक और अधिक पिछड़े हुये वर्ग को जन्म देंगे, यद्यपि वे बृद्धिमान होंगे, किन्तु उनकी आर्थिक दशा बहुत ही क्षीण होगी।

पह भी अतिशय अवांछनीय है कि अब भी लमींदारों की निन्दा की जाती है और उनको गालियां दी जाती हैं। मृत्युशय्या पर पड़े, लेटे हुये किसी व्यक्ति की निन्दा करना मर्यादा और नैतिकता के समस्त सिद्धान्तों के विश्व है। इस दिशा में बढ़ाबा देने से जो गम्भीर परिणाम होंगे उनसे किसानों के हदय में जमींदारों के विश्व स्थायीक्षप से मृणा उत्पन्न हो जायगी और यदि घटनाचक निर्वाध गति से चलने दिया जायगा तो केवल इन तथा कथित पुरान पापियों के लिये ही नहीं किन्तु उनके बाल-बच्चों और आगामी पीड़ियों के लिये भी, जो इस विषय में जिल्कुल निर्दोध होंगे और जिनका समींदारों से छोई प्रयोजन न रहेगा, गांव नर्कतुल्य बन सकते हैं। प्रान्त की शान्ति और नम्बन्ता के नाम पर में सरकार से यह अपील करता हूँ कि जहां तक समींदारों का नम्बन्व है समींदारी-विनाश-कोष में घन संचय के लिये प्रचार संयम भाषा में किया जाय।

सरकार की नीति यह होनी चाहिये कि ज्ञनोंदार को अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिये प्रोत्साहित करें कदाचित इसी तथ्य के आधार पर छोटे—छोटे ज्ञमोंदारों को पुनर्वासन अनुदान देने की व्यवस्था की गई है पद्याप यह उपलक्षित रोति से हैं तथापि सरकार को मानना एड़ा है के उनका साम जिक्क देवित शरणाथियों की सी कर दी गई है और यह बात कदाचित, सत्य है।

यह स्मरणोत्र है कि कुछ समय पहिले जमींदारों को ब्यागर के लाइसेंस यह कह कर नहीं दिये गये कि उन्होंने उससे गिन्ते कुछ बिशेष बर्गुष्रों का ब्यागर नहीं किया था। इस प्रकार जमींदारों तथा नये उद्योग करने वालों को हतोत्साह कर दिया जाता है तथा चीर बाजारी करने वालों को प्रोत्ताहन निजता है। मैं यह बाहना है कि सरकार इस अभागे वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाये तथा एक प्रकार के जमींदार उद्योग को प्रोत्साहन दे। इसके अलावा सरकार को जमींदारों के प्राधितों को जीविका के साधन देने का उत्तरदायित्व लेना चाहिये।

अभी भी भूमि व्यवस्था का पूरा चित्र हमारे सामने नहीं है, क्योंकि यह नियम कुमायूं डिवीजन, सरकारी सम्पत्ति, म्युनिसिनैलिटियों, नोटीकाइड क्षेत्रों, टाउन क्षेत्रों और कैन्ट्रनमेंट बोर्ड पर लागू नहीं है। ऋण के सम्बन्ध में वह मसविदा, जिसके लिये अधिकारी बचन दे चुके हैं, अभी हमारे सामने नहीं है। इससे भी क्षतिपूर्ति की धाराओं पर काफी प्रभाव पड़ेगा। बिहार और मद्रास के जमींदारी-विनाश कानूनों में ऋण के सम्बन्ध में घारायें जोड़ दी गई हैं, यह और भी अच्छा होता यदि भूमि-सुवार का सारा ससविदा एक साथ प्रस्तुत कर दिया जाता ताकि सारे पहलुओं पर एक साथ विचार किया जा सकता और उसे एक साथ ही लागू किया जाता।

जमींदारों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत मसविदे में प्रतिकर तथा 'सीर और खुदकाइत' ही दो प्रमुख बातें हैं। हमें इनका अलग—अलग विदल्खण करना चाहिये। जहां तक प्रतिकर का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि यह केवल नाममात्र के लिये हैं, तिस पर भी जमींदारों के दुखों तथा संकट को और बढ़ाने के लिये इसकी बहुत सम्भावना है कि यह कई किस्तों में दिया जाय, क्योंकि इसके लिये धन प्राप्ति की आशा कम है। मसविदे के सुझावों के अनुसार यह प्रतिकर कुल सम्पत्ति का आठगुना उस बची हुई सम्पत्ति का होगा, जो कुल आय में से जमीन की व्यवस्था के खर्च का १५ गुना पिछली बाकी किस्त, भूमिकर, स्थानीय कर और भिम आय कर घटाकर बाकी रहेगी। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिये कि यह भूमि आय कर प्रयोकत्चर इन्कमटेक्स) पिछले साल ही जमींदारी—विनाश के समय से शुष्ट हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त विधि के उपरान्त जमींदारों के। नाममात्र के लिये जो प्रतिकर मिलेगा वह भी यिव बांडों में चुकता किया जाय, जिस पर उन्हें केवल २ १/२ प्रतिशत

नितथया १०९

ब्याज मिलेगा, तो जमीदार भी वर्तमान आय मे, जो भूमिकर के लगाये जाने के बाद यहुत ही घट गई है, ८० प्रतिशत कपी हो जायगी। इस हिमाब से यदि हम कुषि के अयोग्य बंजर, परती जमीन और बिखरे पेड़ो से उसकी आमदनी को भी जोडते हे तो उसका लाभ बीस प्रतिशत से भी कम रह जाता है, किसी व्यक्ति से उसकी आप का अस्ती प्रतिशत से भी अधिक त्यागने को दिना किसी प्रकार न्यायसगत नहीं है। नह जीवन की निवान आवश्यकताओं को कैते पूरी करेगा यह समझ से नहीं आता है।

9१ वी घारा के अन्तर्गत विचार यह जान पड़ता है कि सरकार ज़िमीदारी-विनाश कोष के संचय पर आशा किये येंगे हैं। यदि यह सफल ोती हैं तो वह नकर रुपयों में प्रतिलर देगी नहीं तो बांडों में। कई अवसरों पर सरकारी वक्ताओं ने इस तरह का अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है। नि सन्देह यह सरकार के लिये बड़ी समस्या है कि रुपय कहा से मिले, अपने साधनों के बल पर वह रुपया नक्द नहीं चुका सकती है, और भारत- सरकार ने इसके लिये उधार देना अस्वीकार कर दिया है। अधिकृत मुत्रों से नड़ी आशा प्रकट किये जाने पर भी जमीदारी-विनाश कोष के सचय की आज तक की सफलता से १७५ करोड रुपये जमा किये जाने की सम्भावना युक्तिसगत नहीं प्रतीत होती है, मेरा दृढ़ मत है कि प्रत्येक ज़मीदार को इस संचय में हार्दिक सहयोग देना चाहिये, परन्तु मुझे भय है कि इसकी मफलरा की आशा करना किन है। निपुण अर्थ गास्त्रियों का यह मत है कि मुद्रा का देहातों में इतना प्रचलन नहीं है कि य पि सन कृषक चाहें भी तो भी वे यह पूंजी दे सकें।

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि जमीदारों को इस विनाश योजना के अन्दर केवल नाममात्र का प्रतिकर मिलेगा उनका रुपना बांडो में चुकता करना उनके लिये और भी अधिक अनुचित और कठिन होगा, और अन्त में इसका परिणाम आर्थिक पतन होगा। इसलिये में एक सुप्ताव देना चाहता हू। कहा पाता है कि हैदराबाद के निजाम के पास प्रचुर धनराशि है, जो कि निरुपयोग पड़ी हुई है। यदि सयुक्त प्रान्त को सरकार उनसे या भारत-सरकार की मध्यस्थता की सहायता से कही दूसरी जगह से ढाई प्रतिशत ब्याज की दर पर १७५ करोड़ रुपये उपार लेने को बातचीत करे तो वह जमीदारों का रूपया नमृद भुगतान कर सकती हैं और साथ ही सब झंतरो, लोक अप्रियता और जमीदारी-विनाश कोष योजना के भार व्यय से बच जायगी। जुमीदारी को देने के बदले जैसे कि बाड़ी के बारे में किया जाता है, वे निजाम को भुगतान कर सकते है, जिसे कि व्याजरूप में प्रतिवर्ष ४ करोड़ से भी अधिक रुपये मिलेंगे औग इस प्रकार उनकी धन-सम्पत्ति बद्ध जायगी। इस ढंग से जमीदार अपने रुपयो को लाभप्रद व्यापार आदि में लगायें और इस प्रकार अपने जीवन-स्तर का निर्वाह करेंगे और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सम्बृद्धि करेंगे। किसानों को बिना कुछ भुगतान किये भूमिधरी के अधिकार मिल जायंगे और तब संयुक्त प्रान्तीय काइतकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई॰ [(यू॰ पी॰ एग्रीकल्चरल टेनेन्ट्स (एक्वीजिशन आफ प्रिविलेजेज)] के अधीन भूमिधर बनाने का जो प्रस्ताव किया गया है उसके फलस्वरूप सरकार की कई करोड़ के सारे लगानो या मालगुजारी से प्राप्त धन के आधे की हानि उठाने आवश्यकता न होगी । मुझे आज्ञा है कि संबधित दिशाओं से उपर्युक्त प्रस्ताव पर समुचित विचार किया जायगा।

यह विदित हो जायगा कि किसानों को भूमिधरी अधिकारों को प्राप्त करने के लियें दस गुना लगान सरकार को देना ही पड़ेगा, किन्त जमीदार को उसके जमीदारी अधिकारों के हस्तगत करने के बदले में उसकी वास्तिवक सम्पत्ति का केवल अठगुना ही दिया जायगा। सब के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिये और उनके साथ न्याय होना चाहिये और इसी एक सिद्धान्त के आधार पर जमीदार यथोचिन रीति से

दमग्न प्रतिहर (मुखावजे) का दावा कर सकता है, जिस के लिये जिस सभा-सचिव, चौघरा वरज पिंह ने अपनी जमीदारी विनाश नामक पुस्तक में सुझाव दिया है।

पत्ना भूमि, कृषि योग्य बंबर भिम और शिखरे हुए बृक्षों के लिये कोई प्रतिकर न दिया जायना जबिक जमींदारी-विनाश सिमिति में यहा तक कि समाजवादियों न भी पत्नी भिम के लिये दो छए। प्रति एकड़ देने का सुझाब रखा था। कृषि योग्य बंजर भूमि इत प्रान्त में एक करोड़ एकड़ है और इसलिये जमींदारों को १६ करोड़ छपए का हानि होती है। बिहार में यह भूमि जमींदारों के पास रहने दी गई है। बिखरे बृक्षों और जमींदार के खुदबाय हुए कुओं के लिये भी प्रतिकर दिया जाना चाहिये। मीर और खुदकाक्त भूमि की जमींदार को अतिआक्षयकता है, क्योंकि भिवय्य ये उने पूर्णकांग इसी पर अवलिम्बत रहना पड़ेगा। वर्तमान संविधान के अनुसार जो सीर निषया— नुमार शिकनी हा में कियो को दो जायगी, बहु हाथ में निकल जायगी। यह बिलकुल अमंगर है और इन कार्य-विवि से, जिये कि न्याय और वां के समस्त उद्देश्यों के निम्मिन किसी वियन पूर्वविध से कार्यन्तिन हुआ न सप्तझा जाग चाहिये, यह सम्भव हे कि उम्प पन के विधान पर से लोगों का विश्वास हट जाय। उन जमोंदारों के लिये लेप- गितक क्य से खन जोतने की कोई ब्यवस्था नहीं को गई है, जिन्होंने सीर भूमि को शिकनी नहीं कर दिया था और जो अब जनांदारों-विनाश होने के उपरान्त खेत जोतकर जीवन-निर्वाह करने के लिये बहुत उत्सक है।

उन्होंने निक्र हिनों में जुनाई नहीं को है, इसिक्ये की भूमि हस्तगत करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कोई दर्जा नहीं है। स्पष्टतः अकी जनकी आमदनी रहीं ओर इपी कारण उन्होंने अपने काक्तकारों से जबरदस्ती भूमि अपने जाक करने के कि वायस न ली। इपका भी ज्यान रखना वाहिये। परती भूमि, जोत में जान जायक वेकार पड़ी भूमि और इबर-उबर के बिखरे हुए पेड़ों को उनके राक्त म रहन दम अधिक बांछनीय है। ऐसा करने से इन विज्ञ के उद्देशों में कोई उमी रहीं आती, ननोंकि जहां तक परनो नूमि, जोन में लाने लायक बेकार भूमि तथा इबर-उबर बिखरे हुए पेड़ों से उनका मन्त्रंग है उनको मध्यवर्ती नहीं कहा ना सकता।

अब हुन बिच पर उनहो एक-एक घारा लेकर विचार करें। बारा ८ तथा पारा ६ के अन्तर्गत विज्ञापित के अनुतार प्रश्नेत आस्थान के मध्यवित्यों के समस्त अधिकार, आगम न मा स्वत्व श्रीमान् ममाट में निहिन है। गांव में स्थित कबस्यम या स्मन्नान-मूमि के मंत्रंत्र म इन बिल में कोई ब्यवस्या नहीं की गई। हिन्दुओं, नुसब्सानों तथा ईसाइयों की जपती-अपनी फबस्यान तथा स्वज्ञान भूनियां है। जिन व्यक्तियों की निजी इसारनें इत्यादि वन्यत्ति है उनके सम्यन्य में उनके वाय बन्दोशत करने की ध्वस्था बारा १२ के अरी को गई है। इस बारा में ऐने कबत्यानों तथा स्मज्ञान भूमि के सरूबन्य में, जो िनी कुरुम्य तथा मां का नम्यति है उनके साथ बन्दोबस्त केरने का कोई हवालाया जिक भी नहीं किया गरा है। इसी कारग यह अबन्त आवद्यक जिन के बाक्यलंड १२ के तन्तर्गन ऐमी व्यवस्था और की जाय जिने या सनझा जा सके कि रेते कब्रह्यानों नथा स्मज्ञान भूनि के सम्बन्ध में उन हुदुस्य नया वर्ष के साथ, रिनहो यह मन्यनि है, बन्दोबस्त कर लिया हा। उसमें जो पड यह हों उन्हें भी देन वाहिन को हैना बाहिने, जिपका उनमें स्वत्व हो । ऐसे किसें द रिनो में से, जो अब कत्र व्यान है, कु इ ऐने हैं, जो बिल हुल भर गए हैं और उनमें आग के जिय पूर्वे गाड़ने के वास्ते कोई स्थान नहीं रह गया है। इस कारण यह बहुत आवश्यक प्रनीत होना ह कि ऐसे गांदों में, जहां कबस्थानों की ऐसी दता हो, सरकार को चाहिये कि वह उपयुक्त क्षेत्र मुर्वे गाड़ने के लिये नियत कर दे और गांव-समाज से उसका कोई संबन्ध त रहे।

इस बिल की घारा ८ के जाराखंड—क के अनुपार समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। भोगायिकारों के लिये भी अपराद नहीं किया है या छूट नहीं दी है। इसीलिये यहअधिकार भी अब समाप्त हो जायेंग। जहां तक वक्फ का संबंध है ये अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक साल अनेक उर्स और मेले लगते हैं। इन अवसरों पर इतनी भीड़ होती है कि न केवल वक्फ़ों के अधीन जमीनों पर ही परन्तु मन्दिरों आदि के निकट की जमीनों पर भी दर्शनार्थी अपना अड्डा जमा लेते हैं। गांववासियों का सम्मान तथा भोगाधिकारों के कारण ही उ- प्रकृति मनुष्य ऐसे जन-समूहों में हस्तक्षप नहीं कर पाते। इसी कारण यह बांख्यनीय ए कि बिल की घारा १२ में ऐसी व्यवस्था और कर दी जाय जिससे घारा ८ के वाक्यखंड-क अधीन समाप्त किये गए अधिकार पुनः लागू कर दिये जायं और उस व्यक्ति के साथ, जो धारा ५ के अधीन विज्ञप्ति के फ्राजित होने के पहले से, जो एसे अविकार रखता था, बन्दोबस्त कर लिया जाय। दूसरा १६ तरीका है कि भोगाधिकारों पर यह ऐक्ट लागू न किया जाय।

९-ख--लगान के बकाया, अबवाब, सायर या अन्य देय, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले हुए हों, पहले की भांति ही उस व्यक्ति द्वारा वसूल किये जायेंगे, जिसे उन्हें वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो। प्रन्तु एसी डिग्नियों में बेदखिलयों का निषेघ है। जमींदार के लिये ऐसे देय वसूल करना द्वित कठिन हो जायगा और यह उचित ह कि यह व्यवस्था की जाय कि वे मालगुजारी के ब्लाया के रूप में दसल किये जा सकें।

घारा १२—मुझे प्रसन्नत है कि जोत के अन्दर वाले निजी कुयें काझ्तकार या सम्बन्धित व्यक्ति के ही रहेंगे। जैसा कि हाल में संशोधन किया गया है। किन्तु किजी कुओं को भी, जो जोतों के बाहर हैं, नध्यवितयों की ही सम्पत्ति माना जाना चाहिये और ऐसा न करने की दशा में उस व्यक्ति को उन कुओं के हस्तगत करन का उचित मुआविजा दिया जाना चाहिये।

वारा २४—इस धारा के निरंश से और अधिक अनुचित कुछ नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जनीन बच दी ह या दान में दे दी है तो उसका थह कार्य क्यों उस तारीख से, जब कि उसन ऐसा किया है, गैर—कानूनी समझा जाय। वाक्यसंड के निकाल देने से यद्यपि सरकार को कुछ अधिक प्रतिकर देना पड़ेगा किंतु न्याय और साम्य की यही मांग है।

वारा ३३——िक ही आस्थान के ले लेने से पूर्व, आगम ऋण सम्बन्धी सब प्रश्नों का समाधान कर लेना चालि । वाक्य खंड ६ के अधीन आस्थान को स्वत्वाधिकार में करने की सरकारी विक्रित प्रकशित होने से पूर्व, इन सब मामलों का समाधान हो जाना चाहिये। आस्थान सम्बन्धी किये गए मुतालबों के निर्णय करने के तरीके की व्यवस्था धारा ३५ और ७३ तथा धारा ३०४—क और ३०४—ख में निर्धारित कर दी गई है। यह बड़ा लम्बा—चौड़ा तरीका है और इससे मध्यवितयों का विनाश हो जायगा। इसलिये की धृता के विचार से इस सम्बन्ध में विशेष अदालतें स्थापित की जायें, जैसा कि बिहार में किया गया है। किसी भी दश्च में ऐसे मामलों में प्रतिकर या भुगतान न रोका जाय। प्रतिभूति लेकर जमींदार को इसका भुगतान किया जा सकता है। यदि ऐसा न हो सके तो जितने समय तक भुतगान न किया जाय उतने समय का सूद भी उसे दिया जाय।

धारा ४८ (ख)—किसी मध्यवर्ती की पक्की निकासी अब वारित करने में कृषि-कर की वनराज्ञिन घरायी जानी चाहिये। प्रतिकर के सम्बन्ध में में इस प्रश्न पर पहले ही विचार कर चुका हूं। कारण स्पष्ट ही ह। भविष्य में अबवाब लागून होंगे और इसी कारण उनके गुणक प्रतिकर में से घटा दिये जाते हैं, किंतु कृषि आयकर नारी रहेंचे और इसलिये उनके गुणक को नहीं घटाना चाहिये।

४८ (ग) — प्रबन्ध-व्यय, जो घटाया गया है वह उससे अधिक है, जिलजे की व्यवस्था कृषि आयकर ऐक्ट में की गई है। यह किसी दशा में भी १० प्रति संकड़ा से अधिक न होना चाहिए। लगान की ऐसी बकाया पर, जो वसूल न हो सके, वधीं कोई छूट

ही जाय। यह उस जमींदार पर दोहरी मार होगी जिसने पहले ही अलग से न हुए लगान के भाग पर मालगुजारी दे दी हो।

वन्त-हममें से कुछ ने इस विषय पर लम्बा-चौड़ा नोट प्रस्तुत किया है। जहां तक पुनर्वामन अनुदान के देने का सम्बन्ध है, यह बहुत अनु चित है कि 'वक्फ अललऔलाद' को एक इकाई माना गया है। यह उचित है कि वर्तमान फल भागियों को पृथक इकाइयां मानी जायं, क्योंकि व्यावहारिक रूप में वह पृथक इकाइयां ही है। तदनुसार घारा ७२ और ७८ को संशोधित करना चाहिये। घारा ७८ का स्पष्टीकरण 'वक्फ अललओलाद' के धार्मिक पहलू पर अनुचित हस्तक्षेप।। दान घर से आरम्भ होता है और इसीलिये कुट्म्ब या वंशजों के भरण-पोषण के सम्बंध में कोई व्यवस्था करना अधार्मिक या अनुदार व्यय नहीं करार दिया जा सकता। बिल के भीन जो प्रतिकर दिया गया है, वह केवल नाममात्र ही है। इस कारण फलभागियों को पृथक काइयो मानने से पुनर्वासन अनुदान के रूप में कुछ अधिक रुपया इन अभागे व्यक्तियों को मिन्न जायगा और हमें इसे बुरा न मानना चाहिये। वक्फ संस्थापकों ने उन्हें इसिलिये स्थापित क्या था, जिससे सम्पत्ति अयोग्य उत्तराधिकारियों के हाथों में न चली जाय, परातु उन्हों यह न सोचा था कि ऐसा करना उत्तराधिकारियों के हाथों में न चली जाय, परातु उन्हों यह न सोचा था कि ऐसा करना उनके उत्तराधिक रियों और वंशजों के लिये एक अतिरिवत आर्थिक हानि का कारण होगा।

द्दफ के फलभागियों के लिये घारा ७५ किताई और रिशानी पैदा करती है। प्रतिकर घनराशि उनके अधिकार में न रहेगी। मुझे डर है कि घारा ३० के अधीन देय अंतरिम प्रतिकर के सम्बन्ध में भी यह स्थिति होगी। अंतरिम प्रतेकर का उद्देश्य मध्यवितयों का भरण-पोषण करना है। जब तक पूरे प्रतिकर का अवधारण और भुगतान न हो जाय। जहां तक वक्फ के फलभागियों का सम्बन्ध है, मध्यवित्तयों को सहाता पहुंचाने का जो अंतरिम प्रतिकर का उद्देश्य है वह विफल हो जायगा। मेरे विचार में युक्त प्रान्तीय सरकार के लिये सबसे उपयुक्त यह होगा कि वह इस बिल को ऐक्ट बनाने के पहले केन्द्रीय सरकार से कहे कि वह वक्फ ऐक्ट को रह कर दे। उन मामलों के सम्बन्धमें यह और भी आवश्यक है, जिनमें वक्फ सम्पत्ति विशोधकर जायदाद के रूप में है। जमेंदारी विनाश के उपरान्त वक्फ ऐक्ट निदेशों के अधीन बचे हुये छोटे घरों या दूसरी समित्त का प्रबन्ध करना बहुत असुविधाजनक और खर्चीला हो जायगा। 'वक्फ अलल- औलाद' के फलभागियों को अंतरिम प्रतिकर देने के नियमों के अंतर्गत जो भी कार्यवाहे की जाय वह यथार्थ रूप में हो। जिससे जब वह बिल ऐक्ट बन जाय तो फलभागियों के अंतरिम भरण-पोषण के लिये उनको अंतरिम प्रतिकर देने में कोई अड़चन न रहे। मुझे यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है।

धारा ११९ (ल) वाक्यलंड ल से आबादी स्थल और पूरा वक्यलंड ग निकाल दिया जाय। ऐसे स्थलों को जमींदार के अधिकार में ही रहने दिया जाय, यदि वे बिल के अंतर्गत नहीं आते। इन स्थलों के सम्बन्ध में कोई भी ध्यक्ति मध्यवर्ती नहीं है।

अध्याय ५—यह निविद्याद है कि ऐसे जमींदारों को कृषि-अणकर से सबसे अधिक हानि हुई है, जो पांच हजार से लेकर दस हजार तक मालगुंगरी देते हैं। इसलिये पुनर्वासन अनुदान पाने की अधिकतम सीमा बढ़ाकर दस हजार उपये की मालगुजारी तक कर दी जाय।

अध्याय ६—इस अध्याय में पत्थरों और कंकड़ों को अपवाद गिना जाय। इस दशा में एक काश्तकार के श्लोष्ण का प्रश्न ही नहीं उठता।

हाट, वाजार और मेलों को अधिकार में न दिया जाय। इनसे जो आयहोती है वह जमीदारी आय बिलकुल नहीं है। मेला लगाने वाले जमीदार और गैर जमीदार दोनों ही हो सकते हैं। इनमें केवल ब्यापारिक स्वार्थ निहित है और निजी प्रयक्षों से मेले लगाये गये है। इनके सम्बन्ध में उनके मध्यवती होने का कोई प्रश्न ही नही उठना। इस अतिरिश्न आय के सम्बन्ध में किसो को बुरा न मानना चाहिये और इस आय को स्नमीदार की निजी सम्पत्ति ही रहने देनी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो घारा १०८ के आधार पर हाटो, बाजारों और मेलो को पट्टे पर देने की कोई व्यवस्था इस बिल में कर दी जाय। मेला लगाने वालों का काम किसी भी रूप में खानों के मध्यवर्ती के काम से नीचे दर्जे का नहीं है।

वारा १३५—इस संशोधित बिल में धारा १३५ के अधीन एक अनुसूची जोड ही गयी है, इसके अनुसार सरकार कृषि (कारतकारी) विशेषाधिकारों के हस्तगत करने के ऐक्ट सन् १९४९ ई०के निदेशों को संशोधित करना चाहती है। यह एक बहुत विचित्र और हास्या-स्पद तरीका है, जिससे ऐक्ट के सम्मान को धक्का लगने की सम्भावना है। यदि सरकार अधिकार प्राप्त करना चाहती है तो उसे इसके लिये या तो धारा सभा के सम्मुख जाना चाहिये या एक आडिनेंस जारी करना चाहिये, जैसी कि स्थिति हो, किन्तु ऐसे कार्यों को कार्यकारी अविकारों द्वारा पूरा करना वांछनीय नहीं ह। धारा १४६—१४७ मूल बिल की धारा १४६—क का संशोधन कर दिया गया है। मेरी राय मे मूल वाक्यखंड अधिक उपयुक्त था। संशोधित वाक्यखंड के अधीन प्रख्या—पन से पूर्व कलेक्टर को इस बात के लिये सन्तुष्ट करना पडेगा कि भूमि रखने या उद्योग के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त भूमि भूमिदारी भूमि ही रहेगी, चाहे वह प्रख्यापन के उपरोक्त कृषि के लिये उथयोग मे न लाई जाय और क्षेत्रपति को उसका लगान देना पड़ेगा, यह अनुचित है।

१५५ — भूमि का लगान पर उठारा जाना निषिद्ध है, किन्तु इस प्रचुर भूमि को लगान पर उठाये जाने की व्यापक मांग है ओर इसके कई कारण भी है। ऐसे मजदूरों को, जिसके पास भूमि नहीं है, साझेदार या किसी प्रकार के 'सेवा अधिकार' (Advoice renalca) मिलने चाहिये। मेरी राय मे भूमिदारों को अपनी जोत का हिस्सा लगान पर उठाने की आज्ञा दी जानी चाहिये। इससे यू० पी० एग्रीकल्चरल टिनेन्ट्स (एक्विजिज्ञन आफ प्रिविलिजेज) ऐक्ट, १९४९ ई० के अधीन जमीदारी-विनाज कोष का संचय तीव्र गति से बढ़ेगा। सरकार इस पर अवश्य विचार करे और यदि इसी सिद्धान्त के अनुसार वह भविष्य मे भूमि को लगान पर उठाने की अनुमित दे तो इस समय भूमि को शिकमी पट्टे पर उठाने का परिणाम यह न होना चाहिये कि भूमि मालिक आला (tenants in charge) या जमीदारो, जैसी भी दशा हो, के हाथ से निकल जाय।

१५६ — अक्षम व्यक्तियों की सूसी में (च) के बाद केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकार या स्वशासन संस्थाओं में आवश्यक सेवा करने वाले व्यक्तियो को सिम्मिलित करने के सम्बन्ध में मेरा यह विचार हैं कि पुलिस वाले और स्थानीय बोर्डो के अध्यापक समाज के प्रति उनको उपयोगिता के विचार से इस रियायत को पाने के योग्य है।

घारा २२४-३७--इस घारा के अधीन इस बिल का उद्देश्य यह है कि ऐसे किसानों को कुछ सुविधायें दी जायं, जिनके पास अलाभकर खाते हैं, परन्तु यह घारा भी उन्हीं क्षेत्रों पर लागू होगी, जिन्हें प्रान्तीय सरकार निर्दिष्ट करे। इसे व्यापक होना चाहिये और इस पर कोई प्रतिबन्ध न लगाना चाहिये। इससे केवल उन्हीं लोगों को लाभ पहुंचना चाहिये, जो वास्तव में ऐसे लाभ के अधिकारी हों। यह रियायत ऐसे किसी व्यक्ति को क्यों न दी जाय जो वैध रूप से इसे पा सकता हो। मेरा यह दृढ़ विचार है कि इस प्रतिबन्ध को हटा लेना चाहिये और घारा २२४ के वाक्यखंड (१) को निकाल देना चाहिये।

किसी संयुक्त लाते के सम्बन्ध में प्रत्येक साझीदार को यह अधिकार होना चाहिये कि निजी काइत में ८ एकड़ भूमि रखने के लिये वह अपने अधिवासी को बेदखल कर सके। घारा २५२—यह विचार है कि मालगुजारी एकत्रित करने का प्रबन्ध और तत्सम्बंधी कारिन्दों की व्यवस्था नियमों के अधीन होने दी जाय । धारा २५३ के अधीन गांव पंचायतों को यह काम सुपुर्द किया जायगा। मुझे खेद, है कि में इससे सहमत नहीं हो सकता, इन संस्थाओं को इस काम का कोई अनुभव नहीं है और वे स्वयं अभी परीक्षण की अवस्था में हें और उनको अभी से यह महत्वपूण काम सुपुर्द करने में खतरा है। यदि सरकारी अमीनों द्वारा वसूली कराई जाय तो उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होगी और वे उत्तरदायी व्यक्ति नहीं होंगे। मेरा विचार यह है कि जब मालगुजारों के संचय के सम्बन्ध में संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धान्त मान लिया गया है तो पुराने लम्बरदारों को ही यह काम तब तक करने दिया जाय जब तक इन पंचायतों को पर्याप्त अनुभव न हो जाय। पुराने लम्बरदार अनुभवी व्यक्ति हैं और में आशा करता हूं यदि उन्हें वसूली का पारिश्रमिक दिया जाय तो वे यह कार्य करना पतन्द करेंगे। यदि इस ढंग से काम किया जाय तो सस्ता भी पड़ेगा।

घारा २६५ — यद्यपि इस ऐक्ट में सहकारिता के आधार पर खेती करने की व्यवस्था की गई है किर भी इसे उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि देना चाहिये था। इस आघार पर वही लोग खेती करें जो स्वयं ऐसा करना चाहते हों और इस ऐक्ट में इस सम्बन्ध में तिनक भी विवश करने की व्यवस्था नहीं की गई है। श्रमिकों के न मिलने की समस्या बढ़ती ही जायगी और अल्प खातों में यंत्र द्वारा खेती करना सम्भव नहीं है। अभाग्यवश हमारे देश का किसान आलसी और लकीर का फकीर हैं और मुझे डर है कि इस ऐक्ट में सहकारिता के आधार पर खेती करने की जो व्यवस्था की गई है उससे सहकारिता के कामों और यंत्र द्वारा खेती करने के लाभों का उपयोग करने का प्रोत्साहन उसे मिलना कठिन होगा और उपज बढ़ाने के लिये इस ओर ठोस कार्य—वाहियां करनी पढ़ेंगी। 'अधिक अन्त उपजाओ' आन्दोलन को तीव्र गति से चलान के लिये सहकारी आधार पर खेती करने की अपेक्षा खातों को एकजा करना अधिक आवश्यक है। हमारी स्टेट्यूट बुक (Statute Book) में एक ऐक्ट अवश्य है, परन्तु सयस्त व्यवहारिक प्रयोजनों के लिये वह बेकार हो गया है। इस बिल में भी इनकी व्यवस्था नहीं की गई है। यद्यपि अन्य सभी बार्ते बार—बार आई हैं।

धारा २९१—इस वाक्यखंड के अन्तर्गत जिन अफसरों की नियुक्ति की जाय वे दीवानी के अनुभवी जुड़ीशियल अफसर हों। इस विषय पर बिहार या मद्रास के ऐक्टों की अपेक्षा यह बिल बहुत लम्बा चौड़ा ह और फिर भी इससे बहुत आवश्यक निदेश नियमों के लिये छोड़ दिय गये ह। यहां ऋण सम्बन्धी कानून का एक पृथक कानून होगा जबकि उन प्रान्तों ने इसी प्रकार के ऐक्टों में ऋण संबंधीप्रस्ताव सम्मिलित कर दिये हैं, जहां तक हो सके खंडों में कानून नहीं बनाना चाहिये। उपर्युक्त मुख्य मुझाबों के अतिरिक्त इस बिल के आदेशों को सुधारने के लिये बहुत से अन्य प्रस्ताव किये जा सकते हैं।

उपर्युक्त विचारों के अधीन में इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता हूं और संशोधनों के प्रस्तुत करने का अधिकार उस समय के लिये सुरक्षित रखता हूं जबकि यह बिल धारा सभा के सामने विचार के लिये आयेगा।

लखनऊ, तारीख २२ दिसम्बर, १९४९ ई०

सुल्तान आलम खां, एम० एल० ए**०**। सर्वश्री वःरेन्द्रशाह, जमशेट पछी खां, सुरेश प्रकाश सिंह, एजाज रस्त, राम नारायण गर्म तथा श्रीमतो फूलकुरारी प्रौर वेगम एजाज रस्त के मतभेट का नोट

जमीदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था बिल सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति की बैठकों में हम इस हार्दिक इच्छा से सम्मिलित हुये कि इस अति प्रभावकर प्रस्ताय की इस प्रकार पुनर्रवना करने में सहायता दे, जिसने जमीदारवर्ग के साथ घोर अन्याय न होते हुये काश्नकारों का वास्तिबक लाभ हो। हमें यह लिखते खेद होता है कि प्रवर समिति में वादिववाद होते समय कोई महत्व का विषय स्वीकार कराने में हम असफल रहे और समिति द्वारा सशोधित बिल में उसकी प्रायः सभी बुरी बाते मौजूद है। धिल की अधिकतर धाराओं के सम्बन्ध में बहुमत रिपोर्ट से मतभेद प्रकट करने के सिवा हमारे लिये कोई मार्ग नहीं ह। अब हम इस मतभेद के कारण बताते हैं और बिल के कुछ मुख्य दोष प्रदित्त करते ह। हम इसकी पूरी स्वतंत्रता अपने पास रखना चाहते हैं कि जब प्रवर मिनि द्वारा संशोधित बिल व्यवस्थापक मंडल में पेश हो तब उसमें आवश्यक संशोधन उपन्यित करे।

२-आरम्भ में हम उन बड़ी कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिदमें हमन काम किया। इस बिल में लगभग ३०० धाराओं के यु० पी० टिनेन्सी ऐपट, १९३८ के संशोधन, २२० से अधिक धाराओं के लेड रेवेन्य ऐक्ट, १९०१ के संशोधन और य० पी० एग्रीकल्चरच दिनन्द्रा (एक्बीजीनन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट, के संशोधन सम्मिलित किये गये हा। हमें बिल के यादयलड या इन ऐंदरों के राशोपन। पर कोई टिप्पणियां नहीं दी गई है और इस कारण हमारे सामने रख गये बहसंख्यक संशोधनों का पहत्व समझने में हमें सहायता देने के लिये हमारे पास कोई लिखित मार्ग प्रदर्शन नहीं था। समिति के बहुसंख्यक सदस्यों के व्यवहार से ऐपा मालूम होता था कि ऐसे महत्व का और जटिल बिल, जिसका करोड़ों आदिनयों पर प्रभाव पेडेगा हमारे यहां से अधिक से अधिक शीघता के साथ पास होना चाहिये, बहसख्यक दोषों के कारण इसमें शीघ्र ही संशोधन क्यों ने करने पर्डे। युनाइटेड प्राविन्सेज एग्रीकल्चरल टिनेन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐकेट. १९४९ के विचार के समय जो असाधारण कार्यीयधि अपनायी गयी उससे यह बात अच्छी तरहं स्पष्ट हो जाती है। मुलतः उपस्थित किये गये जमीदारी-विनाश बिल मे जमीदारी के विनाश के बाद भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध से एक अध्याय था। सरकार जमीदारी-विनाश के पहले ही जमींदारी-विनाश कोष के लिये काश्तकारी से घन लेने के लिये उत्सुक थी इसलिये जल्दी से एक कानून बना दिया गया, जिससे कुछ श्रेणियों के काश्तकार अपनी पेशगी भुगतान कर दें ओर जमीदारी-विनाश के बाद भूमिधरी अधिकार प्राप्त करे। कानुन बना देने के बाद सरकार ने उसके क्षेत्र को बढ़ाना ओर उसमें ठोस परिवर्तन करना चाहा। कानून को संशोधित करने के बजाय इस कानुन के संशोधन इसलिये प्रवर सिमिति के सामने पेश किये गये हैं कि वे विनोश बिल में सम्मिलित कर दिये जायें और सब से निन्दनीय बात यह है कि इन संशोधनों के सम्बन्ध में किये गये प्रवर समिति के निश्चय संशोधनों के व्यवस्थापिका के समक्ष उपस्थित किये जाने के पूर्व ही तुरन्त निष्पादक आज्ञाओं के रूप में परिवर्तित किये जा रहे है। कानन बनाने और उन्हें संशोधित करने के मान्य ढंग का व्यंग चित्रण करने वाले इस ढंग का हम घोर विरोध करते हैं। जमींदारी-विनाश कोष की वसूली को किसी भी उपाय से बढ़ाने के लिये यदि सरकार इतनी उत्सुक है तो वह कानून बनाने के सम्बन्ध में ऐसी कार्यविधि को अपनाने के बदले जो आगे के लिये अयंकर उदाहरण होगी, एक आडिनेंस बना सकती ह। इन संशोधनों में से जो हमारी बैठकों के आखिरी समय में, जब जमींदारी-विनाश कोष की वसूली योजनानुसार

नहीं हो पा रही थी, हमारे सामने उपस्थित किये गये कुछ का हवाला देकर हम अपनी टीका को सुस्पद्ध करना चाहते हैं। संशोधनों के अनुसार ज्योंही कोई व्यक्ति यू० पी० एग्रीकल्चर टेनेन्ट्स (एक्वोजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट के अधीन डिक्लेरेशन प्राप्त कर लेता है त्योंही वह भ्मिधर हो जाता है, यद्यपि जनींदारी-विनाश विल अभी प्रवर समिति में ही है और इस भूमिधर को दूसरे भूमिधर बनाने में सहायता देने के लिये असाधारण अधिकार दिये जाते हैं। वह बिना जनींदार को पूछे किसी को भो सहकाश्तकार लिख सकता है। इस समय सचिव-गंडल का एक मात्र लक्ष्य यह है कि वर्तमान कानूनों को संशोधित करने के लिये की जाने वालो साधारण विविधों का कोई भी विचार किये बिना किसी भी प्रकार जमींदारी-विनाश कोष के लिये धन प्राप्त किया जाय।

३--अब हम पूरे बिल को लेते हैं। उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि "वर्तमान भूमि-व्यवस्था में बिना मौलिक परिवर्तन किये कृषि-कार्यक्षमता तया वृद्धिगत खाद्योत्पादन के सुनिश्चित करने, ग्रामीण जनता के व्यक्तित्व के पूण विकास के लिये अवसर देने के हेतु ग्राम-निर्माण की कोई योजना नहीं चलाई जा सकती"। हम देखना चाहते हैं कि इन महत्वाकांक्षी दावों को बिल कहां तक पूरा करता है। हम पहले इसका पता लगाना चाहते हैं कि क्या बिल से काश्तकार की वर्तमान स्थिति सुवरती है और यदि सुवरती है तो किन दृष्टियों से। जमींदारी के विनाश के बाद कुँवकों के तीन मख्य वर्ग होंगे - भूमिधर, जिन्हें हस्तान्तरण करने का सीमित अधिकार होगा, सीरदार, जिन्हें ऐसा कोई अधिकार न होगा और असामी, जिन्हें कोई स्थायी भौमिक अधिकार न होगा और इस कारण जो जमींदार द्वारा बदखल किया जा सकेगा। काइतकारों (जिनमें बिना सहमित दखल किये हुये और ऐसे व्यक्ति भी सिम्मिलित होंगे जिन्होंने जमींदार की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है) और मातहत-दारों को भूमिबरी अधिकार तभी प्राप्त हो सकेंगे जब काश्तकार अपने लगान की दस गुना रकम और मातहतदार मुख्य काश्तकार के लगान की साधारणतः पंद्रह गुना रकम अदा करेगा। सरकार आज्ञा करती है कि वह तुरन्त ही १९५ करोड़ रुपया और विनाज्ञ बिल स्वीकार हो जाने के बाद और स्पया एकत्र कर लेगी। भूमियर को जो नये अधिकार मिलेंगे, वे ये होंगे :--

- (१) उसका मौजूदा लगान आधा घट जायगा (बिल का वाक्यखंड १४३)।
- (२) उसे हस्तान्तरण का सीमित अधिकार मिलेगा (वाक्यखंड १५१)।
- (३) वह अपनी जमीन को चाहे जिस काम में ला सकेगा (वाक्यखंड १४५, १४७) ।
- (४) वह अपने भाग को विभक्त करा सकेगा (वाक्य खंड ३, १४३-अ)।
- (५) वह वसीयतनामा लिख कर अपने खाते की वसीयत कर सकेगा (वाक्यखंड १६७)।

४——भूमियरी के निदेशों पर हम कुछ विस्तार से विचार करना चाहते कारण वे भूमि अधिकार की नयी प्रणाली की घुरी हैं। रुपये के भुगतान पर लगान के आधा कर दिये जाने और उसका नया नाम मालगुजारी रखने का मतलब यह है कि उन काश्तकारों ने, जिनके पास तैयार रक्षम है और कर्ज नहीं लिया ह, सरकार को ५ प्रतिशत व्याज पर वापस न हो सकते वाला कर्ज दिया, बशते कि अगले ४० वर्षों में मालगुजारी न बढ़े। उन काश्तकारों के मामले में, जिन्हें कर्ज लेना है इसका अर्थ यह है कि जिस व्याज पर रक्षम कर्ज दी जायगी उससे बहुत अधिक व्याज पर कर्ज लिया जाय और इस कर्ज को वापस करने का भार भी उस पर रहे। जहां तक आर्थिक लाभ का संबंध है दोनों ही मामलों में काश्तकारों की स्थित वर्तमान द्विष्टात से खराब हो होगी। ऐसे भी बहुत से मामले होंगे जिनमें ऐसे लोग जिन्हों कोई

अधिकार नहीं है, इस आज्ञा से रकमें दे देंगे कि इससे उनके दावे मे मजबूती आयेगी। वे अफसर जिन्हें धन संग्रह का काम सोंपा गया है यथाशक्ति अधिक धन संग्रह करने की व्यग्रता के कारण इसकी ओर विशेष प्यान नहीं देते कि कौन अधिकारी दावेदार है। परिणाम यह होगा कि बाद में अत्यधिक मुकदमें इसके निर्णय के लिये चलेगे कि एक विशिष्ट व्यक्ति को रक्तम जमा करने और भूमिधरी अधिकार का दावा करने का अधिकार था या नहीं। दूसरों के सामने दृष्टान्त उपस्थित करने के लिये मुखिया, पंच, सरपंच, स्कूलों के अध्यापक आदि सरकारी नौकरों पर जो दबाव निःसंकोच डाला जा रहा है उसका विचार हम अपने परीक्षण में छोड़ देते हैं। हम इस प्रश्न के अधिक मंगीन पहलुओं पर विवार करना चाहते है। भूमि को जोतने वाले लगभग उँढ़ करोड व्यक्तियों को भू निघरी अधिकार देने और उन्हें जमीन को चाहे जिस काम में लाने की अनुमति देने का उद्देश्य क्या है ? यह स्पष्टरूप से लिखा गया है कि भूमिधर अपनी जमीन को किसी भी काम में ला सकता है (वाक्य खंड १४५) वह उसे ऐसे काम में ला सकता है जो कृषि, बागबानी या पशुपालन से संबंधित नहीं है। वह उसे औद्योगिक अथवा रहने के काम में ला सकता है। बिको के अधिकार सहित इस वाक्यखंड का परिणाम क्या होगा ? अपेक्षाकृत गरीब काश्तकारों की बहुत सी भूमि जमीन के सट्टेबाजों और महाजनों के हाथ बिक जायगी। अन्नों व फर्लों के उत्पादन अथवा पशुपालन के अलावा दूसरे किसी काम में ग्राम भूमि का उपयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता किस प्रकार देश को खाद्य-सामग्री के विषय में आत्मिनिर्भर बनाने में सहायक होगी। क्या इसी प्रकार भिमधरों को अधिक अन्न उपजाने के लिये प्रोत्साहित किया जायगा। इस वाक्यखंड का क्या परिणाम होगा कि भूमिधर अपने भाग को विभक्त करा सकता है (वाक्यखंड-१४३-अ)? ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि विभक्त भाग ६ १/४ एकंड से, जो मौलिक जीत का प्रमाण है, कमन होगा। बिल की मूल योजना का इस प्रकार मौलिक त्याग स्पष्टत: इसलिये किया गया है कि कोटन्योर होल्डर, यू०पी० एग्रीकल्चरल टिनेन्ट्स (एक्वीजीशन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट, १९४८ ई० के अधीन भूमिधरी अधिकार प्राप्त करन के हेतु अपने हिस्से के लगान का दसगुना देने के लिये प्रवृत्त हों। अविभाज्यता के इस सि द्धान्त का यदि अब पालन नहीं करना है तो कोई कारण नहीं कि दूसरे टेन्योर होल्डरों के मा के ले में विभाजन की अनुमति क्यों न दी जाय और पूरे १९१ वाक्यखंड की फिर से रचना न की जाय। यही आलोचना वसीयतों (वाक्यखंड१६७) परलागू होती है। क्यों भू मिधर अपने खाते की इसप्रकार वसीयत कर सकता है कि उससे बहुत से अलाभकर खाते तैयार हों।यदि वह ऐसा कर सकता है तो अलाभकर खातों की संख्या घटाने की यह सब बात सुखद कल्पनामात्र है।

५—हस्तान्तरण (मुन्तिकली) के सीमित अधिकार देने के सम्बन्ध में हमें इस बात की शंका है कि क्या इस प्रकार का अधिकार देना सर्वथा लाभदायक होगा। २५० ६० से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों की भूमि मुन्तिकल और रेहन करने के सम्बन्ध में १९४० ई० के एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट में कड़े प्रतिबन्ध रक्खे गये थे। यदि बिक्री द्वारा हस्तान्तरण करने में केवल यही प्रतिबन्ध है कि अन्तरण के बाद अन्तरिणी ३० एकड़ से अधिक भूमि का मालिक न बन सके, तो साहकारों के हाथ में काफी भूमि चली जायगी। क्योंकि मकरूज (ऋणग्रस्त) होने की सम्भावनायें बहुत बढ़ जायेंगी और प्रान्त के किसी भी भाग में खेतिहरों और अखेतिहरों में कोई भेद न रह जायगा।

६—इसि तथे यह कहने के लिये हम विवश है कि जमीं दारी उन्मूलन कोष के लिये अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की सरकार की इच्छा के कारण भूमि—व्यवस्था के अनेकों सिद्धान्तों का, जिनकी घोषणा सरकार द्वारा उच्च स्वर से की गई थी, त्याग किया गया है और बहुत सी एसी कायकारी आज्ञायें जारी की गई है, जो मौजूदा कानूनों की घोर विरोधी हैं। हम लोगों को घारा १३५ (२) से घोर आपित है, जो उन तमाम आज्ञाओं, कार्यवाहियों और प्रख्यापनों की क्षतिपूर्ति करता है, जो १९४९ ई० के

यू० पी० एग्रीकलचरल टनेन्ट्स (एक्वीजी इन आफ प्रिविलेजेज) ऐक्ट केअविध काल में जारी किय गर्येथे। हम लोगों को यह विश्वास करन के लिये कार्रण है कि खर्मीदारी उन्मूलन कोष के लिये वन-संग्रह करने के लिये माल विभाग के कर्मचारियों की बहुत सी अपित-जनक आज्ञामें जारी की गई है। हमने सरकार से उन तमाम कार्यकारी आज्ञाओं की नकल मांगी है, जो बोर्ड ओफ रेवेन्य, माल विभाग और नय निर्मित विभाग, जिसके श्री खेर प्रधान है, द्वारा जारी किये गये है। हम केवल ऐसी एक आज्ञा का हवाला दग। हमें मालूम हुआ है कि हाल ही मेए के आदेश जारी किया गया था कि खातों में नये इन्दराज की तस्दीक ज़मींदार की स्वीकृति के बिना ही कार्नगी द्वारा की जा सकेगी या ऐसे लोगों का नाम खातों में मातहत कर्मचारियों की उपेक्षा द्वारा दर्ज कराना, जिनका उन खातों में कोई अधिकार नहीं है या जिनका अधिकार संदिग्ध है, एक अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी प्रलोभन है। हमने पटवारियों द्वारा बांटे गये छपे हुये परचे भी देखे हैं। गन्ना पैदा करने वालों की ओर से बांड रूप है कि गन्ने की कीमत-जो चीनी के कारेखानों से तय हुई है, जमींदारी उन्मूलन कोष मे दें रे के लिये कारखानों द्वारा काड कर जना की जा सकती है। हमें मालूम हुआ है कि गन्ने का काश्तकार जिस कम और तादाद में गन्ना किसी कारखाने में लेजा सकता है उसकी पूरी व्यवस्था इस प्रकार बदल दी जाने वाली है कि दोनों बातों के सम्बन्ध में उन्हीं को तरजीह मिले, जो भूमिधर होने के लिये तैयार है। हमने घन-संग्रह करने के इन आपत्तिजनक तरीकों की ओर अपने इस दलील के समर्थन के लिये संकेत किया है कि क्षतिपूरक सम्बन्धी धारा [धारा १३५ (२)] इसलिये बनाई गई है कि उसके अन्तर्गत ऐसी निन्दनीय आज्ञाये आ जाये। इस प्रश्न के विवाद को हम जमींदारी उन्मूलन समिति की सिफारिशों की ओर संकेत करके समाप्त करेंगे, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री महोदय थे और जिसमें सेलेक्ट कमेंटी प्रवर समिति) के बहुत से सदस्य शामिल थे। इस समिति ने तमाम बिना किसी मूल्य (शूल्क) के ही हस्तान्तरण अधिकार प्रदान किये जाने की सिफारिश की थी। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि अब उनसे ऐसा रुपया क्यों मांगा जा रहा है। हमारा विचार है कि यदि बहुमत द्वारा स्वत्व हस्तान्तरण अधिकार वांछनीय समझा जाय तो यह अधिकार निःशल्क प्रदान किया जाना चाहिये।

७—अब हम बिल के एक दूसरे मौलिक सिद्धान्त पर विचार करेंगे यानी यह कि जमीन जोतने वालों का जमींदार को लगान देने का अर्थ हैं उनका शोष ण, पतन और अधीनता। अक्षमों के सिवा जिनकी तालिका घारा १५६ में दी गई है दूसरों का और उन असामियों के सिवा जिनकी व्यवस्था घारा १३४ में की गई है दूसरों से लगान वसूल करना निपिद्ध किया जाने वाला हैं।

यदि उद्देश्य यह था कि कृषि उत्पादन साधनों का समाजीयकरण किया जाय तो किती जमींदार द्वारा मजदूरों के जिरये जमीन की जुताई कराना उसे लगान पर उठाने से कुछ कम शोषण की बात नहीं समझना चाहिये था। उदाहरण के लिये कोई भी व्यक्ति उस अमीन पर किसी आदमी को मजदूरी देकर काम नहीं करा सकता है जो उसे मवेशियों को पालन के लिये या अपने काम में लाने के लिये दी गई हो। बिल में लगान वसूल करने के सम्बन्ध में जो निवेध किया गया है उससे एक विचित्र परिणाम निकलता है। वह जमींदार, जिसके पास एक फार्म हो, जिसमें गांव की कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग शामिल हो, (आ गया हो) और जिसे मजदूरी देकर जोता जाता हो और इस प्रकार यद्यपि उसने भूमि रहित लोगों की संख्या बड़ा दो हो, किर भी उसे 'हितेषी' कह कर पुकारा जाता है और उस जमींदार को शोषक कह कर पुकारा जाय जिसने अपनी जमीन का अधिक भाग काश्तकारों को लगान पर दे दिया हो, जिन्हें अपनी भूमि के सम्बन्ध में तुरन्त स्थायी और मौक्सी अधिकार प्राप्त हो जाते है और जिनका लगान कानून द्वारा नियंत्रित होता रहता है और यह लगान कृषि पँदावार के मौजूदा मृत्य उपज के हिसाब से उसकी पँदावार

की कुल की मत का १/२० या १ ३० होता है। यह एक ऐसा भेद रक्खा गया है जिसकी तर्क मे प्रिंट नहीं हा सकती और वह समाजवाद के अवपके सिद्धान्तों पर आधारित है। आखिर हेसे विकृत सिद्धान्तों को पश्चात् दर्शी (retrospactive) प्रभाव रखने वाला मिद्धान्त उयो मान लिया गया। आगरा टेनेन्सो ऐक्ट जो मौजूदा प्रधान मंत्री के प्राम कार्यकाल में पास हुआ था उसके अन्तर्गत काश्तकारों ने कानूनी तौर पर जो जमीन शिक्यो पर उठाई है उसका कूल रक्तबा लगभग १७।। लाख एकड़ है। जमींदारों द्वारा शिकमी पर उठाई गई जमीन का रकवा लगभग १०,६ ३,००० एकड़ है (देखिये पुष्ठ ८, खंड २ जमीदारी-उन्मुलन समिति की रिपोर्ट) । इस जमीन का काफी हिस्सा उन लोगों के कब्जे से निकल जायगा, जिन्होंने उसे शिकमी पर उठाया था। इस सम्बन्ध में हम दो उद्धरण देना चाहते है--एक १९३९ इ० की आगरा टेनेन्सी बिल सम्बन्धी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से, दूसरा जमींदारी जन्मलन सिमिति की रिपोर्ट से ओर इन दोनों सिमितियों में प्रधान मंत्री महोदय ने प्रमुख भाग लिया था 'इसलिये हम लोगों ने ांदचय किया है कि ऐसी हालतो में सीर के काइतकारों को मौल्सी हक नही दिया जाना चाहिये जब तक कि जमींदार का उत्तराधिकारी (दारिम जानशीन) कोई ऐसा व्यक्ति न हो, जो काश्त की देख-भाल करने के योग्य हो या गमीदारी कोर्ट आफ वार्ड की निगरानी (संरक्षण) से मुक्त न हो जाय। हम यह भी नहीं चाहते कि बड़े जमीदार भविष्य में अपनी निजी काश्त के लिये एक मुनासिब रकबा हासिल करने के अधिकार से वंवित रहें सिर्फ इसलिये कि ऐक्ट लाग होते समय उन्होंने अपनी सीर को सम्भवतः उचित कारणो से शिकसी पर उठा दिया था; क्योंकि वे घर से दूर मरकारी नौकरी या व्यवसाय या व्यापार में लगे हुये हैं। इस्र्लिये हम लोगों ने एक सीमा निर्घारित कर देने का निश्वय किया है ताकि अयेक्षाकृत बड़े जमीदारों की सीर उनके मीर के कास्तकारों का हक मोरूसी प्रदान कर दिये जाने से कम न हो सके।" (१९३९ के आगरा टेनेसी डिल सम्बन्धी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट वाक्यलंड १३ बी)।

(२) "असल काइतकार को अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को एक सीमित काल के लिये शिकमी पर उठा देने का कानूनी हक हासिल है और यदि कानून द्वारा उसे प्रदान कियेग्ये अपने अधिकार को अमल में लाने के लिये दंखित किया जाय तो इससे उनने ऐसी भावना पैदा हो जायगी जिससे वह अपने को मुरक्षित नहीं समझेंगे। इसके अलावा शिकमी काइतकारों में से बहुत से ऐसे हैं जो केवल भित्र रखें (allotment holders) है और जिनके पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा होता है कि वह उसके द्वारा अपनी आमदनी बढ़ा सकें। आमतौर पर वे कुशल काइनकार नहीं हैं और यहुवा उनके पास खेती के कारोबार को अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में स्थायों तौर पर चलाने के लिये पारिन (कार्यशील) पूंजी या स्टाक (राशि) नहीं होता है।" (युक्त प्रान्तीय जमींदारी—उन्मूलन सिमिति की रिपोर्ट खंड १, पृष्ठ ३८१)।

८--२५० रुपये से अपिक मालगुजारी अदा करने वाले जमींदारों के सम्बन्ध में १९३९ के टेनेंसी ऐक्ट (कानून कब्जा आराजी) द्वारा उन्हें ५० एकड़ तक की सीर रखने का हक दिया गया था। अब यह अधिकार भी छीन लिया गया है और उनके सीर के काक्तकारों को तात्कालिक प्रभाव सिहत मोरूसी के अधिकार दे दिये गये है। ऐसे अचानक कानूनी परिवर्तनों से वर्तमान सरकार द्वारा किये गये व्यवस्थापन कार्यों में

(बनाये गये कानूनों मे) और भी संरक्षण की भावना उत्पन्न होगी।

९--हम लोगों का यह दृढ़ बिचार है कि शिकमी पर उठाने के सम्पूर्ण निषेधों से बहुतेरी छल-कपट की वार्ते उत्पन्न होंगी और ऐसे लोगों को विशेष क्लेश पहुंचेगा जैसे स्क्लों के अध्यापक और उन्हें जो स्वशासन संस्थाओं में नौकरी करते हों या सरकारी नौकरी करते हों। स्कूल के अध्यापकों और पुलिस दल के लोगों के सम्बन्ध में, चाहे वे नागरिक क्षेत्र में काम करते हों या सशस्त्र दल में, अपवाद करना बहुत हो न्यायोचित है। हम लोगों का यह भी मत है कि शिकमी उठाने के निषेध को पश्चात्वर्शों (retrospe-chive)न होना चाहिये और जिन लोगों ने मौजूदा कानून के अनुसार शिकमी उठाया है उन्हें ठकों की समाप्ति के बाद उनकी जमीन यापस मिन्नी चाहिये।

१०—हमें खेद हैं कि मौक्सी काश्तकारों का लगान खाते के रकबे के अनुसार रूपये में ६ आना से १ आना तक घटाने के सम्बन्ध में जमींदारी—विनाश कमेटी की सिफारिश को और इस सिद्धान्त को दखीलकार और गैरदखलोकार काश्तकारों के लगान पर लागू करने की बात के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कमेटी ने यह अनुमान लगाया था कि लगान में लगभग १३२ लाख रु० की कमी हो जाती (जमींदारी—उन्मूलन की रिपोर्ट खंड १, पृष्ठ ५३८)।

११—हम प्रस्तावित भूमिसुधार व्यवस्था का किसानों पर प्रभाव पड़ ता है उसकी जांच को काश्तकारों से मालगुजारी वसूल करने के डंग का संकेत करके समाप्त करेंगे। भूमिधरों और सीरदारों द्वारा मालगुजारी अदा करने का दायित्व संयुक्त और पथक-पृथक होगा [वाक्य खंड २१०, (१) नये वाक्य खंड २३० (२)] में सच्ची सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है और सब बात सरकार के विवेक पर छोड़ दी गई हैं। पौने दो करोड़ किसानों की दशा में जिनमें से अधिकतर बिना पढ़ें लिखें हैं संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को लागू करने से उत्पीड़न और अध्वकतर बिना पढ़ें लिखें हैं संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को लागू करने से उत्पीड़न और अध्वकतर बिना पढ़ें लिखें हैं संयुक्त दायित्व के सिद्धान्त को लागू करने से उत्पीड़न और अध्वकतर बिना पढ़ें जनमें न केवल गिरफ्तारी और हिरासत शामिल है, किन्तु जन-सम्पत्ति की कुकी और नीलाम भी, जिसमें फस्ल भी शामिल है और अचल सम्पत्ति का विक्रय भी। यह स्पष्ट है कि राज देय धनराशियों का भुगतान न करने के दायित्व और वंड दोनों ही वहुत बढ़ जायेंगे और वे अधिक से अधिक दृढ़ता के साथ लागू किये जायेंगे।

१२—इस सम्बन्ध में हम काफी कह चुके हैं कि यदि भूम मुधार योजना बिल में सम्मिलित की गई तो उससे काश्तकार को कोई सहायता न मिलेगी बिल्क उसके भार और खतरे काफी बढ़ जायंगे, उसका लगान कम न होगा । छोटी छोटी जोतों का तरीका जारी रहेगा, अलाभकर जोतों की संख्या में कोई कमी न होगी, कुल जोतों के रकबे का ९१ प्रतिशत ऐसे जोतों का रकबा होगा यदि लाभकर जोतों का रकबा इस समय ८ एकड़ नियत कर दिया जाता है। भूमिथरी अधिकारों को प्रदान करने के लिये जो जर पेशगी मांगा जायेगा उसके कारण और जमींदारो-उन्मूलन कोष की वसूली के लिये जिन बढ़े तरीकों का प्रयोग किया जायगा उसके कारण बहुत से लोग कर्नदार हो जायेंगे, भूमि शिकमी देने पर पाबन्दियों को पश्चात् दशी प्रभाव सहित लागू करने से लगभग १७ १/२ लाख एकड़ भूमि मुख्य काश्तकारों के हाथ से निकल जायगी जिसके कारण वे बड़ी कि लिनाई में पड़ जायेंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी देय धनराशियां वसूल करने के तरीकों से "काश्तकार के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास" न हो सकेगा बिल्क माल विभाग के मामूली कर्मचारी, जो अपने लालच भ्रष्टाचार के लिये बदनाम हैं, उन्हें और भी तुच्छ बना देंगे।

१३—अब हम बिल की योजना पर संक्षेप में इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे कि जमींदारों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता हैं। पुनर्वासन अनुदान संबंधी भुगतान के और अतिरिक्त १० रुपया मालगुजारी देने वाले और एक लाख रुपया माल-जारी देने वाले जमींदारों में कोई भेद न किया जायगा, २० लाख से कुछ अधिक जमींदारों में से प्राय: २० लाख जमीदार २५० रु० या इससे कम मालगुजारी देते हैं भीर इनमें ८६ प्रतिश्वत से कुछ अधिक २५ रु० या इससे कम मालगुजारी देते हैं। जमींदारी—उन्मूलन सिमित ने उन्हें लगान पाने वाला नहीं बिल्क वास्तव में काश्तकार बताया है। जमींदारी—उन्मलन सिमित की रिपोर्ट भाग १, पृष्ठ ३४३। वे ऐसे जमींदार या मालिक नहीं हैं जो अपनी जमींदारी में न रहते हों। फिर भी उन्हें समाप्त करना है क्योंकि वे लगान पाने वालों के निन्दित वर्ग में आते हैं, यद्यपि कि यह मान लिया गया है कि उनमें से बहुतों की हालत काश्तकारों से भी अधिक खराब हैं। अपनी बहुत सी सीर जमीन भी जो उन्होंने शिकमी दे रक्खी है और जो कुल ५९ लाख एकड़ में से ८ लाख एकड़ है यानी लगभग १४ प्रतिशत है, उनके हाथ से निकल जायगी। इसके अतिरिक्त इनके वे मालिकाना अधिकार भी बिना किसी मुआवजे के समाप्त हो जायंगे जो इन्हें काश्तकारी योग्य परती जमीन और उस जमीन में आबादी और इधर—उधर फले हुये पेड़ों में प्राप्त

है। मैंनें तीन ही उदाहरण दिये है, इन २० लाख जमींदारों को कितना मुआवजा मिलेगा। जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट भाग १ के पृष्ठ४१८ और ४२० मे दी हुई कच्ची निकासी और मालगुजारी के आंकड़े को लेकर और कच्ची निकासी की मालगुजारी पर १८॥ प्रतिशत के लगे कर और १५ प्रतिशत के प्रबन्ध व्यय को लेकर सब हिसाब लगाने से जैसा कि विल में व्यवस्था की गई है, कुल संपत्ति का ८ गुना मुआवजे की रकम केवल २६ करोड़ ८० लाख रुपये होगी। स्पष्टतः यह बहुत ही अपर्याप्त है। जमींदार, दस श्रेणियों में विभाजित किये गये है। उनका मुआवजा निर्धारित करने के लिये यदि विभिन्न गणकों का प्रयोग किया जाता, उनसे उत्पन्न कानूनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, और मुआवर्ज को पूरा करने के लिये पुनर्वासन अनुदान देने के तरीके पर अमल किया गया है, किन्तु पुनर्वासन अनुदान पाने वाली श्रेणियों के लिये विभिन्न गुणकों का प्रयोग करके पुनर्वासन अनुदान नीचे के क्रमानुसार निर्धारित की जायगी। २५० रु० या इससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों की सूरत में पुनर्वासन अनुदान की रक्षम लगभग ५२ करोड़ ९६ लाख रुपये होगी। हमारा अनुमान है कि समस्त आठों श्रेणियों, अर्थात् ५,००० रु० और इससे कम मालगुजारो देने वाले सब जमींदारों को कुल मुआवजा और पुनर्वासन अनुदान की रकम ११२ करोड़ २३ लाख रुपये होगी जिसमें से ६५ करोड़ ८३ लाख की पुनर्वासन अनुदाने होंगी। यह पुनर्वासन अनुदान दी कैसे जायगी? बिल में यह बात सरकार के ऊपर छोड़ दी गई है कि वह इसके देने का तरीका नियत करे (वाक्यखंड ७१) । किन्तु हमारी समझ में नहीं आता कि नकद या काबिले इन्तकाल बांड के रूपमे रेने के अतिरिक्त पुनर्वासन अनुदान और दूसरे किस रूप में दी जा सकती ह। २० लाख छोटे-छोटे जमींदारों का पुनर्वासन कैसे सम्भव हो सकता है, यदि उनका मुआवजा और पुनर्वासन अनुदान नकद न देकर एनुइटोज (सालाना किरतों) मे दिया जायगा। इसका अर्थ पुनर्वासन कराना नहीं किन्तु बेघरबार करना होगा। किन्तु शायद जमींदारों के मामले में, जिसका वह जानबूझकर उन्मूलन कर रही है, पुनर्वासन का अर्थ ऐसा है जो साधारणतया लोग उस शब्द से नहीं समझते ह। हमारा यह दुढ़ विचार है कि ऐसे जमींदारों की सूरत में जिनका मुआवजा इतना अपर्याप्त है कि पुनर्वासन अनुदान देकर उसे पूरा किया जा रहा है, मुआवजे और पुनर्वासन अनुदान की सारी रकम नकद दी जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो १ करोड़ ऐसे लोगों को हटाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त यह बहुत ही कठोर विचार है कि खेती करने वाले मालिकों से लगभग ८ लाख एकड़ अच्छी भूमि ले ली जाय और इसके ऊपर खेती योग्य परती पड़े हुये बड़े रकबों और एक बड़ी संख्या में इघर-उधर फैले पेड़ों को उनसे छीन लिया जाय और फिर उन्हें ऐसे ढंग पर, जिन्हें सरकार निर्धारित करेगी, एक पुनर्वासन अनुदान दिया जाय। सरकार द्वारा दी गई अनुदानों से ये हटाये गये व्यक्ति दूसरा कौन सा नया पेशा शुरू करगे। इनके काम करने के लिये कौन सी नई राहें खोली गई हैं। पश्चिमी पंजाब के काश्तकार शरणािथयों को भी खेती ही के काम में लगाकर फिर से बसाया गया है इस प्रान्त में हठपूर्ण सिद्धान्त कि काश्तकारी को जमीन को लगान पर देना एक समाज विरोधी कार्य है, के लिये छोटे-छोटे जमींदारों के हितों का बलिदान किया जा रहा है। इंगलैण्ड या अमेरिका मे इसे ऐसा नहीं समझा जाता।

१४——अब हम उन जमींदारों के मामलों पर विचार करेगे जो ५,००० ६० और इससे अधिक मालगुजारो देते हैं किन्तु ऐसा करने के पहिले इस मसले को ठीक से समझने के लिये हम कुछ बातें बता देना जरूरी समझते हैं। मिनिस्टरों द्वारा हमें बार—बार आश्वासन दिया गया है कि सरकार को भूमि—सुधार नीति जमींदारों के विरुद्ध किसी शत्रुता की भावना पर नहीं आधारित है। हम चाहते हैं कि कहने और करने में अन्तर न हो। जब अगस्त, १९४६ ई० में सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का निश्चय कर लिया था तो उसने इसके बाद मालगुजारों के १० प्रतिशत से १८।।। प्रतिशत तक कर (अबवाब) क्यों बढ़ा दिया और ज़मींदारी—उन्मूलन बिल को असेम्बली में पेश करने के ६ महीने पहिले

एक कृषि आय कर ऐक्ट (एग्रीकल्चरल इनकम् टैक्स ऐक्ट) क्यों पास किया? इन दोनों कार्रवाइयों को कार्यान्विन किये जाने के बारे में भी हम कुछ कहेंगे। बढाये गये अबवाब का पर्ता १ आना ६ पाई फी रुपया होता है जिसमें से ३ पाई फी रु किसान देना है। चूंकि लगान देने वालों की सूची के अनुसार उनकी संख्या १७ करोड़ है, इसके माने हैं कि कास्तकारों को एक साल में लगभग २७ लाख देने पड़े। सरकार कर की पूरी रकम लमींदार से वमूल कर लेती है जिन्हें काश्तकार से उस कर का हिस्सा बमूल करने का अधिकार है। किन्तु जहां तक है, जमींदारों ने लगभग ल रकम अदा कर दी है और ज्यादा जिलों में किसानों ने इसका भुगतान नहीं किया क्योंकि किसानों के इस भुगतान के वायित्व के सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं जारी की गई। ५,००० र० और इससे अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों के ऊपर छुषि आयकर का एक बहुत वडा भार पड़ गया है, यही नहीं, कि यह केवल कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है, बल्कि दो वर्ष का कर उनसे एक ही वर्ष में वसूल किया जा रहा है और यह वसूली इतनी कड़ाई के साथ की जा रही है कि बहुत सी बड़ी-बड़ी रियासतों को भी अपनी नियत किस्त अदा करने में कठिनाई हुई। इससे यह साफ सावित होता है कि यह एंक्ट राज्य की आय के विचार से नहीं पास किया गया था बल्कि बड़े-बड़े जमींदारों को आर्थिक रूप से असमर्थ बनाने के लिये पास किया गया था ताकि वे जमींदारी-उन्मलन का विरोध न कर सक। हम जमींदारी-उन्मूलन समिति की रिपोर्ट के भाग शेका पष्ठ ३५७ के निम्नांकित उस अंश की ओर ध्यान दिलाना नितान्त आवश्यक समझते हैं जिस पर कि प्रान्त के प्रघान सचिव और माल सचिव ठाकुर हुकुम सिंह ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। "जबतक कि जमींदारी जिस पर कि निश्चय ही बार-बार अकाल पड़ने और स्थायी रूप से खाद्यात्र की कमी की जिम्मेदारी है, समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक हमारे खाद्यात्र सम्बन्धी संकट का स्थायी और अन्तिम हल नहीं हो सकता"। ४० वर्ष हुये इस प्रान्त में कोई दुभिक्ष नहीं आया। किसान जितना आज खुजहाल है उतना कभी नहीं या और मंत्रिमंडल के अपने अनुदानों के अनुसार भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लगभग २०० करोड़ रुपया आसानी से दे सकते हैं। खाद्यान्न का अभाव जमींदारी प्रया के कारण हैं क्योंकि अधिकतर भूमि किसान के पास है, जिल्हें उस पर स्थायी और मौरूसी अधिकार प्राप्त हैं, और जिसका लगान आजकल उनकी कुल पैदाबार के मूल्य के हिसाब से लगभग ६ पाई फी रुपया है। भारत का विभावन जिसके कारण एक अधिक मात्रा में मिलने वाले गेहूँ और चावल की सप्लाई बन्द हो जाने, बरमा के अलग होने और लड़ाई के कारण बर्बादी होने तथा इसके फलस्वरूप वहां अन्दरूनी गड़बड़ होने, बरावर तेजा के साथ आबादी के बढ़ने और अनाज का उनभोग बढ़ने और उपज करने वाले के पास अधिक मात्रा में अतिरिक्त अनाज रह जाने के कारणदेहातों में रहने वालों द्वारा अच्छी किस्म का अनाज खाये जाने, क्योंकि उसकी फसल के दाम बहुत बढ़ जाने के कारण पहिले की अपेक्षा थोड़ी ही मात्रा में अनाज बेचकर वह अपने देय अदा कर देता है, हमारे क्रुषि विभागों की अयोग्यता और अभी हाल तक राजनीतिक शान्ति और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं में सरकार के उलझे रहने के कारण कृषि विभागों की ओर ध्यान न दे सकने, आदि के कारण गल्ला न पैदा करने वालों के लिये गहने की कमी हैन कि ज़मींदारों के होने के कारण, जो कि इस प्रान्त में अधिकतर संस्थाओं में काश्तकारी करते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं कि माननीय सचिवों से जो इस प्रकार के बयान देते हैं यह आशा नहीं कीजा सकती कि व क्रमींदारी उन्मूलन समस्या पर निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग १/५ आबादी को निर्मूल करने का सवालहै। दूसरा अस्त्र जो प्रायः ज़र्मीदारों पर चलाया जाता है वह यह अभियोग है कि वे सामन्तशाही अत्याचारा है। केवल यह बात कि ज्यादातर भूमि किसानों के कड़ने में है जिनके लिये स्टेच्यूट में अवधि और लगोन की सुरक्षा की गई है, और यह कि २० लाख से अधिक ज़मींदार २५० ६० और इससे कम मालगुजारी देते हैं और इसलिये बहुत छोटे-छोटे मालिक है, इस अभियोग को ख़त्म कर देती है। इस पूरे वाद-विवाद में मंत्रिमंडल ने अपने समर्थकों पर अधिक

सांत्यम १२३

विश्वास किया ह ओर दिवेक और तर्क की दिल्कुल ही परवाह नहीं की क्यों कि इनके विवार में यह दुर्बलों के अस्त्र हे। हम यह नहीं भूल हैं कि संविधान में सम्पत्ति सम्बन्धी मोलिक वान्यलंड की अन्त में जानबंझ कर इसलिये संशोधन किया गया कि युक्त प्रान्त के ज़मीदार कानूनी अदालतों में मित्रमंडल के मुआवजा सम्बन्धी प्रस्ताओं के खिलाफ दावा न कर सकें। वैधानिक वकील और ड्रांभिटण एमटी के तभा ति डा० अम्बेदकर ऐसे नुझल ला मिनिस्टर ने इस संगोधन यो बेकायदा समझा ओर विधान परिपद में उन्होंने इसे पेश करने की जिम्मेदारी न ली।

१५--अबहम बडे-बड़े जमींदारों के मुआवजे के प्रश्न पर वास्त्रवित बातों के आधारो पर विचार करेगे न कि ज़मींबारी भूमि अधिकरण के लिये ज़ब्त फरने के सिद्धान्तो पर। ऐसे जमीदारों को कुछ सम्पत्ति का ५ करोड़ से कुछ अधिक और उनकी सालगुजारी का १८१ चाल का तल्योंना किया गया है। सरकार उहा जगभग १० करोड स्पये का कुल म आवजा देने का विचार करती है ये लोग कोई पुनर्वासन अनुदान पाने के अधिकारी न होंगे। हम एक साधारण सूत्र उपस्थित करते है, हप चार व्याल्यात्मक विवरण-पत्र नत्थी, जिसके देखने से फौरन हो पता चल जायगा कि बिल के मुआवजा संबंधी वाक्यखंडो के अधीन ऐसे जमींदारों की वर्तमान आमदनी किस प्रकार घट जावगी। उनकी वर्तगान आमदनी, यदि मिर्फ वही कुल अभिरती ली जाय जिस पर मालगुजारी निर्धारित की गई है, मालगुजारी, अबबाय कर, प्रबन्ध व्यय तथा कुषि आयकर देने के बाद लगभग ८० प्रतिशत कम हो जायगी। वास्तव में कमी इससे भी अधिक होगी क्यों कि गांवो को इमारती लकड़ खाली जमीन जिसका कुल रकबा लगभग १ करोड़ एकड़ है, बेचने, खेती योग्य देकार जमीन में काश्त करके होने वाली आगदनी आदि पिविध आय बिना किसी मुआविजा के खत्म हो जायगी और सायर की अन्य आय नाममात्र की रक्ष देकर ले ली जायगी। इसके अतिरिक्त ऐसे जमींदारों के पास सीर और खुदकारत का लगभग १,६१,००० एकड़ का जो कुल रक्ता है उसमे से ६०,००० एकड से अधिक लगान पर दिया हुआ है न कि केवल वह सारी भूमि जो लगान पर उठा दी गई है, निकल जायगी बल्कि ऐसी भूमियों के लिए क्षतिपूरक वन मौद्धती दरों के आधार पर आंका जायगा, क्योंकि सभी शिकमी असामियों को अविलम्ब मौरूसी अधिकार देदिए जायंगे। सरकार ने ऐसे जमींदारो में से प्रत्येक को अधिक से अधिक ५० एकड भूमि के लिए आज्ञा दे रक्खी थी, जिसमें मोरूसी काक्तकारी के अधिकार नहीं उत्पन्न हो सकते थे। यह मामूली रियायत भी अब उनसे छीन ली गई है और इस रियायत का छीना जाना पश्चानदर्शी प्रभाव से कार्यान्वित होगा। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि जमींदारों को इसके बदले मे जो क्षतिपूरक धन दिया जायगा वह वास्तव में जन्ती के बराबर है। इनमें से कुछ अमींदार कुर्जे के भार से दबे हुए हैं और उनकी रियासते कोर्ट आफ वार्ड म की देखरेख मे है। इनमें से बहुत से ज़मीदार मुफलिस हो जायेगे। कोर्ट आफ बोड्स की हाल की प्रकट होता है कि सभी कर्जदार तथा कुल दायित्वों को अदा करने की क्षमता रखने वाली रियासतों की बार्षिक आय ८६ लाखँ रुपये प्रतिवर्ष है जब कि कुल ऋण १४५ लाख रुपये हैं।

सरकार के क्षतिपूरक धन-सम्बन्धी प्रस्तावों का बडे जमीवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इस बात को प्रकट करा के लिए कि किस सीमा तक बिल में विणत क्षतिपूरक प्रस्तावों द्वारा वार्डों की वर्तमान आय घट जायगी और कर्ज से लदी हुई रियासतों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी वर्णन कोर्ट आफ वार्ड स के प्रेसीडेट द्वारा दो गई रिपोर्ट से अधिक विश्वासपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट आफ वार्ड स के प्रेसीडेट ऐसे सरकारी अधिकारी हैं जिनकी सेवाएं कुछ राज्य के लिये कोर्ट आफ वार्ड स को दे दो गई है। हम बलपूर्वक यह कहते हैं कि सरकार इस सम्बन्ध में अविलम्ब एक रिपोर्ट मांगे और यह रिपोर्ट बिल पर विवाद होने से पूर्व ही ध्यवस्थापक मंडल के सम्मुख रक्खी जाय। यह रिपोर्ट इतनी ठीक होगी कि इस पर शक ही नहीं किया जा सकता और इस प्रसंग स्थित में न्याय के अर्थ के विषय में कोरा वाद—विवाद करने की अपेक्षा यही रिपोर्ट बड़े

जमींदारों के सम्बन्ध में प्रस्तावित क्षतिपूरकं धन आंकने का अधिक सच्चा साधन होगी। हम कोर्ट आफ वार्ड स द्वारा सीरों को लगान पर उठाए जाने वाली पूर्व नीति के उलटने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। ऐसी भूमियां उसी स्तर पर क्यों नहीं मानी जातीं, जिस पर असमर्थ व्यक्तियों द्वारा उठाई हुई भूमियां है। ये भूमियां अपने मालिकों को वापस मिलनी चाहिये। हम बहुत शोक है कि सिमिति ने बहुमत से हम लोगों द्वारा प्रस्तुत क्षुद्ध संशोधनों को भी ठुकरा दिया। बिल के अन्तर्गत बड़े जमीदारों की मुसीबत का वर्णन समाप्त करने से पूर्व ही हम बड़े जमींदारों के कर्मचारियों की उन कठिनाइयों का वर्णन करेगे जो जमींदारी—उन्मूलन के फलस्वरूप उन पर आ पडेगी। सपरिवार इन कर्मचारियों की संख्या ५ लाख है। क्या सरकार इनके लिये दूसरा धंघा ढूंढेगी अथवा इनका भरण—पोषण करेगी या इनको सड़क पर यों ही मारे—मारे फिरने देगी। बिल में उनके अस्तित्व पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया है और इनके लिये कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है।

१६—हम यह बता देना चाहते हैं कि सरकार के क्षितपूरक धन—सम्बन्धी प्रस्तावों पर तब तक यथेष्ट रूप से विचार नहीं किया जा सकता जब तक हम यह न जान जाएं कि सरकार जमींदारों के ऋण का प्रश्न किस प्रकार हल करेंगी। बिहार और मद्रास के जमींदारी—उन्मूलन बिलों में इस महत्वपूर्ण प्रश्न की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रस्ताव मौजूद हैं। किन्तु इस बिल में जब कि ४० वर्ष बाद होने वाले मालगुजारी के बन्दों उस्त के विषय में तो व्यवस्था कर दी गई हैं, (धारा २३९ और इसके बाद की बाराएं) ऋणों के प्रश्न को दूसरे बिल के लिए छोड़ रक्खा गया है। हमारी राय में तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को असन्तोषप्रद ढंग से निपटाना है। हमारा यह दृढ़ मत है कि ऋणों के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव अविलम्ब ही प्रकाशित किए जाएं।

१७--बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए तथा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार आधुनिक ढंग से संचालित निजी जंगलों से संबंधित प्रस्तावों से भी हमारा बड़ा ही गहरा मतभेद है, इन्हें तो झाड़ियों का जंगल मान लिया गया है [बारा ४३ (घ)] इन जंगलों में मुक्किल से कोई कृषि-योग्य में भूमि है तथा उनमें असामी जमींदार प्रथा तो है ही नहीं। ऐसे जंगलों के संरक्षण के लिये मई, १९४९ ई० यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट्स ऐक्ट पास किया गया था और इस ऐक्ट के अन्तर्गत बहुत सी विज्ञिन्तियां जारी की जा चुकी है। इन जंगलों के बहुत से मालिकों ने ऐक्ट के आदेशों के अनुसार कार्यशील योजनाएं तैयार कर ली है और सरकार ने योजनाओं को स्वीकार भी कर लिया है और इन लोगों ने इन्हीं योजनाओं के अनुसार वृक्षों को काटना आरम्भ कर दिया है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि इस ऐक्ट के अन्तर्गत नीति को इस प्रकार एकदम क्यों बदल दिया गया है और इन जंगलों को ऐसे मुआविजे के आघार पर प्राप्त कर लिया गया है जिससे बहुत बड़ी हानि होगी, क्योंकि जंगलों के बहुत से मालिकों ने लकड़ी के व्यवसाय में बहुत सी पूंजी लगा रक्खी है। जमीं दारी — उन्मूलन से लकड़ी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि फिर भी सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो जंगलों का मूल्य उसी आधार पर आंका जाना चाहिए जो आधार सरकारी जंगलों के लिए स्वीकृत है। हमारी राय में यू० पी० फारेस्ट्म ऐक्ट को पर्याप्त समय तक प्रभावशील रखना चाहिये जिससे कि इसकी कार्यविधि का सम्यक् निर्णय किया जा सके। इसे एक वर्ष तक भी प्रभावशील न रख कर रह कर देना, हमारी राय में अनावश्यक है। हम यह भी बता देना चाहते हैं कि विशेषतः बस्ती और गोरखपुर के जिलों में उन स्वामियों को मुआविजा देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं किया गया है जिन्होंने असामियों के लिए सिचाई-सम्बन्धी निर्माण-कार्य संचालित किए है और इनमें बहुत सी रकम खर्च की है। हमारा विचार है कि सिचाई-सम्बधी निर्माण-कार्यो के ऐसे स्वामियों को पर्याप्त मुआविजा देना चाहिये और इस बात नित्यमा १२५

का प्रबन्ध करना चाहिये कि इन निर्माण—कार्यों की रक्षा भली प्रकार से हो सके और कुब्यवस्था तथा असावधानी के कारण उनकी उपादेयता में कमी न पड़े।

१८—हम अब बिल के उन महत्वपूर्ण आदेशों पर विचार करेगे जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। हम जोरों से नई धारा (२—क) पर आपित करते हैं, जिसके अनुसार घोषणा द्वारा इस बिल के अतिरिक्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत सरकार सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि प्राप्त कर सकती हैं और इस प्रकार दीवानी न्यायालयों में कोई भी सुनवाई न हो सके।

१९—हमें कोई वजह नहीं पालून होती कि घारा ३ (१) में ठेकेदारों को मध्यवर्ती क्यों माना गया है। वह तो केवल पट्टेदार हैं और आगरा टेनेसी एक्ट की घारा २१४ के अबीन उनके पट्टे की अधिकतम अविध १० वर्ष निर्धारित की गई है। और नहमें उसकी कोई वजह मालम होती है कि उन नियमों को जिनके अनुसार उन्हें मुआविजा मिलेगा, क्योंकि अस्पष्ट रूप में और मुआविजा अफसर की मर्जी पर छोड़ दिया गया है (घारा ५८, ५९ और ६०)।

२०--क्योंकि ठेकेदार एक सीमित अवधि के लिये केवल पट्टादार ही होना है, इसलिये समस्त भूमि जिस पर वह काश्तकारी करता हो ठेके की अवधि की समाप्ति पर पट्टा देने वाले को वापस मिल जानी चाहिए और किसी क्षेत्र को खाली की हुई भूमि न मानना चाहिये। घारा १५ (२) ख (१) और घारा १५ (३) (ख) कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैराग्राफ १४ में कहा है कि कुछ तालुकों मे बहुत से ठेके केवल इस नियत से दिए गए हैं कि ठेकेदारों को उनके सम्बन्ध में मौरूसी अधिकार प्राप्त न हो जाएं। हम नहीं जानते कि कमेटी के ध्यान में कौन से तालुके है। किन्तु इसका स्पब्ट उद्देश्य यह है कि ऐसे बहुत से तालुकों से उनको सीर और खुदकारत भूमि छीन ली जाय। हमारे ध्यान में भी एक विशेष तालुका है जिसके ओर सरकार के बीच दीवानी का एक मकदमा चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि पट्टा देने वाले की नियत के सम्बन्ध म कौन निर्णय करेगा। क्या किसी रेसे ठेकेदार को जिसने किसी मालिक की सीर और खुदकाइत भूमियां इस स्पष्ट प्रतिबन्ध से ली हों कि उन पर वह खुद खेती करेगा। अब यह आज्ञा दो जायगी कि वह अपने ठेके की शर्ती का उल्लंघन करें और अपने लिए मौक्सी असामी के अधिकार प्राप्त कर ले। हम इस प्रस्ताव का घोर विरोध करते है कि कुछ बड़ी बड़ी रियासतों में कुछ ठेकेदारों के साथ रियायत की जाय। किसी भी दशा में नियत के प्रश्न पर निर्णय देने का अधिकार मुआविजा अफसर के हाथ में न छोड़ देना चाहिए। यह उचित और आवश्यक है कि दीवानी की अदालतें ही रेसे मामलों पर निर्णय हैं। इन ठेकेदारों के साथ असाधारण बर्ताव करने के विशेष उद्देश्य के लिए साक्ष्य विधान (Evidence Act) में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और न हमको इसका कोई उचित कारण प्रतीत होता है कि राहिन की सीर और खदकाश्त के अतिरिक्त भूमि पर मुर्तिहिन के व्यक्तिगत कब्जे को उस दशा में जब कि मुर्तिहिनी के अधिकारों का अन्त हो जाय, राहिन का कब्जा क्यों न मानें। [धारा १६ (२) (ख)]।

२१—बिल में उन मालिकों के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है जिनकी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में "हकीयत" (स्वामित्व) के मुकदमे चल रहे है या बाद में दायर किए जाएं। इस पूरे प्रश्न को अस्पष्ट छोड़ दिया गया है। [घारा ३० (२)] इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से व्यवस्था करनी चाहिए।

२२—विल की धारा ६६ में "अधिकार रखने वाले व्यक्ति" की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि धारा ५० के अधीन नोटिस जारी होने के बाद "अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों" को हकीयत के ऐसे मुफ्दमे जो झूठे हों और जिनका उद्देश्य परेशान करना हो, दायर करने के लिए असीमित अवसर मिल जायगा। २३—- घारा ३९ (१) यह धर्म शास्त्र के स्वीकृत नियमों के विषरीत है। बिहार ऐक्ट (घारा २०) में ऐसी सम्पत्ति को एक यूनिट नहीं माना गया है। वैसी ही इत्रवस्या इत विज में भी करनी चाहिए।

२४—हमारा विचार है कि हिन्दू ट्रस्ट या एन्डाउमेट के सम्बन्ध में आर्रवाई का कोई प्रयस्त करने के पहिले यह आवश्यक हैं कि उक्त ट्रस्टों या एन्डाउमेंटों का वर्गीकरण कोई ऐसा अधिकारपूर्ण कमीशन करे, जिसमें हिन्दूमत के नर्यान्त प्रतिनिधि हों। हमारा यह दृड़ मत है कि हिन्दू ट्रस्टों और एन्डाउमेटों का प्रश्न जमोंदारी—उन्मूलन के प्रश्न में सम्मिलित न करना चाहिए और उक्त प्रश्न के लिए इस बिल में नहीं बल्कि एक और अलग बिल के द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए।

२५—हमारी चेट्टा हैं कि भूमि—सम्बन्धी प्रवन्ध तथा शासन में गांव पंचायतो, गांव समाओं और गांव सभाओं का उत्तरदायित्व उस सीमा से कहीं अधिक होना चाहिए, जिसका कि इस बिल में प्रस्ताव किया गया है। हमारा मत है कि अब वह समय आ गया है कि राजस्व—शासन ग्रामीण प्रजातन्त्रों के हाय में होना चाहिए और पटवारियों की नियुक्ति और बरखास्त करने का अधिकार कलेक्टरों को नहीं बिल्क इन्हों प्रजातन्त्रों को प्राप्त होना चाहिये। अब राजस्वशासन की ब्रिटिश नौकरशाही प्रणाली में मौलिक रूप से परियर्तन करना चाहिए। राजस्व—सम्बन्धी समस्त अबिकार को जो कलेक्टर को अब तक प्राप्त रहे है उसी रूप से जारी न रहना चाहिए।

२६—बोर्ड आफ़ रेवेन्यू (माल बोर्ड), किमश्तरों और कलेक्टरों की वर्तमान व्यवस्था को इसी रूप में न रखने दिया जाय। हमारा विचार है कि माल के जिन वादों (मुक़दमों) पर पंचायत निर्णय न दे सकती हो उन पर भविष्य में दोवानी के न्यायालय निर्णय दिया करे। हम उस सुधार पर बहुत अधिक जोर देते हैं, क्योंकि हाल के अनुभव से हमें यह मालूम हो गया है कि माल के न्यायालय नासनाविकारियों (executive) की उंगलियों पर नाचते रहते हैं। एक ही प्रकार के लोगों के हाथ में कार्यकारी (executive), माल सम्बन्धी और वैचारिक (जुडीशियल) शक्तियों के संचित हो जान से शासन के अधिकरियों की इच्छा से विव को उचित प्रक्रिया (डचू प्रोसेस आफ ला) विफल हो जाती है।

२७—हन इम सिद्धान्त के बिल्कुल विरुद्ध हैं कि प्रान्तीय सरकार को जह अविकार प्राप्त हो कि वह किसी व्यक्ति को मालगुजारी वसूल करने के लिए नियुक्त कर सके (खंड २५२)। इस निदेश का किसी दल विशेष के सदस्यों को उस दल को में गएं करने के उपलक्ष्य में पुरस्कार देने के लिए दुष्पयोग किया जा सकता है। ऐसे माल के कलेक्टरों की नई जगहें बनाने का हम घोर विरोध करते है।

२८—(खंड २०४) हम समिति के बहुसंख्यक सदस्यों के इस अविश्वास से सहमत नहीं है कि दीवानी के न्यायालय इस बिल के भाग १ के अधीन दी हुई आज्ञाओं पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई न कर सकगे और उन्हें ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं हैं। इसके विपरीत हमारा यह विचार है कि ऐसे न्यायालय और उनके अफसर ऐसे मामलों पर बिना भय के कार्यवाही करेंगे, क्योंकि उनकी भावी उन्नति शासनाधिकारियों के ही उनर निर्भर न रहेगो। हमारा विचार है कि यह खंड निकाल दिया जाना चाहिये।

२९--(खंड २९१)हमारा यह मत है कि इस खंडम जिन अधिकारियों का उल्लेख कि मा गया है वे सब नियमित वैचारिक विभाग में ही लिए जाएं और प्रतिकर कमिश्नर (Compensation Commissioner) तो हाईकोर्ट के विचारपित (जज) के पद का होना चाहिये जब तक उक्त अधिकारी सरकारी शासनाधिकारियों (Executive - Government) के प्रभाव से मुक्त या स्वतन्त्र न होंगे तब तक उनके निर्णयों का जमींदारों के हितों के विरुद्ध

होने का भय बराबर बना रहेगा। आयरलैंड की भूमि व्यवस्था कमीशन (लैंड कमीशन) के सदस्यों में से एक वैचारिक (जुडीशियल) किमश्नर हैं जो हाई कोर्ट का जज है और छः सामान्य कारबारी किमश्नर (lay commissioner) हैं जो अत्यन्त आवश्यक बामलों में सरकारी प्रभाव से मुक्त या स्वतन्त्रहोते हैं। सामान्य किमश्नरों के निर्णय के विरुद्ध अपील दिब्यूनल के सामने जिसका एक सदस्य हाई कोर्ट का जज होता है, करने की भी व्यवस्था की गई है। हमें यह भय हैं कि प्रतिकर निर्धारण करने के काम को कम से कम समय में और ऐसे अधिकारियों द्वारा जो पूर्णत्या उसके वश्च में हों पूरा पूरा करा लेने के प्रयोज्जन से सरकार यह काम शासन के छोटे और अनुभवहीन अधिकारियों को यहां तक कि तहसीलदारों को भी सौंपेगी। यदि यह अत्यन्त महत्व और उत्तरदायित्व का काम ऐसे लोगों के हाथ में दिया गया जिनकी ईमानदारी, योग्यता, निष्पक्षता और स्वतन्त्रता पर आलोचना की जासकती हो, तो २० लाख सेअधिक मालिकों के जो ४ करोड़ एकड़ से ऊपर भूमि के स्वामी हैं और जिनको जमाबन्दी निकासी १७ करोड़ रुपये से ऊपर है, प्रतिकर निर्वारण का काम कम से कम समय में समाप्त तो किया जा सकता है, किन्तु यह बात सत्य और समुचित व्यवहार के प्रतिकृत ही होगी।

३०—लंड १ (३) हमारी राय तो यह है कि यह विधान इस समय लागू न करके आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद जिसके होने की सम्भावना एक दो वर्ष में है, लागू किया जाय। इस सुझाव के लिए हमारा यह विचार है कि बिल की सब से मुख्य बात अग्रिम धनराशि या लगान का भगतान करके भूमिधारी अधिकार प्राप्त करना है। अत्यव निर्वाचक—वृन्द या जनता को इसके समझाने और इतनी व्यापक और ऐसी अपूर्व योजना पर जिसमें किसानों को १७५ करोड़ से अधिक रुपये का भगतान करना होगा, अपना निर्णय देन के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इंगलैण्ड के अमिक दल (मजदूर दल) की सरकार भी इस्पात उद्योग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधान को आगामी सामान्य निर्वाचन के बाद लागू करने के लिए राजी हो गई है, यद्यपि उक्त विधान का जमींदारी—विनाश और भूमि व्यवस्था बिल के सामने कुछ भी महत्व नहीं है। इसमें अचम्भे की कोई बात नहीं है यदि ऐसे भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कान्तिकारी परिवर्तन करने में जिनका प्रभाव लाखों व्यक्तियों पर पड़ता है, कुछ समय लग जाय और इस सम्बन्ध में कुछ महीनों का विलम्ब जब तक कि आगामी निर्वाचन का परिणाम ज्ञात न हो जाय, हो जाना निर्तान्त उपयुक्त है।

३१—उस तर्क का कि कांग्रेस के घोषणागत (man festo) के अनुसार मंत्रिमंडल के लिए यह आवश्यक हैं कि वह अगले निर्वावन की प्रतीक्षा न करके जमींदारी उन्मूलन के लिए विज्ञान बनाए और उसे लागू करे, हमारे पास यह उत्तर है कि उक्त घोषणा-पत्र के आदेशात्मक (mandatory) होने पर औचित्य से अधिक जोर दिया जाता है। कांग्रेस का घोषणा-पत्र बहुत व्यापक और विस्तृत लेख-पत्र था, जिसकी केवल एक मद यह थी कि राज्य और भूमि जोतने वाले कृषकों के बीच से मध्यवित्यों को दूर कर दिया जाय। किन्तु उसमें मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देने के लिये वाध्य किया जाय। उक्त घोषणा-पत्र (मेनीफेस्टो) में सभी मध्यवित्यों के सम्बन्ध में आदेश दिए गए थे। किन्तु प्रवर समिति में इस बिल की भूमिका ही बदल दी गई है कि जिससे कि एक ही वर्ग के मध्यवित्यों अर्थात् जमींदारों पर ही जोर दिया जा सके। यदि मध्यवर्ती शब्द की ठीक-ठीक व्याख्या

की जाय तो इसका यह अर्थ निकलेगा कि रैयतवारी और काश्तकार अदना की मिल्कियत (peasant propritorship) की पद्धतियों का भी उन्मूलन किया जाय और ऐसे लोगों को भी हटाया जाय, जिन्हें हस्तान्तरण करने, उप-पट्टेपर भूमि देन और विकास करन के प्रतिबन्ध रहित अधिकार प्राप्त है, जैसे कि स्थायी बन्दोबस्त के क्षत्रों म शरह मुअयन काश्तकार, और दूसरे वर्गों के उन काश्तकारों को भी दूर किया जाय, जिन्होंने अपनी भूमियां उप-पट्टे पर उठा दी थीं। कांग्रेस के घोषणा-पत्र के आदेशों का इस प्रकार से अस्पष्ट और संकुचित सा अर्थ कर दिया है कि वे केवल जमींदारों पर ही लागू हो सकें। सम्भवतः इसका कारण यह है कि उनमे संगठन का अभाव है और इसी से राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका दल शक्तिहीन है। अतएव चार वर्ष पहले निर्वाचन के समय पर निकाले हुए घोषणा-पत्र में की हुई प्रतिज्ञाओं को अधित्रम्ब गालन करने के अतिवार्य दायित्व पर बहुत अधिक जोर न दिया जाना चाहिए। और उस घोषणा-पत्र में भी भूमि व्यवस्था के सुधार की चर्चा महत्वपूर्ण और मूच उद्योगों के राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय नियंत्रण के अपीन लिए जाने की बात के बाद और बहुत सो शोर बातों के बाद की गई है। यदि उद्योगों के राष्ट्रीय-करण की बात घोत्रगा-तत्र में रहते हुए भी स्यगित को गई है, तो इस बिल में प्रस्तात्रित भड़ी और असंगत भूमि व्यवस्था भी उस समय तक रोकी जा सकती है, जब तक कि एक दो वर्ष बाद अगचा सामान्य निर्वादन न हो जाय और जनता उसके द्वारा अपने मत को घोषणा त कर दे।

३२--हम यह कहते का साहस करते हैं कि मंत्रिगण और वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं में उनके अनुरायोगण निर्वादकों के विवारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । वे कांग्रेस की नीति बनाने बाले कुछ बड़ बड़े लोगों के बिश्वासों को ही दोहराते रहते हैं। लगभग ३० वर्ष पर्व लोगों के मन में उक्त विश्वासों की घारणा हो गई थी। उस समय अवध के किसानों के न तो खाते ही सुरक्षित होते थे और न लगान की ही कोई व्यवस्था थी। ये विश्वास अब बहुत पुराने पड़ गए हैं, क्योंकि वे इस प्रान्त के काश्तकारी विधानों में १९२१ ई० से किए गए परिवर्तनों से बहुत पहले के विश्वास हैं। यहां पर यह कह देना असंगत न होगा कि पहले दो महत्वपूर्ण परिवर्तन उस समय किए गए थे जब व्यवस्थापक सभा में उन्हीं जमींदारों का बहुनत था जिनकी आज कल बहुत निन्दा की जाती है। हमारा संकेत अवध रेन्ट ऐक्ट, १९२१ और आगरा टनेंसी ऐक्ट. १९२६ से हैं। उकत परिवर्तनों के कारण आज संगुक्त प्रान्त की भूम्यधिकार की व्यवस्था, रैयतवारी और मालिक अदना के स्वामित्व को (पीजेंट प्रोप्राइटर शिप) व्यवस्थाओं से अच्छी है जिनमें इस प्रान्त की अपेक्षा अस्थायी कृषकों (tenants at will) या ग्रैर दखीलकार असामियों की संख्या बहुत अधिक रहती है। यह बात कि कृषक जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने और उसके इस स्थान पर बिज को योजना रखने के लिने वाध्य कर रहे हैं, तथ्य के प्रतिकूच है। वे काश्तकार जो सरकार के मत के अनुसार इस समय इतने सम्बन्न हैं कि वे लगभग २०० करोड़ रुपय निस्तंकीच दे सकते हैं, उस जमींदारी प्रथा को

नित्थयां १२९

उन्मूलन करने के लिए क्यों उत्सुक होंगे जिसके अधीन वे इतने फलते-फलते रहे हैं। अरि यदि वे स्वयं इतने उत्सुक है तो सहकार को उन्हें यह समझाने के लिए क्यों इतना घोर परिश्रम करना चाहिए कि जमींदारी प्रथा बहु दी जानी चाहिए। इनके विश्रीत हम यह दयनीय दशा देखते हैं कि सरकार अपने सब साधनों और ता युक्तियों से इस प्रयोजन के लिये काम ले रही है कि किसान इस बिल के मुख्य सिद्धान्त अर्थात् जनींदारी प्रथा के उन्मूलन को स्वीकार कर लें। यदि इस बिल को किमानों से अभिमन कराने के लिए इनना संगठित प्रयत्न और कर दाताओं का इतना अधिक धन व्या उरना आवश्यक है तो हमारी यह सांग बिल्कुल उचिन है कि इस बिल के लागू होने के नहने, इस पर अगले चुनाव में जनता की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। हम इस युक्ति को और अधिक पुष्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमों अरने मन के प्रतिश्वन और परर्थन लरने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए है।

३३--उपसंहार --हसने इस अत्यन्त विवादास्यद बिच पर मोटे रूप में अपने विचारों को व्यक्त किया है। यह बिल गांव में रहने वाले २० लाख से अधिक जमींदारों नो दूर करके गांव समाज के सारे संगटन को ही छिन्न-भिन्न करता है और इस प्रकार से उस स्थायी आधार को नष्ट करती है जो शान्ति और नई व्यवस्था बनाए रखने में अमूल्य सेवा करता रहा है। गांवों में पहले से ही अव्यवस्था के चिन्ह प्रकट होते लगे हैं। जो लोग वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को हिसात्मक उपायों और साधनों से नष्ट करने में विश्वात करते हैं हमारे उन पूर्वीय पड़ोसियों की ओर से हमें उत्तरोत्तर भय होता जा रहा है। यह समय प्रान्त की भूम्यधिकार व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यापक और विस्तृत परिवर्तन करके अनुभव प्राप्त करने का नहीं है। और उस दर्शा में जब इससे किसानों को लाभ नहीं पहुँचेगा, किन्तु इसके विपरीत लाखों जमीदार उन्मलित और निर्धन हो जायंगे। उनमे उप रोष और घोर असन्तोष के भाव उत्पन्न हो जायंगे और वे हिंस तमक सिद्धान्तों के अनुयायी हो जायंगे। हम यह जानते है कि किमानों को हमारे विकद्ध भड़काना और हम पर बुरे से बुरे दोष लगाना सरल है। हम उस अत्याचार से अपरिचित, नहीं हैं जो कियी एक प्रवल राजनीतिक दल द्वारा उस दशासे कियाजा सकता है, जब कोई प्रवल विरोधी दल नहीं और जब जनना घोर अज्ञान से आवृत हो और सरकार के सम्बन्ध में जो यह सनतनी हो कि वह उन्हें जब चाहे उत्पीड़ित कर सकती है और जो चाहे, सो कर सकती है और जितका सरकार के सम्बन्ध में यह विचार न हो कि वह उसे बनाया बिगाड़ सकती है। प्रत्रर सिनित में हम अन्तर्संक्रक थे और व्यवस्थापक सभाओं में तो उमारी संख्या बहुत ही कम है। तो भी हम उन लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने में चूक न करेंगे, जिन्होंने हमें अपना प्रतिनिध्नि चुना है। वतन्त्रता की सच्ची कसौटी अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुरक्षा है। बहुसंख्यक दल को इस देश के लिये स्वतन्त्रता प्राप्त करने के अपने गौरवान्वित कार्यों पर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे इस प्रकार से आचरण करना चाहिए कि स्वतन्त्रता की मूल भावनाएं ही नष्ट न हो जाएं। और अस्पतंत्रकों के अधिकार किसी मृगनरीचिका का अनुसरण करने में परों तले न रौंदें जायं निष्पक्षता और न्याय, राजनीतिक दलों के नेताओं के पूर्वद्वष या पक्षपात और पूर्व स्नेह की अवेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजे हैं।

जनना की इच्छा ओर किमी सार्वजनिक नेता की उमंगे और उसकी हटीली चित्तवृत्तियां सदा एक ही बान नो नहीं होतीं।

हस्ताक्षर--

लखनऊ, २२ दिनम्बर, १९४९ फूल कुमारी।
के॰ एजाज रसूल बेगम।
मो॰ जमशेद अली खां।
एस॰ एजाज रसूल।
सुरेश प्रकाश सिंह।
वीरेन्द्र शाह।
राम नारायण गर्गः।

परिशिष्ट जिसका उल्लेख १४ पैरा में किया गया

पृष्ठ १ फारमूळे

एक = कृषि आयकर घटाने से पूर्व पक्की निकासी ।

एक = भिन्न जो कच्ची निकासी देव मालगुजारी के भाग से बनती है, उदाहरणार्थ

३०/१००, ३५/१००, ४०/१००, इत्यादि, इत्यादि।

उदाहरण

यदिमालगुजारी = कन्वो निकासो का ३२ प्रतिशत भाग (एफ) = ३२/१०० = ८/२५

19	ep) 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	۵۰ ۵۰	क्षम् ।	×.×9	१,४३,२	્ર કે છ <i>ે</i> કે	5,04 ×	3,06.0	अ. १५५.६	3.50	१.०%'७
PIP	जार घोड़ र्क निड्ड नी क्षिक्ष	°~	कृषक	r~ °	87	44.0	3.95	4.25	er 85	يو. مون	7.22
अथि- हः	स्तम्भ २ का प्रतिशत	۰,	क्राय	وم مر	e.	عب نو	ம்' த்	×. 6 6	70 70 cur	0.4·0	40.9
क्ष	मनराज्ञि	V	स्वयं	9.	۵٠ ۲	**	₩. %	5: % %	2.45	***	30 30
ţħ.	मार घोड़ के निट्य हमी किश्य	9	क्ष्ययं	° &	30	57	e.	0	49	606	3.5
	हिं € इस्प्रह्म इ. इ. इ	na.	हप्य	E 0	4.01	ر ج. م.	20.5	mr ext	કુ. કુ.	3,04 1	2.44.
क्तिकानी	म्बर्ग सम्बद्ध स्थितक स्पाउ स्थार स्था	•	द्याय	~	صه عود	ૐ. ૐ.	٠ <u>.</u>	3.5	75.6	स्० द	3.
ક.' દ	자 마 PIPP - 25 T과 다위보	>>	ह्यम्	8.8	er V	36	3	9:	5; V	**	51 9* 9*
ा मिनक	हार लाम नी किन्त ट ८६ कि	W.	रुपये	uż v	83.3	84.8	2.2	ب م م	بر عر س	2.03	8.8.8
St. St.	निकासी	or	ध्ये	6. 6.	ار مر	95	ns. 5.	8,0%,3	8.94.8	4,02.4	3,50,5
i H Si	संख्या	~		~	or.	m	>	5	us	9	v

८ , ७७,२	6,586.0	2.88.68	6,5,00.0	20,00.0	० ००० १४ ८ ८	0 001)	33,000	38,000	80,000
३३०,९ ५,०९९	0.95,9	8.43.8	2,00.0	3,40.0	٥٠٥٥، إ	3,40.0	8,00.0	8,40.0	4,00.0
۵ ۲	23 6	इ.४.इ	१४.७	१४.७	9.%5	9.×	१४.७	१४%	28.6
200	0 58'8	ठे १४ १	2,0000	००५'८	g,000	3,40.0	8,00.0	0.07,8	0 00%
3,00	3,40	004	00'8	6,00	00%	000	00'2	6,00	80,00
\$.40.5 2.03	3,46.3	३,०७,६	8,80.8	9.59.2	ह १९५३	୭. ୭ ≿′୭	٢,٩٥٠٩	2.55.2 . 8 fold	१०,२५.३
2.03	0.03 0.03	8.53	4.85.9	5.47.9	६ ८७%	3,83.6	3,53.8	१ हें के 'ट	इ.१५,०१ ८.५०,६
23.5	4:26	5.95	رد در	0.97	۶ ۲	ଶ.୨୭	8.5	१,०२५	% है है ते
82.8	४.५१.५	8,62.3	0,58,5	3,03.6	m So	£.74.3	8.32,8	2.88.2	3 9005
8,04.8	2. 6.6.	۾ ه. ه. و	8,28.0	80,88,08	१२,१६.२	গ্ৰন্থ, ধৃত্	१६,२०.स	१८,२२.६	र.१५५०
•	°~	۵٠ ۵٠	3	es.	× ~	<u>ئ</u> مە	w.	9 ~	22

(२) क्ष निकासिया से तान्त्यं उन कच्ची निकासियों से हैं, जिनके अपर माल्जुंअरी नियत की गई है। (३) कुल माल्जुजारी अबवाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी का ५०.६२५ प्रतिशत है। कुषि आय-कर घटाने के बाद कुल प्रतिशत कटोती के अक निकालने के लिये ५०.६२५ प्रतिशत के अक में मबधित कच्ची निकासी के सामने स्तम्भ (९) में दिये हुये प्रतिशत अको को जोड़िये, इस प्रकार मद १८ में सपूर्ण सपतिया २०,२५,३०० है और फुल फटौती ५०.६२५ + २४.७ = कच्ची निकासी का ७५.३२५% है। (५) २०, २५, ३० हपये की संबधित कच्ची निकामी का मुआविष्या लगभग २४ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है। से ह। उदाहरणाय.१ भे टिष्पणी—(१) सारे अंक हजारों में है। इसिलये दशमलव बिन्दु के बाद, अक से लात्ये उतने ही सैकडो हपयो तान्पर्ष १०० क्पये से है. ३ से तान्पर्ष ३०० हपये से है, .७ से तात्पर्य ७०० हपये और ५३.३ से तात्पर्य ५३,३०० हपये से है।

• •										
क्रमिस (मुआविजा) स्नम्भ का ८ गुना	<i>≈</i>	ह्यम	6 % .%	१,४३.२	o.fe.o	3,03.2	3,06.0	% अतः ह	4.28.6	प्र.०५,७
रक प्राप्ट थीकु कि निउद्य के क्रिक्म इाक मिल्मिन	02	हपये	o, W	o∕ o⁄ o⁄	99.0	४.१५	ት ፡2ዩ	3, E.	n, n,	2:22
आय कर स्तम्भ २ का प्रतिश्वन 	~	हमये	ur ur	» »	ur S	8.9	2.0%	9. 9.	8.48	۵۰ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د
कृषि ः धनराशि	v	हत्त्व	ં	ب	us.	>°	5. 8. 8.	28.6	2.55	કે કે
– घाष्ट छीकु र्क नाडड रुक् क्रिक्म इंप् क्रिकिनी	9	र्वय	°~	. 02	24	er o	0 5	<i>5</i> ′	6,00	04%
भ हिंद ध∓हरू र्गिष्ट कि कह	us	हमये	e. %	ج. ه.	76.7	25.62	پي پي	% % %	2.59.3	ج. ج. ه.
ਭੀ।ਲਾੜ੍ਹ ਬ•ਾਬਦ ਬਿਦਾक ਸ਼ਖ਼ਤ ।क ਅੰਤ੍ਰ ਜ਼ਿਸ਼ਾਕਜ਼ੀ ਜਾੜਜੀਦ	 	ह्मये	us Si	ئوں خوں	07	6 ²	0 13 0	23.8	3%	×6.8
अबदाव माल्ज्यू— जारी का १८ ३/४ प्रति— शत	>0	रुवये	m· ov	Uş. Azı	er.	m.	کن خونا	O.	2.5%	3.58
िराक मुख्यम भिगकनी किन्क काइतीय दृह कि	m	हत्त्वे	nş.	هـ ب	% %	3000	9 × 0	3.03	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	8,03.8
कच्ची निकासी	~	हिषये	€. 6.	\$ \$ \$	رد جن دي	7:23	\$°06°	\$\ \$\ \$\.	3,83.6	
क्रम- संख्या	~	i	~	m	œ	>	س	ųγ	9	v

र्ष .१ से तात्पर्य	.चटाहरणा	् न न न न न न न न न न न न न न न न न न न						;	30 40100
		٠ ١٠ ٢	4,00.0	6,000	১,২৬.৬	3,88.8	9,96,8		
20,000	6.00.0	2		•	\ :0 \ fo \	3,66.4	%,8%.	2.88.3	96,88.9
0,00,0 0,00,00 0,00,00	४५०.०	23.6	0.07,8	0018		6			×·> o '9>
9.00 of		•	100	0017	8,03.8	3,44.3	8,05.8	9.88.4	6
32,00.0	8,00.0	3.85	%,00.0	00			ŝ	بر ش بر	8.52,89
		۲. ښ۲	3,40.0	00'9	8.82,0	2.03.8	× • • •		
36,000	3,40.0	e (•	r r r r	4,74,5	ອ ຫຼຸ່າ ຫຼ	7,20,8	3,000
500	3,00.0	3°.	9,00,5	00	u u u	6		7	25.50
0,00.XC			•		7.4.5	9° 9° 9°	2.53	2.0%	7.63.0
30,00.0	2,40,0	7.3%	2,40.0	9	- 1	,		****	×. 4.4.5.7
		r å	2,00.0	%,00	8,48.8	9,98,8	8. 8. 3	ส เ <u>.</u>	
85,000	0.00.0						36.2	7,08.3	5.36.3
100	×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×, ×	23.2	8,86.8	3,00	3,36.3	9,30	61 1		\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
0000					3,64.5	5.59	300	5.00.0	6
٥٠,४८.٥	8,38.0	85. ×	8,88.0	3.40	0			ار الد الد الد	४,२५.५
	٠. د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	28.2	8008	3,00	7.24.4	2	2		
4.69.7	000								

हिप्पणी:—(१) सम्पूर्ण अंक हजारों मे हैं। इसलिय दशमलव बिन्डु के बाद अंक से तात्पर्य उतने ही सैकड़े रुषयों से हैं, उदाहरणार्थ १ से तात्पर्य १०० हपये से हैं, ३ से तात्पर्य १३,३०० रुपये से हैं, ७ से तात्पर्य ७०० रुपये से हैं और ५३,३ से तात्पर्य ५३,३०० रुपये से हैं। (१) कच्ची निकासियों से हैं, ३ से तात्पर्य ३०० रुपये से हैं। (१) कुल मालगुलारी अवधाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी से तात्पर्य उन कच्ची निकासियों से हैं जिनके उपर मालगुलारी नियत की गई है। (१) कुल मालगुलारी अवधाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची निकासी सामने के स्तम्भ का पृश्य प्रतिशत कच्ची निकासी सामने के स्तम्भ का पृश्य प्रतिशत है। कृष्णि-आय-कर घटाने के बाद कुल प्रतिशत कटौती के अंक निकालने के लिये ५३ प्रतिशत के अंक मे संबंधित कच्ची निकासी सामने के स्तम्भ ९ दिये हुये प्रतिशत अंकों को जोड़िये, इस प्रकार सद १८ में कच्ची निकासिया २१,२७,७०० है और कुल कटौती ५३ + २३.५ कच्ची निकासी ७६.५ प्रतिशत है। (४) २१,२७,७०० हप्ये की संबंधित कच्ची निकासी का ७६.५ प्रतिशत है। ४,२१,२७,७०० हप्ये की संबंधित कच्ची निकासी का मुआविजा २२ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है।

प्रतिकर (मुआविजा) (रतम्भ १०- का ८ गुना)	۵٠ ۵٠	रुपये	१११०	१,४३.२	6,66.0	5,03.2	0,20,5	3,50	4,29.6	8.09,0
रुक घास−छोकु डाड रू नाउड माक्नो दिक्का	°~	हव्ये	e, ui	8.6.8	27.0	۶. ۱۶.	7.25	43.2	na. Car	2.22
कृषि-आय कर हा रतम्भ (२) का पनि शत	∞	ः पय	եչ. 3	}> >>	6.3	9.3	60.0	83.E	9.%	9.98
कृषि धनराशि	>	र्वयत्र	Ð,	3.8	w.	>0 n3-	5. % %	2.85	23.6	8.
ज्रक-प्राप्ट ष्रीकु क्रिक्प डेप्ट के निज्ञ निक्ति	9	त्रवये	°	30	74	w.	9	<i>5</i> ' 9	00%	6,40
ह (ह) भग्ना किक्त (भ) गिष्ठ	us	स्पये	9.0	3	ال ب ب	٠ ١	8.5 15.	ବ.୭.୬	१,३०.२	8,94.3
क्ति शास्त्रह स्कार मित्रक्ती क्रिक्स सम्ब हाइहीय भ्रु क्रि	ۍ	क्षये	ar m	o^ w	w. V	٨٠٥	86.3	ठ. १	5°,≿	2.44
-गुलाम घाष्ट्रस् ४ ६ २९ कि ग्रिक माहीद	>	हप्ये	3° 00	w.	us.	<i>5</i> ′ %	<i>છે</i>	% % u.	٥٠	33.6
ग्रिसः ' राम मिल्कार्गे क्रिक्क , जहानीस एक	W.	रुपये	2 '2	م. نن م	3005	28.5	۳۰ م	۶۰۰° د ۲۰۰۰	3.02	8.50.6
कच्ची निकासी		ह्मय	0. m	ر نور کر	3,007	m. 9.	8.84.8	8,62.6	7,30.7	3,84.3
1	٠		o	o	M?	*	سی	سويا	ඉ	V

~	۶٬۰ ۶٬۶		m. o	ns. o.	४.०३,५	00%	80.8	0.0 0.0	8,08.8	به
° *	からから	१ ० १ १	2.95	er 37	3,74.5	3,40	6,88.0	20.08		6,3%.0
o	05. 0.	2,8%.6	**************************************	8,0 0,0 B. B. B	3,00.5	€ 00 €	१,४७.९	۶۰۰	مت	४.५२.१
2	8,70.8	क,स्ट्र- , ह	₩ •••	8,35.8	4.30.8	0062	3,000	9.85	6	2,00,0
m	88748.8	8,04.8	3·50	୭.၄୭,୨	8.44.3	6,00	2,40.0	9.%	3,6	9,40.0
%	83,68.3	0,00	२,०७.२	६,१८१.३	n. 0	3,00.0	9.%	3,00.0	५४,०	४४,००.०
2	7.99	و مورد	2.40.8	৽ ৽১৯'১	4.88.8	٥٥°٩)	3,40.0	७.% ह	er F	3,40.0
W-	a, y x 2 y	9. 88.	8,30.8	इ.३७,५	9.9%,o9	6,00	8,00,0	9:32	×,	۵,00,8
න ~	२०,७१.९	७,२५.२	8,38.0	3,80.5	8.98.88	6,00	8,40.0	2%	<u>بر</u>	0,07,8
2	र.५०,६५	2.40,2	0.37.9	3,84.3	83,03.0	80,00	6,00.0	9.%	يق	6,00,0
1								1		

१०० रुपये से हैं, '३ से तात्पर्य ३०० रु० से है ७ सेतात्पर्य ७०० स्पये से है अरैर ५३.३ से तात्पर्य ५३,३०० रुपये से हैं, (२) कच्की निकासियों से तात्पर्य उन कच्ची निकासियों से है जिनके ऊपर मालगुजारी निग्धत की गई। (३) कुल मालगुजारी अबवाब और प्रबन्ध का ध्यय कच्ची निकासी का ५६.६ प्रतिशत कुषि आय कर के घटान के बाद, कुल प्रतिशत कटौती के निकालने के लिये ५६.६ प्रतिशत के अंक में कच्ची निकासी के सामने स्तम्भ ९ में दिये हुये प्रतिशत अंकों को जोडिये, इस प्रकार मद १८ में कच्ची निकासियां २२,०२,२०० है और कुल कटौती ५६.६ × २१.७ = कच्ची निकासी का ७८.३ प्रतिशत है। अंक हजार की संख्या में हैं। इसिलये दशमलब बिन्दु के बाद अंक से तात्पर्यं उतने ही सैकड़े रुपयों से हें, उबाहरणार्थं १ से तात्पर्य महीने की कच्वी निकासी के बराबर है संबंधित कच्ची निकामी का मुआविका लगभग २१ टिप्पणी--(१) सारे (४) २३,०२,२०० सपये की

प्रतिक्र मुआखिता स्नम्भ १० का ८ गुना	۵. ۵.	रुपये	8,29	१,४३,२	8,65.0	7,03.2	3,06.0	કે કે કે કે કે	4.28.6	×.0%'9
क्षिमि क्षिम रुक्-शार बोकु झाह क् निडाट	°à	क्पये	e.	8.98	33.0	४.५५	4.25	43.5	m G	2.22
कृषि आय-कर स्तम्भ २ का प्रतिशत	~	रुपय	છે. જ	87°	3. ×	2.4	3,	8.08	9.5%	६५७३
कृषि घनराधि	٧	हत्त्व	ల.	8.5	w. 0	رون نحر	5:22	3.8.5	هـ ک•	۳. ج. د.
मितम्ति क्षिम् रुक्ष-प्राप्त घीकु केपू कि नाउस	9	हत्त्वय	°~	39	3,	War.	9	5 •	8,00	004'8
े स्वस्म स् स्वस्म सक धोग	ús.	हमये	9 13 8	us. us. us.	ອ: & %	30.07	£:£2	१,२५०	8,5°F.6	2,40.0
कि शाफड़ वन्हर किन्क फफ़ १९ के झिक्सी ७० काइनीस	5"	ह्मयम्	×	٠.	60.0	63.0	30.0	30.0	%o.o%	0.0,
-लाम बाबक्स क्रीहार अहितीद्देष्ट्र ४/६ ४१ मुब्बम्डी क्	>>	हप्ये	8	°,	9	rz,	60.0	0.7%	50.0	6. 0.
रिग्राकारनाम मिकानी क्रिक्क नाइनीस ०४ कि मिकामडी क्र	m·	हत्त्वये	୭.º ≈	5.5 5.3	ð:35	भू ५०		0.05	१,०६७	०५ ००
कच्ची निकासी	er	हम्पये		ال الم الم	9.5.67	0°0	85 85 85 85	°:	2,00,5	र्के० ६०
ाल्या	~	-	o.,	G.	tu.	>	5	(J)	<u>စ</u>	V

						-			
C,68.4°	60,86.0	2.39,59	6 6,000	20,00.0	58,000	\$6,0.00	35,000	०.००,६३	0.00,08
8.80%	6,38.0	8.44.8	2,000	a:2}	3,00.0	3,40.0	8,00,0	8,40.0	6,000,
9. 9.	2.9%	5.7°	9:28	0.07.5	9.2%	ด:2%	9.2%	9.2%	9.2%
3.03	6,89.0	३. ७४.९	0.00	3,40.0	3,00.0	3,40.0	0,00,0	0.04,8	0.00,4
2,00	3,40	3,00	۶,00	001/2	003	00,0	00,5	6,00	00'08
EL EL EL	श.११ १.१	4,000	S. E. E. & S.	0.55.8	60,00,09	9.33,89	83,33.3	0.00,49	9. 6. 8.
0.02	8,00.0	6,30.0	6,5000	2,00.0	2,80.0	2,60.0	3,70.0	3,50.0	0,00,0
80.0	60.0	0.0	0.05	8,00.0	8,30.0	6,80.0	6,50.0	6,60,18	3,000,5
7. 64 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	9,55,5	3,70.0	४,२६.७	12 m	0.0%	o,3%.e	5,43.3	6,60.0	80,44.08
, 3 3 5 0 . 3 . 5 . 5 . 3 . 3	m m m	0,00,2	9,5,5,0%	१ से स	6,0000	৯.३४,७ ७.३३, ७९	रशुक्कन	58,000	ণ্ড্ৰ'ণ্ড কণ্ড্ৰ'ড্ৰ
e.	0%	~	()* @*	ori Us	× ~	3	w	2	2

हित्पणी——(१) सारे अंक हजारों में हैं। इसिल्ये दशमलव बिन्दु के बाद अंक से तारपर्य उतनोही सेकड़े क्षयें हैं, उदहरणार्थ, ११ से तारपर्य केवल उन कच्ची तिकासी का ६२.५ प्रतिशत है। कुल माल्यांबारी अबवाब और प्रबन्ध का व्यय कच्ची तिकासी का ६२.५ प्रतिशत है। कुल आय कर घटाने के बाद, कुल प्रतिशत कच्ची तिकासी के अंक तिकाल के लिये ६२.५ प्रतिशत के अंक से संबंधित कच्ची निकासी के सामने स्तम्भ ९ में दिये हुये प्रतिशत अंकों को बोड़िये, इस प्रकार मद १८ में कच्ची निकासी का ८१.२ प्रतिशत है। १४) २६,६६,७०० हप्ये की संबंधित कच्ची निकासी प्रतिकर (मुआविजा) लगभग १८ महीने की कच्ची निकासी के बराबर है।

थी त्रिलोको सिंह जो, एम॰ एउँ॰ ए॰ की विरोधात्मक टिप्पको

घारा १—इस बिल के द्वारा किसानों को कुछ अधिकार दिये गये हैं। इसका कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि ऐसे आस्थानों के किसान, जो धारा १ के वाक्यखंड २ उपवाक्यखंड (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिये इस बिल के नियमों से मुक्त कर दिय गये हैं, उन अधिकारों से वंचित रक्खे जायं। सरकारी आस्थानों के किसान अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के आस्थानों के किसान या किसी ऐसे आस्थान के किसान जो सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोग के लिये हो, किसी प्रकार अन्य आस्थानों के किसान से भिन्न नहीं है। ऐसे किसानों को भी उन अधिकारों के दिये जाने की आवश्यकता है जो दूसरे किसानों को दिये जा रहे हैं। यदि इन क्षेत्रों में स्थित ज्यों की त्यों रहने दी गई तो किसानों को बड़ा दु:ख होगा और यह ठीक ही है।

'सार्वजिनिक प्रयोजन' और 'सार्वजिनिक उपयोग के कार्य' शब्दों की परिभाषा की जानी चाहिये। यदि विस्तृत परिभाषा देना संभव न हो तो इस सम्बन्ध में कुछ संकेत करना ही पड़ेगा कि इनके अन्तर्गत कौन—कौन सी बाते आती है। ऐसी किसी परिभाषा के बिना बहुत से झगड़ों के उठ खड़े होने की सम्भावना है जिनसे गड़बड़ी पैदा हो सकती है।

पारा १ के वाक्यखंडों के उपवाक्यखंड (ग) और धारा ७८ के वाक्यखंड (क) के आदेशों में परस्पर विरोध प्रद्वीत होता है। साधारणतया- वक्फ, ट्रस्ट, ऐसे धर्मादायों जो पूर्णरूप से पुण्यार्थ हों, सार्वजनिक प्रयोजन की सम्पत्ति होती है और इसलिये ये घारा १ के वाक्यखंड २ के उपवाक्यखंड (ग) के अपवादों के अन्तर्गत आती है, जो प्रत्यक्ष रूप से इस बिल का उद्देश्य नहीं है। इस परस्पर विरोध को मिटा देना चाहिये नहीं तो बहुत से आस्थानों के सम्बन्ध मे इस क़ानून का उद्देश्य विफल हो जायगा।

घारा १ के पहले प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंड के द्वारा प्रान्तीय सरकार को अधिकार विया जाता है कि वह इस ऐक्ट को अन्य क्षेत्रों में ऐसे संशोधनों के साथ लागू करे जैसा कि परिस्थितियों के अनुसार मामले में आवश्यक हो। किसी ऐक्ट के आदेशों को संशोधित करने का अधिकार एक व्यवस्थापक अधिकार है और वह किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। सिद्धान्त यह है कि-धारा- सभाये वह अधिकार दूसरों को दे सकती है जो मुख्य कानूक के 'अधीन ' हों। इस मामले में बिना किसी प्रतिबन्ध के दूसरे को अधिकार दिये गये हैं और इसलिये उससे संबंधित आदेश घारा सभाओं के प्रतिकृत है और उसे निकाल देना चाहिये। कुछ दशाओं में ऐक्ट में संशोधन करने के इसी प्रकार के अधिकार दूसरे और तीसरे प्रतिबन्धात्मक वाक्यखंडों में दिये गये हैं। इनको भी निकाल देना चाहिये।

धारा ८ उपधारा (इ) और (६) में व्यवस्था की गयी है कि मध्यवर्ती का हित ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८८ ई० की धारा ७३ के आदेशों के अधीन होगा। इन प्रान्तों के बहुत से आस्थान कर्जंदार है और यदि उनके कर्जों का निपटारा किये बिना उनको ऋण मुक्त कर दिया जाय तो यह बिलकुल अनुचित होगा। पिछले समय में जमींदारी का मूल्य बहुत था और विशेष रूप से बड़े बड़े आस्थानों को जो प्रतिकर देने का विचार किया गया है वह उन आस्थानों के मूल्य से बहुत कम है जो इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट में निर्धारित किया गया है। ऐसी सम्पत्तियों का मूल्य भी जिन पर पेशियां दी गयी है और जिनका मूल्य पहले से घट गया है, उसी अनुपात से अवश्य घटा दिया जाय।

मेरा यह मुझाव है कि या तो साथ ही साथ एक पृथक कानून प्रस्तुत किया जाय या इस बिल में इसकी ब्यवस्था की जाय। इस सम्बन्ध में मेरा निजी विचार यह है कि इनक्रमबर्ड स्टेटम ऐक्ट या डेट रिडम्पबन ऐक्ट या एप्रीकत्चिरिस्ट रिलीफ ऐक्ट या ऋणं सम्बन्धी किमी अन्य ऐक्ट के अधीन दीवानी, माल या विशेष कोर्ट में कार्यवाहिया जारी रहें, जैसे कि यह ऐक्ट पाम ही नहीं हुआ और किसी डिग्री के करने के यदले किसी मध्यवर्ती के आस्थान का भाग वर्तमान ऋण ऐक्ट के आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायगा और ऐसे भाग के सम्बन्ध में यह समझा जाय कि डिग्री की पूर्ति के लिये उसका स्वत्व हस्तातरण डिग्रीदार को किया गया। और इस विल के अध्यान ३ के अधीन उसका प्रतिकर जिग्रीदार को बादा कर दिया जायगा। इस विल के अध्यान ३ के अधीन उसका प्रतिकर जिग्रीदार को बादा कर दिया जायगा। इस विल के अध्यान ३ के अधीन उसका प्रतिकर जिग्रीदार को बादा कर दिया जायगा। इस विल के अध्यान ३ के अधीन उसका प्रतिकर जिग्रीदार को बादा कर दिया जायगा। इस विल के अध्यान ३ के अधीन उसका प्रतिकर जिग्रीदार को बादा कर दिया जायगा। इस विल की जा रही हों और उन दशाओं में की जा पक्ती है जिनमें डिग्री दे दी गयी हों और किस्त अदा की जा रही हों और उन दशाओं में कि एसी ब्यवस्था की जा सकती है जिनमें ऋण की वसू शि के लिये अब कोई कार्रव इया विवाराधीन न हो।

इमिलिये मेरी राय में ट्रांसफर अप्क प्रापर्टी ऐस्ट के वा रायड (ङ) और (६) के सम्बन्ध में घारा ७३ का उल्लेच निकाल दिया जाय। इस घारा के रहने देने ते ऋणगस्त आस्थानों के हिन को बहुत हानि पहुँचेगं और बन्धक−भोगियो को अनुचित अधिकार प्राप्त हो जायंगे।

घारा ४३ (ग)

किसी भी मध्यवर्ती (Intermediary) के लिये यह कठिन होगा कि वह १० वर्ष के सायर आय के आकड़े दे। साधारणतया वह भू-आगम (रेवेन्यू) के रेकाड़ों में ऐसे इन्दराजात के कराने की परवाह नहीं करता और यदि ऐसे इन्दराज किये भी जाते तो उनके प्रनाणिन उद्धरणों को प्राप्त करने में बहुत ध्यय और समय नष्ट होता और परेशानी भी होगी। अत्युद ऐसी दशाओं में जब १० वर्ष को आप के आंकड़े न दिये जा सकें वर्तमान आदेश (Provison) से उससे उद्देश्य के जिकल हो जाने की सम्भावना है। इसके वजाय मेरा यह सुझाव है कि ३ वर्ष के आकड़ों से काम चल जायगा।

वाक्यखंड (घ)

बनो का इस प्रकार सामान्यरूप से श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। उगने वाले साधारण बन तथा भली प्रकार आयोजित अमूल्य बन जैसे टौन्या (Taungya) प्लान्टेशन इत्यादि। आयोजित बनों की दशा में वृक्षो के पूर्णरूप से तैयार होने में सामान्यरूप से ५० वर्ष से अधिक लग जाते है। २० से ४० वर्ष तक के आकड़ों के आधार पर हिसाब लगाने से यह पता चलता है कि कुछ बनों से कुछ भी आय न होगी। इसलिये ऐसे अमूल्य बनो को सांथा भिन्न आधार पर रखना बाहिये। हाल ही में संयुक्त प्रान्तीय बन (जंगलात) ऐक्ट के अधीन इनमें से अधिकाश विज्ञापन निकले थे मं समझता (Compensation) निर्वारित करने की प्रस्तावित विधि से कुछ दशाओं में बड़ी कठिनाई होगी। मैं यह सुझाव रखता हूं कि खड़े वृक्षों की लागत बन विभाग के वर्तमान नियमों के अधीन निर्धारित की जाय और इस प्रकार प्रतिकर निर्धारित मूल्य का एक एक-वौथाई के रूप में दिया जाय। वर्तमीन मूल्यों के अनुसार भुगतान करना अन्याग्रूण होगा, क्योंकि असाघारण दशाओं के कारण मूल्य बहुत बढ़े हुये है और मूल्यों के बहुत समय तक उसी स्तर पर बने रहने की सम्भावना नहीं हैं और ऐसी सम्पत्तियों का मूल्य जबसे उन्मूचन योजना का प्रस्ताव हुआ है, बहुत गिर गया है।

बन एक अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति है और जिन्होंने इन बनों को सुरक्षित रखा है, उन्हें दंड न देना चाहिये।

घारा १६९

अमामियों ने भी कुछ ऐसे वर्ग है जिनमे व्यक्तिगत कानून के अनुसार ही सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त है। भूमिधरों को कम से कम यह अधिकार प्राप्त होना चाहिये कि उत्तरा-धिकार के मामलों मे वे अपने व्यक्तिगत कानून के अधीन रहें।

अध्याय ११ कोआपरेटिव (सहकारी) फार्मिग

प्रामीण दशाओं के विकास के लिये महकारी फार्मी को प्रोत्माहन देना आवश्यक है, किन्तु कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन आय का एक पर्याप्त भाग लाभों के रूप में बाटा नहीं जा सकना। यदि यह आदेश लागू रहेगा तो किसी ऐसे सहकारी फार्म को चलाने के लिये कोई प्रोत्माहन न रह जायगा। जहां तक लाभों के विभाजन का सम्बन्ध है मेर राथ में कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के इस आदेश को लागू न रहने देना चाहिये।

२७-१२-१८५२

त्रिलाकी सिंह

१६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश स्नीर सूमि-व्यवस्था विल

जैसा कि विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित किया गया है (विशिष्ट समिति के संशोधन रेखांकित कर दिये गये हैं)

कृषक गौर राज्य (state) के मध्यवर्तियों (Intermediaries) से युक्त जमींटारी प्रथा को हटाने, संयुक्त प्रान्त में स्थित ग्रास्थानों (estates) में उनके ग्राधिकार, ग्रागम गौर स्वत्व (rights, title and interest) को हरतगत (acquire) करने तथा इस प्रकार हटाने ग्रीर हस्तगत करने के परिणामस्वरूप भौमिक ग्राधिकार (land tenure) सम्बन्धों विधि (law/), में सुधार करने ग्रीर इनसे सम्बद्ध अन्य विषयों को व्यवस्था के लिये,

बिल

यह उचित ग्रोर ग्रावश्यक है कि कृषक ग्रीर राज्य (state) के मध्यवित्यों से युक्त जमींदारी प्रथा को हटाने ग्रीर संयुक्त प्रान्त में स्थित ग्रास्थानों में उनके ग्रधिकार (rights) ग्रागम (title) ग्रीर स्वत्व (interest, हस्तगत (acquire) करने ग्रीर इस प्रकार हटाये जाने ग्रीर ग्रधिकार ग्रागम ग्रीर स्वत्व हस्तगत करने के परिणामस्वरूप भौमिक श्रधिकार (land tenure) सम्बन्धी विधि में सुवार ग्रीर इनसे सम्बद्ध ग्रन्थ विषयों की व्यवस्था की जाय, इस्लिये निम्नलिखित विधान (ऐक्ट) बनाया जाता है—

भाग १

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, १--(१) यह विधान (ऐक्ट), १६४९ ई० का प्रसार ग्रीर ग्रारम्म। संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश ग्रीर भूमिज्यवस्था विधान (ऐक्ट) कहलायेगा।

त्वः प्राः ऐक्ट १७, १६३६ हे०

- (२) इसका प्रसार (extent) निम्नलिखित की कोड़कर पूरे युक्त प्रान्त में होगा—
 - (क) यूनाइटेड प्राविन्क्षेज़ टेनेन्सी ऐक्ट, १६३६ ई० को अथम परिशिष्ट (the first schedule) में दिए क्षेत्र,
 - (ख) ऐसे आस्थान (estates) या उनके भाग, जो केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार या किसी स्थानिक अधिकारिकी (Local authority) के स्वामित्व में (owned by) हों, या
 - (ग) ऐसं चेत्र जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन या सार्वजनिक उपयोगिता (public
 purpose or public utility) के काम के
 िलये हैं। और उसी के लिए दखल में हों तथा
 जिनके विषय में प्रान्तीय सरकार ने इस
 वात का प्रध्यापन कर दिया है। अथवा जो
 लैन्ड पक्वीजिशन ऐक्ट, १८६४ संयुक्त प्रान्त के
 शरणार्थियों को वसाने के लिये भूमि प्राप्त करने
 कर ऐक्ट, १६४८ ई० या १६४८ ई० का संयुक्त
 प्रांतीय सम्पत्ति के इस्तगत करने का (बाढ़
 सहायक) (प्रस्थायी प्रधिकार) ऐक्ट या इस
 विधान से मिन्न सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
 भूमि इस्तगत (acquisition) करने से
 सम्बन्ध रखने वाले किसी दूसरे विधायन
 (enactment) के अधोन प्राप्त किये गये हो.
- षं० प्रा॰ ऐक्ट १, १८६४, सं० प्रा॰ ऐक्ट २६, १६४८, सं॰ प्रा॰ ऐक्ट २६,

(घ) कोई क्षेत्र जो ३० नत्रम्बर, १६४६ ई० के। निम्नलिखित के ग्रन्तगीत था:—

- (१) वनारस स्टेट (पेडिशिनस्ट्रोशन) आर्डेर, १६४६ ई० में दी हुई परिभाषा के अनुसार वनारस स्टेट।
- (२) रामपुर स्टेट (येडमिनिस्ट्रेशन) साडर, १६४६ ६० वें दी हुई परिमाषा के अनुसार रामपुर स्टेट, या
- (३) टेहरी-गढ़वाल स्टेट (ऐडिमिनिस्ट्रेशन)
 बार्डर, १९४६ ई० में दी हुई परिभाषा
 के अनुसार टेहरी-गढ़वाल स्टेट।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विद्याप्ति द्वारा प्रान्तिय लरका पेसे अपवादेंं (exceptions) [*] और परिष्कारें (modifications) के साथ, जिनसे की गीलिक ग्रन्तर नहीं पड़ता हो, गौर जा परिस्थिति के अनुसार ग्रावश्यक हों, पेसे क्षेत्र या ग्रास्थान में यह पूरा विधान या उसका कोई भाग प्रसारित (extend) कर सकेगी;

गौर यह भी प्रतिबन्ध है कि अब यह विधान या इसका के हि भाग ऐते श्रीत या ग्राह्थान में ग्रप-वादों, [ॐ] या परिकारों के साथ या उनके बिना इस प्रकार प्रसारित कर दिया जाय, तो वहां प्रच-लित कोई ऐक्ट या अधिनियम (regulation) जो इस विधान से या उसके इस प्रकार प्रसारित भाग से या उसमें किये गये किसी [*] परिष्कार से मांगत (inconsistent) हो, रह् (repealed) समभा जायगा।

श्रीर यह भी प्रतिबन्ध है कि जहां तक बनारस जिले के परगना कसवार राजा में इस विधान के लागू है।ने का सम्बन्ध है वह ऐस परिवर्तन, परि-

^{|*|} निकाल दिया गया।

कार और अनुकलन (alteration, in differtions and adaptation) के जाथ लाउ हागा जिनके विषय में गान्ती खें कार गणा में कि कत हारा यह प्रख्यापित कि कि के विकास का उक्त गरमने में प्रचानित करा के खिले कि का

(२—क) उत्तथारा (२) क शंड (भ) व्यापित प्रांतीय सरकार द्वारा किया गया प्रयापन इस बात का निश्चायक प्रभाग (conclusivo ovidence) होगा कि भूम साय जाग ह प्रभा न के छिये या सार्व जिन ह उपोतिता के अये के जिये हैं या सार्व जिनक प्रभावन के लिए। एउनता हा गई थी।

स्पन्ते करण:— ऐसे क्षेत्र के विषय में, ओ के प्रावदेखित सिसाइटाज ऐक्ट, १९१२ क प्रधान निवंधित (registered) किया सहकारों कारणा (Co-operative Society) के, या सासाइटाज रिजिन्हें ज्ञान ऐक्ट, १८६० के प्रधान निवंधिया किसा संस्था (Society) के या इन्डियन केंग्यनी ज ऐक्ट, १६१३ के मधीन स्थापित किसी सार्वजनिक परिसोमित कम्पनी (Public Limited Co.) के पास ७ जुलाई, १६४६ ई० की किसा गृह-निर्माण याजना के प्रयाजनों के लिये रहा हो, यह समभा आयगा कि वह ऐसी भूमि है जो सार्व जनिक उप-येगिता के काम के लिये हैं।

(ই) । বিষয়ে মুদের নথানৈ রা আখ্যা (Shall come into torce at once)। इस विघान का कुऋ भेत्री मेन लग्म होना द—हरिशिश ते सन पेने विसी

स्तेम , १ ७ ६१८ ६ ०

के स्ता विसी विसी

१६१ विसी । श्रिक्त विसी
शिक्ष के स्ता विसी
शिक्ष के स्ता विस्ता के स्तान
द्वार के स्ता विस्ता के स्तान
द्वार के स्ता विस्ता के स्तान
द्वार के स्तान

. सं० गा० **ऐ**ंट, २ १६१६ स २, **१**६२४

सं० प्रा० ऐक्ट २, १६१४

३—शिया ता (obje t or con ext) में कार श्राह्म (, , , ,) होने पट इस शिक्षात में :

(१ कार्या (ben to ry) का ताहायं यक्षा, नेता (brast) म नियम्ब (ordownions) के अन्य में प्रंत व्यक्ति से है जिसके लाभ (bon ils) का उप यक , न्यास (brust) या नियम्ब (endowment) अवेदन में लायां जाश (ex recod)।

(२) "क्रन्तिया सारायां का वर्षा अर्थ है। जो जैनका को केर, १८९० की घाषा दे पेक्ट १०,१८६७ में, क्रिक्ट कार्नियां का कि

परिभाषायें

(३) 'एम विं . ४ न के रिनार्थनी तो नहायला, विद्धा, किं । ११ न का मान्यता नदा साव-जाति के उपयोगिता (११ मान्यो public utality) स्थापनी क्षिणी 'अन्य विष्याता स्विति हैं, किन्तु इसके सन्त्रमत ऐसा कीं 'प्यातन नहीं है किसका सन्दन्ध के ब्ला गमिक-शिक्षा या स्थासना (veorship) से हैं।;

[*] निकाल दिया गया।

- (४) 'हिन्हा' है। जनती प्राम भेगो हैं। ऐसा अपि उन को हर भी है, िले प्राम्भेय सरकार ने गाट में चिनांक का स्ट. एवंट क अधीन कठो हर के सब या काइ कार्य (funct-1008) सम्पादन करने का स्रविकार दिया है।
- (४) 'त्रतिकर किमइनर' (Compensation Commissioner) का तारपर्य धारा २६१ के खबीन नियुत्त प्रतिकर किमश्नर से है आर उसके अन्तर्गत सहापक प्रतिकर किमश्नर (Assistant Compensation Commissioner) भी है;
- (६) 'प्रतिकर अधि शरा' (Compense bion Officer) का ताटार्य प्राग २९१ के प्रघोन विद्युत्तर प्रतिकर क्रिकारी से ६;

क्टि ४, १६०८

(७) 'डिकी' का वही अर्थ है, जो उसे के। इ आफ सिविल प्रोमीजर, १६०८ में दिया गया है;

सं॰ घा॰ ऐक्ट ३, १६०१ (८) 'शान्धान' (estate) का तात्पर्य पेरी क्षेत्र (area) से है, जो यूनारटेड प्राविन्तः. हैंड रेवेन्थ् ऐक्ट, १९०१ की घारा ३२ के खंड (clauses) (प), (वी), (र्ती) था (डी) के ग्रधीन तैयार किये गये और रखे गये रिजन्टों के का उक्त घारा के खंड (है) के न्थीन रक्ते गये [*] रिजन्टों के, जा नक उसा मन्तन्ध दारी काइतकार (permanent tenure holder) से है, एक ही इन्द्राज के ग्रंतर्गत (included under one-entry) हो; और उसमें किसी ग्रास्थान के ग्रं अपास्थान में के ग्रंश (share) का भी ग्रंतर्भीय ही (includes);

L*] निकाल दिया गया I

(६) 'गांव-कोष', 'गांव-पक्रचायत' ग्रीर 'गांव-सभा' का तात्पव यूनाइटेड ग्राविसेज पञ्चायत राज पेकट, १९४७ के ग्रंथीन संघटित या स्थापत कमा उसार गांव-फंड, गांव-पञ्चायत ग्रीर गांव-सभा से है, सं० प्रा॰ देक्ट २६, १६४७

- (१०) 'गांव-समाज' का तात्पर्य घारा ११४ के मधीन स्थापित गांव समाज से है;
- (११) 'ब्रुबि' का अर्थ किसी खाते (holding) के सम्बन्ध में निम्निखिखित है :--
 - (१) खाते की भूमि में खाते-दार (tenure-holder) द्वारा अपने रहने के लिये बनाया गया घर या ऐसे अन्य निर्माण, जो उसने कृषि (Agriculture), फहोत्पादन (Horticulture) या पशु-पालन (Animal Husbandry) सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये खाते की भूमि में बनाये या खड़े किए हों;
 - (२) कोई ऐसा निर्माण, जिससे जाते की भृति के मूल्य में वास्तविक (material) वृद्धि होती है।, जी पूर्विक प्रयोजनी से सङ्गत (consistent) है। और जी, यदि खाते की भृषि पर न बनाया गया है। तो, बह या तो डां सीधे (directly) लाभ पहुंचाने के लिये बनाया गया है। या बनाए जाने के बाद खाते की सीधे लाभ पहुंचाने के योग्य कर दिया गया है। और इस खरड के पूर्विक निर्मेशों को बाबितन करते हुए (subject to), इसके भंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:—

- (क) कुवें।, जल-प्रणालियें (water channels) और पूर्वोक्त प्रगेडनें के लिये पानी पहुंचाने या उसके बंटने (distribution) से सम्बन्धित किसी दूखरे निर्माणें ,works) का बनाना,
- (ख) भूमि से पानी के निकास के लिए या बाढ़ मधना कटान या ऐसी न्यं नम्भन जल स्वित से भूमि को भरक्षित स्थते के लिए बनाय स्था निर्धाण-स्था
- (ग) भूमि का उद्धार (reclaiming), भूमि को जगल-माड़ से रहित करना (clearing), उसमें घेगा बांचना, उसे चौरस (levelling या समसमुन्नत करा। (terracing),
- (घ) ऐसी इमारत का बनाना जो खाते की भूमि के सुविधानुक्छ का नागदाय कर्षा । प्रथम है। और जा उक्त भूमि के बिलकुळ समीप किसी भूमि पर बनाई गई हो जा गांज की बस्तो (village site) से भिन्न हो,
 - (ड) पूर्वो के परी जनों के ियं तालाब या मन्य जलाशा- बयाना,
 - (च) खाते की भूमि गंपेड़ तेर रहा का ना,
- (क) पूर्वोक्त किला निर्मा । नर्वाकरण (renewal) या पुनर्निमोग (recon truction) अथवा उसमें पेसे परिवर्तन या परिवर्द्ध न करना, जो केवल मरम्मत के ही प्रकार के

ेंद्रस्तु शितवन्य यह है कि पेसी जन-प्रवास्तियां, बांच (ombankments), धेर (molosures) तस्थाया बुद्धा । बन विस्तार, जिन्हें कीई, बाति प्रप्ति प्रवास नगी है । वा सामान्य हप स (in the dimery course of his requirments) दनाय, उन्मान नहीं साम नायंगे।

- (१२) 'स गता' (macinicalisty) हा तात्वय किसी भा पान के नान प्रसं पस तात्थान या उसके मिला नान फ स्वासा (proprietor), मात-द्वदार (under proprietor), भदना मालिक (sub-proprietor), डेफेदार, अवध में पट्देदार इस्तमन्दा (permanent lessen in Avad h), भोर द्यामा नाइन हार (permanent tenureholder) से क,
- (१२) 'मन्यवता का याग' (intormodiary's grove) का तात्पय पसा वाग-भूमि से हे, जिस काइ का नात पने पास या दखल में एक दा,
- (१४) 'भूमि' (land) का तात्पर्य थारा १४६ चार १४७ का छाड़ शेष पेक्ट में पेसी भूमि स है, जा किसी के पास या दखल में रूषि फलात्पादन, पशुचर था पशु—पालन से सम्बन्ध रखने याले किसा प्रयोजन के लिये हैं।,
- १४-(क) "वहा 'कं भन्तगंत जब वह खानें।
 या मानित पदाधों के राज्यन्य में गुक्त हो, शिकमी
 पहा, न्वेषण पहा (prospecting lease) और
 पहा देने 'या शिकमी देने का अनुबन्ध (agree-ment) हैं। भीर"पह दार" की ब्याख्या इसी प्रकार

पेक्ट सं० ४, १६०८

(१४) 'विधिक प्रतिनिधि' का मधे वहीं है जो कोड आफ सिन्दि भे साजः, १६०० में, 'legal representative का ह्या गा। है,

१४-(क) "खान" का नाराजे पेसो सभी खोट(इयों (excarations) से है जिनमें खनिज पदार्थी की खोज या पातिक लिय काई कार्य (operation) फिना गया हा या किया जा रहा हा, किन्तु खान से लम्बन्य एखने वाले कोई मशीनरी, ट्रामवे या साइडिज निर्माण. (siding) उसके अन्त्यगत नहीं हं; और काई खान तभी चालू (in operation) असमा जायगी जब उसके व्यापार प्रार म (commencement of operation) का कोई नेटिस इन्डिन माइन्स पेक्ट, १६२३ की घारा १३ के अनुसार उस जिले कं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जिसमें यह खान स्थित है।, दे दिया गया है। आर । जनी समर्थ आ।धकारिक (competent authority) हा उस हे व्यापार बन्द करने की सूत्रना न दो गई हो।

- (१६) 'नियत' (proseribed) हा तात्पर्य इस पेक्ट के प्रवीन की नियती द्वारा नियत से हैं,
- (१७) 'विक्ता कृषि-वर्ष' (previous agricultural year) का तायय उस क्षाप-वर्ष से है, जा उस कृषि-वर्ष से ठीक पहले हो, जिसम स्वत्याधिकार का दिनांक पड़ता है।,
- (१प) 'सम्पत्ति' का मध्याय ४ मं तात्पर्या मास्थानों से भिन्न सम्पत्ति से है.
- (१६) 'रवामो' (proprictor) का तात्परं किसो मास्थान के सम्बन्ध में ऐस व्यक्ति से है, आ ग्यासी के रूप (in trust) में या अपने हो लाभ वे ग्लये किसी आस्थान में स्वामित्व रखता है।

ग्रौर 'स्वामी' के ग्रम्तर्गत स्वामी के दाय के उत्तराधिकारी (hoirs) श्रौर स्वत्व के उत्तरा-धिकारी (successors-in-interest) हैं;

- (२०) 'प्रान्तीय सरकार' (Provincial Government) का तालय' संयुक्त प्रान्त की सरकार से है;
- (२१) 'धर्मार्थ' (roligious purpose) के अन्तर्गत ऐसे सभी प्रयोजन हैं, जिनका सम्बंध धामक उपासना, शिक्षा या सेवा अथवा धार्मिक कृत्यों (religious rites) के सम्पादन से हो;
- (२२) 'पुनर्वासन मनुदान श्रधिकारी' (Rohabilitation Grants Officer) का ताल्पर्य धारा १६१ के प्रधीन नियुक्त पुनर्वासन ममुदान मधिकारी से है;
- (२३) 'गांव' (village) का ताल्ये ऐसे स्थानीय क्षेत्र से हे, जो, चाहे पकत्र (compact) हो या नहीं, तत्सम्बन्धी जिले के माल-ग्रिभिछेख (Rovenue Records) में गांव के रूप में ग्रिमिछिखित (recorded) हो ग्रीर उसके अन्तर्गत 'ऐसा क्षेत्र भी है जिसे प्रान्तीय सरकार गजट में प्रकाशित सामान्य या विशेष ग्राजा द्वागा गांव होना प्रख्यापित कर द,
- (२४) पेसे शब्दों और पदों (oxpressions) का, जिनकी परिभाषा इस पेक्ट में नहीं की गई है भीर जिनका प्रयोग यूनाइटेड प्राविसेज देनेन्सी पेक्ट, १६३९ ई॰ में किया गया है, वहीं मर्थ होगा जो उनकी उक पेक्ट में दिया गया है,
- (२५) पेस शब्दों श्रीर पदां का, जिनकी परि-भाषा इस पेक्ट में या यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी पेक्ट, १६३९ ई॰ में नहां की गई है श्रीर जिनका प्रयोग यूनाइटेड प्राविसेज लैंड रेवेन्यू पेक्ट, १६०१ ई० में किया गया है, वही शर्थ होगा, जो उनकी उक्त पेक्ट में दिया गया है।

सं॰ प्रा॰ पेक्ट १७, १६३६

सं० प्रा० चेषट १७, १६३६ सं० प्रा० चेषट सं० इ, १६०१

8--[*]

अध्याय २

मध्यवर्तियां के स्वत्वे। का इस्तगत किया

X--[*]

६—(१) इस ऐक्ट के पारम होने के बाद यथाशोध प्रान्तीय सरकार विकरित द्वारा प्रस्यापित (declare) कर सकेंगो कि निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक से संयुक्त प्रान्त में स्थित सब ग्रास्थान (estates) महामहिम के स्वत्वाधिकार में ग्रा जायेंगे (shall vest in His Majesty) ग्रीर इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक से [जिसे ग्रागो चलकर स्वत्वाधिकार का दिनांक (date of vesting) कहा जायगा] ऐसे सब ग्रास्थान सब भारों से मुक्त (free from all encumbrance) इस प्रान्त के प्रयोजनों के लिये महामहिम के। इस्तान्तरित (transfer) हो कर उनके स्वत्वाधिकार में उस दशा की छोड़ जिसकी आगे व्यवस्था को गई है ग्रा जायंगे।

(२) प्राक्तीय सरकार के लिए वैघ (lawful) होगा कि यदि वह आवश्यक सममे, तो उपधारा (१) में भ्रमिद्घ्ट (referred to) विक्रिप्त समय-समय पर केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जारो करे जी निद्धि हिए जायं और उपधारा (१) के सब निदेश (provisions) ऐसी प्रत्येक विक्रिप्त पर और उसके विषय में लागु होंगे।

७—धारा [*] ६ में अभिदिष्ट विज्ञति गजट में भौर ऐसे भन्य प्रकार से प्रकाशित की जायंगी जो नियत किया जाय.

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गजट में विज्ञप्ति का हिन्दी में प्रकाशन इस बात का निश्चायक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि उसका यथावत् (due) प्रकाशन हो गया है।

[क्षे] निकाल दिया गया।

ग्रास्थानें का महा-महिम के स्वन्वा-चिकार में ग्राना

विज्ञप्ति का गज़ट में प्रकाशित किया ग्रास्थान के महामहिम के स्वत्वाधिकार में जाने कं परिग्णाम ८—जब किसी क्षेत्र के विषय में घारा ६ के अनुसार विज्ञास गजट में प्रकाशित हो जाय तब किसी संविदा (contract), लेख्य (document) या उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि (any other law for the time being in force) में किसी बात के रहते हुये भी, आर इस पेकृ में किमी भिन्न व्यवस्था के न होने पर (save as otherwise provided in this Act) स्वत्या- चिकार के दिनांक के प्रारम्भ से पेन क्षेत्र में धारो लिखे परिणाम उत्पन्न होंगे:—

(क) ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि योग्य या ऊसर भूमि, वाग-भूमि, गांव की सीमा भी के भीतर भीर बाहर के जंगलों, (गाव की याबादी), खाता (holdings) या बागा के पेड़ें। की छोड़ ग्रम्य पेडां, मीनाशयां (fishories) तथा (खातों, बाग अथवा ग्राबादी के निजी कुमों का छोड), रूच कुछो, तालाबों, पोखरों, जल-प्रमा-लियां (water channels), नाय-बाटों (forrios), रास्तों, मायादी के स्थलों (abadi sibes), गादें। [*]बाजारें। ग्रीर मेलें सहित प्रत्येक ग्राम्यान में, तथा चलती हुई या न चलती हुई खानें और खनिज-पटार्थी (mines and minorals) में यदि कोई पधिकार हैं।, तो उनके सहित और भूमि के नीचे के (in subsoil), मध्यवर्तिया के सब प्रधिकार, ग्रागम भीर स्वत्व समान्त होकर सब भारों से मुक, प्रान्त के प्रयोजना के लिए, महामहिम (His Majosty) के स्वत्वाधिकार में या जायंगे;

(ख) इस प्रकार हस्तगत किए गए ग्रास्थान को भूमि का तथा ऐसी भूमि या उसकी मालगुजारों से सम्बन्ध रखने वाले मधिकारों और विशेषात्रिकागें का प्रत्येक यनुदान और पागम का पुष्टिकरण, चाहे वह वापस लिया जा सकता है। या नहीं, समान्त हो जायंगे,

क्षिश्री निकाल टिया गया।

(ग) किसी चास्थान या उसमें स्थित खाते की भूमि से सम्बन्धित ऐसे सभी लगान, भववाब (cess) स्थानिक कर (Local rates) ग्रीर सायर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक के बाद के हों और जी ग्रास्थान न हस्तगत किये जाने की दशा में मध्यवर्ती का हेय (payable) हाते, पान्तीय सरकार के स्वत्वाधिकार में या जायंगे और उसका देय होंगे, न कि मध्यवर्ती का, ग्रौर यदि इस खंड के निदेश के विपरीत कुछ दिया जाय, ता देने वाला अपने दायित्व से वैध रूप से मक्त न होगाः

(घ) इस प्रकार हस्तगत किये गये ग्रास्थान से सम्बन्धित ऐसी सभी मालगुजारी (13venue), प्रववाब (cesses) या अन्य देयां (dues) की सब बकाया (arrears) जी मध्यवर्ती से स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के किसी समय के लिए प्राप्य (due) है।, पेसे मध्यवर्ती से वसुल की जाने येग्य रहेगी ग्रीर वसली के ग्रन्य ढङ्ग को वाधित न करते हुए (without prejudice to any other mode of recovery), ऐसे मध्यवतीं की, अध्याय ३ के अनुसार मिलने वाले प्रतिकर (compensation) की, धनराशि से काटकर वसल को जा सकेगी;

(ङ) किसी ग्रास्थान में इस पकार इस्तगत किया गया मध्यवर्ती का स्वत्व किसी दीवानी या माल (civil or revenue) न्यायालय को किसी डिको या अन्य प्रसर (process) के निष्पादन (execution) में कुर्क या नोलाम नहीं हो सकेगा ग्रौर स्वत्वाधिकार के दिनांक पर वर्तमान (existing) प्रत्येक कुकी ग्रीर उस दिनांक से पहले दी गई कुर्की को बाज्ञा, ट्रांसफर आफ पापर्टी पेकेंट, १८८२ की घारा ७३ के निदेशों visions) का वाधित न करते हुए, निष्प्रभाव हो जायगो (shall cease to have force);

ऐक्ट ४. 2553

- (च) (१) ऐसा प्रत्येक भोगबन्धक (mortgage with possession) जो स्वत्याः विकार के दिनांक से ठी क पहले के दिनांक पर किसी धास्थान या किसी धास्थान या किसी धास्थान के किसी भाग (part share) पर हो, धारा ६ के अधीन प्रान्तीय सरकार के अविकारों की घाधित न करते हुए उस धनराशि के लिए, जो ऐसे धास्थान या उसके भाग पर सुराक्षत हो, दृष्टिवन्यक (simple mortgage) में परिवर्तित (substituted) समभा जायगा,
- (२) बन्धक-पत्र (mortgage deed) या किसी दूसरे इकराग्नामे (agreement) में किसी यात के रहते हुए भी उपखरह (१) के अनुसार परिवर्तित हिष्टबन्धक के सम्बन्ध में प्रख्यापित धनगशि पर व्याज ऐसी दर से और ऐसे दिनांक से चलेगा जी नियत किए जाए;
- (क्) किसी पेसे रुपये के लिए, जो किसी पेस आरथान या उनके भाग के बम्धक से सु। क्षित (secured) ही या उस पर भार-रूप (charged) हो, काई दावा (claim) जो स्वत्वाविकार के दिनांक से पहले मध्यवर्ती के विरुद्ध किया जा सकता हो या दायित्व जो उसने स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले पहले उपगत (inourred) किया हो, द्राम्सफर ग्राफ प्रापटी पेक्ट, १८८२ को धारा ७३ में दो हुई रीति से भिन्न किसो रीति से, ग्रास्थान में उसके स्वत्व के विरुद्ध स्ववहार में नहीं खाया जा सकेगा (shall not be onforceable);
- (ज) नियत किये जाने बाले प्रकार के पेंस सब याद (suits) और व्यवहार (proceedings), जो किसो व्यायालय में स्वत्वाधिकार के दिनांक पर विचाराधीन (pending) हो और स्वत्वाधिकार के दिनांक न पूर्व पेंस किसी बाद या व्यवहार में हुई हिकी या फाजा

धेकट ४,

से सम्बन्ध रखने वाली सब कार्यवाहियां स्थागत कर दी जायंगी (shall be stayed)।

(भ) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर विद्यमान सभी महाल और उनके उपविभाग तथा किसी स्वामी, मातहत-दार, ग्रदना मालिक, हिस्सेदार या लम्बरदार द्वारा मालगुजारी के देन के सम्बन्ध में किये गये सभा ग्रनुबन्ध (engagement) समाप्त और निष्प्रभाव हो जायेंगे।

६--इस ग्रध्याय में कही गई किसी बात का प्रमाव किसो व्यक्ति के निम्निळिबित ग्रधिकारें। पर नहीं होगां—

(क) इस पेक्ट के पूर्वोक्त निदेशों के अनु-सार इस्तगत किये गये किसी आस्थान के अंतर्गत किसी खान के। चलाते रहने का अधिकार, जी समय विशेष पर प्रचलित (for the time being in force) विवि (law) द्वारा नियमित है।गा (shall be governed);

(ख) स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले के लगान, ग्रववाब (cess), सायर या [%] ग्रन्य देयां को बकाया (arrears) की वस्तां का श्रधिकार इस ऐक्ट में किसी बात के रहते हुए भी, वे पहले की तरह ऐसे व्यक्ति द्वारा वस्तुल किये जा सकेंगे जिसे उन्हें वस्तुल करने का ग्रधिकार पाप्त हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लगान की बक़ाया की कोई डिकी या लगान की बकाया न देने के कारण बेदखळी की प्राज्ञा किसी खाते से बाद ऋणी (judgment-debtor) की बेदखली द्वारा निष्पादित (executed) नहीं की जायगी;

श्रीर यह भी प्रतिबन्ध है कि जिस मध्यवतीं का ऐसे श्रास्थान में स्वत्व, जिसके विषय में बकाया देय है, इस ऐक्ट के निदेशों के ग्रधीन इस्तगत कर लिया गया है।, उसके द्वारा देय कुछ ग्रधिकारों के सम्बन्ध में अपवाद लगान, श्रववाब, स्थानिक कर (local rate) सायर या पूर्वा क्त श्रम्य देय उसे मिलने वाले प्रतिकर में से वस्त किये या खुकाये जा सकते हैं ग्रीर पाने वाले व्यक्ति कें। वसूली के दूसरे साधनें के ग्रतिरिक्त यह सायन भी प्राप्त रहेगा।

१०—(१) ऐसे ग्रास्थान में स्थित किसी निजी जंगल या मीनाशय के सम्बन्ध में जंगल से उपज या मीनाशय से मक्कों लेने के लिए मध्यवर्ती ग्रीर किसी ग्रम्य व्यक्ति में ८ ग्रगस्त, १६४६ ई० के बाद हुई प्रत्येक संविदा (contract) स्वत्वा विकार के दिनांक से व्यर्थ (void) हो जायगी।

(२) इस यध्याय में दो हुई किसी बात का प्रभाव ऐस व्यक्तिया के उपधारा (१) में उव्लिखित पकार की किसी ऐसी संविदा (contract) के शश्रीन प्राप्त अगिकारों पर न पड़ेगा जो द ग्रगस्त, १६४६ ई० की या उसके पूर्व हुई हो।

87--[器]

१२—किसी प्रास्थान में स्थित ऐस राज निजा कुएं, जो खातों, बाग प्रथवा प्राबादों में हीं। या प्रावादों के पेड़ ग्रीर सब इमाग्तें, जो किसी मध्यवर्ती या काइन हार या दूसरे व्यक्ति की हैं या उसके उपभोग में हीं, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता है।, मध्यवती , काशतकार या ग्रन्थ व्यक्ति के, जैसी भी दशा हो, बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे ग्रीर सम्बद्ध (appurtenant) क्षेत्र सहित उन कुगों या इमारतों के स्थल (sites) के विषय में यह समभा जायगा कि उनका बम्होबस्त प्राम्तीय सरकार ने उसके साथ पेसे प्रतिबम्धों ग्रीर शतों पर किया है, जो नियत की जायं।

१२— पेसी भूमि का प्रत्येक काश्तकार जी पेसे मध्ययती की सीर श्रमिलिखित है। जिस पर स्वत्वाधिकार के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक

द ग्रगस्त, १६४६ ई० से पहिले की संविदायों का स्व-वाधिकार के दिनांक से व्यथं है।ना

८ ऋगस्त, १६४६ ई० को या पहले हुए संविदा पर प्रभाव न पड़ना

निजी कुर्ो, पांबादी के पेड़ी श्रीर इमारती का बंदीबस्त वर्तमान स्वामियी के साथ होना

सीर के काश्तकार

^[*] निकाल दिया गया '

पर संयुक्त प्रान्त में २५० ह० से अधिक वार्षिक मालगुजारो लगी हो और यद मालगुजारो नहीं लगी है तो इतना स्थानिक कर (local rate) लगा हो जो २५० ह० की वार्षिक मालगुजारों पर देय हैं।, उस भूमि का मौरूसी काशतकार सममा जायगा और उसके लगान की दर वही समभी जायगी जो उक्त दिनांक पर उसके द्यारा देय हो और घारा १६ के प्रयोजनों के लिये ऐसी भूमि सोर नहों मानी जायगी।

१४—यदि किसी व्यक्ति ने अपनी सीर या खुदकाश्त किसी दूसरे व्यक्ति की मरण-पोषण (maintenance) के लिये दे टी हो 'तो ऐसा दूसरा व्यक्ति [%] घारा १३ में किसी बात के होते हुए भी उस भूमि का असामी समभा जायगा और उसकी वह भूमि उस अविध तक रखने का अधिकार रहेगा जब तक उसकी मरण-पोषण पाने का अधिकार रहे।

१४ क—(१) यदि कोई भूमि स्वत्वधिकार के दिनांक के ठीक पहिले के दिनांक पर ठेकेदार की निजी जोत में रही हा और यह सिख हो कि ठेका इस हिंद से दिया गेंचा था कि ठेकेदार उस भूमि में स्वयं खेती करें, ता यू॰ पी॰ ठेनेन्सी ऐक्ट, १६३६ ई॰ में किसी बात के रहते हुए भी ठेकेदार उस भूमि का भूमि का मौहसी काश्तकार समभा जायगा और उसके लिये मौहसी देरें से लगान का देनदार होगा।

(२) उक्त भूमि का ठेके के प्रारम्भ से ठेकेदार की निजी जीत में रहना, इंडियन एविडेन्स ऐक्ट, १८७२ ई॰ की घाराय ६१ और ६२ में किसी बात के रहते हुए भी इस बात के प्रमाण में प्राह्म होगा कि ठेकां उपघारा (१) में ग्रामिद्घ प्रकार काथा।

भएण-पोषण के लिये दी गई सीर या खुदकाश्त

ठेकेदार का कुछ यव-स्थायों में मौहसी कारतकार समभा जाना ठेकेदार के कब्जे का ग्रास्थान

- १४—(१) उपधारा (२) के निदेशों की बाधित न करते हुए (subject to), किमी आस्थान या उसके अश के ठेकेदार की स्वत्वाधिकार के दिनांक से ऐसे आस्थान की किसी भृमि की ठेकेदार के रूप में अपने पास या कब्जे में रखने का अधिकार न रह जाएगा।
- (२) जहां ऐसी कोई भूमि स्वःवाधिकार के दिनांफ से ठोक पहले के दिनांक पर ठेकेंद्रार की निजी जोत में गही हो, वहां—
 - (क) यदि वह ठेका दिये जाने के दिनांक पर ठेका देने वाले की सीर या खुदकारत थी, तो घारा १९ के प्रयोजनों के लिये स्वत्वाधिकार के दिनांक में ठीक पहिले के दिनांक पर गह ठेका देने वाल की सीर या खुदकारत सममी जायगी तथा स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठेकेदार उमका प्रमामी हो जायगा श्रीर स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठेकेदार उमका प्रमामी हो जायगा श्रीर स्वत्वाधिकार के दिनांक पर लागु मौकमो दों से लगान का देनदार होगा पवं भूमि पर, ठेके की शेष ध्यवित्व (unexpired period) या स्वत्वाधिकार के दिनांक में पांच वर्ष, दोनों में में जो कम हो उस प्रवित्व के लिये उसी क्ष्य में काबिज रहने का श्रीधकारों होगा,
 - (ख) यदि वह ठेका देने के दिनोक पर ठेका देने वाळे की सोर या खुदकारत नहीं थी, भीर
 - (१) उसका क्षेत्रफल तोस पकड़ से प्रधिक नहीं है तो, घारा २० के प्रयोजनों के लिये यह समभा आयगा कि ठेकेदार उस पर मौक्सो कारतकार के इप में ऐसे लगान पर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर लागू मौक्सी दरों सं लगाये गये लगान के बराबर है।, का बिज रहा है,

(२) उसका क्षेत्रफल तीस एकड़ से ग्रिंघक है, तो यह समभा जायगा कि उसमें से तीस एकड़ पर वह उक्त घारा के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के रूप में काबिज रहा है ग्रीर शेष खाली भूमि समभी जायगा तथा ठेकेंद्रार घारा २०६ के निदेशों के ग्रनु-सार उससे बेदखल है। सकेगा:

[*]

(३) उपधारा (२) के वएड (क) और (ख) में दिए निरोधों (restriction) के रहते हुए भी, यदि कलेक्टर कें। ठेकेदार का प्रार्थना पर और ऐसी जांच के बाद, जो नियत को जाय, सन्तोष हो जाय कि ऐमा करना किसी वर्तमान कृषि फार्म के सुचाह और सफल (efficient and successful) संचालन (wor King) के लिये आवश्यक है, तो वह ठेकेदार कें।, भूमि रखने की आज्ञा दे सकता है:—

(क) यदि वह उपघारा (२) (क) में ग्राने वालो भूमि हो ते। ५ वर्ष से ग्राधक ग्रवधि के लिए ग्रीर

(ख) यदि वह उक्त उपघारा के खंड(ख) में ग्राने वाली भूमि है। ते। ३० एकड़ से अधिक रखने के लिये।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेकेदार इस प्रकार

अनुज्ञात भूमि ठेके की अवधि के बाद रखने का

अधिकारी न होगा और उस अतिरिक्त भूमि का
जो उस खरड (ख) के अधीन ३० एकड़ से ऊपर

मिली हो, वह गांव-सभा को और से असामी होगा

और उसके निमित्त उस लगान का देनदार होगा

जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठोक पहिले के

दिनांक पर लागु मौक्सी दर के अनुसार हो।

^[🕸] निकाल दिया गया।

भोगबन्धकों के कब्जे का श्रास्थान

- १६—(१) उपनारा (२) के निदेशों के। वाधित न बन्ते हुए किसी ग्रास्थान या उसके ग्रंश (share) के किसी भागवन्थकी (mortgagee with possession) को स्वत्वाधिकार के दिनांक से यह ग्रधिकार न रह जायगा कि वह उस श्रास्थान की किसी भूमि के। भोगवन्थकी के नाते से ग्रपने पास या कब्जे में रख सके।
- (२) जहा ऐसी कीई भूमि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर बन्यका (mortgagee) के निज जीत में रही हैं।, वहां--
 - (क) यदि वह भूमि बन्धक (mortgage) के दिनांक पर बन्धककर्ता की सीर या खुदकारत रही है तो धारा १६ के प्रयोजना के लिए यह समभा जायगा कि वह बन्धक-कर्ता या उभके विधिक प्रतिनिधि (logal-roprosontativo) की मीर या खुदकारत है, श्रोर
 - (ख) यदि बन्धक के दिनांक पा वह वन्यककर्ता (mortgagor) को सोर या खुदकाइत नहीं थी ते। बन्धकी द्वारा अगले छः माम के भीतर प्रान्तीय सरकार की पेसी धनराद्यि दं दिये जाने पर, जो स्वत्याधिकार के दिनांक पर लागू मोरूमी काइतकारों की दर से लगाये लगान का पांच गुना हो, धारा २० के प्रयोजनों के लिए यह समभा जायगा कि वह भूमि बन्धकों के पास पूर्वीक दिनांक पर ग्रीर उक्त दर के लगान पर मौरूसी काइतकार के नाते थी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि बन्धकों दिये गए समय के भीतर उपर्युक्त धनराशि न दे तो, ऐसी भूमि में उसके सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे; और यह भूमि खाळी भूमि समभी जायगी तथा बन्धकों धारा २०६ के अधीन गांव-सभा द्वारा यद प्रस्तुत किये जाने पर ऐसे बेदखल

है। सकेगा मानें वह उक्त भूमि पर इस ऐकट के निदेशों के प्रतिकूछ काविज रहा हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के छिए भागवन्यकी के अन्तर्गत उसके भागवन्यक सम्बन्धी अधिकारों का ठेकेदार भी होगा।

१७—(१) यदि स्वत्वाविकार के दिनांक से ठोक पहिले के दिनांक पर किसी पेसे आस्थान या आस्थानों में जो मध्यवर्ती और अन्य व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व में हों, ठेकेदार से मिन्न मध्यवर्ती के पास कोई भूमि उसके आनुपातिक यंश से अधिक निज जोत में अथवा सौर, खुदकारत या मध्यवर्ती के बाग के रूप में रही हो, तो यथाशों च नियत अधिकारिक (prescribed authority) ऐसे मध्यवर्ती के ग्रंश के अनुपात में भूमि का परिच्छेद कर देगा।

संयुक्त ग्रास्थानां में सीर खुदकाश्त श्रादि का परिच्छेट

- (२) (क)—धारा १६ के प्रयोजनों के लिए केवल उतनी भूमि, जिसका इस प्रकार परिच्छेद किया जाय, उसकी सीर, खुदकाइत या मध्यवर्ती का बाग समभी जायगी, और
- (ख) वह भूमि, जो उसके पास उसके गंश से अधिक हो, धारा २० के प्रयोजनों के लिए उसके पास साकितुल मिल्कियत काइतकार (exproprietary tenant) की भूमि के रूप में सममी जायगी और उसे स्वत्वाधिकार के दिनांक पर लागु साफ़ितुल मिल्कियत काइतका में के दर से लगान देना होगा।

१८—ऐसा पत्येक व्यक्ति, जिसका नाम ऐसी
भूमि के सम्बन्ध में (जो उस भूमि से मिन्न हो जो
धारा १३ में अभिदिष्ट मध्यवर्ती के प्रतिरिक्त किसी
मध्यवर्ती की सीर या खुदकाइत अभिछिखित हो
या जो बाग भूमि प्रथवा धारा २० के खंड (१) से
(७) तक में डिल्लिखित व्यक्ति या शरह मीग्रह्यन
कारतकार या माफीदार के खाते के यन्तर्गत भूमि

पेसी भूमि के काबिज का मौक्सी कारत-कार होना जिसमें प्रवर अधिकार न हों अभिलिखित हो) [अ] ऐसे अभिलेख (record) में, जो। यूनाइटेड प्राविसेज़ छैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरोक्षित (revised) किया गया हो या ऐसे ऋघिकारी द्वारा संशोधि त किया गया हो जिसे किसी क्षेत्र में वार्षिक रिजिएटरें। के संशोधन के लिये प्रांतीय सरकार ने विशेष रूप से नियुक्त किया है।, काविज के क्ष मं दर्ज है। अरीर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उस मुमि पर काविज था या जिसे युनाइटेड प्राधिनसेज टेनेन्सी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की घारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) [clause (c)] के बनुसार कब्ज़ा वापस पाने का ब्रधिकार हो। ऐसा मी इसी का स्तकार समभा जायगा जो उक्त दिनांक पर ऐसे काइतकारों पर लागु दर से लगान का देनदार था।

सं० प्रा॰ ऐक्ट ३. 8038

ं० प्राप एंक्ट १०, १६४७

सीर की जमीन जो कारतकार के ग्रधि-कार में पट्टा दवामी या इस्तमरारी रूप में हो।

सीर, खुदकाश्त या

मध्यवती के बाग का उसके मध्यवती

साथ भूमिधर के रूप

में बन्दाबस्त किया

जाना

१८—(क) पेसी भूमि जे। स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी मध्यवतीं को सीर थी किन्तु उक्त दिनांक पर पट्टा दवामी या इस्तमरारी पर किसी कारतकार के पास थी, धारा १६ के प्रयोजनों के लिए ऐसे मध्यवर्ती की सोर न समभी जायगी पर वहां धारा १३ और १७ के प्रयोजनों के लिए उसकी सोर समभी जायगा।

१६--(१) घारा १३, १७, १८ ग्रौर १८ (क) के निदेशों के। बाधित न करते हुए ऐसी सब भूमि जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर

क) किसी मध्यवती के पास या काने मं सीर, खुदकारत या मध्यवती के वाग के रूप में हो, या समभी जाती हो,

(ख) जो अवध में स्थायी पर्टेदार के

पास बाग के रूप में या निज जोत में है।,

[*] निकाल दिया गया।

(ग) जो शरह मुबद्यन काश्तकार के पास शरह सुग्रइयन काश्तकार के नाते ग्रीर माफी-दार के पास माफीदार के नाते हैं।, ता

यह समभा जायगा कि प्रान्तीय मरकार द्वारा ऐसे मध्यवर्ती या पर्टेटार के साथ उसका बन्दो। बस्त कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति के। अधि-कार होगा कि वह उस भूमि के। इस ऐक्ट के निदेशों का बाधित न करते हुए भूमिधर के नाते श्रपने कब्जे में छे छे या रखे।

(२) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के विषय में जो संयुक्त प्रान्तीय कारतकार विशेषाधिकार उपार्ज न विधान, १६४६ ई० की धारा ३ में उल्लिखित वर्ग का है। ग्रीर जिसे किसी खाते या उसके किसी ग्रंश के सम्बन्ध में उक्त विधान की धारा ६ में ग्रिभिटिड्ट प्रख्यापन पदान कर दिया गया है, उक्त प्रख्यापन के बाद में निरस्त न होने की दशा में यह समभा भ जायगा कि वह उस खाते या उसके उस ग्रंश का भूमिघर है जिसके सम्बन्ध में प्रख्यापन दिया गया है ग्रोर सप्रभाव है।

२०--ऐसी सब भूमि के विषय में, जो स्वत्वा- खाते की भूमि का धिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास नीचे लिखे रूप में हो या रही समभी जाय, यह समभा जायगा कि उसका बन्दोबस्त प्रान्तीय सरकार ने उस व्यक्ति के साथ कर दिया है और इस ऐक्ट के निदेशों की बाधित न करते हुये, केवल उम दशायों की छोड, जिनकी कि धारा १६ को उपधारा (२) में व्यवस्था की गई है, उस व्यक्ति की अधिकार होगा कि सीरदार के रूप में वह भूमि अपने कब्जे में छे ले या रखे--

(१) [*]

[*] निकाल दिया गया।

उसके कारतेकार के साथ सीरदार के इप में बन्दाबस्त है।ना

- (२) सवध में विशेष शतीं वाला काहत-कार (tenant holding on special terms in Avadh),
- (३) सािकृतुल मिक्कियत कारतकार (ex-proprietary tenant),
- (৪) ব্জান্তকাৰ কাংলকাৰ (occupancy tenant),
- (४) मौरूसी काइतकार (heroditary tenant),
 - (६) [*]
- (৬) কাহনকান বিযায়নী লগান (grantee at favourable rate of rent), সখবা
 - (द) बाग्दार (grove-holder)।
 - (६) केाई व्यक्ति जिसके पास घारा १८-क में श्रीभदिष्ट भूमि पटा द्वामी या इस्तमरारो पर है।

मीर के काश्तकारी शिकमी या काविज का पश्चिवासी होना

- २१--ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक सं ठीक पहिले के दिनांक पर इस ऐक्ट के निदेशों के ग्रनुसार निम्नलिखित था या समभा गया हो, ग्रथीत्-
- (क) सींग का ऐसा काइतकार, जो उस काइतकार से भिन्न हो, जिसका उच्छेष धारा २० (९) में है या जिसके पक्ष में धारा १३ के निदेशों के अनुसार मौरूसी प्रधिकार उत्पन्न होते हो,
- (ख) बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि का पेसा शिकमी काइतकार (sub-tenant), जो यूनाइटेड प्राविन्सेज़ टेनेन्सी समेंडमेंट पेक्ट, १६४७ की घारा २० की उपधारा (३) सं सम्बद्ध प्रति-बन्ध में समिदिष्ट शिकमी काइतकार से भिन्न हो, या
- (ग) पेसा व्यक्ति, जिसका नाम पेसी किसी
 भूमि पर (उस भूमि को छोड़ जिस पर धारा
 १८ के निदंश लागु होते हैं। काबिज़ के
 कप में [*] पेसे अभिछेख में दर्ज हैं।, जो

^[*] निकाल दिया गया।

सं० प्रा० ऐक्ट सं० ३,१६०१

सं॰ प्रा॰ ऐक्ट १०, १६४७ यूनाइटेड प्राविसेज लैंड रेवेन्यू ऐस्ट, १६०१ के अध्याय ४ के अनुसार पुनरीक्षित (revised) या ऐसे अधिकारी द्वारा संशोधित किया गया हो, जिसे प्रान्तीय सरकार ने किसी क्षेत्र (tract) में वापि क रजिस्टरों के संशोधन के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया हो, जौर जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठोक पहिले के दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो या उसको ऐसी भूमि पर कब्जा वापस पाने का यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी (प्रमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, १६४० को धारा २७ को उपधारा (१) के सम (सी) [clause (o)] के अनुसार अधिकार रहा हो,

जब तक कि वह घारा १६ को उपधारा (२)
में उल्झिखित जमीन का भूमिधर न बन गया हो,
उक्त भूमि का अधिवासी कह्छायेगा और
इस ऐक्ट के निदेशों की बाधित न करते हुए, उस
उस भूमि पर कृष्ता छेने या रखने का अधिकार
हे।गा।

२२—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास या दखल में स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर कीई भूमि निम्नलिखित के नाते रही हो, इस ऐक्ट में किसी बात के रखते हुए भी, उस भूमि का बसामी समभा जायगा—

- (क) किसा मध्यवती की बाग-भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant),
- (ख) बाग-भूमि का शिकमी काश्तकार (sub-tenant),

(ख ख) यूनाः देड प्राविन्मेज देनेंसी [अमेंडमेंट] ऐक्ट, १६४७ की धारा २७ की उपधारा (३) से सम्बद्ध प्रतिबन्ध में ग्रमिद्बट शिकमो काश्तकार,

(ग) <u>घारा १६ को उपधारा (१) के खंड</u> (स) ग्रीर (ग), तथा घारा २० के खंड (२)

गैर दखोलकार कारत-कारों, बाग-भूमि के शिकमियों ग्रीर कारत-कारों के बंधकियों का ग्रसामी है।ना

- से (१) तक में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग के व्यक्ति का वन्धको (mort-gagee),
- (श) पेंडुचर भूमि का या ऐसी भूमि का, 'जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा और किसो दुसरी उपज पैदा करने के काम में आती हो अथवा ऐसी भूमि का, जो नदी के तल (bed of a river) में हो और कमी-कमी खेती के काम में आती हो, गैरदखील-कार काइतकार,
- (ड) पेसी भूमि का गैरदखीलकार कारत-कार, जिसके जिषय में प्राम्तीय सरकार ने गजट में विज्ञान्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया है। कि उसमें टैंगिया रोति से बन लगाने का बिचार है या यह उसके लिये अलग कर दी गई है, या
- (च) पेसी भूमि का काश्तकार, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञिति द्वारा प्रस्थापित कर दिया है। कि वह अस्थायी या अस्थिर (shifting or unstable) खेती के क्षेत्र का भाग है।

स्पष्टाकरण—"टैांगिया रोति से बन लगाने" का तात्पर्य बन लगाने को उस रीति (system of afforestation) से हैं, जिसमें प्रारम्भिक मवस्था में पेड़ों के लगाने के साथ—साथ खेती की फसलें भो बोई जाती हैं भौर जिसमें फसलें का बोना उस समय बन्द हो जाता है जब इस प्रकार लगाये गये पेड़ पेसी छत्ररी के रूप में हो जाय! जिससे खेती की फसलें का बोना ग्रसम्भव है। जाय।

१ जुलाई, १६४८ का या उसके बाद हुप लगान-परिवर्तन का न माना जाना २३—यद्यपि इस पेक्ट के अधीन हस्तगत किये गए आस्थान के अन्तर्गत किसी भूमि कं सम्बन्ध में १ जुलाई, १६८८ ई॰ की या उसके बाद किसी मध्यवर्ती या किसी काइतकार द्वारा या उसकी बोर से कोई संविदा (contract) को गई हो या केई बात की गई या है।ने दो गई है।, तब भी उस भूमि के सम्बन्ध में स्वत्या-धिकार के दिनाक से ठोक पहिले के दिनांक पर काहतकार द्वारा देय लगान उस लगान के बराबर समभा जाग्गा जिपका यह काहतकार या उसका पूर्वाधिकारी (predecessor-in-bible) देनदार रहा है। गौर यदि उक्त दिनाक के बाद किसी स्यायालय की हिकी या भाजा के भितरिक किसी शौर प्रकार से कोई कमी है। या छूट मिले, ता उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त डिकां या प्राज्ञा के कनुसार कम ित्या हुआ लगान जो उपयुक्त सर्किछरेट के प्रनुसार लगाये गए लगान से कम हो ते। इस प्रकार लगाया गया लगान हो देय लगान होगा।

२४—(१) किसी बिधि (law) में किसी वात के रहते हुए भी किसी आस्थान या उसके भाग का ऐसा हस्तान्तरण, चाहे वह विकय (salo) दारा हुआ हो या दान (gift) द्वारा—

(क) जो १ जुलाई, १६४८ ई॰ को या उसके बाद हुआ हो, मध्यवतीं को देथ पुनर्वासन धनुदान को मात्रा निर्धारित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

(स) जो ७ जुलाई, १६४६ ई० के बाद हुमा हो, किसी भो प्रशेजन के लिए आन्य नहीं होगा और उस मास्थान के विषय में यह सममा जायगा कि उसका स्वत्व हस्तान्तरण-कर्ता के अधिकार में ही स्थित है।

(२) उपवारा (१) में फही गई काई बात किसी ऐग विक्रय पर छागू नहीं होगो :

(क) जो रुपया दिये जाने की किसी दिकी या भादा के निष्पादन में किसी न्यायालय की याद्वा के सधीन हुमा हो,या

(ज) जो किसी केंग्रल पुरायार्थ स्थापित, वस्फ, न्यास (trust) निषम्ध (पंजास-

विकय या दान द्वारा हस्तांतरण का,मान्य न होना मेंट) या संस्था के लिए किया गया हो; जब तक कि प्रान्तीय सरकार किसी विशेष दशा में इसके विपरीत आदेश न है।

स्पष्टीकरण-उपधारा (२) के प्रयोजनें के लिए संस्था का बही यथ है जो सोसाइटीज रिज-स्ट्रेशन ऐयट, १८६० के यधीन निवन्धित हुई (registered) "सोसाइटी" का है।

इस ऐक्ट के निदेशों को विफल करने वाले संविदा और इकरार-नामी का व्यर्थ होना

२४—ऐसी अत्येक संजिद्धा (contract) या इक्तरारतामा (agreement) जो १ जुलाई, १६६८ ई॰ की या उसके बाद किसी मध्यवर्ती और दूसरे व्यक्ति के योच हुआ है। और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित हैं।, व्यर्थ और विफल (null and void) होगा और इस धारा द्वारा व्यथ और विफल प्रश्वापित (declared) किया जाना है:—

- (क) सीरदार को उसके खाते के अन्तर्गत किसी भूमि की मालगुजारी (land revenue) के दायित्व से पूर्णतः या अंशतः मुक्त करना, या
- (ख) किनी मध्यक्ती की पुनर्वासन-प्रमुदान (rehabilitation grant) के निमित्त के हि देसी वनराशि पाने का अधिकार देना जो उक्त संविदा या इकरारनामा के न होने पर इस पेक्ट के अनुसार उस मिलने वाला धन-राशि से प्रधिक है।।

कलेक्टर द्वारा गा-स्थानें का ग्रवधान में ले लिया जाना २६ - भारा ६ के अधीन विज्ञान्त प्रकाशित होने पर, के कटर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी प्रधिकारी के लिये यह वैध (lawful) होगा कि वह

(क) कोई शास्थान या शास्थानों के मांग तथा सभी पेसे स्वत्य (interests) अपने सय-यान (charge) में छे छे जो इस अध्याय के निदेशों के श्रमुसार महामोहम के स्वत्याधिकार में या गये हों शौर पेसे कार्य करे या कराय भीर पेसा बल प्रयोग करे या कराये जो कछे-

नियम बनाने का

ग्रधिकार

कटर या उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी के मतानुसार इस प्रयोजन के लिये आयश्यक है।,

- (ख) इस अध्याय के निदेशों के अनुसार इस्तगत किये गए ग्रास्थान के ग्रन्तर्गत किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश कर, [*] ग्रीर उसका पर्यालोकन (survey) या पैमायश (measurement) करे या कोई दूसरा ऐसा कार्य करे, जी उसके विचार से इस पेक्ट के प्रयोजनों की कार्या-स्वित करते के लिये आवश्यक हो।
- (ग) किसी व्यक्ति का किसी ग्रास्थान या उसके भाग से सम्बद्ध (relating to) वही (books), हिसाब (accounts) या अन्य छेख्य (documents) निर्दिष्ट (specified) अधिकारी के सामने प्रस्तुत करने की और देस यधिकारों के। ऐसी यौर सूचना, जो निर्दिष्ट की जाय या मांगी जाय, देने की श्राज्ञा दे, ग्रौर
- (घ) यदि बही, हिसाब भीर भ्रन्य लेख्य याज्ञा के अनुसार प्रस्तुत न किये जायं तो किसी भूमि, इमारत या दूसरे स्थान में प्रवेश करे और ऐसी वही, हिसाब तथा दूसरे छेख्य लेकर अपने कब्जे में कर ले।

२७-(१) बान्तीय सरकार इस ग्रध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के छिये नियम बना सकती है।

(२) पूर्वेशक अधिकारों की न्याति को वाधित न करते हुए (without projudice to the generality of the foregoing powers), ऐसे नियम निम्निखिबित वातें की व्यवस्था कर सकते हैं:-

(क)[*]

(ख) घारा ६ के अधीन आस्थानें के (proceedings).

स्वत्वाधिकार में ग्राने के पूर्व की कार्यवाहियां

^[*] निकाल दिया गया।

- (ग) इस प्रध्याय के अधीन रथित किये हत वादों और व्यवहारी का निस्तारण (disposal of suits and proceedings),
- (भ) नार। २६ के मधीन अस्तानां के प्रतिया में लिये जाने म सम्बन्ध रखने बाले ांच चरा.
- (ङ) पेसे विषय जी मियत किये जाने वाल हों भीर नियत किये चायं।

ख्रधाय है

प्रतिकर का निर्धारण

ग्रास्थान ह₹तगत किये जाने के लिये मध्यवर्ती का प्रतिकर

पाने का ग्रधिकारी होना

प्रतिकर देय है।ने का ।टिक

२८-प्रत्येक मध्यप्ती, जिल्ला िसी श्रान्थान में ध्रिष्टार (right), भ्रापम (title) या स्वत्व (interest) इस पेक्ट के निदेशों के अधा । ह लगत कर लिया जाय, प्रागे की गर्न व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर पाने का अधिकारी होता और उसके। प्रतिकर दिया जायेगा।

- २९.-(१) इस पेकट के अधीन ग्रास्थान तरत-गत किये जाने के निमित्त दिशा जाने वाला प्रति कर स्वत्वाधिकार के दिनांक से देव हैं। जायगा, किन्त ह बात उसकी मात्रा के अववारण पर उपाश्रित रहेगी।
- (२) इस प्रकार अवधारित मात्रा पर प्रान्तीय मग्कार स्वव्वाजिकार के दिनां ह न अवनारण के दिनांक (date of determination) नक २ १/२ प्रतिशत ज्याज देगी।

मन्तारम प्रतिकः

३०--(१) प्रान्तीय सरकार ऐसी मात्रा में भौर पेसी रीति से, जो नियत की आय, अन्तरिन (interim) प्रतिकर देने का निर्देश कर सकतो है।

किन्तु प्रनिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से नी मास के भीतर मध्यवतीं को देग प्रतिकर इस पेक्ट के निदेशों के प्रनुसार

अवधानित न हिया न या, तो मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रान्तीय सरकार की उसे ऐसा यन्तिसम प्रतिकर निधे जाने का निर्देश करना देगगा।

(२) यदि कि नी मां थानं या उसके भाग में किसी मध्ययती के मधि हार, मागम और स्वत्व के वियय में कार्इ वर्गत दिवाद करता हो (disputes) तो, ऐस माहजान या भाग के सम्बन्ध में दिया जाने वाल। अन्तरिम प्रतिकर ऐसी रोति के, ऐसे ब्रिक्त की और ऐसे प्रतिबन्धों और निरोधों (restrictions) के अजीज, जो जमानत, वापसो या दूसरी बातों के िषय में नियत किये जामं, निया जायेगा।

३१—धारा ३० के ग्रधीन दिया गया अन्त-रिम प्रतिकर इस पेक्ट के अधीन देय प्रतिकर का भाग समभा जायना प्रीर इसी में से काट कर संघानित (Adjusted) कर दिया जायगा।

३२—घारा ६ कं अधीन हस्तगत किये गये आस्थान के विषय में प्रतिकर निर्धारण तथा प्रतिकर पाने के अधिकारी मध्यवर्ती की उसके भुगतान भे, सम्बन्ध रखने वाले सब व्यय- हार ऐसे प्रतिकर अधिकारी के सामने होंगे, जिसके अधिक्षेत्र में हस्तगत किया गया आस्थान स्थित हो।

स॰ प्रा॰ ऐक्ट ३, १६०१ ३३—धारा २४ और ३४ के निदेशों को बाधित न करते हुए और उस दशा को छोड़ जिस की व्य-वस्था धारा ५- में की गई है, युनाइदेड प्राविसेज तैंड देवेन्यू एंकट, १९०१ के निदेशों के प्रधीन तथार किय गयं या पुनराक्षित (revised) श्राधिकार- फांमलेखों (record of rights) में पिछले छांप-वर्ष के प्रत्येक इन्द्राज के विषय में,इस ऐकृ के अधीन प्रतिकर के निर्धारण भौर भुगतान के प्रयोजनों के लिये यह सममा जायगा कि वे उससे सम्बन्ध रखने वाले आस्थान या माग के प्रत्येक मध्यवर्ती के अधिकार, भागम भौर स्वत्व (right, title and interest) के ठीक-ठोक व्यक्त करते हैं।

श्रन्तरिम प्रतिकर का संघान

पतिकर के निर्धारण भौर भुगतान औ प्रक्रिया

मधिकार-मभिलेखों के इन्दराजों के सम्बन्ध में परि-कल्पना (presump: tion) किन्तु प्रतिबन्ध नह है कि सूनाइटेड प्राविसेज लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ निदेशों के जीन या किसी न्यायालय की डिकी या प्राज्ञा के परिष्णमस्वरूप अधिकार-समिल्लों (record of rights) में किये गए निस्ता किकार (medification), परिवर्तन (alteration) प्रथवा संशोधन (correction) पर जोहे वह स्वत्वधिकार के दिनांक से पहिले हुगा ह ना बाद में, प्रतिकर अधिकारी स्थान राखेगा!

सं॰ प्रा॰ पेक्ट ३, १६०१

ग्रधिकार-ग्रभिलेखा में हेख था गणना की श्रशुद्धि का ठीक किया जन! ३३ - यूनाइटेड माविराज लेंड रेवेन्यू ऐकट, १९०१ ई० ना समय निशंगार प्रचलित किसी रणा विधि में निरुष कि के ग्रह पण्तोप हो जार कि प्रांतकर यिककारों के यह पण्तोप हो जार कि पिक्ले कृषि नर्थ के के प्रांतकार-यभिनेष में कोर्र लेख रणाना की प्रश्चित (clorical crarithme ical mistake) या पेसी होई मल है जो निल्कुल रण्या (orror apparent on the face) ना वह स्थ्यं म्यूया किसा स्वल्य रणने वाले व्यक्ति की प्रार्थना क उसका शुद्ध कर सकता है।

सं॰ ग्ना• ऐवट ३, १६०१

दोवानी न्यायालय में स्वत्व स्थापित करने का चांचकार ३५—धारा ३६ * 3 [1] मौर ५२ में कही गर्य। किसी जात का प्रभाव िसो व्यक्ति के इस श्राधिकार पर नहा हागा कि वह किसी जा सिश्त प्राप्तः वाश्यक्तय में उचित विधिक व्यवहार (duo process of law) द्वारा किसी भाष्यान या उसके भाग के सम्बन्ध में भपना ग्वत्व स्थापित कर सके।

श्रधिकार- प्रिमिलेखीं के इन्दराजों स्व सम्बन्धित विचारा-धीन वाद भौग स्ववहार ३६--यदि किमां दीवानी यो माल के न्यायालय
में स्वरमधिकार के दिनांक पर पेना के वाद
या स्वर्धा विकास प्रेमें देश या उक्त दिनांक पर
या उसके बाद प्रत्तुत शिया जार जिसमें घारा
३३ में उच्लिकित अधिकार मिलेख के किसी
इम्प्राज की शुद्धना पर अक्षंप किया जाता है।
(is challenged) या जिसमें उसकी शुद्धता
पर प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्ष हम से बिवाद है। (directly
or indirectly in dispute), ते। उम बाद

^[*] निकाल दिया गया।

या व्यवहार का कोई भी फरीक वाद-पत्र या डजदारी की प्रमाखित प्रतिलिप प्रतिका अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु केवल ऐसा करने से ही यह न समभा जायगा कि वह प्रतिकर अधिकारी के सामने चल रहे व्यवहार में फरीक हो गया है

३७--[*]

३८—वारा ३६ के अधीन [*] प्रस्तुत किए गए वाद-पत्र या उज़दारी की प्रतिलिप प्रतिकर अधि-कारों के सामने चल गई ज्यवहार के अभिलेख का अंग है। जानगी (shall form part of the record) और प्रतिकर अधिकारों धारा ४४ के अधीन तैयार की गई प्रतिकर निर्धारण तालिका में तत्सम्बन्धों विवाद का विषय ऐसे ब्यारों के साथ दर्ज करायेगा जी नियत किये जायं।

३६—इस ऐक्ट के अधीन प्रतिकर निर्धारण और पुनर्दासन अनुदान के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक मध्यवर्ती एक अलग इकाई (suparate unit) सममा जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब

(क) यदि पिता स्वत्वाधिकार वे दिनांक पर जीवित था तो वह पुर पौत्रादिक कम वाली अपनी पुंसन्तिर के साथ (with his male lineal descendants in the male line of descent) संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति के विषय में पक ही इंकाई समस्ता जायगा (स) खंड (क) की दशा को कोड़ उसके

(ख) बंड (क) की दशा की छोड़ उसके सभी ग्रंग (members) ग्रह्णग-ग्रहण इकाइयां माने जायंगे।

स्पष्टोकरण-यदि द अगस्त, १६४६ ई० के। या अकि बाद कोई बटवारा द्या हो तब भी कुटुम्ब संयुक्त हा सम्भा जाएगा।

٧٥___[*]

वाद-पत्र या उज्जदारो का प्रतिकर व्यवहार के ग्रमिलेख का ग्रग होना

प्रत्येक मध्यवर्ती का अलग इकाई माना जाना

^[*] ਜ਼ਿਲਾਲ ਇਹਾ ਜਹਾ

महाल या गांव की कची निकास का विवरण ४१—िकसी महात या गांव के सम्बन्ध में किसी मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका तैयार करने से पूर्व प्रतिकर प्रधिकारी—

- (क) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गांव में नहीं है, तो महाल की, और
- (ख) यदि महाल की भूमि एक से अधिक गांव में है, तो गांव की,

कच्ची निकासी (gross assets) का एक विवरण तैयार करेगा।

धारा ४१ के ग्रधीन विवरण पर उन्न धर—(१) घारा धर के अधीन विवरण तैयार हो जाने पर प्रतिकर प्रधिकारों उस विवरण से सम्बन्ध रखने वाले गांव या महाल में नियत की जाने वाली रीति से एक सामान्य आक्षा प्रकाशित करके ऐसे महाल या गांव में स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आक्षा देगा कि वह उस समय के मीतर जो निर्दिष्ट किया जाये, उक विवरण के किसी इन्द्राज के ठीक न होने या उसके प्रकार के विषय में या उसमें किसी बात के छूट जाने के सम्बन्ध में उसे जो कुछ उज़ करना हो करे, यदि इस बात से महालया गांव की, जैसी भी दशा हो, कच्ची निकासी की धनराशि के प्रवधारण (determination) पर प्रभाव पड़ता हो या उसके पड़ने को सम्भावना हो।

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध रहेगा कि यदि भीर जहां तक कोई उन्न धारा ३३ में श्रमिद्ध्ट (referred) ग्रधिकार-प्रमिलेख के किसी इन्द्राज की शुद्धता पर ग्राह्म प के इप में होगा तो वह वहां तक प्राह्म नहीं होगी (shall not be entertained)।

(२) पेसी उज्ञदारी प्रस्तुत किये जाने गौर उसकी सुनवाई भौर निस्तारण को तथा उसके निर्णय में ग्रनुसरण किये जाने वाळे सिद्धान्तीं की, प्रकिया प्रान्तीय सरकार नियत कर सकती है।

महाल या गांव को कच्चो निकासी ४३—िकसी महाळ या गांव के सम्बन्ध में कच्ची निकासी (gross assets) महाल या गांव के अन्तर्गत भूमि या प्रास्थान की कुल कच्ची गाय (aggregate gross income) होगी और उसमें निम्नतिखित का अन्तर्भाव होगा (shall include) :--

- (क) स्रोर के काश्तकारों (tenants of Sir) को कोड़ अध्य काश्तकारों, मातहतदारों (under-proprietors), अदना माछिकों (sub-proprietors), द्वामी काश्तकारों (permanent tenure-holders), अवध के द्वामी पह दारों (permanent lessees in Avadh), रियायतो लगान के काश्तकारों (grantees at a favourable rate of rent) या बागदारों द्वारा या उनकी भोर से देय अववाबों और स्थानिक करों (local rates) सहित:—
 - (१) नकटो लगान, या
 - (२) यदि लगान जिम्सो है या गंशतः नकदो भीर ग्रंशतः जिन्सी है ता, वह लगान जो यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सो ऐक्ट, १९३९ ई० के निदेशों के मनुसार लगाया जाए, ग्रीर
- (३) यदि लगान देय हो किन्तु अव-धारित न हुचा हो तो मातहतदार चौर साकितुल-मिल्कियत काश्तकारों के सम्बन्ध में साकितुल-मिलिकयत दरों से अवधारित लगान चौर बाग-दारों को कोड़ चन्य के सम्बन्ध में मौरूसो दरों से ग्रवधारित लगान।
- (ख) ऐसी भूमि के लगान के निमित्त, जी पास्थान के समस्त मध्यवर्तियों की निज जीत में हो या उनके पास मध्यवर्ती के बाग, खुदकाइत या ऐसी सीर के रूप में हो, जिसमें मीरूसी घधिकार न उत्पन्न होते हों, तो वह धनराशि, जो उसी प्रकार की भूमि के साकितुलमिल्कियत कारत कारों को लगा दरों से लगाई जाय, तथा ऐसी सीर के निमित्त, जिसमें मीरूसी अधिकार उत्पन्न होते हों, वह धनराशि जो मीरूसी दरों से लगाई जाय,
- (ग) सायर, जिसके अन्तर्गत हाढों, बाज़ारें। मेलों और मोनाशयों (fisheries) की आय होगी और जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के

दस कृषि-वर्षी की उसी प्रकार की ग्राय के जोड़ के दसवें ग्रंश के बराबर हो,

- (घ) वनेंं की वार्षिक गौसत आय की गणना की जायगी:—
 - (१) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठोक पहिले के २० से ४० वर्ष तक की, जैसा प्रतिकर प्रधिकारी उचित समम, ग्राय के आधार पर लगाई हुई वन की ग्रोसत वार्षिक आय,
 - (२) स्वत्वाधिकार के दिनांक पर बन के वार्षिक ग्राय के ग्रनुमान पर।
- (ड) ऐसे मध्यवर्ती के विषय में, जिसे अपने आस्थान या आस्थानों के अन्तर्गत खानों या खनिज-पदाधों (minerals) के निमित्त स्वा-मित्व (royalties) मिलता हो, स्वामित्व की वह औसत आय, जो उस क्रवि-वर्ष से, जिसमें स्वत्वाधिकार का दिनांक पड़ता हो, ठोक पहिछे के बारह वर्षों में मध्यवर्ती द्वारा अबवाब (cess) या आय-कर (income-tax) के निर्धारण के लिख वार्षिक विवर्णों के आधार पर या यदि ऐसे विवर्ण उससे कम हो काल के वार्षिक विवर्णों के आधार पर वा विवर्णों के आधार पर वा तिवर्णों के आधार पर वागई जाय,
- (च) यदि कोई मध्यवती यपने पास्थान या पास्थानी के मन्तर्गत खानें को स्वयं चलाता हो, तो ऐसी खानें से होने वाली घोसत कच्ची वार्षिक घाय, जो खब्द (ङ) में निर्दिष्ट पाधार पर कगाई जाय।

प्रसावित प्रतिकर निर्धारण तालिका ४४—इस पेक्ट के अधीन प्रतिकर के निर्धा-रण गोर भुगतान के लिये प्रतिकर प्रधिकारी नियत रौति से पक पेसी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण ताळिका (draft compensation assessment roll) तैयार करेगा, जो उक्त प्रधि-कारों को सुविधानुसार एक या अधिक महाल या गांव में उस मध्यवती के स्वत्वों के सम्बन्ध में होगी ग्रौर जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई जायंगी:—

- (क) घारा ४६ से ४९ तक में से जो भी धारायें लागु हैं।, उनके निदेशों के अनुसार लगाई गई उसकी कच्ची और पक्की निकासी (gross assets and net assets),
- (ब) पूर्वोक्त महाछें या गांवां में मध्यवतीं के गंश या स्वत्वों के सम्बन्ध में उसके द्वारा पान्तीय सरकार के देय मालगुजारी, अबवाब या दूसरे देयां की ऐसी बकाया (arrear), जिसका उच्छेख धारा न के खएड (घ) में है,
- (ग) पूर्वोक्त महालें या गावें में अपने गंश या स्वत्व के सम्बन्ध में मध्यवतीं द्वारा देथ पिछले कृषि-वर्ष की मालगुजारी, गीर
- ् (घ) **पें**से दूसरे न्यौरे जे। नियत किये जायं।

पहला स्पष्टीकरण—ऐसे ग्रास्थानों के विषय में, जिन पर स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर मालगुजारी निर्धास्ति न है।, मालगुजारी ऐसी घनराशि सममी जायगी, जो स्थानिक करों (local rates) के ग्राधार पर या जहां स्थानिक कर न हों।, तो ऐसे सिद्धान्तों पर जो नियत किये जायं, लगाई जाय।

दुसरा स्पष्टोकरण—गृद किसी ग्रास्थान पर केवल देखावटी (nominal) मालगुजारी निर्धा-रित हो, तो इस जारा के प्रयोजनों के लिये यह न समभा जायगा कि उस पर मालगुजारी निर्धारित नहीं है।

४५—धारा ४१ के अंधोन तैयार किये गये विवरण भौर धारा ४४ के प्रधीन तैयार की गई प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका पर प्रतिकर-मधिकारों के हस्ताक्षर होंगे भौर उक्त विवरण तथा तालिका उन बातों के प्रमाण में प्राह्म होंगे जी उनमें लिखी हैं। (shall be receivable as evidence of the facts stated therein)।

४६—धारा ४४ के प्रयोजनों के लिये महाल या गांव में किसी मध्यवर्ती के स्वत्वें के सम्बन्ध विवर्ण ग्रौर प्रतिकर निर्घारित तालिका पर प्रतिकर ग्रधि-कारो के हस्ताकर होना में उसकी कच्चो निकासी निम्नलिखित का जोड़ होगी:—

- (क) महाल या गाव के किसी ऐसे भाग या भागों के सम्बन्ध में, जिसमें उसका ऐकान्तिक (exclusive) स्वत्व हैं।, धारा ४१ के अधीन प्रस्तुत किये गये विवरण में दर्ज कुल कच्ची निकासी, और
- (ख) ऐसे भाग या भागों के सम्बन्ध में, जिसमें श्रीरों के साथ उसका स्वत्व में धारा ४१ के ग्रधीन प्रस्तुत किये गये विवरण महाल या गांव के उक्त भाग या भागों में उसके गंदा के यनुपात में हो।

हेकेदार के कब्जे के ग्रास्थान की निकासी ४७—जहां स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहाँ से के दिनांक पर किसी ग्रास्थान या उसके भाग में किसी मध्यवर्ती का स्वत्व या ग्रंश किसी ठेकेदार के पास हो, वहां धारा ४३ में दिये सिद्धान्तें के अनुसार लगाई जाने वाली उस ठेकेदार की कच्ची निकासी, चाहे वह मध्यवर्ती के। देय न भी हो, पेसे ग्रास्थान या भाग के, जैसी भी दशा हो, सम्बन्ध में, उस मध्यवर्ती की कच्ची निकासी समभी जायगी।

स्पष्टाकरण—ठेका प्रारम्भ हाने के दिनाक पर जा भूमि ठेका देने वाले की सीर या खुदकारत हो, उसकी छोड़कर, अन्य ऐसी भूमि की कच्ची निकासी, जो ठेकेदार की निजी जोत में हो, वह धनराशि समभो जायगो, जो छागु मौहसी दरें के मनुसार ग्रवधारित हो।

मध्यवर्ती की पश्को निकासी

४८—धारा ४४ के प्रयोजनों के लिये महाल या गांव के सम्बन्ध में किसी मध्यवतीं की पक्की निकासी ऐसे मध्यवतीं की कड़ची निकासी में से निम्नलिखित की घटा कर निकाली जायगी:—

(क) पेसी धनराशि जो पिक्छे कृषि-वर्ष में उसके द्वारा पांग्तीय सरकार या प्रवर संजयति (superior land holder) को महाल या गांव में मध्यवर्ती के ग्रंश या स्वत्व के सम्बन्ध में भालगुजारी या लगान तथा ग्रववाब या स्थानिक करके निमित्त देय थी,

- (ख) मध्यवती द्वारा महाल या गांव में उसके गंदा या स्वत्वों के सम्बन्ध में पिछ्छे कृषि-वर्ष के लिये दिये गये या दिये जाने वाले कृषि-ग्राय कर के, यदि काई हा, निमित्त ऐसी धनरादा जो नियत रीति संलगाई जाय,
- (ग) प्रबन्ध व्यय (cost of management) आर लगान को ऐसी बकाया, जो बसूल न हा सकती हा—दोनें मिलकर कच्ची निकासी के १४ प्रतिशत के बराबर,
- (घ) जहां कोई भूमि मध्यवर्ती के पास इसकी निज जीत में या खुदकारत, मध्य-वर्ती के बाग या पेसी सीर के रूप में हो, जिसमें मौहसी यधिकार न उत्पन्न होते हों वहां उसकी निज जीत, खुदकारत, बाग या सीर की भूमि के केवल पेसे भाग के निमित्त, जो घारा १६ में उल्लिखत है, ऐसी धनराशि जी सांकृतुलमिल्कियत दरों से लगाई गई है। भीर जिसमें से १ से ३ तक की निम्नलिखित कटौतियां (Deductions) निकाल दी जायं:—

[१] कृषि-आय-कर, यदि कोई है।, जो पिछले कृषि-वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा है।; यह नियत रीति से निश्चित किया जायगा।

[२] मालगुजारी, भववाव और स्थानिक कर जो पिछले कृषि-वर्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में देय रहा हों, ये नियत रीति से निश्चित किये जायंगे।

[३] खंड (ग) में अमिदिष्ट विषयें। के निमित्त उपयुक्त धनराशि का १४ प्रतिशत।
(क) आरा ४३ के खरड (ङ) में डिल्लिखित

स्वामित्व में हुई माय पर दिये गये भाय-कर के (income-tax) का ऐसा गौसत जो उक्त खरड में उच्छि बित काल के अनुसार छगाया गया है। तथा नियत की जाने वाली दरों में लगाया गया वसूछी का व्यय,

(च) धारा ४३ के खरह (च) के मधीन प्रवधारित क्षेत्री माय का ६४ प्रतिशत; यह मध्याय ६ में जारी रखे गये अधिकारों के सम्बन्ध में उसके लिये सुरक्षित आय का भाग समभा जायगा।

स्पष्टोकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये ऐसी मालगुजारी, जो महामहिम (His Majesty) या प्रान्तीय सरकार या किसी दुसरे समर्थ प्राधिकारिक (competent authority) द्वारा या उसकी ग्रांर से दिये गये ग्रनुटान (grant) या किये गये पुष्टीकरण (confirmation) के कारण ग्रभ्यपित (assigned) ग्रास्थक (released), ग्रास्थित (compounded) या निष्कीत (redremed) को गई हा, प्रान्तीय सरकार के देय मालगुजारी नहीं समसी जायगी।

प्रश्नमात्हतदारों (under proprietors)

प्रदन्त-मालिकों (sub-proprietors), द्वामी
काश्तकारें (permanent tenure-holder)

और प्रवध के द्वामी पट्टदारों (permanent lessees in Avadh) पर धारा ४४ से ४८ तक के निदेश ऐस आनुषंगिक (incidental)

परिवर्तनों (changes) और परिष्कारों (modifications) के साथ जो नियत किये जायं, लाग्र होंगे और फिर ऐसे मध्यवर्तियों की कच्चों भीर पक्की निकासी तदनुसार लगाई जायगी।

४०—(१) किसी मध्यवर्ती के विषय में प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण-तालिका तैयार हो जाने पर प्रतिकर प्रधिकारो—-

(क) गज़ट में घौर ऐसी यन्य रीति से, जो नियत की जाय, उस सम्बन्ध में नेपटिस प्रकाशित करेगा, घौर

मातहतदारों, ग्रदनाः मालिकों, दवामी काश्तकारों ग्रौर ग्रव्य के द्वामी पृष्ट दारों की कच्ची ग्रीर पक्की निकासी निकालना

प्रस्ताविक प्रतिकर निर्घारण तालिका का प्राथमिक प्रकाशन

- (ख) प्रस्तावित. प्रतिकर निर्धारण-ताळिका की प्रति (copy) के साथ पूर्वोक्त ने टिस की एक प्रति सम्बन्धित मध्यवर्ती पर तामील करेगा या करायेगा।
- (२) इवत्व रखने वाले व्यक्तियों की ग्रोर पेसे व्यक्ति की, जो यह कहता हो कि किसी पेसे ग्रंश या स्वत्व में जिसमें उसे ग्रंधिकार प्राप्त है मध्यवर्ती का नाम प्रतिनिधि हप में या संयुक्त हिन्दू क्रुद्धम्ब के कर्त्ता के रूप में दर्ज है, उपधारा (१) के ग्रंधीन ने टिस द्वारा ग्राज्ञा दी जायगी कि वे उपस्थित हो कर दो मास के भीतर ऐसी तालिका के विषय में उज्जदारी करें;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई उच्चदारी इस ग्राधार पर ग्राह्म नहां होगी (shall not be entertained) कि ग्रांस्थान में मध्यवतों का ग्राधक या कम ग्रंश या भाग है या उसका कोई ग्रंश या भाग नहीं है; किन्तु यह बात उस दशा में न लागू होगी जब उक्त उच्चदारी नेटिस में उल्लिखित ग्राधारों में से किसी श्राधार पर हो या धारां ३३ ग्रथवा ३४ के ग्रधीन किसी ग्राह्मा के ग्रनुसार की गई हो।

११—दिये गये समय के भातर कोई उन्नदारों होने पर प्रतिकर यधिकारो उसका रिजस्टर में दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निद्वित करके उसकी सूचना सम्बन्धित मध्यवर्ती को और ऐसे स्वत्व रखने वाले व्यक्ति (person interested) को देगा, जो धारा ५० के यधीन नेतिस के प्रतिवाद (reply) में उपस्थित हथा हो।

४२—धारा ५० के ग्रधीन प्रस्तुत की गई उज्जदारियों की सुनवाई और निर्णय करने में प्रतिकर अधिकारी के दीवानी न्यायालय (Civil Court) के समी ग्रधिकार, जहां तक वे लागु है। सकें ग्रीर इस गृध्याय के निदेशों से असंगत (inconsistent) न हों, प्राप्त होंगे ग्रीर ऐसे प्रिकारों (modifications) की बाधित न करते रहते हुए जो नियत किये जायं, वह उस

उन्नदारा सुनने का दिनांक

उज्जदारियों की सुन-वाई ग्रीर निर्णय प्रक्रिया का उनुसरण करेगा, जो कोड प्राफ हिवल प्रोसोजर, १६०८ में उचल स्मान्ति (immovable property) सम्बन्धी वार्दो की सुनवाई यौर निस्तारण (disposal) के लिये दो गई है।

ऐक्ट सं**०** ५, १९०८

धारा ४२ या ५२ के श्रधीन ग्राज्ञों का दीवानी न्याया तय की डिकी समभा जाना

डिस्ट्रिक्ट जज के। श्रपील र्र—प्रतिकर श्रिधकारी द्वारा किसी उज्जदारी के सम्बन्ध में धारा ४२ या ४२ के अधीन दी गई निर्णयाताक ग्राज्ञा दीवानी न्यायालय की डिकी सप्तमी जायगी और उसमें मुकदमें का संक्षिप्त विवर्ण, विचारणीय विषय, उनका निर्णिय और ऐसे निर्णयों के कारण दिये जायंगे।

५४—यदि प्रतिकर ग्रधिकारो द्वारा किसी उज्जदारी के सम्बन्ध में घारा ४२ या ५२ के श्रधीन दी गई निर्णयात्मक गज्ञासे कोई व्यक्ति श्रसन्तुष्ट है। तो वह, किसो विधि (law) में किसो बात के गहते हुये भी, उक्त श्राज्ञा के विध्द डिस्ट्रिक्ट जज के सामने श्रपील कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि गालिका में दर्ज पक्की निकासी (net assets) ग्रीग् मध्यवर्ती द्वारा बताई गई पक्को निकासी मं २,५०० ६० से अधिक का ग्रन्तर हो तो, अपील हाईकोर्ट में हो सकेगी।

४४—धारा ४४ के अधीन हिरिद्रक्ट जल द्वारा दो गई धर्माल को हिकी के विरुद्ध, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०५ की घारा १०० में दिये गये धाधारों में से किसी आधार पर अपील हाईकोट में हो सकेगी।

प्रकाट में हा स्वर्णा।

प्रक्—(१) यदि घारा ४० के ग्रंथान ने टिम
जारी होने । र प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण तालिका के सम्बन्ध में के हि उच्चदारी न की गई
हो या यदि ऐसी उच्चदारियां होने पर उनका
ग्रन्तिम निस्तारण (disposal) हा गया
हो ग्रीर तदनुसार प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण
तालिका में संशोधन, परिवर्तन या परिष्कार कर
दिया गया हो, तो प्रतिकर ग्रंथिकारो उन १
ग्रंपने हस्ताक्षर कर देगा ग्रीर प्रपनी मृहर भी
लगा हेगा।

पॅक्ट सं० ५, १६०८

हाईकार का अपील

त्रम्तिम प्रतिकर निर्घारण तालिका (२) इस प्रकार हस्ताक्षर किये और मुहर लगाये जाने परं प्रतिकर निर्धारण तालिका अन्तिम हें। जायेगी।

४७—प्रतिकर ग्रांघकारो प्रतिकर निर्धारण तालिका की एक प्रतिलिपि बिना ग्रुटक सम्बन्धित मध्यवर्ती के। दे देगा ग्रीर एक प्रतिलिपि परगना के ग्रंघिकारी ग्रासस्टेन्ट कलेक्टर (Asstt. Collector incharge of the sub-division) के कार्यालय के सूचना-पष्ट (notice board) पर भो लगवा दंगा। तालिका की प्रति-लिपि का मध्यवतीं को दिया जाना

• • ५८-- ऐसे महालों या गांवों में जिनसे प्रतिकर निर्धारण पांडु तालिका का सम्बन्ध है, किसी मध्य वर्ती के स्वत्वों के निमित्त उस प्रतिकर रूप में देय धनराशि, ऐसी दशा की छोड़ जहां मध्यवतीं का स्वत्व ठेकेदार के पास हो या जहां मध्यवतीं स्वयं ठेकेदार है।, तालिका में लिखित पक्को निकासी के ग्रदगुने के बराबर होगी।

प्रतिकर को मात्रा

१९—जहां मध्यवर्ती का स्वत्व किसी ठेकेंदार के पास हो वहां मध्यवर्ता की प्रतिकर निर्धारण तालिका में दी हुई पक्की निकासो पर धारा १८ में दिये सिद्धान्तों के ग्रनुसार लगाया गया प्रतिकर उक्त ग्रास्थान में मध्यवर्ती और ठेकेंदार के स्वत्यों के संबन्ध में उन दोनों को संयुक्त रूप में देय प्रतिकर होगा और प्रतिकर ग्रधिकारी उक्त धन-राशि के निम्निसिखित बातों पर ध्यान रखते हुए उन दोनों में बांट देगा:—

ठेकेदार को देय प्रति-कर को मात्रा

- (क) नज़राना (premium), यदि ठेके या पह के प्रारम्भ में कोई दिया गया हो, (क क) के की चवधि (term) और प्रतिबम्ध (conditions);
 - (ख) ठेके की समाध्ति कं कारण ठेकेदार का यदि कोई हानि हुई हो तो वहा
 - (ग) ठेके के अन्तर्गत ग्रास्थान या ग्रास्थानों को कची ग्रीर पक्की निकासी,
 - (घ) ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष देय धनराशि।

(घघ) यह तथ्य (fact) कि मध्यवतीं के तो सभी श्रधिकार, जो सब के सब हस्तगत किए जो रहे हैं, सदा के लिए (held in perpetuity) थे, पर ठेकेदार के श्रधिकार सीमित प्रकार ही के हैं; श्रीर

धारा ४२ के अधीन प्रक्रिया (ङ) ऐसे ग्रम्य विषय जो नियत किये जायं। ६०—मध्यवतीं श्रीर उसके ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने में प्रतिकर प्रधिकारों ऐसी प्रक्रिया का ग्रनुसम्म करेगा, जो नियत की जाय।

घारा ५९ के ग्रधीन ग्राज्ञा का दीवानी न्यायालय की डिको समभा जाना।

- ६१—(१) मध्यवती और उसके ठेकेदार के बीच प्रतिकर विभाजित करने के सम्बन्ध में प्रतिकर प्रधिकारी की पांचा प्रधिक्षेत्र-प्राप्त (of competent of jurisdiction) दीवानी न्याया छय की डिकी समभी जायगी।
- (२) समय विशेष पर प्रचित्तत किसा ग्रन्थ विश्व में किसी वात के रहते हुए भी, उपवारा (१) में उल्लिखित हिस्री के विरुद्ध हिस्ट्रिक्ट जन के सामने अपील हो सकेगी [88]।

हाईकोर्ट को अपीत

६१-क-धारा ६१ के ग्रधीन हिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दी गई ग्रपीन की हिकों के विरुद्ध ग्रपील कोड ग्राफ सिविल प्रोसीजर १६०८ ई॰ की धारा १०० में दिये गए ग्राधारा में म किसी ग्राधार पर हाई॰ कोट में हो सकेगो।

प्रवीस्त्र के स्मरण-पत्र पर देथ न्याय शुल्क ६२—कार्ट फोम पेक्ट, १८७० ई० में किसी
बात के रहते हुए मी धारा ४४, ४४, ६१ या
६१ (क) के ग्रधीन प्रस्तुत को जाने वालो ग्रपोल
के स्मरण-पत्र (memorandum) पर देथ पेक्ट सं०
स्याय-शुक्क (court fee) वह होगा, जो नियत १,१८७० ई०
किया जाय।

तातिका में प्रतिकर का दर्ज किया जाना ६३—िकसी मध्यवती को प्रतिका के हप में देय धारा ५८ भौर ५६ के अधीन सवधारित धनराशि के विषय में प्रतिकर अधिकारी यह प्रवर्गापत करेगा कि वह उस मध्यवती की उन महाछों या

[*] निकाल दिया गया।

गांवों में, जिनका सम्बन्ध प्रतिकर-निर्धारण तालिका से है, उसके स्वत्व के निमित्त देय प्रतिकर है प्रौर प्रतिकर ग्रधिकारी उसे तालिका में ग्रपने हो हाथ से ग्रभिलिखित करेगा।

६४—(१) प्रतिकर निर्धारण तालिका के यन्तिम (final) हा जाने पर, पेसी दशा के छोड़, जिसकी व्यवस्था इस पेक्ट के द्वारा या प्रधीन की गई हो, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जायगा।

(२) ग्रधिक्षेत्र-प्राप्त प्रतिकर ग्रधिकारी प्रातकर दिये जाने के समय से पूर्व किसी समय भी चाहे स्वतः या स्वत्व रखने वाले किसी व्यक्ति (a person interested) की प्रार्थना पर प्रतिकर निर्धारण तालिका में किसी छेख सम्बन्धी या गणना सम्बन्धी श्रशुद्धिया (clerical or arithmetical mistakes) की या किसी ऐसी श्रशुद्धि की, जी उसमें किसी प्राकस्मिक भूछ या चूक (accidental slip or omission) से है। गई

६४—ऐसे न्यायालय या अधिकारिक (authority) के अतिरिक्त, जिसके सामने प्रतिकर आधिकारिक की आहा या डिकी के विरुद्ध इम अध्याय के अधीन कोई अपील विचाराधीन हो, किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी कोई न्यायालय या अधिकारी इस अध्याय के अधीन प्रतिकर अधिकारों के सामने चल रहे व्यवहार (proceeding) के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा समादेश (injunction) नहीं जारी करेगा, जिसके परिणाम-स्वरूप डक्त व्यवहार रक जाय।

६६—इस ग्रध्याय में "स्वत्व रखने वाला व्यक्ति" के ग्रन्तर्गत ऐसे सब व्यक्ति हैं, जो चाहे उनका नाम ग्रधिकार-ग्रिमलेखों में ग्रिमिलिबत हो या न हा, ग्रपने ग्रापका मध्यवर्ती के नाते ऐसा प्रतिकर या उसका कोई भाग या ग्रंश पाने का ग्रधिकारी बताते हैं, जो इस ऐक्ट के ग्रयोम

पेसी मशुद्धियों का ठीक किया जाना, जो मकामतः हुई हों

म्थायालय द्वारा समादेश का निषेध

स्वत्व **रखने वा**छे ब्यक्ति को परिभाषा मास्थानें के हस्तगत किये जाने के कारण निर्धा-रित किया या दिया जाने वाळा हा।

नियम बनाने का प्राथकार

- ६७—(१) इस ग्रध्याय के निदेशों के। कार्यान्तिय करने के लिये पान्तीय सरकार नियम बना सकती है।
- (२) पूर्वेक्ति अधिकार की ब्याप्ति की बाधित न करते हुए (without prejudice to he generality) ऐसे नियम निम्निस्थित की ब्यवस्था कर सकते हैं:—

(क-१) धारा २६ के ग्रधीन उयाज लगाने को रीति ग्रौर सिद्धान्त;

- (क) घारा ३१ के अधीन धन्तरिम (inter im) प्रतिकर की घटाने और संघानित करने (deducting and adjust ing) की रीति;
- (क क) जिन चे त्रों में लगान का दर ग्रव-धारित नहीं को गई हैं उनमें ऐसी दर निर्धारित करने की रोति और सिद्धान्त;
- (ख) धारा ३४ के ग्रधान ग्रधिकार-ग्राम-छेखों में संशोधन करने की प्राक्रया;
- (ग) धारा ३६ के प्रधोन प्रार्थना-पत्र या उज्जदारी के दाखिल करने को प्रक्रिया।
- (घ) विवरण प्रस्तुत करने को रीति (ma nner) गौर ग्राकार (form); घारा ४१ के ग्रधीन;
- (क) प्रतिकर-निर्धारण तालिका तैयार करने को रीति गौर भाकार, घारा ४४ के भधीन;
- (च) उन्नदारी प्रस्तुत करने की रीति और भाकार, धारा ४० के प्रधीन:
- (क्) उन्नदारी रिनस्टर में दर्ज करने की रीति और माकार, धारा ४१ के अधीन;
- (ज) संशोधन करने में चनुसरण की जाने वाली (to be followed) रोति और प्रक्रिया, धारा ६४ के चधीन;
- (भः) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं भीर नियत किये जग्यं।

इस्याय ४

प्रतिकर का भुगतान (Payment of

Compensation)

६८—प्रत्येक मध्यवर्ता के। प्रत्येक कारधान में उनके जियकार, ग्रांग और स्वत्व के हस्तगन ितये जाने के निमित्त प्रतिकर के रूप में ऐसी धनगांकि टो जायगों, जो धाग ६३ के ग्रांधान इस सम्बन्ध में प्रस्थापित जो गई है।

तालिका में दर्ज प्रतिकर का मध्य-वर्ती को दिया जाना

६६—धारा ७३ के निदेशों को वाधित न करते दुष, दम विधान के ग्रायान देय अतिका उम मध्यवर्षों की दिया जायगा, जिलाता गोम प्रतिका निर्धारण-तालिका में दर्ज है।।

तालिका में दुर्ज मध्यवर्ती का प्रति-कर पान।

७०--यदि अति हर पाने का अधिकारी प्रतिकर पाने के पहले ही मर जाय तो प्रतिकर उमके जिधिक प्रतिनिधि के। देय है। गा।

विधिक प्रतिनिधि को द्य प्रतिकर

७१—इस विधान के अर्घात देग । तिका पेसे क्य में [अ] दिया जायगा, जो नियन किया जाय।

प्रतिकर के भुगतान कारूप

७२—(१) जहां प्रतिका पाने का अधिकारी तक्फ, न्यास (Trust) या निवन्ध (इन्हाऊमेंट) है। यथवा वह प्रवयस्क हो, किसी व्यावहारिक अक्षमता (legal disability) के प्रधीन हो, या को मीमित स्वास्य वाला व्यक्ति हो वहां किसी विचि (law) में किसी वात के रहने हुये भी किन्य

कुछ दशाओं में बैंक या अन्य प्राध्यिका-रिक के पाम प्रतिकर का जमा किया जाना

व्यापक निदेशां (general Direction) की बाबित न करते हुए, जो प्रान्तीय सरकार दे, प्रति-कर उम व्यक्ति के लिये और उमकी और से ऐसे ग्राधिकारिक या बक के पास, जो नियत किया जाय, जमा नर दिया जा मकेगा।

(२) ऐमे किसी व्यक्ति के, जिसके लिए या जिसकी कोर अप्रतिकर जमा किया गया हो, उकत प्रतिकर के उपयोग (utilization) ग्रौर विनियोग

[अ] निकाल दिया गया।

(disposal) करने कं आंत्रकारों को नियमित करने वाले विजि के जिला जिला अपना और विनियाग के ने का जोध कार उपमास (१) के कही गई किसी वात सुधाधत हाला न सक्का आयगा।

स्पष्टा हरण-अस घारा पा प्रयोग ो के लिंध काई व्यक्ति केवल इस फारा म मित स्वास्थ म ला व्यक्ति न समभा जायगा कि सवन सेमल्ड इ उद्स एक्ट, १९६७ के विश्वा के प्रयोग उस प्रास्थान के नावन्य में, जिसके लिए प्रतिकः देय है, प्रख्यापन कर दिया गया है।

प्रतिकर का न्यायान लयया ग्राधि कारिक के हाथ में दिया जाना प्रभागने देना कर्न कर्म क्रिकार क्रिक

नियम ब**ाने** का मुधिकार ७४ —(१) इस ग्रध्याय के निदेशों का कार्या-ंग्यत करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त ग्रधिकार को व्यास्ति कर बायित न करते हुए, ऐसे नियम निम्न लिखित की ब्यवस्था कर सकते हैं:--

(क) प्रतिकर की धनगदित की धारा ७३ औ ग्रधीन न्यायालय या आधिकारिक के प्रधिकार में देने में (in placing at the disposal of) में तुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, (ख) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हेां या नियत किये जायं।

अध्याय ५

पुनर्वासन अनुदान (Rehabilitation Grant)

७५ छेकेदार के अतिरिक्त प्रत्येक मध्यवतीं को, जिसके ग्रास्थान इस विधान के निदेशों के मधीन हस्तगत कर लिए गए हों, ग्रागे की गई ध्यवस्था के अनुसार पुनर्वासन ग्रनुदान दिया जायगा।

पुनर्वासन ग्रनुदान का दिया जाना

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठोक पहले के दिनांक पर ऐसे क्षेत्रों में स्थित, जिनमें यह विधान लागू हो, उस मध्यवतीं के सब ग्रास्थानों के सम्बन्ध में देय कुछ माल-गुज़ारी (aggregate land revenue) पांच सहस्र रुपये से ग्रिधिक रही हो, तो उसके। ऐसा कोई ग्रनुदान नहीं दिया जायगा।

७६—घारा ७५ के स्रघीन देय पुनर्वासन स्रमुदान पेसे दिनांक पर या पेसे दिनांक से देय होगा, जिस पर मध्यवर्ती के। पेसे क्षेत्रों में, जिनमें यह विधान लागु होता हो, उसके सब सास्थानें के सम्बन्ध में दिया जाने वाला प्रातकर [*] स्रवधारित है। जाय।

दिनांक, जिससं ग्रनु-दान देय होगा

७७—धारा ७४ के सधीन पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी मध्यवर्ती यदि मर जाय तो उसका विधिक प्रतिनिधि (legal representative) उक्त अनुदान पाने का अधिकारी होगाः सौर पाएगा। विधिक प्रतिनिधि का ग्रनुदान पाने में त्र्राधिकारी होना

७८—पुनर्वासन चनुदान के निर्धारण गौर भुगतान के प्रयोजनी के लिए सभी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) नीचे लिखे तीन वर्गों में रक्खे जायेंगे:—

वक्फ, ग्यास (trust) या निबम्ध (endowment) का वर्गीकरण

^[*] निकाल दिया गया।

- (क) ऐसे वक्फ, न्यास (trust) या निवन्ध (endowment) जो पूर्णनः धर्मार्थ या पुरवार्थ (for religious or charatable purpases) हो.
- (ख) ऐसे वक्फ, न्याम (trust) या निवन्ध (endowment) जो प्रशतः धर्मार्थ या पुरवार्थ हों श्रीर ग्रंशतः दूसरे प्रयोजनों के लिए हों,
- (ग) ऐसे वक्फ, न्यास (trust) या निवन्ध (ondowment) जो पूर्णतः ऐस प्रयोजना के लिए हों जो धर्मार्थ या पुरुवार्थ से भिन्न हो। स्पष्टीकरण—किसो विधि में किसी प्रतिकृत बात के रहते हुए भी किसी वक्फ, न्यास (trust) या निवन्व (ondowment) की सम्पत्ति से होने वाले ऐसे लाभ के (profits), या लाभ के ऐसे भाग के विषा में, जो सस्यापक (founder) या उसके कुटुन्वियों अथवा उनके या उनके बंशजों (descendants) के भरण-पाषण (maintonance) के उपयोग में चाता हो या प्राने के लिए हो (intended to be used), यह समभा जाएगा कि वह समार्थ या पुरुवार्थ उपयोग में नहीं प्राता है गोर न वह उनत उपयोग में लाए जाने के लिए हो।

द प्रगस्त, १९४६ ई० के। क्ष उसके बाद हुए वक्फ, ट्रस्ट, इन्डाऊमेंट का न माना जाना 98—समय विशेष पर प्रचित्त किसो विधि
में किसी बात के रहते हुए भी, इस विधान के निर्देशों
के अयीन इस्तगत किए गए किसी आस्थान या
आस्थान के भाग के सम्बन्ध में कोई ऐसा वक्फ,
न्यास (brust) या निबन्य (endowment),
जिसके विषय में आगे चलकर अपवाद
(exception) न किया गया हा और जिसका ८
अगस्त, १६४६ ई० का या उसके बाद स्तान हुआ
हा (created), इस विधान के अधान पुनर्वासन
अनुदान के निर्वारण और भुगतान के प्रधाननों के
लिए वक्फ, न्यास (trust) या निबन्य (endowment) नहीं माना जायगा और प्रत्यंक ऐसा
आस्थान या आस्थान का भाग, जिसके सम्बन्य

में कोई वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) इस प्रकार किसी मध्यवर्ती द्वारा किया गया हो, ऐसे मध्यवर्ती का ही माना जायगा ग्रीर उसके सम्बन्ध में पुनर्वासन अनुदान इस प्रकार प्रवधारित किया जायगा मानो उक्त वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) का सुजन हुआ हो नहो

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऊपर किसो बात के रहते हुए भी उक्त ग्रास्थान या भाग के सम्बन्ध में दिया जाने वाला पुनर्वासन ग्रनुदान, मुतवल्ली, न्यासी (trustee) या ऐसे ग्रन्थ व्यक्ति का देय होगा, जिसका उक्त वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के प्रबन्ध का ग्रिथकार प्राप्त हो न कि मध्यवर्ती को।

ग्रपवाद (exception)—ऐसा वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment), जो पूर्णतः पुरुवार्थ (for charitable purposes) हो, यदि प्रान्तीय सरकार किसी विशेष मामले में केर्डिग्रीर निर्देश न दे, तो मान लिया जायगा।

द०—श्रिधिक्षेत्र प्राप्त किसी न्यायालय की डिकी या ग्राज्ञा के बाधित न करते हुए मध्यवर्ती, जिसे ग्रध्याय ३ ग्रीर ४ के श्रधीन किसी ग्रास्थान के सम्बन्ध में प्रतिकर देय हो या दिया गया हो, पुनर्वासन ग्रनुदान के प्रयोजनें के लिए ऐसे ग्रास्थान का स्वत्वाधिकारी (entitled) समभा जायगा।

८१ — अनुदान पाने का अधिकारी मध्य-वर्ती, अनुदान के देय हो जाने पर अनुदान के अवधारत किये और दिये जाने के लिए पुन-वासन अनुदान अधिकारी (Rehabilitation Grant Officer) को यथाशीच लिखित प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

८२-धारा ८१ के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित ब्यौरे दिये जायंगे:-- पुनर्वासन अनुदान पाने का ग्रव्धिकारी मध्यवर्ती

पुनर्वासन अनुदान के लिये प्रार्थना-

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र के व्यारे

- (क) ऐसे क्षेत्र में स्थित, जिसमें यह विधान लागु होता हो, प्रार्थी के सब श्रास्थानों के विवरण,
- (ख) ऐसे सब आस्थानें। को ग्रध्याय ३ के ग्रधीन ग्रवधारित पक्की निकासी,
- (ग) यह दिनांक, जिस पर या जिन पर प्रति-कर प्रन्तिम हप से अवधारित हुचा हो या प्राथीं को दिया गया हो और उस प्रतिकर को मात्रा,
- (घ) स्वत्वाधिकार के दिनाक से ठीक पहले के दिनांक पर पार्थी द्वारा उसके पूर्वोक्त प्रत्येक आस्थान के सम्बन्ध में निर्धारित या निर्धारित समभी गई मालगुजारी,
- (ङ) यदि प्रार्थी संयुक्त हिन्दू कुटुन्व का ग्रंग है। तो उसकी सीधी वंश-परम्परा में जीवित सब पुंजातीय सन्तित तथा पूर्वजों के नाम (the names of all his male lineal descendants or ascendants who are alive) भीर ऐसे ग्रास्थानों के, यदि कोई हों, ज्यौरे, जिनका इस विधान के ग्रंथीन हम्तगत किये जाने के कारण प्रतिकर अवधारित क्या गया हो या ऐसा किसी सन्तित या पूर्वज को दिया गया हो,
- (च) यदि प्रार्थी वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) हो, तां—
 - (१) वह वर्ग, जिसमें घारा ७८ के खंड (क) से (ग) तक के शब्दों में वह वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) चाता हो,
 - (२) उसकी समस्त सम्पत्ति श्रीर ग्रास्थानों से, चाहे वे इस विधान के ग्रधीन इस्तगत किये गये हो या नहीं, होने वाली कुल ग्राय,
 - (३) इस विधान के अधीन हस्तगत किए गए श्राह्थान या आस्थानों की अलग-अलग आया,

(४) धारा ७८ के खंड (ख) में आने वाले वक्फ, न्यास (trust)या निबन्ध (endowment) के विषय में.

उसको ऐसी ग्राय, सम्पत्ति ग्रीर त्रास्थान, जो पूर्णतः धर्मार्थं या पुरयार्थं अलग कर दिए गए हों, उपयोग में प्राते हैं। या उपयोग में आने के लिए हों ग्रीर उसकी ऐसी श्राय, सापति ग्रार ग्रास्थान, जो पूर्णंतः ऐसे प्रयोजनों के लिए ग्रलग कर दिए गए हों, उपयोग में माते हेां या उपयोग में ग्राने के लिए हों जो धर्मार्थ या पुरुवार्थ से भिन्न हों,

- (क्) वह अधिकार, जिसके **याधार** पर प्रार्थी अनुदान मांगता है।,
 - (ज) ऐसे दूसरे ब्योरे जो नियत किये जायं।

ऐक्ट ५, 2039

८३—धारा ८१ के ग्रधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र पर उस रोति से हस्ताक्षर ग्रौर सत्यापन (verification) किया जायगा, जो कोड ग्राफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में वाद-पत्रो (plaints) के हस्ताक्षरण और सत्यापन के लिये विहित किया गया है।

८४-(१) घारा ८१ के अधीन दिये जाने घारा ८१ के अधीन वाले प्रार्थना-पत्र के साथ एक (affidavit) स्वयं प्रार्थी का या यदि प्रार्थी यक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) हो या ग्रवयस्क (minor) श्रथवा ऐसा व्यक्ति हो, जो किसी ग्रम्य व्यावहारिक ग्रक्षमता से प्रस्त हो (suffering from any-other, legal disability), ता मृतवल्ली, न्यासी (trustee) प्रबन्धक (manager) या ग्रामिरक्षक (guardian) का, जैसी भी दशा हा, होगा गौर उसमें यह लिखा होगा कि इसके पहले ऐमा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया था और न दिया गया है और यह भो कि प्रार्थी की ग्रब तक इस विधान के निदेशों के प्रनुसार कोई पुनर्वासन प्रनुदान नहीं दिया गया है।

धारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र सत्यापन ग्रीर उस पर हस्ताकर

प्रार्थना-पत्र के माथ शपथ-पत्र का प्रस्तुत करना

(२) प्रत्येक ऐसे प्रार्थना-पन्न के साथ ग्रविकार-ग्रिमिलेख (record of right) के संगत उद्धरण (relevant extracts) ग्रीर प्रत्येक ऐसे ग्रास्थान के विषय में, जिन्मके सम्बन्ध में इस विवान के ग्रांचान प्रतिकर ग्रन्तिम इप से ग्रवधारित किया जा खुका है। या दिया जा खुका हो, प्रतिकर निर्धारण नालिका की प्रतिक्षिप है।गो।

प्रार्थना-पत्र में भूते यक्तत्य के िये ८५--यदि घारा दर में डिल्लिखित सत्यापन (verification) में के। ई व्यक्ति ऐमा दक्तव्य दे, जो मूठा हो और जिमे वह भूठा होना जानता है। या जिसके भूठा है। ने का उसे विश्वास है। या जिसके मता है। ने का उसे विश्वास न है। तो यह समभा जायगा कि उसने इस्डियन पोनल के। ड की धारा १६३ के अधीन दर्हनीय अपराध किया है।

पंकट ४५, १८६० ई०

धारा ८१ के अर्थान प्रार्थना-पत्र का प्रस्तकना ८६—घारा ८१ के अधीन प्रार्थना-पत्र ऐसे पुनर्वापन अनुदान अधिकारों का दिया जायगा, जिमके अधिक्षेत्र में प्रार्थी साधारणतः रहता हो तथा वक्फ, न्यास (trust), निवन्ध (endow-ment) या निगम (corporation) के विषय में, जहां उसका प्रधान कार्योळय हो।

स्पष्टोकरण—यदि प्रार्थी किसो भी पुनर्वा— सन अनुदान अधिकारों के अधिक्षेत्र में साधा— रणतः न रहता है।,ता प्रार्थना—पत्र किसो ऐसे पुनर्वासन अनुदान अधिकारों की दिया जायगा, जिसके अधिक्षेत्र में आम्थान स्थित है। या हों।

पार्थना-पत्र को सुग-बाई का दिनां क द७—(१) यदि प्रार्थना-पत्र यथोचित हप (proper form) में है। प्रौर यथावत् प्रस्तुत किया गया हो। ग्रौर ऐसी प्राथ-मिक जांत्र (preliminary enquiry) के बाद, जी नियत की जाय, पुनर्वामन ग्रनुदान ग्रियकारों की सम्तेष है। जाय कि उक्त प्रार्थना-पत्र की विचारार्थ ग्रहण करने के लिये (for entertaining) श्राधार है, तो वह उमकी सुन-वाई के लिये दिनांक निश्चत करेगा ग्रौर प्रार्थना-पत्र का तथा उसकी मुनवाई के लिए निश्चित दिनांक का ने।टिस—

- (क) प्राथि पर ग्रीर ऐसे व्यक्ति पर, जिसके। उसके विचार से प्रार्थना-पत्र का विशेष नेरिम दिया जाना चाहिये, तामील करा-एगा, ग्रीर
- (ख) ग्रपने कार्योलय के किसी प्रमुख भाग पर लगवाएगा।
- (२) किसो वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के विषय में पुनर्वासन अनुदान अविकारी गज़ट में और पेमी अन्य रीति से, जो नियत की जाय, एक सामान्य नेटिस (general notice) प्रकाशित करेगा, जिसमें सब स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के। उस्रदारी, यदि कोई हो, नियत समय के भीतर करने का आदेश होगा।
- (३) यदि किसी मध्यवर्ती की प्रतिकर निर्धारण तालिका में घारा ३८ के अधीन किये गये विवाद के विषय में कोई इन्दराज या कोई व्यक्ति घारा ३६ में अभिदिष्ट प्रकार के वाद या व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले वाद-पत्र या उच्चदारों की प्रमाणित प्रतिलिपि (certified copy) प्रस्तुत करे, तो यदि ऐसे वाद या व्यवहार के परिणाम से घारा १०० के अधीन अवधारित किए जाने वाले गुणक (multiple) पर प्रमाव पड़ने वाला है। या उसके पड़ने की सम्भावना हो, तो पुनर्वासन अनुदान अधिकारी उस पाथना-पत्र की सुनवाई स्थागत कर देगा (shall stay)।

८८—कोई स्वत्व रखनेवाला व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट दिनांक पर या उससे पहले पार्थना पंत्र के किसी इन्दराज की विशुद्धता या प्रकार पर ग्राक्षेप के रूप में, या उसमें किसी बात के छूट जाने के सम्बन्ध में, उज़दारी कर सकता है, यदि ऐसे इन्दराज या छूट का प्रभाव निम्नलिखित प्र पड़ता हो या. उसके पड़ने की सम्भावना हो— घारा प्रश्ने के अधीन प्रार्थना-पत्र पर उज्ज

- (क) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के ग्रन्तगत सम्पत्ति या ग्रास्थानों का ग्रवधारण,
- (ख) ऐसी सम्पत्ति या श्रास्थान का अव-धारण, जो धर्मार्थ या पुरुयार्थ अलग कर टी गई हो, उपयाग में आती हो या उपयाग में आने के लिए हो,
- (ग) ऐसे ग्रास्थान या सम्पत्ति की ऐसी ग्राय या ग्राय के भाग का ग्रवधारण, जो धर्मार्थ या पुण्यार्थ ग्रलग कर दी गई हो या उपयाग में ग्राती हो,
- (घ) प्रार्थी का देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा का अवधारण,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहां तक कोई उज्ञदारी ग्रास्थानें के सम्बन्य में अध्याय ३ के प्रधोन ग्रवधारित कच्ची या पक्को निकासी की मात्रा की ग्रुद्धता पर आक्षेप के रूप में होगो वहां तक वह शाह्य नहीं होगी।

षज्ञदारियों की राजि-स्ट्री ग्रीर फरीकों का ने।टिस दर—यदि पुनर्वासन अनुदान मांगने वाले एक से प्रधिक हों या यदि घारा दर के प्रधीन कीई उज़दारी की गई हो, तो पुनर्वासन अनुदान प्रधिकारी ऐसे दावों या उज़दारियों की (claims or objections) नियत रीति से रिजिस्टर में दर्ज करेगा और उससे सम्बन्ध रखने वाले फरीकों (parties) पर ऐसे प्रत्येक दावे या उज्जदारों की प्रतिलिप सिंहत नेाटिस तामील करके या कराके उन्हें आदेश देगा कि वे घारा द० के अधीन निश्चित किये गये सुनवाई के दिनांक पर उपस्थित होकर उसका उत्तर दें।

डज़दारियों की जांच श्रीरानक्तारण ६०—इस प्रकार निर्दिष्ट दिनांक पर या ऐस दिनांक पर, जिसके लिए सुनवाई बढ़ा दो गई है।, पुनर्वासन यनुदान अधिकारों दावों ग्रीर उन्नदा-रियां पर विचार ग्रीर उनका निस्तारण (dispose of) करेगा।

प्रबन्ध परिब्यय

६१—िकसी लेख्य (document) में या वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (indowment) के प्रशासन (administration) की ये। जना में किसा बात के रहते हुए भी पुनर्वासन अनुदान अधिकारी प्रबन्ध और यन्य पिन्य थें (charges) के निमित्त वही धनराशि या धनराशियां दिलाएगा जी नियत की जायं।

१२-- थारा ६२ के अथान प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र और धारा ८८ के अधान प्रस्तुत उज्जदारी का निर्णय करते समय पुनर्वासनग्रनुदान अधिकारी प्रत्येक ग्रास्थान के ऐसे हस्तान्तरण या बंटवारे को वैधता (validity) की जांच करेगा, जी धारा २४ और ३६ के निदेशों के प्रतिकृत प्रार्थी के पक्ष में या उसके द्वारा या उसकी ग्रोर से किया गया हो, और पुनर्वासन अनुदान के निमित्त प्रार्थी केंग देय धनराशि प्रख्यापित करने में वह ऐसे हस्तान्तरण या बटवारे ५र विचार नहीं करेगा। श्रास्थान के विषय में हुस्तान्तरण या बंदबारे की वेचता की जांच

६३—दावों गौर उज्जदारियों के निस्तारण के सम्बन्ध में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा दी गई ग्राज्ञा में ऐसे व्योरे होंगे, जो नियत किए जाय'।

ष्टजदारियों के निस्ता-रण के सम्बन्ध में ग्राज्ञा

९४—धारा ८८ के अधीन की गई उच्चदारियों के निर्णय के बाद तथा घारा ६२ के अधीन
जांच पूरी हो जाने पर पुनर्वासन अनुदान अधिकारी पार्थी के विषय में एक ऐसा विवरण तैयार
करेगा, जिसमें नीचे लिखी बातें दिखाई जायंगी :--

श्रास्थानों के विवरण

- (क) देसे क्षेत्र में स्थित, जिसमें यह विधान लागु हो, पार्थी के सब ग्रास्थानों के ज्योरे,
- (ख) ऐसे सब ग्रास्थानें की ग्रध्याय ३ के ग्रधीन ग्रवधारित पक्की निकासी,
- (ग) स्वत्वाधिकार के दिनांकसे ठीक पहिले के दिनांक पर ऐसे सब ग्रास्थानें के विषय में निर्धारित या निर्धारित सममी गई कुल मालगुजारी,

- (घ) यदि प्रार्थी संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का ग्रंग हो, तो स्व एसे आस्थाने के ब्योरे, जिनके विषय में प्रार्थी या उसके पुंजातीय सीधे वंशा कि प्रांचीय वंशा था पूर्वंज (male lineal descendants or ascendants in the male line of descent and ascent) की प्रतिकर देथ हो या दिया गया हो, ऐसे सब आस्थानों की ग्रध्याय र के ग्रधीन ग्रवधारित पक्की निकासी तथा पूर्वोक्त दिनांक पर ऐसे सब ग्रास्थानों के विषय में निर्धारित या निर्धारित सममी गई मालगुजारी, और
- (ङ) ऐसे अन्य ब्योरे जो नियत किए जार्य।

ध्र--वकफ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के विषय में धारा ९४ के म निवार किये जाने वाले विवरण में उस धर्म का उब्लेख हागा, जिसमें धारा ७८ के मधान किये गयं वर्गीकरण के मनुसार वह माना हां और यदि वह वक हा न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) उक्त धारा के वर्ग (ख) मं माता हो, तो निक्नलिखित और व्योशें का भी उल्लेख होगा :--

(या) असके अन्तगत सब सम्पत्ति और आस्थानां के व्योरे.

- (म्व) पेसी सम्पत्ति ग्रीर ग्रास्थान, जी-
- (१) ऐसे प्रयोजन के लिये पूर्णतः (exclusively) भलग कर दिए गए हैं।, जो धर्मार्थ या प्रयार्थ हैं।,
- (२) पेसे भयाजनां के लिए पूर्णतः मलग कर दिए गए हों, जे। धर्मार्थ या पुरवार्थ स भिम्न हों,
- (३) पुर्वेकित प्रयोजनें में से किसी के लिए भी पूर्णतः अलग न किए गए हों;
- (ग) श्रलग-अलग ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति या भास्थान से होने याली कच्ची भौर पक्की भाय,

वक्क, न्यास (trust) या निवन्ध (ondowment) के सम्बन्ध में विवरण

- (घ) खंड (ख) के उपखंड (३) में उख्ळिखित सम्पत्ति ग्रीर ग्रास्थानेंं से होने वाळी पक्की ग्राय के वे भाग, जी—
 - (१) धर्मार्थ या पुख्यार्थ, हीर
 - (२) धर्मार्थ या पुरवार्थ से भिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग में ग्राते हैं। या ग्राने के लिए हों;
- (ङ) पक्की आय के उस ग्रंश का, जिसका उल्लेख खंड (घ) के उपखंड (१) में है ग्रीर उस पक्की ग्राय का, जिसका उल्लेख खंड (घ) के उपखंड (२) में है, ग्रनुपात;
- (च) (१)—खंड (ख) के उपखंड (१) में डिल्लिखित आस्थानें की पक्की निकासी;
- (२) खंड (ख) के उपखंड (२) में उल्लिखित ग्रास्थानें को पक्की निकासी;
- (३) खंड (ख) के उपद्धंड (३) में उल्निबंधत पेसे पास्थानें। की पक्की निकासी, जिनकी , भाय धर्मार्थ या पुरुयार्थ उपयोग में प्राता है या माने के लिये हैं;
- (४) खंड (ख) के उपखंड (३) में ्र िल्लिखत ऐसे मास्थानों की पक्की निकासी, जिनकी माय धर्मार्थ या पुरवार्थ से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग में माती है या श्राने के लिख है:
- (क) ग्रास्थानां की ऐसी पक्की निकासी का जाड़, जो--
 - (१) धर्मार्थ या पुरवार्थ,
- (२) धर्मार्थ या पुरवार्थ से भिन्न प्रयोजनें के लिये, उपयोग में ग्रलग कर दी गयी हो, उप-योग में ग्राती हो या उपयोग में आने के लिये हो;
- (ज) खंड (क्क) के उपखंड (१) और (२) में यानेवाले यास्थानें के विषय में निर्माति या निर्धारित समभी गई मालगुजारी।

धारा ६५ के ग्रधनी मम्पत्ति के वर्गोकरण पौर पको निकासी के विभाजन के सिद्धान्त E4—धारा ९४ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति ग्रौर ग्रास्थानों के वर्गीकरण श्रौर उक्त धारा के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिये पक्की ग्राय के विभाजन (apportioning) करने में पुनर्वासन प्रनुदान अधिकारों निम्नलिखित का ध्यान रखेगा :—

- (क) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के संस्थापक की, यदि कोई इच्छा हो, ता उसका,
- (ख) सम्पत्ति और ग्रास्थानें। की ग्राय के उन भागों का, जो इन प्रयोजनें में सामान्य रूप से उपयोग किये और लगाये गये हो,
- (ग) न्याय (justice), साम्या (equity) श्रीर सद्विचार (good conscience) के सिद्धान्तों का।

ग्रास्थान की पक्की निकासी का विभाजन ९७—धारा ६४ के खंड (च) के उपखंड (३) गौर (३) के प्रशेतनें। के लिये उक्त धारा के खंड (ख) के उपखंड (३) में उिल्लिम्बित ग्रास्थानें। की पक्की निकासी का विभाजन करते समय पुनर्वासन श्रमुदान ग्रधिकारी पक्की निकासी की उक्त धारा के खंड (ङ) में डांइलिखत ग्रमुपात में बांडेगा।

धर्मार्थ या पुरवार्थ या अन्य प्रयोजनीं कं लिए आस्थानीं की मालगुजारी का अव-श्रारण ५८-- ऐसे यास्थानें के सम्बन्ध में, जिनकी स्राय--

- (क) धर्मार्थ या पुरवार्थ,
- (ख) धर्मार्थ या पुरवार्थ से भिन्न,

प्रयोजनें के लिये उपयाग में काती है। या उपयोग में काने के लिये हो, निर्धारित या निर्धारित समभी गई मालगुज़ारी भवधारित करने कं लियं धारा ६४ के खंड (ख) के उपखरड (३) में उल्लिखत सब ग्रास्थानें पर निर्धारित मालगुज़ारी उक्त धारा के खण्ड (ङ) में उल्लिखत मनुपात में बांटां जायगी।

६६—धारा ६४ के अधीन विवर्ष तैयार हो जाने पर पुनर्वासन व्युदान अधिकारी प्रत्येक मध्यवर्ती को देय पुनर्वासन अवुदान की मात्रा गवधारित करेगा।

पुनर्वासन अनुदान को मात्रा का अवधारण

१००--वनफ, न्यास (trust) या निबन्न (endowment) को दशा के। छोड़ और ऐसे न्यूनायिक सन्धानें (marginal adjustments) के साथ, जो नियत किये जायं, किसी मध्यवतीं को देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा धारा ६४ के स्थीन तैयार किथे गये विवरण में उक्लिखित पक्की निकासी और ऐसे गुणक का गुणनफल होगी, जो परिशिष्ट १ में दी हुई तालिका के अनु सार लागू है।

चनुदान की माश

१०१—वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) के दिख्य मे देय पुनर्वासन अनुदान की मात्रा िस्निलिखित होगी—

वक्फ, न्यास(trust), निबन्ध (endowment) के विषय में पुनर्वासन अनुदान की मात्रा

- (क) यदि वदफ, न्यास (trust) या निवन्ध (endowment) धारा अट में छित्सिखित वर्ग (क) में घाता हो, तो ऐसी वार्षिक चुत्ति (annuity), जो ऐसे वदफ, न्यास (trust) या निवन्ध (endowment) कं अन्तर्गत सभी धास्थानेंं को पक्की निकासी में से वदफ, न्यास (trust) या निवन्ध (endowment) की देय प्रतिकर पर २६ प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज घटाकुर बची धनर शि के बराबर हो,
- (ख) यदि वक्फ, न्यास (trust) या निबन्त्र (endowment) धारा ७८ में उल्लिखित वर्ग (ग) में आता हो, तें। वह धनराशि, जो धारा १०० में दिये गये। सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय,
- (ग) यदि वक्फ, न्याम (trust) या निबन्ध (end wment) धारा ७८ मे उक्लिखित वर्ग (ख) में प्राता हो, ता—
 - (१) घारा ६५ के खंड (इह) के उपखरह (१) में डिल्लिखित आस्थानें के सम्बन्ध में

ऐसा बाापक दृति, जो खण्ड (क) में टिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय,

(२) धारा ६५ के खरह (क्) के उपखंड (२) में उल्लिखित जास्थानें के सम्बन्ध में, पेसी धनराशि, जो धारा १०० में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार लगाई जाय।

कुक्क वर्गी की मध्यवर्तियों के विषय में पुनर्वासन ग्रनुदान १०२—मातहतदारों, ग्रदना मालिकों, दब्दमी काइतकारों श्रीर ग्रवध के दवामी पहे-दारों के विषय में दल श्रध्याय के निदेश ऐसे आनुषंगिक परिवर्तनों और परिब्कारों के साथ, जो नियत किये जायं, लागु होंगे।

ग्रपील

१०३--[%] घारा ८० के अधीन प्रार्थना-पश्र अखीकत करने की या धारा ९० के अधीन उच्च-दारी के निस्तारण की या धारा ६२, १०० या १०१ के अधीन दी गई पुनर्वासन अनुदान अधि-कारों को, आज्ञा के विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अधील हो सकेंगी।

(マ)[*]

पुनरोक्षण (revision)

१०३—इस बात के विषय में प्रवने सन्तीष के लिये कि घारा १०३ के अधीन प्रपील के निर्णय में दिस्ट्रिक्ट जात की माना विधि के प्रमुसार दी है या नहीं, हाईकेंग्डें उक्त अपील का प्रमिलेख (record) मंगा कर उस विषय में पेसी पाता दे सकता है, जी वह उचित सममे।

मालगुजारी की परिभाषा। १०४-क-इस अध्याय में "मालगुजारी" पद के अन्तर्गत मातहतदार, दवामी काशतकार तथा अवध में पहें दार इस्तमरारी द्वारा अवर स्वामी (superior proprietor) या स्वामी (proprietor) की, जैसी भी दशा है, देय लगान भी है।

यनुदान के भुगतान की प्रक्रिया १०५--यध्याय ४ के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ (mutatis mutandis) पुन-वासन अनुदान के भुगतान पर भी छागू होगे।

[[]अ] निकाल दिया गया।

१०६—(१) इस ग्रध्याय के निदेशों को कार्या-निवत करने के निये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकतो है। नियम वनाने का ग्रधिकार

- (२) पूर्वोक्त ग्रियकार को व्याप्ति के। बाधित न करते हुए ऐसे नियम निम्निलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—
 - (क) यह ग्रवधारित करने की प्रक्रिया कि कोई वक्फ, न्यास (trust) या निवन्ध (endowment) धर्मार्थ या पुरवाध है या नहां,
 - (ख) घारा ८१ के ग्रांन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का ग्राकार (form) ग्रीर प्रकिया,
 - (ग) घारा ५४ के ग्रधोन शपथ-पत्र का ग्राकार ग्रीर उसे अस्तुत करने की रोति,
 - (a) घारा ५७ के अधीन प्रकाशित होने वाले सामान्य नेटिस का याकार,
 - (ड) वह माकार भीर प्रकिया, जिसमें धारा देश भीर देद के अधीन उच्चदारियां प्रस्तुत का जायंगी,
 - (च) घारा ६० के प्रधोन की गई उच्चदा-रियों को सुनवाई और निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,
 - (क्) धारा ६१ के ग्रधीन दिलाये जाने वाले प्रबन्ध-परिज्ययों (management charges) के ग्रवधारण की रोति,
 - (ज) धारा ६२ के मधीन जांच की प्रक्रिया.
 - (म) वह आकार, जिसमें भौर वह रीति, जिसके अनुमार धाग ६४ और ६४ में उल्लिखित विवर्ण तथार किए जायंगे;
 - (ञ) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हैं श्रीर नियत किये जाय'।

ग्रध्याय ई

स्वान और स्वनिज पदार्थ (Mines and

Minerals)

खानें के संचालन का इस ग्रध्याय द्वारा नियमित होना १०७—इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी खानों की चलाने और उनसे खनिज पटार्थ निकालने का ग्रधिकार स्वत्वाधिकार के दिनांक से इस अध्याय के निदेशों द्वारा नियमित है।गा (shall be governed by)।

मध्यवतीं द्वारा चलाई जाने वाली खाने १०८--(१) स्वत्वाधिकार के दिनांक से ऐसी सब खाना के विषय मं, जो इस विधान के प्रधीन हस्तगत किये गये श्रास्थान या ग्रास्थानों के ग्रन्तगत हो श्रीर उक्त दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर चालू रही हैं। तथा जिन्हें मध्यवर्ती स्वयं चला रहा है।, मध्यवर्ती के ऐसा चाहने पर यह सममा जायगा कि वे प्रान्तीय सरकार द्वारा मध्यवर्ती के। पट्टे पर दे दी गई है श्रीर ऐसे मध्यवर्ती के। उन खानें के। पट्टे दार के नाते में श्रपने कब्जे में रखने का प्रधिकार होगा।

(२) प्रांतीय सरकार द्वारा दिये जाने वालं उक्त पट्टे की शर्तें और प्रतिबन्ध ऐसे हेंगे, जो गांतीय सरकार और मध्यवर्ती के बीच तय हो जायं या र्याद इस प्रकार तय न' हो पायें तो वे, जिन्हें घारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचा रक्त महदल (Minos Tribunal) तय कर दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे। सब प्रतिबन्ध और शतें खान चलाने के नये पट्टों के प्रदान (grant of now mining leases) की नियमित करने के लिये समय विशेष पर प्रचलित केन्द्रीय (Central) विधान (Act) के निदेशों के अनुसार होंगी।

खानों ग्रीर खनिज पदार्थी के चाल पटे १०६—(१) यदि ग्रास्थान या ग्रास्थाने। के स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले उक्त ग्रास्थान ग्रथवा उसके या उनके किसी भाग के, ग्रन्तगैत किसी खान या खनिज पदार्थी का कोई चालू पट्टा हो, तो पेसे पट्टे के श्रन्तगैत सम्पूर्ण

मास्थान या मास्थानों के मथवा उसके ा उनके उस भाग के विषय में यह समभा जायगा कि स्वत्वाधिकार के दिनांक से उस चालू पट्टे के पट्टे दो पट्टे के एंटे मिंग मिंग पट्टे के पट्टे के एंटे के पट्टे के उस पट्टे की सम्पत्ति अपने कन्जे में रखने का मांचिकार रहेगा।

(२) प्रान्तीय सर कार द्वारा दिये गये पूर्वीक पट्ट की शतें ग्रीर प्रतिबन्ध श्रावद्यक परिवर्तन के साथ वे ही होगी, जो उपधारा (१) में भ्रमिदिष्ट (referred) चालू पट्ट की थां; किन्तु उनमें एक प्रतिबन्ध यह श्रीर हे।गा कि यदि प्रांतीय सरभार का यह मत है। कि पट्ट दार ने इस विधान के प्रारम्भ के दिनांक से पहिले काई प्रन्वेषण (prospecting) या विकास (development) का नही किया है, तो प्रांतीय सरकार की श्रधिकार है।गा कि उक्त दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व िश्सी समय तीन मास का लिखत नोटिस देवर पट्टे को समान्त कर है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वर्तमान खान सम्बन्धो पहों के परिष्कार का नियमन (regulabing) करने वाछे समय विद्योष पर प्रचलित किसी केन्द्रीय विधान के निदेशों के प्रमुखार उक्त पहे की शतीं और प्रतिबन्धों में कोई परिष्कार करने में इस धारा में कहो गई कोई वात बाधक नहीं समभी जायगी।

(३) उपधारा (१) में सभिदिष्ट खान और खनिज पदार्थों के पहेंदार की यह अधिकार नहीं होगा कि भूतपूर्व मध्यवर्ती से इस साधार पर कोई अतिपूर्ति मांग सके कि उक्त खान कौर खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में ऐसे एध्यवर्ती द्वारा दिए गये पहें की शर्तें इस विधान का व्यापार प्रारम्भ (operation) है। जाने के कारण प्रा किये जाने के योग्य नहीं रह गई हैं।

स्नानें से सम्बद्ध इमा रतें ग्रीर भूमि

११०-यदि किसी गस्थान या चास्थानें के ग्रम्तर्गत खाने। ग्रौर खनिज पटाधीं का कोई पट्टा धारा १०८ या १०६ के कारण प्रांतीय सरकार द्वारा दिया हुग्रा समभा जाय, तो ऐशी सब इमारतें ग्रीर भूमि, जी ऐसे पट्टे के ग्रन्तर्गत न हैं।, उस भूमि के सहित, जिस पर खान सम्बन्धी काई निर्माण (works), मशीनरी, द्रामवे या साइडिंग (siding) स्थित हैं। ग्रास्थान या ग्रास्थानें। के स्वत्वाधिकार में जाने के दिनांक से प्रांतीय सरकार द्वारा पट्टेदार को पट्टेपर दे दी गई समभी जायंगी, चाहे वे उस श्रास्थान के अन्तर्गत हों या ऐसे जिसी दसरे आस्थान या ग्रास्थानें के अन्तर्गत हों, जो इस विधान के व्यापार (operation) में याने के कारण महामहिम के स्वत्वाधिकार में मा गए हों श्रीर पट्टे के मन्तर्गत खानें के चलाने और जनिअ पदार्थों के निकालने से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए पट टार के उपयोग ग्रीर कन्ते में है। ग्रीर पट दार की ग्रध-कार होगा कि ऐसो सब इमारतें और भूमि ऐसे उचित और न्याय (fair and equitable) लगान पर भ्रपने कब्जे में रखे, जो प्रास्तीय सरकार श्रीर पट्टे दार के बीच तय है। या यदि तय न हा, तो उस लगान पा, जिसे धारा १११ के अधीन नियुक्त खानिक विचारक मगहल (Minos Tribunal) निश्चित कर दे।

सानिक विचारक मण्डल १११—(१) धारा १०८, ११० और ११२ के प्रयोजनों के लिए नियुक्त प्रत्येक खानिक विचारक मरहल में एक अध्यक्ष (Chairman) और एक सदस्य होगा, जिनमें से पहिला कोई हिस्ट्रिक्ट जज और दूसरा कोई खान विशेषज्ञ होगा और दोनों प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायंगे।

(२) घारा १०८ के अधीन प्रान्तीय सरकार द्वारा किये गये पहें की हातों और प्रतिबन्धों के तय करने में खानिक विचारक मण्डल के। यह अवधारित करने का अधिकार रहेगा कि कितनी सम्पत्ति प्रांतीय सरकार द्वारा पहें पर दी गई समभी जाय। 4 1

- (३) विचारक मरहत उस प्रक्रिया का श्रनु-सरण करेगा, जो नियत की जाय।
- (४) यदि किसी विषय पर अध्यक्ष और सदस्य में कोई मतमेद हो, तो अध्यक्ष इस सम्बन्ध में चीफ जिस्टस द्वारा नामांकित (nominated) हाई कोर्ट के किसो जज के पास वह विषय अभि-देश (reference) के लिए भेज देगा और विचा-रक मंडल ऐसे जज के निर्णय से बाध्य होगा।
- ११२—(१) यदि घारा १०९ की उपधारा (२)
 में . डिल्डिखित म्रितिरक्त प्रतिबन्ध (additional condition) के मनुसार खानें या खनिज पदार्थीं का केई पट्टा प्रांतीय सरकार द्वारा समाप्त कर दिया जाय, तो समय से पूर्व पट्टे की ममास्ति के निमित्त पट्टेदार, प्रांतीय सरकार से ऐसा प्रतिकर पाने का मधिकारी होगा, जो प्रांतीय सरकार और पट्टेदार के बीच तय है। जाय या इस प्रकार तय न होने पर, जो धारा १११ के मधीन नियुक्त खानिक विचारक मंडल द्वारा अवधारित किया जाय।
- (२) उपधारा (१) के अधीन देय प्रतिकर अव-धारित करते समय विचारक मंडल और बातेंं के साथ उस मामले (transaction) के जेन्य या अजेन्य (genuine or otherwise) होने का और पेसे काल का, जिस तक वह पट्टा चालू रह जुका है, ध्यान रक्खेगा।

११३—प्रान्ताय सरकार इस अध्याय के प्रयोजनें का कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

समय से पूर्व खानें।
ग्रौर खनिज पदार्थी
की समाप्ति के
निमिन्न प्रतिकर

नियम बनाने का विश्व का विश्व का विश्व का विश्व कार्य कार्य

भाग २

ख्रध्याय ७

गांव-समाज श्रीर गांव-समा

११४—(१) प्रत्येक गांव के लिये ऐसे दिनांक गांव - समाज का या दिनांकों से श्रीर ऐसे नाम से, जो नियत किये स्थापना श्रीर निगमा-बायं, एक सतत श्रमुक्रम वाले (having per- करण petual succession) ऐसे गांव-समाज की स्थापना की जायगी, जो एक निगमित संस्था (body corporate) होगी घौर, किसी दूसरे विधायन (enactment) के। बाधित न करते हुए उसे यह भी सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (corporate name) से दूसरे पर वाट प्रस्तुत कर सके और दूसरा उस नाम पर उसके विध्द्व वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति की उपार्जित (aqcuire) कर सके, रख सके, उसका प्रशासन (administering) और हस्तान्तरण कर सके तथा संविदा भी कर सके; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार के निर्देशानुसार एक गांव मे ग्रधिक या कम के लिये भी एक गांव-समाज स्थापित हो सकेगा।

गांव समाज का निर्माण ग्रौर उसकी सदस्यता। (२) वह क्षेत्र, जिसके लिये कोई गांव-समाज स्थापित किया आय, मंडल (circle) कहलायेगा। ११४—गांव-समाज में ऐसे सब वयस्क (adult) व्यक्ति होंग, जो सम। विशेष पर—

- (क) उस मण्डल में माधारणतया निवास करते हों, जिसके लिये गांव-समाज की स्थापना हुई हो, या
- (ख) उस मण्डल में भूमिघर, सीरदार, ग्रसामी या श्राधवासी के नाते भूमि रखते हों।

(ग) [अ

स्पष्टीकरण (१)—यदि कोई व्यक्ति किसी
मंडल में सावारणतया ग्हता हो या उसमें उसके
कुदुम्ब के ग्हने का कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह
कभी—कभी रहता हो या उसमें रहने का उसका
कोई ऐसा घर हो, जिसमें वह जब चाहे तब रह
सके और जिसमें वह कमी—कभी रहता भी हो, ते।
यह सममा जायगा कि वह उस मरहल में सावा—
गणतया निवास करता है।

स्पष्टोकरण (२)—यदि कोई खाता, किसी न्यास (trust), संस्था (society) या इयक्तियों के किसी दूसरे संघ (association) के पास हो, या उसकी ग्रोर से किसी श्रीर के पास हो, तेा ऐसे न्यास (trust), संस्था या संब का प्रधान अधिकारो या कार्यकर्ता (functionary) इस धारा के प्रयोजनों के लिये खाते के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में भूमिधर, सीरदार, ग्रधिवासी या असामी सममा जायगा।

•११६—प्रान्तीय सरकार गज़ट में विज्ञप्ति गांव-समाज की सीमा-द्वारा-

ग्रों का परिवर्तन।

- (क) किसो ऐसे मरडल की सीमार्की की। जिसके लिये गांव-समाज स्थापित किया गया हो, बटल सकतो है, और
- (ख) किसी मण्डल के धन्तर्गत कुल क्षत्र या उसका कोई भाग किसी दूसरे मण्डल को संक्रामित कर सकती है।

११७-यदि प्रान्तीय सरकार--

(क) किसी क्षेत्र के। एक गांव-समाज के ग्रधिक्षेत्र से किसी दूसरे गांव समाज के यधिक्षेत्र में संकामित (transfer) कर दे, या

(ख) किसी क्षेत्र के। किसी गांव-समाज के अधिक्षेत्र में समिमलित कर दे या उसे किसी गांव-समाज के श्रधिक्षेत्र से निकाल दे,

तो वह ऐसी मानुषंगिक या पारिणामिक (incidental or consequential) uranu दे सकती हैं, जो ग्रावश्यक प्रतीत हो।

११८-धारा ६ में उल्लिखित विज्ञास्त प्रका-शित हो जाने पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे चलकर निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)--

- (१) समय विशेष पर किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि के। छोड़ अन्य सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,
- (२) गांव की सीमार्थों के भीतर स्थित सब जंगल,

गांव-समाज के ग्रधि-क्षत्र में परिवत ने के कारण आनुषंगिक ग्राज्ञायें।

कुछ भूमि ग्रादिका गांव-समाज के स्वत्धा-धिकार में ग्राना।

निकाल दिया गया।

- (३) खाते, वाग या ग्राबादो के पेड़ें। के। क्रोड़ ग्रन्थ सभी पेड़,
 - (४) सार्वजनिक कुषं,
 - (४) मीनाशय,
 - (६) हाट, बाजार और मेले,
- (७) तालाब, पाखर, निजी नाव-घाट, उट-प्रणालियां (water-channels), रास्ते ग्रांग भाबादा के स्थल (abadi sites),

जो मंडल में स्थित हाँ और इस विधान के अधीन महामहिम (His Majesty) के स्वत्वा-धिकार में पा गये हीं, उस मंडल के लिये स्थापित गांव-नमाज के स्वत्वाधिकार में या जायंगे:

किन्त गतिबन्ध यह है कि यदि [अ] प्रान्तीय सरकार की राय में किसी गांव में उस भूमि का क्षे फिल, जिलमें खेती न होती हो, गांव-समाज की साधारण बावइयकता ब्रों में ब्रधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार की प्रधिकार होगा कि उक्त भूमि के किसी भाग का, इस धारा के प्रधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में जाने से श्रहण रबखे और ऐसी ब्रानुषं गक बौर पारिणामिक (incidental and consequential) आजाप दे, जो प्रायश्यक हों,

गौर यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि किसी
नमय पूर्वोक्त कोई भूमि या वस्तु प्रान्तीय सरकार
हस्तगत कर छे, तो गांव-समाज के। उस प्रतिकर
के ग्रितिरिक्त, जो उसे उक्त भूमि में या उक्त भूमि
पर किए गए किसी विकास-कार्य के निमित्त प्राप्य
हो, हस्तगत किये जाने के निमित्त इस प्रकार
कोई ग्रीर प्रतिकर पाने का ग्रिधकार न होगा ग्रीर
न यह पायेगा।

गांव-सभा द्वारा भूमि पादि का अधीक्षण, प्रवन्ध ग्रीर नियन्त्रण। ११६—(१) इस विधान के निदेशों के। बाधित न करते हुए निर्दिष्ट दिनांक से गाव-सभा के। गांव-समाज के लिए घौर उनको घोर मे ऐसी सब भूमि, गांव की सीमामों के भीतर के जंगलें। (खातों, बागों या आवादी के ऐड़ों के। छोड़) ग्रन्य पेड़ों, सार्वजनिक कुंगों, मोनाशयों, तालावों, पेश्वरों, जल-प्रणालियों, रास्तों, ग्राबादों के स्थलों, हाटों तथा वाजारों गौर मेलों के, जो धारा ११८ के अधीन गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में ग्रा गये हीं, सामान्य ग्रधीक्षण (general superintendence), प्रवन्ध गौर नियंत्रण का भार सौंप दिया जायगा।

- (२) पूर्वे कित निदेशों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, गांव-सभा के कार्यों और कर्त्त व्यां के ग्रंतर्गत निम्नलिखित होंगे :--
 - (क) कृषि का विकास ग्रौर उन्नति,
 - (ख) जंगलें। ग्रौर पेड़ेंग [अ] की रक्षा, रख-रखाव ग्रौर विकास,
 - (ग) ग्राबादी के स्थलें ग्र<u>ौर गांव के गमनागमन मार्गी (village communica</u>— tions) का रख-रखाय ग्रौर विकास,
 - (घ) हाटों, बाजारों अगैर मेलें का प्रबन्ध,
 - (ङ) सहकारी खेती का विकास,
 - (च) पशुपालन का विकास,
 - (इ) खातों की चकबन्दी (consolidation of holdings),
 - (ज) गृह-उद्योगेां (cottage industries) का विकास,
 - (भ) मीनाशयों, कुग्रों ग्रौर तालाबें का रख-ग्खाव तथा विकास,
 - (ञ) [ঞ্চ]
 - (ट) ग्रन्य ऐसे विषय, जो नियत किए जायं।

१२०—धारा ११८ ग्रीर ११६ में किसी बात के रहते हुए भी, प्रान्तीय सरकार किसी समय गजट में विज्ञान्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले टिनांक से ऐसे हाट, बाजार, मेले, निजी नाव, घाट ग्रीर जल-प्रणालियां, जो इस विधान के पूर्वोक्त निदेशों

हाट, बाज़ार, मेले और निजी नाव, घाट पादि का हिस्ट्रिन्ट बोर्ड या दूसरे ग्राधिकारिकों के स्वत्वाधिकार में ग्राना।

के श्रनुसार गांव-समाज के स्वत्वाधिकार में ग्रा गये हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या निर्दिष्ट किए जाने वाळे किसी अन्य श्राधिकारिकी के। संकामित ही जाय'ने ग्रीर उसके स्वत्वाधिकार में चले जायंगे ग्रौर तब उस बार्ड या श्राधिकारिको पर इस विधान में किसी बात के रहते हथे भो, समय विशेष पर लाग की जा सकने वाली विधि के ग्रनुसार उसके प्रबन्ध, अधीक्षण और नियन्त्रण का भार द्वागा।

गांव-पंचायत के कर्ताच्या कार्य ग्रीर ग्रधिकार।

१२१--गाव-सभा के लिये और उसकी ग्रोर से गांव-पंचायत ऐसे कार्यों का सम्पादन करेगी. उसकी ऐसे ग्रधिकार प्राप्त होंगे ग्रीर वह ऐसे कर्ताव्यों का पालन करेगी, जी इस विधान के 👕 🖘 विधान के अधीन बने नियमा के द्वारा या मभ्यपित (assigned), दिये गये (confo या लगाप गये (imposed) हैं। १६४७ ई

भूमि-प्रबन्ध के लिप गांव-पंचायत को समिति।

१२२ - यूनाइटेड प्राविन्संज पंचायत ऐवट, १६४७ ई० में किसी वात के रहते हुए उक्त पेकट की धारा २९ के निटेशों के 🤻 प्रत्येक गांव -पंचायत ग्रागे चल कर की गई स्था के अनुसार अपने अधिक्षेत्र के प्रत्येक (circle) के छिये पक समिति (commit भूमि के प्रबन्ध श्रीर बंदे।बस्त से सम्बन्ध वाळे कर्त्तव्यों का पालन करने तथा पेसे कार्यों के लिए, जो नियत किए जायं, स्थ करेगी।

सं० प्राट पेक्ट २६. १६४७ ई

सं० प्रा॰

पेक्ट २६

समिति का संगठन

१२३--धारा १२२ के ऋघीन स्थापितः में गांव-पचायत के उस समय बाले ऐसे सदस्य होंगे, जो उस मंडल के हैं।, जिसके समिति स्थापित की गई है।

सं० प्रा० पेक्ट २६, १६४७ ई।

किन्त प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे सन् . को संख्या दस से कम हो, ता गांव-सभा के पेसे सटस्य, जो तत्सम्बन्धी मंडल के हों, गांव-समाज के सदस्यां में स इतने सदस्य चुन लोंग, जिन्हें मिलाकर समिति के सदस्यें। को संख्या दस हो जाय।

[[]अ] निकाल दिया गया।

१२४—समिति को अवाध (term) आकः हिमक रिक्तियों (casual vacancies) की भरा की रीति, उसके कार्य करने की प्रक्रिया और उसके कार्यों का संचालन (conduct of business ये सब नियत प्रकार के होंगे।

•• १२४—गांव-के।ष (Gaon Fund) में निम्न-लिखित जमा किये जायंगे :--

- (१) वह कुल धन, जो इस विधान के अधीन गांव-पंचायन या समिति की मिले, चाहे वह उसे अपने लिए मिला है। या गांव-समाज य गांव-सभा के लिए या उसकी और से,
 - (२) पेसा श्रौर घन, जो नियत किया जाय

१२६—यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत-राज ऐक्ट, १६४७ ई० की घारा ३२ में किसी बात के ग्हते हुए भी, गांव-पंचायत की अधिकार होगा कि नियत रोति के अनुसार गांव-केष (Gaon Fund) की इस विधान के अधीन अपने कर्त ब्यें। के पाल्का और कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होने वाले परिच्यों (charges) में लगांव,

किन् प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा या यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत-राज ऐक्ट, १६४७ ई० की किसी ात का ऐसा धर्य न होगा और न लगया जायगा, जिसके फलस्वरूप गांध-पंचायत किसी ऐसे धन को, जो प्रान्तीय सरकार के लिए या उसकी घोर से वस्त किया या उगाहा गया हो, उक्त उपयोग में ला सके।

१२७—(१) यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत-राज ऐक्ट, १६४७ ई॰ में किसी बात के रहते हुए भी, प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञायें ग्रौर निर्देश गांव-पंचायत या समिति को दे सकती है, जो इस विधान के प्रयोजनों के लिये गावश्यक प्रतीत हों

(२) गांव-पंचायत या समिति ग्रीर उसके पदाधिकारियों का यह कर्त व्य होगा कि तुरनत ऐसी ग्राज्ञायें कार्यान्वित करें ग्रीर ऐसे ।नदशों का पालन करें।

समिति की ग्रवि

इस विधान के ग्रधीः गांव-पंचायत द्वार प्राप्त द्रव्य का गांव कोष में स्मार केवन

गांव-काप का इस् विवान के सम्बन्ध में

गांव-पंचायत या समिति का प्रान्तीय सरकार की ग्राज्ञाओं ग्रोर निर्देशों की कुछ परिस्थितियों में गांव-पंचायत या समिति के कार्यों के निर्वहण करने की वैकल्पिक व्यवस्था।

१२८—(१) यदि किसो समय प्रान्तीय नर-कार को यह सन्तोष हो जाय कि—

- (क) गांव-पंचायत या समिति ने इस विधान के अधीन था द्वारा लगाय गए अपने कर्ना होता का पालन या दिये गये कार्या का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के न रहते हुए भी (without reasonable cause or excuse) नहीं किया है,
- (ब) ऐसी परिस्थित उत्पन्न हो गई है कि इस विधान के अधीन या द्वारा लगाए गए कत्त व्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में गांव पंचायत या समिति असमर्थ हो गई है या हो जा सकती है, या
- (ग) श्रीर कारकों से ऐसा करना उपयुक्त या ग्रावक्यक है,

तो गजट में विज्ञिष्त प्रकाशित करके यह प्रस्यापित कर सकतो है कि इस विधान के अवान गांव-पंचायत के कर्तांक्यों, यधिकारों ग्रीर कार्यों का पालन, प्रयोग ग्रीर सम्पादन पेस व्यक्ति या ग्राधिकारिक द्वारा ऐसी अवधि के लिए ग्रीर ऐसं निरोधों (restrictions) के साथ, जो नियत किए जायं, किया जायगा।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे ग्रानुसंगिक ग्रीर पारिणामिक निवेश बना सकती है, जो उसके। इस प्रयोजन के लिए श्रावश्यक प्रतीत हैं।

नियम बनाने का प्रधिकार।

- १२६—(१) प्रान्तीय मरकार के। अधिकार होगा कि इस अध्याय के निदेशों के। कार्याम्बित करहे के लिए नियम बनावे।
- (२) पूर्वोक्त ग्रधिकार की व्याप्ति के। बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्मिकिबित की स्ययमधा कर सकते हैं:--
 - (क) गांव-समाज के स्थापन से लम्बन्ध रखने वाली प्रक्रिया और कार्यवाही,

- (ख) धारा १२२ में डिल्डिखित सिमिति के लिए व्यक्तियों के चुनाव का संचालन (conduct) ग्रीर उक्त चुनाव के समय या सम्बन्ध में शंकाग्रों का समाधान तथा विवादों का निर्णय,
- (ग) गांव-पंचायत या समिति द्वारा अपने कत्तं क्यां का पालन, कार्यां का सम्पादन और अधिकारों का प्रयोग करने की रोति और प्रांक्या,
- (ध) इस विधान के प्रयोजनों के लिए गांव-के प (Gaon Fund) के उपयोग ग्रीर उसलें से छपया देने की रीति ग्रीर प्रक्रिया,
- (क) वे विषय, जिनके सम्बन्ध में और वह रीति जिसके अनुसार प्रान्तो । ्रिकार .स विधान में घारा १२७ के अधान गांव-पंचाय त या समिति की निर्देश दे,
- (स) धारा १२८ के अधीन गांव-पंचायत के कार्यों और कर्तांच्यें के किए जाने की वैकल्पिक व्यवस्था (alternative arrangement) की प्रक्रिया (procedure) और कार्यवादों (proceedings),
- (क्) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए हिसाब की बहियों (books of account), अन्य रिजस्टर और विवरण (statement) रखने की प्रक्रिया और माकार,
- (ज) इस विधान के प्रयोजनों के लिए गांव-पंचायत के वेतन-भागी सेवकों (paid employees) की नियुक्ति, नियंत्रख ग्रीर उनकी सेवागों की गन्य शर्ते,
- (क) इस विधान के प्रयोजनों के लिए गांव-पंचायत द्वारा किए जाने वाले पत्र-व्यवहार की रीति और लेखों (documents) और संविदाओं (contracts) का निष्पादन (execution),

- (ञ) गांव-पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध वादे। श्रीर व्यवहारीं का संचालन,
- (ट) इस भव्याय के निदेशों के। कार्यान्वित करने से सम्बन्ध रखने वाले किसी विषय में गांव-पञ्चायत, समिति या किसी सरकारो अधिकारी का सामान्यस्प मे पथ-प्रदर्शन (guidance), और
- (ठ) ऐस अम्य विषय, जो इस प्रध्याय के अधीन नियत किये जाने वाले हें या किये जायं।

अध्याय ८

मौमिक अधिकार (Tenure)

जातें। का वर्गीकरण

बातेटारां के वर्ग

१३०—इस विधान के प्रयोगितों के लिए खाते-दारों (tenure-holders) के निम्निलिखत वर्ग (classes) होंगे:—

- (१) भूमिधर,
- (२) सीरदार, ग्रौर
- (३) ग्रस।मी।

भ्मिधर

१३१—निम्नलिखित वर्गां में ग्राने वाला प्रत्येक व्यक्ति भूमिधर कहलाएगा और उसका वे सब ग्राधिकार प्रास्त होंगे श्रीर वह उन सब दायित्वां के श्रधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके ग्रधीन भूमिधरा का दिये गये हों या उन पर लगाये गये हों, ग्रधीत:—

- (क) पेसा प्रत्यक व्यक्ति, जो ग्रास्थानों के हस्तगत किये चाने के फलस्वरूप धारा १९ के श्रधीन भूमिधर हा जाय,
- (ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान के निदेशों के अधीन या अनुसार भूमियर के अधिकार प्राप्त कर छे।

१३२—निम्नलिखित वर्गों में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सारदार कहलायगा और उसका वे सब ग्रधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायित्वों

सीरदार

के ग्रधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा या इसके श्रधीन सीरदार के। दिये गये हैं। या उस पर लगाए गए हों, अर्थात्—

- (क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो आस्थानें के हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप धाग २० के प्रधीन सीरदार हो जाय,
- (ख) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस विधान के निदेशों के अनुसार खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दी जाय,
- (ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस विधान के निदेशों के भनुसार या प्रधीन किसो अन्य प्रकार से मीरदार के ग्रधिकार प्राप्त कर है।

१३३—घारा १३२ में किसी बात के रहते हुए भो किन्तु घारा २० के निदेशों की बाधित न करते हुए, निम्निलिखित भूमि में सीरदारी ग्रधिकार प्राप्त होगे:— वह भूमि, जिसमें सोर-दारी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे।

- (क) पशुचर भूमि (pasture land) या ऐसी भूमि, जिस पर पानी हो और जो सिंघाड़ा या दूसरी उपज पैदा करने के काम में आता हो या ऐसी भूमि, जो नदा के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में याती है।,
- (स) ग्रस्थर (shifting) या ग्रस्थायी (unstable) खेती के ऐसे भूषंड, जिन्हें प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञति द्वारा निर्दिष्ट कर दे, ग्रीर
- (ग) ऐसी भूमि, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गज़ट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टैांगिया रीति से वन लगाने का विचार है या वह इसलिये भलग कर दी गई है।

१३४—निम्निलिखित वर्गों में याने वाला प्रत्येक ब्यिक ग्रसामी कहलायगा और उसका वे सब अधिकार प्राप्त होंगे और वह उन सब दायिखों के भ्रधीन रहेगा, जो इस विधान द्वारा था

षसामी

्सके ग्रधीन असामी का दिये गये हों या उस वर लगाये गये हों, ग्रधीत्—

- (क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर के कि भूमि—
 - (१) मध्यवर्ती के बाग के गैर-द्वीलकार काश्तकार (non-occupancy tenant) के नाते,
 - (२) बाग भूमि के शिकमी (subtonant) के नाते,
 - (२=क) यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनैसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १६४७ की घारा २७ की उपधारा (३) के प्रतिबन्धात्मक अनुच्छेद (Proviso) के अधीन शिकमी काश्तकार के नाते,
 - (३) धारा २० में कहे गये (१) से (८) तक के वर्गों में से किसी में ग्राने वाळे व्यक्ति के बंधकी (mortgagee) के नाते,
 - (४) धारा १४ के प्रनुसार भरण-पोषण के यदले में,
 - (५) पशुचर-भूमि या ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काइतकार के नातं, जिसमें पानी हो और जी सिंधाड़ा या अन्य उपज पेटा करने के काम में घाती हो या जो किसी नदी के तल में हो और कभी-कभी खेती के काम में शाती हो,
 - (६) ऐसी भूमि के गैर-द्खीलकार काइत-कार के नाते, निसे प्रान्तीय सरकार ने उत्त दिनांक के पहिले गजट में विश्वदित द्वारा श्रद्धिर श्रीर अस्थायी (shifting and unstable) खेती के भू-खण्ड का भाग धरुयापत कर दिया हो,
 - (७) ऐसी भूमि के गैर-द्योलकार काइतकार के नाते, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने उक्त दिनांक से पहले गजट में विश्वप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो कि

उम्ममें टैांगिया रीति से बन लगाने का विचार है या बह इमिलिये एलग कर दी गई है,

- (८) ऐसे ठेकेदार के नाते, जिसके विषय में घारा १४ की उप गरा (२) के खड़ (क) में व्यवस्था की गई है,
- (ख) ऐसा पत्थेक व्यक्ति, जिसे इस ऐक्ट के निदेशों के पनुसार किसी भूमिधर या सीरदार ने अपने खाते के अन्तर्गत भूमि पह पर उठा टी हो,
- (ग) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्वत्वाविकार के दिनांक पर या उसके बाद गांव-सभा ने या ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसा करने का ग्रधि-कार हो, धारा १३३ में वर्णित भूमि पट्टे पर उठा दो हो, और
- (घ) एस। प्रत्येक व्यक्ति, जो स्वत्वाधिकार काद्रनाक पर या उसके बाद इस विधान के निदेशों के ग्रधान ग्रसामी के अधिकार प्राप्त कर छ।

भूमिघरी अधिकार उपार्जन

१३५--(१) यदि कोई खाता संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ ई॰ की धारा ३ में उल्लिखित (क) से (घ) तक के वर्गी में से किसी में आने वाले दो या अधिक व्यक्तियों के पास रहा हो और उक्त विघान की घारा ६ के अधीन कोई प्रख्यापन संयुक्त रूप से उन सब के पक्ष में न होकर उनमें से एक या अधिक के ही पक्ष में हो, तो उक्त प्रख्यापन केवल इसलिए हो अवैध न समझा जायगा कि वह खाते के एक भिन्नात्मक अंश (fractional share) के ही सम्बन्ध में हुआ है और उक्त विधान के निदेश, उसमें किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार पढ़े जायेंगे और उनका इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो परिशिष्ट २ में दिए संशोधन उसमें कर दिए गए थे और उक्त विधान के प्रारम्भ से ही प्रचलित थे।

(२) संदेहों के निराकरण (removal of cloubts) के लिए यह प्रख्यापित किया जाता है कि उक्त विधान के अधीन और उसके प्रचलन के काल में किसी समय जो आज्ञाएं दी गई होंगी, जो कार्यवाहियां

थू॰ पी॰ ऐक्ट १०, १६४६ ई० के अन्तर्गत संयुक्त खाता में भूमिघरी अधिकार उपार्जन करना। की गई होंगी, जिन प्रख्यापनों का प्रदान हुआ होगा तथा जो अधिक्षेत्र प्रयोग में लाए गए होंगे वे सब उसी प्रकार ठीक (good) और वैध (vulid in law) समझे जायंगे मानों उक्त विधान उपधारा (१) द्वारा संशोधित रूप में सभी प्रभावी दिनांकों (material

dates) पर प्रचलित था।

१३६—[क्ष १३७---[६ १३८—[ध्

₹3E..... \$B]

ऐक्ट के प्रारम्भ के बाद भूमिधरो श्रधि-कारों के उपार्जन के लिये प्रार्थना-पत्र। १४०—यि प्रान्तीय सरकार द्वारा विज्ञापित किये जानेवाले दिनांक से तीन मास समाप्त होने से पहले किसी समय धारा १३२ के खंड (क) में उल्लिखित वर्ग वाला सीरदार ऐसी भूमि के लिये, जिसका वह सीरदार हो, प्रान्तीय सरकार को स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर देय या देय समझे जाने वाले लगान का दस गुना वे दे तो, परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को उस विषय में यथावत् प्रार्थना—पत्र देने पर उसको इस बात का प्रस्थापन पाने का अधिकार होगा कि उसने ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा १४३ में उल्लिखित अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

धारा १४० के ऋधीन प्रार्थना-पत्र के साथ खजाने का चालान। १४१—— बारा १४० में अभिविष्ट प्रार्थना—पत्र के साथ खजाने (treasury) का चालान रहेगा, जिससे यह व्यक्त हो कि पूर्वोक्त धनराशि जमा कर वी गई है और उसमें उस अधिकार का भी संक्षिप्त वर्णन रहेगा, जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त भूमि को अपनी क्तलाता हो।

धारा १४० के ग्रन्तगैत धनराशिका जमा करना।

१४२—यिव कोई सीरवार या उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी (predocessor in interest) स्वत्वा-धिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर खाते का मौकसी कारतकार रहा हो तो घारा १४० के अधीन जमा की जाने वाली घनराशि, इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी, उसके द्वारा देय लगान की, और यदि उक्त देय लगान लागू मौकसी वरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो, तो इस प्रकार लगाए गए लगान की दुगनी धनराशि की ही, दस गुनी होगी।

प्रमाख-पत्र का दिया जाना। १४३—(१) यदि प्रार्थना—पत्र यथावत दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर को यह सन्तोष हो जाय कि प्रार्थी बारा १४० में उल्लिखित प्रस्थापन का अधिकारी है, तो वह उसे इस बात का प्रमाण-पत्र दे देगा।

^[\$] निकाल विया गया

- (२) उपधारा (१) के अधीन प्रमाण-पत्र दिये जाने पर उसके दिनांक के ठीक याद के कृषि-वर्ष के प्रारम्भ से सीरदार--
 - (क) उस खाते या खाते के अंश का, जिसके सम्बन्ध में उक्त प्रमाण-पत्र दिया गया हो, भूभियः हो जायगा और हुआ समझा जायगा, और
 - (ख) [अ] उस खाते या उसमें के अंध ही माल-गुजारी के निमित्त ऐसी कम की हुई घनराशि का देनदार होगा, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके लिये देय या देय समझे जाने वाले लगान की आधी हो।

स्पष्टीकरण—यदि उपरोक्त दिनांक पर किसी सोरदार द्वारा देय लगान लागू मौक्सी दरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो, तो उसके द्वारा देय लगान खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार लगाए के लगान की दुगनी धनराशि के बराबर ही समझा जायगा।

१४३—(क) यंदि कोई व्यक्ति बारा १९ या धारा १४० के अभीन किसी ऐसे खाते के एक अंश के सम्बन्ध में भूमिश्वर हुआ है, जो उसके पास दूसरे या दूसरों के साथ में, जो सीरदार है, संयुक्त रूप से रहा है, तो उक्त भूमिश्वर, खाते में अपने अंश के बंटवारे के लिए बाद प्रस्तुत कर सकता है और बंटवारा हो जाने पर उसके अंश में जो भूमि पड़ेगी उसका वह भूमिधर समझा जायगा।

भूगिधरी श्रिष्कारी कं पात होने पर जात का बंटवारा

१४४-- चारा १४०, १४१ और १४३ के सब निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ घारा १३२ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग के सीरदार को लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रान्तीय सरकार को देय धनराशि उस मालगुजारी की दतगुनी होगी, जो खाता मिलने पर उसके द्वारा देय हो और उक्त धनराशि खाता मिलने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय दी जा सकेगी.

और यह भी प्रतिबन्ध है कि घारा १४३ में अभि-विष्ट प्रमाण-पत्र मिलने पर देय मालगुजारी उस मात्रा तक कम कर दी जायगी, जो खाते के मिलने पर देय माल-गुजारी की घनराशि की आधी हो। धारा १३२ के खंड (ख) में उल्लिखित वर्ग के सीरदार का भूमिधरी अधिकार उपाजन करना।

भूमि का उपयोग और उन्नति

भूमिधर का ऋपने स्नाते की कुल भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार।

उद्योग या निवास के प्रयोजनां के लिये जात का उपयाग १४५—इस ऐक्ट के निदेशों पर उपाधित रहते हुए, भूमिघर को ऐसी सब भूमि पर, जिसका वह भूमिघर हो, एकान्तिक (exclusive) क्रब्जे का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि जिस प्रयोजन में चाहे उसमें उसका उपयोग कर सके।

- १४६—(१) भूमिधर, जो अपने खाते या उसके किसी भाग को उद्योग या निवास के प्रयोजन के लिए (for industrial or residential purposes) काम में लाता हो, कलेक्टर से इस बात के प्रख्यापन के लिए प्रार्थना कर सकता है और कलेक्टर ऐसी जांच के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, संतुष्ट हो जाने पर तदनुसार प्रख्यापन दे देगा।
- (२) उपधारा (१) मे उिल्लिखित प्रख्यापन के प्रदान पर (इस धारा से भिन्न) इस अध्याय के निर्देश ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उनत भूमिधर की लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तरा—धिकार के विषय में ऐसी व्यक्तिगत विधि (per—sonal law) से, जिसके वह अधीन हो , नियमित होगा।

कृषि के लिये भूमि

- १४७——(१) यदि किसी भूमिघर के पास की कीई भूमि, जो कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले प्रयोजनों के लिए उपयोग में न आ रही हो, ऐसे प्रयोजनों के लिये उपयोग में आने वालो भूमि हो जाय, तो कलेक्टर, यदि उन्हें इस बात का संतोष हो जाय, इस बात का प्रख्यापन कर सकते हैं और तदुपरान्त भूमिघर उक्त भूमि के सम्बन्ध में इस अध्याय के निवेशों के अधीन होगा।
- (२) उपवारा (१) के अधीन किसी भूमि के वार में प्रख्यापन प्रदान हो जाने पर भूमिषर भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके क्रब्जे में उक्त गाटा (plot) हो—
 - (क) यदि वह भूमि उसके पास किसी ऐसी संविदा या पट्टे के अधीन हो, जो इस अध्याय के निदेशों से असंगत (inconsistent) हो, सो वह ऐसा क्राबिज समझा जायगा, जो धारा २०६ के अधीन बेदलक हो सके,

(स) यदि वह भूमि उसके पास किसी ऐसी संविदा या पट्टे (contract or lease) के अधीन हो, जो इस अध्याय के निदेशों से असंगत न हो, तो वह उकत भूमि में ऐसे अधिकारों का अधिकारी होगा, जो उक्त संविदा या पट्टे के निदेशों के अनुसार अवधारित किये जायं,

(३) उपघारा (२) के उपखंड (क) में अभिदिष्ट ऐसा पट्टा या संविदा, जो इस अध्याय के निदेशों से असंगत हो, प्रख्यापन के दिनांक से बहुां सक ध्यर्थ (void) हो जायगा जहां तक वह असंगत हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी भूमि का भोगबंबक (mortgage with possession) उस देय चनराशि के लिये, जो उस भिम द्वारा सुरक्षित की गई हो, ऐसे ब्ष्टिबन्धक (simple mortgage) में परिवर्तित समझा जायगा, जिस पर ऐसी दर से ब्याज चलेगा, जो नियत की जाय।

१४७-क-धारा १४६ और १४७ के अधीन विए गए प्रत्येक प्रख्यापन की एक प्रतिलिपि कलेक्टर द्वारा तत्सम्बन्धी सब-रिजस्ट्रार को भेज दी जायगी और वे, इंडियन रिजस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ ई० में किसी बात के रहते हुए भी, उसे बिना शुल्क और नियत शित से निबंधित (register) कर लेंगे।

१४८—इस ऐक्ट के निदेशों पर उपाश्रित रहते हुए, सीरदार या असामी को अपने खाते के अन्तर्गत सभी भूमि पर एकान्तिक क्रब्जा (exclusive possession) का अधिकार होगा और उसकी यह भी अधिकार होगा कि वह कृषि, फलोत्पादन या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये उस भूमि का उपयोग करे और उसमें किसी प्रकार की उन्नति करे;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भूमि, जिसके विषय में प्रान्तीय सरकार ने गजट में विज्ञिष्त द्वारा यह प्रख्यापित कर दिया हो कि उसमें टोंगिया रीति से बन लगाने का विचार हैं या वह उसके लिए अलग कर वी गई ह, उसके असामी द्वारा किसी ऐसे उपयोग में नहीं लाई जायगी, जो खेती की फसल बोने के प्रयोजनों मे भिन्न हो।

१४८-क-सीरदार या असामी कोई ऐसी उन्नति न कर सकेगा, जो किसी ऐसी भूमि पर हो, या किसी ऐसी भूमि के लिए हानिकारक हो, जो उस खाते के अन्तर्गत न हो, जिसको उस उन्नति द्वारा लाभ पहुँचाना अभिन्नेत है, जब तक ऐसी भूमि के खातेदार घारा १४६, १८७ कं अन्तर्गत की गई घेषिणा का निबंधन

सीरदार या असामी का अपने खाते की भूमि पर एका न्तिक कब्जे का अधिकार।

उन्नति के कार्यां में प्रतिबन्ध की या जहां एसी भूमि किसी खाते का भाग नहीं है, तो गांव-सभा को लिखित अनुज्ञा (willton permission) न मिल जाय।

श्चन्य भूमिको उन्नति केकार्य।

१४८-ख--(१) यदि खातेदार ने भूमि पर कोई उन्नति की हो ओर ऐसी भूमि मालगुजारी की बक्ताया मे या रुपये को किसी डिक्री के निष्पादन जाय या खातेदार ऐसी भूमि से बेदखल हो जाय, तो ऋता purchaser) या क्षेत्रपति holder), जैसी भी दशा हो, उक्त अधिपति (owner) हो जायगा, भूमि मे. खातेदार ऐसो जो सम्बन्ध उसके क्रब्जे में बच रही हो, उपत उन्नति से पहुँचने लाभ का उतना ही ौर उसी प्रकार अधिकारी और जिस प्रकार उरा उन्नति द्वारा रहेगा जितना उसे अब तक लाभ पहुँचता रहा है।

(२) यदि खातेदार ने ऐसी भूमि पर कोई उस्न ति की हो, जो मालगुजारी की बकाया में या किसी न्यायालय हारा वी गई रुपये की किसी डिकी या आज्ञा के निष्पादन में उसके किसी भाग के बिक जाने के बाद या अपनी भूमि के किसी भाग से उसके बेदखल हो जाने के बाद, उसके क्रब्जे में बच रही हो, तो केता या क्षेत्रपति, जैसी भी दशा हो, उस भूमि के सम्बन्ध में, जो खातेदार के क्रब्जे में नहीं रह गई है, ऐसी उन्नति के लाभ का उतना ही और उसी प्रकार अधिकारी होगा जितना और जिस प्रकार उस उन्नति हारा ऐसी भूमि की अब तक लाभ पहुँचता रहा है।

श्रसामी द्वारा की गई उन्नति के लिये प्रति-कर पाने का श्रिधि-कार। १४९—(१) असामी को, जिसने गांव-सभा वा क्षेत्रपति की, जैसी भी दशा हो, लिखित सहमति से कोई उन्नति की हो, निम्निक्षित दशाओं में, प्रतिकर पाने का अधिकार होगा :—

- (क) जब (धारा १६५ या २०३ में चिल्लिखित आधारों के अतिरिक्त) धारा २०० में चिल्लिखित किसी आधार पर कोई बेदेखली की डिकी या आजा हो गई हो;
- (क) जब वह गांव-सभा या अपने क्षेत्रपति (land-holder) द्वारा, जैसी भी दशा हो, अवैध रूप से बेदखल कर दिया गया हो और उसने अपने खाते पर कब्जा वापस न पा लिया हो; या

- (ग) जब वह खंड (क) में उल्लिखित आघारों में से किसी आधार पर बेदखली का भागी (liable to ejectment) हो जाने पर या अपने पट्टे की समाप्ति पर खाते को छोड़ दे।
- (२) असामी को उस दशा में कोई प्रतिकर न दिया जाएगा जब उसने पूर्वीक्त लिखित सहमित के बिना कोई उन्नति की हो।

१५०-- उन्नति के लिये प्रतिकर की धनराशि प्रतिकर की माश का अवधारित करते समय नीचे लिखी बातों पर ध्यान रक्खा जावेगा:--

ग्रवधारण।

(क) निर्माण की लागत,

(ख) निर्माण की दशा और वह अवधि, जिसमें खाते के मल्य में उसके द्वारा वास्तविक वृद्धि होते रहने की सम्भावना हो।

(ग) निर्माण द्वारा खाते की उपज के मूल्य

या परिमाण में होने वाली वृद्धि की मात्रा,

(घ) वह अवधि, जिसमें प्रतिकर मांगने वाला असामी उन्नति का लाभ उठा चुका हो, और (इ) पेड़ों की आयु, उनका वर्ग और उनसे हो सकने वाली आय।

- १५०-क--(१) किसी असामी की बेदखली के लिए लाए गए किसी वाद या व्यवहार में, यदि उन्नति के लिए कोई प्रतिकर देय हो, तो न्यायालय बेदखली की कोई डिकी या आज्ञा देने के पूर्व घारा १४९ के अधीन असामी को देय प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करेगा।
- (२) यदि प्रतिकर की मात्रा उस धनराशि से अधिक हो, जो खाते के सम्बन्ध में असामी से, यदि कोई वाद-व्यय देय हो तो उसके सिहत, बकाया लगान के रूप में, चाहे उसकी डिकी हुई हो या नहीं, वसूल की जा सकती हो, तो बेदखली की डिकी या आज्ञा इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि क्षेत्रपति या गांव सभा उक्त काइतकार द्वारा प्राप्य अवशेष (balance) ऐसे के भीतर, जो न्यायालय निर्दिष्ट कर दे, उस काइतकार को देदे।
- (३) यदि प्रतिकर की मात्रा असामी से वसूल की जा सकने वाली उस धतराधि से अधिक न हो, जो उपधारा (२) में उल्लिखित है, तो उसकी बेदखली हो जाने पर यह समझा जायगा कि उक्त प्रतिकर का भुगतान हो गया और (balance) घारा २०० (क) के निदेशों को बाधित न करते हुए उस असामी से वसूल किया जा सकेगा।

हस्ताम्तर ग

भूमिधर के स्वत्वेां का ग्रम्तरणीय होना। १५१--इस अध्याय में आगे दिये गये प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुए, भूमिधर का स्वत्य हरतान्तरणीय (transforable) होगा।

मीरदार या ग्रमामी के स्वत्वें फा ग्रन्तरणीय न होना। १५२--उस दशा को छोड़, जिसमें इस विवान द्वारा स्पष्ट रूप से अन्ता दी गई हो, सीरवार या असामी का स्वत्व हस्तान्तरणीय न होगा (shall not be transferable)।

भूमिथर के ग्रम्तरसा-धिकार पर निगेध। १५३—किसी भूमिधर को कोई भूमि विकय या दान द्वारा (पृण्यार्थ स्थापित संस्था से भिन्न) किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार न होगा, यदि ऐसा व्यक्ति उक्त विकय (sale) या दान (gift) के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी हो जाय, जो उस भूमि से मिलकर जो उसके पास, चाहे अकेले चाहे अपने अवयस्क पुत्र या अन्य अवलम्बी अथवा उसके साथ रहने वाली पत्नो या साथ रहने वाले पति के साथ, संयुक्त प्रान्त में ३० एकड़ से अधिक हो जाय।

ामियर का भूमि के। बन्धक रखना।

१५४—कोई भूमिवर अपनी ऐसी भूमि का, जिसका वह भूमिपर हो, इस प्रकार का बन्धक न कर सकेगा, जिससे दिये गये या दिये जाने वाले रुपये की सुरक्षा के लिए बन्धक की हुई भूमि में बन्धकी को क़ब्जा दिया जाता हो या भविष्य में दिया जाने वाला हो।

भूमि का लगान पर उठाया जाना।

१५५—उन दशाओं को छोड, जिनकी व्यवस्था घारा १५६ में की गई ह, किसी भूमिघर, सीरदार या असामी को किसी भी काल के लिये अपने खाते की कोई भूमि लगान पर उठाने का अधिकार न होगा।

ग्रक्षम व्यक्ति का भूमि का लगान पर ज्ठाना

- १५६--(१) ऐसा भूमिथर या सीरदार जो--
 - (क) स्त्री,
 - (ख) अवयस्क (minor),
 - (ग) पागल या जड़,
- (घ) ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन, दाहण रोग या अन्य शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम (incapable) हो,
- (ड) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो,

- (च) भारत की स्थल सेना, नौसेना या वायु-सेना सम्बन्धी सेवा में हो, अथवा
- (छ) निरोधन (dutention) या कारावास में हो अपना कल खाता या उसका कोई भाग लगान पर उठा सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो और वे सभी खंड (क) से (छ) तक में उल्लिखित अक्षमताओं के अधीन न हों, किन्तु उनमें से एक या अधिक ही उक्त अक्षमताओं के अधीन हों तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिकार है कि खाते में अपना अंश लगान पर उठा दें।

(२) यदि उपवारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य (proviso) के अधीन खाते का कोई अंश लगान पर उठा दिया गया हो तो असामी या खातेदार की प्रार्थना पर न्यायालय उठाने वाले का अंश अवधारित करके खाते का बटवारा कर सकता है।

(न्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ पट्टे का नियम्धन। रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९०८ में किसी बात री, एक वर्ष से अधिक अविध के लिये, या वजानुकर्म from year to year), पट्टा रजिस्टडं करण (instrument) द्वारा अथवा नियत रीति से, किया जा सकता है।

१५८--केवल इसलिये कि उसके सम्बन्ध में घारा १५७ के निदेशों का पालन नहीं हुआ है, घारा १६५ के प्रयोजनों के लिए किसी पट्टे के विषय में यह नहीं समझा जायगा कि वह इस विधान के निदेशों के प्रतिकुल हस्तान्तरण है।

धारा १५७ के ग्रान पट्टे का निबन्धन न होना।

१५९--यदि कोई खाता घारा १५६ के निदेशों के अनुसार उठाया गया हो तो, भू मिवर या सीरदार के, जैसी भी दशा हो, स्वत्व का उत्तराधिकारी (successorin-interest) पट्टे की शतों से जहां तक वे इस विधान के निदेशों के प्रतिकृत न हों, बाध्य होगा।

भ्वत्व के उत्तराधि-कारी का पट्टे ने बाध्य होना।

१६०--(१) कोई भूमियर या सीरदार अपनी घटना-व उली। उस भूमि को, जिसका वह भूमिषर या सीरदार हो, किसी अन्य भूभियर या सीरदार से बदल सकता है ;

किन्तु प्रतिजन्य यह है कि ऐसी कोई बदलाई, जिसके परिणामस्वरूप उसके किसी फरीक की भूमि ३० एकड़ से अधिक हो जाय, वैध (valid) नहीं होगा।

(२) उपचारा (१) के अनुसार बदलाई होने पर बदले में मिली भूमि में वे ही अधिकार होगे, जो बदले में दी गई भूमि में थे।

१६१--दस प्रकार बदली गई भू सियों पर निर्घारित या उनके लिए देय मालगुजारी की धनरागि पर घारा १६० की किसी बात का प्रभाव नहीं होगा।

१६२—(१) यदि किसी खाते या उसके भाग का हस्तान्तरण धारा १५३ के निदेशों के प्रतिकूल किया गया हो तो,
वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण हुआ हो, किसी विधि
में किसी बात के रहते हुए भी, गांव—सभा के वाद पर ऐरो
खाते या भाग से बेदखल हो सकेगा और तब वह भूमि खाली
भूमि हो जायगी, किन्तु इस धारा म कही गई कोई बात,
देने से शेष रह गए कुल मूल्य या उसके भाग को वसूल करने
के हस्तान्तरण कर्ता के अधिकार को, या जिसके पक्ष में हस्ता—
न्तरण किया गया है उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को यदि
ऐसे खाते या भूमि के प्रति कोई दावा है तो उसके उस दावे
को कार्यान्वित करने के लिये व्यवहार में लाने के अधिकार
को, बाधित न करेगी।

(२) इस धारा के अधीन बेदखली के प्रत्येक वाद में हस्तान्तरणकर्ता फरीक बनाया जायगा।

१६३ [*] किसी भूमिधर द्वारा किया गया किसी खाते या उसके भाग का ऐसा हरतान्तरण जिसके द्वारा उपार दिए गए या दिए जाने वाले रुपए की तथा वर्तमान या भविष्य ऋण की अदायगी को, या किसी ऐसे अनुबन्ध के सम्पादन (engagoment) कोई आर्थिक दायित्व उत्पन्न होता हो, सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिये हस्तान्तरणी को कब्जा हस्तान्तरित किया जाय, हस्तान्तरण के लेख्य में या समय विशेष पर किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, सदा और सब प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति के पक्ष में, हस्तान्तरण किया गया हो, विऋय समझा जायगा और इस प्रकार के प्रत्येक विकय के विषय में घारा १५३ और १६२ के निदेश लागू होंग।

१६३-क--यदि घारा १५६ में अशिदिष्ट भूमिधर से भिन्न कोई भूमियर अपने खाते को या उसके किसो भाग को लगान पर उठा दे तो, किसी विधि, संविदा या पट्टे के लेख्य में किसी बात के रहते हुए भी, पट्टेदार--

ग्रदला−बदली से माल गुजाशी पर प्रभाव न पडना ।

इस ऐक्ट के प्रति-कूल हस्तान्तरम्।

भूमियः द्वारा कब्ते महित हस्तान्तरण का निकय समभा जाना।

धारा १४६ के प्रतिकूल पट्टे का परिकास ।

(क) यदि उस भूमि की मिलाकर जो उसे लगान पर उठाई गई है उसके पास की कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक नहीं होता है तो उस भूमि का सीरदार हो जायगा और सीरदार हुआ समझा जायगा।

(ख) यदि उपरोक्त कुल भूमि का क्षेत्रफल तीस एकड़ से अधिक होता है तो उस भूमि का ऋता हो जायगा और केता हुआ समझा जायगा तथा घारा १५३ और १६२ के निदेश आवश्यक परिवर्तनो के साथ उसको लागू होंगे।

१६४-- [%] किसी सीरदार या असामी द्वारा या उसकी ओर से [क्षेड] इस अध्याय के निदेशों के प्रतिकृत किया गया प्रत्येक हस्तान्तरण व्यर्थ (void) होगा।

१६५--यदि इस विधान के निदेशों के विरुद्ध किसी सीरदार या असामी ने कोई हस्तान्तरण किया हो तो, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में हस्तान्तरण हुआ हो और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने उस पूरे खाते या उसके भाग का इस प्रकार कब्जा प्राप्त कर लिया हो, गांव-सभाया क्षेत्रपति के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा।

१६६--वारा १६५ के अधीन वाद के फलरवरूप सीरदार या असामी के बेदलल हो जाने पर खाते में या उसमें की गई किसी उन्नति में उक्त सीरदार या असामी के सभी अधिकार और स्वत्व तथा ऐसी उन्नति के लिये प्रतिकर पाने के भी अधिकार और स्वत्व समाप्त हो जायंगे।

इस ग्रध्याय के प्रति-कूल हुए हस्तान्तरण का व्यथे होना। हस्तान्तरण के व्यथे होने के परिणाम।

घारा १६५ के ग्रधीन बेदखली परिगाम।

उत्तराधिकार

१६७--(१) उपवारा (२) में की गई व्यवस्था की भूमिधर द्वारा वसीयत दशा को छोड़ कोई भी भूमिबर अपने खाते या उस किसी भाग की दिरसा (वसीयत) कर सकता है (bequeath by will)!

१६७--(२) कोई ऐसा भूमिधर जो किसी खाते या उसके भाग में किसी विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामह, पितामही, अविवाहित पुत्री या अविवाहित बहिन के अधिकार के आधार पर अधिकार रखता हो, ऐसे खाते या भाग की दित्सा (वसीयत) नहीं कर सकता।

(३) उपधारा (१) के निदेशों के अधीन की जाने वाली प्रत्येक दित्सा (वसीयत) किसी विधि, आचार tom) या व्यवहृत (usage) में किसी बात के रहते हुए भी, लिखित, और दो व्यक्तियों द्वारा होगी।

क्षि निकाल दिया गया।

सीरदार ग्रीर ग्रसामी द्वारा वसीयत ।

उत्तराधिकार का सामान्य-क्र**म**। १६८-- किसी सीरदार या असामी को अपने खाते पा उसके भाग की दित्या (वसीयत) करने का अधिकार नहीं होगा।

१६९—-यदि कोई पुरुष भूमिधर, सीरदार या असामी मर जाय तो उसके खाते में उसके स्वत्व का उत्तराधिकार धारा १६७ ओर १७१ के निदेशों को वाधित न करते हुए, निम्नलिखित क्रम से होगा :--

(क) पुरुष जातीय वंशानुकम में पुंसन्तति (male lineal descendants in the male line of descent),

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुश्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी नीची पीढ़ी में हो, वह अंश उत्तराधिकार में मिलेगा, जो मृतक को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

- (ख) विधवा पत्नी,
- (ग) पिता,
- (घ) विघवा माता,
- (**3**) [**3**;]
- (च) वितामह (fathor's father),
- (9) विश्ववा पितामही (lather's mother),
- (ज) पुरुष जातीय वंशानुक्रम में पुंसन्ति । में से किसी की विधवा (widow of male lineal descendant in the male line of descent),
 - (ज ज) विषवा सौतेली माता,
 - (झ) अविवाहिता पुत्री,
 - (अ) नवासा (daughter's son),
 - (ट) भाई अर्थात् मृतक के पिता का पुत्र,
 - (ठ) अविवाहिता बहिन,
- (ड) भतीजा अर्थात् मृतक के पिता क पुत्र कापुत्र, । रा
 - (ढ) पितामह का पुत्र,
 - (ढ ढ) भाई का पौत्र,
 - (ण) पितामह का पौत्र।

१७०—(१) यवि कोई भूमिपर, सीरवार या असामी, जिसे स्वत्वाधिकार के दिनांक के [*] बाव किसी खाते में विश्वा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, अविवाहिता पुत्री या अविवाहिता बहिन के नाते उत्तराधिकार मिला हो, मर जाय, विवाह कर ले या ऐसे

विधवा पत्नी, माता
पुत्री इत्यादि के रूप
में उत्तराधिकार पाने
वाली स्त्री के विषय
में उत्तराधिकार कम।

^{*} निकाल दिया गया।

खाते अथवा उसके किसी भाग का परित्याग कर दे (abandons) या समर्पण कर दे (surrenders) तो, ऐसा खाता या भाग अंतिम पुंजातीय (male) भूमिघर, सीर-दार या असामी के ऐसे निकटतम जीवित उत्तराधिकारी (neares surviving heir) को मिलेगा, जो ऐसा स्पिक्त न हो जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो; ऐसा उत्तराधिकारी घारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

- (२) यदि कोई भूमिधर या सीरदार जिसने स्वत्वाधिकार के दिनाक से पहले किसी खाते में कोई स्वत्व विधवा पत्नी, माता, सौतेली माता, पितामही, पुत्री, बहिन या सौतेली बहिन के नाते उत्तराधिकार में पाया हो—
 - (क) मर जाय और ऐसा भूमिधर या सीरदार उपर्युक्त दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उकत खाते के अन्तर्गत भूमि का मध्यवर्ती रहा हो, या वह खाता उसके पास शरह मुअ्यन काश्तकार या अवध में साकिनुलमिल्कियत अथवा दखीलकार काश्तकार या अवध में विशेष शर्ती वाले काश्तकार के नाते रहा हो, और
 - (१) वह अपनी व्यक्तिगत विधि (por50 1al law) के अनुसार खाते में केवल
 आजीवन स्वत्य की अधिकारिणी रही हो तो, खाता
 उत्तराधिकार में अन्तिम पुंजातीय मध्यवती या
 अंतिम पुंजातीय पूर्वोक्त प्रकार के काइतकार के
 सब से निकटतम जीविन उत्तराधिकारी को मिलेगा,
 ऐसा उत्तराधिकारी धारा १६९ के निदेशों के
 अनुसार निश्चित किया जायगा, और यदि
 - (२) वह अपनी व्यक्तिगत विधि के अनुसार खाते में पूर्ण स्वत्व की अधिकारिणी रही हो तो खाते का उत्तराधिकार घारा १७२ में उल्लिखित क्रम के अनुसार चलेगा।
 - (ख) मर जाय, विवाह करले या ऐसे खाते का परित्याग या समपण करदे तो उपय कत दिनांक से ठीक पहले के दिनांक ,पर खाता ऐसे भूमिघर या सीरदार के पास, खंड (क) में अभिदिष्ट मध्यवती या काश्तकार के नाते न होकर और किसी प्रकार रहा हो तो खाता उत्तराधिकार में ऐसे अंतिय पुंजातीय काश्तकार को मिलेगा, जो ऐसा

व्यक्ति न हो, जिसे पितामह के रूप में उत्तराधिकार मिला हो, एसा उत्तराधिकार घारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) के निदेश आवश्यक परिवर्तन के साथ उस असामो को भी लागू होग जिसन स्वत्वाधिकार के दिनाक से पहले खाता उत्तराधिकार में पाया हो।

(४) उपधारा (१) की कोई ऐसी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नही होगी जिसे घारा १७२ के निदेशों के अधीन किसी खाते म किसी स्वत्व का उत्तराधिकार मिला हो।

स्पष्टीकरण—इस घारा के प्रयोजनो के लिये अंतिम पुंजातीय भिन्यर, सीरदार या असामी पद के अन्तर्गत, जैमी भी दशा हो, अतिम पुंजातीय काश्तकार बागदार, अवध में दयामी पट्टदार, माफीदार या सीरदार अथवा खुदकारत रखन वाला व्यक्ति भी है।

वितामह की उत्तरा-धिकार मिले खाते के सम्बन्ध में उत्तरा धिकार का कम। १७१—विद कोई भूमिधर, सीरदार या असामी, जिसको स्वत्वाधिकार के दिनांक से पहले या बाद किसी खाते में पितामह के रूप में स्वत्व का उत्तराधिकार मिला हो, मर जाय या ऐसे खाते का या उसके भाग का परित्याग या समर्पण कर दे (abandons or surrondors) तो ऐसा खाता या उसका भाग उत्तराधिकार में ऐसे अन्तिम पुंजालीय भूमिधर, सीरदार या असामी के, जिससे ऐसे पितामह ने खाते में स्वत्व का उत्तराधिकार पाया हो, निकटतम जोवित उत्तराधिकारी को मिलेगा। ऐसा उत्तराधिकारी घारा १६९ के निदेशों के अनुसार निश्चित किया जायगा।

श्रन्य प्रकार से स्वत्व पाने वाली स्त्री के सम्बन्ध में उत्तरा-घिकार का क्रम।

१७२—यदि कोई रत्री जातीय भूमिघर, सीरवार या असामी (घारा १६९ या १७० में उल्लिखित भूमिघर, सीरवार या असामी से भिन्न) मर जाय तो खाते में उसका स्वत्य निम्नलिखित कम से उत्तराधिकार में जायगा :—

(क) वृंजातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तित (male lineal descendants in the male line of descent):

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पिता से पूर्व मरे हुए पुत्र के पुत्र या पुत्रों को, वे चाहे जितनी नीची पीढ़ी में हो, वह अंदा उत्तराधिकार में मिलेगा जो मृतक को, यदि वह उस समय जीवित होता, मिलता।

- (ख) पति,
- (ग) पुंजातीय वंशानुकम में किसी प्रंस पति की विधवा,
 - (घ) पुत्री,

- (জ) বুরিকা-বুর, (daughter's son)
- (च) भाई
- (छ) भाई का युत्र,
- (ज) बहिन,

(झ) बहिन का पुत्र (sister's son)।

१७३—[%] यदि जोई विषया सपत्नी या सहस्राते— दार (co-tenure-holder) इस विधान के निदेशों के अधीन कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाए, तो ऐसे स्नाते में उसका स्वत्व गलितांश रूप में संक्रमित होगा (shall pass by survivorship)।

गलितांश द्वारा स्वत्व का संक्रमण।

(২) [ঞ্চী

बंटवारा

१७४--(१) म्भिघर और सीरदार अपने खाते के बंदनारे का बाद प्रस्तुत कर तकते हैं (may suo) भूमिधर् या सीरदार के खाते का बंटवारा नेग्य होना।

(२) ऐसे प्रत्येक वाद में उससे सम्प्राय रखने वाली गांव-सभा फरीक बनाई जायगी।

१७५---[E १७६---[E १७७---[E १७८---[E

१८०——यदि वाद के सब फरीक प्रत्येक खाते में संयुक्त रूप से स्वत्व रखते हों, तो एक से अधिक खाते के बँटवारे के लिए केवल एक वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा। कई खातों के बंटवारे का एक ही वाद।

१८१--(१) उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था उप-घारा (३) में की गई है, यदि बटवारे के किसी वाद में त्यायालय इस परिणाम पर पहुंचे, कि खाते का विकय

- (क) बटवारा किए जाने वाले खाते या खातों का कुल क्षेत्रफल (Aggregate Area) ६.१/४ एकड़ से अधिक नहीं है, या
- (ल) बंटवारे का परिणाम यह होगा कि कोई लाता ६.१/४ एकड़ से कम बन जाएगा, तो लंड (क) में आने वाली दशाओं में, लाते या लातों को बांटने की कार्यवाही करने के स्थान पर यह निर्देश करेगा कि वे बेच दिए जायं और उनके विकय से मिला धन बांट दिया जाय, और, लंड (ल) में आने वाली दशाओं में, या तो वाद को लारिज कर देगा या लाते को ऐसे सिद्धांतों के अनुसार, जो नियत किये जायं, बांट देगा।

[*] निकाल दिया गया।

- (२) उपप्रारा (१) ते आगित प्रार्गण नियम उन परिस्थितियों को नियत करेंगे जिनमें किसी सहखातेदार को खाते में उसके अंश के स्थान पर प्रतिकर दिया जा सके और ऐसे सहखातेपार को गांव-सभा द्वारा धारा १९४ के निदेशों के अधीन भूमिठाई जा सके।
- (३) उस खातेदार के विषय में, जिसे घारा १५६ के निदेश लागू होते हो, और जिसने खाते में अपना अंश या उसका कोई भाग दूसरे को उठा दिया हो तथा ऐरो सह- खातेदार के विषय में, जिसने इस विधान के या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान, १९४९ के निदेशों के अधीन यथावत खाते के केवल एक अंश के सम्बन्ध से ही भूभिधरी अधिकार प्राप्त किये हों, न्यायालय बाट कर उक्त अंश को अलग कर देगा किनु जहां शेष खाते का सम्बन्ध है यदि इस धारा के निदेश लाग हों, तो उनके अनुसार न्यायालय कार्यवाही करेगा।

बेचे जाने वार्धे खाते का मृह्यांकन। १८२—यदि न्यायालय ने घारा १८१ के अधीन खाले या खातों के विकय की आज्ञा वी हो, तो यह ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, आज्ञा के द्वारा उनका मृत्यांकन (valu-ntion) कराएगा ओर फिर इस प्रकार निश्चित विए गए मृत्य पर उन सहका दियों की क्याधिकार के ऐसे तारतम्य (order of preference) के अनुसार, जो नियत किया जाए, मोल लेने की कहेगा।

क्रयाधिकार तारतम्य । १८३—म्यि वो या अभिक ऐसे सहस्रातेवार, जिन्हें तारतम्य के अनुसार बराबर का क्याधिकार हो, मोल लेगे की अलग—अलग इच्ला प्रकट करें, तो न्यायालय उसे उनमें से ऐसे के हाथ बेचने की आजा देगा, जो घारा १८२ के अजीन निश्चित किए गए मूल्य से अपर सब से अधिक मूल्य पर मोत लेने की तैयार हो।

धारा १८३ के अधीन क्रय न करने पर विक्रय। १८४—यदि कोई भी अंशधर (share—holder) बारा १८२ के अधीन निश्चित किए गए मूल्य या उससे अधिक पर मील लेने की तैयार न हो तो न्यायालय उसे ऐसे अंशधर के हाथ बेच दिए जाने की आजा देगा, जो सब से अधिक मूल्य देने को तैयार हो।

विकय की प्रक्रिया।

१८५—उस दशा की छोड़कर जिसके विषय में इससे पहले व्यवस्था की गई है, यदि किसी खाते के सम्बन्ध में [*] धारा १८१ के अधीन वी हुई आज्ञा के अनुसार बेचने की आज्ञा वी गई हो तो न्यायालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो नियत की जाय ।

समर्पण, भित्याम, समादि। पौर उपार्जन

१८६——चाहे खाता लगान पर उठा हो या नहीं, उसका कब्जा छोउकर नर्तितदार को लिखिन प्रार्थना— पत्र देगर और गांव—सभा को अपने ऐसे विचार का लिखित नोटिस देवर गीरदार अपने खाते या उसके किसी भाग का समर्पण कर सकता है।

१८७—-असामी गाव— रेमा या क्षेत्रपति को, जैसी भी दशा हो, अपने ऐसे पिनार का लिखित नोटिस देकर और खाते का कन्त्रा छोड़कर अपने कुल खाते का समपंण कर सकता है, परन्तु उसके केवल भाग का नहीं।

१८८—यदि सीरदार या असामी १ अप्रैल से पूर्व पार्थना-पत्र प्रस्तुल न जरे या नोटिस न दे तो, वह समर्पण करने पर भी समर्पण के दिनांक से ठीक बाद के कृषि वर्ष के लिये उस खाते की मालगुजारी या लगान का, नैसी भी दशा हो, देनदार होगा।

१८९-[*](१) यदि किसी सीरदार ने, (जो अवयस्क, पागल या जड न हो) या किसी असामी ने अपना खाता लगातार दो कृषि वर्षों तक कृषि, फलोत्पादन या पशु-पालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये काम में न लाया हो, तो गांव-सभा या क्षेत्रपति तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि ऐसे सीरदार या असामी को, जैसी भी दशा हो, इस आशय का नोटिस दिया जाय कि वह इस बात का कारण दिखलावे कि उनत खाता परि-त्यक्त क्यो न गाना जाय।

- (२) उक्त प्रार्थना-पत्र में ऐसे क्योरे होंगे, जो नियत किए जायं।
- (३) यदि तहसीलदार इस निर्णय पर पहुंचे कि प्रार्थना— पत्र यथावत् दिया गया है, तो वह सीरदार या असामी पर, नियत किये जाने वाले आकार में एक नोटिस तामील करवा के या नियत रीति से प्रकाशित करा के उसे निश्चित किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने के लिये, और इस बात का कारण प्रकट करने के लिये, आदेश देगा कि उक्त खाता परित्यक्त क्यों न समझा जाय।
- (४) यदि नोटिस के उत्तर में सीरदार या असामी उपस्थित न हो या उपस्थित हो पर उसका प्रतिवाद न करे, तो तहसीलदार खाते को परित्यक्त (abandoned) प्रख्यापित कर देगा और तदुपरान्त, उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था घारा १७० और १७१ में की गई है, खाते के विषय में यह समझा जायगा कि वह खाली भूमि है। [ध्रि] निकाल दिया गया।

सीरदार द्वारा खाते का समपण (surrender)।

श्रसामी द्वारा खाते का समर्पण। ग्रक्षय सीरदार की में श्र**सामी** जीत की स्वीकृति।

१८९--(क) यदि किसी ऐसे सीरदार ने, जो अवयस्क, पागल या जड हो, अपना साता लगातार दो कृषि वर्षा तक कृषि, फलोत्पादन या पशुपाला से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये काम में न लाया हो, तो सीरदार अभिरक्षक (gnaidian) उसके नोटिस देने और ऐसी जांच के बाद, जो नियत की जाय, तथा पूर्वोक्त दो वर्षों की समाप्ति के बाद गाव सभा, किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी, उक्त खाते के अन्तर्गत भूमि उक्त सीरदार की ओर से किसी व्यक्ति को असामी के रूप में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों पर जो नियत की जायं, उठा सकती अार इस विधान के ऐसे सब निदेश, जो धारा १०४ के खड (ख) मे उल्लिखित वर्ग के असामी को लागू होते हैं, उसे भी उसी प्रकार लागू होगे, मानो उक्त भूमि उसे स्वय सीरदार द्वारा उठा दी गई हो।

पारत्यक्त जात में प्रवेश।

१८९ (ख) बारा १८९ या १८९-क के निदेशों के प्रतिकल खाते पर कब्जा कर लेन वालो गाव-सभा या क्षेत्रपति के विषय में यह समझ। जायगा कि उसने खातेबार को इस प्रकार बेदखल कर दिया है जो इस विधान के निदेशों के अनुकूल (otherwis than in accordance—with) नहीं है।

भूमिधर के स्वत्व की समाप्ति(extinction)

१९०--भूगिषर के खात या उसके किसी भाग में उसका स्वत्व निप्नलिखित बजाओं में समाप्त हो जायगा:--

- (फ) पदि वह कोई हिस्सा (बसीयत) किए बिना और इस दिया के निदेशों के अनुसार उत्तराधिकार का कोई अधिकारी छोड़े बिना सर जाय.
- (स) यदि खाते के अन्तगत भूमि, भूमि हस्तगत करने (acquisition of land) से सम्बन्ध रखन वाली सगय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अनुसार हस्तगत कर ली गई हो, या
- (ग) यदि वह क्रब्जे से रहित कर दिया गया हो और क्रब्जा वापस लेने का उसका अधिकार अवधि-वाधित (barod by limitation) हो गया हो।[%] (घ) [%]

सीरटार के स्वत्व की समाप्ति (extinetion)। १९१—(१) धारा १७० ओर १७१ के निदेशों को माधित न करते हुए किसी खाते या उपके भाग में सीरदार का स्वत्य निम्नलिखित दशाओं म समाप्त हो जायगा:—

[*] नि ए छ दिया गया।

- (क) यदि यह इस विधान के निदेशों अनुसार उत्तराधिकार का कोई अधिकारी छोड़े बिना गर जाय,
- (ख) यदि खाता घारा १८९ के निदेशों के अनुपार परित्यक्त प्रख्यापित हो गया हो,
- (ग) यदि वह अपने खाते या उसके भाग का तम-पर्ण कर दे,
- (घ) भूमि हस्तगत करने से सम्पन्ध रखने वाली, समय विशेष पर प्रचलित, किसी विधि के अनुसार यदि खाते के अन्तर्गत भूमि हस्तगत कर ली गई हो,

(ङ) यदि इस विधान के निदेशों के अनुसार उसकी

बेदखली हो गई हो, या

- (च) यदि वह कब्जे से रहित कर दिया गया हो और कब्जा वापस लेने का उसका अधिकार अविधवापित हो गया हो,
- (२) उपघारा (१) के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ असामियों को भो लागू होंग।

१९२—किसी भूमिधर या सीरदार के अधिकार, आगम और स्वत्व के समाप्त होने पर, उसके अधीनस्य (holding under him) असामी का भी स्वत्व समाप्त हो जायगा।

मसामी के स्वत्व की समास्ति।

विलय

१९२-क-यदि पूरे खाते में असामी का स्वत्व तथा भूमिचर या सीरदार का स्वत्व एक ही व्यक्ति के स्वत्वधिकार में, अधिकार के अधीन (in the same right) आ जायं तो खाते में असामी का स्वत्व समाप्त हो जायगा।

१९२-ख--सोरदार या असामी स्वत्व समाप्त हो जाने पर उसे अपना खाता छोड़ देना पड़ेगा और उस दशा को छोड़ जिसमें कर उसका भूमि हस्तगत करने से सम्बन्ध रखने वाली, समय विशेष पर प्रचलित. किसी विधि के निदेशों के अधीन या अनुसार समाप्त हुआ हो, उसे खाते पर विद्यमान खडी फसल और किसी निर्माण को हटा के सम्बन्ध में वही अधिकार होगा, जो उसे इस विधान के निदेशों के अधीन बेदखल हो जाने पर होता।

१९३—निम्नलिखित अवस्थाओं म गांव—सभा को किसी खात या उसके भाग के अन्तर्गत भूमि पर क्रब्जा कर लेने का अधिकार होगा जहां :——

(क) भूमि किसी भूमिधर के पास रही हो और ऐसी भूमि में उसका स्वत्व घारा १९० के खंड (क) के अधीन समाप्त हो गया हो,

सोग्दार या श्रसामी के स्वत्व समाप्त होने पर उसके श्रधिकार श्रीर दायित्व।

स्वत्वें का समाप्ति पर भूाम का गांव सभा द्वारा छे छिया जाना।

- (ख) भूमि किसी सीरदार के पास रही हो और ऐसी भूमि में सीरदार का स्वत्व घारा १९१ के खंड (क), (ख), (ग) या (ङ) के अधीन समाप्त हो गया हो, या
- (ग) धारा १३३ में उल्लिखित किसी वर्ग के अन्तर्गत कोई भूमि असामी के पास रही हो और असामी बेदखल हो गया हो या उसका स्वत्व इस विधान के निदेशों के अनसार किसी अन्य प्रकार से समान्त हो गया हो।

भूमि का उठाया जाना

१९४—गांव—सभा को अधिकारहोगो कि घारा १३३ मं उल्लिखित वर्गो की गूमि को छोड़ कोई भूमि किमी व्यक्ति को सीरदार के रूप में उठा दे, यदि

- (क) भूमि खाली भूमि हो,
- (ख) भूमि घारा ११७ के अधीन गांव-सभा के स्वत्वाधिकार में हो (is vested in the Gaon Sabha), या
- (ग) भूमि धारा १९३ के, या इस विधान के किसी दूसरे निदेश के, अधीन गांव-सभा के कबजे में आ गई हो।

कुछ द्शाष्ट्रों के मध्य-वितेयों का सारदार के साथ में जमान उठा देना।

१९४-क--यदि कोई भूमि घारा १५ की उप-घारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) के अधीन खाली हो जाय और ऐसी भूमि स्वत्वाधिकार के विनांक से ठीक पहले के विनांक पर किसी ऐसे मध्यवर्ती के स्वामित्व में रही हो, जिसकी सीर में धारा १३ के अधीन मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गए हों तो गांव-सभा ऐसे मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रार्थी को ऐसी भूमि या उसका भाग सीरवार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के इस प्रकार उठाए जाने के परिणाम स्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी न होगा, जो उस भूमि से मिल कर, जो उसके पास हो, संयुक्त प्रान्त में ५० एकड़ से अधिक हो जाय।

धारां १३३ में उद्दिल-खित भूमि का उठाया जाना। १९५—गांव—सभा को अधिकार होगा कि घारा १३३ में उल्लिखित वर्गों में से किसी वर्ग को भूमि किसी व्यक्ति को असामी के रूप में उठा वे, यवि

- (क) भूमि खाली भूमि हो,
- (ख) भूमि गांव-सभा के स्वत्वाधिकार में हो, या
- (ग) भूमि घारा १९३ को, या इस विधान के किसी दूसरे निवेश के अधीन गांव-सभा के कब्जे में आ गई हो।

घारा १६४ और १६४

तारतस्य।

के प्रधीन भूमि उठाने

व्य चि.ये गं

१९६—(१) घारा १९४ या १९५ के अधीन किसी व्यक्ति को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय गांव—सभा, घारा १८१ या २२४ के अधीन बने नियमों या न्यायालय की आज्ञा को बाधित न करते हुए, निम्नलिखित तारतम्य (order of preference) का अनुसद्य रखेगी :—

- (क) इस विधान के अधीन स्थापित ऐसी सहकारी खेती संस्था (co-operative farm) जिसके पास उस गांव-सभा के अधिक्षेत्र में की भूमि हो, ताकि उसके क़ब्जे में कृषि सम्बन्धी या खेती-योग्य पर्याप्त भूमि आ सके,
- (ख) ऐसा भूमिघर जिसे घारा १९ की उपधारा (२) या घारा १४३ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में ६१/४ एकड़ से कम

क्षेत्रफल की भूमि हो,

- (ख ख) उन भूमिचरों से भिन्न जिन्हें खण्ड (ख) लाग होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल को भूमि हो ,
- (ग) उस मंडल में रहने वाला ऐसा मजदूर जिसके पास कोई भूमि न हो, और

(घ) कोई दूसरा व्यक्ति।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उन दशाओं में जिन्हें खण्ड (ख) और खण्ड (ख ख) लागू होते हों, ऐसे खातेदार को केवल उतनी ही भूमि मिलेगी जितनी उसके पास की कुल भूमि के क्षेत्रफल को ६ १/४ एक इकर देने के लिए पर्याप्त हो।

(२) जो व्यक्ति गांव-सभा द्वारा उपघारा (१) के अधीन दी गई आज्ञा से असंतुष्ट हो वह परगना अधिकारी के सामने अपील कर सकता है, परगना अधिकारी अपील की ऐसी रीति से मुनवाई और निर्णय करेंगे, जो नियत की जाय।

वेद्खली

१९७--कोई भी भूमिषर बेदलल नहीं हो सकेगा।

१९८--उस दशा के छोड़, जिसकी व्यवस्था इस ऐक्ट में की गई है, कोई सीरदार या असामी अपने खाते से बेवखल नहीं हो सकेगा।

१९९——धारा १६५, २०३ या २०९ में उल्लिखित किसी आधार पर और गांव—सभा के बाव पर सीरदार की वेदखली उसके साते से हो सकेगी।

भूमिधर का बेदबल न हैं। सकना सीरदार चौर बसामी को बेदखळी।

सोरदार की बेदखती की प्रक्रिया। २००—घारा २१६ और ३०७ के निदेशों को बाधित न करते हुए, असामी की बेदखली उसके खाते से क्षेत्रपति के बाद प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित आघार या अवारों पर हो सकेगी:—

- (क) जो घारा १६५, १९२ या २०३ में उल्लिखित है,
- (ख) कि यह घारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [१], [२], (२ क), [५] और [६] या खंड (ग) में उल्लिखत किसी वर्ग का है और उसके पास भूमि वर्षानुवर्ष कम से है या [*] उसकी अविध बीत गई है, या प्रचलित (ourrent) कृषि—वर्ष के अन्त के वृष्य बीत जायगी,
 - (ग) कि वह घारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [३] में उल्लिखित वर्ग का है और बन्धक सम्बन्धी ऋण की भरपाई हो गई है,
 - (घ) कि वह घारा १३४ के खंड (क) के उपखंड [४] में उल्लिखित वर्ग का है और भरण-पोषण की वृत्ति (maintenance allowance) पाने का उसका अधिकार अब विद्यमान नहीं रह गया है (does not any longer subsist),
 - (ङ) कि यह घारा १३४ के खंड (क्त) के उपखंड [७] में उल्लिखित वर्ग का है और खेती की फसलों का पैदा करना असम्भव हो गया ह,

(च) कि वह घारा १३४ के खंड (ख) में

उल्लिखित वर्ग का है और

(१) क्षेत्रपति भूमि को अपनी निज जोत में स्रेना चाहता है और उन दशाओं में जहां पट्टा एक निश्चित अविध के लिए हो, यह कि ऐसी अविध बीत गई है, या

(२) अञ्चनता (disability) का अन्त हो

गया है।

(छ) कि वह घारा १३४ के खंड (क) के उपखंड (८) में उल्लिखित वर्ग का है और घारा १५ की उप-घारा (२) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अविध बीत गई है

- (ज) कि उसके विरुद्ध कोई ऐसी बकाया लगान की डिकी है जिसके रुपए का भुगतान अभी नही हुआ है और ऐसी डिकी बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सकती है।
- २००-क-(१) यवि (धारा २०६ के अधीन दी गई डिकी से भिन्न) किसी डिकी है, या वखल होने की आज्ञा के निष्पावन में न्यायालय की इस बात का संतीष हो जाय कि उस भूमि पर, जिसकी वखल विहानी होने की है,

बदलली होने पर फसल और पेड़ सम्बन्धी अधिकार कोई ऐसी बिना बटोरी फसल था पंड़ विद्यमान है, जो वादऋणी (judgment debtor) की संपत्ति है, तो डिक्री या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा:—

- (क) यदि घारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद वादऋणी से प्राप्य धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो तो न्यायालय गांव—सभा या क्षेत्रपति को, जैसी भी दशा हो, उक्त भूमि पर क़ब्जा फसलों और पेड़ों के साथ दिलवा देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में वादऋणी के समस्त अधिकार डिकीदार को संक्रमित हो जायगे।
- (ख) यदि घारा १५० के अधीन निर्घारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद, वादऋणी से प्राप्य धनराशि ऐसी फसलों या पेड़ों के मूल्य से कम हो, और

[१] गांव-सभा या क्षेत्रपति ऐसी धनराशि और मूल्य का अन्तर वाबऋणी को दे दे तो ग्यायालय तत्संबंधी गांव-सभा या क्षेत्रपति को खाते पर दखल दे देगा और ऐसी फसलों या पेड़ों में वाद ऋणी के समस्त अधिकार डिकीदार को संक्रमित हो जायंगे;

[२] गांव-सभा या क्षेत्रपति ऐसे अन्तर को न दे तो वादऋणी को अधिकार होगा कि एसी फसलों या पड़ों को या ऐसे पेड़ों के फलों को, जब तक ऐसी फसलें या पेड़ बटोर कर हटा न लिए जाये या नष्ट न हो जाये या काट न डाले जाये, जैसी भी दशा हो, भूमि के उपयोग और दखल के लिए ऐसा प्रतिकर देकर, जो न्यायालय निश्चित करे, पाले पोसे, बटोरे या हटा ले जाय।

(२) बेदलली की डिकी या आज्ञा का निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी फरीक की प्रार्थना पर फसलों और पेड़ों का मूल्य, तथा उपधारा (१) के खण्ड (ख) के निदेशों के अधीन वादऋणी द्वारा देय प्रतिकर, अवधारित कर सकता है। घारा २०० के अधीन बेदखली के बाद का न प्रस्तुत होना या ऐस वाद में मिली डिक्री का निष्पादित न होना।

ारा २०० के अधीन वद्**ख**ळी के परिणाम।

इस **पे**क्ट के निदेशों के प्रतिकुछ भूमि के। काम में लाने पर बेदम्बलो।

धारा २०३ के प्रधीन बेदखती की डिक्री।

क्षति या हास ठीक फरने के लिए या उसके निमित्त प्रति-कर दिलाग जाने के लिए वोद।

भूमि पर श्वागम बिना काविज व्यक्ति का बेदखती। २०१——यदि उसके लिए नियत अवधि के भीतर किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे असामी की बेदखली का कोई वाद जिसे थारा १३४ के खंड (क) के उपलंड [१] से [४] तक में से कोई या खंड (क) लागू होता हो, प्रस्तुत न हुआ हो या ऐसे बाद में हुई डिक्री निष्पा—दित न हुई हो, तो ऐसी अवधि के समाप्त हो जाने पर असामी ऐसी भूमि का [%] सोरदार, [%] हो जापगा।

२०२—यदि घारा २०० के खड (ब) (१) में उद्धिशिवत किसी आधार पर असाम, अपने खाते से बेद वल हो गया हो तो बेदखली के दिनांक से दो वर्ष के भीतर क्षेत्रपति किसी व्यक्ति को उस खाते का पट्टा नहीं देगा।

२०३—-कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से संबंध रखनेवाले प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन में भूमि का उपयोग करने के कारण सीरदार या असामी गांव-म्भा या क्षेत्रपति (land-holder) के, जैसी भी दशा हो, बाद पर बेदखल हो सकेगा और उसको ऐसी क्षतिपूर्ति (dansages) भी देनी होगी, जो उस भूमि को उक्त प्रयोजनों के लिये फिर से उपयुक्त बनाने के लिये आवश्यक कार्यों पर होनवाले व्यय के बराबर हो।

२०४—(१) परिस्थितियों का ध्यान रखते हुये घारा २०३ के अघीन बेदखली की किसी डिक्री में न्यायालय यह निर्देश कर सकता है कि सीरदार या असाभी की बेदखली कुल खाते से की जाय या उसके किसी भाग से।

(२) डिक्री में यह भी निर्देश रहेगा कि यदि सीरदार या असामं। डिक्री के विनांक से ठीक वाद के तीय मास के भीतर क्षति को ठीक कर दे, ते। डिक्री वाद-व्यथ (oosta) के अतिरिक्त और किमी बात के लिये निष्पाति (oxognical) नहीं की जायगी।

२०५—धारा २०३ में किसी बात के रहते हुए भी गांव—सभा था क्षेत्रपति को अधिकार होगा कि बेदबारी का बाद न लाकर निम्नलिखित विषय में बाद प्रस्तुत कर सके:—

(क) प्रतिकर सहित या प्रतिकर बिना सगादेश

(injunction) के लिये, या

(ख) खाते की भूमि की काति (damage) या हाल (wast) के ठीक करा पाने के लिये (for repairs)

२०६--यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निवेशों के अनुकूल, और (otherwise then

in accordance)

(क) जहां भूमि किसी भूमिषर, सीरदार या असासी के खाते का भाग हो, वहां ऐसे भूमिषर, सीरदार या असामी की सहमति बिना,

निकाल विया गया है।

(स) आहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के सात का भाग न हो, वहां गांव-समा की सहमति बिना, किसी भूमि पर क्रव्जा कर ले या अपना का उले रहे तो वह भूमिधर, सीरदार, असामी यागांव-सभा के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेंदलल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

२०७--यदि तत्सम्बन्धी अविध के भीतर घारा २०६ के अधीन बाद प्रस्तुत न किया जाय या ऐसे वाद में हुई डिकी निष्पादित न की जाय, तो कब्जा कर लेने या रक्खे रहने वाला व्यक्ति।

(क) [*]

(१) जहां भूमि भूमिधर या सीरदार के खाते की भूमि का भाग हो, उसका सीरदार हो जायगा और ऐसी भूमि पर यदि कोई असामी हो तो उसके अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायंगे;

(२)यदि भूमि गांव-सभा की ओर से क़ब्जा रखने वाले किसी असामी के खाते का भाग हो, उसका असामी हो जायगा।

(३) एसी दशा में जहां घारा २०६ के खण्ड (ख) के निदेश लागू होते हों, [*] सीरदार या असामी हो जायगा, मानो उसे क़ब्जा गांव—सभा हो द्वारा मिला हो।

ं २०८—(१) ऐसा व्यक्ति, जो घारा २०७ के खंड (क) के निदेशों के अधीन [भं सीरदार हो गया हो, इस विधान में इससे पूर्व किसी बात के रहते हुए भी, ऐसी अविध के भीतर जो नियत की जाय, गांव—सभा द्वारा भूमि से बेदखल किया जा सकता ह।

(२) यिव उपधारा (१) के अधीन [*] किसी सीरदार के विरुद्ध बेदलली की डिफी हो जाय और ऐसा [*] सीर-दार उस डिकी के निष्पादन में बेदलल हो जाय, तो खाते म उसके अधिकारों का अन्त हो जायगा और भूमि खाली भूमि हो जायगी।

२०९--(१)यदि क्सि मध्यवर्ती ने ८ अगस्त, १९४६ ई० को या उसके बाद कोई ऐसी भूमि जो अभिलिखित (recorded) या आचारिक (customary) सार्व-जिनक पशुचर भूमि, इमशान या क्रिबस्तान, तालाब, रास्ता या खिलहान थी, अपनी जोत में कर लिया हो य किसी काश्तकार को उठा विया हो वह ऐसा प्रतिकर देने पर, जो नियत किया जाय, धारा १९७ में किसी बात के रहते हुए भी गांव-सभा द्वारा प्रस्तुत वाद पर, उस भूमि से बेदखल किया जा सकता है।

भूमि पर ग्रागम विना काविज ब्यक्ति की बेदखली।

धारा २०० के अधीन
वाद का न प्रस्तुत
होना या उसके
अधीन मिली डिग्री
का निष्पादन न
होना।

धारा २०७ के सीर-दार की बेदखली।

सार्वज्ञानक उपयोग को भूमि से व्यक्तिया की **बेदख**ली।

^[*] निकाल दिया गया।

(२) [88]

लगान

असामी का लगान।

२१०—ऐसे प्रतिबन्धों ओर निरोधों को वाधित न करत हुए, जो नियत किये जायं, प्रत्येक असामी भूमि का कब्जा मिलने पर ऐसे लगान का देनदार होगा, जो उसके और उसके क्षेत्रपति या गांव—सभा के बीत, जैसी भी दशा हो, तय हो जाय।

लगान में परिवर्तन न किया जाना।

२११-- किसी असामी द्वारा देय लगान उस रीति और उस आयित (extent) के अतिरिक्त जिसकी ज्यवस्था इस विधान द्वारा या उसके अधीन की गई हो और किसी रीति से या आयित तक परिवर्तित नहीं हो सकेगा।

लगान निश्चित करा रे का बाद।

२११-- क--(१) यदि किसी व्यक्ति ने, जिसे कोई
भूमि किसी के कब्ज में देने का, या किसी को किसी भूमि पर
कब्जा रख रहने की अनुज्ञा देने का, अधिकार हो, किसी को
किसी भूमि पर उस भूपि के अपामी के हप में कब्जा दे दिया
हो या कब्जा रख रहने की अनुज्ञा दे दी हो पर लगान न
निश्चित हुआ हो तो असामी था कब्जा अथवा अनुज्ञा
देने वाला व्यक्ति कब्जा के काल के गीतर या उसके बीतने
पर तीन वर्ष के भीतर लगान निश्चित कराने का वाद
प्रस्तुत कर सकता है।

- (२) उपघारा (१) के अधीन लाए याद में दायी— कालावधि संबंधी विधि को बाधित न करते हुए (subject to the law of limitation) बकाया की डिक्री की भी प्रार्थना कर सकता है।
- (३) उपघारा (१) के अधीन लाए गए बाद में जिस लगान की डिकी होगी वह वही लगान होगा, जो कब्जा या अनुज्ञा विए जाने या असामी—अधिकार उत्पन्न होन के, जैसी भी दशा हो, वर्ष से पहले वाले वर्ष में देय रहा हो, या यदि उक्त वर्ष में कुछ लगान न देय रहा हो तो लगान उस दर से लिया जायगा जो उक्त भूमि में लागू— मोक्सी दरों के १३३ १/३ प्रतिशत के बराबर हो।

छगान देने के निमित्त उपज का भाराकांत रहना। २१२—किसी असामी की जोत के प्रत्येक खाते की उपज और ऐसे खाते में स्थित प्रत्येक पड़ के फल उस खाते के सम्बन्ध में उस असामी द्वारा देय लगान के लिये बन्धक रखें समझे जायंगे और जब तक वह लगान दे या किसी दूसरे प्रकार से चुका न दिया जाय तय नक किसी ग्यायालय की डिकी या आज्ञा के निष्पादन में नीलाम द्वारा ऐसी उपज या फल के सम्बन्ध में कोई

और दावा (claim) उसके विरुद्ध कार्यान्वित नहीं हो सकेगा (shall not be enforced)। २१३[*]

२१३-(स)—(१) किसी भी असामी के लिए डाकघर के मनीआईर द्वारा अपना लगान देना बैध होगा, किन्तु गांव सभा या क्षेत्रपति का इस प्रकार दिया गया रुपया ले लेना क्षेत्रपति यागांव-सभा के, जैसी भी दक्षा हो, यह सिद्ध करने के मार्ग में कि किसी वर्ष या किसी किस्त के निमित देय धनराशि प्राप्त धनराशि से भिन्न थी, कोई बाधा नहीं उपस्थित करेगा।

लगान के यदायगी का हंग।

(२) जहां लगान डाकघर के मनीआर्डर द्वारा भेजा गया हो, वहां पान वाले की रसीद या ऐमे मनीआरड पर, जिसपर यथावत् डाकघर की मोहर लगी हो, उसकी अस्त्रीकृति सूत्रक अनलेख (Endorvement of refusal) रीतिक रूप से सिद्ध हुए तिना ही (without formal proof) प्रमाण में प्राप्ता होगा और जब तक इसके प्रतिकूल सिद्ध न हो जाय, उसके विषय में यह प्रकृतित कर लिया जायगा (shall be presumed) कि उसमें उक्त लगान की प्राप्ति या अस्वीकृति अभिलिखित है।

लगान का नगदी में परिर्वतन।

२१३-(ल)--यदि लगान जिन्सी हो या लड़ी फसल के अनुमान (estimate) या कूत (appraisement) के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली ररो पर गा ऐसे ढंगो में से अंगतः एक पर और अंगतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर उसे नियत रीति के अनुसार स्वतः (at his own distorition) नगदी में परिवर्तित कर सकते है और गांव सभा के या उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा, या जिसे, लगान देय हो, चाहने पर अवश्य ही ऐसा कर देंगे।

२१३-(ग) — किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर (in the absence of a contract to the contrary) लगान दो बराबर किस्तों में उस कृषि—वर्ष के, जिसके संबंध में उक्त लगान देय हो, नवम्बर के पहले दिनांक और मई के पहले दिनांक को, देय होगा।

खगान ग्रदा करने की किन्त । बकाया लगान की अदायगो और उसके न होने पर बेदखलो के लिये प्रार्थना-पत्र। २१४—(१) यदि किसी असामी के किसी खाते का कुल लगान या उसका कोई भाग तीन मास के ऊपर बकाया में पड़ा रहे तो गांव—सभा या क्षेत्रपति, जैसी भी दशा हो, बकाया की अदायगी की, तथा उसके अदा न होने पर खाते से असामी की बेदखली की, आज्ञा के लिए प्रार्थना—पत्र दे सकता है।

२ — उक्त प्रार्थना — पत्र कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ ई० में वादपत्रों के हस्ताक्षर (signing) और सत्यापन (verification) के लिए नियत रीति से हस्ताक्षरित (signed) और सत्यापित (verified) किया जायगा।

धारा २१४ के अधीन प्राथना-पत्र के नेटिस का असामी के नाम जारी होना ।

२१४-(क)—(१) घारा २१४ में उल्लिखित प्रार्थना— पत्र पाने पर अधिक्षेत्र प्राप्त न्यायालय (the court having julisdiction) असामी पर नोटिस तामील करवा कर उसके द्वारा उसे आदेश देगा कि वह य तो प्रार्थनापत्र के व्यय सहित बकाया को नोटिस को तामील के दिनांक के तीस दिन के भीतर, दे दे या दी जानेवाली अविध के भीतर इसका कारण दिखलावे कि खाते से उसकी बेदखली की कोई आजा उसके विरुद्ध क्यों न दे दी जाय।

(२) यदि दिए गए समय के भीतर असामी नोटिस में उल्लिखित धनराशि प्रार्थी को दे दे या जमा कर दे तो न्यायालय उसकी भरपाई दर्ज कर देगा और प्रार्थना-पत्र को खारिज कर देगा और जमा की हुई धनराशि प्रार्थी को दे वी जायगी।

भारा २१४-क में के अधीन जारी हुई नोटिस के अपालन पर अदा-यगी की आज्ञा। २१४—(ख)—(१)यिंद असामी परधारा २१४(क) के अधीन दिया गया नोटिस यथावत् तामील हो गया हो, किन्तु उसने पूर्वोक्त धनराशि दी या जमान की हो और कोई उज्जवारी भी न प्रस्तुत करे तो तहसीलदार उक्त धनराशि को अदायगी की, और उसके न अदा होने पर खाते से असामी की बेदखली की, आज्ञा दे दगे।

(२) यदि असामी उपस्थित होकर दावे (claim) का प्रतिवाद करे तो प्रार्थनापत्र वादपत्र मान लिया जायगा और यदि आवश्यक हो तो न्यायालय प्रार्थी को ऐसे अतिरिक्त न्याय—शुल्क के देने की आज्ञा देगा, जो बकाया लगान और बदखली के वादपत्रों से संबंध रखने वाली समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार देय हो।

- (३) यदि प्रार्थी लिए गए समय के भीतर न्याय-शुल्क न दे तो प्रार्थनापत्र अपासित कर दिया जायगा (shall be rejected)।
- (४) यदि न्याय-शुल्क यथावत् दे दिया जाय तो, एसी दशा में जहां असामी यह कहता हो कि प्रार्थी क्षेत्रपति नहीं है या खाते अथवा उसके किसी भाग का वह स्वयं भूमिधर या सीरदार है, न्यायालय मुक्तद्दमें को अधिकार-क्षेत्र प्राप्त दीवानी न्यायालय को संक्रमित (transfer) कर देगा और तब दीवानी न्यायालय उसकी उसी प्रकार मुनवाई और अवधारण करेगा मानो वह ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया बकाया लगान और बेदखली का वाद हो।

(५) उपधारा (३) के अधीन किसी प्राथनापत्र का अपासन (Rejection) बकाया लगान की वसूली के लिए प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुत करने में बाधक न होगा।

२१४--(ग)--(१)कोड आफ सिविल प्रोसीजर,१९०८ में किसी बात के रहते हुए भी किसी असामी के विरुद्ध बकाया, लगान की अदायगी की डिक्रो या आज्ञा, उस धनराज्ञि के जिसकी डिक्रो हुई है, न देने पर निष्पादन के दूसरे ढंगों के अतिरिक्त खाते से असामी की बेदखली द्वारा निष्पादित हो सकेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह ह कि दखलदिहानी की कोई आज्ञा तब तक न दी जायगी जब तक वादऋणी पर निश्चित किए जाने वाले दिनांक पर इस बात का कारण प्रकट करने के लिए, कि उक्त आज्ञा क्यों न दी जाय, कोई नोटिस न तामील हो जाय।

- (२) यदि दखलदिहानी के बाद एक मास के भीतर कारतकार उस कुल धनराशि को, जिसके संबंध में वह बेदखल हुआ हो, जमा कर देतो बेदखली की आज्ञा निरिसत (cancel) कर दी जायगी और काश्तकार को कब्जा तुरन्त वापिस कर दिया जायगा।
- २१४-(घ)—उस दिनांक से, जिसपर लगान देय हो जाय, असामी ऐसी किस्त पर जो देने से रह जाय, ६-१/४ प्रतिशत सूद का देनदार होगा।

२१४—(ङ)—लगान की ऐसी बकाया, जो किसी ऐसी संपत्ति के संबंध में हो जो केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकार के सत्वाधिकार में हो या एसे क्षेत्रों के संबंध में हो, जो धारा २६३ के निदेशों के अधीन कुर्क हुआ हो, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

बकाया लगान की डिक्री या आज्ञा के निष्पादन का ढंग।

वकाया लगान पर

सरकारी सम्पत्ति के सम्बन्ध में बकाया लगान की वसूली । बकाया को डिक्री देते समय विपत्ति के निमित न्याया छय का छूट देना २१५—(१) यदि लगान की बकाया का बाद सुनते समय न्यायालय की यह सन्तोष हो जाय कि उस काल में जिसके लगान की लकाया का दावा किया जाता है, खाते का क्षेत्रफल जलाप्लाबन के कारण (diluvion) या किमी दूसरे कारण से तत्त्वतः (substantially) घट गया था या उसकी उपज सूखा, ओला, बालू पड़ जाने या अन्य विपत्ति (calamity) हे कारण तत्त्वतः कम हो गई थी, तो उसके लिए यह वैध होगा कि वह लगान में ऐसी छूट दे दे जो उसको न्यायसंगत प्रतीत हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी किसी छूट से यह नहीं समझा जायगा कि जिरा काल के लिये वह दी गई है उसके अतिरिक्त किमी और काल के लिये भी असामी द्वारा देय लगान में कोई परियान हो गया है।

(२) यदि न्यायालय उपपारा (१) के अधीन छूट दे तो, प्रान्तीय सरकार या इस संबंध में अधिकृत कोई दूसरा आधिकारिक ऐसे निद्धान्तों के अनुसार, जो नियत किये जायं, माठगुजारी में पारिणामिक (consequential) छूट की आज्ञा देगा।

विविध (Miscellaneous)

सिंचाई संबंधी देयों की बकाया का वाद २१५-क — यदि किसी व्यक्ति को कोई रुपया नार्व इंडिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, १८७३ की धारा ४७ के अधीन नहर संबंधी देय (canal duos) के निमित्त प्राप्य हो तो वह ऐसे रुपये की बसूली के लिए बाद प्रस्तुत कर सकता है।

२१६--- क्रि

प्रस्थापनिक वाद (Declaratory)

२१६-क-स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट, १८७७ की धारा ४२ में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी गांव-सभा किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो अपने को किसी भूमि में किसी अधिकार का अधिकारी बतलाता हो, ऐसी भूमि में ऐसे व्यक्ति के अधिकार के प्रख्यापन के लिए वाद प्रस्तुत कर सकती है और न्यायालय स्वविवेकानुसार (in 1ts discretion) ऐसे व्यक्ति के अधिकार का प्रख्यापन कर सकता है और गांवसभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे वाद में किसी अपर उपशम (further relief) की प्रार्थना करे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि वादी आगम के प्रस्थापन मात्र (mere declaration of title) के अतिरिक्त कोई अपर उपशम मांग सकता हो पर न मांगे तो न्यायालय इस प्रकार का कोई प्रस्थापन न करें।

[*]-ess

२१८--(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित नियम बनाने के करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

ग्रधिकार

- (२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति की बाधित न करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:--
 - (報) [器]
 - (ख) [क्कि]
 - (ग) [क्कि]
 - (ঘ) [ৠঃ]
 - (च) [िश्री
- (छ) घारा १४० के अधीन दी जाने वाली घनराशि देने की प्रक्रिया,
- (ज) धारा १४० के अधीन दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसके देने की प्रक्रिया,
- (१) बारा१४३ के अधीन प्रमाण-पत्र (certificate) के प्रदान की प्रक्रिया और ऐसे प्रमाण-पत्र का आकार,
- (२) घारा १४३ क के अधीन खाते के बटवारे की प्रक्रिया और ढंग,
- (ञा) घारा १६० के अधीन भूमि की बदलाई की
- (ट) घारा १६३ के अधीन हसस्तान्तरण के विक्रय रूप में पुष्टीकरण (confirmation) की प्रक्रिया।
- (ठ) घारा १६५ के अधीन सीरदार और असामी बेदलली की प्रक्रिया.
- (इ) बारा १८६ और १८७ के अधीन दी जाने वाली नोटिस का आकार और उसकी तामील का हंग,
 - (ह) [क्क]
- (ण) बारा १९३ के अधीन गांव-सभा द्वारा भूमि की क़ब्बे में ले लेने की प्रक्रिया,
- (त) घारा १९४ और १९५ के अधीन भूमि को उठाने की प्रक्रिया,
- (य) इस अध्याय के अधीन वादों, प्रार्थना-पत्रों और अन्य व्यवहारों को निर्णय करने वाले अधि-कारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन (guidance),
- (द) वे विषय, जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

श्रिष्ठो निकाल दिया गया।

अध्याय ह

ग्रधिवासी

ग्राधवासी के ग्रधिकार

२१९--(१) उस दशा को छोड़ जिसकी व्यवस्था घारा २२०, २२१ और २२४ में की गई है, लगान देने पर अधिवासी को वे सब अधिकार और दायित्व प्राप्त रहेंगे, जो उसको स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भिम के सम्बन्ध में प्राप्त थे या जिनके वह अधीन था।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी संविदा या दूसरे अनुबन्ध (engagement) में किसी बात के रहते हुए भी, अधिवासी द्वारा देय लगान में कोई ऐसा परिवर्तन न किया जायगा, जो इस विधान के अधीन न किया जा सके।

(२) किसी अधिवासी के मर जाने पर खाते में उसका स्वत्व उत्तराधिकार के विषय में धारा १६९ से १७३ तक के निदेशों द्वारा नियमित होगा।

ग्रधिवासी का लगान

२२०--यदि अधिवासी द्वारा देय लगान के संबंध में कोई अनुबन्ध (engagement) न हो, [%] तो स्वत्वाधिकार के दिनांक से उसके द्वारा देय लगान उकत भूमि के सम्बन्ध में लागू मौरूसी (hereditary) दरों से लगाए गए लगान के १३३ १/३ प्रतिशत के धराबर होगा।

ग्रधिवासी की बेदखली

२२१—घारा २२४ के निदेशों को बाधित न करते हुए कोई अधिवासी निम्नलिखित आधारों को छोड़ किसी दूसरे आधार पर अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा और निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर लाये जाने वाले बेदखली के वादों से सबंध रखने वाले अध्याय ८ के निदेश, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस प्रकार लाग होंगे मानो उक्त अधिवासी असामी रहा हो :—

(क) कि उस पर लगान बाकी है,

(ख) कि उसने अपने खाते या उसके किसी भाग का हस्तान्तरण कर दिया है, या

(ग) कि वह भूमि का किसी ऐसे प्रयोजन में उपयोग करता है जो कृषि, फलोत्पादन या पञ्चपालन से संबंध न रखता हो।

पिघवासी का भूमिघर ग्रिचकार उपाजित करना

२२२—(१) यदि इस विधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की अवधि के बाद किसी समय या ऐसे पांच वर्ष के भीतर अपने क्षत्रपति की सहमति से किसी समय अधिवासी प्रान्तीय

[अ] निकाल दिया गया।

सं० प्रा० पेक्ट, ३ १६०१ ई० सरकार को निम्नलिखित घनराशि दे दे, तो वह परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर का इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने पर उस भूमि का भूमिघर प्रख्यापित होने का अधिकारी होगा :--

- (क) यदि उसके पास ऐसी भूमि है, जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर सोर या खुदकाश्त अभिलिखित थी, तो ऐमी घनराशि जो उक्त दिनांक पर प्रचलित मौक्सी दरों से लगाये गये लगान पत्द्रह गुनी हो, और
- (स) किसी और दशा में ऐसी घनराशि जो उक्त दिनांक पर उस भूमि के काश्तकार द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान की पन्द्रह गुती हो।
- (२) उपवारा (१) में उल्लिखित प्रख्यापन हो जाने पर ऐसी भूमि में क्षेत्रपति के सब अधिकार ओर स्वत्व समान्त हो जायंगे।
- (३) घारा १४०,१४१ और १४३ के निदेश आव-इयक परिवर्तनों के साथ उपघारा (१) के अधीन प्रार्थना-पत्र देने और उसकी सुनवाई के सम्बन्ध में लागू होंगे।
- (४) उपधारा (१) में किमी बात के रहते हुए भी उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर किसी समय प्रान्तीय सरकार गजट में विक्राप्ति द्वारा सब अधि— वासियों को आदेश दे सकेगी कि निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक पर या उससे पहले उक्त उपधारा (१) में उल्लिखित धनराशि जमा कर दें।
- (५) ऐसे प्रत्येक अधिवासी की, जो उक्त दिनांक पर या उससे पहले रुपया जमा न कर सकें, क्षेत्रपति के वाद पर भूमि से तुरन्त बेदबली हो सकेगी, मानो वह ऐसा व्यक्ति था जो इस ऐक्ट के निदेशों के अनुकूल और क्षेत्रपति की अनुमति बिना कब्जा किये हुए या रक्खें हुए था।
- (६) उपघारा (१) में किसी बात के रहते हुएभी, ऐसा अधिवासी जिसके पास कोई भूमि किसी पुण्यार्थ या धर्मार्थ संस्था की ओर से हो, उक्त उपघारा में उल्लिखत धनराशि किसी समय दे सकता और उपधारा (१) से (५) तक के निदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे।

२२२— [अ]यदि किसी अधिवासी ने घारा १२२ के निदेशों के अनुसार भूमिधर के अधिकार और स्वत्व उपाजित कर लिये हों, तो प्रान्तीय सरकार क्षेत्रपति को निम्नलिखित धनराशि देगी:——

ग्रधिवासी के श्रेत्रपति का प्रतिकर पाना

^[*] निकाञ द्या गया।

- (क) यदि क्षेत्रपति या उसका पूर्वाधिकारी (Predecessor) घारा १९ की उपधारा (१) के खण्ड (क) में अभिदिष्ट भूमिपर था तो ऐसी घनराशि, जो धारा २२२ के अधीन जमा की हुई धनराशि की एक-तिहाई हो, और उसी के साथ ऐसी धनराशि जो इस विधान के निदेशों के अनुसार उसे देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के, यदि कोई हो, बराबर हो;
- (ख) यदि वह धारा २२२ की उपधारा (१) के अधीन दिए गए प्रख्यापन के दिनाक पर खण्ड (क) में अभिदिष्ट भूमिधर से भिन्न भूमिधर था, तो धारा २२२ के अधीन जमा की गई कुल धनराशि;
- (ग) यदि वह या उसका स्वत्व पूर्वाधिकारी धारा २२२ की उपधारा (१) के अधीन दिए गए प्रख्यापन के दिनाक पर सीरदार था, तो वह धनराशि, जो उक्त धारा के अधीन जमा की गई धनराशि की एक-तिहाई के बराबर हो।

२२४—(१) गजट में विज्ञादित द्वारा प्रान्तीय सरकार यह प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञादित के विनांक से निर्दिष्ट क्षेत्रों में इस घारा के निदेश लागू हो जायंगे।

- (२) जहा किसी मंडल में भूमिपर या सीरदार का कोई खाता या उसका भाग किसी अधिवासी के दखल में है वहां यदि संयुक्त प्रात में भूमिधर या सीरदार की निजीजोत में कोई भूमि नहीं है या ८ एकड़ से कम है, तो यह परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर को इस आधार पर अधिवासी की बेदखली के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि वह अधिवासी के दखल वाली भूमि को अपनी निजीजोत में लाना चाहता है।
- (३) गांव-सभा और ऐसे सब अधिवासी, जो प्रार्थी की ओर से किसी भूमि पर काबिज हों, [*]इस घारा के अधीन लाए गए व्यवहार में फरीक़ बनाये जायंगे।
- (४) यदि प्रार्थना-पत्र यथावत् दिया गया हो और असिस्टेंट कलेक्टर को ऐसी जाच के बाद, जो नियत की जाय, यह संतोष हो जाय कि प्रार्थी के पास अपनी निजी जोत में कोई भूमि नहीं है, या आठ एकड़ से कम भूमि है, और अधिवासी के कब्जे की भूमि को वह अपनी निजी जोत में लाना चाहता है, तो वह अधिवासी या अधि—वासियो की बेदलली की आज्ञा इतनी भूमि से दे देगा जितनी को मिलाकर प्रार्थी की निजी जोत में आठ एकड़ भूमि हो जाय।

ग्रलाभकर खाते से ग्रियवासी की बेदखली—

(५) जब-कभी कोई अधिवासी उपघारा (४) के निदेशों के अधीन बेदखल हो गया हो, असिस्टेंट कलेक्टर गांव-सभा के कथन को सुनकर गांव-सभा को यह आदेश दे सकता है कि उक्त भूमि के अधिवासी को, लागु मौरूसी दरों से लगाए गए इतने मुल्य की, खाली भूमि सीरदार के रूप में उठा दे, जो उसी प्रकार लगाए गए उस भूमि के मृत्य के बराबर हो, जिससे उसकी बेदलली की आज्ञा हुई है।

२२५--यदि क्षेत्रपति या जहां एक से अधिक क्षेत्र-पति हों वे सब ऐसे व्यक्ति रहे हों जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर घारा १५६ में उल्लिखित वर्गों में से किसी के अन्तर्गत थे तो घारा २२१ से २२४ तक की कोई बात अधिवासी को लागू नहीं होगी ।

ग्रक्षम क्षत्रपतियों के सम्बन्ध में ग्रपवाट।

२२६ एसा अधिवासी, जिसे घारा २२५ लाग् होतो हो, इस विधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर, ऐसे सब अधिकारों और दायित्वों के साथ, जो इस विधान के द्वारा या अधीन किसी असामी को दिये गये हों, या उस पर लगाए पए हों, असामी हो जायगा और असामी समझा जायगा।

अधिवासी का ४ वर्ष बाद , ग्रसामी हो जाना--

२२७—(१) इस अध्याय के निवेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती है।

नियम ग्रधिकार--

- (२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :---
- (क्र) घारा २२४ के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र का आकार और उसमें दिये जाने वाले व्यौरे.
- (ख) घारा २२४ के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निर्णय करने की प्रक्रिया,
- (ग) यह निर्णय करने के सिद्धान्त कि कौन-कौन अधिवासी और कितने क्षेत्र से धारा २२४ के अधीन बेदखल किया जाय या किए जायं,
- (घ) भारा २२४ के अधीन दी गई आजाओं को कार्यान्वित करना, और
- (ङ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

अध्याय १०

मालगुजारी

२२८—(१) किसी गांव में स्थित भूमि के सम्बन्ध गांव पर निर्धारित में सभी भूमिषरों और सीरदारों द्वारा देव कुल मालगुजारी उस गांव पर निर्धारित मालगजारी समझी जायगी।

मालगुजारी।

(२) किसी गांव पर निर्धारित मालगुजारी पूरे गांव के अन्तर्गत सभी भूमि तथा उसके लगान, लाभ या उपज पर प्रथम भार (first charge) होगी।

भूमियर या सोरदार की भूमि पर माल-गुजारी का टायित्व

- (३) [अ]
 २२९—(१) ऐसी भूमि को छोड़ जो इसके बाद
 प्रान्तीय सरकार के अनुदान या उसके साथ हुई संविदा
 द्वारा पूर्णतः या अंज्ञतः मालगुजारी के दायित्व से
 मुक्त कर दी जाय, ऐसे व्यक्ति के पास की, जो उसका
 भूमिधर या सीरदार हो या समझा जाय, सभी भूमि पर,
 वह कहीं भी स्थित हो, प्रान्तीय सरकार को देय मालगुजारी का दायित्व होगा।
- (२) यद्यपि अभ्यपित (assigned), अभित्यक्त (released), अभिसंधित (compounded) या निष्कीत (redeemed) होने के कारण मालगुजारी प्रान्तीय सरकार को देय न हो, तब भी वह भूमि पर निर्धारित की जा सकती है।
- (३) न तो किसी भूमि पर किसी के कब्जे की कोई दीर्घकालीनता (longth of occupation) न इस विधान के प्रारम्भ से पहले सम्प्राट प्रान्तीय सरकार या क्षेत्र—पति द्वारा दिया गया कोई अनुदान ऐसी भूमि को मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर सकेगा।

भूमिधर ग्रौर सीरदार गांव पर निर्धारित मानगुजारों के छिये दायित्व

- २३०—(१) गांव के सभी भूमिधर और सीरदार उम गांव पर समय विशेष पर निर्धारित मालगुजारी देने के प्रान्तीय सरकार के प्रति संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हें ऐसे भूमिधर और सीरदार के स्वत्व उत्तराधिकार द्वारा या किसी अन्य प्रकार से मिलें वे उस स्वत्व को पाने के समय वेय मालगुजारी की कुल बकाया के लिये उत्तरवायी होंगे।
- (२) उपधारा (१) के निदेशों. के होते हुए भी, कोई भूमिश्वर या सीरवार, ऐसे खाते की, जिसमें वह पूर्णतः (wholly) या अंशतः स्वत्व रखता हो, माल-गुजारी की बकाया को छोड़ और किसी मालगुजारी की बकाया देने को तब तक न बाध्य (compelled) किया जायगा जब तक प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञिन्ति द्वारा यह न प्रख्यापित कर दे कि उपधारा (१) के निदेश किसी निविद्ध क्षेत्र को लागू होंगे।

दूसरें की ग्रोर में मालगुजारी का दिया जाना २३१--- यदि किसी भूमिथर या सीरदार ने अपने अंश से अधिक मालगुजारी दी हो तो वह दूसरे भूमिथरों और सीरदारों से उनकी ओर से इस प्रकार दिये गये अधिक घन की प्रतिपूर्ति करा सकता है (may require to reimburse)। २३२—इस विधान के निदेशों को बाधित न करते हुए प्रत्येक भू मिधर अपनी भू मिधरी भूमि के लिये प्रान्तीय सरकार को मालगुजारी के निमित्त निम्नलिखित का देनदार होगा:—

भूमिधर द्वारा देय माल-गुजारी को मात्रा

- (क) यदि वह स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर,
 - (१) मध्यवर्ती था, तो धारा ४८ के खंड (घ) के उपखंड (२) में अवधारित धनराज्ञि,
 - (२) शरहमो अहयन काश्तकार था, तो ऐसी धनराशि जो उक्त दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान के बराबर हो, और
 - (३) माफीदार था, तो ऐसे सिद्धान्तों के आधार पर, जो नियत किए जायं, अवधारित धनराशि;
- (क क) यदि वह धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर हुआ हो, तो ऐसी धनराशि जो स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिए देय लगान के आधे के बराबर हो।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त लगान लागू मौक्सी दरों से लगाए गए लगान के दुगने से अधिक हो तो मालगुजारी ऐसे दरों से लगाए गए लगान के ही बराबर होगी।

- (ख) यदि उसने भूमिषर के अधिकार घारा १४३ के अधीन उपाजित किये हों तो उक्त घारा की उपधारा (२) के खंड (ख) में उल्लिखित मालगु-जारी की घनराशि,
- (ग) यदि उसने भूमियर के अधिकार घारा १४४ के अधीन उपार्जित किये हों तो उक्त घारा में उल्लिखित मालगुजारी की घनराशि,

(घ) [क्कि]

- (ङ) यदि वह घारा २२२ के अधीन भूमिषर प्रस्यापित हुआ हो तो वह धनराशि जो नियत किये जाने वाले सिद्धान्तों पर अवधारित की जाय।
- २३२—(१) इस विधान के निवेशों को बाधित न करते हुए प्रत्येक सीरदार उस भूमि के लिये, जो उसके पास सीरदार के नाते हो, मालगुजारी के निमित्त प्रान्तीय सरकार को निम्नलिखित का वेनदार होगाः—

[क] यदि वह घारा २० के अधीन सीरदार हुआ हो तो वह घनराशि जो उक्त दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारावेंय या देय समझे गये लगान के बराबर हो, सीरदार द्वारा देव मालगुजारी को मात्रा

निकाल दिया गया।

[ख] यदि सीरदार को धारा १९४ के अधीन भूमि उठाई गई हो तो ऐसी धनराज्ञि जो नियत किये जाने वाले सिद्धान्तों पर अवधारित की जाय, या

[ग] यदि उसने सीरदार के अधिकार घारा २०१ या २०७ के अधीन उपार्जित किये हों तो वह धनराज्ञि जो ऐसे सीरदार द्वारा देय थी जिसके अधिकार उसने इस प्रकार उपार्जित किये हैं।

(२) यदि उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट सीरदार स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उक्त भूमि के लिए ऐसे लगान का देनदार हो जो जिन्सी हो या खंडी फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा देय लगान वह धनराशि समझा जायगी जिसे असिस्टेट कलेक्टर नियत की जाने वाली रीति से और नियत किए जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित कर दें।

१ जुलाई, १६४८ ई० की या इसक बाद मिली भूमि के लिये सोरदार द्वारा माल-गुजारी २३४—घारा २३३ में किसी बात के रहते हुये भी, किसी सीरदार द्वारा ऐसी भूमि के लिये देय मालगुजारी जो उसे कादतकार के रूप में १ जुलाई, १९४८ ई० को या उसके बाद उठाई गई है, ऐसो दशा में जब स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहिले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान उक्त दिनांक पर लागू मौहसी दरों से अवधारित लगान की धनराशि से कम निकले, उक्त धनराशि के बराबर होगा।

धारा २३२ श्रीर २३३ के ग्रधींन मालगुजारी देने के दिनांक ग्रीर किस्ते

२३५—(१) प्रान्तीय सरकार ऐसा याऐसे दिनांक, जिनसे और ऐसी किस्तें, जिनम घारा २३२ और २३३ में अभिदिष्ट भूमिधरों और सीरदारों द्वारा मालगुजारो देय होगी, नियत कर सकती है।

(२) जो मालगुजारी या उसकी कोई किस्त निश्चित दिनांक पर या उसके पहिले देने से रह जायगी मालगुजारी की बकाया हो जायगी और उसके देनदार व्यक्ति बाकीदार (defaulters) हो जायगे।

भूमिघर या सीरदार द्वारा देय ग्रववाव ग्रीर स्थानीय कर २३६—(१) यदि स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी क्षेत्र में किसी आस्थान के सम्बन्ध में अबवाब या स्थानिक कर निर्धारित और देय हों तो स्वत्वाधिकार के दिनांक पर इस विधान के निवेशों के अनुसार भूमिधर या मीरदार द्वारा देय माल-गुजारी के अन्तर्गत उतना ही अबवाब और स्थानीय कर समझा जायगा जितना उसके खाते की भूमि के सम्बन्ध में ३० जून, १९४९ ई० को आदेय हो (levied with respect to the land in his holding on June 30, 1949)।

(२)—उपधारा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जा सकेगा कि किसी स्थानिक अधिकारी को मालगुजारी में इस प्रकार अन्तर्गत धनराशि को अबवाब और स्थानिक कर के निमित्त आरोपित (1mpose) करने का अधिकार है।

२३७—यदि घारा १८६ के अघीन सीरदार अपने खाते का केवल एक ही भाग समर्पित (surrender) करे तो, उसके द्वारा देय मालगुजारी की घनराशि ऐसे सिद्धान्तों पर, जो नियत किये जायं, घटा दी जायगी।

२३८—इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी, भूमिधर [अ] द्वारा देय मालगुजारी उसके खाते के क्षेत्रफल के घटने या बढ़ने के आधार को छोड़ किसी और आधार पर इस विधान के प्रारम्भ से ठीक बाद के चालीस वर्षों के भीतर परिवर्तित नहीं की जायगी।

२३९—इस विधान के प्रारम्भ से चालीस वर्ष के बाद किसी समय प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी का बन्दोबस्त (settlement) करने का निवश दे सकती है। आगे चलकर इसकी आरम्भिक बन्दोबस्त (original settlement) कहा जायगा।

२४०—आरम्भिक बन्दोबस्त से चालीस वर्ष बाद किसी समय प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी का नया बन्दोबस्त करने का निर्देश दे सकती हैं। इसको आगे चलकर पुनरीक्षित बन्दोबस्त (revision settlement) कहा जायगा—

किन्त प्रतिबन्ध यह है कि समय विशेष पर प्रचलित बन्दोबस्त की समाप्ति से पहिले मालगुजारी में कोई वृद्धि कार्यान्वित नहीं होगी।

२४०-क- प्रान्तीय सरकार के यह निश्चित करने के बाद कि किसी जिले या उसके भाग का नया बन्दोबस्त प्रारम्भ किया जाय, उस आशय की विज्ञिष्त यथाशीष्र प्रकाशित कर दी जायगी और तदुपरान्त उक्त जिला या उसका भाग तब तक बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन समझा जायगा जब तक बन्दोबस्त कार्यवाही की समाष्ति को प्रख्या-पित करने वाली विज्ञिष्त प्रकाशित न हो जाय।

[क्कि] निकाल दिया गया।

सीरदार द्वारा खाते के किसी भाग के समप्ण के कारण मालगुजारी में कमी

पेसे भूमिघर की मालगुज।रो में परि-वर्त न जिसकी घारा २३२ छागु होती है

माळगुजारी का श्रा**र-**म्भिक बन्दोबस्त

बन्दोबस्त मालगुजारी का पुनरीक्षण

बन्दोबस्त की विज्ञप्ति

बन्टोबस्त ग्रधिकारी की नियुक्ति श्रीर उसक श्रधिकार। २४०-ख--प्रान्तीय सरकार किसी जिले या उसके भाग के बन्दोबस्त का भार ग्रहण करने के लिये एक अधिकारी (जिसे आगे चल कर बन्दोबस्त अधिकारी कहा जायगा) तथा इतने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, जितने वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है, और जब तक उक्त जिला या उसका भाग बन्दोबस्त कार्यवाही के अधेन रहेगा, तब तक ऐसे अधिकारी उन अधिकारों का प्रयोग करेगे, जो उन्हें इस विधान द्वारा दिये जायं।

क्लेक्ट्र के ग्रधिकारी का वन्दोवस्त श्रधिकारी के पाम सक्रमण।

२४०-ग--कोई जिला या उसका कोई भाग बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन हो जाने पर प्रान्तीय सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी को नक्शा और खसरा के रख-रखाव तथा वार्षिक रजिस्टरों की तैयारी के कर्त्तंच्य संक्रमित (transfer) कर सकती है और ऐसा होने पर बन्दोबस्त अधिकारी को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो यूनाइटेड प्राविन्सेज लैन्ड रेवेन्य ऐक्ट, १९०१ के तीसरे अध्याय द्वारा कलेक्टर को दिये गये हैं।

बन्दे। बस्त की अवधि

२४१—वन्दोबस्त चालीस वर्ष तक प्रचलित रहेगा; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एहतमाली प्रदेशों (precarious tracts) और कछार क्षेत्रों (alluvial areas) के विषय में प्रान्तीय सरकार यह निर्देश कर सकती है कि ऐसे क्षेत्रों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, वन्दोबस्त किसी ऐसे समय के लिये प्रचलित रहेगा, जो चालीस वर्ष से कम हो,

और यह भी प्रतिबन्ध है कि यदि प्रान्तीय सरकार का यह भत हो कि पुनरोक्षित बन्दोबस्त की कायवाही अनुपयुक्त होगी यदि ऐसे बन्दोबस्त में किसी कारण से देर हो गई हो तो, प्रान्तीय सरकार समय विशेष पर प्रचलित बन्दोबस्त की अविध ऐसे समय के लिये बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे।

पहतुमाली या कक्कार दोनेंं का कलेकुर द्वारा बन्दोबस्त i

२४१-क--यदि किसी पृहतमाली प्रदेश या कछार क्षेत्र के विषय में निश्चित की गई बन्दोबस्त की अवधि ४० वर्ष से कम हो और ऐसी अवधि बीत जाय या बीतने को हो तो कलेक्टर ऐसे प्रदेशों और क्षेत्रों की मालगुजारी का निर्धारण और उनका बन्दोबस्त ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।

धारा २४१-क के
अन्तर्गत कलेक्टर
द्वारा बन्दोबस्त
अधिकारों के अतिः
कारों का प्रयोग।

२४१-ख- (१) धारा २४१ (क) के अधीन बन्दोबस्त करने और मालगुजारी का निर्धारण पुनरीक्षण करने के प्रयोजन के लिये कलेक्टर को बन्दोबस्त अधिकारी के सब अधिकार प्राप्त होंगे। (२) कोई बन्दोबस्त धारा २४१-क के अधीन किया गया मालगुजारो के निर्धारण का पुनरीक्षण (revision) या धारा २५० के अधीन मालगुजारी का स्थगन (suspension) तब तक अंतिम न होगा जब तक वह किमइनर द्वारा स्वीकृत नहीं जाय।

२४२—जब किमी जिला या उसके भाग के बन्दोबस्त कार्यं वाही के अधीन आजाने पर बन्दोबस्त अधिकारी या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (Settlement Officer or Assistant Settlement Officer) बन्दोबस्त कार्यवाही के अधीन प्रत्येक गांव का निरीक्षण करेगा और ऐसी रीति से और ऐसे सिद्धान्तों पर, जो नियत किये जार्य, उस जिले या भाग को भूमि-श्रेणियों (soil classes) और निर्धारण मंडलों (assessment circles) में बांट देगा।

२४२-क बन्दोबस्त अधिकारी ऐसी सब भूमि के विषय में जो किसी प्रतिबन्ध के साथ या किसी विशेष अवधि के लिये मालगुजारी के दायित्व से मुक्त कर दी गई हो जांच करेगा और यदि उसे यह ज्ञात हो कि प्रतिबन्धों का उल्लंघन हुआ है या अवधि समाप्त हो गई है तो ऐसी सब भूमि पर मालगुजारी का निर्धारण कर देगा।

२४२-ख--(१) यदि किसी ऐसी भूमि के विषय में, जो मालगुजारी से मुक्त न अभिलिखित हो, कोई यह दावा करे कि वह मालगुजारी से मुक्त है, तो उसे ऐसी भूमि को अपने अधिकार में मालगुजारी से मुक्त रखने का आगम सिद्ध करना पड़ेगा।

(२) यदि वह अपने आगम को सिद्ध कर ले और उससे बन्दोबस्त अधिकारी को सन्तोष हो जाय तो यह मामला प्रांतीय सरकार को प्रसूचित कर दिया जायगा (shall-be reported) और इस संबंध में सरकार जो आज्ञा देगी वह अंतिम होगी।

(३) यदि आगम (title) इस प्रकार सिद्ध न हो तो बन्दोबस्त अधिकारी उस भूमि पर मालगुजारी— निर्धारण की कार्यवाही करेगा और उस भूमि के अधिकारी व्यक्ति के साथ उसका बन्दोबस्त करेगा।

२४३—वह भूमि जिस पर साधारणतया मालगुजारी निर्धारित की जायगी, ऐसी भूमि को छोड़ जिसके विषय में इस धारा में आगे अपवाद किया गया है, गांव के भूमिधरों और सीरदारों के अभिलेख वर्ष वाले सभी खातों की संकलित भूमि (aggregate holdings area) होगी:——

बन्देग्बस्त ऋधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

क्<u>क</u> दशा शे' में
 माफी पर माल गुजारी का निर्धारण।

गाफी रखने का ज्ञागम।

गांव में खातों के कुल क्षेत्रफल पर माल-गुजारी का निर्धा-रित होना।

ग्रपवाद

- (१) ऐसी भूमि जिस पर ऐसी इमारतें हो जो उन्नानि न समझी जायं,
 - (२) खलिहान,
 - (३) कब्रिस्तान और इमशान भूमि, और
 - (४) ऐसी और भूमि जो नियत की जाय। (४ (१) निकी निर्धाण पंतन में किसी नार्

मालगुजारो-निर्घारण के सिद्धान्त ।

- २४४—(१) किसी निर्धारण मंडल में किसी खाते के लिये देय मालगुजारी निर्धारित करते समय बन्दोबस्त अधिकारी ऐसे खाते की उपज की उस अनुमानित औसत बचत का ध्यान रक्ष्येगा जो नियत की जाने वाली रीति से निश्चित (ascertained) या अनुमानित (estimated) खेती के साधारण ध्यय घटाकर बचे और मालगुजारी उपज की बचत का ऐसा प्रतिशत होगी जो प्रान्तीय सरकार की सिफारिशों पर विचार करके संयुक्त प्रान्तीय विधायिका (United Provinces Legislature) द्वारा पास किये गये प्रस्ताव से निश्चित किया जाय, ऐसी सिफारिशों गजट में तथा निर्धारण मंडल में, ऐसी किसी दूसरी रीति से, जो नियत की जाय, प्रकाशित हो जान के एक मास बाद किसी समय विधायिका के सामने रखी जायंगी।
- (२) उपज की बचत पर जितने प्रतिशत से मालगुजारी निर्धारित होगी वह प्रान्तीय सरकार द्वारा नियत क्रिये हुये क्रमिक मान (graduated scale) के अनुसार बदलता रहेगा, वह उपज की सबसे अधिक बचत वाले खातों पर सबसे अधिक होगा और उपज की सबसे कम बचत वाले खातों पर सबसे कम।
- (३) भूमिघर को लागू प्रतिशत सीरदार को लागू प्रतिशत के आधे से अधिक नहीं होगा।

२४५--[

भालगुजागी निर्धा-एण सम्बन्धी प्रस्ताव।

२४७—बन्दोबस्त अधिकारी, किसी गांव की माल-गुजारी का निर्धारण पूरा कर चूकने पर, अपने प्रस्ताव ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा, जो नियत की जाय, ऐसी उज्जदारियों पर विचार करेगा, जो प्रस्तुत की जायं और फिर अपने प्रस्ताव ऐसी उज्जदारियों के साथ, यदि कोई हों, और ऐसी आजाओं के साथ, जो उन पर वी गई हों, नियत आधिकारिक (authority) को भेज देगा और ऐसा आधिकारिक अपनी आलोचना (comments) के साथ उन्हें प्रान्तीय सरकार के पास भेज देगा।

निर्धारण के प्रस्तावों पर प्रान्तीय सरकार की ग्राजायें।

२४८—(१) प्रान्तीय सरकार घारा २४७ में उल्लि-खित सामग्री पर तथा नियत आधिकारिक की आलोचना (Gomments) पर विचार करके ऐसी आज्ञा वेगी जो वह उचित समझे।

^[*] निकाल विया गया।

- (२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रान्तीय सर-कार की आज्ञा पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जा सकेगा(shall not be called in question)।
- २४९--(१) उम दशा की छोड जब खात क्षेत्रफल या उसके अन्तर्गत भूमि का उपजाऊपन नदी के बहाव (fluvial action) या किसी दूसरे प्राकृतिक कारण से घट या बढ़ गया हो, किसी खाते पर निर्धारित मालगुजारी बन्दोबस्त के प्रचलित रहते हुये घटायी या बढ़ायों नही जा सकेगी, पर यह बात इस विधान के निदेशों को किसी प्रकार बाधित न करेगी।

वन्दोबस्त के प्रचलित काल में मालगुजारा का नघटाया या बढ़ाया जाना।

- (२) जब-कभी उपघारा (१) के अधीन मालगुजारी घटाई या बढ़ायी जाय, तो प्रान्तीय सरकार ऐसी भूमि पर काबिज असामी द्वारा देय लगान घटा या बढ़ा सकती है।
- २५०-(१) इस विधान में किसी बात के रहते हुये भी, ऐसी कृषि सम्बन्धी विपत्ति (agricultural calamity) के आने पर, जिससे किसी गांव या गांव के भाग की फसल पर प्रभाव पड़े, एसी विपत्ति से प्रभावित किसी खाते की पूरी मालगुजारी या उसके किसी भाग को प्रान्तीय सरकार किसी समय के लिये छोड़ सकती है या स्थगित कर सकती है।

कृषि सम्बन्धी विपत्ति ग्राने पर मालगुजारो मं छूट या उसका स्थगन ।

(२) जब-कभी प्रान्तीय सरकार उपघारा (१) के अधीन कार्य करे तो, ऐसी भूमि पर कार्बिज असामी द्वारा देय कुल लगान या उसके किसी भाग की यह छोड़ सकती है या स्थगित कर सकती है।

की अदायगी स्थिगत कर दी जाय तो लगान की वसूली का वाद प्रस्तुत करने के लिये दी गई अवधि की गणना करते समय वह अवि , जिसमें लगान की अदायगी स्थगित रही हो, निकाल दी जाएगी।

२५०-क-यदि धारा २५० के अधीन लगान

२५०-ख--(१) धारा २५० के अधीन दी गई किसी आज्ञा पर किसी दीवानी या माल न्यायालय मे कोई आक्षेप न किया जा सकेगा (shall not be questioned) 1

(२) कोई वाद या प्रार्थना-पत्र न तो ऐसे रुपये की वसूली के लिये, जिसकी अदायगी के विषय में धारा २५० के अधीन छूट दे दी गई हो और न स्थगन की अविध के भीतर किसी ऐसे रुपए के लिये, जिसकी अदायगी उक्त धारा के निदेशों के अधीन स्थगित कर दी गई हो, लाया जा सकेगा।

कालावधि के प्रयोजनों के लिये धारा २५० के अधीन हुए स्थगन की अवधि का निकाल दिया जाना ।

धारा २४० के ग्रम्त-गैत ग्राजा का न्या-यालय द्वारा ग्राक्षेप न किया जाना।

कृषि सम्बन्धी पैदावार के मूल्य मे हास के कारण पुनरीक्षित बन्दोबस्त का होना। २५०-ग--यदि प्रान्तीय सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि कृषि सम्बन्धी पैदावार के मूल्य में कोई ऐसा तात्त्विक हास (substantial decay-ing) हो गया है, जिसके कुछ समय तक बने रहने की सम्भावना है, तो इस विधान में, या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरे विधायन (enactment) में, किसी बात के रहते हुए भी, वह गजट में विज्ञित हारा किसी क्षेत्र विशेष में पुनरीक्षित बन्दोबस्त का आदेश दे सकती है।

धारा २५०-ग के अधीन बन्दोबस्त के लिये अधिकारी की नियुक्ति। २५०-घ--धारा २५० ग के अधीन विज्ञिष्ति जारी हो जाने के बाद किसी समय भी प्रान्तीय सरकार ऐसे क्षेत्र में बन्दोबस्त अधिकारी के अधिकारों से युक्त कोई अधिकारी, ऐसे निरोधों और प्रतिबन्धों के साथ, जो उसे उचित जान पड़े, नियुक्त कर सकती है, किनु इस प्रकार नियुक्त किसी अधिकारों को कोई ऐसा अधि-कार न दिया जा सकेगा, जिससे वह उक्त क्षेत्र की माल-गुजारी बढ़ा सके।

[मालगुजारी से मुक्त अनुदानो के सम्बन्ध में वार्षिक जाच । २५०-इ--ऐसी सब भूमि के विषय में जो मालगुजारी की अदायगों से, किसी प्रतिबन्ध के साथ या किसी विशेष अवधि के लिये मुक्त कर दी गई हो, कलेक्टर प्रति वर्ष अाच किया करेगा।

यदि प्रतिबन्ध का उल्लंघन हुआ हो तो वह उस मामला को आज्ञा के लिये कमिश्तर को प्रसूचित (report) कर देगा और यदि अवधि समाप्त हो गई हो या, जहा माफी का अनुदान माफीदार के जीवन-काल के ही लिये हो, यदि माफीदार मर गया हो, तो वह भूमि पर मालगु-जारी निर्धारित करके अपनी कार्यवाही स्वीकृति के लिए कमिश्तर को प्रसूचित कर देगा।

खेती-भूमि घटाने या बढ़ाने के कारण मालगुजारी का घटाना या बढाना। २५१—जब प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आज्ञा द्वारा इस प्रकार के निर्देश दे तो, प्रत्येक कृषि—वर्ष के प्रारम्भ में गांव—सभा, एहतमाली प्रदेशों या कछार—क्षेत्रों में स्थित खातों के क्षेत्रफल के सभी परिवर्तनों के विषय में कलेक्टर को सूचना देगी और तब कलेक्टर, ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, ऐसी भूमि का, जो खेती से निकल गई हो, या खेती में ले ली गई हो, ध्यान रखते हुये, गाव पर निर्धारित मालगुजारी बढ़ा या घटा सकता है।

मालगुजारो की वस्ली

२५२—मालगुजारी की वसूली के लिये प्रान्तीय सर-कार ऐसा प्रबन्ध कर सकती है और ऐसे साधनों (agencies) का उपयोग कर सकती है, जो वह उचित समझ।

२५३—(१) गजट में सामान्य या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके प्रातीय सरकार गाव-सभा को ऐसे क्षेत्र में जिसके लिये वह स्थापित की गई हो या उसके किसी भाग में, प्रांतीय सरकार के लिये या उसकी ओर से माल-गुजारी और ऐसे दूसरे देय जो नियत किये जायं, वसूल करने और उगाहने का भार सौंप सकती है।

(२) जब गांव-सभा की उपघारा (१) के अधीन इस प्रकार भार सौंपा गया हो तो तत्सम्बन्धी गांव-पंचायत का कर्त्तं व्य होगा कि वह इस विधान के निदेश के या समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अनुसार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के सम्ब ध में समय-समय पर प्रांतीय सरकार के। देय मालगुजारी तथा पूर्वे क्ति देयों को वसूल करे और उगाहें।

२५४——जब गांव—सभा को घारा २५३ के अधीन भारतगुजारी और दूसरे देयो की वसूस्ती और उगाही का भार सौंपा गया हो तो,

- (क) धारा २३० के आदेशों को वाधित न करते हुए, प्रत्येक भूमियर ओर सीरदार अपने द्वारा समय विशेष पर देय मालगुजारी और दूसरे देयों का गांव-सभा के प्रति देनदार होगा।
- (ख) मालगुजारी और दूसरे देयों की ऐसी धनराशि, जो गांव-पंचायत के किसी सदस्य (जिसके अन्तर्गत प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडट भी हैं) या किसी अधिकारी ने वसूल कर ली हो और प्रांतीय सरकार को न मिली हो, समय विशेष पर प्रचलित किसी दूसरी विधि के अधीन उसके दायित्व (liability) को बाधित न करते हुए, उससे या उसकी ऐसी सम्पत्ति से, जो उसके विधिक प्रतिनिधियो (legal representatives) के हाथ में हो, मालगुजारी की खनाया (arrears of land revenue) के इप में वसूल की जायगी, और
- (ग) उसके द्वारा या उसकी ओर से बसूल की और उगाही गई मालगुजारी या दूसरे देयों पर गांव— सभा को ऐसा कमीशन दिया जायगा, जो नियत किया जाय।

२५४-क-तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हिसाब का लेखा, इस अध्याय के प्रयोजनो के लिये मालगुजारी के बाकी होने का, उसकी मात्रा का और ऐसे व्यक्ति के विषय में जो बाकीदार हो, निश्चायक प्रमाण होगा; मालगुजारो की वसूलो का प्रबन्ध।

गांव-पंचायत द्वारा मालगुज़ारी का वस्ली।

गांव-सभा द्वारा माल-गुजारी की वस्त्री क परिणाम। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे गांव मे, जिसके सम्बन्ध में घारा २५३ के अधीन आज्ञा दी गई हो, ऐसा लेखा किसी विशेष बाकीदार के सम्बन्ध में गांव—सभा द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

२६०—मालगुजारी की बकाया निम्नलिखित रीतियों में से एक या अधिक से वसूल की जा सकेगी:--

- (क) किसी बाकीदार पर मांग-पत्र (writ of domand) या उपस्थिति-पत्र (citation) तामील कर के,
- (ख) उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध (detention) से,
- (ग) उसकी चल-सम्पत्ति की, जिसके अन्तर्गत उपज भी है, [¾] कुर्की या नीलाम से,
 - (घ) खाते की कुर्की से,
- (ङ) उस खाते का हस्तान्तरण कर के जिसके सम्बन्ध में बकाया हो,
- (च) बाक^भदार को दूसरी अचल—सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम से।

मांग-पत्र और उपस्थिति-पत्र। २६०-क--(१) मालगुजारी की बकाया के देय होते ही तहसीलदार माग-पत्र जारी करके बाकीदार को आदेश दे सकते हैं कि वह निर्दिष्ट किये जाने वाले समय के भीतर बकाया दे दे।

- (२) मांग-पत्र के अतिरिक्त या उसके स्थान पर तहसीलदार निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक पर उपस्थित होने और देय बकाया को जमा करने के लिये बाकीदार के विरुद्ध उपस्थित-पत्र जारी कर सकतें है।
- (३) जहां घारा २६१ के अधीन गाव-सभा को अधिकार दिया गया हो, वहां उपघारा (१) और (२) में अभिदिष्ट मांग-पत्र और उपस्थिति-पत्र गांव-सभा की ओर से गांव-पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है।

^{[* |} निकाल द्या गया।

२६०-ख-- कोई भी मालगुजारी का बाकी- गिरफ्तारी और निरोध दार गिरफ्तार किया जाकर ऐसी अवधि के लिय, जो १५ दिन से अधिक न हो, निरोध में रखा जा सकता है, जब तक कि वह गिरफ्तारी और निरोध का क्यय, यदि कोई हो, उक्त अविध से पहले ही न दे वॅ.

किंतु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारके अधीन किसी स्त्री या अवयस्क की गिरफ्तारी या निरोध न हो सकेगा;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध ऐसे बकाया के लिये न हो सकेगी, जो किसी ऐसे खाते के सम्बन्ध में हो, जिसका भूमिधर या सीरदार न हो।

२६०-ग-(१) बाकीदार चाहे गिरफ्तार हुआ चल-सम्पत्ति की ककी हो या नहीं, कलेक्टर उसकी चल-सम्पत्ति को कुर्क और और नीलाम। नीलाम कर सकते है।

- (२) इस धारा के अधीन प्रत्यक कुर्की और नीलाम दीवानी न्यायालय की डिकी के निष्पादन में चल-सम्पत्ति की कुर्की और नीलाम के विषय म, समय विशेष पर प्रचलित विधि के अनुसार, किया जायगा।
- (३) कोड आक्त सिविल प्रोसीजर, १९०८ की धारा ६० के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के खंड (ए) से (ओ) तक में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, एसी वस्तुएं भी, जो केवल धार्मिक उपासना के लिये अलग कर दी गई हों, इस घारा के अधीन कुर्की और नीलाम से मुक्त रहेंगी।
- (४) कुर्की और नीलाम का व्यय मालगुजारी की बकाया में जोड़ दिया जायगा और उसी प्रकार वसूल किया जा सकेगा।
- (५) जहां धारा २६० के खंड (ग) के अधीन गांव-सभा को बसूली का अधिकार दिया गया हो, वहां गांव-सभा चत्र-प्रस्पत्ति की कुर्की और नीलाम करने में ऐसी प्रिक्रया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

गांव-पञ्चायत का धारा २६० के ऋधि-कारों का प्रयोग।

मालगुजारी की बकाया की वसूली के लिये खाते का नीलाम——

विक्रय-मृत्य का प्रयोग

दूसरी अचल-सम्पति में बाकीदार के स्वत्व के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार--

धारा २५२ के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा अदा की गई बकाया की बसूली— २६१ — यदि गांव-सभा को घारा २५३ के अधीन मालगुजारी बसूल करने और उगाहने का भार सौंपा गया हो तो, प्रान्तीय सरकार गजट में तत्सम्बन्धी या विशेष आज्ञा प्रकाशित करके सामान्य गांव-पंचायत को अधिकार दे सकती है कि वह मालगुजारी की वसूली और उगाही में घारा २६० के खंड (क) (ग) और (घ) में उल्लिखित सब अधिकारों या उनमें से किसी का प्रयोग करें।

२६२—(१) इस विधान में किसी बात के रहते हुय भी, यदि किसी खाते की मालगुजारी बाकी हो तो, कलेक्टर को अधिकार होगा कि वह स्वयं या गांव-पंचायत की प्रार्थना पर खाते को ऐसी रीति से जो नियत की जाय बेचकर बिकी से प्राप्त आय को बकाया के भुगतान में लगा वे और यदि कुछ बचे तो उसे भूमिषर या सीरदार को, जसी भी दशा हो, खौटा वे ।

(२) इस घारा के अधीन हुए विक्रय की प्रसूचना (report) कलेक्टर नियत अधिकारी को देगा।

२६२-क-- खाते का घारा २६२ के निदेशों के अधीन बिकने पर उसका विकय-मूल्य, पहले नीलाम के व्यय की अदायगी में लगाया जायगा और फिर उसके बाद माल- गुजारी की बकाया के भुगतान में और जो बचेगा, वह उस व्यक्ति को देय होगा, जो उसका अधिकारी हो।

२६२-ल--(१) यदि मालगुजारी की कोई बकाया थारा २६० के खंड (क) से (ङ) तक में उल्लिखित किसी भी प्रसर (process) द्वारा वसूल न हो सके तो कलेक्टर, बाकीदार की किसी दूसरी अचल-सम्पित्त में बाकीदार के स्वत्व से, बकाया वसूल कर सकते हैं, मानो उक्त बकाया ऐसी दूसरी सम्पित्त पर निर्धारित मालगुजारी की बकाया ही और उसी के सम्बन्ध में देय हो।

(२) ऐसा रुपया जो मालगुजारी के रूप में वसूल किया जा सकता हो, पर किसी भूमि विशेष के सम्बन्ध में देय न हो, इस घारा के अधीन बाकीदार की किसी अचल-संपत्ति से वसूल किया जा सकता है।

२६२-ग-धारा २५२ के अधीन नियुक्त ऐसा ध्यक्ति, जिसने ऐसे गांव के, जिसके लिये वह नियुक्त हुआ हो, किसी खातेदार द्वारा देय मालगुजारी की बकाया देदी हो, उसे देने से ६ महीने के भोतर कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से

उक्त बकाया को वसूल करा दिया जाय, मानो वह सरकार को देय मालगुजारी की बकाया हो।

एसा प्रार्थना-पत्र पाने पर, और इस बात का संतोष कर लेने के बाद कि मांगा जाने वाला रुपया ऐसे व्यक्ति को देय हैं, कलेक्टर उक्त खातेदार या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो खाते के कब्जे में हों, व्यय और द्याज सहित ऐसी धनराशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो।

यदि ऐसी धनराशि के सम्बन्ध में, जिसकी वसूली के लिये इस धारा के अधीन कलेक्टर ने आज्ञा दी हो, कोई बाद (suit) लाया जाय तो उसमें कलेक्टर प्रतिवादी न बनाया जायगा,

इस धारा के अधीन कलेक्टर द्वारा दी गई किसी आज्ञा के विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी, किंतु उस आज्ञा की कोई बात या इस धारा के अधीन दी गई कोई आज्ञा, मालगुजारी की बकाया के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा वाद प्रस्तुत किए जाने के मार्ग में बाधक न होगी।

२६२-घ—मालगुजारी की बकाया की वसूली से सम्बन्ध रखने वाले इस विधान के निदेश, इस विधान के प्रारम्भ के समय देय मालगुजारी की सभी बकाया की तथा ऐसे रुपयों की जो मालगुजारी की बकायों के रूप में वसूल किए जा सकते हों, लागू होंगे।

२६३—(१) कभी मालगुजारी बकाया में पड़ जाने के बाद किसी समय कलेक्टर उस गांव को या उसकी किसी भूमि की जिसके सम्बन्ध में वह बकाया हो, कुर्क कर ले और उसे ऐसे काल के लिये जो उसे उचित जान पड़े या तो स्वयं अपने प्रबन्ध में ले ले या किसी ऐसे एजेंट के प्रबन्ध में दे दे जिसे उसने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है।,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुकीं के दिनांक से ठीक बाद के कृषि—वर्ष के प्रारम्भ से तीन वर्ष से अधिक के लिये कोई गांव या उसमें की कोई भूमि इस प्रकार कुर्क नहीं की जायगी और यदि बकाया इस अवधि के भीतर ही चुका दी जाय तो कुर्की निरस्त (cancelled) कर दी जायगी।

(२) कुकी की अवधि के समाप्त हो जाने पर गांव के सम्बन्ध में देय मालगुजारी की बकाया सम्बन्धी सरकार के समम्त दावों से मुक्त होकर गांव छोड़ दिया जायगा, और उस पर उसकी मालगुजारी की किसी बकाया के लिये सरकार का कोई दावा न रह जायगा। विधान के प्रारम्म समय देय बकाया के निदेशों का लागू किया जाना-

मालगुजारी की बकाया में गांव की कुकाँ-- उसके प्रबन्ध के अधीन क्षेत्र के सम्बन्ध में कलेक्टर के अधिकार और आभार। र६३-क--जब तक कोई निविष्ट क्षेत्र इस प्रकार कलेक्टर के पास अपने ही प्रबन्ध में रहे, कलेक्टर ऐसे अनुबन्ध (engagement) से, जो बाकीवार और असामी या अधिवासी के बीच हुआ ही और कुर्का के काल में विद्यमान रहा हो, बाध्य होगा, और इस प्रकार अपने प्रबन्ध में ली हुई सम्पत्ति का प्रबन्ध करने और उससे उत्पन्न होने वाले लगान और लाभ को पाने का अधिकारी होगा। उक्त सम्पत्ति से इस प्रकार वसूल किया गया मालगुजारी की ऐसी किस्त की, जो। कुर्का के बाद देय हुई हो तथा कुर्की ओर प्रबन्ध के व्यय की, अदायगी में लगाय जायगा और फिर यदि कुछ बचेगा तो वह उस बकाया के भुगतान में, जिसके निमित्त कुर्की हुई हो, लगाया जायगा।

उस खाते को, जिसवे सम्बन्ध में बकाया देए हो, लगान पर उठाने के कलेक्टर के अधि-कार। २६३--ख (१) यदि मालगुजारी की बकाया किसी खाते के सम्बन्ध में देय हो, तो इस विधान में किसी बता के रहते हुए भी फलेक्टर उक्त खाते को, बाकीदार से भिन्न किसी व्यक्ति को अगली जुलाई के पहले दिन से लेकर धिक से अधिक दस वर्ष के काल के लिये तथा ऐसी शर्ती और प्रतिबन्धो पर, जिन्हें किमश्नर निश्चित कर दे, उठा सकता है।

- (२) इस धारा की किसी बात का किसी ऐसे खाते -दारों के दायित्व पर, जो इस विधान के अधीन मालगुजारी की बकाया का देनदार हो, कोई प्रभाव न पड़ेगा।
- (३) पट्टों की अवधि के बीत जाने पर खाता तत्स-ग्रन्थी खातेदार के पक्ष में, उक्त खाते की बकाया के लिये प्रातीय सरकार के समस्त दावों से मुक्त होकर, प्रत्यित (restored) हो जायगा।

कुर्क क्षेत्र के लगान तथा तत्संबंधी अन्य देयों की अदायगी। २६३-ग--धारा २६३ के अधीन किसी क्षेत्र के कर्क होने या धारा २६३-ख के अधीन उसके लगान पर उठा दिए जाने, पर घोषणा (proclaimation) के दिनांक के बाद, असामी, अधिवासी या कटजा रखने वाले अन्य व्यक्ति के द्वारा, उस भूमि के लगान या अन्य देयों के निमित्त, कलेक्टर से भिन्न, किसी व्यक्ति को की गई किसी अदायगी से वैध रीति से किसी दायित्व का परिशोध (discharge) न होगा।

२६३-घ--इस विधान द्वारा संशोधित यूनाइटेड प्राविसेच लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ९ और १० के निदेशों, जहां तक वे इस विधान के निदेशों से असंगत न हों, इस अध्याय के अधीन दिये गए प्रार्थना-पत्रों और चलने वाले व्यवहारों (proceedings) पर लागू होंगे।

२६४--(१) इस अध्याय के निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकार नियम बना सकती हैं।

- (२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये, ऐसे नियम निम्निलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं:—
 - (क) भूमियर या सीरदार द्वारा दिये गये अधिक धन की घारा २३१ के अधीन प्रतिपूर्ति (reimbursement) की प्रक्रिया,
 - (ख) घारा २४७ के अधीन उज्रदारी करने की रीति,
 - (ग) घारा २५१ के अधीन मालगुजारी के बढ़ाने में अमुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,
 - (घ) मालगुजारी के वसूली के लिये घारा २५२ के अधीन रीति और व्यवस्था (arraugement),
 - (ङ) घारा २५३ के अधीन गांव-पंचायत द्वारा मालगुजारी की वसूली की प्रक्रिया,
 - (ङ ङ) भारा २६० के अधीन अचल-सम्पत्ति की कुर्की, हस्तान्तरण और विक्रय की प्रकिया,
 - (च) धारा २६१ के अधीन गांव-पंचायत द्वारा अधिकारों के प्रयोग की रीति,
 - (छ) इस अध्याय के अधीन कर्त्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में अधिकारियों का सामान्य पथ-प्रदर्शन,
 - (ज) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायें।

झध्याय ११

सहकारी फार्म (Co-operative Farm)

२६५ — गांव-समाज के ऐसे दस या अधिक सदस्य, जिनके पास सब मिला कर ती एकड़ या उससे अधिक भूमि में भूमिधरी या सीरदारी अधिकार हों और जो सहकारी फार्म (farm) खोलना चाहते हों, को—आपरे— दिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ ई० के अधीन नियुक्त

यू० पी० ऐक्ट ३,

१९०१ ई० के निदेशों
का इस अध्याय के
अधीन प्रार्थना-पत्रों
और व्यवहारों पर
लागू किया जाना।

नियम बनाने का ऋष्टिकार।

सहकारी खेती संस्था का निर्माण ।

पेक्ट सं०२, १**८१**२ ई∙ रिजस्ट्रार को (जो आगे चलकर रिजस्ट्रार कहा जायगा), उसकी रिजस्ट्री के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं।

रजिस्ट्री के लिये पार्थना-पन्न। २६६ — सहकारी फार्म की राजिल्ड्री के लिये प्रार्थना-पत्र के साथ अधि हार अभिलेखों के ऐसे उद्धरण (extracs) जिनमें उस मंडल के प्रत्येक प्रार्थी के पास के सब खेतों की अभिलिखित कम संख्या (recorded numbers) सहित उन का कुल क्षेत्रफल दिखाया गया हो और जिनमें ऐसे और भी ध्योरे हों, जो नियत किये जायं, प्रस्तुत करने होंगे

सहकारी खेती संस्था को रजिस्ट्री। २६७——(१) यदि रिजिस्ट्रार को ऐसी जांच के बाद, जो नियन की जाथ, यह संतोष हो जाय कि प्रार्थना— पत्र सथावत् (duly) दिया गया है, तो वह कोआपरंदिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ ई० के अधीन सहकारी कार्भ की रिजिस्ट्री कर देगा और रिजिस्ट्री का एक प्रमाण-पत्र (Corbine 16c) दे देगा।

(२) रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र मी एकप्रति कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के लिये, जो नियत की जाय, भिजवा देगा।

िम्सो सदस्य की मूमि का संस्था का अन्तरण होना २६८-- किसी सहकारं प्रवामं की धारा २६७ के अधीन रिजिस्ट्री हो जाने पर उस गउल में स्थित सभी खातों की भूमि, जो भूमिधर, सीरवार या असामी में से किसी भी वर्ग के सवस्य के पास हो, उस सहकारी फार्म की रिजिस्ट्री के निरक्षित (canoelled) होने तक, उस सहकारी फार्म को हस्तान्तरित, और उसके कब्जे में समझी जायगी, और उसके बाद से उपत भूमि उस फार्म के पास, इस अध्याय के निदेशों के अनुसार रहेगी और इस विधान में किसी यात के रहते हुए भी, वह फार्म धारा १४८ में उत्किश्तित किसी प्रयोजन के लिये या गृह-उद्योग (cottage industries) के विकास के लिये उसे उपयोग में ला सकेगा।

ग्रलासकर खाती की महकारी खेती संस्था का निमाण २६९—यदि किसी मंडल के अलाभकर (uneconomic) खातों में भूमिधरी या सीरदारी अधिकार
रखने वाले कुल व्यक्तियों में से कम से कम ऐसे दी—
तिहाई, जिनके खातों का क्षेत्रफल सब मिलाकर उस
मंडल के ऐसे कुल खातों के संकलित (aggregale)
क्षेत्रफल का कम से कम दो—तिहाई हो, कलेक्टर को
संयुक्त रूप से प्रार्थना-पा दे कि एक सहकारी फारम
स्थापित । हया जाय, तो कलेक्टर नोटिस द्वारा उस मंडल
के शेप ऐसे खातों के सज धातवारों को आजा देगा कि
वे यह बतायें कि उस मडल के ऐसे खातों के अन्तर्गत
सब भूमि को मिलाकर एक सहकारी फारम क्यों न
स्थापित और संगठित (constituted) किया जाय।

ऐक्ट २, १६१२ ई०

२७०--कलेक्टर उन खातेदारों के उन्न सुनेगा, जो अपनी सुनवाई चाहते हों और उन्हें सुनकर, यदि उसको यह संतोष न हो कि ऐसा करना उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के परम हित (best interest) के लिये नहीं है, तो वह यह आज्ञा देगा कि उस मंडल के अलाभकर खातों के अन्तर्गत सभी भूमि सम्मिलित करके एक सहकारी फार्म स्थापित कर दिया जाय।

उजदारियों का निस्ता-र सम ।

२७१-धारा २७० के अधीन सहकारी फार्म धारा २७० के ग्रधीन स्थापित करने की आज्ञा का नोटिस उससे प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर तामील किया जायगा और नियत रीति से मंडल में घोषित भी किया जायगा।

ग्राज्ञा कीतामील।

२७२--यदि कोई व्यक्ति धारा २७० के अधीन दी गई कलेक्टर की आज्ञा से असन्तुष्ट (aggrieved) हो तो, वह आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर कमिश्नर को अपील कर सकता है, और अपील में कमिश्नर द्वारा दी गई आज्ञा अन्तिम और निश्चायक (conclusive) होगी।

ग्रवील

षें हर १६१२ का

२७३--(१) सहकारी फार्म स्थापित करने के लिये घारा २७० या २७२ के अधीन दी गई आजा की एक प्रतिष्ठिप कलेक्टर रजिस्ट्रार को भिजवा देगा और तब रिजस्ट्रार को आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट १९१२ के अधीन उस फार्म की रजिस्टी कर देगा और रिजस्ट्री का एक प्रमाण-पत्र (certificate) देवेगा।

ग्रलाभ हर ख।तां की सहकारी खेती संस्था का रजिस्टी।

(२) रजिस्ट्रार प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि कलेक्टर को ऐसी कार्यवाही के निमित्त, जो नियत की जाय, भिष्ववा देगा।

२७४ — किसी सहकारी फार्म की घारा २७३ के अधीन रजिस्ट्री हो जाने पर उस मंडल मे स्थित सभी अलाभकर खातों की भूमि, जो भूमिधर, सीरदार या असामी में से किसी के भी पास हो, उस सहकारी फार्म की रजिस्ट्री के निरसित (cancelled) होन तक, उस सह-कारी फार्म को हस्तान्तरित, और उसके कठज में समझी जाएगी और उसके बाद से उक्त भूमि उस फार्म के पास, इस अध्याय के निदेशों के अनुसार रहेगी और इस विधान में किसी बात के रहते हुए भी, वह फार्म धारा १४८ में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिये या गृह-उद्योग (cottage industries) के विकास के लिये उसे उपयोग में ला सकेगा।

ग्रनाभकर खातों की भूमिका संस्थाको ग्रन्तरग होना

२७५--यदि कोई ऐसा भूमिघर या सीरदार, जिसके पास किसी ऐसे मंडल में कोई अलाभकर खाता हो, जिसमें फार्म की रजिस्ट्री रा २७३ के अधीन की गई हो, उस फाम म्मलित न होना चाहे तो

ऐसे भूमिधर या सीर-दार की भूमि का छै लिया जाना, जो संस्था में सम्मिछित नही।

रिजस्ट्री के प्रमाण-पत्र के प्रदान से तीन मास के भीतर उस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र देने पर घारा २७४ में उल्लिखित भीम में अपने स्वत्वों के निमित्त ऐसा प्रतिकर, ऐसे सिद्धान्तों पर और ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, पाने का अधिकारी होगा, और तब ऐसी भूमि में उसके सब स्वत्व उक्त सहकारी फार्म को न्स्तान्तरित होकर उसके स्वत्वाधिकार में चले जायेंगे और वह ध्यक्ति फार्म का सदस्य नहीं रहेगा।

रजिल्ट्री के परिखाम।

२७६ — यदि घारा २६७ या २७३ के अधीन किसी सहकारी फार्म के सम्बन्ध में रिजम्ट्री का प्रमाण-पत्र दिया गया हो तो, को-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, १९१२ के निदेश, जहां तक वे इस विधान या इसके अधीन बने नियमों से असंगत (inconsistent) न हों, उसे लागू होंगे।

ऐक्ट २. १६१^२

संखा की उपविधि

संस्था को दी गई भूमि

का उसके भूमियर

या मीरदार के स्व

त्वाधिकार मे रहना।

सस्थाको दी गई

भूमिका विनियोग।

२७७—धारा २६५ या २६९ के अवीन प्रत्येक प्रार्थना -पत्र के साथ सहकारी फ़ार्म की प्रस्तावित उपविधियों
(by laws) की एक प्रतिलिपि वी जायगी और उन
उपविधियों के विषय में यह समझा जायगा कि वे ऐसी
उपविधियां हैं, जिनका की-आपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट,
१९१२ ई० की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन
प्रस्तुत होना आवश्यक है।

१९१२ का पेक्ट २

२७८--[*]

२७९—इस थाध्याय की किसी बात से यह नहीं सगझा जायगा कि सहकारी कार्म में भिमधर या सीरदार द्वारा या उसकी ओर से दी गई भूमि में उक्त असिधर या सोरदार कस्वत्व नहीं रह गया है।

२८०--(१) उस दशा को छोड़, जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गई है, सहकारी फार्म के किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं होगा कि अपने द्वारा फार्म में दी गई किसी भूमि का वह किसी प्रकार से विनियोग (disposition) कर सके।

(२) सहकारी फार्म का कोई ऐसा सदस्य, जो उस फार्म को अपने द्वारा दी गई भूमि का भूमिघर हो, ऐसी भूमि की विदशा वसीयत (testamentary disposition) और फार्म की अनुज्ञा (permission) से किसी अन्य प्रकार का भी विनियोग (disposition) कर सकता है।

सदस्यों के अघि-कार, विशेषाधिकार, भार ग्रार दायित्व। २८१—सहकारी फार्म के प्रत्येक सदस्य को ऐसे अधिकार और विशेषाधिकार होंगे और वह ऐसे आभारों (obligations) और दायित्वों (liabilities) के अधीन रहेगा और उसको ऐसे कर्त्तव्य पालन करने होंगे, जो इस विधान द्वारा या इसके अधीन उसको दिव्या उसपर लगाये गये हों।

^{[*]--}निकाल दिया गया।

२८२- -[*]

२८३- -ऐसी पिस के सम्बन्ध में को तहकारी फार्म के पास धारा २६८ या २७४ के अधीन आई हो, उक्त फाम अपने संघठित होने के दिनांक से भूमिधर, सीरदार या असाभी द्वारा देय सब मालगुजारी, अंबनाय स्थानिक कर या लगान का देनदार होग।।

२८४ - कोई ऐसा व्यक्ति, जो उस मंडल का रहने वाला हो, जिसमें कोई सहकारी फाम स्थित हो, या जो ऐसे मंडल में बसने का विवार करता हो या जो उसगे खेती करता हो, ऐसी शतों और प्रतिबन्धों के साथ, जो उस फार्म द्वारा लगाए जायं, उस फार्म का सदस्य बनाया जा सकता है।

२८५-यदि कोई सदत्य, जिस हो भूमि सहकारी फार्म में हो, मर जाय तो इस िधान के अधीन होने वाले उसके उत्तराधिकारी उस फ। मं के सदस्य हो जायंगे।

२८६--(१) प्रत्येक सहकारी फार्म का यह संस्था की भूमि की कर्त्तव्य होगा कि वह अपनी भूमि की चकवन्दी (consolidation) का उद्योग करे।

- (२) सहकारी फार्म परगना के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant Collector the Sub-Division) को अपनी भूमि की चकवन्दी के लिए ऐसे व्योरों (particulars) के साथ, जो नियत किए जायं, प्रार्थना-पत्र दे सकता है।
- (३) असिस्टेंट कलेक्टर, यदि किन्हीं कारणों से, जिन्हें अभिलिखित करना उसके लिए आवश्यक होगा,[*] ऐसा करना अनुपयुक्त (inexpedient) न समझे तो भूमि की चकबन्दी की आज्ञा दे देग। और ऐसे प्रयोजन के लिये वह मंडल के भीतर की भूमि की अटला–बदली (exchange) का भी निर्देश कर सकेगा।
- (४) भिम की बदलाई का निर्देश करते समय असिस्टेंट कलेक्टर, जहां तक सम्भव हो, बदलाई में मिली हुई भूमि के बदले लगभग उसी के ।राबर मृत्य की भूमि के दिये जाने की आज्ञा देगा और ः दि दोनों के मुल्य में अन्तर हो, तो वह नक़द प्रतिकर रेने का भी निर्देश कर सकता ह।
- (५) उपघारा (३) के अधीन भूमि ती बदलाई का निर्देश होने पर सहकारी फार्म उसके सदस्यों और ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी भूमि की बदलाई हुई हो, बदले में मिली भूमि में वे ही अधिकार होंगे, जो उन्हें बदले में ती गई भूमि में थे।
- (६) इस घारा के अधीन दी गई असिस्टेंट कलेक्टर की प्रत्येक आज्ञा के विरुद्ध कमिश्तर के सामने अपील हो सकेगी।

संस्था का मालगुजारी ग्रीर भन्य देथों के लिये दायित्वं।

नये सदस्यों का प्रवेश

उत्तराधिकारियों का संस्था के सदस्य होना।

चक्षन्दी ।

सहकारी खेती संस्था जो ऋण देना।

- २८७—(१) सहकारी फार्म द्वारा इस सम्बन्ध मं प्रार्थना-पन्न दिये तने पर प्रान्तीय सरकार उम फारम को ऐसी मात्रा तक और ऐसी रीति है, तो लित की जाह, धारा २७५ के अधीन प्रतिकर देने के डिडें ा देगी।
- (२) उरपारा (१) के निहेतों हे लाधीन िया गया ऋण, ऐसी रीति से और ऐसी िस्तों थे, जो नियत की जायं, चुकाया (repaid) जायगा और समय निशेष पर प्रचलित किमी विधि में किसी बात के रहे हुए भी और धारा २२८ के निहेशों को बाधित न करते हैं, ऐसा ऋण समय विशेष पर उस कार्म के अन्तर्भत सभी भूमि पर प्रथम भार (first charge) होगा।

सहकारो खेती संस्था को रियायत और सुविधायं।

- २८८—(१) सहकारी कार्म को ऐसी रियायतें (concessions) र सुविधाय (fact lities), जो नियत को जाप, गाने का अधि अर होगा ;
- (२) वृर्वोक्त निदेशो की ज्याप्ति को बाधित न करते हुए, रियायतो और पुविधाओं के अन्तर्गत निस्नित्सित होंगे:—

(क) मालगुजारा में कमी,

- (u) क्रांब-आय कर में कभी या उसले मुस्ति (exemption),
- (ग) सरकार हारा नियुक्त विशेषको से निःश्टूट शिल्पाका सम्मानी राथ (free technical advice),
- (प) त्यान पर गा विना त्यान के घन ही सहायता (unancial aid), सहायत अनुदान तथा अत्य (grant of subsidy and loans),

(इ) गरा-सभा से काइतकारी पर भूमि

पाना, और

(च) शिवाई क सरकारी लावने ते सिवाई की प्रयमता (priority)।

श्रलाभकर खाते।

- २८५--(१) परि ति मंदल में िसी मृजिधर या सीरार के कुल वानों हा गंहिलत क्षेत्रकल ऐसी वाजा से कम हो, तो प्रान्तीय सरकार गुजर में विज्ञाप्ति द्वारा प्रस्थापित हरे, तो ऐसे सभी खाते मिलकर मूनिघर या सोरदार का "जलाभकर थाना" (uneconomic holding) कहलायेंगे।
- (२) उपपारा (१) ें नर्पान विश्वादित सामान्य ख्ला ने या प्रान्त के जिसी भाग या भागों के लिये प्रकाशित को जा सकेगी और उसके द्वारा भिन्न-भिन्न भागों के लिये भिन्न-भिन्न गानार्थे निर्दिष्ट की जा गार्थेगी।

[#] ानकाल दिया ग भ ।

२९०--(१) प्रान्तीय सरकार इस अध्याय के प्रयो- नियम बनाने का जनों को कार्यान्वित करने के लिप नियम बना सकती है,-

अधिकार।

- (२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुए ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते है:--
 - (क) घारा २६५ के अधीन प्रार्थना-पत्र का आकार और उसकी सुनवाई ओर निर्णय फी प्रक्रिया.
 - (ख) घारा २६७ की उपधारा (२) या धारा २७३ की उपधारा (२) के अधीन कलेक्टर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :
 - (ग) घारा २६९ के अधीन प्रार्थना-पत्र का आकार और घारा २७० के अधीन उज्रदारियों की सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया ;
 - (घ) घारा २७२ के अघीन प्रस्तुत की जाने वाली अपीलों का आकार और अपील के स्मरण-पत्र (memorandum) पर दिये जाने वाले न्याय-शुल्क (court-fee) की मात्रा ;
 - (ङ) वे सिद्धान्त, जिनपर, और वह रीति, जिससे, घारा २७५ के अधीन प्रतिकर अवधारित किया या दिया जाय ;
 - (च) इस अध्याय के अधीन निबन्धित(रजिस्टर) किये जाने वाले सहकारी फामों की उपविधियों के आदर्श आकार (model form);
 - (छ) ऐसा या ऐसे आधार जिन पर सह-कारी फार्म किसी भूमिथर को घारा २८० के अधीन अपनी भूमि का विनियोग करने की अनुज्ञा दे:
 - (ज) सदस्यों के अधिकार, विशेपाधिकार, आभार, दायित्व और कर्तव्य ;
 - (झ) सदस्यों का प्रवेश,त्याग-पत्र (resignation) देना और निकाला जाना (expulsion);
 - (ञा) सबस्य के त्याग-पत्र देने या निकाले जाने के परिणाम और फार्म को दिये गये भूमि, धन, कृषि सम्बन्धी पशु और उपकरणों के सम्बन्ध में ऐसे सदस्यों द्वारा प्रतिकर की मांग का चुकाया जाना ;
 - (ट) धारा २८६ के अधीन खातों की चकबन्दी करन, भूभि की बदलाई का निर्देश देन और प्रतिकर अदायगी में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त ;
 - (ठ) घारा २८७ के अधीन दिये जाने वाले त्रहण और उम पर लिया जाने वाला **द्या**ज :

- (ड) धारा २८८ के अधीन सहकारी फार्म को दी जाने वाली रियायते और मुनिधाये;
- (ढ) सदस्यों द्वारा भूनि, धन जोर दूसरी सम्पत्ति का अंशदान उनका मृत्यांकन (valuation) जोर सधान (adjustment);
- (ण) फार्म में काम करने वाले सदस्यों का वेतन और जजदूरी (remuneration and wages);

(त) फार्म के व्यय और अन्य देयों की

अदायगी

- (थ) फार्म की उपज और लाभ का बांटना,
- (द) फां द्वारा या उसकी ओर से वादों का प्रस्तुत किया जाना या उनका प्रतिवाद (defending)ओर मंदिदाओं (contracts) तथा अन्य लेख्यों (documents) के निष्पादन की रीति;

(१) सामान्य रूप रो सस्या क कार्या का प्रचालन (conduct of aflairs) और उसका

संचलन (working);

- (न) सदस्यों के निजी ऋणों । भुगतान (liquidation) आर उनकी माख का नियमन (regulating of their credit),
- (प) कृषि के विकास के लिये तथा नियंत्रित योजनु के अनुकूल कृषि सम्बन्धी उत्पादन (planned agricultural production) के लिये प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले निर्देश;
- (फ) भ्मिधरों और सीरदारों से भिन्न सदस्यों के सम्बन्ध में उत्तराबिकार का नियमन (regulating the succession to members); तथा
- (ब) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत कियं जायं।

अध्याय १४

रकोर्ग (Miscellaneous)

इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये प्रधिकारियों ग्रौर ग्राधिकारिकों की नियुक्ति। २९१—इस विधान के प्रयोजनों के लिये प्रान्तीय सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:——

(क) प्रतिकर कमिश्नर (Compensa-

tion Commissioner),

(ख) सहायक प्रतिकर कमिश्नर (Assistant Compensation Commissioners),

अभिकारी (Compen-(ग) प्रतिकर

sation Officers), तथा

(घ) पुनर्वासन अनुदान अधिकारी (Rehabilitation Grants Officer:)

२९२--(१) प्रतिकर किथ्निर और सहायक प्रात- व्याधिकार भीर कत्त व्य। कर किंगिश्नर ऐसे कर्त्तव्यो का पाछन करेंगे और प्रतिकर अधिकारियों और पुनर्वासन अनुदान अधिकारियों के कार्य के पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगें जो नियत किये जायं।

(२) प्रतिकर अधिकारी और पुनर्वासन अनुदान अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्तें व्यों का पालन करेंगे, जो इस विधान या उसके अधीन बने नियमों के द्वारा या प्रधीन उन्हें दिए गए या उन पर

लगाए गए हों।

२९३-- जबट के विज्ञप्ति द्वारा प्रान्तीय सरकार इस विधान द्वारा मिले अपने अधिकारों में से किसी को अपने अधीन किसी भी अधिकारी (officer) या आधिकारिक (authority) को विक्षित में निदिष्ट किए जाने बाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों (conditions) और निरोधों (rostrictions) के अभीन प्रयोग करने के लिये सींप सकती है।

२९४--निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध में किसी भी प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (powers), अधिकार (rights, और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंने, जो किसी व्यवहार (action) के सम्बन्ध में दोवानी न्यायालयों (Uivil Courts) की है:--

(क) साक्षियों की उपस्थित और उनको शपय देकर, प्रकथन (altirmabion) करा के, या अन्य प्रकार से उनके वक्तव्य लेना और अपने अधिक्षेत्र ते बाहर साक्षियों का वक्तव्य लेने के लिये कमीशन या निवेदन-पत्र

(letter of request) जारी करना;

(碑) लेख्य (documents) प्रस्तृत

करने का बाध्य करनाः

(ग) न्यायालय के अपमान (contempt) के लिए लोगों को वंड देना; और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित कराने और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिए दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formalprocess) के स्थान पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उस ही के बराबर समझा जायगा।

ग्रधिकारों का प्रति-निधान।

कुक् विषयों में साक्षियों को उपस्थित कराने का अधिकार।

२९५--(१) नियत किये जाने वाले किन्हीं भी प्रतिबन्धों या निरोधों का बाधित न करते हुए, प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रिजस्टर प्रस्तुत करें या ऐसी सूचना दे जो प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनु-दान अधिकारी इस विधान के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या अपने कतन्त्रों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझे।

लेख इत्याद प्रस्तुत कराने का ग्रांधकार।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रिजस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की घारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

भूमि पर प्रवेश करने पर्यालोकन इत्यादि का अधिकार

२९६--ऐसे प्रतिबन्धों या निरोधों पर उपाश्चित रहते हुए, जो नियत किये जायं, इस ऐक्ट के अधीन नियुक्त प्रत्येक अधिकारी इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए किसी समय, किसी भूमि पर, ऐसे जनसेवकों (public servants) सहित जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रवेश कर संकता है और उसका (survey) या पैमाइश (measurements) कर सकता है या अन्य ऐसा कार्य कर सकता है, जो वह इस ऐक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक समझे।

२९७--किसी प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह इंडियन पीनल कोड, १८६० की घारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिय एक वैचारिक ज्यवहार (judicial proceeding) है।

प्रतिकर अधिकारी ग्रीर पुनर्वासन त्रानु-दान अधिकारी के सामने व्यवहारी का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

२९८--इस ऐक्ट के अभीन प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुवान अधिकारी द्वारा वाव-व्यय (costs) के सम्बन्ध में वी गई आज्ञा, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उक्त वाव-स्थय पाने का अधिकारी हो, उस आज्ञा की एक प्रतिलिपि सहित अधिक्षेत्र प्राप्त मुंसिफ को प्रार्थना-पत्र वेकर कार्यान्वित कराई जा सकती है और मुंसिफ उसे इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस मुसिफ द्वारा दिये गये रुपये की डिकी के निष्पादन का प्रार्थना-पत्र हो।

वाद-व्यय।

२९९--ऐसा नोटिस या अन्य लेख्य, जिसको तामील ने टिस के इस विभान द्वारा अपेकित (required) या अधिकृत को रोति।

तामील

(authorised) हो, निम्नलिखित प्रकार से तामील किया जा सकेगा --

- (क) उस व्यक्ति को देकर, जिसपर उसकी तामील होनो है, या
- (ख) उस व्यक्तिक साधारण अयथा अन्तिम जात निवासस्थान (usual or la t known place of abode) पर उसे छोड़ कर, या

(ग) उसके माधारण या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर ∗से रजिस्ट्री–पत्र द्वारा भेज

कर, या

- (घ) किसी निगमीकृत कम्पनी था संस्था (meorporated company or hody) के विषय में उस कम्पनी या संस्था के मंत्री (Secretary) या किसी दूसरे प्रधान कार्याधिकारी (procepal functionary) के नाम से उसके प्रधान कार्यालय में देकर या उसके पते से रिजस्ट्री-पत्र द्वारा भेज कर, या
- (ङ) [*] (च) ऐसी अभ्य रोति **। तः नियत की जाय ।

३००-इस विधान या इसके अधीन बनें नियमों के अनुसार रक्खे जान वाले सब लेख्यों, विवरणों ओर रिजस्टरों का निरीक्षण ऐसे समय पर, ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन और ऐसा शुल्क [*] देने पर, जो नियत किया जाय, किया जा सकेगा, और ऐसा शुल्क ['] देने पर प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि किसी ऐसे लेख्य, विवरण या रिजस्टर, | या जगके किसी अंश की प्रतिलिप ले सके।

लेखें कं विवरणें गौर गिन्टरें के निरीक्षण करने गौर प्रातितिप लेने को ग्रधिकार।

308--[*]

३०२—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी प्रतिकृत बात के रहते हुए भी, इस विधान के निवेश ऐसा कोई आस्थान या उसका भाग हस्तगत (acquisition) करों के सम्बन्ध में जो यूनाइटेड प्राविसेज कोई आफ़ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ या समय निशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन कोई आफ़ वार्ट्स या प्रान्तीय सरकार के प्रबन्ध में हो, उसी प्रवार लागू होंगे जैसे वे इस विधान के अधीन हस्तगत किए गए किसी आस्थान पर छागू होंगे।

कोर्ट ग्राफ वाइ स के प्रबन्ध में ग्रास्थान या खाते।

३०३—(१) किसी फरीक (party) के प्रार्थना— पत्र पर और दूसरे फरीक़ों को नीटिस वेकर और ऐसे फरीक़ की सुनवाई करके, जो अपनी सुनवाई चाहता हो, या ऐसे नीटिस बिना स्वयं ही, जिस्ट्रिक्ट जज अपने अधिक्षेत्र के किसी प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुवान

व्यवहार का अन्तरण

स॰ प्रा॰ वेक्ट ४, १९१२ ई० अधिकारी के सामने चल रहे किसी व्यवहार (proceeding) को अपने यहां मंगा सकता है और अपने अधिक्षेत्र में नियुक्त और उस व्यवहार के निस्तारण में समर्थ (competent to disperse of) किसी अन्य प्रतिकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुवान अधिकारी को, जैसी भी दशा हो, उसे मिस्सारण (disposal) के लिये संक्रामित (transfor) कर महता है।

(२) उपधारा (१) के अधीन किसी व्यथहार के संक्रामिन होन पर उस अधिकारी की, जो उसके बाद उस. व्यवहार का निस्तारण कर, जीवकार होगा कि यांच संक्रमण (bradesfor) की आजा में कोई विशेष निर्देश हो तो उसे वाधित न करों हुए याहे वह उसकी कुछ भूनवाई आदि से फिर करें या भ अवस्थान (point) से प्रारम्भ कर जिस पर वह व्यवहार संक्रामित हुआ था।

कुक् विषयें। मं दीवानी न्यायालय का ग्रधि-क्षेत्र न होना।

३०४-- उभ दशा की छोड़ [*] जिसकी व्यवस्था इस विधान के क्षारा या अधीन किसी अन्य प्रकार ने की गई हो, ऐसा कोई बाद या दूसरा व्यवहार किसी दीवानी न्याया-ख्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, जिसका सम्बन्ध प्रति-कर निर्धारण तान्त्रिका में किसी इन्दराज के होने या न होने से था भाग १ के अधीन दी गई किसी आज्ञा से हो। [*]

इस विघान के मधीन वादों आदि की मवेक्षा।

३०४-क--(१) ऐसी दशा को छोड़, जिसके विषय में इस विधान द्वारा या इसके अधीन कोई ज्यवस्था की गई हो, परिशिष्ट ३ के स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय का छोड़ कोई दूसरा न्यायालय, उपत अनुसूची के स्तम्भ ३ में उल्लिखित किसी याद, प्रार्थना-पत्र या व्यवहार (proceeding) की, सिविल प्रोसीजर कोड, १९०८ में किसी बात के रहते हुए भी, अवेक्षा न करेगा (shall not take cognizance)।

- (२) ऐसी दशा को छोड़, जिसके विषय में आगे क्यवस्था की गई है, पूर्वोक्त परिजिब्द के स्तम्भ ३ में उल्लि किस वादों और व्यवहारों में से किसी में दी गई किसी आज्ञा के विश्द्ध गोई अपील न हो राकेगी।
- (३) उक्त परिशिष्ट के स्तम्भ ३ में उल्लिखित व्यव-हारों में स्तम्भ ४ में उल्लिखित न्यायालय द्वारा दी गई अन्तिम आज्ञा (linal order) के विरुद्ध उसी परिशिष्ट के स्तम्भ ५ में उल्लिखित न्यायालय या आधि-कारिक के सामने अपील हो सकेगी।

^{[&}lt;sup>1</sup>] निकाल दिया गया।

(४) उपधारा (३) के अधीन की गई अपील में की गई अन्तिम आज्ञा के विरुद्ध उसी के आगे पूर्वोक्त परि-शिष्ट के स्तम्भ ६ में उल्लिखित आधिकारिक के सामने द्वितीय अपील हो सकेगी।

३०४-ख--(१) यदि परिशिष्ट ३ के स्तम्भ ३ में उल्लिखित किसी वाद या व्यवहार मे, किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जो उक्त वाद या व्यवहार का विषय हो, कोई ऐसा प्रक्त उठाया जाय, जिसका सम्बन्ध किसी फरीक के आगम (title) से हो, और जो सीधे तौर से तथा तत्वतः विचारणीय विषय (directly and substantially in issue) हो, तो न्यायालय, यदि उस प्रश्न का किसी समर्थ न्याया-लय द्वारा उसके पूर्व निर्णय न हो चुका हो, धारा ३०४-क में किसी बात के रहते हुए भी किसी ऐसे फरीक को, जिसे वह ऐसा आदेश देना उचित समझे, आदेश देगा कि वह ऐसी आज्ञा से तीन मास की अवधि के भीतर अधिक्षेत्र-प्राप्त न्यायालय में ऐसे प्रक्त के अवधारण (determination) के बाद प्रस्तुत करे और तदुपरान्त जब तक पूर्वीक्त अवधि समाप्त न हो जाय तब तक के लिये, और यदि कोई बाद प्रस्तृत कर दिया गया हो, तो जब तक उक्त वाद का निर्णय न हो जाय तब तक के लिये. अपने सामने चल रहे वाद या व्यवहार को स्थगित कर देगा।

- (२) यदि वह फरीक, जिसे उपधारा (१) के अधीन वाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया हो, उसके निमित्त दिये गए समय के भीतर उक्त आदेश का पालन न करे, तो न्यायालय उक्त विचारणीय विषय का निर्णय उसके विरुद्ध कर देगा।
- (३) यदि उपर्यंक्त निर्देश के अनुसार बाद प्रस्तुत कर दिया गया है, तो न्यायालय उस वाद के निर्णय के अनुसार कार्यवाई करेगी ।

३०४-ग-परिशिष्ट ३ में अभिविष्ट किसी ऐसे वाद या व्यवहार का अभिलेख (record), जिसे किसी अपीनस्थ न्यायालय ने निणित किया हो और जिसमें कोई अपील न हो सकती हो, या यदि हो सकती हो तो न प्रस्तृत की गई हो, बोर्ड अपने यहां मंगा सकता है, और यदि यह प्रतीत हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय मे— श्रागम सम्बन्धी प्रश्त के उठने पर प्रक्रिया।

मुकद्मों के। म'गा भेजने का बोड को अधिकार।

(क) किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया हें जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था, या

(ख) विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) अधिक्षेत्र का प्रयोग करने मे अवैध) या वास्तविक अनिय-रूप से (ıllegally मिततापूर्ण (with material irregu-) आचरण किया है, तो बोर्ड ऐसी larity आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

३०५--(१)[३4]

(२) यदि ऐसा कोई कार्य सद्भाव से और इस विधान के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्त्ताच्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्पादन में किया गया हो तो, उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई दीवानी या फौजवारी व्यवहार न चल सकेगा।

(३) इस विधान के किसी निदेशों के कारण या इस विधान के या उसके अधीन बने नियमों के अनुसार सर्भाव से की गई या की जाने वाली किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति (damage) या अन्य हानि (mjniy) के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई दुसरा व्यवहार नहीं चल सकेगा।

३०६--इस विधान के निदेशों के अनुसार प्रतिकर या पुनर्वासन अनु हान देने पर प्रान्तीय सरकार ऐसे व्यक्ति को, जिसे वास्तविक अधिकार हो, प्रतिकर या पुनर्वासन

अनुदान देने के अपने दायित्व से पूर्णतया मुक्त हो जायगी, किन्तु यदि किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे प्रतिकर या अन्दान के सम्बन्ध में कोई ऐसा अधिकार हो, जिसे वह उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे प्रतिकर या अनुदान दिया गया ह, उचित व्यवहार द्वारा कार्यान्वित कर सके, तो प्रतिकर या पुनर्वासन अनुदान के ऐसे प्रदान का उस दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ३०६-क- (१) किसी

(custom उपचार या अनुबन्ध (agreemont) के रहते हुए भी, ऐसे क्षेत्र में, जिसमें यह विधान लागू होता हो, किसी अचल-सम्पत्ति के किसी भी विक्रय के सम्बन्ध में, वह चाहे ऐच्छिक रूप से (voluntarily) किया गया हो, या चाहे न्यायालय की आज्ञा अग्रक्रयाधिकार (right of pre-emption) न होगा।

[*] निकास विया गया।

प्रान्तीय सरकार कं दायित्व की भरपाई

जिन क्षेत्र में यह विघान लागु होगा वहां से शफा के ग्रधिकारी का लोप। (२) किसी न्यायालय में, चाहे वह मिलक न्यायालय (court of first instance) हो, चाहे अपील का और चाहे पुनरीक्षण (revision) का, ऐसी सम्पत्ति के विषय में अग्रक्रयाधिकार सम्बंधी सभी वाद खारिज हो जायंगे, किन्तु ऐसे किसी वाद में हुआ वाद-व्यय (cost) दिलाना न्यायालय के स्वविवेक (discretion) पर निर्भर होगा।

३०६-ख-इस विधान के किसी निदेश के अधीन निद्या किये गये क्षेत्र की गणना के प्रयोजनों के लिये बुंदेलखंड तथा जमुनापार वाले इलाहाबाद, इटावा, आगरा और मथुरा ज़िले के भागों में जो दो एकड़ है वह एक एकड़ के बराबर गिना जायगा।

कुछ जिलों में क्षेत्रफलों का अवघारण ।

३०७—(१) किसी विधान (Act) के निदेशों को इस विधान (Act) के निदेशों के अनुकृल बनाने के लिये प्रान्तीय सरकार आज्ञा द्वारा (by an order) किसी ऐसे विधान (Act) के निदेशों को अनुकलित, परिष्कृत, संशोधित या रद्द कर सकती है (may adapt, modify or amend or repeal) और इस प्रकार अनुकलित, परिष्कृत, संशोधित या रद्द किये हुए विधान का ऐसा प्रभाव होगा मानो वह इस विधान द्वारा अनुकलित, परिष्कृत, संशोधित या रद्द किया गया हो।

इस ऐक्ट के ग्रधीन ग्राज्ञा द्वारा ग्रन्य विधानों का संशो-धन ग्रीर ग्रनुकत्तन।

- (२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा का पांडुलेख प्रान्तीय विधायका (Provincial Legislatura) के सामने रखा जायगा और विधेयकों (Bills) के पास करने और उनपर विचार करने (passing and consideration) की प्रक्रिया, जहां तक हो सके उक्त आज्ञा के विचार, संशोधन और पास करने के सम्बन्ध में लागू होगी।
- (३) ऐसी प्रत्येक आज्ञा इस विधान के प्रारम्भ के विमान से सप्रभाव होगी (shall take effect)।

३०७-क-- किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में घारा ६ के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से लेकर--

(क) परिशिष्ट ४ की सूची १ में उल्लिखित विधायन (enactment) जहां तक वे ऐसे क्षेत्र में लागू होते हैं, रद्द हो जायंगे और इसके द्वारा रह किये जा रहे हैं;

(ख) कोई दूसरे विधायन, जो इस विधान के अध्याय ८ से १० तक के निवेशों से असंगत हों, जहां तक वे असंगत होंगे, रद्द हो जायंगे और इसके द्वारा रद्द किये जा रहे हैं;

निवर्तन ।

(ग) युनाइटेड प्राविसेज लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट ३, १९०१, पूर्वोक्त परिशिष्ट की सूची २ के स्तम्भ ३ में उल्लिखित आयित पर्यन्त (to the extent) संशोधित समझा जायगा और इसके द्वारा संशोधित किया जा रहा है;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस विधान के अधीन कोई व्याख्या (interpretation), कार्यवाही या बात युनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के निवेशों के अनुसार की जायगी, तो वह उसी प्रकार की जा सकती है, मानो इस ऐक्ट द्वारा वह रह न हुआ हो।

कठिनाइयों को दूर करने का प्रधिकार।

३०८—(१) ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड प्राविसेज लेंड रेवेन्य एक्ट, १९०१ या यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ या भौनिक अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाली किसी अन्य विधि (Any other law relating to land tenure) के निदेशों से इस विधान के निदेशों पर संक्रमण(ध्राध्यादाराता) होने में कठिनाइयां उत्पन्न हों,

इसलिये प्रान्तीय सरकार उक्त पंत्रमण की मुनिधा के लिये आज्ञा द्वारा ---

(क) निर्देश कर सकती ह कि यह विधान यूनाइटेड प्राविसेज लंड रवेन्स ऐनट, १९०१ या यूनाइटेड प्राविसेज लंड रवेन्स ऐनट, १९०१ या यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी एंक्ट, १९३९ अथवा भौमिक अधिकारोंसे सम्बन्ध रखने वाली किसी अन्य विधि के कोई निदेश ऐसी निश्चित अवधि के लिए और ऐसे क्षेत्रों में, जो आज्ञा द्वारा निरिष्ट किए जायं, ऐसे अनुकलन और परिष्कार के साथ, जो निर्विष्ट किए जायं, सप्रभाव रहेंगं,

(ख) उपर्युक्त किसी कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसे अन्य अस्थायी निदेश बना सकती हैं, जो आज्ञा में निदिष्ट किये गये हों।

(२) भारा ६ के अधीन हुई विज्ञेप्ति के विनांक से एक वर्ष बीत जाने पर किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई आज्ञा इस घारा के अधीन न वी जायगी।

(३) इस घारा के अधीन दी गई आज्ञा उसके दिये जाने के बाद यथाशीच प्रान्तीय विद्यायिका के दोनों भवनों (both Chambers of the Provincial Legislature) के सामने रखी जायगी।

३०९—(१) अध्याय ३ मे ५ तक के कि प्रितंकर अधिकारी या पुनर्वासन अनुदान १९ सामने प्रत्येक व्यवहार में प्रान्तीय सरकार एक , १९ और फरीक समझी जाएगी और प्रान्तीय तामील किया जाने वाला या सामील किए जान के लिए अभिन्नेत (intended) प्रकोन नेटिस कलेक्टर या

१७, १५३६ सं० प्रा० ऐक्ट सं० ३, १९०१

सं० प्रा०

ऐक्ट मं०

१७, १६३६

सं॰ प्रा०

ऐक्ट सं०

३, १९०१

स॰ प्रां॰

एक्ट स०

ग्रध्याय ३ से ४ तक के ग्रधीन व्यवहारों में प्रांन्तीय सरकार का फरीक होना। ऐसे आधिकारिक पर तामील किया जा सकेगा जिसे कलेक्टर नामांकित (nominate) कर दे।

- (२) उक्त अध्यायों या बारा ३१० की उपधारा (१) के खंड (घ) में किसी बात के रहते हुए भी, प्रान्तीय सरकार द्वारा या उसकी ओर से अपील प्रस्तुत करने की कालावधि (period of limitation) उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरुद्ध अपील की जायं, नब्बे दिन की होगी।
- ३१०—(१) नियम बनाने के सम्बन्ध में इस विधान द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिकार के विषय में यह समझा जायगा कि निम्नलिखित की व्यवस्था करने का अधिकार उसके अन्तर्गत है:—
 - (क) ऐसी कालावधि (time-limits) लगाने के लिए जिनके भीतर नियमों के प्रयोजनों के लिए की जाने वाली बातें अवस्य की जायं, लगाई हुई अवधि को बढ़ाने के सम्बन्ध में नियमों में निर्दिष्ट किसी आधिकारिक को अधिकार देकर या म देकर;
 - (ख) एसी दशाओं में, जिनके विषय में इस विधान में कोई विशष निदेश नहीं बनाया गया है, इस ऐक्ट के अधीन किसी वाद या दूसरे व्यवहार में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
 - (ग) इस विधान के अधीन प्राप्त अधिक्षत्र वाले किसी अधिकारी या आधिकारिक के कर्सक्य और ऐसे अधिकारी और आधिकारिक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया:
 - (घ) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस विधान में कोई विशेष निदेश नहीं बनाया गया है, इस विधान के अधीन प्रार्थना—पत्र वेने और अमील करने की कालाविध:
 - (ङ) ऐसी दशाओं में, जिनके विषय में इस सम्बन्ध में इस विधान में कोई विशेष निदेश नहीं बनाया गया है, इस विधान के अधीन अपील और प्रार्थना-पत्रों पर देय शुल्क ;
 - (च) इस विधान के अधीन दिए जाने वाले प्रार्थना-पत्रों (applications), अपीलों और व्यवहारों (proceedings) पर इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के निदेशों का लागू किया जाना (application);

सामान्य नियम

- (छ) इस विधान द्वारा प्रान्तीय सरकार या किसी दूसरे आधिकारिक, अधिकारी या व्यक्ति को मिले अधिकारों का प्रतिनिधान (delegation); तथा
- (ज) एक आधिकारिक या अधिकारी के यहां से दूसरे आधिकारिक या अधिकारी के यहां व्यवहारों का संक्रमण ।
- (२) इस विद्यान द्वारा दिया गया नियम बनाने का प्रत्येक अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद ही बनाये जायं।
- (३) इस विधान के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट (official Gacette) में प्रकाशित किये जायंगे, और यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न किया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (come into force)।
- (४) इस विधान के अधीन बनाये गये मब नियम बनाये जाने पर यथाशीच्च प्रान्तीय विधायिका के सामने कम से कम चौदह दिन तक रखें जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधायिका अपने उस अधिवेशन में करें जिनमें वह इस प्रकार रक्ते जायं।

परिशिष्ट १

(बारा १००)

क्रम− सस्या	ऐसे क्षेत्रों के, जिनका यह एक्ट छागू हाता है, व वितयों के सब ग्रास्थानों पर निर्धारित निर्धारित समभी जाने वालो मालगुजारी	मध्य- । या	धारा १०० के प्रयोजनें के लिये शुखक
१	२५ रु० तक		२०
२	२५ रु० के ऊपर हिन्तु ५० रु० से नीचे		१७
3	५० रु॰ के ऊपर किन्तु १०० रु० ल नीचे	****	ર ્ક
ક	१८० हर के ऊपर किन्तु २४० ह० मे नीचे		११
K	२५० ह० के ऊपर किन्तु ५०० ह० से नोचे		T
Ç	५०० रु० के ऊपर किन्तु २,००० रु० न नीचे	• • •	¥
G	२,००० रु० के ऊपर किन्तु ३,४०० रु० से नीचे	• • •	3
۷	३,५०० रु० के ऊपर किन्तु ५,००० रु० से नीचे	***	ર

नाट - यन्य सब परिशिष्ट विशिष्ट सिर्मात द्वारा एवे गये हैं।

परिशिष्ट २

(धारा १३५)

ऋम- संख्या	घारा	परिष्कार या संशोधन
9	ą	वर्तमान घारा ३, घारा ३ की उपधारा (१) होगी और निम्नलिखित खंड र्रेड (ङ) के रूप मे जोड़ी जायगी :— "(ङ) काबिज (ऐन आक्युपायर)"
	72	वर्तमान स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जायगे:— "स्पष्टीकरण (१)—यदि खाता दो से अधिक काश्तकारों (टेनेन्ट्स) के पास संयुक्त रूप से हो तो किसी काश्तकार द्वारा देय लगान इस धारों के प्रयोजनों के लिय वह धनराशि समझी जायगी जो उस
		खाते में उसके अंश के अनुपात में हो।" स्पष्टीकरण (२)—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद —
		"(१) 'भूमि पर क़ाविज' (आक्युपायर आफ लैन्ड) का तात्पर्य किसी ऐसे भूमि के (आक्युपायर) क़ाविज से हैं, जो घारा ६ के अधीन स्वत्वाधिकार के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक पर किसी ऐसे खाते के अन्तर्गत नहीं हैं, जो दवामी काश्तकार, अवध में इस्तमरारी पट्टेदार, बागदार, काश्तकार माफीदार रियायती लगान के काश्तकार की हो, या जो सीर या खुदकाश्त न हो अथवा जो ठेकेदार या किसी बन्धकी के निजी जोत में न हो।"
		"(२) 'मौरुसी काइतकार' के अन्तर्गत सीर का ऐसा काइत- कार भी है, जिसके स्वामी पर घारा ६ के अधीन प्रख्यापन के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक पर संयुक्त प्रान्त में २५० ६० से अधिक माल- गुजारी लगाई गई हो अथवा यदि ऐसी मालगुजारी न लगाई गई हो तो ऐसा स्थानिक कर लगाया गया हो, जो उस धनराशि से अधिक हो, जो वार्षिक २५० ६० के मालगुजारी पर स्थानिक कर के रूप में लगाया जाय।"
	∓ ₹ —क	निम्नलिखित उपघारा (२) के रूप में जोड़ा जायगा:— "(२) उपघारा (१) में किसी बात के रहते हुए भी यदि कोई खाता दो से अधिक काश्तकारों के पास संयुक्त रूप में होतो, ऐसे काश्त— कारों में से कोई भी उक्त उपघारा में अभिदिष्ट घनराशि को खाते के दूसरे सभी काश्तकारों की ओर से जमा कर सकता है।" धारा ३ के बाद निम्नलिखित घारा ३—क के रूप में जोड़
		दिया जाय:— "३-क(१) यदि घारा ३ की उपधारा (१) के खंड (क) से (घ) तक में लिखित किसी व्यक्ति के खाते का कोई भाग किसी शिकमी- दार के पास हो तो ऐसा व्यक्ति, खाते के अवशष भूमि के लिय देग

दार के पास हो तो ऐसा व्यक्ति, खाते के अवशष भूमि के लिय देय लगान का १० गुना देने पर (ऐसी धनराशि असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा अवधारित की जायगी) अवशेष के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन प्रार्थना—पत्र दे सकता है और घारा ४ से ७ तक के निदेश ऐसे प्रार्थना— पत्र को लागू होंगे मानो कि अवशष भूमि एक पृथक खाता थी।

海科一 परिष्कार या संशोधन बारा संख्या (२) घारा ३ की उपघारा (१) के निदेश शिकमीदार के विषय में भी संप्रभाव होंगे मानो कि वह भी अपने पास की भूमि का काश्तकार है: "िकत्तु प्रतिबन्ध यह ह कि उक्त घारा के अधीन जब तक कि क्षेत्रपति की लिखित सहमति न हो, कोई प्रार्थना-पत्र नही दिया जायगा और यह कि प्रान्तीय सरकार को देय धनराशि उस भूमि के सम्बन्ध मे क्षेत्रपति द्वारा देय लगान की १५ गुनी होगी और यदि क्षेत्रपति इससे भी सहमत न हो तो ऐसे लगान की १० गुनी होगी। स्पष्टीकरण—उपधारा (१) और (२) में 'पद देय लगान' का तात्पर्य ऐसे लगान से है जिसे असिस्टेन्ट कलेक्टर निम्नलिखित का ध्यान रखते हुए निश्चित करें:-(१) पूरे खाते के लिये क्षत्रपति द्वारा देय लगान, (२) उस खाते का भाग जो शिकमीदार के पास हो, और (३) ऐसे भाग का भेद और प्रकार (नेचर एन्ड क्वालिटी), (३) यदि घारा ३ क-और ६ के अनुसार किसी शिकमीदार के पक्ष में प्रख्यापन प्रदान हुआ है तो प्रख्यापन के दिनांक से क्षेत्रपति के विषय में यह समझा जायगा कि किसी विधि या मसविदा में किसी बात के रहते हुए भी उसने ऐसी भूमि को समिपत कर दिया है ओर शिक-मीदार उस भूमि का ऐसा मौरुसी काइतकार हो गया है, जिसे लगान की ऐसी घनरांशि देनी पडेगी, जो घारा ३-क के स्पष्टीकरण के अनु-सार अवधारित धनराशि के बराबर हो।" वर्तमान घारा ४, उपधारा (१) होगी और निम्नलिखित उपधारा ų (२) के रूप में बढ़ा दी जायगी:--"(२) यदि काश्तकार द्वारा देय या देय समझा जाने वाला लगान ऐसी भूमि की लाग मौकसी दरों से लगाये गए लगान से दुगुना या दुगुना से अधिक हो तो उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिय देय लगान वह धनराशि होगी जो उक्त धनराशि से दुग्नी से अधिक नहीं होगी और जिसे असिस्टेन्ट कन्नेक्टर उचित और ठीक तौर से अवधारित करगा।" उपधारा (२) की पंक्ति ४-५ में शब्द "गाटों के" के स्थान Ę Ę शबद "खाते के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान " रखा जायगा। उपधारा (३) में शब्द "खाते के लगान" के स्थान पर शब्द 9 ''खाते के सम्बन्ध में उसके द्वारा देय लगान'' रखा जायगा। उपधारा (८) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा:--C Ę "(८) उसे खाने की दशा में जो दो से अधिक काश्तकारों के पास संयुक्त रूप में हो, प्रख्यापन-(क) यदि घारा ३ की उपधारा (१) के अनुसार धनराशि जमा की गई हो तो केवल प्रार्थी के पक्ष में प्रदान होगा, और (ख) यदि उक्त धारा की उपधारा (२) के अनुसार धनराशि जमा की गई हो तो सभी सह-काश्तकारों के पक्ष में संयुक्त रूप से, प्रदान होगा।" उपधारा (९) के बाद निम्नलिखित उपधारा (१०) जोड़ दी Ę जायगी:--"(१०) ऐसी कोई घनराधि, जो उपधारा (९) के अनुसार देय हो,

किसी व्यक्ति द्वारा जो उसका अधिकारी हो, मालगुजारी के बकाया के रूप

२९२		लाजस्वाटव असम्बला [९ जनदरा, १९५०
त्रम सच्य	घारा	परिस्कार या सक्षोधन
१०	\9	में वसूल किया जा सकेगा, मानो कि वह ऐसी धनराशि थी जिसे संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्बवस्था विवान १९४९, ई० की धारा २६२-ग लागू है।" वर्तमान धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा:
		"(७) धारा ६ के अधीन प्रख्यापन के प्रदान होने पर, धारा ३ के अधीन भगतान के या धारा ६ की उपधारा (४) के अधीन जमा करने के, जैसी भी दशा हो, दिनांक से प्रार्थी निम्नलिखित विशेषाधिकार का अधिकारी हो जायगा, अर्थात्— (क) (१) यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में किसी बात के रहते हुए भी प्रार्थी बेदखली की किसी डिग्री या आज्ञा या बकाया लगान की किसी डिग्री के निष्पादन में बेदखल नहीं किया जा सकेगा। (२) यदि धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन धनराशि जमा कर दी गई हो तो ऐसे खाते से या उसके ऐसे भाग से। (३) यदि धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन धनराशि जमा कर दी गई हो तो ऐसे खाते से या उसके ऐसे भाग से जो उस खाते
₹ १	U	में उसके अंश के अनुपात से हो। (ख) लगान की ऐसी किस्त के सम्बन्ध में, जो उक्त दिनांक के बाद देय हो जाय तो प्रार्थी, और उस दशा में जबिक धारा ३ की उपधारा (२) लागू हो तो खाते के सभी काश्तकार संयुक्त रूप से, किसी विधि या मसिवदा में किसी बात के रहते हुए भी, ऐसी किस्त के लिये उस धनराशि के देनदार होंगे जो प्रार्थी द्वारा या काश्तकारों द्वारा संयुक्त रूप से देय धनराशि के आधे के बराबर होगी और अवशेष के विषय में यह समझा जायगा कि वह उस दिनांक पर जबिक किस्त देय हो गई, वह प्रार्थी के द्वारा या काश्तकारों के द्वारा प्रान्तीय सरकार के पास जमा कर दिया गया: किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त प्रकार का भुगतान ३१ दिसंबर, १९४९ ई० को या उसके पूर्व कर दिया गया है तो इस खंड के लाभ उन किश्तों के सम्बन्ध में भी होंगे, जो १ ली अक्तूबर, १९४९ ई० और ३१ दिसम्बर, १९४९ ई० के बीच में देय हो गई थी।" धारा ७ के बाद निम्नलिखित नवीन धारायें ७-क और ७-ख
		जोड़ दो जायंगी:— ७—क—धारा ६ के अधीन किसी प्रख्यापन के कारण कोई व्यक्ति अपने खाते में उससे अधिक अंश का अधिकारी नहीं होगा जितनें का कि वह इसके अतिरक्त अधिकारी या और प्रख्यापन के होने पर भी खाते में किसी दूसरे काश्तकार का स्वत्व अप्रभावित रहेगा। ७—ख—यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ ई० में किसी बात के रहते हुए भी और जमींदारी बिनाश और भूमि व्यवस्था ऐक्ट, १६४६ ई० की १५१ से १६६ धाराओं (जिसमें दोनों धारायें अंतर्गत हैं) के प्रतिबन्धों को बाधित न करते हुए धारा ६ के प्रख्यापन के विनांक से प्रार्थों को बारा ७ में बिणत विशेषाधिकारों के अतिरिक्त यह भी अधिकार प्राप्त
१२	१२	होगा कि उस खाते का सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, जिसके वारे में प्रख्यापत हुआ है, दित्सा (Will) कर सके अथवा हस्तान्तरण कर सके।" शब्द "द्वारा" और "निरस्त" के बीच में शब्द "या परिष्कृत" रख दिया जाया।

रख दिया जायगा।

परिश्चिष्ट ३ (धारा ३०४-क)

कम				न्याय	ालय
संख्या	धारा	कार्यवाही का व्योरा .	• •	प्रथम अपील	द्वितीय अपील
8	२	3	8	ų	Ę
१	१५	भूमि की स्वीकृति या जोत की अवधि के बढ़ने के लिये ठेकेदार का प्रार्थना-पत्र ।	कलेक्टर	कभिइनर	
२	१६		असिस्टेन कलेक्टर प्रजम श्रेणी ।	"	• •
m	₹8			"	बोर्ड
ሄ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	भूमिधारी अधिकार के उपार्जन का प्रार्थना -पत्र ।	असिरटेट क्लेक्टर, प्रयम श्रेणी।	33	33
ધ		त्रथ्यापन का प्रार्थेना-पत्र	परगना के इंबार्ज असिस्टेट करेज्दर	"	77
Ç	१६५ १९२ २०० (स (ग) (घ (ड) (च और (ज	r) a) r)	अभिस्टेट क रेक्टर, प्रथम श्रेणी	77	>>
ঙ		समर्पण का प्रार्थना-पत्र	तहसीलदार	לל	
۷	१८९		"	"	.,
९	१९६		परगना के इंचार्ज असिस्टेट कक्षेटर	,, 1	• • •
१०	२१०	गांव–सभा द्वारा निश्चित किये हुए लगानके विरुद्ध उद्धारी ।	"	"	बोः

१६

क्रम सख्य	घारा	परिस्कार य	प्रासंशोधन		
११	२११-क	लगान अवधारित करने और बकाया लगान के लिये वाद ।	असिस्टेन्ट कलेक्टर, प्रथम श्रेणी।	कमिश्नर	बोर
१२	२१३–ख	लगान को नकदी में परिवर्तन का बाद ।	"	"	19
१३	२१४	बकाया लगान की वसूली और बेदखली का प्रार्थना -पत्र ।	तहसीलदार	77	33
१४	२१५-क	नहर संबंधी देयों की वसूली के लिये वाद ।	77	> 7	37
१५		अधिवासी के लगान को अवधारित	असिस्टेन्ट कक्लेटर, प्रथम श्रेणी ।	77	"
१६	∫ २२१-ख } और (ग)	करने का प्रार्थना-पत्र । अधिवासी की बेदखली का वाद	27	55	77
१७	२२२ -	वालगुजारा का नकदा म पार वर्तन का प्रार्थना—पत्र ।	77	77	77
१८	िर३७ ३ २३८	मालगुजारी की घटाने के लिये प्रार्थना–पत्र ।	परगना के इंचार्ज, असिस्टेट कलक्टर	37	Đ
१९	२६९ र	तहकारी फार्म के बनाने के लिये प्रार्थना–पत्र ।		77	"
२०	२८४ ।	फार्म के भूमि की चकबन्दी के लिये प्रार्थना–पत्र ।	"	77	33

अनुसूची ४ (धारा ४) सूची १

विधायन (enactment) का नाम कम संख्या

```
बंगाल पर्मानेन्ट सेटिलमेट रेगुलेशन नं० १, १७९५ ।
      दी बनारस फेमिली डोमेन्स रेंगुलेशन नं० १५, १७९५ ।
      बंगाल पर्मानेन्ट सेटिलमेंट (संप्लीमेंटल) रेगुलेशन नं०२७, १७९५ ।
      बनारस इन्हेरीटेन्स रेगुलेशन नं० ५४, १७९५।
      दी बनारस फेमिली डोमेन्स रेगुलेशन नं० ७, १८२८।
      बंगाल लैंड रेवेन्यू (सेटिलमेंट ऐण्ड डिप्टी कलेक्टस) रेगुलेशन नं० ९, १८३३।
      अवध सब-सेटिलमेंट्स ऐक्ट नं ० २६, १८६६।
      दी परगना कसवार राजा ऐक्ट नं० १, १९११।
  6
      परगना कसवार राजा एक्ट नं० ४।
      यूनाइट ड प्राविसेन प्राइवेट इरीगेशन वर्क्स ऐक्ट नं० २, १९२०।
१०
     कोनिंग कालेज ऐण्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन कन्ट्रोब्यूशन ऐक्ट नं० ४, १९२०।
११
     आगरा प्रिएम्पशन ऐक्ट नं० ९, १९२२ ।
१२
     आगरा जमींदारी एसोसियेशन कन्ट्रीब्यूशन ऐक्ट नं० २, १९२७ ।
१३
     यूनाइटेड प्राविसेज अबेटमेंट आफ रेन्ट सूट्स ऐक्ट नं० १३, १९३८ ।
88
१५
     यूनाइटेड प्राविसेज रेगुलराइजेशन आफ रेमिशन्स ऐक्ट नं० १४, १९२८।
     यूनाइटेड प्राविसेज टेनेन्सी ऐक्ट नं १७, १९३९ ।
```

२९५

नत्थियां सूची २ यू० पी० छैगड **रेवेन्यू पे**क्ट नं० ३**, १**६०१

ऋम- संख्या	घारा	परिष्कार या संशोधन
?	२१	(क) पंक्ति २ में शब्द "mahals" के स्थान पर शब्द "villages"
ર	२३	रख दिया जायगा, और (ख) पंक्ति ३ और ४ में शब्द "Patwari's circle" and "circles" के स्थान पर शब्द "halka" रखा जायगा । "a patwari 10 each circle" के स्थान पर शब्द "halka"
*		रखा जायगा ।
74	२७	(क) पंक्ति ४ मे ज्ञाब्द "papers" के स्थान पर ज्ञाब्द "docu- ments" रख दिया जायगा। (ख) पंक्ति ६ में ज्ञाब्द "Crown" के स्थान पर ज्ञाब्द "Provincial Government" रख दिया जायगा।
*	२८	पंक्ति ६ मे शब्द "vɪllage" और "or" के बीच में से विलेज के बाद का कामा और शब्द "mahal" निकाल दिया जायगा।
ય	₹ ९	वर्तमान धारा २९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा : "29. (1) It shall be the duty of every tenure-holder to maintain and keep in repair at his cost the perma- nent boundary marks lawfully erected on his fields. (2) It shall be the duty of the Gaon Sabha to main- tain and keep in repair at its cost the permanent boundary marks lawfully erected on the village situate within its jurisdiction. (3) The Collector may at any time, order, as the case may be, a Gaon Sabha or tenure holder— (a) to erect proper boundary marks on such villages or fields; (b) to repair or renew in such form and nature, as may be prescribed, all boundary marks lawfully erected therein.
Ę	₹०	शब्द "the owners of the counterminous villages, mahals or fields" के स्थान पर शब्द "tenure holder or Gaon Sabha of counterminous fileds or villages as the case may be," रख दिये जायंगे।
9	₹ ₹	"31. The Collector shall prepare and maintan in the prescribed form a list of all villages and will show there in the prescribed manner the areas— (a) liable to fluvial action. (b) having precarious cultivation, and (c) the revenue whereof has, either wholly or in part been released, compounded, redeemed or assigned. Such registers shall be revised every five years in accordance with the rules framed in that behalf."

क्रम- संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
6	३२	वर्तमान धारा ३२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :
		"32. There shall be a record of rights for each village subject to such exceptions as may be prescribed by rules made under the provisions of section 234 the record of rights shall consist of a register of all persons cultivating or otherwise occupying land specifying the particulars required by section 55."
8	त्र	(क) उपधारा (१) में शब्द "set of the register enumerated in section 32" के स्थान पर शब्द "register mentioned in section 23" रख दिये जायगे। (ख) उपधारा (१) के अनुच्छेद पैरा २ में और उपधारा (२) की पंक्ति २ में आये हुए शब्द "registers" के स्थान में शब्द "registers" रखा जायगा।
		(ग) उपधारा (३) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगः:
		"No such change or transaction shall be recorded without the order of the Collector or as hereinafter provided, of the Tahsildar or the Panchayati Adalat as constituted under section 42 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947."
१०	38	(क) उपधारा (१) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगाः——
	ı	"(1) Every person obtaining possession by succession or transfer of any land in a village which is required to be recorded in the register specified in section 32 shall report such succession or transfer to the Panchayatr Adalat exercising jurisdiction in the village in which the land is situate." (ख) उपधारा (२) और (३) में जहां—कहों भी शब्द "mortgage or" आये हों, निकाल दिये जायेंगे।
		(ग) स्पष्टीकरण मे
		(१) शब्द "proprietary share" के स्थान पर शब्द "hold- ing" रखा जायगा, और
		(२) शब्द "register of proprietors" के स्थान में शब्द "regord of rights" रखा जायगा।
		(३) स्पष्टीकरण के बाद फुलस्टाप को हटाया जायगा और निम्न-
	•	लिखित जोड़ दिया जायगा:—— "or in exchange of hording under section 160 of the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949."

कम- संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
ec as sr di th th		(?) वर्तमान घारा ३५ के स्थान में निम्निल्खित रखा जाय:— "35. Notwithstanding anything contained in the Panchayat Raj Act, 1947, the Panchayati Adalat, on receiving such report, or from the facts otherwise coming to its knowledge, shall make such inquiry as appears necessary and in undisputed case of succession, if it appears to have taken place, shall direct the patwari of the halka to record the same in the annual register; if the succession is disputed the Panchayati Adalat shall refer the case to the Tahsildar who shall dispose it of after deciding the dispute in accordance with the provisions of section 40".
		(२) संशोधित धारा ३५ को ३५(१)पुनरांकित किया जाय। (३) निम्नलिखित उपधारा (२) और (३) के रूप में इस धारा में बढ़ा दी जाय:— "(2) The Panchayati Adalat shall make inquirics in the prescribed manner in all cases of transfer and shall submit them with its report
		(3) The Tahsildar shall, if the case is not disputed before him, after satisfying h mself that the transfer is valid, record the same in the annual register; if the transfer is disputed or the Tahsildar finds that it is in contravention of the provisions of the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949, he shall refer the case to the Collector, who shall, after such inquiry, as may be prescribed, dispose it of."
१ २	३६	धारा ३६ निकाल दो जायगी।
१३ १४	<i>७६</i> ३८	शब्द "one hundred" के स्थान में शब्द "five" रखा जायगा।
१ %	₹ <i>९</i>	पंक्ति ३ मे शब्द "mortgage or" निकाल दिया जायगा। वर्तमान धारा ३९ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा:— "The Collector may, on his motion, and shall, on the application of any person, correct any mistake or error in the annual register arising from any accidental slip or omission."
१६	४०	शब्द "Collector" के स्थान में शब्द "Tahsildar " रखा जायगा।
99	द्ध-प	घारा ४१–ए निकाल दिया जायगा ।
१८ १९	४ ३ ४२	बारा ४२ निकाल दिया जायगा। (क) पंक्ति १ से ४ में शब्द "rent payable" से पहले, शब्द "revenue or" रख दिया जायगा। (ख) पंक्ति २ में शब्द "tenant" के स्थान पर शब्द "tenure—holder" रख दिया जायगा।

ऋम- संख्या	घारा	परिष्कार या संज्ञोधन
		(ग) इस घारा के अन्त में अंक "1939" के बाद शब्द "or the United Provinces Zamindarı Abolition and Land Reforms Act, 1949" रख दिया जायगा।
२०	88	वर्तमान धारा के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जायगा :—— "4. All entries in the annual register shall, until contrary is proved, be presumed to be true"
२१	४५	घारा ४५ निकाल दी जायगी।
२२	५०	(क) पंक्ति २ से ३ में शब्द "owners of villages, mahals and fields" शब्द के स्थान में "Gaon Sabha, bhumidhars and sirdars" रख दिया जायगा। (ख) पंक्ति ५ में शब्द "their villages, mahals or fields"
		के स्थान में शब्द "the villages and flelds" रख दिया
		जायगा। (ग) इस धारा के अन्त में शब्द "owner" के स्थान पर शब्द "Gaon Sabha, bhumidhars or sirdars concerned" रख दिया जायगा।
		(घ) "स्पष्टीकरण" निकाल दिया जायगा ।
२३	43	वर्तमान धारा ५३ के स्थान में निम्निङ्खित रखा जायगा:— "53. Where any local area is under record; operation the record officer shall frame for each village therein the record specified in section 32 and the record so framed shall thereafter be maintained by the Collector instead of the record previously maintained under section 33."
२४	48	अन्त की पंक्ति में सं०४२ निकाल दी जायगी।
24	५५	वर्तमान घारा ५५ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा :
		"55. The register of persons cultivating oro therwise occupying land specified in section 32 shall specify as to each tenure-holder the following particulars: (a) the class of tenure as determined by the United Provinces Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1949. (b) the revenue or rent payable by the tenure-holder, and (c) any other conditions of tenure which the Provincial Government may by rules made under section 234 require to be recorded."
२६	५६	घारा ५६ निकाल दो जायगो ।
२७	५७	पंक्ति १० में शब्द "clauses (A) to (D) of" निकाल दिये जायेंगे।
२८	५८से	
, -	•	(चंष्टर्स ५ से ७ तक)

ऋम- संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
२९	२१०	उपधारा (१) के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा'— "(1) Appeals shall lie under this Act as follows .— (a) to the Record Officer from orders passed by any Assistant Record Officer; (b) to the Commissioner from orders passed by Assistant Collector or Tahsildar; (c) to the Board from judicial orders passed by a Commissioner or Additional Commissioner or Record Officer."
₹0	२१२	(ख) उपघारा (२), (३) और (५) निकाल दिये जायं। धारा २१२ निकाल दी जाय।
₹ १	२१	३ वर्तमान घारा २१३ के स्थान में निम्नलिखित रखा जायगा :
		"213. A second appeal shall lie to the Board from a final order deciding an appeal under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 210 on any of the following grounds and no other, namely- (1) that the decision being contrary to law or to some usage having the force of law— (2) the decision having failed to determine some material issue of law or usage having the force of law,
		(3) a substantial error or defect in the procedure as prescribed by this Act, which may possibly have produced error or defect in the decision of the case upon the merits."
३ २	२१४	(क) उपधारा (१) निकाल दिया जायगा ।
		(ख) पंक्ति १ में
		(१) शब्द "or second appeal" निकाल दिये जायंगे ।
		(२) शब्द "to" और "the Commissioner" के बीच में शब्द "Record Officer or" रख दिये जायंगे ।
		(ग) ंक्ति २ में शब्द "sixty" के स्थान पर शब्द "thirty"

रला जायगा।

ऋम सस्या	धारा	परिष्कार या संशोधन		
		(घ) उपधारा (३) मे—		
		(१) जन्द "appeals, second appeal or third appeal" के स्थान में जन्द "appeal or second appeal" रखे जायंगे।		
		(२) शब्द "ninety" के स्थान पर शब्द "sixty" रखा जायगा।		
3 3	२२६	थारा २२६ निकाल दी जायगी ।		
38	२२७	खंड ६ से १७ तक निकाल दिये जायं।		
३५	२३१	धारा २३१ निकाल दो जायगी।		
३६	२३२	धारा २३२ निकाल दी जायगी।		
इंख	२३३	खंड (सी) ओर (ई) से (एम) तक निकाल दिये जायंगे।		
३८	२३४	बैकेट और अक्षर ''(एफ)'' निकाल दिये जायं और उसके स्थान में बैकेट और अक्षर ''(ई)'' रख दिये जायं। (एम), (आई),(ओ) से (एस) तक निकाल दिये जायं।		
		(जी) से (एल) तक, (एम) (२), (एन),(टी) और (यू) निकाल दिये जायं। खंड (वी) (१) में शब्द "not connected with settlement" निकाल दिये जायं।		
		क्लाज(बो)(२) में शब्द "or settlement" और शब्द "other than costs recoverable by the Provincial Government in proceedings in partition cases" निकाल दिये जायं।		
		क्लाज़ (डब्ल्यू) (१) में शब्द "not connected with settle- ment" निकाल दिये जायं।		
		क्लाज (डब्ह्यू) (२) में शब्द ''or settlement'' निकाल दिये जायं।		
		क्लाज (एक्स) (१) में शहद "not connected with settlement" निकाल दिये जार्ज ।		
	and standing and security and	क्लाज (एक्स) (२) में शब्द "or settlement" निकाल दिये जायं।		

उद्देश्यों भीर कान्यों का विवर्ण

८ अगस्त, १९४६ ई० को संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा (United Provinces Legislative Assembly) ने जमींदारी प्रथा को, जिसके अनुसार राज्य और कृषक के बीच मध्यवितयों की स्थिति है, हटाने के सिद्धान्त को स्वीकृत किया और यह प्रस्ताव पास किया कि ऐसे मध्यवितयों के अधिकार उचित प्रतिकर देकर हस्तगत कर हिये जायं। व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव के अनुसार जमींदारी-उन्मूलन मिनि नियक्त ्री गई थी, जिसने इस जटिल प्रश्न के विविध पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करके अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जपींदार के विनाश और उसके स्थान पर हमारे देश की प्रतिभा और परम्परा के अनुकुल मृति-व्यवस्था की विस्तृत योजना दी गई है। इस विषय में जनता ने बड़ी उत्सुक्ता प्रकट की और समाचार-पत्रों और सार्वजनिक सभाओं से इसके समान्य प्रक्तों पर बहुत वाद-विवाद हुआ। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उसकी सिफारिशों की भी खुब चर्चा हुई। अब यह बहमन से स्वीकृत किया जाता है िक कृषि सम्बन्धी निप्णना और खाद्य-उत्पादन में वृद्धि की सुरक्षित र खने, ग्राम वासियों के जीवन-स्तर को उन्ना करने और कृषक के व्यक्तित्र के पूर्वविकास के निमित्त अवसर देने के लिपे वर्तमान मुमि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किये जिया ग्राम्य-समाज के पुनम्तरयात की कोई मगठित योजना नहीं बनाई जा सकती है। शासन की सुविधा और उपयोगिता के कारणों से अंग्रेजों द्वारा स्थापित जमींदार-काश्तकार की प्रया राजनैतिक स्वतंत्रता के आपिर्भाव के साथ एक नयी परिपाटी में परिवर्तित हो जानी चाहिये, जिससे कुषकों को वे अधिकार और स्वतंत्रता फिर से प्राप्त हो जायं, जो उनके थे, और गांव-समाज को वह प्रभुत्व फिर से प्राप्त हो जाय, जिसका उपयोग वह प्राम्य-जीवन के प्रत्येक अंग के सम्बन्ध में करता था।

बिल में यह क्यवस्था की गई है कि मंध्यवितयों को उनकी पक्की निकासी का अठ-गुना प्रतिकर देकर उनके अधिकार हस्तगत कर लिये जायं। इससे बड़े जमींदारों को इतनी आय हो जायगी जो उनके उपयुक्त रहन-सहन के लिये पर्याप्त हो। अधिकतर जमींदार छोटी श्रेणी के हैं और उनके पुनर्जासन के लिए उनकी पक्की निकासी के दो-गुना से बीस-गुना तक कमबद्ध पुनर्वासन अनुदान की भी व्यवस्था की गई है, जो कम आय वालों के लिये सबसे अधिक और अपेक्षाकृत बड़ी आय वालों के लिये सबसे कम होगा। आर्थिक और विधिक किठनाइयों को दूर करने के लिए काइतकारों से ८ ह कहा जायगा कि वे अपने लगान का दम गुना स्वेच्छा से दे दें। ईससे जमींदारी का शीघू विनाश हो सकेगा, मुद्रास्फीत रोकी जा सकेगी और, कृषकों की बचत उत्पादनशील प्रयोजन में लगाई जा सकेगी। जो काइतकार इस प्रकार धन देंगे उनको अपने खातों में अन्तरण योग्य अधिकार मिल जायेंगे, वे भूमिवर कहलायेंगे और अपने वर्तमान लगान का ५० प्रतिशत मालगुजारी के रूप में देंगे।

यह आवश्यक समझा गया है कि वर्तमान खातेवारी अधिकारों के भामक भेदों के स्थान पर एक सरल और समान योजना रक्खी जाय। इसलिये यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में केवल दो प्रकार की खातेवारी होगी। यह आशा की जाती है कि अधिकतर कृषक भूमिषर हो जायंगे। वर्तमान मध्यवर्ती अपनी सीर, खुदकाश्त और बागों के सम्बन्ध में भूमिषर के वर्ग में रक्खे जायेंगे और इसी प्रकार वे काश्तकार भी, जो अपने लगान का दस-गुना दे दें। शेष काश्तकार सीरदार कहलायेंगे और उनको भूमि में स्थायी और वंशानुगामी अधिकार मिलेंगें, वे कृषि, फलोत्पादन या पशुपालन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए अपनी भूमि का उपयोग कर सकेंगे, और कोई भी उन्नति—कार्य कर सकेंगे।

खातेदारी का एक छोटा रूप असामी कहलायेगा, जो बहुत थोड़े व्यक्तियों को लागू .होगा। इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि के गैर-दखीलकार काश्तकार होंगे जिसमें स्थायी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं, अर्थात् अस्थिर और अस्थायी खेती के क्षेत्र और ऐसे क्यक्ति, जिनको भविष्य में ऐसे भूमिधर और सीरदार अपनी भूमि लगान पर उठा द, जो स्वयं खेती करने में असमर्थ हों। जमींदारी प्रथा फिर से न उठ खड़ी हो इसको रोकने के लिये यह आवश्यक जान पड़ता है कि केवल ऐसे भूमिधरों और सीरदारों को अपनी भूमि लगान पर उठाने का अधिकार दिया जाय, जो असमर्थ हों, अर्थात् अवयस्क, विध्ववायें और ऐसे व्यक्ति, जो किसी शारीरिक या मानसिक निबंलता से प्रस्त हों।

ऐसे बहुसंख्यक कृषकों के स्वत्व को रक्षा करना भी वांछनीय है, जिनको इस समग्र भूमि में कोई स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, किन्तु जिनकी भूमि के छूट जाने पर सामाजिक अन्याय और गम्भीर आर्थिक कि नाइयां उत्पन्न हो जायंगी। साधारणतया सीर के सभी काइनकारों के, जिन्हें वंशानगामी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तथा वर्तमान शिकमी काइतकारों के, पांच वर्ष के लिये काइतकारी अधिकार सुरक्षित रक्ष्व जायंगे और उसके बाद वे मौक्सी दरों का या असली काइतकार के लगान का १५-गुना देकर भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

अलाभकर खातों की वृद्धि रोक ने के लिए यूनाइटेड प्राविसेज टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में दिये गये परिमित उत्तराधिकारों की तालिका कुछ परिवर्तनों के साथ उसी रूप में रख ली गई है और भविष्य में खातों के ऐसे बटवारे का निषेच कर दिया गया है, जिससे अलाभकर खाते उत्पन्न हों। इस अभिप्राय से कि बड़े-बड़े खाते अत्यधिक संख्या में न ही जायं और उसके फलस्वरूप श्रमिकों का शोषण न हो, भविष्य में किसी व्यक्ति को ऋय या दान द्वारा इतनी भूमि प्राप्त करने की अनुज्ञा न वी जायगी कि उसका खाता ३० एकड़ से अधिक का हो जाय।

सार्वजितक उपयोगिता की सब भूमि, जैसे आबादी—स्थल, रास्ते, बंजर—भूमि, जंगल, मीनाइाय, सार्वजितक कुंयें, तालाब और जल—प्रणालियां, गांव—समाज के, जिसमें गांव के सभी निवासी तथा पाही—काइत कृषक सिम्मिलित होंगे, स्वत्वाधिकार में आएंगी। गांव—समाज की ओर से कार्य—संचालन में गांव—पंचायत की भूमि के प्रबन्ध के विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। गांव को एक छोटा सा प्रजातन्त्र और सहकारी समाज बनाने की इस व्यवस्था का अभिप्राय आधिक और सामाजिक विकास की सुविधा देना और सामाजिक उत्तरदायित्व और भाईचारे का प्रोत्साहन है।

वर्तमान अलाभकर खातों की खेती के सम्बन्ध में होने वाली हानि और अकुशलता को दूर करने के लिए इस बिल में हमारी स्थिति के अनुकूल सहकारी खेती के प्रोत्साहन और शीघृ उन्नति की व्यवस्था की गई है।

इस ऐक्ट के पास होते पर यथाशीच्च उसके निदेशों को सरकारी आस्थानों पर भी लागू करने का विचार किया जाता है। म्युनिसिपैलिटी, कैन्ट्रनमेंट, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया की सीमाओं में स्थित कृषि-क्षेत्रों के सम्बन्ध में अलग क़ानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसे मध्यर्वातयों के, जिनके अधिकार हुस्तगत कर लिये जायंगे, ऋण कम करने के लिए एक दूसरा बिल होगा।

> हुकुम सिंह विश्वेन, माल सचिव।

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

मंगलवार, १० जनवरी सन् १९५० ई०

ग्रसेम्बली की बैठक ग्रसेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में ग्रारम्भ हुई

स्पीकर-माननीय श्री पु षोत्तमदास टर्डन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१८८)

अचल सिंह अजित प्रताप सिंह अब्दुल बाक़ी अब्दुल मजीद अब्दुल मजीद ख्वाजा अब्दुल वाजिद, श्रीमती अब्दुल हमीद अर्नेस्ट माईकेल ।फेलिप्स अलगूराय शास्त्री अल्फ्रेड धर्मदास असर्गर अली खां अक्षयवर सिंह आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती जदयवीर सिंह ऐजाज रसूल कमलापति तिवारी करीमुर्रजा लां कालीचरण टण्डन कुंजबिहारी लाल शिवानी कुशलानन्द गैरोला क्रपाशंकर कुरण चल्द्र कुष्ण चन्द्र गुप्त केशव गुप्त सानचन्द गीतम खुशवन्तराय

खुशीराम खबसिह गंगाधर गंगा प्रसाद गंगा सहाय चौबे गजाधर प्रसाद गणपति सहाय गणेश कृष्ण जैतली गोपाल नारायण सक्सेना गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री गोविन्द सहाय चतुर्भुज शर्मा चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री चन्द्र भानु शरण सिंह चरण सिंह चेतराम छेदालाल गुप्त जगन्नाथदास जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जगमोहन सिंह नेगी जयपाल सिंह जयराम वर्मा जवाहर लाल रोहतगी जहर अहमद जाकिर अली जाहिद हसन जुगुल किशोर त्रिलोकी सिंह

दयालदास भगत दाऊदयाल खन्ना द्वारिका प्रसाद मौर्य दीन दयालु अवस्थी दीन दयालु शास्त्री दीप नारायण वर्मा नफ़ीसुल हसन नवाजिश अली खां नवाब सिंह नाजिम अली नारायण दास निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री निहालुद्दीन पूर्णमासी प्रकाशवती सूद, श्रीमती प्रागनारायण प्रेम किशन खन्ना फखरल इस्लाम फतेह सिंह राणा फूलसिंह बदन सिह बनारसी दास बलदेव प्रसाद बशीर अहमद बशीर अहमद अन्सारी बादशाह गुप्त बाबू राम वर्मा बुजमोहन लाल शास्त्री भगवती प्रसाद दुबे भगवती प्रसाद शुक्ल भगवानदीन भगवानदीन मिश्र भारत सिंह यादवाचार्य भीम सेन मंगला प्रसाद मसुरिया दीन महफूजुर्रहमान महमूद अली खां मिजाजी लाल मुकुन्दलाल अग्रवाल मुजपफ़र हुसेन मुहम्मद अदील अब्बासी मुहम्मद असरार अहमद मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री मुहम्मद इस्माइल मुहम्मद जमशेद अली खां

मुहम्मद नबी मुहम्मद नजीर मुहम्मद याकूब मुहम्मद युसुफ़ मुहम्मद रजा खां मुहम्मद शक्र मुहम्मद शमीम मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी मुहम्मद सुलेमान अधमी यज्ञनारायण उपाध्याय रघुनाथ विनायक घुलेकर रघुवंशनारायण सिंह रघुवीर सहाय राघव दास राजाराम मिश्र राजाराम शास्त्री राधाकृष्ण अग्रवाल राधा मोहन सिंह राधेइयाम शर्मा रामकुमार शास्त्री राम कृपाल सिंह रामचन्द्र पालीवाल रामचन्द्र सेहरा रामघारी पांडे रामबली मिश्र राममूति रामशंकर लाल रामशरण रामस्वरूप गुप्त रक्नुद्दीन खां रोशन जमां खां लक्ष्मी देवी, श्रीमती लताफत हु सेन लाखन दास जाटव लालबहादुर, माननीय लाल विहारी टण्डन लोलाधर अष्ठाना लुत्फ अली खां लोटन राम वंश गोपाल वंशोधर मिश्र विजयानन्द मिश्र विद्याघर बाजपेयी विद्यावती राठौर, श्रीमती विनय कुमार मुकर्जी विश्वनाथ प्रसाद

विश्वनाथ राय विद्वम्भर दयाल त्रिपाठी विष्णु शरण दुब्लिश बीरबल सिह वीरेन्द्र शाह वेकटेश नारायण तिवारी शंकर दत्त शर्मा शान्ति प्रपन्न शर्मा शिवकुमार पांडे शिवकुमार मिश्र शिवदयाल उपाध्याय शिवदान सिह शिवमंगल सिंह शिवमंगल सिंह कपूर इयाम लाल वर्मा व्याम सुन्दर शुक्ल श्रीचन्द सिंघल श्रीपति सहाय सज्जन देथी महनोत, श्रीमती सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री

सरवत हुसैन सलीम हामिद खा साजिद हुसन सालिग्राम जयसवाल सिहासन सिह सोताराम अष्ठाना सुदामा प्रसाद सुरेन्द्र बहादुर सिंह सूर्य प्रसाद अवस्थी सईद अहमद हबीबुर्रहमान अन्सारी हबीबुर्रहमान खां हरगोविन्द पन्त हर प्रसाद सत्य प्रेमी हर प्रसाद सिंह हरिहर नाथ शास्त्री हसरत मोहानी हुकुम सिंह, माननीय श्री होतोलाल अग्रवाल हैदर बख्य

प्रश्लोत्तर

९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्य सूची के शेष प्रदन तारांकित प्रश्न

कोर्ट ग्राफ़ वार्ड्स के ग्रधीन की गई ज़मींदारियां

*९८--श्री मृहम्म इ ग्रसरार ग्रहम द--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कोई आफ वार्ड्स में नये सुवार के बाद, जो इस सरकार के समय में हुए, कौन-कौन सी जमींदारियां और किन कारणों से उसके अधीन की गर्यी ? उनका नाम और विवरण पृथक-पृथक दिये जांय तथा किन कारणों से ऐसी आवश्यकता हुई और कोई की गयी जमीदारियों की निकासी क्या है ?

*९९—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि ऐसी कौनसी अन्य जमींदारियां है, जिन के लिये जनता की और से अथवा अन्य किसी तरीक़े से कोर्ट करने की मांग की गयी ? वह किस निकासी की थी ? उनके कौन मालिक थे तथा उनको कोर्ट आफ़ वार्ड स के अवीन करने के क्या कारण थे ?

माननीय माल सचिव(श्री हुकुर्मासह)--पूचना अभी एकत्र नहीं की जा सकी है, अतएव उत्तर बाद में दे दिया जायगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि साल भर में अब तक यह इंस्तिला इकट्ठा न होने के क्या वजूहात है ?

माननीय मा न सिचव--इतिला बड़ी पेनीदा मांगी गयी है, उसमें काफ़ी बक्त लगेगा। श्री महम्मद ससरार सहमद--क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि कोई भी जमींदारी कोर्ड आफ़ बार्ड समें अब तक ली गयी है या नहीं ?

माननीय माल संचित--८-९ रियासतें ली गयी है। *१००--श्री मुहम्मद असरार ग्रहमद--(वापस लिया गया।) पंचायती ग्रदालतों के सरपंचों के चुनाव के सम्बन्ध में भगड़े *१०१-श्री मुहम्मद असरार श्रहमद-(स्थगित किया गया ।)

*१०२--श्री मुहम्मद् चसरार ग्रह्मद्--(क)क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायती अदालतों के सरवंचों के चुनाव के सिलसिले में हर जिले में कितने झगड़े हुए?

(ख) इन झगड़ों में कितने आदमी जल्मी हुए और कितने मारे गये ?

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मुक्तइमों का इन्दराज हुआ और कितने मुक्रइमे चलाये गये ? इस मुक्रइमों में से कितनों में सजा हुई, कितने छूटे, कितने अदालत के विचाराधीन हैं और कितने पुलिस के पास जांच के लिए हैं ?

मानतीय स्वशासन सचिव (श्री श्रात्माराम गोविन्द खेर)--(क) पंचायती अदालत के सरपंचों के चुनाव के सिलसिले प कानपुर, आजमगढ़, उन्नाव रायबरेली तथा

प्रतापगढ़ में झगड़े हुये। इन जिलों में एक-एक स्थान में झगड़ा हुआ।

- (ब) इन झगड़ों में एक व्यक्ति घायल हुआ, कोई मारा नहीं गया।
- (ग) २ मुत्रहमों का इन्दराज हुआ, १ मुक़हमा चलाया गया, न तो किसी मुक़हमे में सजा हुई और न कोई छोड़ा गया है, एक मुक़हमा अदालत के विचाराधीन है और एक के सम्बन्ध में पुलिस जांच कर रही है।

स्थान, जहां १ ग्रगत्त, १६४७ ई० से दका १४४ लागु है

*१०२--श्री मुह्म्मद् ग्रसरार ग्रह्मद्--(क) क्या सरकार बतायेगी कि प्रांत की किस-किस म्युनिसियेलिटी और जिले में १ अगस्त सन् १९४७ ई० से अब तक दक्षा १४४ लागू की गयी और क्यों ?

(ख) प्रश्नेक स्थान पर यह दका कि उने दिन लागू रही ?

माननीय प्रयान सिवव(श्रो गोविन्द वरतम पन्त)—(क) दफ्ता १४४ जान्ता फीजवारी के अन्त गंत हुकुम जारी करने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेटों तथा सब-डिवीजनल मिजिस्ट्रेटों को प्राप्त है। वे लोग इस दक्ता के अनुसार शान्ति स्थापित रखने के लिये जब जरूरत समझते हैं आजारें जारी करते हैं। सरकार की ओर से ऐसी आजारें जारी नहीं होतीं।

पहली अगस्त सन् १९४७ ई० से अब तक थोड़े—थोड़े दिनों के लिये दफ़ा १४४ की आज्ञायें बहुत से जिलों में जारी की गई हैं, लेकिन उनका पूरा ब्योरा देना संभव नहीं है। माननीय सदस्य जिस जगह के बारे में विशव तौरसे जानना चाहते हों वहां की पूरी इत्तिला इकट्ठी की जा सकती है।

(ख) इसका उत्तर १०३ (क) में शामिल है।

श्री मुहम्मद चसर।र चहमद्—क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि अब तक हर म्यनिसिवैलिटी में साल भर दक्षा १४४ जारी रहती है। क्या उसको खतम करने के लिये गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनायो है ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)—जी नहीं, यह इतिला माननीय सवस्य की ग्रस्त है।

सोशल वर्कर्स के। बंदुक और पिस्तील के लाइसेन्सों का दिया जाना

*१०४—श्री मुहम्मद घंसरार ग्रहमद—क्या यह सही है कि सरकार ने सोशस्त वर्क्स को बन्द्रक और पिस्तौल के लाइसेन्स के लिए माली हैसियत संबंधी बंधन से मुक्त कर विया है ?

माननीय प्रधान सचिव-जी नहीं।

*१०५-श्री मुहम्मद् यसरार चहुमद्-क्या सरकार बतायेनी कि सोशल वर्कस से र कार का क्या मतलब है और इस खेणी में कौन-कौन से लोग शामिल किये गये हैं ? मानीय प्रधान सचिव--यह प्रश्न नहीं उठता।

*१०६--श्रो मुहम्मद ग्राहार ग्राहम द्र-- इत्रा सरकार बतायेगी कि १६ अगस्त सन् १९४७ ई० से अबतक विभिन्न जिल्लों में किन-किन लोगों को और किस-किस तारीख से लाइसेन्स दिये गये हैं ?

माननीय प्रयान सचिव--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है उसका ब्योरा देने म बहुत समय और मेइनन की जरूरत हैं। माननीय सदस्य यदि किसी खास जिले या व्यवित के बारे में सूचना चाहें तो उन्हें खुशी से बताया जा सकता है और वे मुझसे जान सकते हैं।

श्री मुहम्मद श्रासरार ग्रहम द्--क्या गवर्नमेंट के पास ऐमी शिकायत आयी है कि सोशल वर्कर्स को स्टेट्स न होने के बावजूद भी बन्दूक और पिस्तील के लाइसेंस दिये गये हैं।

माननीय पुलिस सचिव--ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आयी है।

विभिन्न जिलों में इमारतों का सत्कारी काम के लिये हस्तगत क ना

*१०७--श्रो मुह्म्मद ग्रस्एर ग्रह्मद्र--(क) क्या सरकार बतायेगी कि किस-किस जित्रे में कोत-कौत सी इपारतें किस सरकारी काम के लिए ली हुई है ?

(ख) यह इनारतें कित सनय से लो गयी हैं और इनका मासिक किराया क्या है ?

माननीय सार्वजिनिक निर्माण सिचव के सभा मंत्री (श्री लताफत हुसैन) — (क) (ख) सरकार यह समझती है कि इस सूचना के हासिल करने में जो वक्त और मेहनत लगगों वह ज्यादा मुक्कीर न होगी।

जिलें में सरकारी ग्रफसरों के रहने का प्रबन्ध

*१०८--श्रो मुहम्मद् ग्रमगर ग्रहमद्--क्या सरकार बतलायेगी कि प्रत्येक जिले में सरकारी अफ़सरों के रहने के लिए क्या प्रबन्ध है ?

श्री लताका हुसैन--कुड अकारों को सरकारी मकान या प्राइवेट मकान किराये पर लेकर दिये गये हैं। बाकी अकृतर अपने रहने का इन्तजाम खुद करते हैं।

विभिन्न वर्षीं में सिविल सेक टेरियट में प्रत्येक विभाग के कर्म चारियों की संख्या

*१०९--श्रो मुहम्मद् अस्टार ग्रह्मद्--क्या सरकार बतलायेगी कि ३१ मार्च सन् १९४६ ई०, १९४७ ई०, १९४८ ई० व १९४९ ई० को गवर्नमेंट सिविल सेकेटेरियट में कुलकिनने ते केटरी, अतिरिक्त सेकेटरी, डिप्टी सेकेटरी, असिस्टेंट सेकेटरी, सुपरिन्टेंडेंट, असिस्टेंट सुरिन्टेंडेंट, अन्य अफसर व क्लर्क काम कर रहे थे १ क्या सरकार प्रत्येक विभाग की सूची अलग-अलग देने की कृपा करेगी ?

मान रीय प्रधान सिचित्र के समा मन्ती (श्रो गोविन्द्र सहाय) -- पू॰ पी॰ सिविल से के टियट के प्रत्येक विभाग में ३१ मार्च सन् १९४६, १९४७, १९४८ तथा १९४९ ई॰ को गवर्तमेंड तिविल से केटे रियट में कार्य करने वाले से केटरी अतिरिक्त से केटरी, डिप्टी से केटरी, अतिरहेंट से केटरी, सुपरिन्टेंडेंट, अन्य अफसर व असिस्टेंट आदि की सूची । प्रत्येक वर्ष की अलग-प्रलग प्रस्तुत की जा रही है।

श्रो मुहम्मद् ग्रस्एर ग्रहमद्--क्या गवर्नमेंट बतलायगी कि अन्य आफिसर्स से क्या मतलब है।

श्री गोविन्द सहाय--पुरिन्टेंडेंट्स और कई स्पेशल आफित्स, जो इस किस्म के होते हैं, सभी की सूची †इसमें दे दी गयी है।

श्रो मुहस्मद् असरार अहमद्--श्या गवर्नमट बतलायेगी कि १५ से ४० आफिससँ क्यों मुक्तरर किये गये ? श्री गाविन्द सहाय—उसकी जरूरत थी, इसीलिये मुकर्रर किये गये। श्री मुहम्मद ग्रम्पर ग्रहमद —न्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि असिस्टेंट सेकेटरी १० के बजाय अब २० दो साल के अन्दरक्यों किये गये ?

श्री गोविन्द सहाय--हुश्रतन काम बढ़ गया है, इसलिये मुक्तर्र रिक्ये गये है। राजनीतिक पीड़ितों को मोटर श्री लारी के परिमट

*११०—श्री बनारसी दास—(क) क्या सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों को मोटर और लारी चलाने के परिमट देने का निश्चय किया है ?

- (ख) ऐसे कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?
- (ग) इनमें से अब तक कितने लोगों को परिमट दिये गए हैं और कितनी लारियां चलने लगी है।

माननीय पुलिम सचिव--(क) जी हां।

- (ख) पुरानी योजना (१९४८ ई०) के अन्तर्गत लगभग ५५० प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुए, नई योजना (१९४९ ई०) के अन्तर्गत करीब ५०० दर्ख्वास्तें आई है।
- (ग) पुरानी योजना के अन्तर्गत कुल १६६ लोगों को परिमट स्वीकृत किया गया, जिसम से १४३ लारियां व १८ ठेले चल रहे हैं। बाकी लोगों ने गाड़ी नहीं चलाई।

नई योजना के अन्तर्गत अभी परिमट दिया जा रहा है, इसलिये अभी यह बताना कि इस योजना के अन्दर कितने परिमट दिये गये संभव नहीं है।

*१११--श्रो बनारसी दास--सन् १९४८ ई० तथा सन् १९४९ ई० में अब तक कुल कितने नये परिमट दिये गये हैं। कृपया जिलेवार सूची दी जाय।

माननीय पुलिस सचिव-सन् १९४८ ई० तथा १९४९ ई० में अब तक कुल २,५७१ नये परिमट दिये गये। इनकी जिलेबार सूचना नत्थी है।

(देखिए नत्यी 'क' आगे पुष्ठ ३७३ पर)

*११२--श्रा बनारसो द्स--क्या यह सही है कि मेरठ के एक सज्जन को भिन्न-भिन्न नामों से १३ लारियों के परिमद्र मेरठ व बुलन्द शहर जिले में दिये गये है। यदि हा,तो क्यों ?

माननाय पुलिस सिचव—जी नहीं, जेन रल ट्रेडर्स ऐण्ड ट्रान्सपोर्ट कंपनी, मेरठ से संबंधित भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को अवस्य कुल मिला कर १३ परिमट, ९ स्टेज कॅरेज के तथा ४ पब्लिक केरियर के दिये गये हैं। किसी एक व्यक्ति को यह परिमट नहीं दिये गये हैं।

श्रो बनारसी दास--मेरठ के जन रल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के श्रेयर होल्डर्स क्या राज-नीतिक पीड़ित हैं ?

माननीय पुलिस सचिव——जी नहीं, राजनीतिक पीड़ित उस अर्थ में, जिसमें माननीय सदस्य यूछना चाहते हैं, नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो कि राजनीतिक कार्य कर्ता है और उन्होंने कष्ट भी उठाये हैं।

श्री बनारसी टास-जन लोगों को परसिद् स किस आधार पर दिये गये हैं ?

मानवीय पुश्चिस सिच्चय--जब कि रोडवेज की स्कीम चलाने और नेकान इसे का को फैसला हुआ उस वक्त जो लोग कि प्राइवेट आपरेट में थे, उनकी तरफ से बहुत कि काम मार सबे में और ऐसी दिक्कत भी मालूम हुई कि काम का चलाना ही मुक्किल हो जायगा। मेरठ डिवीजन की यह कम्पनी जिन लोगों की है उन्होंने जास तौर से हमारे कामों में बड़ी मुद्द पहुंचायी है। उनकी तरफ से बहुत सी गाड़ियां चलती थीं, इसिलये कुछ समय तक के लिये इस कम्पनी को ये रिमिट्स दिये गये है और वैसे भी जो कि डिस्प्लेस्ड आपरेट में हैं उनको हम प्रायरिटी देते हैं परिमट देने में। इस वास्ते यह कोई नयी बात नहीं की गई है। ऐसे बहुत से लोग उस कम्पनी में शामिल है। इस वास्ते कुछ ज्यादा परिमिटस उनको दिये गये हैं।

श्रा बनारसी दास—क्या गवर्नभेट उन व्यक्तियों के नाम बतलाने की कृपा करेगी, जो कि इस कम्पनी के अन्दर सम्मिलित हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—इस वक्त नाम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मै माननीय सदस्य को बाद में बतला सकता हूं।

बुलन्दराहर जिला प्रदर्शनी का प्रबन्ध ग्रार उस पर खर्चा

*११३—-श्रो बना सी दास——(क)क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बुलन्द— शहर में कोई जिला प्रदर्शिनी कथेटी हैं ? इस कमेटी का क्या विधान है ?

- (ख) क्या जिलाधीश महोदय उसके प्रधान है?
- (ग) ऐसी जिला प्रदर्शनियों से सरकार का क्या सम्बन्ध है?

माननीय स्वशासन सचिव—(क) जी हां, इस कमेटी में पैट्रन, प्रेसीडेट वाइस प्रेसीडेंट जनरल सेकेंटरी, ज्वाइन्ट सेकेंटरी आडीटर और सदस्य होते हैं। साधारण सदस्यता की फीस ५० ६० हैं तथा विशेष सदस्यता की ५०० ६० और २०० ६० देने पर कोई भी पैट्रन बन सकता है। चन्दा देने वाली सभी सार्वजनिक संस्थाओं को प्रति संस्था एक सदस्य और हर म्युनिसिपल व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को प्रति वार्ड दो सदस्य जनरल कमेटी के लिये नामजद करने का अधिकार है। कमेटी के जनरल सेकेंटरी, ज्वाइन्ट सेकेंट्री और आडीटर प्रति वर्ष जनरल कमेटी द्वारा चुने जाते हैं तथा प्रदर्शनी का प्रबन्ध पदाधिकारियों के अतिरिक्त जनरल कमेटी द्वारा नियुक्त १५ सदस्यों की एक कार्यकारिणी सिमिति द्वारा होता है।

- (ख) जी हां, जिला मैजिस्ट्रेट पद की हैसियत से जनरल कमेटी के प्रधान है।
- (ग) कोई सीधा सम्बन्ध नहीं हैं। परन्तु प्रतिवर्ष सरकार ग्रान्ट देती है। सरकार की तरफ से उसी प्रदर्शनी में एक घोड़ो की नुमाइश की जाती है और पब्लिक वर्क्स, पशु-पालन और कृषि-विभाग इसमें सहयोग देते है।

श्रो बनारसी दास-क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है ?

माननीय स्वशासन सिचिय—इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी वही है, जो अन्य प्रदर्शनियों का हुआ करता है। जो वहां पर बड़ी—बड़ी चीजे होती है उनको जनता में दिखाया जाता ह और उनको इन सब चीजों का ज्ञान कराया जाता है।

श्री बनारसी दास--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि यह प्रदर्शनी वास्तव म एक रईस और सरकारी अफसरों के मनोरंजन का एक साधन है?

माननीय स्वशासन सचिव-इस प्रकार की कोई खबर सरकार को नहीं है।

श्री बनारसी दास--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि यह प्रदर्शनियां बिटिश सरकार की भोर से अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिये ही कायम की गई थीं और इस समय केवल यह रूपये का दुरुपयोग हैं?

माननीय स्वद्यासम सिचिव—किटिश सरकार के जमाने में कोई भी इसका हेतु रहा हो, हैं किन आनरेबिल मेम्बर यह जानते हैं कि इस सरकार का भी वही उद्देश्य हो सकता है कि जनता में प्रचार करके उसका ज्ञान बढ़ावें और उससे जानकारी करावें।

श्री चनारसी दास--क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि जिला बोर्ड बुलन्दशहर ने इस किस्म का एक प्रस्ताव पास किया है कि जिला के उद्योग-वंबों की तरक्की के लिये इस प्रदर्शनी का तमाम प्रबन्ध जिला बोर्ड को दे दिया जाय? माननीय स्वशासन सचिव--इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास नहीं ह। श्राबनार नी दास--क्या गवर्नमेंट इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि इन जिले की प्रदर्शनियों का तुमाम प्रबन्ध जिला बोर्ड को दे दिया जाय?

माननीय स्वशासन सचिय--जी हां, एक इस प्रकार का आम प्रस्ताव मेरे पास

आया है और उस पर विचार हो रहा है।

*११४--श्री बनारसी दास-क्या सरकार को मालूम है कि इस जिला प्रदर्शनी का सारा प्रबन्ध और संगठन जिलाधीश के मातहत प्रायः सरकारी कर्मचारी ही करते हैं?

माननीय स्वशासन सचिव—जैता कहा जा चुका है वास्तविक प्रबन्ध जनरल कमेटी द्वारा निर्वाचित १५ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति करती है। प्रदर्शनी की भिन्न-भिन्न शालाओं के प्रबन्ध के लिये अलग-अलग उप-समितियां बनाई जाती है, जिनम मुख्यरूप से ग्रैर-सरकारी सदस्य होते है। अलबत्ता अभी तक यह प्रथा रही है कि जनरल सेकेटरी कोई डिप्टो कलेक्टर होता है और एक ज्वाइन्ट सेकेटरी तहसीलदार होता है।

*११५—श्री बनारमीटाम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ ई० में जिला प्रदर्शनी में कुल कितना रुपया व्यय हुआ ? इसमें चन्दे से कितना रुपया प्राप्त

हुआ ?

माननीय स्वशासन सचिव—सन् १९४९ ई० की प्रदर्शनी पर अब तक ३४,४९९ र० १ आ० ५ पा० खर्च हुआ है, जिसमें सदस्यता की फीस से १०,१०७ रू० प्राप्त हुआ था।

*११६--श्री बनारसि द म--(क)क्या सरकार को मालूम है कि सारा चन्दा प्रायः सरकारी नौकरों ने वसल किया ?

(ख) यह चत्दा सरकारी कर्मचारियों ने किस अधिकार से वसूल किया?

माननीय स्वदासिन सिविव—(क) जी हां, स्वेच्छा से विये गये इन चन्दों को सिर्फ जिला के माल विभाग के कर्मचारियों ने वसूल किया था।

(ख) सरकार ने इसकी अनुमति दे दी थी।

श्री बनारसी दास—क्या गवनंमेंट को मालूम है कि जिसको स्वेच्छा से चन्दा वसूल करना कहा जाता है उसके लिये जनता को आम असन्तोष है कि प्रदर्शनियों का चन्दा वसुल करने में सरकारी अधिकारी जबरदस्ती करते हैं?

माननीय स्वशासन सचिव-इस प्रकार की शिकायत कम से कम मेरे पास तो नहीं आई है। लेकिन में यह समझता हूँ कि शायद वहां हो। किन्तु वहां पर लोगों को इतनी गहरी

कोई तकलीफ नहीं है, जिसकी शिकायत सरकार के पास भेज सकें।

मंगलवार, १० जनवरी सन १९५० ई० के

ताराङ्कित प्रश्न

पीलीभीत में सेशन्स के मुकदमों की सुनवाई तथा असेसरों की उपस्थिति

*१--श्री मुकुन्द लार्ल अप्रवाल-क्या यह सत्य है कि सेशन्स के मुक़दमों में गवाहों
असेसरों, अभियुक्तों और जामिनों पर सम्मनों की तामील जिलाधीश द्वारा हुआ करती है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण सिंह)-जी हां।

*२--श्री मृकुन्द्रत्नाता ग्रथ्रव (ल-क्या यह सत्य है कि प्रत्येक सेशन्स के मुक़दमे के लिए ८ असेसर बुलाये जाते हैं; और कम से कम ३ के आ जाने पर मुक़दमे की सुनवाई हो सकती है ?

श्री चर्या सिंह—प्रत्येक सेझन्स के मुक़दमें के लिये कम से कम ३ परन्तु यदि सम्भव हो सके तो ४ असेसरों की आवश्यकता होती है और इसलिये इस संख्या के बुगने असेसर प्रायः बुलाये जाते है।

*३-- श्री मुकुन्द लाल ग्रयवाल--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पीलीभीत में १ जनवरी सन् १९४८ ई० से--

- (क) सेशन्स के कितने मुकदमे इस कारण से स्थगित किये गये कि उनके गवाह, अभियुक्त या असेसर तामील न होने के कारण नही आये?
- (ख) सेशन्स के कितने मुकदमे असेसरों के पर्याप्त संख्या में उपस्थित न होने के कारण विलम्ब से आरम्भ हुए जब कि अनुपस्थित असेसरों के स्थान में शहर से नये असेसर तुरन्त तलब करके असेसरों की कमी सेशन्स जज साहब ने पूरी की ?

श्री चरण सिंह— (क) पीलीभीत में १ जनवरी सन् १९४८ ई० से गवाहों के न आने के कारण ८ सेशन्स के मुकदमे, अभियुक्तों के न आने के कारण १ और असेसरों के न आने के कारण ४ मुकदमें स्थिगत किये गये।

(ख) असेसरों के न आने से ७ सेशन्स के मुकदमो म शहर के दूसरे असेसरों को खलाना पड़ा, जिसमें देर हुई।

"४--श्री मुक्, इद लाल ग्रयवाल--क्या यह सत्य है कि जिन तिथियों पर सेशन्स के मुक़दमे लगे होते हैं, उन पर प्रायः और कोई काम नहीं लगाया जाता है ?

श्री चरण मिह—जी हां।

*५--श्री मुकुन्द लाळ ग्रग्नवाल-क्या सरकार कृपा करके पीलीभीत सेशन्स न्याया-लय के सम्बन्ध में १ जनवरी सन् १९४८ ई० से गवाहो, अभियुक्तो या असेसरो की अनुप-स्थिति के कारण स्थिगित किये गये मुकदमों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना देगी:--

(क) संख्या सेशन्स मुकदमा ?

(ेख) नाम अभियुक्ते?

(ग) संख्या धारा व नाम कानून, जिसके अन्तर्गत मुकदमा चला हो ?

घ) सेशन्स न्यायालय की तिथि या तिथिया?

(ड) तिथि या तिथियां, जिसके लिए मुक्रदमा स्थगित हुआ ?

(च) कारण, जिससे स्थगित हुआ ?

(छ) अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे ?

(ज) सरकारी रुपये की हानि, जो मुकदमें में स्थागित होने से हुई--

(१) जज के वेतन में?

(२) गवाहों और असेसरो के मार्ग-व्यय और भोजन में ?

(३) बकील सरकार की फीस में ?

श्रा चरण सिंह-- प्रावश्यक सूचना मेज पर रक्ली है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७५ पर)

#६--भ्रो मुकु द लाल त्राप्रवाल--क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मुक़दमे केवल इस लिए स्थागित करने पड़े कि गवाहों और असेसरों पर सम्मनों की तामील में लापरवाही की गयी ?

श्रो चरण सिह—जी हां, सम्मन तामील करने में लापरवाही के लिये कुछ सम्मन तामील करने वालों को उपयुक्त सजा दी गई है तथा कुछ के सम्बन्ध में जाच हो रही है।

*७—भ्रो मुकुन्द छ ल ग्रग्रवाळ—क्या यह सत्य है कि सेशन्स जज साहब और सर-कारी वकील ने कई बार जिलाबीश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, किन्तु फिर भी इसका प्रबन्ध नहीं किया गया ?

श्री चरण सिह—पह सत्य है कि सरकारी वकील और सेशन्स जज ने जिलाधीश का क्यान इस ओर आकृष्ट किया और अब असेसरों और गवाहों के सम्मनों की तामील में काफी देख—भाल व सख्ती से काम लिय जाता है और दशा काफी सुधर गई है।

*८--भ्रो मुकुन्द लाल ग्रग्रवाल--क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना है कि जिससे गवाहों और असेसरों आदि पर सम्मनों की तामील न होने पर मुक़दमों के स्थिगत होने से जो सरकार का व्यय व्यर्थ नष्ट होता ह न हुआ करे?

श्रो च ए सिह-- इस समय सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी योजना नहीं है, परन्तु

वह इस विषय पर विचार करेगी।

पी॰ सी॰ एस॰ में परिगणित जा तिवालों के लिए जगहों को व्यवस्था

*९--श्रो द्वारिका प्रसाद मौर्य--(क) क्या पी० सी० एस० में शेंड्यूल क्लास वालों के लिए कुछ जगहें रिजर्व थीं ? यदि हां, तो कितनी ?

(स) कुल कितने शिड्यूल क्लास वाले (पिछलो) परीक्षा में बैठे ? कितने लिये गये ? श्रो गोविन्द सहाय--(क) जो हां। परिगणित जाति के उम्मीदवारों के लिये पांच जगहें सुरक्षित (रिजर्व) रखी गयी थीं।

(ख) परिगणित जाति के २८ उम्मीदवार परीक्षा में बठे ओर उनमें से दो उम्मीदवार डाक्टरी परीक्षा में पास होने को शर्त पर नियुक्ति के लिये मंजूर किये गये थे।

*१०--श्रो द्वारिक। प्रसाद मौर्य --क्या पी० सो० एस० के चुनाव में रिजर्वेशन का कुछ लिहाज किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रो गोविन्द सहाय-जो हां। इस प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य-क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ५ जगह रिजर्व थीं और २८ उम्मेदवार बठ थे, उनमें से ५ सबसे अच्छ उम्मोदवार क्यों नहीं चुन लिए गए ?

माननोय प्रचान सिचित्र—पिंडलक सर्विस कमीशन ने २८ उम्मीदवारों में से इम्तहान का नतीजा और मिनिमम क्वालिफिकेशन देखकर एक नाम भेजा था, मैंने कहा कि कम से कम दो होने चाहिए, इस तरह से दूसरे को बाद में हमने शामिल कराया।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य-न्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो बिकया ३ जगहें रिजर्व से पूरी न हो सकीं वह किनको और किस लिहाज से दो गईं।

माननीय प्रयान मचिव--उस लिस्ट में जो लोग आर्डर आफ मरिट से मुस्तहक थे, उन्हीं को दी गईं।

जनाने ग्रह्पतालों को सरकारी सहायता

*११--श्रा राजाङ्गा ग्रामाल--[स्थगित किया गया।]

यदालतो' तथा सरकारो दक्तरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग का समाव

*१२—श्रा राधाकुष्ण ग्रग्नवाल—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि प्रान्त के विभिन्न जिलों में किस—किस विभाग में राजकीय लिखा—पढ़ी देवनागरी लिपि में नहीं होती और किस—किस अदालत में अब भी उर्दू भाषा में काम होता ह।

श्री गोविन्द महाय—प्रान्त के विभिन्न जिलों में सभी दफ्तरों और अदालतों में राजकीय काम में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरी तौर पर ऐसा होने में समय लगेगा। अदालतों में भी उद्दे भाषा के बदले हिन्दी का प्रयोग बढ़ रहा है।

श्रो राधाकुष्ण ग्रग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि जिलों के विभागों में जो लिखा—पढ़ी प्रान्तीय सरकार से होती है वह अब भी अंग्रेजी भाषा में होती है और नागरी का व्यवहार नहीं किया जाता ?

श्री गोविन्द सहाय--जहां तक सरकार की पालिसी का सम्बन्ध है, इस बात का आदेश विया गया ह कि जहां तक भी हिन्दी को प्रोत्साहन विया जा सके, दिया जाना चाहिए। *१३—-श्री राधाकृष्ण अग्रवाल—क्या यह सही है कि लखनऊ के सरकारी दफ्तरों और अदालतों में अब भी अधिकांश कार्य फ़ारसी लिपि में होता है और देवनागरी लिपि का व्यवहार बहुत कम किया जाता है ? क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सरकारी विज्ञप्ति की अवहेलना करने वाले राज कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्रो गोविन्द सहाय--जी नहीं। अधिकतर सरकारी कर्मचारियों ने हिन्दी सीख ली ह और सबको आदेश दे दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी हिन्दी भाषा सीख लें?

चालानी मुकद्मों का सबूत न मिलने के कारण स्थगित किया जाना

*१४— श्रो राधाकृष्ण ग्रग्रवाल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विभिन्न जिलों में सन् १९४९ ई० में कितने चालानी मुकदमे पुलिस की तरफ से सबूत मौजूद नहीं होने के कारण दो बार से अधिक स्थिगत करना पड़े?

माननीय पुलिस सचिव--सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है। (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२० पर)

हरदोई जिले में, १९४८-४६ ई० में चोरी, इकेती ग्रीर कत्ल की घटनाये

*१५--श्रो राधाकृषण ग्रग्रवाल-क्या सरकार यह बतलायेगी कि हरदोई जिले के विभिन्न थानों में १ मई सन् १९४८ ई० से ३१ मई सन् १९४९ ई० तक चोरी, डकैती और क़रल की कितनी दुर्घटनाएं हुई ?

माननीय पुःलस सचिव——१ मई सन् १९४८ ई० से ३१ मार्च सन् १९४९ ई० तक हरदोई जिले के विभिन्न थानों में १,४६४ घटनायें चोरी, ३० घटनायें डकैती और ४९ घटनायें क्रत्ल की हुईं।

*१६--श्री राघ छुष्ण अग्रवाल--[स्थगित किया गया।]

मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में विजली की सण्लाई

*१७—-श्री राधाकृष्ण ग्रयवाल—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में सन् १९४८ ई० में किन—किन लोगों को, कितनी—कितनी और किस—किस काम के लिए बिजली दो गयी?

श्री छताफत हुसैन—एक नक्तशा, जिसमेंमांगी गई सूचना वी है, मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

कमिश्नरों के कार्यालयां के हेड मिस्टेंटों के बारे में प्रश्न

*१८—श्रो निहालुद्दीन (श्रनुपिस्थत)—क्या यह सब है कि कुछ किमइनरों के कार्या लयों के हेड असिस्टेंट उसी कार्यालय में चार वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे हेड असिस्टेंटों के नाम, डिवीजन का नाम, जिसमें वह काम कर रहे हैं और समय जब से वह लगातार उस डिवीजन में काम कर रहे हैं, बताने की कृपा करेगी ?

माननोय माल सचिव—पह सच है कि कुछ किमश्नरों के कार्यालयों के हेड असिस्टॅट उसी कार्यालय में चार वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे थे। उनका विवरण नीचे विया हुआ है:—

> १--श्री एम० एच० सिंह, रहेलखंड डिवीजन--१ नवम्बर, १९४२ ई०। २--श्री सूरज प्रसाद सिन्हा, इलाहाबाद डिबीजन--१४ जून, १९४५ ई०।

*१९-- श्री निहालुद्दीन (ग्रनुगिस्थित)--क्या यह सच है कि आम तरीके पर एक हेड असिस्टेट एक डिवीजन में चार वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया वह विक्षेष वजह बतायेगी, जिससे इन हेड असिस्टेटों को एक ही कार्यालय में चार साल से अधिक रखा गया ?

माननीय माल सिचिव——जी हां, श्री एम० एच० सिंह का बरेली में ही रखना इस कारण उचित समझा गया कि वहां के किमश्नर की जगह तोड़ दी गई श्री और वहां एक अनुभवी हेड असिस्टेट का रखना आवश्यक था। श्री एम० एच० सिंह का तबादला अब दूसरे डिवीजन में कर दिया गया है और वह २७ सितम्बर से दें। नहींने की छुट्टी पर चले गये हैं।

श्री सूरज प्रसाद सिन्हा, सितम्बर सन् १९४९ ई० में अवकाश ग्रहण करने वाले थे, अतएव उनके तबादले का प्रश्न नहीं उठाया गया। अब उन्होंने अवकाश ग्रहण र लिया है।

*२०--श्री निहालुद्दीन (अनुपिथत)--नया यह सच है कि इन हेड असिस्टेटों मं से गत तीन वर्ष के अन्दर किसी-किसी के तबादले का आदेश हुआ था? यदि हां, तो हर एक के लिए कितनी बार यह आदेश हुआ था और उसका क्या नतीजा हुआ?

माननीय माल सिचव--जी हाँ, श्री एम० एच० सिंह के तबादले का आदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू द्वारा दो बार हुआ, किन्तु दोनों बार बाद में रह कर दिया गया।

*२१—श्री निहालुद्दान (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह इन हेड असिस्टेंडों के तबादला करने का इरादा रखती है या नहीं?

माननीय माल सचिव--यह प्रक्त अब नहीं उठता।

संयुक्त प्रांतीय स्कूछों के शिक्षकों के वैतन का कम

⁴२२—श्री राम शरण—क्या सरकार कृपा कर केयह बतलायेंगी कि उसने पे कमेटी के हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल (आधुनिक जूनियर हाई स्कूल) के अध्यापकों के वेतन के स्केल सम्बन्धी निर्णय को मान लिया है ?

माननीय शिक्षा मचिव के सभा मंत्री (श्रो महफू जुर्हमान) -- जी हां, जहां तक मिडिल स्कूलों का सम्बन्ध है, लोकल वाडीज द्वारा व्यवस्थित स्कूलों के अध्यापकों के लिये कमेटी द्वारा व्यवस्थित वेतन-क्रम में सरकार ने कुछ संशोधन किया था।

श्री रामदार ग्य—क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि प्रदन संख्या २२ में जो संशोधन का जिक्र किया गया है, वह क्या है?

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णीनन्द)—इस वक्त में ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन जिस वक्त पे—कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर असेम्बली में बहस हुई थी उस वक्त मैने बतला दिया था कि वह सब बात उसमें की गई है।

*२३--श्री रामशरण--क्या यह ठीक है कि पे-कमेटी ने ट्रेंड अन्डर ग्रेजुएट "सी॰ टी॰" के लिए बेतन का स्केल ७५--५--१२०--८--२०० ६० रक्खा है।

श्री महफूजुर हमान--जी हां।

*२४—श्री रामदार ग्रा—क्या यह ठीक है कि संचालक, शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक २४ फरवरी, १९४९ ई० की पत्र संख्या जी० एल० नं० एच०—५६/३०——२०(३०), द्वारा ए० टी० सी० अंग्रेजी शिक्षकों का बेतन पे—कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ४५——२—५५— प्र० अ०——२—७५ र० देने का आदेश दिया है?

श्रो महफू जुर्रहमान--जी हां।

*२५--श्री रामशरण--क्या यह ठीक है कि पे-कमेटी की रिपोर्ट में जो अन्ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट शिक्षकों के वेतन का स्केल दिया गया है वही शिक्षा विभाग ने ए० टी० सी० के लिए देना स्वीकार किया है?

श्री महफूजुर्रहमान--अन्ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट शिक्षकों के लिये पे-कमेटी के रिपोर्ट में कोई वेतन नहीं दिया है।

श्री रामश्राण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू॰ पी॰ पे-कमेटी ने मिडिल स्कूलों के उन अध्यापकों के लिये, जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं और ट्रेन्ड नहीं हैं, ४५-२-५५ ६० वेतन की दर नियत की है ?

माननीय शिक्षा सचिव--मैं इस वक्त ठीक नहीं कह सकता। रिपोर्ट इस वक्त मेरें सामने नहीं है।

*२६--श्रो रामशरख--क्या यह ठीक हैं कि सरकार के आदेशानुसार सरकार से सहा-यता पाने वाले विद्यालयों में भी सी० टी० पास अर्थात् ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट अध्यापकों को भी ७५-५-११०-६-१४०-७-१७५ रु० के स्केल से मासिक वेतन दिया जाता है ?

श्री महफू जुरंहमान-जी हां।

*२७—-श्री रामशरण--क्या यह ठीक है कि गवर्नमेट हाई स्कूल में ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट को मासिक वेतन पे-कमेटी के निर्णय के अनुसार ७५-५-१२०-८-२००२० के ग्रेड से दिया जाता है ?

श्री मध्कुजुर्रहमान-जी हां।

*२८--श्री गम्ञरण--यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलायेगी कि गवर्नभेट हाई स्कूल के ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट अध्यापकों तथा उन सी० टी० अध्यापकों के ग्रेड में, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं इतना अन्तर अभी तक क्यों है ?

श्री महफूजुरंहमान--उनके काम सर्वथा एक से नहीं है।

*२९—श्री रामश्ररण—क्या यह ठीक है कि पूरे सूबे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीनस्थ ज्नियर हाई स्कूलों में सी० टी० (ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट) शिक्षकों की संख्या केवल ५२ है ?

श्री महफूज़रेंहमान-जी हां।

*३०--श्री रामशरण-क्या यह ठीक है कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपने यहां के जूनियर हाई स्कूल्स के सी० टी० पास अंग्रेजी शिक्षकों को ए० टी० सी० पास शिक्षकों के वंतन से, जो पे-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अन्ट्रेन्ड टीचर्स के वेतन के बराबर है, अधिक देना स्वीकार नहीं किया है?

श्री महफूजुर्रहमान-अभी हाल में सरकार ने अंग्रेजी अध्यापकों के लिये ४५-२-६५ कौ० वा०-३-८० का ग्रेड स्वीकार किया है और यह मुरादाबाद सहित समस्त बोडों में लागू है।

श्री रामदाग्या—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापकों में जो ट्रेंड है और जो ट्रेंड नहीं है उनके वेतन के दर में कुछ अन्तर किया गया है?

माननीय शिक्षा सचिव--में समझता हैं फर्क़ जरूर होगा, लेकिन इस सवाल से तो यह बात पैवा नहीं होती। प्रश्न ३० में तो आपने कोई दूसरा ही सवाल पृद्धा था।

श्री रामश्राण—क्या गवर्नमेंट को यह मालूम है कि २० साल से पहिले उन ट्रेंड अध्या-पकों को ५० रुपये मासिक प्राथमिक वेतन दिया गया था ?

माननीय शिक्षा सचिव-बीस साल पहले क्या हुआ था, मुझे ठीक नहीं मालूम।

श्री रामशरण-नया ४५-२-६५ रु० की वेतन दर जो नियत की गई है वह ट्रेड अध्यापकों के लिये भी लागू है?

माननीय जिक्षा सचिव--मेरा ख्याल है कि यह दर ट्रेंड के लिये ही लागू है।

*३१--श्री रामशरण--क्या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों के सी० टी० पास अंग्रेजी अध्यापकों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्रार्थना की है कि वह उनको पे-कमेटी के निर्णयानुसार सी० टी० (ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट) के स्केल के अनुसार वेतन दे ?

श्री महफूजुरंहमान-जी हां।

*३२--श्री रामशरण--वया सरकार यह बतायगी कि ए० टी० सी० शिक्षकों की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त होने पर क्या ग्रेड दिया जायगा?

श्री महफू जुर्रहमान-- कृपया प्रश्न ३० के उत्तर को देखिये।

*३३--श्रा रामशरण--क्या सरकार इन ट्रेन्ड अन्डर गेजुयेट (सी० टी०) शिक्षकों के वेतन के विषय में अपना स्पष्ट निर्णय सूचित करेगी ?

श्री मह्फूजुरंहमान--ऋष्या प्रश्न नं० २० के उत्तर को देखिये। भांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा विजली का उत्पादन तथा वितरण

*३४--श्रीं कुछ जिंबारी छाल शिवानी--तारील १६ जुलाई सन् १९४६ ई० तक झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्रतिदिन कितनी बिजली उत्पन्न करती थी? इसमें से कितने युनिट बिजली प्रतिदिन खर्च होती थी तथा किनने यूनिट बिजली रिजर्व में रखी जाती थी?

श्री छताफ । हुसैन--माननीय सदस्य के सवाल से यह ठीक-ठीक जाहिर नहीं होता कि वे दरअसल क्या जानना चाहते हैं। बिजली रिजर्व में नहीं रखी जाती और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी ने जब से बिजली देना शुरू किया है तब से १६ जुलाई,१९४६ ई० तक वह कितनी बिजली हर रोज पैदा करती थी और कितनी हर रोज खर्च करती थी इसकी सूवना इकट्ठी करने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह उससे हासिल होने वाले फाउदे के मुकाबिले में कहीं ज्यादा होगा। हां, यह बताया जा सकता है कि १६ जुलाई, १९४६ ई० को २,२५२ कीलोवाट पावर्स बिजली पैदा हुई थी और २,११२ कीलोवाट पावर्स खर्च हुई थी।

*३५--श्री कृष्णविहारी लाल शिवानी-- तारीख १५ जून सन् १९४९ ई० तक झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी प्रतिदिन फितनी बिजली उत्पन्न करती थी? उसमें से प्रतिदिन कितनी बिजली खर्व होती थी तथा कितनी रिजर्व में रखी जाती थी?

श्री छताफत हुसैन—इस सवाल का जवाब भी सवाल नं० ३४ के जवाब से मिल जाता है। १५ जून सन् १९४९ ई० को ४,२२८ किलोवाट पावर्स बिजली पैदा हुई थी और ३,६९७ किलोवाट पावर्स खर्च हुई थी।

*३६-- श्री कुन्जिवहारी लाल शिवानी-क्या यह सच है कि झांसी बिजली सप्लाई कम्पनी ने अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिये एक और नया इंजन लगाया है ? यह नया इंजन कब लगा है और उससे कितनी बिजली उत्पन्न होती है ?

श्रो लताकत हुसैन--जी हां, यह इंजन मई, १६४९ ई० में लगाया गया था और इस इंजन की बिजली पैदा करन की शक्ति ३५० किलोबाट है।

*३७--श्रो कुञ्जबिहारी शिवानी--क्या बिजली प्राप्त करने के लिये वी हुई दरख्वास्तों पर नम्बर सिलक्षिलेव।र दिये जाते हैं ? यदि नहीं तो दरख्वास्तों पर नम्बर देने के क्या नियम हैं और उनकी लिखा-पढ़ी कहां तक की जाती है ?

श्री लता कत हुसैन—जी हां बिजली प्राप्त करने के लिये दी हुई दरख्वास्तों पर नम्बर सिलसिलेवार दिये जाते हैं। श्री कुञ्जिबिहारी छाछ शिवानी—क्या यह सत्य है कि झांसी बिजली कम्पनी के खिलाफ बहुत सी दर्खास्तें आनरेबिल मिनिस्टर साहब के पास आईं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)—जो दरख्वास्ते जरूर आई।

श्री कु न जिंबहारी लाल शिवानी—क्या माननीय मंत्री महोदय ने अपने पार्लियामेंटरी सेकेटरी की उनकी जांच के लिये झांसी भेजा था ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--जो, यह भी सही है।

श्री कुन्जबिहारी लाल शिवानी--उस जांच का क्या नतीजा निकला?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सिचित्र--नोटिस की जरूरत है। इस वक्त मुझको कुछ याद नहीं है।

श्री कुञ्जिविहारी लाल शिवानी—क्या पालियामेंटरी सेकेटरी की रिपोर्ट सरकार प्रकाशित करने के लिये तैयार हैं ?

माननीय सार्व प्रनिक निर्माण सिचिय--उसको पब्लिश करने की तो कोई जरूरत नहीं मालूम होती है। हां, आनरेबिल मेम्बर को मैं दिखला सकता हूँ।

श्री कुन्जबिहारी लाल शिवानी—क्या जो दरस्वास्ते बिजली कम्पनी में दी जाती हैं उनका इन्दराज सिलसिलेवार किसी रिजस्टर में होता है ?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--इस बात का जवाब तो जी जवाबात पहे गये हैं, उनमें मौजूद हैं।

श्रो कुञ्जबिहारी लाल शिवानी — क्या सरकारको इन्मीनान है कि जो दरक्वास्तें जिस सिल्सिले में आती हैं उनको उसी सिल्सिले से बिजली के कनेकान दिये जाते हैं ?

माननीय सार्वज्ञनिक निर्माण सचिव——इल तो यही है। कभी-कभी अगर ऐसी शिकायतें आई तो उनके बारे में जांच की गई और जैसा मुनासिब समझा गया किया गया।

दिवियापुर-बेळा रोड, इटावा का प्रकी करना

*३८--श्रो दीनद्यालु अत्रस्थी (अनुपस्थित)--क्या सरकार को मालून है कि विविधापुर-वेला रोड, इटावा को पक्की कराने के लिये सन् १९४६ ई० में साढ़े पांच लाख रुग्ये का अनुमान (इस्टिमेट) स्वीकृत हुआ था?

माननीय साव जिनक निर्माण सिचव--एक इस्टिमेंट ६.५८ लाख रुपये का सन् १९४७ ई० में मंजूर किया गया था। सन् १९४६ ई० में कीई इस्टिमेट मंजूर नहीं हुआ था।

*३९—श्रो दीनद्यालु ग्रव त्यी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि चीफ इंजीनियर ने जो काम के रेट सूबे भर के लिये मंजूर किये हैं, वही रेट दिबियापुर—बेला रोड परक्यों नहीं लागू किये गये?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--वीक इंजीनियर ने जो रेट सूबा भर के लिये मंजूर किया था वही रेट दिबियापुर-बेला सड़क के लिये भी लागू था।

*४०--श्रो दोनद्यालु ग्रवस्थी (अनुपस्थित) -- श्र्या सरकार अनुभव करती है कि कम दरें (रेट्स) होने के कारण इस सड़क का फाम रुका पड़ा है ?

*४१—यदि हां, तो सरकार इस सड़क का काम चालू करने के लिये क्या उपाय सोच रही है?

माननीय सार्वजिनिक निर्माण सचिव--ये सवाल पैदा नहीं होते।

पंचायत निरीक्षकों के पदीं पर नियुक्तियां

*४२--श्रो मुकुन्द लाल ग्रमवाल--क्या यह सच है कि अभी कुछ समय हुआ सरकार ने पंचायत निरोक्षकों के पदों के लिये नियुक्तिया की है? यदि हां, तो कब और कितनी ऐसी नियक्तियां की हं?

माननीय स्वजासन सचिव--जी हां।

६ जून, १९४९ ई० को ४६२ । १६ जलाई, १९४९ ई० को २१ ।

२ अगस्त, १९४९ ई० की २२।

२३ अगस्त, १९४९ ई० को २।

५ सितम्बर, १९४९ ई० को १२।

इनमें से ११ पंचायत निरीक्षकों ने त्यागपत्र देदिया है तथा ७ ने कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया है। एक पंचायत निरीक्षक की मृत्यु हो गई है।

*४३--श्री मुकृत्ट लाल ग्रप्रव।ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि :--

(क) पंचायत निरीक्षकों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये थे ?

(ल) पंचायत निरीक्षकों की न्यूनतम योग्यताये क्या रखी गई थी?

(ग) उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाक।क्षियो के थे ?

- (प्र) सरकार ने उपरोक्त पदाकांक्षियों में से कितनों को पंचायत निरीक्षक नियुक्त किया ?
 - (ङ) स्वीकृत पदाकांक्षियों में कितने समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त थे ^१
- (च) जो पदाकांक्षी समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त युवकों के अतिरिक्त छांट में आये हैं, उनकी शिक्षा की एवं अन्य योग्यताये क्या है ?
- (छ) क्या समाज—सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों में से कुछ को या सब को सरकारकी ओर से कुछ ओर शिक्षायें भी (उदाहरणार्थ एरिया राशनिंग आफिसर के पद के लिये) दी गयी थीं ? यदि हां, तो वह शिक्षायें क्या थीं, और कितने दिनों की थी और किस-किस को दी गई थीं और कहां-कहां दी गयी थीं और सरकार का उसमें कितना व्यय हुआ ?

माननीय स्वशासन सचिव--

(क) (ख) इस सम्बन्ध में सरकारी विज्ञापन तथा आदेश संलग्न है, जिनमें योग्यताओं का स्पष्टीकरण किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पुष्ठ ३२६ पर)

- (ग) ४२१।
- (घ) १५९।
- (इ.) पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी सूची "अ" तथा "ब" में समाज—सेवा शिक्षा प्राप्त २०५ व्यक्तियों को पंचायत निरीक्षक पद पर नियुक्त करने के लिये स्वीकृति दी है।
- (च) प्रत्येक को योग्यता देना प्रश्नोत्तर में असम्भव तथा इसमें समय का सदुपयीग नहीं होगा।
 - (छ) सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन पोलीटिकल सकरमें ओर सेनाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों तथा अन्य के लिये सरकार ने कोई अनुपात निश्चित किया था?

माननीय स्वशासन सचिव-समाज सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों औरपोली-टिकल सफरर्स के लिये अनुपात निश्चित किया था।

श्री द्वारिक। प्रसाद मोर्य-सरकार से मैं यह उत्तर जानना चाहता हूं कि क्या हिस्जिनों के लिये भी कोई अनुपात निश्चित किया गया था?

मानर्नाय स्वशासन सचित्र--इसमे हरिजनों के लिये साधारण हरिजनों के बारे में जो अनुपात का विचार है वह और जो बाकी बच रहे हैं उनमे विचार किया गया है।

*४४--श्री मकुन्दलाल ग्रम्याल--क्या यह तय है कि पंचायत निरीक्षको के अब भी कुछ पद रिक्त है ? यदि हां, तो कितने ?

मानर्गाय स्वशासन सचिव--५ सितम्बर, १९४९ ई० को कोई रथान पंचायत

*४५--श्रो मुरुन्द ाल ग्रय्याल--क्या सरकार यह कृपा , रके बतायेगी कि उपरोक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब ओर किस प्रकार से करने का विचार रखती है ?

मःनर्नाय स्वाशासन सचिव--प्रश्न नही उठता।

*४६—-अ। सुकुन्द ल।ल प्रयवाल—-क्या यह सर्च है कि सरकार का इरादा अब शेष रिक्त स्थानों की पूर्ति केवल समाज—सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों में से ही करने का है? यदि नहीं, तो क्यो नहीं?

माननाय स्वशासन सचिव--प्रश्न ही नही उठता।

*४७--श्रा मकुन्द्लाल ग्रंथवाठ--क्या सरकार कृषा करके बतायेगी कि पंचायत निरीक्षकों के चुनाव करने की समिति के कौन कौन सदस्य थे ?

माननीय स्वशा पन सिच्य-शो भगवत नारायण जो भागंव सचालक, पचायत राज तथा श्री प्रकाश नारायण माथुर, सचालक सीशल सिवत चुनाव सिन्ति के सदस्य थे। समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों के चुनाव के पश्चात् श्री भागंव जी के अस्वस्थ्य हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री चरण सिंह जी सभा सिवव, चुनाव सिमिति के सदस्य हुरे। राजनीतिक पीड़ित तथा साधारण श्रेणी के पदाधिकारियों का चुनाव इन लोगों ने किया था।

*४८--श्री मृकुन्दलाल ग्रग्रवाल--क्या सरकार ने इस समिति के चुनाव के सम्बन्ध में कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उनमें यह भी आदेश था कि समाज-सेवा शिक्षा प्राप्त पदाकांक्षियों को चुनाव में प्राथमिकता दी जावे ? यदि हां, तो क्या इस आदेश का पालन किया गया ?

माननीय रवशासन सचिव- जी हां।

जी नही।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तराई भावर गवर्नमेंट इस्टेट का सुधार

*४९--श्रा श्रोचन्द सिंघल (३ तुपस्थित)-- क्या यह सच है कि सरकार तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट के सुधारार्थ ६ लाख रुपया सालाना ग्रान्ट देती हैं ? प्या सरकार अब तक कियं गये सुधार का विवरण देगी ?

माननीय स्वशासन सिचिव—सरकार ५ लाख रुपया सालाना ग्रान्ट तराई (क) भाबर व गढ़वाल भाबर स्टेटों के सुघारों के लिये देती है, इस गांट का अधिक भाग तराई भाबर स्टेट के लिये ही दिया गया है।

(ख) तराई भावर इस्टेट में किये गये सुधारों का संक्षिप्त विवरण एक अलग व्योरे में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'चं आगे पृष्ठ ३८९ पर)

तराई भावर गवर्नमेंट इस्टेट के किसानों का माफा की लकड़ी गौर सीमेंट की चाटरे दिया जाना

*५०—आ श्राचिन्द् निघल (श्रानुप्रिथत)—क्या सरकार यतारेगी कि तराई भावर गवर्नमेट इस्टेट के किसानों को काश्तकारी के लिये जो साही की रहाड़ी जगलात में दी जाती है वह उनको गत २ वर्ष से सरकार। श्रेड्यून के मृताविष्य पुरी दी गई ह या हम? अगर कम, तो क्या कमी किसी और रूप में पूरी की गई या नहीं?

माननीय क्वशासन सच्चिय-- गत हो वर्ष में तराई भावर बा बिलाग से गवर्नमेंट स्टेट्स के किसाना को सरकारो शेड्यूल के मृताबिक काश्तकारों के लिये पूरी-पूरी लकडी दी गई ह।

*५१—-श्रा श्राचन्द्र मिछ ॥—-(१ नुप्रियत) क्या यह सच है कि २ पर्ष से अपर हुए तराई भावर गवर्नमेट की ओर से काइतकारों ो आधी कीमत पर गोनेट की चादरें देने के लिए काइतकारों से इन्डेन्ट लिए गए थे? यदि हां तो किन्नी चादर काइतकारों ने इन्डेन्ट की ओर उममें से कितनी चादर अभी तक प्रकेमकान बनाने के निमित्त काइतकारों की दी गई ?

माननाय स्वशायन सचिव--जी हां।

क इतकारों ने ३४७० चादरें इन्डेन्ट की थीं परन्तु रेल धारातात की किताइशों के कारण अभी तक कोई भी चादर इन लोगों को नहीं दी जा सकी।

फनेहपुर जिले के शाखा याम में ६ ग्रादमियों से १६०० रु० वसूल करने का मामला

#५२─-श्री वंदा गोपाल--क्या सरकार को मालूम है कि फतेहपुर जिले के शाखाग्राम में ६ आदिमयों से लगभग १,६०० ६० का अनाज तहसीलदार फतेहपुर ने इस कारण वसूल करित्या कि अनाज देने के रिजिस्टरमें उनके नाम और निशान अंगूठा फरजी दज थे?

माननीय कृषि मिचिष (श्री निमार ऋहमद होग्यानी)—जी हां, विदित है। डिस्ट्रिक्ट एप्रीकत्चर अफसर फतेहपुर की प्रार्थना पर तहसीलदार फतेहपुर ६ कृषकों से १६०० ६०१२आ० की बीज की वसूली की जो उन कृषकों के नाम रिजस्टर में दर्ज था निशान अंग्ठा फरजी होने की बात बाद को जात हुई। कृषकों की दरख्वास्तों के बावजूर भी बीज की वसूली तहसीलदार द्वारा कराई गई क्योंकि यदि किसानों की शिकायतें निराधार सिद्ध होतीं तो फिर बीज वसूली का कोई दूसरा इलाज न रह जाता।

श्री वंशगे पाल-जब काश्तकारों ने दरख्वास्त दी तो रूपया वसूल करने के पहले क्यों तहकीकात नहीं कर ली गयी ?

माननीय कृषि सचिव —-रिपोर्ट यह थी कि जिन काश्तकारों ने दरख्वास्त दी हैं उनके पास जो कुछ भी था वह उसको अलग कर रहे थे और ख्याल यह था कि जब वह उसे अलग कर देंगे तो वसूली की कोई तरकीब नहीं रहेगी।

श्राव शो।पाल-जवाब में यह कहा गया है कि तहकीकात जारी है। क्या यह बात सही नहीं है कि तहकीकात खत्म हो गई है और चार्ज शोट आ गयी है।

माननीय क्रिष मिचिव—जो शस्स सुपरवाइजर था उसके खिलाफ मुकद्दमा चल रहा है।

श्री वंशगोपाल—तहकीकात खत्म होने के बाद साबित होने पर क्या मुकद्मा चल रहा है ?

माननीय कृषि सचिव--मामला अदालत में हैं इसके मुताल्लिक यह कहना कि सहकोकात जो हो चुकी है वह सही है या गलत यह अदालत के फैसले के बाद पता चलेगा।

५३-- प्रा बंशगे। पाल--क्या ऊपर लिखे भामले हे पुलिए ओर जिला प्रधिकारियों ने नहकीकात की ओर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि उन अः काश्नकारों के नाम ६ निशान अंगूठा फरजी दर्ज थे ? क्या सरकार तहकीकात के ननो प्रशी एक नकल भेज पर रखने की कृपा करेगी ?

माननीय कृषि मिचिय--उपरोक्त विषय में जिला अभिजात तथा पुलिस जांच कर रहे ह। पुलिस ने श्री देवकली प्रसाद सुपरवाइजर, कृषि विभाग पर लाजीय दंउ विधान संग्रह की धारा ४०९, ४६६ के अनुसार अभियोग लगाया है तथा जाज अभी जारी है।

*५४--र्थ्या पंश्योगपाल-प्या उन काश्तकारों ने इस मामले मे सरकार की कोई कानूनी नोटिस है दी ?

माननीय कृषि सचिव--जी हां, कृषकों ने तिविल प्रोसिड्योर कोड की घारा ८० फे अन्तर्गत नोटिस दी है।

"५५--र्थ्या वंशगे।पाल--सरकार इस मामले मे क्या करना चाहती है ?

माननीय कृषि सचित्र--कृषकों की नोटिस पर जिले के सरकारी वकील की सम्मित से सरकार ने निश्चय किया है तथा कलेड्ट फतेहपुर को आदेश दे दिया है कि फिगर प्रिंट ब्युरो (Finger Print Bureau) की रिपोर्ट के अनुसार जिन कृषकों का निशान अंगूठा रिजस्टर में दर्ज निशान अंगूठा से मेल नहीं खाता उनका रुपया वापस कर दिया जाय किन्तु रुपता वापस करने से पहले श्री देवकली प्रसाद, कृषि सुपरवाइजर के विरुद्ध लगाये गये फौजदारी अभियोग के फैसले की प्रतीक्षा कर ली जाय।

श्रा बंशगोपाल-पह कहा गया है कि उको हिदायत दी गई है जिनका निशानी अंगूठा नहीं मिलता है, क्या सरकार को पना नहीं है कि गवर्नर ने यह आदेश दे दिया है कि जिनके निशानी अंगूठा नहीं मिलने ह उनको भी रुपया वाणिस दे दिया जाये।

माननीय कृषि मिचव—सबाल संख्या ५५ के जवाब में यह बता दिया गया है कि जिन लोगों के मुतालिलक फिंगर प्रिन्ट ब्रूरो से जवाब आ गया है कि उनके निशानी अंगठा नहीं मिलने उनके लिये डिस्ट्रिन्ट मैजिन्ट्रेट को हुक्म दे दिया गया है कि उनको रूपया वापिस दे दिया जाये।

फतेहपुर जिले में गल्ले की वसूली

*५६--श्री बंदागे। पाल--क्या यह ठीक है कि सन् १९४६ ई० में फतेहपुर जिले में कम अनाज वसूल होने के कारण सन् १९४७ ई० में तहकीकात की गई और उसके फलस्वरूप फतेहपुर जिला गेहूं के लिये डेकिसिट एरिया पाया गया और फतेहपुर जिले में सन् १९४७ ई० में अनाज नहीं वसूल किया गया?

म ननीय त्राच्च सिचव (श्री चद्रभान गुप्त)—(क) १९४७ ई० में कोई ऐसी तहकीकात फतेहपुर जिले में नहीं की गई (ख) और नयह जिला अनाज की कमी वाला (डेफिसिट) क्षेत्र पाया गया। इसके वियरीत इसमें अनाज बचता है।

र्था वंदागे।पाल--सन् १९४६ ई० में कोई तहकीकात नहीं की गई तो फिर सन् १९४७ ई० में डाइरेक्ट प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं किया गया ।

माननीय ग्रम्न सिचिय--फतेहपुर जिला हमारे प्रान्त के उन जिलों में है जहां कोर्स ग्रन्स अधिकांश मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इसिलये सन् १९४६ ई० में तथा सन् १९४९ ई० म जब सरकार को कोर्स ग्रेन्स भी इकठ्ठा करने की आवश्यकता हुई तो वहां पर डाइरेक्ट प्रोक्योरमेंट स्कीम भी जारी की गयी। सन् १९४७ ई० में कोर्स ग्रेन्स की आवश्यकता नहीं थी, इसिलये वहां डाइरेक्ट प्रोक्योरमेंट की स्कीम जारी नहीं की गयी।

श्री वंशगीपाल—क्या सरकार को स बात कापता नहीं है कि फतेहपुर में कोर्स ग्रेन्स अधिकतर बांदा और रायबरेली से आते हैं?

माननीय ग्रन्न सचिव—मेरे पास जो इत्तिला है वह यही है कि वहां जौ और चना अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। इसीलिये वह जिला इन चीजों के लिये सरप्लस समझा जाता है।

श्री वंशगोपाल—तो क्या सरकार ने सन् १९४९ ई० में फिर कोई तहकीकात करने की आवश्यकता नहीं समझी कि यह डेफिसिट एरिया है या नहीं ?

मानर्न,य ग्रन्न सचिव—इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी चूंकि सरकार के पास इत्तिला थी कि वहां कोर्स ग्रेन्स अधिकांश मात्रा मे पेदा होते है।

*५७—श्चां बंदागोपाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कोई तहकीकात की गई है कि जिसके फलस्वरूप फतेहपुर का जिला सन् १९४९ ई० में स्थानीय आपस्यकता से अधिक पैदा करने वाला क्षेत्र (सरप्लस एरिया) हो गया है? यदि हा, तो तहकीकात किसने की और उसका क्या नतीजा निकला? यदि नहीं तो सन् १९४९ ई० में गल्ल। वसूली की आज्ञा क्यों दी गई?

माननोय ग्रन्न सचिव--(क) ऐसी कोई तहकीकात १९४९ ई० मे नही की गई।

(ख) यह प्रक्त उठता ही नहीं।

(ग) १९४९ ई० में अनाज वमूल किया गया था क्योंकि फतेहपुर बचत वाला (सरप्लस) जिला माना जाता है।

गरला वस्तुलो के सिलसि हे में फते हपुर जिले में गिरफ्ता रियां

*५८--श्रा बंशगोपाल--(क)गल्ला वसूली के सिलसिले में फनेहपुर जिले में कुल कितने आदमी गिरफ्तार हुये ?

(ख) कितने आदिमियों को सजा हुई, कितने जेल भेजे गये और बाद को जमानत

पर छूटे ?

माननीय ग्रन्न सचिव--(क) १२२ आहमी गिरपतार किये गये थे।

(ख) सब मिलाकर ४८ व्यक्ति फिर हवालात भेजे गये। इनमें से ३३ व्यक्ति जमानत देने पर छोड़ दिये गये। सिर्फ १५ व्यक्तियों को सजा हुई। किसी की भी कैंद की सजा बहाल नहीं रक्खी गई।

*५९—श्री बंशगोपाल—क्या यह ठीक है कि खागा तहसील जिला फतेहपुर मे एक ऐसा आदमी गिरफ्तार किया गया जिसका ल का एक दिन पहले मर चुका था? क्या यह भी ठीक है कि वह गल्ला दे रहा था किर भी उसकी हथकड़ी डालकर थाने के लिये भेज दिया गया?

माननीय ग्रन्न सिचिव—यह बात ठोक नहीं है। श्री जगदेव प्रसाद पांडेय के लड़के की मृत्यु हैजे से एक दूसरी जगह पर हुई जबकि वह बारात में गया हुआ था ओर उसकी मृत्यु का पता जिला अधिकारियों और उसके पिता को तभी चला जब वे जमानत पर छूटे।

(ख) यह बात ठीक नहीं है।

*६०—श्री बंदागपाल—क्या यह बात ठीक है कि गिरफ्तार किये हुमे आदमी हथकड़ी डालकर १०-१०,१५-१५ मील तक पैदल लाए गये और उनकी खाना—पानी कुछ नहीं दिया गया?

मानोनीय ग्रम सचिय-पह बात ठीक नहीं है।

खजुहा तहसील जिला फतेहपुर में सरकारी गरला वस्ली की कीमत ग्रीर वाजार भाव के फर्क का वस्ल किया जाना

*६१--श्रा वंशगोपाल-क्या सरकार को मालूम है कि खजुहा तहसील, जिला करोहपूर में ऐसे सैकड़ों आदमी है जिनसे सरकारी गल्ला बसूली की कीमत और बाजार भाव गल्ले की कीमत का फर्क ले लिया गया? अगर हा, तो ऐमा क्यो किया गया? वया सरकार की इसमें अनुमति थी?

माननीय सन्न सन्तिव--(क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नही है। यदि ऐसी कोई बात हुई भी हो तो उसका पता अधिकारियों को नहीं था।

(ख) यह प्रदन उठता ही नही ।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नही ।

प्रांत में गल्जा वसूनी के सिल्लिमले में गिरफ्तारियां तथा दण्ड का बगरा

4६२—श्री वंशगापाल—सूबे में अनाज वसूली के सिलसिले में प्रत्येक जिले में कितने कितने आदिमियों के खिलाफ वारन्ट निकले, कितने जेल भेजें गये और कितनों को सजा हुई?

मान ीय ग्रन्न मचिव-एक नकशा माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गप्रा है। (देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३९१ पर)

श्रा वंशगोपाल-क्या सरकार को इस तरह की गिरफ्तारिया जो प्रान्त भर में हुई, उससे सतोष हैं ?

माननीय ग्रन्न सिचय—सरकार तो यह नहीं चाहती कि किसी काम में गिरफ्तारिया की, जाय। लेकिन जब लोग सरकार की योजनाओं से असहयोग करते हैं तो मजबूरी हालत में कानून की रक्षा के लिये ओर योजना को सफल बनाने के लिये लोगों को विवशतः जल भेजना पडता है।

श्रावशायाल -- क्या आइन्दा फिर प्रोक्योरमेट करने का ओर वही नीति बरतने का सरकार का इरादा है ?

माननीय ग्रन्न सचिव—यह मसला विचाराधीन है। माननीय सदम्य से भी इस बात की राय ली जायगी कि हम आइन्दा साल प्रोक्योरमेट करें या न करे।

म्युनिसिनल व ब सोरो, जिला पटा में मेसे, पड्वा ग्रादि जिवा करने की मनाही

५६३ - श्रा निहालुई। (श्रनुपस्थित) -- क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड सोरों, जिला एटा ने कोई उपनियम (बाईला) बाबत मजबा बनाये है कि जिससे सोरो म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर भैसे, भैस, पड़वा के जिवह करने की मुमानियत की गयी है?

मौननीय स्वशासन सचिव-- जी हां।

*६४--श्रा-निहालुनीन(ग्रनुपिश्वत)--अगर हां, तो कब ओर क्या सरकार उसकी एक नकल मेज पर पर रखेगी?

माननीय स्वशासन सचिव—यह प्रतिबन्ध बोर्ड द्वारा १५ अगस्त, १९४७ मे लागू किया गया था।

बोर्ड के उपनियम की एक नकल प्रेषित है-

Copy of the relevant byelaw--

No horned cattle such as cows, bullocks, he-buffilees, she-buffalces and other young ones shall be slaughtered in any slaughter house.

सम्बद्ध उपनियम की प्रतिलिपि निम्न है :--

("कोई सीग वाला मवेशी जैसे गाय, बैल, भैसा, भैस और अन्य बच्चे बघस्थानो में बध न किय जायेंगे।")

तहसीलदारों को एक जिले में रखने की प्रविध

*६५-श्री मुहम्मद ग्रमगार ग्रहमद--(क)क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह कायदा है कि एक तहसीलदार एक जिले में ५ साल से अधिक नही रक्खा जाता है ? (ख) यदि हां, तो क्या इस कायदा पर अमल हो रहा है?

माननीय माल सिचव—(क) ऐसा कोई कायदा नहीं है, पर सन् १९३५ की एक राजाज्ञा के अनुसार कोई भी तहसीलदार किसी एक तहसील में साधारणतः पांच साल से अधिक नहीं रह सकता।

इस सरकारी आदेश पर पूरा अमल हो रहा है।

(ख) यह सवाल नहीं उठता।

*६६-७५--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--[स्थगित किये गये]

कुमायूं डिवोजन में रेगुलर पुलिस के थाने। में थानेदारों का निजी अथवा सरकारी व्यय पर क़ानूनी पुस्तकें यादि रवना

*७६—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार बतायेगी कि कुमायूं डिवीजन में रेगुलर पुलिस के थानों में कौन—कौन सी कानूनी पुस्तकें, नियम, उपनियम, गजट या समाचार-पत्र सरकारी व्यय पर दिये जाते हैं और कौन—कौन थानेदार को निजी व्यय पर रखना पड़ता है ?

माननीय पुलिस सचिय-- कुमायूं डिवीजन के पुलिस के थानों में निम्नलिखित प्रकाशन सरकारी व्यय पर दिये जाते हैं:--

१--इंडियन पीनल कोड।

२-- िकमिनल प्रोसीड्योर कोड।

३--पुलिस रेगुलेशन्स।

४--आम्सं रूल्स, आडिनेंस इत्यादि।

५-पुलिस गजट।

६--क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स गजट।

कोई समाचार-पत्र सरकारी व्यय पर नहीं दिया जाता। थानेदारों को जिला पुलिस के पुस्तकालयों से भी पुस्तकें दी जाती है। किसी थानेदार को निजी व्यय पर कोई पुस्तक नहीं रखनी पड़ती।

*७७-१०३--श्रो यज्ञनारायण उपाध्याय-[स्थगित किये गये।]

गढ़वाल जिले में यात्रा लाइन पर काम करने वाले सरकारी सैनिटरी इन्स्पेक्टरी तथा मेहतरा का वेतन

*१०४--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९४५, १९४६, १९४७ और १९४८ ई० में तथा जून सन् १९४९ ई० तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गढ़वाल जिले में कुल कितना रुपया यात्रा लाइन में खर्च हुआ है ?

माननीय ग्रन्न सचिव--यात्रा लाइन में व्यय का व्योरा निम्नांकित तालिका में दिया हुआ है--

सन् १९४५–४६ १९४६–४७ १९४७–४८ अप्रेल से जून, १९४९

रुपया ९३,६९८ १,२६,३३६ १,४६,४६० ५१,१७६

*१०५ — आ) यज्ञनारायण उपाध्याय — क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि गढ़वाल जिले में कितने सरकारी सनिटरी इन्सपेक्टर रहते हैं। तथा इनमें से कितने यात्रा लाइन में रहते हैं। तथा उनमें से प्रत्येक को कितना बेतन तथा भन्ना मिलता है?

माननाय अन्न सिव्य--गढ़वाल जिले में सेनिटरी इसपेक्टो की संख्या सात है। यदी-नाथ तीर्थ ११त्र के पमय सातों इस्पोक्टर गत्र - जार्ग पर नियुक्त कर दिये जाते है। उनका वेतन--,म ७५--५--१२० है। इसके अलाया उन्हें ३० ६० नियत भना नथा १५ - बतोर स्तिपूर्ति भने के मिलता है। वे साधारण महााई भी पाते है।

-१०६--८'ा यज्ञा ायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा कर तल रेग कि यात्रा लाइन के हर लेनिटरी इन्स्पेक्टर के सहायतार्थ अन्य कितने और कोन से कर्मचारी रहते हु ओर उनमें ने प्रत्येक को क्या मासिक वेतन व भता आदि व्यय दिया जाता है?

माननीय ग्रन्न सचिव--ए एक रोनिटरी इंस्पेक्टर को दवाइया, कीटाणु नाइक द्रव्य तथा निजी स्पन्नात दोने दे जिन्ने दो पुर्ली पिलते ए। इन कुलियों को केवल स्थानीय दर से वेतन मिलता है।

'१०७—-श्रो यज्ञन राया उपाध्याय—-रा भरकार कृपा कर बतलायेगी कि गढवाल यात्रा लाइन में बाहर से आये हुये मेहतरों को सन् १९४५-४६,४७-४८ ई० में फिन दर से मासिक वेतन तथा भत्ता दिया गया था?

माननीय प्रन्न सिचिय—पन् १९४५-४६ तथा ४७ ई० में मेहतरों को ३५ ६० प्रतिमास वेतन गिलता था। इसके अलाया उन्हें ८ ६० वतोर भन्ते के पहली बार अपनी नौकरी पर जाने के लिये मिलता था। जन सन् १९४९ से उन्हें ४५ ६० प्रतिमास वेतन तथा नजीबाबाद से नियुक्त स्थान पर पहुँचाने का यथार्थ रेल तथा मोटर का भाडा भी मिलता है।

पिक्छे चार वर्षों में बद्रोनाय तथा केदारनाथ में ग्राटा तथा चावछ का भाव

*१०८--श्रो यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि गढ़वाल जिले में बद्रीनाथतथा केदारनाथ में पिछले ४ वर्षों में प्रत्येक वर्ष किस भाव से आटा-चावल बिका तथा वर्तमान समय में किस दर से बिकता है।

माननीय माल सचिव--

१६४५ १६४६ १९४७ १९४८ वर्तमान भाव

नोट--अपर लिखें हुए भाव प्रतिमन के हिसाब से है ।

चमोली तहसील के क्लकों की महंगाई बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र

*१०९—श्री तज्ञनारायण उगाव्याय—क्यायह सच है कि सन् १९४६ ई० में जिला— घीदा, गढ़वाल ने चमोली तहसील के क्लकों की महंगाई बढ़ाने के लिये प्रार्थना—पत्र सरकार की सेवा में भेजा था? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया? माननीय माल सिचव—यह सब है कि सन् १९४६ में जिलाधीश, गढ़वाल ने बमोली तहसील के कर्म बारियों के महंगाई के भन्ने की बृद्धि के लिये सरकार से प्रार्थना की थी, परन्तु १—४—४७ से नवीन वेतन—प्रणाली के लागू हो जाने के कारण तथा महंगाई के भन्ने में बिद्धि हो जाने के कारण सरकार गे जिलाधीश के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्या नया वेतन और भत्ता जो बढ़ा है, वह जिलाधीश की तिफारिश के बराबर आता है?

माननीय माल सचिव-नोटिस की जरूरत है।

कुम यूं डिवीजन भंनयावाद प्रोसीडिंग का काम

*११०—-श्रो यज्ञनारायण उप्ध्याय—क्या सरकार कृषा करके यतलायेगी कि कुमायूं डिवीजन में न गथाद प्रोसी उंग का काम जो लड़ाई के समय में यन्य था अब चालू हो गया है ?

माननीय माल सचिव--जी हां।

कुमायूं दिशोजन के परवारियों व उतरता ग्रशीनों के। मानिक वेतन तथा भत्ता
"१११--श्री यज्ञतारायण उगध्याय--न्या मह सही है कि हाकिम इड़ाक़ा की अहालत में ज्ञतीत को दरख्यास्त के लिए प्रार्थी को अमीत कीस के नाम से कुछ एवगा जना करना
पड़ता है? यदि हां, तो कितना?

माननोय म/ल सिच्य — जो हां, यि अमोनों के कार्य – क्षेत्र हेड क्वार्टर से १५ मील के भीतर हैं तो प्रार्थी को १॥ ६० प्रतिदिन के हिसाब से अमोन फीस जमा करनी पड़तो हैं।

*११२—श्री यज्ञ नार।यण उगाध्याय—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि कुनायूं डिबोजन के प्रत्ये के जिल्ले की तहतीलों में कितने पडवारी व उजरती अमीन हैं और उन्हें क्या क्या मासिक वेतन उजरत तथा भत्ता मिलता है ?

माननाय मान सिचय--मूर्जी (१) संलग्न है। ६०--४--८० द० रो० ४--१०० रु० के बेतन स्केल में अमोनों को पातिक बेतन मिलता है साथ ही महंगाई का मता भी मिलता है। इसके अतिरिक्त साहे ५ रु० मासिक कुली भत्ता मिलता है। उजरती अमीनों को काम करने पर १।। रु० प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पुष्ठ ३८३ पर)

ं *११३—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि कुमायूं किम्हनरी में कुल कितनी डिप्टी कलेक्टर्स की अदालतें हैं तथा प्रत्येक अदालत में कीन—कौन उजरती अमीन हैं ?

माननीय माल सचिव-- हमायूं डिवीजन में डिग्टी कलेक्टरों की १० अदालतें हैं, इन अदालतों में काम करने वाले उजरती अमीनों के नाम सूची में २ में दिये हुए हैं।

जमीदारी उन्मूलन ऐक्ट का कुमाय किमरनरी में लागू होना

*११४--श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय--क्या जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट कुमायूं कमि-इनरी पर भी लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माननीय माल सचिव--यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है। बद्रांनाय-केंदारनाथ के यात्रियों की सुविधायें

*११५--श्री यज्ञ नारायग उपाध्याय--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि बद्री-नाथ-केदारनाथ की यात्रा के लिए पिछले दस वर्ष में किस-किस प्रान्त के कितने यात्री गये हैं ? माननीय शिक्षा सिचिय--श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ के दर्शन के लिये पिछले दम वर्षों में हिन्दुस्तान के सब ही प्रान्तों के यात्री आये, परन्तु यह गणना नहीं की गई कि किस प्रान्त के कितने यात्री आये।

- ''११६—श्री यज्ञ नारायण उपाध्यार—(क) क्या सरकार का ओर से उक्त यात्रियों को गणना के लिये कोई प्रवन्ध हैं?
- (ख) पिछले दस वर्ध से बद्रोनाथ-केदारनाथ की पात्रा में कितने पात्री मरेह ओर उनके दाह संस्कार के लिए सरकार की ओर से दया प्रबन्ध किया गया?

माननीय शिद्या सचिव--(क) नही।

- (ख) गणना का कोई प्रबन्ध न होने के कारण यह नहीं कहा जा राकना कि नत दम वर्षों में फितने यात्री भरे। श्री बढ़ीनाय पुरी से कमेटी की ओर के भया सामित स्वयसेवको द्वारा मृतक यात्रियों का दाह अंस्कार धामिक प्रथा से किया जाता है और गत दो वर्षों से यात्रा लाइन पर भी कमेटी द्वारा नि हुन्त स्वयसेवको द्वारा मृतक वात्रियों का दाह रांस्कार होता है, जो लावारिस यात्री गर जाते है उनका एहं ।स्कार सरकारी खर्च पर होता है।
- *११७-- भ्रो यज्ञ ारायण उपाध्याय-वना अन्य प्रान्ता की तरवार भी उन प्रान्तों के यात्रियों की वहीनाथ-केदारनाथ यात्रा में सुविधा के लिये कुछ प्रदाध करती है ? यदि हा, तो क्या ?

माननीय शिक्षा सचिव--नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नही उठता।

- *११८--श्री यज्ञ नार।यण उपाध्याय--(क) त्या भरकार कृपा कर पाठावेगी कि बंद्रीनाथ-केदारनाथ के यात्रा मार्ग पे उपने वाजियों की सुविधा के तिए किता भवन, किन-किन स्थानों पर बनायें हैं?
- (ख) इनको बनाने के लिये न्पया किस फंड के लगाया जाता है और কী বল भाल कौन करता है ?

माननीय शिक्षा सचिव--(क) बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कोई सरकारी भवन नहीं ह ।

(ख) प्रक्त नहीं उठता।

ै ११९—श्री यज्ञनारायण उपाध्याय—क्या सरकार कृषा कर जतलायेगी कि केदारनाथ—प्रद्रीताथ यात्रा लाइन में कुली, डटी, फंडी, घोड़े, प्रोझा, गाइड आदि की मजदूरी के सम्बन्ध में तरकार की ओर से नियंत्रण के लिये क्या व्यवस्था है ?

माननीय शिक्षा सिचिव—सरकार की ओर से केंदारनाथ—पद्गीनाथ यात्रा लाइन में कुली, डंडी, कंडी, घोड़ा, बोझ, गाइड आदि की मजदूरी के नियंत्रण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

*१२०—श्री यज्ञ नारायण उपिध्याय—क्या सरकार कृपा करके वतलायेगी कि पिछले तीन वर्षों में केदारनाथ—बद्बीनाथ यात्रा के यात्रियों को कुली, डंडी, घोड़े, बोझा, गाइड दैनिक मजदूरी पर मिलते रहे हैं ?

माननाय शिक्षा सचिव—पिछले कुछवर्षों से केदारनाथ-बद्रीनाथ यात्रा मे यात्रियों को कुली, डंडी, कंडी, घोड़ा, बोझा, गाइड आदि दैनिक मजदूरी पर मिलते तो है पर कुछ कठिनाई से।

*१२१—श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय—क्या यह सब है कि केदारनाथ—बद्रीनाथ यात्रा में जाने वाले यात्रियो ने अपनी असुविधाओं के विषय मे कोई प्रार्थना—पत्र सरकार के पान भेजे हैं ? यदि हां, तो कब और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की हैं ? माननीय शिक्षा सिच्चिय-सरकार के पान बढ़ीनाथ यात्रा मार्ग के विष्य से अक्सर प्रार्थना-पत्र आने रहते हु। ऐसी शिकायती को दूर फरने के लिये जो कुछ भी उत्तित तथा सम्भय होता है वह किया जाता है।

१२२—-श्री यज्ञ नारामण उपाध्याय—क्या सरकार कृषा महि बताये है कि नेदार-नाथ—बद्रीनाय यात्रा को सुरिधाजनम ननाने के लिये परकार ता हुन। व्यवस्थ पर कोई योजना बनायी है ?

माननीय शिक्षा सिवय-- रिशर ने अभी कोई ऐसी योजना नही बनाई है।
सन् १९४६ - का सयुक्त प्रातीय जूट का बनी वन्तु ने के नियम्बर्ण का प्रार्थिन स

माननीय प्रन्त सचिव--प सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जूट की बनी वरतुओं के नियत्रण के प्राटिनेस (पन् १९४९ ई० की सख्या ९) की प्रतिलियि मेज पर रखता हूँ।

सन् १९३९ ई० का संयुत्रत प्रान्तोय कार्ट कोस [छूट (रेमाञ्चन)] आडिनेन्स माननीय माल मचिव--मै सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फीस [छूट (रेमोञन)]आडिनेस सन् १९४९ ई० की सख्या २२ की प्रतिलिपि मज पर रखता है।

सन् १६४६ ई० का यूनाइटेड प्र विसेज इन्टरमिडियेट ऐज़केशन (ग्रमेडमेंट) आर्डिनेन्स

माननीय शिक्षा सिचव--मैं सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविसेज इटरमिडियेट एजूकेशन (अमेडमेट) आडिनेस (सन् १९४९ ई० की सख्या ७) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

यार्कालाजिकल म्युजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिको समिति के लिये एक मदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय शिक्षा सिचिव—में प्रस्ताव करता हूँ कि आर्कालाजिकल स्युजियम, मथुरा की प्रवन्थकारिणी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दे, किया जाय।

पान्तीय म्युजियम छखनऊ की प्रवन्धकारिखी समिति के लिये एक सदस्य के निर्माचन का प्रम्ताव

माननीय शिक्षा सचिव—में प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय म्युजियम, लखनऊ, की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

संयुक्त पान्तीय म्युजियम एडवाइजरी बोडं में काम करने के लिये दो सदस्यें। के निर्वोचन का प्रस्ताव

माननं।य शिक्षा सिव्य — में प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय म्युजियम, एडवाइ— जरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर—इन तीनों प्रस्तावों पर, मेरा अनुमान है, किसी को कुछ कहना नहीं है। (कुछ ठहर कर) क्या मैं यह मान ल् कि भवन को ये स्वीकार है? (तीनो प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रक्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल ३२९

कृषि तथा पशु-पालन स्थायो समिति में स्वर्गीय श्री बलभइ सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सटस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय माल सिट्व—में प्रस्ताव करता हूँ कि स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान पर, कृषि तथा पशु—पालन स्थायी समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्थोकर आदेश दें, किया जाय ।

माननीय स्पीकर—प्रश्न यह है कि स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान पर, कृषि तथा पश्—पालन स्थायी समिति में काम करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय ।

(प्रक्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

यूनाइटेड प्राविसेज नर्सेन ऐएड मिडवाइन्ज कैंसिल में काम करने के लिये दी सदस्यों के निर्दाटन का प्रताव

माननीय ग्रन्न सचिद्य—में प्रस्ताव करता हूँ कि यूनाइटेड प्राविसेज नर्सेज, मिडवा— इन्ज ऐंड हेल्थ विजिटर्स रिजस्ट्रेशन ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की घारा ४(१)(ब)(२) के अनुसार यूनाइटेड प्राविसेज नर्सेज ऐंड मिडवाइन्ज कौसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों का तीन वर्ष के लिये निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पीकर—अब प्रश्न का रूप यह है कि यूनाइटेड प्राविसेक नर्सेक, मिडवाइक्क एँड हेल्थ विजिटर्स रिजस्ट्रेशन ऐक्ट, सन् १९४७ ई० की धारा ४ (१) (ब) (२) के अनुसार यूनाइटेड प्राविसेक नर्सेक ऐंड मिडिवाइक्क कौंसिल में काम करने के लिये हो सदस्यों का तीन वर्ष के लिये निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश हैं, किया जाय।

(प्रक्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बुनोलबन्ड यायुर्वेदिक कालेज भांसी की प्रदन्यकारियो समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

माननीय इन्न सचिव—में प्रस्ताव करता हूं कि श्री शिवराम वैद्य द्वारा रिक्त हुए स्थान पर बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में काम करने के लिए एक सदस्य का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

माननीय स्पोकर—प्रश्न यह है कि श्री शिवराम वैद्य द्वारा रिक्त हुए स्थान पर बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में काम करने के लिए एक सदस्य का तीन वर्ष के लिए निर्वाचन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) माननीय स्पोक्तर—जितने प्रस्ताव अभी आपने स्वीकार किए हैं उनके संबंध में मैं अपना निश्चय आपको पीछे बताऊंगा।

(इस समय श्री नफ़ीसुल हसन, डिप्टी स्पीकर, ने १२ बज कर १० मिनट पर सभापति

का आसन ग्रहण किया।)

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्राम्तीय जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल *

श्री रोशन जमां खां—जनाब डिप्टी स्पोकर साहब, जमींदारी के मिटाने और जमीन का एक नया इंतजाम करने के बारे में सरकार की तरफ से जो क़ानून पेश किया गया है उस पर तक़रीर करते हुये कल मैंने यह बताया था कि जमींदारी को मिटाने की क्यों जरूरत है और वह

^{*}९ जनवरी, सन् १९५० की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रोशन जमां खां]

किस नुक्ते-निगाह से होना चाहिये। आज मै अपनी तकरीर में, ए द हुकूगत की तरफ से बिल में दिये गये अगराज व मक्रासिद, उद्देवको और कारणों, स्टेटमट आफ आब्जेदटस ऐक्ड रीजंस पढ़ना चाहता हूं।

इपमें हुकूमत की तरफ से इस कानून की लाने के लिये दो यजूहात बताये गये है यानी दो मकसद करार दिये गये हैं।

It is now widely recognised that without a ridical change in the existing land system no co-ordinate | plan of itial reconstruction can be undertaken to ensure agricultural efficiency and increased food production, to raise the standard of living of the itial masses and to give opportunities for the full development of the peasant's personality.

(इस वात को अब तभी स्वीकार करने लगे है कि जय तक वर्तमान भूमि—प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन न किया जाय तब तक ग्राग पुर्नानर्गाण की सहकारी थोजना नहीं की जा सकती जिससे कृषि में सुनार तथा उत्पादन में पृष्टि तथा ग्रामीणी के जीवन स्तर को उप्तत किया जा सके ओर किमानों के व्यक्तित्व के पूर्ण यिकास के लिए अवसर प्रदान किया जाय।) दूसरा मक्तसद यह यताया गया है ——

The landlord-tenant system established by the British for icasons of expediency and administrative convenience, should, with the dawn of political freedom, give place to a new order which restores to the cultivator the rights and the freedom which were his and to the village community the supremacy which it exercised over all the elements of village life."

(जमींदार-किमान प्रणाली जिपको अंग्रेजों ने उपयोगिता तथा शासन सुविधा के कारण स्थापित किया था, उसके स्थान में स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर कोई नवीन ध्यवस्था होनी चाहिए जिससे किसानों को अधिकार ओर स्वातन्त्रय प्राप्त हो, जिन पर उनका जन्म-पिद्ध अधिकार है ओर ग्रामीण जनता को वे अधिकार मिल जायं जिनका प्रयोग वह ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंगो पर करती थी।

देखना यह है कि ये मका तिद कहां तक इस बिल के जरिये से पूरे होते हैं। आज जो हमारी हालत है, आज जो हमारे समाज को सोसाइटी की हालत है उसमें क्या सबमुख इस क़ानून के जरिये से कीई रेडिकल चेज हो रहा है, कोई बड़ी भारों तब्दीली की जा रही है। आज हमारे सुबे में खेती करने वालों की जो हालत है उसके बारे में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एक एकड़ तक खेती करने वालों की तादाद ३७.८ फ़ी तदी खाते हैं और जो आराजी उनकी जोत में हैं वह सिर्फ ६ फ़ीसदी है। एक से तीन एकड़ तक जो खाते है वह २९.६ फी सदी है और इनके कब्जे में १६.८ फ़ीसदी आराजी है। ३ से ६ एकड़ तक जो खाते है वह १८ फ़ी सदी है और उनके-खाते में २२.८ फ़ीसदी आराजी शामिल है। ६ से १२ एकड़ तक जो जोत है वह १०.२ फी सदी है और उनमें २४.८ फ़ीसदी आराजी शामिल है। १२ एकड़ से ज्यादा जो जोत है उनकी तादाद ४.४ फ़ी सदी है और जिनमें २९.६ फ़ी सदी रक़बे शामिल है। इन २९.६ फ़ीसदी रक़ बे में ४११ बड़े-बड़े फार्म्स भी शामिल है। इनके देखने से यह बात साफ हो जाती है कि हमारे सूबे में बसने वाले यानी खेती करने वालों में से ६७.४ फ़ीसवी आबादी ऐसे लोगों की है जिनके कब्जे में सिर्फ २२.८ फ़ीसदी आराजी है। और अगर ३ से ६ एकड़ वालों को भी शामिल कर लिया जाय तो उसकी ताबाद ८५.४ यानी १०० में सिर्फ ८५.४ ऐसे है जिनके कब्बे में ४५.६ फी तदी रक रा है। यह बड़े अफ ती स की बात और यही चीज है जिसमें हुकूमत का इम्तहान है, उसकी सियासत का इम्तहान है। अगर्चे १२ एकड़ से ज्यादा जीतने वालीं की तादाद सिर्फ ४.४ फ़ी सदी है लेकिन उनके क़ब्जे में सबसे ज्यादा रक्तवा है यानी २९.६ फ़ीसदी।

अब उस मक़सद को अगर हासिल करना है जो खुद हुक़ूमत ने इस बिल में बयान किया है तो उसके लिये क्या तरीक़ा हो सकता है जिससे यह न बराबरी जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई है दूर हो सकती है।

हक्तमत की तरफ से कल वजीरेमाल साहब ने अपनी तक़रीर की लेकिन यूझे अफसोस है कि उन्होंने इस नुक्ते निगाह से हुक़ुमत की पालिसी को वाजै तौर पर बयान करने की कोई कोशिश में अपनी तरफ से यह बताना चाहता हूं कि आखिर हमारे पास ऐसे कौन से तरीक़े हैं कि जिससे हम और आप इस न बराबरी को दूर कर सकते हैं उन तरीक़ों में ज्यादातर ऐसे हैं जो हक़मत को करने हैं। हुकूमत के लिये उनको करना जरूरी है लेकिन साथ ही साथ एक जम्हरी मुल्क में जहां पर प्रजा का राज्य हो वहां पर सिर्फ हुकूमत की ही कोशिश जरूरी नहीं है बल्कि हुकुमत को इस बात के लिये भी कोशिश करना जरूरी है कि अवाम में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करें, अवाम में एक ऐसा जोश पैदा हो कि जिसके जरिये से वह खुद ही बहुत साकाम करने को तैयार हो जायं और जो हुकूमत की पालिसी के अग़राज व मकासिद है वह पूरे हो सकें। इसके लिये सब से पहिले तो यह जरूरी है कि जमींदारी को एक सिरे से खत्म किया जाय। अलबत्ता जमींदारों में से जो लोग गरीब है, जिनको जरूरत है और जो खुद इस न बराबरी के शिकार है उनके पुनर्वास के लिये, उनके गुजर के लिये एक ऐसा मुआविजा दिया जाय जिससे वह अपनी गुजर-बसर कर सकें। लेकिन में निहायत साफ तौर पर यह बताना चाहता हूं कि यह गजरबसर और पुनर्वास का अनुदान जो दिया जायगा इस गरज से हरगिज नहीं हो सकता कि वह ज्यादा जमीन हासिल कर सकें, उनको ज्यादा जोत मिल सके और वह ज्यादातर मालदारहो बल्कि इस गरज से होगा कि उससे गरीब आदमी आराम के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकें। एक जम्हरी पार्टी का यह फ़र्ज है कि अपने मुल्क में सब बसने वाले लोगों के लिये गुजर-बसर की फिक्र करे।

दूसरा तरीक़ा जो इस नाबराबरी को दूर करने के लिये जरूरी है वह यह है कि इस बात को हर शक्स ध्यान में रखे, खासतौर से जमींदारी के मिटाने के सिलिसिले में, कि जो आराजी जिस आदमी के क़ब्जे में है वह उसका मालिक हो और उन जोतने वालों में कोई मेदभाव नहीं होगा, कोई जाति—पांत नहीं होगी, कोई बड़ा—छोटा नहीं होगा। बल्कि उनका एक क्लास होगा, उनकी एक जमात होगी और जो तरीक़ा कि इस क़ानून के अन्दर कियागया है कि बहत सी क्लासेज क़ायम की गई हैं, ऐसे नहीं होंगे।

तीसरी बात जो इस न बराबरी को दूर करने के लिये जरूरी है जैसा कि मेंने अभी बतलाया और जैसा कि हमारे सूबे में है जिसके बारे में मेंने अभी आंकड़े इस ऐवान के सामने पेश किये हैं कि जमीन का फिर से बटवारा हो। जब तक जमीन का फिर से बटवारा नहीं होता है तब तक कोई भी मकसद आपका पूरा नहीं होता और वह अगराज व मक़ासिद जो हुक़्मत की तरफ से इस बिल में बयान किये गये हैं वह हरगिज पूरे नहीं होंगे। वह सिर्फ हवाई बातें ही रह जायंगी और उनका कोई असर नहीं होगा। जमीन का बटवारा फिर से हो। इसके लिये इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोई शख्स ऐसा न हो, कोई खेती करने वाला ऐसा न हो कि जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो और कोई खानदान ऐसा न हो जिसके पास १२ १/२ एकड़ से कम जमीन रहे। इसलिये इस न बराबरी को दूर करने के लिये यह बटवारा निहायत जरूरी है और जब तक यह हदबन्दी साफ तौर से नहीं कर दी जायगी तब तक समाज में किसी भी परिवर्तन से कोई कामयाबी नहीं हो सकती है।

चौथी बात जिसकी इस न बराबरी को दूर करने के लिए जरूरत है वह यह है कि गांवों में छोटी २ मशीनों की कारीगरी कायम की जाय और गावों में नौजवानों के लिए स्कूल खोले जायं। कहा जा सकता है कि इस बिल से इसका क्या ताल्लुक है, इसके बारे में मैंने कल भी आप से अर्ज किया था कि इस परिवर्तन को लाने के लिए आप को एक प्लान के मातहत चलना होगा और जाहिर है कि गांव के नए समाज का जो नक्षशा आप बना रहे हैं उसमें इसका जिक्र आ सकता है। जब हम जमीन का फिर से बटवारा करने की बात करते हैं तो ऐसी सूरत पेश आ सकती है कि जो

[श्री रो ान जमां लां]

मोजूदा जमीत है वह हमारे सूबे में बसने घाले खेती जरने पाले कुरुम्बो क लिए का कि तो, फिर बाकी जो सरफल आबादी रह जाती े उत्तके लिए आप क्या करेंगे ? उसे लाय करित और सुस्त बनाकर नहीं बैठा सकते। हम नो उससे भी काम लेना वाहिए। इम अपने मृत्क ओर सूबे की पैदावार को वहाना है। जिनको नए बटवारे में जमीन नहीं भिलेगी उनको हमें छोटे २ कारीगरी के कामो में लगाना है। जापान ने अमरीका ओर जर्मनी के कारधानों का मुकाविला किया और उसने अपने इस मुकाबिले में जो कामयाबी हासिल की यह उराने अपने बड़े २ कारखानों के जिरए से हाणिल नहीं की वित्य उसने अपने मुक्क भर में छोटे २ कारीगरी के कामो को फैलाया और उसने उन्हों के जिरए से जर्मनी ओर अमरोका का तमाम सनअतोहिरफन और कारीगरी में मुकाबिला किया और किसी तरह की दस्तकारी में नह उनसे कम न रहा। इसलिए हमें भी इस चीज को अपने सूबे के लिए ध्यान में रखना जरूरी है ओर नोजवानों के लिए स्कूल रोलकर उनको इस तरह के कारीगरी के कामो में लगाया जाय।

पाचवी बात जो इस नाबराबरी को दूर करने के लिए जरूरी है वह यह है कि गाय वालो को सहयोग ओर कोआपरेशन के जरिए से काम करने की तरगीव दी जाय। यह बहुत अहम चीज है और में समझता हूं कि यह इस वक्त मुल्क के लिए बहुत जरूरी है मगर अफसोस की बात है, हुकूमत की तरफ से अगर इन बातो को मंजूर भी किया जाता है तो महज लफ्ज तो ले लिए जाते हैं लेकिन उसका जो मंशा हाता है ओर जो मतलब होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। एक बात और में कहने वाला हूं और वह यह है कि एक खेतीहर पल्टन खड़ी की जाय जिसके जरिए से गल्ले की पैदावार को बढ़ाया जाय ओर आज जो हमारे स्टिल्ंग बैलेन्सेज है और जो आमदनी हमको बाहर को सामान भेजने से होती है वह डेफिसिट में है और हमको कोशिश करनी चाहिए कि वह सरप्लस में हो जाय। हमारी खेतिहर पल्टन की बात का शुरू २ में मजाक उड़ाया गया, उसके बाद नाम अपनाने की कोशिश की गई ओर फिर कुछ लोगो को कही—कही पर लाकर खेतीहर पल्टन का नाम दे दिया गया। इसके बारे में फिर जब बहस होगी तो अर्ज करूंगा।

छठी बात जिसके जरिए से हम इस नाबराबरी को दूर कर सकते है वह यही थी कि हम खेतीहर पल्टन खड़ी करे।

सातवीं बात यह है कि हुक्मत इस बात के लिए पूरी कोशिश करे कि खेती की पैदावार और कारखानों की पैदावार शहरों की पैदावार और देहातो की पैदावार की कीमतो में पैरिटी बराबरी और समानता क़ायम की जाय।

८ वी बात यह है कि जमीदारी ख़त्म करने के साथ ही साथ लगान घटाकर इतना कर देना है कि वह मालगुजारों के बराबर हो जाय। जो लगान किसान से आजतक जमीदार और ताल्लुक़ेदार साहबान लेते रहे हैं वह जमीदारी मिटाने के साथ ही इतना कम हो जाय जितनी मालगुजारी उस जमीन के बारे में जमींदार साहबान देते रहे हैं, उतना ही लगान किसान से लिया जाय।

९ वीं बात यह है कि खेतिहर मजदूरों का कर्जा माफ किया जाय। उनके मकान के बारे में साफ २ कानून बनाया जाय कि किसी किस्म की बेदखली नहीं हो सकती है। मुझे अफसोस है कि में ज्यादा बक्त ऐवान का लेना नहीं चाहता। इस बारे में वजीर माल साहब ने कुछ बातें कहीं थीं अगर मौक़ा मिला तो में कोशिश करूंगा कि किसी मौक़े पर उनकी इन बातों का जवाब दं। में उनको बताऊंगा कि उनके मौजूदा क़ानून से खेतिहर मजदूरों को फायदा नहीं है। आपने मकानों के बारे में आसानियां और रियायतें देहात में बसने वालों को दी है। हमारा मतालबा इससे आगे है कि साफ साफ क़ानून हो कि अगर खेतिहर मजदूर ने गांव में मकान बना लिया है तो उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता।

एक सदस्य--यह भी होता है।

अहिराज्ञन जमा खां—१० यो बात जो उप न परायरी को दूर करने के लिये उस्ती है वह यह है कि हुकूनत सरकारी आमदनी का एक मुनास्यि हिरान कात नगर गोर जिला पंचायत को दे और वह रकम गान-सुवार के काम में सर्क की जाय। गाव पजायतो को सही मानो ये विलेज रियन्लिंग बनाया जाय। विलेज रियन्लिंग बनाया जाय। विलेज रियन्लिंग बनाया जाय। विलेज रियन्लिंग को उस दिन है। विलेज रियब्रिंग वजरा माह्यान को इतना प्यारा ह कि उसे हर मोके एन दर्भ गाल करते है। हमारे सूबे में विलेज रियब्लिंग के लक्ज का मखी उअनली तोर पर हुकूनत की करकी जिया जा रहा है। इस के बारे में आज भी कुछ बाते अर्ज करूंगा।

११ वी वात जो है वह हुक्तन से बराहरास्त वास्ता नही रखती लेकिन म यह स्प्रस्ता हूं कि जम्हरी हुक्त्मत के नुक्ते—िनगाह में यह होना चाहिए कि सरकारी अफसरो पर ज्यादा भरोस न करे और सूबे ओर मुक्त के बमनेवालो पर ज्यादा भरोपा करे। वह वात यह है कि तालाब और कुओं खोदना, बन्ध बांधना, खाद बनाना हर काम के लिये कि तान नोजवानो की वालिस्टियर टोलिया बनायो जाये। मैं इस बारें में अर्ज करना चाहता हूं कि हुक्सत ने पारसाल २५ लाख स्पया तालाब खोदने पर सर्फ किये। कागज पर तो बहुत से तालाब खोदे गए मगर जमीन पर बहुत कम तालाब खोदे गये।

सै नफनील में नहीं जाना चाहता। इस मौके पर में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सुबे की हालन को सुआरने के लिये पोशलिस्ट पार्टी यह नय कर चुकी है कि फरवरी और मार्च में वह एक निवाई सेना भर्नी करेगी ओर अप्रैल से वह निवाई सेना अपना काम शुरू कर देगी। हमारे काग्रेस की बेवों पर बंठे हुय दोस्न इस वात का रुगल भी नहीं कर सकते हैं कि अवाम ओर जनता भी अपनी तरफ से कोई काम कर सकते हैं। सेना का लक्ज जो आ गणा तो उनके कान खड़े हो गये। हुकू पत की कुर्तियों पर बैठने के बाद उनको इसका कुछ ऐसा नशा सवार हो गया है ओर ऐपा बस्का लगा है कि उनकी मनोवृत्ति, उनकी फितरत ही बदल गई है, यानी वे यह सनझ ही नहीं सकते। में उनसे इस बारे में, अगर वे सुनना चाहते हैं तो अर्ज कर दं कि हमारे एक सो बलिस्ट साथी ने एक खेतिहर पल्टन को भर्ती करके सूबा बिहार में १४ मील लम्बी नहर सोद डाली और सरकार का सारा पैना बच गया। सरकार ने उसके लिये पांच लाख रुपये बजर में रखे ये लेकिन कभी भी वह रुपया दरतयाब नही होता था। (हंसी) यह हंमने की बात नहीं है। हम और कुछ नहीं चाहते। आपसे पैता नहीं चाहते। आपसे इतना जरूर चाहते है कि आप हमारे रास्ते में कोई एकावट न डाले। आप साफ २ इस बात का ऐलान करें कि जो तालाब, जो नालाजिस तरीके से वह सिवाई सेना सोशलिस्ट पार्टी की खोदना चाहती है वह खोद सकती है और हुकूमत की तरफ से उसमे कोई रुकावट नहीं होगी इसी के साथ २ एक दूसरा आख्वासन भी आपको देना चाहिये और वह यह है कि इस तरीके से जो पैदाबार बढ़ेगी उस पर आप किसी किस्म का टैक्स लगाने की कोशिश नहीं करेगे। सवाल यह पैदा होता है कि जो अगराज व मकासिद इस बिल में हुकूमत की तरफ से बयान किये गये हैं और उनको पूरा करने के लिये जो तरीक़ा अभी बयान किया गया है, उसके बारे में बिल में कोई चीज है ? में तो शुरू से इस चीज को गायब पाता हूं, वह है ही नहीं। यह स्टेटमेट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स (प्रयोजनीं और कारणों के वक्तव्य) में लिख तो जरूर दिया गया लेकिन उसको पूरा करने की कोई कोशिश इस बिल में नहीं की गई। जमींदारी मिटाने का मतलब क्या है ? एक आम इन्सान की निगाह में तो जमीदारी मिटाने का यही मतलब है कि उसकी जरूरियात पूरी हों, उसकी ग्रारीबी दूर हो, उसके पास अगर जोतने के लिये काफी खेत नहीं है तो काफ़ी खेत मिले और उसकी जिन्दगी एक डीसेट लिविंग (सुखनय जीवन) हो, उसकी जिन्दगी एक माकूल नियार की जिन्दगी हो। निगाह में है। किसान की निगाह में तो जनींदारी मिटाने के माने यह है कि उस पर कोई दबाव न रह जाय, कोई उसका खून न चस सके। लेकिन यह बात इस बिल में मौजूद नहीं है अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस हालन को बदलें जिसकी बाबत मेने आज आदादोशुमार पेश किये हैं, तो आपके लिये यह जरूरी है कि जमीन का आप फिर से बटवारा क़बूल करें। अगर जमीन का फिर से बटवारा नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि आप स्टेंटस को

[श्री रोशन जनां खां]

क़ायम रखना चाहते हैं। यह एक और बात है कि आप एक बड़े आपरेशन से भाग कर छोटी-छोटी हिन्तियों का इलाज करने की कोशिश करे, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा। अगर आप कुछ छोटी-छोटी बाते कर रहे हैं तो उनसे कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होती है। जो समाज की गुलत बनियाद या गुलत आधार इस वक्त है, उसमे कोई तब्दीली नहीं होती है, वह यह है कि एक मालदार गरीब का खून चूसे और ऐशोइ शरत की जिन्दगी बहर करे, गरीब मुसीबतों का शिकार रहे। यह बुनियादी कमी एव वक्त भी क्रायम रहती है जब कि आप इस कानून की बना देते हैं। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि जमीन का फिर से बटवारा हो। हालत क्या हुँ ? इत कानून के बन जाने के बाद भी बड़े-बड़े फार्म कायम रहेंगे, उनका रक्रवा कुछ कम नहीं होता है। सीर और खुदकाश्त का रक्रवा जो जमींवारों के क्रव्जे में है, बिला लिहाज इसके कि किसके पास कितना रक्तवा है, सबका सब क्रायम रहेगा। मौजदा बिल जो सेलेक्ट कमेटी से आया है उरामे इतनी तरमीम जरूर की गई कि अब यह बात लाफ कर दी गई है कि जो लोग, जो जमींदारान, २५० रु० से ज्यादा मालगुजारी देते हैं उनकी सीरपर जिन काश्तकारों का कब्बा है वे मौक्सी काश्तकार हो जावेंगे। लेकिन इसके अलावा और कोई तरमीम नहीं की गई। मसलन, अगर एक जमींदार है, उसके पास बहुत ज्यादा रक्तबा है और खद काइत में है, किपान के कब्जे में नहीं है, किसी काइलकार के कब्जे में वह जमीन नहीं है, तो वह सबकी सब उसके कब्जे में रहेगी और उसी की मिल्कियत होगी। इसी तरह से बड़े-बड़े जो काश्तकारान है उनको भी उसी तरह क्रायम रखा गया है।

इस बात का भी इन्तजाम इस बिल में नहीं है कि जो लोग छोटे-छोटे खाते रखे हुये है, जो थोडे-थोड़े रक़बे की आराजी को जोतते हैं, उनकी आराजी में इजाफ़ा किया जाय। उनकी अनद्दकीनामिक हो ल्डिंग्ज (कम आमयनी वाली जोतों) को इकोनामिक (आमरनी वाली) बनाने की कोशिश करनी चाहिये। जो कुछ भी कोशिश की गई है उसके बारे में मै आगे चल कर बताऊंगा। लेकिन यहां में सिर्फ इतना ही कहना चाहंगा कि ग्ररीब की ग्ररीबी दूर करने की कोशिश नहीं की गई है। हां, यह जरूर कोशिश की गई है कि जो मालदार है उनकी दौलत क़ायम रहे। और खेतिहर मजदूरों को कौन पूछता है। इस हुकूमत की तरफ से पहिले यह बताया गया था कि खेतिहर मजदूर की हालत सुधारने के लिये हुकूमत तहक्रीकात करायेगी और उनकी हालत सुधारने के लिये, उनको अच्छा बनाने के लिये, पूरे तौर पर कोशिश करेगी। लेकिन हमने जो यात सुनीहै, हम चाहते है कि हुकूमन उसका जवाब दे। अगर हमारी इतिला ग़लत है तो आप कह दी जियेगा कि गलत है, हमें संतोष हो जावेगा। वह यह है कि अब जब कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ करने का इरादा कर चुकी है तो हमारे सुबे की हुक़मत ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि खेतिहर मजदूरों के बारे मे कुछ न किया जाय। जमीन का बटवारा करने के लिये सरकार तैयार नहीं है। और उसके लिये वजह जमींदारी अबालीक्षन कमेटी की रिपोर्ट में यह बताई गई रैं कि हां, जमीन का बटवारा फिर से होना ती बहुत जरूरी है अगर हम इस सूबे के खेती करने वालों को आराम की जिन्दगी देना चाहते है, लेकिन क्या बतायें कुछ डर लगता है, हमको कुछ भय सा मालूम होता है।

चनांचे इस रिपोर्ट के अल्फाज में पढ़े देता हं :---

We must reckon the fact that it would arouse a spirit of opposition among the substantial tenants and would inflict great hardship upon the landlords whose income will in any case be reduced by our scheme for the abolition of the zamindary.

(हमें इस तथ्य को मानना चाहिए कि यह वास्तिवक किसानों के बीच में विरोध की भावना पदा करेगा और इससे उन जमींदारों को बड़ी कठिनाई होगी जिनकी आय जमींदारी विनाश से किसी न किसी प्रकार घट जायगी।)

इसमें जो अल्फ ज लास तोर पर करने के काबिल है वह गह हे कि सब्बटेशियल टनेटस, इसके बारे में नने पहिले ही कह दिया है कि हमारी मरकार राब्पट वियल टेनेट्स और जमीदारों में उरनी ३ ओर वह गरीब किन(नों को शुन।र में नहीं लाती है । हाल। कि मै हुकूबत को बतला द कि इन्तलाब जब आता है तो गरीय ही क्रस्ता है। जिशको तक्तले कि होनी है बही इन इक्लाब के लिये वल में देवसोक वह रामझत। है कि वह एक खास निशन के लिये जा रहा है। डर को बात होना चाहिये लेकिन यहां तो उल्टो गगा वह रही है या री सबल्टे रियल टेनेटस से तो डरते हु ओर गरीब किसानों से नही डरते इसीलिये जनोन का फिर से बटवारा कर ने की बात को बकन कर दिया गया है। दालि में सार्व करू कि अगर हुतूपत इस नुक्ते-निगाह से चलती हैं कि न खालिक न होगी ओर मकाबिला करना पडेगा ओर इससे उसकी जान खतरे में पड़ जायेगी लिहाँचा वह इन गुलालिकन को सोल न ले, तो यह कह देना चाहता हूं कि इससे उसकी जान नही बब सहती है। पेने आपकी बतलाया कि लिए ४.४ फ़ीतदी लोग ऐसे है जिनके पास २९.६ आराजो है। भेने आपको यह भी बतलाया कि ८५.४ फीनदी ऐसे खेती करने वाले है जिनके पास ४४.८ फी नदी आराजी है। अब सवाल यह है कि किन से डरना चाहिये, मैने आज आंकड़े दिये हैं उतसे यह पाबित होता है अगर आप मेरी बात जाने, सोशल्लिस्ट पार्टी की बात मानें कि इको नामिक होत्डिंग्स का रकबा १२१/२ एकड़ करार दे तो मुक्किल से २ फ़ीसदी ऐसे कास्तकार या जनींदार होंगे जिनके पास १२ १/२ एकड़ आ राजी है। इस यात की भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं भेजी पन खाता का रकबा ३० एकड़ करार दिया है फिर तो मुक्लिल से आधे प्रतिशत लोग ऐसे है। जिनको आपकी इत रिडिस्ट्रीब्यू जन से नुके बान पहुँचेगा। फिर डरने की ज इरत किससे हैं आत्रा १/२ प्रतिज्ञत लोगों से यानी सब्सटैशियल टेनेन्टस से या ९९.५ फ़ीसदी ग्ररीब काश्नकारों से जिनके पास साढ़े बारह एकड़ से आराजी कम है। अगर हुकुमत की बात मानी जाये याती जवाइन्ट सिलेक्ट कमेटी की बात देखी जाये तो नवा छ' एकड़ इकोनोमिक होल्डिंभ मानी है। अगर इसी नियार को ठी क करार दिया जाये तो भी १४.६ फ़ीसदी लोग ऐसे हैं। अत्र तवाल यह है हि १४.६ फ़ीसदी सब्पटेशियल टेनेन्टम से डरना चाहिये या ८६ फ़ी रही लोगों से डरना चाहिये जो ग़रीज काश्तकार है। इस मुखालिकत ओर बगावत के बारे में हुकूमत का नजरिया कतई ग़लत है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक हुकूमत जो जम्हरी है जिस की आयन्दा जिन्दगी इसी बात पर मुन्हसिर है कि हमारे सुबे में बसने वाले बालिग मर्द और ओरत चाहें तो रखें चाहें निकाल दें। फिर वह किस तरह से १५ फ़ीसदी से कम लोगों से डरती है और ८५ फ़ीसदी लोगों को कुछ भी नहीं समझती। मैंने अर्ज किया है कि ज्वाइंट निरुव्ट कमेटी की रिपोर्ट में जो बात बतलाई गई है कि जमीन का बटवारा न हो कतअन ग्रलन वेद्रुनियाब और लगो है। अगर यह वजह नहीं है तो में समझता हूं कि हुक़ुमत जम्हरी उसूल से हट रही है और यह इसके लिये बिल्कुल नाम्नासिब है कि वह इस तरह की बात करे कि जमीन का बटवारा फिर से न करे। 1 1.

जून सन् १९४९ के महीने में वजीरे आजम साहब ने एक बयान दिया था। इस बयान में डिस्प्रोगोर शनेट, डिसकंटेंट और एजीटेशन का जिक था और दूसरी तरफ यह कहा कि स्पीडी मैनर में जमीन का फिर से बंटवारा कर दिया है और उसे इस तरह बतलाया कि हम कहते है कि अब कोई एक मुकरंर रक बे से जाबा आराजी खरीद नहीं सकेगा। एक तो हद की बात कहीं है। दूनरी बात यह बतलाई कि जब हम कह देते हैं और कानून बना देते हैं कि जो शख्स खुद अपनी आराजी नहीं जोत सकता है, वह आराजी छोड़ने के लिए मजबूर हैं और वह आराजी नहीं जोत सकता है, वह आराजी छोड़ने के लिए मजबूर हैं और वह आराजी का मालिक नहीं रह सकता। इसका नतीजा यह होगा जैसा कि वजीर आजम साहब की बात का मतलब है कि जो लोग जमीन को खुद नहीं जोत सकेंगे वह खुद ब खुद उसे छोड़ देंगे। लेकिन में निहायत सफ़ाई के साथ अर्ज कर दूं कि वह लोग जो बड़े रक़ बे रखे हुए हैं, और वह उसे नहीं जोतते तो वह उसे खुशी से नहीं छोड़ देंगे। यह आपकी उम्मीद गलत है और अगर ऐसी उम्मीद आपकी है तो में क्या कहूं सिवाय इसके कि अानकी खुद अवान पर इत्मीनान नहीं रहा। आप यह समझ सकते है क्या किसी तरह का कानून बना कर बड़े रक़ बे की खती करने वालों को मजबूर कर देगे कि वह आराजी छोड़ दें यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि किसी काम के करने में केवल

[श्री रोशन जमां खां]
मेहनत की जरूरत नहीं होती बल्कि मेहनत के साथ-रााथ कैपिटल भी होती है, जिन लोगों के पास
बड़े रमबें है, बह मेहनत नहीं करते, उनके पास आदमी कम है, जोतन वाले कम है, खुद
न जोत सकें लेकिन उनके पास रुपथा है, उसके जरिये से वह आराजी पर हमेशा क़ब्जा रखेंगे।
हुक़ूमत खुद ही फार्मों की शंक्ल उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी सूरत मे
यह उम्मीद करना कि वह लोग खुशी से छोड़ दे गलत हैं। स्पीडी मैनर में रिहिस्ट्रीब्यूशन आफ
लैंड (जमीन का दुबारा बटवारा) हो जायगा, यह ल्याल बिल्कुल बेबुनियाद है। स्पीडी
मैनर की बात जो कही गई, उसे ही नहीं बिल्क पूरे बिल पर सरकारी कार्यवाही को में
डिलेइंग टैक्टिक्स (देर करने की नीति) समझता हूं। इस बात की कोशिश मरकार की
तरफ से हैं कि जमींदारो को मिटाने में जितनी भी देरी हो सके की जाए ताकि एक गैर
यक्तीनी हालत क़ायम रहे और इस तरह से उनकी गद्दी बरकरार रहे इस पर में आगे चल
कर सफाई से अर्ज करूंगा।

में यह अर्ज कर रहा था कि स्पोड़ो मैनर में कोई चीज सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। यह जो रिडिस्ट्रोब्यकन आफ लैंड के खिलसिले में स्पीड़ी मैनर की बात कही गयी है यह बात

किसी त'रह से सही नहा करार दी जा सकती है।

उनको मुआविजे की शक्ल में दी जा रही है।

मैने अभी यह कहा था कि जो बड़ी जोत वाले हैं उनके पास सरमाया और पूंजी है। उसम एक चीज और जोड़ दूं। और वह यह है कि उनके पास जो पूंजी आज है वह तो मौजद ही है। इसके अलावा यह हुक भत कहती है जरा थोड़ी सी पूंजी ओर ले लो और फेड़लत अमाउंट्स, बड़ी—बड़ी रक़में मुआविज की कक्ल में दी जा रही है। क्या हुक़मत की निगाह में जैसा कि इस बिल को देखने से मालूम होता है यही नजरिया है कि पूंजी के मुकाबिले में मेहनत की कोई हक़ और दर्जा हासिल नहीं है, में आगे चल कर इसकी वजहत करूंगा कि जो कुछ दर्जा हासिल है वह पूंजी और सरमाय को है। उनके पास पहिले से सरमाया मौजद है। उसके बाद और पूंजी

जहां तक छोटे-छोटे खेतों की बात है, अनइकोनामिक हो हिंडाज (अलाभ कर जोत) की बात है। उनकी इस जमीन का बटवारा करके खत्म किया जा सकता है। और अगर सरकार इस बान की कोशिश करती, जैसा कि वह एलान भी करती है कि हम तो नहीं चाहते कि हमारे सूबे में छोटे-छोटे खेत रहें तो उसको इस जमीन का फिर से बटवारा करके खत्म करना चाहिये था। छोटे खातों को खत्म करनें के लिये दो तरीक़ हो सकते हैं। एक तो यह कि बड़ी जोतों से खत निकाल करके छोटी जोतों में शामिल कर दिये जायं। दूपरे यह कि छोटी जोतों को जत्म करके बड़ी जोतों में शामिल कर दिया जाय। लेकिन हमारी हुकूमत ने उत्टी बात की 🗓, उत्टी गंगा बहाई है। वह बड़ी जोतों को खत्म करके छोटी जोतों में आर। जी को दिलाकर बड़ी नहीं करना चाहती। मैं इसकी बजाहत जरा और कर दूं इसिल पे कि हमारे उन बेचों पर वाले दोस्त जरा समझने में देर करते हैं। इस लिये में चाहता हूं कि इस चीज को में और ज्यादा साफ कर दुं। आपने इ.स. कानून के जरिये से जमीन को एक क्मोडिटी बना दिया है। ऐसी वीज बना दिया है जो बाजार में फरोस्त की जा सकती है और खरी दी जा सकती है। यह तो बात साफ रैं कि सवा छ: एकड तक जीतने वाले लोग अपना लगान भी अदा करने की अहलियत नहीं रखते हैं। और ये लोग कभी भी कसी दूसरे की आराजी को खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। किर कीन खरीयेगा? अमीर खरीदेगा, अमीर अपनी पूंजी के बल पर ग़रीब की दौलत ख़रीत कर अपने हाथ में घसीट लेगा। यह जो आगने ख़रीदने और बेच रे का हक दिया है उनसे किसे फायदा पहुँचेगा, क्या वह ग़रीब काइतकार क्या वह ७३ फीसवी लोग जिस के बारे में हुक्मत की तरफ से कहा गया है कि उन के पास खाने भरको नहीं होता या खा पीकर सब बराबर हो जाता है, वह इसको खरीद सकते हैं ? इसको वही २७ फ़ीसदी वाले लोग खरीद सकते हैं जिनके पास खाने-पीने के बाद भी बचा रहता है।

फिर क्या नतीजा होगा ? इसका नतीजा यह होगा कि छोटी जोत वाले जो किसान है छोटी जोत वाले जो लोग है उनकी सारी जमीन निकल कर बड़ों के क्रब्जे में आ जायगी। एक बात में यहां और अर्ज करदूं और वह यह है कि आपने कंट्रोल आफ प्राइसेज की भी बात रखी है। आपने इस बिल में इस बात की कोशिश की है कि जब बेचने के लिये कोई शख्स तैयार हो तो उसके लिए आपने जो शतें लगाई है उन शतों में भी गरीबों को ही नुकसान होगा और अमीरों को फायदा होगा। इस तरीके से मेरा यह कहना है कि इस बिल के जिरये में अनइकोनािमक होल्डिंग्ज को इस तरह लत्म किया जा रहा है कि जो ढांचा आपने आइन्दा समाज का बनाया है उसमें छोटी जोत बाले अपनी सारी आराजी को बेचकर उन अमीरों के हाथ दे दे जिनके हाथ में पहले से ज्यादा अराजी मौजूद हैं और इसत रह से आपने अमीरों को ही फायदा पहुंचाया है। आपकों शायद यह मालूम हो कि आज ऐसे लोग भी समाज में मौजूदह है जो गलत तरी के से आरा— जियां हािसल कर सकते हैं ओर इस तरह से बह अमीर लोग हर तरी के से फायदा उठावेंगे।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजे डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राशन जमा खा--जनाब डिप्टो स्पीकर साहब, उठने से पहिले में इस ऐवान में यह अर्ज कर रहा था कि सरकार ने इन बिल को जिस तरह बनाया है उससे अनइको।न। मिक होलेडिंग्स इकोनामिक होलेडिंग बनाने के बजाय तमाम अनइकोनामिक होलेडिंग्स खुद व खुद बत्महो जाती है और जो इकोना भिक होलंडिंग्स हं उनके रकवे में इजाफ़ा हो जाता है। इस सिल सिले में मुझे केवल एक बात और कहनी है और वह यह है कि दक्ता १८१ और दफा २६० इस तरह बनायी गयी है कि जिससे अगर कोई किसान, जिसके पास ६ एकड़ से कम आराजी हो, खद न बेचना चाहे, खुद न देना चाहे तो सरकार ओर सरकार की पूरी मशीनरी इस बात की कोशिश कदेगी कि उससे आराजी छीन लीजाय। मैं जरा इस चीज की और ज्यादा तफसील में अर्ज करदूं। दफा १८१ में बटवारे का जिक्र किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी भी खाते के बाबत बटवारे का दावा दायर है जिसका कि रकबा ६ एकड़ से कम है तो उस हालत में अदालत को यह अख्तियार होगा कि खाते का बटवारा केरने के बजाय उसे नीलाम कर दे और नीलाम से जो रकम मिले उसे बाट दे, और दक्रा २६० में मालगुजारी की वसूली का तरीका बताया गया है, उसमें भी साफ-साफ यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि अगर किसी खाते की मालगुजारी वसूल न हो नो उत हालत में वह उस खाते को किसी दूसरे के नाम मुन्तिकिल कर दे। नो मेरी गुजारिश यह है कि इन दो दफात से ६। एकड़ से कम वाले खाते को हकुमत और अदालत के जरिये से खत्म करने की कोशिश की गई है और इसके वही नतीजे होंगे जो मैने अर्ज किया कि बजाय इसके कि अनइकोनामिक होलंडिंग्स इकोनामिक होलंडिंग्स बन जाय, तमाम अनइकोनिमक होर्लींडग्स खत्म हो जायेंगी और इकोनामाकि होर्लांडग्स मे शामिल हो जायंगी।

अब जो बातें मंने जमीन के फिर से बटवारे के बारे में कहीं है उनसे कुछ नतीजे निकलते हैं। एक नतीजा तो यह है कि जो नबराबरी हमारे समाज में हैं वह नबराबरी बराबर कायम रहती है, दूर नहीं होती और जिस तरह से इस वक्त अमीर गरीब का खून चूसता है, इसी तरह से आइन्दा भी चूमता रहेगा। दूसरी बात जो नतीजें के तौर पर निकलती हैं वह यह है कि समाज का ढांचा जिस तरह बनाया जा रहा हैं उसमें पूंजी को मेहनत के मुकाबिले में बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है और जो भी कायदे और कानून बनाये गये हैं वे इसी नुक्तेनिगाह से बनाये गये हैं। किसी की गूंजी को सदमा न पहुंचाया जाय, इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि एक तानाशाही निजाम, एक फासिस्ट आईर हमारे सूबे में कायम होगा जिसका दूर करना एक जम्हरी हुकू मत का सब से बड़ा फर्ज होना चाहिये, खात तौर से उस हक्मन का जगा यह दावा है कि वह तन्नाम क्लासेज को बता करके एक क्लासलेश नो अहाना चाहती है।

लेकिन इस बिल में जो चीजे रक्खी गई है उनसे वे सारी उम्मीदे जो कांग्रेस के ऐलानात की बिना पर उससे की जा सकती थी, खत्म हो गई। इस बिल में गांव समाज और कोआपरेटि। फार्मिंग की बाबत भी अलग—अलग अध्याय और बाब कायम किये गये हैं। कोआपरेटिव फार्मिंग का जो कानून बनाया गया है उसे हम ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी का कानून कह दें तो कोई ताज्जब नहीं होना चाहिये। इस कोआपरेटिव फार्मिंग की सारी थारायें औ सारी बातें इन्डियन कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट

श्री रोशन जमां खं]

हर समझदार आदमी ने मलामत की है, सही मानों में कोआ-परेटिव फांसिंग नहीं हो उसकी बनियाद पर है। और सब से सकती, बड़ी बात यह है कि जब तक आप जमीन का फिर से यटवारा न कर कोआपरेटिव फर्मिंग कामयाब नहीं हो सकती है । में कोआपरेटिव फार्मिंग के बारे में शेकेंड रीडिंग के मौके पर ज्यादा वजाहत के साथ अपने ख्यालात पेश करूंगा। इस मौके पर मुझे सिर्फ इतना ही अर्ज कर देना है कि इसने जो चीजे रखी गई हे उनसे सिर्फ यही नतीजा निकलता है कि मालदारों की हालत और मजयत हो और गरीब और मजदूरों की हालत बद से बदतर हो जाय। गांव समाज का जिके इस कानून में पढ़कर बहुत खुशी होनी चाहिये थी कि कनअनकम हमारी सरकार ने एक नया समाज बनाने की कोशिश को है लेकिन अफसोस है कि गांव समाज के सिलिसिले में जो कानून यहां पर रखा गया है वह हरिगज-हरिगज से संतोषजनक नहीं है। जो समाज कि इस बिल में है और जो समाज पंचायत राज ऐक्ट के उरिये से कार्यम होगा उससे यह नहीं मालूम होता कि इस बिल के जरिये से एक नया समाज कायम होगा या वह समाज रहेगा जिसे गांय-सभा या गाव-पंचायत कहते है। इस गांव समाज में गांव के तमाम बसने वाले शरीक होते तो बड़ी खुशी की बात होती लेकिन अि्तयार किसको दिये गये हैं? क्या सारे गांव वालों की अि्तयार दिये गये हैं; नहीं बिल्क एक एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है, एक कार्य समिति बनाई गई है और उसीको सारे अख्तियारात दे दिये गये हैं। ऐसे अख्तियारात को देने से क्या लाभ होगा जब तक कि हम एक वर्ग विहीन समाज न बना दें और वह उसकी एक्जोक्यूटिव कमेटी न हो, जब तक कि हम एक ऐसा समाज न बना दें जिसमें एक तबका के अलावा दूसरा तबका न हो नबराबरी को खत्म न कर दिया हो। लेकिन जब हमारी सोसाइटी मल्टीक्लास सोसाइटी है तो हमारी पंचायत भी मल्टीक्लास पंचायत होगी । जब बहुत से वर्ग होंगे तो अमीरों और मजबतों के जरिये गरीब सताये जायंगे। इन पंचायतों के इस गांव-समाज को, जो हमारी सरकार इस बिल के जरिये से बना रही है, रिपव्लिक का बड़ा उम्दा नाम दिया गया है उसको प्रजातांत्रिक हुकुमत का नाम दिया गया है, बडी खुशी की बात है और बहर-हाल इस बात को तो इस सरकार ने और सरकार की पार्टी ने तसलीम किया है कि गांव का इंतजाम अगर होना है, इस नये समाज में अगर हमें गाव का इंतजाम करना है तो हमको एक विलेज रिपब्लिक बनाना होगा, और गांव वालों को सारे अख्तियारात देने होंगे, लेकिन क्या हालत हैं ? क्या इस कानन के जरिये से उनको कोई अख्तियारात दिये जा रहे हैं? क्या इस कानून के जरिये से वह अख्तियारात विलेज रिपब्लिक की मिल रहे हैं कि जो आज कल सुबाई और मरकजो हुकूमत यानी प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकार को हासिल हैं। हरगिज नहीं, बिल्क बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने गांव पंचायतों को एक खिलौना बना रक्खा है, अपना एक एजेंट बनाने की पूरी कोशिश की है। सब से पहिली बात जो इस सरकार ने इस सिलसिले में की, जिसकी सब से ज्यादा निन्दा और मलामत होनी चाहिये, वह यह है कि इसने जो वफादारी की हलफ इन गांव पंचायतों के सदस्य, प्रधान, पंच और सरपंचों को दिया उसमें बजाय राज्य और स्टेट के वकादारी के, सरकार और गवर्नमेंट की वकादारी का जिक्क है। यह चीज बिल्कुल गलत है। किसी जम्हूरी मुल्क में किसी सरकार की पार्टी को यह हक हासिल नहीं है कि वह अपनी बकादारी का मतालबा करे, खास तौर से एक विलेज रियब्लिक से, एक ऐसी पंचायत से कि जिसको खुद सरकार के लोग और सरकार के वजीर विलेज रिपब्लिक का नाम देते हैं।

१० गुना लगान की बसूली के सिलसिले में सरकार और सरकार के अफसरान ने जो तरीका इन पंचायतों के साथ इस्तेमाल किया है वह तो दुनिया के लिये आंख खोलने के लिये बहुत है। मैं इस चीज का जिक तो जब १० गुना लगान की वसूली का जिक करता, उस वक्त करता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन बात आ गई है इसलिये मैं इसका जिक इसी मौके पर किये देता हूं। सरकारी अफसरान ने इस बात की पूरी कोशिश की है क गांव पंचायतों के प्रधान, पंच और सरपंच सरकार के एजेंट बन कर १० गुना लगान

वसूल करावे। क्या यही विलेज रिपब्लिक ह ? इस बारे में म कुछ मिसाले देना जरूरी समझता हूं। जिला अलीगढ़ तहसील सिकन्दराराव के पद्मायत इंसपेक्टर ज्ञिव ज्ञाकर वर्मा माहब ने २४ दिसम्बर सन् १९४९ ई० को कुअर इन्द्रपाल सिह सरपच अदालत रकसोल को हुक्म दिया कि जवाब दो कि तुम ओहदा से क्यों न अलग कर दिये जाओ ? जुर्म क्या थ। ? जुम यह था कि——नुमने ६ दिसम्बर सन् ४९ को मटगरी गाव में एक सोज्ञालिस्ट पार्टी की मीटिंग में जमीदारी अबालिज्ञन फड की मुखालिफत की थी।

दूसरी वजह यह बतलाई गई है कि १० गुना लगान के खिलाफ कह कर आपने सरकार के खिलाफ बगावत किया है। इसलिये इस ओहदा पर आप के लिये रहना जनता के लिये नुक्सानदेह हैं। लिहाजा आप का यह काम दफा ९५ पंचायत राज ऐक्ट ओर कायदा ६१ पंचायत रूप्स के खिलाफ है।

अब आप खुद सोचे कि अगर यह विलेज रिपब्लिक है तो उनको पूरे अख्तियागत होने चाहिये। अगर कोई ज हूरी सरकार किसी ऐसे कायदे को बनाती है कि जिसके जरिये से गाव की पंचायतो को महज सरकार का एजेट बना दिया जाय तो उस हुकूमत को एक जम्हूरी मुल्क में हरगिज नहीं बर्दाइत करना चाहिये। जिला अलीगढ़ की एक दूसरी मिसाल यह हे कि पचायत इंसपेक्टर तहसील कौल जिला अलीगढ़ ने १५ दिसम्बर सन् ४९ को एक नोटिस श्री लाल सिंह, सरपंच अदालत शाखा को दिया कि आप को ओहदे से क्यो न हटा दिया जाय? इस जुर्म मे कि आप गुना लगान देने की मुखालिफत करते है। उसके बाद उन्हें। इंसपेक्टर साहब ने २४ दिसम्बर सन् ४९ को एक दूसरा नोटिस उस सरपंच साहब को दिया कि आप ने दस गुना लगान देने की मुखालिफत करके अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है। दूसरा चार्ज उन पर यह लगाया गया कि २५ नवम्बर सन् १९४९ को लखनऊ मे होने वाले किसान प्रदर्शन में शिरकत करने के लिये आप जा रहे हैं। यह कहा का जुर्म हैं? क्या एक प्रजातंत्र मुल्क का यही तरीका है ? क्या एक ऐसे सूबे मे जहां कि गाव पंचायतो को विलेज रिपि लिक का दर्जा दिया जाय जहां पर डेमोक्रेमी और प्रजातंत्र का नारा लगाया जाता है, जहां सोद्यालिस्ट पार्टी खुल्लमखुल्ला एक डेमोक्रेटिक पार्टी की हेसियत से डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की बुनियाद पर फॉम करती है, उसके आदिमयो को इस तरह से सताया जाय । मैं यह मान सकता हूं कि इस तरह के फर्जी या अस्ती जुर्म आप के पंचायत इंसपेक्टरों ने लगाये, लेकिन उनके अलावा आपके पंचायत आफिसरों ने भी धमकी दी है, और वह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यह कहा तक जायज और मुनासिब है। बहरहाल एक हद तक यह हो सकता है, लेकिन महज इस जुर्म में कि २५ नवम्बर सन् ४९ को लखनऊ में होने वाले किसान प्रदशन में शिरकत होने वालें है या दस गुना लगान की मुखालिफत करते है या सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में जाते हैं, यह तो ऐसी चीज है कि जो खुद सरकार के लिये वायसे द्यमं है। और अगर सरकार अपने उत्तरदायित्व का, अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखती है तो उसको खुद इस मामले में एक कदम उठाना चाहिये। इन्ही इन्सपेक्टर साहब ने १५ दिसम्बर सन् १९४९ को सरपंचों तक की ही यह बात नहीं है, बल्कि प्रधान तक को भी उन्होंने नहीं छो । है। मैने सुना है कि हमारी सरकार सरपंचों के लिये कायदे और नियम में कुछ इस तरह की तब्दीली कर चुकी है या करने वाली है जिसमें वे सोशलिस्ट या किसी पार्टी में हिस्सा नहीं ले सकते है। में इस बात को मानने के लिये एक हद तक तैयार हूं कि अगर वे कांग्रेस और कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी में हिस्सा न लें तो उसमें कोई मुजायका नहीं हो सकता है। लेकिन आप इस तरह के कायदे बनावें जिसके माने यह हों कि वे सरकार और सरकारी पार्टी के कामों में हिस्सा ले सकते हैं और विरोधी दल के कामों में हिस्सा नहीं ले सकते है तो यह चीज हरगिज-हरगिज बर्दाइत नहीं की जा सकती है और यह चीज सही भी नहीं कही जा सकती है। यह बात जो सरपंचीं के बारे में हुई है वह प्रधानों के बारे में नो न होनी चाहिये थी लेकिन उन्हीं इन्सपेक्टर साहब ने तहसील कौल जिला अलीगढ, १५ नवम्बर सन् ४९ को भंवर सिंह प्रधान ग्राम पंचायत वाराहटी पर इस तरह का जुर्म लगाया कि तुम दस गुना लगान की मुखालिफत करते हो

[श्री रोशन जमां खां]

लिहाजा तुम्हे क्यों न हटा दिया जाय? यह तो इंसपेक्टर साहब की बात थी , यही तक नहीं है कि छोटे—छोटे आफिसर्स ही इस तरह के काम किये हों बिल्क देवरिया के जिला पंचायत आफिसर साहब ने ३० नवम्बर सन् ४९ की सरपंच अदालत छतौनी तहसील सलेमपुर को यह हुक्म दिया और यह नोटिस दी कि तुम्हे क्यों न ओहंदे से हटा दिया जाय। उन पर जो इल्जाम लगाया गया हे वह सबसे ज्यादा निराली बात हैं। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि तुमने दस गुना लगान देने की मुखाितफत करके अपने हलफ के खिलाफ काम किया है। वह चीज है सरकार की वफादारी का हलफ जिसके बारे में मैंने अभी आप के सामने जिक्क किया है। वह हलफ वफादारी का जो आपने गलती से लिया उसको लेकर आप डेमोकेसी को ठोकर मार रहे ह। उस हल्फ के माने आप यह लगाते ह कि कोई शख्स सरकार नी बनार्या हुयो किसी योजना के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता है।

इसी तरह की एक नोटिस जिला गाजीपुर में पदमपुर पंवायत के प्रथान त्रिवेणी को भी दी गई। इसी ररह की एक नोटिस १५ नवस्बर को जिला सीतापुर में प्रधान रामदत्त वर्मा को भी दी गई कि तुमको क्यों न इस पद से हटा दिया जाय। उनका जुर्म बताया गया कि उनकी गांव—सभा ने यह प्रस्ताव भेजा था कि १० गुना लगान के खिलाफ उनकी सभा थी। महराजपुर, जिले कानपुर में १५ दिसम्बर सन् १९४९ ई० को वहां के प्रधान को यह हुक्स दिया गया कि क्यों न उनको उस पद से हटा दिया जाय। उतका जुर्म सुनने के काविल है। उन पर यह जुर्म लगाया गया कि उन्होंने १० गुना लगान के खिलाफ पर्च छपवाकर बांटे थे, वह सरकार विरोधी मोर्ची संगठित कर रहे थे और उन्होंने अपना १० गुना लगान नहीं जमा किया था। क्या यही कानून है जो कि इस भवन से पास कराया गया था जिसमें यह साफ—साफ कहा गया था कि सरकार इस जमीदारी को बेचने के सिलसिले में एक दुकान लगा रही है जिस खरीदार का जी चाहे इस सौदे को ले सकता है जिसका जी चाहे वह इस सौदे को न ले। मगर यह क्या हो रहा है। खरीदारों की गर्दन पकड़ कर जबरदस्ती वहां लाया जाता है कि तुम खरीदो।

एक सदस्य-- क्या आप से भी कहा गया था।?

श्री र शन जमां खां -- आपकी सरकार मुझसे ऐसा करने के लिये कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन जिन मिसालों को मैने अभी दिया है वह सब सोशलिस्ट पार्टी के दफतर की फाइल में मौजूद है। अगर सरकार चाहे तो में उनको यह दिखा भी सकता हूं ओर पढ़ सकता हूं। इस तरह की बाते पंचायतों के बारे में करें और फिर उनको विलेज रिपब्लिक का नाम विया जाय तो यह बड़ी तौहीन की बात है। मैने अभी इन पंचायतों के बारे मे कहा एक दो मिसाले अपने जिले गोंडा के बारे में भी आप के सामने रखूंगा। हमारे दोस्त कांग्रेस बेचों पर बैठे हुये गोंडा की मिसाल को सुनना चाहते हैं लेकिन मै यह समझता हूं कि इस तरह की बात को जब मै आगे और मजालिम का जिन्न करूंगा उस वक्त पेश करूंगा। जो गांव सभायें बनाई गई है जिनको विलेज रिपक्लिक का नाम दिया गया है वह जिस तरह से सरकार ने अपने लिये खिलौने बनाया है उसका मेने थोड़ा सा जिक्र किया। में यह समझता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ था तब कुछ ऐसी हालत थी कि उस पूरे कानून पर बहसे नहीं हो सकती थी और सरकार का मसविदा जिस तरह से आया था उसी तरह से चन्द दफाओं की छोड़कर उसी शकल में वह पास होगया था और वैसा ही बाकी रह गया था। इस बिना पर सरकार ने जो नाजायज अख्तियार रूल्स बनाने के लिये अपने लिये रखे थे उसका नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया है और अभी तक उन अख्तायारान का नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा इस ऐवान का यह हक है और फर्ज है कि पंचायत राज ऐक्ट की इस तरह से तरमीमात करे, संशोधन करे कि जिसके जरिये से यह सही मायनों मे विलेज रिपब्लिक बन सके।

इस गांव सनाज के सिलिसिले में एक सब से बड़ा बुनियादी सवाल यह उठता है कि क्या इस कार्न के अन्दर सरकार गांव-समाज को लगान की वसूली या मालगुजारी की वसूली का हक भी दे रही हैं या नहीं मैंने देवा तो ऐसा कहीं नजर नहीं आता और न इसका कहीं जिक ही है। गांव-सनाज को लगान व नाल गुजारी की बसूली का हक जिलता एक बुनियादी सवाल है।

एक कांग्रेसी दोस्त मेरी बग़ल में बैठे हुए यह करना रहे हैं कि जब सारी आराजी गांव समाज में वेस्ट करेगी तो जाहिर है कि उसको इस बात का अब्तियार हासिल होगा कि वह लगान व मालगुजारी भी वसूल करे। मुझे खुशो होती, अगर ऐसा होता, लेकिन शायद उन्होंने उस दक़ा को पढ़ा नहीं हैं कि जिस में दिया गया है कि जितनी परती, आबादी और कुएं वगैरा होंगे उन पर गांव-प्रशाल कड़ोल करेगा लेकिन उसमें कोई अब्तियार मालगुजारी की वसूली का नहीं दिया गया है और इस बिल को देखने से आलून होता है कि यह काम सरकारी अफसर करेंगे जो शायद जनींदारों और ताल्लुकदारों के जिलेदारों वगैरा से कहीं ज्यादा जालित साबित होंगे जैसे कि आज तक होते रहे हैं।

अभी तक वेंने आप को गांव—समाज और को आपरेटिव कार्मिंग के बारे में बतलाया। कुछ और बात मुझे अर्ज करनी थी लेकिन में समझता हूं कि उनमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका जिक से केंग्ड रोडिंग के वक्त आसानी के साथ किया जा सकता है। वह इतके मुताल्लिक है कि आपने कितानों की, खती करने वालों की ४ अगियां बनाई हैं। भूमित्रर, सीरदार, असामी और अविवासो । एनेंडेड अल में ३ किहनों का ही जिक है और अधिवासो का जिक नहीं है। वजीर माल साहब के गुंह से भी कल यह बात निकली थी कि ३ क्लास ही बनाई गई है। बटवारे के बारे में इत कानून में जिक है, बेदबली, लगान और मालगुजारी का भी जिक है और कुछ दूतरी बातों का भी जिक है। कुछ बातों पर में यह ज्यादा बेहतर समझता हूं कि से केंग्ड रोडिंग के वक्त तकतील के साथ अपने ख्यालात पेश कर्ष लेकिन दो एकबातें जरूर इस मौके पर कहना चाहता हूं। एक तो यह कि आप बड़ा भारी जुल्म उन लोगों पर कर रहे हैं कि जिनको आप भूमिधर बना रहे हैं। आप कहते हैं कि उनकी भालगुजारी अहा करने की जिम्मेदारी ज्वाइंट और सेवरल होगो गती अगर एक बेत वाले ने अगना लगान अदा कर दिया तो उसकी रिहाई नहीं होती बल्कि वह पाबन्द है कि वह गांव के तमाम खेत वालों की सबकी मालगुजारी सरकार को अदा करे और इसके लिए आप ने वसूली के सारे वह जालिनाना तरीके जो अंग्रेजी राज में रायज थे बरकरार रखे हैं।

दूसरी बात यह है कि आप जो आराजी का बन्दोबस्त करना चाहते हैं वह ४० साल के बाद कर रहे हैं।

यह वोज तो गलत हैं। यह गोना चाहिये कि जब आप जमींदारी मिटा रहे हैं तो उसकी जगह एक दूसरा निजाम लाया जा सके। आप का दावा है कि आप नया गांव-समाज बना रहे हैं। सो ताइडी में तब्दी ली कर रहे हैं तो आप को जल्द से जल्द एक दूसरा बन्दी बस्त करान। चाहिये न कि ४० साल तक आप बन्दी बस्त न करें। इस ४० साल के अन्दर जो शोषण जो जुल्म सरी बों पर हो रहे हैं माल दारों की तरक से वह बराबर होते रहें।

अब में कम्देन्से रान और मुआविज के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं हालांकि इस चीज का मुझे पहिले जिक करना चाहिये था लेकिन मैंने इसिलये इस चीज को आर चीजों के बाद लिया है ताकि इस पर अलाहिदों से और सन्जीदगी के साथ गौर हो सके। सरकार ने इस बिल में मुआविज के बारे में जो बातें रखी हैं उसकी में नुखालिकत करता हूं और सो शिलस्ट पार्टी का जो तुक्ते-निगाह है उसकी में ताईद करता हूं। मेरा कहना यह है कि हम किसी शख्स को मुआविजा देने के लिये तैयार नहीं है। हां, उन लोगों को जो ढाई सौ रुगए से कम मालगुजारी अदा करते हैं। उनकी पुनर्वात और अद्वान की शक्ल में दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग ढ़ाई सौ रुगए से जरादा माल गुजारी अदा करते हैं उनकी जमीतों, उनके फारमों उनकी सीर और खुदकाश्तका जब तक किर से बटवारान हो जाय उनकी कोई मुआविजा नहीं दिया जा सकता। जो मुआविजा दिया जाय अगर बटवारे को मान भी लिया जाय तो उस सुरत में किसी शख्स को एक लाख से ज्यादा पाते का हक नहीं होगा। कुल मुआविजा ५० करोड़ से ज्यादा न हो लेकिन इस कानून

[श्री रोशन जमां खां]
में पुआविज की गुनियाद शापटीं ओर जायदाद रखी गयी है। जिसके पास जितनी जायदाद हैं जितनी आराजी हैं उसी हिसाज से उसको मुआविजा दिया जाय। हम हरिश्रज-हरिश्रज इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी ने लुई फिशर में बात करते हुए यह कहा था कि जमींदारों की जमींदारी मिटाते वक्त मुआविजा देना नामुमकिन और असम्भव हैं। में ऐवान की इत्तिला के लिये महात्मा गांधी ओर नुईफिशर में जो बातचीत हुई और वह मुहतसर है उसको पढ़ना चाहता हूं।

एक मदस्य-आवार्य जी वाली भी पढ़ दीजियेगा।

श्री रोहान जमा खां—आप लोग तो उनके नाम का माला जप रहे है उसी से आप लोगों की नजात होगी, अच्छा पढ़गा।

''प्रसिद्ध अमरीकन लुईकिशर और महात्या जी'' लुई फिशर अपनी एक पुस्तक में अपने एक

इंटरव्यू का लेख इस प्रकार करता है।

छैं फिशा--इस पारत में क्या होगा किसानों की हालत को सुधारने के लिये आप के

पास क्या त्रोग्राम है ?

गांत्रा जी—किसान जमीन का दखल करेंगे। हमें उन से कहना होगा वह इंतजाम ले लेगे। जमींदारों को मुआविजा देने का तरीक़ा मेरी दृष्टि में असम्भव है। करोड़ नियों के एहमान भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। हर गांव एक स्वशासित इकाई होगा और स्वेच्छा नुसार अपने जीवन का संचालन करेगा।

छुं फिश्रर—तो आपका ख्याल है कि जनोंदारी का नाश बिना नुआवजा दिये होना चाहिये। गांबी जी—"जहर, जनोंदारों को मुआवजा देना फिसानों के लिये असम्भव होगा।"

अभी हमारे एक दोस्त ने आचार्य नरेन्द्रदेव जी का जिक किया और यह कहा कि उन्होंने क्या कहा था। में निहायत खुत्ती के साथ उनकी बात को क्रबूल करने के लिये तैयार हूं। आप ख्याल फरमायें कि जमींदारी अबालिशन कमेटी बनायी गई थी। इस ऐवान की तजवीज अगस्त, सन् १९४६ के बमूजिब जब कि हमारा मुक्त आजाद नहीं हुआ था, गव में टे आफ इंडिया ऐक्ट की दक्ता २९९ को बदलने का हमें कोई अख्तियार नहीं था, उस वक्त जब कि वह सवालनामा जमींदारी अबालिशन कमेटी की तरफ से सन् १९४७ में जारी हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी खुद कांग्रेस का एक अंग थी। आचार्य नरेन्द्रदेव जी के पात जो सवालनामा सेजा गया वह सोशलिस्ट पार्टी के नेता की दैसियत से नहीं भेजा गया था बक्ति इस ऐवान के एक मेम्बर की हैसियत से उनके पात में जा गया था। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वह ऐसा है कि उससे खुद यह वात साफ २ जाहिर हो जाती है कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी किसी मुआविजा देने के खिलाफ थे। चूंकि राम हुमार जी ने उनके बारे में खासतौर से सवाल उठाया है इसलिये में यह चाहता हूं कि उस जवाब को जिसका ओरिजनल अंग्रेजी में है, पढ़ दूं।

If we were to examine this question in the light of the origin of the zamindari system and of the tortures, cruelties, extortions and oppressions perpetrated by the zamindars on the peasantry right up to the present day then the question of compensation as well as of acquisition recede to the background calling for an immediate confiscation of all lands by the State. But we refuse to yield to sentiments and want to examine the question dispassionately in its economic and social background.

Land is a gift of nature, with it is closely bound the life of the entire community. It can not be dealt as an individual property. In fact it is the sacred trust of the nation. Its fortility is the wealth of the society. Let us see how far these intermediaries have discharged this trust and preserved and augmented this wealth. It is common knowledge that the zamindars have not cared at all to even preserve the fertility of the soil, to talk little of effecting any reform in agri-

383

culture Their only aim has been to exploit the peasanting and lead a life of luxuing and dissipation.

Let us also inquire into the manner in which these intermediaries acquired their present interests in the land. There are some who have become masters of large traces of land without spending a single pie. Among the superior intermediaries the taluquars of Avidh are a claring example. There are others who had to pay in varying measures. But these zimindais in course of time have contented themselves not only with the rent which they could have lawfully realised from the peasant-ry but have employed the most herious and barbarous methods in extorting maximus, concealed rents, unauthorised realisation of sayar and other dues. They devised various methods and adopted several legislature measures to secure the ejectment of the tenant from time to time so that they may admit new tenants on enhanced rent and fresh premiums. They have taken forced labour from their tenants and have paid only nominally where they have paid at all.

It is only these days that the peasantry having become conscious has asserted itself at some places against forced or low paid labour. Considering all these factors we come to the conclusion that even those intermediaries who paid for their land have realised through these various methods several times more than the price they had paid for their land. Where then does the question of compensation aris? What do they want to be compensated? They realized their price long long ago not through rents but through their illegal exections. And if an accounting were to take place the balance in favour of the persantry would be impossible of payment by the zamindars. The poor peas int has paid with his life blood not only the so-called contracted rent to the zamindar, not only the entire price of the land he has been cultivating but for every pleasure of the landlord. No question of compensation can arise now. It arises less in case of Taluqdars who got all their estates only for their treachery to the nation if for anything at all?.

(यदि हम इस प्रश्न की जमींदारी प्रणाली के मूल तथा उन यात नाओं, अत्याचारों, बलात्कारों और जुटमों के प्रकाश में जांच कर जिनको आज तक जमींदार किसानो पर करते रहे हैं तो क्षति-पूर्ति तथा प्राप्ति का प्रश्न पीछे पड़ जाता है और राज्य हारा समस्त भूमि के हस्तगत करने का प्रश्न आगे आ जाता है। किन्तु हम भावनाओं के बशीभूत नहीं होते और इस प्रश्न की शान्त—चित्त से आर्थिक ओर सामाजिक आधार पर जांच करना चाहते हैं।)

भूमि प्रकृति की एक देन हैं जिसके साथ समस्त जाति का जीवन आबद्ध है। यह वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं समझी जा सकती। वास्तव में यह प्रकृति की एक पवित्र देन हैं। इसका उर्बरापन समाज की सम्पत्ति हैं। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि इन मध्यस्थों ने इस प्रतिभूमि का किस प्रकार प्रबन्ध किया और इसकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार की ? यह एक सर्वविदित बात है कि जमींवारों ने भूमि के उर्बरापन की रक्षा के लिए भी बित्कुल प्रयत्न नहीं किया और फूषि में किसी प्रकार का सुधार करना तो दूर की बात रही। उनका उद्देश्य किसानों का शोषण मात्र, तथा आराम और अपन्यं करना ही रहा।

इन मध्यस्थों ने भूमि में वर्तमान अधिकार किस प्रकार प्राप्त किये इसके विषय में भी मालूम करना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और विशाल भूमि—खंड के स्वामी बन गये। उच्च श्रेणी के मध्यस्थों में से अवध के ताल्लुकेदार विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ ओर लोग हैं जिन्हें विभिन्न आयीजनों में देना पड़ा। किन्तु कुछ समय के पश्चात् केवल उस लगान से ही संतुष्ट न हुए जो उन्हें क़ानूनी तौर से किसानों से मिलना चाहिए था किन्तु उन्होंने नजराना, गुप्त लगान तथा सायर और अन्य करों को वसूल करने में अत्यन्त घृणित

[श्रीरोशन जमां खां]

और पाशिवक तरीके इस्तेनाल किये। उन्होंने समय-समय पर किसान की बेदखली के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके ढूंढ़े और अनेक क़ानूनी आयोजन अख्तियार किये जिससे कि वे नये किसानों को बढ़ाये हुए लगान और किश्त पर रख सकें। उन्होंने अपने किसानों से बलात् श्रम लिया और यदि उन्होंने इसके लिए कुछ दिया भी तो नाम मात्र के लिए।

केवल आज कल कितानों में कुछ जागृति हुई है और उन्होंने कुछ स्थानों में बलात् तथा स्पन पारिश्रमिक वाले श्रम का विरोध किया है। इन सब बातों पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि उन मध्यस्थों ने भी जन्होंने अपनी भूमि का मूल्य दिया किन्तु उन तरीकों से कई गुना अधिक कितानों से वसूल किया किरक्षति—पूर्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है? वे किस बीज की अतिपूर्ति चाहते हैं। उन्होंने बहुत पहिले ही केवल लगान के द्वारा नहीं अपितु, अवैध प्राप्तियों द्वारा अपना मूल्य वसूल कर लिया है और यदि कोई लेखा—जोखा किया जाय तो जनींदारों को किसानों के पक्ष में भुगतान करना असंभव हो जाय। गरीब किसान ने अपना खून पतीना एक करके जमींदार को अनुबद्ध लगान ही नहीं दिया, उस भूमि का समस्त मूल्य ही नहीं चुकाया जिस पर वह कृषि कर रहा है, किन्तु जमींदार की इच्छानुसार हरप्रकार के उनके आनन्द के लिए अब क्षति—पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ताल्लुके—दारों के विषय में तो यह प्रश्न और भी कम उठता है जिन्होंने वह भूमि राष्ट्र को धोखा देकर प्राप्त की। इससे ज्यादा सख्त कोई शख्त मुआविज के खिलाफ क्या कह सकता है? आचार्य जो को दर्व हो रहा है मुआविजा देते हुये लेकिन कानून उनको मजबूर कर रहा था, मुल्क की वह गुलामी मजबूर कर रही थी जो कि अंग्रेजी राज्य ने हमारे ऊपर डाली थी। इसलिय वह कहते हैं:—

Thus if under the present law the zamindari system could be abolished without the payment of any compensation it would be most equitable to all the parties. But unfortunately section 299 of the Government of India Act requires that compensation must be paid for the transference to public ownership of any land and that the amount of compensation or the principle upon which it is to be determined must be laid down. We have, therefore, to determine the principle upon which the amount of compensation to be paid to intermediaries is to be determined.

(इस तकार यदि वर्त प्रांत का तून के अन्तर्गत जमींदारी प्रथा जिना क्षतिपूर्ति दिये समाप्त की जाती है तो यह सभी पन्नों के लिये न्याय संगत बात होगी। किन्तु दुर्भाग्य से गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का से इशन २९९ में आदेश है कि भिन्न के स्वत्व के हस्तान्तरण पर क्षति—पूर्ति अवश्य दो जाय ओर भीत —पूर्ति की यनराशि या वह तिद्धान्त जिस पर यह निर्धारित की जाय अवश्य लिखित होनी चाहिए। अतः हमें उस तिद्धान्त को निर्धारित करना चाहिए जिसके आधार पर अति—पूर्ति को यनराशि निर्धारित की जाय जो मध्यस्थ को दो जाय)।

जैसा नैंने पड़ा, आवार्य जी अपने इस बयान में निहायत साफ-साफ कहते हैं कि इस वक्त जो हनारे मुन्त की गुलामीं हैं, जिस कानून में हम बंधे हुये हैं, उसकी वजह से हम मआवजा देने के लिये मजबूर हैं। उसके खिलाफ हमें कहने या करने का हक नहीं है। सर्फ हम मुआविजे का प्रितिपल डिटरमिन कर दें यह निहायत जरूरी है। उसके आगे वह कहते हैं:--

One of the claims advanced by the zamindars is that the compensation must be of a nature as to maintain their present income. Some of them go to the length of saying that they must be paid an amount which yields an annual income equal to the rents they receive. The tota annual rental demanded at present is about Rs. 24 crores. To talk of an amount yielding an annual interest of 24 crores is simply fantastic and does not deserve any examination. The next claim put by the zamindars is that they should be paid full market price prevailing at present. Even though the claim of the zamindars for full market price is not justifiable on other grounds it is absolutely impossible for the State to pay. The total area of land under cultivation in 1942 was 3, 307 crores of acres out of which 59.6 lacs was under sir and khudkasht and 2.711 crores held by various classes of tenants. Even if we pay the price of the land held by the tenants alone, and put it at a flat rate of Rs. 500 per acre it comes to Rs. 1356 crores

If this amount were spread over a period of 50 years even which is an inordinately long period the annual amount of payment of compensation comes to Rs. 27 crores which is absolutely impossible for the state to pay.

If to this we add the market price of sir and khudkasht as well the amount comes to Rs. 33 crores per annum which is simply fabulous. Then it is neither expedient nor feasible to pay the zamindars at the prevailing market price.

The next question is about paying the zamindars under the Land Acquisition Act which means about 31 times the revenue demand. This again is not feasible. The Land Acquisition Act was meant for acquisition of small portions of land in which case a fairly high rate could be paid. But this is not possible where the entire landed property of the province is going to be acquired. This posistively is also ruled out.

(ज्ञांदारों का एक दावा यह भी है कि क्षति—पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जो उनकी वर्तमान न्याय के बरावर हो। कुछ तो यहां तक कह बैठते हैं कि उनको ऐसी धनराधि क्षति—पूर्ति के स्थान में मिलनी चाहिए जिससे उतनी ही आय हो जितनी उन्हें किसानों से मिलती है। वार्षिक लगान जो उन्हें इस समय प्राप्त होता है २४ करोड़ रुपये होते हैं। ऐसा कहना कि उनको इतनी धनराशि मिले जिससे वार्षिक आय २४ करोड़ रुपये हो एक कल्पना मात्र है, अतः इस पर विचार की आवश्यकता नहीं।

दूतर। तमंशरों का दावा यह है कि उन्हें इतना मूल्य जिलना चाहिए जितना इस समय देश ने आब हो । चाहे जनोंशरों का वर्तमान भाव का दावा न्याय गत नहीं है इतना देना राज्य के लिए असंभवहें। १९४२ में जिस क्षत्र में कृषि हो रही थीं, वह ३.३०७ करीड़ एकड़ है, इसनें से ५९.६ लाख एकड़ सीर और खुदकारत की भूषि है और २.७११ करोड़ एकड़ अने के प्रकार के किसानों के पास है। जो भूमि केवल किसानों के पास हो और उतका मूल्य ५०० ६० प्रति एकड़ भी दिया जाय तो कुल १३ अरब ५६ करोड़ रुपया देना पड़ेगा। यदि यह धन राश्चि ५० वर्ष में दो जाय, हालांकि यह एक बहुत लम्बी अवधि है तो भी प्रतिवर्ष २७ करोड़ रुपये देने पड़ेंगे यह भी राज्य के लिए देना सर्वथा असंभव है यदि इसके साथ हम सीर और खुदकारत की कीमत आम भाव से भी जोंड़ें तो यह धनराश्चि ३३ करोड़ प्रतिवर्ष होगो जो कि एक मनगड़न्त जोज है। फिर जमींदारों को वर्तमान भाव से पूल्य देना न तो उचित ही है और न न्यायसंगत ही।

आका प्रश्न ज्ञांशिरों को लेंड एक्वोजीशन ऐक्ट के अन्तर्गत मूल्य देने का है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लगान की मांग से ३० गुना। यह भी उचित नहीं है। लेंड एक्वी—जीशन ऐक्ट का अभिप्राय छोटे—छोटे जमीन के हिस्सों का प्राप्त करना था, ऐसे मामले में बहुत ऊंबी की मत दी जाती थी। किन्तु यह ऐसे मामले में संभव नहीं है जहां प्रांत की समस्त भूमि प्राप्त की जा रही हो। यह भी सर्वथा अनियमित है।

माननीय माल सचित्र-इससे तो एबालीशन में देर होगी।

श्री रेश्चान जमा खा—मुझे अफनोम ह कि ह्यारे दूसरे दोस्त यानी रामकुभार जी जसे लोग कहे तो कहे, बजीर माल साहब भी जहा कहीं बाहर जाते हु और जब यह कानून जुलाई के सेशन में पेश हुआ था, उन्होंने आवार्र हों के नाम पर भारता जानी थी और यह कहा था कि उनकी तो बहुत जगदा कह है। तो अब जबिक मुशामार्य की के बयान को पृद देन हाउस के सामने पेश कर रहा हूँ तो उनको जगदा बेमबी से काम गृही लेना चाहिये। यह जबर ह कि जिस बीज का यह व्यान करते फिरते ह वह इससे राजित नही होती। म जानता हूँ कि उनकी सारी इमारत, उन्हा नहा महल, जो अहीने अपनी दलीको हा नवार कि माथा, वह आचार्य जी के इन व्यान के पढ़ने के बाद सममता कर बैठ जाता ह। लेकिन में महज इसिलिये कि आचार्य जी पर जो मलत इल्जाभात लगाये गये थे उनको दूर कर दिया जाय इसिलिये इन व्यान का पढ़ना जरूरी समझता हूं।

Thus the only sound principle which can be applied in determining the amount of compensation is the principle which is based not only upon the interest of the saminiars but also on the capacity of the State to pay, otherwise it would be reduced to a man prous wish incapable of realisation. We are of the opinion that the only principle that can be applied is neither of the full market price nor of full compensation but the principle of making an equitable provision.

(अत केनल एक ही उचित सिद्धान्त जोिक क्षितिपूर्ति की रकम के निर्धारण में लागू किया जा सकता है, ऐसा सिद्धान्त हैं कि जो जमीवारों के हित के आधार पर नहीं हैं किन्तु वह राज्य की देने की योग्यता पर भी आधृत है अन्यथा यह केवल एक पित्र आशा ही रह जायगी जिपसे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारी यह सम्मति है कि जो सिद्धान्त लागू किया जाग वह आम भाव का मिद्धान्त भी न हो और न वह पूर्ण क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त भी हो किन्तु वह एक ऐसा सिद्धान्त हो जिसके अनुसार उचित रकम दे वी जाय।)

अब आगे आचार्य जी अपने इम बयान में उन जमीदारों के लिये एफ स्केल बताते हैं और वह यह है कि:--

- 1. Zamindais paying lind revenue up to Rs. 100 to be paid 25 times their revenue demand.
- 2. Zamınd»rs paying land revenue between Rs 100 and Rs. 250/- 20 times.

```
3.
4.
5.
7.
8. 250 and R: 700/- 15
7.
R: 500 and R: 1,000 12
7.
R: 1,000 and over 10
7.
8. 5,00,000/- which ever is less.
```

therefore, we lay the following principles for the rehabilitation of the ex-propriated zamindars:

(अतः हम भूतपूर्व सम्पत्ति धारी जमीदारों की पुनर्व्यवस्था के लिए निम्नलिखित ग्नि निर्धारित करते हैं:—

१-- जमीं बार को जो कि १०० रु० तक भूमिकर देते हैं उन्हें उनकी लगान की की माग का २५ गुना दिया जाय।

```
२—जो १०० से २५० के बीच देते है उन्हें २० गुना
३—जो २५० से ५०० ,, ५१ ,,
४—जो ५०० से १,००० ,, १२ ,,
५—जो १,००० से अधिक ,, १० ,,
य ५,००,०००० रु० जो भी कम हो।)
```

उस वक्त आचार्य जी ने यह कहा था कि ५ लाख से ज्यादा मुआविजा किसी शख्स को पाने का हक नहीं है।

"This scale is meant only for arable land but so far as waste land, grove land, forest s, tanks pasture lands and abidi lands are concerned no compensation ought to be paid except the most nominal, say Rs. 2 per acre, in order to comply with the provisions of the Government of India Act. Similar is the case for sir and Khudkasht and laud left in the possession of the intermediary.

According to this scale the total amount the State would be required to pay will come approximately to Rs. 100/- crores. It is not possible to pay it in a lump sum. To a large extent it has to be paid out of the rents realised from the peasantry. The total rental demand at present is approximately 24 crores."

(यह स्केल केवल कृषि-युक्त भूमि के लिए हैं, किन्तु जहां तक बंजर भूमि, बाग वाली भूमि , जंगल, चरागाह और आबादी भूमियों का सम्बन्ध है कोई क्षति-पूर्ति न दी जानी चाहिए, केवल नाममात्र के लिये २ ६० एकड़ प्रति देना चाहिए, जिससे कि गवनं में आफ इंडिया ऐक्ट के आदेशों का पालन हो सके। इसी प्रकार सीर, खुदकाश्त तथा उधि भिम के विषय में भी जो मध्यस्थ के पास है।

इस स्केल के अनुसार राज्य की ओर से जो धनराशि दी जायगी वह लगभग १ अरब रुपये होगी। यह एक ही बार नहीं दी जा सकती। यह प्रायः उस रुपये में से दी जायगी जो लगान के रूप में किसान से वसूल किया जायगा। इस समय कुल लगान की मांग लगभग २४ करोड़ रुपये हैं।)

तो अगर आचार्य जी अपने लिये, कैबीनेट के लिये, कांग्रेस पार्टी के साथियों के लिये इतने ही पूज्य हैं तो क्या आपने कोई छूट दी किसान को?

बजाय इसके हमारी सरकार १८० करोड़ रुपया जमा करने का इरादा कर रही है।

After the abolition of the zamindari system we must give remission to the tenant; to the extent of 4 crores. The collection charges of the rents at 13 per cent, come to 2.6 crores leaving the net total of 174 crores. This is accounted for as follows:

Government revenue at present realised ... 7 crores

Loss of revenue from stamps, court fees

and registration. ... 2

Improvement of Agriculture ... 4 ,,

Balance left in the hands of the Government 4.4 ,,

TOTAL 17.4 crores

Thus we are left with Rs. 4 crores approximately. To this we can add another Rs. 4 crores which we shall realise as rents from the sir and Khudkasht land of intermediaries and the tenants settled on the new lands. This will enable us to pay Rs. 8 crores per annum to the expropriated zamindars. We are of the opinion that all amounts of compensation up to Rs. 1000 to be paid in a lump sum in the very first year and the rest be spread over 15 years. In order to meet the amount payable in a lump sum the Government has to raise loan.

श्री रोशन जमा खां]

Besides the superior and inferior proprietors the following classes of intermediaries should also be compensated:

- (1) Permanent tenure holders;
- (2) Tenants holding on special terms in Avaih; and
- (3) Occupancy tenants

जमींदारी प्रथा के विनाश के बाद हमें किसानों को ४ करोड़ तक की छूट देती चाहिए। लगान के इकट्ठा करने का खर्चा १३ प्रतिशत के हिसाब से २.६ करोड़ होता है जिसमें कुल योग १७.४ करोड़ सम्मिलित नहीं हे। इसका लेखा इस प्रकार है—

सरकारी कर जो इत समय वसूल हो चुका .. ७ करोड़ स्टाम्प, कोर्ट फीस और रिजस्ट्रेशन के न्यून कर .. २ करोड़ कृषि का सुधार .. ४ करोड़ सरकार के हाथ में शेष रकम . .. ४.४ करोड़

कुल योग .. १७.४ करोड़

इस प्रकार हमारे पास प्राय: ४ करोड़ रुपये हे। इसके साथ ४ करोड़ और भी जोड़ विये जायंगे जो हम मध्यस्थों की सीर और खुदकाइत भूमि से नवीन भूमि वाले किसानो से वसूल करेगे। इससे हम भूतपूर्व भूमि मालिक जमीदारों को प्रति वर्ष ८ करोड़ रुपये दे सकेंगे। हमारी सम्मति है कि १,००० ६० तक क्षतिपूर्ति की धन—राशि पहले वर्ष एक मुक्त दे देनी चाहिए और शेष १५ वर्षों में विभक्त कर दी जाय। इस एक मुक्त रक्तम को देने के लिये सरकार को ऋण लेना होगा।

छोटे और बड़े जमींदारों के अतिरिक्त निम्नलिखित मध्यस्थों को भी क्षति-पूर्ति मिलनी चाहिए:—

(१) स्थायी खातेदार,

(२) कि सान जिन्हे अवध में विशेष शर्त पर जोत मिली है, और

(३) साधिकार (आकूपेसी) किसान।

यह सारा बयान है जो आचार्य जी ने उस वक्त यानी सन् १९४७ ई० में दिया था। उसके पढ़ने से बहुत सी बातें साफ साफ मालूम होती है एक तो यह कि आचार्य जी को यह कह कर बदनाम करना कि वह मुआवजे के उसूल की तस्लीम कर चुके थे महज गलत है। वह खुद कहते हैं कि जमींदारों को न तो मुआविजा पाने का हक है और न कानून और अखलाक के बम्जिब देना चाहिए। लेकिन मजबूरी यह है कि हमारा मुल्क गुलाम है और हम मजबूर है कि गवर्न मेंट आफ इंडिया ऐक्ट की दफा २९९ को नहीं बदल सकते। इसलिये मुआवजां देना जरूरी है। इस मजबूरी की हालत में उन्होंने इस उसूल को तस्लीम किया था। फिर भी उन्होंने कुछ उसूल रखें है एक तो यह कि जायदाद की बिना पर किसी को मुआवजा पाने का हक नहीं है । चुनांचे साफ साफ कह दिया है कि किसी शख्रा को पांच लाख रुपये से ज्यादा मुआवजा पाने का हक नही है। इस उसूल को सोशलिस्ट पार्टी तस्लोम करती है और यह कहती है कि एक लाख रुपये से ज्यादा किसी को मुआवजा नहीं देना चाहिये। इस कानून में इस उसूल को भी खत्म कर दिया गया है। जो मौजूदा कानून है उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी शहस को एक सीमा तक मुआवजा दिया जायेगा। इससे ज्यादा नहीं दिया जायगा। दूसरा उसूल यह है कि इस मुआवजे का बार किसानों पर नहीं पड़ना चाहिये उन्होंने साफ साफ यह कह दिया या कि अगर इसी तरह से देना है तो साल ब साल ८ करोड़ दिपया जो किसानों का लगान है उससे अदा कर सकते हैं लेकिन हमारी सरकार बहादुर आज क्या कर रही है ? यह तो आप सब लोगों को मालूम ही है। वह तो यह कहते थे कि २४ करोड़ में से कुछ तो प्रामों को तरक्की के लिये छोड़ हें और कुछ वह मालगुजारी की शक्ल में ले लें और कुछ रूपया किसानों से लेकर जमींदारों को अदा कर दें। आजकल जो लगान है उसका एक तिहाई हिस्सा लें ले। लेकिन मौजूदा सरकार इस बिल के जिरये क्या कर रही है। वह कहती है कि हम मौजूदा लगान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है।

इस मौके पर में सब्स्टैन्शियल जमींदारों का जो खौफ़ तारी ह उसका जिक करता हूं। सर-कार हमारी कहती है कि क्योंकि इन सब्स्टैन्शियल जमींदार साहबान को मुआबिजा अदा करना है लिहाजा तुम १० साल का लगान पेशगी अदा कर दो। इस हकीकत को मानते हुए भी कि हमारे सूबे में ८५ फीसदी से ज्यादा ऐसे किसान बसते हैं जिनके पास खाने भर को भी पैदा नहीं होता उनसे यह मतालबा करना कि १० साल का लगान अदा करो कहां तक इंसाफ पर मबनी है इस पर आप खुद ही गौर फरमायें। आप तो सारा बार किसानों पर डाल रहे हैं आचार्य जी अपने, बयान में किसानों पर कोई बार नहीं डाल रहे हैं। वह कहते हैं कि अगर मजीद रुपया देना भी है तो सरकार कर्जा ले लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप तो किसानों का गला दबा रहें हैं। उनसे आप १० साल का लगान देने को कह रहे हैं जिससे आप जमींदारों को मुआविजा देंगे।

आचार्य जी ने यह जो बयान दिया उसकी बिना पर यह कहना कि उन्होंने जमींदारों को मुआविजा देने के उसूल को तसलीम किया गलत है। उन्होंने १०० करोड़ रुपया मैक्जीमम एमाउँट देने को कहा, सोशिलस्ट पार्टी ने ५० करोड़ कहा लेकिन आपकी सरकार ने किसी भी मेवजीमम एमाउंट को नहीं माना, हां सरकार कहती है कि जितना भी हिसाब लगाने से आ जाये वह दिया जायगा । तो ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि जो तीन उसूल आचार्य नरेन्द्र देव जी ने ले डाउन किये उनका आपने खून किया। और आपका यह कहना कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी मुआविज के सवाल को तसलीम कर चुके हैं, महज गलत है। देर के लिए आइये हम आपकी खातिर, रामकुमार जी के खातिर, वजीर माल साहब के खातिर, कांग्रेस की बेन्चेज पर बैठे हुए दोस्तों की खातिर माने लेते हैं कि आचार्य जी ने तसलीम किया था। वजीर आजम साहब और वजीर माल साहब सरका र की पूरी मशीनरी अपने कड़जे में रखते हुए जिस रिपोर्ट को बनाने में उन्हें ३ साल लगे हों, उस रिपोर्ट की बनियादों से हट कर उन्होंने यह क़ानून जुलाई में बनाया और अब जो मजीद ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में यह कानून आया, उसमें भी आपने तरमीमात कर दीं। क्या वजरा को इस बात का अख्तियार है ? वजीर आजम साहब पिछली कौंसिल में अपीजिशन के लीडर थे, वह ती बहुत पुराने काम करने वाले हैं, वह तो अपनी राय वक्तन फवक्तन बदल सकते हैं लेकिन अगर आचार्य नरेन्द्र देव जी अपनी राय बदल दें तो एक जुर्म करार दे दिया जाता है, उसका एक मखील उड़ाया जाता है। क्या यह तरीका अख्तियार करके आपने अपना मजाक नहीं उड़ाया ? जब जुलाई के सेशन में कांग्रेस की तरफ से हमारे वजरा साहब ने और दूसरे कांग्रेसी दोस्तों ने आचार्य जी का नाम बराबर लिया तो उन्होंने एक मजमून लिखा जो किताब की शक्ल में छप चुका है और जो पैम्फलेट की शक्ल में भी छप चुका है और बजीर माल साहब ने गालिबन उसे देखा भी होगा। उसमें उन्हों ने आखिर में यह कहा है कि अगर हमारी बुद्धि पर इतना ज्यादा भरोसा है तो जरा थोड़ा सा और भरोसा ज्यादा कर दीजिये और जो कुछ मैंने कहा था अगर वह उसुल आप सरासर मान लें तो अब भी में सोशिज़िस्ट पार्टी से खशामद करूंगा कि आप मेरी राय अपना लें। लेकिन यहां तो यह है "मीठा मीठा हप, कड़ुवा कड़वा थू।" जिस चीज के माने किसी हद तक सरकार के माफिक लगाये जा सकते हैं उसे तो सरकार तसलीम करने को तैयार है, मगर पूरा का पूरा बयान तसलीम करने को तैयार नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। न इसकी दलील का कोई तरीका बताया जा सकता है। जहां तक सोशिलस्ट पार्टी का ताल्लुक़ है उसकी आचार्य जी की राय की, बदलने का हक़ था। सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार जो अपनी राय जमींदारी के मिटाने और मुआविजा

[श्री रोशन जमां खां]

देने के बारे में दी वह अमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट छपने के बाद दी। औं अव्वल वक्त से कह दिया एक लाख से ज्यादा किसी को मुआविजा नहीं दिया जा सकता है और पांच करोड़ से ज्यादा कुल मुआविजा नहीं दिया जा सकता है। इतमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप कहें कि आचार्य जी अपने बयान से हट गये या सोशलिस्ट पार्टी ने अपनी राय बदल दी। राय बदलना हमारे लिये और आपके लिये, हालात के बमूजिब हमेशा मुनासिब है। लिकन सवाल यह होता है कि जो राय में या आप तब्दीली कर रहे हैं वह फहां तक सही है। जता मैने अर्ज किया आवार्य जी का इस बारे में बारबार नाम लेना और यह कहना कि यह कांग्रेस और सरकार की स्कीमों की ताई द करते हैं, सरासर गलत है।

श्रो द्वरिका प्रस द मौर्य--अपा में आनरेबिल मेम्बर से एक सवाल पूछ सकता हूं? जमीन के नालिक कितान हों या सरकार, इसको जरा साफ कर दीजिए।

श्रा रे। रात जमां खं — जहां तक सरकार के जनीन का मालिक होने का ताल्लुक है अगर आपने इन बिल को पढ़ लिया होता तो बहुत अच्छा होता। में उन दका को पढ़ कर ऐवान का व्यत बर्बाद नहीं करना चाहता जिसके जिरये से खुद इस बिल में इस बात को कहा गया है कि जिस दिन जमीं दारों मिटाने का नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन जमींनों के नारे राइट्स और इंटरेस्ट्स सरकार के हो जायंगे। उमके बाद इस बिल में उसूल है कि उसके बाद सरकार कुछ लोगों को अधिकार देती है। जहां तक सोशलिह पार्टी का सवाल है, मैने सुबह अर्ज कर दिया था कि "दि टिलर आफ दि स्वायल शुड बी दि मास्टर आफ दि लेंड हो कल्टीवेड्स।" जमीन जोतने वाला ही उस जनान का मालिक हो जिसे वह जोतता है। मैं नहीं समझता कि इससेज्यादा वजाहत की क्या जरूरत है।

माननीय माल सिव--में आपके जरिये से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने जो कहा है, वह कह दें।

श्रा राजाराम शास्त्री--में यह चाहता हूं कि सरकार की तरक से आचार्य जी के बयान को छात्रा कर भवत में बटवा दिया जाय।

मान नीय मात सिचित्र -- में आति है जाति से भाननीय सहस्य से पूछना चाहता हूं कि करा उनको आवार्य नरेन्द्र देव जी के बरान के उस हिस्से की जो इस प्वाइंट पर है कि जनींदारी अवालियन होने के बाद कि तानों को प्रोप्राइटरी राइट्स दिये जायं या न दिये जायं, पढ़ने में कोई गुरेज हैं?

श्रो रे| दान जमा खां—मुझे तो उस बयान के किसी लग्ज से गुरज नहीं था चुनांचे मैंने पूरा बयान पढ़ दिया और वह चीज जो मैंने पढ़ी थी उसके बारे में आप इस बात का भी स्थाल रक्खें कि जब कांग्रेस बेंचेज पर बेंठे एक साथी श्री रामकुमार जी ने खुद यह मतालिंबा किया कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने सन् १९४७ ई० में जमींदारी अवालीशन कमेटी के सामने क्या कहा था। आप सोशालिस्ट पार्टी के बयान को और आचार्य जी के बयान को जो मैंने यहां पढ़ा है और जो सोशिलस्ट पार्टी के एलानात हो चुके हैं उसको मिला देते हैं। हमने सोशिलस्ट पार्टी के एलान में साफ काफ कह दिया है कि टिलर आफ दि स्वायल शुंड बी दि मास्टर आफ दि लंड ही कल्टीवेट्स। जमीन जोतने वाला ही उस जमीन का मालिक हो जिसे वह जोतता है उसके बाद यह सवाल उठता नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र--ओनर या मास्टर।

श्रो राशन जमां खां--डिक्शनरी देखिये या किसी टीचर से पूछिये कि ओनर और मास्टर में क्या फर्क होता है।

डिप्टी स्पीकर--आप मुझको ही मुखातिब करते रहे। मुझे अफसोस होता है कि जब आप मुझे छोड़ कर दूसरे की मुखातिब करने लगते हैं।

श्री राज्ञान जमां खां—-आचार्य जी के बयान को (जिसे कांग्रेस के दोस्तों ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है में कहूँ हदीस कुरान या गीता के बराबर पढ़ा है) पढ़ने के बाद क्या उन्होंने, आचार्य जी ने कांग्रेस अग्रेरियन कमेटी के सामने जो गवाही दी है उसकी भी पढ़ा है? उसको क्यों बिलकुल भूल जाते हैं और उसका जिक्र तक नहीं करते। में उनसे निहायत अदब के साथ कहूँगा कि वह उस गवाही को देखें और उस बयान को भी देखें और जब उसमें आचार्य जी ने बार-बार यह कह दिया कि मैं वह मुआदि के उसूल को नहीं मानते तो फिर किसी माहब को यह हक नहीं है कि वह यह कहें कि उनको अपनी राय बदलने का हक नहीं है।

जनाबवाला इसके बाद एक बड़ा भारी सवाल यह पैदा होता है कि मुआदिज का भार किस पर पड़े। हमारी सरकार मुआविज के सारे बोझ को सूबे के किसानों पर डालना चाहती है और उसने यह एलान किया कि वह इस सूबे के बसने वालों से, सूबे के काइतकारों से १८० करोड़ रुपया दसूल करेगी। २ अक्टूबर सन् १९४९ ई को जब दस गुना लगान की वसूली शुरू की गई उस वक्त जो बयान सरकार की तरफ से दिया गया था वह यह था कि तीन महीने के अन्दर यानी ३१ दिसम्बर तक कुल १८० करोड़ रुपया दसूल हो जायगा और इस सूबे से प्यूडलिज्म का खारमा हो जायगा। मैने कहते हुये सुना है, इसकी हक़ीक़त को तो वही समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस बात को वहा कि कुछ साहबान कांग्रेस में और गवर्नमेंट में ऐसे थे कि जो यह कहते थे कि छः हपते के अन्दर सारा १८० करोड़ रुपया दसूल हो जायगा लेकिन हालत दया है? ३१ दिसम्बर के अन्दर बहुत फर्ग्र के साथ इस बात का ऐलान किया गया है कि १२ करोड़ रुपया दसूल हो गया। कहां १८० करोड़ और कहां १२ करोड़ और उसमें भी बहुत कुछ फर्जी रकमे दिख ई गई हैं। माननीय माल सचिव—क्वेडचन (गलत)—

श्री रोशन जमां खां—फर्जी रक्तम का आप हवाला चाहते हैं तो मैं जनाव दर्जीर माल साहब से आपके तवस्सुत से कहना चाहता हूँ कि मेरी तक़रीर के लग्बे होने की सारी जिम्मेदारी आपके दोस्तों पर हैं, वे सब्खि पर स्वाल कर रहे हैं। मैं सब्खित के जवाबात देने से नहीं घबराता, बोलन के लिये शाम तक बोल स्वता हूँ, ५-४ दिन बोल सकता हूँ; लेकिन मुझे इसके लिये मुजरिम न ठहराइये।

पकसदस्य--फर्जी जवाब न दें?

र शनजमांख--

फर्जी इस तरह से हैं कि मसलन एक खाते वाले ने, जिसके खाते का लगान २० रुपया है, दो रुपया जमा कर दिया तो यह मान िलया गया कि कुल लगान जमा हो गया और इसी तरह से २० रु० जमा समझ िलया गया है। मैं तो कहता हूँ कि जितने नक्तो आपके पास इस सिलिसिले में हैं वे सब फर्जी हैं, सब ग़लत हैं। एक चीज आपने और की हैं कि जो को आपरेटिव सोसाइटीज हैं, केन सोसाइटीज हैं उनसे एक प्रस्ताब यह पास कराया गया है कि जो रुपया उनके पास किसानों का है वह उससे इस गुना लगान अदा कर दें। यहां तक किया गया है कि एक एक खते में चार-चार आहि स्यों ने रुपया जमा किया है। इस तरह से यह १२ करोड़ की रक्तम ऐसी हैं जिसमें से बहुत ज्यादा रक्तम वापिस करनी होगी दयों कि वह कानून के बमूजिब आपके पास रह नहीं सकती। सही मानों में जो सही काइतकार है उन्होंने रुपया अभी तक जमा नहीं किया है हालांकि आपकी हुकूमत की दमन की स्शीनरी बहुत तेज हो गई है। मैं तो साफ साफ कहता हैं कि आपकी जो १० साला लगान जमा करने की स्कीम थी वह बिलकुल ऐल हुई है, नाकामयाब हुई है और शायद इससे ज्यादा नाकामयाबी आपको किसी स्कीम में नहीं हुई होगी।

एक सदस्य-इससे आपको खुशी हुई होगी।

जी, हां खुशी हैं। हम तो इसके मुखालिफ हैं ही और इसकी नाकामयाब बनाना चाहते हैं। उसकी नाकामी का नमूना अभी इस बिल में मौजूद है, जिससे कि हमारे लायक कांग्रेसी दोस्तों को भी इन्कार नहीं हो सकता। वे भी इसकी मानते

श्री रोशन जमां खां]

है कि रुपया वसूल नहीं हो रहा है। वसूलयाबी की मियाद अब तक ३१ दिसम्बर थी, अब बढ़ा कर वह फरवरी कर दी गई है। उन्होंने फिर यह भी सोचा कि ये जो २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले मालगुजार है उनके जो काश्तकार है उनको फोरी मोरूसी काश्तकारी का हक दे देना चाहिये ताकि वे राया जना कर दे। हम उनके इस ख्याल से बहुत खुश है कि उन्होंने मोहती काश्तकारी का हक दिया, लेकिन जो में अर्ज कर रहा हूँ वह यह है कि पहनरकी बहुँ जो आपने निकाली है कि उनसे भी स्पया वसल हो जाय। इसके अलावा जो सबसे बडी ज्यादती आपने की है और जो निहायत ही गलन है वह यह है कि जब आपने यह अस्पुल ले डाउन किया है कि ६। एकड़ से कम वाले खाते का बटवारा नहीं हो सकता तो फिर रुपया वसूल करने के लिये आपने यह भी रक्खा है कि अगर वह बाहते हैं तो जिनका खाता ६। एकड़ से कम है उसका बटबारा भी हो सकता है। क्या आप फिर भी अपनी नाकामयाबी को डंके की चोट पर एलान नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं बता रहे हैं कि आपकी सारी स्कीम खत्म हो चुकी है, नाकामयाबी रही है और अपनी अर्म मिटाने के लिये आप सारी कोशिश कर रहे हैं। दस साला लगान वसूल करने के लिये आपने यह भी बेहूदगी की है कि अपना दमन चेक जोरों पर चला रहे हैं। जो बन्दूक वाले हैं, आर्म्स वाले हैं, उनको बुला कर आपके डिग्टी कलेक्टर साहब कहते है कि अपना दस साला लगान दो जवाब मिलता है कि मै तो जमींदार हूँ, में तो काश्तकार नहीं हूँ, मुझको दस सालाना लगान नहीं देना है, तो उनसे कहा जाता है कि अगर नहीं देना है तो वसूल कराइये। वे कहते है कि उनका कोई जोर नहीं है, वह शहर में रहते हैं, देहात उनके असर में नहीं है तो उनसे कहा जाता है कि आपका लाइसेंस रख लिया जाता है। आप १५ दिन के बाद आइये और बताइये कि आपने कितना वसूल करवाया । क्या जिस तरह से अंग्रेजी हुकुमत में हो रहा था, जिस तरह से वार फंड जमा कराया जा रहा था उसी तरह से आपकी हक्मत इस दस साला लगान को वायुल नहीं कर रही है। फिर जाब्ता फौजदारी की दफा १०७ और ११७ क़ायम रहे उसका भी इस्तेमाल निहायत आजादी के साथ हो रहा है।

एक सदस्य-क्या इनकी कोई मिसाल है।

माननीय माल सचिव--मिसाल बता दीजिये।

श्री रोशन जमां म्वां—हमारे जिले में मौजा हरिक शुन है उसमें १० गुना लगान जमा नहीं हुआ तो वहां एक आदमी ने दूसरे आदिमयों के ज़िलाफ एक रियोर्ट लिखाई कि फलां फलां आदमी रात को बैठे हुये यह कह रहे थे कि लगान मत दो।

एक सद्स्य--में नाम जानना चाहता हूँ कि कि अके खिलाफ रिपोर्ट दी गई।

श्रो रोद्दान जमां खां——नाम आप अपने आफोसर्स से पूछ लीजिये और वह तो जनाब की कान्स्टी टुएन्सी का ही है।

एक सदस्य-क्या वही जहां पटवारी मारा गया था?

श्री रोशन जमां खां--किसी गांव म नहीं मारा गया। आप गलन कह रहे हैं।

डिप्टी स्पीकर--में आपको कई बार कह चुका हैं कि आप दूसरी तरक तबज्जुहन हों।

श्री रोशन जमा खां—कांग्रेस की बेंचों में खलबली मच जाती है जब मै कोई बात बताता हूँ और चारों तरफ से शोर होने लगता है।

हिष्टी रूपीकर--हर एक आदमी अपनी तरक मृतवङ्जह करना चाहता है लेकिन आप मुझ ही तक तवज्जह रिखये।

श्रो रोशन जमां खां--जहां तक आपके डिव्टी कलेक्टर्स का सवाल है, अवालन में जब कोई मुक़दमा पेश होता है। प क सद :य--कहा होना चाहिये ?

श्री रोशन जमां खां—जब मुकदमा पेश होता है तो मुकदमेबाजों से सवाल होता है कि आपने १० गुना लगान जमा किया है या नहीं। और जब तक आप रुपया जमा नहीं करेंगे रोजाना मुकदमे की पेशी होगी और मुकदमा फैसिल नहीं होगा। तहसील शर साहब तल बगंज ने कई अर्जी नवीसो की मुअतली का आर्डर दे दिया ओर कहा कि आपने १० गुना रुपया क्यों नहीं जमा किया? वह तहरीरी असली हुक्म मेरे पास है, अगर माननीय वजीर माल साहब या दूमरे का गेसी दोस्त उसे देखना चाहें, तो मैं वह पेश करने को तैयार हैं।

एक मद न्य--वह आपके पास कैसे है, वह तो अर्जी नदीसों के पास होना चाहिये ?

श्री रोशन जमां खां—इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन अर्जीनवीसों ने यह लिखा कि उनके नाम में कोई खाता नहीं हैं और यह इल्जाम लगाना कि रुपया जमा नहीं किया गया है, बिलकुल गलन है। यह इल्जाम लगाना निहायत जुल्म है। अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी मेंने इसका जिन्न किया, लेकिन में देखता हूँ कि उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज गवर्नमेंट अपने बनाये हुने कानून को, असेम्बली के बनाये कानून को खुद तोड़ रही हैं। कानून के बमूजिब इस रुपये के जमा कराने में आपकी गवर्नमेंट मुजरिन हैं। आपको उसके लिये सजा मिलनी चाहिये। अभी पूरक बजट तो आया नहीं। में तो बहुत सी आशाये लेकर आया था कि सप्लीमेटरी बजट देखने को निजेगा उनमें देखा जायगा कि इस दस गुने लगान को वमूल करने के लिये किन—किन मदों से रुपया दिया जा रहा है।

मेरी मालूमात यह है कि प्राविशिय र काग्रेस कमेटी को बहुत अच्छी खासी रकम दी गयी है। एक सदस्य—कितनी?

श्री रीशन जमा खां—गालिबन ५० हजार और आपने सरकारी सवारियों का जिस तरह गलत इस्तेमाल इस बारे में किया है वह भी बहुत ही काबिले मलामन है। यह हमारे दोस्त बहुत जोर से शोर करते हैं। जरा लखनऊ के उन काग्रेसी दोस्तों के बयानात को पढिये जो कहते ह कि १० गुना लगान की वसूली में जो इम्दाद सरकारी सवारियों या रुपया—पैसा से काग्रेस वालों को की जा रही है उससे कांग्रेस वाले अपनी दलबंदी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले। आपके बीच में बैठे हुये, आपके अंग बने हुये लोग जब एसी बातें करते ह, उसके बाद भी आप कहते हैं कि दमन चक्र नही है। सुना जाता है कि इस सूबा के कुछ अखबारात ऐसे हैं, जिनको इस सरकार ने कुछ रुपया दिया है और यह कहा है कि वह दस साला लगान की वसूली की मुआफकत में अगर मजामीन छापें तो उनकी इतनी इतनी कारियां खरीदी जायेगी और उनकी इम्दाद की जायेगी।

शूगर फैक्ट्रीज से यह कहा जाता है कि जिन काश कारों ने १० साला लगान अदा कर दिया है उनके साथ आप रिआयते करे और आपके यहां उनका जो रुपया है उसको आप दस साला लगान के अदा करने में मुजरा कर दें। गन्ने के दाम में जो कटौती होती है उसके लिए एक बात यह कही गयी है कि अगर कोई किसान यह कहे कि हम दस साला लगान देना चाहते है तो उसके लिए यह आसन पैदा की जाय कि यह दो आना की कटौनी जो बाद में अदा होती वह आज हो अदा हो जाय।

इसके अलावा पटवारियों की तनख्वाहे रोकी गयी और उन तनख्वाहों को रोक करके उनको १० साला लगान की वसूली में लिया गया । तकावी का रुपया एक तरफ कागज पर लिखा जाता है कि फलां किसान को दिया गया लेकिन उसी जगह दूसरा क्लर्क यह लिख लेता है कि हमने दस साला लगान में वनूल पाया । तकावी का कानून इस तरह का नही है कि उस रुपया को दस साला लगान की वसूलो में लिख लिया जाय । अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ही अपने कानून का उन्लंघन करते हैं । माननीय माल सचिय—आपकी इजाजत से म अपने लायक दोस्त से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा काश्तकार है किस जिले में, किस तहसील में, किस मोजे में जिसकी तकावी उसके दस गुना लगान में जमा की गयी हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—जब मिनिस्टर साहब यह पूछते है कि ऐसे आदमी का नाम बताया जाय, तो क्या वह इस बात की गारंटी कर सकते है कि जब हम ऐसा मामला पेश करें तो वह उनके नीचे के कर्मचारी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे?

श्रो र शन त्रमा खां—जनाब वाला हमारे जिले में आम तौर पर ऐसा किया गया है, और दूसरे जिलों से भी ऐसी इत्तलाआत आई है। हमारे वजीर साहब उन लोगों का नाम जानना चाहते हैं जिनका तकावी का रुपया दस साला लगान में बसूल कर लिया गया है लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अंग्रेज़ी हुकूमत की मशीनरी जिस कदर दमनात्मक थी उससे ज्यादा दमनात्मक आज उनकी मशीनरी है। अगर वह काश्तकार शिकायते करे तो उसका घर में रहना मुश्किल हो जायेगा। में इस मौके पर जिला बिजनौर की धर्मपुर फैक्ट्री का जिक करना चाहता हूं।

धर्मपुर शुगर फैक्टरी के किसानों को जब यह एहसास हुआ कि उनका रुपया दस साला लगान में ले लिया जायगा तो वहां की सोशलिस्ट पार्टी के कारकूनों ने किसानों को समझाया और किसानों ने यह तय किया कि अब हम ग्रंबनायेगे और अपना गन्न। शुगर फैक्टरी को नहीं देगे। तो उसका जवाब सरकार की तरफ से यह दिया जाता है कि सरकार ने सोशलिस्ट पार्टी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। मगर उसका नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि वहां पर गन्ने वालों ने हड़ताल कर दी और मजबूर होकर सरकार को मोशलिस्ट पार्टी के कारकुनों को छो उना पड़ा और यह धांधली जो सरकार करने वाली थी उसको सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकत्ताओं ने चलने नहीं दिया। आज भी मुझे एक इत्तिला दी गयी है और वह यह है कि बाराबंकी जिले के बुढवल मिल में इस बात का इन्तजाम किया गया है। आपके डिप्टी कलक्टरों और आफिसरों ने इस बात का इन्तजाम किया है कि जो लोग दस गुना लगान देकर भूमिधर बन गये 🖰 उनकी गा ी वजन करके उनको दाम दे दिया जाय और जो नहीं बने है उनको न दिया जाय । यह क्या है ? क्या यह जुल्म नहीं है ? क्या यह दमन नहीं है ? क्या यह बेइंसांफी नहीं है ? क्या यह कातून का तो हो नहीं है ? जिस कानून को आपने बनाया उसी की आपती 'रहे हैं ? क्या यह कानेन की तोहीनी नहीं है ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जालिमाना कानन और जालिमाना बर्ताव करने के बावजूद भी कराब तीन महीने में मिर्फ १२ करो ! हो १८० करो ! मे से अप वमूल कर पाये है जो आपके लिये बायसे शर्म है और सोचने का मौका है। आपको इसके ऊपर सोचना चाहिये और इस गलत स्कीम को, इस गलत योजना को छोड़ देना आपने जो दस साला लगान वसूल करने का यह कान्न बनाया है वह सरकार की डिलेइंग टैक्टिक्स (विलम्बकारी चालांकियां) ही मालुम होती है। सरकार यह चाहती है कि जितनी भी देर जमींदारी मिटाने के कानून में ही सकती हो की जाय और इसीलिये आपने दस साला लगान की वसूली का ढोंग रचा है ओर यह बात इससे भी साबित होती है कि सरकार देर करना चाहती है, वह यों कि आज भी जब कि बिल ज्वांयट सेलेक्ट कमेटी से वापस आया है तो उसमे भी कोई निश्चित तारीख मुकर्रर नही की गयी है। किस तारीख से सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जायगा। न आप इस सूब से जल्दी जमींदारी को पत्म करना चाहते है और न पूरे सूबे में एक साथ आप जमींदारी को मिटाने जा रहे है। तो यह डिलेइंग टैक्टिज नहीं है तो और क्या है ? तरह से जमींदारी मिटाने के कानून में देर करना चाहते है तो फिर आपका यह कहना जेबा नहीं देता कि आप जमींदारी भिटाने के लिये बहुत ज्यादा उत्सुक और ख्वाहिशमन्द है।

अब इस दस साला लगान की वसूली के बारे में मुझे कुछ चन्द बातें और कहना है। में आनरेबिल वजीर माल साहब के एक वक्तव्य का जिक्र करूंगा। रायबरेली जिले में एक जगह हमारे वजीरे माल साहब के बहुत कुछ दिया और समुद्र पार करते हुये पहुंचे और वहां आपने कहा कि किसानों, दस साला लगान तुम लोग अदा कर दो, हमें अदा कर दो, कांग्रेस सरकार को अदा कर दो और सोशल्स्टि पार्टी के आने पर वापस मांग लेना। रिफंड क्लेम कर लेना। म आनरेबिल वजीर माल साहब में पूछना चाहता हूं कि ये बाते जो अखबारों में छपी थी क्या ऐसा उन्होंने कहा था या नहीं? क्या ये बाते सही नहीं है?

माननीय मान सचिव--जी, विलकुल सही है।

श्री रे। शन जमां खां——उन्होने मिसाल हो नही बल्कि दलील भी दी कि जिस तरह से सन् १९४२ ई० में अंग्रेजी हुक नत ने बहुत कुछ जुर्माना कांग्रेसी लोगों से वसूल किया था और बाद में जब हमारी कांग्रेस सरकार आई तो उसने सब को वायस कर दिया।

अब जरा आप इस बुलाद ख्याली पर ख्याल फरमाये कि एक जम्हूरी हुकूमत का वजीर कह रहा है और वह वजीर कह रहा है जो इस बिल का स्पान्सर करने वाला है। क्या वजीरे माल का मतलब यह है कि इस मूबे के रहने वाले यह समझें कि आप जनता पर उसी तरह से यह जुर्माना कर रहे हे जिस तरह से अंग्रेजी सरकार ने सन् १९४२ ई० में किया था। जब किसी पार्टी की सरकार अपनी पालिसी की वजह से कोई गलती करती है और उसकी मुखालफत दूसरी पार्टी किया करती है तो वह पार्टी किसी तरह से सरकार की गलती की जिम्मेदार नहीं हुआ करती। क्या इस वक्त आपका वही दर्जा है जो सन् १९४२ ई० में अंग्रेजों का था और क्या अब यह जो दस साला लगान वसूल किया जा रहा है यह कोई जुर्मांना है क्या सोशलिस्ट पार्टी का और आपका वही ताल्लुक है जैसा कि आपका सन् ४२ में अंग्रेजों के साथ था? अगर यह बात हो तो में मान सकता हूं बरना आपको इस पर गौर करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि कांग्रेस बेचों पर बठन वाले दोस्त वजीर म ल से कोई सवाल इसके बारे में नही पूछते कि वह इस तरह की बाते क्यों कहा करते है जो निराधार है।

जनाब वाला, दस साला लगान की बनूली बहुत बुरी तरह से नाकाय हुई है और इस स्कीम का जो अभी तक नतीजा रहा है उससे तो एक समझदार सरकार को यह सबक लेना चाहिये कि वह इस स्कीम को खतम कर दे, छोड़ दे ओर जनींदारी को खतम करने के लिये कोई दूसरा प्रयत्न करे। और अगर इस चीज का हिसाब लगाया जाये कि १२ करोड़ रुपया तीन महीने में वसूल हो सका है तो १८० करोड़ रुपया के बसूल करने में ४५ महीने लग जांयगे। तीन साल से कम में तो यह वसूल नहीं होगा। मान लीजिये कि आपने अपना दमन चक्र तेजी से चलाया तो साल भर तो कम से कम इसमें लग ही जायगा। जब कि जैसा पं० जबाहरलाल नेहरू ने कहा है कि अगली सिंद्यों में चुनाव होने वाला है यह स्कीम आपकी धरी रह जायगी और मुमिकन है कि यह स्कीम बिला पूरी हुए ही रह जाये और सरकार अपनी गद्दी से हट जाय। आप ऐसी बाते करते हैं। बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, पता नहीं कि क्या हो। आप ४० साल के हिसाब की बाते करते हैं, दो साल की बाते करते हैं और साल भर का इन्तजाम करते हैं। यह चीज बिलकुल नामुनासिब हैं। आपको इस चीज को वायस लेना चाहिये। आप यह चाहते हैं कि सूबे के लोगों को कशमकश में रखें उनको गैर यकीनी हाल ने से रखें। अगर आप इसके। अपनी बोटों के। मजबूत करने का तरीका ही बनाना चाहें तो इसकी बात दूसरी है।

जनाब वाला, मुझे कहना तो बहुत कुछ है। मैने काफी वक्त ऐवान का लिया है। मुझे जब दूसरी रीडिंग के वक्त मौका मिलेगा तो मैं और बाते कहूंगा। इसलिये मैं अब अपनी तकरीर को खतम करना चाहता हूं लेकिन चन्द बाते आखिर में अपने दोस्तों से जरूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि आप जो कानून बना रहे हैं उस कानून से गरीबों की गरीबी और मजबूरों की मजबूरी दूर नहीं होती है।

उससे मालदारों को फायदा हो सकता है और गरीब किसानों और खेती करने वालों का कोई फायदा नहीं है और मौजूदा समाज की जो बुनियाद है उसमे कोई तबदीली नहीं होती हैं। लिहाजा आपको समझदारी से काम लेना चाहिए और दोबारा गौर करना चाहिए और जिस तरह से आप यह मौजूदा बिल लाए है उसको बदलने की कोशिश कीजिए तािक यह काम सही बुनियादों पर हो सके और जमींदारी मिदाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाइए और ज्यादा देर न कीजिए वर्ना इससे सुबे के लोगों का और गरीबों का ज्यादा नुकसान होगा।

श्री राम कुमार शास्त्रो—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो जमींदारी उन्मूलन बिल विशिष्ट सिमिति द्वारा संशोधित होकर सभा भवन के सामने उपस्थित किया गया है में उसका हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूं। जमीदारी उन्मलन योजना के संबंध में हमारी सरकार ने विश्वास मानिए जो अपने प्रान्त की तथा समस्त भारतवर्ष की खास तौर से किसानों की सेवा की है उसका कोई मुकाबला हमारे इतिहास में अभी तक नहीं पाया जाता है। हम ज्यों ज्यों इस स्कीम को कार्य रूप में परिणित होते हुए देखते हैं और उसकी रचना की तरफ गौर करते हैं

हों साथ ही यह भी विश्वास बढ़ता जाता है कि हमारी सरकार ने जो उत्तम प्रकार का आर्थिक ढांचा बनाने की व्यवस्था की है वह सर्वोत्तम हैं और वह हमारे हृदय की भावनाओ और आर्थिक विचारों को पूरा करती रहेगी। माननीय सभासद गण ?

डिप्टी न्धीकर--आप स्पीकर को ही मुखातिब करे, यही यहां का तरीका है।

श्री राम कुमार शाही--डिप्टी स्पीकर साहब, में रोशन जमा था साहब के व्याख्यान को जब जब सुनता हूं तब तब मेरे मन पर यह भाव प्रकट होता जाता है कि वह जमीदारी उन्मुलन बिल से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं बल्कि वह इस भवन के जरिए से अपने समाजवादी विचारों का प्रान्त में प्रचार करना चाहते हैं। उन्होंने जब कमपैन्सेशन (मुआविजा) दस गुना लगान, रिहै-बिलिटेशन ग्रान्ट (पुर्नवास अनुदान) आदि का जिक्र किया तो उसमे उन्होने सिवा इसके कि किस तरह से ज्यादती हो रही है और जुल्म हो रहा है और कुछ नही कहा। जो स्कीम (योजना) इस सूबे में भूमिधरी की रायज हो रही है और जिसका प्रचार प्रान्त के कोने कोने में हो रहा है और जिसमें हमें काफी सफलता भी मिलती जा रही है उसको हमें हमेशा विशाल हृदयता और अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए और ऐसा ही श्रो रोशनजमां यां का भी ख्याल होना चाहिए। वह इस संशोधित बिल की मखौल उडाना चाहते हैं लेकिन में उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहता हूं कि २८ सितम्बर से रोजबरोज न मालूम हमारे और हमारे साथियों के कितने दिन किसान भाइयों के बीच गुजरे है और उनके द्वारा लाखों रुपया दस गुना बसूल हो रहा है और होता रहेगा। जो सज्जन कहते हैं कि अलीगढ़ और गोंडा जिले में सरकारी अधिकारियो द्वारा किसानो पर तथा सरपंचों और लाइसेंसी बन्दूको पर ज्यादितयां की जा रही है उनका हमेशा यह भाव और विचार रहता है कि जिस से यहां के बैठे हुये सदस्यों और गैलरी के दर्शक लोगों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ें और वे दूसरी तरफ हो जांग । लेकिन आप विश्वास जानिए कि रोशन जमां साहब कहते कुछ और है और बात वास्तव में कुछ और होती है।

प्रान्त का आर्थिक ढांचा जो बनने जा रहा है उस सिलसिले में हर एक किसान भाई दिल खोलकर दसगुना लगान जमा करना चाहता है और घूमी भूमिधर बन रहा है। शिकायत इस बात की रोशन जमां साहब करते हैं कि चीनी की फैक्ट्रियों से किसान रुपया लेते हैं और खुशी से दसगुने का रुपया नहीं देते हैं। में श्रीमान के द्वारा उनने पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी मिसाल वह बता सकते हैं कि कहां से कर्जा या उधार अथवा दाम लिया जा सकता है और किस आधार पर? अगर किसान भाई के घर रुपया—पैसा संयोग से नहीं हैं और अपने खेत की ईख तोला कर या बेच कर रुपया लेते हैं और सरकारी खजाने में जमा करते हैं तो कौन सी ज्यादंती हुई? अगर मिल वाले उनको ईख के खरीदने की सुविधा और दाम तथा उनको भूमिधर बनने में सहायता पहुंचाते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? अपने देश कीय दि आर्थिक स्थित सुधारना है तो थोड़ी सी सुविधा उनको मिल गई अर्थात् उनकी गाड़ियां पहले तौल ली जायें या पर्ची के जिरयें किसान को रुपया मिल जाय तो क्या यह जुल्म हैं? इसे ज्यादती आप कहते हैं। जुल्म का मियार क्या यही है ? में समझता हूं कि श्री रोशन जमां साहब की जितनी

बातें हैं अथवा जितनी उनकी दलीलें हैं वे सब थोड़ी हैं। वह इस स्कोम का वास्तव में मजाक उड़ाना चाहते हैं

श्रीमान डिप्टो स्पीकर साहब, खां साहब ने यह भी बताया है कि दसगुना लगान के सिलसिले में बन्द्रक के लाइसेंस दिये गये लोगों को धमकाया गया। मैं आपके जरिये उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई जमींदार जिसकी ज्यादती तोड़ फोड़ करने की आदत रही है और वे यदि अपनी जमींदारी के किसानों को दबाना चाहते हैं और जिन्हें लाइसेंस बन्दूक के मिले हैं और बराबर धमकी देते हैं तो क्या उन्हें रोकना चेतावनी देना कि अगर इस प्रकार कार्य करेंगे तो अनुचित होगा क्या यह जुल्म करना है ? उनसे पूछा जाय कि जो बन्दूक दी गई है यदि उसका दुरुपयोग हो तो मनाही नहीं करना चाहिये? क्या यह ज्यादती हुई ? में उनसे पूछुंगा कि शासन कैसे चलेगा ? शासन का क्या ढंग हो सकता है वे ही बतायें। उनको पूछना चाहिये यह बहुत साधारण बात है वह तो तरह-तरह से हमारी जनित्रय कांग्रेस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। में श्रीमान के द्वारा उनसे पनः पूछुंगा कि वह इस प्रकार का प्रक्न उठाकर ज्यादती करते हैं। मेरे मित्र ने यह भी कहा है कि आठ एकड़ का होना ठीक नहीं, साढे छः एकड़ ठीक है। वह तो पड़े-लिखे वकील है । आखिर यहां पर बहुत से साथी बैठे हुये हैं जिन्होंने कानून को खूब पढ़ा है और उनका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं । प्रधान मंत्री पं० गोबिन्द बल्लभ पन्त की सारी जिन्दगी किसानों के कल्याण में गुजरी हैं क्या वह आठ एकड़ और ६॥ एकड़ का फर्क नहीं समझते हैं ? मैं समझता हूं कि यह सारी बातें सामने रखकर जायज समझा गया है। इससे तो किसानों का कल्याण ही होने वाला है। उन्होंने वह चीज पेश की है जिससे वह खेती में उचित ढंग से लाभ प्राप्त कर सकें। लागत कम लगें और उपज अधिक हो वहीं खेती लाभदायक होती है। इसी से आठ एक ! माना गया है। एक हल की जोत हो सकती है आठ एकड़ में। कम छोटे बैलों से हो सकती है। लेकिन १० एकड़ तक एक बरेबैल-हल से अच्छी तरह जोत सकते हैं। यह कहना मुनासिब नहीं मालूम होता है। सरकार इस बात को समझती नहीं है। राजाराम शास्त्री को यह बात पसन्द होती तो उन्होंने उन रिपोर्टी और बयानात को जिन्हें आचार्य जी ने समय-समय पर दिये थे जनता के सामने उपस्थित किया होता या अखबारों और समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया होता। क्योंकि शिष्य के नाते उनको अधिकार हो सकता है। श्री रोज्ञन जमां साहब इधर-उधर की गड़ी बातों को कहते हैं। तुलसीदास की रामायण की टीका सबको पसन्द नहीं। भाई राजाराम को टीका करने का पूर्ण अधिकार है। हजुरवाला रोशन जमां लां रिपोर्ट की निची की बात छोड़ गये। उस रिपोर्ट के किसी कोने में इस बात का भी जिक है कि किसान को मालिकाना हक नहीं दिया जायगा। जमीन का स्वामित्व स्टेट के हाथ में होगा। इससे स्पष्ट हुआ कि समाजवादी किसानों को मालिकाना हक नहीं देना चाहते हैं केवल हवा की बातों से गुपराह करके किसानों की सहान् भृति चाहते हैं।

क्या यही इतनी देर तक आप क्यान कर रहे थे? क्या इसी छ्वर बात को सामने रख कर आपने इस हाउस का इतना वक्त वरबाद किया? में उनके ध्यान को आकि का करना चाहता हूं कि वह मेहरबानी करके ऐसी बातें न कहें। आचार्य नरेन्द्रदेव जी की हमारे जितने भी कांग्रेस में सदस्य हैं कदर करते हैं और उनके पाण्डित्य का सदैव हम सम्मान करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी बात वह कह गये हैं कि जमींदारों को मुआवजा देना चाहिये, उनको मुआवजा देना उचित हैं तो उसको आपको भी मानना चाहिये। न मालूम कितने जमींदार भाइयों ने अपनी गांठ के रुपये को लगा कर जमींन खरीदी हैं वे मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। हमारे किसान के कंथे इतने जबरदस्त व मजबूत नहीं हैं कि बाजार भाव के भार को वह सह सकें। जो थोड़ा बहुत वह दे सकते हैं उसको दे करके वह जमीन लेगा ताकि वह मुफ्तखोरा न कहलाये। हम चाहते हैं कि जमींदारों को

[श्री रामकुमार शास्त्री]

कुछ अवश्य िया जाय। मानकीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी का निश्चित मत उस समय रहा है। चाहे वह गर्यनमेट आफ इंडिया ऐक्ट के जमाने की बात हो उन्होंने इस राय को समझ—बूझ कर दिया है। जमीपारी प्रथा तो उस जमाने से आज तक उसी पसे चली आ रही है उसमें जरा भी फर्क नही हुआ है। इसचित्रे उनको सुआवजा देना जिसे आचार्य जी कह चुके हे वह ठोक है आर देना चाहिये। उनको तमाम ऐसी बातों को भी याद रखना चाहिये जो देश के लिये अपप्रद राजाचार्य जो की जो उचित बाते हे उनको मानना रोशन जमां का कर्तव्य है। मीदारो को सुआवजा देना है। लेकिन जब हम सुआवजा देने को बात करते है तो उनमें समाज्याको रोज अट हाते हैं और गांवों में जाकर तरह—तरह की बात कहते हैं जिसते हमारी यह स्कोम नाकाश्रा हो। किसान दमगुना देकर भूमियर वन रहा है।

हुजूर वाला, भुझको अच्छी तरह से मालून है कि जिम जिले का मे प्रतिनिधित्व करता हं वहाँ पर इस प्रकार के आदमी नहीं है; वहां तो आर० एस० पी० के लोग है कम्युनिस्ट है और सोशल्स्टि भाई भी है। किन्तु इसकी संख्या नाममात्र की है और कुछ प्रभाव भी मुझें उस दिन की बात बाद है जब लखनऊ में बड़ा जलूस पहुचा । मै भी अपने हलके में दोरा कर रहा था। बंध शोर सचा था कि लखनऊ के शहर में एक बड़ा भारी जन्या सूबे के कोने-कोने रें जा रहा है। श्रीमान् बस्ती जिले में में रहत। हं उसकी २८ लाख की अखादी है। मेने भी दौरा करके शुमार करना शुरू किया और अपने भ।इयो से पूछा कि अ.पके यहां से कितने आदभी लखनऊ गये है ? विश्वास मानिये हुजूर १०-२० जादमी से ज्यादा लखनऊ नहीं आये थे। यह कहना कि किसानों पर ज्यादितयां हो रही है गलत है। मेरे वहां कोई ज्यादतो नहीं हुई है। सूत्रे से कितने रामाजयादी प्रतिनिधि आये है। इसका एक उदाहरण आगके द्वारा भवन के तमाम सदस्यों के सामने उपस्थित करता हूं। वह इस तरह से है कि बस्ती जिले के कलेक्टरेट कावहरी के मैदान के पामने एक जल्हा बहुत छोटा जा रहा था जिसमे आर० एत० एत० के लोग रहे, आर० एत० पी० के लोग रहे और कम्युनिस्ट भो रहे। साथ ही दो-चार फुटकर लोग भी थे, ज्यादा से ज्यादा कुल ५० आदमी होंगे। उनका स्लोगन समाजवारो जिन्दाबाद, दशगुना लगान मत दो रहा जहां कहा गया कि दस गुनालगान मत दो उस पर तो उनकी राय मिलतो रही लेकिन जब कहा जाता रहा कि समाजवाद जिन्दाबाद लब या दूसरी तरक से यह आत्राज उठती रही कि आर० एप० पो० जिन्दाबाद स्पाज गर्द घोला है। एक दूसरे दल को कता जाता रहा कि घोखा है। इस किस्म को अवनी स्थिति तथा चालों को लेकर आप इस प्रान्त की गार-पांच करोड़ जनता की कितने दिनों तक धोखे में रख जकते हैं? इस तरह से नाय किसानों को कब तक बर्गलायेगे ? इस तरह किसानों को मगाहते मे डाल कर क्या आप किसानों को गुमराह करना चाहते है ? उन पर ज्यादितयों का जिक कर के जो ज्यादितयां नहीं है, हमारे अहलकारों को बदनाम करना चाहते हैं। मै बस्ती जिले के कलेस्टर डिप्टो कलेक्टर्स के साथ कई दिनों तक जिले के कोने-कोने में दोरा करना रहा हूं। लेकिन मुझे एक भी जि़कायत इस किल्म की नहीं भिली। मुमकिन है कि कोई छोटी-मोटो शिकायत हुई हो। लेकिन उनके अपर कोई टार्चर हुआ हो, मैने तो देखा और सुना नहीं। मालूम नहीं गोंडे को कचहरी में बैठ करके, उस छोटी सी कोठरी वाले दपतर में कहां से उनको ऐसी बातों का पता चलता रहा है। आइचर्य की बात है। हुजूरवाला मै समझता है कि आपके इस ब्याख्यान का मतलब सिवाय थियायत वातावरण पैवा करने के और कुछ नहीं है। इससे वह अपने समाजवाद का प्रचार कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं िक्वांस है जनता अपने भले-बुरे को अच्छ। तरह जानती है। उसे गुमराह करने का प्रयत्न असफल रहेगा।

दसगुना लगान जमा करने के सिलिसले में में यह जानता हूं कि हमारे लीडर्स ने भी बडे-बडे प्रोसेशन निकाले हैं। दो दिसम्बर का वाक्या में सदस्यों के लामने उपस्थित करना चाहता हं। दो दिसम्बर को एक काफी लम्बा जुलुस जिसमें लगभग ६ हजार आदमी पांच सौ झंडों को लेकरके जिसमें जमीदार उनके जिलेंदार और बड़े-बड़े किसान जिनकी मालगुजारी १ लाख, २ लाख और ढाई लाख रुपये की है सियत है वह बीसों सुत्रज्जित हाथियों २०-२५ घोड़ों के साथ और झंडों को फहराते हुये बस्ती जिले की बढ़नों बाजार से ले करके इटवा थाना तक पहुंचे और साढ़े छियालिस हजार रुपया एक दिन में उन्होंने खजाने में जमा कर दिया। में रोशन जमां साहब के ध्यान को आकिंषत करना चाहता हूं बस्ती जिले की ओर और गोंडा जिले का जिन्न में नहीं करना चाहता हूं। उसे वह सब जानते होंगे मैं वस्ती जिले का जित्र कर अपना निजी अनुभव बता रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक तहसील में नहीं, हरैया, बांसी इमरियागंज में २८ दिसम्बर से लेकर ५ जनवरी तक मैं बराबर दौरा करता रहा और मेरे साथ में जमींदार श्रिक और व्यापारी सभी लोग मौजद थे। एक भी शिकायत वहां नहीं मिली जैसी वह बयान करते हैं। ३८ लाख रुपया से अधिक अब तक उस जिले से एकत्र हुआ जिस क्षेत्र का में प्रतिनिधित्व करता हुं वहां से भी २० लाख या २२ लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। किसी किस्स की शिकायतें हमको नहीं मिलीं। आचार्य जी की सारों गायायें जितनी भी उन्होंने अपनी लेखन तथा वनतत्वकला से की हैं क्यों नहीं कोई चीज ऐसी कहीं लिखी हो, उसको उठा करके यहां पर वह रखते हैं ? मुझे तो भय मालूम होता है और आशंका होती है उनके कथन की सत्यता पर। में दावे के साथ नहीं कहता कि कुछ बातें छोड़ दी गयी हैं। लेकिन सुझको भ्रम होता है कि उस स्टेटमेंट में भ्रमात्मक बातों को रख करके जनता को और यहां के लोगों को ऐसे भाम में उन्हा जाता है कि हमारी यह जमींदारी उन्मूलन कोष के एकत्र करने की स्कीम कामयाब न हो। यह स्कीम जनता से और सरकार में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करती है। यह भेरा विश्वास है अगर कोई सरपंच कायदे के खिलाफ कोई काम करता है तो क्या आपकी ही शासन-अयवस्था में जो शोशलिस्ट जमाने में यदि हो तो गल्जी करने की क्या आप चेतावनी भी न देंगे? इसमें दमन-चन्न कहां से हुआ ?

आखिर हम लोग भी तो काम करने वाले हैं। हमारा भी तो सारे प्रान्त में जाल फैला हुआ है और ऐसे बक्त में हमने इस स्कीम को कामयाब बनाया है जिस बक्त हमारे पास कोई फनल नहीं थी उस समय हमने इतना रुपया एकत्रित किया, क्या यह गौरव को बात नहीं ? अगर हमने कि सी तरह की ज्यादती की होती जैसा कि साम्प्राज्यवादी सरकार जो आपको अंग्रेज सरकार वहां रह चकी है उसने की थी, तो आज सुबे का किसान हमारे साथ कदापि न होता। उस सरकार ने लोगों का लोटा और थाली तक विकवाया और लोगों को मुरमा तक बनाया यह सब उन्होंने वार-फंड के लिये किया था। अगर आप कोई ऐसी मिताल जुल्म की दे देवें तो में कह सकता हूं कि हां हमसे कुछ गलती हुई है। आजकल के जमाने में रुपया एकत्र करना कोई आसान बात नहीं है। में भूरि-भूरि प्रशंसा करता हं अपने अहलकारान की कि उन्होंने इस स्कोम को कामयाब बनाया है। जिन पटवारियों के बारे में निन्दा की जाती है में उनकी प्रशंक्षा जोरदार शब्दों में करता हूं और बुलन्द आवाज में। आज १२ करोड़ रुपया जो मिला है, उसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों का हाथ रहा है। इसका तो में यहां दावा नहीं करता कि उनमें कोई कमी नहीं है लेकिन इस स्कीम को और पंचायती राज्य को सफल बनाने में पटवारियों का जबरदस्त हाथ रहा है इसे में तस्लीम करता है। इस स्कीम के द्वारा सरकार का जनता से बहत ही घितिष्ट सम्बन्ध और सम्पर्क रहा है। अब हमको इस दसगुना लगान के सिलसिले में गांव-गांव में भ्यमण करना पड़ रहा है। नये-नये अनुभव हो रहे हैं।

किसानों को हम ऊंचे स्थान पर पहुंचाते हैं जल्द से जल्द दसगुना लगान जमा करके हमें उनको एक ऐसे ढांचे पर लाना है जिससे वह अपने खेतों में

[श्री रामकुमार शास्त्री]

ज्यादा अन्न पैदा कर सके और अपने खेतों पर मालिकाना हक पा सके। पंचायतों के बारे में आप जिक्र करके विलेज रिपब्लिक की बात कहते हैं। सुनिए, दुनिया में अमरीका और रूस तथा अन्य देशों में डेमोक्रेसी है। लेकिन में बड़ी शान के साथ कहता हूं कि जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारे यहां होने जा रही है उस तरह की कही और नहीं हो अकती। हो सकता है कि प्रारम्भ में कुछ ब्रुटियां रह गई हों इसे में मानता हूं। जो अपने यहां की सुन्दर व्यवस्था हो रही है उसके लिये शुरू में कुछ गलतियों का होना स्वाभाविक रा है लेकिन मुझे उसकी सफलता पर काफी संतोष है। श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, जो व्यवस्था पंचायतों की की गई है जिसके बारे में आप लोग शिकायत करते है उसकी देखते हुये मे तो यह कहंगा कि पंचायतो तथा इस स्कीम द्वारा सरकार प्रान्त के कोने-कोने में गरीब के घर-घर पर अपने प्रतिनिधियों द्वारा पहुंच गई है, हर एक प्रतिनिधि गांवों में जाता है आला से आला आफिसर वहां जाने में ओर उस गरीब की दूदी चारपाई में गुरेज् नहीं करते। ब ल्कि पर बैठने जो दें सकता है उसको लेकर सरकारी खजाने में जमा कर देते हैं और गरीब-अमीर सब को उत्साहित करते हैं। आप कहते हैं कि न जाने उसमें से कितनी रकम गलत जमा होती है। इससे मन में आंशंका होती है। उसको जो खेत मिला है या जोतता है कहीं उससे चला न जाये इस भय से पहले उसे रखने के लिये जमा करता है यह उराको अपने कलेजे से चिपकाये रखना चाहता है और यह भी चाहता है कि उसकी चप्पा-चप्पा जमीन उसके कब्जे में रहे फिर १०, २० और ५० बोघे की तो बात ही क्या है। उसके पास जो थोड़ा बहुत रुपया होता है उसको वह चाहता है कि ऐसी जगह रखें ताकि वह खतरे वाली जमीन चली न जाये ओर इसके साथ ही साथ जो दखीलकारी यानी मौकसी जमीन होती है उस पर भी वह दसगुना लगान खुशी से जमा करता है। इस पर भी यह कहना कि फरजी रुपया जमा हो रहा है आधार रहित है तथा गलत बात है। ऐसी विकट सूरत भे गलत रोक—थाम में जब हम १२ करोड़ रुपया इक द्ठा करते है तो बजाय इसके कि हमको दाद दें उल्टे नुक्ताचीनी करते हैं। समाजवादी लोक वेस्टेंड इंट्रेस्ट से सहायता लेते हैं। म श्री रोशन जमां खां साहब की तो बात नहीं कहता लेकिन उनके बहुत से कारकुनान मुझे मिला करते हैं। वह लोग जमींदारों से ही पैशा लेते है और उनको बुरा-भला किसानों के समक्ष कहते हैं और उनके राग में राग भी अलापते है। आज यहां पर कहते हैं कि जमींदारी उन्मूलन होन चाहिये और कोई मुआवजा न दिया जाय। वह चाहते है कि यहां का आर्थिक ढांचा जो है वह बहुत नीचे दरजें का है जिनके पास जमीन ने हो उसको हम कहां से देवें ? कीन सी ऐसी जमीन है जिसे हम दूसरे से काट कर उनको दे दें ? जैसे कि सवाल लैन्डलेत लेबर के बारे में है। हम जानते है कि हमारा सूबा कृषिप्रधान है लेकिन जो कानून है उसके अन्तर्गत ही हमने चार तरह के जमीन दुकड़े मालिक वनाकर किये है एक भूमिधारी, दूसरे नीरदार, आतामी और अधिवासी है। २४ घंटे में कहीं जमींदारी हट नहीं तकती है। उनके बड़े नेता जो इस समय जेललाने में है उनका फरमाना था कि २४ घंटे में वह जमींदारी खत्म कर शकते जितको २०० वर्ष से जड़ जमी हुई है। उसे हटा कर हम चाहते है कि अनादि काल तक भूमिधर की प्रया रहे और उसके फलस्वरूप हमारे गरीब किसानों का आधिक ढांचा अच्छा मजबूत होता रहे। देर जो होती है उन्मुलन में उसमें आपकी यडी भारी जिम्मेदारी है। आप उन स्टेटमें इस वक्तव्यों पर बहस करते हैं जि को बारे में आपको पता तक नहीं है। इससे आप सभा-भवन का अम्लय समय व्यर्थ नव्द करते है।

अगर हमारे भाई राजाराम जी शास्त्री कुछ जिक करते होते तो ठीक होता। काफी समय तक वह भी आचार्य जी के शिष्य रहे और मैं भी रहा। जहां नाजुक वक्त की बात हो, आचार्य जी जो कुछ भी कह रहे हों, उसे खेलाड़ी की भांति मान लेना चाहिये, उसकी मुखालिफत नहीं करना चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मं रोशन जमा साहब की जो बहुत गलत और लचर दलीले ह उनका में इन थोड़े लक्जो के साथ घोर विरोध करता हूँ। जो हमारी जमीदारी उन्मूलन की स्कीम चल रही है और जो सफल हो रही है हर तरफ से, हर कोने पर कुछ समय के बाद हर किसान सूबे का, इसके मुताबिक भूमिधर अवश्य बनेगा, इसमें सन्देह नहीं। इस सफलना से हमें संतोष है और काग्रेस सरकार को इसके वास्ते हम बधाई देते । आशा है सरकार इसके द्वारा देश, प्रान्त व जिले की ग्रामीण जनता के आधिक ढांचे को सुधार कर उत्तम सेवा कर राम-राज्य की स्थापना करेगी।

श्री मुहःमट यृमुफ — जनाब डिप्टो स्पीकर साहब, मैकोई बड़ी तक़रीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। में इस हाउस में बहुत कुछ शोर—गुल कर चुका हूँ। जमीदारों पर जो दिक़्क़ते और मुमीप्ते आई है उनका में जित्र कर चुका हूँ। हमारे मिनिस्टर साहब और प्रीमियर साहब को उससे पूरी वाकिफ त है। अब तो वक्त यह है कि इसका सवाल नहीं होता आया। जमीदारी एढ़ालिश हो या न हो, वह स्टेज जो खत्म हो चुकी हैं। अगर हुक़्मत चाहनी है कि जमीदारी खत्म हो तो खुली हुई बात है कि कोई उसको रोक नहीं सकता। तमाम इख्तिलाफ त के होते हुए भी यह अख्तियार उनको है कि जमीदारी एबालिश करें। अगर वह समझती है कि एबालिशन से मुल्क का फायदा होगा, कौम का फायदा होगा, इक्त सादी हालत ब्लन्द होगी, हर शख्स खुश होगा तो इन हालात में जमीदारी का एबालीशन ज़करी मालूम होता है।

यह चीज साफ है कि वह स्टज खत्म हो चुकी कि आया जमीदारी का एबालिशन हो या न हो। अब सिर्फ मसला यह ह, कि अगर अबालिशन आफ जमीदारी होती है तो किस से होती है, और क्या-क्या चीजे ऐसी है जो तरमीम की जाएं जिससे यह बिल एक खुबसुरत बिल बन जाए और हर शब्स के हुकूक की हिफाजत हो सके। यह छोटे जमीदार है, यह बडे जमीदार है, यह भूमिधर है और यह सीरदार, इस किस्से मे पड़ कर अब कोई फायदा नहीं। अब तो अगर जमीदारी जाती है तो हमें देखना चाहिए कि कहां किस तरह से अबालिशन हम फौरन कर सकते है जिससे हमारी क़ौम की माली हालत दुरस्त हो सके। आजादी मिल गयी लेकिन आजादी के लिए यह जरूरी है कि अवाम की माली हालत बढ़े और हर तबका तरक्क़ी करे। यह नहीं कि फलां तबका मेजारिटी में है और फलां माइनारिटो में। यह ताक़त में है और वह नहीं। हमें सारी क्रौम को नुक्तेनिगाह से देखना है। आजादी के जितने फल हे उन्हे हमें हासिल करना है। अगर आप बेनुल अकवामी दुनिया मे एक वर्ल्ड सिटीजनिशिप के बेसिस पर इसे कर सकें तो अच्छा है, ताकि दुनिया में शान्ति रहे, दुनिया में तरक्की हो और दुनिया अपनी तफर्काती जंग को खत्म कर दे। और रवादारी की बिना पर मोहब्बत की बिना पर पहले मुत्तफिक़ क़ौम हो, मुत्तफिक एशिया और इंटरनेशनल सिटीजन-शिप हो। एल्लाक, मोहब्बत, लव (धार) और ब्रादरहुड (भातृभाव) का तख्ययुल यह मियार है जो हमारे सामने आता है।

यह जरूर है कि पहले नेशनलिज्म (र(ज्ट्रीयता) का सवाल आता है, क्यों कि जब तक हम भाई—चारा पैदा नहीं कर लेते और महात्मा गांधी के फिलसफें की बिना पर, समझौते की बिना पर, रवादारी की बिना पर, अकल की बिना पर, दिमाग की बिना पर अपने को समझ नहीं लेते हैं, अपनी इक्तसादी हालत को दुरुस्त करने के लिये अपनी तमाम पालिसी और स्कीमों को दुरुस्त करने के लिये, इंटरनेशनल बादरहुड तो आखिरी मझसद है हो, लेकिन पहले नेशनेलिज्म का सवाल आ जाता है, इसिलये इंटरनेशनल ब्रदरहुड तक पहुँचने के लिये नेशनलिज्म एक जरूरी चीज हो जाती है। हम महात्मा गांधी के फिलसफें को मान ने वाले है। उसी की बिना पर हम इम्पीरियलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, कालें—नियलिज्म को खत्म करना चाहते हैं और उसी की बिना पर हम कहते हैं कि हम तमाम बराइयां खत्म करने के लिये तैयार है और हमें उम्मीद है कि हम दुनिया के तमाम मर लो

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

को हल कर लेगे और एक निहायत बुलंद ओर खूबसूरत जिन्दगी पेदा कर सक्षेम, लड़ाई, जंग न होने पाये, भाई—भाई न लड़े, तजका—तबका न लड़े, न मजहब की बिना पर झगड़े रह जायं, और न तबके की बिना पर झगड़े रह जायं, और न तबके की बिना पर झगड़े रह जायं, ओर न पोलिटिकल इस्ति—लाफात की बिना पर झगड़े रह जायं, यह हमारो को जिज्ञ है।

इस बिल में एक चीज यह है कि हमारे मिनिस्टर जाहब ने जो इसके इंचार्ज ह, फरमाया कि हमने इसमे और तरमीमें कर वी है जा गालिबन लोगों की कुबूल होगी। एक तरमीम के मुताल्लिक से फोरन अर्ज करूँगा ओर वह है फियस्ड रेंटे टिनेटस के (द्वारह मुख्यार तदलकार) मुताल्लिक कि उनको आपने राइट्स दे दिये हं। यह एक बँड़ी चीज है कम से कम जह पूरबी जिलों का ताल्लुक हे, जोनपुर, आजमगढ़, बिलया, बनारस यकीनी बहुत उम्दा अपर होगा। लोग समझेगे कि यह चीज इन्साफ की बिना पर की गयी है। उसके बाद पं जानता हूँ कि इतका अक्षर अच्छा होगा जमोदारों के लिये भी। जमींदार भी आखिर में भूमिधर होगा। जमीदार के नाम से लोगों को इतनी नफरत हो गयी है कि उसका नाम बदल ही दिया जाय तो अच्छा है। यह ख्याल हो जाय कि सभी भूमियर है। कोई तबादुम ख्याल न रह जाय, बल्कि सुहब्बत का ख्याल हो, रवादारों का ख्याल हो, सच्चाई का ख्याल हो ओर हम अवनी जिन्दगी को निहायन खूबसूरत और बुलंद पना सके, ओर माली जिन्दगी की, सियासी जिन्दगी की, अखलाकी जिन्गी को दुरुत कर सके, चाहे तखय्युल कुछ भी हो, इस्तिलाफात कुछ भी हों। जब हमने आजादी हातिल कर ली है तो हमको उसे किसी बिना पर भी छोड़ना नहीं है, चाहे वह इिल्त गफाल की बिना हो, चाहे वह तसादुम की बिना हो, किसी भी बिना पर हम अपनी आजादी छोड़ने के लिये तैयार नहीं है। बल्कि हम यह चाहते है कि हमारी आजादी क्रायम रहे। लिहाजा अगर इस नुक्तेनिगाह से इस बिल को देखा जाय तो में यह अर्ज करने की जुरत कर सकता हूँ कि इस बिल में बहुत सी तरमीमात ऐसी है का तिकारों को यकीनी फायदा है। हो सकता है कि चन्द चीजे उसमें ऐसी भी हों जो कि बहुत क़ाबिल क़बूलन हों काश्तकारों के लिये और खासकर बड़े काश्त-कारों के लिये। लेकिन जहां तक जनरल इंटरेस्ट का सवाल है, जहां तक आमतौर पर कास्तकारों को स्कूक देने का मज़ला है और उनकी हालत को दुरस्त करने का ताल्लुक है इस बिल से उनको यक्नीनी फायदा होगा। लिहाजा सबको थोडा-थोड़ा सा सैकि-फाइत (त्राग) तो करना ही पड़ेगा ओर बग़ेर सैकिफाइस किये काम नहीं चल सकता। यह हो सकता है कि इसमें चन्द ऐसी चीजे हों जो काश्तकारों को काबिले क़बूल न हों लेकिन उसमें ऐसी चीजें भी है जो काश्तकारों के फायदे की जरूर है ओर वह ऐसी की गई है जो एक किस्म का एडजस्टमेट इंट्रेस्ट्स है। यह हो सकता है कि काश्तकारों को अब बाते पूरी न हुई ही क्योंकि यह इन्सानी फितरत है कि वह चाहता है कि और निले और मिले और मिले, लेकिन तवाजुम करना होता है, बेलेन्स कायम करना पड़ता ह और तराज़ में तोल करके बाते करनी चाहिये, ताकिए सी बाते न हों कि फलां के साथ फेजर (पञ्चपति) किया गया है या फला के साथ ज्यादती की गई है। यह बात ठीक है और बिलकुल सही है कि जहां तक काश्तकारों का ताल्लुक है उनके साथ इसमें इन्ताफ किया गया है, लेकिन जहां तक जमींदारों का ताल्लुक़ है उनको जिस हद तक इस बिल में जो मुआविजा रखा गया है उससे उतनी तशक्की नहीं हो सकती है जितनी होनी चाहिये। उसको यह मालूम होना चाहिये कि वह तबाह नहीं हो जायेगा उसकी हालत ऐसी हरगिज नहीं होगी कि उसके बाल-बच्चे तालीम न हासिल कर सकें और उसकी हालत इन्तहाई खराब हो जाय। जहां तक उनकी इक्तसादी हालत का ताल्लुक है वह तो इस बिल से खराब होती ही है, मगर अगर देखा जाय मिनहैसुल काम के और मिनहैं मुल्क के तो यह मानना पड़ेगा कि सब चीजों के देखते हुये जो कुछ भी दिया जा रहा है वह ऐसा है कि उनकी माली हालत किसी न किसी तरह चलती रहेगी, लेकिन इसमें

जो बाते रखी गई ह वह किसी तर के से इस तरह की नही ह जो जमीदारो को फाबिले कब्ल हो, लेकिन गवनंमेट की दिक्कतो को देलते हुये, करेन्सी की हालत हो देखते हुये, मुल्क को हालन को देखने हुये यह ८२ ल हमें भी है। अगर गवर्नमेट रहत कसीर रकम हमको देगों तो उनके लिये दिशकते पैदा हो जावे ।। और नेशन बिल्डिंग रू र्मेट्न जो एक बंडे लम्बे जमानेत क स्टार्न करना (भूषो २ रना) पडेगा। हम उन लोगो मे से नहीं है जो यह न पमझे कि गवर्नमेट की क्या जिस्मेदारिया है और गवर्नमेट के ाम पैसानही है तो अब हमारे पास कोई चारा नहा है हम सिर्फ गवर्नमेट से कह सकते ह कि आप ऐं। न करे िह हमारी रोटो छिन जाय । क्योकि हमारी भी जिम्मेदारी गवर्नमेट पर है । य_ि नजरिया मने आपके सामने रखा है कि आपको यह भी देखना है कि हमारी माली हालत को कैसे दुरुस्त करेगे। हमारी जिन्दगी अलग नहीं है हम भी यहां के हैं। हमारी जिन्दगी बधी हुई है अपने रिश्तेदारो अपने मुलााजमीन से, पिटलक से, गवर्नमेट के साथ, अवाम के साथ, हर उस तबके के साथ जिनकी जिन्दगी से हमारी जिन्दगी गुथी हुई ह उन उबसे है और एक दूसरे से वाबस्ता है। अशी हमने मुना था कि विचिल साहब पर हमला किया गया उनकी गवर्नमेट पर हमला किया गया कि उनकी हकमत के जमाने मे ११ लाख आदमी अनइम्प्लायड बेकार रहे। मझे बडी तकलीफ हुई। म सोचने लगा कि हमारे यहा अगर यह बोज पैदा हो जाये तो हम कैसे सम्हाल सकेंगे, हमारे लिये बड़ी दिक्कत होगी। मेरे कहने का मकसद यह है कि गवर्नशेट को यह कहना चाहिये कि हमारी माली हालत दुरस्त हो जाय अगर यह न हुआ तो बडी दिक्कन पैश आयेगी। चनावे आप समझ लीजिये कि एक करोड आदिमियों की माली हालत का सवाल ह। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि इनको माली हालत का अपर हमारे सुबे की रवादारी के लिये बेहद पड़ता है। जैपा कि हमला हुआ है कि आपके जमाने मे ११ लाख आदमी अनइम्प्लायड हे, उसी तरह यहा भी एक करोड अनइम्प्लायड हो जायेगे ओर वह एक बड़ी हो ख़तरनाक चीज हो जायगी। लिहाजा आपकी कोशिश यह होनी चाहिये कि यहा की एकानामिक प्राबलम हल कर सकें। अगर आप यह कदम उठायेगे तो बडी भारी गलती करेगे। आपको सबकी माली हालत को दुरुस्त करना है, आप कभी नहीं कर सकते कि किसी एक खास ताके की माली हालत की दूरस्त नरने के लिये दूसरे तबके को बरबाद कर दे, नेस्तनाब्द कर हे। अगर आप यह गलती तो करते है आप सरा जिन्दगी को एक दम खत्म कर देगे सरल एको ग्रोमिक खत्म हो जायगी। इन सब ख्यालात को देश करने का मक्सद यह है कि हम आपको आगाह कर दे कि आप सच्चाई के साथ, रयादारी की बिना पर, भसाबात की बिना पर, हमदर्दी से यह सोचे कि हम किय तरत में इतने बेकार लोगों की जिन्दगी रिहेबीलेंट करेंगे, जिसका असर सारे सुबे की एकानामी पर होगा। इसका असर खाली सुबे पर ही न पड़ेगा बरिक इसका असर और भी दूर तक पहुँचेगा और सारे हिन्दुस्तान की माली हालत पर इसका बडा असर पडेगा। यह बीजे ऐसी नही ह कि लोग आसानी से समझ ले। यह तो बहुत बडा प्राबलम सम-स्या है, इस पर जितना भी गौर किया जाय कम है। गौर करने के लिये और फिर उसका हल निकालने के लिगे अभी तो कुछ वक्त जाया ही नही हुआ है। मेरी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कि जो भी तरमीमात सामने आवे उन पर गवर्नमेट रवादारी से, सच्चाई को जिना पर सोचे ओर अगर वह उसको पसन्द आवे, काबिलेकबूल हो तो बिना हिचक के गवर्नमेट को कबूल कर लेना चाहिये। गवर्नमेट जितना भी आगे सकती हे उतना बढना उसके लिये जरूरी है, क्योंकि आपको सारे कौम को अपने साथ लेना है। अगर काश्तकारो की, अनइम्प्लायड लेबरर की, लैडलेस लेबरर की ताबाद ज्यादा है, तो इसलिये यह सोचना कि उसके मफाद के लिये काम करना चाहिये और चिक जमीदार एक छोटा तबका है, उसकी तादाद में भारी कमी है तो उसको छोड दे अपनी हाल पर । इस शक्ल से ये चीजे नही होनी चाहिये बल्कि सोच लेना चाहिये कि हम इस तरीके से चलें कि सबकी माली हालत अच्छी हो, चाहे वह काश्तकार तबका हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मजदूर हो चाहे जो

[श्री मुहम्मद यूसुफ] हो, सबको मिलाकर रूरल एकानामी (ग्राग आर्थिक व्यावस्था) को इस तरह करे, इस तरह बनावे कि माली हालत दुरुस्त हो और तभी आप अपने सूबे की माली हालत को दुरुस्त कर सकते हैं और दूसरे जो प्राबलम हैं उनको भी हल कर सकते हैं।

आपको बड़े उसूलों पर चलना है, अपना काम खूब पूरती और रवादारी से करना है। महात्मा गांधी के जो उसूल है वे एक प्रैक्टिकल उसूल (क्रयार क) है। गांधी जी का कहना था, उनका उसूल था कि मसावात की बिना पर अगर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा गाल भी उसको दे दो। यह टालेरे । की बात है। इंसान एक बड़ी चीज है, इंसान तो सचमुच एक बुलन्द हैसियत है। वह जानवर से अपनी अलग हस्ती रखता है। हर इंसान का असर होता है, चाहे वह कोई हो, छोटा हो या बड़ा। मेरा गवर्नमेट से यह कहना है कि सच्चाई की बिना पर, रवादारों को बिना पर, इंसाफ की बिना पर आपको अपना कदम उठाना है। अलको उन उपूलों पर चलना चाहिये कि जिनसे इंसान इंसान रहे, भाई भाई रहे और ऐसो फिजा आ जाय कि हम ऐटम बम बनाना खत्म कर दें और जिन्दगी ही बदल जाय। अपने बिल में हम ऐटन बम वाली जिन्दगी को जगह नहीं दें सकते हैं। गवर्नमेट की पालिसी तो यह है कि वह कन्युनित्म का मुकाबिला करना चाहती है, कोम कौम के दरमियान जो हैटरेड (घृणा) है उसको दूर करना चाहती है और ऐसी पालिसी पर चलना चाहती है जिससे आपसी इंख्तिलाकात दूर हो जायं। यकोनन यह बिल ऐसा है जो कम्युनिज्म को रोकता है और नकरत को बिना को खत्म करता है। लेकिन कुछ ससले ऐसे है जिन पर जरूर गौर करना चाहिये। हमको तो अभी काफी ऊंचा जाना है दुनिया हमारी तरफ देख रही है। वायलेंस (्रिसा)की तरफ हमें नहीं जाना है। हमे तो महात्मा गांधी के फिल्सफे से काम लेना है। जब भाई-भाई को, कौम-कीम को, इंसान-इंसान को मोहब्बत की नज़र से देखे तब हम समझ सकेंगे कि हम आराम ओर सुकृत की जिन्दगी बसर कर सकेंगे। लिहाजा इस बिल में कम्यूनिजम को खत्म करने की स्कीम है, मगर सवाल यह है कि क्या यह अमल में आयेगा। मोहब्बत, सच्चाई और महात्मा गांथी के उसूल जिनके मातहत हम रहना चाहते हैं क्या उन पर हम अमल भी करेंगे या नहीं। अगर इंसान इंसान के साथ, कोम कोम के साथ, तबका तबका के साथ रवादारी नहीं बरत सकता है तो हमारा कदम बेकार है। यह मसले महज वैसे ही तय नहीं हो सकते तो गवर्नमेट की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे उसूलों पर चले जिससे ऐसी बातों को और उसूलों को कोई बरबाद न कर पाये। और हमारी इकानामिक हालत ऐसी खराब न हो जाय कि हमें अफसोस करना पा। यह नहीं होना चाहिये कि मेजारिटी की वजह से हम कुछ भी न सोचैं। देखिये और समझ लीजिये कि आपके फायदे की बात हम कहते है। यह मैं मानता हूँ कि आप काइतकारों और मजदूरों के हकूक को पहिले देखिये, लेकिन उसके साथ हो साथ दूसरे तबकों के उसूल को भी देखिये। अभी तो हमें बहुत ऊंचा जाना है। हमारी इकोनोमिक लेबिल (गार्थिक स्तर) क्या है यह आपको देखना चाहिये। जब जमींदारों का नाम आता है तो लोग कहते है अक्खहा, यह तो जमींदार है, ताल्लु केदार है और बहुत मालदार है। लेकिन देखिये कि हम अपनी जिम्नेदारियों की भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारी को, पब्लिक के साथ अपनी जिम्मेदारी को, औरतों और बच्चों के साथ अपनी जिम्मेदारी की, पुलाजिमीन के साथ अपनी जिम्मेदारी की हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनकी एको नोमिक पोजोशन (स्थित) का जहां तक ताल्लुक है बह ऐसा है "मेक दू एंड्स मोट " (गुजर इसर और यह बड़ा डिफिकल्ट (कठि) हो रहा है। कहते हैं कि यह ब है सरमायेदार है। अरे साहब सरमायेदार तो अफ़ीका और इंगलिस्तान में देखिये। यह तो गरीबों का मुल्क है। गरीब से गरीब मुल्क के लोगों से भी हमारी हालत बहुत खराब है।

आज हमारी इक्तिसादी होलत एसी है कि हमारे पास मुलाजिमान निक नहीं हैं। अगर मफानात वगैरा कुछ दुरुस्त नजर आते हैं तो यह कहा जाता है कि जमींदारों की माली हालत बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर देखा जाय तो उनके पास माजिन निल (गुंजायदा बहुत कम) है, सिवाय उनके जो विजनेस वगैरा करते रहे हैं। चन्द हस्तिया ऐसी हो सकती है जिनकी हालत अच्छी हो लेकिन ज्यादातर लोगो की हालत खराब है और बहुत तो नकरूज हैं। जो लोग मकरूज ह उनकी तो इक्तिसादी मोत हो जायेगी। इन सब दातो के बावजुद हम यह समझते ह कि हमारी जो नेशनल गवर्नभेट है उसका हम साथ दे, लेकिन हम यह इल्तिजा जरूर नरेगे कि हमारी इक्तिसादी हालत, हमारी रेली हालत और हमारी इज्जत की वकत बहैसियत एक खाहिमें काम के रहना चाहिये ओर मौका हंसको देना बाहिये कि तम अपने कोम की खिदनत कर सके, हुकूमत की खिदमत कर सके और मृत्क की खिदमत कर सके। इगलिस्तान में देख लीजिये। सोशालिस्ट गवर्तनेट है लेकिन उन्होने वहा अभी तक जमीदारी को अबालिश नही किया ह क्योंकि वह जहरत नहीं समझते ह। वह प्रैक्टिकल सोशलिस्ट है, वह थ्यूरेटिकल सोशिलस्ट नहीं ह। स्टील वगैरह का मागला उन्होने लिया है, लेकिन जमीदारी को उन्होंने टच नहीं किया ह। यहा उनको एक इकोनामिक दूस करना पड़ा है और बहुत मुमिकन है कि उनको कोलिशन रवर्नपेट बनाना पडे। सवाल यह है कि अगर किसी बोज को नेशनलाइज करने में तमाम हान की जिन्दगी बुलन्द होती ह तो ऐसा करने मे कोई हर्ज नहीं है लेकिन सवाल यह है कि कही ऐसी हालत न पैदा हो जाय कि तमाम मुल्क की इवितसादी जिन्दगी बरबाद हो जाय। जमीदारी का मसला हर जगह के लिए है और ऐज ए वर्ल्ड प्राब्लम यह जरूरी है कि ऐसे फाइनेमें का इन्तजाम किया जाय जिनते हमारी इक्तिसादी जिन्दगी बुलन्द हो सके। ने शनल वेल्थ बढ़ाने के यह माने नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट के पास बहुत सा रुपया टैक्स से आ जाय। जरूरत यह है कि लारी कोम की हालत इतनी मजबूत हो जाय कि वह अपनी बलन्दी की जिन्दगी गुडिर कर सप्रे। यह शुत्र की बात ह कि यहा गवर्नमेट ने यह तसलीम नहीं किया है कि वह कम्यूनिस्टिक उसूल की तहत में अपनी स्कीम को चलाये। उसने यह बात साफ कर दी है कि हम कम्यूनिस्टिक उसूल पर नहीं चलेंगे बल्कि गाधियन फिलासफी की बिना पर हम काम करेगे। पहेली चीज जी इस बिल में है वह काबिले गौर है और यकीनन यह वीज उम्दा है। अक्सर साहधान को यह डर है कि मुमकिन है कि इस तरह से जो लोग इस जगह पर है वे कम्युनिज्म की तरफ घूम जायं। यह हो सकता है लेकिन पुझे यकीन है कि कम्युनिज्य की मानने पर ओर कम्युनिस्टो से कोआपरेशन करने पर हमको गुलाम होकर रहना पट्टे, उनके फिलासफे के हम गुलाम होकर रहे, उनके नफरत के फिलासफें को मान ले, जंग के फिलासफें को मान ले और तमाम नफरत के उसल की बिना पर अपनी जिन्दगी बसर करे तो यह चीज हमारे यहा नहीं हो सकती है और न हम इसको मान ही सकते रु। मुख्तलिफ गये हो सकती है लेकिन जो मुख्तलिफ राये हों उनको ऐडजस्ट करना चाहिये, बीसवी सदी ऐडजस्ट करने के लिये ही है। अगर कम्यू-निस्ट पार्टी अपनी जगह से हट जाय और सब अपनी जगह से हट कर खूबसूरती और बुलन्दी के साथ फिलासफे जिन्दगी को प्रैक्टिकल बनावे और उसी बिना पर अपनी कौमी जिन्हगी को मुनज्जम कर दे तथी यह जग मिट सकता है, लडाई खत्म हो सकती है और मुहब्बत की फिजा कायम हो सकती है। हमारे नेताओं ने सारी दुनिया में हिन्दुस्तान का एक लीडिंग पोजीशन बना दिया है। यह अभी का वा या है कि प० जवाहरलाल जी नेहरू ने बाहर जाकर बुलन्दी का डंका बजा दिया। महात्मा गाधी के फिलासफी की सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो वह उसका गलत तर्जुमानी करता अर उस पर लोग हंसते। कोई हंसता कोई मजाक उडाता और कोई गुस्सा होता। मगर नही, नफरत की निगाह से उन्हे कोई नहीं देख सका। सारी दुनिया के लोगो मे हमारे पोजीशन को बहुत बुलन्द बनाने में पं न तेहरू का पूरा हाथ है इसकी सभी की मानना पड़ेगा। हमें चाहियें कि हम अपने उसूल की बिना पर दुनिया के लोगों से कहे कि तुम हमारी तरफ आओ, और हम सब और दुनिया के लोग मिलकर एक ऐसी फिजा पैदा कर दें कि लडाई ही खत्म हो जाय और जो भीतरी लड़ाई इंसान की इंसान से है वह खत्म हो जाय तबके

[श्री मुहस्मद यूमुफ]

तबके की लड़ाई खत्म हो जाय अगर आज हम उम मकसद को हासिल करना चाहते है तो मुहब्बत की बिना पर सारी दुनिया एक हो जायगी। यूनिफार्मिटी आफ यूनिवर्सल लाइफ की बिना पर हम सारी कौम को एक साथ कर सकते ह जिसमे किसी को कोई नफरत की निगाह से न देखे। वयोकि आपकी लीडिंग पोजीशन होगी और हम समझते हैं कि हम इसको जरूर कर सकते ह और इस पर नाज कर सकते है कि दुनिया को हम अपने रास्ते पर ला रहे हैं और सब को अपनी तरफ खीचे ला रहे हैं। तो यह खुली हुई बात है कि यह बिल नफरत की बिना पर नहीं बनाया गया है बल्कि महब्बत की बिना पर, रवादारी की बिना पर और सच्चाई की बिना पर यह बिल लाया गया है। यह जरूर है और हम तो इसको साफ कर देना चाहते है कि आज कल की दुनिया ऐसी नहीं है कि इतनी लराबियों के बाद, इख्तलाफ राय होने के बाद और इतना जिल होने के बाद कोई झूठी बात रक्खी गई हो। यह तो सूबे के रुब कोमो की जिन्दगी को अच्छा बनाने के लिये बिल लाया गया है। कोई भी चीज हो वह तजबें की बिना पर जरूर हो। इंसाफ की बिना पर ओर सच्चाई की बिना पर कोई चीज सामने आनी चाहिये और उसकी बिना पर हम अपनी जिन्दगी गुनज्जम करे और तमाम कौम की जिन्दगी मुनज्जम करे और उसके साथ-साथ तमाम टुनिया की जिन्दगी मुनज्जम करने की कोशिश करे तभी आपका मकसद पूरा हो मकता है और इसी से अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर कर सकते हैं, तमाम दुनिया की कौमें अपनी जिन्दगी बसर कर सकती है और तमाम अन्दरूनी मसले इसी से तल कर सकते हैं। अगर हो जाय तो फिर यह शिकायत हो नहीं हो सकती है कि हम खिच कर कही कम्यूनिज्म की तरफ न चले जायं! जहां पर कम्यूनिज्म गवर्नमेट हैं वहां भी लेबर केपिटल के सिलसिले में बड़ी मुक्किलात लोगों के सोमने आ रही है। वहा उसूल तो यह है कि सरमाया किसी के पास न हो लेकिन यहा भी बहै-बड़े सरमायेदार होते जा रहे है। क्योंकि अपारचुनिटी देखकर काम िया जाता है। इक्वल का माने इक्वैलिटी आफ राइट्स होता है यह नहीं कि अपालोजो बिफोर जस्टिस ! माली हालत होती है वही अपने लास जगह रखती है ओर उसने सब को नीचा कर दिया है। इसलिये माली हालत ो दुरस्त करने की निहायत जरूरत है; अगर आप गुरबत को सब मे बांटकर इस काम को करेगे तो इससे आप बुलन्दी हासिए हरगिज नहीं कर सकते है। ओर इसी बिना पर इकानामिक हालत को भी बुलन्द करने में आप कामपाब नही हो सकते हैं। लिहाजा यह ख्याल गलत है कि कुछ आदिमियों की माली हालत को खराब करके, बिगाड़ कर दूसरों की हालन अच्छी हो जायगी और देश की हालत उससे सूपर जायगी। सब के पास बिना दौलत के हुये आप दुनिया की किसी चीज को बुलन्द नही कर सकते। उसके लिये हर तबके का ख्याल आपको करना होगा। मजदूरों का भी ख्याल करना होगा और जिनसे आप जमीन छीनकर काश्तकारों को दे रहे है उनका भी ख्याल करना होगा। गरज कि सब तबकों की हालत को दूरस्त करने के लिये उनका खगाल करना होगा। अगर आप चाहते है कि मुल्क के अन्दर सब तबकों की हालत बुलन्द करे तो आपको जरूर इस उसूल को अस्तयार करना होगा। सब तबकों की हालत बुलन्द करने की यहां पर बहुत जगह है। काइतकारों की हालत को बुलन्द करने की यहां पर बहुत जगह है लेकिन जब तक आप इंडिविजुअल की हालत को बुलन्द नहीं कर सकते तब तक आप किसी जमात या तबके की भी हालत की दूररत नहीं कर सकते हैं और बुलन्द नहीं कर सकते हैं। जब तक आप गांधी जी के बताये हुए उसूल पर नहीं चलेंगे तब तक आप दुनिया के अन्दर बुलन्दी हासिल नही कर सकते है और दुनिया के अन्दर जो अपनी जगह लेना चाहते है वह आपको नहीं मिल सकती है। रूहानी दुनियामे हमारानाम बहुत बुलन्द है लेकिन इकानामिक दुनियामे भी हमको नाम पैदा करना है मगर वह गरीबी सब में बांटकर नहीं पैदा किया जा सकता। हांला— कि गुरबत कोई बुरी चीज नहीं है कि जिसको नफरत की निगाह से देखा जाय

हर तबका गुरबत नवाजी का शिकार है जिस शख्स के अन्दर गुरबत, मुहब्बत, हमदर्दी, त्याग और सचाई है वह शख्स बहुत ऊंचा है और बहुत बुलन्द है, वह कोई भी तबके का आदमी हो वह बहुत ऊंचा आदमी हे, उसकी कीमत उस आदमी से भी ज्यादा है जिसके पास करोड़ों रुपया है लेकिन फिर भी माली हालत को दुरस्त किये बिना मुल्क की इकानामिक हालत को बुलन्द नहीं किया जा सकता। अगर किसी काम को रवादारी के साथ, ईमान्दारी के साथ, इन्साफ के साथ किया जाय तो फिर उसके नतायज खराब होने का अन्देशा नहीं रहता है। जमींदारी जो अभी तक कायम रही है वह भी आपके भाइयों की ही है, मुल्क मे रहने वालो की है और उनके जरिये भी मुल्क के अन्दर बहुत काम हुए है। उसको अगर उनका ख्याल रखकर किया जाय तो वह काम आसानी से हो सकता है। हम इस बात को मानते है कि यह चीज जरूरी है और यह जरूर किया जाना चाहिये लेकिन उनकी माली हालत को मद्देनजर रखकर इस पर पूरी तरह से विचार करना जरूरी है और इंसाफ और ईमान्दारी से इसको ख़त्म करना चाहिये। (कोरम के लिये घंटी बजी) तो मै अपने वजीर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होने जो पालिसी इस अमर के मुताल्लिक अख्तियार की है वह नफरत की बिना पर नहीं है बल्कि वह मुहब्बत की बिना पर है, जरूरत की बिना पर है। उसके अन्दर कुछ गलती जरूर है लेकिन मै उम्मीद करता हं कि गवर्नमेट को उन पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि कही ऐसी शक्ल न हो जाय कि उससे और हालत मुल्क की खराब हो जाय और बजाय कुछ फायदा पहुंचने के और तबाही बरबादी में मुल्क फंस जाय और ज्यादा गड़बड़ हो जाय। लिहाजा उस पर दोबारा गौर करने की जरूरत होगी। में इस्तदुआ करता हूं कि जिस तरह से अमेंडमेंट आयेगे उनके ऊपर गौर किया जावेगा । जो मुफीद होगे उनको जरूर लिया जायगा और कोई मिडिल कोर्स (बीच का रास्ता) अख्तियार करने की सरकार जरूर कोशिश करेगी। मजदूरों की क्या डिमान्ड है और काश्तकारों की क्या डिमान्ड है इन सब को सरकार को भूल जाना चाहिये। और सही ख्यालात की बिना पर इस पर अमल करें और इस बिल को ऐसा बनायें कि जिससे सब को फायदा पहुंचे और सब के फायदे के लिये हो, किसी की इससे बरबादी न हो।

अब एक चीज और अर्ज करना जरूरी है और वह यह है कि आगे जो अमेंडमेंट वगैरा आवें और वह तो अपनी जगह पर आवेंगे ही और हालांकि जो कुछ तरमीमात अब तक हो गई है वह भी यक्तीनन कारतकारों के फायदे के लिए ही है। वैसे प्रोपैगेन्डे के लिए बहुत सी चीजें होती है लेकिन यह चीज साफ है कि यह बिल जिस शक्ल में अब आप के सामने आया है उससे यह साफ जाहिर है कि वह बड़े काश्तकारों के लिए मुफीद है और उस से ज्यादा मुफ़ीद छोटे काश्तकारों के लिए है। इसके साथ-साथ यह भी है कि जमीदारों की हालत तो रही होगी ही लेकिन हम उसको मंजूर करने को जरूर तयार हो जायेंगे अगर गवर्नमेंट हमारे साथ हमदर्दी करेगी और ऐसी स्कीम लावेगी और हमारी माली इमदाद करेगी जिससे हम अपनी जिन्दगी को दोबारा मुनज्जम कर सकें और अपने फरायज व डच्टो को पूरा कर सके।

एक चीज और है जिसकी तरफ में खास तौर पर मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह हमारा वक्फ का मसला है। यह चीज सेलेक्ट कमेटी में भी आ चुकी है और वहां डिसकस हो चुकी है। अब जिस शक्ल में बिल में प्राविजन किया गया है उसमें वक्फ़ अललऔलाद को नहीं माना गया है और खाली जिस तरह से जमींदारी का मुआवजा मिलेगा उसी तरह से इस पर भी मुआवजा दे दिया जावेगा । इस सवाल पर सरकार को और मिनिस्टर साहब को तवज्जह करनी चाहिए क्योंकि यह बुनियादी सवाल है और पहले से मानी हुई चीज है और मजहबी नुक्तेनिगाह से भी जरूरी है। इससे गवर्नमेंट की कुछ बहुत थोड़ी सी आमदनी पर तो ज्ररूर असर पड़ेगा लेकिन इससे आप अपनी माइनारिटी की हमदर्दी हासिल करेंगे और यकीन मानिए कि हम लोग आप को इस चीज को एप्रिशिएट करेंगे और आप की मेहरबानी होगी कि अगर हमें सरकारी ट्रेजरी से इसका रुपया भी मिल जाया करे। इससे रवादारी बढ़ेगी और आपका इक्तबाल बुलन्द होगा और यह समाज के लिए बड़ी अच्छी, बेहतर और जरूरी यह सरकार का शानदार क़दम होगा क्योंकि इस चीज को पहले भी माना जा चुका है और क़ानून भी पास हो चुका है और इस पर काफ़ी बहस-मुबाहिसा हो चुका है और गवर्नमेंट

[श्री मुहम्मद यूसुफ]

आफ इंडिया में ऐक्ट भी पास हो चुका है। जिस तरह से भी हो सके इस चीज को बरकरार रखना चाहिए। यह चीज भी मुझे मिनिस्टर साहब और हाउस के सामने लानी थी। इसका असर बहुत अच्छा होगा और बहुत ही उम्दा चीज होगी और गवर्नमेट की बहुत थोड़ी सी आमदनी पर ही इसका असर पड़ेगा, लेकिन इससे मुसलमानों के अखलाक पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। वह समझने लगेगे कि अक्रलियत में होते हुए भी हमारे साथ इन्साफ किया जाता है और हमारे हक़्क़ की हिफ़ाजत की जाती है और इसमें इक्तसादी और बुनियादी सवाल दोनों हल हो जाते लिहाजा में यह अर्ज करना जरूरी समझता हूं और में आप से इस्तदुआ करता हूं कि इसके मुताल्लिक और आइन्दा जो भी अमेन्डमेंट आवें उन पर आप सहूलियत और इन्साफ़ के साथ गौरोखौंज करे और प्रैक्टिकल सोशलिज्म पर अपना क्रदम बढ़ावें। पंडित जवाहर लाल जी सब से बड़े सोशिलस्ट है उनसे ज्यादा सोशिलस्ट कौन हो सकता है। वैसे तो तमाम किस्म के अमेंडमेंट हर पार्टी और जमाअत की तरफ से आवेंगे लेकिन आप की यह पालिसी होनी चाहिए कि उनमें जो अच्छे हों और काबिल क़बूल हों उन पर जरूर गौर करना चाहिए और उनकों मान भी लेना चाहिए। खास तौर पर मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जह इसकी तरफ दिलाना चाहता हं कि वह महज स्लोगन्स पर न जांय ओर एक प्रैक्टिकल व्यू हर चीज का अपने सामने रखें वर्नी यह सब एक अजीबोगरीब चीज हो जावेगी और हमें डर है कि तमाम एकानामिक आर्डर और इन्डस्ट्री वगैरा सब खत्म हो जायंगी एकानामिक इंडिपेंडर्स की बिना पर अरबन एरिया में जमींदार और काश्तकारों के ताल्लुक़ात और सब मामलों का फसला मिल कर करें तो अच्छे तरीक़ों से हो सकता है। सोशलिज्म का इस तरीक़े पर प्रैक्टिकल पालिटिक्स से तसादुम होगा। यह खुली हुई बात है इसमे बहस की जरूरत नहीं है। अगर डिक्टेटरिशय हुई तो यह चीज चल नहीं सकती है। जवाहरलाल से बड़ा सोशलिस्ट कौन है ? अब तो सिर्फ स्लोगन्स रह गए है। इस सरकार में और सोशलिज्य में कोई फर्क नहीं है। नेशनलाइजेशन हो जायगा तो तमाम तबकों और मुल्क और क़ौम और आजाद हिन्दुस्तान के लिये होगा। हर आदमी को गौर करने के लिये तैयार रहना चाहिये। नेशनलाइजेशन बुलन्द उसूलों की बिना पर ही किया जा सकता है। नेशनलाइजेशन लंड का कभी भी हिन्द्स्तान में चल नहीं सकता है उससे बरबादी और कुलैप्स होगा। सूबे और मुल्क में गड़बड़ हो जायगी। इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन धीरे धीरे और वक्त के साथ होना चाहिये ओर कार्डेज इंडस्ट्रीज को चलाना होगा। एग्रीकलचर इंडस्ट्री को डेवेलप करना हमारी माली और इक्तसादी हालत को अच्छा करना होगा। इन अल्फ़ाज के साथ में ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि जहां तक काश्तकारों के फायदे का ताल्लुक़ है यह एक अच्छा बिल है। जमींदारों के ख्याल से तो यह उतना अच्छा नहीं है में उम्मीद करता हूं कि आप इस बात की कोशिश करेंगे कि जमींदार भी अंच्छी तरह जिन्दगी बसर कर सकें और वह अवाम और काश्तकारों और मुल्क की खिदमत कर सकें।

श्री जागन्नाथ प्रसाद यग्रवाल--जनाबवाला, अभी थोड़ी देर हुई रोशन जमां खाँ साहब की तकरीर हुई। उससे मुझमें जोश आया कि तकरीर करूँ। लेकिन आज इस मौक्रे पर यह चन्द बन्द पढ़ना चाहता हूं।

डिट्टो स्रोकर--न्या इसका उसी विषय से ताल्लुक है जो इस वक्त पेश है ?

श्री जगन्नाथ प्रमाद श्रव्रवाल--जी हां, सिर्फ उसी मसविवे को इसमें नक्तल कर दिया गरा है।

डिप्टी स्पोकर--तो अच्छा।

सन् १९४९ ई० का सत्रत प्रातोत्र जमोंदारी विनाश ओर भूनि व्यवस्था बिल ३६९

श्री जगन्नाथ प्रसाद ग्रप्रवाल--

(8)

निजामे मुमलकत की जलवह सामानी का क्या कहना।
हुसूले मृद्दा की गौहर अफ़शानी का क्या कहना।
मां आले जीस्त की आला निगहबानी का क्या कहना।
हुजूमे शौक की, इस बज्मे इरफानी का क्या कहना।।
चमक उट्ठा हर एक जर्रा निगाहे अद्ल परवर से।
निजाते दायमी दुनिया ने पाई फ़ितनह व शर से।।

(२)

मुबारक हो तुझे ऐवाने सूबाई मुबारक हो।
किसानों के यह दुख की चारा फ़रमाई मुबारक हो।।
विज्ञारत को अपोजीशन की एकजाई मुबारक हो।
हुर्फुमसिह जी को खुशी फिकी व दानाई मुबारक हो।।
मुबारक टडने जी जाह को यह फस्टे इनसानी।
कि आखिर सत्य निकली आज इन राजिष की बानी।।

(३)

जनाबे 'पंत' के जलनों से यह सूबा चमक उट्ठा।
वह कोहेनूर का शोला सरे मैदा भड़क उट्ठा।।
व रानाई ब जेबाई चमन अपना महक उट्ठा।
पपीहा, कोयले ताउस हर नाएर चहक उट्ठा।।
शजर सूमे चरागाहों का सब्जा लैलहा उट्ठा।
सदाए आफ़रीं आई वह शोरे मरहबा उट्ठा।।

(8)

जमोदारी कभी होगी ब उनवाने जिमीन्दारी।
मगर अब तो यह है इनसायिनत के हक्त में गद्दारी।।
करोड़ों आदमीयों की यह करती है दिल आजारी।
इसी ने मुल्क की खोदी जहांबानी जहांदारी।।
मिटा दो इसकी हस्ती को जमाना दुख से छुट जाए।
कटें आराम से दिन-रात दुनिया मुख में हो जाए।।

श्री कमलावित त्रिवाठो--श्रीमान् डिप्टी स्शीकर साहब, क्या कविता के पढ़ने के बीच में चे खूब, चे खूब और वाह-बाह के नारे लगाये जा सकते हैं ? डिप्टो स्पोकर--नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल--

(ㅂ)

किसानों ने हुकू के मिलकियत पाए किसानी पर । ब अन्दाजे जुनूं आया बुढ़ापा अब जवानी पर ॥ ग्रमे फ़र्दा हुआ गायब हमारी कामरानी पर ॥ निगाहें लोट जाएं क्यों न किश्ते जाफ़रानी पर ॥ दुआएं ऐ जमीन्दारों तुम्हें भी दिल में देते हैं ॥ अजावा इसके हर सामाने राहत बिल में देते हैं ॥ [श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल]

(६)

वह क्या है जो नहीं देते तुम्हें मुन्की खजाने से।
जमीन व जर मकां बागात पाते हो ठिकाने से।।
बचाया तुमको दुनिया की मलामत के निशाने से।
तरक्क़ी होगी सच्ची अब तुम्हारी इस जमाने से।।
हरी, बेगार, बेदखली व नजराना व मुटराना।
निगाहे मेहरबानी से भुलाया इसका अफसाना।।

जिमींदारी को देकर मुआवजा हमने सखावत की।
यही तो थे जिन्होंने कौम से अकसर बगावत की।।
कहां से मुस्तहक होते थे यों कहिये इनायत की।
जो सच पूछो हुकुमत ने नुमायां यह शराफत की।।

जा सच पूछा हुकूमत न नुमाया यह शराफत का। चलो मिल—जुल के अपनाओ हुकूमत के तरीकों को। बराबर हो के बिठलाओ अमीरों को ग़रीबों को।।

(८)

असामी आदबासी सीर का हलधर कि भूमिधर।
न कोई तफरिका डाला न की तक्षसीमे माल व जर।।
जिराअत का बने पेशा वसीला रिज्क का घर—घर।
वही महकूम हाकिम हो वही अफसर वही मेम्बर।।
तखैयुल यह मुसाबाती बयक रफतार बढ़ जाए।
सुकूं से मंजिले तामीर पर मेमार बढ़ जाए।।

(9)

किसानों तुम जमींदारी के ऐबों में न फंस जाना।

मिटा देता है इंसा को बुरी बातों में लग जाना।।

कहीं तुम ऐश की दुनिया में भूले से न फंस जाना।

मजा जब है कि अपनी मेहनतों में और कस जाना।।

जमाने को तुम अब अपनी तरक्की कर के दिखला दो।

अगर चाहो तो हिम्मत कर के तुम पत्थर को पिघला दो।।

(80)

जमींबारी किसानों के लिये थी आंख का जाला।
इसे दस्ते करम से पंत जी ने साफ़ कर डाला।।
बहारे जिन्दगी का तुम में हर एक हो के मतवाला।
दिखा दे बन के भूमिधर तो अपना बोल हो बाला।।
करेगा याद हमको हथ तक अपना व बेगाना।
कुछ इस अन्दाज से लिखा गया है अपना अफ़साना।।

(88)

रहो आजाव होकर जिन्दगी में फिर बहार आए। तरक्क़ी के मदारिज का तुम्हें हुस्ने शेआर आए।। मए इन्सानियत का कुछ तो आंखों में खुमार आए। फलो फूलो निहाले जिन्दगी में बर्ग व बार आए।। जरा हम याद कर लें किसने यह दीवान लिक्खा था। "रफ़ी अहमद" ने इस क़ानून का उनवान लिक्खा था।। श्री मुहम्मद जमशेद ग्राठी खां—हुजूरवाला, कम से कम इतना तो में क्वाबिल नहीं हूं कि अपने मजमून को नजम में अदा कर सकूं लेकिन एक छोटी सी नज्म में उसका कुछ जवाब तो पेश करना जरूर ही चाहता हूं। और वह एक शेर की सूरत में हैं, जो में पढ़ता हूं:—

उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जबान मेरी है बात उनकी। उन्हीं को महिकित्र संवारता हूं, चिराग्र मेरा है रात उनकी।।

इसके अलावा जो कुछ मेरे दोस्त रोशनजमां खां साहब ने इस बिल के सिलसिले में फरमाया है, इसका जवाब देना कम से कम जमींदार मेम्बर के लिये ठीक नहीं है। बिल्क इनका गवर्नमेंट की बेंचेज से ज्यादा तात्लुक है। जो थोड़ा बहुत उनकी तक़रीर के मफहूम से में समझ सका हूं और जहां तक जमींदारों का तात्लुक है इस मौक़े पर में मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता हूं। इलेक्शन लड़ना है, इसिलये किसी न किसी तरह से कहना है। उनकी तक़रीर की बहुत सी बातें ऐसी है जिनकी बातों का जवाब आनरेबिल मिनिस्टर साहब देने की तक़लीफ गवारा करेंगे।

हुजूर वाला, जानीं दार कलास का जो नुमायन्दा सेलेक्ट कमेटी के अन्दर गया था उन्होंने अपने ख्यालात इस बिल के मुतालिलक वजाहत के साथ नोट आफ़ डीसेन्ट (मतमेद) में पेश कर दिये हैं अब इस मौक़े पर दो चार ची जों जो मेरे जहन में हैं वह पेश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेसी भाई और खतूसन हमारी गवर्नमेंट के मेम्बर इस पर गौर फरमायेंगे।

में यह कहना चाहता हूं कि इस मौके पर जब कि आप समाज और सोसाइटी के निजाम में एक ऐसी बड़ी तब्दोली करने जा रहे हैं उस वक्त सीरियसनेस (संजीदगी) और तवज्जह के साथ आपको गौर करना चाहिये। आप कितना जबरदस्त इन्कलाब इसके जरिए से मुल्क में ला रहे हैं, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं कभी भी इस राय का नहीं रहा कि जमींदारी को मुतलक ल लत्म कर दिया जाय। मैं कभी भी इसकी मआफिक़त में नहीं रहा। जब सेलेक्ट कमेटी में इस बिल के जाने का मसला आया तो इस लिहाज से कि हमारी गवर्नमेंट और सरकार बक़ौल मलक की बेहतरी के और भ लाई के लिये एक ऐसा सिस्टम जारी करने जा रही है तो हमने यह समझकर सेलेक्ट कमेटी में जाना मंजूर कर लिया और यह समझकर कि गवनंमेंट की जानिब से, कांग्रेस सरकार की जानिब से एक ऐसा निजाम आयेगा जो सबकी बेहतरी के लिये और इसलिये नेशन और मुक्क की भलाई के लिहाज से हमने उसमें जाने से इन्कार नहीं किया। इस नजरिये को लेकर हम सेलेक्ट कमेटी में शरीक हुये और तमाम चीजों को जो गवर्नमेंट की जानिब से कही या पेश की गई देखा और गौर किया, लेकिन बहत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोगों की कोई तजवीज नहीं मानी गई। यह चीज नोट आफ़ डीसेंट से बख्बी जाहिर है। आप जब समाज में इस कदर इन्क़लाब करने जा रहे हैं तो उस सिस्टम के रायज करने के बाद समाज और मुल्क या सुबे में क्या हालत हो जायेगी, इस पर आपने गौर नहीं फरमाया। पुराने जमाने की हिन्दू सलतनत के जमाने में भी, में हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऐतिहासिक घटनाएं कह रहा हूं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, उन्होंने चाहे जो तब्दीलियां की हों मगर इस सिस्टम को किसी न किसी सुरत में जरूर कायम रखा। इसके बाद मुगली की हुकुमत आई और उन्होंने ७०० बरस तक सल्तनत की और उन्होंने भी इस निजाम को क्रायम रखा।

जसके बाद बाहर की हुकमत देश पर मुसल्बत हुई और उन्होंने किसी न किसी तरह से इस निजाम की क्रायम रखा और इस तरह से कायम रखा कि लोगों का यह ख्याल होने लगा कि यह इतना पुराना निजाम अंग्रेजों का ही बनाया हुआ ह।

लयनऊ में सदस्यों के लिए कफ्यू के परिमट

डिप्टी स्पोक्तर—मुझे यह बतलाना है कि लखनऊ में रात के लिए कपर्यू लगा हुआ है। ७ बजे शाम से सबेरे ७ बजे तक कोई नहीं निकल सकता है। मैंने आज शास्त्री जी से कहा था कि कोई इन्तजाम कर दिया जाय। चुनांचे उन्होंने वह इन्तजाम कर दिया है कि हमारे असेम्बली के सेन्नेटरी मेम्बरान को परमिट जारी कर सकते हैं। दो—तीन मिनट में वह जारी हो जाएंगे। सेन्नेटरी साहब से वह परमिट ले ले ताकि उनके लिए कोई चकावट न रहे।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थिगित हो गया)।

लखनऊ, १० जनवरी सन् १९५० केलासचन्द्र भटनागर, मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली।, संयुक्त प्रान्त

नत्थो 'क'

(देखिए ९ जनवरी, १९५० ई० के शेष ताराकित प्रश्न १११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३०८ पर) सन् १९४८ ई० तथा मन् १९४९ ई० मे अब तक कुल निम्नलिखित जिलेबार परिमट दिये गये:——

नाम ज्ञिला		संख्य। परमिट	नाम जिला		संख्या परमिट
मेरठ	• •	380	गोंडा		४३
मुज्जपफरनगर		દ્દ	बहराइच		१०
सहारनपुर		20	बलिया		१२
देहरादून	•	१४८	आजमगढ़		१६
लंबनऊ		६६	गाजीपुर		8
उन्नाव		9	इलाहाबाद		११३
सीतापुर		११	बनारस		60
खी री		6	मिर्जापुर		29
प्रतापगढ़		88	जौनपुर		९
सुलतानपुर	•	१०	बरेलों		१००
फेजाबाद		१०	मुरादाबाद		38
रायबरेली		4	बिजनौर		३७
बाराबंकी		१२	बदायुं		१७
हरदोई		4	भाहजेहांपुर		३६
हरवोई मनपुरी		१५	पीलीभीत		२३
मथुरा		34	कानपुर		११०
फर्रेलाबाद		28	फतेह्पुर		8
आगरा		१०५	झासी		१३
अलींगढ़		२७	जालौन	٤	१०
एटा		8	हमीरपुर		?3
बुलंदशहर		२४	बोंदा		ų
गौरखपुर		४२	इटावा		6
देवरिया		२६	नैनीताल व अल्मोड़ा		४२२
बस्ती		80	गढ़वाल	• •	३०१
			योग		२,५७१

नत्थी (देखिए १० जनवरी, १९५० के तारांकित प्रश्न सं०

कि हुउ	या त त्रह्मा त े—	या सेशंस मुकद्दमा	नाम अभियुक्त	संख्या धारा व नाम कानून जिसके अंतर्गत मुकद्दमा चलाया गया हो	सेशंस न्यायालय की तिथि या तिथियां
?		२	₹	8	4
?	स० टि० न	० ४, १९४९	रेक्स बनाम जानकी	धारा ३९५ ताजी– रात हिंद	\$-3-8¢
२	स० टि॰ न	० ३३, १९४८	रेक्स बनाम हेतराम वगैरा	भारा १४७ १४९ ३०२ ४३६ ता० रा० हिंद	२५-१-४९ २६-१-४९ २७-१-४९ २९-१-४९ ३१-१-४९
įv	स० टि० न	० ३, १९४६	रेक्स बनाम मोहन चंद्र वर्गरा	धारा ३७९ ताजी– रात हिंद ५२ पो० आफिस ऐक्ट	२-१२-४८ ४-२-४९ ५-२-४९ ६-२-४९ ७-२-४९ २९-२-४९
४	स० टि० न १९४८	υξ ο	रेक्स बनाम लालता प्रसाद वर्गरा	धारा ३०४ ताजी- रात हिंद	५-२-४९ ७-३-४९ ८-३-४९

∉खं ७ का उत्तर पोछेपृष्ठ ३११ पर)

तिथि या तिथिया जिसके लिये मुकद्दमा स्थगित हुआ	ां कारण जिससे स्थगित हुआ	अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये घे	सरकारी रु० की हानि, जो मुकद्दमें में स्थिगित होने से हुई। १जज के वेतन में, २गवाहों और असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में, ३वकील सरकारी की फीस।
Ę	৬	د	٩
	••	जमानत पर	यह कुछ देरी से आरम्भ हुआ, पूरे असेसर नहीं आये, शहर से दूसरा नया असेसर बुलाया गया। कोई हानि वेतन की नहीं हुई। दो दिन का मुकद्दमा था और दो दिन में ही समाप्त हो गया।
₹८ - १-४९	गवाह साबित नहीं आये । २७ को प्रार्थना–पत्र देकर २८ न होकर २९ को हटाया ।	जमानत पर थे	६ ६० असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में। जजव वकील सरकारी के वेतन में कोई हानि नहीं हुई।
२८ से २९ को स्थगित हुआ	७-२-४९ को पूरे गवाह नहीं आये। कलकत्ता व इटावा व अमृतसर के निवासी प्रार्थना-पत्र पर २९ को तारीख पड़ी। २८ को गवाह न आये, २९ को मुकद्दमा हुआ।	जमानत पर थे	७ रु० ३ आना असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में ।
५ –३–४९	हुआ। । केवल दो असेसर आये । दुबारा सम्मन जारी हुए ७ ता० को ।	जमानत पर थे	५ रु० असेसरों के मार्ग व्यय व भोजन में। ४ रु० ८ आना गवाहों आधे दिन की फीस १५ वकील । सरकार की फीस की हानि हुई।

स्थिगित किया हुआ मुकद्दा ऋस संख्य	ा संख्या सेशंस मा मुकद्दमा —	नाम अभियुक्त	संख्या घारा व नाम कानून जिसके अंतर्गत मुकद्दमा चलाया गया हो	सेशंस न्यायालय की तिथि या तिथियां
१	2	₹	8	4
4	स० टि० न० १०-१२, १९४९	रेंक्स बनाम हुलासी वगैरा	धारा ३९५ ताजी- रात हिंद	६—५—४९ २५—५—४९ २६—९—४९ २७—९—४९
ę,	स० टि० न० ९, १९४९	रेक्स बनाम रामलाल वगैरा	धारा ३६३–३७६ ताजीरात हिंद	३७-४-४९ २८-४-४९ २९-४-४९
ø	स० दि० न० ८, १९४६	रेक्स धनाम हेतराम वर्गरा	धारा ३०४, ३२५, ३२३सब धारा ३४ ताजी-ारत हिंद	२०-४-४९ १६-५-४९ ५-५-४ ९
۷	स० टि० न० २१, १९४९	रेक्स बनाम काली वर्गरा	। भारा ३०२, ३२३, १४८, १४९ ताजीरात हिंद	२८-४-४९ १६-५-४९
9	स० टि० न० १४, १९४९	रेक्स बनाम गिरधारी वर्गरा	धारा ३९५ ताजी- रात हिंद	६–६–४९ ७–६–४९ ८–६–४९

तिथि या तिथियां जिसके लिये मुकद्दमा स्थगित हुआ	कारण जिससे स्थगित हुआ	अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे	सरकारी ह० की हानि, जो मुकद्दमें में स्थिगित होने से हुई। १—जज के वेतन में, २—गवाहों और असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में, ३—वकील सरकार की फीस।
Ę	৬	۷	٩
६—५—४९ २६—५—४९	असेसर पूरी संख्या में नहीं आये, २६ को गवाह पेंश होकर बाद दोपहर थानेंदार तफ- तीश, जिसने दी नहीं, आया, इस कारण २७ को हटा दिया।	हुलासी जेल में अर्जुन व मथुरा जमानत पर	१६ ६० ४ आना गवाहों के और ७ ६० असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में और कोई हानि नहीं हुई ।
<i>२७</i> –४–४९	को असेसर देर से आये तामील गलत हुई, देरी से आरम्भ हुआ ।	जमानत पर	कोई हानि नही हुई ।
२०-४-४९	,,	जमानत पर	३ रु० गवाहो के वेतन में हानि हुई ।
२८ –४–४९	गवाह सबूत थानेदार नहीं आये केवल एक असेसरआया, २८को हटाकर १६ को हुआ	२ जमानत पर ८ जेल में	२ ह० ८ आना असेस _र ों के मार्ग व्यय भोज न में हुए। ४१ ह० ८ आना असेसर के मार्ग व्यय व भोजन में। यह मुजफ्फरपुर, के पुलिस के गवाह न आने से हुए और वही जिम्मेदार है।
६-७-१९४९ को हटाया	६ को भागीरथ मुलजिमव एक असे— सर नहीं आया, ७ को बाद दोपहर ३ बजे श्री अस्तर आलम कार्रवाई शुरुआत करने वाले नहीं आये तो ८ को हटाया।	जमानत पर	७ ६० ८ आना गवाहों और १३ ६० असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन में खर्च हुये आधे दिन की फीस वकील सरकार में हानि हुई।

^{स्} थगित किया हुआ मुकद्दमा कम— संख्या	संख्या से मुकद्द		नाम अभियुक्त	संख्या धारा व नाम कानून जिसके अंतर्गत मुकद्दमा चलाया गया हो	सेशंस न्यायालय की तिथि या तिथियां
?	₹		₹	8	4
१०	स० टि० न० १९४८	₹₹,	रेक्स बनाम ब्रह्मानन्द वर्गेरह	धारा ३९५—३९७ ताजीरात हिंद	\$ \(\xi - \xi - \x\\\ \$ \(\xi - \x - \x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
* ?	स० दि न० १९४८	१ ५,	रेक्स बनाम अब्दुल अजीज वर्गरह	वारा ३७३–३७८ ताजोरात	₹५-८-४८ ₹६-८- ४ ८ ७-९-४८ ७-९-४८
१ २	स० टि० न० १९४८	₹७,	रेक्स बनाम शिवलाल वगैरह	धारा ३६६ ताजीरात हिंद	२०-१२-४८ २१-१२-४८ २३-१२-४८
१३	स० हि० न० १९४९	₹€,	रेक्स बनाम नियाज उल्ला	धारा ३९५ ताजी रात हिंद	२०-६-४९ २ १-३- ४९

तिथि या तिथियां जिसके लिये मुकद्दमा स्थगित हुआ	कारण जिससे स्थगित हुआ	अभियुक्त जेल में थे या जमानत पर छूटे हुये थे	सरकारी ह० की हानि, जो मुकहमे में स्थिगित होने से हुई। १जज के वेतन में, २गवाहों और असेसरों के मार्ग व्यय और भोजन मे, ३वकील सरकार की
Ę	હ	۷	3
२२-६-४९ से २ ३ -६-४९	२० तारीख को बाद बोपहर श्री हरीशचन्द	२ जमानत पर और ७	३० ६० गवाहों और २६०८ आना असे⊸
को हटा	श्रीवास्तव जिनके नाम सम्मन नहीं निकला २२ को हटा दिया २२ को नहीं आये तो २३ को हटा दिया इस तारीख को भी नहीं आये तो २४ को हटा दिया।	जोल में थे	सरों में खर्च हुये।
२६–६–४८	यह मुद्दकमा २६ को श्रो सुख दर्जन ज्ञमा यानेदार व चपरासी मु० सदीक के न आने के कारण हटा	जमानत पर थे	१ रु० ८ आना गवाहीं और ७ रु० ८ आना असेसरों के मार्ग ब्यय भोजन में खर्च हुये।
२१-१२-४८	इस तारीख पर गवाह सबूत नहीं आये इस कारण बाद दोपहर हटाया गया	उ.मानत पर	कोई हानि नहीं हुई।
२०६४९	२० ता० को गवाह सब्त तलब नहीं हुए, इस कारण मुकद्दमा हटाया गया।	एक जमानत और एक जेल में	: ७ ह० ८ आना असे- सरों के मार्ग व्यय व भोजन में हानि हुई।

नत्थी 'ग' (देखिने १० जनवरी, १९५० के तारांकित प्र० सं० १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)

नाम जिला		स्थगित किये हुये मुक़द्दमों कं संख्या	नाम जिला ो	मुक मुक	थगित किये हुये हमों की पंख्या
आगरा	• •	२२२	भाहजहांपुर		40
अलीगढ़			बहराइच		, ,
बुलन्दशहर			बाराबंकी		१६
देहरादून		88	फैजाबाद		93
एटा "		32	गोंडा		
मैनपुरी		१०४	हरदोई		३६५
मेरठ		34	लंबनऊ		३२
मथुरा		9	प्रतापगढ़		१३
मुजप्फ़रनगर	• •	४०	रायबरेली		
सहारनपुर		६२	सीतापुर		
इलाहाबाद		90	सुलतानपुर		
बांदा		9	उन्नाव ँ		
कानपुर	• •	२२३	आजमगढ़	• •	२६
इटावा	• •	४९	बलिया		92
फर्रुखाबाद	• •	६१	बस्ती	;	१४
फतेहपुर	• •	२१	बनारस		ેદ્
हमीरपुर		२२	गाजीपुर	• •	٦٥
जालीन		34	देवरिया		१५
झांसी			गोरखपुर		१००
बरेली	• •		जौनपुर	* *	
बिजनीर	• •	• •	मिर्जापुर		११
बदायूं		• •	सी० आई० डी०		Ę
बीरी		ų	जी आर॰ पी॰, ए॰ सी॰		7
नै नीताल	• •	Ę	ई० संक्शन		१४५
मुरादाबाद		દ્ ષ	बी० सेक्शन		828
पौलीभीत		8		• •	111

नत्थी 'घ'

(देखिये १० जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१३ पर)
मुरादाबाद, मुजफ्करनगर ग्रीट सहारनपुर ज़िलों में सन् १६४८ ई० में
टिये गये बिजठी के कनेक्शनों का नक्शा

क्रम- संख्या	बि	जिली पाने वाले का नाम	ৰি	जली का भार		न जिसके लिये जली दी गई	कैफियत
?	श्री रह स्ट्रीत	जिला मुरादाबाद युबर दयाल, पुजारी इ. मुरादाबाद	••	०.६ किल	गोवाट रं	ोशनी और पंखा	
२	"	नन्दकिशोर मेहरा, राजोगली, मुरादाबाद	• •	०.२४	71	71	
7	"	मुहम्मद नौशा, गुनियां बाग्र मुरादाबाद		०.४६	"	79	••
8	**	पृथ्वोराज मिश्रा, जिलाल स्ट्रीट, मुरादाबा		8.0	11	"	
فر	**	डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर मुरादाबाद	ζ,	५ हार्स प	ावर '	पम्पिंग सेट	• •
Ę	**	अनवर अलो, भाई सराय, मुरादाबाद	••	०.७८ कि	लोवाट	रोशनी और पंखा	٠
৩	,,	अजीजुल रहमान, पक्का सराय,मुरादाबाद	••	०.२७	**	**	• •
۵	"	अमर सिंह, गंज, मुरादा <mark>ब</mark>	ाद	०.३१५	"	12	
9	11	सेक्रेटरी, खत्री घर्मशाला, मुरादाबाद	••	०.७९५	**	93	• •
80	**	केदारनाथ,दी माल, मुरादाबाद	••	१.३८	"	33	• •
११	**	सैयद हातिमउद्दीन राहत मौलाई मुहल्ला डहरिय मुरादाबाद	 T,	0.38	79	,,	••

ऋम- संख्या	<u>ৰি</u>	जली पाने वाले का नाम	बिजली भार		ाम जिसके लिये बजली दी गई	कैफियत
१२	श्री	अनवरुल हक्क, गलशहीद, मुरादाबाद	0.78	किलोवा	ट रोशनी और पं	खा .
१ ३	,,	बेनीदास पोरवल मु० गुजरात मुरादाबाद	ो, ०.४६५	. ,,	"	•
१४		मैनजर, कारोनेशन इंटर — कालेज, मुरादाबाद	१.८	"	**	•
१५	"	चुन्ना लाल शंखधर, गरीखाना मुरादाबाद	०.४५	"	"	•
१६	11	शाबिर हुसेन, मुहल्ला डहरिय मुरादाबाद	ा, ०.४५	"	**	
१७	,,	अमीनुद्दीन बारसी, बछरावां	१० हार	र्ग पावर	आँद्योगिक	
१८	12	रामनिवास, चांदपुर	०.५ कि	लोवाट व	रोशनी और पंखा	
१९	"	बृजवासी लाल, चांदपुर	0.4	"	**	• •
२०	71	हकीम मुहम्मद मेहदी, अमरो	हा ०.१६५	>>	19	• •
्र ^{क्ष} २१	11	बृज मोहन शरण, अमरोहा	०,१०५	27	"	• •
२२	"	मृहम्मद मृजफ्फर हुसेन, बछरावां	. ०.२२५	17	***	• •
२३	11	बाकेलाल गुप्त, अमरोहा	०.२२५	. 11	**	• •
१४	"	मुहम्मद आविद, अमरोहा	०.२४५	. 23	"	• •
२५	22	अजहर हुसेन सिद्दीकी, चांबपुर	०.४९	"	77	
२६	2.7	सुदर्शन दयाल, हसनपुर	०.४९५	11	11	
२७	21	फजल अहमद, अमरोहा	6.28	* 1	11	• •
२८	"	जगदीश शरण, चन्दौसी आइल मिल, चंदौसी	o .१ ६	"	"	• •
२९	**	गोपालदास बदामी, हयातनगर, सम्भल	०.१६	"	72	• •

ऋग- संख्या	बि	जली पाने वाले का नाम	विजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	के कियत
३०	श्री	मनकूल शरण, मु० ठेर, . सम्भल	. ०.३ किलोवा	ट रोशनी और पंखा	• •
38		आनरेरी सेकेटरी, एस० एम कालेज, मिहीवाल, फारी होस चन्दौसी	० १.०६ ,, टल	"	• •
***	11	प्यारेलाल, मु० कोट, संभल	0.꼭 ,,	***	• •
in the	11	यशोदानन्दन वार्शनी मुहल्लापील, चन्दौसी	0.77 ,,	, 17	••
38		आनरेरी सेक्रेटरी, एस० . एम० कालेज, म्यू० होस्टल चन्दौसी		,, तथा काम	•
३५	11	शम्भू शरण रस्तोगी, . हथात नगर, सम्भल जिला मुजदकरनगर	. १५ हार्स पावर	तेल व आटा मिल	
35		डा० होरालाल सेकेंटरो . डो० ए० वी० कालेज, मुजफ्फर नगर	. ३ हासे पावर	टचूबवेल	• •
३७ ३८	श्री "	हरी रतन स्वरूप, नई मंडी, मुजफ्फरनगर रघुवीर शरण, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुजफ्फरनगर	₹ "	,, खती के के f	काम लेये
38	,,	पद्म प्रसाद जॅन, खदेरवाली स् मुजफ्फरनगर	ट्रीट, १० ,,	नेवाड़ फैक्टरी	
80	**	सज्जाद अहमद, कैराना, . जिला मुजफ्फरनगर जिला सहारनपुर	. ०.१९ किलोबाट	इ रोजनी और पंखा	
88	and the second	तेज अनामल वक्सं, सहारनपुर	८ २५ हास पावर	औद्योगिक काम के लिये	•••

ऋम− संख्या	बिजली पाने वाले का नाम	विजली का भार	काम जिसके लिये बिजली दी गई	कैफियत
४२	रानी राजकुमारी लयोरा, रुड़की जिला सहारनपुर	०.५ किलोबा	ट रोशनी ओर पखा	
४३	श्री चमन लाल, गगोह, जिला सहारनपुर	۰.३८ ,,	n	•
४४	,, आशाराम शराफ, देवबन्द . सहारनपुर	०.२४५ ,,	"	•
४५	,, नरेन्द्र कुमार जंन, देवबन्द, सहारनपुर	. ०.२५ ,,	**	••
४६	,, मकबूल अहमद, देवबन्द, . सहारनपुर	. १५ हार्स पावर	,, आटा	की चक्की
'ধও	सहारमपुर महत मनी भारती, निर्वानी अलाडा, कनलल हरद्वार यू		पानी पम्प करने के लिये	
ሄሪ	श्री जगदीश सिंह, नवाबगंज, सहारनपुर	०.२२५ किलोवा	ट रोशनी ओर पत्ना	• •
४९	डा॰ आर॰ बागची, कोट रोड, सहारनपुर	0.340 ,,	**	• •
५०	डा० आर० बागची,	. ३ हार्स पावर	एक्सरे प्लाट	• •
५१	श्री गिरधारी लाल ब्रह्मानन्द, विटीगंज, रुड़की, सहारनपुर	०.६ किलोवाट र	ਲਿ	शादी के ये टेम्पो- कनेक्शन
५२	,, राधाकृष्ण कबाड़ी बाजार. रुडकी, सहारनपुर	. १ "	"	**
५३	,, गणेश दास, रुड़की, सहारनपुर	o. પ ,,	"	"
ષ૪	,, सुन्दरलाल जैन, रुड़की, . सहारनपुर	. ং "	1)	,,
५५	,, यम० आई० अन्सारी, मु० सत्ती, रड़की, सहारनपु	०.५ ,, _] र	"	री कनेक्शन

ऋम – संख्या	बि	जली पाने वाले का नाम	बिजली भार	का	क⊺म जिसके लि बिजली∶दी गई	षे कैफियत
५६	श्री	धनप्रकाश गुप्ता, ५८ ई० डब्ल्यू० रुड़को, सहारनपुर	०.१ कि	लोवाट	रोशनी और पंखा	री–कनेक्शन
५७	"	कैलाशचन्द्र, गवर्नमेंट कंट्रेक्टर रुड़की, सहारनपुर	8	37	n	शादी के लिये टेम्पोरेरी कनेक्शन
५८	"	नेमचन्द जैन, रुड़की, . सहारनपुर	. २.५	22	37	19
५९	, ,,	हरनाम सिंह, मंगल भवन . इड़को सहारनधुर	• 8	* **	***	?
६०	77	सुन्दर लाल जैन, रुड़की, . सहारनपुर	. १	***	23	27
६१	23	प्रेमचन्द, कबाड़ी बाजार, रुड़की, सहारनपुर	०.५	2,	2,7	19
६२	. 77	भागोरय लाल सुमेरचन्द्र, . रुड़की, सहारनपुर	. ०.५	"	**	19
६३	71	कुंदालाल परशुराम, रडकी, सहारनपुर	4	"	n	,,
	i iyas					
ÉA	37	ज्ञानचन्द्र, होस्टल सुपरिन्टेंडेंट, गवर्नमेंट हाई स रुड़की, सहारनपुर	०.२५ कूल	**	17 (2)	13
६५	**	ज्ञान चन्द्र वर्मा, घड़ी साज, सहारनपुर	०.२५	99	. 11	95
६६	13	चण्डो प्रताद शर्राफ खड्की,. सहारनपुर	. ३		n , "	
Ę (9	77	महंत आज्ञाराम पुरी ९८ नम्बर तालाब रड़की, सहारनपुर			**************************************	22
ĘĞ		सुरजा मल वल्द भागीरथ ल सहारनपुर	ाल ०.५	,,		
६९		सेकेटरी, रामलीला कमेटी रुड़की, सहारनपुर			•	17

नन्धो 'ङ'

(देखिए १० जनवरी, १९५० के तारांकित प्रक्त सं० ४३ का उत्तर पीछे पष्ठ ३१८ पर) विज्ञापन

पंचायत इन्सपेक्टर की नियुक्ति--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हे कि युक्त प्रांतीय शासन द्वारा पंचायत इन्सपेक्टरों के पद पर नियुक्ति के ६ च्छुक उम्मीदवार को. जो निम्नांकित योग्यताये रखता हो, अपना मुद्रित (टाइप किया) प्रार्थना-पत्र आवश्यक सचना के साथ संचालक, पंचायत राज, प्रान्तीय संधित्रालय, लखनऊ के पास दिनांक मार्च, १९४९ ई० के ४ बजे सायंकाल तक भेज देना चाहिये। प्रार्थना-पत्र के प्राप्ति की सूचना चाहने वाले व्यक्ति उसे जवाबी रजिस्ट्री द्वारा भेजे।

- २--योग्यता (क)--उम्मेदवार का हाई स्कूल तथा इन्टरमिडियेट बोर्ड इन्टरमिडिवेट परीक्षा हिन्दी विषय के साथ अथवा सरकार द्वारा मान्य अन्य समक्ष परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि हिन्दी भाषा इन्टरमीडियेट परीक्षा का एक विषय न रहा हो तो हाईस्कूल परीक्षा का विषय हिन्दी अवश्य होना चाहिये।
- (ख) जिस उम्मीदवार ने निम्नांकित परीक्षाओं में से एक को भी हाईस्कुल परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ पास की हो या अंग्रेजी भाषा को ऐच्छिक विषय के रूप मे लेकर निम्नांकित परीक्षाओं में से किसी एक को पास किया हो तो ऐसी योग्यता प्रस्तर २(क) में निर्धारित न्य्नतम योग्यता के समकक्ष मानी जायगी।
 - (१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन , प्रयाग की मध्यमा परीक्षा।

 - (२) काञ्ची विद्यापीठ की शास्त्री परीक्षा। (३) गुरुकुल कांगड़ी की विद्याविनोद परीक्षा।
 - (४) क्वीन्स मंस्कृत कालेज की मध्यमा परीक्षा।

३--वेतन--वेतन दर १२०-६-१८० दक्षता रोक १०-२०० होगी।

४--आयु--उम्मीदवार की आयु १ जनवरी, १९४९ ई० को २२ वर्ष से कम और २५ वर्ष से अधिक न होनी चाहिये। सरकारी अथवा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी ४५ वर्ष की आयुनक के लिये जा सकेंगे। देश की सेवा मे त्याग किये और कष्ट पाये हुये व्यक्तियों के लिये आयुकी चरम सीमा ४ वर्ष अधिक होगी।

५--निवासी--उम्मीदवार युक्त प्रान्त अथवा बनारस, रामपुर या टेहरी-गढ़वाल की रियासत का निवासी हो।

६--आय तथा शिक्षा सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण-पत्रों की और दो जिम्मेदार व्यक्तियों के , जो उम्मोदवार के संम्बन्धी न हों , उत्तम आचरण के प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियां, तथा देश की सेवा में त्याग किये और कब्ट पाये व्यक्तियों के लिये इस सम्बन्ध में शिक्षा-प्रमाण का नीचे उल्लेख है उसकी प्रतिलिपि का आवेदन-पत्र के साथ भेजना आवश्यक है। उम्मीदवार की नियुक्ति के अधिकारियों से भेट करने (इन्टरव्यू) के समय कुल प्रमाण-पत्रों की मुल प्रतियां प्रस्तुत करनी पड़ेंगी।

७--उम्मीदवार को ग्रामीण-जीवन और समाज-सेवा कार्य का भी अनुभव होना चाहिये।

८-- उन्मीदवार को अपने व्यय पर चुनाव समिति के सन्मुख उपस्थित होना होगा।

९--चने जाने के पश्चात उम्मीदवार को एक पक्ष की शिक्षा दी जायगी जिस काल में उसे चार रुपया प्रति दिन के हिसाब से विद्व दी जायगी।

१०--इस पद के कुछ स्थान देश की सेवा में त्याग किये और कष्ट पाये व्यक्तियों लिये तथा समाज-सेवा (सोशल सर्विस)डिप्लोमा प्राप्त लोगों के भी लिये सुरक्षित कि गये हैं।

- ११—देश सेवा में त्याग करने वाले जो उम्मीदवार शासकीय पत्र सं० ओ—१२९०— ११८/१००३—४७, दिनांक ५ अप्रैल, १९४८ ई० जिसका संक्षेप में उद्धरण नीचे दिया जाता है, के अधीन शिक्षा सम्बन्धी योग्ताओं में सुविधा करने के इच्छुक हों, उसे उसमें दिये गये आदेशा-नुसार आवश्यक प्रमाण—पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा।
- १२--यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव डालेगा, तो वह पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायगा।
- १३—-प्रारम्भ में यह पद अस्थायी होंगे, परन्तु कालान्तर में उनका स्थायी हो जाना सम्भव है।
- सूचन (१) ज्ञासकीय पत्र सं० ओ०-१२९०/११८,-१००३ ४७, ता० ५ अप्रैल, १९४९ हैं० के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा या युक्त प्रान्तीय सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा, इंटरमीडियेट परीक्षा की योग्यता के बराबर समझी जायगी।
- (२) उपर्युक्त सुविधा का लाभ साधारणतः ऐसे उम्मीदवार के लिये सीमित रहेगा, जिसने कम से कम ६ मास की सजा पाई हो तथा जिसके प्रमाण में वह उस जिलाधीश का जिसके कार्यक्षेत्र में उसका निवास है, एक सार्टीफिकेट उस आशय का प्रस्तुत करेगा कि उम्मीदवार ने देश की राजनैतिक उन्नति के हेतु कम से कम ६ मास की सजा भोगी है।

मुक्ट बिहारी लाल दर,

मंत्रो, स्वशासन विभाग।

शासकोय आदेश संख्या २९१०/पं० रा० वि०—-११४-४८ दिनांक२६, फरवरी १९४९ ई० जो संचालक पंचायत राज विभाग से पबलिक सर्विस कमोशन के मन्त्रों को प्रेषित किया गया था, का उद्धरण—-

- २-- पदों के लिये निर्धारित योग्यतायें निम्नलिखित हैं --
- (१) निवास स्थान-सामाजिक कार्यों तथा ग्राम जीवन के अनुभवों के साथ संयुक्त प्रान्त का निवासी हो।
- (२) आयु-२२ से ३५ वर्ष केवल सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के कर्म-चारियों को छोड़ कर जिनकी अधिकतम आयु सीमा में ४५ वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।
- (३)शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें इन्टरमीडियेट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष संपुक्त प्रान्तीय सरकार से मान्य परीक्षायें, हिन्दी का अच्छा ज्ञान अनिवार्य ह।

शासकीय आदेश संख्या ९१७३ (पं रा० वि० दिनांक १३ जुलाई, १९४९ ई०) जो संचालक पंचायत राज विभाग द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के मन्त्री को प्रेषित किया गया था का उद्धारण—

३——मुस्लिम पदाधिकारियों में से थोड़े ही पदाकांक्षी प्राप्त होने के कारण शासन में मुसलमान पदाकांक्षियों को हिन्दी विषय के साथ हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण— पत्र को प्राप्त करने से मुक्त कर दिया है, यदि वे हिन्दी लिखने तथा पढ़ने में पूर्णतया योग्य हैं।

शासकीय आदेश संख्या ५०२८ पं० रा० वि०—-११४-४८, दिनांक २५ मार्च, १९४९ ई० जो संचालक पंचायत राज विभाग से पब्लिक सर्विस कमीशन के मन्त्री को प्रेषित किया गया था, के उद्धरण—-

३—इसिलये शासन ने निश्चित किया है कि वर्तमान चुनाव के लिये तथा आदेश संख्या २९१० ई० दिनांक २६ फरवरी, १९४९ के आंशिक संशोधन में निर्धारित योग्यताओं में निम्न-लिखित छूट दे दी जावे, यदि चुनाव समिति की राय में पदाकांक्षी पद के लिये पूर्णतया योग्य है तथा इन छूटों के न दिये जाने पर वह चुना नहीं जा सकता है।

(क) राजनैतिक पीड़ित (श्रेणी अ)।

- (अ) ज्ञासकीय आदेश संख्या १२९०, ११८---१००३-४७, दिनांक ५ अप्रैल. १९४७ ई० में निर्धारित ६ मास के कारावास के दंड की शर्त का पालन दृढ़ता के साथ न किया जावे। केवल इतना ही पर्याप्त होगा कि यदि पदाकांक्षी ने व्यक्तिगत रूप से देश के हित के लिये हानियां उठाई है तथा आदर्शनीय सेवाये की हों तथा अब वह अपने को निन्दनीय कार्यो मे पृथक रखता हो,
 - (ग) न्यूनतम आयु सीमा मे एक वर्ष की कमी कर दी जावे तथा अधिकतम आय सीमा ३५ से ४५ वर्ष तक बढ़ा दी जावेगी।
- (स) जिक्षा सम्बन्धी योग्यताये-यदि राजनैतिक पी़ितो में से निर्धारित जिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं के योग्य पदाकाक्षी पूर्ण संख्या मे न प्राप्त हो तो ऐसे पदाकांक्षी को उसके अत्युक्त जनकार्यों, साधारण कार्य क्षमता तथा अधिक अनुभव के दृष्टिकोण से चुना जा सकता ह, यदि उसकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, उस प्रकार के राजनैतिक पीडितों के लिये निर्धारित योग्यता से एक कक्षा कम है।
- (ख) साधारण तथा । समाज-सेवा प्राप्त पदाकांक्षी । श्रेणी ब तथा स विशेष परिस्थिति में 'निर्धारित न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमाओं मे एक वर्ष की छट दी जा सकती है।

नत्थी 'च' (देखिये १० जनवरी सन् १९५० ई० के ताराकित प्रदन सं० ४९ का उत्तर पोछे पृष्ठ ३१९ पर)

	संलग्न व्यो	रा	
योजनाओं के नाम	अनु दान व्यय १९४७–४८	अनुदान च्यय १९४८-४९	अनुदान १९४९–५०
१-ट्रैक्टरो की खरीद	१,५०,०००	१,६०,०००	६०,०००
-	९,६९१	१,८१,३४२	
२–कुषे (आरटीजन वेल्म) बनानेका कर्च	५०,०००	20,000	40 000
		९,६३८	
३-तार(Fancing Wire)	7,00,000	१,००,०००	५०,०००
	४९ ४७६	३,४३९	
४–५ ट्यूबवेल बनाने का खर्चा	१, ००,०००	Ę0,000	५०,०००
५-सीमेट (असवैस्टस) की चादरे और जाली की	40,000	२५,०००	પ ,૦૦૦
खरीद ६-पुराने हथकलो की मरम्मत	20,000	१५,०००	१६,०००
और नयों की खरीद	८,९३०	१३,५८६	
७–गांवों में नल द्वारा पानी पहुंचाने की योजना	१५,०००	80,000	१५,०००
	३,७३६	८,२१५	
८–भावर मे पानी की नालियों में टूट–फ्ट की मरम्मत	20,000	80,000	६०,०००
	५८,३५९	ऽ४७,६	
९रामनगर गन्दे नाले की योजना	80,000	40,000	७०,०००
		१७,८३३	
१०गांव की सड़कें बनाने की योजना		• •	१५,०००
११-मलेरिया रोकने के सम्बन्ध ग्राम कम्पाउन्डरों की योजना	H		20,000
कुल	६,३५,०००	५,१०,०००	8,88,000
	१,००,१९२	२,३७,८०१	
		'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

सन् १६४७-४८ ई०

सन् १९४७-४८ ई० में हल के मोल लेने में ९,६९१ ६० व्यय हुआ। जंगली जानवरों से बचाने के लिये खेतों के चारों ओर लगान के लिये ४९,४७६ ६० का तार खरीदा गया। भाबर में जल का अत्यन्त कष्ट है। गावों को पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की योजना पर ३,७३६ ६० खर्च किया गया। पानी लेजाने वाले नलों के सुधार एवं बनाने के लिये २८,३५९ ६० का व्यय हुआ। (हथकलों) हैन्ड पम्प के सुधारने तथा लगाने में ८,९३० ६० खर्च हुआ। इस तरह से १९४७-४८ में १,००,१९२ ६० कुल व्यय हुआ।

सन १९४८-४६ ई०

सन् १९४८-४९ ई० में १,८१,३४२ ६० से ६ ट्रैक्टर मय औजारों के मोल लिये गये। ३,४३९ ६० का तार खरीदा गया। नलों में पानी ले जाने की योजना पर ८,२१५ ६० व्यय हुआ। (हथकलों) हुँ-ड पम्प्स् की मरम्मत एवं लगान में १३,५८६ ६० व्यय हुआ। पानी की नालियों की टूट-फूट एवं सुधार में ३,७४८ ६० का खर्च पड़ा। तराई में कुछ कुयें इस प्रकार के बनते हैं कि उनमें से पानी सदैव बाहर फुवारे की तरह निकला करता है, ऐसे आरटीजन बेल्स बनाने में ९,६३८ ६० लगे। रामनगर के गन्देनाले की योजना में १७,८३३ ६० का व्यय हुआ। इस प्रकार सन् १९४८-४९ में २,३७,८०१ ६० का काम हो सका। सन् १९४९-५० ई० की योजनायें सरकार की स्वीकृति के लिये माल परिषद से आ चुकी हैं और ये अब सरकार के विचाराधीन हैं।

जेल भेजे गये जिला गिरफ्तारी के सजा पाने वाले जो वारन्ट जारी व्यक्तियों की व्यक्तियों की किये गये उनकी संख्या संख्या संख्या सहारनपुर Ę १,२६५ मुजफ्फरनगर ७४४ 86 मेरठ २,२५४ २८ ξ बुलन्दशहर १४८ 9 अलीगढ़ ६१३ १३६ मथुरा १९ ų आगरा 28 १६३ २० मनपुरी १७६४ ७० क्टा १५२ १०१ १ बरेली 385 Ę १३ विजनौर २०० 3 ₹ बदायं ३२२ 38 १५७ मुरादाबाद 88 ३१८ 22 **शाहजहांपुर** ५५३ ९ २० पीलीभीत

	51	व्यक्तियों की संख्या	गिरफ्तारी के जो वारन्ट जारी किये गये उनकी सख्या		जिला
६०८		• •	٥٥٧		फर्श्वाबाद
१०१		१८२	६९०	• •	इटावा
8		५०	SR	• •	कानपुर
१५		86	१५१	••	फतेहपुर
• •			८५३	••	इलाहाबाद
२१६		• •	८३४		झांसी
8		२५	२११	••	जालौन
8		• •	५१	••	हमीरपुर
•		१५६	५०४	••	बांदा
ą		Ę	४३७	••	स्रवनऊ
Ę			२२२	••	उन्नाव
६		, .	१२७	••	रायबरेली
२		3	ч	••	सीतापुर
		હ	395	• •	हरवोई
. •			8.8	• •	खोरी
७०		9	७८९	• •	गोंडा
		8	११९	• •	बहराइच
	-	<u> </u>	५९	4 8	बाराबंकी
٠	and any and any other con-	<u>१</u> ८२८	५९ १५,०३५	4 4	बाराबंकी कुल

३९३ नत्थी 'ज' (देखिये १० जनवरी, सन् १९५० ई० का तारांकित प्रश्न सं० ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

जिला		बटवारा अमीन	उजरती अमीन
नैनीताल 💳		• •	Ę
———— अल्मोड़ा	• •	• •	•
 बारामंडल .	•	२	۷
पाली रानीखेत तहसील	••	२	Ę
पिथौरागढ़ तहसील		8	Ę
लोहाघाट	•	8	२
गढ़वाल	• •		
 पौड़ी तहसील	• •	२	7
लैन्ड रेकार्ड आफिस पौड़ी	ı	8	
लैन्सडाउन तहसील	•	₹ .	२
चमोली तहसील		२	२

सूची २

कोर्ट का नाम जिला कार्यालय	उजरती अमीन का नाम १श्री श्री किसन २श्री देवान सिंह ३श्री किसन सिंह ४श्री रामदत्त ५श्री दान सिंह ६श्री हर दत्त
	२—श्री देवान सिंह ३—श्री किसन सिंह ४—श्री रामदत्त ५—श्री दान सिंह
	२—श्री देवान सिंह ३—श्री किसन सिंह ४—श्री रामदत्त ५—श्री दान सिंह
	४—–श्री रामदत्त ५—–श्री दान सिंह
	४—–श्री रामदत्त ५—–श्री दान सिंह
	५श्री दान सिंह
कारामंडल	१श्री गंगा दत्त
	२श्री मनी राम
	३श्री रेवाधर
	४श्री जीत सिंह
	५श्री दुर्गादत्त
	६श्री उम्मेद सिंह
	७श्री विष्णु दत्त
	८श्री मोती सिंह
मली रानीखेत	१श्री बच राम
dien andere	२श्री हर सिंह
	३श्री टीका राम
	४श्री हीरा बल्लभ
	५—श्री चिन्तामनी
	६-शी गोबिन्द बल्लभ
Combaras 2	१श्री मनोरथ
(प्यारागक	२श्री मोहन सिंह
	३श्री मदन सिंह
	४श्री बंशीधर
	५श्री धनोराम
	६श्री पूर्णानन्व
	१श्री खीम सिंह
लाहाघाट	२—श्री लक्षमन सिंह
and a real life rating	१श्री भूवन चन्द्र
बारहस्यू	२—श्री गुनानन्व
	३श्री शंकर सिंह
	State All All State Control
	१श्रो चन्दन सिंह
लन्सडाउन	२श्री विद्यादत्त
	A STATE OF THE STA
	१श्री नारायण सिह
चमाला	२—श्रो दरबान सिंह
	पाली रानीखेत पिथौरागढ़ लोहाघाट बारहस्यूं लेन्सडाउन चमोली

संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेम्बली

बुववार, ११ जनवरी सन् १६५० ई०

ग्रमेम्बली की बैठक ग्रमेम्बला-भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में ग्रारम्भ हुई

स्पोकर--माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टएडन

उपस्थित सदस्यां की सूची (१८७)

अचल सिंह अजित प्रताप सिंह अब्दुल बाक़ी अब्दुल मजीद अब्दुल मजोद ख्वाजा अब्दूल वाजिद, श्रीमती अब्दुल हमीद अम्मार अहमद खां अनेस्ट माईकेल फिलिप्स अली जर्रार जाफ़री अल्फ्रेड धर्मदास असगर अली खां अक्षयबर सिंह आत्माराम गौविन्द खेर, माननीय श्री आचिबाल्ड जेम्स फन्थम इन्द्रदेव त्रिपाठी इनाम हबोबुल्ला, श्रीमती उदयवीर सिंह एजाज रसूल कमलापति तिवारी करीमुरंजा लां कालीचरण टण्डन किशनचन्द पुरी कुंजबिहारी लाल शिवानी कुशलानन्द गैरोला कृपाशंकर कुण्ण चन्द्र

कृष्ण चन्द्र गुप्त केशव गुप्त केशवदेव मालवीय, माननीय श्री खानचन्द गौतम खुशवक्तराय खुशीराम खुबसिह गंगाधर गंगा प्रसाद गंगा सहाय चौबे गजाधर प्रसाद गणपति सहाय गणेश कृष्ण जैतली गोपाल नारायण सक्सेना गोविन्द वल्लभ पन्त, माननीय श्री गोविन्द सहाय चतुर्भुज शर्मा चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री चन्द्र भानु शरण सिंह चरण सिंह चेतराम छेदालाल गुप्त जगन्नाथ दास जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जगन प्रसाद रावत जगमोहन सिंह नेगी जय कृष्ण श्रीवास्तव जयपाल सिंह

जयराम वर्मा जहीरल हसनैन लारी जहूर अहमद जाकिर अली जाहिद हसन जुगुल किशोर त्रिलोकी सिह दयालदास भगत दाऊदयाल खन्ना द्वारिका प्रसाद मौर्य द्दीन दयालु अवस्थी दीन दयालु शास्त्री दीप नारायण वर्मा नफ़ीसुल हसन नवाजिश अली खां नवाब सिंह नाजिम अली नारायण दास निसार अहमद झेरवानी, माननीय श्री पूर्णमासी प्रकाशवती सूद, श्रीमती प्रागनारायण प्रेम किशन खन्ना फल्रहल इस्लाम फतेह सिंह राणा फुलसिंह बदन सिंह बनारसी दास बलदेव प्रसाद बशीर अहमद बादशाह गुप्त बाबू राम वर्मा बुजमोहनलाल शास्त्री भगवती प्रसाद दुवे भगवती प्रसाद शुक्ल भगवानदीन भगवानदीन मिश्र भारत सिंह यादवाचार्य भोम सेन मंगला प्रसाद मसुरिया दीन महफूजुर्रहमान महमूद अली खां मिजाजी लाल मुकन्द लाल अग्रवाल मुजयक्षर हुसैन

मुहम्मद अदील अब्बासी मृहम्मद असरार अहमद महम्मद इब्राहीम, माननीय श्री महम्मद इस्माइल मुहम्मद जमशेद अली खां मुहम्मद नबी मुहम्मद नजीर महम्मद यूसुफ़ मुहम्मद रजा खां मुहम्मद शकूर मुहम्मद शमीम मुहम्मद शाहिद फाख री मुहम्मद सुलेमान अधमी यज्ञनारायण उपाध्याय रघुनाथ विनायक घुलेकर रघुवंशनारायण सिह रघवोर सहाय राजकुमार सिंह राजाराम मिश्र राजाराम शास्त्री राधाकृष्ण अग्रवाल राधा मोहन सिंह राधेश्याम शर्मा रामकुमार शास्त्री राम कृपाल सिह रामचन्द्र पालीवा ल रामबन्द्र सेहरा रामधर मिश्र रामधारी पांडे राम बली मिश्र राम नूति राम शंकर लाल राम शरण राम स्वरूप गुप्त रोशन जमां खां लक्ष्मी देवी, श्रीमती लताफ़त हुसेन लाखन वास जाटब लालबहादुर, माननीय श्री लाल बिहारी टण्डन लीलाधर अष्ठाना लुत्फ अली खाँ लोटन राम बंशीधर मिश्र विजयानन्द मिश्र विद्याधर बाजपेयी

विद्यावती राठौर, श्रीमती विनय कुमार मुकर्जी विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ राय विष्ण शरण दुब्लिश वीरेन्द्र शाह वैकटेश नारायण तिवारी शंकर दत्त शर्मा शान्ति प्रपन्न शर्मा शिव कुमार पाटे शिव कुमार मिश्र शिव दयाल उपाध्याय शिवदान सिह शिवमंगल सिंह शिवमंगल मिह कपूर इयाम लाल वर्मा इयाम सुन्दर शुक्ल श्रीचन्द सिंघल श्रीपति सहाय सज्जन देवी महनोत, श्रीमती

सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री सरवत हुसेन सलीम हामिद ला साजिद हुसैन सालिग्राम जयसवाल सिहासन सिह सीताराम अञ्जाना सुदामा प्रसाद सुरेन बहादुर सिह सूर्य प्रमाद अवस्थी सईद अहमद हबीबुर्गहमान अन्सारी हबोबुर्रहमान खां हरगोविन्द पन्त हरप्रसाद सत्यप्रेमी हरिहरनाथ शास्त्री हसरत मोहानी हुकुम निह, माननीय श्री होती लाल अग्रवाल हेंदर बख्श

मश्नोत्तर

बुधवार, ११ जनवरी सन १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

प्रान्तीय रक्षक दल के सेक्शन लोडरों की ट्रेनिंग

*१--श्री बंदा गी गल (अनुपस्थित) -- क्या यह बात सही है कि सरकार सेक्शन स्रीडर की ट्रेनिंग प्रान्तीय रक्षक दल के प्रूप लीडरों द्वारा कैम्पों में हर थाने की अलग करवाना चाहती है ?

माननीय पुलिस सचिव(श्री लाल बहादुर)--जी नहीं।

*२--श्री बंदागो प्राल (त्रानुपस्थित) --क्या यह भी सच है कि सरकार न तो सेक्शन लीडरों को खाने का खर्च देना चाहती है और न उन्हें वर्दी-पेटी या सीखने के लिए राइफल या कोई दूसरा सामान ही देना चाहती ह ?

मनताय पुनिस सचिव-सेश्वान लोडरों की शिक्षा अपने गांव या उसके पास के गांव में होती हैं इसलिये उनके खाने के खर्च का सवाल नहीं उठता। उनको शिक्षा के सम्बन्ध में राइफिडें दी जाती हैं पर शिक्षा के बाद वापस ले ली जाती है। वर्दी-पेटी नहीं दी जाती।

*३--९-श्री बंश गोपाछ (ऋतुपंस्थित)-[स्थगित किये गये।]

जिला बोर्ड के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की बरखास्तगी

*१०—श्री वंशगोपाल (अनुपस्थित)—(क) क्या यह सच है कि जिला बोर्ड के जिन अध्यापकों ने हड़ताल की थी उनमें से बहुत से अध्यापक नये खुले हुए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर नियुवत किये गये हैं?

(ख) यदि हां, तो फतेहपुर जिले में ऐसे कितने अध्यापक है ? माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णा नम्द)—(क) जी हां।

(ख) ३२।

*११——श्रो बंदागोपाल (ग्रनुपस्थित) (क) क्या यह भी सच है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों के उन अध्यापकों के लिए बरखास्तगी का आदेश हो गया है जिन्हों ने जिल्हा बोर्ड के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट की थी ?

(ख) यदि हां, तो फतेहपुर जिले में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के कितने ऐसे

अध्यापक है।

माननीय शिक्ष सिचव--(क) जी नहीं, ऐसे सब अध्यापकों को बरखास्त नहीं किया गया है।

(ख) एक भी नहीं।

*१२—-श्री बंदागोपाल (ग्रनुपिधत)-सरकार ने यह नीति क्यों बरती कि जिन अध्यापकों ने स्वयं हड़ताल की उन्हें तरक्क़ी दी गयी और जिन्होंने केवल सहानु-भूति प्रकट की वह बरखास्त किये गये?

माननोय शिक्षा साँचव—जिन अध्यापकों ने हड़ताल में प्रमुख भाग लिया और जिनके सम्बन्ध में ऐसा विश्वास करने का समुचित कारण प्रतीत हुआ कि भविष्य में उनका व्यवहार ठोक रहेगा उनको बोर्डों ने क्षमा करिवया। उनमें जो हेडमास्टर होने के योग्य समझे गये उनको यह स्थान दिया गया है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जो १ फरवरी १९४९ के पश्चात् चेतावनी दी जाने पर भी ३ दिन से अधिक हड़ताल पर रहे, बरखास्त कर दिया गया। सरकारी नौकरी के नियमों में अपवाद करने का कोई कारण नहीं देख पड़ता।

फतेहपुर शहर में कन्ज्यूमर्स को प्रापरेटिव स्टोर्स का सरकारी बोरों की अधिक दामों पर खरादना

*१३—श्री बंदागोपान (ग्रमुपस्थित)—क्या सरकार को इस बातका पता है कि सरकारी गल्ले के राज्ञन की दूकानों में दूकानदार को बोरे एक रुपया चार आने की दर पर सरकारी गोदाम से खरीदने पड़ते हैं जबकि यह बोरे बाजार में १२ आने या अधिक से अधिक एक रुपया प्रति बोरा की दर से बिकते हैं।

माननीय श्रन्त सचिव (श्री चन्द्रभानु गुष्त)—डो० डब्ल्यू० क्वालिटी के नये बीटों के दाम आज्ञा-पत्र संख्या ११६३ २९-ए०-एफ दिनांक १८ मई १९४९ ई० द्वारा १ इपया ४ आना प्रति बोरी निर्धारित हुआ था।

बाजार का भाव उसके उपरान्त कुछ घटने लगा पर घटकों को प्रायः नये बोरों के दाम नहीं देन पड़ते हैं किन्तु एक बार उपयोग किये हुये बोरों की दर से ही दाम देना पड़ता है।

*१४—श्री बंदामोपाल (ग्रनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फतेहपुर शहर के कंड्यूमर्र कोआपरेटिय स्टोर ने, जिसके पास राशन की दूकानों का प्रबन्ध है, और अन्य दूकानदारों न जिलाशीश तथा जिला संप्लाई अफसर से यह प्रार्थना की कि उन्हें हर बर बोरा लेने पर मजबूर न किया जाय और उन्हें इस बात की अनुमति दी जाय कि वह लोग सरकारी गोदान से अपने बोरों में गल्ला ले जाया करे ?

माननीय ग्रन्न सचिव--जी हां।

*१५—श्री बरागोपाल (ग्रनुपस्थित)—क्या यह भी सच है कि फतेह्युर के जिलाधीश और जिला सप्लाई अफनर ने इस बात की सिफारिश प्रान्त के खाद्य विभाग से की? यदि हा, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया ? क्या सरकार इस निर्णय की एक नकल मेज पर रखने की कृपा करेगी?

म् निर्वाय श्रन्न सचिव--प्रथम भाग--जी हां।

द्वितीय भाग—सरकार ने बड़े—बड़े नगरों में माह जून के दूसरे पक्ष में बोरियों के प्रच— लित दाम की सूचनाये मंगा कर यह निश्चय किया कि माह मई और जून में गल्ले सहित दिये हुय बोरियों के दाम दो आना प्रति बोरी के दर से कम कर दिया जाय तथा हिसाब करके यह घंटकों के हिसाब में मजरा कर दिया जाय अथवा उनको यह रकम लोटा दो जाय।

तृतीय भाग—आज्ञा पत्र संख्या ११६३/२९-ए-एफ, दिनांक १८ मई, १९४९ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखी है।

(देखियं नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

*१६--श्री बदागे।पाल (अनुपस्थित)--सरकार इस प्रकार की नीति क्यो बरतती है कि दूकानदार को इस बात पर मजबूर किया जाय कि वह सरकारी बोरों को बाजार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदे!

मानर्नाय ग्रन्न मिचित्र--यह सही नहीं है कि सरकार बोरियों के दाम बाजार भाव से अधिक लेती हैं। सरकार इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखती है कि सरकारी बोरियों के दाम बाजार भाव के आधार पर ही रक्खे जाये।

ग्रागरा-बाह सड़क पर सरकार का बसें चलाने का विचार

*१७--श्रीमती लक्ष्मी देवी (अनुपस्थित) — (क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा-बाह सड़क पर कितनी सवारी की लारियां (बस) चलती है और औसतन कितने यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं ?

(ख) क्या सरकार इस सड़क पर यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज की बसे चलाने का विचार करती हैं? यदि हां, तो कब से ?

माननोय पुलिस् सिचय--(क) आगरा-बाह सड़क पर इस समय २९ बर्से चलती है और औसतन ६९० यात्री प्रतिबिन सफर करते है।

(ख) जी हां। आशा है इस साल के अन्त तक रोडवेज की बसें इस पर चल सकेंगी।

त्रागरा जिले में इकैतियों को रोक-धाम

- *१८--श्रामनी लक्ष्मी देवी (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में गत दो वर्षी में कितनी डकैतियां और क़त्ल हुए?
- (ख) इनमें से कितनी घटनाएं तहसील बाह और फतेहाबाद में हुई और कितनी अन्य तहसीलों में ?
 - (ग) इनको रोकने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय पुलिन सिच्च--(क) सूचना इस प्रकार है--

डकैती कत्ल		• •	१ <i>९४</i> ५ ६	4	१९४९ ६३ ४६
		(ख) बाह ओर फतेहाबाद तहसील में		अन्य तहमीलो मे	
		१९४७	१९४९	१९४ ७	१९४९
डकैती		२६	१९	२९	ጻጸ
करल	•	१६	१५	४९	38

(ग) इन सम्बन्ध में इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने आगरा जाकर डकती रोकने के बारे में आगरा शहर और जिले के प्रधान लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से भी उन्होंने बाते की और विशेष आदेश दियें। हाल ही में दो नई पुलिस चोकी खोलने और चार यानों में पुलिम की सख्या बढाने की आज्ञा दे दी गयी हैं। इस जिले में रेलो और सडको की कमी तथा नदी के कछार की भूमि अधिक हैं और ग्वालियर तथा धोलपुर की रियासतों मिली हुई होने के कारण उधर से डकँतों के जत्थे आया करते हैं। कोशिश की गयी हैं कि रियासतों के साथ सिम्मिलित प्रयत्न करके इसका मुकाबिला किया जाय। जिले की पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में काफी सतर्कता से काम किया है और मशहूर डकैतों के जत्थों के कुछ आदमी गिरफ्तार किये गये हैं। इस साल २६ डकैतियों में से १० का पता लगाया जा चुका हैं। पी० ए० सी० की पाच कम्पनिया वहा है। उनके साथ पुलिस ने लगभग १५० छापे मारे हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बहराइच के पशुवध सम्बन्धी उपनियमें। पर सरकारी नीति पर ग्रसन्तोष

- *१९—श्री भगवान दीन मिश्र(अनुपस्थित)—(क) क्या सरकार को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच ने पशुबध सम्बन्धी उपनियम सर्वसम्मति से पास करके ता० ९ फरवरी, १६४९ ई० को सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे ?
- (ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि ये उप-नियम सरकार द्वारा घोषित नीति के ही आधार पर बनाये गये थे ?
- (ग) क्या सरकार को मालूम है कि दो बार तार द्वारा स्मरण कराने पर भी अब तक उसकी स्वीकृति नहीं आयी?
- (घ) क्या यह सही है कि कमिश्नर फैजाबाद ने लगभग ४ महीने के बाद उपनियमो की अंगेजी प्रतिलिपि बोर्ड से मांगी?
- (ङ) प्रान्त की भाषा हिन्दी घोषित हो जाने पर अंगेजी प्रतिलिपि भेजना बोर्ड के लिए क्यों आवश्यक था ?

मोननोय स्वशासन सच्चिव (श्री आत्माराम गोबिन्द खेर)—(क) कमिश्नर की रिपोर्ट द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के पशु—संबंधी उप नियम कमिश्नर की २५ फरबरी, १९४९ को मिले।

- (ख) ऐसे उपनियमों की स्वीकृति का अधिकार अब किमश्नरो को दे दिया गया है इस कारण वे उपनियम सरकार के पास नहीं आये।
- (ग) कमिश्नर की रिपोर्ट से सरकार को विदित हुआ है कि इस सम्बन्ध में किमश्नर को केवल एक तार ता० १७-मई, १९४९ ई० को मिशा था।
 - (घ) जी नही, उपनियमों की अंग्रेजी प्रतिलिपि लगभग २।। माह बाद मागी गई।
- (ट) चूकि गजट अभी हिन्दी ओर अंगेजी दोनो ही भाषाओं में प्रकाशित होता है अतः गजट की अंगरेजी प्रति के लिये उपनिथमों की अगरेजी प्रति का भेजना बोर्ड के लिये आवश्यक था।

ं२०--श्रो भगवान दोन मिश्र (अनुपस्थित)--क्या यह भी सही के बोर्ड हरा अंगरेजी प्रतिया भेजने पर भी बोर्ड को बाध्य किया गया कि वह अगरेजी से भी उपित्यम पास करके भेजे?

माननीय स्वज्ञामन सचिव--जी हा, क्योंकि बोर्ड ने अपने २३ मई मन् १९४९ पत्र में उपनियमों की अगरेजी प्रति की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं ली थी।

ै २१--श्री भगवान दीन भिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार ऐसी अवस्था में यह बतलाने की कृपा करेगी कि कमिश्नर की यह टाल-मटोल की नीति किम आधार पर अवलिम्बत है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि म्यूनिसिपल बोर्ड बहराइच के पशुअध सम्बन्धी उपित्यमी पर सरकारी नीति के विरुद्ध जिले में असन्तोप फैला है ?

मन्ताय स्वशासन सचिव--किमश्नर ने अपनी जिस्मेदारी के कारण उपनियमों की अंगेजो प्रति को भी बोर्ड द्वारा पाम कराना आवश्यक समझा। असन्तोष के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आई।

राजनीतिक पाडितों को मुविधायें

*२२—श्री श्रोचन्द सिहल (अनुपस्थित)—सरकार ने राजर्न तिक पंडितो को रोजगार में लगाने के लिये क्या—क्या सुविधाएं दी है ?

मौननीय पुलिस सचिव--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है उसका सक्षिष्त व्योरा यह है--

इस प्रान्त में राजनीतिक पीड़ितों को उद्योग में लगाने के लिये २९,५०० रू० एकमुस्त धन के रूप में तथा ४३,००० रू० उधार दिया गया है।

अगस्त, १९४२ आन्दोलन से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के लिये सरकार ने अब तक २३,१८,४१० रा॰ दिये हैं।

म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के १७७ अध्यापक जो नौकरी से हटा दिये गये थे फिर से अपनी जगह पर नियुक्त किये गये। कुछ अध्यापकों को जिन्होंने सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लिया था १६,४८३ ६० ११ आ० बकाया तनख्वाह के रूप में दिया गया।

सरकार ने तराई और भावर स्टेट में कुछ राजनीतिक पीड़ितों को ११६ एकड़ जमीन खती करने के लिये दी है।

यातायात विभाग से भी उन्हें ट्रकों के परिमट दिये जाने की व्यवस्था है।

श्री जगमोहन मिंह नेगी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि सन् १९२१, १९३१ और १९४०-४१ के सत्याग्रहियों को राजनीतिक पीड़ित मानना क्यों अस्वीकार किया गया?

माननीय पुलिस सिचिव—राजनीतिक पीड़ित मानने से तो कभी इन्कार नहीं किया जा सकता चाहे जिस किसी राजनीतिक काम में किसी ने भी तकलीफ उठाई हो लेकिन जहां तक इस मुआविजे का सवाल था इसके बारे में जो सरकारी हुक्म निकला था उसमें यह लिख दिया गया था कि जिन लोगों ने सन् १९४२ में नुकसान उठाया है सिर्फ उनके मुआविजे का सवाल पैदा होता है और उन्हें मुआविजा दिया गया है। श्री जगम'हन सिह नेगी ——मैं यही जानना चाहता था कि यह मुआविजा उन लोगों को भी क्यों नहीं दिया गया जो पहले के हैं ?

माननीय पुलिस सचिव—जहां तक नुकसान का सवाल हे यानी कि सी का मकान उजाड़ दिया गया हो, जला दिया गया हो इस तरह के नुकसान बहुत ज्यादा सन् १९४२ में ही हुये। इससे पहले दूसरे किस्म के नुकसान थे। यानी जो गिरपतार हुये उन पर जुर्माने हुये। तो जहां तक जुर्माने वग्नैरह का सवाल है उस जुर्माने वग्नैरह को लोटाने की बात तो पुरानी हुई, जिन पर जुर्माने वग्नैरह हुये उनको दिये भी गये। लेकिन बड़े पेमाने पर जुर्माने वग्नैरह सिर्फ १९४२ में हुये। उन्हीं को लोटाने की बात सरकार ने इस हुक्म में उठाई।

*२३--भ्रो भ्राचिन्द सिघल (अनुपस्थित)--इम्दाद के लिये कितने राजनीतिक पीड़ितों ने प्रार्थना-पत्र भेजे ? उनमे से कितनों को इम्दाद मिली और किस-किस रूप में ?

माननीय पुलिस सचिव—हर एक आदमी का पूरा व्योरा देने में सूनना बहुत लम्बी हो जायगी ओर उसे इकट्ठा करने में काफी समय भी लगेगा परन्तु माननीय मदस्य जिस व्यक्ति विशेष के बारे में सूचना चाहे यह दी जा सकती है। सरकार ने प्रान्त में अब तक ५६२ राजनीतिक पीड़ितों को १,००,७४० रु० सालाना पेशन के रूप में ओर ५८,३५० रु० एक मुक्त रकम के रूप में दिया है।

श्रा मुहम्मद् अन्तार अःमद्—क्या गवर्तमेट बतलायेगी कि सन् १९४२ ई० मे मारे गये लोगों को कुल कितनी दरख्वास्ते मुआविजे और कर्जे के लिये आई !

माननीय पुळिम सचिव-इसके लिये नोटिस की जहरत है।

थ्रा मुहत्मद स्थारार ग्रहमद—क्या गवर्नमेट बतलायेगी कि जन लोगां की दरख्वास्ते आईं उनमें कितने फीसदी लोगों को इम्दाद दी गयी ?

मानर्न,य पुलिस सिचव--बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकता लेकिन अंदाजा यह है कि ३५, ४० फीसदी लोंगों को दी गयी।

र्थ्या मुहम्मद् श्रासरार श्राहमद्—क्या गवर्नमेट बतलायेगी कि बकीया ६० फीमदी लोगों को इम्दाद किस वजह से नहीं दी गयी ?

माननीय पुल्लिस सचिव—बहुत से ऐसे केसेज है जिनकी अभी जांच हो रही है, कुछ लोगों ने दरख्वास्तें ही ठोक से नहीं दीं। बहुत से लोगों ने समय के बाद दरख्वास्ते दी। इसी कारण इतनी तादाद है जिनको अभी तक इम्दाद दी जा चुकी है।

श्री मुहः मद श्रामरा श्राहमर--क्या गवर्नमेंट बतलायेंगी कि कुछ लोगों को इस कर कर्मेन्सेशन दिया गया कि उन्होंने कम्पेन्सेशन लेने से इनकार कर दिया ?

माननीय पुिल्स सचिय--मुमिकन है कि दो-चार ऐसे हों, लेकिन अच्छी तरह से जांच कर फैसला किया गया है।

*२४--श्रा श्राचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित) -- क्या एप्रूवर्स (इकबालियो) को भी सरकार ने राजनीतिक पीड़ितों की श्रेणी में रक्खा है ? क्या सरकार को पता है कि कुछ इक्कबाली राजनीतिक पीड़तों की तरह से सरकार से इम्दाद और सहूलियत ले रहे है ?

माननीय पुलिस सचिव--सरकार ने अपनी जानकारी में किसी भी एप्रूवर्स (इक्तबाली) को कोई सह्हिल्यत और सहायता नहीं दी है।

श्र शंगढ़ के हाफिज उस्मान को हथकड़ी डालक जेल भेजना

*२५—थ्रा श्राचन्द्र सिञ्चल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस-किस दफा के मुलजिम और क्रेंबी हथकड़ी डाल कर कचहरी से जेल भेजे जाते हैं? माननीय पुलिम सिच्च—विचाराधीन और सजा पाये हुये कैदी के हथकड़ी डालने के नियम साथ नत्थी है।

(देखिये नस्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४६१ पर)

*२६--श्रो श्राचन्द्र मिघल (अनुपस्थित) -- नया तरकार को पता है कि हाफिज उस्मान साहब, जो अलीगढ़ के एक प्रतिष्ठित कांग्रेसमैन है और जिनको अलीगढ़ में दफा १७४ आई० पी० सी० में ५० र० जुर्माना हुआ था, हथकड़ी डालकर ता० २७ जून को जल भेजे गये?

माननाय पुलिस सचित्र—श्री हाफिज उस्मान को अलीगढ़ के जुडीशिल मिजस्ट्रेट ने २६ जुलाई, १९४९ ई० को इंडियन पीनल कोड की घारा १७६ के अन्तर्गत ५० ६० जुर्माना और जुर्माना न देने पर १ महीने की सादी क़ैंद की सजा दी थी। श्री हाफिज उस्मान ने जुर्माना नहीं दिया और वे क़ैंद भुगतने को जेल भेजे गये। जब वे अदालत से अदालत की हवालात ले जाये जा रहे थे तो साधारण श्रेणी के क़ैंदियों के नियमों के अनुसार उन्हें हथकड़ी डाली गयी थी। रास्ते में अकस्मात् सुपरिन्टेडेट पुलिस ने जो अपने दफ्तर से निकल रहे थे उनको देखा और उनकी हथकड़ियां उतरवा दी। श्री हाफिज उस्मान के जेल जाते समय हथकड़ियां नहीं थीं।

श्री मुहम्मद ग्रस्रा श्रह्मद--क्या गवर्नमेट बतलायेगी कि हाफिज उस्मान को जब सजा दी गई तो उन्हें। किम क्लास के लिये रखा गया ?

मानीय पुलिस सचिय--अदालत ने जब कोई क्लास नहीं दिया तब वे आडिनरी क्लास में ही आते हैं।

श्री मुहम्मद इसरार ग्रहमट—क्या गवर्नमेंट को इल्म है कि हाफ़िज उस्मान के मुताल्लिक सब लोगों को मालूम था कि वह न भाग सकते ह ओर उनकी वहां काफी इज्जत भी है तो फिर उनको हथकड़ी क्यों लगाई गई?

माननीय पुलिस सिवन—जहां तक हाफिज उस्मान साहब की जात का ताल्लुक है मैंने उन्हें इस वाक्रये के बाद पहले—पहल देखा और इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मुअज्जिज शख्स है और जो मुझ पर उनकी बानों का असर पड़ा वह मुझे एक बहुत ऊंचे किस्म के आदमी मालूम हुये और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि उनको हथकड़ी लगाई गई। लेकिन आप देखेंगे कि उनको गिरफ्तार कर ले जाने वाले कांस्टेबिट्स थे और कांस्टेबिट्स को इस बात का ख्याल होना या इस बात की जानकारी होना कोई लाजिमी बात नहीं थी। जबकि अदालत ने उनको क्लासिफाई नहीं किया तो उन्होंने जो माम्ली कायदा था उसको बरता। मगर वह कुछ हो क़दम गये थे कि मुपरिन्टेडेट पुलिस ने उनको देखा और अपने सामने हथकड़ी उतरवा दी और वह जेलखाने बगौर हथकड़ी पहनाये हुये ही ले जाये गये।

श्रा मृहम्मट शाहिद फाखर्।—क्या गवनंमेट मेहरबानी करके बतायेगी कि जिन लोंगोंने उनको हथकड़ी लगाई थी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी?

मानीनय पुलिस सचिव--कार्यवाही इसिलये नहीं की जा। सकती, क्योंकि उन्होंने कोई बेकायदा काम नहीं किया।

*२७--श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेंगी कि हाफिज उस्मान के हथकड़ी किस नियम के अनुसार डाली गयी थी?

मानर्नाय पुलिस सचिव--जैसा प्रश्न २६ के उत्तर में कहा गया है, श्री हाफिज उस्मान के हथकड़ी नियमानुसार ही डाली गयी थी।

प्रतिस के सोशल प्रामीक्यूटिंग अफसरों का जुडोशियन मैजिस्ट्रेट बनाया जाना

*२८--श्री श्रीचन्द ियाल (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि मरकार ने कुछ पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यूटिंग अफ़सरों को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाया है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा-मंत्री (श्रोगोविन्द सहाय)—पिंडलक सर्विस कमीशन द्वारा चुने गये जुडीशियल मिजस्ट्रेटों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहिले स्पेशल प्रासोक्यूटिंग आफिसर रह चुके हैं।

मैजिस्ट्रेटों के मुकदमों की पाक्षिक रिपार

*२९--श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि हर मैजिस्ट्रेट अपने मुकदमों की पक्षिक रिपोर्ट अपने जिलाधीश के पास भेजता है ?

माननीय प्रयान सचिव के सभा-मंत्री (श्री चरण गिह)--जी हां।

श्री मुहस्मद ग्रस्रार ग्रहमद—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि जुडीशियल मैजिस्ट्रेट और दूसर डिप्टी कलेक्टर जिलाधीश के लिये यह रिपोर्ट किस गर्ज से भेजते हैं? श्री चरण खिह—उनकी इत्तिला के लिये और अगर बाद में कभी जरूरत पड़े तो

नके मश्रविरे के लिये।

श्री महस्मद ग्रस्रार ग्रहमद—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि यह कायदा कब से चला आ रहा है और कब तक जारी रहेगा?

श्री चरण सिह— यह बहुत दिनों से चला आ रहा है और गवर्नमेंट जब तक जरूरी

समझेगी कायम रखेगी।

श्री मुहस्मद् ग्रसरार ग्रहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि यह रिपोर्ट बजाय सेशन्स

जज के कॅलेक्टर को क्यों भेजी जाती है ?

श्री चरण सिह—यह पन्दह रोजा रिपोर्ट कहलाती है, पहिले से मजिस्ट्रेट इसको मजते रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी किसी अदालती मामले में हिदायत नहीं देता। अगर कोई एक्जीक्यूटिव मामला हो तो हिदायत जरूर देता है, लेकिन अदालती मामले में नहीं।

*३०-श्री श्रीचन्द्र सिंघल (अनुपस्थित)--क्या यह भी सच है कि जिलाधीश उनके फैसलों पर टोका करके और अपनी राय देकर रिपोर्ट को मैजिस्ट्रेंट के पास उसकी जानकारी के लिये भेज देता है ?

श्रीचरण सिंह--जी नहीं।

कृषि विभाग के लिए ट्रैक्टरों को खरीट

*३१—श्री मुहम्मद ग्रसरारग्रहमद—क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि विभाग यो किसी और विभाग के लिए फ़ोर्डसन मेजर ट्रैक्टर खरीदे हैं ? यदि हां, तो कब ? कितने और कितने दामों पर ?

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार ग्रहमद शेरवानी) — जी हां।१५ नवम्बर सन् १९४७ ई० से सितम्बर सन् १९४८ ई० तक १०० द्रैक्टर। प्रति द्रैक्टर का मूल्य १२,००० रुपया।

श्री महम्मद् ग्रम्सरार श्रहमद—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ये १२ लाख के ट्रैक्टर्स एक ही किस्म के बराहरास्त खरीदें गये या स्टोर पर्चेज के जरिये से और किस गर्ज से ?

माननीय कृषि सञ्चित—गर्ज तो जाहिर है जो परतो जमीन पड़ी है तराई भावर और मेरठ को खादर की जमीन को काइत में लाने के लिये खरीदे गये और इसके मुताल्लिक जो भी खरीददारी हुई वह स्टोर पर्चेज डिपार्टमेंट के जरिये से हुई।

*३२--श्री मुहम्मद ग्रसरार श्रहमद--इन ट्रैक्टरों की हार्स पावर क्या है? सरकार ने इसकी कैसे जांच की ह ?

माननोय कृषि सचिव---२२ हार्स पावर। अमेरिका की मेसर्स फीड कम्पनी ने हास पावर का प्रमाण दिया है।

हर एक कारलाने के हर एक ट्रैक्टर की हार्स पावर अन्तर्राष्ट्रीय बेक हार्स पावर की जांच के अनुसार ३५ हार्स पावर है। यह जांच इंजिन के बोरें स्ट्रोक की ओर खोलने

के बाद अन्तर्राष्ट्रीय कांस्टेट को गुणा करके निश्चित की जा सकती है।

ऐसी जांच वहीं पर की जा सकती है जहां पर विस्तृत सुविधायें मिलती हैं कि इंगलैंड की नेशनल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इस्टीट्यूट और अमेरिका की अमेरिकन इंस्टोटचूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग निवास-का में। इस देश में इस प्रकार की आसानियां भी नहीं मिलती है। इस कारण भिन्न-भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध कारलानों द्वारा प्रमाणित हार्स पावर सत्य मान ली गई है।

*३३--श्री मुहम्मद ग्रस्रार ग्रहमद्-यह ट्रैक्टर किस फर्म से खरीदे गये हैं और

उस फर्म के कौन-कौन डाइरेक्टर हैं।

माननीय कृषि सचिव-सर्वश्री यूनाइटेड प्रावितेज कर्माशयल कारपोरेशन ३, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मैनेजिंग प्रोप्राइटर श्री एम० वाही। यह एक प्राइवेट संस्था है।

*३४--श्री मुहम्मदग्रसरार ग्रहमद--क्या सरकार बतायेगी कि इस फर्म ने

क्या कमीशन दिया है?

मं ननीय कृषि सचिव--कुछ नहीं।

*३५--श्री मुहम्मद् असगार ग्रहम्द्-क्या सरकार बतायेगी कि इस प्रान्त में किस-किस माडल, किस-किस हार्स पावर, किस-किस कारखाने और किस-किस कीमत के द्रैक्टर मंगाये जा रहे हैं और उनको खरीदने के लिये सरकार क्या सुविधायें देती है ?

माननीय कृषि सचिव--इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना नत्थी है-

सरकार कोई भी सुविधा प्रत्येक सरकारी विभाग को ट्रैक्टर खरीदने में नहीं देती है। आमतौर से प्रत्येक सरकारी विभाग में किसी भी सामान को खरीदने के लिये आईर कानपुर में स्थित प्रान्तीय डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के पर्चेज आफिसर के द्वारा दिये जाते हैं।

प्रत्येक फर्म जो कि ट्रैक्टर का व्यापार करती है जब कभी चाहे इस आफिसर

से स्वयं मिल सकती है या पत्र-व्यवहार कर सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग 'आगे पृष्ठ ४६२ पर)

श्री मुहम्मद् असरार अहुमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि सवाल में एक जगह २२, एक जगह ३५ और नत्थी में १८ हार्स पावर दिया हुआ है, तो कौन सा हार्स पावर सही

माना जाय, फोर्डसन मेजर का ?

माननीय कृषि सचिव-यह एक टेक निकल मामला है जिसको में समझता हूँ मुअज्जिज मेम्बर खुद नहीं समझे। हार्स पावर एक-एक ट्रेक्टर में कई-कई किस्म के होते हैं। एक हार्स पावर ड्रा पावर होता है जो हर ऐंजिन में डिफरेंट (भिन्न) होता है। यह ऐंजिन की साल के ऊपर कैलकुलेट हिसाब किया जाता है। इसके अलावा उसमें और भी हार्स पावर रहती है।

श्री मुहम्मंद् ग्रस्ार ग्रहमद-क्या गवर्नमेंट यह बतायेगी कि जिस कम्पनी से यह

ट्रैक्टर्स खरीदे गये उनके हिस्सेदार और डाइरेक्टर्स कौन-कौन से हैं?

माननीय कृषि सचिव--इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है। माननीय सदस्य सवाल नम्बर ३३ की तरफ तवज्जह करें।

श्री मुहस्मद् असरा स्माद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि मैनेजिंग डाइरेक्टर के अलावा और कौन-कौन से डाइरेक्टर्स हैं?

माननीय कृषि सचिव--मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मुझे मालूम

नहीं है। श्री मुहम्मद ग्रसरार श्रहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि इस कम्पनी से गवर्नमेंट को कोई डिस्काउंट क्यों नहीं मिला जबकि और सब ट्रांसपोर्ट वेहीकिल्स पिक्लिक को कमोशन पर मिलते हैं?

माननीय कृषि मिचव--मुझे इसके मुताल्लिक माल्म नही है। यह डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रोज के द्वारा पर्चेज किये गये। जो कीमत ठहराई गई, वह कमीशन का लिहाज करके ठहराई गई?

जिजा बदायूं में विजली के लोड में वृद्धि

ं ३६—श्री मुहम्मट ग्रसगर ग्रहमद्—क्या सरकार बतायेगी कि जिला बहाय में इस्लाम—नगर डिमयानी तथा बिलसी में बिजली का लोड मन् १९४६-४७-४८ और १९४९ ई० में कितना बढ़ाया गया और किस आधार पर?

माननीय सार्वजनिक निमाण माँचिय क मभा-मही। (श्रीलताफत हुमन)--मान-नीय सदस्य के प्रश्न से यह ठीक-ठीक जाहिर नहीं होता कि वे इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की बिजली की अधिकतम मांग की सीमा (Maximum Demand Limit) की वृद्धि जानना चाहते हैं या यह जानना चाहते हैं कि इन स्थानों में नये कनेक्शनों के देने से लोड में

क्या वृद्धि हुई है।

जहा तक अधिक तम मांग की सीमा (Maximum Demand Lunt) का सवाल है, इस्लाम नगर, उझानी और बिलसी के बिजली पहुँचाने वाली कम्पनी की माग की सीमा १७० किलोवाट तक सरकार द्वारा १९४६ में बढा दी गई थी ओर इसी तरह बदायूं की बिजली कम्पनी की मागे १९४६ में १३० किलोवाट बढा दी गई थी। इन कम्पनियों की मांग की सीमा सरकार ने चीफ इजीनियर, नहर विभाग को सिफारिश पर मुक्रेर की थी। इसके बाद और कोई वृद्धि नहीं की गई।

यदि माननीय सदस्य का मंशा नये क्नेक्शनों के देने से बिजली के लोड में हुए इजाफे से

है, तो उसका विवरण निम्नलिखित है--

स्थान		वर्ष	बिजली क	ा लोड
इस्लाम् नगर		१९४६	o.३४ किल	ोवाट
•		१९४७		, ,
		१९४८		
		१९४९		
बिलसी	4 8	१९४६	१.६४	13
		१९४७	१६.९०२	,,
		8886	• • • •	17
		3686		29
उझानी		१९४६	८७.४७६	**
		१९४७	२.२४२	"
		8886		•
		१९४९	१९.५	"
बदार्यु		१९४६	२४.५१०	,,
		१९४७	22.300	77
		१९४८	०.७६५	11
		१९४९	39.000	"

उपर्युक्त कनेक्शन सरकार या बिजली कम्पनियों द्वारा मंजुर किये गए थे।

प्रश्नोत्तर ४०७

श्री मुहम्मद स्रामराग ग्रहमद—क्या गवर्नमेट यह बतायेगी कि शहर बदायं के मुकाबिले में कस्बा डिमयानी की बहुत ज्यादा बिजली की माग क्यो मजूर की गई?

श्री छता कत हुसैन—वहा ज्यादा बिजली की जरूरत पेश आई, इसलिये वहा ज्यादा

दी गई।

~३७--श्री मुहम्मट श्रसरार ग्रहमद्--क्या सरकार बतायेगी कि शहर बदाय्ं का लोड उपरोक्त सालो में कितना-कितना बढ़ाया गया ?

श्री ताताकत हुसेन--यह सूचना प्रक्त संख्या ३६ के उत्तर मे दी जा चुकी है।

पशु-पालन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*३८--श्री हर गे। विन्द् पत्त-(क) संयुक्त प्रान्त के सरकारी पशु-पालन विभाग में किनन सीनियर पोल्ट्री इन्स्पेक्टर तथा कितने जूनियर पोल्ट्री इन्स्पेक्टर काम करते हैं ?

- (ख) वे उक्त पदों पर कितने वर्षों से आरूढ़ है तथा उनके वेतन के वर्तमान ग्रेड क्या है? माननोय कृषि स्चिव—(क) ६ सीनियर और १० जूनियर।
- (ख) पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुनाव किये जाने से पहले ये कर्मचारी इन जगहो पर १९४४ ई० से काम कर रहे थे। १ अप्रैल १९४७ ई० से इन जगहो के लिये जो नये स्केल मंजूर किये गये हैं वे ये है।

सीनियर--२००--१५--३५० रु० जूनियर १२०--६-२१०--१०--२५० र०

श्रो हरग बिन्द पन्त--जिन पदाधिकारियों के विषय में प्रश्न है और जिनकी नियुक्ति सरकारी मुहकमों में सन् ४४ में हुई, क्या ये लोग उससे पहले यू० पी० पोल्ट्री एसोसियेशन में भी नौकरी पर थे ?

ं माननोय कृषि सचिय—इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे मकता। नोटिस मिलने पर दे सकता हं।

* ३९-भ्रा हर्गा बन्द पन्त--स्या सरकार ने उक्त पदों के लिये हाल मे पिंडलल सर्विस कमोशन से चुनाव करवायाथा? यदि हां, तो उसका नतीजा क्या हुआ?

माननीय कृषि सचिव--(१) जी हां।

(२) सीनियर पोल्ट्री इंस्पेक्टरों की ५० फीसदी जगहे इन जगहों पर पहले से काम करने वालों को मिली ओर ५० फीसदी जगहे बाहर वालों को, जबिक जूनियर पोल्ट्री इन्सपेक्टरों की सभी जगहे मुहकमें मैं पहले से काम करने वालों को मिली।

*४०—-श्राहरग बिन्द् पन्त—उक्त चुनाव के फलस्वरूप किस-किस ग्रेड के कौन-कौन कर्मचारी अपने पदों से हटाये गये हैं या हटाये जा रहे हैं? जो नौकरी में कायम रहेंगे उनका वेतन कितना होगा?

माननीय कृषि सन्तिव (१) सीनियर पोल्ट्री इन्सपेक्टरों में से एक इन्सपेक्टर की जिसे पिंडलक स्विस कमीकान ने नहीं चुना, सहकारी विभाग (कोआपरेटिव डिपार्टमेट) में उसकी असली नौकरी पर वापस भेज दिया गया है। ऐसे बाकी तीन ओहदेदारी (कर्मचारियों) का जूनियर पोल्ट्री इन्सपेक्टरों के नीचे दर्जे की जगहों पर १२०-६-२१० १०-२५० ६० के स्केल में नौकरी में बनाये रखने के सवाल पर अभी विचार हो रहा है।

(२) अपर के भाग (१) में दिये गये उत्तर को देखते हुय यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्रो हरग बिन्द पन्त-सरकारी नौकरी में आने से पहले इन लोगों का वेतन कितना

था ? घट गया है या बढ़ गया है ?

मानना कृषि सनिव--बढ़ गया है।

श्री जगमीहन िह नेगा--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ये आफिन्सं कहां-कहां पर काम करते ह ?

माननीय कृषि सचिव--में इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता।

*४१-- आ हरगोबिन्ट पन्त--पूराने सरकारी कर्मचारियों की उपरोक्त नये प्रबन्ध से जो क्षति पहुँची है, उसकी पूर्ति के बारे में क्या सरकार का कोई विचार है ? यदि है, तो क्या ?

म। ननीय कृषि सि चिव — जी नहीं। जिनकी छटनी की गयी है वे सभी अस्थायी (आरजी) जगहीं पर काम कर रहे थे और उन्हें मुआविजा देने का प्रश्न उठता ही नहीं न इस प्रश्न पर नब विचार किया गया था जब ९ सीनियर और ३६ जूनियर पोल्ट्री इन्सपक्टरों में से ऊपर बताये गयें सिर्फ ६ सीनियर और १० जूनियर पोल्ट्री इंसपेक्टरी को अक्तूबर १९४७ ई० में नोकरी में रहने दिया गया था और बाकी लोगों को छटनी में हटा दिया गया।

÷४२--५३--श्री चतुभु ज शर्मा--(स्थगित किये गये।)

पंचायत गाज से सम्बन्धिन चुनावों के बाद गांवो में वलवें। की अधिकता

*५४--श्रोमर्ता निक्मी दंवी--(क) क्या यह सच है कि पंवायत राज से सम्बन्धित चुनावों के बाद ग्रामों में अधिक बलवे होने लगे हैं?

- (ख) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कितने पंची ओर मरपंची पर दफा १०७ लगायी गयी हैं ?
 - (ग) क्या यह पंच तथा सरपंच केवल काश्तकार ही है या जर्मादार भी ?

माननीय पुलिस सिचिव--(क) ऐसा नहीं हैं।, परन्तु नुनाव के कारण कही कही गांव के आपसी मनमुदाव शुरू में बढ़ गये थे जो अब शान्त हो रहे हैं।

- (ख) ७९४ पंच और सरपंचों पर दफा १०७ लगाई गई है।
- (ग) यह पंच तथा सरवंच जिमींदार अथवा काश्तकार दोनों ही है।

र्था इन्हित्य [अपाठ] — क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि गांव राज कातून के लागृ होने पर जनता में एक नया जोश व खरोश पैवा हो गया ह ?

माननाय पुलिस सचिल--इसमे कोई शक नही।

नीलगायों में खेती को हानि

*५५--श्रामती लक्ष्मी देवे।--(क) २५ अक्तूबर सन् १९४८ ई० के प्रक्त ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खती को नीलगायों से बचाने का सरकार ने कोई प्रबन्ध विचार लिया हैं ? यदि हां, तो क्या और वह प्रबन्ध कब तक हो जायगा ?

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि नीलगाप नामक जानवर इस समय भी खेतो मे बहुत नुकसान पहुँचा रहा ह ?

माननीय कृषि मन्विच—(क) खेती को नीलगायों से बचाने के लिये जंगल विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति नं० ३४०६/१४—५८५-१९४७ तारीख २६ अक्तूबर, १९४९ जारी हुआ है जिसमें नीलगाय को न मारने के बारे में पूर्व निकाली गई विज्ञप्ति नं० २१५६/१४, तारीख ४ अक्तूबर १९४७ ई० को रह कर दिया गया ह।

(ख) जी हों। परन्तु अब आशा है कि नीलगाय के मारने पर प्रतिबन्ध हटाने के पश्चात् यह तक्तलीफ कम होती जायगी।

खेती की उन्नति के लिये काश्तकारों का मुवियाणं

ेप६--श्रोमती लक्ष्मा देता--(क) क्या सरकार कृषा कर बतलारेगी कि खनी की उन्नति के लिये किननी ऐसी दरख्वास्ते आयी ह जिन पर तकावी मागी गयी है और अभी तक कितनी तकावी दी गयी है?

(ख) खेती के लिए क्या क्या सुविधा सरकार काश्तकारो को देने का इरादा रखती हैं ?

माननाय कुषि सचिव—(क) इच्छित सूचना निम्नलिखित है-—

१९४८-४९ १९४९-५० (लगभग अ≢त-बर म^न ५० तक्

(१) 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के सम्बन्ध में तकादी के लिये जो कुल दरख्वास्ते आई, उनकी सख्या .. ६३०

९५६

(२) कुररोकड तकावी जो प्रदान की गयी..

३,४२,२०३

२,१३,११२ ६०

(ख) खती की उन्नति के लिये वर्तभान सुविधाओं के अतिरिक्त सरकार अर कोई अन्य सुविधा इस समय देने का विचार नहीं रखती।

र्थ्यामता लक्ष्मा द्वा--क्या सरकार को यह भाल्म है तकावी देते समय (० परमेट

उसमें से अहलकार काट देते हैं ?

माननीय कुषि सिच्य-गवर्नमेट को इमका इल्म नहीं है। अब तो तकावी के मताल्लिक जो नधी योजना जारी की गयी है वह यही है कि जिला मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेबल्यमा एसोस्थितन के चेयरमेन, डिस्ट्रिक्ट बोड के चेयरमैन, और डिस्टिक्ट काग्रेस कमेटी के चेयरमैन ये इन तमाम तकावी को अपने इन्तजाम में बाटेगे।

श्री खुशवकत राय-क्या सरकार को यह माल्म है कि तकावे की जो दररवारते

आती ह उन पर तकावी मिलने ने काफी देर होती हैं ?

माननीय क्रीप मिचिय-जी हा। मगर अब उम्मीद ह कि आइग्दा ऐसा नहीं होगा। श्रा कुन्ज बिहारी लाल शियानी-क्या सरकारको यह माल्म है कि जो किसान तकावी के लिये दरख्वास्ते देते हैं वे माल-साल दो-दो साल तक दफ्तरो में पडी रहती है और कम से कम १५, २० क्लर्को के हाथ से निकलती है ?

ग्राननाय क्रिप सचिव--इसके मुताल्लिक जवाब दिया जा चुका है। श्रा मुहम्मद ग्रह्मरा श्रहमद--क्या गवर्नमेट बतलायेगी कि जल्दी तकावी देने के लिये नया कायदा गवनमेंद्र ने क्या तजबीज किया है जिसका अभी जिक्र किया गया ह?

ताननीय कृषि मचिय--नयी तजयीज यह है हर जिले में एक प्लानिंग कमेटी बरेगी जिसमें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चेयरमैन डेवल्पमेट एसोसियेशन, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और जितने हर मुहक्तमें के आफिसर हैं वह जिले के मुताल्लिक प्लानिंग करेंग और वह प्लानिंग सूबे में आवेगी और यहा एक कमेटी मुकर्रर की गयी हैं जो सारे जिलो की प्लानिंग होगी उनको देख कर और उसकी पूरी तसवीर सामन रख कर हरजिले के लिये हपया और सामान का एलाटमेट करेगी और उसके बाद जिलों को मुत्तला कर दिया जायगा कि हर जिले के हिये इतना एलाटमेट किया गया उसके बाद एक कमेटी जिले में होगी। जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चेयरमैन होगा और चेयरमन डवल्पमेंट एसोसियेशन चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, चेयरमैन, कांग्रेस कमेटी उसके मदस्य

होंगे। यह कमेटी जो एलाटमट हुआ है उसको देखते हुये जो भी जिले की योजनायें हैं उनमें सामान और रुपया तक़सीम करेगी।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी—क्या सरकार को यह भालूम है कि जो लोग तकाबी लेते हैं उनको जमानत देना पड़ती है, जमानत देने वाले के लिये बहुत सस्त नियम हैं, जिसके अनुसार किसानों को तकाबी में सहू लियत नहीं मिल सकती है?

माननीय कृषि सचिव—इस मसले पर गवर्नमेंट ने काफी विचार किया है। यह मसल रेवेन्यू डिपाटमेंट का है और वहां पर जो तकावी देने के नियम थे उनमें अब तरमीम की गई है। उसमें यह ख्याल रखा गया है कि जिन लोगों को सरकार रुपया दे उसकी वसूलयाबी में किसी तरह की दिक्कत नहीं। उसकी वसूलयाबी की पूरी उम्मीद हो तो उसी के मुताबिक रुपया दिया जाय।

श्री महम्मद ग्रसरार ग्रहमद-क्या गवर्नमेंट यह बतलायेंगी कि जिले में दरख्वास्त देने के बाद डिस्टिक्ट प्लानिंग कमेटी के विचार करने में और सूबे की प्लानिंग कमेटी के विचार करने में कितना समय लगाना गवर्नमेंट ने तथ किया है ?

माननीय माल सिचव (श्री हुकुमं सिंह)—इसका अन्दाजा नहीं लगाया गया है। गांवों में खेतों की चकवन्दी

*५७--श्रीमती लक्ष्मी देवी--क्या निकट भविष्य में खेती की उन्नौत के लिए सरकार गांवों में चकबन्दी कराने का विचार रखती है?

माननीय माल सचिव—इस प्रान्त में जमींदारी प्रथा के अन्त होन के पश्चात् सरकार चकब-दी के प्रश्न पर फिर विचार करेगी।

*५८--श्री कून्ज विहारी लाल शिवानी--[वापस लिया गया।]

जिला फैजाबाद के घरेलू उद्योग-धंघों के विषय में पूछ-ताछ

*५९--श्री गणेशकृष्ण जैतली--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद कोआपरेटिव सोसाइटी सहकारिता समिति का कितना रुपया उद्योग में लगा है?

(ख) उसमें से कितना रुपया महाजनों का है और कितना श्रेयर का है?

माननीय उद्योग निचय (श्रा केश्यदेव मालवीय) — (क) फेंजाबाद की सिमितियों के व्यवसाय में लगभग ८,७,७७० रुपया लगा हुआ है।

(ख) इसमें से लगभग ८६,३४६ रुपये शेयर का है और शेष अमानत जमानत तथा क़र्जे का है अमानतें मेम्बरों तथा गैर मेम्बरों की हैं। जिनमें सभी वर्ग के लोग हैं। महाजनों का रुपया नहीं है।

श्री गरादाकुष्ण जैतली—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ८६,३४६ र० कितने लोगों के शेयर में से मिला है ?

माननीय उद्योग सचिव-इस वक्त इसकी तो कोई संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन काफी सबस्यों का होगा, क्योंकि १० र० हर सबस्य को देना होता है, उसमें से वह , २, ३ रुपया तो अवस्य ही दे चुके होंगे।

श्री गणिशक्रुष्ण जैतली—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि इसके अलावा जो रुपया लगा हुआ है उस पर किलना व्याज या मुनाफा होता है ?

माननीय उद्योग सचिव — कर्जे पर व्याज बाजार की दर के अनुसार ही होता है और उसी के मृताबिक यहां भी है।

*६०--श्री गणेशकृष्ण जैतली--क्या केवल इन क्षेयरीं द्वारा प्राप्त रुपया उद्योग-धंधों के चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है ?

माननीय उद्योग सिचिव—केवल शेयर से इतना व्यवसाय नहीं चल सकता है। शेयर हर साल बढ़ाया जा रहा है। एकाएक इतने काम के लिए शेयर इकट्ठा होना असम्भव है।

*६१--श्री गणेशकृष्ण जैतली--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में घरेलू उद्योग-घंधों पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है और कौन-कौन से घंधे खोले गये हैं।

माननीय उद्योग सचिव——जिला फैजाबाद में निम्नलिखित घरेलू उद्योग—धंधे भिन्न— भिन्न प्रकार के लोगों की रुचि के अनुसार खोले गये हैं——

व्यवसाय और उद्योग-घंधों कब खोला गया स्थान का नाम व्यय का नाम औद्योगिक शिक्षालय योजना बनाई लोरपुर अगस्त सन् १९४६ ३८,५४२ ६० मार्च सन् १९४७ ई० से अगस्त सन् १९४९ तक ध्यय हुआ। पकरेला जुन सन् १९४६ २ बनाई मार्च सन् १९४७ टांडा रंगाई छपाई

खद्दर योजना

अकबरपुर

अक्तूबर सन् १९४७

सिलाई

\$ \$	स्थानाय व काशि		विय हुये ढंग से व्यय हुआ।		
3	32	" रनीवा आश्रम गुसाईंगंज		,, १––७,३७५ ६० जिला विकास संघ रनीवा आश्रम को दिया	
				गया ।	

व्य वस।	य और उद्योग–धंधों काम नाम	स्थान का नाम	कब खोला गया	च्यय
R	स्वावलम्बी योजना	चना बाजार के नजदीक	नवम्बर सन् १९४८	२—-२५,००० रु० का अनुदान जिला विकास संघ को दिया गया।
ጸ	महिलाओ का चर्खा संबंधी शिक्षालय	रनीवा आश्रम गुसाईगंज		३२०,०७८ रु० का अनुदान रनीवा आश्रम को दिया गया।
	उन्नत प्रकार से गुड़	बनाने तथा उन्न निकालने र्क		ग धानी से तेल
१	गुड़ व्यवसाय की उन्नति तथा वारधा धानी के प्रचार के लिय	फैजाबाद जिले मे	अप्रेल सन् १९४८	२१,८७३ ६० नीचे दिये हुये ढंग से व्यय हुआ।
				१—-२,५९५ ६० सन् १९४८
				२—–१३,५०० रु० उन्नत प्रकार के कोल्हू के लिये बांटा गया।
				३——५,६०० रु० उन्नत प्रकार की बारघा घानी के लिये बांटा गया।
				४—–१७८ ६० स्थानीय कर्मचारियों को बोनस दिया गया।

^{*}६२--श्रा गर्णेट्राष्ट्राच्या जैतर्छा--(क) क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन उद्योग-धंत्रों में कितने आदिमयों ने और किस-किस विभाग से शिक्षा प्राप्त की ?

⁽ख) इन संस्थाओं का पैवावार से कितना लाभ है?

माननीय उद्य ग सचिव-(क) शिक्षार्थियों की संख्या जिन्होंने फैजाबाद जिले में भिन्न-भिन्न व्यवसायों में शिक्षा पाई है निम्नलिखित हैं-

ऋम- संख्या	व्यवसाय और उद्योग–धंधों का नाम	योजना	ऐसे शिक्षार्थियों की संख्या जो शिक्षा प्राप्त कर चुके
	औद्योगिक	शिक्षालय योजना	
	बुनाई	लोरपुर	३३
2	बुनाई	पकरैला	3°
Ą	रंगाई व छपाई	टांडा	२१
8	सिलाई	अकबरपुर	
	सहर र	योजना	
?	स्थानीय कर्मचारियों का शिविर	बड़ा गांव	२०२
2	33 23 23	रनीवा आश्रम	४५१
3	स्वावलम्बी योजना	चना बाजार	३९७
8	महिलाओं का चर्ला सम्बन्धी शिक्षालय	रनीवा आश्रम	२०
	गुड़ तथा वारधा घानी	योजना	
१	गुड़ व्यवसाय उन्नति विभाग कि किले उन्नत प्रकार की वारघा घानी से तेल पेर	फैजाबाद ना "	Ę

(ख) ये योजनायें जनता में उद्योग की केवल शिक्षा व प्रचार करने के लिये चलाई गई हैं न कि तिजारत के लिये इसलिये लाभ हानि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश कृष्ण जैतलो—क्या सरकार यह बतलायेगी कि २ वर्ष में जो शिक्षा पाए हुए लोग हैं और जिनकी संख्या अभी आप ने ३३, ३०, २१ और ५ इस प्रकार दी है, यह क्या इतने खर्च के बाद पर्याप्त हैं?

माननीय उद्योग सचिव—सरकार को जितना भी अवसर मिलंगा वह ऐसे शिक्षा— थियों की संख्या बढ़ाने का उद्योग करेगी और इस संख्या से सन्तोष तो न हमें हो सकता है और न आपको होना चाहिये और हमारा और माननीय सदस्य का इस संख्या को बढ़ाने का उद्योग होना चाहिए। अभी तो यह बात ठीक ही है कि खर्च ज्यादा हुआ और शिक्षार्थी कम रहे।

श्री गरेक्श कुड्या जैतली—क्या सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि यह जो धन शिक्षा के

लिए दिया गया है उसको हर साल बढ़ाया जाता है?

माननीय उद्योग सचिव--जहरत होती है तो बढ़ाया जाता है।
किसानों से सीर के खेतों का छीना जाना

*६३—श्री गर्धेशक्रुटम जैतली—क्या सरकार को पता है कि जमींदारी उन्मूलन बिल उपस्थित होने के कारण, जमींदारों ने किसानों से सीर के खेत छीनना आरम्भ कर दिया है ?

माननोय माल सचिव--जी नहीं।

ऐलापेथी, होमियापेथी, ग्रायुर्वेदिक संस्थाश्रों की सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां

*६४--श्री गरेपशक्तरण जैतली--क्या सरकार एलोपंथी, होमियोपंथी और आयुर्वेदिक शिक्षा की उन संस्थाओं का नाम बतायेगी जिनके द्वारा दी हुई उपाधियां वह स्त्रीकार करती हैं ?

मानर्नाय ग्रन्त सचिव-

(१) डाक्टरों के लिये—मनुष्य व स्त्री दोनों,
आगरा यूनीर्वासटी की एम० बी० बी० एस० डिग्री।
शिक्षाकेन्द्र—सरोजनी नायडू मेडिकल कालिज आगरा।
लिखनऊ यूनीर्वासटी की एम० बी० बी० एस० डिग्री।
शिक्षाकेन्द्र—महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज,
लखनऊ।

केवल महिलाओं के लिये—लेडी हार्रांडग मेडिकल कालिज देहली की एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ डिग्री, उसके अलावा इंडियन मेडिकल कॉसिल के द्वारा स्वीकृत वह देशी या विदेशी उपाधियां जो लखनऊ या आगरा के एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ के बराबर या उससे ऊंची हैं उनको भी सरकार स्वीकार करती है।

(२) नसीं के लिये — सरकारी नरसेज ट्रेनिंग सेन्टरका प्रमाण-पत्र या अन्य प्रान्तों के या विदेशी कुछ बराबर वाली या उनसे ऊंची उपाधियां जो उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिड वाइब्ज काँसिल द्वारा स्वीकृत हों। ३—कम्पाउन्डरों के लिये—सरकारी कम्पाउन्डर्स ट्रेनिंग

सेन्टर का प्रमाण-पत्र।

अभी यह चिकित्सा प्रणाली सरकार द्वारा मान्य नहीं है। इसकी किसी शिक्षालय की उपाधियां स्वीकार करने का प्रका अभी नहीं उठता।

सरकारी नौकरियों के लिये स्वीकृत उपाधियां।

आयुर्वेदिक--(१) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की आयुर्वेद की या आयुर्वेद शास्त्राचार्य की उपाधियां।

(२) बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन उत्तर प्रदेश की डी० आई० एम० डी० आई० एम० एस० (जो अब बी० आई० एम० एस० की उपाधि में परिवर्तित कर दी गई है) की उपाधियां।

(ख़) होमियोपैथिक

(ग) आयुर्वेदिक

- (३) मुस्लिम युनीर्वासटी अलीगढ की बी. बी. टी. एस.की उपाधि।
- (४) आयवैंदिक तथा यूनानी तिब्बिया कालेज देहली की अन्तिम उपाधिया (आयुर्वेदाचार्य या भिषगाचार्य तथा कामिल--उल-तिब-बा-जराहन या काबिल उत-तिब-बा-जराहत)।
- (५) आयुर्वेदिक कालिज कांगडी जिला सहारनपुर की आयुर्वेदालंकार की उपाधि।
- (६) छी० ए० वी० कालेज लाहौर की "वैद्य वाचस्पति" की उपाधि।
- (७) सनातन धर्म प्रेमगिरी आयुर्वेदिक कालिज लाहौर की आयुर्वेदाचार्य की उपाधि ।
- (८) गुन्कुल विश्वविद्यालय ब्न्दाबन की आयुर्वेद शिरोमणि की उपाधि। स्थानीय बोडों की नौकरियों के लिये स्वीकृत उपाधियां १ से ८ तक जसा ऊपर लिखा है।
- (९) अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ की ''आयुर्वे दाचार्य'' की उपाधि ।
- (१०) डी० ए० वी० कालेज लाहोर की "वैद्य कविराज" की उपाधि।
- (११) तिब्बिया कालेज लाहोर की हकीम हाफिज की उपाधि।
- (१२) भ्पेन्द्र तिब्बिया कालेज पटियाला की (हाफिजुल हुक्म) तथा माहिर-तिब-बा-जराहत) की उपाधिया।

श्री गरोदा कुःशा जैतली—क्या सरकार उन प्रैक्टिशनर्स की संख्या कम करने का कोई रास्ता निकाल रही है कि जो बिना स्वीकृति लिए हुए प्रैकटिस कर रहे है ?

माननीय अन्न सचिव—हां, बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन ने जगह जगह पर कमेटियां नियुक्त की है और उनकी सिफारिश पर बिना स्वीकृति और उपाधियां प्राप्त लोगो को निकालने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

नहर विभाग के चीफ इंजीनियर की त्राज्ञा के विरुद्ध पद्च्युत व्यक्तियों द्वारा अपील

*६५--श्री विजयानन्द्रिमिश्र--(क) क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि चीफ़ इन्जीनियर, नहर विभाग ने ९ दिसम्बर १९४७ को सकिल आफ़िसों में हेड असिस्टेटो की नियक्ति के विषय में कोई आज्ञा निकाली थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त आज्ञा द्वारा कई सीनियर कर्मचारियों को पदच्युत किया

नया है ?

(ग) क्या इन पदच्युत व्यक्तियों ने चीफ इन्जीनियर की आज्ञा के विरद्ध सरकार से अपील की थी ? यदि हां, तो सरकार ने कितने व्यक्तियों की अपील मंजूर की और कब ?

श्री लताफन हुसैन—(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जो हां, सिवाय श्री जै भगवान शर्मा के सरकार ने सब लोगों की अपील मंजूर कर ली श्री और इसके बारे में सरकारी हुक्म ७ जनवरी, १९४९ को चीफ़ इन्जीनियर नहर विभाग को मेज दिया गया था।

राजनीतिक ग्रान्दोलन में किये गये जुर्मानें। का वापसी

*६६—श्री कुन्ज बिहारी छाल शिवानी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सन् १९३०—३२ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के संबंध में किये गये जुर्मानों के वापस करने के संबंध में उसकी क्या नीति है ?

श्री चरण सिंह-सन् १९३०-३२ ई० के आन्दोलन में किये गये जुर्मानों को वासप करने में सरकार को कोई आपित नहीं है, यदि ऐसे व्यक्ति जिन पर जुर्माना किया गया था, इस बात

का प्रमाण दे सकें कि उनसे जुर्माना वास्तव में वसूल किया गया था।

श्रा कुन्ज बिहारी छाउ शिवानी—किस प्रकार के प्रमाण से सरकार को सन्तोब होगा?

श्री चरण सिह--अगर वाक़ई यह साबित हो जायगा कि जुर्माना वसूल किया गया है।

श्रा कुन्ज विहारी लाल शिवानी—क्या सरकार की मालूम है कि उस वक्त के काग्रजात सरकारी लजानों में नहीं है ओर रसीदें भी लोगों के पास नहीं रही हे, इस। हालत में सरकार किस तरह के प्रमाण से सन्तुष्ट होगी ?

श्री चर्ग भिंह--अगर रसीद होगी तो उसका विश्वास किया जायगा और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट समझेगे कि वह विश्वसनीय है तो उसकी बिना पर वह जुर्माना वापिस किया जा सकेगा।

श्री कुन्ज विहारो लाल शिवाना—ओर यदि रसीद नहीं हे क्योंकि इतने दिनों के बार रसीद होना संभव नहीं है तो उस हालत में क्या होगा ?

श्री चरण सिह--में समझता हूं कि यह बात माननीय सदस्य भी स्वीकार करेगे कि जबानी कह देने पर ही कि जुर्माना हुआ था उसका बापिस कर देना मुनासिब नहीं है और इस तरह की जबानी बात पर अमल करना मुनासिब न होगा।

र्श्रा कार्ला चरण टन्डन—क्या सरकार को पता है कि जुर्माना वसूल करने का रेकार्ड अदालत में भी रहता है और पुलिस के पास भी जुर्मानों का रेकार्ड रहता है ?

श्रो चरण सिह—जी हां।

श्री काली चरण टन्डन--तो क्या पुलिस के रेकार्ड का सबूत इन जुर्मानों को वापिस कर के लिये सरकार मान लेगी?

श्रो चरा सिह--मान लेगी अगर वे क़ायम हों, लेकिन वे आम तोर पर तलफ़ हो चुके हैं।

*६७--श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी--(क) क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने झांसी जिले में सन् १९४०-४२ ई० के आन्दोलन के संबंध में किये गये किन-किन लोगों का जुर्माना अब तक वापस नहीं किया है ?

(ख) इसका क्या कारण है?

थ्या चरण सिंह—(क) सर्व श्री (१) भैरों प्रसाद (२) अहमद लां (३) प्रागीलाल गुप्ता के जुर्माने अभी तक बापस नहीं किये गये हैं।

(ख) उक्त सत्याग्रहियों के प्रार्थना-पत्र मियाद के बाद आये थे ओर अब सरकार की विशेष आज्ञा से उनका भी जुर्माना वापस करने के संबंध में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी—क्या सरकार को मालूम है कि श्री भैरों प्रसा**व है** जुर्माना वसूल करते समय उनकी बहुत सी जायबाद पुलिस द्वारा लेकर बहुत कम क़ीमत प्रव नीलाम की गई थीं?

श्री चरण सिंह—हां, ऐसा श्री भैरों प्रसाद जी कहते है। अगर उनका यह नुः साद

साबित हो जाय तो सरकार उसकी पूर्ति करने पर भी विचार करेगी।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी—क्या सरकार को मालूम है कि भैरी प्रसाद जी ने अपनी क्षतिपूर्ति के लिये ३,८०० ६० का क्लेम किया है और उसकी दरख्दास्त सरकार के पास भेज वी गई है ?

श्री चरण मिह—उनके जुर्माने के वापिस किये जाने का हुक्म तो १२ नवम्बर को हो चुका है और वह उनके जिले में पहुंच भी गया होगा। जहां तक नुक़सान के पूरा करने का सवाल है, वह मसला अभी विचाराधीन है। उन्होंने दरख्वास्त कब दी थी यह तो मैं सही नहीं बता सकता लेकिन जब माननीय सदस्य कहते हैं कि दी थी तो मैं कह सकता हूं कि जल्दी ही फसला हो जायगा।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी—क्या सरकार को मालूम है कि उन्होंने जो दरख्वास्ते दी है उनमें से एक की कई एक प्रतिलिपियां माननीय पुलिस सचिव को वहां के एम० एल० ए० के द्वारा, प्रश्नकर्त्ता के द्वारा दी गई हैं और उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ ?

माननीय पुलिस सिचय—मुझे अफ़सोस है कि मैने बाक़ी सवालात नहीं सुने ? लेकिन जहां तक जुर्माने के वापिस करने का सवाल है, देर तो जहर लगती है क्योंकि पुराने रेकार्ड को खोजना पड़ता है और ऐसा भी है कि २०, २५ के रेकार्ड आसानी से नहीं मिलते । मिलने पर जुर्माना वापिस कर दिया जाता है क्योंकि एक केस ऐसा मैने देखा और उसमे जुर्माना वापिस कर दिया गया , तो यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि इसमें भी पता चलेगा तो वापिस जरूर कर दिया जायगा ।

*६८--र्श्री कुन्ज विहारी लाल शिवानी-क्या सरकार उन व्यक्तियों को, जिन पर सन् १९३०-३२ ई० के आन्दोलन में जुर्माने हुए थ, कुछ सहायता देने का विचार कर रही ह ?

श्री चरण सिह—सरकार उन ध्यक्तियों को, जिन पर सन् १९३०—३२ ई० के आन्दोलन में केवल जुर्माने ही हुये है किसी प्रकार की विशेष रूप से सहायता देने पर विचार नहीं कर रही है।

श्री कुन्ज बिहारी लाल शिवानी—वया सरकार उन व्यक्तियों को सहायता देने का विचार कर रही है जिन पर जुर्माने हुए हैं या सजाएं हुई है ?

श्री चरण सिद--जहां तक जुर्माने का संबंध है वह वापिस कर दिया जायगा और कोई विशेष सहायता देने का विचार नहीं है।

यम्ना किनारे की घाटों चादि वाली जमीन के संबंध में जागरे की जनता की शिकायत

*६९--श्री रामचन्द्र सेहरा--क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि आगरा नगर में यमुना किनारे की जमीन जिस पर घाट, शिवालय, मंदिर, बगीचा इत्यादि बने हुए हैं, किस सरकारी विभाग के नियन्त्रण में है ?

माननीय स्वशासन सचिव—आगरा जिले के उत्तरी पूर्वी कोने के सामने स्थित केलों की बगीचों से उत्तर की ओर छावनी सीमा के १८ नम्बर स्तम्भ तक जितने घाट स्थित है वे गैरिजन इन्जीनियर कोर्ट वान के नियंत्रण में है। इससे आगे अवशेष यमुना तट की भूमि जिस पर घाट आदि बने हुए है नजूल विभाग के नियंत्रण में है।

*७०—श्री रामचन्द्र निहरा—क्या यह सच है कि यह स्थान जनता के हितार्थ सार्व जितक प्रयोग के लिये दिये गये थे तथा इन स्थानों पर स्नान घाट, विश्वान्त घाट. गऊ घाट इत्यादि बने हुए थे ?

मं। ननीय क्वशासन सिच्च — नजूल विभाग संबंधी यमुना तट पर स्थित ९ घाट किराये पर पटटे पर उठे हुए हैं जिनमें से अधिकतर जनता के हितार्थ सार्वजनिक उपयोग के लिये दिये गये हैं। इनके अलावा अवशेष स्थान भिन्न-भिन्न पुरुषों के नाम बिला किराया जनता के हितार्थ नजूल विभाग के कागजात में दर्ज हैं। इन स्थानों पर घाट बने हुये हैं।

श्री रामचन्द्र सेह्रा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन ९ आदिमयों के नाम क्या २ है ?

माननीय स्वशासन मचिव--मेरे पास उनकी फेहरिस्त नहीं है। इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र सेहरा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन ९ घाटो को पट्टे पर दे रखा है उनको जनता की कमेटी के अख्तियार में देने का विचार रखती है ?

माननीय स्वाज्ञासन सिचिय-पिंद माननीय सदस्य सरकार को लिखेगे तो इस विषय पर विचार कर लिया जायगा।

*७१--श्री रामचन्द्र सहरा--क्या यह भी सच है कि इन स्थानों पर घाट इत्यादि नष्ट करके रहने के स्थान, होटल, ट्रास्पोर्ट कम्पनियां, आढ़त की दुकाने, इत्यादि बनवा दी गयी है ?

माननीय स्वशासन सचिव--यह सच है कि कुछ स्थानो पर घाट वालों ने इमारतें बनवा ली है जो कि प्रश्न में कहे गये कामो में इस्तेमाल हो रही है।

अ७२—श्री गामचम्द्र सहरा—वया स्थानीय जनता की ओर से इस विषय में सरकार के पास कोई शिकायत आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी शिकायतो को दूर करने तथा मांगों को पूरा करने का विचार रखती है ?

माननीय स्वशासन सचिव--जी हां, इस विषय पर कलेक्टर से जाच करने तथा रिपोर्ट भेजने के लिये कहा गया है। पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं है।

श्री श्रचल सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन शिकायतो को दूर करने के लिए क्या किया गया है ?

माननीय स्वश सन सचिय—इन शिकायतों के बारेम बराबर जिलाधीश को लिखा गया है। वह तहक्रीक्रात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगे।

*७३--८६--श्री बलभद्र सिंह--[तब से माननीय सदस्य की मृत्यु हो गई।]

महोली, जिला सीतापूर के ग्रादश थाने में चोरो, डफेती तथा कत्ल के मामलें। की संख्या

*८७—श्री कृष्णचन्द्र गुप्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि महोली, जिला सीतापुर में जब से आदर्श याना कायम हुआ है, तब से अब तक उस थाने में कितने चोरी, उकैती तथा कृतल के मामलों का इन्दराज हुआ है ?

माननीय पुलिस सचिव--सूचना इस प्रकार है।---

चोरी	ende	••	1 *	४१
डकैती	***	* *	4 4	
क़रल	(Close)		•	P

श्री खुशवक्त राय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो आदर्श थाना स्थापित किया गया है उसमें कौन २ से आदर्श रखें गये हैं ?

माननीय पुलिस सन्त्रिय-प्रश्न ८७ से इसका मतलब नहीं निकलता है लेकिन सभी बातों में कोशिश की जाती है कि जो भी पुलिस के काम हों वह उनको अच्छो तरह से करें।

*८८ श्री क्रुडणचन्द्र गुप्त-क्या नरकार क्रुपया बतलायेगी कि इनमें से कितने मुक़हमे चल रहे हैं और कितनों में सजा हो चुकी ह ?

माननीय पुलिस सचिव--इस समय चोरी के ४ मुक्त हमे चल रहे है और चोरी के ११, डकेती के ३ और कत्ल के १ मामले की अभी जांच हो रही है। शेष मामलों के जांच में सफ लता नहीं मिली।

ग्राटर्श थानें। में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये योग्यता

*८९--श्री कृष्णचन्द्र गुप्त--आदर्श थानों तथा चौकियों में सब-इन्स्पेक्टर तथा हेड कांस्टेबिल की नियुक्ति के लिए क्या न्यूनतम योग्यता आवश्यक है ?

माननीय पृत्तिस सचिव—आदर्श थानों में नियुक्ति के लिये शिक्षा संबंधी आदि योग्यता वही है जो और थानों के लिये हैं, परन्तु इनके लिये विशेष मेहनती और ईमानदार कर्मचारी चुने जाते हैं।

जिला सीतापुर में गांव सभा के मंत्रियों का चुनाव

*९०—श्री कृष्णचन्द्र गुद्त—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला सीतापुर में गांव सभा (ग्राम पंचायत) के मंत्रियों का जो चुनाव किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है ? क्या सरकार ने इसके लिए कोई कमेटो नियुक्त की थी ?

माननीय स्वशासन सचिव--चुनाव कमेटी के द्वारा जो सरकारी आदेश द्वारा नियुक्त की गई थी।

*९१—भ्रो कृष्णचन्द्र गुप्त—यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी के सामने कुल कितनी दरख्वास्तें पेश हुई थीं और उनमें से कितने व्यक्तियों का चुनाव किया गया ?

माननीय स्वशासन सचिव--लगभग ५०० पेश हुई थीं, २६० चुने गये।

श्री कृष्णचन्द्र गुष्त--सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें लगभग ५०० के बताया गया है। क्या सरकार सही संख्या बताने की कृषा करेगी?

माननीय स्वशासन सचिव--सही संख्या सरकार के पास होती तो बतला दी जाती। ५०० के लगभग ही उत्तर आया है। शायद एक दो कम या ज्यादा हो।

*९२--श्रो कृष्णचन्द्र गुण्त--इनमें कितनी दरस्वास्तें राजनैतिक पीड़ितों की थीं ? उनमें से कितनों का चुनाव किया गया ?

माननीय स्वशासन सचिव-४० में से २०

*९३— श्रो क्रुडग्गचन्द्र गुप्त—क्या सरकार यह बतलान की कृपा करेगी कि इन मंत्रियों के चुनाव में कितनी हरिजनों की दरख्वास्तें थीं ? उनमें से कितनों का चुनाव हुआ है ?

माननीय स्वशासन सचिव-१२ में से ५

सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रान्त में शहद की पैदावार

*९४--ध्री हरगोविन्द पन्त--सरकार ने संयुक्त प्रान्त में कहां-कहां ऐपीकल्चर (मौनपालन) केन्द्र खोले हैं और उनसे कितना शहद प्रतिवर्ष प्राप्त होता है ?

माननोय कृषि सचिव—सरकार ने ज्योलीकोट, लखनऊ, पीलीभीत, लखीमपुर तथा बरेली में मौन पालन केन्द्र खोले हैं। ज्योलीकोट में प्रतिवर्ष लगभग १०० से १२५ पाँड शहद प्राप्त होता है। लखनऊ और पीलीभीत के मौनपालन केन्द्रों से पिछले वर्ष क्रमशः ३४ और १४ पाँड शहद प्राप्त हुआ था। बरेली और लखीमपुर में मौनपालन केन्द्र कुछ ही दिन पहले कायम किये गये हैं।

*९५—श्रो हरगोविन्द प≇त—उक्त विभाग पर कुल कितना वार्षिक व्यय होता है और उससे सरकार को कितनी आय होती है ?

माननीय कृषि सचिव--सन् १९४८-४९ की आय तथा व्यय निम्नलिखित है --

	पहाड़ी देशों मे	मैदानो मे	
	रु०	₹०	
व्यय	३१,८६४	२२,०७८	
आय	१,८१८	ঙ	

'९६--श्र्रा हरगोविन्ट पन्त--प्रान्त के किन-किन जिलो में शहद की अधिक पेदावार होती है ओर कहा कहा उत्तम शहद (मधु) प्राप्त होता है ?

माननीय कृषि मचिव-प्रान्त के निम्नलिखित जिलों में शहद अधिक पेदा होता है:--

पहाड़ी इलाका—अलमोडा, नैनीताल। मैदानी इलाका—सहारनपुर, बिननोर, बहराइच, गोडा, बस्ती, देवरिया,

गोरखपुर, इग्सी, पीलीभीत।

उत्तम शहद अलमोड़ा नैनीताल, गश्वाल ओर देहरादून जिलो में गिलता है। जिला ऋक्मोड़ा में मधुमक्खा पातने के लिये सतायता

*९७--श्रा ग्रेगिविन्द पन्त-क्या सरकार को मालूम है कि जिला अत्मोड़ा मे मधु-मक्खी पालने वालो का एक सघ बन गया है, जो अखिल भारतीय सघ से संबंधित है ?

माननाय कृषि सचिव--जी हा, परन्तु जहां तक ज्ञात हुआ है इस संघ का काम अल्मोड़ा नगर ओर इसके आसपास तक ही सीमित है।

र् १८--र्श्रा हर्गाविन्द पन्त-क्या सरकार से उक्त संघ ने कोई सहायता मागी है ? यदि हां, तो उसे कितनी सहायता दी गयी ?

माननय कृषि मा चय-जो हा, सरकार कुछ कर्मचारियो की ननख्वाह के अलावा २,००० रुपये की सहायता देने का विचार कर रही है।

*९९—श्री हरम विन्द् पन्त—यदि नहीं दी गयी, तो क्या यह सब है कि उसके स्थान पर अल्मोड़ा के किसी व्यक्ति को मौन पालन के लिए आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

माननीय कृषि मन्त्रिय--प्रक्त ९८ के उतर के अनुसार यह प्रक्त ही नहीं उटता।

³ १००—श्री हुए गोबिन्द पन्त—क्या यह सच है कि अल्मोड़ा में एक ही व्यक्ति को मौनपालन के लिए तीन भिन्न अनुदान कमड़ा मौनपालन विभाग, कृषि विभाग तथा उद्योग विभाग से सहायतार्थ मिले हैं ? यदि हां, तो इन अनुदानों का योग कितना होता है ?

माननीय कृषि सचिव—जी हां, यह सच है। इन अनुदानों का योग २,७६० र० है।

*१०१—श्री हर्गाविनद पन्त—संघ के मुकाबिले व्यक्ति को अनुदान देना क्यों
उचित समझा गया ?

*१०२--जिस व्यक्ति को उपरोक्त तीन अनुदान दिये जा रहे है, उसकी विशेष योग्यता क्या है ?

माननीय कृषि सचिव--श्री रामकृष्ण धाम एक संस्था है व्यक्ति नही इसलिये ये प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री हरगोविन्द पन्त--रामकृष्ण धाम नाम की संस्था कब और किस उद्देश्य से स्थापित की गयी है इसके सस्दय कौन और कितने हे ?

माननीय कृषि सिचव--इसका मुझे इल्म नही है।

श्री हरगाविन्द पन्त--क्या सरकार को मालूम है कि रामकृष्ण धाम केवल एक कुटी है ओर इसका अल्पोड़ा रामकृष्ण मिशन से भी कोई विशेष संबंध नहीं है ?

माननीय कृषि सिविब--मुझे इसका इल्म नहीं है। मेरे सामने जब यह सवाल आया था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा और इसके डिप्टी डाइरेक्टर मृद्रू साहब से इसके मुताहिलक मज्ञविरा कर लिया था ओर यह मालूम हुआ था कि यह सही है कि वह ज्ञहद की मक्खी पालने का काम कर रहे है।

श्री हरगोविन्द पन्त-यह संस्था कब से मौन पालन करने लगी है ओर इसमे काम करने

वाले सज्जन कितने हे और उनकी क्या योग्यता है ?

मानीय क्रांष संचिव--जहा तक मुझे याद हैं ब्रह्मानद कोई स्वामी है, वह उसको चला रहे हैं।

*१०३--११६--भ्री हरगोविन्द पन्त--[स्थिगत किये गये।]

मन् १६४६ ई॰ का यूनाइटेड प्राविक्ज एकोमोडेशन रिक्वीजिशन (अमंडमेंट) आडिनेंस

माननीय अञ्च मिच्च--म सन् १९४९ ई० के यूनाइटेड प्राविमेज एकोमोडेशन रिक्शे-जिशन (अमडमट)आडिनेस (सन् १९४९ ई० की म०४)की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

सन् १६४६ ई० का यूनाइटेड प्राविज्ञ (टेम्प्रेगी) कन्द्राल ग्राफ रेन्ट ऐन्ड रेविक्शन श्राहिनेस

मानीनय श्रञ्ज सचिव--मं सन् १९४९ ई० के यूनाटेड प्राविसेज (टेम्पोरेरी)कंट्रोल आफ रेट ऐंड एविक्शन (अमेडमट) आर्डिनेस (सन् १९४९ ई० की सं० ५) की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

मन १६४६ ई॰ का संयुक्त प्रान्तीय जमोटारी-विनाश चोर भूमि व्यवस्था *बिल--(जारी)

माननीय स्पोका--माननीय माल सचिव के प्रस्ताव पर कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय, विवाद चल रहा है।

कल श्री जमशेद अली खां साहब बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेगे।

श्री मुहम्मद्र जमशेद ग्रजा का —हुज्रवाला, कल में यह कह रहा था कि मेरे दोस्त रोशनजमा लां साहब ने जो कुछ भी इस जिल के सिलसिले में फरमाया वह मेरे ख्याल में इस से ज्याद नहीं था कि एक खासपोलिटिकल जमात को एलेक्शन में कामधाबी हासिल करनी इ उसके लिये वह जमीदारों की तबाही व बर्बादी सामने रखकर कामयाबी हासिल करना चाहते है। इस सिलसिले में उन्होंने आचार्य नरेन्द्रदेव जी के जवाबात जो उन्होंने एबालिशन कमटी के सिलसिले में दिये थे वह भी बयान किये और उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने जो अपनी राय उस क्त जाहिर की थी वह दूसरी पोलिटिकल जमाअत से चूंकि उनका ताल्लुक था लिहाजा उनकी वह राय उस सिलसिले में थी। लेकिन चंकि अब वे सोशिलस्ट पार्टी के सदर है और सोशिलस्ट जमाअत से उनका ताल्लुक है लिहाजा अब उन्होंने अपनी राय को बदल दिया। यह इस ऐवान का हर शख्स समझ सकता है कि जिसकी राय ऐसे मामले के ऊपर कि जो खास ताल्लुक रखता है एक ऐसे अहम बिल से महज पार्टी के उलटफर की बिना पर तबदील हो जाये

^{*}९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

उसकी जौन सी राय मानने के क़ाबिल हो सकती है, इसका फैसला मै ऐवान के उपर छोड़ता हूँ। दूसरी चीज जो मेरे दोस्त रोशन जमां साहब ने निहायत जोर के साथ कही थी वह यह थी कि जमीनों का रिडिस्ट्रोट्यूशन (पुर्नावतरण) किया जाय। लेकिन बाज चीजे कहने में बहुत आसान मालूम होती है। गोया उनके नजदीक़ यह तरीक़ा हो कि पहले तमाम जितने काश्तकार और जमींदार है उनको एक जगह इकट्ठा करके खड़ा कर दिया जाय और फिर जमीन को जिस तरह से कपड़ा फाड़ कर तक़सीम किया जाता है इमी तरह से जमीन तक़सीम करके उनको दी जाय। यह चीज कहने के लिये आसान है लेकिन इसके क्या असरात होंगे ? जमीन से जमींदारों और काश्तकारों का कितना गहरा ताल्लुक है और किस—किस चीज से और किस-किस सोबये जिन्दगी से उसका ताल्लुक है इस पर उन्होंने गौर नहीं फरमाया, बहरहाल यह एलेक्शन की कशमकश है और एलेक्शन को जीतने के लिये जो कुछ कहना चाहे वे कह सकते हैं, इसका उनको हक़ हासिल है। लेकिन यह चीज जाहिर है कि वह इसके हक़ में है कि जमीदारों को मुआविजा दिया जाय लेकिन चूं कि काग्रेस ने एक खास तादाद मुआविजे की रखी थी इसलिये उसको दूसरा जामा पहनाने के लिये आपने कम तादाद उस मुआविजे की मक़र्रर कर दी।

अब मै दो-चार बाते अर्ज करूंगा। इससे पेश्तर कि आप इस क़दीम निजाम को हमेशा के लिये खत्म करे आपको यह सोचना जरूरी है कि आखिर इसके बाद वह कौन सा निजाम होगा, वह कौन सा सिस्टम आप क़ायम करने जा रहे हैं जिससे कि कौम और मुल्क की फलाह और बहबूदी हो सके ? क्या यह आपने गौर किया कि आप जमीदारी को खत्म करने के बाद इस सूबे की किस २ चीज को खत्म कर देगे ? आपके जमींदारी को खत्म करने के साथ ही इस सूबे के तमाम जितने कोम और मुल्क की फलाह व बहबूदी के काम में रुपया सर्फ किया जा रहा है वह सब बन्द हो जायेगा ? इस जमींदारी के ख़त्म होने के बाद आप यहा के जो मदरसे है और मकतब है और पाठशालायें है उनको ख़त्म कर रहे है, उसी के साथ आप इनकी इमदाद को ख़त्म कर रहे है, आप यहां के कल्चर और तहजीब को तबाह करने जा रहे हैं। इन तमाम चीजो पर गौर करने के बाद आपको यह देखना चाहिये कि कौन सा बेहतर निजाम आप ला रहे है। में तो यह देख रहा हूं कि आप जमींदारी को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही आप काश्तकारों की फलाह व बहुबूदी के लिये कोई चीज नहीं कर सके। यह इससे जाहिर है कि जमींदारी एबालीशन फण्ड आपने जारी किया । अगर काश्तकार, टिलर आफ दि स्वायल (जमीन जोतने वाला) यह समझता कि यह चीज उसके लिये कोई फायदेमन्द है या कि उसके लिये ऐसी है जिसकी उसको तमन्ना और आरज् है, तो आपको जेड० ए० एफ० के लिये इसकदर मेहनत और मशक्कत और दौड़-भाग न करनी पड़ती। आपने जमीदारी एखालीशन फन्ड हासिल करने के लिये और जमा करने के लिये, दस-गुना रुपया जमा करने के लिये जो तदाबीर अख्तियार की है वह मेरे ख्याल में बहुत सी ऐसी है कि जो नामुनासिब और बेजा है, और कोई गवर्नमेंट ऐसी चीजों को पसन्द नहीं करेगो। आपने इस चीज को बिल्कुल पसेपुरत डाल दिया है कि जमीदारी एबालीशन फण्ड खत्म हो जाने के बाद कितनी मुझ इमेबाजियां इस सूबे के अन्दर शुरू हो जायेंगी इस वास्ते कि यह तो जाहिर है और मुझे यह मालूम है कि जिस वक्त जमींदारी एबालोशन फ॰ड का दस-गुना रुपया हासिल किया जा रहा है उस वक्त इस चीज का बिल्कुल ख्याल नही रखा जा रहा है कि आया कितने हिस्सेदार इस खाते के अन्दर है और आया वे कितना हक रखते हैं। कहा तो सिर्फ यह जाता है कि वह उसका दस-गुना दाखिल कर दे, बाद को और देखा जायगा। आपको यह मालूम होगा कि ज्यादा तादाव उन काश्तकारों की है जिनको खुद ही यक्तीन नहीं था कियह जमीन उनके हाथ में रहेगी या नहीं और इस तरीक़े से उन्होंने १०-गुना जमा करके अपने कब्जे में जमीन करने का अच्छा तरीक्ना निकाल लिया है। आप अपने इस जोश के अन्दर कि किसी न किसी तरीके से जिस स्कीम को आपने शुरू किया है कामयाब बनावें, सब के लिये एक अजीब व गरीब विक्कृत पेश कर रहे हैं।

जमींवारों के मुताल्लिक सब से बड़ा एतराज यह किया जाता रहा है कि ये लोग बेकार को जमीन से इतना रुपया पाते रहे हैं और उससे क्षीम और मुस्क को कोई नक्षा हासिल नहीं होता ।

तो इसका तरीक़ा यह नहीं था कि आप जमींदारों को खत्म कर दें। इसका तरीक़ा यह था कि आप जो जो जरूरी दूरस्ती इसमें करना चाहते वह करते। और भी बातों से ऐसी सूरतें हो सकती थीं जिससे आप बहुतर तरीक़े से हमारी आमदनी का इस्तेमाल करते और यह सब चीजें आसानी से कर सकते थे। मसलन, आप यह कर सकते थे कि आप जमींदारी को क़ायम रखते हये यह तय करते कि इसकी आमदनी का इतना हिस्सा जमीन की इम्प्रवर्मेट के लिये और दूसरे जो मुल्क की फलाह और बहबदी के काम हैं उनमें सर्फ किया जाय, लेकिन यह सब इन्हीं लोगों के हाथों से सर्फा हो। इससे उनको यह ख्याल रहता कि हमारा वजूद कायम है, मौजूद है और हमारे हाथ से ही गांव की भलाई और बेहतरी के लिये इतना रुपया सर्फ कराया जाती है. ऐसी बहुत स[ृ] चीजें आप कर सकते थे जिन पर आपने गौर नहीं किया । आप जमींदारी को खत्म करने के बाद कितने आदिमयों को बेरोजगार कर देंगे, इसके बाद कितने आदिमी ऐसे होंगे जिनको अपना पेट पालना दुश्वार हो जायगा। आपने अभी तक रिष्युजी प्राबलेम पूरे तीर पर साल्व (हल) नहीं किया और अब आप एक करोड़ के करीब आदिमियों को और रिफयजी बनाने जा रहे हैं। यह कहां का इंतजाम है, इसको आप अच्छो तरह सोचें और देखें कि इसके क्या नतायज होंगें ? यह कहा जाता है कि चूंकि कांग्रेस मेनीफोस्टो के अन्दर यह चीज है इसलिये हमारे ऊपर लाजिम था कि चाहे जो कुछ भी नतीजे हो इसको खत्म कर दें। तो मेरा कहना है कि वह में नीफेस्टो बहुत बड़ी चीज है, उसके अन्दर और भी बहुत सी चीजें हैं, क्या उन सबको आपने पूरा किया ? इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या किया, और भी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें दी हुई है, क्या सब को पूरा कर लिया जो आप इतने बड़े इंतजाम को खत्म करने के लिये तायार हो गये हैं ? कुछ की जवान पर यह है कि यह तरकी ब हम एलेक्शन में राय हासिल करने के लिये कर रहे हैं। किस तरह मैं कहं कि आया राय हासिल करने का जो तरीका आपने अस्तियार किया है वह कहां तक दूरस्त है ? में तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि इस तरीक़े से आपने जमींदारों को भो दुश्मन बना लिया है और एलेक्शन की दुश्वारियां भी इससे दूर नहीं हो सकतीं। आप ठंडे दिल से गीर करेंगे तो खुद ही देखेंगे और उसका जवाब पा जायेंगे। आज किसान क्या कह रहा है, जो लेबरर है वह क्या कह रहा है और जो दूसरे सेक्शन के लोग है वे कांग्रेसी सरकार के खिलाफ क्या राय रख रहे हैं इसको आप बख्बी समझ लें और गौर कर लें।

आप एक दिन में दुनि गं का इंतजाम करने जा रहे हैं और उसके क्या असरात होंगे। इस पर आपने कोई ग़ौर नहीं किया। में आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आपने ग़ौर नहीं किया है तो उसका नतीजा यह होगा कि जिस गर्ज के लिये आपने यह सब किया है वह गर्ज आपको हासिल नहीं होगी। मेरी तो यह राय और गुजारिश है कि आप इतना बड़ा इंकलाब पैदा कर रहे हैं। १७५ करोड़ एपया आप काश्तकारों से वसूल करने का इरादा कर रहे हैं। क्यों न आप आने वाले एलेक्शन का इंतजार करें जिससे कि यह मालूम हो जाय कि आया मुक्क इसके लिये क्या कहता है, इस तरह से १७५ करोड़ एपया वसूल करने के मुताब्लिक क्या कहता है। में इसरार करूंगा कि आप इस एक्ट का नाफ़िज करना दूसरे जनरल एलेक्शन तक के लिये मुक्तवी कर दें। उसका बहुत जमाना अब बाकों नहीं है सिर्फ कुछ महीने हैं उसके बाद आपको यह हक हासिल होगा। आप एलेक्शन में इस चीज को खास इक्यू बनावें। बिना मुक्क की राय लिये इतने बड़े इंकलाब को करना नामुनासिब होगा, इसलिये ऐसे बड़े मसले पर आप पब्लिक की राय मालूम करके एपया वसूल करें।

अब देखना यह है कि भूमिघरों के हक्कू जो आपने काश्तकारों को दिये हैं क्या इस कीमत पर काश्तकार उसे हासिल भी करना चाहते हैं? इससे ५ फ़ीसदी का सिम्पिल इंटरेस्ट (साधारण ब्याज) ही काश्त कारों को मिलता है। अगर वह इस रुपये को दूसरे कामों में लगाते तो कहीं ज्यादा फ़ायदा उनको होता। इससे आपने उतना भी नहीं किया जो जमींदारों ने किया जब कि उनके हाथ में इनाने हुकूमत थी और जबिक रेंट ऐक्ट जारी किया गया था और उसके जिरए से काश्तकारों को हकूक दिये गये थे। वे उन हकूक से कहीं ज्यादा हकूक थे जो आप आज काश्तकारों को देने जा रहे हैं। जो कुछ आप देने जा रहे हैं वह सिवाय इसके कि काश्तकारों को म्जिर साबित [श्री मुहम्मद जमशेदअली खां]

हो और फुछ नहीं है। आपने ट्रांसफर राइट्स जो कयूद से रिहा कर दिये हे उनसे सिर्फ यही होगा कि जमीन बनियों और साहू कारों के हाथ में चली जायगी, और नान ऐग्रोकल्चिरिस्ट्स ऐग्रीकल्चिरिस्ट्स बन जायेगे। इसके सिवाय और कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है।

आपने अपने बिल में सब देनेंद्र को, शिकमी काश्तकारों को भी मुस्तिक्रल कर दिया है और आपने अपने कानून से उन काश्तकारों को भी रिट्रास्पेक्टिन इफेक्ट देकर मुस्तिक्रल बना दिया हैं। बहुत से ऐसे छोटे—छोटे जमीं बार लोग है जिन्होंने किसी लास मजबूरी की नजह से अपनी जमीन को साल भर के लिये उठा दिया था और इस नजह से उठा दिया था कि मौजू दा कानून की क से वह ऐसा कर सकते थे और यह सोचकर कि इस साल यह मजबूरी है और अगले साल खुद उसे कर लेगे वह सबके सब इस बिल के जिये से खत्म कर दिये गये और जो बरसहा बरस से उस जमीन को बो रहे थे उनसे वह जमीन छीन ली गई और साल भर से या ६ महीने से काश्त करने नाले को नह जमीन दे दी गई। इस तरह से शिकमी काश्तकार को जमीन देकर यह हकूक देकर उन छोटे जमीं दारों को आपने नुक सान पहुंचाया ह जिनके बारे में जमीं वारी एबालोशन कमेटो की रिपोर्ट में भी तहरीर किया गया है कि जो २५ ६० तक की मालगुजारी देने नाले जमीं दार है उनकी हिसयत बिल्कुल काश्तकारों की सी है, उनके लिये कोई एबालीशन करना बसूद है लेकिन इसके तहत आपने उनकी जमीं दारी का भी एबालीशन कर दिया। लेकिन आज आप उनको भी एबालिश कर रहे हैं और उनके सीर के हुकूक को आप इस तरह पामाल कर रहे हैं कि आप खुद अंदाजा की जिये कि आप उनको क्या दे रहे हैं।

अब में मुआविजा के मुताल्लिक एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूं। आप अगर यह कहते कि हम जब्त कर रहे हैं तो में उसको समझ सकता था। अगर आप यह तय करते कि हम काश्निस्केशन करना चाहते हैं तो वह भी बात समझ में आने वाली थी। एक तरफ आप कहते हैं और आप के मैनिफेस्टो में भी मौजूद है कि इक्विटेबिल कम्पेंसेशन दिया जायगा लेकिन दूसरी तरफ जो मुआविजा दिया जा रहा है उसकी हकीकत कुछ और है। मैं आपके सामन यह अर्ज करदूं कि एवालिशन कमेटी रिपोर्ट में जो कुछ आपने वर्ज किया था उसके अन्दर ऐग्री-कल्चर इनकम्-टैक्स का कहीं जिक्र नहीं था। इस बिल को लाने से पहले आप ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल ले आये जो कि बिल्कुर गलत चीज थी और बेमीका थी। कोई भी शख्स इस चीज को पसन्द नहीं करता कि ऐग़ी कल्चर इन कम्-टैक्स बिल उस वक्त लाया जाय जबकि हम जनींदारी लत्म करने जा रहे हों। लेकिन जिम्मेदार लोगों ने और हमारे प्रीमियर साहब ने यह कहा था कि जहां तक उस बिल का ताल्लुक है यह न समझिये कि यह आप की आमदिनयों को कम करने के लिए हैं और उससे आपका मुआविजा कम हो जायगा। मुआविजा पर इसका कोई असर नहीं होगा। जब सिलेक्ट कमेटी के मौक़ा पर यह बात याद दिलाई गयी तो यह कहा गया कि वह तो उस वक्त हमने रक्खा या जबकि एबालिशन कमेटी ने ३-गुना मुआविजा तजवीज किया था और अब इस बिना पर कि हम इनकम-टैक्स शामिल कर रहे हैं हमने ८-गुना मुआविजा कर दिया है। क्या यह आपके लिखे शायांशान हैं ? क्या यह आपके लिए मुनासिब ह कि एक मर्तबा आप यह कहें कि तीन-गुना मुआविजा दे रहे हैं और दूसरी मर्तबा यह कहें कि ८-गुना मुआविजा दे रहे हैं लेकिन इनमें इनकम-टैक्स वजा कर लेंगे ? आपको उस वादा के बमुजिब, जो मुख्तलिक मौक्रों पर दिया गया है, हरिग्नच कोई हक्र नहीं है कि मुआविचा तय करने के वक्त आप इनकम्-दैक्स का लिहाज न रक्षों। इसी तरह मैं अर्ज करूंगा कि १५ परसेंट आपने लर्च रक्खा है जो बहुत ही गैर-वाजिब है। जब आप खरीवना चाहें तब तो कुछ और कीमत हो और जब कोई दूसरा लरीदना चाहे तब कुछ और क्रीमत हो, क्या यही तरीक़ा होना चारिये जस गवर्नमेंट का जो यह कहे कि हम पापु रुर गवर्नमेंट हैं और हम तमाभ पब्लिक की जानिब से रिप्रेजेटेटिव है। आपको यह तरीक़ा हरिता नहीं अख्तियार करना चाहिये। में आनरेबिल वजीर, माल से पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त मुल्क को जरूरत होती है, जिस वक्त कौम के सामने जरूरत होती है, उसे वक्त किसी कलास का ख्याल नहीं किया जाता है बहिक बड़े-बड़े इंटरेस्ट के मुकाबिले में छोडे-छोटे इंटरेस्ट लक्ष्म कर दिये जाते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस कोमी जरूरत के लिये, इस मुल्क की जरूरत के लिये आप जमीं दारों से कितनी कुरबानी लेना चाहते है ? आखिर आप क्या चाहते हे ? आप कितनी कुरबानी चाहते है ? जमीं दार अपनी आमदनी का कितना परसेट मुल्क की जरूरत के लिये पेश कर दे, हमने इसके बारे में वार—बार दिर्याफ्त किया। आप हमें यह तो बता दी जिये। मुल्की जरूरत के लिये और साहबान के सामने भी तो आपने सब चीजे रखी होगी। आखिर मुल्क में इंडिस्ट्रियलिस्ट्स भी तो है। आपने उनसे कितनी कुरबानी मांगी है, आपने उनसे कितनी कुरबानी ली है ? जिस हिसाब से आप ने औरों से कुरबानी ली है उसी हिसाब से हमसे भी ले लीजिये। मगर आप तो जमीं दारों की आमदनी का ८०, ८५ फ़ीसदी ले लेना चाहते हें यह कहां तक मुंसिफाना है और कहा तक इक्वीटेबिल है ? आप जब मैंनिफेस्टो की बिना पर जमीं दारों एबालिश करने जा रहे ह तो उसी मेनिफेस्टो में 'इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन' के अल्फाज भी तो लिखें हुये है। वया यह इक्वीटेबिल है कि किसी की आमदनी का ८०, ८५ फ़ीसदी ले लिया जाय और उसको इक्वीटेबिल और जस्ट कहे ?

कर्जेजात के मुताल्लिक भी हमारे सामने कोई चीज नहीं है कि आप क्या तजवीज रखते है। कोर्ट आफ वार्ड स की रिपोर्ट मौजूद है जिससे मालूम हो जायेगा कि कितनी रियासते मकक ज है और कितनी केसीर तादाद में, एक सौ कई लाख उन पर क़र्जा है । उसके लिये आपने हमारे सामने क्या तजवीज रखी है? वह कोई चीज ऐमी नही है। मै तो चाहता था कि कर्जे को स्केल डाउन (कम) करने के मुताल्लिक जो तज्रवीज होती उसको भी इसके साथ ही लाया जाता ताकि पूरी तसवीर हमारे सामने होती और हम अपनी सही राय उस पर क़ायम कर सकते। में चाहता हूं कि आप ईमानदारी ओर इंसाफ के साथ ये तमाम चीज करे । अगर आप यह चाहते है कि वाक़ई काश्तकारों को भी नफा पहुंचे और जमींदारों को भी नुक़सान न हो तो आप इस चीज को काश्तकारों और जमींदारों के दरमियान ही छोड़ दे। और कोई सेलिंग ब्राइस मुक़र्रर (विक्रय-मृत्य) कर दे जिससे वे आयस में ही तय कर ले कि इसके लिये कितना मुआविजा तजवीज करते हैं। इस तरीक़े से मैं पहले भी अर्ज कर वुका हूं। जब यह मसला सामने आया था तो मैने कहा था कि काश्तकारों को जमींदारों के साथ वालंटरी परचेज (ऐन्छिक क्रय) की छूट होनी चाहिये जिससे वे आपस में ही सारी चीजें तय कर ले और ये तमाम चीजे आपको न करनो पड़ें जोकि आप कर रहे हैं जिस रंपतारसे आपके इस फंड का रुपया वसूल हो रहा है उससे मुझे तो यकीन नहीं होता कि आपका वह टारगेट फीगर, जो १७५ करोड़ का है, पूरा हो आप एक तरफ रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने जा रहे है। क्या रिहैबिलिटेशन ग्रांट काग्रज की सूरत में होगी ? क्या आप छोटे जमींदारों को काग्रज देकर रिहै बिलिटेशन करेंगे ? जबिक आपके पास इतना रुपया नहीं होगा तो आखिर आप क्या करेंगे ? इसके लिये आपने क्या सोचा है ? आपने फैसला किया है और आप का यह हुक्स है कि इन चीजों को आपको करना है तो फिर आप यह कह कर नहीं छूट सकते कि रुपया वसूल नहीं हुआ इसलिये मजबूरी है। इसलिये कि आप उसके लिये जिम्मेदार है और आपने यह स्कीम पेश की है। आप यह बिल लाये है और खुद लाये है लिहाजा तमाम पहलुओं पर आपको गौर करना है। जितने असरात होंगे और हो रहे हैं उन तमाम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप परती और ऐग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड जमींदारों से ले रहे हैं। वह दरस्त जो क़सीर तादाद में इस वक्त मौजूद है उन सबको आप जमींदारों से ले रहे है। बाजार, हाट जो कसीर तादाद में सर्फ करके जमींदारों ने क़ायम किये थे उनको आप उनसे ले रहे है। दरस्तों मुआविजा आप जमींदारों को नहीं दे रहे है, परती लैंड का कोई मुआविजा आप नहीं दें रहे हैं। कहा यह जाता है कि साहब, इतने दिनों से आपके पास ये जमीने थीं लेकिन आपने उनको डेवलप (उन्नत) नहीं किया। में अर्ज करूंगा कि अब जो सहूलियते क्या वे सहलियतें इनको डेवलप करने के लिये उस वक्त मौजूद थीं ? आपे अगर यह करते, कोई वक्त मुअयन करते कि इतने दिनों के लिये यह परती जमीने तुमको डेवेलप करने के लिये दी जाती है, इतना हम टाइम लिमिट करते है, अब मुल्क आजाद हुआ है सब लोगों को हर क़िस्म की आजादी बहम पहुंच रही है। अब दो चार वर्ष के अन्दर [श्री मुहम्मद जमशेद अली खां]

तुम इन परती जमीनों को डेवेलप करो और अगर हम लोग नही करते तो हमसे ले ली जाती। अगर ऐसा होता तो मैं समझ सकता था कि आपने ठीक किया लेकिन आप एक कलम से इसको खतम कर रहे हैं। उनकी लखूखा एकड़ जगीन को एकदम ले रहे हैं। हमने जो बागात लगायेथे, जिनके लगाने में हमने एक कसीर रकम सर्फ की थी उनको भी एकदम ले रहे हैं। क्या यह तरीका है, जिस तरीक़ के मातहत इस बिल को चलाना चाहते हैं।

कल बारबार यह दरियाफत किया जा रहा था कि आचार्य नरेन्द देव जी ने क्या कहा और उन्होंने क्या फरमाया। अरे जनाब उनके ऊपर न जाइये। आपको तो यह ख्याल करना चाहिये कि अवाम में आपके लिये क्या ख्याल पेदा हो रहा है। आपके मुताल्लिक क्या ख्याल अब पहिलक का होता जा रहा है। "कहती हे तुझको खल्क खुदा ग्रायबाना क्या" आचार्य जी ने कुछ भी कहा हो लेकिन किसानो का अब आपकी तरफ से बया ख्याल हो रहा है, लैडलेस लेबरर्स का क्या ख्याल हो रहा है, छोटे जमीदार आपको क्या कह रहे है, इन सब बातो पर आपको ख्याल करना चाहिये। आपको इसका पता लगेगा जब आप उनके पास एलेक्शन के लिये जांयगे। आप उनसे राय हासिल करने के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपने एलेक्शन को जीतने के लिये जो मशीन बनाई है वह गलत साबित होगी क्यों कि इसी वजह से एलेक्शन में भी आपके लिये सख्त दिक्क़त पैदा हो जायगी। किसी ग़लत चीज पर इसरार करना कोई अक्लमन्दी नहीं है। महज इस बिना पर कि आप इस बिल को ऐवान के सामने लाये है, एक स्कीम आपने पेश की है जो कि नाकामयाब साबित हो चुकी है आप उसको वापस लेने के लिये तैयार नहीं है। आप उसके ऊपर इसरार कर रहे हैं। यह कोई अच्छी स्टेट्स्मैनशिप नहीं है। आप पापुलर मिनिस्टर है, आप बेतकल्लुफ़ कहे जाते है। जो तजबीज आपने एक बार पेश की वह जब नाकामयाब हो चुकी है तो आपको उसको वापस लेना चाहिये ओर कोई दूसरी तज्जवीज लाना चाहिये। यह जमींदारी का मसला तो एक बहुत बड़ा जबरदस्त इन्स्टी— टेंचु ज्ञान है। लेकिन जो आपने हालात मुल्क में पैदा कर दिये है उनके बम्जिब उसका खत्म हो जाना ही अच्छा है। आपके रात-दिन के प्रोपेगन्डे ने वह हालात पैदा कर दिये है कि जिनसे जमींदार और काश्तकार के बीच ताल्लुक अच्छे होना बहुत नामुमिकन है। इसलिये में खुद चाहता हुं कि जल्द से जल्द इस जमीदारी को आप ख़र्म कर दे। अब जमीदारों के लिये कोई मौक़ा नहीं रह गया है कि अब वह आराम से अपनी जिन्दगी बतर कर सकें और उनकी खुश-गवारी काश्तकारों के साथ और ज्यादा दिन तक चल सके। आप यह सोचिये कि आप अवाम के सामने क्या रख रहे हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिये कि जिससे किसी को भी कोई नक़ा न पहुँचे। और हरएक बसर के लिये दिक्क़त और परेशानी पैदा हो जाय। आपने जमींदारी एवालीशन फंड के इकट्ठा करने में उन सब चीजों को तर्भ कर दिया है जो आपने ख़ुद ही लागू की थीं। आपके बनाये हुए ऐक्ट जितने थे वह सब आपने पसेपुक्त में डाल दिये हैं। आपने जो एक्जिक्यूटिय आर्डर भेजे है वह इतने शर्मनाक है कि उसके लिये आपको शर्म आनी चाहिये। यह ऐवान जो फ़ुल्ली अख्तियारात रखता है जहां कि तमाम क्रानुन बनाये जाते है लेकिन आपने यहां के बनाये हुए क़ानूनों को भी अपने एक्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से खत्म कर दिया और उनकी तरफ जरां भी तवज्जह नहीं की महज इसेलिये कि आपका जो १०-गुना फंड है वह हासिल हो जाय। यह बहुत गलते बात है। अगर आप यह मिसाल अपने लिये कायम करने वाले है कि आपके बनाये हुए क़ानून इस तरह से ठुकराये जांय तो आप यक्तीन मानिये वि मुल्क के अन्दर आप अच्छा इन्तजाम, अच्छी हक्ष्मत की मिसाल नहीं कर क्रायम आप बड़े जोर शोर से कहा करते हैं कि एकजीक्युटिव और जुड़ी शियरी अलहवा होने चाहिए और हमेशा से जब से कांग्रेस पार्टी बरसरे हुक् मत आई है और पहली मर्तबा भी जब आप बरसरे हुकुमत थे उस वक्त भी हमारे यही प्रीमियर साहब कहते थे कि एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी अलहवा २ होने चाहिए। क्या आपका यही तरीक्रा उन दोनों को अलग करने का है कि आज आप एक्जीक्यूटिव आडंर के जरिए से तमाम उन क़ाननों को वरहम बरहम करते जाते हैं जो यहीं इस ऐवान ने पास किए थे। यही चीजें आपको सोचना है।

इसी सिलिसिले में एक बहुत जरूरी बात मुझे विद्याल औलाद के बारे में भी कहना है।
मैंने सिलेक्ट कमेटी में भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि यह हमारा एक मजहबी
मसला है और मुतलमानों के नजदीक विद्याल के नाम पर होता है और औलाद
के नाम होता है वह एक ही है और एक ही दर्जा रखता है और इसी बिना पर
इसका कानून भी पास हो चुका है और यह कानून मौजूद है और आपको इस वास्ते
इसको अलहदा नहीं करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ कि आप इसको चैरिटेबिल
विद्याल से अलाहदा कर रहे हैं। इस तरह से तो आप उन विद्याल साहब से कहूँगा
कि वह इस पर गौर व तवज्जह करें। इस सिलिसिले में मैंने अपना नोट आफ डिसेन्ट
भी दिया है।

एक बात और जरा सी तवज्जह दिलाने के क़ाबिल हैं जिस की तरफ मैंने सेलेक्ट कमेटी को भी मुखातिब किया था और वह यह है कि आपने तमाम हाट बाज़ार भी गांव पंचायतों के सुपुर्द कर दिए हैं। बेहतर यह था कि जिस तरह से जमींदार उनको अब तक कामयाबी के साथ चला रहे हैं उन्हों को चलाने दिया जाता। लेकिन अगर आप यह पसन्द नहीं करते हैं तो ज्यादा अच्छा होता कि आप इनको डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को ही दे दें। अगर आपने यह गांव—पंचायतों को दे दिए तो हर पांच—पांच कदस पर यह बाजार लगेंगे और नतीजा यह होगा कि काशतकारों को अच्छी नस्ल के मवेशी जो अब तक एक जगह पर मिल जाते हैं वह न भिल सकेंगे और करीब—करोब मेले होंगे तो सवेशियों की बीमारी भी ज्यादा कुलेंगे और गांव—पंचायतें उसको रोक न सकेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही अच्छी तरह उनके पास कोई वेटरनरी का महकमा नहीं है और यह इन्तजाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही अच्छी तरह से कर सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।

श्री गरापति सहाय-माननीय अध्यक्ष महोदय, में जमीदारी-उन्मूलन तथा मूनि-व्यवस्था बिल का हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसके साथ हो यह भी बतलानों चाहता हूँ कि जिस जिले में से में आया हूँ उस जिले में भी इस बिल का बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। कल हमारे एक समाजवादी भाई ने बड़ी पुरजोश तक़रीर करते हुए यह कहा था कि सरकार की तरफ से उन जमींदारों के खिलाफ जो इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं या उन समाजवादी भाइयों के विरुद्ध जो भूमियर बनने के लिये जगह जगह खिलाफ प्रचार कर रहे हैं सरकार की तरफ से दमन-चक चलाया जा रहा है। मैं उनकी इतिला के लिये यह बताना चाहता हूँ कि वह मेरे जिले में चलें और देखें कि वहां के जमींदारों और ताल्लुकदारों ने जो जमीदार यूनियन के मेम्बर हैं उन्होंने खुल्लम-खुल्ला नोटिसें बांटी हैं और लेक्चर दे रहे हैं और किसानों को रोक रहे हैं कि वह दसगुना लगान जमान करें। समाजवादी भाई हमारी कांग्रेस की मीटिंगों में जाते हैं और वहां इसकी मुखालिफत करते हैं। किसानों को जो रवया दाखिल करने तहसील में जाते हैं उनकी वहां से हटा कर और बर्गलाव र रुपया जमा करने नहीं देते। अभी थोड़े दिन हुए कि माननीय माल मंत्री हमारे जिले में दौरे के सिलसिले में गए थे। उस दौरे के सिलसिले में जो सभा हुई उस सभा में हमारे समाजवादी भाई अपनी लाल झंडी लेकर पहुँचे और अपने लाल झंडे से हमारी भूमिधरी की चलती हुई रेल को रोकना चाहते थे। में आपसे यह बतलाना चाहता हूँ कि बावजूद इसके कि जमींदार मुखालिकत कर रहे हैं और ताल्लुकदारान काश्तकारों को दबा रहे हैं और जावजूद इस के कि समाजवादी भाई हमारी मीटिंगों में आते हैं और उसको दरहम व बरहम करने की कोशिश करते हैं और किसानों को तहसील से वापस ले जाते हैं मगर हमारे जिले में किसानों ने इसका बड़ा स्वागत किया है। शायद आपको यह मालूम है कि हमारा जिला लखनऊ और फैजाबाद की कमिश्नरी में भूमिधरी के मामले में अब्बल है। जितना र पया हमारे जिले से दाखिल हुआ है उसकी फीसदी दूसरे जिलों से मिलाकर देख लिया जाय तो आपको पता चलेगा कि बावजूद इसके कि छोटा जिला है।

श्री गणपति सहाय । लेकिन लखनऊ और फैजाबाद की कमिश्नरी को मिला कर उन १२ जिलों में जिला सुल्तानपुर अञ्चल है। मुझे यह भी मालूम है कि हमारे कुछ भाई इस बात के लिये तैयार हो रहे हैं कि आपके सामने दो एक मिसालें ऐसे जमींदारों की पेश करें जिन पर १०७, ११७ जाब्ता फीजदारी का मुकदमा चल रहा है। मैं उनकी इत्तिला के लिये बतलाना चाहता हूँ कि जो जमींदार भाई और समाजवादी भाई ग्रामीण पंचायतों के सरपंच हं और अदालती सरपंच हैं वे खुल्ल न-खुल्ला हमारी मुखालिकत कर रहे हैं। हमारे जिले के हुनकाम ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। में उनकी इतिला के लिये बतलाना चाहता हूँ कि अगर कोई जमोदार किसी किसान की ४० बीधे की कच्ची फसल कटवा ले और हाथी पर चढ़कर उनको मारने के लिये बन्दूक लेकर यसकायें और उसको गिरफ्तार कर लिया जाय तो क्या इसको भूमिघरी रोकने का कुकदमा कहा जायगा। जो मुकदमा कच्ची फसल काटने और हाथी पर चढ़कर और बन्द्क लेकर किसान को धमकाने के लिये कायम हुआ है तो क्या वह मुक्रदसा मुस्थिर की मुखालिकत करने का कहा जायगा। अब इसके साथ-साथ में सिलेक्ट

अच्छी है। इसके साथ-साथ चन्द बाते ऐवान के सुझाव के लिये पेश करना चाहता हूं जिसके लिये में उम्मीद करता हूँ कि यह ऐवान काफी ग्रीर करगा और हमारे माल मंत्री उसे बिल में लान की ओर उसमें संशोधन करने की कोशिश करेंगे।

पहली बात जो मुझे बतलानी है वह यह है कि आपने अपने बिल में यह लिखा है कि यह क़ान्न क़ैंट्नमेंट एरिया, म्यूनिसिपैलिटीज और रामपुर स्टेट, बनारस स्टेट और टेहरी गढ़वाल स्टेट के लिए लागू नहीं होगा। में जानता हूँ कि जो अंगेजी में बिल छपा हुआ है उसमें एक सेक्शन में ये तीनों स्टेट भी लिखी हुई हैं। लेकिन अगर उसकी जाने दिया जाय तो में यह कहूँगा कि आपने कैट्नमेंट और म्युनिसिपैलिटीज को इस बिल से अलग करने में थोड़ी बहुत भूल की है। भूल इस वास्ते की है कि बहुत सी म्यूनिसिपैलिटीज और बहुत से कैंट्रनमेंट एरियाज ऐसे हैं जिनमें जमीदारों की जमीने आ गई हैं और व जमीनें काश्तकारों को उठी हुई हैं। में अपने जिले के लिये बतला सकता हूँ कि मेरे जिले में जो म्युनिसियलिटी हैं उसमें प्राइवेट जमींदारों की जमीने हैं और वह काश्तकारों की उठी हुई हैं। वे काश्तकार बेबारे अभी तक सताये जा रहे हैं। जैसे देहातों में सताये जाते हैं। उन काइतकारों से म्यूनिसिपैलिटी लगान नहीं वसूल करती, उन काइतकारों पर म्यूनिसिपैलिटी इजाफा लगान नहीं करती, उन काश्तकारों को म्यूनिसिपैलिटी पट्टा नहीं देती बल्कि वह प्राइवेट जमींवारियां म्यूनिसिवल एरिया में शामिल हो गई 🗗। वह जमींवारान ही उनका पट्टा देते हैं, वहीं लगान वसूल करते हैं और वहीं हर तरीक़े से मालिक हैं। अगर् आप इस बिल को या इस ऐक्ट को तमाम म्यूनिसिवैलिटी ज पर नहीं लगायेंगे, तो उन बेचारे किसानों की हालत, जो अभी तक पीसे और चूसे जा रहे हैं, वैसी ही रहेगी और कोई तरकती नहीं कर सकेगा। ऐसे किसानों की भूमिधर बनने में कठिनाई ही नहीं है बल्कि भूमिथर बनना ग़ैर-मुमकिन हो रहा है।

दूसरी बात जो मं आपकी तवज्जह में लाना चाहता हूँ यह है कि आपके इस बिल में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी तारीफ आपने बिल में नहीं दी है। मसलन आपने बिल में यह लिखा है कि गांव-समाज को वे तमाम अधिकार उस तमाम प्रापर्टी के सम्बन्ध में होंगे जो हिज मैजेस्टी में वेस्ट करेंगे। उसी के साथ गांव-समाज को पूरा अधिकार ह दावा करने का, पट्टा देने का और तमाम इन्तजाम करने का। में बतीर जवाब के यह बता वेना चाहता हैं कि उसमें यह भी कानून मौजूद है कि गवर्नमेंट गांव-समाज को पूरे अख्तियार् भूमि के इन्तजाम के सम्बन्ध में दे सकती है। जहां लगान वसुल करने के बारे में कुछ साफ़ नहीं लिखा हुआ है, बहां यह भी लिखा है कि गवनमट की

अधिकार है कि रूल बनाये। तो गवर्नमेट रूल बना सकती है। ऐसी हालत में हमारे समाजवादों भाई का यह एतराज कि उसमें लगान बसूल करने का कोई

अधिकार गांव समाज को नहीं दिया गया है, बित्कुल व्दर्थ है।

इसके आगे म यह भी बतलाना चाहता हूँ कि आपने इसे बिल में लैण्डहोल्डर रुख्द इस्तेमाल तो किया है मगर उनकी कोई डैफीनीकन नहीं दी है हालांकि इसकी तारिक्र यू०पी० दनेपी ऐक्ट में और और एक, दो में है। मगर आपने इसे दिल में लैंग्ड-होल्डर की कोई डेफीनीकन नहीं रखी है और इस लफ्ज का इस्तेमाल कई सेक्कानों में आया है चाहे गांव तमाज एक तरह का लैंड होल्डर तमाम गांव का होगा मगर गांव सराज के प्रलावा भी आयन वह इस्तेमाल किया है और कहा है कि उनको बदखनी का अहिम्यार होगा, यकाया लगान का अधिकार होगा और तरह-तरह के अख्तियार किसानों पर होंगे।

द्वपरे आन्ते अवरे ि । ते २ इ.से हिवा है कि जो कोई गुआहिदा किसं इंटरम् डिटरी से ओर किसी दूसरे शख्त से किसी जगल के बारे में यानी प्राइवेट फारेस्ट के बारे में हुआ होगा तो वह पुआहिदा नाजायज समझा जायेगा। मै निहायत अदच के माथ गुजारिश करूँगा कि इस बात की जरूरत है कि आप प्राइदेट फारेस्ट की डेफीनीशन भी इस बिल में दर्ज कर दे नोंकि क़ाल्स्ट के माने बहुत हुछ हो सकते हैं गांवों में और खास करके हमारे पूर्वी जिलों में फारेस्ट बहुत कम हैं। वह फारेस्ट जो बड़ी तादाद में हैं ज्यादातर गवर्नमेंट के अधिकार में है। गांचों में रूसा, ढाक और रेंव के जंगल हैं जिनमें दो चार दक्ष और १५ बीघे में ढाक रेंव अड्सा गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनको भी फारेस्ट की तारीफ में लाते हैं तो किसानों और जमींदारों के लिये बहुत मुश्किल पड़ेगी। इन ढाक के जंगलों से किसान लोग ढाक काटते हैं और ऊख पकाते हैं। इस वास्ते में गुजारिश करता हूँ कि प्राइवेट फारेस्ट के बारे में जो आपने लिखा है कि अगर कोई मुआहिदाँ हुआ होगा तो नाजायज समझा जायेगा इसलिये प्राइवेट फारेस्ट की तारीफ करना बहुत जरूरी है कि आपका प्राइवेट फारेस्ट से क्या मतलब है। अब इसके बाद में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने अपने बिल में इस बात का प्रावीजन किया है और इस बात का एक्सेप्शन रखा है कि जो लोग मुआवजे के एवज में सीर या खुदकाइत की आराजी आये होंगे उनकी सीर या खुदकाइत की आराजी उनके कब्जे में रखी जायेगी जबतक उनके गुजारा का हक कायम है। में आपसे अर्ज करूँगा कि सब गुजारेदारान ऐसे नहीं है जो जमीन पाये हुये हों या जिनको सीर या खुदकाश्त मिली हो। में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अवध स्टेट ऐक्ट देखें तो आपको मालूम होगा कि ताल्लुक़ेदार साहबान के जो छोटे भाई या भतीजे हैं जिनको क़ानून से गुजारा पाने का हक़ है। वह जमीन नहीं पाये हुए हैं, सीर खुदकाश्त या मौजा नहीं पाये हुये हैं बल्कि नक़दी नुजार पाते हैं। उनको भाहवार एक रक़म मुक़र्रर कर दी गई है। चाहे वह डिकी या दस्तावेज से मुकर्रर हुई हो, चाहे वह प्राइवेट कंट्रेक्ट इसे मुकरर हुई हो। आपने इस बिल में इस बात का कोई भी इन्तजाम नहीं किया है कि ऐसे गुजारेदारान को जिनको कि नक़दी गुजारा मिलता है और जिनके पास कोई जमीन नहीं है और सीर, खुदकास्त या मौजा नहीं है उनका क्या हुआ होगा। उनके लिये आपने क्या इन्तजाम किया है ? उनको आप क्या देना चाहते हैं। आपने यह भी नहीं लिखा है कि जो र आवजा जमींदारों को दिया जायेगा उसमें से कोई रक़म गुजारेदारान को भी मिलेगी। ऐपी हालत में मेरी गुजारिश है कि इन गुजारेदारान की हालत को देखें ओर विचार करें और ऐसे गुजारेदारान को जिनको नक़दी निल्ती है और जिनके पास जोतने को एक बिसवा जमीन तक नहीं है। उनको क्या दिया जादगा।

तीसरी बात जो मैं आपके सुझाव के लिये पेश करना चाहता हूँ वह यह है कि आपने भूमियर के सम्बन्ध में जो कुछ नये सेक्शंस लिखे हैं उनमें आपने चन्द बातों पर विचार नहीं किया। एक तो मैं आपसे यह बतलाना चाहता हूँ इस गुजारे के सम्बन्ध में अलावा

[श्री गणपति सहाय]

ताल्जुकेदारान के, गुजारेदारान के जिनको अवध स्टेट ऐक्ट के अनुसार नकदे गुजारा मिलना चाहिये उनको छोड़ कर आपने उन बेवाओं का भी कोई खयाल नहीं किया जिनको कोई हिस्सा नहीं मिला, जिनको केवल नकदी गुजारा पिल रहा है। खानदान मुक्तकों में उनके पति के देहान्त हो जाने के कारण उनको जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलता, महज गुजारा मिलता है। या तो वह घर में रह कर अपने समुर, अपने जेठ या खानदान के किती आदमी की नजरें इनायत पर रह कर गुजर-बसर कर रही है या वह घर से निकाल दी गयी है तो उनका नकदी गुजारा अदालत से मुकर्रर हो गया है। ऐसी हाल में उन बेवाओं का जिनको केवल नकदी गुजारा मिल रहा है उनका क्या हिश्र होगा, उनको क्या मिलेगा, उनकी जीविका कैसे चलेगी। ऐसी हालत में आपको उन लोगों के वास्ते जिनको नकदी गुजारा मिल रहा है अवध स्टेट ऐक्ट के मुताबिक जैसे ताल्लुकेदारान के रिक्तदार या भाई बन्द वग्नैरह और उन हिन्दू बेवाओं को, जिनके पित के मर जाने से जमींदारी में कोई हिस्सा नहीं मिलता, उनके लिये कोई न कोई इन्तजाम करना चाहिये।

भूमिधारी के हक हासिल करने के लिये आपने बहुत सहू लियते दी है लेकिन उसी के ताथ-साथ आपने जो यह कानून रखा है कि असल काश्नफारों का शिक्षमी काश्तकारान ५ साल के बाद १५-गुना लगान दाखिल करें तब उनको भूमिधर के हक हासिल हो सकते हैं। मैं अर्ज कलँगा कि इन ५ साल को मियाद रखने से आपका क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आपने असल काश्तकारान के लिए यह रखा है कि जो जमीन उनकी जोत में हैं, जिसको उन्होंने शिक्षमी पर नहीं उठाई थी, उस बची हुई जमीन के वास्ते अगर वह रसदी लगान का १० गुना दाखिल कर दे, तो वह भूशिधरहों मकते हैं लेकिन जो शिक्षमी है वह अगर १५ गुना लगान अभी अदा कर दें और भूगिश्रर बन जातं तो इ गमें क्या कानूनी नुक्स पड़ेगा ?

कतिपय समिति गं के ठिये सदस्यां के चुनाव का कार्यक्रम

माननीय स्पीकर—अब एक बजा है आप कृपया बैठ जाइये। मुझे गुळ घोषणायें करती है। कल माननीय सदस्यों ने कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किये थे जिनके अनुमार कुछ मंस्थाओं के न्विये चुनाव करवाना मेरा कर्तव्य है।

और के लाजिकल म्यूजियम, मधुरा की प्रबन्यकारिणी समिति के लिये १ सदस्य। प्रान्तीय म्यूजियम लखनऊ, की प्रवन्धकारिणी समिति के लिये १ सदस्य। प्रान्तीय म्यूजियम ऐडवाइजरी बोर्ड के लिए २ सदस्य। कृषि तथा पशु—पालन स्थापी सजिति के लिए १ सदस्य। प्रान्तीय नर्सेज एंड निउवाइक काउन्सिल के लिए २ मदस्य। प्रान्तीय नर्सेज एंड निउवाइक काउन्सिल के लिए २ मदस्य। ब्रुट्टेल बंड आयुर्वेदिक कालेज, आसी की प्रबन्यकारिणी समिति के लिये १ सदस्य।

मैने चुनाव के लिये यह कार्य कम नियत किया है। नामांकन-पत्र यानी नामिनेशन पेपर प्राप्त करने के लिये कल १२ बजे तक।

नामांकन-पत्र की जांच के लिये कल साढ़े बारह बजे अर्थात् प्राप्ति से आध घंटे बाद जांच होगी।

चुनाव से नाम वायस लेने के जिये कल चारवमें तक और परसों यानी तेरहतारी ख को रोडिंग रूप में बारह बजें से चार बजें तक, अगर जरूरत होगी तो, मत प्रदान किये जायंगे।

श्री नवाजिश कली सां--तेरह तारील या चौदह तारीख?

मोननीय रुपाकर—चोदह तारील मैने इसल्यि नहीं रखी कि चौदह तारील की आप लोगों को पालिशामेंट के लिये चुनाब हरना होगा, यदि नामांकन—पत्र पच्चीस से प्यादा आये।

(कुछ एक कर)

गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव विभाग ने एक प्रार्थना भेजी है कि हज कमीशन के लिये असेम्बली के एक मुस्लिम सदस्य का चुनाव किया जाय। पिछला चुनाव, संभव है कि मेम्बरों को याद हो, फरवरी सन् १९४७ ई० में हुआ था। तीन साल हो गये और उनका समय ३१ जनवरी तक है। अब वह समय समाप्त हो रहा है। इसलिय इस असेम्बली से एक सदस्य को चुनना है। में घोषणा करता हूँ कि कल तीन बजे दिन तक नामांकन-पत्र यानी नामितेशन पेपर आ सकेंगे। तेरह तारीख को एक बजे दिन के समय तक नाम वायस लेने की तिथि होगी और मत प्रदान चौदह तारीख को एसेम्बली रीडिंग रूम में दो बजे से चार बजे तक होगा। इसमें इस असेम्बली के सिर्फ मुस्लिम सदस्य हिस्सा ले सकेंगे।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर भवन स्थिगित हुआ और २ बज कर १० भिनट पर श्री नफीसुल हसन, डिप्टो स्पीकर, की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

सन १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश ग्रीर भूमि-व्यवस्था विल--(जारी)

श्रो गरापति सहाय--माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं भूमिधरी अधिकार के सम्बन्ध में कुछ निवेदन कर रहा था। भूमिधरी का रुपया दाखिल करने के सम्बन्ध में यह कहा गया ह कि यह रुपया बहुत कम दाखिल हुआ और १२ करोड़ रुपया जो दाखिल हुआ है वह इतना कम ह बमकाबिले उस तादाद के जोकि गवर्नमेंट ने उम्मीद की थी कि दसूल होगा, इस क़दर कम है कि गवर्नमेंट को यह स्कीम डाप कर देनी चाहिये और यह कह देना चाहिये कि हम नाकामयाब हुये। में बडे अदब से गुजारिश करूँगा कि यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट की यह योजना असफल हुई है या गवर्नमेंट की तजवीज नाकामयाब हुई है बिल्क वाक्रश यह है कि किसानों के पास इतना रुपया नहीं है कि वह एकबारगी दस-गुना दाखिल करके भूमिधर बन सकें। में मिसालन आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जिला सुल्तानपुर शोयद अवध में क्या बल्कि तमाम सूबे में सबसे गरीब जिला है। यह डेफीसिट डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार किया जाता है। हमारे यहां न तो कोई टचूब-वेल्स है, न हमारे यहां नहर हैं और न और कोई आवपाशी की सुविधायें हैं। किसान बहुत गरीब है लेकिन इस गरीबी की हालत में भी हमारे किसानों ने निहायत खुशी के साथ १०-गुना लगान दाखिल करके इतना दाखिल किया है और उसमें दाखिल करने में अपना इतना फायदा समझा । कि एक-एक तहसील में पांच-पांच, छ:-छ: गांव के गांव भूमिधर बन गये यानी वहां एक किसान भी ऐसा नहीं है जो भूमिधर न बन गया हो।

श्री हसरत महानी--यानी सब किसान जमीदार हो गये?

श्रो गणपति सहाय-जमींदार नहीं भूमिधर।

श्री हसात मुहानी--जमींदार और भूमिधर में फर्क़ न्या?

श्री गर्णपति सह।य—यह फर्क़ तो आप जब कानून पढ़ेंगे तो पता लगेगा। इसी के सम्बन्ध में में माल-मंत्री महोदय का ध्यान दूसरी ओर आकाषत करना चाहता हूँ। यह भूमिधरी का कानून जो बना है इस सम्बन्ध में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे लोगों को भी अधिकार दिया गया है कि जिनके नाम खाते में दर्ज नहीं हैं। कहा यह गया है कि जो रुपया वाखिल हुआ है वह उन लोगों का है कि जिनका न कोई हक है बिल्क जो यह समझते हैं कि हम रुपया दाखिल करके भूमिधर बन जायेंगे।

यह बिल्कुल गलत बात है असल में रुपया उन कि तानों ने दाखिल किया है जो खाते में दर्ज हैं जोकि खाते के काश्तकार हैं, जो लगान देते हैं और जो काबिज हैं। अगर कोई

[श्री गणपति सहाय]

रकम ऐसी दाखिल हुई है तो उन खातो के बारे में जो खाते निजाई है। अगर कोई ऐसे निजाई खाते में हैं जिममे एक भाई का नाम दर्ज है उसका छोटा भाई भी है ओर उसके यह भाई ने क्या दाखिल किया है लेकिन चिक बंधे भाई के नाम खाता है लिहाजा छोटे भाई का नाम खाते में नहीं था तो छोटे नाई ने भी रुपया दाखिल किया ह लेकिन उसको भिम-धरीका जिक्लेरेशन या शनद नहीं जिली है वह तो अब अया का से फसला हो जायेगा कि उरका यह हक है तो पाको उस कुक े हिम्से ने भूमियरी अधिकार मिल जायमे। तो हैरे खाते म्तनाजिया में जो राये दाणिल हुते नु गर्गलत , यह बित्कुल गलत बात रा पंचार मत्री जी का ध्यान आ तिष्त तरना बाहता ह वह यह है कि नापने भूमिधरी दे कानन के सभ्यन्य में यह लिखा ह जि भूमिधरों ना अख्तियार उन्त नाल हो गे लावने उसकी हिबा करने का अध्वितार दिथा, अये करन का अस्ति गर दिया, े तेर हर किस्म का इन्त काल करने का अख्तियार दिया है लेकिन रेहन करने का अस्तियार नही जिया है। यह मेरी सगन में बान नहीं लाई कि उनकी रेहन करने का अख्तियार प्या नहें। दिया जा रहा है ओर इसिल अर्प जापसे बड़े अरब में कहुंगा कि अगर आप रेहन करों के भी अख्तियारात दे दे तो म आपको यकीन दिलाता ह कि सबे ये कोई भी किमान ऐसा न बाकी बचेगा जो मिन्धरी का १० गुना रुपना सारितल न करे। ३१ यवत वह एक म, दो सौ या हजार जितन, लरू त होगी उतना रुपया लेकर मूमिधर बन जायगा और उसके बाद अपनी जमीन छुड़ा लेगा।

इसके बाद मैं यह भो अर्ज करूना कि आपके कानून में इप बात की कमी ह कि जब आपका कानून जारो हो नायगा, गजट में नोटीकिक तन हो जायमा नव जमीदार का हक खत्म हो जोगा पोर उसी के पाथ मुर्तिहिन का हक भी खत्म हो जायगा। मुतिहिन के निये । ए रक्खा है कि जो जमीन जमीवार की रेहन के कवल हार थी यह सीर जैमीबार को यापिन होगी प्रार उनदा वह भूमियर होगा, लेकिन अगर काई जमीन मुर्तिहिन के रेहन लेने के बाद सीर होती है तो वह जमीन उस नृतिहिन की रहेगी ओर अगर वह पार्च गुना लगन हे बगा लो उसका भूमिबर हो आयगा। मैं जनाब से अर्ज कहना कि आप जमादार को तो यह अधिकार दे रहे है, लेकिन यह काइतकार जिसने अपनी २, ४, १० बाबा जमोन रेटन कर दि । ते, अगर यह कि वो जरूरत के बक्त चाहे तो उसे अभिकार नहीं है। ३ न ऐक्ट भर को उल्ट डाफिये तो कही भां दा नात का पता नहीं यलेगा कि जुन काइनकार अन्ती जमान की रेइन कर देला है अपनी जमीन रेड्न ने छुटा कर मुसिधर बनने का अधिकार है। पहुरे पह कानून था, लेकिन अब राई कोर्ट ने 13 फे ाला कर दिया है कि काइनकार यका १२ के अन्दर दावो करके अपनो जमीन फक्ररेहन करा कता है। अगा जनाब जम बार क साथ । त रियायत है तो काइतकार के नाय भी होना चाहिये। काइतकार को भी अपनी जमीन को फकरें हन कराने काओर उन्ने भूभिधरी अधिकार प्राप्त करने का हक ि जना चाहिये।

इ। के बाद आपने जो अख्तियारात इतकाल के दिये हैं ्सभे आपने बेवा के लिये, सशोधन में यह लिला है कि बेबा को अख्तियार वसीयत करने का नहें। होगा। मेहरबान जरा देखिये अपनी दफा को, बेबा को अख्तियार यगनामा करने का है, हिबा करने का है तो उसके पाप वतीयत करने को रह ही क्या जाता है। अगर यसीयत करना हे तो वह हिबा कर देगी, बयनामा कर देगी, फिर वयीयत का हक उससे लेने का क्या मतलब है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसके बाद आयने जो कानून बनाया है कि भूमिधर के मरने के बाद कौन-कौन उसके वारिस होगे तो आप देखेगे कि वह भूमिधर के साथ अन्याय है। आप भूमिधर के उन्ही वारिसों को रखते हैं जो असामी या सीरदार के हो सकते हैं। अगर आप भूमिधर, सीरदार बौर असामी को एक ही पैमाने पर रखते हैं और उनकी वरासत भी वही रखते हैं

जो असामी और सीरदार की रखते है, तो आखिर में भूमिधर को दसगुना देने से क्या अधिकार मिला, सिवाय इसके कि वह अपनी जमीन बेच दे, हिबा कर दे या अपनी जमीन वसीयत कर दे। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि भूमिघर के साथ यह सराप्तर अन्याय है, क्योंकि आप उसको केवल इतना ही अधिकार देते ह कि फलां फलां आपके वारिस होगे ओर अगर ये वारिस न होग तो आपकी जमीन नजल हो जायगी। खास कर अवध के जो कब्जेदारान है उनकी कब्जेदारी की जमीन, उनके पर्सनल ला, (जाती कानून,) से मिलती है। इसी तरह से अवध एक्स प्रोप्राइट ी टेनेट प की बराप्त उसी तरह से होती ह जो उनका पर्मनल ला ह। अगर वह हिन्दू ह तो हिन्दू ला के मुताबिक और अगर मुसलमान ह तो में हमडेन ला के मुताबिक । मगर आपने १०--१२ वारिस बना कर उसको रात्म कर दिया है। अगर वह काइतकार ताकित्लिनिक्यत रहता तो कभी भी उसकी वरासत खत्म नहीं होती। मैं अर्ज करता हूँ कि कम ने कम भमिधरों के लिये यह कानुनी तरमीम दीजिये कि उनकी भी पर्सनल ली के मताबिक ही बिरामत होगी न कि उनकी उरात्त महदूद होगी। इनके साथ ही साथ र यह भी अर्ज करना चाहता है कि आपने एक अनोखी बात इस कानून में रख दी है जिसका उहत बडा असर संतानो पर पडेगा। आपने लिखा है कि बगेर बपाही बहन और बगैर ब्याही लउकी दोनो वारिस हो सकतो है। मगर उसके साथ ही यह भी लिखा है कि वह बहन ग लडकी जादी कर लेगी तो उस हक से महरूम हो जाशेगी। जो आराजी उसके बाप की थी, जो आराजी उसके भाई की थी वह आराजी खत्म हो जायगी जिस वक्त शादी कर लेगी। अगर कोई बेवा शादीशदा है और उसने अगर कोई जायदाद पाई है और अगर उसने भूमिवरी या सीरदारी का हक पाया है तो अगर वह जादी कर लेती हैं ओर उसको उम जमीन से महरूम कर दिया जाता है तो यह पूराना कानुन है वह हो सकता है। मगर यह कि लड़की अगर क्वांरी रहे तब तक तो उसका हक रहे लेकिन अगर वह ब्याह कर ले तो उस हक से महरूम कर दो जाय। बहन यदि क्वारी रहे तो उसका हक रहे लेकिन अगर ज्याह कर ले तो उसकी वह जायदाद जाती रहे वह उससे महरूम हो जाय। आपके समाज में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित हो रही है उसको भी इस कानून से कितना धक्का पहुँचेगा यह आप देखेंगे। छोटी जातियों में विधवा-विवाह और पुनर्विवाह अब भी प्रचलित है। इसके क्या मानी कि अगर कोई कुरमी की औरत ने अपने पति की जायदाद पाई है, लेकिन जब तक वह विधवा है तब तक तो उस पर उसका हक है, लेकिन अगर वह शादी कर लेती है तो उसका हक खत्म हो जाता है। जब वह दूसरा शौहर कर लेती है, हालाकि वह उसकी जाति में रायज है ओर हमेशा से चला जाता है कि वह दूसरी शादी कर सकती हैं, लेकिन आपके कानून के जरिये से अगर वह छोटी जाति की विषवा आज शादी कर लेती है तो वह उस अपने हक से महरूम कर दी जायगी। इसके साथ ही आप अब ऊंची जाति में भी विधवा विवाह ओर पूनविवाह जारी कर रहे है तो इस क़ानून से उसको भी बहुत घक्का पहुँचेगा। वे लोग भी विधवा विवाह और पुनर्विवाह करने में हिचकेगे। यह बहत ही अहम मसला है इसलिये आप अपने कानून में से उस दफा को जिसमे आपने यह लिखा है कि शादी करने से वे अपनी जायदादों से महरूम कर दी जायगी, आप निकाल वें। समय बहुत हो गया है। मैं सिर्फ दो एक छोटी-छोटी बातें आपकी तवज्जह मे लाना चाहता हैं। आपने जहां पर इंटरमीडियरीज की तारीफ लिखी है और जहां पर उनके काश्तकारों का जिक्र किया है वहा पर आपने पट्टेदार इस्तमरारी बन्दोबस्त अवध, का जिक्र किया है। अगर आप ज्यादा और गौर करते और ऐसे आदिमयो से मशिवरा लेते जो रोजमर्री अदालत दीवानी या अदालत माल मे काम करते है, तो आपको पता चलता है कि अवध में कुछ ऐसे भी इंटरमीडियरीज है जिनके काश्तकारों का कोई भी तजिकरा आपके बिल में नहीं है। वह कौन लोग है ? वह वही लोग है जिनको बन्दोबस्त अव्वल से ठेका दवामी नाकाबिले इंतकाल और काबिले तवरीस का अधिकार मिला है और जो लोग कहे जाते हैं ठेकेदार दवामी । आप बिल को एक सिरे से दूसरे सिरे तक उलट डालिये, लेकिन ठेकेदार दवामी का कहीं जिन्न नहीं है। अगर आप अवध

[श्री गणपति सहाय]

प्रान्त में ढूढें तो आपको हर जिलें में ठेकेदार दवामी मिलेंगे। बाज-बाज जिलों में तो यह लोग हजारों की तादाद में मिलेंगे, लेकिन आपने उनका कहीं जिक्र नहीं किया है। मैं आपसे अर्ज करूँगा कि ठेकेदार दवामी को भी आप इंटरमीडियरीज में रिखये और उनके काश्तकारों के मुताल्लिक जो कुछ आप अधिकार देना चाहते हैं वह दीजिये।

आखिर में में एक बात और अर्ज क गा कि उन लोगों की क्या हालत होगी इस क़ानून के पास होने के बाद जिनके पास जागीरें हैं। वह जागीरें उन लोगों की नहीं हैं जो बड़े—बड़े जागीरदार कहलाते हैं, बिल्क वह छोटे—छोटे मजदूर और छोटे २ काश्तकार हैं जो एक बीधा, २ बीधा या ४ बीधा जमीन नौकरी—चाकरी करने के सिलिसले में माफी पाये हुये हैं। इन लोगों के बास्ते आपके बिल में कोई भी दफा या क्लाज नहीं है। इन लोगों का क्या हस्र होगा।

आखिर में में ज्वाइंट हिन्दू फैमिली था हिन्दू खानदान मुक्तर्का के बारे में कहना चाहता हूँ। जहां पर आपने मुआविजा का जिक किया है वहां पर आपने लिखा है कि जो इंद्राजात का ग्राजातदेही हैं होंगे उन इंद्राजात को कम्पेंसेशन आफिसर या मुआविजा का अफसर, जिसको आप मुकरेर करेंगे, कर्ताई और नातिक मानेगा और किसी ज्वाइंट फेमिली की जायदाद के सिलसिले में अगर कोई उच्च कर सकता है तो सिर्फ यह कर सकता है कि उसका मुनाफा कम है या ज्यादा है। वह कोई इस बात का उच्च नहीं कर सकता है कि उसके खानदान मुक्तर्का में सिर्फ एक आदमी का नाम खेवट में दर्ज है, लेकिन मेरा भी हिस्सा है, इसलिये हमको भी मुआविजा मिलना चाहिये। इस क़ानन को उसी हालत में रहने से बहुत बड़ा जुल्म होगा ज्वाइंट हिन्दू फैमिली के मेम्बरान पर। ज्यादातर ऐसा ही है कि ज्वाइंट हिन्दू फैमिली में सिर्फ एक आदमी का नाम खेवट में दर्ज है। जिस आदमी का नाम दर्ज है उसी का नाम कर्तई मान करके और इंद्राजातदेही को सही मान करके उसको आप मुआविजा देंगे और खानदान के दूसरे मेम्बरान को अगर उच्च करने का हक नहीं होगा तो उनकी बड़ी हक़तलफी होगी। लिहाजा में अर्फ करता है कि आप इन सब बातों पर गौर करके आप अपने मसविदा में संशोधन करने की कोशिश कीजिय।

*श्राह्मरत महानी--जनाबवाला, में समझता हूँ कि में शुरू ही में इस बात का एलान कर दूं कि में इस जमीदारी एबालिशन बिल का सक्त मुखालिक हैं। इस लिये नहीं कि में जमीदारी एबालिशन को नहीं चाहता बल्कि में यह कहता हूँ कि यह बिल जो आपने पेश किया है यह जमींदारी एवालिशन बिल नहीं है बरिक जमींदारी को बदस्तर क्रायम रखने वाला बिल है। जमींदारी को खत्म करने और उसकी मंसूख करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वह है नेशनलाइजेशन आफ लंड। अगर आप जमीन का नेशनलाइजेशन कर दें तो जमींदारी खत्म हो जायगी। अगर आप कैपिटलिंग्म को खत्म करना चाहते हैं तो नेशनलाइजशन आफ इण्डस्ट्रीज कीजिये। जब इंडस्ट्रीज का नेश-नलाइजेशन हो जायगा तो प्राइवेट कैपिटलिउम खुद ब खद खत्म हो जायगा। यह दो शक्लें हो जमीं वारी को खत्म करने और सरमाये दारी को खत्म करने के लिये हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है नेशनलाइजेशन आफ लेंड और नेशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज। अब नेशनलाइजेशन आफ लेंड के क्या माने हैं? उसके माने यह हैं कि जमीन जो है वह खुदा की इतायत है, खुदा की दी हुई है जिसको अतिया इलाही कहते है, जो मजहब को नहीं मानते हैं, जैसे कुछ कश्यूनिस्ट हैं जो मजहब को नहीं मानते हैं, वह कहते हैं कि जमीन जो है वह खुदा की तरफ से गिपट है। इस पर किसी का क़ब्जी नहीं है। कोई शख्स इसका मालिक नहीं है। मालिक सिर्फ उस हिस्से का हो सकता

^{*} माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

है जो उसके इस्तेमाल में आदे। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रख दूं। जैसे एक दरिया है वह बहता चला जाता है। जहां जहां से वह बह कर जाता है उस पर किसी का क़ब्जा नहीं है। अलबत्ता अगर कोई झख्स अपने घर में एक घड़ायाएक बधनाया एक लोटा पानी उसमें से निकाल कर अपने इस्तेमाल के लिये लावे तो उतना पानी उसकी पर्सनल प्रापर्टी हो जायगी। बाक़ी दरिया बदस्तूर उसी हालत में रहेगा और वह किसी की प्राइवेट प्रापर्टी नहीं होगा। उस पर उन सबकी मिस्कियत है जहां-जहां से वह बहता हुआ जाता है। अगर आप यह चाहते हैं कि जमींदारी को खत्म करें, अगर वाक़ई आपका संज्ञा ऐसा है तो इसके माने यह है कि जमीन जो है उसको प्राइवेट मिल्कियत से निकाल कर स्टेट की लिल्कियत में देना चाहिये। जब तक स्टेट की मिल्कियत में नहीं होगी तब तक आप जमीदारी का एवालिशन नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें आपने किया ज्या है ? चन्द बड़े-बड़े जमींदारों को तो आपने खत्म किया है और उनको खत्म करने के बाद फिर उनकी जमीन को नीलाम में लगा दिया है। आप कहते हैं कि जो काश्तकार लगान का दसगुना दे देगा उसका लगान आधाहो जायगी और उसको अपनी जमीन पर पूरा हक होगा, उस जमीन की मिल्कियत उसको देदी जायगी और वही उसका मालिक होगा। इसके क्या माने हुए ? फर्ज की जिये कि एक जिले में दस बड़े—बड़े जमींदार हैं तो उनकी जमोदारी तो आपने जब्त कर ली और नीलाम पर लगा कर दस हजार और छोटे छोटे जमोदार बना दिये में नहीं समझता हुँ कि आपके इस भूमिधर और जमीदार में फर्क़ क्या है सिवा इसके कि वे बड़े बड़े जमींदार थे, उनकी जगह पर ये छोटे-छोटे जमींदार हो गये। एक बात में और कहदूं, में समझता हूँ कि जिन लोगों ने यह बिल बनाया है उनको उर्दू जबान और फ़ारसी जबान के अल्फाज की कर्तई जानकारी नहीं है। जमीन जो फारसी का लक्ज है उसको तो भूमि कर दिया और दार जो फारसी का लक्ज है उसकी जगह पर घर कर दिया। इसके क्या माने हैं? जमींदार की जगह पर भूमिधर करने के सिवा और कोई फर्क़ इसमें नहीं है। चन्द बड़े-बड़े ज़मींदारों को खत्म करके उससे हजार गुना छोटे-छोटे जमींदारों को आप पैदा कर देते हैं। उसमें और जमेंदार में कोई और फर्क नहीं है। आप जिस बिना पर जमीदारी को खत्म करना चाहते हैं वह कौन सा उसूल भूमिथर के अन्दर नहीं है। जमींदार भी खुदकाइत नहीं करता है, वह दूसरों के जरिये से काइत कराता है और उससे फायदा खुद उठाता है। आपने ५० एकड़ की करेंद लगाई है कि इतना मिलेगा इससे ज्यादा कोई नहीं रख सकेगा। तो उसके बाद क्या होगा ? क्या वह एक आदमी खुद जोतेगा और उस जमीन को बोयेगा। यह जाहिर है कि जो हालत जमींदार की थी वहीं हो जायगी। जाहिर में दिखाने के लिये वह यह कहेगा कि में नौकर रखे हूँ, उन्हीं से जुतवाता हूँ और बुवाता हूँ। इसके अलावा जितनी जमींदारों की सीर की जमीन है क्या उसमें से वह खुद जोतेंगे, बोयेंगे। वह उनके पास रहेगी। वह भी काइतकारों के पास चली जायगी। तो क्या इससे फर्क पड़ जायगा? तक जो जमीन जमींदारों के कब्जे में थी अब भिमधर के कब्जे में हो जायगी। जो खराबी जमींदारों के वक्त में थी वही खराबी भूमिधर के वक्त में भी होगी। इसलिये में कहता हूँ कि मैं इस क़ानून की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसकी यह वजह नहीं है कि में जमींदारी एबालिशन नहीं चाहता हैं। मैं इसको इसलिये मुखालिफत करता हूँ कि यह कानून हमारी मरजी और मंशा के बिल्कुल खिलाफ है और वक्राअतन जमींदारी को एबालिश नहीं करता बल्कि इसको और बेहतर शक्ल में क़ायम करता है। चन्द बड़े–बड़े जमींदारों को खत्म करके उनकी जगह पर हजार गुणा छोटे-छोटे जमींदारों को बना कर रख देता है। इसके अन्दर वह तमाम खराबियां मौजूद हैं जिनको मिटाने का आपको दावा है कि हम यह मिटाने के लिये कर रहे हैं। मुझको मालूम है कि इसके अन्दर जो यह सिलसिला जारी किया है कि इंटरमीडियरी न रहे, इस इंटरमीडियरी का मिटाना मुमकिन नहीं है जब तक कि आप किसी क़िस्म का काइतकार रखते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इंटरमीडियरी के माने यह है कि जो जमीन की मिल्कियत या गांव की जमीन है,

[श्रो हसरत मुहानो]

या मुल्क की जमीन है उसका सिवाय स्टेट के और कोई मालिक नहीं हो सकता। कोई भी प्राइवेट प्रापर्टी न रहे। जब प्राइवेट प्रापर्टी नहीं रहेंगी तो जितनी भी जमीन होगी वह सब स्टेट के पास चली जायगी। तब स्टेट का फर्ज हो जायगा कि वह अपने इन्तजाम में उस पर काक्त कराये। काइत कौन करेगा? काइत वहीं करेगा जो कि अब कर रहा है। फर्क क्या होगा? फर्क यह होगा कि काश्त तो वह जरूर करेगा लेकिन काश्त करने के बाद जब फ़सल काटने का वक्त आयेगा और उससे जो गल्ला पैदा होगा वह गल्ला काइतकार के पास नहीं जायगा बल्कि वह गल्ला स्टेट की मिल्कियत हो जायगी और उससे जो बडे-बडे फायदे होंगे वह मैं अभी आपके सामने बयान करूँगा। फिर जो लोग काइत करते हैं वही करेंगे, वही बोयेंगे और काटेंगे, लेकिन काश्तकार की हैसियत से वह मजदूर हो जायगा और वह उजरत लेकर ही काम करेगा। स्टेट उनको उजरत देगी। जी लोग खेत में काम करेंगे वह स्टेट से उजरत पायेंगे। वह उजरत इस शकल में पायेंगे कि उनको कोई नुक़सान नहीं होगा जैता कि रूस में आज कल होता है। वहां खुद स्टेट जमीन की मालिक है, काश्तकार वही है, जो बोता है और जोतता है। और वह सब काश्त-कार उजरत पर काश्तकारी करते हैं। साल भर काम करने के बाद जितनी उजरत उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है उनको दी जाती है। एक हिस्सा नक़दी के रूप में उजरत दी जाती है और एक हिस्सा गल्ले की शकल में दी जाती है। और वह जितने आदिमयों की बाबत साबित कर देते हैं कि हमारे घर में इतने आदमी खाने वाले हैं उतना गरला उनको मिल जाता है और बाक़ी उनको नक़दी की सूरत में मिल जाता है अगर आप भी करेंगे और जब गल्ला स्टेट की मिल्कियत होगा तभी आपकी स्टेट को कृव्वत हासिल होगी और इस तरह से वह गल्ले की क्रीमत भी मुक़र्रर कर सकती है और अगर वह चाहे तो अपने एहतमाम में रार्शानंग की दूकानें भी कायम कर सकती हैं और इस तरह से लोगों को आग सस्ते से सस्ते दामों पर ग्रहला दे सकते हैं और पढ़ा, बग्नैर पढ़ा, गरीब अमीर, बच्चा या बूढ़ा कोई भी अपना गल्ला इस तरह से आसानी से पा सकता है जेता कि आज कल सोवियट रूस में होता है। आयकी राशन की दूकान जैसे आज चल रही है वह बिल्कुल फजूल है, लगो है और उनसे कोई फायदा नहीं है। में आपको एक उसूल की बात बतलाता हैं और वह यह है कि जब तक आप ऐसा न करेंगे कि प्रोक्योरमेंट भी आपके हो हाथ में हो तब तक आपको किसी तरह की कामयाबी हासिल नहीं हो सकती और न उस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूशन के कोई, मोनी हैं। इस तरह से आप आसानी के साथ गल्ला भी हासिल कर तकेंगे और उसके बाद आप जिस तरह से चाहें गल्ला तक्तमीम कर सकते हैं। जब तक आपके हाथ में गल्ले का हासिल करना नहीं तब तक भागे-भागे काश्तकारों के पीछे फिरना आपकी हिमाकत है ओर काश्तकारों से कहना कि इतना गल्ला दे दो उतना दे दो यह लगो है। इस तरह से दुकानें खोलना आप की लग्नवियत की बात है और इससे बढ़कर दुनियां में और कौन सी लगवियत की बात हो सकती है। इसकी वजह यह है कि आप ऐसी स्कीम लाते हैं जो कामयाब नहीं हो सकती और जो इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। आप ग़ौर कीजिए और मुझे तो कानपुर जिले का अपना जाती तजुबा है। यहां के कलेक्टर लाहब में, कृष्ण चन्द्र साहब ने यह मक्रारेर किया कि हम हर काइतकार से दस फीसदी या इतना गल्ला प्रोक्योरमेंट (प्राप्त) कर लेंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि हम गेहूँ सादे दस दपया मन ले लेंगे और फिर उन्होंने हातिम की कब पर लात मारी और कहा कि अब हम १३ रुपया १० आना मन ले लेंगे। मगर काश्तकार बेबक्रफ नहीं हैं। उसके विमारा में भी यह जीज है कि क्यों इस निर्ख पर गल्ला दें जब उस का घर बैठे २० रुपये और २५ रुपये मन अिक सकता है। अगर वह इस तरह से आपको देता है तो उससे ज्यादा पागल और कीन होगा, जब घर बंठें आपको मालूम होना चाहिये कि बलेक मार्केट करने बाले आप के आदमी जाकर काइतकारों से २०, २५ और ३० हपया मन गेहें खरीदते हैं और फिर वह सवा सेर और डेढ़ सेर का लाकर बेंचते हैं तो क्या आप उम्मीद रखते हैं

कि आपको साढ़े १३ रुपये में गेहूँ मिल सकता है। ऐसा खयाल करना मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे ज्यादा और क्या हिमाक़त और बेवकूफी आप की हो सकती है। नतीजा यह होता है कि आपकी स्कीम जो प्रोक्योरमेंट की डिस्ट्रोब्युशन की और चीप रार्शानंग की दूकान खोलने की और शहर में गल्ला बांटने की थी वह फेल होती है, चल नहीं सकती क्योंकि वह क़तई खिलाफ फितरत है और अन्तेचुरल है।

हमारे दोस्त रोधनजमां खांसाहब जो सोधालिस्ट हैं उनका दावा और उनके खयालात भी अजीबोगरीव हैं। वह भी उसी हिमाक़त में मुझ्तला हैं। वह कहते है कि साहब सारी जमीन उसी की है कि जो उसको जोतता बोता है। कास्तकार की मिलकियत होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यह तो बिल्कुल लगो बात है और कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। जिस शहस के पास जमीन होगी बह उसकी मिलकियत हो जायगी। वही जमींदार है चाहे वह छोटा जमींदार हो। फिर आपका यह दावा कि हम जमींदारी को अवालिश करते हैं बिल्कुल गलत और उत्टा दावा है। आप जमींदारी को अबालिश नहीं करते बल्कि दस जमींदारों के दस हजार जमींदार कायम करते हैं। यह आप अच्छा घोका देते हैं कि वह दस गुना लगान दे दे तो मालिक हो जायगा। क्या काश्तकारों को यह मालूम नहीं। हां, एक बात की में तारीफ करता हूँ। सोशलिस्टों ने अच्छा सबक पढ़ा दिया है। यह जो कहते हैं कि तुम मालिक हो गए यह नहीं होगा। जमींदारी एवालिशन किया गया है। चन्द साल के बाद वह कहेंगे कि यह भी जमींदार है। इनकी भी अबालिश करो। उनको मुआतिजा भी दिया है। जो भूमिधर है उनको मुआविजा भी नहीं मिलेगा। उनसे कहेंगे कि तुमने इतने दिन तक खा लिया, जोत भी लिया। मुआविजा कसा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वाक़ई इसे दूर करना है तो जब हमारे यहां से यन्त जी और मेरे दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू कांस्टीटुएंट असे बली में बकालत करने के लिये गए और वहां यह मजमून पेश किया तो मैंने खड़े होकर बहुत सखती के साथ मुखालिफत की और एक घंटे तक तकरीर की। वन कहा कि मैं जो एतराजात कर रहा हूँ पड़ले उनका जवाब दीजिए। उसके बाद इस क्रानून की पेश कीजिये और पास कीजिए। वहां क्या हुआ ? जो यहां होता है वही वहां भी हुआ। आय लोगों को मालून है कि हनारे यहां प्राइन मिनिस्टर हैं। फाइनेंन्स विनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं। वह सब क्या कहते हैं। वन पार्टी वन रूल और यह कहा जाता है कि नाउ दी क्वेडचन इज पुट (अब सवाल पेश किया जाता है) और वह क़ानून यात हो गया। लाहील बला कुटवत इल्ला बिल्ला। यह कीन सा तरीका इसाफ है, यह कीन सा द्यानतदारी का तरीका है। आप कम्यू-नलिस्ट है क्योंकि आप कम्यूनल एलेक्टोरेट से मुन्त खिब होकर आए हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि हिन्दुओं को हिन्दुओं ने और मुसलनानों को मुसलमानों ने एलेक्ट किया है। इस बिना पर वह सारा काम कर रहे हैं। मुस्छिम लीग खत्म हो गयी। एक सेक्शन खत्म हो गया। अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी बाकी है सेण्टर असेम्बली में और वह पियोर कम्यूनलिस्ट है। यही वजह है कि जो कानून आप पेश करते हैं और पास करते हैं वह दयानतदारी के खिलाफ है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुरा कहते हैं। आप कहते हैं कि हमारी सेक्युलर स्टेट है। इन बातों से आपकी मेरे दिल में जरा वकअत नहीं वाक़ी है। मेरे दिल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिये गुन्जायश है।

श्री राममूर्ति—इस समय किस मजमून पर बहस हो रही है। क्या आय रिलेकेंट बोल रहे हैं?

डिप्टी स्पीक (--मौलाना हतरत मोहानी, जो मजमून इस वक्त जेर बहस है आप उसी पर बोलिये।

श्री हसारत मुदानो—मेरा सारा ताल्लुक इती बात पर है। में इस बिल का मुखालिफ हैं। बजाय पहले के आप बेस्ट फार्म में जर्मदारी को क्रायम कर रहे हैं। पहल दस जमीदार थे तो अब दस हजार जमीदार होंगे। पक सदस्य--यह इर्र लीवेवट (असंगन) बोल रहे है।

श्री हसरत महानी--रेलीवेट किसको कहते है यह मैं आप लोगो से बेहतर जानता हैं। मैं यह कह रहा था कि जब तक आप बीच में से कुल इन्टरमी डियेरीज को नहीं निकालेंगे तब तक यह ऐबालीशन आफ जमीदारी नहीं हो सकती। और जब म कुल इटंरमीडियरीज को कहता हूँ तो मौस्सी काश्तकार, दखीलकार काश्तकार, जितनी भी किस्म काश्त-कारान की है, वे सब की सब इटरमीडियरीज में हो जायेगी। इटरमिडियरीज कब लत्म होंगे। जब कि जमीन की मिल्कियत स्टेट के पास चली जायगी ओर नेशनलाइजेशन आफ लैण्ड के मृताबिक सब मिल्कियत होगी। सब जमीन की काश्तकारी स्टेट की तरफ से होगी। जो काइतकार होगे वे काइतकारी तो करेगे मगर वह मालिक की हैन्दित से नहीं करेगे बल्कि उनको उजरत दी जावेगी। जेशा कि मैं कह चुका हैं कि जब साल में खेत कटगे, उनको मजदूरी दे टी जायगी, समिथिंग इन कैश ऐन्ड संगिथिंग इन काइड (कुछ नकदी के रूप में ओर कुछ गल्ले के रूप में)। ओर अगर इसके बाद भी उनमें से कोई ऐसे मनचले होगे जो कहेंगे कि जितना हमकी दिया गया है वह हमारी जरूरत के लिये काफी नहीं है, हमकी इससे ज्यादा मिलना चाहिये, हमको इससे ज्यादा की जरूरत है तो वह आम बाजार मे जाकर आम गोदाम से खरीद सकते हैं। वहा कीमते मुकर्रर होगी उन पर कोई भी खरीद सकेगा। न उनमें कोई ख़राबी है, न खतरा। मैने वहा पर कस्टीटचूएंट अमेम्बली में भी, यही कहा था और यहा भी यही कहता हूँ। हमारे मिनिस्टर लोग जो है व यहां मौजूद भी नहीं है और कोई सुनता भी नहीं। वे कहते है कि बकते क्या है बकने दो। बीट तो हमारे हाथ में है और जब हम पेश करेंगे या जो भी पेश करेंगे, पास तो हो ही जावेगा। में आपसे कहता हूँ कि इस बात का इत्मीनान न कीजियेगा। यह तरीका जो है यह गरूर का है और बन पीर्टी गवर्नमेंट का है? इसका नतीजा कभी दुनिया में अच्छा नहीं निकलता। मुझको यह मालूम होता है कि चीटी के पर निकल आये और अब उसकी मौत करीब है।

माननीय माल अचिव--जब त्रोंटी बहुत पुरानी हो जाती है, तब उसके पर निकल आते है।

श्रो रसरत मृहानी—मं यह चैलेज के साथ कहता हूँ ओर कोई साहेब जिनिस्टर हो या कोई भी हों, पहले मेरी बातो का जवाब दे कि किस तरह मे आप इसकी एवालोशन कह रहे हो। जब तक आप इनका जवाब नहीं देते ओर सिर्फ अपने वोट के भरोसे पर यहा आकर बंड जायेने तो "Now it may be a question of years but it will be a question of months and days and if you will persist in this policy you will be finished soon. There is no alternative other than that" (हो सकता है कि कई वर्ष लग जाये किन्तु महीनों और दिनो ही का मामला हो जायगा आर यदि आप अपनी इसी नीति पर अड़े रहे तो शीघ ही आप का अन्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है।)

भाननीय माल सिचिय—मं दरख्वास्त करूँगा कि अगर अंग्रेजी मे न बोला जाकर हिन्दी मे बोला जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

डिप्टो स्पोक -- वह गालिबन किसी तहरीर का हवाला दे रहे थे। श्री हसरत मुद्दानो-जो कुछ मैं कहना चाहता था, मैने कह दिया। एक सदस्य--मोलाना कहिये आप कहिये, हम सुन रहे है।

श्रो हस्तरत मुहानी—कोई मुननेवाला नहीं है, यही तो मैं कहता हूँ। मैं इस त्रिल की मुखालिफत सिर्फ एक बिना पर करता हूं और वह यह कि यह एबालीशन आफ जमीदारी नहीं बित्क यह हमेशा के लिये जमीदारी कायम करने का और एक जमीदार के बजाय सैकड़ों ह

जमीदार पैदा करने के लिये बिल है। यह कहा जाता है कि माहब भूमिधर बन जायगे यह सरासर घोखा है इसमे कुछ और नहीं रक्खा हुआ है कोई फर्क भूमिधर और जमोंदार में नहीं है। जो खरावियां जमीदार में मोजूद है या जनीदारी में मौजूद है और जिनके मिटाने के लिये आप इते पेश कर रहे हे. उससे बदतर शक्ल हो जायगी। आपने कहा कि ५० एकड़ से कम एक शख्म को नहीं दी जावेगी, यह भी नहीं हो तकता है मेर। ह्याल है कि जिन लोगो ने यह बिल बनाया है उन्होने एक बुरी नकल की है हमारी सोवियट युनियन की। सोवियट युनियन ने भी पहलें गलत फ मो की बिना पर यह कहा था कि भाई, एकदम से नेशनलाइजेशन आफ लैंडन करे। उन्होने यह किया था कि एकदम नेशनलाइजेशन आफ लैंड न करके बल्कि जो बडें–बड़े काश्तकार थे उनके पास जमीन रहने दी ओर छोटे– छोटे काश्तकारो की जमीन को मिला दिया। उन्होने वह कुराक तिस्टम कायम किया। यह वही था जैना कि आपका भूमिधर सिस्टम है। नतीजा क्या हुआ छै महीने भी नही ग्जरे कि उनको अपनी हिमाकत का सबक मिल गया ओर एक सालके अन्दर उनको बिल्कुल मिटा करके प्योर सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट निस्टम जारो कर दिया और जमीन की कार्य स्टेट के हाथ में रखी। जिन लोगों को काक्तकारी के लिये मकर्रर किया वह सिर्फ उजरतदार थे। जब फसल काटने का वक्त आयेगा तो सारी फसल स्टेट की हो जायेगी। ओर डिस्ट्रीब्यूशन उनके हाथ में होगा। फिक्सेशन आफ प्राइसेज (कीमत मुकर्रर करना) उनके हाथ में होगा आप लोगों को तरह नहीं। जिनके हाथ में प्रोक्योरमेट नहीं है वह फिक्सेशन आफ प्राइसेज कैसे कर मकते हैं और क्या गल्ला हासिल कर सकते है। मैने पंडित जवाहरलाल जो मे दो बाते कही थी। एक तो यह कि कब्ल इमके कि आप इसको पास करे मेहरबातो करके मेरो बातों का पहले आप जवाब दे। अगर नही देते तो इसके कोई माने नहीं हैं। बेकार आप दुनिया को घोखा देते हैं कि हमारी तो सेक्यूलर स्टेट है। लोकल गवर्नमेंट ओर सेट्ल गवर्नमेट आर० एस० एस० को बुरा कहती है लेकिन को उनका प्रोग्राम है उनको आयने भी तो नकल को है। उन्होने मुझसे कहा कि आप काग्रेस गवर्नमेट की मुखालफत करते है। अगर यह चली जायेगी तो इसकी जगह पर हिन्दू सभा या आर० एस० एस० आ जायेगे I hav- zot softest corner in my heart for them (मेरे दिल मे उनके लिये बहुत हमदर्दी मौजूद है।) आर० एस० एस० चाहे म्सलमानो के खिलाक कुछ भी करें लेकिन यह एक फड़ोमें टल प्रितिपल तो यह है जो हमने कायम किया है। हमारी हिन्दुस्तान की जो गवर्नमेट क्रायम हुई है वह सोशलिस्य रिपब्लिक है। यह नहीं कि जवाहर लाल अभी भी किन जार्ज के पुछल्ले बने हुये है। आर० एस० एस० के लोग ईमानदार है।

माननी ग्रमात मा नव -- यह मै कैसे कहूँ कि यह रेलीबेन्ट है या इर्रलीबेट। डिप्टो स्पीकर--पोलाना जो बिल है उसी पर आप अपनी बहस को महदूद रखे।

श्रो हसर्त महानी—जिस उसूल पर बिल बनाया गया वह बिल्कुल गलन है। इसिलये मैं आपको बतला रहा हूँ कि एबालीशन के माने तब पैदा होंगे जब आप सीक्ष—लिस्ट बेसिस पर अपनी सोमाइटी की तजीम करें, जिम यक्त आप नेशनलाइजेशन आफ लैंड करें। जब आप ऐसा करेंगे नब आपकी जमीन प्राइवेट से निकल कर स्टेट की सिल्कियत में आयेगी। साथ ही स्टेट काइतकारी का इन्तजाम करेगी, काइनकार वही होंगे लेकिन काइत की पैदाबार उनके पास नही रहेगी। वह स्टेट की मिल्कियत होगी। मेरा दाबा है कि इम वक्त हिन्दुस्तान की सरजमीन पर काइतकार से बढ़ कर बलैक—मार्केट करने वाला और कोई नहीं है। एक—एक काइतकार ने अपनी हैसियत से १००—गुना इपया इस बलैक—मार्केट से जमा किया है। हमारी कांग्रेस सरकार को भी इसका हाल मालूम है और यही वजह है कि उन्होंने यह समझ कर कि

[श्री हसरत मुहानी]

काश्तकार ने ब्लंक—मार्केट में खूब रुपया जमा किया है, यह १०—गुना लगान दे देगे और १८० करोड़ रुपया आसानी से जमा हो जायगा जिसमें से हम १३० करोड तो बड़े—बड़े जमीदारों को जिनकी हम जमीदारी खत्म कर रहे हैं उनको दे देगे और बाकी ५० करोड़ को हजम कर जायेंगे, बलंकमार्केट के तोर पर। बड़े जमीदारों से जमीन ले ले, उसके बाद नीलाम पर बोली चढ़ा दे। १०—गुना लगान लेकर उसको जमीदार बना दें। १८० करोड़ रुपया वसूल होगा, १३० करोड़ जमीदारों को चला जायेंगा, बाकी बच्चेगा ५० करोड़। इससे बढ़कर बलक—मार्केट ओर क्या हो सकती है ? खंर मेरा मतलब यह है कि होना यह चाहिए कि जमीन स्टेट की मिल्कियत हो, कोई इंटर—मीडियरी न हो, न कोई जमीदार न मोमसी काश्तकार और न कोई दल लकार। काश्त रटेट की होगी, उजरतवार के तोर पर जिसे स्टेट चाह मुकरर कर ले, उनकी उजरत दे श जायेंगी। जिताना फायदा होगा उत्के हिमाब से उजरत मुक्तर्य की जायगी। इसमें बठक—मार्केट की गुजाइश नही रहेगी। बलंकमार्केट में बेचने के लिये काश्तकार के पारागाल ही नहीं रहेगा।

केकित पह जो सुरत कायम है यह बिल्कुण अनने बुरल है, यह चल नहीं सकती। इसी-लिए जास्यी उच्च एट असेम्बलो में नने कहा था "यू शुड देक करेज इन बोथ हड्स एड शई ट ऐक्ट' (आपको हिम्मत से काम लेकर काम करने की कोशिश करनी पाहिये)। जंब तक आप यह नहीं करेगे यह चीज चलने वाली नहीं है। १० करोड रुपया भी अब तक वसूल नहीं हुआ। क्या इन थोड़े से लोगों को ही आप मूमिधर बना देंगे, जिन्होने कि हमया दे विया है और बाकी सब मोची के मोची रह जायेंगे। एक उसूल कायम करके उस पर चलना चाहिए, जिससे इधर-उधर न हो सके। इसीलिये कहता हूँ कि वह मौका मही है, बिल्कुल बेमौक़ा यह बिल है। इसमें कोई तोहीन की बात नहीं है। गवर्नमेंट का यह खयाल था कि का इतकार आसानी से अपने लगान का दस-गुना दे देगा ओर उसकी वजह यह थी कि जमींदारों की जमीन होती थी और वह किसी काश्तकार को जमीन उठाता है, तो सिर्फ एक-एक पट्टे के लिये पांच-पांच सी, और एक-एक हजार लोग देते है। जब पटटा लिखवाने में पाच-पाच सी रुपया, एक-एक हजार रुपया अदा कर देते है तो अब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को यह उम्मीद थी कि ऐसी हालत मे जमीन का मालिक बनने के लिये दस-गुना लगान देने में किसको क्या तक्तलीफ हो सकती है। सोशलिस्ट पार्टी वाले भी यही कहते है कि जमीन की मिल्कियत उसकी ही है जो जोते-बोवे। हरएक मजहब में यही है कि पानी, हवा, जमीन और आग यह चार चीजे खुदा की देन हैं और जो खुदा को नहीं मानते वह कहते हैं कि नेचर की देन है। यह किसी की मिल्कियत नही है। एक इंसान सिर्फ उतने हिस्से का मालिक हो सकता है जो उसके इस्तेगाल में आता है। उतने हिस्से का मालिक हो जो उसके इस्तेमाल में आता है। इसके मानी यह है कि जमीन किसी की पिल्कियत नहीं है। लेकिन हर इंसान को यह हक्क हासिल है कि वह अगर चाहे तो अपनी जरूरत के मुताबिक एक बीघा, दो बीघा जोते-बोये। वह उसकी पर्धनल प्रापर्टी हो जावगी। बाक़ी अगर इसते ज्यादा रखना चाहे और उसमे का तकार बसाये तो फिर बह जमीदारी हो गयी। इगलिये मेरी दरख्यास्त है वजीर माहबान यहां मौजूद नही है, में समझता हूँ कि अगर इस बक्त नही है, तो जब कल आएंगे तो मेरी बातों का जवाब देगे, अगर उनके विमाश में जर्रा बराबर भी इंसाफ और हक़पसन्दी का माद्दा होगा तो मेरी इस बात को मानेगे कि जब तक वह अपने दिल में पूरे तौर से इस पर क्रायम न हो जायं, जब तक सोशिलस्ट या कम्यूनिस्ट सिस्टम अख्तियार करने के क़ाबिल न हो जायं, उस वक्त तक जमींबारी के एवालिशन का दावा बिल्कुल लगो है। मैं तो हुकूमत से यह कहता हूँ कि जो लोग प्राइवेट भी रखना चाहते हैं और एबालिशन आफ जमींबारी भी करना चाहते हैं "आइवर दे आर फूल्स

आर दे आर नेब्ज" (वे या तो बेवकूफ है या धूर्त हैं) मेरे कहने का मतलब यह है कि मेहरबानी फरमा कर इस बिल को वापस लीजिये क्योंकि अव्वल तो इसका मौक़ा नहीं, दूसरे इसके जो सेक्शन हैं उनसे एबालिशन आफ जमींदारी नहीं होता बल्कि उससे दस हजार गुना बुरी शक्ल में जमींदारी क़ायम हो जाती है। जब तक आपको खुदा तौफीक न दे, निगाह और बसीरत अता न फरमाये कि आप यह सोचें कि एबालिशन आफ जमींदारी बगैर नेशनलाइजेशन आफ लैंड के नहीं हो सकता उस वक्त तक इस बिल को लाना सिवा इसके कि हिमाकत कही जाय और कोई चीज नहीं है।

श्रा फूल सिंह—श्रीमान डिप्टो स्पोकर साहब, विशिष्ट समिति से संशोधित बिल पर जो बहस इस भवन के सामने विछले तीन दिनों से हो रही है मैंने उसको गौर से सुनने की कोशिक्ष की। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी तक़रीरें तो इस बिल से कुछ संबंध नहीं रखतीं। माक्तिंग, सैक्युलर स्टेट, कंट्रोल, राशनिंग, शुगर, सेपरेशन आफ जुडीशियरी और एक्जीक्युटिव इनिया में जितने मसले हो सकते थे सभी इस पर बहस में आ गये। में समझता हूं कि उन चीजों पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहिये। कुछ साथियों ने इस बिल के जरा नजदीक से चर्चा करने का प्रयत्न किया । उनका ज्यादातर जोर इस बात पर रहा कि जो रुपया १०-गुना लगान को शक्ल में जमा किया जा रहा है उसमें किसानों पर दबाव डाला जा रहा है, तरह–तरह के लोभ किसानों के लिये पैदा किये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस दलील से भी इस दिल का कोई संबंध नहीं है। सवाल इस भवन के सामने यह है कि विशिष्ट समिति द्वारा संशोधित बिल जो भवन के रू-बरू पेश है उसमें क्या-क्या कमियां है और उसमें क्या क्या इस्लाहात होने चाहिये। जमींदार साहबान में से जो बुजुर्ग किस्म के लोग है जिनकी रहनुमाई और नुमाइन्दगी कल के दिन नवाब यूसुफ़ साहब ने की उनका यह कहना है कि अब यह बहुत देर हो गई है इसका चर्चा करने के लिये कि आया जमींदारी का उन्मुलन हो या नहीं अब तो यह काम जल्द हो और किस तरह से हो इस मामले पर विचार करना चाहिये। इस बिल की मंशा से जो लोग इत्तफ़ाक़ नहीं करते उनकी दो बातें तो मेरी समझ में आ सकती हैं। एक तो वह फरीक जिसकी यह राय हो कि जमींदारी जैसी की तैसी बनी रहे और कोई हेरफेर इसमें न हो और दूसरी बात जो मेरे बुजुर्ग मौलाना हसरत मुहानी साहब ने अभी बयान की है वह में समझता हूं कि इन तीन दिनों में इस बात की तो सिवाय चन्द जमींदार भाइयों को छोड़कर किसी ने भी ताईद नहीं की कि मौजुदा जमींदारी प्रथा जो है वह नध्ट न की जाय। इस पर सब इत्तफाक़ राय से मालूम पड़ते हैं। मौलाना साहब भी इस पर मुत्तफिक थे और हमारे दूसरे लाल टोपी वाले सोशलिस्ट भाई भी इसके पक्ष में थे और सब इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं। मौलाना साहब का कहना है कि जमीनों के काक्तकारों को भूमिधर न बनाकर नेशनलाइज करना चाहिये। उन्होंने अपने रूस की मिसाल पेश की थी।

श्रों इसरत मुद्दानी--भूमिधर बनाकर नहीं बगैर भूमिधर बनाये।

श्री फूल मिह—में निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि मौलाना साहब की तरह उन सब भाइयों की जिन्होंने किताबें पढ़कर राय कायम की है यही राय है कि जमीन को नेशनलाइज करना चाहिये। मैं इस की बातें बहुत जानता नहीं हूं लेकिन इतना मालूग है कि जब इस में यह क़ानून बना और इस पर अमल किया जाने लगा कि जमीन की मालिक सरकार और किसान को मजदूरी मिले या सरकार इसकी जुरूरत को मुहइया करें तो दो नतीजे उसके हुये।

एक यह कि जितने बैल वगैरह थे सब सरकार के हो गये और चारा भी सरकार का हो गया लेकिन किसान को अपने बैल से मोहब्बत रही। तो जब शाम को सब बैल बांधे जाते थे और चारे डालने का काम होता था तो सारे किसान चारा भर-भर कर बैलों कि पास डालते थे, हालांकि यह काम सरकारी नौकरों का था। ततीजा यह हुआ कि जो चारा साल भर के लिये था वह चार महीने में खत्म हो गया। दूसरे यह कि उन्हें यह मालूम था कि काम करो यान करो तनख्वाह तो मिलनी ही है। हिल लिया तो किसी ने १० क्रदम ले जाकर खड़ा कर दिया और किसी ने २५ क्रदम ले जाकर खड़ा कर दिया। हां, काम तो किया शाम तक लेकिन काम हुआ कुछ नहीं।

श्री हुस्। त मुहानं। — हमार दोस्त को यह मालूम ही नहीं कि कलेक्टिव फार्मिंग के क्या माने हैं। इसके माने यह है कि सब काश्तकार जमा होकर काम करते हैं और जितना काम करते हैं वही उपको उजरत मिलती है।

श्री कृत सि .——तो किसी ने कहा कि मेरे बैं ल का पाव खराब हो गया उसे ठीक करले, या कुछ न कुछ बहाना हो गया। गज यह कि पब के सब जब तक छुट्टी का घंटा न हुआ खेत में रहे लेकिन खेत की जुताई न की गई। नतीजा यह हुआ कि पहले साल बहुत ज्यादा जमीन बिला जुते रह गई और रूस में कहत पड़ा।

जो लोग इस देश में खेती से सम्बन्ध रखते हैं उनको मालूम है कि खेती करने वालों में तीन किस्म के लोग है। पहला नंस्वर उनका है जो जमीन के मालिक या काश्तकार है। दूतरा उनका जिनका जमोन से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिन्हें पैदावार का कुछ अंग्र मिलता है। जिन्हें हल शहा कहते हैं। तीसरे वे लोग जो मजदूरी पर खेती करते है। यह हर आदमी को तज्ञा है कि जो मजदूरी पर खेती करते है शायद अपनी मजदूरी के बराबर काम नहीं करते है। हलवाहे जो है, जिनको पैदावार का कुछ अंश मिलता है वह कुछ काम करते है, लेकिन जो मालिक है जनीन का उसकी बुखार चढ़जाय तब भी खेती का काम करता रहता है, उसकी टांग ट्ट जाय तो भी काम करेगा, उसका बाप मर जाय तो भी काम करता रहेगा, धूप हो, पानी बरसता हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, काम करता रहता है। तो मैं अपने उन दोस्तों से जिन्होंने किताबे पढ़ कर यह राय कायम कर ली है कि देश की पैदावार बढ़ाने का तरीका एक ही है और वह यह है कि जमीन को नेशनलाइज कर दिया जाय, निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि यह खतरे की घंटी है। इस तरफ च उने में देश की पैदाबार बहुना तो एक तरफ रहा, देश की तबाही होने का इमकान है और यह खुशी की बात है कि किसान की इस बात की सरकार ने मंजूर किया और यह क़ानून बनाया। दूसरा तरीक़ा जो हो सकता है और जो निकलता है, यानी यह है कि जमीन में काश्तकार का हक पैदा कर दिया जाय, उसकी अपनी मिल्क्रियत दे दी जाय ओर कांग्रेन गरकार ने इसकी अख्तियार किया। जो राय मेरे बी ग्रांतरूट भाई रखते है गुझे ये माफ करेंगे, वह न तो हियां में है और न शियों में है, न ने बनलाइजेशन के साफिक न पेटी प्रोप्राइटरशिप के माफिक। कल जब रोशन जमां शारुब तकरीर कर रहे थे तो उनसे पृंछा गया कि आखिर आपको क्या राय है तो उन्होंने एक तकील की तरह से दाव-पेच की बातें की और यह नहीं कहा कि किलानों का क्या होना चाहिये।

रोशन जमां लां साहब तो इस पेच से निकल गये। लेकिन उनके और उन लोगों के युजुर्ग आचार्य नरेन्द्रदेव साहब ने जो लिखित वयान और जनानी प्रयान दिया था उसमें दो तीन बातें साफ है। उन्होंने कहा कि किसान को जमीन पर मालिकाना हकतो दिया जाय लेकिन कि पान को हक इन्तक़ाल न रहे, किसान को जमीन के बेचने का तक न रहे। एक बात और कही कि किसान के पास उतनी हो जमीन रहे और यह अतनी ही जमीन का मालिक रहे कि जिम को यह खुद जीत सके। अगर कोई मजदूरों और हलवाहों को रूप कर खेती कराता है तो इस बात को भी वह मंजूर नहीं करते हैं। इस तरह से आचार्य नरेन्द्र देव जी की यह मंशा थी कि कि । नों के जो इक़्क़ हैं उनमें थोड़ा मा इजाफ़ा हो जाय लेकिन उन्होंने यह माफ कहा कि में यह नहीं चाउता हूं कि किसान पेटी प्रोपराइटर हो जाय। आज भले ही सोशलिस्ट पार्टी के लोग कि नानों को बहकायें कि अगर हमारे हाथ में सता आयेगी तो हम सब किसानों को जमीन मुपत बांट देगे, लेकिन देखने के क्राबिल दो घातें है कि जो कुछ वह देते है या देना चाहते है वह वया चीज है और किस क्रीमत पर वह देना वाहते हैं ओर काग्रेस सरकार जो देना चाहती है वह क्या चीज है और किस क्रीमत पर वह देगी। सोशिलस्ट भाई तो किसानों को मालिक बनाना चाहते ही नहीं है। भूमिधरी के वे बिल्कुल खिलाफ है। वे पर्सनल प्रोपराइटरिशप और पेटी प्रोपराइटरशिप के क्रायल नहीं हैं। इसके विरद्ध कांग्रेम सरकार ने जो बिल इस भवन के सामने उपस्थित किया है, उसमें भूमिषरी के राइट्स है। ह्सरत मुहानी साहब ने फरमाय कि भूमिधरी और जमींदारी में क्या फर्क़ है वे नहीं समझ पाये। में निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस बिल की मंशा रिम्बल आफ इन्टरमिडियरो की है।

श्री हसरत मुहाना--क्या भूमिधर इंटरमीडियरी (मध्यर्ती) नहीं है

श्रा क्र नान हुन्न गों हारों के नानों अगर देवा जाय तो यह है कि जमों हार को उसके इस्तेमाल का पूरा-पूरा हक होगा (जमा) हक इंतकाल होगा, (जमा), हक विरासत होगा। यह तीन चीज मिल्कियत के मानों में आती हैं। मिल्कियत के एक मानी यह भी है कि वह जिस चीज का मालिक है उसको यह हक हासिल है कि वह उस चीज को जिसको चाहे बेच दे, रेहन कर देया काक्ष्त पर दे दे। इसका दूसरा मतलब यह है कि वह जिस चीज का मालिक है उस चीज को जिसको चाहे दे दे। तीसरी बात यह है कि वह जिस चीज का मालिक है उस चीज को जिसको चाहे दे दे। तीसरी बात यह है कि वह जिस चीज का मालिक है उस चीज उसके बाद उसके वारिसों को मिलेगी। भूमिधरी हक्ष में विरासत का हक्ष शामिल है उसका यह हक्ष उसको मिलेगा लेकिन इन्तकाल के हक्ष में कुछ मोडी फिकेशन्स किये गये है। भूमिधर को यह हक्ष हासिल होगा कि वह जमीन का बयनामा कर दे लेकिन भूमिधर को यह हक्ष हासिल नहीं होगा कि वह उस जमीन को किसी काश्तकार को उठा दे और भूमिधर बना बैठा रहे और उसे यह भी हक्ष नहीं है कि वह जमीन को रहन दखली कर दे। मैं समझता हूं कि यह दो बड़े खड़े फ़र्क है।

श्री इसरत मुहानी--यह बाल की खाल तो मेरी समझ में नहीं आती।

श्री फूल सिंह-बाल पतला है, घबराइयेगा नहीं, आप समझने की कोशिश करे।

तो मैंने अर्ज किया कि किसानों में यह फ़र्क है और जमींदारों में यह फर्क़ है। इससे यह साफ जाहिर है कि जो चीज इस क़ानून के जिर्यों से किसानों को दी जा रही है वह उस चीज से कहीं ज्यादा है जिसकी चर्चा आचार्य नरेन्द्र देव जी ने अपने बयान में की है।

दूसरी चीज यह है कि किस क़ीमत पर जमींदारी ली जा रही है। हमारे दोस्त सोशिलस्ट पार्टी के लोगों ने तमाम देहात में बड़ा शोर किया कि हम तो किसानों को मुपत में जमीन दे देगे और यहां भी वह कहते हैं कि साहब यह व्यर्थ रुपया लराब किया जा रहा है। मैं अपने दोस्त रोशन जमां साहब से अगर यह अर्ज करूं तो बेजा न होगा कि जितने घंटे उन्होंने अपना भाषण दिया उतने घंटों में कम से कम दो हजार रुपया सरकार का खर्च हुआ होगा इस भवन की हाजिरी पर, और यह रुपया उस रुपया के मुक़ाबिले में जो कुल जमीदारी स्कीम पर अभी तक सरकार ने खर्च किया है कही ज्यादा मालूम होता है। (एक आवाज—असेम्बली ही न बोलायी जाय)। असेम्बली तो बोलायी जाय लेकिन आप इतने घंटे तक न बोला करे। मैं माफ़ी चाहूंगा अगर मैं कहूं कि अगर कोई माकूल बात हो तो आप कहें मगर राशन की बातों के लिये और कंट्रोल की चर्चा करने के लिये यह भूमिधरी का बिल शायद मौजू मौक़ा नहीं था।

श्री अब्द्रल बार्का-ट्रस्ट मे विरासत कैसे चलेगी

श्री फूल सिह—में ट्रस्ट के मुताल्लिक भी अर्ज करूंगा। मुआविजा की चर्चा में कर रहा था। आप देखिये कि जो स्कीम आचार्य जी ने कमेटी के सामने पेश की उस स्कीम के ऊपर अगर गौर किया जाय तो यह मालूम होगा कि उस स्कीम की रू से मालगुजारों का २५ गुना मुआविजा देना चाहिये उन जमींदारों को जिनकी मालगुजारों १०० रुपया तक है। इस बिल के जरिये जो इस भवन के सामने उपस्थित ह २५ रुपया तक के मालगुजारों को २८ गुना मुआविजा मिलेगा, यानी अगर आप इधर गौर करे कि २० लाख में से १७ लाख जमींदार ऐसे हैं जिनकी मालगुजारी २५ रुपया से कम हैं तो आपको यह मालूम होगा कि २० लाख में से १७ लाख जमींदारों को सोशिलस्ट पार्टी की स्कीम से नुकसान होने जा रहा था। इस शक्ल में कि वह उनको २५ गुना मुआविजा देने वाले थे लेकिन इस बिल में उनको २८ गुना मुआविजा मिल रहा है। यही एक बात इसमें नहीं है, दूसरी एक और बात भी इसमें है। कल रोशन जमां खां साहब ने चर्चा की कि हमारी राय में तो मुआविजा ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपया होना चाहिये। में नहीं जानता कि रोशन जमां साहब की जो बात है वह सोशिलस्ट पार्टी को मंजूर है या नहीं। चृंकि उनके नेता अपने बयान में यह बात कह चुके है कि ज्यादा से ज्यादा ५ लाख रुपया मिलना

[श्री फुल सिह]

चाहिये। वैसे तो उमूलन में सोशलिस्ट पार्टी की इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मुआविजा की ज्यादा से ज्यादा कितना कितना मुआवजा दिया जाय इसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिये। तो में आपसे यह कह रहा था कि उसूलन यह बात सही है कि कितना मुआविजा ज्यादा किसी शहस को मिले, यह मियार मुकर्रर होना अच्छा होता है और अच्छा होता कि कांग्रेस सरकार भी इस बात को मानती । लेकिन देखना यह है कि आया इस बात को न मानकर कांग्रेस सरकार ने कुछ बड़ी भारी गलती की है या नहीं। मैने वह आंकड़े निकाले है जिनसे यह फर्क़ मालम होगा कि अगर आचार्यजी की स्कीम मानी जाती तो क्या होता। वे जमींदार कि जिनको ५ लाख रुपये से ज्यादा मुआविजा मिलने वाला है उनकी तादाद कुल ३७ हैं। उन ३७ आदिमियों को इस बिल के मसविदें के मुताबिक ३ करोड़ रुपया मिलने वाला था। आचार्य जी की स्कीम के मुताबिक़ ५ लाख रुपया की आदमी के हिसाब से एक करोड़ ८५ लाख रुपया मिलना चाहिये। इस तरीक़े से सोशिलस्ट भाइयों की बात न मान कर कांग्रेस सरकार एक करोड़ पन्द्रह लाख रुपया ज्यादा देने जा रही है। यह १ करोड़ १५ लाख रुपये की रकम १८० करोड़ रुपयों का जो कि कुल मुआवजों के बराबर है, एक बहुत छोटा हिस्सा है। आप यह भी गौर करे कि इस बिल में उन लोगों को जो कि ५ हजार रुपये से ज्यादा के मालगुजार है, आठ गुना मुआविजा मिलेगा और आचार्य जी की स्कीम में उनको दस गुना मुआविजा दिया गया है, तो मेरे ख्याल में सोशलिस्ट पार्टी के भाइयो को यह इत्जाम कांग्रेस पर लगाने की गुंजायश नहीं होती कि कांग्रेस पुंजीपतियों की ज्यादा मदद कर रही है बल्कि यह इल्जाम उन पर ख़ुद आयद होता है। आचार्य जी की स्कीम के मुताबिक १७ लाख छोटे-छोटे जमींदारों को जो कुछ मिलना चाहिये, हम उससे ज्यादा उनकों दे रहे है। उनकी स्कीम के मुताबिक ५ हजार से ज्यादा मालगुजारी देने वालों को जो मिलना चाहिये, उससे हम उनको कम दे रहे है । एक तरह से आचार्य जो और सोशलिस्ट पार्टी के लोग बड़े जमींदारों के माफिक है और छोटे जमींदारों और छोटे काइतकारों के खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी का यह मसविदा जो है, उन लोगों की मदद कर रहा है। एक चर्चा और की गयी। आचार्य जी ने तो अपने बयान में यह कहा या कि कम से कम होत्डिंग ६ या ७ एक इका होना चाहिये। लेकिन रोशनजमां खांने साढे बारह एकड़ का कम से कम होत्डिंग बताया। मैं इस बात को मानता हूं कि आपको यह अख्तियार है कि जैसे-जैसे मौक़ा पड़े, वैसे-वैसे अपनी राय बदलते रहें। लेकिन में आपसे यह कहना चाहता हं कि जरा आप हिसाब लगा लीजिये। मुमकिन है कि रोशनजमां लां साहब हिसाब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी न रखते हों। इस प्रान्त में एक करोड़ बाईस लाख किसान है और बीस लाख जमींदार है। इस तरह से एक करोड़ ४२ लाख किसान और जमींदार हुये। अगर रोशन जमां साहब की बात मान ली जाय और हर आदमी को साढ़े बारह एकड जमीन मिले और उनकी यह बात भी मान ली जाय कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी को नहीं मिले तो में यह समझता हूं कि इस बात में कुछ वजन है, ऊपर की भी कुछ लिमिट होनी चाहिये। लेकिन जैसा मैने मुआवजे के मताहिलक अर्ज किया, इसके मुताहिलक भी में आपको यह दिखाऊंगा कि इससे भी कोई बड़ा भारी नफा होने वाला नहीं है। अगर १२ १/२ एकड़ जमीन हर आदमी को मिले तो प्रान्त के अन्दर कुल जमीन १७-१८ करोड़ एकड़ होनी चाहिये। अगर आप आंकड़ों को देखें रहे आपको यह मालूम होगा कि खेती जिस रक़बे में होती है वह कुल ३६७ लाख एकड़ है और जिस जमीन पर काइत नहीं होती है वह २३, २४ लाख एकड़ है और अगर खेती के रक़बे का मीजान किया जाय तो कुल प्रान्त के खातों का रक़बा ४ करोड़ १९ लाख एकड़ है। अगर सारे जंगल और जितनी उपतादा जमीन है वह भी शामिल कर ली जाय तो ६ करोड़ ८० लाख एकड़ जमीन प्रान्त में कुल होती है। तो बाक़ी १०--११ करोड़ एकड़ जमीन आप किस प्रान्त से लाकर देंगे यह में जानने से कासिर हूं।

श्री रोशन जर्मा खो--आप इन्डस्ट्रीज से ले सकते है।

श्रो फूल सिह--इन्डस्ट्रीज के अन्दर सामान पैदा होता है। जमीन पैदा नही हुआ करती हैं। आप तो तमाम दुनिया भर में न्योता देते फिरते हैं कि तुमको भी जमीन मिलेगी। अगर आप साढे बारह एकड़ जमीन हर आदमी को नही देते है, तो दुनिया भर में न्यौते देने का क्या मतलब है ? में आपसे यह कहना चाहता हूं कि अच्छा हो इस मसले पर आप ध्यानपूर्वक गौर हम लोगों ने शेख चिल्ली की कहानी बचपन में सुनी थी। अब वह शेख चिल्ली की कहानी देखने को मिलती है। कितना देश के अन्दर रक्षबा है और उससे कितनी पैदावार हो सकती है, यह सब चीजे आप लोगों को मालूम है। जिन्होने हमेशा कलम चलाई है, जिन्होने खेती के लिये किताबों से इल्म हासिल किया हो। उनको जरा इसके समझने में देर लगेगी और में निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वे लोग इस मामले में दखल देगे तो देश के लिये हितकर नहीं होगा। यह जमीन की बात जैसा कि मैने कहा कि यह ऐसी आसान नही है जैसा कि वह समझते है। मुवावजे की बहुत शिकायत की जाती है कि जमीदारों को इतना मुवावजा रहा है। यह मेरे दोस्त भूले न होंगे कि आचार्य जी ने पड़ती जमीन पर, चरागाह पर, बंजर पर, इन सब पर दो रुपया की एकड़ मुआवजा तजवीज किया था। उनके हिसाब से ४ करोड़ रुपया और बढ़ जाता अगर इसी हिसाब से मुआवजा दिया जाता। मे निहायत अदब से यह कहना चाहता हूं कि यह चीजे कुछ देखभाल करने से ताल्लुक रखती है। अच्छा हो कि हम सब लोग वाकयात को जहन में रखकर स्कीमे बनावे। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जो तजबीज है इस में कोई इसलाह नहीं हो सकती । नहीं, यह काबिल इसलाह है और अगर इसमें खामियां होंगी तो उनका सुधार भी हो सकता है लेकिन उनका कुछ संबंध वाकयात से होना चाहिए महज स्याली बातो से देश का ज्यादा भला नहीं हो सकता है।

एक बात और जो बहुत क़ाबि ले ग़ौर है और में समझता हूं कि उसमें भी कुछ सदाक़त है और वह यह ह कि यह जो क़ानून हमने बनाया है इसमें यह तै किया गया है कि जो भूमिधर बनेगा उसका लगान आधा हो जायगा। में समझता हूं कि एक ही किस्म की जमीन पर किसी का लगान कम हो और किसी का ज्यादा हो यह कोई अच्छी बात नही है और ज्यादा अच्छा तो यही है कि जमीनों का लगान उन जमीनों की क़िस्मों से कुछ ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि लगान को किसी उसूल पर लाने के लिए कुछ समय की जरूरत है। कल मेरे दोस्त रोशन जमां खां साहब फरमा रहे थे कि इस क़ानून में जो यह लिखा हुआ है कि ४० साल तक बन्दोबस्त नहीं होगा यह बेजा बात है और वह जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारी कफियत उस किसान की सी है कि जो अगर खुद घोड़े पर बैठता है तो लोग कहते है कि घोड़ा इसका मालूम नहीं होता और जब वह घोड़े के पीछे-पीछे चलता है तब भी लोग यही कहते है कि घोड़ा उसका मालूम नहीं होता और जब वह घोड़ा कन्घे पर लेकर चलता है तब भी लोग कहते हैं कि घोड़ा इसका मालूम नहीं होता । अगर हम कहते हैं कि जो लगान अब तै हो जायगा वह ४० साल तक घटेगा-बढ़ेगा नहीं तब आप कहते हैं कि बन्दोबस्त जल्द होना चाहिए और अगर हम कहते हैं कि बन्दोबस्त जल्द ही करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि आप के मन में बेईमानी है और आप अब लगान आघा कर देंगे और भूमिधरी का क़ानून ख़त्म होते ही लगान फिर बढ़ा देंगे। आपका यह कहना है कि मौजूदा मालगुजारी ही रहनी चाहिए और लगान को आधा करने से किसान का नुकसान है। आप भाइयों में से कुछ लोगों को यह तो मालूम होगा कि अगर किसी जमीन का लगान एक रुपया है तो उस क़िस्म की जमीन के मौरूसी खाते का लगान १२ आने होगा और मालगुजारी ८ आने। जिस खाते का लगान १२ आने है इस क़ानून के रहते हुए उसे सिर्फ ६ आने ही देना पड़ेगा और अगर मेरे दोस्त की बात मानी जाय तो उस तरह ६ आने के बजाय ८ आना देना चाहिए। मेरें अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर लगान का निस्फ़ न रखकर मौजूदा मालगुजारी की तरह ही सबके लिए रख दिया जाय तो इस से भी सब किसानों का फायदा ने होगा, यह स्याल ग्रलत है। बहुत से किसान ऐसे है कि जिनको लगान का निस्फ़ देने में ही नफ़ा ह और मालगुजारी देने में नुक़सान है। में यह उसूल मानता हूं कि

[श्री फूल सिंह]

दर क़ायदे से ही होनी चाहिए। मालगुजारी वसूल करने से ही कोई भारी नफ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आप के सामने दो-तीन आंकड़े पेश करना चाहता हूं। कुल लगान अठारह सौ सत्तर लाख रुपया है और मालगुजारी ६७८ लाख रुपया है, जो अब सरकार वसुल करती है और १३२ लाख रुपया लोकल रेट (दर) है। १०८ लाख इनकम टैक्स है। इस तरीक़े से जो जमींदार है, वे सरकार को ९१८ लाख क्पया सालाना देते हैं। यह ९१८ लाख कुल लगान का ४८.९ फी सबी है। इस मसविदे की क् से किसान से ५० फ़ीसदी लिया जायगा। जो तजवीज रोशन जमां खां साहब ने पेश की है और जो तजवीज इस बिल में दर्ज है, इन दोनों में १.१ फीसदी का फर्क है। अगर इस फ़र्क को भी बीघा बांटा जाय तो एक पैसा भी बीघा में आता है इसलिये कहने के लिये यह एक बडी तजवीज है। मनासिब उसूलन तजवीज है लेकिन इससे कोई बड़ा अन्तर पड़ने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। आचार्य जी ने जो बयान दिया था, उस समय उन्होंने आधे लगान की बात नहीं की थी। उनका कहना यह था कि लगान बदस्तूर रहेगा महज ४ करोड़ रुपया कम कर दिया जायगा। लगान ज्यों का त्यों बना रहे। यह अच्छी बात है या यह अच्छी बात है कि उसको फौरन आधा कर दिया जाय । फौरन बन्दोबस्त होना चाहिए । यह बात कहने के लिये तो आसान है, लेकिन जिन लोगों को खेती की मालुमात है, वह जानते है कि एक बन्दोबस्त में कम से कम तीन साल लगते हैं। सरकार के पास इतना स्टाक मौजूद है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा तीन जिलों का बन्दोबस्त कर सके। इसलिये फौरन बन्दोबस्त किया जाय, तो प्रान्त भर में बन्दोबस्त करने में ५० साल लग जायेंगे। जो लोग इस बात के कायल हैं कि जिस तरह से क़ानून बन रहा है, खेती के लिये और बन्दोबस्त के क़ानून को लिया जाय, वह यक़ीनन यह चाहते हैं कि जमींदारी प्रथा क्रायम रहे और जो नया क्रानून लिया जा रहा है, वह किसी तरह से टल जाय। यह चीज भी कोई बड़े वजन की चीज नहीं है। इस क्रानुन में जैसा मैने शुरू में अर्ज किया, काफ़ी गुन्जायश है, संशोधन करने के लिये, लेकिन जितने भाषण इस भवन में हुए हैं, उनसे यह मालूम होता है कि आम तौर से सब लोग इससे संतुष्ट है। फिर भी काफ़ी गुन्जायशे है, तरमीम करने की। यह क़ानून म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और छावनी में जो जमीनें हैं, उन पर लागू नहीं हो रहा है। विशिष्ट समिति ने इस दफ़ा में जो खामी थी, एक हद तक उसे दूर कर दिया है। अगर धारा ज्यों की स्यों बनी रहती तो सब गांव वाले यह कहते कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया में यह कानुन लागु नहीं है, इसलिये हमारे हैं । गांवों के जमींदार ये कहते कि हमारे गांव टाउन एरि-याज में शामिल कर लिये जांय। ७ मार्च, १६४९ से मगर पहले यह क्रानून उन जमीनों पर लागू न होगा। पहले म्युनिसिपल में शामिल की जाय। इस दक्षा के रहने से भी उन सब जमीदारों को बहुत नफ़ा है और उन हलकों के काइतकारों का बहुत नुक़सान है। यह भी सब जानते हैं कि २६ जनवरी तक जमींदारी संबंधी जितने क्रानुन देश और प्रान्त की असेम्बली में पेश हो जायेंगे उन क्रानुनों में जो धारायें मुआविजे के मुताहिलक रखी जायंगी उनके मुताहिलक अदालतों में चाराजुई न हो सकेगी। २६ जनवरी के बाद पेश किये हुए क्रानुनों के मुताल्लिक अदालतों में चाराजुई हो सकेगी। में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। कि इन जमीनों के संबंध में जो 'म्युनिसिपलिटो टाउन एरिया नोटीफाइड एरिया और छाउनियों के हदूद के अन्दर है उनके संबंध में क्रान्न २६ जनवरी के पहले इस भवन के सामने आ जाना चाहये। बरना यहां के काइतकारों को नुक़सान पहुंचने का डर है। एक बड़ी चीज जिसकी चर्चा मेंने भू मिधर और जमीदारका फर्क दिखलाते हुये की यह है कि भू मिधर को जमीन किसी काश्तकार को उठाने का हक नहीं होगा। पिछले कानून में भी और यह मसविदा भी जब इस भवन के सामने आये, इन दोनों में बेवा औरतें, नाबालिश बच्चे और और इसी क्रिस्म के लोग इस धारा से बरी रखे गये थे। लेकिन पिछले क्रानुन में भी यह बात थी और जो असली मसिवदा इस कानून का या उसमें भी यह बात थी कि शर्त यह है कि अगर किसी खाते में बेवा औरते भी हों यां नाबालिय बच्चे भी हों और कुछ लोग उस खाते के बालिय हों तो यह धारा उन पर लागू हो जावेगी। यानी वे बेवा औरते और नाबालिंग बच्चे इस क़ानन का नक़ा नहीं उठा सकेंगे। नतीजा यह होता था कि बेवा औरते और नाबालिग्न बच्चे उन लोगों के रहम पर थे जो बालिग्न थे ओर खातो में हिस्मेदार थे। विशिष्ट समिति ने इस घारा का संशोधन करके यह किया कि अगर कोई शख्स डिमेबिल्ड परसन्स की फेहरिस्त मे आता है, यानी बेवा है, नाबालिग़ है या अपाहज है या फौज में नौकर या जेल में नौकर है, तो भले ही खाते का कोई हिस्सेदार बालिग हो, वह अपने हिस्से को शिकमी को उठा सकता है और तकसीम करा सकता है। यह संशोधन करके ऐसे लोगों पर सरकार ने एक बड़ा एहमान किया है। जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि कुछ मौके ऐसे रहने चाहिये जिनमे किसानों को यह गुंजायश हो कि वे जमीन को उठा सकें तो दो बाते इस भवन के सामने आई। उसूलन यह मान लिया जाय कि किसी शहस को यह हक नहीं है कि वह अपनी जमीन को औरो को जोतन के लिये दे लेकिन ऐसे मौके आ सकते हैं जब कोई अपनी जमीन को जीतने के क़ाबिल न रहे तो ऐसी हालत मे उसकी दूसरे से जुतवाने का यदि वे जमीने खाली पड़ी रही तो देश की पैदावार में कमी पड़ेगी और उन लोगों का भी नुकसान होगा जो अपनी जमीनों को जोतने के काबिल नहीं है। इसलिये विशिष्ट समिति ने एक और धारा बना दी है यानी यह कि अगर कोई किसान बीमार हो और बीमारी की वजह से खेती नहीं कर सकता है तो उसे यह हक है कि अपनी जमीन को बीमारी के असे के लिये दूसरे को जोतने के लिये दे दे।

म सरकार का ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। हममे से जो किसान है वे यह बात जानते होगे कि किसान को अपना बैल खुद से ज्यादा प्यारा होता है। अगर उसको अपने को बुलार आ जाय तो ऐसी लास बात नहीं है लेकिन अगर बैल बीमार हो जाय तो यह उसके लिये बहुत बड़ी चीज है। मवेशियों की बीमारी का इलाज बहुत कम होता है। पिछले साल सरकार की और से जब गल्ला इकट्ठा करने की स्कीम चल रही थी, मुझे कुछ जिलो में घूमने का मौका मिला और यह मालूम हुआ कि बैलों में बीमारी थी इस वजह से किसानों का बहुत मा काम रुका पड़ा था। मैने मार्च, अप्रैल, मई और जून इन चार महीनो के आंकड़ेमवे--शियों के इकट्ठे किये हैं जिनसे मालूम होगा कि मार्च सन् १९४९ ई० मे ३,८०० मवेशी बीमार अप्रैल में १८,४००, मई में ७४,५०० और जुन में ४१,६०० मवेशी बीमार थे। इससे अंदाजा होगा कि बहुत सी हालतों में किसान खेती करने से महरूम रह जाता है। इसलिये कि उसके मवेशी बोमार हो जाते थे। मै समझता हूं कि इन हालतों में किसान को गुंजायश मिलनी चाहिये कि वह अपनी जमीन और लोगों से जुतवा सके। इस क़ानून में भूमिधरी और सीरदार को भी जमीन तब्दील करने का हक्र दिया गया है और यह लिखा गया है कि अगर कोई जमीन बदली जायगी तो उस बदली हुई जमीन में भी वही हुक उसको पैदा हो जायेगे जो उसके असली जमीन में उसको थे। इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग खेती करते है वह जानते है कि चकवार खेती करने से नक्ता होता है। यानी अगर कहीं ऊख की पैदावार करना है तो अच्छा हो कि सब लोग एक ही जगह बोये लेकिन दिवकत यह होती है कि सब किसानों के खेत एक जगह पर नहीं होते। इसलिये आम तौर से किसान ऐसी फसलों के लिये खेत बदल लिया करते हैं। लेकिन इस क़ानुन की रू से बदली हुई जमीन में वहीं हुक़ पैदा हो जायेंगे।

श्रो इसरत मुहानी-कलेक्टिव फार्मिंग इसीलिये रखा गया है।

श्री फूलिसिंह—आप लोगों ने कलेक्टिव फामिंग किताबों से मालूम किया है। अपका ख्याल है कि फामिंग किताबों में किया जाता है लेकिन असल में यह जमीन में होता है। इसलिये किताबों का फामिंग जमीन के फामिंग से भिन्न है में आपसे कह रहा था कि इस तरह से जो जमीन में तब्दीली की जाती है उनमें ऐसे हक पैदा नहीं होने चाहिये। यह संशोधन भी इस क़ानून में आना चाहिये। अगर यह आ जायेगा तो इससे किसानों को बहुत नफ़ा पहुंचेगा। काश्त पर जमीन उठाने के संबंध में एक चीज और है और जिस पर लोग एक मत नहीं है वह है सरविस टेन्योर की। उन जमीन के संबंध में जो जोतने के लिये किसी खिदमत के एवज में दी जाती

श्री फूल सिंह]

हे, मसलत किसी गांव का कोई बढ़ई है उसके पास एक भेस हे तो गांव के किसान अक्सर ऐसा कर देते हैं कि एक आध बीघा जमीन उसकी दे देते हैं तािक वह उसको जोतकर अपने जानवर की गुजर कर ले। लेकिन इस मौजूदा क़ानून से अगर कोई शख्स इस मतलब से भी जमीन देगा तो जिसको वह जमीन मिलेगी उसको हक़ पैदा हो जायेगा। इस मामले पर जब चर्चा हुई तो बहुत से दोस्तों की यह राय थी कि ऐसे संशोधन इस बिल में नहीं आने चाहिये क्योंकि इससे गरीब खेतिहर मजदूरों को नुकसान पहुंचेगा और उन पर जबरदस्ती होगी। इन कुछ जिलों में, जब में दौरे पर गया, इस बात की चर्चा की और मेरी इत्तिला यह हैं कि अक्सर गांव में ऐसे आदिमयों की तादाद काफ़ी हैं जो खेती नहीं करते और जिनके पास एक न एक मवेशी जरूर है। बेश्तर लोग गांव में जो खेती नहीं करते दूध के मवेशी गाय या भैस रखते हैं। यह मुमिकन हैं कि उस गांव में खेती करने वालों के पास इतने मवेशी न हों अब अगर यह कानून बन जायेगा तो मेरी राय में ऐसे सब लोगों को, जो खेती नहीं करते हैं मगर मवेशी रखते हैं, उनको मवेशी रखना मुक्किल हो जायेगा क्योंकि यक्कीनन गांव के मजदूर लोग मोल लेकर चारा मवेशियों को नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल में ऐसा होने से गरीब खेतिहर मजदूरों और गांव के उन सभी लोगों को जो खेती नहीं करते, नफा है।

दरहतों के संबंध में भी मुझे एक बात अर्ज करना है। हमारे बुजुर्ग आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने अपने बयान में यह फरमाया था कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसमें जो दरस्त है अगर वह किसी के लगाये हुए है तब तो वह मालिक रहे। अगर किसी के लगाये हुए नहीं है तो जमींदारों को हक्त है कि उन दरस्तों को काट लें। अगर ऐसा क़ानून बनता तो परती जमीनों मे जितने दरस्त होते वह सब खत्म हो जाते । इसलिए सरकार ने उन दरस्तों की कटाई रोकी । मगर उस रोक से अब किसानों को नुक़सान है। मैं यह बात कह सकता हूं कि अगर मंत्री जी अपने जिले के कलेक्टरों से मालम करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस पावन्दी से किसानों को अपने खेती के काम में बड़ी अड़ेचन पड़ रही है। पिछले दिनों में लोगों ने यह कहा कि इन दरस्तों के काटने की इजाजत देने का काम जंगलात के महकमे का है लेकिन जंगलात के महकमा के लोग हर जिले में नहीं होते। उन लोगों के पास दरख्वास्तें जाती है तो आसानी से मंजूर नहीं कई तरीके लोगों को अख्तियार करने पड़ते है। मैं जो बिल संबंधी बात थी उसकी चर्चा करने जा रहा था। जब सन् ३९ में क़ानून लगान बना उस वक्त खेती करने वालों की बात सुन कर यह तै किया गया था कि खेतों के अन्दर के दरख्तों के मालिक काइतकार होंगे और मेड़ पर के दरख्तों के मालिक जमींदार। यह दफ़ा इस क़ानून पर एक बदनुमा घब्बा थी। खेती की मेंड कोई इतनी चौड़ी नहीं होती कि अगर उसके ऊपर दरस्त खड़े रहें तो उससे खेतों को नुक्रसान न पहुंचे । उनकी छाया खेतों पर पड़ती है, उनकी जड़े खेती को खराब करती हैं। अगर ऐसे दरहतों के मालिक दोनों तरफ के काइतकार हों, तब यह कहना कि यह दरहत मेंड़ के जमींदार को इसलिए दे दिये गये ताकि काश्तकारों में झगड़ा न हो बन्दर-बांट का जिन्न करना है।

में समझता हूं कि इसमें यह लिखा हुआ है कि यह सब दरस्त गांव सभा को पहुंच जाएंगे। अच्छा हो कि हम इस बिल में यह संशोधन लाएं कि मेंड़ के दरस्तों का मालिक मेंड़ के दोनों तरफ के भूमिचर या सीरदार हों। इससे दरस्तों की हालत भी किसी हद तक सुधर जायगी।

कल एक बात गांव सभा के संबंध में कही गयी। यह कहा गया कि गांव—सभाएं तो आजाव जमातें हैं। उनको पूरा हक है कि वह अपनी राय का खूब प्रचार करें और यह मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह सरकार की राय से सहमत हों। जहां तक मेरा ख्याल है सरकार ने गांव— सभाओं पर कोई जोर डाला भी नहीं है और गांव—सभाओं को स्वतन्त्र मानती है। लेकिन मेरी जाती राय में यह सरकार की कमजोरी हैं। अगर गांव—सभाओं को या डिस्ट्रक बोडों या म्युनिसिपल बोडों को यह आजावी दी जा सकती है कि सरकार की जो बुनियादी स्कीमें हों उनकी मुखालिफत में वह प्रचार कर सकें और उनके खिलाफ अमल कर सकें तो मेरे ख्याल में इस आजावी के बहुत ग़लत माने लगायें जा रहे हैं। आजादी के माने यह हैं कि आप इस तरीक़े से आजाद है कि आप जो सोसाइटी का दूसरा इंतजाम है उसको दरहम बरहम न करे। आजादी के यह मानी नहीं है कि जो चाहे सड़क पर मकान बना ले, जो चाहे कहीं कृष्णा कर ले, जो जिस स्कीम की मुखालिफत करना चाहे वह करे। अगर इस किस्म की आजादी दी गयी तो उसका भविष्य अच्छा नहीं होगा। यह आजादी जो आज गांव सभाओं के फर्जी हमदर्व पुकार रहे हैं, सही मानों में आजादी नहीं है, पिछले दिनों कुछ रियासतों के बारे में भी यही कहा गया था कि रियासते अब आजाद है, अब हमें हक है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर ले या किसी दूसरे मुल्क से कर ले। मेरे ख्याल में यह बुनियादी सवाल है। किसी नजाकत में आकर या झंझट से बच कर सरकार को इससे पीछे नहीं हटना चाहिये। किसी गांव सभा, डि० बोर्ड, म्यु० बोर्ड या किसी भी आटोनामस बार्डी को यह मजाज नहीं होना चाहिये कि सरकार के बुनियादी उसूलों की मुखालिफत करे। सरकार की बुनियादी स्कीमों के साथ—साथ चल कर वह स्वतन्त्र है। लेकिन स्वतन्त्रता के माने यह नहीं है कि सरकार के उसूलों और क़ानूनों की मुखालिफत करने लगे। में समझता हूं कि सरकार इस बात पर ध्यान देने की कुपा करेगी।

कल एक बात और कही गयी कि मालगुजारी कि अदायगी की जिम्मेदारी मुझ्तरका और मुनफरदन है। मेरे दोस्तों ने संशोधित बिल की धारा २३०, जिम्न २ का अध्ययन नहीं किया । यह सही है कि हर शख्स उसी क़दर मालगुजारी के देने का जिम्मेदार होगा जो उसके हिस्से यह सही है कि सरकार ने अपन पास कुछ हक महफूज रख लिये है लेकिन के मुताल्लिक है। सरकार के पास तो बहुत सारे हकूक महफ़्ज़ है। जैसी कि घारा अब है उस घारा मे यह संभव नहीं है कि किसी और की मालगुजारी की नादेहन्दी मे किसी दूसरे आदमी को नुक़सान पहुंचे। मगर यह खुली बात है कि और जो पाबन्दियां है या जो तरीके मालगुजारी की वसूली के लिये है। मसलन् यह कि अदमअदायगी मालगुजारी में गिरफ्तारी की जा सके या यह कि उस शहस की जमीन अदमअदायगी मालगुजारी में नीलाम की जा सके,यह दोनों धाराये रहनी चाहिये या नहीं। मेरा ख्याल है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और शायद यह सख्त पड़ेगी। मेरी राय है कि इसको निकाल दिया जाय। यह बात मैं इस बिना पर कहता हूं कि जो काश्तकार कल तक काश्तकार थे, सौ रुपये लगान के काश्तकार थे, अगर वह सौ रुपये लगान बिना जेल जाये. बिना अपनी जायदाद नीलाम कराये अदा कर सकता था तो क्या वजह है कि आज हम यह सोचें कि अब जब कि वह सौ का आधा ५० रुपया लगान उसका रह गया है वह नहीं देगा और अब इन हथियारों की ज€रत पड़ेगी मेरे ख्याल में इन मामलों पर हमारी सरकार ध्यान देगी।

गांव सभा की चर्चा करते हुये हमारे दोस्तों ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इन्हें माल-मुजारों की वसूलयाबी का अस्तियार नहीं दिया गया है। मेरे स्याल में यह भी सही नहीं है। धारा २५३ इस मामले में काफ़ी स्पब्ट है। कुछ अख्तियारात जो इन मामले में सरकार ने अपने पास रखे है, मै समझता हूं इस बात को ध्यान मे रखते हुये कि जो तजुर्बा यह सरकार करने जा रही हैं अपने क़िस्म का नया तज़ुर्बा है और उससे बड़े भारी नतायज निकलने का मौक़ा ह, यह लाजिमी हैं कि सरकार उन सब हालतों को भी ध्यान में रखे जब कि कोई गांव सभा इस काम को न कर सके या करने से कासिर हो या करने से इन्कार करे तो ऐसे समय के लिये यह धारा में समझता हूं अपनी जगह पर मुनासिब ही है। लगान के दस गुना जमा करने के संबंध में जो इस भवन से चर्चा थी, हमारे दोस्तों को यह शिकायत थी कि सरकार ने यह भी कह दिया कि जिनका लगान ज्यादा है उनका लगान कम कर दिया जायगा । इस संशोधित बिल मे एक घारा यह है कि अगर किसी शल्स का लगान सर्किल रेट की दोचन्दी से ज्यादा हो तो उसको सरकिल रेट की दोचन्दी में समझता हूं कि यह घारा इस बिल में लाकर सरकार ने से हो दस गुना देना पड़ेगा । किसानों की हमदर्दी की है। अगर यह संशोधन न होता तो इसके माने यह होते कि वह जमींदार जो किसानों का हमदर्द है, वह घाटे में रहता और उन जमींदारों के किसान घाटे मे रहते है और वह जमींदार जो दबा सकता हं, इजाफा कर सकता है उसको फायदा था और उसके किसानों की नुक़सान रहता । इस संबंध में एक संशोधन की गुंजायश है कि जहां सरकार ने यह तय किया है कि किसानों का यह हक़ है कि अपने लगान को सरकिल रेट की दोचन्दी समझकर उसका **बुगना जमा कर दे, ज़र्मोदारों को जो मुआविजा मिलेगा वह** उसको असल लगान के हिसाब से

[श्री फूल सिह]

मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह जमीदार को रियायत है और अच्छा यह है कि जिस कायदे से किसान लगान का दसगुना जमा करे उसी क़ायदे से जमीदार को मुआविजा मिले। सिकंल रेट की द्विचन्दी वाली जो बात है यह भी कुछ मुनासिब नहीं मालूम होती। अच्छा तो यह है कि यह क़ायदा बन जाय कि सिकंल रेट का दसगुना जमा करे और सिकंल रेट ही आइन्दा मालगुजारी हो जाय, बजाय इसके कि किसी की सिकंल रेट की द्विचन्दी मालगुजारी है, किसी की सिकंल रेट से ज्यादा है और किसी की सिकंल रेट की द्विचन्दी मालगुजारी है, किसी की सिकंल रेट से ज्यादा है और किसी की सिकंल रेट से कम है। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि इसको भी सोचे कि क्या यह संभव है या नहीं कि बजाय इसके कि आइन्दा कि मालगुजारी लगान क। आधा हो, यह इस कानून में हो जाय कि आइन्दा की मालगुजारी सिकंल रेट होगी। अगर इस तरीके से यह कानून बन जाता है तो जनता को बहुत नफा होगा।

कुछ भाइयो की यह भी जिकायत है कि पहले ३१ दिसम्बर की तारीख़ रखी गई थी, अब उसे बढ़ाकर २८ फरवरी कर दिया है। मुझे ताज्जुब हुआ जब यह शिकायत उन लोगो की तरफ से आई जो किसानों के नुमाइन्दे बनने का दावा करते हैं, जो किसानों के हमदर्द होने का दावा करते है। अगर कीई रियायत सरकार ने किसानो को दी है तो उनको तो सरकार का शक्तिया अदा करना चाहिये न कि उस रियायत की बिना पर सरकार की आलोचना करनी चाहिये। वाक्या यह है कि ३१ दिसम्बर तक किसान को इतना मौका नहीं था जो अपनी फसल वर्गर बेचकर उस समय के अन्दर दस-गुना रुपया जमा कर सकते। सरकार ने बहुत नफा तो किसानो को नही दिया यानी यह कि ३१ दिसम्बर से पहले जो लोग अपने लगान का दस-गुना जमा कर देते उन्हे तो पिछली खरीफ का लगान आधा देना पड़ता। अब ३१ दिसम्बर के बाद २८ फरवरी तक जो लगान का दस-गुना जमा कर देंगे उनकी पिछली खरीफ का ३/४ हो जायगा, १/४ माफ हो थोडा नफा किसानों की इससे है। मै समझता हू कि यह जो काम सरकार ने किया उसके लिये हम किसानो की तरफ से सरकार के आभारी हो। यह भी शिकायत है कि जो भूमिघर बनने जा रहे है उनको गन्ना देने के लिये पर्चियों में रियायत की जा रही है। रौशन जमां खां साहब या उनके साथी यदि खेती करते होते तो उनको यह मालूम होता कि यह जो गन्ने के काटे पर जाने का क्रायदा है उनकी पींचयों की वितरण करने का काम सरकार का काम नहीं है बल्कि यह काम किसानों की अपनी को-आपरेटिव सोसाइटी किया करती है। को-आपरेटिव सोसाइटीज का यह हमेशा क्रायदा रहा है कि अगर किसी को जरूरत है तो उसकी रियायत की जाती है। अगर किसी किसान के यहा शादी है या उसको और कोई खर्चा करना है तो बाकी किसान इस बात पर रजामंद हो जाते है, बाकी किसान उसको मौक़ा देते हैं कि वह गन्ना बेचकर अपना काम कर ले। इस उसूल पर को-आपरेटिय सोसाइटीज ने अपने किसान भाइयों को जो भूमिधर बनने का इरादा रखते थे, यह मौक़ा दिया। इसके लिये वह को-आप-रेटिव सोसाइटिया और बाराबंकी की को-आपरेटिव सोसाइटी जिसका जिक्र रोशन जमां खां करते थे, धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ यह हमदर्दी की।

इस क़ान्न का जिक्र करते वख्त उन २८ हजार पटवारियों की, जो मुहक़ मे माल की संगे बुनियाद है, कोई चर्चा न की जाय तो बात आधी ही रह जायगी। में जानता हूं कि पटवारी गांव का वह तबक़ा है जो बहुत ही बदनाम है और उतना बदनाम है जितना शायद वह निकम्मा नहीं है। मुझे पटवारी वर्ग के साथ पिछले एक साल से काम करने का मौक़ा मिला है और में यह कह सकता हूं कि इस पिछले एक साल में पटवारी वर्ग में जो सुधार हुआ है अगर आप उसे वेखें तो प्रसन्न होंगे। में आपको बता सकता हूं कि पटवारी संस्था इस बात पर जोर देती है कि अगर कोई पटवारी ठीक तरह से काम नहीं करता है तो सरकार के सजा देने के अतिरिक्त पटवारी संस्था भी अलहदा से उसे सजा देने का इरादा रखती है। आपको यह जान कर खुशी होगी और इस बात का अहसास आज जिले-जिले के कलेक्टर, कमिश्नर और कांग्रेसी कार्यकर्ता है। में तो यह चाहता हूं और यह मुमकिन भी है कि यह २८ हजार पटवारी, यह २८ हजार पटवारी, यह २८ हजार पटवारी, यह २८ हजार पटेंगरी, यह विश्वर एके-लिखे आदमी इस देश के एक मुफ़ीद अंग बन जायें और उमकी मुनासिब सेवा कर

सकें। मैं यह इक़बाल करता हूं कि अभी तक पटवारी इसके मुस्तहक़ नहीं हुये हैं लेकिन आपको यह याद रखना चाहिये कि जब यह बिल बने तो यह २८ हजार आदमी जो सरकार का हर काम करते है, जिनकी तनख्वाह अनपढ़ आदिमियों से भी कम है, जो बाल-बच्चेदार आदमी है, उनके लिये इस बिल को बनाते वनत सरकार इस बात का अवध्य ध्यान रखेगी कि यह २८ हजार आदमी जमींदारी उन्मूलन में सरकार का साथ देकर अपनी मौत को नजदीक़ ला रहे हैं और वे इस बात के लिये तैयार है कि सरकार और देश को नक्षा हो और उनके लिये चाहे जो कुछ हो । में समझता हूं कि सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह इन लोगों का ध्यान रक्खे और कोई ऐसा तरीका सोचिये जिससे २८ हजार पटवारी सही तरीक़े से कहीं खपाये जा सकें और जो सेवा करने के वह योग्य है उनसे वह सेवा ली जाय।

एक स्दर्य -- उन्मूलन कर दिये जायं तो अच्छे रहेंगे?

श्री फूल सिंह--यक्नीनन उनका उन्मूलन तो हो ही रहा है और शायद उधर के लोगों का भी उन्मूलन हो रहा है लेकिन मैं यह समझ रहा था कि उस तरफ की बेंचेज के बैठने वाले लोग जो अपने उन्मूलन से घबड़ाते हैं उनको बाक़ी और लोगों के उन्मूलन से डर नहीं होगा। बात ऐसी हो हुई कि हमारे दोस्तों के नाखुन जो थे वह कम हो गये है वर्ना अभी तक वह खून निकाल लेते ।

तो मैंने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि वह किसी जमात का उन्मूलन नहीं करना चाहती है, न सोशलिस्ट पार्टी का, न मुस्लिम लीग का बिल्क वह जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना चाहती है निक जमींदारों का। इसी तरह सरकार की यह मंशा नहीं है कि वह पटवारियों का उन्मूलन कर दे बल्कि वह पटवारी जो सरकार की सबसे ज्यादा सेवा इस वक्त कर रहे हैं उनका वह ध्यान रक्लेगी और उनसे मुनासिब काम लेगी। मैं यह चन्द बातें इस बिल के संबंध में इस भवन के सामने कहना चाहता था।

श्रो वारेन्द्र शाह—माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में भी जो भवन के सामने बिल उपस्थित है उसके विरोध में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस बिल की सिलेक्ट कमेटी का में भी एक मेम्बर था और मैं इस उद्देश्य से उसमें गया था कि शायद वहां जाकर काश्तकारों और आम जनता की भलाई के लिये और जमींदारों को अन्याय से बचाने के लिये अपनी राय सरकार के सामने रख सक्। मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि हम लोगों ने जो कुछ संशोधन वहां रखना चाहे सरकार ने अपनी जिद के सामने एक को भी नहीं सुना। यह बात आपको इससे साबित होगी कि इतने अहम बिल की सिलेक्ट कमेटी कुल चार सिटिंग में बीस दिन के अन्दर खत्म होगई। इसमें ऐसे बिल के ऊपर भी विचार करना था जिनके बनाने में १२ महीने सिलेक्ट कमेटी की लगे थे जैसे यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट। में आप से यह कहना चाहता हूं कि कब्ल इसके कि इसकी धाराओं के ऊपर अपने विचार प्रगट करूं। मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इनके ऊपर कोई विचार नहीं किया न सिलेक्ट कमेटी ने कुछ किया और न आज हो यहां पर कुछ कर रही है। आज भी हम यह देखते हैं कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। इस बिल से २३ लाख जमींदारों के घर परिवार और आश्रित, सब मिला कर एक करोड़ जनता पर असर पड़ता है। उसको आप किस तरह से खपाने जा रहे हैं। उनकी रोटी के लिये और उनका जीवन आगे रहने के लिये आप कौन सी चीज करने जा रहे हैं? ऐसी कोई चीज आपने हमारे सामने नहीं रखी है। में आप से यह अर्ज करूं कि अगर आप यह चाहते हों कि एक करोड़ आदिमयों को बरबाद करके प्रान्त में सुख शान्ति बनी रहे और प्रान्त तरक्की करे तो यह आप की भूल है। आप कदापि ऐसा नहीं कर पायेंगे। एक करोड़ आदिमियों को बरबाद करके आप फिर चाहें कि प्रान्त की तरक्की हो, यह नामुमिकन बात है। अब मैं यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और कांग्रेस ने जो बारबार

[श्री वीरेन्द्र शाह]

अपने इलेक्शन सम्बन्धी मैनिफेस्टो का उदाहरण दिया है कि पहले वैसा हम तय कर आय हैं और उसी वजह से यह करने जा रहे हैं तो में यह कहना चाहता हूं कि उस मैनिफेस्टो में तो आप ने मध्यवर्ती, यानी बीच वाली जो जमात हैं उसकी खत्म करने के लिये कहा और उसको खत्म करके काश्तकारों को जमींदार बनाने के लिये कहा है। आज हर एक काश्तकार यही समझता है कि जमींदारी खत्म होने के बाद जमींदार हो जांयगे। आप कहन के लिये चाहे जो भी कह लें लेकिन वे जानते हैं कि जमींदारों के बाद जमींदार हम बनेगे। और यही कांग्रेस ने वादा भी किया है। लेकिन इम बिल के जरिये से हम देखते हैं कि हमारे समाजवादी लोग जैसा चाहते थे कि हर एक चीज स्टेट की हो, उसको स्वयं हमारी सरकार ने खुद श्री गणेश कर दिया है और इस बिल से जमीदार आज खुद सरकार बना रही है। आपने वादा किया था कि किसानों को जमींदार बनायेंगे। अगर इसमें किसी को सन्देह हो तो में चैलेज करता ह कि कोई भी जाकर किसानों से पूछ कर देख ले कि कि वह क्या कहता है। किसी किसान से पूछने पर वह यही कहेगा कि हमको जमीन्दार बनाने के लिये यह जमीदारी खत्म की गयी है या खत्म को जारही है। पर आज आप कदापि ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप उनको भूमिवर या नाना प्रकार के नाम देते हैं, लेकिन उन जमींदारों का जरा सा अंश भी बेचारे किसानों की नहीं मिलने वाला है। उल्टे आप उनसे टैक्स लेकर उनको भूमिधरी देते है। आप कोई बड़ा भारी अहसान की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बातों को सरकार ने सेलेक्ट कमेटी में नहीं सुना। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप भाइयों को अपनी बातें सुना वूं। क्यों कि मैं समझता हूं कि सरकार ने वैसे नहीं सुना तो आप के जरिये सरकार पर कुछ असर होजायगा और वह आप की बात सुरेगी। हा, तो मैं यह अर्ज हर रहा था कि आज २३ लांख जमींदारी को खत्म करके हुनारी सरकार बहादुर किसानों को भी बरबाद करने जा रही है। में आप को यह बतलाना चाहता हूं कि इससे वास्तव में किसानों का कितना चड़ा लाभ और हानि हो रही है। किसानों का लगान तो आधा होने का नहीं जब तक कि वे भूमि घर नहीं बनते। और तब तक उनके लगान में कोई कमी भी नही हो रही है। इस बिल में कोई घारा ऐसी नहीं हैं जिससे हम यह जान सकें कि लगान में कमी ही रहो है। एक उम्मीद यह थी कि जमीन्वारों से जो जमीन मिलेगी वह किसानों को मिलेगी लेकिन वह भी नहीं होने जारहा है। जिनके पास जमीन है वे खुद जोन रहे हैं या और जो जमीन है वे सब सरकारी फार्मों में चली जायंगी। कोई जमीन खाली नहीं है जो किसानों को दी जायगी। तीसरा जो हक शिकमी का काश्तकारों को था जिससे किसी मजबूरी की हालत में वे शिकमी पर अपनी जमीन उठा सकते ये वह हक भी आप आज उनसे ले रहे है। चौथी बात यह है कि जो अपनी जमीन का बटवारा १ बीघे से लेकर २० बीघे तक कर सकते थे वह बटवारा अब नहीं कर सकेंगे। उनके खान्दान का बटवारा करने का हक आपने इसमें रोक दिया है। इस हक्त को भी आपने उनसे ले जिया है और अब वह अपनी जमीन का बटवारा नहीं कर सन ते हैं। (एक आवाज घर में कर सकते हैं) खेत-को नहीं बांट सकते हैं। भविष्य में आपने जो वसूली का तरीका रखा है उसकी जिम्मेवारी अभी तक तो व्यक्तिगत थी लेकिन अब आप ने उसको सामृहिक कर विया है सामूहिक जिम्मेदारी से वसूल की जायगी। अभी हमारे माननीय बोस्त फूल सिंह साहुव बतला रहे थे कि जब तक कलेक्टर लिखेगा नहीं वह इसकी इस्तेमाल नहीं कर सकेंग। आप यह जानते हैं कि कलेक्टर ऐसा लिखेगा नहीं कि वह ऐसा हुक्म वे वेगा। लिहाजा किसानों पर एक आफत मौजूद है। इससे किसानों का कोई फायदा नहीं होगा। तरफ यह है कि जमींदारों को आप यह कह कर मुआवजा दे रहे हैं कि उनको खत्म किया

जा रहा है। काश्तकारों को जमींदार बनाने के लिये आपने उनको भूमियर बनाया है अब उस भूमियर के बनाने में जो १०—गुना लगान उनसे मांगा है, तो इससे यह साबित है कि आप यह समझतेथे कि जमींदार इतने खराब है, जमींदारी के अन्दर इतने ऐब आगये हैं कि काश्तकार फोरन इस बात को सुनते ही आपको लगान दे देगा। उम रुपये से आप अपना भी काम चलायेंगे और उसमें से कुछ जमीन्दार को भी दे देगे लेकिन अब तीन महीन के तजुर्बे से आपको मालूम होगया होगा कि यह किस तरह से वसूल हो रहा है। इस भवन में और सदस्यों ने भी बताया और हम भी आगे चलकर यह बतायेंगे कि आप ने वसूल प्रावी के लिये कौन—कौन से हथकन्छे और तरीके अख्तियार किये हैं जो कि एक प्रजातंत्रात्मक सरकार को शोभा नहीं देते हैं।

अब मैं प्रीऐम्बिल के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। उसमें आपने कहा है कि जो मध्यवर्ती लोग है, उनको हटा दिया जायगा और उनको हटाने के लिये ही आपका यह बिल था। अब इस सिलेक्ट कमेटी में जमींदारी प्रथाको भी आपने शामिल कर दिया इसका मतलब यह है ओर हमने कमेटी में इस सवाल को उठाया भी था कि जहां जमीदार का सीधा सबंघ हो जैसे सायर, हाट, बाजार जो मध्यवर्ती के नियम के अन्दर आते नहीं है, तो इन चीजों की जमींदार के लिये छोड दिया जाय। सरकार जमीदार से ऐसी चोजों में अपना सबंब रखे। जहां तक लगान का सबंध है, असामी और जमींदार का संबंध है उसको सरकार ले ले। और उन चीजों को छोड़ दें, जिससे कि जमीदारों को मीबी आमदनी होती है और जो इस तरह से आमदनी होती है, वह उनकी बनी रहे, लेकिन इन चीजों का भी अन्त करने के लिये सरकार ने जमीदारी प्रथा को भी उसमे जोड़ दिया है। फिर सरकार का यह कहना कि हम जमिश्वारों से दुवमनी नहीं रखते है और जमींदारों से यह कहा जाय कि उनको बरबाद नहीं किया जाता है तो इस गरह से इस आमदनी की लेने का क्या मतलब है ? हम जानना चाहते है कि सायर की आमदनी, बाजार, हाउ और बागात की जो आमदनी होती है, उसका मध्यवर्ती से क्या संबंध है। उसका काश्तकार और जमें दार से क्या ताल्लुक है, आप क्यों उसको लेना चाहते है। इस पर सरकार को घ्यान देना चाहिय कि जब सरकार यह कहती है कि हम जमें दारों को खतम नहीं करना चाहते, तो फिर सरकार क्यों इस तरह की रीति को बरतती है। हमने कमेटी में भी यह कहा कि हम आपके साथ है, जिससे मुल्क का फायदा है, हम साथ देने के लिये तैयार है। किन्तु यदि आप हमको रखना चाहते है तो इस बिल मे ऐसी चीजे छोड़ सकते है, जिससे हम भी जिन्दा रहें । आप मध्यवर्ती को मिटाना चाहते हैं तो मिटा दीजिये। आप चाहते हैं कि सरकार और काश्तकारों के बीच में कोई न रहें तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारी सायर की आमदनी है, बागात है, जंगल है, कुएें है बाजार है, हाट है जिनसे हमारा सीघा संबंध है। अगर उनको छोड़ दिया जाय तो जमीदारों के पास बहुत चीजें रह सकती है और उनके पास उन चीजों को तरक्क़ी देने और डेवेलप करने का काम भी रह सकता है। कहती है कि इस तरह से परती जमीन पर ज्यादा अन्न पैदा होगा, लेकिन में आप से कहता हूं कि इस जमींदारी ऐबालिशन बिल से अन्न की पैदावार बढ़ेगी नहीं बल्कि और घट जावेगी। क्योंकि जो जमींदार रुपया वर्गरह लगाकर और देकर परती को अच्छा बनाने को जुर्रत रखते है और खेती को बढ़ाने की आज्ञा रखते हैं वह इस बिल को देखकर हताज हो गए और वह अब सोचते हैं कि अब हमाराजमीनों में क्या इन्टरेस्ट है और जमींदारों के अलावा काश्तकार भी सोचते हैं कि आगे चलकर सोशलिस्ट तरीक़े से भी जमीनें हमारे कब्जे में नहीं रहेंगी, लिहाजा इस तरह से हम खेती में कोई ज्यादा तरक्की नहीं करेंगे। सरकार अपनी तरक्की चाहे जैसे करे। चाहे फार्म बनावें या ट्रैक्टर चलवाए, लेकिन गांवों में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो अब अन्न-उत्पादन की ओर घ्यान दे सके । हमारा कहना यह है कि सायर की आमदनी जहां मध्यवर्ती का सवाल नहीं पैदा होता है, उस चीज को तो सरकार को जमींदारों के लिए छोड़ना ही चाहिए और अगर आप यह चीज छोड़ देते है, तो बहुत सी बातें आप ही हल हो जाती है।

श्री वीरेन्द्र शाही

अब बिल में कुछ मुख्य धाराये ऐसी ह कि जिनके बारे में में कहना चाहता हू। एक घारा ३९ हैं। यह जवाइन्ट हिन्दू फैमिली के बारे में है। इसमें यह हैं कि बाप-बेटे में बटवारा नहीं हो सकता जिसका भी हिस्सा हो उमको जरूर मान लेना चाहिए। ऐसा ओर बिलो में भी हैं ओर बिहार में माना गया हैं। उसको में आप लोगों को अभी पढकर सुनाए देता ह, यह इस प्रकार हैं और बिहार जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की २० वी धारा में लिखा हुआ है कि .--

"In preparing such compensation assessment roll, every proprietor or tenure-holder or a number of a joint Hindu family having or entitled to a share in the estate or tenure, as if there were a partition on the day fixed for the purposes of assessment and payment of compensation, shall be treated separately."

(ऐसी प्रतिकर निर्धारण सूनी तेपार करते समय प्रत्येक स्यामी या खातेदार या हिन्दू सयुक्त कुटुम्ब के किसी सदस्यको, जिसका किसी आस्थान या पट्टे में भाग हो या वह उसका अधिकार। हो, अलग २ समझा जायगा जेसा कि प्रतिकर निर्धारण ओर दे न के उद्देश्य के लिये नियत दिन को विभाजन हुआ हो)। लेकिन आपने यहा पर कोई इस तरह की चीज नहीं रक्षी है। आपने सिर्फ भाइयों के लिए हो रखा है और लड़कों के लिए पहीं नहीं रखा है। मैन यह बात सेलेक्ट कमेटो के सामने भी रक्खी थो। जब बाप जिन्दा है तो वह हिस्सेदार हं और अपना हिस्सा पाता है, लेकिन आप बाप के जिन्दा रहने पर बटवारे का हक उस को नहीं दे रहे है। यह मुनासिब नहीं है। यह चीज भी आपको ठीक करना चाहिए।

तोसरी चोज यह है कि आप क्लाज १२ में जमीवार को जमीन उसके रहने का मकान और कोर्ट यार्ड ओर सामने की जमीन के बारे में कुछ ते नहीं करते हुँ और आप कहते हैं कि बाद में यह चोज सरकार ते कर देगी। आप देखेंगे कि बिहार एक्ट की घारा ५ में भी उन्होंने रखा है और होम स्टेट्स के नाम से यह रखा गया है। लेकिन आप की घारा १२ में यह है कि सूबे की सरकार इसे बाद में ते करेगी और जो इलाको पर मकान और कोर्ट यार्ड वगैरह है उनका सगड़ा इस वक्त बीच में ही छोउ विया जायगा। में सरकार से अर्ज करूगा कि बिहार में उन्होंने ऐसा रखा है कि वह सब ऐसी चोजे फीरेन्ट पर उन मालिकों को दे दो जावेंगी। में आपसे कहुगा कि आप भो बिहार की तरह ते कर दीजिय तो इसस हमारा काफ़ी फ़ायदा है जिससे बाद में सरकार को ते करने में विक्कत भी नही।

अब दूसरी चीज कम्पेंसेशन के बारे में है। आप कहते है कि हम इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन दे रहे हैं। में आप से कहता हूं कि आप का इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन तो इसी से जाहिर होता है कि जो कम्पन्सेशन आप दे रहे हैं उससे कहीं उपादा उस रुपए की तादाद है कि जिसको आप किर से बसाने की ग्रान्ट या रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट कहते हैं। आपने इसमें जरा—जरा सी छोटी—छोटी बातों पर ध्यान देकर रुपया बचाने की कोशिश की है। में आपसे आर्ज करूंगा कि आपने ऐसी कई धारायें रखी है और उनमें आप ने रखा है कि इस बिल के पास होने के बाद अगर कोई बटवारा या हिस्सा जमींदार ने बांटा तो गवर्नमेंट कुल पर ही कम्पेन्सेशन का हिसाब लगावेगी। आपने शायव यह चीज सन् १९४६ से ही लाग कर दी है। में सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह से तो सरकार ने जो बिल के आने पर टैक्स लगाया है वह भी नाजायज है और यह भी सरकार की नाजायज चीज है और उसके भी कोई मानी नहीं है। आप इस तरह की चीज करते हैं और आ। किसी की नहीं सुनते हैं। आपने जमींदारी बिल के पास होने के पहले अबवाब एक दम ने दस फीसदी से सवा १८ फीसदी कर दिया।

६ महीने के बाद ऐप्रीकत्चरल टैक्स लगा दिया। दूसरी चीज यह है कि १५ टाइम्स आप टैक्स लेते ह । अब मुआविज का सवाल है इस कानून के पेश हो जाने के बाद ३ टैक्स सरकार ने जमीदारो पर लगाए। जमीदारो की आमदनी का ८० फीसदी सरकार इन करो के द्वारा ले लेती है। हमसे सरकार मालगुजारी, अबवाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स वगैरह ले रही है। ८० फी सदी का १/५ हिस्सा दे रही है अगर उमकी नेट इनकम एक हजार हे तो दो सौ दे रही है। आप रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि दरअस्ल जमीदारो को कितना मुआविजा मिलता हं यह कहूँगा कि हमे कुछ भी न दिया जाय और सरकार हमारी जमीदारी को जब्त कर ले। सरकार हमे रुपयो की जायदाद का मुआविजा कौड़ियो मे दे रही है। अगर किसानों का फायदा है तो मे यह कहना चाहता हूँ कि मै ट्यक्तिगत तरीके से मालगुजारी नहीं देता हूँ सिर्फ ४ हजार रुपया देता हूँ। म कहता हूँ कि यह ४ हजार लगान में कम कर दिया जाय तो मुझे एक पैसा मुआविजा न दिया जाय। यह मे नहीं मान सकता कि सरकार मुझको तो कम दे और खुद ज्यादा वसूल करे, भूमिधर से आप दस—गुना लेते हैं तो हमे २० गुना देना चाहिये जो बाजार का भाव है। यह २० गुना रेट हुआ जो आपको जमोदारों को देना चाहिये। तभी यह इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन (जायज मुआविजा) हो सकता है।

श्री फतेह सिंह रागा — कहां से दे?

श्री वीरेन्द्र शाह—यह आप जानें। इस बिल में बहुत सी किमयां है। जब दूसरी रीडिंग आवेंगी उस समय हम उनका और जिक करेंगे। लेकिन फिर भी दो—चार चीज अब बतला देना चाहत हूं जैसे हिन्दू रिलीजस ट्रस्ट। आपने देखा कि वक्फ के बारे में आवाज उठाई गई। हिन्दू रिलीजस ट्रस्ट की मंदिरों में जायदादें लगी हुई है। आज तो सरकार इस बात को मानती है कि हम उसको पूरा खर्चा देगे। दुनिया के हाल को देखते हुये और जो रवया मुलक का इस समय चल रहा है उसको देखते हुये में तो भय खाता हूं, आगे चल करके इसमें ऐसा होगा कि इसके खर्च में कमी की जावेगी। इस बिल की घाराये ऐसी रखी गई है कि आपका कम्पेन्सेशन आफिसर उस खर्चें को काट सकता है। तो हमारे मंदिरों में जो खर्चे होते हैं उसमें सरकार कमी कर सकती है। इस तरह से तो सरकार एक हाथ से देगी और दूसरे से ले लेगी। इसलिये में चाहता हूं कि मन्दिरों में जो जमीदारियां लगी हुई है उनको इससे एग्जेम्प्ट किया जाय। यह समस्या इतनी जटिल है कि इसको आप अलहदा दूसरे बिल के जिये लावे। अलहदा दूसरे बिल में आप इसको कंट्रोल करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार ने पहाड़ी तीन जिलों को छोड़ दिया है और स्टेट्स जो अब मर्ज्ड होकर आई है उनको भी छोड़ दिया है।

श्री केशव गुप्त—वे तो शामिल है।

श्री वीरेन्द्र शाह—तो कम से कम तीन पहाड़ी जिलों को तो जरूर छोड़ा है और वहां पर कोई ऐसी जिटल समस्या जरूर होगी। कोई वजह ऐसी जरूर होगी जिससे आप उनको नहीं ले रहे है। में कहता हूँ कि हिन्दू रिलीजस ट्रस्ट भी ऐसी ही समस्या है, इसको भी आप छोड़ दें। इसमें लाने से में यह समझता हूँ कि हमारे धर्म में आक्षेप होगा। हिन्दू धर्म में यह लिखा है कि कोई मिन्दर जब कायम किया जाता है तब कोई स्थायी सम्पत्ति उसके लिये लगा दी जाय। तो जमींदारी एक ऐसी स्थायी सम्पत्ति मानी गई है और आप उसको ले रहे है, यह ठीक नहीं है। अगर कल कोई कंम्यूनिस्ट या सोझलिस्ट सरकार हुई तो उसके लिये मिस्जद या मोन्दर कोई मतलब नहीं है। वह समझेगे कि हमारे पास हक़ आ गया है कि इनको भी हड़प करो। आगे चलकर के धर्म के मामले में मुमिकन है कि कुछ और नुकसान पहुँच जावे।

श्री रोद्यान जमां खां--हम ऐसा नहीं करेंगे।

श्री विरम्द्र शाह—कोई भी आये, हमको सबसे भय है। में चाहूँगा कि इस पर सरकार जरूर ग़ौर करे। पन्त जी जब फैजाबाद गये थे तो यह कहा था कि तुम्हारे मिन्दरों में कोई कमी नहीं होगी और पूजा में कोई कमी नहीं होगी। तो जब आप खर्चा दे रहे हैं तो उसको ए जेम्प्ट क्यों नहीं कर देते ? में तो चाहता हूँ कि एक अलहदा बिल से इसको किया जाय। इसमें झगड़ा पड़ने का डर है क्यों ? न जाने आगे गवर्नमेट कौन आये जो मित्दर की जायदादों को नष्ट कर दे। में मानता हूँ कि हमारे महंत लोग उसको बरबाद करते हैं और यह भी मानता हूँ कि कुछ फीसदी खराब भी जाती है। आप इटली में देखिये कि पोपकी कितनी बड़ी स्टेट हैं।

एक सद्स्य--हस में।

श्रा वं रिन्द्र शाह—हां, वहां नहीं है, लेकिन एक दिन आयेगा जब वहां भी धर्म पहुँचेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार उन चीजों को न ले जिनसे मामला जिटल पड़ जाये। में समझता हूँ कि अगर आप उनको छोड़ देंगे तो वह कही भाग नहीं जायेग। जायदाद उनके हाथ में रहेगी। आप उसको कोर्ट आफ वार्ड्स भले ही कर ले, लेकिन इस बिल के साथ नही जानी, चाहिये और अगर इस बिल के साथ जायेगी तो वह खतरे में पड़ जायेगी।

अब में सरकार से अर्ज करूगा कि दस गुना लगान वसूल करने के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा गया है। में भी कहना चाहता हूँ। कहा यह जाता है कि दस गुना लगान वसूल कर रहे हैं। में यह कहूँगा कि अगर साफ—साफ जमीं वारों से मतलब होता तो जमीं वारों का इस्मीनान क्यों न किया जाता। जबिक जमीं वार लाखों रुपये का लगान वसूल करता है और सरकार में रेवेन्यू जमा करता है तो फिर क्या बजह थी कि उसे बेईमान समझा गया और उसकी जमाक रने के लिये नये तरी के कायम किये गये। इसके क्या माने हैं। जमीं वार आज यह देखता है कि जिसके नाम पर आप रुपया ले रहे हैं वह सब धोखा है। आप जो जमीं वार को दे रहें हैं वह न देने के बराबर है। पता नहीं कि आप इस रुपये को किस चीज में लगायें और इसका भी पता नहीं कि आप खुद चले जायं या वापस कर दे जैसा कि सन् १९४२ में हुआ था। उसी की तरह यह भी वसूल हो रहा हो। में एक अखबार की बात आपको पढ़े देता हूँ। अगर हम कोई बात कहेंगे तो कहा जायेगा कि वह जमीं वार जला हुआ है, क्यों कि जमीं वारों की जमीं वारी जा रही है। लिहाजा यह जलत कह सकता है। इसलिये में तो आपके मेम्बर की बात कहेंगा जो आपके मेम्बर ने बयान दिया है उससे आपको सबक़ सी खना चाहिये। इस अखबार का नाम स्वतंत्र भारत है।

दस गुना लगान जमा करने में पुरानी नौकरशाही का तरीक़ा ही बर्ता जो रहा है। लाला अज मोहन लाल शास्त्री एम० एल० ए० ने बरेली में दस गुने लगान को चर्चा करते हुये एक बक्तव्य में कहा है कि दस गुना लगान जमा करने में बरेली में अधिकारियों की ओर से वही पुराने नौकरशाही तरीक़ों का प्रयोग किया गया है जो तरीक़ा (युद्ध-कोष) वार फंड वसूल करने में प्रयोग किये जाते थे। हमारे पास काफी शिकायतें इस बात की आई है कि जिन लोगों के पास बन्दूकों के लाइसेंस है उनको काफी परेशान किया गया। उनसे साफ-साफ कहा गया कि या तो दस गुना लगान जमा कराओ नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस पुनः जारी नहीं किया जायगा। इस प्रकार की शिकायतें हर जगह से हमारे पास आई है। आपने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है कि श्री खेरा साहब अभी हाल ही में बरेली आये थे और सिक्ट हाउस में अधिकारियों और ग्रेर-सरकारियों की सभा हुई थी। इस सभा में श्री खेरा साहब ने जोर दिया था कि खंडसारियों से भी १० गुना लगान जमा करने में सहायता ली जाय। अगर कोई खंडसारी सहायता नहीं दे तो उसका लाइसेंस जबत कर लिया जाय। जब अंचे-अंचे अधिकारियों की जोहिनयत यह है तो मामूली

अधिकारी तो एक दम आगे ही चलेगे। क्या यह वही पुराने हथखंडे नही ह जिनका कांग्रेस ने बराबर विरोध किया है? क्या यह वह तरीक़े नहीं थे जिनके जरिये वार फंड आदि जनता से वसूल किया जाता था? अपने वक्त में आपने कहा कि बरेली जिले में केवल २ प्रतिश्वत रुपया वसूल हुआ है। इसकी जिम्मेदारी इन तरीक़ों पर ही है। यह एक एम० एल० ए० साहब का बयान है जो आपकी पार्टी में है और अभी निकाले नहीं गये हैं। आइंदा निकाले जाएं या न निकाले जाएं। (एक सदस्य—इस पर उनके दस्तखत हैं?) यह तो अखबार वाले जाने।

इसके अलावा जितनी दरख्वास्तें मेरे पास आई है। इनमे कहा गया है कि दस गुना लगान नहीं देना चाहते, क्योंकि हमारे पास एपया नहीं है, आप कोई जिरया बतलावे जिससे हम बच सकें। लोग हमें परेशान करते है। गल्ला वसूली की बात कही जाती है। गल्ला है नहीं, फसल खड़ी हुई है। कोई वजह है कि सरकार उनसे गल्ला मांगे। उनको पकड़ा जाता है और कहा जाता है कि फौरन् गल्ला दो। आपके प्रधान मंत्री जी का यह भाषण था कि किसी पर जोर नहीं डाला जा सकता। जब आपकी नीति यह है तो फिर क्यों आपके कमचारी इस तरह से जोर-जुल्म करते है? अगर आपका इशारा नहीं तो मैं कभी नहीं मान सकता कि आपके कर्मचारी इतने निडर होकर इजलास में कहें कि १० गुना लगान की रसीद दाखिल करो तब मामला मुना जायगा। में यह नहीं कहता कि आप वसूल न करें, जरूर करें। लेकिन जो रवया चल रहा है उससे वसूली होगी नहीं। जो वसूल होगा उससे ज्यादा आप खर्च कर डालेंगे। अभी सप्लीमेंटरी बजट नहीं आया है जिसके जरिये से हम इसका विरोध करते। १० हजार आदमी इसमें मुला-जिम रखें गये हैं। वे इस काम को कर रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-आपको मुआविजा कैश में लेना है या बांड्स में ?

श्री वीरेन्द्र शाह—इस तरह से टारचर (सताना) करके रुपया वसूल किया जाए तो नकदी आप नहीं दे सकेंगे। जहां तक आपने कहा कि नकदी में लोगे या बांड्स में, तो सरकार ने इस बिल में बतलाया ही नहीं हैं, आप पूछते कैंसे हैं? सरकार बतलाए कि किस तरह से देना चाहती है। हम तो जरूर चाहेंगे कि नकदी दी जाए। आप समझ लीजिए कि अगर आप छोटे जमींदारों के। नकदी नहीं देंगे तो आप उनको खत्म भी नहीं कर सकेगे। जमींदारी अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट में यह चीज कोई नहीं थी कि आप शिकमी ले लेगे। लेकिन आपने इसमे यह कहा है कि चाहे छोटा जमींदार हो या बड़ा, यह १८ लाख एकड़ जमीन जो शिकमी पर उठी हुई है वह उनके हाथ से चली जायगी। जो जमींदार ढाई सौ के उत्पर हैउनको आपने हेरीडिटरी टेनेंट बना दिया और छोटे जमींदारों को आपने पांच साल तक लटका दिया है, पांच साल के बाद वह भी जमीन उनसे निकल जायगी, क्योंकि आपने रखा है कि पन्द्रह गुना देने के बाद वह शिकमी भी मौरूसी हो जायगा।

जिस वक्त टेनेंसी बिल आया था उस वक्त मैने मिनिस्टर साहब से इस्तदुआ की थी, तो उन्होंने कहा था कि पचास एकड़ जमीन रहने दिया है, लेकिन आज जब जमीं दार उस जमीन को रखना चाहता है तो आप कहते हैं कि पांच साल तक इंतजार की जिये। दो दफा इसी भवन में जमीं दार की सीर और खुदकास्त पांच—पांच साल के लिये शिकमी पर उठाने की आपने इजाजत दी। जब अबालिशन का वक्त आया तो आप ही अपने बनाये हुए कानून के विरुद्ध यह कहते हैं कि नहीं, हम उसको बेदखल नहीं कर सकते हैं, जो जमीन को जोते हुए हैं। आपने बीस साल तक वह मौका दिया। उसके बाद आप यह कहते हैं कि हम आपको एक महीने का भी अब मौका नहीं दे सकते। इसके मानी यह हैं कि आपने बीस साल पहले जमीन को अबालिश कर दिया।

अगर गवर्नमेंट छोटे जमींदारों से हमदर्दी करती है तो उन्हीं की मदद करे। हम तो देखते हैं कि जमींदार क्या किसानों तक के लिये खतरा है। अब सरकार जमींदार हो जायगी और लगान सख्ती से वसूल करने का जो तरीका रखा गया है, वह कब तक निभ सकेगा। [श्री वीरेन्द्र शाह]

ठेकेदार को आपने मध्यवर्ती माना है। उसको भी हमारे बराबर मान लिया है। हमने लगान वसल करने के लिये ठेका दे दिया कि आप इस गांव का लगान वसूल करके इतना रुपया देते रहेंगे, बाकी मुनाफा आप लेते रहेंगे। अब सरकार यह पास करती है कि अगर तीस एकड़ उनकी जोत होतो वह देदी जाय उसके बाद जितनी जमीन बाकी बचे वह जमीन गांव-सभा की होगी, यानी वह सरकार लेना चाहती है। जमींदारों के पास फिर कहां से जमीन आयेगी। टेनेंसी ऐक्ट में ठेकेदार के लिये आपने यह किया था कि दस साल के ऊपर किसी ठेकेदार के पास जमीन नहीं रहेगी। उन्हीं पर आप इतनी कृपा कर रहे हैं। तीस एकड़ जमीन दे रहे हैं मुफ्त की, जिस पर उनको कोई हक नहीं है। उसके बाद अगर वह फार्मिंग किये हुए हैं तो कलेक्टर की इजाजत से उसकी जारी रखे कुछ दिनों तक बाद में गांव-सभा को वह जमीन मिल जायगी। न आप मुआविजा देते हैं, न जमीन जोतने के लिये देते हैं और न सायर की आमदनी देते हैं, तो जमींदार किस तरह से जिन्दगी बसर करेगा। आप छोटे या बड़े जमींदार की क्या मदद करते ह उनके लिये सरकार ने क्या सोचा है कि ये २३ लाख जमींदार जिस वक्त बेकार हो जायंगे और परिवार समेत मिलाकर करीब १ करोड़ आदमी के होंगे इनको सरकार किस तरह से काम में लगायेगी, सिवाय इसके कि जिस तरह से शरणार्थी लोगों की है सियत है, उनकी भी रह जायगी। मैं इस शब्द को नहीं दुहराना चाहता। हमारे देश में एक विपत्ति आई और उसके परिणामों को हम आज तक भोग रहे हैं और बही गलती आज आप फिर करने जा रहे हैं जिसके जरिये यही आफत, यही दुखें अपने प्रान्त में किर आयेगा और आपको यह झेलना पड़ेगा। जब जमींदार मारे-मारे फिरेंगे उनके पास रोटी नहीं होगी आप सुनेंगे कि फलां गांव लूट लिया गया, फलां जगह लूट-मारहो गई तो में कहता हूँ कि आप इसे देखिये। हम भी इस प्रान्त के निवासी हैं। मैं उन जमींदारों की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि सरकार ने कौन सी योजना उनके काम में लगाने के लिये बनाई है, कौन सी मिलें तैयार की हैं ? कोई लड़ाई भी तो नहीं हो रही है, जिसमें जाकर मर खप जाते। में एक ठाकुर की है सियत से कहता हूं कि हम नहीं चाहते कि अपने रोटी के लिये अपने भाइयों का खून करें। किसी बाहरी देश की लड़ाई होती तो हम दिखात कि किस तरह से अपनी जमीन की रक्षा की जाती है। महाराजाओं की मिसालें दी जाती हैं कि फलां महाराजा ने अपने स्टेट को छोड़ दिया। में कहता हूँ कि उन्होंने देश के लिये छोड़ा था बाहर वालों के लिये नहीं। हम भी आज जो कुछ भी करने के लिये तैयार हैं वह इसीलिये। हम अध्यक्ती इस कार्यवाही का कोई जवाब नहीं देते हैं तो सिर्फ इसोलिये कि यह हमारे देश के भाई हैं। हम समझते हैं कि हमारे देशवासी हैं गलती करते हैं। लेकिन फिर भी अपना समझ कर आपसे कहते हैं और कहेंगे और अपनी रोटो को लेकर मानेंगे। आपको उसका इन्तजाम करना होगा। देश सेवा के लिये जहां भी आप हमसे कहें हम लड़ने-मरने के लिये तैयार हैं, लेकिन आपको हमारा खयाल करना होगा। हमारी रोटी का सवाल आपको हल करना होगा। आज हमारी आमदनी १ हजार है तो पांच सौ कीजिये, दो सौ कीजिये, लेकिन आप आज जो कम्पेन्सेशन दे रहे हैं उससे आप आमदनी का अन्दाजा लगा लीजिये कि क्या आमदनी रहती है। जमींदार एक मिडिल क्लास सोसाइटो है। अगर आप उसके हक को मार देंगे तो यह समझ लीजिये कि आज यह जो आपकी नौकरशाही है, आपके यह जो नौकर है, क्लर्क है, उनके ऊपर भी आफत आयेगी। कितने बड़े बोझ को हम सम्हाले हुये हैं। जिस दिन जमींदारी खत्म हो जायेगी, इनके ऊपर कितना भारपड़ेगा इसको आप समझ लीजिये।

(इसके बाद भवन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिए

स्थगित हो गया।)

केलास चन्द्र भटनागर, मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली, संयुक्त प्रान्त ।

लखनऊ , ११ जनवरी, सन् १९५० ई०

नत्थी 'क'

देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर

 T_{ℓ}

The COMMISSIONER,
FOOD & CIVIL SUPPLIES,
UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow May 18, 1949. Subject —Prices Of Gunny Bags.

SIR,

In continuation of G. O. no. 662/XXIX-A (F), dated February 26, 1949 fixing the prices of gunny bigs for the quarter ending March 31, 949, I am directed to say that Government have fixed the following prices for the bags specified below to be charged from the date of receipt of this Government Order and to be operative till these prices are revised.

FOOD & CIVIL SUPPLIES
(A) DEPARTMENT

	•	$\mathbf{R}\mathbf{s}$.	a.	p.	
1.	New Gunny bags, D. W quality	1	4	0 per	bag
2.	Once used gunny bags, D. W. quality	1	0	0 ,,	,,
3.	More than once used bags	0	12	0 "	51
4	Not serviceable, damaged and repaired	0	8	0.,	33
5.	Foreign bags containing imported wheat, large size	1	4	0 "	,•
6	Foreign bags containing imported wheat small size	0	12	0 ,,	13

I am to add that an additional charge of annas four per bag over D. W. quality will be made for the corresponding quality of 'B' Twill bag.

I am to make it clear that a new bag means that which is actually new and has not been used before. A new bag used in storage for a period more than a fortnight shall be treated as once used bag. As such all bags in which grain is received by Regional Food Controllers and Town Rationing Officers shall be treated as once used and charged for at Re. 1-per bag of D. W. quality and at Re. 1-4 per bag of 'B' Twill quality.

Yours faithfully, TUFAIL AHMAD, For Secretary.

FINANCE (SUPPLY) DEPARTMENT.

No. 1163 (i)/XXIX-A (F)

Copy forwarded to the Accountant General, United Provinces, Allahabad, for information.

Copy also forwarded to all Regional Accounts Officers and Senior Accounts Officers, Headquarters for information.

By order,
KESHAV DAS
Assistant Secretary (Finance).

OFFICE OF THE COMMISSIONER, FOOD & CIVIL SUPPLIES, UNITED PROVINCES, LUCKNOW No. 1163 (ii) XXIX-A (F)

Copy forwarded to all District Magistrates for information and necessary action with the request that their reports on tendency of rise and fall in the prices of the bags along with their recommendations for the revised prices should reach this office not later than June 15, 1949.

Copy also forwarded to -

- 1. All Town Rationing Officers, United Provinces.
- 2. All Regional Food Controllers and Deputy Regional Food Controllers.
- 3. Provincial Marketing Officer (Food).
- 4 Deputy Director, Rationing.
- 5. All Sections of Food and Civil Supplies.

By order,
S. S. L. KAKKAR,
Assistant Commissioner (Rationing).

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०२ पर)

वन्दियों के स्थान परिवर्तन करने के नियम

१-- घोषित बन्दी--

१५३——(अ) हथकड़ी निम्नलिखित नियमों के अनुसार घोषित बन्दियों को रेल द्वारा या सड़क से ले जाते समय हथकिडयां डाली जायंगी:——

- (१) जब तक सुपरिन्टेडेट पुलिस कोई विशेष कारण नहीं समझता, ए श्रेणी के बन्दियों को हथकड़ी नहीं लगाई जायगी।
- (२) बी श्रेणी के वे पुरुष बन्दी जिन्हे दो वर्ष से अधिक सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया गया है, जे हथकड़ी डाल कर ले जाये जायेगे।
- (३) बी श्रेणी के अन्य बन्दी, उस समय तक जब तक कि सुपीरटेडेट पुलिस कोई विशेष कारण नहीं समझता हथकड़ी नहीं पहनेगे।
- (४) वे पुरुष बन्दी जिन्हें ए या बी श्रेणी नहीं मिली है तथा वे साधारणतः हथकड़ी पहनेगे।

२--विच।राधीन बन्दी--

नियम १८५ और १८६ के अन्तर्गत जिन बन्दियों को कवहरी मे य मैजिस्ट्रेंड के सामने ले जाने का भार पुलिस को दिया जाता है उन्हें हथकड़ी या बेड़ी या दोनो डालमें के निर्णय और उसके पालन करने का उत्तरदायित्व भी पुलिस पर होता है।

जब तक भागने, आक्रमण करने या आत्महत्या करने का विशेष भय नहीं होता, तब तक परिशिष्ट में दिये हुए अभियोगों के बन्दियों को रेल द्वारा या सड़क से कचहरी ले जाते समय हथकड़ी नहीं डाली जायगी इन्हें हथकड़ी डालते समय सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस या किसी उच्चादाधिकारी को लिपिबद्ध आज्ञा ले लेनी चाहिये।

परिशिष्ट में दी हुई धाराओं के अतिरिक्त धाराओं के विचाराधीन बन्दियों को भागने, आक्रमण करने या आत्महत्या करने से रोकने के लिये हथकड़ियां डाली जायंगी।

परिशिष्ट

भारतीय इंड-विधान के अध्याय ५-ए, ६ और ७ मे दिये हुए अपराध भारतीय इंड-विधान के अध्याय ८ मे दी हुई १५३-ए के १६० धाराये, धारा १७० और १७६ के अपराधों को छोड़कर अध्याय ९-ए और १०, धाराये ११६-ए, २२४, २२५-बी और २२६ के अपराधों को छोड़कर अध्याय ११, अध्याय १३, १४ और १५, १६ मे दी हुई धाराये ३१२ से ३१६, ३२३, ३२४ से ३२२, ३४१ से ३५० और ३५२ से ३५५। अध्याय १७ की धाराये ३२४ से ३२९, ४०३, ४०४, ४२१ से ४३४, ४४७ और ४४८, भारतीय इंड-विधान के अध्याय १८, १९, २०, २१ और २२ और अन्य ऐक्टों के समस्त अननुसंधेय अपराध और वे व्यक्ति जिन पर भारतीय इंड-विधा संग्रह धारा १०८ की कार्यवाही जारी हो।

नत्थी 'ग' (देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पव्ठ ४०५ पर) धीरे धीरे चलने वाले द्रैक्टर

नाम तथा प्रकार	डावर हार्स पावर	सप्लाई करने वाले	म्ल्य
एलिस चैमर्स			₹ο
एच० डो० ७	६१	सर्वश्री पाशाभाई पटेल	१ ६,०००
एंच० डो० १०	९०	ऐण्ड कम्पनी, बम्बई।	34,000
एंच० डी० १७५	१७५		20,000
इन्टरनेशनल हारबेस्टर			
टी॰ डी॰ ९ -	३५	सर्वश्री बीलकर्ट बदर्स, बम्बई।	११,०००
ओलीवर क्लैट्रिक			
<u> জী০</u>	६१	सर्वश्री विलियम जैक ऐंड कंपनी, कलकत्ता ।	२९,७५०
बी॰ डी॰	३५		३१,२३०
का उलर			
एफ० डी० ३	३५	सर्वश्री मार्शल ऐंड संस, कलकत्ता ।	२५,०००
<u>उस्तवाक</u>	२०	सर्वश्री मुघालाल ऐंड संस, कानपुर।	१४,०००
भनसाल्ड इटालियन	५०	11	35,000
हाऊलर मा <u>र्शल</u>	३५	सर्वश्री मार्शल ऍड संस, कलकत्ता।	१८,०००
हील ट्रेक्टर		* * * * ***	•
ोर्डसन मेजर	१८	सर्वश्री यू० पी० कर्माशयल कार्पेरिशन, लखनऊ ।	१२,०००
म० एम०	80	सर्वश्री बी० के० खन्ना ऐंड कम्पनी, देहली।	१७, ०००

नाम तथा प्रकार	ड्रावर हार्म पावर	सप्ताई करने बार	पू ल्य
चै सी हैरिम			₹0
५५ के	४२	सर्वश्री करस्क्रान इक्यपमेंट कम्पनी, बम्बर्ट ।	१४,०००
४४ के	३५	12	82,000
३० के	२२	27	6,000
ओलोवर ८० के० डी०	१८	सर्वश्री विलियम जैक कम्पनी, कलकत्ता ।	6,000
फील्ड मार्शल	३५	सर्वश्री मार्शल ऍड संस, कलकरा।	१०,०००
सिम्पसन	३५	सवश्री मुन्नालाल ऍड सम, कानपुर।	९,०००

संयुक्त प्रान्तीय लेजिरलेटिव असेम्बली

बृह पितिवार, १२ जवनरा, सन् १६५० ई०

अने माली की बेठ है, अने बिकी भारत, लवतऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई

रुपीकर-माननीय श्री पुरुपात्तमदास टण्डन

उपस्थित सदस्यों की सची (१८१)

अचल सिंह अजित प्रताप सिंह अब्दुल बाकी अब्दुल मजीद अब्दूल मजीद ख्वाजा अब्दुल वाजिद, श्रीमती अब्दुल हमीद अम्मार अहमद खां अर्नेस्ट माईकेल फ़िलिप्स अली जरीर जाफरी अल्प्रोड धर्मदास असगर अली लां अक्षयबर सिंह आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री आर्चिबाल्ड जेम्स फैन्थम इन्द्रदेव त्रिपाठी इनाम हबोबु ला, श्रोमनी उदयवीर सिंह एंजाज रस्ल कमलापनि तित्रारी करीमुर्रजा ला कालीचरण टण्डन किशनचन्द पुरी कुशलानन्द गरोला कृपाशंकर कृष्णचन्द्र गुप्त केशव गुप्त **केशवदेव मालवीय, माननीय** श्री

वानचन्द गौतम खुशवक्त राय खुशीराम खुर्बासह गंगाघर गंगाप्रसाद गंगासहाय चौबे गजाधर प्रसाद गनपति सहाय गणेश कृष्ण जैतली गिरघारी लाल, माननोय श्री गोवाल नारायण सक्सेना गोविन्दवल्लभ पन्तः माननीय श्री चन्द्रभान् गुप्त, माननीय श्री चन्द्रभानु शरण सिह चरणसिह चेतराम छेदालाल गुप्त जगन्नाथ दास जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जगनप्रसाद रावत जगमोहर्नासह नेगी जेपाल सिह जैराम वर्मा जहीहल हसनैन लारी जहर अहमद जाकिर अली जाहिद हसन

जुगुलिकशोर त्रिलोकी सिह दाऊदयाल खन्ना द्वारिका प्रसाद मौर्य दीनदयालु अवस्थी दीनदयाल शास्त्री दीपनारायण वर्मा नफोसुल हसन नवाजिश अली खा नवाब सिह नाजिम अली नारायणदाम निसार अहमद शेरवानी पूर्णमासी पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती प्रकाशती सूद, श्रीमती प्रयोगनारायण प्रेमिकशन खन्ना फ़ख़रुल इस्लाम फजलुर्रहमान वा फतेहसिंह राणा फूल सिह बदन सिह बनारसी दास बलदेव प्रसाद बशीर अहमद बशीर अहमद अनसारी बादशाह गुप्त बुजमोहन लाल शास्त्री भगवती प्रसाद बुबे भगदती प्रसाद शुक्ल भगवान दोन मिश्र भारत सिंह यादवाचार्य भीमसेन मंगला प्रसाद मसुरिय। दीन महफूज़ुर्रहमान महमूद अली खां मिजाजी लाल मुक्दलाल अग्रवाल म्जक्फर हुसेन मुहम्मद अदील अब्बासी मुहम्मव असरार अहमद मुहम्मद इब्राहीम, माननीय श्री मुहम्मव इस्माईल नुहम्मद जमशेदअली खां मुहम्मद नबी

मुहम्मद नजीर मुहम्मद रजा ला मुहम्मद शकूर मुहम्मद शमीम मुहम्मद शाहिः फालरी मुहम्मद सुलेमान अधमी यज्ञ नारायण उपाध्याय रघुनाथ विनायक धुलेकर रघुवंशनारायण मिह रघुबीर सह'य राजकवार मिह राजाराम मिश्र राजाराम शास्त्री राधाकृष्ण अग्रवाल राधामोहन सिह राधेक्याम क्षमी रामकुमार शास्त्री राम कृपाल सिह रामचन्द्र पालीवाल रामचन्द्र सेहरा रामजी सहाय रामधारी पाडे रामन। रायण रामबली मिश्र रामम्ति रामशकरलाल रामशरण राम स्टब्स गुप्त े रोशन जमां खां लक्ष्मी देवी, श्रीमती लताफत हुसैन लाखन दास जाटव लालबहादुर, भाननीय श्री लाल बिहारी टण्डन लीलाधर अस्थाना लुत्फ अली खां लोटनराम वंशीधर मिथ बिजयानन्व मिश्र विद्याधर बाजपेयो विद्यावती राठौर, श्रीमती विनय कुमार मुकर्जी विश्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ राय विष्णुदारण दुब्लिदा वीरेन्द्रशाह वेंकटेश नारायण तिवारी

शकर दत्त शमी
शान्ति प्रयन्न शर्मा
शिव कुमार पाण्डे
शिवकुमार मिश्र
शिव दयाल उपाध्याय
शिवदान सिंह
शिवमंगल सिंह कपूर
श्यामलाल वर्मा
श्याम सुन्दर शुक्ल
श्रीचन्द सिंघल
श्रीपति सहाय
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
मरवत हुसँन
सजीम हामिद खा
साजिद हुसँन

सिट्टासन सिह
सीताराम अस्थाना
सुदामा प्रसाद
सुरेन्द्र बहादुर सिह
सुल्नान आलम खा
सूर्य प्रसाद अवस्थी
सईद अहमद
हबीबुर्रहमान अन्सारी
हबीबुर्रहमान खा
हरगोविन्द पन्त
हरप्रसाद सत्यप्रेमी
हसरत मोहानी
हुकुम सिह, माननीप शी
होतीलाल अग्रवाल

प्रशासर

बुहस्पतिवार, १२ जनवरी, १९५० ई०

तारांकित प्रश्न

की ग्रापरेटिव से साइटी की मदस्यता के लिये नियम

*१—श्रो महम्मद शाहिद फाखरो-- क्या गवर्नमेट यह बतलायेगी कि वितने प्रतिशत मेम्बर हो जाने पर किसी जगह पर कोआपरेटिव सोसाइटी बन सकती है ?

माननीय उद्याग सिचिव (श्री केशव देव मालबीय)—कम से कम १० सदस्यों को एक सहक री समिति रिजिस्टर की जा सकती है। उन्नभोक्ना सहकारी स्टोरों को अपने कार्न क्षेत्र को जन महया का प्रतिनिधि बनाने और अधिक से अधिक उपभोक्ताओं की सह नुभूति प्राप्त करने के उड्देश्य से यह निभाग ऐसे स्टोरों के लिए यह जोर देता है कि रिजिस्टरी के पहुले से अधिक से अधिक सदस्य भर्ती कर लें।

*२--श्रो सुहम्मद् शाहिद् फाखरा--न्या यह सही है कि चाहे जितने कम प्रति-शत मेम्बर हों, किपी भी कोआ रिटिव सोसाइटो को रार्शानग की दूकान दी जा सकती है?

माननीय उद्योग सिविव—उपभोक्ता सहकारी स्टोरों को सा गरणतः खाद्यान्त की राशीनग की दूकारों तब दो जाती है जबिक उस सब-एरिया के कार्ड रखन वालों के पच्चीस प्रिश्तित उसके सहस्य हों और जब के जिला अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जान कि वे स्टोर खाद्यान विनरण का कार्य कुशन्तापूर्व के चला सकेगे।

*३—श्रो मुह्म्तद्शाहिद फाग्वरो—नया इन कोअपरेखि सोम इटियों को इस बान का हक है कि वे किसी भी कार्ड होल्डर को शिशो समन भी राज्ञन देना बन्द कष्ट दें?

माननीय उप ग सचिव-नही ।

१३५६ फान ही में दबरिया (जले में खर्त की पटावार एवं इक ल से उत्पन्न म्थिति के विषयमें पूक्त ताक

'४-- श्री रे। जान जमां खा-- (क) क्या सरकार कृपः कर बतलायंगी कि १३५६ फस्ली में दबिर्या जिले में खेती होने बाली जमीन में कितने एकउ में अनाज, कितने में ईख और सिनने में दूतरी फनने वैदा की गयी !

- (ख) खीफ ओर रबी की अलग-अलग कितने एकड़ भूमि में खेती की गयी थी?
 - (ग) इस जिले की जन-संख्या कितनी है ?
- (घ) एक व्यक्ति पर औसतग कितनी अनाज पैदा करने वाली जमीन पडती है?
- (ड) इस जिने में ओसत पैदावार प्रति एक उक्या है ?
- (च) इस वर्ज अनाज ओसत पेदावार प्रति एकड़ क्या हुई है?
- (छ) इस वर्ष यानी १३५६ फस्ली में रबी की औसत पैदावार प्रति एकड़ कितनी हु[°] हैं ?

माननीय माल पांचव (श्रा ह कुम सिह)--(क) १३५६ फस्ली मे देवरिया जिले में खे 11 होते वाली जमीन पर निम्नलिखित क्षेत्री मे अनाज, ईख तथा दूसरी फसले पैदा की गई--

अनाज ११,९६,५६१ एकड

र्डख १,१५,३९१ एकड

दूसरी वस्तुएं ५५,७६७ एमड

- (ब) खरीक १३५६ फसली में ८,२०,६१५ एकड़ पर तथा रबी मे ५,४७,१०४ ५कड भृति में खेती की गई।
 - (ग) इस जिले की जन-संख्या १९,६५,५३१ है।
 - (घ) एक व्यक्ति पर ओसत न ५३४ एकड अनाज पैदा करने वाली जमीन पडती है।
 - (ड) इस जिले मे ओसत पैदावार १० मन फी एकड है।
- (च) १३५६ फसली में इस जिलें में अनाज की औसत पैदावार ६ १/४ मन फी एकड हर्द ।
 - (छ) १३५६ फ नली रबी में ६ मन प्रति एकड की औसत पैदाबार हुई है।

थ्री। रोशन जमां ग्वां--देवरिया जिलेका जहा तक ताल्लुक है, वया सरकार यह बतलायेगी कि वह जिला गन्ले के लिएाज से डिफीसिट (कमीवाला) एरिया है?

माननी । माल सचिव--मेरा स्थाल है डि तीसिट एरिया है।

श्रा र शन जमां खां--सरकार ने देवरिया जिले में गल्ले की कमी की पूरा करने के लिये क्या-क्या यत्न क्रिये है ?

माननाय माल मिवय-पैदावार बढ़ाने की तरकीब करती है।

माननीय यन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु ग्रुप्त)--और समय-समय पर जब गल्ले की कमी पही है वहां गल्ला भेजा गया है.

* ५--श्री रोज्ञान जमा खां--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस वर्ष इस जिले में रबी की फसल रुपये में बारह आने से अधिक मारी गयी थी ?

माननीय माल मांचान-पह गलत है। इस जिले में केवल ३७ गावों में रबी की फसल को आठ आना से ज्यादा नुकसान हुआ।

श्री र ज्ञान जमां जां-क्या १३५६ की रखी की फ़सल के बारे में सरकार को डिस्टिक्ट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने कुछ कम्यूनिकेशन भेजा था?

माननीय भाल मचित्र-नोटिस की जरूरत ह।

श्री मुख्तान ग्रालम खा--क्या मरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि जब देवरिया जिला डिफोसिट एरिया माना जाता है तो वहा प्रोक्योरमेट स्कीम में गहला लिया गया या नहीं?

माननीय ग्रन्न सचिद-- नही।

श्री रोशन जमा खा--क्या ९ जुलार, १९४९ ई० को १३९६ में देवरिया जिले में रबी की फसल मारे जाने के बारे में एक डेप्युटेशन माननीय प्रधान सचिव से मिला था?

माननीय प्रयान मन्ति उ-(श्री गे। विन्द दहनभ पन्त)—तारीख तो मुझे याद नहीं, कुछ लोग मिले में, उसे डेप्यूटेशन लहा जा सकता है। उनसे बाते भी हुई थी और समझा भी गया था कि उनके जो ख्यालात है वे गन्त है। उनकी समझ से भी आ गणा था, लेकिन बाहर जा कर फिर उन्होंने अपनी बात कहनी गुरू कर दी।

श्री रे। शन जमां ख'--का उन डेप्यूटेशन ने माननीय प्रधान सिंद्रव से एक नान अफिशियल इन्क्वायरी करने की माग को थी ?

माननीय प्रधार मिचि अ—-माग किहिये गा दरण्या त किहिये जो किहिये, कुछ किया था, लेकिन गर जरूरी समझा गया। जहां कही रेमीशा वगैरा का सवाल उठे और अगर नान आफिश्यल इन्क्वायरी होने लगे तो उन्हें वक्त न मिले। आफि नियत्स ने बहुत लिबरली सारा काम कि गा और देवा और उनकी जो सिकारिशे भी उन एर का किया गया। वहां चीप प्रेनशाप्स लो हे गये और वहा कोर्स प्रेन्स रक्ले गये, लेकिन वरीदने वाला कोई नही था।

 $*६--श्री रे। शन जमा खा--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिले में अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है <math>^{2}$

माननीय माल माच ब--इस जिले में अकाल की स्थिति नहीं है।

#७--श्री रे।शन जमा ख'--क्या यह सच है कि जिले भर मे आमतौर से ३२ रु० मन चावल और ३० रुपया मन से कम पर गेहुं नहीं मिल रहा है ?

मानतीय माल मचिव--जी नही।

#८—-श्री देशित जम खा—-क्या सरकार को यह जात है कि सन् १९४७ ई० की बरसात में बिसनपुरा थाने के बतरी जी धुरखडवा के श्री रोझन जी (हरिजन) भूख से पीडित होकर मर गये थे ?

माननीय माल सचिव--जी नहीं। श्री रोझन की मृत्यु साधारण तौर पर बुखार के कारण हुई।

*९--श्रो रेशिन जमा खा--उस वर्ष और कितने लोग भूख से पीडित होकर मरे थे ? माननीय माल स्विध--कोई भी मनुष्य भूख से पीडित होकर इस जिले में नहीं मरा। *१०--श्री रोशिन चमा खा--क्या मरकार को जात है कि इस वर्ष भी वैसी ही

*१०--श्री रोशन जमा खा--क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष भी वैसी ही स्थिति पैदा हो गयी है?

माननोय माल मचिव--जी नही।

*११--श्रा राशन जमां खां-अकाल से बचाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

माननीय मान सचिव--पह सवाल नही पैदा होता।

*१२--श्री रे दान जमां खा--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि गाव मे ८० प्रतिशत लोगों के पास न तो अनाज है और न खरी इकर खाने के लिए पैसा है?

माननीय माल सचिव-ऐसे लोगों की संख्या लाभग नहीं के बराबर है।

• १३-१५--श्री रे [हान जमां खां--[स्थगित किए गए]

जिला देवरिया में गह के बीज के दाम

'१६--श्रांगान जमां खां--गेहूं के बीज का दाम इस समय किस दर से लिया जा रहा है ओर दो महीना पहिले किस दर से लिया जा रहा था?

माननीय क् ष म च्या । श्री निमार ग्रहमद होर्यानी)—मई सन् १९४९ ई० को बीज गोदाम बन्द कर दिये गये थे और गों के बीज के बारे जितना रुपया बाकी था, जून, जुलाई और अगस्त माह मे नकदी के रूप मे निम्नलिखित दर से जमा कर लिया गया—

(क) बाज रदर तथा उसके ऊपर १२ १/२ प्रतिशत दन्छ।

(सं) सरकार हारा निर्वारित दर तथा उसके अपर ५० प्रतिशत दन्ड। बाजार में थोक निकय की दर प्रति मन, जून जुलाई ओर अगस्त माह में इस प्रकार थी —

४० आ० पा०

जून २०-९-११ जुल:ई २०-६-२ अगस्त १९-४-१

इस समय सरकारद्वार। लिप्ने गए एफ० ए० क्यू० गेहू की सबसे ऊंची दर १३ ६० प्रति मनथी।

जिला देवरिया में बीत तथा तक। वी की वसूली

*१७-- श्रो रोशन जमा ख --बीज की वसूली में कितनी वारन्ट गिरफ्तारी और क्कीं जारी की गयीं ?

माननीय माल स्वित्र--बीज की वश्ली के सिलसिले मे २१ वारन्ट गिरफतारी और

८२ बारन्ट क़ुकों के जारी किए गए।

*१८- श्री रोज्ञान जमां खां--क्या सरकार को ज्ञात है कि बीज और तकावी की वसूली में भारी कि जनाई पड रही है ?

माननीय माल मचिय--बीज तथा तकावी की यसूली में कोई असाधारण कठिनाई

नहीं पड़ी।

*१९--भ्रा रोशन जमा म्वां--क्या सरकार इस सम्बन्ध में वसूली स्थगित करने का आदेश देने का विचार रवती है ?

माननाय म ल मन्त्रिय—सरकार इस सम्बन्ध में सामान्य तौर पर वसूली स्थिगित करने का आदेश देने का विचार नहीं रखती, परन्तु उन व्यक्तियों के लिये जिन्हें कोई िश्वेष किताई पड़ती हैं सरकार माफी देने या वसूली स्थिगित करने के प्रश्न पर हमेशा हमदर्शी से गौर करती है।

जि । देवरिया में खतो के य ग्य परती जमीन

*२०--श्री गाञान जमां खां--जिने भर में कितनी जमीन ऐसी है जिस में खेती हो सकती है लेकिन वह परती है?

माननीय माल सन्विच--इस जिले ने १,१८,८४३ एकड़ कृषि योग्य भूमि परती पृशि है। कलेक्टर देवरिया को लेड यूटिलाइजेशन ऐक्ट, १९४८ के अनुसार इस भूमि पर खेती कराने का नियमानुसार प्रबन्ध करने का आदेश दिया गया है।

रियासत कुंडवां तमकोही सलंमगढ़, पडरीना में परती जमीन

*२१--श्री राज्ञान जमा खा--रियासत कुंडवां, तमकोही, सलेमगढ़ तथा पडरोना में कितनी जमीन जिस में पहले खेती होती थी, इस समय परती पड़ी हुई है ?

माननीय माल सचिव--रियासत तमकोही में कोई भी भूमि परती नहीं पड़ी है। कुंडवां सेलेमगढ़ तथा पडरौना रियासनीं में ६१०, १७३ और १, ०९४ एकड़ भूमि क्रमशः परती पड़ी है। $^+$ २२—श्री रे।शन जमा खा—-स्यायह सच है कि उक्त रियामतो के मालिकान ने इरादतन इन खेतो को परती छोड रखा है ?

मानतीय माल सिच्च -- यह सर्वथा सन्य नहीं है कि उक्त रियासतों के मालिकान ने इरादतन इन जमीनों को परती छोड़ दिया है। इसमें से बहुत सी उमीन इस वास्ते परती पत्री हैं कि रियासत में बद इन्तजामी है या कि मजदूर नहीं मिलते ह या कि जमीदारों तथा काश्तकारों में कुछ झगा है।

े२३--श्री रे। शत जमां खां--यह जमीने कितने दिन से परती परी हुई है ?

माननीय माल मिच्या--२३३ एकड भूमितीन सालतक से परती पडी है। ५६९ एकड भूमि ४ से ६ साल तक से परनी पडी है और ३० एकड ७ साल से ऊपर से परती पडी है। इन रियासनो में १,०४५ एकड सीर की जमीन भी परनी पडी है, पर उसकी मुद्दत का ठीक अनुमान नहीं मिल सकता।

श्री राञ्चान जमा म्वा—नया सरकार यह बतलायेगी कि परती जमीने जो किसानो के साथ तय की गयी है उनके लगान की शरह सर्किल रेट के बमूजिब है या उससे ज्यादा रखा गया है?

माननीय माल मिचित्र-यह बात बतलाना इस वक्त तो नामुमिकन है लेकिन शरह जो दरिमयान फरीकेन तय हुई है वही मुकर्रर हुई है।

मकाहो राज, जिठा देवरिया का कार्ट ग्राफ वार्ड्स के प्रवन्य में श्राना तथा उनसे वहां की खनी तथा मजररों पर ग्रमर

*२४--श्री गेशान जमां ख --क्या सरकार कृषा करके बतलायेगी कि तमकोही राज, जिला देवरिया कर से कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रम्बन्ध में आया है ?

माननीय मील सिंच य--तमको हो रियासत, जिला देव।रिया कोड आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में १० मई सन् १९४८ ई० से आई है।

*२५--श्री रे। जन जमा खां--कोर्ट आफ वार्ड्स में आने के बाद रियासत की आमदनो बढ़ी है या घटी ? यदि बढ़ी है तो किननी और किन जिस्यों से और यदि घटी है तो इसके क्या कारण है ?

माननीय माल सिच्या--जब से यह रिशासत कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आई है इसकी आय २,९६,९०१ रु० से बढ़कर ३,००,०६० रु० हो गयी है और परती जनीन के उठाने से यह इजाका हुआ है।

*२६--श्री रेश्चान जमां खां--क्या कोर्ट आफ वार्ड्स खेतो का बन्दोबस्त करते समय किसानों से कोई रकन वसूल करता है। यदि नहीं तो पुराने किसानों को बेदलल करने का क्या प्रयोजन है?

माननीय माल सचित्र—जी नहीं कोर्ट आफ वार्ड सकी तरफ से किसानों की बेदलिंगी बहुत कम होती है और केवल निमालिशित अवस्थाओं में होती है—

- (१) जब कि किसान लगान नहीं देता।
- (२) जब बिला इजाजत जमीन जोत छेता है और लगान देने पर तैयार नहीं होता ।
- (३)जब कानून के खिलाफ जनीन शिकमी पर उठा देता है।

*२७--श्री रेश्रान जमा खां--पिउले जून में किता मुकहमे बेदलली के दायर हुए हैं ? माननीय माल सिच्च अ--गत जून, १९४९ई ० में बेदलली के २५२ मुकहमे दायर किये गये।

*२८--श्री रेशिन जमां खां--कोर्ट आफ वार्ड स कितनी जमीन पर खेती करने जा रहा है । माननीय माल मांच्यव—ऐसे रक्षितों की तरफ से जो नाबालिंग होने या दूसरे कारण से स्वयं जमीन नहीं जोत सकते है कोर्ट आफ वार्ड स १४३२ एकड भूमि जोत रहा है।

*२९—श्री राञ्चन जमां वा—उस खेती से अगले वर्ष में कितना लाम और व्यय का अनुमान हैं ?

माननीय माल सिचिव--जो भूमि कोर्ट आफ वार्ड स जोत रहा है उस पर १,४५ ०५२ रुपये का व्यय और ३२,००८ रुपये के लाभ का अनुमान है ।

*३०--श्री राज्ञन जमां खा--उस खेती पर कितने आदमी काम करेंगे ?

माननीय माल मचिव—१४३२ एकड भूमि पर लगभग १०० मुस्तकिल गजदूर काम करेंगे और आवश्यकतानुसार गेर मुस्तकिल मजदूर रक्खे जायेगे।

13१—श्रो रोज्ञान जमा खां—उस खेती के कोर्ट आफ वार्ड्स में आ जाने की वजह से कितने मनवूर बेरोजी हो जायेंगे ?

माननाय मान्न सिन्निय-कोई भी मजद्र बेरोजी न होगा बल्कि पहले से ज्यादा मजद्र काम में लगेंगे क्योंकि इस रकबें में बहुत सी जमीन जो पहले बजर थी अधिक अन्न पैदा करने की योजना के अनुसार जोती ज। रही ह।

देवरिया जिल मं पुलिस के अमल म बृद्धि

ै २२—-र्आ। राञान जमा खां——देवरिया जिले में वर्तमान कप्तान के जमाने में कितनी डकंतियां। कत्ल, चोरी, बलवे हुये हैं और इनके पहले के कप्तान के जमाने में कितने ? दोनों कप्तान कितने दिन तक यहां रहे ?

माननीय पुलिस सचिव (श्री लालबहाद्र)--

	and made to being developed the common and	tophy des			
अफपर कानाम	अवधि	डकैंनी	हत्या	चोरी	बलवा
पहले के कप्तान	ता० १८-५-४६	•	इ १	९९५	१५१
इस समय के कप्तान		ते ४५	\$?	<i>६१७</i>	२२४
	_ ता० २६-८-४९ त	ক 			

श्री रोशन जमा न्वां—क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिन कातान साहब का जिक इस सवाल में वर्तमान कप्तान से किया गया है वह अब भी मौजूद है या उनका तबादला हो गया है?

माननोय पुलिस साचय--उनका तबादला हो गया है।

*३३--श्री गाञानजमा खां--कितने पुलिस के अफसर इस वक्त पहिले से बढ़ाये गये हैं? माननीय पुलिस सचिव--मांगी गई सूचना साथ की सूची में दी गई है।

(बेखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५२९ पर)

जिला देवारिया में यू० पो० शुगर कम्पनी लिमटेड के फार्मों के वारे में पृक्ताक्र *३४—श्री रे। दान जमां खां—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बभनोली बैकुंठपुर सपहा और डोमांठ जिला देवरिया में यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड के फार्म क्तिने एकड के हैं ?

माननीय उद्योग सचित्रवमनौली फार्म	१२३८. ७५	एकड
बंकुंठपुर फार्म	५६३. ७७	एकड
संपहा फाम	५०३. १५	एकड
डॉमोठ फार्म	४३२. ७५	एकड

"३५--श्रो रोशन जमा खां--इम में कितने मजदूर काम सरते है ? क्या इनका कोई संघ है ?

भाननीय उद्याग सचित्र--इन फार्सी में ३६१ मजबूर काम करते ह और इनमा एक संघ भी ह।

*३६--श्री र ज्ञान जमा व्या--यदि हां तो क्या यह संब देंड पूनियन के आधार पर संगठित है ?

मानर्गाय उद्य ग मचित्र—पह संघ भः तीय ट्रेड यू नियन ऐक्ट, १९२६ ई० के अन्तर्गत प्रमाणित है।

*३७--श्रं। रोशन जमां खं--क्या इसके सन्बन्ध रे कोई एउंड भी हुआ है? माननीय उद्य गर्माचव--र्ज हा ।

*३८-- श्री र शन जमान्यां--क्या यह मच हे कि जिले भर में यही एक खेतिहर मजदूरों का संघ मंगिटत है ?

भाननाय उद्र ग मचित्र--जी हां।

* २९-- भ्रोर जन - मांखां--इस फार्म से उप वर्ष कितनी जमेन ले ली गई?

माननोय उद्य ग सचित्र--३० जुन १९४९ के बाद इस फार्म से १°६३ ३१ एकड़ जमीन वाविस ले ली गई।

*४०--र्भा राज्ञन तमा खां--गह ले हुई जमीन किसे दी जा रही है ?

मानर्नाय उठा म सिचव--यह ली हुई जमीन तमकोही राज्य को वापस दे दो गई है।

*४१--श्री रोशन जनां खीं--इस जमीन के हे हेने की वजह से कितने मजदूर बेरीजी के हो रहे हैं ?

माननीय उद्योग सचिव--९६ मजदूर।

*४२--श्री रोशन जमां खां--इस प्रकार बेरोजी के मजदूरों के लिए सरकार वया व्यवस्था कर रही है ?

माननीय उद्योग सचिव—इन निकाले हुये महादूरों के नाम कोर्ट आफ़ वार्ड्म तमकोही के स्पेशल मैनेजर के पास भेज दिये गये थे। सरकार को आज्ञा है कि उनमें से बहुत मज़दूर कार्य में लग गए होंगे:

*४३--श्री रोशन जमां खां--इस फामं ने अपनी खती की जमीन के कितने अंश में अनाज की खेती और कितने में ईख की खेती की है ?

माननाय उद्योग सिच्चन-लगभग ७९७.१७ एकड़ में ईख की खेती और ९३५.१६ एकड में अनाज की खेती की गई है।

*४४—श्री र शन जमां खां—क्या सरकार यह जानती है कि इस जिले मे अनाज की कमी रहती है और है ?

माननीय दद्योग सचिव--जी हां।

*४५--श्री ोशन जमां खा--किन-किन फ़ैक्टरियों के पास कितने-कितने किसानों की ईख का दाम बाको है ?

माननीय उद्योग मा प्रव--नि-नलियित फेक्टियों के पास किसानों के ंख के दाम बाकी है --

१फरेदा		43	£
	•	<i>ሪ</i> ን	किसान
२ल∻मी गंज		१२	
३—-रामकोला पंजाबी		038	
४पडरौना		388	
५—-कठकुइ्यां		400	
६सिवराही		४५०	
७—–घुघुली		₹००	
८सिसवां बाजार	•	200	
९—-छितौनो		१५७	
१०—कैप्टनगंज		۶۶۶	
११पिपराइच डायमन्ड		३००	
१२—गौरी बाजार	•	९२	
१३प्रतापपुर		२ १ ०	
१४भटनः		१५०	
१५देयरिया		७१८	

थ्रा में शन जानं खां--क्या सरकार यह बनला ने की कवा करेगी कि जिन जिन किसानों का हरवा जिन कैन : रियों के वि का क बाकी है उसकी बच्छी के लिये सरकार ने क्या-क्या प्रयत्न किया है ?

माननीय उद्योग मचिव--सरकार ने बहुत प्रयत्न किया है। में उम्मीद करता हूं कि जिस वस्त में इस सवार का जवाब दे रहा हं शायर इसनें से बर्न से किसानों की दाम मिल गये होंगे।

सबं के किनानों में गल्ला वस नी का याजन। में ग्रमन्तीय

*४६--श्री वंश गापाल (ग्रनुपन्धित)--ाया सरकार यह बताने को कृप। करेगी कि अभी तक सुबे में गह हा वसली की योजना के अन्तर्गत कितने व्यायत पकड़े गये, कितनों पर मुकहमे चले, कितनों पर ज्ानाहआ और कितनों को जलखाने की सजा हुई?

माननी । ग्रन्न सन्तिव--एक नका माननीय सहस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिए नःथी 'ख' आगे पळ ५३२ पर)

श्रारे ज्ञान जमा जा--क्या सरकार ने भी इस बात की भी जाच की है कि यह जो गिरपनारियां या दूसरी बातें हुई हैं इसके बारे में सरकारी अफ़तरों ने कहां तक गलती की?

मानना । यन्त स्वित--जहां जहां से इस सिन्तिले में शिकायत आई सरकार ने उन शिकायतों के सम्बन्ध में इन्द्रायरी कराई । कहीं अगर किसी अफसर को गलती सरकार की मालुम हुई तो सरकार ने उन सरकारी अफ नरों को या तो ताक़ीद की, या सखत हिदातत वी या उनके कैरेक्टर रोल में कुछ बातें लिख दी गई।

*४७--आं वंदा गोपाल (अनुपन्धित) -- क्या सरकार को इस बात का पता है कि गःला बसूली नीति के कारण सूत्र के किसानों में बहुत असन्तोष फेलू गया ह ? यदि हां, सो क्या सरकार उसको दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है?

माननीय अन सिचव-सरकार इस सत्यता से भिन्न है कि किसानों के एक तवके ने अनिवार्य सरकारी गन्ला व बली को नापसन्द किया। सरकार उनकी आपत्तियों को यथासंभव दूर करने के उपायों पर विचार कर रही है।

नोट--नारांकित प्रश्न संख्या ४६-४८ श्री रोशन जमां लां ने

ष्ट्रनोत्तर ४७५

ं ४८-- भ्रो वंश नाप ल (यनु मेन्धन) - न्या सरहार खरीक की फरूर में भी गल्ला ब ब्ल करने का विचार कर रही है यदि हा, तो यह योजना कब तह चलेगी ? मानतीय व्यन्त सन्च ब - न्हा, कब प्रारम्भ हो ही च हा है।

पिक्रले दा आर्थिक वर्षों में स्केटेरियट में अवैतनिक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति

- •४९--श्री खुश त्रक्त राय--(क) क्या सरकार यह बतला ने की कृपा करेगी कि पिछ ने दो आर्थिक वर्षों में सेक्रेडेरियट में कितने अवतिनक विशेष अधिकारी (आनरेरी आफिसर्स और स्नेश उद्दो) नियुक्त किये गये ? उनके नाम क्या है और उनकी नियुक्ति किन कामों के लिए की गई ?
- (ख) क्या सरकार यह भी बतलाने की कृश करेगी कि इन अधिकारियों को काम करने के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गयी है?
- (ग) क्या सरकार यह भी बतलाने की कपा करेगी कि इन अधिकारियों ने निछले को आर्थिक वर्शों में प्रतिमास कितना मार्ग – च्या (भता) लिया?

मानना य प्रयान सिचय--(क) पिछले दो आर्थिक वर्षों में निम्नलिखित तीन अवैतनिक विशेष कार्याधिकारी सेकेटेरियर में नियुक्त किये गये।

- १-- श्रीशम्भूनाय चन्वेंदी विशेष कार्यायिकारी, गृह विभाग। माननीय सिचव को राजनैतिक गीड़ितों से सम्बन्धित कार्य में सहायता देने के लिये।
- २--श्रोगोगीनाय दोक्षित, अवैतनिक प्राविन्शियल आर्गेनाइजर पंचायत, युक्त-प्रान्तोय पंचायन राज ऐक्ट के अन्तर्गत पंचायतें संगठित करने के लिये।
- ३--श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा, एम० एल० ए० अवैतिनक विशेष कार्याधि-कारी, शिक्षा विभाग। शहरों में अनिवार्य प्रारित्मक शिक्षा आरम्भ करने उसको बदलने तथा उसका प्रसार करने के लिये और स्कूली पुस्तकों के प्रकाशन के लिये।
- (ख) इन्हें नीचे लिखी सुविधायें दी गईं--
 - १-- भो शःभूनाथ चत्वेंदी -
 - (अ) मुक्त रहने की जगह या उसके बदले १५० ६० प्रतिमास मकान किराये का भता।
 - (ब) सरकारी कार्य के लिये स्टाफ़ कार का उपयोग।
- (स) कार के चलाने के खर्च तथा उसकी देखरेख के लिये १५० रु० प्रतिमास का भत्ता।
- २--श्री गोरीनाथ दीक्षित -
 - (अ) स्टा क कार का उपयोग।
 - (ब) कार चलाने के तथा दूसरे खर्चों के लिये ४५० र० प्रतिमास का भत्ता। ३—-भी रामेश्वर सहाय सिन्हा —
- (अ) हेडक्वाटर में रहने के समय तथा दौरे पर वही भत्ता जो व्यवस्थापिका सभा (लेजिह्डेटिव असेम्बली) के किसी सदस्य को सभा की बंठक के दिनों में मिलता है।

(ब) दस्तर के कि ने ३० ०० मासिक किराये पर मकान।

(ग) इन अकतरों को निम्निशिधित सकर अत्ता प्रतिभास दिया गया--

श्रो शम्भ्ताथ चनुर्वदी	श्रो गोपी ॥थ दीक्षित श्री	रामेक्वर सहाय सिन्हा
क्रु आठ पा		रु० आ० पा०
मार्च १९४८ ई० १७२ ० ०	कोई सफा मई-ान १९४८ ई० भलानी जलाई '' दिशागना अगस्त ,,	७६९ ९० ५३४ ०० ४२६ ५०
मई ,, १४२ o o अगस्त ,, १५४ ८ o	ी सन्तर ,, अक्त्बर ,,	४८५ १० ० २४० १४ ०
अक्तूबर ,, २४५ २ ० नवम्बर , ३०० १ ०	भ्वम्बर ,, दिपग्बर ,,	484 83 0 848 4 0
दिसम्बर ,, ५८००	ानपरी १९४९ ई० फर∙ती ,,	२८३ ११ ० ५१७ १३ ०
योग १०२० १३ ०	मार्च ,,	805 60
याग १०२० १३ ०	यागः	- ४८५८ १

श्रव उगाहा योजना पर सरदारी व्यय

*५०--श्री खुशवक्त राय--(कः) का सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष भी अन्न उगाही पोजना के अतगंत कितना कितना गेहूं, जो य चना एकत्रित किया गया?

(ख) क्या सरहार यह नी बताने की कृता करगी कि इस अन उनाही योजना पर सरकार ने कुल कितना रुपया क्या किया?

माननीय ग्रन्न माचिय-- (क) गेह १,५०,३४१ टन चना १,४७,०८४ टन जी २७,२६८ टन

(ख) ११,६८,६९,०५८ रु० खर्व हुआ हो।

श्रा ख़ुदात्रकत राय--क्या सरकार यह बत जाने की कृपा करेगी कि गेहं, चना व जौ पर प्रति मन उनके प्राप्त करने में कितना खर्च हुआ ?

माननीय ग्रन्न सन्तिव--पही आंकड़े जो विये गए हैं इनको जोड़ लिया जाय तो आप सिसाब निकाल सकते हैं।

श्रो खुशबक्त राय-अध्यक्ष महोत्य, इसमें जो आंकड़े दिये गएहें उसमें गेहूं, चना, जौ पर अस्त्र-अच्य कितना खर्च हुआ ? यह में जानना चाहता हूं ?

माननीय अश्र सिव्यन—अलग-अलग खर्च का सवाल नहीं उठता है क्यों कि जो खरी-वारी होती है वह एजेंटों के द्वारा होतो हैं और जो अफसर गेहूं के लिये नियुक्त किये जाते हैं उन्हों के द्वारा चना व जौ को भी खरीदारी होती है, इसलिये अलग-अलग यह आंकड़े नहीं निकाले गए हैं कि गेहूँ और चना, जौपर कितना खर्व हुआ। बहरहाल जो आंकड़ें दिए गए हैं अगर उनको जोड़ लिया जाय और जितना रुपया खर्च हुआ है उस से उसको भाग कर लें तो उनको पता चल सकेगा कि प्रति भन कितना खर्व हुआ। भ्रो खुशतक्त राय--क्या सरकार कृषा करके बतलाएगी कि गेर्ं, चनाव जी की खरीदारी में अलग-अलग कितना खर्च हुआ ?

माननीय स्पीकर--इसका जवाब दे दिया गया है। अभी उन्होंने जवाब दिया है कि जितने कार्यकर्ता है वे खरीदारी का काम एक साथ करते हे। इसी मे जवाब आ गया।

श्रा रिवान ज्ञां खां——क्या सरकार यह बतला ग्रेगी कि ग्रेन प्रोक्योरमेट का जो खर्च बतलाया गया है उसमें रेबेन्यू विभाग के उन अफिसर्स की तनख्वाहें भी शामिल है मसलन पटवारी कानूनगो वगैरा कि जिन्होंने गल्ला वसूली में काम किया है ?

माननीय ग्रन्न सचित्र--नहीं।

श्रा रे शिन जभा खां--क्या तरकार यह बतलाएगी कि अगर इन खर्चों को भी उसी खर्च मे जोड़ दिया जाय तो ग्रेन प्रोक्शोरमेंट पर कुल खर्च की मन के हिताब से कितना हुआ ?

माननीय ग्रन्न सिचव—पटवारी और दूसरे अफ्सर कि जिनका जिन्न किया गया, वह अनावा गेन प्रो ।योरनेट के काम के और भी काम करते हैं उनक मुख्यतः दूसरा काम रहता है इसिलए वह खर्च जो पटवारियों वगैरा पर होता है उस खर्च के आंकडे इस खर्च में नहीं जोडे गए हैं।

श्रो मुहम्मद् ग्रसरार ग्रहमद्—-क्या गवर्नमेट बतलावेगी कि इस खर्व में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एस० डी० ओ० व तहसीलदार वगैरा को जो भत्ता दिया गया है, क्या वह इसमें शामिल नहीं है ?

माननीय ग्रन्न सचित्र--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरा पर जो खर्व हुआ है वह ज्ञायद इस में शामिल न होगा। मै ऐसा अनुमान करता हूं।

र्था मुहम्मद् ग्रम्गर ग्रहमः — क्या यह भी सही है कि एस० डी० ओ० तहसीलदार वनायब तहसीलहार का भी भता व तनश्वाह इसमें शामिल नहीं है ?

माननीय ग्रन्त सचित्र--में इसका नोटिस चाहता हूं।

*५१-५२-अा राम जी सहाय--[स्थगित किये गए।]

न्यू काउन्सिल्सं रेजिडेन, लखनऊ में पानो की कुव्यवस्था

*५३—-श्रो फखहल इस्लाम—-क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसका क्या कारण है कि न्यू काउन्सिलर्स रेजिडेंस मे पानी म्युनिसिपल बोर्ड लवनक से नहीं लिया जाता और इसका सरकार स्वयं प्रबन्ध करती है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सिच्य के मभामन्त्री (श्री लताफत हुसैन)— लखनऊ वाटरवक्सं में पानी की कभी की वजह से काउन्सिस्स रेजीडेंस में पानी म्युनिसिपल बोर्ड से नहीं लिया गया और सरकार इसका खुद इन्तिजाम करती है।

*५४--%। फाबरुल इस्छाम--नया सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले १८ महीने में न्यू काउन्सिलर्स रेजिडेंस का पिम्पा स्टेशन कितनी बार और कब कब फेल हुआ और प्रश्नेक बार भितने घंटे तक पानी की सप्लाई बन्द रही ?

श्री लताफन हुसौन—इनके बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा गथा है। जब कभी पम्प फल हुआ उसको फौरन ही ठी कराया गया और आदिम में के जरिये पानी पहुंचाने का मुनासिब इन्ति ग्राम किया गया।

श्री फखरुल इस्लाम—क्या सरकार बरायेगी कि ऐसा मोटर क्यों फिक्स क्रिया गया है कौं सिलर्स रंजीबेंस में जो बार बार खराब होता है और जिससे पानी नहीं मिलता है ?

श्री लताफत हमन--मशीन पर मि ।। एतबार नही होता लेकिन जहा तक हो सकता है इतजाम किया जाता है ओर अगर बराबी होती ह तो ठीक कर दी जाती है।

श्री फवरुर इस्ता ।--स्वा नरतार जाननी है कि जो मोटर जमावा गया है वह बहुन खराज और पुराना है और जिसकी वजह से वह बार-जर फेंक नो जाता है ?

आ लिनाफन समान--ऐनी होई इनिका सरकार के पास नही ह कि यह बेकार है. अगर बेकार होना तो उसे नही लगाया जाता।

श्री खुशवक राय-स्या नरतार को मालूम है कि इपी तरह का पान पुराने काउन्सिल रेजीडेन्स में भी उगा हुआ है वहा कभी होई शियापन नहीं हुई?

श्री लगफन हुसेन--जी हा, ठीवा है।

श्री मुहस्मर अवगर प्रहमद-- स्या मरशार बतलावेगी कि इस मुसीबत को इर करने के लिये और पुरसिकल पानी की मालाई का सर धर ने कोई इंतजाम किया है या

माननीय भावंजितिक निर्माण मिन्नव (श्री महामद इब्राहीम)--नम्बर ५५ का जवाब देख लीजिये।

१५०--श्री फरवरुल इन्लाम--इसके सुधार के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रा लतीफन हुसन--एक टयूब वेल का इन्तिजाम किया गया है जो करीब करीब तरयार होने को है उस समय तक जब तक त्यूब वेल तैयार हो पानी पहुंचाने का आरजी इन्तिजाम किया गया है। उसके अलावा एक और पमा लगा दिया है ताकि वन्त जरूरत पर उससे काम लिया जा सके।

बदायूं, पंटा भादि जिला में यादव आति का जगायम पंशा करार देने के विषय में सरकारी नोति

*५६-श्री भारत निह याद्वाचार्य(ग्रनुपिश्यत)-क्या बदापूं, एटा, फर्रुखाबाद और मैनपूरी जिलों में सरकार यादव (अहोर) जाति को जरायम पेशा करार देने का विचार कर रही है ?

माननीय प्रध न मचिव--जी नहीं।

*५७--श्री भारतसिह धादवाचार्य (श्रनुप्रिश्त) -- यवि हां, तो इसके क्या कारण है ?

माननीय प्रधान मचिव--यह प्रश्न नहीं उठता।

के केटेरिकट के चपरासियों को संख्या एवं उनके लिए बवार्टरों का प्रबन्ध

*५८--श्रो इन्द्रद्व त्रिपाठी--क्या सरकार यह बताने को कृता करेगी कि से केटेरियट में कुल चपरासियों की संख्या कितनी है?

श्री लताफत हुमेन--६६१।

*५९--श्रा इन्द्रदेवात्राः ठी--म्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन चपरासियों के निवास करने के लिए कितने सरकारी क्वार्टर है और इस समय उनमे कितने चपरासी निवास करते हैं ?

श्री लताफत हुसैन--१३७ सरकारी क्वार्टर हे और उनमें १४१ चपरासी रहते है। *६०--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस समय लखनऊ मे किराये पर मकान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन तथा खर्चीला है ?

श्री लनाफन हुसैन-जी हां।

*६१--श्री इन्द्रदेव विवाही--क्या बड़े बड़े शहरों में चपरासियों को मकान का भत्ता दिया जाता है ? यदि हां तो सेकेटेरियट के उन चपरासियों को जिन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जा सके हैं, मकान का एलाउन्स पर्यो नहीं दिया जाता है ?

श्री लताफत हुसैन-जी नहीं।

*६२—श्रो इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार सेकटेरियट के चारासियों के निवास करने के लिये कोई प्रबन्ध करने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

श्री लताफत हुसेन--जी हां, जैसे ही कोई ठिसाने को जमीन चपरासियों के क्वार्टर बनाने लायक मिल जाय।

शिक्षा विभाग के जिला इन्सोक्टरों के यन्तरत हरिजन यध्यावकों का यनुपात

*६३—भ्री गर्जाघर प्रसाद (ग्रनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि शिक्षा विभाग के जिला इन्सेक्टरों के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों में जिलेवार कितने अध्यापक लिये जा चुके हैं और उनमें कितने हरिजन हैं?

*६४--क्या सरकार यह भी बताने को कृपा करेगी िः इस वर्ष (सन् १९४८-४९ ई०) राजकीय पाठशालाओं के लिए जिलेवार कितने हेड मास्टरों का चुनाव हुआ है और उन में कितने हरिजन है ?

माननीय शिक्षा सिचिव के सभा मंत्री (श्री महफू जुर्रहमान) -- एक सूची जिसमें जिलेवार सूचना दी गयी है माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पष्ठ ५३३ पर)

*६५-६७--श्री गजाधर प्रसाद (अनुपिस्थत)-[स्यगित किये गये।]

जिला आजमगढ़ के गांधी हरिजन गुहकुल की सरकारी सहायता

*६८--श्री गजाधर प्रसाद (अनुपरिथत) -- क्या सरकार को यह जात है कि जिला आजमगढ़ में एक गांधी हरिजन गुरकुल चल रहा है ?

श्री महफूजुरहमान-जी हां

*६९--श्री गजाधर प्रसाट (र नुपिस्थत) -- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह श्री गांधी गुरुकुल को सालाना कितनी सहायता देती है ?

श्री महपू जुर्रहमान—यह संस्था अस्वीकृत होने के कारण कोई नियत वार्षिक सहायत नहीं पा रही है। इसकी स्वीकृति का प्रश्न विचाराधीन है। इस संस्था को ६६,००० ६० का अस्थायी अनुदान गत वर्ष दिया गया था।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य — क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह प्रक्र जो विचाराधीन है इसकी स्वीकृति का कब तक निर्णय हो जावेगा?

श्रो महफूजुर हमान--वहां टीचरों की ट्रेनिंग के वास्ते स्कूल खोला गया था और जब डिपार्टमेंट को इतमीनान हो जायगा कि वह ठीक काम कर रहा है तो उस वदत उसको रिकगनाइज कर लिया जायगा।

*७०--भ्रो गजाधर प्रसाद (ग्रजुपिश्यत)--(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक नयीं स्कीम के अन्तर्गत जिलेबार कितनी राजकीय पाठशालायें गांबों से अलग बसी हुई हरिजन बस्तियों में बन चुकी हैं ?

(ख) क्या सरकार उन बस्तियों का नाम और पता बताने की कृपा करेगी?

नो :- प्रकृत संख्या ६३ - ६४ तथा ६८ - ७० श्री द्रारिका प्रसाद मौर्र ने पूछे।

श्री महफू जुर्र हमान--एक सूर्वी जिसने जिलेवार सूचना दी गयी है मानने य सदस्य की मेज पर रक्षी है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३३ पर)

पोलोभीत इत्यादि में शराब की दृकानों की बिक्री तथा नीलाम

*७१ — - आ मुहम्म द यस गर चहम द — न्वा सरमार बताने की कृपा करेगी कि पी कीभीत, देशनगर, खनारा, पकरिया व सराय की शराब की दूकानों पर सन् १९४७ - ४८ ई० में कितने गैलन शराब की बिक्री हुई ?

माननीय प्रधान सिचिव के सभा मन्त्री (श्री चरण निनः) — सन् १९४७ – ४८ ई० मे पीलीभीत शहर की शारत को दूकातों पर निम्नलिखिन विकी हुई —

> देशनगर .. ३,६५० गैलन खरुरा .. १,३१२ गैलन पकरिया .. २,०८० गैलन सराय .. ३,१७२ गैलन

*७२-- अ। मृहम्मद् ग्रम् राग्या प्रम्य-म्या यह सव है कि देशनगर वाली शराब की वृकान सन् १२४७-४८ ई० में ४३,००० के को नीलाम की गयी ?

श्रो च रेग सिंह-- जी हां, यह सब है।

*७३--श्री मृहम्मद असरार बहुमद्--क्या यह सब है कि १९४८-४९ ई० में पक्तिया और सराय वाली शराब की दूकानों के नीलाम की बोली कमशः ३७००० ६० और ३६,००० ६० तक आयी परन्तु फिर भी इन का नीलाम स्थगित कर दिया गया! यवि होतो ऐसा क्यों किया गया?

श्री चरण सिंह—पहसव है कि सन्१९४८-४९ ई० में पहरिया की शराबवाजी दूकात की सब से अधिक बोलो ३७००० र० तथा सराय की ३६,००० र० की हुई परन्तु १९४७-४८ की अपेका या बोलियां बहुत कम थीं अतत्व नी जान स्थानत कर दिया क्यों कि इसते सरकार को हजारों रुपये की हानि थी। सन् १९४७-४८ में या दूकानें कमशः ४४,००० र० और ४५,००० र० में नीलाम हुई थीं। परिवर्तित नीलाम में यह दूकानें कमशः ४७,००० र० और ५१,००० र० में सबते अधिक बोली बोलने बालों के नाम नीलाम कर दी गई।

*७४--श्री मुत्ममद अमराग अतमद--क्या यह सब है कि सन् १९४८-४९ ई० में खकरा पतिया सराय ओर बिठौरा की शराब की दूकानों की बोली एक साथ ली गयी और नीराम बोली बोनने वाले व्यक्ति के नाम खतम कर दिया गया ओर बाद को बोली बोलों नले के बनाए हुये व्यक्षिों के नाम उनरोक्त चार दूकानों पर अन्य अलग लिख दिये गरे ? यहि हां तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्रा चरण सिह—-अध्य निलां के ठेकेवारों में से किसी एक ने खकरा पकरिया सराय और विठौत द्वाराब की दूकानों की एक बोडी सवा लाख रू० की दी परन्तु उसकी बोलो नहीं मानी गई और ठेकेवारों से हर दूकान के लिये पृथक-पृथक बोडी बोलने को कहा गया। तब ठेकेवारों ने अला अला बोलियां बोली।

*७५--- हो मुह्म्मद इम्रनरार इम्रामद्--क्या यह सब है कि एह ठेकेबार ने उक्त नीलान के बाद शीघ हो जिलाबीश की शिकायत लेकर खुलो जांच की और नोलाव स्वीकार न करने की प्रार्थना की किन्तु वह प्रार्थना अस्वोकार कर दी गयी ?

श्री चा गा सिंह--जी हां यह सब है कि एक किदार ने उक्त नीलाम के पश्चात् जि शबीश को प्रार्थना-पत्र देहर जांच करने और नीलाम स्वीहार न करने की प्रार्थना की थी पर यह प्रार्थना जिलाधीश द्वारा भशी प्रकार जाच करने और प्रार्थी के वकील के। सुनने के परवात उक्त शिकायत को निराधार पाया गया। अत. प्रार्थना अस्वी ।र कर दी गई।

'७६--श्रा म् मद ग्रम्रा श्राम्य न्या यह सच है कि उक्त ठेवार ने उप-रोक्त मामले में जान के लिए लिखित जिमायन प्रधान सिन्न, मादक-कर सिन्न, एक्साइन कमिजनर ओर स्थानीय भाष्टा बार निरोधक समिति को भी भेजी थी? क्या उपरोक्त अनिशों ने या एक्माइन कमिश्नर ने या भ्राश्वास निरोधक मिनि ने कोई जान की? यदि की, तो उन्हार श्रा परिणाम निकला?

श्री चर शिमह—कार्य लय के लेख्यों से यह विदित होता है कि छोटेलाल नाम-एक व्यक्ति ने प्रार्थना—पत्र भेजा था जिस पर िलाधीश से रिपोर्ट मागी गई। एः प्रार्थना—प माननीय प्रधान सचिव के पास भेजा गया जिम पर कमिश्नर बरेजी को जान करके रिपोर्ट देने का आदेश हुआ।

199--श्रा प्रत्याद् प्र र ग्राच्या-- (क) श्या यह सब है जि जानतीय प्रथान मन्त्री रे रहेलखंड डिबीजन के फिमरनर के पान जाव तरों को आदेश दिया ?

- (ख) क्या उपरोक्त किन्नर महोदय ने कोई जांच की?
- (ग) यदि की, तो क्या नतीजा नि कला?

थ्यो च्या सित -- (क्) माननीय प्रयान सिंड ने किमिन्नर बरेली डिवीजन को इस मामले की जाच करने का आदेश दिया।

- (ख) कमिश्नर महोदय ने जांच के पश्चान् मातनीय प्रशान सचिव को अपनी रिणोर्ड भेज दी थी।
- (ग) उन्होंने माननीय प्रधार मिचव के पाप यह स्पिट भेनी कि प्रार्थना-पत्र निराधार है और यह जमा कर दिया जाय।

"७८—-भ्रो मुहमार सम्मर। र इहमद्— (क) वया यह सत्य है कि एक्साइज किमश्नर ने ठेकेदार की असल अर्जी जिलाधीश पीलीभीत के पास अपनी रिपोर्ट देने को ६ मार्च, १६४८ ई० को भेजो थी?

- (ख) यदि हां तो क्या जिलाधीश ने कोई रिपोर्ट भेजी ?
- (ग) यदि हां लो क्या और कब ?

श्री चरण सिट-(क)एक प्रार्थना-पत्रश्री छोटे लाल ठेकेदार द्वारा आबकारी किम-इतर के पास भेजा गया जिसे उन्होंने जिलाधीश पीलोभीत के पास अपने अनुमोदन (एन्डो संमेन्ट) संख्या ७२८, ता० १४अगस्त, १८४८ ई० द्वारा रिपोर्ट के लिये भेजा। कोई प्रार्थना-पत्र ९ मार्च, १८४८ ई० को नहीं भेजा गया।

(ख) और (ग)-जिलाघीश के पास किमश्नर रहेलखंड डिवीजन ने भी उक्त मामले में जांच व रिपोर्ट देने का आदेश भेजा था। पूरी जांच करने के पश्चात् जिलाधीश ने किमश्नर डिवीजन के जरिये ९ जून, १९४८ ई० को आवकारी शिमश्नर के पास रिपोर्ट भेजी कि शिकायत निराधार है और जमा शर दो जाय।

*७९ -श्रा मुहम्मट प्रसराग ग्रह पट--(क) क्या यह सच है कि जिलाधीश, पीली-भीत ने एक्साइज आफिसर की रिपोर्ट पर उस ठेकेंदार हो जिसने शिकायन की थी ब्लैक लिस्ट कर दिया ?

(ख) क्या सरकार उपरोक्त ठेकेदार को एक्साइज अधिकारी के खिलाफ शिकायत और एक्साइज आफिसर की ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही और रिपोर्ट की प्रतिलिपियां मेज पर रखने की कृपा करेगी?

Į

श्री चर्गा निह—(क) मई सन् १९४८ ई० मे जांच के समय जिलाधीश ने उपरोक्त ठेके-दार को आबकारों के कान का ठेका लेने के अयोग्य ठहराया और तत्पश्वात् वह ब्लेक लिख कर दिया गया।

(ख) किसो भो ठेके तार को बलैक लिस्ट करने की कार्यवाहो गुप्त रक्खी जाती है। अतः खेद है कि सरकार इन पत्रों को साधारण गया दिखाने मे असमर्थ ह।

शाग्दा कंनाल से बाराबंकी जिले की अवर्याण्त पानः

*८०-प्रा हरप्रसाद मत्यप्र मी--क्या ग तमेट को मारूम है कि शारद कैनाल से इस वर्ष बाराबंकी जिले को पानी बहुत कम और रास्य से नहीं मिला है ?

श्रो लताफत हुमेन-इस वर्ष बाराबंको जिलेक शारदा केनाल से पानी समयपर ओर पिछले वर्षो से अधिक मिला है।

*८१--श्रा हरप्रसाद साय प्रमी--क्या यह सही है कि इस वर्ष नहरों की गहराई और चौड़ाई को बढ़ा दिया गया था तब भा पानी कम आया ?

श्रा लनाफन हुसेन-- गहरों को गहरा ओर वौड़ा करने के कारण बाराबंकी जिले को इस वर्ष काकी पानी मिला।

श्री हरप्रसा उसत्य मा -- स्या सरकार ने इस बात भी खोज करने की कोशिश की है जब जिन्ने में पानी ज्यादा मिला तब उत्तर्भ वितरण में कहां पर श्रुटि हुई जिससे किसानों को आम जिकायत पानो की कनी की हुई ?

माननीय सार्व जनिक निर्माण सन्त्रिय—किसानों को पानी न मिलने की आम शिकायत कोई पैदा ही नहीं हुई।

*८२--श्रा हरप्रसाद सत्यप्र मा--बाराबको जिलेको सन् १९४५, १९४६, १९४७ व १९४८ ई॰ में प्रति वर्ष कितरा-कितना पानी विशा गया और नहरों के चौड़ा और गहरा तथा विस्तृत होरे के बाद सन् १९४६ ई॰ में कितना पानी दिया गया ?

र्थाः जताफन हुसेन-- प्रन् १६४५ से १६४८ ई० तक बाराबंकी जिले को निम्नलिखित सूची के अनुसार पानी मिला-

ार्ष	खरीक दिल्लियन क्रोबिक फिट	रवी निक्ष्याक यूबिक फिट
१९४५	५३४०	8300 580
१९४७ १९४६	६४८० ३५७०	३१८५
5838	8860	2

सन् १९४६ ई० में सरी हमें ४८२० जिलियन क्रूबिक फिट पानी विया गया। रबी फसल की सूबन मार्च सन् १६५० ई० के बाद प्राप्त हो सकेगी।

*८३--श्री हरप्रसाद सत्यप्रमी-- ग्या गवर्नमेंट ने इस वर्ष सांवां आदि जायद फ़रजों को नहर का पानी न देकर क़तई रोक दिया है।

था लताफन हुसेन--जीन हीं। सरकार ने जायद क़स र यानी सांबां आदि को पानी देना बंद नहीं किया है।

*८४-- प्रा हर साद स यम्रो मी-- ग्या गवन रेंट अधिक अन्न उपजाने के लिये पानों की व्यवस्था करने की और गान देने का विवार रखती है ? श्री लताकत हुसेन—सरकार ने नहरों को चौड़ा और गहरा करना शुरू कर दिया है जािक पानी का बटवारा ज्यादा अच्छी तरह हो सके और पानी का नुकसान कम हो और उन इलाकों में भी सिंवाई हो सके जिनमें अब तक पानी नहीं पहुंच रहा है, और ज्यादा गल्ला पैदा हो सके।

वैद्यों को ट्रोनिंग देकर मेडि कल कालेजों की अन्तिम परीक्षा में बैठने की सुविधा

*८५—श्रो दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार वैद्यों को एक या दो वर्ष ट्रेनिंग देकर अधिकल कालेजो की अस्तिम परीक्षा में बैठने की सुविधा देने पर विचार कर रही है ?

माननीय यन्न सचिव--जी नहीं।

श्रो जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि उन्होंने इसको उचित क्यों नहीं समझा ?

माननाय अन्न सिचव-अभी मेडिकल कालेज में जो शिक्षा हमारे स्टूडेंट्स को दी जाती है वह वैद्यों को जो शिक्षा दी जाती है उससे भिन्न है। इसीलिए अभी इसके अपर कोई निर्णय नहीं किया जा सका है। गवर्न मेंट आफ इंडिया ने एक चौपड़ा कमेटी नियुक्त की थी। उसकी सिफारिशों केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के सामने आई हुई हैं। इन सिफारिशों पर कोई विवार नहीं किया गया है और जब तक वह मंजूर न कर ली जाएं तब तक यह संभव नहीं कि इन दोनों तरह की प्रणालियों के स्टूडेंट्स को एक ही संस्था में पड़ा सकें और एक ही प्रकार की उपाधि प्राप्त करा सकें।

*८६-श्रो दीनद्यासु शास्त्री--यदि उत्तर हां में हो, तो किन-किन आयुर्वेदिक कालेजों के स्नातकों को यह सुविया दी जायगी?

माननीय ग्रन्न सचिव--प्रश्न नहीं उठता।

*८७--श्रो दीनद्या छु शास्त्री--क्या सरकार आयुर्वेदिक के प्रचार की दृष्टि से स्वास्थ्य विभाग में पृथक आयुर्वेदीय डाइरेक्टर रखने की व्यवस्था पर विचार कर रही है?
माननीय ग्रन्त सचिव--जी नहीं।

*८८--श्रो दीनद्यालु शास्त्री--न्या सरकार स्वास्थ्य विभाग में आयुर्वेद के आषधालयों के निरीक्षण एवं उन्नित के लिए डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति करने जा रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

माननोय ग्रन्त सच्चित्र—जी हां। एक डिप्टी डाइरेक्टर मेडिकल एन्ड हेल्य सर्विसेज आयुर्वेद की नियुक्ति हो गई है और डिप्टी डाइरेक्टर ने अपने पद का चार्ज भी ले लिया है।

सहार अपुर अपुनिसिपैलिटी द्वारा वाटर वक्स व इ नेज के लिए प्रान्तीय सरकार से ऋण की मांग

*८९--श्रो दोनद्यालु शास्त्रो--क्या यह सत्य है कि सहारतपुर म्युनिसिपैलिटी ने बाटर वक्स व ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से कुछ लाख रुपये का लोन मांगा है ?

माननीय स्वशासन सचिव (श्री ग्रात्माराम ग विन्द खेर)--जी हां।

*६०--श्रो दीनदया छु शास्त्री--सरकार के पास यह मांग कब आई थी और इसके निर्णय में अभी कितना समय और लगेगा?

माननीय स्वशासन साचिव—पहले सन् १६४६ में ओर दुबारा अप्रैल सन् १९४८ ई॰ में । वर्तमान आर्थिक कठिनाई के कारण सरकारी सहायता नहीं वी जा सकती। इसलिये बोर्ड को सूचित किया गरा है कि वह इन योजनाओं को वर्तमान काल के लिये स्थिगित कर दे।

एटा से कासगंज तक सरकारी मोटर गाडियों का चालू किया जाना

*९१--श्री दीनद्यालु शास्त्री--एटा मे कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियां कव से चालू की गई हैं ?

माननीय पुलिस सचित--२३ मई सन् १९४९ ई० से ।

*९२-श्री दीनद्या छु गास्त्री--इस मार्ग पर कुल किनती सरकारी गाड़ियां चल रही है ?

माननीय पुलिस सचित्र-१२ बसे ।

*९३--श्रादीनदयालु शाच्त्री-क्या यह सच है कि अब भी दव पार्ग पर एक व्यक्ति को अपनी गाडी चलाने हा अधिकार सरकार ही ओर से मिला हुआ है ?

माननीय पुलिस्म सिचित-प्रह सच नहीं है, परन्तु इस सड़क पर एक पण्जन को पहले से पी॰ एम॰ जी॰ की ओर से डाफ ले जाने का ठेका मिला हुआ था। उनका ठेका अब भी जारी हैं और वह डाक टैक्सी में ले जाते हैं। यह ठेका ३० जून सन् १९५० ई० को समाप्त हो जायेगा।

श्री खुश वक्त राय-क्या सरकार उन मज्जर का नाम बतलाने की कृपा करेगी?

माननीय पुल्लिम मचिव-माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो मे उनको दफ्तर में बतला दुंगा।

*९४—श्री दीनद्याञ्ज ज्ञास्त्रा--इस व्यक्ति को यह धिशेष मुविधा किन आधार पर दी गई है?

मातनाय पुलिस्न सिन्त्रय--इनको होई निशेष सुविना नहीं वी गई है। पिछले प्रश्नों के उत्तर में जैसा बताया गया है डाक निभाग के अधिकारियों के लिनने पर उनकी डाक ले जाने की इजाजत वी गई है।

*९५-९६--श्री टीनद्यालु शास्त्री-- [अगले विन के लिये स्थगित कर विये गये]

ऋषीकेश में खाद बनाने की योजना

*९७—श्री दीनदयालु शास्त्रो—क्या सरकार की ओर से पिछले दो वर्षों में बाद बनाने की कोई विशेष योजना ऋषी केश में जारी की गई थी ?

माननीय कृपि स्चिव-कोई विशेष खाद योजना नहीं जारी को गई थी।

*९८--श्री दोनद्याञ्ज ज्ञास्त्री-इसयोजना को कार्यान्वित होने में कुल कितना क्यय हुआ?

माननीय कृषि मचित्र--प्रश्न नहीं उठता ।

*९९-श्रो दीन ऱ्यालु शाम्त्रो-इस योजना के अनुसार कुल कितना खाव बना और उसकी बिकी में कुल कितनी आमदनी हुई ?

माननीय क्वांष सन्विच-प्रश्त ही नहीं उठता ।

ऋषोकेश के निकट भवस्थित पशुकाक का भाय-व्यय

*१००—श्री दीनद्यालु शास्त्रो—आज कल ऋषिकेश के निकट में अवस्थित पश्-लोक में क्या आय हो रहा है ?

माननीय क्रिष सिचिव--युक्त प्रान्तीय सरकार की आनरेरी एडवाइजर श्रीमती मीरा बैल की वेख-रेख में ऋषीकेश के पास पशुलोक आश्रम में वो योजनायें चालू की गई हैं यानी (१) ऐसे मबेशियों की रक्षा करना जिनका दूध सूख गया हो और (२) बूढ़े और बेकार मवेशियों के लिये कन्सेन्द्रेशन कैम्य खोलना। मरे हुये जानवरों की खालों को महकूज रखने और उनकी हिड्डयों की खाद बनाने का इन्तजाम कर दिया गया है। भटकते हुये मवेशियों से फैलने वाली छूत की बीमारियों पर पूरे तौर से काबू पाने के लिये इस इलाके में भटके हुये मवेशियों को पकड़ने का इन्तजाम कर दिया गया है। इस तरह पकड़े हुये कुछ मवेशी उनके जायज दावेदारों को खर्चे का मुआवजा देने पर दे दिये जाते है और बाकी यवेशी आम नीलाम करके बेच दिये जाते है।

र्श्वा दीनद्या स्त्र शास्त्री—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि अब तक ऋषीकेश के निकट अवस्थित पशुलोक में मरे हुये जानवरों की कितनी खाले इकट्ठा हुई ?

माननीय कृषि सचिव--इसिल्ये नोटिन की जरूरत है।

*१०१--श्रोदीनद्यालु शान्ती--पश्लोक का वार्षिक आय-व्यय क्या है ? माननीय कृषि सचिय--मालाना आय व खर्व हर साल के लिये नीचे दिया गया हें--

	आय	खर्च
	रु०	হ ০
१९४७-४८	কুত নहीं	२२,१८९
१९४८-४९	८,१२६	१,३४,५५६
१९४९-५० (३० सितम्बर, १९४९ ई० तक)	४ - , १ २ १	६०,८२३

^{*}१०२-- आ दो व्यान्त शास्त्री-- त्या यह सच है कि जिस जंगल मे पशुलोक बसा है वहां जानवर मुक्त में चरते थे और अब उन्हों जानवरों पर भारी कीस चरायी के जिए ली जानी है ?

माननीय कृषि सिचिय—जी नहीं जंगलात विभाग उन स्थानीय लोगों से चराई की फीत लेता था जो अपने मवेतियों को वहां चराते थे। उन जानवरों के लिये कोई फीस नहीं ली जाती थी जो अपो आखिरी दिनां को विताने के लिये कन्सेन्ट्रेशन कैम्प में भेजें जाते हैं और उन मवेशियों के लिये नाममात्र की फीस ली जाती है जो ड्राई सालवेज सेन्टर (सूखे मवेशियों के सुरक्षा केन्द्र) में ऐसे मालिकों द्वारा लाये जाते हैं जो उनका दूर सूख जाने के बाद उनको पालने का खर्चा नहीं बर्चास्त कर सकते।

*१०३--श्री दीनटया छु शाः श्री--इस पशुलोक के चारों ओर तार लगाने में कुल क्या व्यय हुआ है ?

माननीय कृषि न्यविव--७,५४० ह०।

[प्रश्रातर का समय समाप्त हो ज ने के कारण शेष प्रश्न अगले दिन की कार्य सूची में रख दिये गये]

सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारो विनाश ग्रौर भूमि व्यवस्था-बिल*

श्री द्वारिका प्रसाद मोर्च-श्रीमान् जी, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि भूमि-व्यवस्था बिल पर जो विवाद हो रहा है वह आज समाप्त किया जाय और कल से इस बिल पर घारा प्रति चारा रूप से विचार किया जाय। अतः आज के लिये विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय और वह १५ मिनट से अधिक न हो और आज विवाव समाप्त कर कल से धारा-धारा विवाद कर लिया जाय।

^{*} ९ जनवरी सन् १९५० ई० ही कार्यवाही में छवा है।

श्री सुहतान ग्रास्म खा—-हुनूरवाका अभी यह तजिशे आई त कि आज इस बिल पर बहस लाम हो जार ओर आज की तकरीरों के लिये १५ मिनट का वक्त मुकर्रर कर दिया जाय में निहायत अदब से आ के मासने यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह तरीका सही नहीं होगा, इसलिये कि यह विल बहुत ही अहम बिल ह ओर बहुत से लोग अभी भी इस पर तकरीर करना चाहते हैं। जिन लोगों को पहले तकरीर करने का मोका मिला उनके उपर वनत का कोई तार्यन नहीं था, लेकिन अब जो तकरीर करेगे उनके उगर १५ मिनट ताय्यन करना मुनासिब नहीं हैं। अगर एक दो दिन ओर नकरीर जारी रहे तो इसमें ऐवान का कोई नुकसान नहीं हैं ओर न गर्ननंमेट को दिक्वत होगी। इस पर पूरी तरह से बहस करने का मौका देना चाहिये ताकि हर पहलू रोशनों में आ जाय। इसके लिये कम से कम एक दो दिन और उदाया जाय और उन्ने की की पावर्यों न लगार्ग जाय कि नकरीर कितने वक्त की होनी चाहिये।

माननीय रपीकर—मं इस प्रस्ताव को अभी नहीं छे रहा हैं। हर एक सदस्य को अधिकार है कि जब वह उचित समारे कि बहस समाप्त हो तो उतके लिये सामने रखे लेकिन जो प्रस्न श्री द्वारिक। प्रसाद जी ने रखा है पह उस तरह का नहीं है इस िये न उसकी बहस बन्द करने के प्रस्ताव के रूप में नहीं ले रहा हूं।

श्री वारेन्द्र शाह--माननीथ म्यीकर महोदय, मैने भन्न का । उ आखीरी समय अपना विचार प्रकट करने में लिया। आज में अपनी छोटी नी तकरीर के साथ अपना भाषण खत्म करूंगा।

आज अभो माननोय सदस्य मौर्य जी ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि अब इसकी बहस आज खत्म करके आगे से क्लाज बाई क्लाज, सेकेण्ड रोडिंग ले लिया जाय।

माननीय रूपाकर--आपको इस विषय पर कहने की जरून नहीं। आपको अपने विषय पर जो कुछ कहना है, कहे ।

श्री वीरेन्द्र शाह—में यह कहना चाहता हूं कि यह जमीवारी उन्मूलन बिल जो पेश हैं वह एक गलत सी चीज है। अभी थोड़ें दिन हुये एक ऐक्ट 'प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट' के नाम से बना है उसमें यह तजवीज थी कि जितने भी फारेस्ट (जंगल) ह उनको सरकार द्वारा नियंत्रित करके ठीक तरह से चलाया जाय।

अब इस बिल में ऐसे फारेस्ट्स भी ले लिये गये है। उनके बारे में में यह कहगा कि ये काइत की जमीन से मुख्तलिफ चीज हं। जिस तरह से और रोजगार है उसी तरह से लकडी का भी एक रोजगार है और दिवर यानी लकड़ी का रोजगार करने वाले लोगों ने बहुत से जगल मोल लिये। जमीदारियों से इन जंगलों का कोई ताल्लुक ही नहीं है और न असामियो से ही इनका कोई ताल्लुक ओर जहा तक मध्यवर्ती का सवाल है वह भी इसपर लागू नहीं होता। में सरकार से कहंगा कि लोगों ने लाखो रुपया अपना इस काम में लगाया है क्योंकि वे रोजगार करना चाहते थे लेकिन आज इस बिल के द्वारा आप उनको खत्म करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जमींदारियों की तरह उनको थोड़ा सा मुआविजा दे दिया जाय। इस तरह से आप उनको हरूप लेना चाहते है। सरकार का उद्देश्य इस बिल से यह था कि मध्यवितयों को हटाकर किसानों से सीधा संपर्क कायम करें लेकिन इस विषय मे वह उस उद्देश्य से बहुत दूर जा रही है। इसिलिये में सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर सरकार इन जंगलों को लेना चाहती है तो उसके एवज में पूरा मुआविजा मिलना चाहिये। या तो वह उनको पूरी कीमत द वरना उनके जंगलों को न लें। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है और वह फारेस्ट्स को लेकर चला नहीं सकती। जो प्राइवेट लोग सुबे की और आपकी मदद के लिये काम कर रहे हैं उनको काम करने का मौका दीजिये और आगे चल कर अगर आप उनको लेना ही चाहते है तो पूरा मुआबिजा देकर उनका ले लीजिये। जिस प्रकार आपने कानपुर की

बिजली कंपनी हो मुआविजा देकर, ओर माकूल मुआविजा देकर लिया ह उनी तरह से आप जाको हो हो। इन फारेन्ट्स हो आप उसी प्रकार कम्पेसेशन देकर ले जिन प्रहार प्राप औं कंपिटेलिम्द्य की वीजां हो लेने हैं यागी बाजार ही रेट से आय उनहा मुआविजा दे।

इस जिल्के बारे में एक दूसरी तजबीत में यह ारता वाहत हूं कि जापने बिहार के मुबे की तरह जनींदारा के ऊपर जो कर्जा है उसके बारे में कुछ नहीं ह। कर्जो पर दनका क्या असर यहेगा उस ही आपने इस बिल में कोई रूप नही खी है। मेने सेलेक्ट अमेटी के मोके पर सकार का ध्यान इस अर क्लिया था तो सरकार ने यह कहा था कि वे जल्द से जल्द इस बारे में एक बिल लायेगे। में सरकार का च्यान फिर इस ओर दिलाऊगा और निवेदन पर्लगा कि इस बिल के पाम होने हे पूर्व ही सरकार वह बिल भी ले अ'ये औ: उसमे यह रखें कि जी कम्पेसेशन उस जारीन पर जी कि उनके अर्ज में साइकारों की गई है जमींदारों को मिले वही रुपया साहकार लोग पाने के हों। इन्कन्बर्ट स्टेट ऐक्ट के मातहर जो डिपिया हुईहै और उन टिपियो डिग्रीहोल्डर को जो हिस्सा दिया गया है हिस्से पर उस कम्यलेशन आये उससे ज्यादा पाने का हकदार डिग्रीहोल्डर यह मेरी जाती तत्तवीज नही है। यह तो आपव अदालनो द्वारा ही क्रशर दिया गया है कि किसी के कर्ने में जमीदारी का किनना हिम्ना शाटा जाय। वह सालाना किस्त अदा करता है। जितना हिस्सा किश्त में लगा है, उसी का कम्पे-सेशन उसको मिलना चाहिये।

तीसरी बात मुने यह अर्ज करनी है कि सरकार ने मालगुजारी वसूल करने के लिए बहुत ब म अिवकार ले रक्खा है। उसमे यह भी लिखा है कि सरकार अगर नाहे तो वह एक व्यक्ति को मुकर्रर करके लगान वसूल करवा मकनी है। यह चीज दका २५७ में है। में इसका विरोध करता हू। जब आप तमोदारियां खत्म करना चाहने हैं, जब आ म व्यवित्यों को हटाना चाहते हैं तो सरकार क्यो ऐसे अधिकार लेती हैं, इसका उद्देश्य हमको मालूम होना चाहिये। एक व्यक्ति को माल्गुजारी वसूल करने के लिए कलेक्टर चाहे तो मुकर्रर करले यह अधिकार उसूल और सिद्धांत के खिलाफ सरकार ने लिया है। इसमें में देखता हूं कि आगे चरकर यह होगा कि गांव सभा और अपने कर्मचारियों द्वारा जो वसूली का इंग आपने रक्खा है वह तो ताक में रखले रह जायेगे, और आप की पार्टी के लोग मुकर्रर हो जायेगे, इस तरह आप नये जर्मीदार और नयी जर्मीदारियां कायम करेंगे। उनके जित्ये आप वसूली करायेगे और उनका परसेंटेज आदि भो तय करेंगे। में इसका विरोध करता हू और आशा करता हू कि सरकार इस अिकार को ही लेगी। भवन को भी यह अधि जर सरकार को नहीं देना चाहिये। अगर यह अधि जर सरकार को मिलते ह तो इसके माने यह है कि हमारी जर्मीदारियों को नध्य करके आप नये जर्मीदार चाहते हैं औ: अपनी पार्टी के जमीदार चाहते हैं।

वौथी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि यह बिल इतना अहम और जिटल है कि इसके लिए में सरकार से अनुरोध करूंगा कि पास आप मले ही करले ले नि इसका अमल दूसरे चुनाव तक के लिए रोक लीजिये ताकि आम जनता ओर किसानों को पूरे तौर से मालूम हो जाय कि हमको इस बिल से क्या फायदे है और क्या नुकसान है ओर फिर वह अपको इलेक्ट करके भेजें, उस वक्त इस पर अमल होना चाहिए। इस बिल की बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो किसानों को मालूम नहीं है। अगर आज हम और अप जल्दी जल्दी में इस बिल को पास कर लेते हैं तो नतीजा यह होगा ि दूसरी सरकार आयेगी और वह इसको बदलेगी जिससे तमाम लिटोगेशन, तमाम मुकदमाबाजी ओर तमाम उथा क-पुथल होगा। सरकार ने जब यह ऐलान कर दिया है कि हम अगली जुलाई में एलेश्शन कराने वाले हैं तो एक साल का माम का है। कमो सेशन वगैरह तय करने में तो एक साल वैसे ही लग जायेगा तो किर आप इस निद्धांत को हो क्यों नहीं मान लेते हैं कि इस बिल पर अमल

[श्रो वीरेन्द्र शाह]

लेक्शन के बाद होगा। आप इगलैंड में देखिये वह। स्टील का जो बिल था उपको हाउस आफ लाइ स न मजूर नहीं किया है बिल्क उन्होंने यह मंजूर किया है कि जनरल एलेक्शन के बाद उन बिल के ऊपर अमल होगा। उसी तरह आप भी तय करें कि आप इस बिल का निकाज जनरल एलेश्शन के बाद करेंगे। अगर आपको सपोर्ट मिलेगा और आप बहुमत में चुने जायेंगे। उसके पहले इन पर अमल करना में समझता हूं कि जनता के लिए हित कर नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से आप तमाम आपस के पग है झझड और परेशानिया बढायेंगे।

मैं इसी सिलिसि हे में यह भी अर्ज हर देना चाहन हैं कि उन लोगों ने होशिश की कि जनता को इस विक के गरे ये बा अप ओर बन हाना चाही है लेकिन उम यह देखते हैं कि तरहार के छोटे—छोटे कर्म बारी लोग एर तरह से कोशिंग करने हैं और हमारे प्रवार में हनारी मदद करने हरारी तरक जो लोग आने वाले हैं उनको धनकाया जना है उनको हर गरह से दबारा जाता है। में उदाहरण के का में पवारा राज के इस्ते हर का है। किया हा ओरिशिन ह नोटिय आरको पह हर सुन देन वास्ता ह निसमें उन्होंने गांव सभा के एक पब को जिन पंचों को जनता ने पहले ए हेक्शन में एडल्ट पर्म बाइज की बिना पर सब की राय से चुन कर भेजा है लिखा है। ओर उनके उत्तर आर इस तरह से नियन्त्रण करना चाउते हैं। सरहार उनसे चोकोदारों को तरह हम कराना चहती हैं, पड़वारियों को तरह काम कराना चाहनी हैं। इससे यह भारना नालूम होतो है कि जनता ने उनको प्रवानन्त्र के उसुत्रों पर बुन कर गांव सप्ताओं में भोजा है लेकिन आप उनको स्वांत्र (इडिपेडेंट) और निष्म होने का मौहा नहीं ने कि वे इस बात को सप्तों और वहां के लोगों को सप्तावों। में इस नोटिस को पड़ देश हु जो कि जालीन जिले के एक इसे ने हर मान स्वांत्र है। इस नोटिस को पड़ देश हो कि जालीन जिले के एक इसे ने हर मान स्वांत्र है।

पंचयात सता जगन्तरपुर। जनही जावन रिरोर्ट मिली है कि आप जमीदारी उत्मलन के बिरोप में प्रवार करते है। आग जाराब दें कि क्यों ने आपके निरद्ध नियम ६२ (ख) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। इसहा उत्तर एक सन्ताह के अन्दर मेरे कार्यारुय में आ जाना चाहिय नहीं तो समझा जावेगा कि आपके ऊपर आरोग सही है। अब आप देखिये कि जमींदारी उन्मूलन बिल के विरुद्ध में बहुत से लोग है जो समप्रते हैं कि जमींदारी एवालिशन का यह बिल बिलकुल नाकिस है और ठीक नहीं है और उमलिये उसका विरोध करते हैं। लेकिन आपके कर्मचारी लोग कहने हैं कि तुमने उस बिज का विरोध किया इस यजह से तुमको पंच के पद ने हटा देंगे। अब आप ही कहियें कि यह कितनी बड़ी जबरदस्ती है। प्रधान मन्त्री जो ने भी कहा था कि आ। अःम पहिलक में कहिये, जनता को समझाइये और अगर जनता इसको ठीक नहीं समझती है तो उसकी खबर हम।रे पास ा जानी चाहिये। लेकिन अब हम जनता से क्या कहे और कैसे कहें ? जनता के पंचों को तो इस तरह ने बमकाया जाता है कि में न्या कहूं। यही चीज नहीं है में देखता हूं कि बहुत से अमीदारी की मोटरें रिक्शोजीशन तक की जाती है लाहि टामीबार लीग सरकार का कहीं पर विरोध न कर सके। कई जिलों से ऐसी खबरें आई है कि अगर कोई जमींबार सरकार के इस जमींबारी एबालिशन फंड के इतट्ठा करने में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता है तो वहां के कलेक्टर लोग उन ज्मींदारों की मोटरें रिक्वीजीशन करते हैं और उनको हर तरह से मजबूर किया जाता है कि वे सरकार का साथ दें। जिस जमीं ग्रार के इलाके में दस गुना लगान की वस्त्री ठीक से नहीं होती है तो वहां के सरकारी कर्नचारी लोग उस जमींदार को हर तरह से परेशान करते हैं। यहां तक कि दफा १०७ का मुकदमा करके या और और तरह से परेशान करते हैं। उन पर मुकदमा चलाया जाता है, उनको धमकाया जाता है ताकि वे उनके साथ आ जायं।

माननाय मात्न मचित्र--माननीय स्पीकर साहर, मै राजा सहब से जानना चाहता इ कि वे कृपा करके ऐसे आदिमिशे के नाम बतला दे।

श्री वीरेन्द्र शाह—अगर मिनिस्टर साहब नाम जानन। चाहते है तो में उनके पास नाम लिखकर भेज दूगा। दो चार आदिषयों का नाम तो में बता ही दूगा। सुल्तानपुर जिले के मुरली पर सेठ वाउली पर दफ १०७ की कार्यवाही चल रही है। ओरो के नाम म बाद को अपके पास लिएकर दे दगा कि कितने आदिमयों पायह कार्यवाही हो रही है और उन हो परेशान किया जाता है। इतने ज्यादा ादम है कि जिनका नाम याद रखन बड़ मुद्दिकल है। आपको दि होगा कि मेरे कल आपको इस न बन्ध में बतलाया थ। इसके अलावा म यह जानमा चाहना हू कि सरकार इस नरीके से इम बिल के बरे में हर एक आदिनों को जानने से क्यो रोक लगानी है। अगर यह जनता के हित में बिल है तो जनन को समझाने में क्यो रोका जाता है। में यह यूछना चाहना हूं कि अगर किमानों के फ यदे के लिये यह जिल है तो किसानों को ठिक बात तान से क्यो मना किया जाता है विशेष करते तो जह तो किसानों को कि जमीदारी उन्मूलन बिल के जिरोग में कुछ हिस्सा न लो। अगर स कार की तरफ से कोई कड जमा होना और उसके लिये वे विरोध करते तो यह तत कुछ समझ में भी आ सकनी थी, लेकिन जमीदारा उन्मूलन िल के बरो में में जनता से कोई आदिरों सच्बी बात नी कह सकना है, आखिर इसने जना माने हैं री जनता से कोई आदिरों सच्बी बात नी कह सकना है, आखिर इसने जना माने हैं री

म सरकार को यह बन कना बाहना हु कि इम तरी के से वह ज्यादा का सयाब नहीं हो सकते। और अत में में यह बता दू कि यह विल जाप भले ही पाम कर ले जाय, लेकिन जनता अगर यह लमनने इ कि इनसे उसका हित नही होगा तो यह बिल जरूर आपको अमेड करना होगा, रह फरना होगा और बदल देना होगा। इसके ऊपर में आपको यह फिर कहंगा कि आप इस पर सोचे और गोर करे। 'जितनी चीजे इसके अन्दर दी हुई है वह सिर्फ इस वजह से लाई गई है कि च्कि जमीदारी खतम हो रही है इसलिये जितनी चीजे लूट की मिले लूट ले। आपने यह कहा था कि हम पुआवजा देकर मध्यवर्ती को खतन करेगे, लेकिन जो दूसरी चीजे है जैसी हमारी सायर की आमदनी है, बाजार है, हाट है, परती है, बागात है यह सब चीजे हे उनको आप मुक्त में ही ले लेन है परती का आप कोई मुवाबजा नहीं देते हैं। आपको अगर मध्यवती को रंाना है तो अप मुआवजा देकर मध्यवर्ती को हटा दीजिये। प्राइवेट प्रापरटी से आप क्यों टच करते है, उसको क्यों हड़ाना चाहते है। धन्दिरो की जाय-दाद है, प्रापरटी है उसको भी आप इसी के साथ झपट लेते है। वह तो कम से कम इस लूट में तामिन नहीं होना चाहिये। जमीदारी ही आपके लिये काफी है। धर्म के ऊपर तो आप हाथ नत डालिये। अन्त में म सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि आ ने बार-बार यह कहा है कि उम जमीदारों को बरबाद नही करेंगे और न उनको बरबाद करना चाहते है। जमीदारो से अप हमददी रखते है। नो हम आपकी हमददी क्या देखे जब हम प्रैक्टिस मे यह देख रहे है कि जो चीजें आप छोड़ सकते थे उनको भी आप लिये लेते है बल्क जमींदारी के खतम करने के साथ आप उसकी सब चीजों को लेलेते है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इम ात पर ध्यान देगी कि इस बिल का निफार्ज बक्त तक न किया जाय तब तक कि दूसरा एलेक्झन न आ जाय ।

श्री इन्द्रदं । त्रिपाठी — श्रोमान् यघ्यक्ष महोदय, जो बिठ सरकार की तरक से जमीदारी विनाश और भूमि व्यास्था के रूप में भवन के सामने पेश है उस पर अभी तक जो बहस मुबाहिसा हुआ उसकी सुनने के बाद कुछ विशेष कहने भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मानीय मान्न मंत्री महादा को मुबारकवाद देना में अपन वर्तव्य समप्तना हूं कि उन्होंने जिम तरीके में इस बिल को पेश कि मा है, जिससे कि हमारे सुबे में इसके सम्बन्ध में जो कुछ काम होगा वह दुनिया में और हमारे देश में और सरकारों के लिये एक बेनजीर चीज होगी। सेलेक्ट करेटो की रियोर्ट है और उसमें जो कुछ सुधार किये गये है और कुछ लोगों ने अपने

िश्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

मतभेद के नोट उसमे दिये हैं उनको भी मने गोर से पढा। राश्वशकरला ह जी ने जो पहला अपना मतभेद का नोट दिया है उसमें एक पात ऐसी लिखी है जिसके अपर मझे कह निवेदन करने की जरूरत हुई। म यह नहीं जानता कि रानशं करणात जी वसे सफल किसान ह। यह जरूर जानता हूँ कि घह एप सफल पकील है, बानून का ज्ञान उनको जरूर है, लेकिन जो नोट उनका है उसको देखकर मुझे यह मालम हुआ कि प्रक्टिकल खेती का ज्ञान उनको नही है। उन्होने लाभकारी खेती के सम्बन्ध में राफ कह दिया है कि एक हल के लिये सत्रा छः एकड ही लाभकारी खेती हो पकती है उससे ज्यादा नही हो सकत । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है ओर कहा है कि आठ एकड एक हल की बहुत लाभकारी खेती नहीं हो सकती । मेरी समझ में नहीं आया कि यह हिमाब उन्होंने कैसे लगाया है। मं तो समझता हूं कि एक उल की खेती जिमां साधारणत अच्छे बैल ही उस से असारी के साथ १० तका तक की खेरी फायदे के राध्य की जा सकती है। कुछ लोग अवना मिर हिला रहे हैं, अगर उनको एम नात मे इनकार है तो मैं उन को जरा तफमील के गाथ बत राना चाहता है। हालांकि वनत कम है और इसिएए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूगा। मैं जानता है कि जिम किसान के गाग एक हल है और अच्छे बल है तो वह कम से कम ३ ए हड धान की खेती कर सकता है। यान के खेत जब जोते जाते ह जब खब बारिश होतो रहतो है और उस वक्त रबो के खेत नहीं जोते जाते। धन की खेती के अलावा जन ऊख की खेती का सा। ल आता है यानी जब ऊख की खेती के लिए हल चलता है तब भी किमान के बैल खाकी होते है और उनके लिए कोई दूसरा काम नहीं होता। इस तरह एक एकड़ ऊल ३ एकड धान और बाजरे के खेती के लिए भी थो जी जुटाई की जरू-रत होती है आर भी कई चोजे खरीफ की खेती मे है। इस तरह से ५ ए , इमें ऊख और खरीफ की खेती हो सकते हैं। इसके बाद में नानता है कि रबी की ऐता में केवल ५ ए.इ ही ए हल के लिये रहती चाहिए। इस तरह से प्री फमल के लिए ओर हर जिस के लिए एक ह ; बाठे किसार के पास १० एक इ लाभकारों जमीन खेती के लिए मुनासिब कही जा सकती है।

अब आगे चल कर हमारे भाई जापाल मिह जी व श्री हारिक, प्रसाद जी मोर्य के मतमें के नोट हैं। मोर्य जी वकील हैं और लय गर्ज सिंग जी भी उन से कान नहीं हैं और वह हर बात के लिए अपने की माहिर सपझते हैं। उन लोगों ने गरीब यादत तारों की भलाई के ख्याल से कुछ अच्छी अच्छी बाते उस में लिखी हैं। में जिनके लिए उन को मुबारकबाद देता हू और समझता हूं कि गरीबों की तप लीफ़ हूर करने भी आग उनके दिल में जरूर हैं। लेकिन वे भी एक दायर से आगे बढ़ गए हैं। यह चीज ठेक नहीं हैं। जब कभी हमकों बोलने और लिखने की इजाजत हो तो हमें अपनी जिम्मेद री को महसूस कर के काम करना चाहिए। उन्होंने जो तबियत में आया घर्स ट गारा और जो तियत में आया वह कह डाला है। यह बीज मेरे ख्याल से ठीक नहीं हैं। हर चीज की एक केंद्र होती हैं और दायर, होता है और उसी के अन्दर सब को रहना चाहिए। आप फरमाते हैं कि जो स्वयं हल जोतता है उसी को जमीन पाने का अधिकार है। हमारी सरकार ने ४ साल का समय महज इस बात के लिए लिया कि हर पहलू पर उसकी अच्छी तरह से गौर करने का मौका मिल सह। हालां कि अब तक सरकार ने ओ कुछ किया है उस में उनकी राय है, उनका सहयोग है और उनको महोनों सेलेक्ट कमेटी में बहस करने का मौका वियागया है, लेकिन न मालूम वयों वे ऐसा समझते हैं।

लेकिन फिर भी वह अपने मतभेद को जाहिर करते हैं सरमार ने यह सीचा कि यह तो मुश्किल चीज है कि जो हल अपने हाथ से जोतता हो वही जमीन पाने का अधिकारी हो इसिलये सरकार ने उदारना से काम लिया और यह साफ कर दिया कि जो अपने हल से और अपनी मेहनत से काइत करता है या मजदूरों से काइत कराता है वह काइतकार है और जमीन रखने का अधिकारी है। इन मेरे लायक दोस्तों को जो शोषित संघ के भी नेता है यह

समझना चाहिये कि अ। खिर हमारे सुबे में बड़ी तादाद गरीब खेतिहर मजदूरों की भी है वे कहां जायंगे और कसे दसर करेगे या तो वह यह कहने कि जमीन का फिर से बटवारा हो और जितने भी हमारे सुबे से खेटी करने वाले लोग हैं उन सब को जमीन की जाय। तब मजदूरों का सवाल नहीं आता। लाखों की तादाद से ऐसे लोग है जिन्हें इस नयी भूमि व्यवस्था के लागू होने के बाद भी हम जमीन नहीं दे सकते हैं। वे वेचारे आखिर कहां जायेगे। उनको मजदूरी कहां विलेगी? आखिर वे खेतों ही पर मजदूर करेगे और उन लोगों के खेतों पर मजदूरी करेगे जो अपने हाथ से जमीन नहीं जीत सकते। जमाने के लिहाज से हर एक मजदूर को ऐसी पूरी मजदूरी देनी पड़ेगी जिससे जिस तरह खेत का मालिक गुजर कर सकता है वैसे ही मजदूर भी। जहां तक आधिक मामले का लाल्लुक है वहां इस तरह से करना ही पड़ेगा। जनां तक श्री रोशन जमां खां की तकरीर का सवाल है में समझता हूं कि हमारे समाजवादी भाई तो इस सभा से चले गए लेकिन अपनी औलाद छोड़ गए। इम कहने से तेरा गलत भतलब न तमाया जाय।

श्री फिल्किल इंग्लाम--क्या अनिबरेल मेम्बर का यह कहना कि अपनी औलाद छोड गए पर्नियामेटरी है।

मानतीय स्पोका--कुछ अच्छा तो नहीं है।

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—मैं माफ़ी चाहता हूं। वे उत्तराधिकारी छोड़ गये। इनमें से कुछ तो बोठ चुके ओर कुछ ऐसे हैं जिनको अभी बोलने का मौका नहीं मिला है। मुक्क आजाद हो गया वह इस डिमोक्रेमी और प्रजातन्त्र का नारा लग ते हैं ओर आजादी का मतलब ऐसा समुद्रवन लगाते हैं जिसकी कोई मीमान हो और इसी तर के उनकी तकरेर हुई है।

में एक साहित्यिक या धार्मिक कथा का उदाहरण देना चाहता हूं। यह राजा भोज के सम्बन्ध में है। जब राजा भोज के बाल्यकाल का जमाना था तो राजा भोज के चचा मुंज के एक लड़का था जो राजा भोज के बराबर अच्छा नहीं था। मुंज जी को यह लगा कि भोज अगर जिन्दा रहेगा तो मेरे लड़के को गद्दी नहीं मिलेगी। इसलिये भोज को उन्होंने जंगल में जल्लादों के लाथ भेजा और यह हुक्म दिया कि इसको मार डालो ताकि हमारे लड़के को गददी मिले। जब जल्लाद लोग भोज को जंगल में ल गये और मारने का समय आया तो भोज ने कहा कि भाई हमको क्यों मारते हो। उन्होंने कहा कि आपके चचा मुंज ने हमारे जिम्मे यह काम सुपुर्व किया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक चिट्ठी ले जाइये और मेरे चचा को दे दीजियेगा और मुझे मार डालिये। वह चिट्ठी लेकर जब जल्लादों ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि इस पृथ्वी पर र।वण जैसे और युधिष्ठिर जैसे बड़े-बड़े महापुरुष पैदा हुये, बड़े-बड़े राजा पैदा हुये लेकिन वह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। यह मालूम होता है हमारे चचा मुंज जी के साथ जायगी क्योंकि इस पृथ्वी से उनको बड़ी महब्दत है। उन जल्लादों ने उनको मारा नहीं और कहा कि आप भाग जाइये। हमें त्या आती है, हम आपको नहीं मारते। वह चिट्ठी ले जाकर उन्होंने राजा मुंज को दे दिया और भोज अपने इघर उबर विचरने लगे । मुंज को उस चिट्ठी के पढ़ने से बड़ा धक्का लगा और कहा कि अगर भोज नहीं आये तो मैं आत्म-हत्या करूंगा। अ। खिर भोज खोज कर लाये गये और उनको गद्दी मिली और मुंज जी जंगल में चल गये। कहने का मतलब यह है कि गद्दी हासिल करने के लिये ऐसे घृणित काम के लिये भी मनुष्य को कटिबढ़ नहीं होना चाहिये जैसे इन दिनों समाजबादी भाइयों का रवैया हो रहा है।

मुझे रोशन जमां साहब की तकरीर का जैसे का तैसा जवाब नहीं देना है बल्कि में तो यह कहूंगा कि दो वर्ष और कुछ महीनों का जो हमारा आजादी का बच्चा है उसको मुन्ज को तरह जिन्दा जमीन में गाड़ने की जो तैयारी हमारे समाजवादी भाई कर रहे हैं जैसा कि

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

मेरी समझ में आता है तो मैं उनसे कहता हूं कि इस चीज पर वे ठंड़े दिल से विचार करें जिसमें आगे उनको मुन्ज की तरह परचात्ताप करना न पड़े। इस तरह से कोई चीज किसी को हासि उनहीं होती। अपनी तकरोर के बौधान में उन्होंने कुछ आजादी और प्रजातंत्र की बात की और अभी हनारे राजा साहब बीरे-द्रशाह ने भी जो आजादी के बें उनासक अपने को समझते हैं कहा। में समझता हूं कि उचित्र सीना के अन्दर हवारी सरकार ने जितनी आजादी दिया है दुनिया में शायद ही कोई ऐसी सरकार हो। जहां पर ऐसी आजादी मिली हो।

हमारे देश में जितन जान्त हैं और जितनी जान्तों की सरकारें हैं उनमें भी कहीं पर इस तरह उदारतापूर्वक आजादी नहीं दी गई है। जहां तक पंचायतों का सवाल है पंचायतों के जब चुनाव हो रहे थे गांवों के लोगों ने अपने गांव में बैठकर एक सुलह के साथ हर फिर्हें के लोगों को लेहर, अच्छे अच्छे लोगों को लेहर, चुनाव करने की तैयारी को। हपारे लगाजवादी भाइयों ने उस नक्शे को बिगाड़ा । कहीं शोबितों के नाम पर कहीं छोटे बड़ों के नाम पर, कहीं कम्युनिस्टों के नाम पर और कहीं समाज-वादियों के न म पर तोड़फोड़ करके हर जगह करीब-करीब चुनाव कराये गये । और अब हमारी सरकार के ऊपर यह दोवारोपण किया जाता है कि हर मामले में सरकार की तरफ से पंचायत के लोगों पर पाबन्दियां आयद हो रही हैं। जहां तक सभापितयों और गांव-सभा के मेम्बरों का सवाल है में जपने जिले की बात अज्छी तरह जानता हं और दूसर जिलों का भी मुझे कुछ ज्ञान है। सभापतियों को और गांव-सभा के मेम्बरों को पूरी आजादी है कि बह अपना लगान दस गुनान वें और दूसरों को भी समझायें कि देस गुना लगान न दो । किसी के ऊपर कोई एकावट नहीं। लेकिन जहां अवालती पंचायत का सवाल है अवालती पंचों के और अवालती सरपंचों के अपर पार्ववियां है और वह पातन्वियां भी पहले नहीं थीं अब आयद को गई हैं। ब इ मयो ? उनकी भी बजूहात हैं। अदालतो पंचों ने और अदालती सरपंचों ने, मेरा यह अतलब नहीं कि सब के सब कुछ अदालती पंचों और कुछ अदालती सरपंचों ने जब नाजायज तरीके से दबाव डालना शुरू किया उन लोगों पर जो वस गुना लगान जना क लो थे मुझे मालूम है कि उन लोगों के अवर फर्जी मुकहमे बनाये गये और बेंचों के सुपूर्व किये गये और सजावें भी की गयीं। ऐसी हाजत में जैसे हाकिमों को ओर मकर्वमें करने वाजों को चाहिये तन व्वाह पाने गले हों या आनरेरी हों पाबन्दियां हैं कि वे इन मामलों में दखलन्दाओं न करें। वैसे ही इन अदालती पंचों और सरपंचों के ऊपर भी पावन्दियां आयद की गई हैं। और उनको यह इक्म दिया गया है कि आप इस मामले में कोई दखलन्दाजी नहीं कर सकते। वे तटस्थ रह सकते हैं इसकी सतको आजादी है अगर हमारे राजा साहब और रोशन जमां खां साहब या चाहते हैं ति सभी की मनमानी आजादी रहे तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए इसमें कोई इन्कार नहीं है। और सरकार ने भी यवि उनकी बात मान ली तो फिर उनकी कोई शिकायत कैसे सुती जायेगी ? जब वे कहने लगेंगे कि ये जितने सरकारी हाकिम है ये सबके सब दसग्ना लगान वाखिल करने के लिये बेजा वबाव डाल रहे हैं।

इसिलयं सरकार ने निहायत गौर और विचार करने के बाद यह तरीका निकाला है कि जिनको कुछ फैसला करने का अधिकार है उन लोगों को इस मामले में तटस्थ रखा जायें ओर उनके ऊपर इस प्रकार की पार्विदयों आयद की जायें। आपने कुछ और भी जिक किया। आधी बात आपने बताई और आधी बात नहीं बताई। कुछ पटवारियों का जिक श्री रोजन जनां खां साहब ने किया। उसमें गाजीपुर का भी नाम आया। में उनसे प्रकृता चाहता है कि यह क्या मुझते गाजीपुर के बारे में ज्यादा जानते हैं या उन्होंने कोई ठेका ले रखा है कि जो कुछ यह कहते हैं वह

सच है और जो में कहूंगा वह गलत होगा। एक प्रवारी को कई दिन कहा गया कि तुम दस गुना लगार जमा करने के लिये बहुत कोशिश करते हो और बर्तमान सरकार के भक्त वने हुने हो। तुम अपनी आदन संभालो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। दूसरे दिन जब वह पटवारा अकेला जा रहा था तो समाजवादियों ने उसको लाठियों से मारा और उसके हाथ पांव की हिंदुडयों को तोड़ डाला। अब भी वह एटवारी अस्पताल में पड़ा हुआ है।

("शेम शेम" की आवाज आई)

यह कोई राज या चोरी भी बात नहीं है। बढि डाकुओं ने उने माना तो में कहंगा कि अब जो नई भर्ती लगाज्यादियां के गिरोह में हो रही है नुझे अब है हि जिलों में जितने चोर और प्रदनाश और डाक है उनमें से शायद ही जोई भर्नी होने से यब जाये। जो नई भर्ती हो रही है वह इसी तरह के लोगों के हो रही यहां तक कि पंच और सरपंचों ने किसानों ने बुलावर शहा है कि अगर तम लोग दस गुना लगान जमा करने एग नाम लोगे तो यह जो धान की फसल तुम लोगों के खेतों में लगी है वह नहीं रहेगी। पचासों तर्को गत इस शिस्म की हो चकी हैं कि गरीब किसानों को धान की फसलों को नत्र भर्नी होने वाले समाज-वादियों मे से बदमाश लोगों ने काट ली है। इस तक्त की जिलों मे शार्यवाहियां हो रही है : हलारे राजा माहब जो अभी बड़े जोश और खरोश के साथ यहां पर बोल रहे थे वह अगर ऐसी आजारी चाहते है तो मैं राजा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा होश संगाले क्योंकि अभी तक वे राजा साहब है। दो-चार महीने अभी जमींदारी खत्म होंने में लगेगे। उनको एक कदम घर से बाहर निकलना मुहिकल हो जायेगा और वह सभा में आकर इस तरह बोल भी न सकेगे। मुबारकबाद दें सरकार को कि अब भी इस अमन व चैन के साथ उनको घुमने फिरने का मौका है। ऐसी मनम नी आजारी किसी काम की नहीं होती । मैं एक वत जो सन्तान आलम कां साहब ने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में उठाई थी कहना चाहता हैं। बरु एक पुराना दुखड़ा है। इसमें उन्होंने कहा है कि अब तो जमींशरी खेस जरूर होगी।

आगे आप फरमाते हैं कि सरकार ने बड़ी गल्ती की। जमींदारों को रियाया का नेता बनाया जा सकता था और कातूनी हंग से जामींदारियों में ऐसा सुधार किया जा सकता था जिससे उनकी रियाया फले फूले। में उनको महात्मा गांधी जी के उस ख्याल की तरफ ले जाना चाहता हूं। महात्मा गांथी हमारे देश के ही नहीं वरन संसार के शिरोमणि थे। सबको मालून है कि महात्मा जी जमींदारी को खत्म करना नहीं चाहते थे। वह चाहते कि जमींदारों को मौका दिया जाय और वह स्वयं अपना सुधार करें ताकि वह जमींदार के रूप में न रह कर ट्रस्टी के रूप में रहें और अपनी आमदनी का एक बहुत मामूली और मुनासिब हिस्सा अपने भरण पोषण के लिये रखकर बाकी रकम रियाया के फायदे के लिए खर्च करें मेरा ख्याल है कि काफ़ी मौका मिला लेकिन जब कोई सुधार नहीं हुआ तो आजिज हो परलोकवास से पहले महात्मा गांधी ने महज कहा ही नहीं, बिल्क आशीर्वाद दिया कि जल्द से जल्द अब जमींदारों को खत्म कर दिया जाए। इसमें किसी का दोष नहीं। अब में यह कहना चाहता हं कि सबसे बड़ी खुशी इस बात में है कि जल्द से जल्द जमींदारी खत्म की जाये।

मुझे इस निलिसले में अब दो एक बातें कहना है। मुझे कहना यह है कि सरकार ने जो जमींदारों को मुआविजा देना निश्चित किया है वह कुछ मुझे ज्यादा मालूम होता है। कोई जिद की बात नहीं है। हमारे चचा मुन्ज यानी समाजवादी लोग जो कुछ कहते हैं मेरा वैसा मतलब नहीं है वह अगर १ अरब रुपये पर मचले हुए हैं तो १ अरब से ज्यादा न दिया जाय।

(इस समय १ बजे समा स्विगित हुई और २ बज कर ५ मिनट पर श्री नकीसुल हसन 'डि॰टो स्थीकर' की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डिस्टी स्पीकर--उठने के पहले श्री इंद्रदेव त्रिपाठी तकरीर कर रहे थे। वह मेहरवानी करके अपनी तकरीर जारी रखें।

श्रो इन्द्रदेव त्रिपाठी--प्रस्तुत बिल में मध्यवित्यों को जो मुआविजा देने का विधान है उठने से पहले मैंने उसके सम्बन्ध में कहना शुरू किया था। उसमें दूसरे लोग क्या कहते हैं खासतीर से हमारे सनाजनादी भाई जो आजकल इस सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनके कहने की तरफ हमको कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक उचित तरीके पर हमको उस पर फिर से विचार करना है। इस बात को हम लोग अन्छी तरह से मानते हैं कि समाजवादियों के नेता आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने एक अरब जमींदारों को मुआविजे के रूप में देने के लिये कहा था। अब जो शरह सरकार ने तैरार की है उस के मुगाबिक करीब डेड़ अरब राया जमींदारों की मुआविजे के रूप में देना पड़ेगा। सरकार की आर्थिक स्थिति जाहिरातौर से अच्छी नहीं हैं खराब है। काश्तकारों से दस गुना के हिसाब से जो रक्तम तखमीने में आई है सम्भव है वह वसू हो जाय। मेरी भी अपती राय कोई उसमें कमी करने की नहीं है। उस रकम को वस्ल करना चाहिये। लेकिन वह सब को अब रकम यह जो शरह मुकर्र है जमींदारों को मुआविजा देने के रूप में उसमें कमी करने की जरूरत है। पांच हजार रुपये तक के जमींदारों को मुआविजे के अलावा पुनर्वातन अनुदान भी देने का निश्चेय किया गया है। इसके अलावा छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जर्नीवारों तक को मुआविजा के रूप में आह गुना देने का उसमें विवान है। मेरी राय में सरकार को थोड़ी दिक्कत तो जरूर होगी लेकिन तरोके में कुछ तब्बोली करने की जरूरत है जिससे करीब-करीब पचास करोड़ रूपये की बवत हो सके जिसको खेरी की उन्नति में और किसानों की भलाई में खर्च किया जा सकता है। मेरी राय यह है कि जो तरीके में तब्दे ली की जायगी उस में कोई दिक्कत न पड़ेगी। जहां तक आठ गुना मुआबिजा देने का ताल्लुक है उसमें जो बहुत बड़ें -बड़े जमींदार हैं, एक-एक लाख रुपये के मालगुजार हैं, उनको अगर आठ गुने के हिसाब से दिया जाय तो आठ लाख रुपये, दस लाख रुपये दिये जा सकते हैं। मेरी सनझ में इस रकम की कोई सीमा मुकरंर हो जानी चाहिये और में समझता हूं कि चार लाख से ज्यावा जिसी जमीवार को या किसी मध्यवर्ती को मुआविजे के रूप में न दिया जाय। और दूसरा यह ख्याल किया जाय कि जिस जमीबार के ज्यादा जमीन कब्जे में हो उसकी मुआबिजे की दर में बहुत कमी कर दी जाय। उसको आठ गुना न विया जाय । जिस जिसके कब्जे में ज्यादा खेत हैं जिस हिसाब से ज्यादा है उसको उसी हिसाब से कम दिया जाव । मुआदिजा देने के माने यह होते हैं कि उस व्यक्ति का जिसका गुजर-बसर उस जमीवारी से होता था उसको कुछ गुजर-बसर करने के लिये दिया जाना चाहिये। अगर किसी मध्यवती के पास सीर में, जोत में, सीर व खुदकाइत, शरह मुअय्यन काइत, मौरूती दखीलकारी काश्त में कुल मिला कर अगर सौ एकड़ खेत है जिनमें एक अच्छी खेती हो सकती है, अच्छा फ़ार्म बनाया जा सकता है, उस आदमी को उस इाल्स को बहुत ज्यादा रकम देने की कोई अरूरत नहीं है। यह बूसरी बात है ऐसे ऐसे भी जमींबार हैं जो अपने गांव में नहीं रहते थे जो लेखनेऊ जैसे बड़े शहरों की शोभा बढ़ाया करते थे। उनके लिये अगर खपाल किया जाय तो उनको ज्यादा रकम देना चाहिये लेकिन हमारा ख्याल है कि हमारी सरकार का यह मंद्रा नहीं कि उनको इतनी रहम दी जाय कि वह लखनऊ और और बड़े-बड़े शहरों की शोभा बढ़ाया करें। बड़े-बड़े फार्न वालों को और बड़ी-बड़ी खेती बालों को कम देना चाहिये। पांच हजार रुपये तक के मालगुजारों को पुतर्वासन अनुदान देने का विद्यान है। में समझता हूं कि पुनर्वासन अनुदान भी उसी लिहाज से देना चाहिये। जिस जमीदार के पास जमीदारी

के खत्म होने के बाद जोत में कम खेत हो तो उन्हें देना चाहिये और अगर किसी के यास बहुत ज्यादा खेत हों तो उसको पुनर्वासन अनुदान देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से थोड़ा सा परिवर्तन करने पर ५० करोड़ रुपये की बचत सीरदार को हो जावगी जिससे गरीब किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो लकता है। अब सवाल एक यह है कि जो मतभेद का नोट श्री द्वारिका प्रभाद जो और श्री जरपाल सिंह जी ने दिया है हमारा खाल है कि सरकार को भी लगेगा और हों भी लगता है और मेरा खाल है कि सभी मेन्बरों को वह बीज लगेगी कि हमारे सूबे में जो खेतों में काम करने हैं उन मजदूरों की तंख्या बहुत काकी हैं। सरकार के लजने यह बहुत दिनों से सवाल है कि भूमिहीन लोगों को खेत दिये जाय तो यह बात कैसे पूरी होगी जब एक तरफ आगे के लिये सरहार तीन एकड़ की सीमा जमीन पर अबजा करने वालों कि थिये निर्यारित करती है और पीछे की तरफ़ इन लोगों को तरफ़ कोई ध्यान नहीं दिया जाता जिनके कब्जे में ३० हजार एकड़ जभीन है। ये दोनों बातें नहीं हो सक्ती कि बड़े लोगों के पास अधिक से अधिक जमीन रहे और भूमि हीनों को भी देने का प्रबन्ध किया जा सके।

सरकार की जो कि तहाल की नीति हैं उस पर ज्यारा टीका टिप्पणी में नहीं करता, में अपनी राय देता हूँ कि कुछ लोगों से जमीन लो जा सकती है और लेना मुनासिब है। २५० राय से जपदा मालगुजारी देने वालों के जो शिक्षमी काश्तकार हैं उनको सरकार ने मौक्सी हक देने का ऐलान कर दिया है, इसके लिये सरकार को वह शिक्षमीदार काश्तकार, आज, सूबे में, कोटि-कोटि घ यावाद दे रहे हैं। उसके साथ लाथ में सरकार से निवेदन करता हूँ कि २५० रुपये तक और २५० रुपये से कर मालगुजारी देने वाले लोगों, जिनके पास ३० एकड़ तक सोर, खुदकाश्त और शरहमुअध्यन काश्त है, उनके शिक्षमी काश्तकारों को भी मौक्सी हक देने की उदारता दिखाई जाय। इस तरीके से हमारे प्रान्त के बहुत से गरीब भूमिहीन लोगों को जमीन मिल जारगी। और जो नई जमीन सरकार बढ़ाना चाहती है उसके लिये तो खासतौर से यह कायदा हो जाना चाहिये कि वह भूमिहीन लोगों को ही दी जायगी।

अब मुझे एक दो बातें और निवेदन करनी हैं। ज्यादा वक्त लेना हम लोगों का काम नहीं है। कुछ जगहों को छोड़ दिया गया है जहां यह जमींदारी विनाश और भूमि बपवस्या बिल का कानून लागू न होगा, जैसे म्युनिसिपल एरिया, टाउन एरिया, कंट्रन्मेंट और वह जाहें जो सरकारों काम के लिये सुरक्षित हैं। में सरकार का ध्यान एक बात को तरफ दिलाना चाहता हूं कि अपने सूबे में मुख्तिलक जिलों में कुछ ऐसी जमीदारियां हैं जो सरकारी जपींदारी कही जाती है। जिनका इंतजाम सरकार खुद करती है। काइतकार को जैसे और जमींदारियों में हक हासिल है वही हक मौकती, वही दखील-कारी हक सरकारी जमींदारियों में भी मुद्दतों से काश्तकारीं को हासिल है। जब एक तरफ दस गुना लगान जमा करके मन्यवितयों के काश्तकार मालिकाना हक हासिल कर रहे हैं तो सरकारी जनीं शरी के काइनकार इस लाभ से क्यों वंचित रहें। वे चाहते हैं कि उनको भी यह अधिकार मिले कि वे भी अपने लगान का आधा करावें और अपनी खेतों में मालिकाना हक हासिल करें। मुझे यह मालून हुआ है कि चूंकि सरकार खुद जमींदार है और उसे मुआविजा नहीं देना है, इसलिये सरकार उस पर कुछ अलग से गौर करेगी और यह कानून पास हो जाने के बाद उन पर भी यही व्यवस्था घोषित की जायगी। मेरा विचार है कि मुआविजान भी देना हो तो भी काश्तकार दस गुना देने की तैयार है और सरकार को रुपया लेना चाहिये, उतना ही लेना चाहिये जितना और दूसरे काश्तकारों से लिया जाता है। वह रुपया लेकर सरकार को किसी दूसरे काम में नहीं खर्व करना है, उन्हीं काइस्तकारों की माली हालत को और खेती को सुधारने में खर्च करना है। वह इपया साथ ही और जल्दी ले लिया जाय तो बड़ा अच्छा है।

[श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी]

तीसरो वात जो घारा ३, उपधारा (११) में व्याख्या को गई है, मवेशी के रखने और बाग लगाने की, ओर खेती की उन्नति के जितने साधन हैं उनको उस व्याख्या में लिया गया है।

मेरा निवेदन है कि शहज खेती से जो सरकार अपने सूबे का सुधार करना चाहती है वह असंभव है। उसमें एक चीज और बढ़ा देती चाहिये। वह है गृह उद्योग । इसको बढ़ा देते से एक बड़ा प्रोत्साहन पैदा होगा और किसानों का बड़ा भारी फायदा होगा। इसके बाद मझे सिर्फ एक बात और कहना है उसको कह कर में खत्म करूंगा। में अपने सम, जवादी भाइयों से बहुत सी बातों में इत्तफाक़ करने के लिये तैयार हूं। वे इस बात को कहते हैं कि काइतकारों से एक पैसा भी न िया जाय और जमींदारों को एक पैसा भी न दिया जाय हालांकि पहिले उन्होंने १ अरब रुपया देने की बात कही थी लेकिन अब प्रचार करने के जिये गलत सलत कह रहे हैं और कहते हैं कि काइतकारों का लगान मोजूदा लगान का एक तिहाई होना चाहिये यानी रुपने में ५ आना ४ पाई। इसके साथ ही उनकी कुछ भी देना न पड़ेगा। एक तरफ़ यह बात कहते हैं और साथ ही कहते हैं कि जमींदारों को कुछ भी न देना चाहिये. लेकिन जमींदारों से जो उनकी सांठगांठ चल रही है उसको देखकर मामली किसान को भी भम होता है। आज सर ार का विरोध करने के लिये और काश्तकारों को गलत रास्ता बताने के लिये उन्होंने यह तरीका अख्तियार िया है। ज हिरा तौर पर कम्युनिस्टों से उनका मेल मिलाप नहीं है लेकिन इस मामले में कम्युनिस्ट, क्रान्तिकारी, हमाजवादी, जमींदार और राष्ट्रीय सेवा संघ ये सभी एक गुट्ट में आ चुते हैं और इन सब का एक संयक्त मोर्ची कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना हुआ है। ऐसी हालत में मुझे यह माजूम होता है कि यह हमारे पुराने साथी जो हमारे साथ मिल कर काम कर रहे थे, दरअवल उनके कारनामों को देखने से यह मालूम होता है कि पित्र हमारा जो उनके प्रति एवं ल था, वरु भूम था। हम समझते थे कि हमारे समाजवादी भाई ग्ररीबों के बहुत ज्यंदा हमर्द हैं अ ज हमें बर अपना भन साफ़-साफ मालूम होने लगा है और मैं समप्रत हूँ कि ये गरीबों के कतई साथी नहीं है यह तो अपने मनलब के फेर में किसी तरह से सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और महज अपनी सरकार बनाने के फेर में पड़े हुये हैं। आखिर में में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस दो बरस कुछ महीनों की आजादी के बच्चे को जिन्दा दक्तनाने की कोशिश वे नहीं करेंगे नहीं तो इस चीज को हनारा मुल्क कभी क्षमा नहीं करेगा । इस तरह के उताबलेपन के कामों को उनको बन्द कर देना चाहिये । हमारे जिले में जिन पटवारियों की बुरी तरह से मारा गया है उनमें परगना कुचेतर का एक पटवारी है सम जवादियों ने उसे बुरी तरह से पीटा, उसके हाथ-पांव तोड़ दिये और अब वह अस्पताल में हैं। अगर दूसरे थाने के थानेदार, जो सायिकल पर चले जा रहे थे, न पहुंच गये होते, तो उस पटवारी की जान चली जाती। दो पटवारी और पीटे गये. लेकिन उनको अँधेरा हो जाने के बाद लोगों ने पीटा, इसलिए वह पहचान नहीं सके कि उनको किसने पीटा । इन पटवारियों ने साफ-साफ अपने बयान में कहा है कि हम मारने वालों को पहचानते नहीं हैं, लेकिन शुबहा में उन्हों ने बताया कि हम को किन लोगों ने धमकाया था कि तुम लोग लगान की वसूली का काम मत करो। इस तरह से लेगा मारे जाते हैं और पीटे जाते हैं। मेरी समन में यह बात नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है। हन।रे भाई अहिसावादी तो कभी रहे नहीं। यह हमेशा हिसावादी रहे, लेशिन उन्होंने एक पालिसी के तौर पर हम अहिसाबादियों का साथ कुछ दिनों तक विया। में आज उनसे निवेदन करूंगा कि नीति में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है। हमारा मुल्क जिस आहसा और सत्य के सिद्धांत को लेकर आजाद हुआ है, अभी हमको उसी पर कायम रहना है और हम अपने देश और अपने वेश में रहने वालों की उन्तति उसी मार्ग पर चलकर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ में एक मर्तबा फिर अपने माल मंत्री को मुबारकबाद देता है और आशा करता हूं कि जो कुछ बिल में मुनासिब संशोधन करने का मौका होगा बादा पूरा किया जायगा। और मुझे पूरी आशा है कि जब बिल बनकर तैयार होगा उसको देखने हुये अपने देश में और सरकारों ने जो कुछ किया है उसके मुकाबिले में इसमें शक नहीं कि हमारी सरकार सब सरकारों से ज्यादा धन्यवाद की पात्र समझी जायेगी।

*श्री फखरूल इस्लाम-जनाब वाला, यह खुशी है कि सन् १९५० ई० में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आयी। ख्याल यह किया जाता था कि अक्तूबर ही के महीने में मिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस ऐवान के सामने रक्खी जायेगी। हमें अब यह देखना है कि जिम तरह से मिलेक्ट कमेटी ने जो रिकमेडेशंस (सिकारिशे) की है उन पर इस हाउम को कहां तक तरमीमे पेश करना है और कहां तक उन्हें कबूल करना चाहिये। कब्ल इसके कि में बिल की दफात पर और उसकी जेनरल पालिसी पर कुछ अर्ज कर्ल में चाहता ह कि अपने लायक दोस्त आनरेबिल मिनिस्टर आफ रेवेन्यू और जनाब वाला के जरिये से तमाम कांग्रेसी दोस्तों मे यह अर्ज करना चाहुंगा कि यह जमीदारी एबालिशन का सवाल सन् ४६ से हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन आप निहायत आहिस्तगी के साथ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अब भी जो बिल हमारे सामने है उसकी बहुत सी दफात देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँच रहे है कि आप शायद अपना कदम तेजी से बढ़ाना नही चाहते हैं और आप पिंडलक को, अवाम को और अपने होम मिनिस्टर को कुछ खास मुसीबतों में डालना चाहते है। यह आज हकी कत है कि इस हाउस ने और इम हाउस के बाहर सब लोगों ने और मुझे खर्जी है कि इस सेशन में जमींदारों के बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों ने यह एलान कर दिया है क्ति जमींदारी जल्द खत्म होनी बाहिये जैसा कि हमने और आपने पहले मतालबा किया था। अगर आप अब भी उतनी ही आहिस्तगी से, जिस तरह से आप चल रहे है, इस कानुन को च गर्येंगे तो उसके खतरात आप अपने सामने रक्खें और फिर आप यह न कहे कि इसके जिम्मेदार सोज्ञ लिस्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संव वाले है जमींदार है। ये हमारी मुखालिफ पींटयां है, बिल्स में तो यह कहूंगा कि उसकी जिम्मेदारी आप पर है और आप उसके जिम्मेदार है। आप ही को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिये कि इस वक्त मत्क के अन्दर एक ऐसी हालत पैदा हो गई है कि जमींदार यह नहीं जानता कि उसे मुआर्विजा मिलेगा भी या नहीं और अगर मिलेगा भी तो किस हालत में मिलेगा यह किसी को नहीं मालूम है। काइतकार भी नहीं जानता कि उसे क्या-क्या हरूक हासिल होंगे। आपने जो नया कानून दस गुना लगान के मुताल्लिक बनाया है उस पर उसे यकीन नहीं है कि आया यह गवर्नमेट बाकी भी रहेगी या नहीं। सोशालिस्ट कुछ और ही कहते हैं। सारी बातों को सोचकर हो आपको कोई कदम उठाना चाहिये। यह एक मुक्किल सवाल ह जिसके लिये गवर्नमेंट बड़ी तेजी से काम कर रही है उसको यह भी नहीं मालूम है कि हमारे मुल्क की क्या हालत है ? यहां के बाजिन्दे, यहां के रहने वाले हम आप सब ऐसे नहीं है कि इस बात को मोर्चे और समझें कि ठंढी हवा आने के बाद बरसात आने वाली है इसलिये अपने मकानों को दूरस्त कर लें और आगे जो खतरात आने वाले है उनसे होशि-यार हो जायं। इसकी वजह यह है कि यहां के लोग लेजी (सुस्त) बहुत है। उनमें लेजिनेस (सुस्ती) बहुत ज्यादा मौजूद है और वह अपने फायदे और नुक्सान की सही तौर पर समझ भी नहीं पाते। इसलिये आपने अपनी इस स्कीम मे जो दस गुना लगान जमा करने की बात रखी है जब तक उनकी समझ में सारी बाते न आ जायं और जब तक वह यह न महसुस करलें कि इस कानून से हम फलां-फलां फायदे हासिल कर रहें है तब तक गवर्न-मेंट की यह दस गुना लगान दसूली की स्कीम उस वेजी से नहीं चल सकती जिस तेजी से आप चलाना चाहते हैं। जब ऐसो जहमते और दृश्वारियां हमारे और आपके सामने है तो हमको गौर करना चाहिए कि हम अपनी पालिसी में कोई ऐसी तब्दीली करें, जिसमें कि मुल्क को फायदा पहुंच सके । आप देखेंगे कि जमींदारी एब। लिशन फंड के सिलसिले में हजारों

^{*}माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री फ़वरल इस्लाम]

किस्म के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। में आपको इलाहाबाद जिले की हालत ही बतलाऊं, कि चन्द आदिमयों ने ही दो हजार बीचे जमीन दफा १४५ और १४६ के सिलसिले में कर्क कर ली और उसके बाद वां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सेकेटरी जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेंट और उस एरिया के एस० डी० ओ० के जरिये करीब २,२०० बीवे जमीन कुर्क करके कोर्ट आफ वार्ड्स को यह अख्तियार देते हैं कि उसके करने का अख्तियार उसकी होगा जो वह जिला मेजिस्ट्रेट की रायसे उसके बाद कांग्रेस के सेकेटरी साहब वहां गये और गाली-गुपना भी दी और सेटिलमेट आफिसर से कहा कि ८०० बीघे जमीन हमें दो ओर हम जिसको चाहें उसको दें। उसके बाद वे तकरीर करते हैं। तकरीर का नतीजा यह होता है कि तीन आदमी दूनरे ही रोज जान से मारे जाते हैं यानी इस तरह के वाकयात एक ही जगह नहीं बल्सि मल्स के हर हिस्से में हो रहे हैं। अगर पुरिप्त का बजट ८ करोड़ ८ लाख से ज्यादा भी हो जाय और यही रिवश जारी रही तो आप समझ लें कि आपके कानून का सही अमल नहीं हो सकेगा ओर इससे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी। बहुत से लोग अभी यही स अते हैं कि शायद गवर्नमें इस कानून का निफाज अभी नहीं करेगी। इसको पास करके दी रहने देगी और फिर नये एलेक्शन के बाद यह जारी होगा। अगर ऐसा ख्याल हैं तो में अर्ज क्षरूगा कि आप इस सूबे की हालत और इस मुल्क की हालत को देखकर और खूब सोच-समझकर जितनी जल्दी हो सके ऋदम उठावे। ने आगसे अर्ज करूगा कि आपने ऐसी कोशिश की और बाद में आप ऐसा करेंगे ऐसी कोई जानकारी मुझे नही है। म इस बिल को सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाना च।हता हूँ। उसमें यह कहा गया है कि कुछ सेश्सन के अन्दर दस गुना लगान हासिल कर रे में फोर्स और कोआर्शन (दबाव) से काम लिया गया है और उन फोर्स और कोओर्शन के इसोमार करने के बाद भी आपने रं।या वसूल कर लिया तो में समयंगा कि आप रे क्यया हासिल कर लिया। लेकिन जो हकी कत है उससे आप इन्कार नहीं कर सकते हैं। मैं अपने जिले ही मिसाल देता हूं कि जहां देहात भी आबादी १७ लाख हे बगां पर सिर्फ ७० बोरे ची गी, ७ बोरे १० लाल आदिनियों के जिये, इस हिसाब से दी जाती है। यह तो सभी जानते हैं कि आजकल चीनी की स्केरसिटी (कमी) हैं। देहानों में किसी की भी जीनी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहां पर भी सरकार के कारिन्दों ने यह सिस्टम चला दिया कि जो अ।दभी जमीदारी एवालिशन फंड में भूमिधरी राइट्स के लिये रपया जमा करता है उसी को बीनी दी जाती ह शोर जो नहीं जमा करता है उसको नहीं दी जाती है। इन मरकारी कारिन्दों के ऊरर आज हमारी सरकार की नाज है जिन्होने हमेगा अग्रेजी हुकूमत मे साम्प्राज्यवादी ताकत का लाथ दिया । आपके ये कारिन्दे पहले करेंसे थे इस बात को सभी अव्छी तरह से जानते हैं।

आपकी खुशामद के लिये लोग इस तरह से जिलो में काम करते हैं। मुझे तो यह जानकर अफसोस हुआ कि आज इस ऐवान के अन्वर एक बुजुर्ग मेम्बर साहब यह फरमाते हैं कि अब पटवारियों की हालत बहुत खुधर गई हैं और उनकी तारीफ में तकरीर करते हैं। अरे जनाब ! पटवारियों की हालत क्या है ? आज जितना भी लिटिगेशन (मुकदमावाजी) वेहात के अन्वर नजर आता हैं वह सब इन्ही पटवारियों की वजह से हैं। में तो यह कहता हूं कि अगर आप इन पटवारियों के इन्स्टीट्यूशन को यककलम अवालिश कर सकते हैं तो आज ही इसको अवालिश कर वीजिये। आज क्या पटवारियों की हालत बवल गई हैं? अभी कुछ दिन पहले जिसके जल्मों का क्यान बहुत जोर से किया जाता था अब क्या वे इतने बदल गये हें? मुझे तो यह वेखकर अफसोस होता है कि आपकी जवान से इस तरह के अल्फाज निकलते हैं। बिहार के अन्वर पटवारियों का इन्स्टीट्यूशन नहीं है आप भी

इस चीज को क्यों नहीं खतम कर देते? में यह एलानिया कहता हूं कि जब तक यह पटवारियों का इन्स्टीट्यूशन बाकी है तब तक जो आपकी काश्तकारी जनता है उसको चैन नहीं मिल सकती, उसको कायदा हासिल नहीं हो सकता । बहरसूरत हमको यह देखना है कि अ।पकी सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट, जो हमारे सामने आई है वह कहां तक ऐसी है कि जिसको यह ऐवान मंजूर करे और इसके अन्दर ऐसी जरूरी तरमीमात पेश करे, जो मुनासिब हों। इस बिल में ४ बुनियादी बाते है, चार इसके खम्भे है। पहजा तो यह है कि मुआवजा क्या दिया जाय। दूसरा मवाल है कि मुआवजा देने का क्या तरीका हो, आखिर वह बांड में दिया जाय या नकदी की शकल में दिया जाय । तीसरा सवाल यह आता है कि इन जमींदारों के बाद जो हमारी रिआया पर इतने जुलन किया करते थे उनके जाने के बाद क्या इन्तजाम हो। यानी काश्तकारों की तरफ से कौन आदमी, जैसा कि अभी तक जमींदार किया करते थे, उसका इन्तजाम करेगा। चौथी बात यह है कि इस कान्न के जिरये से जो अब हम पास करेगे. यह कहां तक काश्तकारों को जो मुसीबते है, उनकी जो तकलीफें है, उनकी हिमायत करता है। यह चार बालें है जो बुनियादी बाते है और इसके खम्भे है और इन बुनियादों को सामने रखकर गवर्नमेट कहां तक आगे बढ़ी है या जैसा कि लोग कह रहे हैं कि यह गवर्तमेंट का एक ढोंग है और पिटलक को वह घोले में रखना चाहती है और इसको खतम करना नहीं चाहती। शायद एलेक्शन के बाद ही इसके ऊपर अमल-दरामद हो सके। लेकिन इस बिल के पढ़ने के बाद में यह समझता हूं कि यकीनन इसके अन्दर ऐसी बाते जरूर है जो अगर इसके अन्दर नहीं होती तो यहां तक नाकामयादी की शक्ल दिखाई नहीं देती। यह रिपोर्ट एक बहुत वडे काबिल, होशियार और विद्वान और जिम्मेदार शख्स ने कई महीने की मेहनत के बाद तैयार की है और उसके बाद सेकेटेरियट के लीगल रिमेम्बरेन्सर साहब ने और दूसरे कानूनदां हजरात ने एक बिल तैयार किया। यह सब बाते समझ में आई' और बहुत इसके उपर वनत लगा। सेलेक्ट कमेटी ने भी इसके ऊपर २२ रोज तक बहस होने के बाद एक रिपोर्ट नैयार की मगर अब सवाल यह होता है कि जनाब कम्पेन्सेशन कैसे दिया जाय। इसका जवाब यह दिया जाता है कि साहब, गवर्नमेट इसके मुताल्लिक फैसला करेगी कि वह कैपे दिया जायगा। अब तक वह नहीं जानती कि बांड में दिया जायगा या नगशी में दिया जायगा। अगर नहीं दिया जायगा तो इसके लिये दूसरा अरेंजनेट (प्रबन्ध) क्या होना और किस तरह से जमींदारी को खत्म किया जायगा जो कि अभी तक खूब नजराना लिया करते थे। और आगे चलकर जमीं शरों की शकल क्या होगी जो अभी तक नजराना और काश्तकारों पर जुल्म किया करते थे? उसके लिये सरकार की तरफ से क्या इन्तजाम होगा ? कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो मनासिब समझेगी इसके लिये वह तरीका अख्तियार करेगी और एक दूसरा प्लान यह भी है कि इसमें गांव-सभा से मदद ली जापगी। यह अख्रियार लेना गवर्नमेंट का जाहिर करता है कि गवर्नमेंट अभी तक जब कि सेलेक्ट कमेटी से यह आखिरी मर्तबा रिपोर्ट आ चुकी है तो हा यह नहीं जान सके कि वह इन साबातों के लिये क्या करने जा रही है, उन ही तजवीज क्या होगी? जाहिर है कि जल्दी में एलेक्झन की बिना पर उसके चकर में पड़कर कोई ऐक्सन ले लेगी तो काक्तकारों के अन्दर बजाय इसके कि उनको यह म सूस हो कि जनींदार हट गये जो हमारा खून चुना करते थे, उनकी जगह पर ऐमें लोग है जो सही मानों में खिदमत करते हैं, मै समझता हूं इस जिल में यह चीज नहीं है और इससे यह वाजेह नहीं होता। किसी को आज नहीं मालूम कि आपके दिल और दिमाग में क्या है और आप की मन्त्रा क्या है ? जो कुछ आप चाहते है वह इस कानून में होना चाहिये और उस पर आपको हाउस के सामने गौर करना चाहिये और हमको मौक़ा देना चाहिये कि हम उस पर अवनी राय का इजहार कर सकें। यह हरगिज-हरगिज म्नासिब नहीं है कि आप कह दें कि साहब, हम यह बाद में रूल्स बनाते वस्त तय कर देंगे। यह आपका सही तरीक़ा नहीं है। आपको साफ कहना चाहिये कि आपका मुड आफ कम्पेन्सेशन (मुआवजे का तरीक़ा) क्या होगा। आप नक़द मुआवजा देना चाहते है या बांड्स की

[श्री फलरुल इस्लाम]

शक्ल में देना चाहते हैं। इसको आप साफ—साफ कह दीजिये ताकि वह आदमी जिसको आप मिटा रहे हैं और इस कानून के जिरये से फांसी दे रहे हैं और जिसकी एगजि—सटेन्स को आप हमेशा के लिये मिटा रहे हें समझ सके कि उसको कितने मुआवजे में जिन्दगी बसर करना हैं और उसकी आइन्दा जिन्दगी का मियार क्या हो सकता हैं और आपको उसे साफ बतलाना चाहिये कि किस तरह से उसको अपनी आइन्दा की इक़तसादी जिन्दगी को ढालना हैं। आपको इसी वक्त यह जाहिर करना चाहिए कि आप बान्ड्स में अदायगी मुआवजे की करेंगे या कैश में। आज ५ साल के अन्दर आप यह छोटी—छोटी बाते भी तय नहीं कर सके और आप बताइये कि किस तरह से जमींदार और उनके लड़के अपनी आइन्दा की जिन्दगी के पैमाने को कायम करें। आज भी उनके वही बड़े—बड़े खर्च चले जाते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि आइन्दा उनकी कितनी आमदनी होगी ताकि वह अभी से अपने इखराजात को ऐडजस्ट कर सके।

आपने जो दस गुना वसूली का कानून बनाया है उससे भी आपको यह तजुर्बा बाजे तौर पर हो ही गया कि काइतकार ने आपकी स्कीम को कहां तक पसन्द किया है। अभी तक आपको एक अरब ७७ करोड़ में से कुल १२ करोड़ की रकम हासिल हुई है और में आपको पूरे यकीन के साथ बतलाए देता हूं कि आप चाहे जितनी जायज नाजायज कोशिश कर ले लेकिन आपको ३५ या ४० करोड़ से ज्यादा वसुली किसी हालत में भी नहीं हो सकती है। से इट डेफिटनिटली (ठीक-ठीक तौर से बतलाइए) कि आप जो उनके हक्क ले रहे हैं उनके एवज में आप उनको क्या देत। चाहते हैं और यह आपका कौन सा इन्साफ का तरीका है कि आप उनको नहीं बतलाते कि किस तरह से उनको मुआवजा देगे। वह नहीं जानते कि उनको आइन्दा क्या आमदनी होगी, वह भी आप ही की सोसाइटी के आदमी है और उनकी जिम्मेदारी बहैसियत हुकू मत के आप ही के हाथ में है, उनकी भी औलादे है। आपको उनको साफ तौर से बताना चाहिये कि आगे समाज में उनकी करा है सियत होगी। यह कौन सा इन्साफ है कि आज पांच-छ साल के अन्दर भी आप उनको नहीं बता सकते कि वह आइन्दा इस सूबे में क्या है सियत रख सकेंगे ? काफी बजाहत के साथ आपको रखनी चाहिये और इस तरह के कानून इधर-उधर की बातों से तैयार नहीं हो सकते। मालूम नहीं कि आपके विमाग में कीन सी पालिसी है और आप बाद में कैसे रूल्स में क्या करेंगे? To show yourself merciful but don't be merciful. To show yourself to be horest but don't be honest. (अपने को दयालु प्रकट करना किन्तु दया न करना, अपने को ईमानदार बताना किन्तु ईमानदार न होना।) लेकिन आप तो महारमा गांबी की फिलासकी पर चलने बाले हे आपका तो फर्ज है कि आप साफतौर से बतलाबें कि हमने रुपये का जहां तक हो सका इंतजाम किया, लेकिन अब हम मजबूर हैं और सिर्फ बान्ड्स की बाक्ल में ही मुआबजे की अवायगी कर सकते हैं और तुम इसके लिये तैयार ही जाओ। तब इस शक्ल में किर कोई सवाल पैदा न होगा। आप आज टालते क्यों है और यह हिर्गीलग की तरह की बाते करते हैं ! जहां तक आलटरनेटिव अरेंन्जमेंट (पाक्षिक प्रबन्ध) का सवाल है आपने तहसी अवार और पटवारी को इसी तरह से रखा तो में आपकी बतलातों हं कि आजकल आपके राज में पटवारी को जितना आराम है और वह जिनने मजे उड़ाता है, में समझता हूं कि उतने आराम की जिन्दगी आज कोई नहीं गुजार रहा है और पहले कभी भी उसने इतना मजा नहीं किया होगा। पहले पटवारी की आमदनी का जरिया यह था कि झूठे इन्द्राजात करके और झूठी गवाहियां वेकर काइतकारों से किसी से २० रुपया और किसी से ३० रुपया लेकर मुक्तवमें बाजी कराता था और कोशों से साफ कहता था कि तुम्हारा यह करा दूंगा और वह कर, दूंगा तुम इतना रुपया दे दो। जब से अप आए हैं तब से तो आपने उसकी आमदनी खूब बढ़ा दी है आप अगर फिगर्स मानूम करें तो आपको मालूम होगा कि आप बीसों चीजों और नई स्कीमों ओर जमींदारों के सिलसिले में बसूली के सिलसिले में, पटवारियों और तहसीलदारों को देवें विंग एलाउन्स वगैरा दे रहे है। आप पटवारी, तहसीलदार, एस० धी० ओर लैन्ड रिकार्य कमिश्नर वगैरा सब को खूब रक्तमें बांट रहे है।

माननीय माल सचिव--उसकी वजह से बकीलों की फीस मे तो कोई करी नहीं हुई है।

श्री फल ह द इस्ताम — उसने तो कभी — कमी नहीं होगी। वह तो आपने भी बढाई होगी। आप के इस कान् को समझने के लिए शायद व की कों को फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगो। मैं जिस्ट्रेटों को भी शायद फिर से पढ़कर ला कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। लीगल श्रीविष्शानमं भी इस कान्न को देखकर परेशान और पजिल्ड है। पार्टीशन ए केट और सकनेशन ए केट इसमें हर एक कान्न मौजूद है। हर एक बात में कन प्यूजन मौजूद है।

बहर मूरत, मैं यह अर्ज कर रहा था कि आन्डरनेटिव अरेंजमेट का आप फैसला करे कि वह क्या होगा । आप क्या करेंगे? तहसीलदारों के जरिये वसूल करायेगे । पटवारियों के जरिये बबूल करायेगे या जिस तरीके से कोई आफ़ वार्ड्स के जरिये से वसूल होता है। यह चीज तो नुकसान की होगी या गांव-सभावें वसूल करेगी। साहब कुछ तो किहए आखिर आप क्या करेंगे। मैंने अभी बतलाया है कि आपके कलेक्टर साहबान गांव-सभाओं को पसन्द नहीं करेंगे। आपको मालूप होगा कि राशींनग डियार्टमेंट ने यह आर्डर भेजा कि कोआ-परेटिव सोसाइटी के जरिये गरुछे की दूकाने खोली जायं और यह भी हुक्म दिया गया कि पुराने रिटेलर्स को भी इममें मनटेन किया जाय, फिर यह कहा गया कि इसमे चूंकि पुराने रिटेलर्स को रखा गया इ प्रलिये यह खराबी पैदा हुई। आप की इस स्कीम की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब पर होगी वह कहेंगे कि यह तो झंझट है। काम तो पटवारियों के जरिये से ही होना चाहिये। साहब, पटवारियों की तादाद बढ़ा दीजिये। नतीजा इस का यह होगा कि जिस तरह से कुई तहसील होता है काइतकारों के साथ कितनी ज्यादितणां होती है। नायब तहसील इर, कुई अमीन और पटवारी किस तरीके रुपया वसूल करते हैं। एक रुपया रसीद की लिखाई का काश्तकार देता है। यह चीनें जारी रहेंगी। यह मैं नहीं कहता कि आप यह चाहते हैं। मैं आपको वार्त करता हूं कि आपके इस लेजिस्लेशन से जनता को फायदा नहीं होगा और काश्तकार को भी फायदा नहीं होगा। आपको चाहिये कि आप अपनी मेशिनरी को ट्रेनिंग दे कि साल भर के बाद जनींदारी खत्म होगी करोड़ों रुपया दसूल होगा। किस फार्म में होगा ? कौन लोग रसी दें लिखेंगे ? आपका इरादा जमीं दारी खत्म करने का नहीं है। सरकार जमीं दारी खत्प करना नहीं चाहती। एलेक्शन से कमिटेड है। सिर्फ एलेक्शन के लिये इसको करना है। आपको जनता का ख्याल नहीं है। मै आपको बहुत सी राहें बतला दूं। जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव की अलाहिदगी है, प्रोहिबिशन हैं और और बहुत सी चीजों में आप किमटेड है। कर्जे के लिये क्या होता है ? यह सब चीजें कौन पूछेगा। यहां की जनता बड़ी लामोश और साइलेंट है। लोग आपके ऐक्शन पर गौर नहीं करेगे।

अब दूसरा अहम सवाल है रिलीफ़ का। इसको आप देखेंगे तो जहां तक लंडलेंस लेबरर का ताल्डुक है तो रिपोर्ट क्या कहती है। जमींदारी बिल में कोई जिक्र नहीं है। उनके लिये किसी किस्म का इंतजान यह कानून नहीं करता। अब हमें यह देखना है कि दूसरी किस्म के जो काइतकार है उन्हें क्या फायदा होता है। दस गुने लगान की हमारे लिये कोई खास अहमियत नहीं है। जमींदारों को मूआवजा मिलता है। इससे क्या होगा? जो चीजें हमें देखना है वह यह है कि आया मौजूदा काइतकार को हालत में फर्क पैदा होता है या नहीं। तो कोई फर्क मौजूदा हालत में पंदा नहीं होता है, हां उसको राइट आफ ट्रान्सफर (हस्तांतरण—अधिकार) मिल गया है। उसकी कोई अहमियत नहीं है। यह मानना पड़ेगा कि जमीं—

[श्री फल्रुस्ल इस्लाम]

दारी अबालिश कर देगे तो जो नजराने लिये जाते थे जो बेगार ली जाती थी उससे नजात हो जायगी । लेकिन बजाय इसके अब वह बड़े जमीदार और ताल्लुकेदार के कही रेवेन्य मिनिस्टर का गलाम न हो जाय या हमारे कांग्रेसी एम० एल० एज० की किसी तरह से जी हुजूरी न करे या कलेक्टर साहबान या तहसीलदारों की बेगार न करने लगे। हमें यह देखना है कि इससे क्या हार्डशिष्स (कठिनाइयां) अराइज (पैदा) होती ह, वे मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हुँ। इस कानून से जो हार्डशिप्स कारतकारों की पैदा हो रही है, उनका इलाज हमको और आपको सोचना चाहिये। आप जानते हैं कि अग्रेजी हकुमत में लैंड रेवेन्यू ऐक्ट एक बड़ा सख्त कानून गवर्नमेट ने बनाया था, इसलिये कि अगर एक पैसा भी जमींदार के पाम रेवेन्यू का बाकी रह जाय तो उसे जेल ने बन्द कर दे, उसके साथ जितनी सख्ती चाहे कर ले और लम्बरदार को भी गिरफ्तार करके ओर उससे रुपये वसूल करे। यह हमारे बृटिश राज्य के जमाने में था। बदिकस्मतो से वही अफसर सेक्रेटेरियट के अन्दर मौजूद है जो बृटिश राज्य को चलाया करते थे। उन्होंने कहा कि साहब यह बड़ा गलत तरीका है। रुपया तो आप हमसे ही वसुल करायेगे। यह चोज उनके दिमाग में मौजूद है, निकली नहीं है। वसूल, तहसीलदार या नायब तहसीलदार ही करेगा आखिर हम क्या करें? वह कहते हैं कि साहब, हर वह कानून जो कि अंग्रेज ने इसके मुताल्लिक बनाया था उसी पर अमल-दरामद हो। और मुझे अफ़मोस है कि सेलक्ट कमेटी ने उसको एक कदम और आगे बढ़ा विया। जैसे आप जानते हैं कि सिविल ला का एक बड़ा ऊंचा प्रिसिपल है कि अगर किसी शहस के ऊपर कोई डिग्री स्टेट की नहीं यानी प्राइवेट इंडिवीजअल (वैयक्तिक) की हो तो एक साथ तीन किस्म के एक्जीक्युशन्स नहीं होते। यानी एक का मकान भी अटेच हो, प्रापर्टी भी अटेच हो और वह जेल में भी बन्द किया जाय। अगर सिविल कोर्ट में यह तीन दरख्वास्तें आप दीजिये तो वह कहेंगे कि वन मोड आफ़ एक्जी-क्यूबान हो सकता है। यह तो दका २५२, २५३ में है कि मोड आफ एक्जीक्यूबान एक हुओ करता है। यह नहीं हो सकता कि आप तीन तरीके अख्तियार करें। लेकिन इस कानून के अन्वर मुझे तो हैरत हुई कि हमारे द्वारिका प्रसाद मोर्य साहब भी, जो काश्तकारों के बड़े हमदर्व है, नोट आफ डिसेट लिखने वाले, उन्होंने यह कह दिया कि जेलबाने के साथ-साथ प्रापर्टी सब चली जायगी। मुझे नाज्ज्य हुआ कि यह चीज उनके जहन में आई कैसे और उन्होंने यह नहीं कहा कि डिस्ट्क्ट मैजिन्ट्रेट को यह अख्तियार नहीं होगा कि एक काइतकार के ऊपर सिर्फ उसके लगान की नाआदायगी के लिये तीन-तीन तरोक़ें अख्तियार करे। में आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जमी-बार का लगान बाकी रहता था तो वह क्या करता था? वह तहसीलदार को नीटिस विया करता था, मुक्तदमा क्रायम होता था, डिग्रो होती थी, क्या उसको यह अल्तियार था ? लेकिन आपका कानून कहता है कि अगर काइतकार मालगुजारी न दे तो आप उसको जेल में बन्द कर सकते हैं। में आपसे पूछता हूं कि आया काश्तकार को इससे कुछ फायदा पहुंचता हैया नुकसान और उसको कहीं तक रिलीफ पहुंचती है। मै महता हैं कि एक मुहाल के अन्वर पांच जमींवार है। तीन ने मालगुजारी दे दी और बो ने नहीं दी। तो कलेक्टर यह हुक्म दिया करता था कि फलां लम्बरदार को गिरफ्तार करके रुपया हासिल करो और आप जानते है कि वह बढ़ा मोटा असामी हुआ करता था। उसने आसानी से वो हजार, पांच हजार रुपया वे दिया, लेकिन अपने उस जमी-बार से पांच परसेंट चार्ज कर लिया। यही नहीं, अगर पांच ही परसेंट का मामला होता तो शायद वह न देता, लेकिन तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एम० डी० ओ० की नजरों में वह एक बड़ा ही सुन्दर आदमी माना जाता था। यानी जिस तरीक़ से आप देखते हैं कि भूमिषरी राइट्स के लिये सीमेंट, लोहे के परमिट मिलते हैं, इसी तरह उस जमाने में कोई रायबहादुर, जानबहादुर, कोई ठेका हुआ तो उसमें ठेकेदारी, कोई लीज हुई तो उसमें खीज, गरज हजारों किस्म की चीजें थीं। लेकिन में आपसे

अर्ज करूंगा कि हमारे मुल्क को हालत, हमारे काश्तकार की हालत अब चाहे जितनी ही अच्छी मालूम होती हो, लेकिन आज भी सैकड़ों किसान हर गांव में और देहात में रात में भूखे सोते हैं, उनके बच्चों के पास कपड़ा नहीं है।

मुल्क के अन्दर जब कहीं पर फलड आता है, कहीं पर ओलाबारी होती है और उसके बाद काश्तकार लगान देने के काबिल नहीं होता है तो आप बहै सियत रेवेन्यू मिनिस्टर रेमिशन्स करते है। फिर आप कहते हैं कि यह तो थोड़े से आदिमियों का सवाल था। अब यहां पर करोड़ों की तादाद में उस गांव के तमाम काश्तकारों का मामला है। अगर दस काइतकारों ने राया नहीं दिया तो उन तभाम काइतकारों की वह ज्वाइंट और से वरल रेसपां सिबलिटी होगी और आप रूपा वसूल कर लिया करेगे। मै अपसे पूछता हूँ कि आज तक यह चीज इस तरह से कभी रायज हुई। जब आप काश्तकार की भालाई के लिये एक कानून लाते है और उस पर ऐसी सिस्तियां हों, तो यह कोई मुनासिब चीज नहीं है। यह कभी भी तसल्लोबस्श नहीं हो सकता। उन तमाम कानुनों क जो हमने आपको दिये कि गवर्न मेंट इनको इस्तेमाल करेगो, डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट्स ने इनका नाजायज इस्तेमाल किया है । आप डिटेंशन लाज को देखिये। पब्लिक के दूसरे मामलात को देखिये। हमेशा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खराब किया है। जब आप ऐसा कानून डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अख्तियार मे देते है तो अगर वह पटवारी और तहसीलदार को रिपोर्ट पर यह लिख दें कि फलां गांव के अन्दर २५ काइतकारों ने रुपया अदा नहीं किया है ओर गांव वालों से वसूल कर लिया जाय, तो में आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर यही कहेंगे कि उस गांव के तमाम लोगों की जितनी जायदादें हैं कुर्क कर ली जावें और उनसे रुपया वसूल कर लिया जाय । जब कान्न के अन्दर ऐसी दक्ता मौजूद है तो कौनसी मुमानियत है, कौनसी रुकावट है, जो कि उसको ऐसा करने से रोके ? एडिमिनिस्ट्रेशन की मौजूदा हालत में आप तमाम पालीसीज पर नजर नहीं रख सकते । मुझे अफ़सोस है कि आप इस पर गौर नहीं करते । आज हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहता है और हर पुलिस आफ़िसर चाहता है कि किसी भी आदमी को बगैर किसी सबूत के और बगैर किसी जुर्म के बंद करदे और इसलिये कि हम मुजरिम के खिलाफ़ सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते। एक ऐंसी टेंडेंसी पैदा हो गई है आपके आफ़िसरों के अन्दर कि वें घर बैठे हुये, बगैर किसी तकलीफ के उठाये हुये, लोगों को जेल में बन्द कर दे। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इसमें कौनसी चीज होगी जो पटवारी डिस्ट्रक्ट मेजिस्ट्रेट राकेगी कि अगर एक को लिखता है कि फलां गांव से रुपया वसूल करना है मुझे डेढ़ करे।ड़ और वहां से अभी वसूलयाबी कुछ नहीं हुई है और डिस्ट्रिक्ट अफ़िसर गवर्नमेंट को मूव करता है तो क्योंकि गवर्नमेंट तो उसे खुदा समझती है, इसलिये वह उसके अपर क़लम भी नहीं उठा सकती है। हमने देख लिया कि जो पावर्स हमने रूल बनाने की इस हाउस में आपको दी हैं उनका आपने गलत और नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया है। तो क्या गारंटी है कि अगर इस कानून को भी हम आपको दे दें तो इसका भी आप नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे ? ऐसी सूरत में मै समझता हूं कि मुनासिब यही होगा कि यह दका इस बिच में से निकाल दी जानी चाहिये।

दूसरी दफ़ा जो हमारे सामने है वह पार्टीशन की है। पार्टीशन उन खेतों का नहीं होना चाहिने जो अनइकोनामिक है। सवा छः एक ह से ज्यादा जिस काश्तकार के पास जमीन थी उसके पार्टीशन के लिये बहुत सी क्कावटे थीं। लेकिन बुरा हो रिश्वतस्तानी का, मैं तो यही कहूंगा कि साहब अजीब बलैकमा हैंटरो है कि अगर किसी काश्तकार ने भूमिधरी राइट्स पाने के लिये दसगुना लगान जना कर दिया तो आप उसको खुदा समझते हैं।

अगर रुपया नहीं आता है तो जमींदरों से कह दें कि हम बांड देंगे, रुपया नहीं देंगे । इसमें कोई हिक कीबातनहीं है। ले किन आप कहते है कि अगर भूमियरी हो गया.

[श्री फ्लक्ल इस्लाम]

है तो उसको जमींन अगर छः एक से भी कम होगी तो भी पार्टीशिन कर दिया जायगा। यह कहां का इंसाफ है ? आप चाहते हैं कि हमारे यहां की इको नामिक होत्डिंग्स ओर भी अनेइ हो गामिक हो लिंडेंग्म हो जाने। मुझे यह शुबह मालूम होता है कि जो प्रोपेगेंडा जमींदार लोग करते थे उस पर अब यक्तीन होता जा रहा है कि जो रुपया जमा हो रहा है यह तो निजाई के खाते का जमा हो रहा है, यानी जिनमें डिस्प्यूट है। "dispute between son and fither, It will go against brother and sister." (पुत्र और पिता के बीच में झगड़ा, यह भाई और बहिन के विरुद्ध जायगा।) लेकिन में यह समझता था हि यह जनींदारों का एक प्रोरेगेडा है, लेकिन आपकी हेल्प-लेसनेस मुझे मजबूर करती है। हो सकता है कि लालव की वजह से आप भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रि हमे डेशन्स और इस बिल के बुनि गादी उसूलों को नजरन्दाज करते हों और कहने हैं कि हम अरइकोनामिस होल्डिंग्स (कम आमदनी वाली जोते) बढ़ायेंने, अगर हमें दस गुना दपया मिल जाय । मैतो यह कहंगा कि आपको किसी भी हालत में अन्इकोनामि ह होत्डिंग्स की नहीं बढ़ाना चाहिए, चाहे आपको रुपया भले हो न मिले। अपको अपइ होनामिक हो डिंग्स को खत्म करके को आपरेटिव फार्निंग की तरफ जाना चाहिये, जिससे एरेकिप्व फार्मिग होने लगे। इससे मुहर को कोई फायदा नहीं हाता है और न गर्नमेंट को रा को फार्यदा होता है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनको कि आपको मअ बजा देता है उत्हों आप बांडमें देदें क्यों कि आखिर में आप हो बाड में देता ही होगा। इसिलिये नहीं कारनाइट(दूरिको) है कि आप अभी से यह कह वें कि हम बांड देना चाहते हैं।

इत गोर पर मे पार्टीशन हा जिन्न कर रहा था। इसमें कुछ वकायें ऐसी है, जो जैबा और मुनासिब नहीं हैं।

ती तरी चीत पर मुपे अब भी शुबर्हें, मुनिकन हैं आप रोशनी डाल परें। वह है कि सेटिल मेंट कितने दिन बाँ हो ।। आज हमारे यहां ५० फीसदी जिन्ने ऐसे है जारां सेटिल-मेंट इयु है आपकी बकात साफ और क्लीपर नहीं है। एक काश्तकार सवाल करता है और इसमें जमीदारों का प्रोपेगेंडा भी शामिल है कि इसकी क्या गारंडी है कि आज हम रुपया दे देने हैं और कल को सेटिल मेंट होने पर आप बड़ायेगे नहीं। हमने जो फल बोरा उसको हम बल सहेंगे या नहीं। इसकी बहुत सी दकार्रे मेरी पमझ में नही आती है, लेकिन किर भाजो कु उमें सनझ प्रसाहूं में तो इस नतीजे पर पहुचाहू कि जिन जिलो का सेटिलमेंट ड्यू है जहां अर भी हो सकता है। आर किसी काइनकार ने दस गुना जाना कर विया और कर तो आवंका सेटिल मेंट हुआ तो इस ती क्या गारन्टी है कि वह इंकीज नहीं हो सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है, हो सकता है और में यह कहता हैं कि पर्वास की सदी ऐसे जिले हमारे सूबे में है जिनका सेटिलमेंट डयू है, वहां के लेग भू म-धरी राइट्स हासिल कर लें तो उनका लगान ४० साल तक नहीं बढ़ेगा, या नये आपरेशन के बाद इस का आपरेशन हो जायगा। यह साफ नहीं है इसलिये यह होना चाहिये कि ४० साल तक यह नहीं बढ़ेगा। यह एशोरेन्स आपकी तरफ से आना चाहिये। इस तरह से आप इन तमाम मसलों पर जो हार्डिशिप्स (कठिनाइयां) काश्तकारों के साथ होंगी या होने वाली है उन पर सार्चे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिनकी भलाई के लिये आप यह कानून ला रहे हैं उनको भलाई होगी। ताकि वह हमको और आपको दोनों को मुबारकबाद दे सके कि ऐसा कानून हमारी कांग्रेस सरकार लोई है जिससे हम जमींवारों के पंजे से छूटें और आज हम सुख की नींव सोते है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी जी ने कहा कि हर जगह दूध और शहद की नहरें बह रही है, किसानों में आज सुख और शान्ति हैं और कांग्रेस सरकार ने जो यह बिल बनाया है यह बहुत बड़ा इन्कलाब पैदा करने वाला है, में चाहता हूं कि वाकई ऐसा हो सके तो बहुत अष्टा है।

मुआविजे के सवाल पर आप बहुत डिटरमिंड है। इसके लिए में मुबारकबाद दूं कि सिलेव: कमेटी के मेम्बरान इस मसले पर बहुत डिटर मंड थे। जमोदार में म्बरान जो उसमें गये थे तो केवल इसी मंशा से कि किसी तरह कम्पेसेशन बढ़ा ले कानुन चाहे जिस तरह से हो। लेकिन आप इस मसले पर इतने डिटर्रामड थे कि आपने म्केल को बदस्तुर कायम रेला। यह स्केल मुनासिब है या नामुनासिब इसके मुतान्तिक म कुछ कहना नहीं चाहता। बजुन इसके मै यह कहूं कि वह बुनियाद जिस पर आप होल स्ट्रक्चर आफ सोसायटी रखना चाह ने है, यानी क्लासलेस सोसाइटी वह इससे बनती नजर नहीं आती। अजीव यह एक जहमन है कि सो साइटी का स्ट्रक्चर आया एवो न्यूशन से बन सकता है या रिवोत्युतन से। एवोल्यूशन सा जो प्रोसेस आप एडाप्ट कर रहें है उसमे सही नतीजे पर देर से पहुंबने ना अंदेशा है हो सकता है कि सही नक्या हमारे सामने न आ सके। आज आ । जर्म दारों से, जर्मादार साहबान माफ करेगे, यह कह दें कि तुमको मुआविजा नहीं मिलेगा तो क्या नतीजा होगा। जमींदार परेशान होंगे। लेकिन न आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस मालिक ने मुझे और उनको पैदा किया है और जो रोजी का जिम्मेदार है वह उनके बच्चों और औ गद को जरूर रोजी देगा, इसमें कोई भी दो राये नहीं हो सकतीं। लेकिन वह रोजी ऐसी होगी जो आराम और आशाइश के साथ नहों मिल सकती बल्कि पसीना जिस्म का निकलेगा तब रोजी हासिल होगी। सोसाउटी के बेहतरीन फर्द होंगे और ऐसा इन्कलाब करेगे। हो सकता है, रिबोल्युशन करे और कम्युनिस्ट बन जायें, लेकिन उस रिवेल्युशन से मुल्क की बहबूदी होगी।

एक सदस्य--अगर डकत हो जायं ?

श्री फखरुल इस्लाम-मेरे दोस्त कहते हैं कि चोर और डकत हो जाये। अगर डकत हो जाये अपनी खुराक के लिए तो यह सो साइटी का फर्ज है कि जिसी को नंगा और भखा न रहने दे। उनकी खुराक का इंतजाम करती रहे। जो तरीका आपने अख्तियार किया है कम्पेसेशन का, उससे क्लाससेज रोसाइटी नहीं वनतो । कैपिटलिस्ट्स बनिया-मगुजन खुर्राटे की नींद सो रहे है। वह समझते है कि हुनारे लिये कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेट आफ इंडिया ने जो कानून बनाया है उसमें जमींदारी से कड़ दिया है कि २६ जनवरी तक जो कानून पेश होगा उसमें क्वेश्चन आफ कर्म्सेशन (मुआवजे का सवाल) कोर्ट आफ ला से डिस इंड नहीं हो सकता। लेकिन महा नों ओर कैंविउलिस्टों के लिये कोई दका मौजूद नहीं हे, उनको छोड़ दिया गया है। इस तरह फिनरी तौर पर जमोदार को यह हा, लहोता है कि यह म्हेप मदली ट्रीटमेंट कार्येस सरकार क्यों करती है। बनियों, हैपिटलिस्टों को पर्लरिश (उन्नित) करने का मौका क्यों दिया गया है ? इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। इस सरकार को और इस मुक्क को एक क्लासलेस सोसाइडी की तरफ जाना है। इती में हशारी ओर आपकी निज त है। जो कदम उडे वह जन्द उठे। पिवचप और पूर्व से हर तरफ से एक लाल नादल हपारे और आपके सामने नजर आता है, उसकी हवाएं ऐसी है जो तमाम सोसायटी स्ट्रक्चर को खत्म करने वाली है, उस खतरे से हमे और अपको डरना चाहिए। है गरीबी और अमीरी का, उसको हटाने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए। जमींदारों के साथ यह ज्यादती की गयी है। सबको हमें एक लेबिल पर लाना चाहिये और अगर ऐसा हो नाता शाय इ किसी जमींदार को कोई एतराज नहीं होता कि आपने हमारे साथ क्यों ज्यादती की। जब कि सब के सब एक ही किश्ती पर सवार होंगे, सब मुसीबत के अन्दर होंगे, सब के लिये दूध मक्खन होगा या जौ की रोटी और चने की दाल होगी। में अर्ज करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें और अप साफ तौर से कह दीजिये कि हम इतना देगे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा और वह बांड की शक्ल में मिलेगा। बाद में अगर रुपया जमा हो जाय तो आप बांड को बदल सकते है। बांड की जगह पर नकद दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको यह कहने में क्या मुक्किल हैं कि बांड की शक्ल में देगे, यह मेरी समझ में नहीं आता।

जब इन चोजों पर आप गौर करेंगे तमी हमारा मुल्क, काश्तकार और गरीब समझ सकेगा कि इस कानून से हमको कुछ फ़ायदा हुआ। और उन चार खम्भों पर, जिन [श्री फलहल इस्लाम]

पर मैंने इस बिल की बुनियाद रखी है, उन परध्यान देवर इस बिल को जब इस तरीके से रखेगे, तभी इस सूबे को कुछ फायदा होगा।

इसी सिलिसिले में में वक्फ ओर चैरिटेबिल इंस्टीट्यूशन्स के बारे में भी कछ अर्ज करना चाहता हूं। इस सिलिसिले में भी आपने कुछ तब्दीलियां की है। हमारे अ नरबिल मिनिस्टर साहब बहैसियत एक वकील के मुस्लिम वक्फ ऐक्ट के बारे में बाकिफ होंगे। उनके बैनिफिशियरीज का लिमिलेड इंटरेस्ट है। हिन्दू बेवागान की तरह और जिस वक्त वह लिमिटेड इंटरेस्ट वैनिश हो जाता है वह प्रापर्टी खुदा को चली जाती है। तो ऐसी सूरत मे जहां चैरिटेबिल इंस्टीट्यू शन्स की प्रापर्टी पचास वर्ष के बाद जाने वाली है, ऐसे कैसेज के लिये आपने कोई प्राविजन नहीं किया है, ह्वाट यू आर गोइंग दड । किस तरीके से आप वक्फ का सेफगार्ड करेंगे ? वाकिफ मर चुका, उसने प्रापर्टी पार्टी कुलर परपज के लिये डेडीकेट कर दी ओर बतला दिया कि यह प्रापर्टी मेरे मरने के बाद, हमारी फेमिली को जाय, उसके बाद फ़ला कारेखैर में चली जाय। ऐसी सुरत में आप क्या करेंगे ? इस बिल के पढ़ने के बाद कुछ प्राविजन्स देखने में आते हैं, लेकिन किसी से इसकी सफ़ाई नहीं होती। में आपसे अर्ज करूंगा कि, इसके लिये बद्दत आसान तरीका है और में सनझता हू कि मुस्लिम वक्क बेलिडेशन ऐक्ट, १९१३ ई० के बारे में वाक फियत रखने वाले सभी लोग जानते होंगे कि अगर कोई चैरि-टेबिल प्रापर्टी गवर्नमेट अक्वायर करती है फ़ार दि पब्लिक परपज यानी कोई गांव कोई खेत कोई मकानमान लिया कि गवर्नमेंट ने अस्पताल के िये अक्वायर कर लिया तो गवर्नमेंट को अख्लियार है कि वह कर सकती है। लेकिन प्राविजन यह कहता है कि जितना रुपया उसते मिले वह सब चैरिटेबिल परपजेज के लिये जाय यानी दूसरे मामलों में इस्तेमाल न किया जाय । में यह सजेशन देता हूं और में समझता हूं कि दूमरे लाइयर्स भी इसमें डिसएगी नहीं करेंगे कि मुआविजा बेनिफिशयरीज को न दे कर तमाम रुपया एक बैंक में जमा कर विया जाय, उसका फापवा जब तक वह बेनिफिशियरीज उठा सकते है, उपते रहें और अगर रिवर्ट हो तो रिवर्ट कर वी जाय । इससे में समझता हूं कि सही और जायज बात भी हो जायगी अगर मुआविजा देना है दस हजार तो देवें, लेकिन बैक में जमा हो जाय। लेकिन जब वह बेनिफिडियरी मर गया तो वह रुपया मौजूद रहेगा और मृतवल्लीन खा नहीं सकेगे। बोर्ड मौजूद है, उसके जरिये से कर दें, वह उसका देखता रहेगा। यह ऐसी चीजें है जिसमें में नहीं समझता कि आपको कोई खास जहमत या कोई खास परेशानी पैदा ।

कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में ने घोषणा

डिण्टी स्पीकर—अब आप मेहरबानी करके पांच मिनट के लिये बैठ जांय मुझे वो एक जरूरी ऐलानात करने है और वह भी इसलिये कि वे ऐलानात इसी वक्त करने चाहिये क्यों कि कमेटियों के लिये माननीय स्पीकर ने आज १२ बजे तक का वक्त नामजदगी के लिये मुकर्रर किया था और आज चार बजे तक नाम वापिस लेना है। इसलिये में चाहता हूं कि में उनका ऐलान कर दूं ताकि अगर कोई मेम्बर साहब चाहे तो नाम वापिस ले सकते हैं।

आकियालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबंधकारिणो समिति के लिये एक सदस्य का चुनाव होना चाहिये। इसमें दो नाम आये हैं, श्री शिवमंगल सिंह, मथुरा और श्री मुहम्मद नजीर। एक का चुनाव करना है, इसलिये अगर ४ बजे तक इनमें से कोई नाम वापिस नहीं हुआ तो कल १२ बजे और ४ बजे के बीच में रीडिंग रूम में चुनाव होगा।

प्रांतीय म्यूजियम, ल इत् इ की प्रबंधकारिणी समिति के लिये एक मेम्बर का चुनाव होना था। श्री बदन सिंह का नाम आया है और किसी का नाम नहीं हैं। यह कायदे के अन्दर ठीक है। इसलिये में घोषणा करता हूं कि श्री बदन सिंह इस कमेटी के सदस्य चुन लिये गये। संयुक्त प्रान्तीय म्यूजियम ऐडवाइजरी बोर्ड में दो जगहें हैं। इसमें तीन नाम आये हैं, डाक्टर रामधर मिश्र, श्री चन्द्रभान द्वारण सिंह और श्री महम्मद नजीर। दो जगहें हें। ये कायदें के अन्दर नाम सब ठीक है ओर जैसा कि माननीय स्रीकर ने कल घोषणा की थी, इनमें से अगर एक नाम चार बजे तक वापिस नहीं हुआ तो कल १२ बजे और ४ बजे के बीच में इसके लिये चुनाव रीडिंग रूम में होगा।

कृषि तथा पशु—पालन स्थायो सिमिति मे एक रिक्त स्थान के लिये चुनाव होने वाला है। समे श्री शाहिद फाखरी का नाम आग्रा है जो कायदे के अन्दर ठीक है और किसी का नाम नहीं है। इसलिये में श्री शाहिद फाखरी को इस सिमिति का सदस्य चुना हुआ घोषित करता हूं।

प्रान्तोय नर्सेज एड मिडवाइफ कोन्सिल में दो मेम्बरों के लिये चुनाव होने वाले थें और दो नाम यानी श्रीमती सज्जन देवी और श्री गजाधरप्रसाद के नाम आये हें और ये कायदे के अन्दर ठीक है। इसलिये में इन दोनों सदस्यों को चुना हुआ घोषित करता हूं।

बुन्देलखंड आयुवेदिक कालेज, झांसी, की प्रबंधकारिणी समिति में श्री भूदेव शर्मा अचीगड वाले का नाम आया है। कायदे के अन्दर इसमें असेम्बली का सदस्य होना जरूरी है। यह नाम जिनशा आया है वे सज्जन इस असेम्बली के सदस्य नहीं है, इसलिये नामांकन पत्र जायज नहीं करार दिया जाता। इसके मुनाल्लिक अगर कोई माननीय सदस्य इस वक्त विचार करके कोई नाम पेश करना चाहे तो पेश कर सकते है।

एक सदस्य--स्या लिखकर भेजना होगा ?

डिप्टी स्पोकर—जबानी तजवीज कर सकते हैं और अभी कर सकते है। श्री महमूद ग्रली खां—मैं श्री दीनदयालु शास्त्री का नाम पेश करता हू। श्री राममूर्ति—में इसका समर्थन करता हूं।

डिप्टी स्पी कर-मै श्री दीन दया चु शास्त्री को इस समिति का चुना हुआ सदस्य घोषित करता हूं।

आर्कियालाजिकल म्यूजियम, मयुरा, की प्रबंग्कारिणी समिति जिसके लिये दो नाम आये हैं, श्रो शिवमगल सिंगु, मथुरा और श्रो मुहम्मद नजीर, इसमें एक जगह है और प्रान्तीय म्यूजियम ऐडवाइजरी बोर्ड, जिसके लिये तीन नाम आये हैं, डाक्टर रामघर मिश्र, श्रो चन्द्रभानु शरण सिंह और श्रो मुहम्मद नजीर, इसमें दो जगहें हैं।

अब ये दोनों चुनाव कर १२ बजे से ४ बजे के बोद में रीडिंग रूम में होंगे, अगर आज ४ बजे शाम तक इसमें से कोई नाम वाजिस न लिया गया । अगर वाजिस लिया गया तो उसकी घोषणा उठते वक्त कर दी जायगी।

भारतीय पार्लियामेंट के रिक्त स्थानों के लिए चुनाव के संबन्ध में घोषणा

डिप्टी स्पीकर—भारतीय पार्लियामेंट की २५ जगहों के लिये जो नाम वक्त के अन्दर आये और उन सब को कायदे के मुताबिक सही पाया गया वे ये हैं :—

१--श्री जहीरल हस्तैन लारी, इलाहाबाद

२--श्री पुरुषोत्तम् सिंह सेठी, लखनऊ

३-शी हा फिज शेख रफी उद्दीन खादिम

४--श्री लक्ष्मी शंकर यादव, जौनपुर

५—श्री जाकिर हुसेन खाँ, अलीगढ़ ६—श्री कामाख्या दत्त राम. लखनऊ

७—शी युवराज दत्त सिंह, लक्षीमपुर खीरी

८--श्री मौलवी मुन्जूरन नवी

९--श्रीमती सुचेता क्रुपलानी, मेरठ

१०-श्रीमती उमा नेहरू, लखनऊ

११——श्री सादिक अली, बनारस

१२--श्री मुह्म्मद हिफूजुर रहमान, देहली

१३--श्रो मुनेश्वर दत्ते उपाध्याय, प्रतापगढ़

१४-शो कृष्ण चन्द्र शर्मा, झांसी

१५-श्री गोपीनाथ सिंह, कानपुर

१६-शो के० के० भट्टाचार्य, इलाहाबाद

१७—श्रो आर० यू० सिंह, लखनऊ

१८-शो इन्द्र विद्या वाचस्पति, हरदार

[डिप्टीस्पोकर]

१९—श्रो त्रिभुवन नारायण सिंह, बनारस २०—श्रो हरिहर नाथ शास्त्री २१—श्रो बेनी सिंह, कानपुर २१—श्रो नेमीशरण जैन, विजनौर २२—श्रो कृष्णानन्द राय, गाजीपुर २४—श्रो श्रोसरयू प्रसाद मिश्र, देवरिया २५—श्रो शिव चरण लाल, इलाहाबाद २६—श्रो राम ललन, बनारस २७—श्रो मुखनार सिंह, मेरठ

२८—शि देवोदत्त पंग, अत्मोग २९—श्रीमतो शान्ति देवी, लखन ह ३०—श्री मनो गंगा देवी चो गरी, मेरठ ३१—श्री नरदेव स्नातक, मथुरा ३२—श्री बल देव मिन् आर्य, गढ़वाल ३२—श्री कन्हें यालाल बाल्मोकी, बुलन्दशहर ३४—श्री सोहन लाल, बस्ती ३५—श्री द्यामलाल वर्मा, नैनीताल ३६-शी पन्ना लाल, फैनाबाद

श्री जमशेद श्रली खां—-में बह दरियापत करना चाहता हूँ कि क्या अब भी यह स्टेजहैं कि अगर कोई अपना नाम वापिस लेना चाहे, तो ले सकता है।

डिप्टी स्पीकर—दो कमेटियां जो मैने अभी बताई उनके नाम आज शाम को ४ बजे तक वापिस लिए जा सकते हैं। पालिशामेंट के नाम कल एक बजे तक शापिस लिए जा सकते हैं। सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जनोंदारी विनाश ग्रीर सूर्म व्यवस्था विन*

डिप्टो स्पाकर--अब श्री फ़खबल इस्लाम अपनी तक़रीर जारी रवेगे।

श्री फखरल इस्लाम—जनाब वाला, में यह कह रहा था कि औकाफ के सल लेमें गर्ननेंद को यह तरीका अखिनयार करना चाहिये जिससे यह हो सके कि वक्क करने वाले की आखिरी ख्वाहिश जो उसके मरने के पहिते या बाद की थी, और वह उस जायदाय के मुतालिक थी, वह इस गर्नमेंट के कानून से खत्म न हो जाय बिक्क बदस्त्र कायम रहे। क्यों कि मरने वाला तो मर गया, उसे यह मालूम न था कि एक ऐसा जामाना भी आने वाला है जब सरकार एक ऐसा कानून बनायेगा और वह कार्न ऐसा होगा जिसमें उसकी ख्वाहिश के खिलाफ उनकी प्रार्थी को सिक्योर किया जायगा। में हि नाउता हू कि प्रार्थी तो खत्म होगी हो लेकिन उसके मुआविज से उसकी मर्जी यहस्तर कायम रहनं चाहिये। में समझना हूं कि यह एक कानूनी और बुनियादी उसूल हे और गर्वा मेंट को और इस हाउस को इसमें कोई एतराज नहीं करना चाहित।

इनी तरह से चैरिटेबिल और रिलिजस अल्फात के ऊपर एक हगामा मचा हुआ है, मालूप नहीं नयों। मेरी समझ में नहीं आया कि चैरिटेबिल और रिलीजस ओकाफ दोनी अलाहियाँ-अलाहिदा क्यों कर दिये गये अब तक दोनों एक ही साथ डील हुआ करते थे। जहां तक गानी का ताल्लुह है बोनों ऐसे औकाफ है हिन्दू और मुमलपानों के जो चेरिडेबिल और रिजीजा परपर्वेज के लिए होते हैं ओर एक हो माना में इस्तेमाल होते आये है, लेकिन इन बिल के अन्दर इपनी डेफिनन अलाहिबा-अलाहिबा कर दी है जिसकी वजह से एक अजीब क्ष्यूजन पैदा हो गया है। दोनों के पड़ने के बाद भी यही मालूम होता है कि दोनों एक ही नेचर के हैं और दोनों को गवर्नमेंट एक ही लेबिल पर लाना चाहती है। इनके मुजाविजे के मुताहिल ह गवर्न नेंट ने जो कानून बनावा है उसकी में लाई द करता हूं। में देखता था कि औकाफ के मृतवल्ली जमींदारान गलत तौर पर बहुत से रुपये की सर्फ करते थे, उसका बेहतरीन इलाज जो इन कानून में किया गया है वह किनी कवर बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट खुद इन औक्रांक का इन्तर्जाम करेगी। रिलीजस परवृत्रेज का रुपया औकाफ की प्ररा-प्ररादि विशा जाम और उसे मुतबल्ली सक्री करें। में समझता हूं कि जी औकार वाले मर गये हैं वे अपनी गर्दनमें को घन्यवाद देंगे, यकीनन उनकी रूह उन को धन्यवाद देंगी और यह कहेंगी कि आज हमारी प्रापर्टी में से मुकद्दमे बाजी के खर्चें में, कारिकों के खर्बे में या मृतविहिलयों के खर्जे में जो वंसा जाता या वह अब न जावगा।

इस सन्य ३ बनकर २५ मिनट पर समानित-सूबी के एक सहस्य श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

^{*}९ जनवरी, १९५० ई०, की कार्यवाही में छपा है।

सन् १२४९ ई० का सन्वत प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ५०९

जनाबवाला, मैं इसके सिलसिले में यह भी अर्ज करना चाहता था कि इस कानून के जरिये से आपने, जैसा कि मेरे एक लायक दोस्त ने कहा, विडो मेरेज को रोकने की कोशिश की है। इस मुल्क में जिनके पास जायदाद है, उनको आइन्दा बेहतर जिन्दगी बसर करने से रोका गया है।

यह ऐसी चीजे हे जिनपर हमको और आप हो प्यान देना चाहिये और अगर आप इसमें कोई खास बाते न पाये तो यह पर्सनल लाज से न गवर्न हो । में समझता हूँ कि इसके अन्दर और कोई खास बात नहीं है । हिन्दू—मुस्लिम लाज के अन्दर वैसे ही बहुत सी आसानियां है अगर किसी को इत्मीनान नहीं होता है तो वह परमेश्वर के ऊपर इन्जाम लगा देता है । जो कुछ इल्जाम होता है वर् परमेश्वर के ऊपर लगा देता है और गवर्नमेट के ऊपर नहीं लगाता है।

इन चीजों को रखते हुये भी में आप से अर्ज करूंगा कि जो मुझ में ज्ञान है, ऐज ए ग्रेजूएट आफ ला, उसके बावजुद मैने इस कानून को काकी पढ़ने की कोशिश की, कल भी में १२ बजे रात तक पढ़ता रहा और आज मुबह भी पढ़ता,रहा और यह सोचता रहा कि यह कानून क्या है और इसका क्या हुआ होने वाला ह, किस तरह से यहा की अवाम इस हो समझेंगी, इसका निफाज कैसे होगा, इसके जरिये से विलेज बैरिम्टर्म की कितनी चमक जायेगी और उनके जरिये से वकीचों की कितनी चमकेगी । कहने का मतलः यह है कि मजबूरियां तो बहुत सी है लेकिन आप कम से कम हमको इतना मौका दे कि इसको हम पहले पढ ले, पढने के बाद इसको समझ ले, समझ ने के बाद इस को डाइजेस्ट कर ले और फिर उसके बाद राइट और रांग का डिस्टिंकशन करके अपनी राय का इजहार कर सके। उधर बैक बेचेज के जो बैठने वाले हं उनके लिए तो मैं कह चुका हूं 'दी डेफ ऐड दी डम्ब। इस जुमला के लिए आप मुझे मार्फ करेगे, लेकिन वाकया यह है कि फैबिनेट का एक डिसीशन हो गया और उसे फा होवर्स हो मानना है। खैर, लीव देम, इस तरफ के भी जो लोग है उनकी भी यह हालत है कि वह चाहै जितनी बुद्धि रखने वाले हों लेकिन वह भी इन तमाम दफान को पढ़कर, समझकर ओर डाइजेस्ट कर इतनी जल्दी ऐसे अमेडमेट्स नहीं पेश कर सकते है जिनसे काश्तकारों की तकली के कम हों। कन्नेसेशन का बढ़ना ओर घटना तो मामूत्री चीज है लेकिन यह एक ऐसा कानून है, जिससे में महसूस करता हू कि काइतकारों की मुसीबत ज्यादा बढ़ आयेगी और आसानियां कम हो जायेगी। इसके छिए काकी मौका हमको भी होता वाहिये और आपको भी होता चाहिये। काफी मौका इसिनए होना चाहिये क्योंकि आपके भी जजमेट में गलती हो सकती है। जब आपने मिनि हो का चार्ज लिया था तब आपने सन् ४७ में कुछ जगली जानवरों का मारना बैन कर दिया था लेकिन सन् ४९ में आपने बैन हटा लिया।

माननीय मान सचिव--उस वक्त कम्यूनल दंगे हो रहे थे, इसलिए आपके लिए खतरा था। अब वह खतरा जाता रहा है।

श्री फखहल इस्लाम—में आपको यह बतला रहाथा कि आपका भी जजमेट गलत हो सकता है, इसलिए आपको भी बहुत सोच—समझ कर काम करना चाहिये। इसके अलावा इस एवान के मेम्बरान को इतना मौका होना चाहिये कि वह इस पर गौरखोज करने के बाद अपने अमेडमेट्स दें सकें। जैसा कि आप समझते हैं कि इस पर कल से अमेंडमेट्स शुरू हो जायं, में समझता हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप इसको १५,१६ तार ख तक ले लें तो ज्यादा ठीक हो। इन अल्फाज के साथ में आपको मुबारकबाद देता हू कि कम से कम आपकी बदौलत सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे यह हूं कि हमने एतराजात के सामने रक्खे हैं उन पर आप गौर करेगे और उनके मुताबिक अमल करेंगे और अपनी पालिसी ज्यादा से ज्यादा वाजह तौर पर हमारे सामने रक्खेंगे।

श्री गाम शंकर लाल-श्री मान् अध्यक्ष महोदय ! मेरा विचार हाउस में डिवेट में हिस्सा लेते का नहीं था, लेकिन कुछ मित्रों ने मुझ ५र कुछ लास अनुग्रह किय। है, इसलिये मै इसमें हिसा लेकर अपने ख्यालात का इजहार हाउस के सामने करूगा। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यह बिल जो जमीदारी एबालिशन और लैडरिफामस का है इसका ताल्लुक हैमारे सुबे में रहने वाले ६ करोड इंसानों से है और इसकी कामयाबी ओर नाकागयाबी पर हमारे सुबे की तरक्की का बहुत कुछ दारोमदार है। इसलिये इसमें कोई शबहा नहीं है कि यह एक बहुत ही इम्पार्टेट बिल है। आगे चल कर में यतलाऊगा कि किस सरह से यह रिवोल्यू जनरी बिल भी है। यह जाहिए हैं कि किसी मुलक में जब इनकलाब होता है तो वह एकांगी नहीं होता है बल्कि वह हर एसपेक्ट में होता है। वह सोशल, इकोनामिक सभी कुछ में होता है। अगर हमारे मुल्क में पोलिटिकल इनक्लाब हुआ तो आर्थिक इनक्लाब भी होगा इसके लिये जमोदारी का जाना जरूरी है और जमीदारी जाने के लिये यह आवश्यक है कि यह बिल पास हो । जैसा कि हमारे नेता पं० गोविद बल्लभ पत ने कहा था कि पोलिटिकल एसरेक्ट के साथ-साथ जमीवारी का खात्मा एक एथिकल नेसे सिटी है। मुझे खुशी है कि इस हाउस के करीब-करीब सभी मेम्बरो ने इस बात को तसलीम कर लिया है कि जमींदारी का खात्मा होना जरूरी है और इसमें किसी को शक य शुबहा नहीं है कि यह खत्म होकर ही रहेगी। सवाल तो सिर्फ यह है कि आगर जमींदारी खतम हो तो कुछ मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय और इसके बाद हमारे मुल्क का जो लंड का कानून हो वह किस तरह से हो इसके ऊपर ज्यादा बहस की गई है। सबसे बहिले तो यहा पर उसूत्र के ऊपर बहम की गई है। कुछ लोगों ने तो सोशलिस्ट प्वाइंड आफ व्यू से, कुण लोगों ने कम्युनिस्ट प्वाइंट आफ व्यू ते और कुछ लोगों ने गांधियन व्याइंट आफ़ व्यू से एप्रोच किया है। लेकिन हमें तो यह देखेना है कि किन प्वाइंट आफ व्यू से हमारे सूबे की प्रासिपरिटी हो सकती है किस तरह से हमारा सुबा खुदाहाल रह कर आगे तरक्की कर सकता है। यही एक अप्टेरियन हो सकता है और उस काइटेरियन से ही हम उसके प्रोविजन को देख सकने हैं। में अपने लायक मुजुर्ग मोलाना हसरत मोहानी साहब के खयालात से बिल्कुल इसफाक करता बशर्ने कि हमारे सबें की सारी की सारी जमीनें खाली होती और उससे किसी को भी कोई कट नहीं होता। में स्वयं इस बात को कहरा कि जमीनों का जरूर नेशनलाइजे गन कर दिया जाय, लेकिन बंदिक स्मती से यहां की हालत ऐसी नहीं है। आज तो हमारे सूबे में जितनी जमीनें है वे बिल्कुल किसानों के कब्जे में है और यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किसान उस पर अपना कब्जा जमाये रखना चाहता है और खेती करता है। अब यहां पर उनका नेशनला-इजेशन किया जाय इमकी कोई पासिबिलिटी नहीं है। में जानता हूं कि हमारे यहा के किसत नेशनलाइजेशन के लिये कभी तैयार नहीं है और यह भी तय है कि हम इस मुल्क में नेवानलाइ जेवान डिक्टेटरिवाप के जरिये नहीं ला सकते हैं और जब तक हमारा बैक पान्उड ऐसा न हो कि किसान नेशनलाइजेशन के लिये तैयार हो तब तक हमारे इस सूबे में दूसरा कोई अल्टरनेटिय नहीं है। इस बिल के जरिये यह भी तजबीज की गयी है कि किसानी की उनकी जमीन का पूरा-पूरा मालिक बनाया जाय उनका लगान कम किया जाय और उनको भूमिघरी का अधिकार दिया जाय। वह इस बिल के जरिये किया जा रहा है। अब तो सवाल कम्पेनसेशन का है। कम्पेनसेशन के मसले पर वो तरह से बहस की गयी है। एक कानूनी तरह से बहस की गयी है। उस का नूनी बहस में जो कानूनी पहलू कम्पेन-सेवान का है उसकी तो हमारे सोवालिस्ट दोस्त भी कबूल करते है। उस जमाने में जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट या वह और आज भी मौजूबा जो विधान परिषद् है उसने तय किया है कि उनकी कम्पेनसेशन विया जाय। फ़िए उनको कम्पेनसेशन न देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने तो इसको भी तसलीम कर लिया है उनके रहतुमा आचार्य जी ने इसकी मान लिया है कि कम्येनसेशन वेना चाहिये। दूसरे जहां तक मारिल उच्छी का ताल्लुक है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जब हम क्लासलेस सोसइटी बनाते हैं तो इस मुक्त में किसी तबके की हम ऐसा नहीं कर सकते कि वह अपनी गुजारा भी नहीं कर सके। इस तरह से कोई जिन्दा नहीं रह सकता और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता।

इस लिहाज से कम्पन्सेशन मिलना जरूरी है। अब कम्पन्सेशन क्या दिया इसके लिये मौजूदा हालत को देखना होगा। जैसा कि हाउस ने रिजोल्यूशन पास किया था कि इक्वीटेबिल कम्पन्सेशन होना चाहिये। इक्वीटेबिल कम्पन्पेशन क्या हो सकता है इसके लिये इस बात से अन्दाजा लगाना होगा कि हमारी कैंगेनिटी अदा करने की कितनी है। उसके हो मुताबिक हमको अदा करना होगा। हमारी मुखालिफ बेचों के भाई किसानों के साथ बहुत हमददी दिखाते है कि किसानों की हालत बहुत है और खराब है वह रुपया नहीं दे सकता लेकिन जब कम्यन्सेशन का सवाल आता हैं तो लम्बी-लम्बो स्कोम बनाई जानी है कि यह होना चाहिये और वह चाहिये। यह देशों बातें साथ-साथ नहीं चल सहती। एक तरफ तो यह कहा जाय कि किस न परेशान है, बेहाल है और दूसरी तरफ लम्बे कम्पन्सेशन की बान कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल यह है कि मुल्क की मौजूदा हालत को देखते हुए इस सवाल को तय करना चाहिये और मुल्क की मौजूदा हालत को देखते हुए जो इस बिल के अन्दर तजवीज किया गया है उसी बढकर ओर कोई स्कीम कम्पन्सेशन के लिये नहीं हो सकती है। अर इसके बाद सवाल यह है कि खेती का जो काम है उसके बारे में आपने देखा उसके लिये बहुत अच्छा उसूल मान लिया गया है कि जमीन उसी की होनी चाहिये जो उसको जीतता है और बोता है। "Land must belong to the actual tiller of the Soil" (भूम वास्तविक कृषि करने वाले कृषक की होनी चाहिए।) हमारे मुल्क में खाने की कमी है की बद इन्तजामी है। उसके लिये यह उसूल ठीक ही है कि जमीन उसी के पास होती चाहिते जो उसको जोतना है और बोता है और जो जमीन को जोतता नहीं है दूसरों से जुतवाता है या और किमी तरीके से एक्सप्ल यह करता है उसके पास नहीं रहिनी चाहिये। यही उसूल इस बिल के अन्दर मान लिया गया है। आपने देखा होगा कि इस बिल के अन्दर सबलैंटिंग को बंद कर दिया गया है। एक सवाल हमारे सापने यह रखा जाता है कि जमीन हा फिर से डिस्ट्रींब्यूशन किया जाय। यह डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सहत ह। हमारे सूत्रे में ४१३ लाख एकड जमोन ऐसी है जो मजरूआ है और इस वक्त कास्त के अन्दर है। ८० लाख एकड के करीय जानि ऐसी बतलाई जाती है जो गैरमजरूआ है और कास्त के अन्दर लाई जा सकती है। और यह अन्दाजा है कि १ करोड़ के करीब किमान हमारे सूबे के अन्दर रहते है अगर यह जमीन इन लोगों में बराबर के हिसाब से बांट दी जाय तो उमका नतीजा यह होगा कि हर एक आदमी के हिस्से में ५ एकड़ जमीन आयेगी। इससे ज्यादा नहीं आ मकती। हमारे सोशिलस्ट भाई किस तरह से उनको इकोनामिक होल्डिंग बढ़ाकर दिलान। वाह है है। उनकी यह बात समझ में नहीं आतो है वह किस तरह से इसको तकमीम करेगे। कल मेरे दौस्त रोशनजमां साहब ने कहा था कि उनको ज्यादा मिलना चाहिये। क्या उनका यह मतलब है कि जो अब किसान है उनसे जमीन छुःवा कर उनके नीचे से निकाल कर उनको बदलल करके दूसरे थोडे से ओदिमयों को दे दो जाय । क्या यह पासिबिल है । मैं जहां तक समझता हूं आजकल की मौजूदा कि जां में यह पासिबिल नहीं हो सकता। दूसरे अगर अप इस तरह से ओसत बटवारा करेंगे तो आप इसको समझ लें कि मूबे के द करोड़ लोगों में १ करों। आदमी शहरों में रहते हैं। वह खेती का काम नहीं करते है। उन लोगों को आपको गहला देना होगा क्यों कि उनके लिये यह मुमकिन नहीं हैं कि वह खुद ही गल्ला पैदा कर सके । अगर आप ५ एकड़ के हिसाब से बांट देने है तो आपको यह मानना पड़ेगा कि गल्ला बाजार में नहीं आ सकेगा और शहर में रहने वालों के लिये खाने का कोई इन्तजाम नहीं हो सकेगा। इसलिये जो कुछ भी पासिबिल है वर तो यही है कि जो जमीन काश्तकार की जोत में है वह उसके पास है। छो । दी जाय। यही सही तरीका था और शही एक पासि । ल तरीका हो सकता थः अगर ५० ए हड़ ज नीन बड़े-बड़े जमींदारों के पास छोड़कर शेष जमीन का बटवारा करना हो

[श्री रामशकर लाल]
तो प्रथम तो इसमें बहुत सम्य लगेगा फिर केवल एक लाख एकड़ जमीन आयेगी।
एक लाख एकड़ जमीन एक करोड़ बाश्त करने वालो में ओर करीब २५ लाख
खेतहर मजदूरों में से आप किसको देगे और किस तरह से बांटेगे, यह हमारी समझ में
नहीं आता। जब कि सोशिलिस्ट पार्टी के लोग कहते है कि अनइकानामिक होलिंडाज नहीं
बढ़ाना चाहिए। फिर आप को डिमारकेशन करना पड़ेगा और उसमे वक्त लगेगा। साथ ही
आप यह भी कहते हैं कि जमींदारी एबालिशन जल्द से जल्द करना चाहिए और दूसरी तरक
यह भी कहते हैं कि जमींदारी एबालिशन में देर लगे। आप अपनी तरकी बों से उन्हीं की
ताईद करते हैं। मैं कम से कम उन लोंगों में नहीं हूं कि जो बदिकस्मती से जमींदारी एबालिशन को टालना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तो यह अब ओवर इस् है और इसको जल्द से जल्द
खत्म करना चाहिये।

अब सवाल यह होता है कि अगर डिमारकेशन नहीं होना चाहिये तो इन ३६ लाख शिकमी काश्तकारों का क्या होगा। में पमझता हूं कि उनके मुताल्लिक पहिले बिल में तजबीज यह थी कि सवा ६ एकड़ से कम के जोत वाले ५ बर्ष बाद अन्ने शिकमियों को बशर्ने कि बेदखल करे, सरकार नोटिफिकेशन करें। यह एक अच्छी तजबीज थी और इससे लाखों मजदूर, बिद्मतगार नाई-बारी और मेहनत पेशा लोग जो जमीनों पर काबिज है उनकी हिफाजत इससे हो जाती है। अब वह लिमिट ८ एकड़ हो गई है हमने जो सवा ६ एकड़ रखी है वह बेसिक

होलिंडिंग की बात रखी है और वह इकानामिक की नहां है।

स्टैन्डर्ड होलिंडिंग क्या होती है यह अलग-अलग मुल्हों में और अलग-अलग जगहों पर मुखतिल हु हो सकती है। स्टैन्ड डं इकानामिक या बेसि होल डिंग यहां तक कि हमारे सूबे के पूर्वी और पन्छिमी हिस्सों में जुदा-जुदा है। अमरीका में इकानामिक होलंडिंग २५ और ३० एकड़ के करीब होती है। हमारे पूर्वी जिलों में औसत होलंडिंग ३ एकड़ से ज्यादा नहीं है। तो ऐसी हालत मे यह कहना कि बेसिक होलंडिंग ८ एकड़ की हो और सवा ६ एकड़ की न हो यह मुनासिब नहीं है क्योंकि जहा आपको ३६ लाख किसानों और मजदूरों को वेखना है वहां सवा ६ एकड़ ही रहना जरूरी है। इस सिलसिले में हमारे बुजुर्ग श्री इन्द्रदेव जी त्रिपाठी ने भी हमको याद किया था। उन्होंने कहा कि हम काइतकारी से वास्ता नहीं रखते और वेसे ही बाते करते हैं। में उनकी यह बतलाना चाहता हैं कि में भी एक किसान हूं ओर भिन्धर हूं और मेरे यहां खेती भी होती है और मेरे पेशे के नाते भी किसान मेरे पास आते है। इसके अलावा कांग्रेस के काम के सिलसिड में भी हजारों किसान मेरे पान आने है। इस वास्ते यह कहना कि मै खेती से वाकिपवत नहीं रखता, ठीक नहीं है । में भिसाल के तौर पर कुछ बातों की तरफ आपकी तवज्जह विलाना चाहता हूं। बस्ती जिला नेपाल के करीब है और वहां भी वही हालत है कि जो नैपाल मे है। हजारों किसान ऐसे है कि जिन की जोतें जमीवारों की सीर व खुदकावत में लिखी हुई हैं। सरकार ने इस को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वावजूद तमाम रिकार्ड आपरेशन कराने और रिकार्ड आफिलर मुकरें करने के भी बहां के रिकार्ड दुरुस्त नहीं हुए और बदिकस्मती से जो रिकार्ड आपरेशन पिछले बार हुए उन में वंका ५४ की कार्यव ही नहीं हुई और बहुत सी अदालतों ने मुकवमों में दफा ६३ के और १४५ के इन काइतकारों का कब्जा नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि बहुत से किसान अपनी जमीन से महरूम कर दिए गए। में खाहता हूँ कि उन बेचारों पाल एक बिस्वा भी को मिलना चाहिये। हजारों काइतकार ऐसे है, जिनके जमीन नहीं है।

इसके बाद में इस बिल से गैर-मृतालिलक और जबरबस्ती की जो बातें इस हाउस में कही गई है उस सिलसिल में दो तीन बातें अपने जिले की कहना च।हता हूं। में यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में सोशिलिस्ट, कम्युनिस्ट और आर० एस० पी० वाले मेरे दोस्त ह और हमारे उनके

ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे उनके कोई झगड़े नहीं है। क्या कार्रवाई की गई है, हाउस के मेम्बरान को जानना चाहिये। आर० एस० पी० वालों ने किसानों से कहा कि एक रुपया सैकड़ा हमें दे दो हम तुम्हारा दस गुना लगान माफ करा देगें। इस तरीके से हजार दो हजार रुपया जमा किये और जब हम लोग उस गांव में गए तो यह मालूम हुआ । हम लोगों ने मीटिंग की। किसानों ने हमारे कहने से लगान जमा कर दिया । अब उन काश्तकारों की आर० एस० पी० वालों ने सिंच।ई बन्द करदी । घर में रहना और निकलना कठिन हो गया । उनका सोशल बाई-काट कर दिया । यही नहीं, हम लोग वहां मीटिंग करने गए तो हमारे सोशलिस्ट दोस्तों ने झगड़ा करना चाहा । हमने पूछा कि आखिर क्या बात है ? देश आजाद है, सबको फ्रीडम आफ स्पीच है। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम लोगों को दबा रहे हैं। हालांकि हरिगज ऐसा नहीं है। हम जलसा कर रहे थे और हमारे सोशिलस्ट दोस्त नाच-पूद रहे थे। शोरोगुल कर रहे थे। हमने उनसे पूछा आखिर क्या बात है ? यह चीज तो अच्छी नहीं है । उन्होंने कहा कि यह भी हमारे प्रोग्राम में है। फिर भी बहुत से किसान भूमिधर बन गए एक बुढिया रोती हुई हमारे पास आई और उसन कहा कि जमींदार ने उसकी फसल कटवाँ दी क्योंकि उसने रुखा जमा किया था। आर० एस० पी० वालों ने इस तरह की हरकतें की है ओर कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है तो कहा जाता है कि दबाव डाला जा रहा है और जब किया जा रहा है। मुझे बहुत सी बातें कहना थीं मगर दो तीन बातें है जिनका जदाब देना पिहुली बात यह कही गई कि यह कानून ऐसा है जिसे काश्तकार जानना भी नहीं । मुझे इस बात पर बड़ो हंसी आई। हिस्ट्री में आप ऐसा कानून नहीं पेश करेंगे जिसके मताल्लिक इतना प्रवार हुआ हो । इस कानून के मुताल्लिक हजारों जरुते किये गय । कार्यसपाटो ने, सेश्चिलस्ट पाटो ने, आर एस० पीठ वालो ने, जर्मीदार पाटों ने, कम्यूनिस्ट पाटों ने और अफसरान ने । दुनिया में कोई ऐसा कानून जिसका इतना प्रचार किया गया हो जायद ही मिले। हमारे दोस्त किसी तहसीलार से नाराज होगए हैं इसलियें उस की बराई करते हैं। हनारे देक्त ने पटवारियों पर छोंटा कसा है। में यह जानना चाहना हूं कि आप यह कैसे कह सकते है। यह तो हाउस की डिगनिटी के खिलाफ बात है कि आप उसके खिलाफ बान कहें जो जवाब न दे सके। मैं यह मानना हूं कि पटवारी बदनाम जराप्तर हैं। मैं पूछरा चाहता हूं कि क्या इस हाउस के मेम्बरान को यह इजाजा है कि वह लीग पाटों से जनना पाटों में हो जायें और सोजलिस्ट पार्टी में हो जयें। क्या पश्वारो को बस्लने और चेंज हो। का मौका नहीं है ? मुझे हैरन है कि पटवारी इतनी जल्दी कैने बदल गए। इस वका सूत्रे में भूमिधर के आन्दो जन का जो रेकार्ड है वह परवारियों का बहुन अच्छा है। करोडों कि नानों को पर्वे उहींन बाडे हैं। कहीं से शिहायत नहीं अई है। करोडों ध्या जमा कि । मै यह मूत्र करने वाला था कि उनको जब वे तहसील में आवें तो उन्हें कम से कम ट्रैबिलिंग एलाउन्स जबर दिया जाय। हाउस को यह मालम है कि परवारी को तिर्फ २५ राया तनस्वाह मिल नी है। इस हाउस के मैम्बरान यह अन्दाजा लगा सकते है कि २५ रुपया में पटवारी की क्या गजर होगो। लेकिन हमारे मुन्ती साहब को इन सब बोजों से क्या वास्ता! उन्होंने कु 3 बानें सुना दीं। उन्होंने कुछ कानून का भी हुताला दिया अरेर कहा कि सिविल ला यह है कि अगर किसी आदमी की कुर्ती हो तो उनको रियनारी न हो। लेकिन बर्दका भूल गये कि निवित्त प्रोसोजर कोड में सब मेयड्न दिये है। इसी तरह से इम बिल में भी यह दिया है कि युद् मेयड्व है जो इस्तेमाल किए जा सकते है मालगजारी की वसूत्री में। उसमें यह कहीं नहीं जिला है कि

[श्रो रामशंकर लाल]

यह सब चाजें एक साथ हो काम में लाई जायंगी। लेकिन उन्हें इन सब चीजों से

क्या वास्ता, उनको जो कहना था कह डाला।

इसके बाद उन्होंने बटवारे की बाबत कुछ फ़रमाया। बटवारे के मुताल्लिक उन्होंने कहा कि शायद आप अनइकोनामिक होल्डिंग्ज बनाने जा रहे हैं और भूमिधर को आपने बटवारे का हक दे दिया। में पूछता हूं कि जब इस हाउस और सब लोगों का यह ख्याल है कि भूमिधर को ऐबसोल्यूट राइट्स दिए जामं तो फिर यह किस तरह से होगा कि हम उसको राइट आफ़ पार्टीशन न दें। यह तो हमारी खुद ख्वाहिश हैं कि अनइकोनामिक होल्डिंग्ज न हों और बटवारा न हों लेकिन हम जबवंस्ती तो नहीं कर सकते। जब हम चाहते हैं कि किसान को हर हक दें तो फिर उसको राइट आफ़ पार्टीशन न दिया जाय, यह तो मेरी समझ में नहीं आता। तो फिर अगर सेलेक्ट कमेटी ने यह राइट दे दिया तो क्या गुनाह किया?

फिर मुपती साहब ने कुछ सेटिलमेंट की बात कही और कहा कि पता नहीं लगान कब बवल जाय। यह किसानों में गलतफहमी पैदा करना है। शायद वह यह समझते ही नहीं हैं कि सेटिलमेंट क्या चीज है। वह यह कहते हैं कि इस बिल में यह लिखा ही नहीं हैं कि यह लगान कब तक रहेगा। यानी जो बात लाखों मीटिंग्स में कही गई कि यह लगान ४० वर्ष तक घट-बढ़ नहीं सकता। उसके लिये भी मुपती साहब यह कहें कि यह चीज साफ नहीं है तो में यह कहंगा कि मुपती साहब जानबूझ कर गलतफहमी फैलाना चाहते हैं और इसके अलावा उनकी क्या मंशा हो सकती है? सेटिलमेंट में बहुत सी चीज होती हैं. रेकाई आपरेशन, सेटिलमेंट आफ़ लैंड रेबेन्यू तो गवर्नमेंट पर हैं। लेकिन जब हमने यह कह दिया कि ४० वर्ष तक नहीं करेंगे तो फिर यह कहना कि उनसे हम लैंड रेबेन्यू का सेटिलमेंट करेंगे, मेरे ह्याल से गलतफ़हमी फैलाना हैं। तो मेरे ह्याल में यह मुनासिब नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये।

मुझे उम्मीद है कि यह बिल बहुत जल्द ला बन जायगा। यह इस मुल्क के लिए एक बहुत ही रिश्रोल्य शनरी मेजर है। हमारे सुबे का इससे कल्याण होगा और में इसके लिए कांग्रेस गवर्नमें द को बधाई देता हूं। में ही नहीं बल्कि इस सूबे का हर एक किसान हमारी सरकार का ऋणी है।

*श्री सुरतान श्रालम खां-जनाब चेयरमैन साहब! इसमें शक नहीं कि ऐसे तारीखी और इन्कलाबी विल के पेश करने पर मुअज्जिज बजीर माल साहब को जितनी खुशी होगी उसकाअन्दाजा हम सब लोग लगा सकते हैं। उनकी इस खुशकिस्मती की भी वाद देनी चाहिये कि इस किस्म के बिल की पेश करने का उनकी मौका मिला। इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं कि इस ऐवान की तारीख में जितने बिल यहां अभी तक पेश किये गये है शायद यह बिस्र उन सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा तारीखी और इन्कलाबी है सियत रखता है। मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि हमारी सहू लियत की खातिर सेलेक्ट कमाडी में बिल पर गौर करने का मौका अंग्ररेजी में बिया गया था और उस बिल पर हमने वहां अंग्ररेजी में ही गौर किया या और बहुत से लोगों ने अपने नोटस आफ डिसेंट और तरमीमात भी अंग्ररेजी में पेश किये थे। लेकिन इस ऐवान की जबान और भाषा हिन्दी होने की वजह से इत बनत जो बिल हमारे सामने हैं वह हिन्दी में है। मुझे यह नहीं मालूम कि यह हिन्दी का बिल इस अंग्रेजी के विल का कितना सही तर्जुमा है जिस पर हमने सेलेक्ट कमेटी में गौर किया था या यों कहिये कि वह अंग्रेजी का बिल जिस पर हमने सेलेक्ट कमेटी में ग्रीर किया था कहां तक इस बिल का सही तर्जुमा है। में अपनी नावाकफियत की वजह से इसके मुताल्लिक कोई ठीक राय तो कायम नहीं कर सकता. लेकिन जो बिल कि हमारे सामने है जिसकी एक नकल अंग्रेजी में है और एक हिन्दी में है, मैंन

[&]quot;आमनाय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

उसे पढ़ने की कोशिश की तो मुझे बाज चीजें ऐसी मालूम होती है जिनसे यह पता लगता है कि ये दोनों बिल बिल्कुल सही तर्जु मा नहीं है। में उन चीजों की बजाहत में जाने की कोशिश नहीं करूंगा बिल्क सिर्फ़ इस सिलिसिलें में आनरेबिल वजीरे माल साइब की तबज्जह इस तरफ दिलां ऊंगा कि इस बात का एक मर्तबा फिर यक्नीन कर लिया जाय कि दोनों बिल वाकई एक है या इनमें कोई फर्क है। पेश्तर इसके कि यह भवन इस बिल पर ग़ौर करे और उसके बाद इस तारीखी बिल को पास करें ऐसी कोई कमी अगर हो तो वह पूरी हो जानी चाहिये।

मैं इस बात का भी एतराफ़ करता हूं कि मेरी बदिकस्मती से मुझे इस बिल के उन तीन दिनों में यहां हाजिर रहने का मौका नहीं मिल सका जिन तारीखों में इस पर आज की तारीख से पहिले बहस हो चुकी हैं। में ९, १० और ११ को इस भदन में मौजूद नहीं था। आज ही हाजिर हुआ हूं लेकिन प्रेस के जिरिये से जो इत्तिला मुझे अब तक मिली है, जिसको मेने पढ़ा है उससे पता लगता है कि इन तीनों दिन बराबर मुख्तिलिफ हजरात ने इस बिल के मुताल्लिक अपने—अपने ख्यालात का इजहार किया है। उससे इस बात का भी पता चलता है कि यह बिल एक ऐसा बिल है जिस पर इस ऐवान के हर तबके का इस ऐवान की हर जमात का, पूरा पूरा ध्यान है और वे इसमें पूरी—पूरी दिलचस्पी ले रहें हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब भी है कि जब हम एक बहुत ही बड़ा मसला हल करने जा रहे हैं यानी जमींदारी सिस्टम को इस सूबे से खत्म करने जा रहे हैं तो कादा यह फैसला एक ऐसे तरीके पर हो कि जिससे लोगों के दिलों को तकलीफ न पहुंचे बिल्क मामले का फैसला इस तरीके पर होना चाहिये कि वह हर शक्स जो इस बिल से एफेक्ट होने वाला है वह शक्स मुतमइय्यन हो।

यह सही है कि जब कोई कानून बनता है तो उससे कुछ न कुछ लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है और इससे यह बिल भी खाली नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी यानी इस ब्नियादी बात को मानते हुथे भी हमें इस बात की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये कि हर तरह से इसमें पूरा कोआपरेशन मिले और हर तरह से इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि इसकी एक ऐसे सांचे में ढाला जाय जिसके मातहत इसमें उन तमाम बातों के हल करने की कोशिश की जाय जिसका मुस्तलिफ जमातों से ताल्लुक ह। इस बिल का काश्तकार से उतना ही ताल्लुक है जितना इसका जमींदाः से ताल्लुक है और न सिर्फ काःतकार और जमीदार से ही बल्कि इसका हुकूमत से भी उतना ही तारलुक है। इस बिल का सूबे की और मुल्क की इकीना सिक कंडीशन से ताल्लुक है। इस बिल का, मै तो यहां तक भी कहने की जुरंत करूंगा, सुबे आइन्दा पौत्टिकलिफजां से ताल्लुक है। इसलिये इस बिल को एक ऐसी फिजा मे, एक ऐसे रंग में, एक ऐसे तरीके पर की कोशिश करनी चाहिये जिससे लोगों के दिलों में बिटरनेस बाकी न रहे बल्कि लोग आसानी के साथ तय कर सकें। में जानता हूं कि इस वक्त इस बात के बहस करने का मौका नहीं है कि जमें दारी बाकी रहे या खत्म हो में भी एक छोटा सा जमीदार हूं लेकिन में समझता हूं कि जिस बक्त मुक्क या सूबे का ' फाद सामने हो हमें अपने जाती मफाद को भूल जाना चाहिये। इसी एतबार पर मैंने पहिले भी कहा है और उस वक्त भी जब कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा रहा था और जय जब ऐसे मौके आये है मैने कहा है कि बेशक अब मौका ऐसा है कि जरूरत है कि अब जमीदारी खत्म की ज ये और किस तरीके पर की जाये। लेकिन इसकी खत्म करना एक बहुत बड़ा मसला है और यह इतना बड़ा मसला है कि अगर मुझे इज जन दी जाये तो में यह कर सकता हू कि बावजूद इसके कि इस पर इतना वक्त सर्फ किया गया है लेकिन फिर भी इस पर इतने तवज्जाह नहीं दी जा सकी जितनी का यह महताज या और जितनी इसके लिये जरूरत थी। कोई बिल ये. मसविदा कानून इस ऐवान में सिर्फ उस वक्त आनः चाहिये जब कि उस पर काफी गौर हो चुका हो उसके हर पहलू पर नजर डाली जाये। वर्ना दिक्कत यह होती है दुश्यारी यह होती है कि बिल के पास होने के बाद जल्दी ही तरमीमात पर तरमीमात [श्री सुल्तान आलन खां]

करने की जरूरत होती है और यह चीज किमी जमात और पार्टी के लिये मुकीद नहीं हो सकती। पेरतर इसके कि जमींदारी खात्में के सिल्सि रे में आगे बढ़ में यह कहता हूं और अपना फर्ज सनमता है। इसने शह नहीं कि इस बिल को इस मौके पर लाने के बजाय और गौर करने के बाद इसको लाया जाता तो ज्यादा मुनासिब होता। में जैसा कि पहिले अर्च कर चुका है कि अब जब यह आगा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह वाक्रया है कि जमीदार इस मुल्क ओर इस सूत्रे में एक खास हैसियत रखता था। ज रो । र देहाती रक वे में एक पोवट था ओर तमाम देहात उसके चारी तरफ घुमता था। में भानता हूं कि इस तबके में भी करण्यान आ गया है लेकिन वह सिर्फ इसी के लिये नहीं है, बिलक ऐसा है कि इसमे कोई भी शोबाबरों या मुस्तसना नहीं है। हो सकता था कि इस कर अन को दूर करने के लिये हम जमीदार को एक ज्यादा मौतू और कारामद आला और उसके जरिये देहात डेव ज्यमेट का प्रोग्राम जोरी करते। इसको एक इंसर् मेट मानकर एक्टोबिटीज चलाते ओर यह भी हो सकता था कि हम जमीदार से सेत्रल गर्वा में को तरह जै । कि उसने इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ किया है एक समझौता कर लेते । सेंट्रल गर्नामेंड ने सनसौता किया है और जैसा कि इंडस्ट्रियलिस्टस को इत्मीनान दिला दिया है। "No nationalisation for the next 10 years" (अगले १०वर्ष तक कोई राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता।) लेकिन यह चीज नहीं की गई। मैं नहीं समझता कि इसको क्या वजह है और क्यों नहीं की गई। एलेक्शन होने बाल। है और यह इलेक्शन तभाम मुल्क में होगा। यह मं नहीं कह सकता हूं कि इससे पहिने यह बिन्ज आजायेगा और इस पर अवल हो सकेगा या नहीं। मै यह चाहता है कि जब जनीदारी एबालीशन होना ही है तो इस बिल को इलेक्शन से पहिले असल में आ जीना चाहिये। में आप से कह सकता है कि इसके लिये बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी तब जाकर कहीं यह बि र स्टैच्ट बुक पर आने के काबिल होगा। मैं नहीं कह सकता कि यह इतनी आसानी से बन सहता है या नहीं।

जनाव दा छा! इस वि ह के अलरात से अप तो आम दती के लिहाज से सब से ज्यादा जमीदारात मुतासिर होंगे। वह इस सूबे के पुराने रहते वाल हैं और बकौल महारमा गांधी के जमीदार इसी मुल्क के हिस्से हैं "Thoy are the sons of this very soil" (इसी मातू मूमि में वे उस्पन्न हुए हैं) और जो इत जान किया जाये वह सिर्फ इस एतबार से बिल्क इस खातिर कि गाड़ी के तमान पहिये बराबर रहें और आसानी से सब चीज ठीक-ठीक चलती चली जाये होना चाहिये, जिससे जमीदार अपने बच्चों की, अपने मुलाजमीन की परवरिश कर सके जितकी तादाद हजारों और लाखों की है और जिनके लिये यह बिल कोई प्रावीजन नहीं करता है।

में शायद शुरू में यह कहने वाला था, जिसको गालिवन में भूल गया, कि में म्बुनियादी और उपूली तौर पर इस बिल का ख़ैरमकत्रम करता हूं। लेकिन इसके साथ—साथ यह अर्ज कर्लगा कि इस बिल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद बुनियादी नहीं हैं, तकसीली हों, लेकिन तकसीली ऐसी है जिनका ताल्लुक बुनियादी चीजों से हैं, उन पर जब में आता हूं तो अफसोस होता है कि यह उनसे खाली क्यों है। काश इस ऐवान से पास हो कर जब यह सूत्रे और मुल्क में रायज हो तब वह तमाम चीजें इसने शामिल कर ली जाएं।

जनाब वाला! बिल पर एक नजर डाली जाए तो हम देलेंगे कि यह बिल एक बहुत लम्बा चौड़ा डाक्यूमेंट है, कमोबेश ३१० वफाएं इसमें मौतूद है। साथ ही साथ तकरीबन सब चीजों का इसमें जिक किया गया है। यह बिल जिसका नाम जमीवारी एगालिशन ऐंड लेड रिकामें बिल है, शायब इसी वजह से जो—जो चीजें डिस्कत की गयी हैं उनमें जमोदारी एवालीशन के साथ—साथ गांव पंचायत, कोआपरेशन, फारेस्ट, मार्डम, वगैरह—वगैरह का भी जिक है। इसके साथ साथ हर चैन्टर के आखिर में यह दिया हुआ है कि इस चैप्टर के मातहत अलाहिदा रूत्स बनेंगे जिन पर अमलदरामद होगा। बहुत सी ऐसो बातें जो बुनियादी है सियत रखती हैं उनको रूत्स पर छोड़ना पड़ा है। जब में अपने सूबे के इस बिल के मुकाबिले में अदरास और बिहार का बिल पढ़ता हूं तो उन बिलों को बहुत मुख्तसर पाता हूं। एक जिल में ७६ दफाएं हैं और दूसरे में शायद ७२ दफाएं हैं। गालिबन कुछ कमोबेश हों। उनमें एक चीज यह भी में पाता हूं जो हमारे बिल में नहीं हैं वह यह कि कि बे मसले को इसी बिल में उन्होंने हल कर दिया है। जाहिर हैं जो जायदादें ली जा रही हैं वह अगर मकरूज हैं जब तक उनका कर्ज न चुका दिया जाए या फंसला न कर दिया जाए तब तक यह नहीं कह सकते कि यह जो कम्पेंसे उन की दफाए बनाई गयी हैं उनका किस तरह से इस पर असर होगा खशह यह उस पर एड़बर्स जी एफेक्ट करेगा या फेदरेबली।

इसके अावा ऐसी दरख्वास्तें जो कर्ज को चुकाने के लिए राइटस और टाइटिल्स के मुताल्लिक आएं जिनमें शायद अंदाजा यह है कि वर्षों लग जाएं जिनके फैसले तक कम्पेंसेशन एक जाएगा उस वक्त तक उन जमीदारों के लिए जिनका गुजारा जमींदारी की आमदनी पर ही होता है और कोई जरिया माश नहीं है उसको हल करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है मदरास और बिहार के बिलों में यह रखा गया है कि बिलों के रायज होने के पहिले ट्रायबुनल्य मुकररे किये जाएंगे जो पहिले ही अदना फैसला दे देंगे और उनको ते करने के लिए कोई न कोई सूरत जल्द से जल्द निकालों जाएगी। लेकिन हमारा बिल इन चीजों से खालो है। बावजूद ३१० दकात के और शायद जब कवायद बनें उन्हें भी शामिल कर लिया जाए तो मेरा अपना तलमीना यह है कि १,००० के करीब दकात कुल निकलेंगी, इस चीज पर कोई तवज्जह नहीं की गयी जिस पर कि बुनियादी तौर से तवज्जह की जानी चाहिए थी।

जनाबवाला ! जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है वह चीज बहुत गौर तलब है क्योंकि जमींदार के लिये इस बिल में दो ही चीजें सब से ज्यादा अहमियत रखती है एक तो मुआविजा, दूसरे सीर और खुदकाइत । जहां तक मुआविजे का ताल्लुक है वह तो हम सब जानते हैं कि वह किस बुनियाद और किस उसूल पर कैल्कुलेट किया जायगा। बिल में यह दिया गया है कि हर जमींदार को आठ गुना मुआविजा दिया जायगा और उसका कैल्कुलेशन इस तरह से किया जायगा कि उसकी ग्रास इन्कम में से पन्द्रह फीसदी वसुली का खर्चा, उसकी मालगुजारी की रकम और जो एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स देता ह यह सब निकल कर जो बाको बचेगा उसका आठ गुना उसको दिया जायगा। अगर इस अहम मसले पर गौर किया जाय तो यह पता चलेगा कि यह आठ गुना नहीं बल्कि उससे बहुत ही कम है। मुझे इस सिलसिले में दो तीन बातें अर्ज करनी हैं। एक तो यह कि यह जो एप्रीकल्चरल इन्कमदैक्स जो कि उसकी आमदनी से निकाला जाने वाला है जैसा कि हमें मालूम है यह गुजिस्ता साल लागू हुआ था। यह टैक्स ऐसे मौके पर लागू हुआ हैं जबकि अमीदारी का खात्मा होने वाला है। अगर यह टैक्स पांच छः दस वर्ष पहिले या जब कि इब्तिदा में कांग्रेस गवर्नमेंट आयी थी उस वक्त लगाया जाता तो कोई एतराज की बात नहीं थी। लेकिन यह टैक्स उस मौके पर लगाया गया है जब कि जमींदारी का खात्मा करने का फैसला हो चुका था। अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी । में यह समझता हूं कि यह चीज जो कही जाती है वह बिल्कुल सही ह कि इससे वह जमींदार जो पांच लाख से ऊपर, मालगुजारी देते हैं उनको बहुत नुकसान है। अगर तखमीना लगाया जाय तो उन लोगों की आमदनों जो इस वक्त हैं उसमें से एग्रीकल्चरल इन्कमटेक्स, वस्ल्याबी का पन्द्रह फीसदी खर्चा और माल-गुजारी की रकंत सब कुछ निकालने के बाद जो कुछ बचता है आइंदा जो मुआविजा हुम देंगे उस मुआविजे की सुरत में उनकी आमदनी सिर्फ एक बटा पांच रह जायगी। सोचिये किसी शहस से यह स्वाहिश करना कि वह अपनी आमदनी का श्री सुन्ता। आलम ला]
अस्ती फोसशे इस तरह से कुरबान कर दे तो यह कहां तक मुनासिब होगा। मेरे
ख्याल में यह रकन बहुन ज्यादा है। दस फोसदी, पन्दह फोसदी, पन्चीस फोसदी, पनास
फोसद कुरबानी करने के लिये कहा जा सकता है मुन्क के फायदे के लिए। लेकिन उसकी
कोई हद जरूर होनी चाहिये। उस हद से वह मृतालिया आगे नहीं बढ़ना चाहिये।
फिर उसके बाद उा लोगो को जो परती या मुतर्कारक दरख्त है उनका भी मुआविजा नहीं
मिलेगा। अगर बिल के त्रिएम्बिल पर गोर किया जाय और उसके साथ भिला कर पढ़ने को
कोशिश की जाय तो यह पता लगता हो, जां तक लफ्ज इटरमीडियरी का ताल्लुक है उसमें
कोई इख्न लाफ इमसे नहीं ह। लेकिन बावजूद इसके मुआविजा नहीं दिया गया।
अगर इसक भी आमदनी प्रास इन्कन में शामिल कर ली जाय तो उनकी आमदनी
एक बटा पांच से भी कन शायद एक बटा छः ही रह जाते ह। ऐसी सूरत में
यह चोज जमोदारों के लिये बहन हार्ड होगी।

र्ग अब इस मसले पर गोर करूगा कि मुत्राविजा हम किस तरीके से देगे। जा तक मेरा ख्याल है हमें मुआविजा बाद की सूरत में देना पड़ेगा इसलिये कि अनली तौर पर यह। सूरन समझ में आती है। हालाकि मेरा भी पही ख्वाहिश है ओर गर्नमें की भी खराहिश है कि मुआबिजा जहा तक ही सहे नक ह की सुरत में अरा किया जाय। लेकिन अदेशा यह है कि आर मुशाबिज। बाड की सुरत में देन। पड़ा तो बाड का जो राया मिलेगा उनके जिर्य से सि गा इनके कि जैसा पहिने वह आइडिल बना बैठा रहता था उस वक्त भी आइडिल बना रहेगा। अवालिशन के पहिले वह आइंडिन ही था और अवालिशन के बाद वह आइंडिल और पापर वो में हो जाया। इस तरह से हम सुबे में एक वैकवर्ड क्लास बनाने जा रहे है जो कि इन मुन्क की रूरल इक्तेनामी के लिये कभी भी मोजू नहीं हो सकता। जमींबार आज िततना हो कुसूरवार हो या उसको ओल्ड सिनर भी कहा जाता ह। यह भी सही है लेकन ननीवारों की आनेवाली नस्ल किसी सूरत से भी कसूरवार नहा है। जिनकी जनींदारियां खत्म हो रही है उनके बच्चे और उनकी नस्लें जो इस सुबे में रहेंगी उनका जनीदारी से कोई दूर का भी वास्ना नहीं होगा लेकिन जिस उसूल पर मुआबिजा आप वे रहे है उससे ने सिर्फ जनीवार तबहा होगा नस्लें, उसके बच्चे, उसके डिपेंडेंट्स, उसके मुलाजमीन, गरजे कि आदिनयों का जरिये माश जमींदारी की आमदनी पर था व बरबाद हो जायेंगे। आपको मालूम हैं कि इस सूबे में जमींदारों की ताबाद गालिबन २३ लाख के है। इसकी मैं जिनीवारों में कोई छोटा जमीवार या बड़ा जमीदार कह कर तकर्म मानने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि हमारी बदकिस्मती से इनने तफ हैं हम में पहले ही से मौजूद है कि और कोई तफ की करने की जरूरत नहीं है और न यह करना इस सूबे और मुल्क के बेहनरीन मकार में कभी मुकीव ही सकताह। इसिलवे ये २३ लाख और अगर इनमें फिक्स्ड रेट टेनेन्ट्स को शामिल करलें तो में सममता हूं कि यह ताबाद सकरीबन ३० लाख के करीब होगी और अगर एक एक के औसतन पांच डिपेन्डेंन्ट्स मां, बाप, बीबी, बच्चे और एक नौकर औसतन समझ लें तो पांच आदमी हु। और इस हिसाब से एक करोड़ ५० लाख आवमा इस सूबे में ऐसे निक रेंगे जिनका जरिये मादा जमींदारी से किसी न किसी तरीके से मुतालिल्क हैं। हमें नालून हैं कि हमारा सूबा जो इंडियन यूनियन में ६ करोड़ आबादी का सूबा है उसने से चोयाई यानी डेढ़ करोड़ आबादी का वर्गर प्राविजन किये, उन्हें वर्गर एम्प्लायमेंट के छोड वें और उनके लिये वह सब इन्तजाम नहीं करते जिसके वे मुस्तहक है तो यह किसी सुरत से भी मारली, इकोनामिकली, मोशली कभी भी मुफीद नहीं हो सकता और इसके मुजिर नतायज में समझता हूं कि ऐसे है कि हम में हर एक को इस बक्त देख लेना चाहिये।

जनाव वाला ! में ने जैसा अभी अर्ज किया कि जहां तक मुआविज का ताल्लुक हैं मुआविजा रुक बहुत ही जहम चीज हैं और मुआविजे की अवायगी अगर नकद सुरत में की जानी हैं तो इससे जमींदारों को यह मौका मिलेगा कि वह अपने पैरो पर खडे हों। उसकी आमदनी जो १/६ रह जाती है उससे अपने दिमागी, अपने जेहन से, अपनी मेहनत से उस रुपने को किसी प्राफ़िटेबिल कन्संस में लगा कर वह उसमें तरक्की दे सकता है लेकिन अगर हम बान्ड की शकल में देते है तो आज जैसे वह जमींदार की शक्ल में जैसे आइडिल हैं और था, आइन्दा भी आइडिल रहेगा और न सिर्फ आइडिल रहेगा बल्कि पायर भी हो जायेगा। तो अब सोचना यह है कि इस चीज मे बचने के लिये हमे क्या करना चाहिये। हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये। हमें इस पर बहुत ठंडे दिल से गौर करने की जरूरत है। में जानता हूं कि गवर्नमेंट के पास इतना रूपया कहां है जिससे वह नकद अदायगी कर सके। में जानता हूं कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से भी रुपया मिलने की कोई सूरत नहीं है। जहां तक जमींदारी अबालीशन फन्डम के कलेकशन्स का ताल्लुक है में गवर्नमेट से पूरी हमददी रखता हू कि उसका यह ख्याल है और उसका यह यकीन है और उसकी यह इमान्दाराना कोशिश भी है कि वह किमी तरह में रुपया हातिल करके जमी-दारों को नकद की शक्ल में अदा करे। और इम सब के एतबार में हर जन दार का फर्ज यह ह कि इस काम मे वह गवर्नमेट का पूरा हाथ प्रटाये। गवर्नभेट की पूरी मदद करे, लेकिन इसके बावजूद में ईमानदारी से इस बान को सोवता हु, वगोंकि नैने इस चीज के मुता-हिलक कान किया है। मैने इसमें दिलचस्पी ली है लेकिन म इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि इस सिलि निले में जितना रुपया हम वसूल करना चाहने है। म भमनता हू कि यह कारेशर ह और इसके मिलने की कोई सूरत नहीं पालूम होती। मैं चाहना है कि कोई जरिया ऐसा हो जाय बन आसमान से फेट पड़े लेकिन मुझे शक है कि आये यह १७५ करोड़ रुपया बसूल कर सकेंगे ओर तमाम जमोदारों को नकद मुआविजा देसकेंगे। मुझे शक है और बहुत बड़ा ज्ञक है कि शायद हम यह रपया वसूल न कर सकें ओर उसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा यह होगा कि यह तमाम कोशिश करने के बाद तमाम गैरहरिहल अजीजी मोल लेने के बाद और तमाम अखराजात करने के बाद हमको मजबूरन थह सूरन कर री पड़ेगो कि हप तो किर बान्ड देना पड़ेगा।

इस सिल्लिसले में में जिस्नी तौर से एक दिक्कत का ओर जिक्र कर दूं। में जानता हूं कि गवर्नमेंट की पूरी तवज्जह इस पर लगी हुई है कि किसी सूरत से जमींदे।री अशलीशन फन्ड के लिये रुपया आ जाय और इसके लिये जो कुछ कोशिश बन पड रही है, वे कर रहे है। इसका जहां एक अच्छा नतीजा यह हुआ है कि अब तक सुनते है १२ करोड़ रुपये हमारे पास आ गये है वहां एक वीज पर शायद जानकर या बगैर जाने हुए गौर नहीं किया गया। वह यह है कि हमारे इस कलेक्शन की वजह से मालगुजारी की वसूलयाबी का काम बिल्कुल ठप हो गया है। मै आपको यकीन दिलाता हूं ओर मै समझता हूं कि बहुत से वे भाई जिनका जमींदारी से कुछ ताल्लुक है, अच्छी तरह जानते है कि जमीदारों की लगान की वसूलयाबी में इस कदर दिक्कत और दुइव।रियां हो रही है कि वह इस काबिल नहीं है कि वह इस फसल का अपना लगान वसूल करले, वह खुद भी खा ले और गवर्नमेंट की मालगुजारी अदा कर दें। पटवारी बकाया लगान के मुकद्दमों की शहादत में नहं। आते बल्कि अपनी सारी तब्ज्जह कलेकान में लगा दी ह। मुझे खुद तजुर्बा है कि बाज जगह मुकदमें धन्द है और फैसले नहीं हो रहे है। इसका नतीजा यह हुआ कि काश्तकार यह समझने लगा है कि हमें लगान देना जरूरी नहीं है। बाज जगह पटवारियों ने, मै जानता हूं कि गबर्नमेंट ने हरगिज नहीं कहा, यह भी कहा कि देखो पहिले आपको दसगुना लगान जमा कर देना चाहिये इसकी अभी जर्रा बराबर फिक न की जिये कि जमींदार की लगान देना है। नतीजा यह हुआ कि काश्तकार ने लगान देना बन्द कर दिया। जब स्रगान नहीं आयेगा तो जाहिर है कि जमींदार मालगुजार अदा नहा कर सकेगा। हुकू-मत के लिये मालगुजारी का वसूल होना बहुत ही जहरी चीज है और इसका नतीजा मह होगा कि बहुत जन्दी हो गर्वर्गमेट को अन्तो तमाप तब जर इधर से हटाकर माल-

[श्री मुल्तान आलम खा] गुजारों की वसूली की तरफ़ लगानी होगी। जब जमीदार की जेब मे रुपया न होगा तो जाहिर है कि वह अपनी बोटी काट कर रुपया देगा नहीं। नतीजा यह होगा कि आप कुर्की करेंगे, अटैचमेंट करेगें, वगैरह-वगैरह। इससे क्लेरिकल स्टाफ का और ज्यादा काम बढ़ जायगा और जितना काम बढेगा उतना ही जमीदारी एबालिशन का काम सफर करेगा। बहुत से दोस्त यह भी कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर ज्यादती होती है तुम्हारे अपर जुल्म होता है। तुम मालगुजारी न ह । प्रोपेगैडा होगा। इसका नतीजा यह भी होगा कि कोर्ट के काम बढ़ जायेगे। सैक रो फैसले करने पड़ेगे और आपके रेवेन्य स्टाफ की सारी ताकत उधर से हटकर इस तरफ लगेगी। ये दिक्कते बढ़ रही है और शायद गवर्नमेंट को यह महसूस हो गया होगा ओर अगर आज महसूस नहा हुआ है तो मैं समझता हं कि आइन्दा चलकर महसूस होगा। इन तमाम बातो पर गीर करने के बाद मैने एक बीज अपने दिमाग से सोची थी और में चाहता था कि अवने बाज वोस्तो के सामने पेश कर दूं। आज यह एक अच्छा मौका है और इसलिये में यहां कहन। च।हता हु। मंने यह सोचा था कि गवर्नमेट बजाय इसके कि इतनी दिक्कत मोल ले. अनुपारलैरिटी मोल ले, एक्सटा एक्सपेन्डीचर करे, वह किसी से कर्ज ले ले। कर्ज मिलने के बहुत से तरीके हो सकते है। गवर्नमें अमेरिका से कर्ज ले सकती है, निजाम हैदराबाद से कर्ज ले सकतो है और भी तरीको से कर्ज ले सकती है। इस कर्ज को वह ढाई प्रतिशत के हिसाब से ले सकती है और अगर वह बांड देगी तो उस पर भी उसको ढाई प्रतिशत का सूद देना पड़ेगा। इससे यह होगा कि जमीदार अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। अपने स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को कायम रख सकेगा। नेदानल बेल्थ बढायेगा और इसके साथ-साथ जब रुपया आ जायगा तो गवर्नमेंट का एक्सट्रा एक्सपेंडीचर, अनपापूलेरिटी और बादरेशन वर्गरह बच जायगा। इसके साथ-साथ गवनेमेंट एक चीज और भी कर सकेगी, जिससे हमारे सोशिलस्ट दोस्त भी मृत-मइन होंगे। वह यह कि कारतकारों को भूमिधरी का हक बिल्कुल मुफ्त वे सक्रैंगे। इस सूरत में गवर्नमेंट ९ करोड़ रुपया बचा सकती है जो गवर्नमेंट के खजाने में आ जायेगा। इस तरीके से ऐसा हो सकता है कि यह जो ९ करोड़ रुपया बचेगा उस ९ करोड़ में से १७५ करोड़ रुपये का ब्याज जो करीब सवा चार करोड़ के होगा वह दे देगी और बाकी तीन या चार करोड़ जो बचेगा वह असल कैपीटल में जमा होता जायगा। इस तरह से गवर्नमें ८२३-२४ सालों म सारा कर्जा अवा कर देगी और काश्तकार को बिना कुछ विषे ही हक्क मिल जायेंगे। हो सकता है कि मेरे कुछ भाइयों को इससे एतराज हो कि बिना कुछ दिये काश्तकारों को अधिकार नहीं मिलने चाहिये। यह एक अलाहिया बलील है जिसकी बहस में में जाना नहीं चाहता हूं। इस सूरत में भी यह हो सकता है कि आप भूमिधर के राइट्स देते रहिये और जो रुपया वसूल होता जाय उससे भी अवायगी होती जा सकती है और इस तरह से आपको न तो प्रोपेगेंडा की जरूरत होगी और न ज्यादा स्टाफ की। आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप रुपया जमा करते जायं वैसे-वैसे अवायगी करते जाइये। जितना दपया आता रहे कैपीटल में जमा होता रहे। इस तरह से आप के सब काम आसानी से हो जायेंगे। यह एक स्कीम है, में चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर गौर करे। में उस वक्त भी कहता या और आज भी कहता हूं कि गवन मेंट आफ इंडिया के जरिये आप गुड आफिसेज कायम करें। निजाम साहब से कर्जा दिलाने या किसी और से कर्जी दिलाने की कहें। हो सकता है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया आपको कहे कि उसकी भी बहुत सी डेवलपमेंट की स्कीमस् है जिनके लिए उसको भी रुपये की आवश्यकता होगी उसका जवाब हम।रे पास यह हो सकता है कि हम केस बना कर लड़ें और कहें कि हम इंडियन युनियन के सबसे बड़े सूबे हैं और जमींदारी अवालीशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमने एक ऐसी जामे स्कीम बनाई जो िसी सूबे ने नहीं बनाई और जो दूसरे सूबों के लिए मिसाल है हमारा सूबा सेटर को डिफेन्स बगैरा में सबसे ज्यादा मदद देता है और क्योंकि हम यह स्कीम एक बहुत बड़े पैमाने पर चाल कर रहे है। इसलिए अगर हम इसे राइड अनेंस्ट में उठाते हैं तो मेरा यह ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि हमारे केस पर गवर्नमेट आफ इंडिया गोर न करें। गवर्नमेंट आफ इंडिया जरूर इस पर गौर करेगी इसका विश्वास रखना चाहिये।

इस सिलिसिले में एक चीज और कहंगा वह यह कि अगर तम काश्तकारो को भूमिघरी के राइट्स न दें तो क्या हमें काइतकारो का लगान कम करना पडगा या क्या काइत-कार इतना लगान दे सकते हैं जितना लगान कि अब है, क्योंकि बहुत से लोगो का यह रयाल है कि यह लगान काफी है और मै समझता हूं कि उसका जवाब उसके पहलू में हैं मोजूद है। मेरे दोस्त फूल सिंह जी ने एक तकरीर की थी, गो मैं उस वक्त मोजूद नहीं था लेकिन वह मैने प्रेस मे पढ़ी थी, मै उनकी इस राय पर काकी ध्यान देता हूं कि भूमिथरी के जो राइट्स दिये जाय तो जो रेट मुकरिर किया जाय वह सरक्वलर रेट से मुकरिर किया जाय। उसका मकसद यह होगा कि जो काश्तकार इस वक्त हमान देता है उसका ३३ फीसदी लगान ज्यादा हो जायेगा ओर अगर आप इस फुलसिह जी की तजवीज को न भी माने तो भी हमें प्रैवटीकल होना पडेगा वह इस तरीके से कि हम जानते है कि रूरल ऐरियाज में टैक्सेशन का बार जमीदारों पर ही पडता है क्योंकि वहा वही एक पैसे वाला कहा जाता है और वही पब्लिक लाइफ में आता है लेकिन अब उसके लिए यही कहा जा सकता है कि "दैट इज दी लास्ट स्ट्रा आन दी केमिल्स बैक" यानी अब उसके ऊपर कोई और टैक्स नही लगाया जा सकता । इसलिए जमीदारी खत्म होने के बाद जो टैक्स लोगों से आता था वह भी खत्म हो जायेगा। इसलिए आप आइन्दा जो रखेंगे उसमें मौजदा लगान और टैक्स दोनों को मिला कर रखेंगे। और इसके अलावा जमींदारों की इन्कम से जो टैक्स लिया जाता था वह खत्म हो जायगा। ऐसी सुरत में जमीन के ऋपर जो कुछ टैक्स था या जो आइदा लग सकता था वह सब खत्म हो जायेगा। हमारे सूबे के बढते हुये वर्चे के लिए स्पये की जरूरत रहेगी ख्वाह इस सूबे में जमीदारियां रहें या न रहें, ऐसी सूरत में क्या होगा ? कानपुर या दुसरे शहरों में आप इंडस्ट्रीज पर टैक्स लगा दें लेकिन देहातों में अगर कोई टैक्स लगेगा तो वह भूमिघर पर ही लगेगा और किसी पर नहीं लगेगा। फर्ज कीजिये आज आपने काश्तकारों का लगान ३३ फ़ीसदी, २५ फीसदी या ५० फीसदी कम कर दिया तो आप यह भी सोच लीजिये कि इसका नतीजा क्या होगा । मै तो यहां तक तैयार हूं कि काश्तकारों का लगान इतना कम हो जाय जितना कि काग्रेस ने किसी जमाने में तय किया था कि अनइको-नामिक होल्डिंग्स का लगान बिल्कुल माफ कर दिया जाय । लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि इस वक्त उसका टैक्स आप कम करहें और अगला बजट जब आये तब आप उसपर एक टैक्स लगा दें और फिर जब दूसरा बजट आये तब आप एक और टैक्स लगा दें । बहर-हाल जब रुपये की आपको जरूरत होगी और उसके लिए आपको टैक्स लगाना ही पड़ेगा तो फिर सवाल यह है कि मौजुदा जो लगान है उसी को ही क्यों न आप कायम रहने दीजिये। इससे आपका इक्यूलीबिरियम भी कार्यम रहेगा और आजकल का जो निर्ख है उसको देखते हुये भी वह बेजा नहीं है। इसलिए में समझता हं कि मेरे तमाम दोस्त जो कर्जा लेने की स्कीम मैने बतलाई है उसपर गौर करेंगे। इससे सोशलिस्टो की जो स्कीम है "प्राम बिगर टू इस्मालर" वह भी कायम रहती है। यानी बडो की जेब से निकल कर छोटो की जेब में जाय और वहां से फिर वाम्स हो जाय यह दूसरी बात है अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोग यह सोचते हैं कि बड़ों की जेंब से रुपया निकल कर छोटो की जेंब में जाय लेकिन वहां से वापस न हो । अगर सोशलिस्ट पार्टी के लोग बरसरे इवतेदार हो जायं और वह ऐसी बात सोचें तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन वह बहुत दूर की बात है। हमें यह सोच-विचार करने की जरूरत है कि इस वक्त हमे क्या करना चाहिये। में समझता हूं और मेंने जहां तक अपने खयाले-नाकिस से गौर किया है मे इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो मेने बतलाया है वही एक ऐसी सूरत है जिसके मातहत जमींदारों को मुआविजा मिल सकता है, गवर्नमेट के पास सेविंग हो सकती है, गवर्नमें की अनपापुलैरिटी भी बच

[श्री सुन्तान आलम खा]
सकती है, काश्तकार भी खुश रह सकते हैं, सोशिलस्ट थ्यूरी भी पूरी हो सकती है और
तमाम चीजें पूरी हो सकती ह। इसिलए निहायत अदब के साथ में गवर्नमें से गुजारिश
करूंगा कि मेने जो चीज इस वक्त आपके सामने पेश की हे आप उस पर बहुत ठंडे
विल से गौर फरमायें। मेने एक मोटी आउट लाइन आपके सामने इसिलए पेश कर दी
है कि आप उसकी देखने के बाद एक ऐसी इनारत बना सके जिसके मानहत इसिबल
में जो खामियां रह गयी है उनको पूरा कर सकें ओर अपनी स्कीम की चला सकें।

जनाब वाला! मुआविजा मिलने के बाद, जैसा कि इस बिल में तरीका बतलाया गया है, जमीदार या तो यह करेगा कि आइडिल बनकर आमननी का १५ फीसदी साल हासिल करेगा, लत्ते पहनेगा एक वयत फाका करेगा और एक वस्त व्यायेगा या वह यह करेगा कि जो रूपया आप उसको दे उस रूपये को लेने के बाद वह उसको उड़ा दे। इन सब बातो को नजर में रखते हुये आपको जमीदारों का स्टेडर्ड आफ लिजिंग भा कायम रखना है।

मुझे एक बात ताद अत्यो है जो मैं आप जोगों के सामने अर्ज कर देना चाहता है। यह में नहीं कहता कि यह आम नोर पर होत है लेकिन यह होता जरूरहैं। जब जमीदारो एबालिशन कमेटो के सिलसिलें में मोन्ग्न होती है तो बाज बन्त बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके पर जमीपारो को गा'लयो लोग दे देते है। यह मुनामिब नहीं है। जो शहम बिस्तरे मर्ग पर लेटा हो और जिसकी ठठरी दिखाई पड़ रही हो उसको अखठाकन, मजहबन, सधाजन किसी उसूल से भी बरा कहना मुनासिय नहीं है ओर बिलखसूस ऐसी सूरत में जबकि जमीदार पार्टी के कई सदस्य उनके साथ हैं और आप जमीं नारी को खत्म कर रहे हैं। में ममझता हूं कि बाज इस किस्म के भी लोग है जो प्रेक्टिकल चीज को समन कर इसकी मुआफिकत करते है। गर्ने वह समझते हैं कि काश ऐसा नहीं होता। लेकिन किर भी उनकी बुरा नहीं कहना चाहिये। आज ये जमींदार तो खत्म हो जायंगे लेकिन उनके बाद आइन्त आने वाली जो नस्लें होंगी जिनका जमींदारी से कोई दूर का सरोकार नहीं होगा उनके लिये आप दोजल और जहन्तुम पैदा कर देंगे, जिससे सोसाइटी के अन्दर उनकी कोई पूछ नहीं होगी । उनके बाग कार्ट जायगे, उनके खेत उजाड़े जायंगे और उनके दरस्त काट जायगे जिससे वे किसी सुरत में भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सर्हेंगे। इस तरह से आप समाज के अन्दर एक नया बैकवार्ड क्लास पेदा करेंगे। आगे चल कर यह प्राबलन हमारे सूबे के सामने आवेगी जिससे बड़ा ही नुक्तान होगा। हमारे सूबे में बैकवार्ड क्लास की कमी नहीं है लेकिन इस तरह से एक और नये बैकवाई क्लास को पैदा करके आप उसमें इजाफा करेंगे। इसलिंगे में चाहता हूं कि आप कोई ऐसी सुरत निकालिये जिससे बैकवार्ड क्लास में एक और इजाफा न हो। में आनरेबिल मुअप्रिजज वजीर माल लाहब से कहता है वे मेरी बातों पर मुस्तुरा रहे है लेकिन में सही बात कहता हूं। में उनके जजबात उनकी काव्लियत-ए-इल्म से अच्छी तरह वाकिक हूं और में उनसे अपील करता हू कि आप इस चीज को जरा इस लाइट में देखें और बहुत सीरिअसली गीर फरमायें कि जमींदारों के लिये अगर यह चीज पैदा हो गई तो आगे चत्र कर उसका क्या नतोजा होगा। उसका नतीजाहोगा कि तमाम सूत्रे की बरबादो हो जायगी। डेढ़ करोड़ मखलूक को बेरोजगार रख कर आइडिल रख कर, पापर रख कर आप सुबे में अमनों-अमान कायम नहीं रख सकते है। यह कह कर में आपको कोई धमकी नहीं दे रहा हूं बरिक हकीकतन जो चीज है उसकी आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी कोलम्बी में बिटिश मिनिस्टर बेविन ओर हमारे वजीर आजम पं० जवाहरलाल मेहक ने जो तकरीर की है लोगों ने अवबारों में पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर एशिया का स्टेड्ड आरु लिबिंग नहीं बढ़ाया जाता है तो समझ लीजिये कि कम्युनिक्म किसी सूरत में भी नहीं रोका जा सकता और यह सबकी मालूम है और सभी बेख रहे है कि कम्युनिज्म न सिर्फ एशिया बल्कि हिन्द्रतान के बरवाजे पर जब खटखटा रहा है उस समय आप

यह बिल ला रहे हैं। आप हो अपने लीडरान के इन ख्यालात और बुलन्द उसलों का भी ख्याल र बना चाहिये। अगर आप चाहने हैं कम्युनिज्म रुके और इसको अपने यहां न आने दे और क्लासलैस सोसाइटी बना सके और बैकवार्ड क्लास न पैदा हो तो बहुत सीरिअसली आपको गौर करना चाहिए कि जमीं गरी एबा जीशन के गा: किप तरी के से जमीदारों के साथ डील करे, कैसे अपलिएट दे और कैसे उनको ऊचा उटाने कोशिश करें इसके लिए उनको योड़ा ज्यादा इन्करेजमेट मिलना चाहिये। एक मिनाल मै आपके सामने रखना हूं। बदिकस्तितो से हिमारी पिछली पालिसी भी ऐपी रही जम दारों को कोई इन्करेजमेंट नही मिला। मैने पहिले ही कहा था कि जम दारों मे भी बलैकशिप रहे है, दुनिया में हर जगह रहे हैं करण्शन रहा है। ओल्ड आर्डर में भी करण्यन था दूपरी जगह भी करण्यान है जेकिन हनको तो इन लागो करना है, उनका रिफार्म है। यहा हमारी पालिसी चाहिये । हनी तो पिछ ने मौके पर मैने यह अर्ज किया था कि हमारी पालिसी ऐसी नही रही है कि जिससे हभने जपींदार को इन्करेज किया हो। मुझे याद है कि डेड्-दो साल पहिले मैने कई दफा यह सवाल किये थे कि क्या बात है कि ट्रेंड के लाइसेंस उन्हों लोगो को दिये जाते है जो बेसिक ट्रेंड करते रहे हैं। में आनरेबिक वजीर माल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यह बात जरा गौर से सुन ले। में यह कह रहा था कि फैक्ट यह है कि पिछने जमाने में हवारी पालिसी ऐसी नहीं रही कि हम जमीद। र को इन्करेज करते रहें हों। जब कि ट्रेड के लाइसेस का सवाल अध्या कि सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों दिये जाते है जो बेसिक ट्रेड करते है जो ब्लॅक-मार्केट कः नाम अंधा करते है, करण्यान फैलाते है। लेकिन जमींदारों को नहीं दिये गये उनको डिस्करेज किया गया और कहा गया कि यह कायदा है इसलिये जमींदारों को नही दिया जायगा। अगर जनींदारों को वह लाइसेन्स दिये जाते, या उसका कुछ हिस्सा ही दिया जाता, उसका कुछ कोटा ही दिया जाता तो इस जमाने में जमींदार लोग अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करते, उनका भला होता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उससे यह मालूम होता है कि हमारो तरफ से भी कमी रही और गलतफ़हमी हुई। अगर जनींदारों के लिये ऐसा कर दिया जाता तो इससे उनके। बहुत कुछ फायदा हो सकता था। जो हमको उनके लिये कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया। हमारा यह फर्ज था कि इन जमींदारों के सुवारने के लिये जो हमकी करना चाहिये था वह हमने नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि ब्लैक-मार्केट बढ़ा, करण्यान की फतह हुई ओर उसकी वजह से शर्म के मारे हमारा सर नीवा करना पड़ता है। आज बलैक-मार्केट, करण्शन जिस कदर हमारे सूबे के अन्दर फ़ैजा हुआ है, शायद हिन्दुस्तान मे क्या दुनियां के किसी कोने में या दुनियां में इसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी जो लोग बलैक-मार्के टिंग करते रहे है, जो लोग खून चूसते रहे है, जंग के जमाने में जिन्होंने बहुत रुपया पैदा किया उनका ही ख्याल रेखा गया। हमारी पालिसी यह होती कि जो नये लोग आवें, जमींदार आवें, उनको कुछ हिस्सा, कुछ कोटा ट्रेड का देते तो वे नये लोग होते कुछ अरसे तक डरते और ब्लैक-मार्क-टिंग भी नहीं होता और जमीदारों का भला होता और गवर्नमेंट को भो इस वक्त इतनी दिक्कत न होती । में बड़े अदब के साथ आनरेबिल मिनिस्टर साइब से अर्ज करूंगा कि हमारी भी कुछ कोताही रही। इसलिये अब उन किम्यों को पूरा करना है। वह कमियां अब इस तरफ से पूरी की जा सकती है कि आइन्दा जो हम श्रीग्राम बनायें वह इस तरीके पर हो कि जिसमें जमींदारों के साथ न सिर्फ इंसाफ ही हो बल्कि में तो यह कहूंगा उनके साथ एक तरह से लिबरल ट्रीटमेट मनासिब होगा । जैसा कि मैने अर्ज किया, जब तक आप यह सब बातें अपने सामने नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी मंजिले-मकसूद पर नहीं पहुंच सकते हैं।

जनाबवा रा! मैने अभी जैसा अर्ज किया, इस बिल के अन्दर ३१० दफायें क्रुमारे सामने आई हैं और हर चैप्टर के मातहत हमको रूटर बनाने पड़ेगे और

[श्री सुल्तान आलम खां]

शायद सारे रूल्स एक हजार बनाने पड़ों। इ के अन्दर बहुत सी कमी रह गई है। बहुत से रूल्स छोड़ दिये गये हैं। मस उन यह कि किस तर : से यसूलय बी करेंगे. किस तरीके से कम्पेन्सेशन पेमेंट करेंगे यह सब जो बुनियाती बातें है बह सब छोड़ ही गई है इसके अलावा यह भी है कि यह बिल कहां कहां लागू होगा। म्युनि गिलिटी. नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया कन्ट्रनमेंट बोर्ड, रिकारी स्डेटम् कुमायं की डिबीजन इसके अन्वर शरीक नहीं है। तो यह कर्जे का सवाल भी बिल्मुल यमें ही है जहां पर था और आज तक वह हल नहीं हुआ। आपने फरमाया कि हम कर्जे को सवाल पहले ही लेगे और शायद आप ऐसा इसलिए कर रहे है कि हमारे कान्सटीट्यूशन ने य्निटी की बात रख दी है और शायद इसोलिए आप को इस को २६ जनवरी से पाउने हो नारे की फिक है। यह भी बड़ी गनीमत है। यह कर्ज का बहुत ही अहम सहाल है। आप कम्पेंसेशन चाहें जितना दे लेकिन वह स्टेट जो मकस्य है उस को काफी तादाद है, जबतक यह मालुम न हो कि कर्ज की अदायगी के बाद क्या पोजीशन होगी तबतक नहीं मालूम हो सकता कि कितना मुआविजा किस को मिल सकेगा पा या होगा। इसलिए इस तरह का पीसमील लेजिस्लेशन नहीं होनः चाहिए और इस चीज क़ी मेरी राय में जहां तक हो सके एवायड ही करना च।हिए और यह जरूरी है कि लैन्ड रिफार्म की पूरी तसवीर हमारे सामने आये और तमाम एमेंडमेंट वगैरा सब एक साथ ही हो सके । मालूम नहीं कि आप ने ३१० वफाओं का बिल बनाकर भी क्यों इस बात की जरूरत छोड़ वी और मालूम नहीं कि कमायूं जितान, सरकारी रास्तो, नोटिफाइड एरिया, सरकारी स्टेटस और लोकल बोर्ड क्यों इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यह चीज मेरी वरख्वास्त है कि इसमें जरूर आ जानी चाहिए। ज्यावा अच्छा होता कि आप चन्व हफ्ते या चन्व महीने और इसमें लगा देते जहां इतना वक्त लगा है और एक मुकम्मिल चीज हमारे सामने यहां आनी और जिससे हर चीज कवर हो जाती और गर्ममेंट की बहुत सी विकल भी बच जाती। गवर्नमेंट का बार-बार बिल का इन्ट्रोडयूस करना, टेक्स पेयर का ख्वया बच जाता और एक्सचेकर का भी नुकसान इस तरह से न होता।

बिल के साथ ही जो एम्स व आब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनमें एक लक्ज भी ऐसा नहीं कहा गया है कि जिससे यह अन्दाजा हो सकता कि आप की इसमें क्या दुश्या-रिया थीं। बिल्खसूस मेरी अर्ज दाइत में और भो वजन पैदा हो जाता है जब मैं मदरास और बिहार के बिल पढ़ता हूं। जब हम यह देखते हैं कि यहां यह चीजें मौजूद हैं और आपने नहीं रखीं तो हमें बड़ो परेशानी होती है। हम खाहने हैं कि आप किसी सूरत से भी इस को प्रेक्टोकेबिल बनाइए ताकि आप एक चीज को राही मानों में और सही तौर पर कर सकें।

एक बीज और आपके सामने हैं जो बहुत ही गौरतलब है और बाबजूद इस के कि आपमें काफी गौर किया है लेकिन फिर भी यह मसला इतना ब ा है कि सके तमाम पहलुओं पर अभी गौर नहीं किया जा सका है और उतना गौर नहीं । सका है कि जितने गौर का यह मसला मुस्तिन था और जितना कि इस पेचीवा मसले को सुलझाना जरूरी था। अगर आप एक दम नहीं कर सकते थे तो आप भी बिहार की गवर्नमेंट की जो 'प्रेजुअल एवालिशन की पालिसो है उसी को अख्तियार कर सकते थे और उस तरह से आपको रुपये की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और इस सिलसिले में जो आप को विकात हो रही हैं उनमें से बहुत सी विकात वा जातीं। मगर अफसोस ही कि इस सिलसिले में और बहुत सी अहम बातें हैं कि जिन पर गौर होना चाहिये था और कतई गौर आप नहीं कर सके हैं।

मं कम्पेन्सेशन के बारे मे दो एक बाते ओर कहूँगा और उसके बाद आगे बहूंगा। उसकी दफाओं को पड़ने के बाद मालूम होता है कि आपने जो ८ गुना कम्रेन्सेशन रखा है वह अगर एक्च्अल विकांग किया जाय तो करीब-करीब ३ गुने से ज्यादा नहीं होता है और यह चीज समझ में नहीं आती। अगर आप कम्पेन्सेशन के उसूल को कर्तई न माने तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं हो मकता है जैसे कि सोशलिस्ट कहते हैं वह बात तो एक हद तक ठीक है और वह बात हमारी समझ में आती है, लेकिन जब उसको देने का सवाल पैदा होता है तो उसके साथ ही साथ यह भी सवाल पैदा होता है तो उसके साथ ही साथ यह भी सवाल पैदा होता है कि वह कम्पेन्सेशन इक्वीटेबिल क्यों न हो। कांग्रेस की तरफ से बार-बार मैनीफैंस्टो में और उस के बाद भी यह वादा किया गया था कि हम सब को इक्वीटेबिल कम्पेन्सेशन देगे। वह कम्पेन्सेशन तो इक्वीटेबिल हरिगज नहीं हो सकता कि जिस को हमारे वजीर माल या रोशन जमां खां साहब कह दें या कोई भी एक शख्स कह दें।

अब मसलन सवाल यह पैदा होता है कि जो परती जमीन है उसका मुआवजा नहीं दिया। कोई वजह मालूम नहीं होती है कि क्यों नही दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने अबालिशन कमेटी में खुद कहा था कि एग्रीकल्चरल वेस्ट का दो रुपया फी एकड़ मुआविजा मिलना चाहिये। हो सकता है कि आज आप बदल जायं। राय बदलने का हर एक को हक हासिल है। मे भी राय बदलता हूं यह भी बदलते है। आखिर क्या वजह है कि यह न दिया जाय? हमारे आचार्य जी भी दसगुना मुआविजा देने को कहते थे। चौधरी चरग सिंह की भी यह सिफारिश थी। मै यह जानना चाहता था कि यह आठ गुना क्यों रक्ला गया। इसकी क्या बुनियाद है ? अगर इस का जवाब यह है कि आज हमारे पास रुपया नहीं है तो में इस दलील को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। १७५ करोड़ आप दे सकते हैं तो दो सौ करोड़ भी दे सकते हैं। हां यह तै हो जाय कि मुआविजा देना होगा या नहीं तब तो वहसोम्बाहिसे की गुन्जायश नहीं है। जमींदार को बाजार और इक्वीटेबिल रेट से हो सकता है। यह जरूर है कि आजकल चीजों के दाम बढ़े हुए है फिर भी इस के लिये कोई उसूल और नजरिया होना चाहिये। चौबरी चरण सिंह ने अपनी किताब में जो तजबीज किया है वह क्यों नहीं दिया जाता। मै समझता हूं कि अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट सौ करोड बीघा है तो सोला करोड़ रुपया उसका होता है इस लिये इस मामले में गौर करना चाहिये। मुझे आप के प्रीएम्बल पर सब्त ऐतराज है। कुछलोगों ने मजाक में कहा है कि ''टिलर आर्क दी स्वायल'' तो हल होता है या बैल होता है। आप को टेनेंट या कोई दूसरा ज्यादा अच्छा लग्ज रखना चाहिये। मे फिर आप से अर्ज करूंगा कि वह कौन से वजूह है कि आप परती जमीन जमींदारी के पास नहीं छोड़ते। बिहार में परती जमीन छोड़ दी गई आप भी यहां छोड़ दीजिये। एक चीज है बहुत से जमींदार ऐसे हैं कि एक इंच जरीन उन के पास नहीं है सब-लेट है वह क्या करेंगे। यह एक लूपहोल है जमीनें महाजनों के पास जा सकती है। उस को तरमीम कर दीजिये। इकोनिमक जमीन बय न हो सकेगी वह जमीन महाजन के पास न जायगी। नान-एग्री-कल्चरिस्ट के पास जमीन न जायगी। जायगी वह जमीन ऐग्रीचल्चरिस्ट के पास में मानता है। अगर आप ऐसी सुरत से उसमें यह चीज रखते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन उसमें यह लपहोल कभी न होना चाहिये वरना नतीजा यह होगा कि महाजन राया देकर उस जमीन की हासिल कर लेगा और कोई चीज उसके अन्दर नहीं है जिससे आप जमीन को उसके हाथ में जाने से रोक सकें।

तो में यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक परती लेंड ओर कल्बरेबिल लंड का ताल्लुक है ये जमीं दार के पास रहेंगी तो कोई हुर्ज नहीं। कानून के बुनियादी उसूल पर इसते कोई अपर नहीं पाता। एक और चीज है। इसके अन्दर आपने मेला (फेयरस) इस किस्म की जो चीजें है वे भी ले ली है लेकिन अगर आप इस पर जरा ठंडे दिल से [श्री सुल्तान जालम खां]

गौर की जिये तो आपके प्रीएम्बल में यह चीज कहां तक आती है ? प्रीएम्बल तो यह कहता है कि "टिलर आफ दी लंड" जो बेल या हल भी हो सकता है। अगर आप इस पर जरा हमदर्दाना स्त्रिट में गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जमींदार को अजसरे नी अपनी जिन्दगी शुरू करने के लिये क्या-क्या चीजें हैं जो आप अपने उसूल को न कुर्वान करके उसके पास छोड़ सकते हैं। अगर इस स्प्रिट में आप गौर करें तो में समझता हं कि इसमें कोई दुश्वारी नहीं हो सकती कि आप उसके भास यह चीज अब मेले का क्या ताल्लुक है ? मेला जो है वह न तो प्रोपराइटरी राइट है और ह टेनेंटरी राइट है। यह एक प्योरली कर्माशयल इंटरेस्ट की चीज है जिसको रेग्युलेंट करना चाहते हैं, अबालिश करना चाहते हैं। तो अगर मेला उसके पास रहता है तो क्या दिक्कत है ? फर्ज कीजिये अगर आप यह चाहते हैं कि कम से कम मेला भी उसके पास न रहे तो में यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चीज हाँगज नहीं आती है। उसके लिये आप अलाहिदा ऐक्ट बनाइये। प्रीएम्बल में आखिर जमींदार ने उसमें मेहनत की है। वह एक प्राइवेट इंटरप्राइज है। उसने उसमें पैसा लगाया है तो यह चीज तो उसके पास लाजिमी होनी चाहिये। जैसे माइन्स के वर्कर्स के साथ आपने लीज कर दी है माइन्स की उसी तरह मेले की भी लीज कर दीजिये। इससे प्रीएम्बल पर कोई असर नहीं पड़ता। इससे इस बिल के बुतियाही उसल पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि आपको कुछ सहस्रियत हो जायगी। या अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही बिलाना चाहते हैं तो वह प्रोपराइटर रहे और कोई ऐसा वर्किंग प्रिसिपल बना वीजिये जिसके मातहत जो जरूरी चीजें हों, जैसे से नीटेशन वर्गरह, उनकी देख-भाल बोर्ड करें और जमींबार बाकी चीजें देखें। में समझता हूं कि जहां तक मेले का ताल्लुक है, माइन्स का ताल्लुक है, इन चीओं का बिल के प्रीएम्किल से कोई ताल्लुः नहीं है जैसा कि कल्चरेबिल बेस्ट लैंड और परती लेंड के बारे में है।

मेंने अखबार में पढ़ा था कि हमारे बुजुर्ग मौलाना हसरत मोहानी साहब ने अपनी तकरीर में यह फरमाया। मुझे अफसोस है कि में उस तकरीर के सुनने के लिये यहां हाजिर नहीं था जूकि काइतकार सब से बढ़ा बलकमार्केटियर है इसलिये उसे प्रोपर इटरिश्य में कोई हक नहीं पहुंचना चाहिये। में मौलाना की इस बलील से तो बहुत इतफाक नहीं करता लेकिन मौलाना ने बात बहुत मार्के की कही है और इससे कुछ बातें ऐसी हैं जो रोहानों में आती हैं। इस बिल में जो तरीका बताया गया ह और जो बुनियावी चीजें रक्खी गई हैं उनमें एक मिल्कियत का सबाल मी हैं। में आपसे सही अर्ज करता है कि में खुब भी अभी तक यह नहीं समझा कि हक्षीकत में प्रोप्राइटरिश्य कहां जा रही है। कुछ तो बिल यह कहता है कि स्टेट की है कभी-कभी प्रोप्तियर साहब की और जनाबबाला की तकरीरों से यह सुन कि भूमिधर को इसका राइट जायगा। लेकिन में यह अब तक जज नहीं कर सका हूं कि प्रोप्राइटरिश्य बाकई किसमें बेस्ट करेगी, हिज मेजस्टी में होगी, इंडियन यूनियन में होगी, पंचायत राज्य में होगी, क्रां होगी। ।

श्री रघुनाथ विनायक घुळेकर—अभी तय नहीं हुआ।

श्री सुत्तान कालम आं— मेरे बोस्त बीबुलेकर की फरमाते हैं कि यह अभी तय नहीं हुआ है तो में जनाब स्पीकर साहब से बहुत ही अवब से अर्थ करना कि अगर यह तय नहीं हुआ है कि प्रोजाइट किय किसमें बेस्ट करेगी तो माननीय सिंबव को यह राय दी जांग कि इस बिल को वापिस ले लें और इस बात को तय करके बिल को हाउस में ल बें। यह तो एक ऐसा ब्नियाबो मतला है जिसके मुताल्लिक दो र में नहीं हो सकती हैं। हम बाब औकात इस बीड के विकार होते रहे कि हमारी ब्नियाबी पालिसी तय न है है भीर हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है और हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है हमारी ब्रियाबी पालिसी तय न हैं। ब्रायाबी ब्रियाबी साम नहीं हुई है हमारी ब्रियाबी साम हमारी हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है हमारी ब्रियाबी साम हमारी हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है। हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है। हमारी ब्रियाबी साम हमारी हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है। हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है। हमारी ब्रियाबी साम हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई है। हमारी ब्रियाबी साम हमारी हमारी हमारी हमारी ब्रियाबी साम नहीं हुई हमारी हमारी ब्रियाबी साम हमारी हमारी

पीरियड्स में ये चीजे कुछ ठीक भी होती हैं लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब हमको कुछ क नेयर कट पालिती अख्तियार करनी पड़ती हैं। शायद वह वक्त आ चुका था और अगर नहीं तो अब जरूर आ गया है। हमको यह तय करना पड़ेगा कि वाकई प्रोप्राइ— टरशिप कहां वेस्ट करेगो। बिल में यह कहा गया है कि प्रोप्राइटरशिप स्टेट को आ रही है। तकरीरों में यह सुनते हैं कि वह काश्तकार को जा रही है। और फैक्ट यह है कि वह कहीं भी नहीं जा रही है उसका पता ही नहीं है। हमने जो अख्तियारात भूमिधर को दिये हैं वह कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड प्रोप्राइटरशिप है। उसे बेचने के अख्तियारात है कुछ शर्नों के साथ।

इस बिल में एक दफा ऐसी भी मौजूद है। मैं उसे कहना नहीं चाहता ओर न उसकी जरूरत है। उसमें यह भी है कि फुर्ज कीजिये एक भूमिधर अपनी उस आराली को जो कि जराअती काम के लिये इस्तेमाल होती थी अगर गैरजराअती, इंडस्ट्रियल या किसी और पर्पंज के लिये इस्तेमाल करना चाहे तो वह कलेक्टर को दरख्वास्त दे और कलेक्टर साहब जब मुतनइय्यन हो जावे कि ठीक है तो वह एक नोटीफिकेशन जारी कर देंगे कि यह अब जराअत की आराजी नहीं रही। तो वह उसके ऊपर कारखाना वगैरह या और जो कुछ चाहे बना सकता है। पहिले ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी लेकिन अब सिलेक्ट कमेटी ने यह कर दिया है। तो अगर वह ऐसा करेगा तो उसके बाट भी वह जमीन एक तीसरी किस्म की आराजो बन जारेगी। हमारे यहां अभी तक एक जराआती और एक शहरी आराजी हं और यह तोसरी किस्म की आराजी होगी। अभी तक फर्ज कीजिये कि एक आराजी जो जराअती है अगर वह गैरजराआती काम में इस्तेमाल होने लगे तो आने वार बन्दोबस्त तक उस पर लगान पड़ेगा और उस वक्त तक उस पर मालगुजारो भी जायगी लेकिन जिस बक्त बन्दोबस्त आवेगा उस वक्त इसका इन्दराज पटवारी के कागजात से हटा दिया जावेगा। वह गरजराअती आराजी करार दे दी जावेगी। और इसके बाद जो भू मधर की आराजी। हो गि, वह एक तीसरी किस्म को आराजी होगी और वह गैरजराअती काम में आयेगी लेकिन उसमें भूमिधर का राइट कायम रहेगा। तो यह एक तीसरी किस्म की चीज है जो हमारे सुबे मे होगी । यानी, जराती, दूसरी शहरी आराजी और तीसरी मुमि-घर की आराजी जो गैरजराअती है यह थोडा सा कनक्यूजन पैदा करने वाली चीज है। लेकिन मैने जब इस पर गौर किया तो मैं इस नती जे पर पहुंचा हि ज्ञायद हम अपने दिमाग में अभी तक क्ल यर नहीं है कि जमीन की मिल्कियत हम किसकी सौंपें। इस वक्त हम कहते हैं कि यह मिल्कियत हमारी है लेकिन हम नहीं कह सकते कि आइन्दा चल करके क्या हो या यह मिन्कियत किसी और को देनी पड़ेगी। तो मै अर्ज करूंगा कि इस किस्म के बिल की, जिसमें करोड़ों इन्सानों की किमतें वाबस्ता है, इस ऐवान में लाने से पहिले इस पर काफो सोच विचार करके एक राय कायम कर लेगी चाहिये। कोई हाफहार्टेड-वे नहीं होना चाहिये। एक उसूल होना चाहिये और उसने ऐसो बात या एलांस्टीसिटी भी नहीं होनी चाहिये कि कभी इघर होजाय और कभी उधर । हम एक परमानेंट स्टैट्यूट बुक्त, एक कानून, लाने वाले हैं जिसमें आइन्दा कोई तरमीम न होगी। ेे किना चाहिये न ं 🚅 , : लेना चाहिये 🛶 हम सूबे में कसा निजाम लायेंगे। हम काइतकार को प्रोप्राइटर बनाना चाहते है या स्टेंट को या ग्राम-पंचायतों में प्रोप्राइटरिशप रखेंगे। किस उसूल पर किस बनि-याद पर हम ईंट रखना चाहते है जिस पर कि सारी इमारत हमकी खड़ी करनी है ? यह चीज इसीलिये जरूरी है कि इसके मुताल्लिक गाव-पंचायतों की बात है। हमारे बिल में जो निजाम है वह गांव-पंचायतों का है यानी हम विलेज रिपब्लिक रखना चाहते है। उनका सम्बन्ध उनसे होगा। इसलिये अगर हमारे दिमाग में सही नक्शा नहीं होगा तो हम उस आसानी के साथ काम को पूरा नहीं कर सकते जिसकी कि जरूरत है।

जनाववाला, इस बिल से एक रिआयत यानी कंसेशन उन लोगों के लिये है जिन के पास सवा छः एकड़ जमीन यो लेकिन अब वह ८ एकड़ कर दी गई है सिलेक्ट

[श्र सुल्तान आलम खां] कतेडो के अन्वर। जिसके पास इतनी आराजी है लेकिन कुछ उठी हुई है उन लोगों को यह हक दिया गया है कि हमने इकोनोमिक होल्डिंग्स की सवा छ एकड मुकरंर किया है। कत से कम उनके इकोनोिम हो लिडाम बन सकें। और इतनी आराजी या कुल आराजी उठी हुई हो उसको बेदबल कर सर्ने जिससे आठ एकड बन सर्हे। इस उन्ल को मान लिया गया है तो ठीक है। अगर नहीं माना जाता तो आगे कहने की गुन्जायश नहीं थी। लेकिन जब इस उसूत्र को मान लिया गया है तो यह चाहिये या कि जितने लोग इससे नफा उठा सकते हो उठा सके। लेकिन में देखता हूं कि इसी दका २२४ के सब कलाज (१) में यह दिया हुआ है कि इसका एन्ही-केशन उन मुकामान पर होगा, जहां प्राविशियल गवनंमेंट नोटी किकेशन कर दे। इसके माने यह है कि एक हाथ से दिया है और दूसरे हाथ से ले लिया है। मेरी समझ में नहीं आया कि इस चीज को रखने की जरूरत ही क्या थी। अगर आप चाहते हैं कि लीग नका उठा सके तो एक जिले में चाहे २०० आदमी नका उठायें और इसरे जिल में चाहे एक आवमी नका उठाये, तो एक आदमी क्यों महरूम रहे? जब आप उसूल मानते हैं तो हुए जगह के लिये यूनीवर्सल होना चाहिये। इसमें कोई फर्क नहीं होता चारिये। में ऐसे कानून को अच्छी नजर से नहीं बेखता जो गवर्नमें टकी बहुत ज्यादा इस्तियारात देता है। जब हम राय आम्मा यानी जनता की राय लेकर यह कानून बना रहे हैं सो इस कानून को चलाने के लिये हमें कानून के दायरे के अन्दर जिल्द से जल्द लोगों की आजादी देना चाहिये। अगर इस कसीटी पर परहें तो आप को यह फैसला करना होगा कि इस वसूल को मानते हैं तो उस दका को कतई हटा दिया जाये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि गोरखपुर में फायदा दें और अलीगढ़ में न दें, इसी तरह से बदायूं में फायदा दें और बरेली में न दें।

चेयरमैन—माननीय सदस्य कितना समय और लेंगे ? श्राम्बलान ग्राजम स्वां—अगर कल के लिये रख विया जाये तो बेहतर है। चेयरमैन—ठीक है।

क्रिय समितियों के चित्र सदस्यों के जुनाय के संबंध में घोषणा अपूक्त यानोजिकल म्यूजियम, मथुरा, की प्रयन्त्र कारिया समित चेयरमैन—कव्ल इसके कि हम उठें हाउस को यह इसिला देनो है कि आर्कियालोजिकल म्युजियम, मयुरा, की प्रबन्धकारियों समिति के लिये दो नाम है।

(१) श्री द्विवमंगल सिंह, (२) श्री मोहम्मद नजीर।

कल १२ वजे से चार बजेतक चुनाव होगा।

प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरो बोर्ड के लिये चुनाव करना है। इसके लिये तीन नाम आये हैं।

(१) डाक्टर रामधर मिश्र

(२) श्री चन्द्रभानु दारण सिंह

(३) श्री मोहम्मव नजीर।

इसके लिये भी कल १२ बजे से ४ बजे तक रीडिंग कम में भत दिये जायेंगे और जुनाब होगा।

श्री के ग्रायमुख्य-- हज्ज कमेटी का भी तो चुनाव होना है।

चे रामीन-इसका चुनाब परसीं होगा।

(इसके पदवात् भवन ५ बाज कर १६ मिनट पर आग हे दिन ११ बाजे तक के लिये स्थागित हो गया।)

केलास चन्द्र भटनागर, मन्त्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली, संयुक्त प्रान्त।

लखनऊ, १२ जनवरी, १९५० ई० ।

नत्थो क

१ अप्रैल,१९३९, १ अप्रैल,१९४७, १ अप्रैल,१९४८ तथा १ अप्रैल, १९४९ को पुलिस के गत्नहेड अधिकारियों की शक्ति का विवरण-चित्र का उत्तर, पीछे पृष्ठ ४७२ पर) (देखिये १२ जनवरी, १९५० ई०, के तारांकित प्रक्रम संख्या ३३

			•		पदाँ ।	पदों का विवरण					•	
तिथि			स्थायी					के	अस्थायी			विशेष
	आई जी	(डो॰ आई॰ जो॰	एस॰ पी॰	ए० एस० मी०	डी० एस० मी०	आई० जी०	डो०आई० जो०	एस० पी०	ए० एस० मी०	एस० पी० ए० एस० डी० एस०	योग	1
१ अप्रैल,१९३९	~	سي	w S	>>	~ ୭	I		r		œ	ンのか	
१ अप्रैल,१९४७	مه و	5"	₩ ₩	~ >>	22	l	lux.	8	•	() >	244	
१ अप्रैल, १९४८	22	5	w 5	% %	£ 0 €	1	m	m o	1	8	us cs. us	
१ अप्रैल, १९४९	٠٠	01	5	2	er 0 ~	Ĭ	1	U3-	Ĭ	w 7)	256	

एक डी॰ आई॰ जी॰ की जगह अभी खाली रक्खी गई

Accessors agrees						4	पृष्टित दल की ग्राक्ति	मि						
मूनिट का नास	75	१ मर्जेल, १	62.0		0	१ अप्रैल, १९४७	ବ୍ୟ		१ अप्रैल, १९४८	22.58		श्रमेल }	अप्रैल, १९४९	विशेष
	757773	सब- इंस्पक्टर	the to	हे कांस- देवल	75种护护	म्ब-	हे काम- टेबिल	5,40,45.4	सब- इंस्नेक्टर	हे॰ कांस- टेबिल	7.5FP7.3	सत्र- इंस्पेनट>	हे कास- टबल	
१—जिला कार्यकारी वल	360	U.S.	200	m'	33%		<u> </u>		328's 083	के के कि	5	2,80	রভাই' ৸ ৫৯১'১	अपराध तथा
२-गुलकर विमाग	3		(13°	0	2%	30	22	3	3,	€ o &	3	ୠୠ	かり	जनसंत्या में वृद्धि
१भृष्टाचार विरोधक	*			*	28	<i>z.</i>	m.	:	:	:	•	•	:	के कारण वृद्धि गुत्तवर विभाग
विभाग														में मिम्मिल्त
४गवर्तमॅट रेलवे युलिस	>0		:	*	ty	9	o. ₩	9	9	m m	ŋ	^ሀ ት ማ	25	गवर्गम्य रेलवे पुलिम्यक् के पुनः मंगठम् के कारण्
५—पुलिस निरीक्षण महा- विद्यालय	9		m»	•	W	200	<i>5</i>	প	స్	65	or or	u)*	> >	एस० आई० सी०पी० कोर्स के लिये अधिक शिक्षायों भेजने के कारण

						חם	पुलिस दल की	भे शिक्त	ic				İ	
यनिट का नाम	१ अप्रैल	प्रेल १९३९		-	अप्रै क,	9898			र अर्थ	अप्रैल, १९४८	\ \ \ \	१ अप्रल,	ज, १९४९	
	7.5FP7}	सब- इंस्पेक्टर	हे॰ कांस- टेबिल	75 7 95		सब- इंस्पे कटर	हे॰ कास- देबिल	75FP7;z	सब- इस्पेक्टर	हे ० कास- : टेबिल	」 ア 5₽∳ 7 夏	सब- इस्पेक्टर	हे० कास- ट्रेबिल	विशेष
६—पुलिस शिक्ष गपाठशाला	।ध्या	:			~	V	ur oʻ	~	ۍ	00	~	Ų.	٠ <u>٠</u>	१९कांसटेबिलो को हे॰ कामहे-
७केन्द्रीय संप्रहालय	:	:	•	:	~	~	o.	~	m	ω	~	lts.	১	बिल के पद
८प्रान्तीय सजस्त्र कांस-	#- :	:	•	•	200	\$ \$	6 X 3	2	368	ee > &	0°	286	% % %	भ भूदार्थात्य में शिक्षाय
टबुलरा ९वेतार मा तार	Ī	:	•		•	2	2%	~	28	288	or	» »	ب م م	नवीन योजना
9 ०मोरर बाइन विभाग	E		•				စ္			9	~	ۍ.	5	
११रेल रसा प्रलिस				~	2	us m	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	م مہ	3	930	حر مہ	5° %	8	
१२रेडियो टेलीफोन विभाग	विभाग	:	•	•		:	8	:	:	30	:	:	3	
१३दियर स्मोक स्ववाड	টো	•	•	•	•	ص	°~	:	ۍ	°~	:	~	œ	
- 1	ho		; >			:	: :	:	:	: 2	w '	<u>ه</u> ۱	er 2	
१५—पुलिस का प्रचान कामाल्य	योग र	उरह ३,०२१		. 8	25.6	238.5	८भूग १३	. 35 35 20 20 20	2,638	"	>0 00-	इ,७८३	088'2	
१६१ अप्रेल, १९३९ के पश्चात्	के पश्चात	برند برسو	I		2%	9 9 8	7,360	5. 13.	هه م	3,९५९	300	9 3 3	24012	

नत्यो 'व ं

(देखिए १२ अनवरी, १९५० ई० के तार्राकित प्रश्न संस्था ४६ का उत्तर पोछ पृष्ठ ४७४ पर)

+hc श्री वंशागेपाल के १४ वें दिन की बैठक के जिये तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर का नक्या जोकि ऊपर कहा गया

	×
	ू र
	वीछे प
	उत्तर
	ह
	৩০ কা
	lo.
	>0 VU
` <u>-</u> -	m.
त्थी भ	संख्या
नं	प्रश्न
	तारांकित
	18
	cho.
	०५०४
	जनवरी,
	~
	(देखिए

	१९५० ई० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६४ व ७० का उत्तर पछि पृष्ठ ४७९ पर)	असेम्बलो प्रश्न सं० ७०	हरिजन बस्ती ओर उसके आस-पास खुले हुए स्कूलो की संख्या (क)	१–गाव कसियारा, 'किखाना चारबधात । २–गाव अढ्डुल्पर,डानक्षान। पुरकाजी । ३-गागकासमपुर तालहिब, डाककाना भोषा। ४-गावयोधाना, टाकखाना मिकरो ।		(१)गाव जिगना पोस्ट सहजनवा,(२) ग्राम हापुड, पोस्ट चीरा, (३)ग्राम गर्नेश पुर, पोस्ट नौगनवा, ४) ग्राम वासाला, पोस्ट सहजन, (५) ग्राम नतवा, पोस्ट च रीचोरा, (६) ग्राम त्रिलोकपुर, पोस्ट नौतनवा ।	
नत्थी 'म्	प्रश्न संख्या ६	>0 13	in the second	yo yo	२ कोईअर्ग बस्ती नही	o w. v.	
	े के तारांकित	असेम्बली प्रदन सं० ६४	हेड हरिजन मास्डरों मस्टर की कुल की कुल संन्यां सख्या	عن م	ร์ กา	o w m	o' mr
	के १५० क	असेम	हरिजन मास्टरों की सं०	2%	5	מר מי	
	(देखिए १२ जनवरी,	न सं० ६३	गवर्नमेंट प्राइ- मरी स्कूलों में मास्टरों की कुल संख्या	۵۰۶	& &	०७२४	er
	(देखि	अमेम्बली प्रश्न सं० ६३	फ़्रस् क्रान्त्रों के नाम संo	मुजफ्फरनगर	बांदा	जालीन उरई मे बरेली गोरखपुर	सुल्तानपुर
			क्रांस् सं ०	~	b.	מ א אמ	Ų.

'		असेम्बली प्रश्न सं० ६३	165	असेम्बली प्रक्त सं० ६४	सं ६४	अमेम्बली प्रश्न सं० ७०	
H. o.	- जिल्हों नाम	गवर्गमंट प्राइ- मरी स्कूलों में मास्टरों की कुल सख्या	हारिजन मास्टरों की सं॰	हेंड मास्टरों की कुल मंख्या	हरियम हेड मास्टर्भ की कुल मंहया	ह रजन बस्नी और उमके आम-पाप ज ले हुए स्कूलो की संस्या (क)	
9	अल्मो डा	र्रक्र	in.	9 & c	ω ο·	१४ (१) कताली "क्लाबोराराज. (२) वननाराड् प का नेवाट, (३) ज्वाकाकोट नाक मिउनारा, (४) गर्वरा मन्ना कनियोर. ७) घटणव, (६) पतराघार बेक्गौना उनयर (१) नकोट लाखनपुर.(८) म्याक प्रग् बम्यानी.(९) लेहर- वीश बिसालकम्पूर.(१६) स्वरेरी बकानया. (११) पन प्रोख्ड मन्ना साक्ट (१२) चुनौका बिबाक्च जाकती (१३) विकताका टानपुर.(१४) अमीताका दानपुर. १५) त्यार देना वगन (१६) काकड पामडो केन्चां (१३) उसा- देशों एक०एक८.(१८) चनाकी नक्ना स्यताग (१२) सनवत्रपट्टी पाला- मान्ट, (२०) बागड बिचाका कमिष्यार.(१८) मनिच्चा पत्नाडोग.	
7	ब्लन्दशहर	os na na	ij) Out	200	42	२ (१) ग्रार मडाकरोम पोस्ट छत्रारी ।२) जोय्ट चदेमा।	
0.	म्त्राबाबाद	28c FI	12.	។ប ស			•
~	अजिमपाङ्	or nor or	m,	a) Lux	or Or	९ (१) झाहुषु रपोस्ट सरायमीत.(२)अमीरामोहिद्दीनषुर पोस्ट मोहम्मदपुर, (३)अत्ताहृषुर पोस्ट माहुक,(४) कचारपुर पोस्ट कचारपुर, (५)पुरवा बेलासुलतानपुर,(६) खुनखुनवा पोस्ट कोपागज,(७) सुसवा पोस्ट पल्लिया (८)कोनवालीपुर पोस्ट अहरील्ड, (२)लफरपुर पोस्ट सबर।	2 2 2 2 2 2 40

٠٠ •٠	एदा	الله در در	or	, ,	•	४ (१)गढ पोस्ट नवाखेरा(२)गोथुवा पोस्टनवाखेरा,(३)न्गला बरजरन पोस्ट मोहनपुर,(४)दलूपुर पोस्ट पिलवा।
6 ~	ब्हायू -	Us. Ns. O	(JS*	° %	>>	२ (१)गांव रामपुर पोस्ट नगरझूना, (२)गाव बखुआ पोस्ट उझियानी।
m-	हरदोई	ሠ. ሁ. በን.	w ⊶	Gr mr	œ	५ (१)गाव संडीला मासित पोस्ट टंडियावाना, (२)गांव पारसपुर पोस्ट अहरौरो,(३)रामपुर रहोिल्या पोस्ट बवन, (४)गांव बिथारी पोस्ट जीरो,(५)तुसऊ पुरवा पोस्ट पिहाई।
>0 •~*	नैनीताल	er er	2	% 5	•	९ (१)हरीनगर पोस्ट पहाड़पानी,(२) तारीखेत पोस्ट नरभपती,(३) चीर— लेख पोस्ट पहाड़गानी,(४) उरबासोती पट री ऊथा कोट पोस्ट बेताल— घाट,(५) हरीनगर चु गसिल पटटो छखता पोस्ट थीमताल,(६) लालपुर पोस्ट काहीपुर,(७) स लेयाकोट पट टी अगोर पोस्ट मुक्तेंडबर,(८) मतें।— लागढ पट्टीकला अनार पोस्ट खानसियून,(९)देबीचीरा पोस्ट ननीत ल।
<i>5</i> ℃	मैनपुरी	us. us.	£	>	O.	१२ (१)म्जयानपौरा पोस्ट बेबार, (२) ओन्चारी पोस्ट शिकोहाबाद, (३) नगलासामसिहपोस्ट जयोतो, (४) लाघुपुर पोस्ट मालनपुर, (५) नगला खनेतरी पोस्ट मिरसागज, (६) नगलासती पोस्ट भेनपुरी, (७) नरघुपा पोस्ट शिकोहाबाद, (८) नगला दुलि दुल्योराबर, (१) कसौली पोस्ट बरनाहाल, (१०) नगला मानाधोता पोस्ट बरनाहाल, (११) नगलाकोठी सिरसा पोस्ट सिरसागज, (१२) नगलाकोठी
6 ~	मेरट	282	%	≫ w	۰.	
୭	फैजात्रवि	w 3	2	ه. ه	•	४ (१) देवराकोट पोस्ट पिलखवां, (२) बुरहानपुर पोस्ट कृकरी बाजार, (३) इटवरा सुन्दपुर पोस्ट, रामनगर(४) हाजीपुर पोस्ट हरवापीताघ्वरपुर।

	•	असेम्बली प्रश्न सं	सं ६३	असेम्बर्ज	असेम्बङी प्रश्न सं० ६४	असेम्बली प्रस्त सँख्या ७०
H, AH	जिलों के नाम	गवर्तमेंट प्राइ- मरी स्कूलों में मास्टरों की कुल संस्या	. हरिजन मास्टरो की	होड मास्टरो कोल सं	हरिजन हेड मास्टरों की केल सं०	हरिजन बस्नी और उमके आय-पाम खुले हुये स्क्लों की संख्या (क)
28	देवरिया	hŁx	149" 00.0"	ů.		३ (१) जगदीत्रापुर पोम्ट तरया स्याम.(२) तिघरा खेरवा पाम्ट इकस्री. (३) ६३पुर पोम्ट ६४पुर।
0° 0° 0°	देहराडून लक्षनऊ मांसी	45% 45%	2 00 12	o/ 5' 0 m N	~- >> m	
6	बहराइच	÷		}	r	
C.	गढ्बान	% Ur V	tu	ග <i>ප</i>	m)	(१)कंडी पोस्ट बघवा गरवा,(२)पंचाली पोस्ट गनीखानी गडवाल. (३)ज्यारापोस्ट गुप्नकाशी गडवाल,(४)किनमुर पोस्ट गुर्डल गढ़- वाल.(५)बरई पोस्ट बगदियाद।
*	सहारनपुर	300 C	m	W	ow.	४ (१) रामनार नोटे रोडपोस्ट महारनपुर,(२)ब्रुवाताला पोस्ट मोहान, (२)सनपुरा पोस्ट बिहारागढ,(४)मग्लाबो पोस्ट सहारनपुर।
2 2 2 2	अलीगढ सीतापुर मथुरा	2 m m	2 8	us us us us so us	ሙ የ ኦ	

३ (१) सैनो पोस्ट सिराथू,(२) विझवनिया पोस्ट सैगबाव(३) शेरपुर नगता पोस्ट जंबई ।		२ (१) सम्दपुर पोस्ट नष्डल, (२) तकीपुर पोस्ट मोहमदाबाद।					१ (१) सुतलह पोस्ट रायबरेली।	१ (१) सुनावा पोस्ट पतिज्या बुजुरा।					(१) औसबालतीफ्रपुर पोस्ट संग्रामण्ड ।	इन स्कूजों में हिन्जिन बस्ती के भी स्कूल है।
o.	• •	lus.	~	: :	:	m·	9	:		~	~	• •	G.	:
5	~ m	% %	% % %	, m	×	\$	>0 >0	۵	, Ž	Us. Us.	ò	<u>م</u> پ	2	9
5-	500	US)» n	> >	3	er er	مرد •	U.	33	9	2	<u>م</u>	V	No.
w. o.	0 5 mm	E C	22 m	260 AGO	7 34	360	5 5 8	976	000	424	30m	3" RY CY	766	0 * pr
इक हिमाब	इटावा हमीरपुर	फर्बाबाद	गाचीपुर बागरा	बल्जिया	मीनपुर	बारा की	रायबरेली	गोंदा	कामपुर	उम्नोव	शाहजाहांपुर	फतेहगुर	प्रतापगढ़	•स्तो
22	÷	*	ton the	X	27	U3"		2	M	»	<u>~</u>) *	*	\$

असोम्बली प्रश्न सं० ६३		असेम्बली प्रध्न सं० ६४	کر وی		असेस्डली प्रश्न सं० ७०
क्य- जिल्लों का नाम सं०	मर्वतंत्रेट प्राइ- मरी स्कूलोंमें मास्टरों कीं कुत्र सख्या	हरितम मास्टरों की सं०	हेंड मास्टरो की कुल सख्या	हरितान हेड मास्टरों मी कुल संख्या	हरिजन बस्ती और उसके आस-पास खुले हुऐ स्कूलों की संख्या (क)
2,4	Š		% %	•	 (१)तारतपुर पोस्ट मुगलसराय, (१) उधरा पोस्ट चौबेपुर, (३) जगदीश- पुर पोस्ट चोलापुर, (४) गनेशपुर पोस्ट शिवपुर, (५) दियापुर पोस्ट सकलडीहा, (६) चारी सेदराज, (७) अखारी पोस्ट रोहानियां, (८) जगदीशपुर पोस्ट धामपुर
४६ जबीमपुर बीचे		2	Ma.	ž. 9	१५ (१) बनतिया पोस्ट विजवा, (२) कन्हैयागंज पोस्ट औरंगाबाद, (३) खेर ताजी पोस्ट बांकेगंज, (४) मदारोपुरवा पोस्ट कलव , (५) शबाबपुर पोस्ट औरंगाबाद, (६)गृंद पिसयापुर पोस्ट बांकेगंज, (७) बानकती पोस्ट हुडवा, (८) मसान खम्भपोस्ट डुडवा, (१) गौरीपाटा पोस्ट डुडवा, (१०) चन्दनचोक्की पोस्ट डुडवा, (११) मेंजगांव पोस्ट मित्तौली, (१२) फजल- नगर पोस्ट मुडासवरान, (१३) पयाग पोस्ट लबीमपुर (१४), मानपुर पोस्ट ऐरा, (१५) रावतपुरा पोस्ट मित्तौली।
ूर्ड मुख्या १९०	3 7 È	•	° >>	or m	(१) रामपुर पोस्ट रामगढ़,(२) मुहूर्लार्या पोस्ट लःलगंज,(३) परागपानी पोस्ट म्योरपुर,(४) विजयापुर पोस्ट गहरवार गांव, (५) होसीपुर पोस्ट सिखद, (६) किरविल पोस्ट मयोग्पुर, (७) परसोय पोस्ट राबर्टस गंज, (८) पनारी पोस्ट राबर्टसगंज,(९) बेलगरही प्रोस्ट राबर्टसगेंज, (१०) च्यो सहियानोस्ट कोन,(११) धाम पोस्ट विद्यानगंज,(१२) इकावरी पोस्ट स्पोरप्रुर,

(१३) गोडमारा पीस्ट राबर्ट्स गंज, (१४) कोरानगी पोस्ट डुघी, (१५) क्रि. वां गोस्ट कोंग, (१६) मितिहानी पोस्ट गहरवार, (१७) निगाई पोस्ट कोंग, (१८) नेकहा पोस्ट कोंन, (१९) पोखरा पोस्ट स्पोरपुर, (२०) रकसवा पोस्ट राबर्ट्स गंज, (२१) रास पहाड़ी गोस्ट राबर्ट्स गंज, (२२) वैका पोस्ट मघोरपुर, (२३) हथवती पोस्ट हुधी, (२४) कोंगा पोस्ट हुधी, (२८) खोटो महुआ पोस्ट हुधी, (२६) जिघनवा पोस्ट हुध, (२७) माचावहृष् पोस्ट हुध, (२८) परानी पोस्ट मापोपुर, (२९) करिद्या पोस्ट मघोरपुर (३०) हराना करचर पोस्ट विन्धानगंज। (३१) पसाही पोस्ट दुधी, (३२) कसौली पोस्ट विन्धानगंज।	à 52
~	880
መታ በታ በታ ርታ	৬৮৮ ১ ৬৮৪
V 22	3 1 9
לגי עג. עג. עג. עג. עג	9 m, m,
पीळीमीत बिज गिर	योग

> ° × × पी० एस० यू० गी०-१३८ वृत्तक ए०-१९५० --५०००

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलो

द्युक्तदार, १३ जनवरी सन् १६५० है।

ब्रह्मस्वल जी पठल, प्रसाखलों भवन, पत्रनक में ११ वजे दिन ने ब्रार्थम पुरे

न्त्री -र--मानिश्य श्रो पुरय एमदास टराइन

उपस्थित सदस्यों भी सूची (१८७)

अचल विह अजित प्रताद भिह अब्दुल वाकी अब्दुल मर्ज द अद्बुल प्रजोद स्वाजा **अब्दुल ना** जिन, श्रीमती अब्दुः इनीद ामपार अहमद खां अर्नेरट नाईकेल फिलिप्स अली जर्रार जाफरी अल्फ्रेड धर्मदास अनगर अली लां अक्षायवर गित आत्माराम गोजिन्द खेर, माननीय श्री आचिनारड जेम्स फेन्थम इन्द्रदेव (त्रपाठी इनाम हबीबुल्ला, श्रीमती उदयवीर सिंह ऐजाज रसूल कमलापति तिवारी करीमुर्रजा खां कालीचरण टण्डन कुतलानस्य गैरोला कुपासकर कृष्ण चन्द कुष्ण चन्द्र गुप्त केशव गुप्त

जान बन्द गालन जु ग्वनराय खुशार ग गग, धर गंग । प्रशाद गंगा वात चोवे गजाधरत्रजाट गणदति सहाय रणेश कुष्ण जैतले. । गिरपारी हाल, मानपीय श्रा गोपाल नारायण सक्सेना ं गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय ६ बन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री चन्द्रभानु शरण सिङ् वरण निंड चेतराम छेदाचाल गुपा जगन्नाथ दास जगन्नाथ प्रताद अग्रवाल , जगन्नाय भिह जगन प्रसाद राजत जगमोहन सिंह नेगी | जयपाल िं≅ जबरान वर्मा जवाहर लाल रोडनगो वहर अहमद

जाकिर अली जाहिब हलन जुगुल किशोर त्रिलोकी सिंह वयालदास भगत दाऊदबाल खन्ना द्वारिका प्रसाद मोर्घ दोन दयालु अवस्थी बीन दयालुं शास्त्री दीय नारायण अमर् नफ़ीसुल हसन नवाजिश अली खां नवाब सिह नाजिस अली नारायण दाल निसार अहमद शेरवानी, माननीय शी पूर्णभासी पूर्णिया बनर्जी, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्रीमती **प्रयागनारायण** प्रेम किशन खन्ना फ़लरल इस्लाम फ़जलुर्रहमान खां फतेह सिंह राणा फुल सिह-बदन सिह बनारसी वास चलदेव प्रसाद बशोर अहमद बशीर अहमद अन्सारी बादशाह गुप्त भगवती प्रताव दुवे भगवती प्रसाद शुक्ल भगवानदोन भगवानवीन मिश्र भारत सिंह यादवाचार्य भीम सेन मंगला प्रसाद मसुरिया वीन महफूजुर्हमान महमूद अली खां भिजाजी लाल मुकुन्दलाल अग्रवाल मुजपफ़र हुसैन मुहम्मद अबील अब्बासी मुहम्मद असरार अहमद

मुहम्मद इब्राहीय, याननीय श्री म्हरमद इस्माईल महम्मद जनशेद अली खां महम्भद नबी मृहस्मद नजीर मुहम्मद यानूब महस्मद व सुफ़ महम्भव रजा लां मुहस्सद शक्रूर मुहस्मुद शमीम मुहम्बद शाहिद फ़ाखरी मुहम्मद शोकत अली खां मुहम्मद सुलेमान अधमी यज्ञनारायण उपाध्याय रघुनाथ जिनायक घुलेकर रव्वंशनारायण सिंह रववीर सहाथ राघव वास राजकुवार सिंह राजाराम मिश्र राजाराम शास्त्री राधाकुरण अग्रवाल राधा मोहन तिह राधेश्याम शर्मा रावकुमार शास्त्री राम कुपा ह सिंह राजवन्त्र पालीवाल रानचन्द्र सेहरा रामजी सहाय रामधारी पांड राम बली मिथा राम मूर्ति राम शंकर लाल राज शरण राभ स्वरूप गुप्त श्वनुद्दीन खां रोशन जमां खां लक्ष्मी देवी, श्रीमती लताफत हुसैन लाखन बास जाटव लालबहादुर, माननीय श्री लालिबहारी टण्डन लीलाधर अष्ठाना लुत्फ अली लां लोटन राम विजयानन्व मिश्र

विद्याघर नाजपेती विद्यानतः र ठौर, श्र मती निनय कु नार मुकर्जी विश्वनाथ प्र नाव िश्यनाथ राय विष्णु दारण दुब्लि । वीरबन्द पित वीरेन्द्र शह वेकटेश नारायण निवारी शंहर इत नर्ना राहित प्राच गर्ना जिय कु रार पाडे हार कुरार मिश्र नित ददाल उपाध्याय ोजदान निह ोशवमगल मिह कपूर -प्रामल, ल नर्मा न्यात सुन्दर शुक्ल श्रीचन्द्र तिघ न श्रीपनि महात दरजन देवें महनोत श्री गती

र स्वूर्णानाइ, गाननीय श्री ज्यात हुनैन नर्तात होन्दि खा r^{*}ज़द *हुन्*न राच्यिय जाय व्हार - हामन निह य नारा "अकाना सुरामा प्रवाद मुरेन्द्र यहादुर गिर मुन्तान जलन लां पूर्व प्रता अवस्थी ⁺ इे− जहमब ुन पुर्रम्यास अन्यारी। ्दीबुर्द्हणात वा तरके किन जनम हरप्रगाद सन्दर्भेगो र =- मोहारि उपुर्विच्, ताननीयश्री होतालाल जग्ना इन्बद्धः

प्रशीत्तर

गुक्रवार, १६ जरवरो सन् १९५० ई०

(गुरुवार, १२ जरवरी मन् १९५० ई० के शेव प्रक्त)

तारांकित प्रकन

नानरेरी लाब सल हकार की नियुक्ति

*९५--श्री दीनद्यालु शास्त्री--प्या सरकार ने गत दो वर्षी से किसी

माननीय ग्रन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु ग्रुप्त)—जी नहीं। श्री दीनद्यालु शास्त्री—दया श्रीमती मीरा बेन इस पद पर नियुक्त नहीं हुईं? माननीय ग्रन्न सचिव— जी नहीं।

*९६—श्री वीनद्या हु शास्त्री—इस मलाहकार के स्टाफ पर इन दो वर्षों में कुल कितना ब्यय हुआ ?

माननीय अन्न सचिव-- प्रश्न ही नहीं उठता।

सन् १६७५ ई० में नायब तहसीलदारों के रिक्त स्थानें का मरा जाना

*१०४—श्री र धुवीर सह। य-नया सरकार कृपा करके बतायेगी कि नायब तहसील-वारों के केडर में सन् १९४५ ई० से कितनी जगहें खाली हुई ? उनमें से कितनी डाइरेक्ट रेक्नूटमेंट द्वारा भरी गई और कितनों पर सुपरवाइवार कानूनगी रक्खे गये?

माननीय माल सिचय (श्री हुकुम सिह)—नायव तहसीलदारों के केडर में सन् १९४४ से १९४९ तक कुल १५० जगहें खाली हुईं। सन् १९४४ व १९४५ की जगहें एक साथ भरी गईं इसलिये खाली जगहों के आंकड़े सन् १९४४ से बताये गये, इन १५० जगहों में से ५५ जगहें सुपरवाइजर, कानूनगोयान को मिलीं और ९५ जगहें डाइरेक्ट रेक्ट्रसेंट (बाहरी आदिमयों) द्वारा भरीं गईं।

श्री रतुवीर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने कोई अनुपात सुपरवाइजर कानूनगो से नायब तहलीलवार होने का मुकरेर किया है?

माननीय माल सिख्य-प्रोमोशन से एक तिहाई और बाकी डाइरेक्ट रेक्ट्रमेंट से नायब तहसीलदार गुकरेर किये जाते हैं।

श्री रघुवीर सताय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सुपरवाइजर, कानूनगो नायब तहसील्यार की हैसियत में काम कर रहे हैं अगर उनका काम ठीक हुआ तो वह तहसील्यारी के लिये भी उम्मीदवार होंगे ?

मानेनीय साल सन्त्रिय—जब तक वह नायव तहसीलदार के पद पर कंफर्म नहीं हो जाते तब तक तहसीलदार के पद के लिये सवाल नहीं उठता।

श्री रख्रवीर सहाय--क्वा सरकार यह वताने की कृपा करेगी कि जो सुपरवाइजर कानूनगो नायब तहसीलवारी के पव पर कंकर्म हो गये हैं, उनकी संख्या क्या है?

माननीय माता सन्त्रिय-वह तो मेरिट के हिसाब से ते होगा। वह इस काबिल हुये, तो जरूर कंफर्म किये जायेंगे।

यू० पी० तहसीलदार एसोसियेशन की तनस्वाह बढ़ाने के सम्बन्त में प्रार्थाना-पत्र

*१०५-श्री रघुवीर सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृषा करेगी कि यू० पी० तहसीलवार एसोतियेशन ने अपनी तनस्वाह बढ़ाने के सन्बन्ध में सरकार को एक प्रार्थना-पत्र भेजा था? यह प्रार्थना—पत्र सरकार को कब प्राप्त हुआ। वया सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रक्खेगी?

माननीय माळ लिचिय—जी हां। यह प्रार्थना-पत्र सरकार को १२ फरवरी सन् १९४७ को प्राप्त हुआ। उनकी एक प्रति प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पुष्ठ ५०८ पर)

*१०६--श्री रघुवीर सहाय--प्या यह तच है कि उस प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एसोसियेशन के प्रतिनिधि फाइनेंस सेकेंड्री से भी १८-१२-४८ को फिले थे ?

माननीय माल लिचव--ऐसा सम्भव है कि तहसीलदार एसोसियेशन के प्रतिनिधि इस सम्बन्ध में फाइनेंस सेकेट्री से १८ दिसम्बर सन् १९४८ को मिले हों।

*१०७--श्री रघुवीर सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृषा करेगी कि प्रार्थना-पत्र और डेपुटेशन के मिलने का क्या परिणाम हुआ ?

माननीय माल सचिव--उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर वी गई।

श्रो रद्धवीर महाय--श्या सरकार पुनः इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने का इरादा रखती है ?

नोट-तारांकित प्रश्न संख्या ९७-१०३ तथा उनके उत्तर १२ जमवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपे ह।

मः निराय माल सचित्र—अभी तो सरकार ने कोई ऐना निश्चय नहीं किया है। श्री रुधुवीर सहाय—फाइनेस सेकेट्री साहब का जो विचार इस प्रार्थना—पत्र के बारे में था वया वहीं विचार सरकार का अब भी है?

नाननीय माल सचिय—जन यह प्रार्थना—पत्र अस्वीकृत हुआ था तब सरकार का वही विचार था, उसके बाद पुनर्विचार के लिये कोई फैरका नहीं हुआ। कुंबर उयाशंकर देश एमा इन्टर काले ।, बरेती के पश्याप हों की वेनन न मिलने की शिकायत

4१०८—श्री रघुवीर जिहाय—वया कु॰ द्यागंकर ई॰ एम॰ इन्टर कालेज, बरेली के टीचर्म ने डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर, बरेली, डिप्टी डाइरेक्टर शिक्षा विभाग और माननीय गिक्षा मंत्री का ध्यान अत्रैल से वेता न निलने की ओर दिलाया था? यदि यह ठीक है, तो क्या सरकार यह वतायेगी कि उपका क्या परिणाम हुआ?

माननीय शिक्षा सचित्र के सभा मंत्री (श्रीमाम्ब्रुजुरेटमान) — क्वर दयां कर ई० एम० इन्टर कालेज, वरेली के अध्यापकों ने इस विषय का एक आवेदन-पत्र डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आक स्कूटर वरेली को भेजा था।

अब ये अञ्जावक अवना वेनन समय पर पाते है।

श्री रघुवी : महाय--या सरकार यह दताने की कृषा करेगी कि कितने मात तक जीक रूप से वेतन नहीं दिया गया ?

श्री महफूजुर हमान-- अप्रैल, मई, ओर जून तक तनस्वाह नहीं दी गई उत्तके बाद फिर सब दी गयी।

(शुक्रवार, १३ जनवरी सन् १६४० ई० के प्रश्न)

तारांकित प्रश्न

र्स:मेंट श्रोर रैयान फैक्टरियों के लिये मशीनां की खरीद

*१—श्री च नुर्भु ज दार्गा (अ पुणिस्थत)—क्या यह सच है कि प्रान्तीय सरकार ने लीमेट फेक्टरी और रेयान फेक्टरी (नक्कलो रेगम) के लिये औजार और सामान खरीदने का प्रबन्ध विदेशों में किया है ?

माननीय पृक्षिस सचिव (श्री लाठ बहादुर) — यह सच है कि सरकार ने प्रस्तावित सीमेंट फैक्टरी के लिये विलायत में यंत्र आदि मोल ले लिये हैं। रैयान फैक्टरी की योजना अभी अपूर्ण है और इसके लिये यंत्र आदि मोल लेने का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया है।

*२--श्री चतुर्भं ज शर्मा (अनुगिह्यत)--प्रवि हां तो--

- (क) कौन-कौन मशीनें और ओजारों को खरीदने का प्रवत्ध किया गया?
- (ख) इन मशीनों के खरीदने के लिये किनना रुपया पेशगी जमा किया गया और किस एजेंसी द्वारा ?
 - (ग) जो रुपया जमा किया गया वह कब जमा किया गया?
 - (घ) उस रुपये पर क्या कोई सूद सरकार को मिल रहा है?
 - (इ) यह मशीनें सरकार को कब तक मिलने की आशा है ?

माननीय पुलिस सिचय---(क) सीमेट फैक्टरी की स्थापना के लिये आवत्यक समस्त यंत्र आदि मोर ले लिये गये हैं।

- (ख) गह यंत्र प्रादि विजायत के मैलर्ग विकर्स आम स्ट्रीग्स लिमिटेड निर्माण कर रहे हैं और भारत में उनके प्रतिनिधि मेलर्स विकर्स (ईस्टर्न) लिमिटेउ—वामो, हारा उपलब्ध होंगे। इनका कुल मूल्य १५७ करोर उपने के उगमन ने निसमें मेलर्स किर्म (ईस्टर्न) लिमिटेड को पहले दो लाख नायें के और उस के उपरान्त सैतीम जाव पदाप हजार का की नकद रकमें दी गई।
- (ग)२,००,००० स० को राम अप्रे " ना १९४८ में तार २७५०, र रूप की रकम मई सन् १९४९ में दी गई।
 - (घ) जी नहा।
- (इ.) मेनसं निर्ह्मा (१८८०)। प्रतिटेष्ट से किये गरे ठेके ने ना सार पास्य यत्र आदि विलायत से १९ अनस्त निरूप्त १० नक मेज दिये जाने चालिये और ला उति । समय में आ जाने वालिये।

ं २--श्री ततं भुज अर्था (प्रमुपा था) -- उक्त फैरर्गरण। वं किन्नः पगति अव तक हुई है और सरकार का नक इनके पूरे हो जाने की जाना रिती ै।

माननीय पुत्तम् स्मित्र-- दैन्टरी काउपे हमान मिर्जापुर जिने से राह् प्राज के निकट निष्टिचत हो जुका है और इमारन के नक्ते इत्यादि जनाये मा रहे है। जाशा है कि सन् १९५१ के उत्तरार्ध तह फीक्टरी नाज़ हा अपेगी ।

टाउन सार्या कमचारिया का नाकरी सं दटने क लिए निर्धारित अयु

*४—भी फासर र उन्लाम (म्रनुपिस्ति)—स्यासरकार कृषा करने बनायेगी कि दाउन एरिया के हर्न वारियों के लिये तो करा से एटने क जिले तृत लिमिट प्रधारमंगी गयी हैं?

माननीय स्प्रशासन सिचव (श्रो श्रात्माराम गोविन्द ग्वर) — -सामान तया कमेटी के किसी भी कमेंचारी को ६० वर्ष को आय पूरी कर लेने पर नो हरी से हटा दिया जायगा परन्तु ६५ वर्ष की आयु पूरो कर ठेने पर उसे किसी भी दशा में नो हरी में नहीं रहने दिया जायगा। ६० वर्ष की आयु हो जाने के बाद, केवल विशेष कारणा के आधार पर यह अवधि अधिक से अधिक फुल ५ वर्ष के लिये बढ़ागों जा सकती है परन्तु शर्त पह है कि अवधि एक वार में केवल एह की माल के लिये नदाई जा गकती है।

*५--श्री फखरल उरलाम (प्रतृपरिधत)-- क्या सरकार जानती है कि टाउन एरिया मैनुअल में कोई एज लिमित नहीं वी हुई हैं '

माननीय रुपशास्त्रन सिव्य-- जी हा इसी कारण सरकार ने अलग से इस विषय पर नियम बना विषे हैं, िनका विवरण प्रक्रन ४ में किया जा चुका है।

संयुक्त प्रान्त म दमाश्र ज्ञात के लाग

र्माजी सहाय-क्या यह मच है कि संयुक्त प्रान्त में ७५ हनः र दुसाव बसते हैं ?

भाननीय प्रधान सम्बिव के सभा मत्री (श्री चरण सिह) –१९४१ की जन-गणना के अनुसार युक्त प्रान्त में रहने वाले बुसाधी की संख्या ७७,४५६ है।

*७--श्री गामजी सहाय--क्या वह सच है कि इ.व प्रान्त में दुसाध सरकारी परिगणित जातियों की सुत्री में नहीं रखें गये हैं ? यदि हा तो क्यों ? श्री चर य सिह—जी हां, कारम यह है कि उन्हें उस नमय की सरकार ने पानंसेट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ ई० के अयोन जनी हुई परिगणित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया था।

े श्री । मजी सदाय—-क्या सरकार को नात है कि दुवाध जाति अस्पृत्य जाति माली

श्री चर्ग निह—प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रोय मरकार को लिख दिया है जि दुनाय जातियों को भी परिगणित जातियों में शामिल कर ले। जहां तक अपने मुहत्तमां जा सम्बन्ध है, हरिजन ओर शिक्षा दोनों विभागों को यह कह दिया गया है कि वह इनको परिगणिन जातियों में सम्बन्धित कर ले।

श्री इन्द्रिय त्रिपाठ!—-र्या परकार अस् इयना निवारण करने के लिये कोई कार्यवाही करना चाहती है

श्री चरण सिह—नावर्नभेट बहुत सी कार्यवाहिया इस सम्बन्ध में कर रही है जिससे इस हाउल के सारे सदस्य वाकिफ है।

श्री इन्द्रदेव त्रियाठो--न्या नरनार अस्पृत्य जानियों की नाबाद पे धीरे-धीरे कमी करना पसन्द करती है ?

श्री च र सासिन—नहा नर नवर्न नेट का नम्बन्य है उसकी ओर में जिसी मो अस्पृश्य या म्यून्य भानने का कोई प्रश्न नहीं उठना । लेकिन हिन्दू समाज की जो वक्ता है उसके देखने हुने उस वयन की गवर्न मेंड और मोजूदा नवर्न पेट ने भी इस तरह था। विभाजन किया है लेकिन आशा यह की जाती है कि बहुत जन्द यह सानाजिक कुरी ति निट जानगी।

श्रो इन्द्रदेव त्रिपाठी— क्या सरहार नरकारी काणजों की सूबी में अब तक परिगणिन जातियों जा नेंद रखती हैं ?

माननीय शिक्षा सिच्च (श्री सम्पूर्णानन्द)——जी हां, मजबूरी है। जो कान्स्टीट्यूशन दिल्ली में मंजूर किया गया है उसमें भी परिगणित जातियों को अलग रखना मंजूर किया गया है।

कमाला, धमाला, जिला नैनीतान में पशुर्यों को चौरा

"८—श्री खुशीराम (क) क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के भावरी इलाके के कमोला, धमोला ग्रामवासियों के मई महीने सन् १९४८ ई० में लगभग ५४ रास गाय, भैस लापता हुई थी, जिसकी ता० १६ मई सन् १९४८ ई० को एक रिपोर्ट प्रेम-राम वगैरह द्वारा थाना कालाढुंगी में दर्ज हुई?

(ख) यदि हां, तो कालाढुंगी थाना पुलिस ने इसमे किसी प्रकार की छान बीन

की? यदि की, तो उन रासों का कोई पता चला?

माननीय पुलिस सचिव--(क) श्री प्रेमराम वगैरह ने १६ मई, १९४९ को ४६ रास गाय, भैस लो जाने की रिपोर्ट कालाढुंगी थाने में लिखाई।

(ख) कालाढुंगी थाने में रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस ने जांच भी की परन्तु खोये

हुये पशुओ का पता नहीं चला।

श्री खुशी राम— क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जानवरो का पता न चलने से गरीब किसानो का कितना नुकसान हुआ है और सरकार इसकी फिर से जांच करने की कृपा करेगी?

माननीय पुलिस सचिव—जांच से तो यह पता लगा कि इतने दिनो बाद अब इनका पता चलाना मुक्किल है। लेकिन अगर माननीय सदस्य दो तीन मामलों में खुद मदद करें तो पता लग सकता है। एक तो यह कि लोग जानवरों पर निशान लगाने से मना करते हैं। अगर कोई निशान हो जाय तो उससे आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि अक्सर छोटे—छोटे बच्चों को चराने के लिये जानवर सौप दिये जाते हैं और जागवर उधर चले जाते हैं जिनका बाद में पता लगना बड़ा मुक्किल है। रङ्की डिवीजन में नहर गंग के शरकी रजवहां से सिंचाह

*९--श्री ग्रब्दुल हमीद (अनुपित्थित)--क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतायेगी कि रुड़की डिवीजन नहर गंग के रजबहा दारकी पर कितने कुलाबे हैं और हर एक कुलाबे का देहन कितना-कितना है और हर एक कुलाबे पर कितना-कितना रक्तबा आबपाती होती है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)--एड्की डिवीजन नहरु गंग के रजबहा शरकी पुर ११४ कुलाबे हैं। उनके देहन और आबपाशी की

फेहरिस्त †मेज पर रखी गई है।

*१०—श्री फ़ब्दुल हमीद (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि उस रजबहा के बहुत से कुलाबों पर ऐसी जमीनें ओसरे बन्दी में शामिल हैं जिनकी कभी आदपाशी नहीं हुई? माननीय सार्वजिनक निर्माण सिचय—ऐसे कोई भाग दारबन्दी में शामिल नहीं हैं

जिनमें आबपाशी नहीं होती है।

*११—श्री श्रब्धुल हमीद (धनुपिश्यत) — क्या यह ठीक है कि रजबहा के बहुत से कुलाबों का देहन सन् १९४७ ई० के बाद कम कर दिया है और ये उलाइ करनीचे से उपर लगा दिये गये हैं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सिचय—सन् १९४७ ई० में कुलाबों के देहन और जगहें नहीं बदली गई थीं। केवल ये कुलाबें जिनके मुहाने से अधिक या कम पानी बहता

था ऊपर या नीचे कर विये गये हैं जिससे कि उसमें से ठीक पानी बहे।

*१२- श्री ग्रव्दुल हमीद (ग्रनुःस्थित)--य्या यह ठीक है कि कस्वा मंगलीर के जिरे काइत रकबें से बो-दो और तीन तीन फसलों का महसूल आवपाशी एक साल में बसूल होता है और ज्यादातर रकवा बागात सब्जी व केले वगरह का है?

माननीय सार्वजनिक निर्माण अचिव-सिचाई का महसूल कानून के मुताबिक लगाया जाता है जो साल के अन्दर बोई जाने वाली मुख्तिलिफ फसली पर मुनहिसर होता है। यह ठीक है कि कस्बा मंगलीर में ज्यादातर आवपाशी बागात सब्जी और केले की है।

जिला विजनीर के पंचायती चुनाव में साम्प्रदायिक अनुपात
*१३—श्री बशीर ऋहमद अन्सारी (अनुपहिश्रत)—क्या सरकार यह बताने की कृषा
करेगी कि गांव पंचायत के चुनाव में जिला बिजनीर में हिन्दू मुस्लिम और अछूत की

कितनी सीटें मुकरेर थीं, और कितने-कितने चुने गये?

माननीय स्वशासन सिचय—(क) गांव पंचायतों के चुनाव में समाज को हिन्दू मुस्लिम अछूत वर्गों में विभाजित नहीं किया गया था घरन अल्पसंख्यक तथा परिगणित जाति के आधार पर सीटें सुरक्षित की गई थों। ऐसी परिस्थित में सुरक्षित स्थानों के लिये अल्पसंख्यक जातियों में हिन्दू और मुस्लिम बोनों ही सिम्मिलित हैं।

(ख) इस जिले में जो पंच चुने गंगे हैं उनमें परिगणित, मुस्लिम और अन्य जातियों के

व्यक्तियों की क्रमज्ञः संख्या ५६४७, ५७२६, ९८३३ है।

*१४—-श्री वशीर ग्रह्मद ग्रन्सारी (अनुपस्थित) — क्या सरकार मेहरवानी करके बतायेगी कि गांव पंचायत के चुनाव में जिला बिजनौर में प्रधान उप-प्रधान, मेम्बर, अदालती पंचायतों और सरपंच, अदालती पंचायत अलग-अलग कितने-कितने हिन्दू, मुस्लिम, अधूत चुने गये?

माननीय स्वशासन सन्त्रिय--

		परिगणित (अछ्त)	मुस्लिम	अन्य
(क)	प्रधान उप–प्रधान	₹ ५ ७६	११७ १३७	३७८ ३७८
(ग)	पंच अवालती- पंचायत फेहरिस्त छापी नहीं	३१३ गई।	485	P 3 F

(घ) अदालती पंचायत के नरपंचों की संस्थाप्य -पृथक अभी मालूम नहीं हो सकी है। ज्ञात होने पर सूचना दी जायगी।

* १५-१६-- भी अञ्चुल हमीद (अनुपत्थित)-- [स्थितित किये गये।]

यन्त संग्रह योजना के यन्तर्गत संग्रहीत गल्ले के भाव

*१७--श्री हर प्रसाद सिह (अनुपत्थित)--प्या मरकार हुपा अपके बनायेगी कि जितना गरला प्ररार की प्रोक्योरमेंट स्कीम हा ए मिला या जिलेगा उनकी जीवर नुकेरों का खर्ची लगा कर क्या होगी?

माननीय प्रत्न सचिव-

अनाज की कीमत और गल्ला वसूगी हे संबंधित ध्यय गला यमूली के लिये एखे गये कर्मवारियों पर क्य हुए हु ५,९१ ७६८ **६०** इ.च., १७,३१० **६०**

दोत (१,५८,६९,०५८ ६०

*१८--त्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित) -- इत गहले का नामग मूल्य ओपेन मारकेट में कितना होता?

ताननीय ग्रम सचित्र-- जुले बाजार में अनाज की कीमन अथवा दोरे इत्यादि की कीमन जामिल न करके ११,४९, २१३, ३२८ ६० ।

श्री भाजान दीन निश्र—क्या गर्वनेवेट यह वतकाने की छ्या कोर्स कि जो गल्ले के मूल्य तथा जो गल्ला वसूल करते पर खर्च पाना है वह दोनों जोड कर अगर बाजार भाव से गल्ला खरीदा जाना है तो किया अन्तर पड़ता है ?

साननीय गन्न सिन्न दिन्न विभिन्न न त्येष्ट्य में विभिन्न दरे प्रचलित थीं, इतिलये यह बताना मुक्तिल है कि अगर खुले दाजार से उस सन्द्र गन्दा खरीदा जाता तो सरकार को कितना और पैसा देना पड़ता।

श्री भगवान दीन भिश्र--त्र्या गवर्नपेंट को भारू गर्ह कि खुले बाजार ने वावल की की मन निरुचय करने पर चावल बहुत आसानी से सरकार को दराजर मिल मकता है?

माननीय सन्न न च र्—वावच के इकड्डा करने का और प्रोक्योर करने का तरीका रवो में जिस तरह से गल्ला वसूल करते हैं उससे भिन्न हैं। चावल चूंकि हलमें के यहां से लियां जाता है इसलिये वहां से रकट्डा करना अविधाजनक हैं और गल्लों के बारे में इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि खुले बाजार में उन हालतों में जिन हालतों में वह आये, खरीडने वे वह किम कीमत पर मिलेगा।

श्री अचल सिंह--क्या परकार बताने की कृता करेगी कि इस पूरे व्यवसाय में सरकार 'को नुकसान रहा या फायदा?

माननीय ग्रम मिचव--यह तो व्यवसाय नहीं है। यह तो एक मजबूरी है। रार्जानंग और कंट्रोल को मजबूरी अवस्था में जारी किया जाता है। जहां तक फायदे का सवाल है वह तो उठता ही नहीं क्योंकि जितनी कीमत पर गल्ला खरीदा जाता है उससे कम दाम पर उसका वितरण किया जाता है। इसलिये सरकार को तो उसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है।

थी अचल भिह--स्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नुकसान की तादाद क्या है?

माननीय ग्रन्न मिन्न --इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। वैसे मैं यह कह सकता हूं कि विभाग के उपर जितना खर्च होता हैं गवर्नमेट आफ इंडिया की सप्तिछी को लेकर वह १॥ करोड़ पिछले वर्ष में हुआ है। इस साल का आंकड़ा अभी कूता नहीं गया है इसलिये वह अभी बताया नहीं जा सकता।

श्री अगवान दीन मिश्र--क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि चावल की समुचित कीमत होने के कारण ही बाजार में धान उचित मात्रा में हल चुलाने वालों को मिलता है?

म (ननीय ग्रंत्र व्यक्ति व्यक्ति वावल बिना हलसं के जाये हुये तैयार हो नहीं किया जा सकता, इसिलये वावल तो आसानी से प्रोक्योर किया जा सकता है, परन्तु गेहूं तथा और दूसरे उससे सम्बन्धित अस इस प्रकार बाजार में नहीं मिल सकते। इसिलये यह नहीं कहा जा सकता कि जिस तरह वावल प्रोक्योर करने की हमें मुजिधा मिलती ह उसी तरह अन्यक अभों को भी इकट्ठा करने की मुविधा हमें मिल उकती है।

अन्त संयह योजना से प्रजा में अधन्तीय

*१९--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--बांदा जिले में कितने आदिमियों के नाम इस स्कीम के सम्बन्ध में वारन्ट जारी किये गये और उनमें से कितने कुछ दिनों हवालात में रक्खे गये?

माननीय ग्रन्न सचिव--गिरफ्तारी के ५५० वारन्ट जारी किये गये और १५६ आसी

जेल भेजें गये, लेकिन उसके बाद ही जमानत देने पर सब छोड़ दिये गये।

*२०—श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार की मालूम है कि बांबा जिले में बुछ लोग जिन्होंने अपने सेन्टरों में गल्ला न देकर दूसरे सेन्टरों पर गल्ला विषा पकड़े गये और हवालात में रखें गये और उस घक्त छोड़े गये जब उनसे दुवारा जनके सेन्टरों परगल्ला ले लिया गया ? अगर ऐसा हुआ है तो इन व्यक्तियों के क्या नाम है और किस है सियत से यह लोग हैं?

माननीय ग्रम सचिव-कीई भी काश्तकार जिसने नियत मात्रा में अनाज दे दिया ग

न तो गिरएतार किया गया और न उससे दुवारा अनाज लिया गया।

*२१—श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—वया सरकार के इत्म में यह आया है कि इस फुड प्रोक्योरमेंट स्कीम से प्रजा में असन्तीष हैं ?

माननीय यस सचित्र--जी हां, काश्तकारों के एक वर्ग ने गल्ला वसुलीकी योजन

पसन्द नहीं की।

बांदा के।तवाली में चे। पे की स्पेट

*२२--श्री हर प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--स्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले ६ मास में कितने चोरियों की रिपोर्ट बांदा कोतवाली में दर्ज हुई और उनमें से कितनी चोरियों का पता चला और कितने मुकबमे चले?

माननीय पुलिस सिचिय-अप्रैल से तितम्बर, १९४९ तक ५२ चोरियों की रिपोर्ट बांबा कोतवाली में वर्ज हुई जिनमें से ११ का पता चला और १० मुकदमें अवालत को

भेजें गये ।

बांदा के बास-पास जुए की अधिकृता

*२३—श्री हरप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि बांदा शहर में और उसके आस-पास ग्रामों में जुआ खूब खेला जाता है ? अगर ऐसा है, तो क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितने मुक्तदमे जुआ के पकड़े गये और कितनों को सजा हुई ?

माननीय पुलिस सच्चित्र-इस संबंध में पहले शिकायत थी, परन्तु इस ओर कड़ी कार्रवाई की गयी है और अब यह जुमें घट गया ह, गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा ३ और ४ इस जिले के

कई गावों में जारी कर दी गई है।

इस साल सितम्बर तक ११ जुए पकड़े गये जिनमें से ५ में सजायें हुई, १ अबालत से छूट गया और ५ मुक्तवमे अभी अवालत में हैं।

वांदा जोल में पक कैंदी की जहर से मृत्यु
*२४—श्री हरप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार की सूचना मिली है कि एक अन्वर
ट्रायल कैंदी की जो कई रोज से बांदा जेल में था जेल के अन्वर जहर दिया गया, जिसके कारण
वह मर गया ?

माननीय मादक कर स्चिव (श्री गिरधारी लाल)—अगर माननीय सवस्य का अर्थ बालेश्वर नामक विचाराधीन केंद्री से हैं तो सरकार को उसकी मृत्यु की सूचना मिली हैं। *२५--६र प्रसाट सिंह (अनुपस्थित)--यदि यह बात सच है, तो क्या सरकार इस विषय में जो भी जानकारी रखती है, उसे इस भवन के सामने कृपया रखेगी ?

माननीय मादक कर सिच्चय—बालेश्वर नामक विचाराधीन कैदी २८ नवम्बर, १९४८ ई० को मलेरिया ज्वर से पीड़ित होने के कारण जेल अस्पताल में भेज दिया गया, जहां उसका इलाज होता रहा । ६ दिसम्बर, १९४८ ई० को प्रातःकाल उसकी भृत्यु हो गई। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में सिविल सर्जन के मृत्यु का कारण ज्वर बताया। केमिकल इक्जामिनर की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उसके विससेरा में न धुलने वाला पारा निकला। संभव है कि पारे के कारण उसकी मृत्यु हुई हो। इस मामले में सरकार अभी और जांच कर रही है।

चुखीं, जिला जालौन।मं पंडित रामचरण के करल की भूठी खबर

*२६—श्री गज्राधरप्रसाद—क्या यह सही है कि गत जून सन् १९४९ ई० के दूसरे या तीतरें सप्ताह में जिला जालान के पुलिस कप्तान इस सूचना पर कि मौजा चुर्खी, जिला जालान में एक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता पं० राम चरण द्विवेदी का किन्हीं दिशेष व्यक्तियों द्वारा करल कर दिया गया है। जांच और गिरफ्तारी के लिए सिंकल इन्स्पेक्टर, पुलिस समेत मौजा चुर्खी में पहुंचे?

माननीय पुलिस सचिव--जो हां।

*२७—-श्री गजाधर प्रसाद—क्या यह सही है कि मौक़े पर जांच करने से यह सिद्ध हुआ कि उक्त पं० रामचरण द्विवेदी कई मास से तपेदिक के मरीज थे, और उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, और वे अपनी मौत मर गये। यदि हां, तो सरकार ऐसी झूठी सूचना देने वाले ध्यक्ति के विरद्ध क्या कार्यवाई कर रही है ?

माननीय पुल्लिस सिचव--जी हां, सूचना देने वाले सज्जन को बाद में पता चला कि उनकी जानकारी ठीक नहीं थी। उसके लिये उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया। कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

याजमगढ़ की जजी कचहरी में कमचारियों की तरक्की

*२८—श्री गजाधर प्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी की आजमगढ़ की जजी कचहरी में इस साल के अन्दर कितने लोगों को क्राब्लियत और अच्छी तालीम की बिना पर तरक्की दी गया है?

श्री चारण सिंह—केवल सन् १९४२ ईं० में श्री कमर अली बेग को मुन्तिफी अदालत की मुंसिरम की जगह पर विशेष तरक्क़ी दी गई थी। परन्तु जजी के कुछ कर्मचारियों के अपील करने पर प्रान्तीय सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से मशदिरा करके जिला न्यायाधीश की उस आजा को रह कर दिया था।

*२९—श्री गजि। प्रसाद्—क्या सरकार एक नक्ष्मा मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें तरक्की पाने वालों का नाम, योग्यता, नौकरी की मुद्दत, वेतन और उनका पूरा पता तथा तरक्की पाने का कारण लिखा हो ?

श्री चर्गा सिंह--प्रश्न नहीं उठता।

प्राप्त सुधार आर्गेनाइजरों का को बापरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत सुपरवाइजर बनाया जाना

*३०--श्री गजाधर प्रसाद--क्या यह सच है कि ग्राम सुधार के सभी आगेंनाइजर वर्तमान कोआपरेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत सुपरवाइजर बना कि€ गये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार यह बतलाने की कुपा करेगी कि उनकी सर्विस कब से शुमार की जायगी १ मान रिय पुलिय न्यांच्य — - जी नहीं, कुछ ग्राम सुधार के र्राफिल आगेंताइ जर जिन्होंने कि को आपरेटिय सुपरवाइ जरी की परीक्षा पास कर ल हैं, यू० घो० को आपरेटिय यूनिक के अंतर्गत सुपरवा जह नियुक्त कर लिये गये है।

उपरोक्त सिंकल अ। निद्वत्तर जिनकी नियुक्ति कोआपरेटिय सुपरवाहजरी के पर पर हो गई है उनकी सिंपस का शुरू दे शुमार करने का प्रका अभी विद्यासानीत है।

* ३१-श्री गजी पर प्रसाद्-- गा तरकार को यह माजूम है कि ग्राम सुधार से आये हुए आर्गेनाइजरों का, जो गोआवरेटिय विभाग में सुगरवानजर का काम कर रहे है, उपुटेशन मानतीय विकास सचित्र से क्लिंग था। यति जजा बहा में है, तो मानवीय गिचय ने क्या उत्तर उनको दिया था ?

मानवीय प्रतिस्मान्य । — जी हा । भने तनकी मांगा पर िधार करने का आखासन दिया था ।

२२--२२-- श ग जा बर पत्नाद--[स्यमित किये गये]।

क्षा प्रापरे टव विज्ञाग के मुपरवाइ गरां का चैतन

ं ३४--श्री गुजा वर प्रसाद--ाया सरकार यह भी ५ते जवनिक कोआपरेटिव विभाग के जनार्गन कार्न करते वाक सुप्रवास नरों के बेतन की धर बया है ?

सानवीय पुलिम्ब सास्त्रव—संयुक्त पान्तीय कीशारिटि। यूनि न के संवर्धन कार्यकर्ते वार्वे स्वर्थन के वेतन की दर निमालिक्षित है—

१—हाई महूत परीक्षा पास सुपराइजरों का वेतन ४८- ८-४-८० र०। २—अन्य पुषरशाइजरों का वेतन ४०-२-६०-४-८० र०। कंडर के १९ पतितत पुषरशाइजरों के जिरे ७५-५-१६० र० स्कृत नियत।

गोंडा जिला के अदिश थाना इतियाठोंक में जुमी का प्रियकता

'३५-'त्री 'तानितिहारी ट्रण्डन--क्या यह राज है कि जिला गांत के इध्याठीक थाने में, जो कि ''आदर्श थाना'' है, पहले के मुकाबिले में अब जुमें जबदा होने लगे हा ? पदि हा, तो क्यों ?

ा। ननो प्र पुल्लिम साचा 1—नी हां, उस थाने में दर्ज हुवे जुर्मों को संख्या बढ़ने का एक विशेष कारण बड़ भी है कि पहले ताजीरात हिद के दका ४५७. ३७९ जोर ४५२ के कई मामले थाने में दर्ज नहीं होते थे। उनमें कुछ की रिपार्ट लिखाई हो नहीं जाती थी या मामूली जाव कर के भाप का खता कर दिया जाता था। और कुछ जुर्म को हलका दिखला कर जनुसंघेय अपराध प्रका किया जाता था। आदर्श थाने में कोई रिपोर्ट दयाने की कोशिश नहीं की जाती।

भीरे-भीरे जनता का विश्वास तथा सहयोग प्राप्त हो रहा है और आशा है अब परिणाम, अच्छा होगा।

श्रो ळाळ बिहारी टण्डन -- मा सरकार कुषा करके बतायेगी कि इस याने को आदर्श याना बनाने से सरकार का क्या उद्देश्य है ?

माननीय पुलिस सिचान—नो उद्देश और जगत् होता है वही उद्देश यहां भी है।
श्री लालिबिहारी द्रण्डन—गरकार ने यह उत्तर दिया है कि जो उद्देश आदर्श याते
का होना है उसका उद्देश्य भी वही है इसलिये में पूलना चाहता है कि यह उद्देश क्या है ?

माननीय पुलिम सचिव — उद्देश्य की पूर्ति हर जगह, हर थाने में एक सी है कि पुलिस के लों। अपना कार्र ईनान्दारों से, सच्चाई से और मुस्तेदी से करें तथा जनता ओर सार्वजनिक कार्य कर्ताओं से यह आशा की जाती हैं कि वे पुलिस की मयद करें और साथ ही ऐसे गलत कामों को रोक्षने में लंगित हम से काम करें।

श्री बरुरेव प्रसाद—क्या जुर्म बढ़ने की एक वजह यह भी है कि थाने में आने वाले मुजरिमों का स्वागत पान, बीड़ी से किया जाता है ?

माननीय पुलिस सचिव—पान, बीड़ी तो ऐसी चीज है कि हर आदमी इस्तेमाल करता है चाहे वह मुजरिम हो या न हो। मुजरिमों के लिये तो माननीय मेम्बरों की सलाह से जेलखानों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ और हर चीज के इंतजाम होते हैं। लेकिन में नहीं समझता कि थानों में पान, बीड़ी मुजरिमों के लिये ही खासतौर पर रखी जाती है। शायद और लोगों को जो वहां रिपोर्ट लिखाने आते हैं, उनको दी जाती हो।

श्री खुशवक्त राय—क्या सरकार यह बतलाने की छूपा करेगी कि इन आइर्ज में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको आदर्श बनाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया है ?

माननीय पुलिस सचिव—को शिवा यह की जाती है कि अच्छे और ईशानदार आदमी चुनकर वहां रखे जायं, लेकिन आदमी ईमानदार बनाना न हमारे अस्तयार में है और न इस हाउस के।

*३६—श्री लाल विहारी टन्डन—क्या सरकार उपरोक्त थाने के 'आदर्श थाना'' होने के वो साल पहले के जुर्नों की तथा आदर्श होने से अब तक के जुर्नों की संख्या बतलाने की क्रुपा करेगी ?

स्तिनोध पुडिस सचिव--सूचना इत प्रकार है:---

१९४७ १९४८ १९४९ जनवरी से आदर्श थाना फरवरी तक होने पर सार्च से सितम्बर तक

अपराध संख्या

११५ ११३

२४

१३४

गोंडा- तखनऊ मार्ग में सरजू तथा घाघरा पर पुछों की गावश्यकता *३७--श्री लाल विहारी टन्डत--क्या सरकार को जात है कि गोंडा से लखनऊ

आने वाली सड़क पर सरजू तथा घाघरा निदयां पड़ती है ? माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव के सभामंत्री(श्री छताफत हुसैन)—जी हां।

माननाय सावजानक निर्माण साचव के सभामत्रा(श्रा छतीकत हुसन)—जो हा।
*३८—श्री छाछ बिहारी टण्डन—क्या यह सच है उपरोक्त दोनों नदियों पर पुल नहीं है ?
और उनको पार करने के लिए खास परिमट लेकर रेलवे के पुल पर से मोटर आदि पार होते हैं ?

श्री छताफत हुसैन—जी हां। श्री भगवान दोन—क्या सरकार यह बतलाने की कृषा करेगी कि इस समय जो अधि— कारी परिवट देते हैं उनका हेड आफिस कहां पर है और यह कौन लोग हैं ?

श्री लताफत हुसैन—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बाराबंकी और चीफ इंजीनियर। डिस्ट्रिक्ट भैजिस्ट्रेट का हेड आफिस बाराबंकी में है और चीफ इंजीनियर का हेड आफिस यहां लखनऊ में है।

*३९-- ओ लाल बिहारी टएडत--क्या यह सच है कि इन दोनों निवयों पर पुल बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही हैं ? यदि उत्तर 'हां' में है, तो कब तक पुल बन जाने की सम्भावना है ?

श्री लताकत हुसैन--जी हों, तरकार उन निदयों पर नाव के पुल बनवा रही है। काम जारी है और आशा है कि एक आध साल में पुल तैयार हो जायंगे।

श्री भगवान दीन मिश्र—क्या सरकार को यह मालूम है कि इस पुल का, जो वाघरा पर बनने वाला है, बहराइच और गोंडा दोनों जिलों से विशेष संबंध है ? माननीय स वंजानकांनर्माण शंचत्र-जो हा, है।

*४०--श्री छ। ल विद्वारी टगडन--या सरकार को ज्ञात है कि उक्त दोनों निद्यो को मोटर द्वारा पार करने के लिए जिन अधिकारियों को पुछ पार करने के लिए परिमट देने का अधिकार है उनमें डिप्टी कमिस्तर गोंडा नहीं हैं ? यदि हा, तो क्यों ?

श्री लताफत इसेन--जी हां, चूं ि पुत्र रेलवे का है इस तजह से रेलवे कर्मचारियों को लिख गरा या कि डिटो किनइनर गोंडा को भो उन अि कारियों में शामिल कर लिया जावे जो कु पार करने के लिए परिमट दिया करते हैं। पर उन लोगों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

श्री ला ठ विदारी टगडा -- न्या सरकार पह छवा करके चतलायेगी कि डिप्टी कमिलर, गोंड। को रेको अभिकारियों ने परिनिष्ट देवे का अधिकार किन कारणों से नही दिया ?

श्री लन। फन तुसे र--प रतो उन्हें अधेरायार ही बान है हि उन्होंने इसको मंदूर नहीं किया।

श्री ता। ना तुसीन -- रेका हे ।।। । गुरार गिनिक नक गरान उन पुलों को खास वार जानों राइ जी एक कर पती है।। यो राहुर, गुजोगों हे कि रुन ही है।

*४२—-श्री ठान निरंगे टण्डा--ग्रागरतार हुग हरके नायेगी कि बहु उस कड़िनाई को तुर हरने हे लिए ग्राग्यान मोन रही हुं?

श्री लातापत्त गुसेन--आनरेबुल गेम्बर माध्यान ३९ वे समाल के जवाब की तरफ विकाया जाता है। जब नाव के पुरुषा अधिगे एक उसकी कठिनाइमां दूर हो जावेंगी।

गेंडा जिला में इंटियाटे। क - घरगपुर गनक की खराव हालत

*४३—-श्री लाल विहारी रण्डन—। मा तरकार को बात है कि गोंडा जिले में इटिया-ठोक से खरगपुर जाने वाली सड़क की हालन खराब है ?

श्री लताफत हुसेन-जी हां।

श्रो ला त्य निहारी रण इत-- क्या पर हार बहु यत अति ही कृया करेगी हि जब सब्द की हालत खरान है तो जिल्हों की दूसरी सड़कों की तरह इत सहक की भी सर हार अपने कब्जे में क्यों नहीं ले लेती ?

भानतीय सार्वजिनिक निर्माण अन्तिय-- गरकार हर सड़क स्रो की अपने कच्चे में है

*४४--श्री लाल विहारी टण्डन--उपरोगन तर्क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में हैं या मार्जजनिक निर्माण विभाग के ?

श्री तताफन दुरीन-धह राड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में हैं।

*४५-श्री लात्न श्रिहारी टमडन-यिव यह सरकारी सम्क है, तो इसके कब तक ठीक हो जाने की उम्मीद हैं?

श्री लताफत हुसैन-पह सवाल पैवा ही नहीं होता।

संयुक्त प्रान्त में जनवरी, १९४८ ई० वंन जुनाई, ११४६ ई० तक कृत्त के मामते

*४६—श्री भारत सिंह याद्वाचार्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९४८ ई० से जुलाई सन् १९४९ ई० तक यू० पी० में कितने क्रत्ल हुए, कितते मुकह्ने, चलाये गये, जनमें से कितने छूटे और कितने सजायाब हुए ?

पाननीय पुल्लिस सचिव--सूचना इप प्रकार है --जनवरी, १९४८ से जुलाई, १९४९ तक --

****	२,६५६
****	१,६२०
••••	८३ ७
****	252
	••••

शेष ने अभी फैसला नहीं हुआ।

संयुक्त पान्त में गुन्छा वसूकी के संबंध में अलाई

*४७--त्री भारत व्यादवाचार्य--द्या तरकार यह वनाने की छना हरेगी कि शहना वनू की के संबंध में यू० पी० में कितनो जाह झनड़ा हुआ और कितने मुकड़ने चलाने गये?

नानर्गय ऋक्त सिच्च-चदायूं--दो जगहों में गल्ले की दसूली का विरोध करने के लिए हिंसा से जाम लिया गया। एक मामले का पुलिस चालान कर चुकी है और दूसरे मामले में तहकीक र की जा रही है।

मुरादाणाद—चार जगहों मे गुल्ले की वसूली का विरोध करने के लिए हिंगा से काम लिया गरा। विरोध करने दालों के विकार एक मुकदना पारा ३३२ के अधीन और तीन मुकदमें धारा ३५३ के अधीन चलाए गए हैं।

मैं रापुरी—-एक गांव में लोगों ने सल्ला वसूल करने वाली डोली पर हमला किया। एक मुकदमा चलाया गया है।

राजबरेली—एक गांव में काश्तकारों ने हिंगा से काम लिया और गल्ला वसूल करने वाली टोली पर हमला किया। एक मुक़दमा चलाया गया है।

संयुक्त प्रान्त में डेरियों की सरकारी सहायता

*४८--श्री भारत सिंह याद्व।चार्य--न्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सूबे में किननी सरकारी डेरियां हैं और कितनी ऐसी डेरियां है जिन्हें सरकार सहायता देती है ?

माननीय कृषि सचित्र (निसार ग्रहमद रोरवानी)--१४ सरकारी डेरियां और १२ प्राह्वेट डेरियां हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है।

*४९--श्री भारत सिंह यादवाचार्य--न्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वह डेरियों को किस नियम या आधार पर सहायता देती है ?

माननीय कृषि सचिव — वे शतें जिन पर प्राइवेट डेरियों को राजसहायता या कर्ज के रूप में ख्या दिया जाता है नत्थी की हुई सूचियों में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०९ पर)

जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत विभिन्न जातियां

*५०-भी भारत सिंह याद्वाचार्य-न्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० के किन किन जिलों की कौन कौन जातियों पर जरायम पेशा क़ानून लगाया जा रहा है ?

श्री चरण मिह--जरायम पेशा जातियों की जिलेवार सूची किमिनल ट्राइब्स ऐक्ट मैनुअल वाल्यूम टू (किमिनल ट्राइब्स ऐक्ट मैनुवल भाग २) में दी हुई है और इस समय सरकार किसी भी जाति को 'जरायम पेशा जाति' घोषित करने का विचार नहीं कर रही है।

*५१--५४-श्री रोज्ञान जमां खां--[स्थगित किये गये]।

माननीय पुलिसा साचित-नो हा ।

*९२--श्री के लिन चरण टन्डस--पिट हां, तो किन किन के कोन कोन विषयार किन किन वजूहात से पाणिस किये गये ?

भाननो । पुलिम्न मांचा -- जिनको हिशियार वापस किये गर्थे उनको स्वो पाथ नत्थी है। अधिकारो इतमे सनुष्ट ये जि उन्हें तथियार गापस वे देना वातिये ।

(देखिये नत्थी 'घ' अभी पृष्ठ ६१२ पर)

श्री कालीचरण रन्डन -- (या शरकार की पता है कि जिनके लाइसेन्स वापिस हुए है उनके नाभ किर कई जिकारते आई है कि जह सम्प्रदायिक वातों में किर हिस्सा ले रहे है ?

मानतीय पाळस साना :-- -मानतीय सदस्य ने एक साह्य के बारे में बतलाया था, उसपर जांच की गई तो कि पक्ष क्या है कि अब उनकी तरक से ऐसी कोई कार्यवाही जहीं हो रही है।

ै९३—-श्रो मालीन्त्ररण टन्डन—-(क) वपा यत् गती है कि सरकार ने हिययार वापिस देने में पहुंचे पाके सादिकों से माम्त्र सिक ननातनी फैजाने सबयी अपने रवैये को बन्द करने का शिवत भाषतायन के लिया है ?

- (व) परि हां, तो पत्रा सरकार उसकी प्रतिलिपिया मेज पर रक्खेगी?
 - (ग)यदि नहीं, ती उसाम त्या कारण है ?

गाननीय पुलिस मांच्य--(ग) जो नहीं।

- (ख) पह प्रश्न नहीं उठता।
- (ग) इसकी आवश्यकला नहीं समझो गई।

क खानाद जित्र में १९४२ ई० म १९०५ ई० तक साम्बिक जुर्माना

*९४--श्री कालीचरण टन्डन--एया सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि फ़र्रखाबाद जिले में सन् १९४२ ई में पन् १९४५ ई० तक किन किन गांवों में, किननी किननी रक्रम, मामूहिक जर्भाने की शक्ल में जनता से गयुल हुई ?

मा भनीय पुलिस माचिय-साग्हिक अमाने के रूपमें निम्नलिशित रक्तमें फर्रेलाबाद

जिते के प्रत्यक गांच से बसूल हुई :---

			रु०
१—तिरवा ओर तिरवागंज			४,०८५
२——संज्ञाला			2,000
३मकरन्दपुर	•	•	३००
४ बरझारू ।	•	4.4	१,५००
५धनसुआ	•	•	५००
६जसपुरापुर नरदथा			400
७विपरागांव		•	8,000
८किसवापुर	•	•	400
९बीबीपुर पु० स्टे० सोरिगा	•		३००
१०बीनापुर			२००
११उघनापुर तहसील छियरामऊ	• •		१७५
१२ंबहादुरपुर			२००
१३दूनाबाडी	•		800
		ingrisign province, pl	

योग .. १०,६६०

*९५--श्री कालीचरण रन्डन--सामू हिंक जुर्गा की रक न में ने कितनी कितनी रकम किन-किन गांवों में, किन-किन कामों में वर्ष करने के लिए कि किन के गारफन दो गयी या देने के लिए मंजूर की गयी ?

जाननीय पुनिन्न स्वित--इ रकम े मे ९,१६० कर फिन फिन र वो से यह रकम वसूल की गई थी दहां के वर्तमान कुत्रों की मररमत तथा उन्हें पन्ना करने अ न हैन्ड पाड कर या परिशयन वहील लगवाने के लिए या नए कुएं खुदवाने के लिए सरकार ने म्लून किए ओर रह रकम डिस्ट्रिवट डेवलरमेट एमोनियेशन (जिला विकास मंघ) के अधिकार में रब्बी गई है, केए १,५०० रुपए बरझाला गांव के जिन लोगों ने जुर्माना वसूल किया गणा था, उनके डन्छ नुमान उन्हें लौटा दिये गये।

श्री कालाचरण टन्डन—न्या सरकार को यह पता है कि पहले सरकार ने यह नीति घेषित की यो कि जो नानू हिक जुर्माने बल्ल होंगे नह जिला बोर्ड की सिफारिश पर बहां के नणरिको की इच्छानुनार अर्च किए जांयगे ?

मानने। पुतिन अचित्र -- यह बात ठीक है।

श्री का ती वरिष टन्डा--न्य त्या जिना एडवाइजरी कमेटी की निफारिशे इस मिलमिले में सरकार के पास पहुंची ?

मानतो ' मिलाम मि बान-इन तनम में इनके बारे में जनाव नहीं दे तकना। लेकिन माधारण नीति यह रही है कि गांव या जहां पर जुर्माना होना है वहा के लोगों की राय भी मानी जाती ह ओर इस जवाब ने बताया गणा है कि जिन गांव ने यह बाहा कि वहा बर एक को अलग अलग दे दिया जाय, उन्हें अलग-अलग दिया गया है। बाकी जगहों में नुओं वगैरह के लिये रुपया खब हुआ।

श्री कालाच स रन्डन--क्या परकार को यह पना है कि डिस्ट्क्ट एडवाडकरी कमेटी फ़र्रुखाबाद ने इन गांबों के लोगों को इच्छा के अनुसार अलग जलग गांबों के लिये अलग-अलग इमारतों ओर दूसरे सार्वजिनक कामों के लिये सिफारिशें की थीं ?

त' ना पुरेत ने बान-हा गार्य में, अगर माननीय तदस्य चाहेंगे. तो कि में काग्रजात देख कर जवाब दिया जा सकता है।

९६--प्रो हत्लो चरण टन्डन--कुछ किननी रकम अनी बाको है और किस कारण से वह रक्तमें खर्च करने से बच रही है ?

पाननीय पुतिन सचित्र--गरकार के पात इम सद में से अब कुछ भी दाकी नहीं है।

फ्रहेबाबाद ज़िले में सन् १६७०--४२ ई० तक सामृिक चन्द।

*১৩--श्रो कालो चरण टंडन--क्या सरकार यह उतलाने की कृपा ५ रेगी कि--

- (क) फ़र्हलाबाद जिले में सन् १९४० ई० में पन् १९४२ ई० तक सामूहिक चन्दे की जुल कितनी रकम जमा हुई थी ?
- (ख) इसमें से कितनी रक्तम किन-किन कामों में कितनी-कितनी तादाद में किम किम के मार्फत खर्व की गयी या खर्च करने के लिए मंजूर की गयी ?
 - (ग) कुल कितनी रक्तम अभी बाकी है ?

(ध्र क्या बक्षाया रकम को व्यय करने के लिए पुनः जिला एडवाइजरी कमेटी से सिफारिशे मांगी है ? यदि हां, तो कितना समय दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों, और अब उस बन को किस तरह किस की सिफारिश पर खर्च करना मंजूर किया जावेगा ?

माननीय मात सचिव--(क) सामूहिक चंदा वसूल करने की अज्ञा १०४३ ई० में जारी की गई थी। इस योजना के अधीन कुल १,०५,८५० ६० १२ आना ९ पार्ट जगा हुआ। (ख) नीचे दी हुई रकमें उन विशेष कामों के लिये मंजूर की गई हैं जो हर एक के सामने लिखे हुये हैं।

ऋम- संख्या		रक्षम		करम	कैंफियत
	रु०	आ०	पा०		
8	५,०००	٥.	o	तिरवा में ब्लाइंड रिलीफ फंड कैम्प का खर्च पूरा करने के लिये	जिला मैजिस्ट्रेट फर्रखाबाद हे सिपुर्व की जाय।
Mana.	२,४५७	23	ō	सिंगीरामपुर सड़क को पक्का करने के लिय	यह रक्षम जिला बोर्ड, फरंखाका को इस शर्त पर दी जाय कि वह सड़क बनवाने के लिये और जितन रुपय की जरूरत होगी उसे देगा और सड़क के संबंध में बार—बार होन वाले खर्चें को पूरा करने की व्यवस्था करेगा।
3	२,५००	0	o	बी० ए० बी० एम० स्कूल, शमशाबाद की इमारत बनवाने के लिये	यह रक्षम वी० ए० वी० एम० खूब, शमशाबाद की मनेजिंग कमेटी की इमारत पूरी करवान और फर्नीचर खरीदने के लिये दी जाय।
8	3,000	0	o	छिवरामऊ में जिस हाई स्कूल के बनाये जाने की तज्जवीजे की गई ह उसके लिये चंदा	यह रक्तम छिबरामऊ के मौजूब मिडिल स्कूल की रजिस्ट मैनेजिंग कमेटी को दी जाय।
•	१,०००	0	o	एस० डी० गर्ल्स स्कूल, कन्नौज, में एक ब्लाक बनयाने के लिये	यह रक्तम एस० डी० स्कूल, कन्नौत की रजिस्टर्ड मर्नीजंग कमेटी को दी जाय ।
***	५,०००	ō	ō	छिबरामऊ के मौजूदा डिस्ट्रि— कट बोर्ड जनरले अस्पताल (हास्पिटल) से मिला हुआ एक महिला (वीमेंस) वार्ड बनवाने के लिये	यह रक्तम इस शर्त पर खर्च की ज सकेगी कि जिस वार्ड को बनान की तज्जबीज हैं उस पर बार बार होने वाले खर्च को पूर करने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर आवश्यक व्यवस्था कर है।

⁽ग) ८६,४९२ र० १५ आना ९ पाई की रक्तम अभी बाकी है और अक्टूबर, १९४९ ई॰ के आखीर तक कुल ब्याज १८,९११ रु० १५ आना होता है।

- ्य) नीचे लिखी हुई योजनाओं के संबंध में ४५,००० रु० के अनुदान मंजूर किये जाने के जिसे न्यानीय डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जो तजयीजे हैं उन पर अभी सरकार विचार कर रही है।
 - (क) बीव दीव बोव अस्पताल, फर्रुखाबाद के लिये २५,००० रूव ।
 - (ख) जी उडी विनिह्ला अस्पताल (फीमेल हास्पिटल), कन्नौज के लिये २०,००० ६० ६०८०४ ६० १४ आना ९ पाई की बाकी रकम को खद्य करन के लिय अभी तक कोई तजवीजें नहीं आई हैं। मरकार की नीति आम तौर पर यह ह कि वह स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कमेटियों की नफारिको मान लेनी हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के लिये कि फोरेको भजने की कोई अवधि नियत नहीं हैं।

कानपुर में गल्ल; गोदान का उद्घाटन

ें.८-श्री पाखरु न्स्लाम--व्या तरकार कृपा करके बतादेगी कि वानधुर में ग्रहण इक्ट्या (योन स्टोरेप) करने के लिये कोई गोताम बनाना मंजूर कि गात है ? माननीर यस सचिय--जी हां।

४९९-श्री फछर इम्ल(म-न्या सरकार कृपा करने बता वेर्ग कि उम इम: रह का तखमोन: कब बनवाबा गया था और बह कि रो रुपए का था?

मानतीय अन्न लिय--तरकारी गोदाग जानपुर के निर्माण का हिमान दिछले मई में निन्चित किया गया था। यह ७,७५,००० ६० का था।

*१००--श्रा खण्ड इन्लास--क्या यह नहीं है जिड गहनारत के बनवाने में तत्वमाने से ६ लाख उनमा अधि । वर्ष हुना ? जिब ऐसा हुआ, तो नवों ?

माननीय रात्र सचित--नहाँ, यह तही तही है। जरन का द्वितीय शंक नहीं उठता। श्री फल रात इ जान--क्या गवर्नमेन्ट बनायेगी कि तखनीने से शितना रुपया ज्यादा खर्च हुआ ?

মানবাৰ স্থান ভিত্ৰ অনুন্দু সকলে কিই तो नोटिश चाहिये। मेरे पाम इस वस्त इसिला नहीं है।

श्री प**खर**ल इम्ल म--न्या यह नहीं है कि यह गोदान १५ लाख रूपये के अन्दर तयार हुआ

माननाय श्रम लियन-नहीं, यह तात तो सही नहीं है। जहां तक मुझे इत्तिला है. इतना रुपया नहीं लगा।

*१०१--श्री प्रखरत इम्लाम--वया ता० १० जलाई सन् १९४९ ई० को माननीय अन्न निवन ने कानपुर में इस गोदाग का उब्घाटन निया और इसमें असेम्बर्ल, के बहुत से सबस्य शरीक हुए?

माननीय ग्रन्न सचिव-जी हां।

*१०२--श्री फावरुल इह्लाम--क्या यह सब है कि शाम को दो हजार आदिमियों को ऐट होन दिया गया?

माननीय ग्रन्त सचिव--लगभग दो हजार व्यक्तियों को सोडा (कोल्ड डिंक) पान कराया गया।

'१०३—अो फलरु इस्लास—क्या सरकार कृया करके बतायेगी कि इस सिलसिले में किनना रुपया जर्ब हुआ और यह रुपया सरकार के किस मद से खर्च किया गया ?

मानतीय ग्रन्त मित्रत्य-व्यक्तियों को सोडा (कोल्ड ड्रिक)पान कराने में सरकार ने कुछ वर्ष नहीं किया।

*१०४-- श्री फलार न इस्नाम--क्या यह सही है कि इस खर्वे की पूर्ति के लिये दान राजींना अ.इ.सर, कानपूर ने अपने अश्रोतस्य कर्नचारियों से चन्दा लिया ?

माननीय अत्र नचित्र--अतिथियों को सोडा (कोल्ड डिंक) पान कराने के लिये राज्ञीनग कर्मवारियों ने स्वेच्छानसार चन्दा दिया।

श्री फल हल इहलाम--नया गवर्न मेंट मेहरवानी करके बतलायेगी कि इस ऐट होम के लिये जो कि राशनिंग के स्टाफ ने चन्दा जमा किया था उससे के हजार रुपया वसुल किया गया |

माननीय बन्न मिवन-जो इतिला आई है उसमें आंकड़े भेरे पास नहीं आएहे लेकिन उत्तर्ने हतारों का समाल तो उठ नहीं सकता क्योंकि उसमें केवल सोडा बारर विलाया गया और इतर्ने हतारों रुपयों का खर्चा नहीं हो सकता।

श्री प्रवारत इस्ताम--क्या यह सही है कि वहां दो हजार आदमी थे और एक बहुत बड़ा शाति माना, कुनी, मेज, पान और लिगरेट का इंतजास किया गया था और लारी ल बाऊ में इतो डिगार्डनेण्ड के जरिये आई थी जो लोगों को वहां पर मुफ्त ले जा रही यो ?

माननीय प्रन्त सचि ब--जहां तक शामियाने की बात है वह बेबुनियादी है क्योंकि में भी वहां गया था और यह जो कुछ किया गया था वह वहां की इमारत में यानी गोताम में जो अभी बना है कोल्ड डिंक का प्रबन्ध किया गया था।

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा

मानतीय कीकर--वानतीय सवस्यों को याद होगा कि प्रांतीय हज कमेटी के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कल तीन जजे तक का समय नामांकिन पत्र आने के लिये मेंने नियत किया था। फल तीन बजी तक तीन नामांकन पत्र आये?

- (१) श्री मुहम्मव नबी,
- (२) श्री हसरत महानी,
- (३) श्री मुहम्मद जाहिद फाखरी।

इसके बाद श्री फाखरी साहब ने अपना नाम वापिस ले लिया है। इसलिये अब एक जगह के लिये वो नाम है। आज नाम वापसी के लिये एक बजे तक का बक्त है। अगर नाम वाधित नहीं हुए तो कल २ बजे से ४ बजे तक वाचनालय (रीडिंग रूम)में चनाव होगा।

> सन् १९४२ ई० का संग्रका प्राम्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी)

मानवीय स्वीकर--वानवीय माल सचिय के इस प्रस्ताय पर कि सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रांतीय जनीं शरी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि संयुक्त विशिष्ट समिति द्वारा संगोधित दुआ है विचार किया जाये, विवाद जारी होगा। कल श्री सुल्तान आलन को भावग दे रहे थे। वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री सुद्रान गातम वा--जनाव स्पीकर साहब, कल शाम को जब इस भवन की बैठक खत्म हुई तो में वका १२४ के उसूल के मताल्लिक कछ अर्ज कर रहा था। जैता मने कल भी कहा था कि उमूल मानने के बाद तफ़सीलात से फिरना कुछ अच्छा नहीं मालून होता। हनने एक उत्तल माना है कि जो अन्रएकनामिक होत्दिण ह उनके इंटरनीडियरीज की अगर उनके पास ८ एकड़ से कम आराजी है तो सब

^{*}९ जनवरी सन् १९५० ई० की कार्यवाही में छपा है।

^{ां} माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

लैट आराजी में से बेदलल करके ८ एकड़ उनके पान पहुंचाने की जरूरत लेकिन ऐसा मालून नहीं होता क्योंकि इसके बाद एक सब-सेक्शन मौजूद है, जिसके जरिये से जो एक हाथ से दिया जाता है दूसरे हाथ से उसे वापिस ने लिया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि वर्गर नोटिफिकेंगन के यह चाज नहीं हो नकती। जहां सरकार नोटिफिके-शन करेगी वहां ऐसा हो सकेगा ? जब यह सरकार इस उसूत्र को यानर्ता है तो मेरे ख्याल में एक गहत भी ऐता न रहना चाहिए जो इस कंसे गर्न (रियायन) की हासिल करने का मुस्तहक है, उसे यह न जिल नके। इसमे एक कमी और रह जानी है। वह यह कि जितनी होस्डिंग्ज है वह सब ८ एकड़ को निलाकर होंगी यानी एए हम उसे १ युनिट मानते है तो आइन्दा होल्डिंग्ज में हर होल्डर इस बात का नक रख नकेगा कि वह अपनी काश्त को ८ ए कड़ बना नके। इसके मुताल्लिक कुछ कहने की आवन्यकता नहीं। में यह इतिलं कह रहा हूं कि जमींदारों की जमींदारी खत्म करने के बाद, हकीक़न में जिसे खत्न करने की जरूरत भी है, जो अब एक लायविलिटी हो गई है, उसे बँकवर्ड क्लास होते से बचाया जा तके। वजुज इसके कि जह इंटेनेक्चुअल क्लास हो, बैकवार्ड क्लास में होते से उसे रोका जाए। जब इस निद्धान्त को हपते नाना है तो कोई वजह नहीं मालूब होती कि १२४ क्लाजुको रखा जाए। अगर हमे देना है तो खुले दिल से दें, अगर नहीं नानते तो बेहनर यही होगा कि उका १२४ को कतअन उड़ा वें।

अब मैं बका १३५ के मुनाल्छिक अर्ज करूँगा। वह उसूछी और बुनियादी हैसियत से करूंगा। में उत्तकी तकनीलात में जाना नहीं चाहना और न इप वस्त उसका मौका ही है। दफा १३५ के मातहन हुरूमत ने एक और नई दफ़ा बनाई है और वह यह है कि जो इस वक्त एक्कीनियन आफ प्रिंदिलेजेज ऐक्ट है और जिनके मुनान्लिक जमीं-दारी एबालीशन फंड इकड्ठा किया जा रहा है, इसके नातहन उस ऐक्ट ने तरमीपत की जाये और एक नया शेंड्यूल (सूची) कायन किया है। मैं कानून की इस बाजीगीरी की समझने से क़ासिर हूं। सरकार के पास तो खुला रास्ता है कि वह अगर कोई तरमीम एक्बीजिशन आफ प्रिविलेनेज ऐक्ट में करना चहिती है तो उसे एक बिल की सूरत में यहां लाए और अगर असेम्बली का सेगन नहीं हो रहा है तो एक आर्डिनेन्स के जिर्य तरमीम हो सकती है और जब हाउस दोबारा मिले तो उसे विल की सूरत में लाकर ऐक्ट में कारवोरेट किया जा सकता है। लेकिन यह तो एक फनी बात है और न ऐसा कभी किसी लेजिस्लेवर में ही हुआ है जिन तरह से यह हमारे यहां पेश किया जा रहा है । इस तरह की चीज लेजिस्लेचर की प्रेस्टिज (मर्यादा) को नीचे गिरा देती है औरएक चूरहो च है निवके नातहन सरकार यह कर सकेगी कि सरकार एक कानून बनाएगी और दूसरे में तरमीय कर देगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बनेगा और म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट ने तरबीन कर देगी। कौने सी चीज ऐसी है जिससे सरकार बराहरास्त एक्वी-जिञ्जन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट को खुद तैरार नहीं कर सकती चाहे जिल के जरिये से या आडिनेत्स की सूरत में?

अब मैं बक्क के मुताहिलक अर्ज करूंगा। वक्फ ऐसी चीज है जो मजहबी है गियत रखती है। हम फख़ करते हैं और हमें खुशी है कि जिस हुक्मत में हम रह रहे हैं वह एक गैर मजहबी हकूमत हैं और उस हुक्मत में जहां तक श्रजहब का नाल्लुक हैं किसी गहस में कोई फर्क नहीं माना गया है।

े लेकिन मुझे, वक्फ के मुताल्लिक जो प्राविजन्स रखे गए हे उनको देखकर थोड़ी हैरत होती है। में समझता हूं कि या तो अदमवाकियत के ऊपर मबनी है या कोई गलती से ऐसी बात रखी गई है, जिस पर नजर नहीं की गई है। लेकिन अगर इन दोनों बातों में से कोई वीज हैं तो गवर्नमेण्ट की प्रेस्टिज इससे बहुत बढ़ जाती है। अगर वह इसको रियलाइज (महसूस) कंरे और बजाय इसके कि फाल्स प्रेस्टिज (झूठी मर्यादा) का मोजन (विचार) आए उसकी इन्जत और ज्यादा बढ़ जाती है अगर वह किसी मौके पर अपनी [श्री सुल्तान आउम पा]

गलतो का इक्रवाल करे। उसके जरिये से 13क्र को दो तकसीये का गई है, एक तो ज्जहबी या जैरानी और दूसरे के। परसनल या पाफ अलल उल ओलाद कहरे हैं यानी कानून के जरिये से दोनों में डिरिक्रिभिनेशन (भेद भाय) कर दिया गना है हाला हि जहां तक पर-सनल ला का लाल्लुक है वह उभ बात में कोई फर्क गही करता। द्वारी बात गह ह कि वक्फ अलल उल अरेलाद को जो कम्पे से तन वने वातरीका है वह भी पहल काबिले एतराज है। वक्फ को एक यूनिट पान कर मुआविजा दिया गएगा, तलाकि वाफ का हर एक बैनिफिशिसरी (लाभ-भोक्ता) गुकमारा तोर पर अलग है। एक परम ने वक्क किया। तीन पुरतों तक कब्बा रहा। दुर निस्त निस्ताहरा रहना है। लेकिन जहा मुआविजे का मोका आएगा सब को एक रिस्ति गान कर मुणाजित दिस्ताएगा। गालिबन यह इस लिये किया गया है कि ।गरे अठवा अन्त्रहं पृत्य मार्गे तो दिल्पिलिटेन ग्राव्ट ज्याबा मेनी पटेगी। में पासा इ िन्न लोगों की जिनकी किस्मते इनसे नाविस्ता हैं, अगर उनकी पाकेट में थो ही रिका पहुरा गान तो हुने गज तनी करना चाहिए। जता तक रिहै िरिष्टे न ग्रान्ट म लाल्यु है "रिहै विलिटेसन" तकत मुझे कुछ ज्यादा भाग नरी। रिवैतिन्द्रियन उन लोगो को विधा माता है जो रेक्यूजीज (जरणाथीं) हो। या तो गर्नामेण्य गुरु कर हि । याकई नितने अमीसार है उनका सर्तेबा बिल्कल रेपगुजीज के प्रसार तीमा, जगर आग यह मानते है तो मुगे मोहिएतरा विकी। लेकिन अगर जाम यह जी । नहीं मानते तो उपन "रिडेबिकिट नि" की जगह पर "रिलीफ" (महायता) ना को दूरा लपच आना जारिए। रितेशि देशन ग्राट महज इस वजह सेवोगई है कि यह छोटे जमीदार जो तकीकत में जो कपेरी पन म निर्ष खा गया है उससे अवने पैरो पर नही खड़े हो नकते, उनको कछ एडिअनल पिक्यनियरी हेल्प (रुपप्रे पैसे के सहायता) वी जा रही ने ताकि यह ।पने ौरी पर खडे हो सके। लेकिन जब यह उसुल मान िया है तय क्या जजा है कि यह वेनिफिशिएरीज जो बिल्कल छोटे जगीदारो की तैनियत रागते हैं उनको इससे गहरून राया जाय, जब कि हम रिहिनिलिटे न गाट महत्त इस बतार से वे रहे ह कि छोटे जमी गरी की कुछ इन्हरेजमें कर (प्रोत्साहन) श्या ाय। तो फिर जब वह अपना जगह पर एक युनिट है, मजहबी तौर पर, अललाको तोर पर और उर तौर तो कोई नजह नही पालुमें होती कि उनकी जोब में थोड़ी सी रक्षम जाते देवकर हम अमसे ग्रज करे। यह जरूर है कि अगर उनकी रिहै बिलिटेशन प्रांट दी जायगी तो कुछ थोडी पी राग्स बढ जायगी। लेकिन एक शहर को उसका हक पहुंचाने के लिये अगर गांची रक्षम गवर्नमेण्ट को देन। पडती है तो मे समझता हूं कि वह किसी सूरत से प्रज करने के काबिल नहीं है। जनायवाला, मैं इसकी तफरी जात में बहुत कुछ वह सकता हूं यह बहुत रद्राग केस है, कम से कम में बहुत ही स्ट्रागली फील (महसूस) घरता हू और में समजना हूं कि बहुत से लोग करते होगे। गवर्नमेन्ट को इन बोनो किस्म के वक्फी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नही करना चाहिए और उनको एक रूनिट मान कर मुशाविजा बेना चाहिये ताकि उनको थोडी सी रिहेबिलिटे-वान गांट पहुंचे सके। पर्योकि अगर जमीबार का मर्तना रेपयुत्रीत के बराबर है तो व । आपकी हर हमवर्दी का मस्तहक है।

जनाबवाला, एक वो अल्फाज में इस सिलसिल में भी कहना नाहता हूं कि आइंबा जमीवारी के खात्में के बाद वसूलयाबी का क्या तरीका होगा। हमने माना है कि जिम्मेवारी अलहवा अलहवा भी होगी और मुस्तरका भी होगी। पहले तो यह या कि मुस्तरका जिम्मेवारी में एक दूसरे पढ़म की लगान अवायगी में तीसरे की गिरफारी जो सकती थी लेकिन गवर्नमेन में उसकी रिगर (सखती) कुछ हत तक कम कर वी के और जवाइण्ड रिसपान्सिबलिटी उसी वक्त रहेगी जब किसी मुकाम का कले करा है और जवाइण्ड रिसपान्सिबलिटी उसी वक्त रहेगी जब किसी मुकाम का कले करा है हो साम के में बड़ा रीजनेबिल ऐंडीइयूड (उचिन मनोवृत्ति) लिया और गवर्न में के वे इस साम के में बड़ा रीजनेबिल ऐंडीइयूड (उचिन मनोवृत्ति) लिया और गवर्न न

सेट ने इम दिक्कत को समझ दर म्याभिव स्टेप लिया। इपने अलावा कलेक्शन्स के स्चिमले ने बहुन सी चीने ऐसी है जिन पर ठंडे दिल मे गीए करने की जरूरत है! मनत्र इसने यह प्रोवाइड किया (रला) गया है कि इसकी असूलयार्ब का तर्र का यह होगा कि इस गाव पंचायनों को शायब यह चीत मुपूर्व करे कि वह बसुलवाबी करे। लेजिन में निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता है कि वह म मानेवा है कि हमारी गांत पंचायते हो आइन्दा हिन्द्स्यान की रिपब्लिक्स बनने वाली हे, वही ऐसी यूनिट्स है जिनसे हम ऐसे जाए लगे लेकिन इमें प्रैष्टिल्ल भी बनवा चाहिए। बना हनने कभी इन बात पर ग़ौर किया कि द्या आज हर्दी गांव पंचायने इन निरित्त है कि इस काम को कर सकें तो इसका अवाव नहीं होता। अब पंचायते इस नाम को नहीं कर सकतीं तो जाहिर है जिललेक्टर से अप इंकार को जरायेंगे। रलेक्टर खुद तो इन काम को करेगा नहीं उक्ते अभीत था पटनारी इन लान की करेगे। वे कोन होंगे? ये ३० या ३५ रुपये के तनख्ाहदार होगे।मुप्तकिन है कि उनसे से बहुत से शख्न ऐसे हों जो लरखेड (पूपलोर) भी हों और नुझे उस्तीद नहीं है नि वे लहीं तरीके से अमूल-याद कर अबे और इन तरीके ने गर्निजेन्ट को बमूलदाई। से पहुन सी उत्तहने और विज्यते पैदा होंगी । इमलिये गवर्तमेन्ट न्योंन इम शामलें ने ग़ीर करे कि जब ता, जि ये गांव पंचायने इनप्पीरियान (यनुभव) नहा हासिल कर लेवीं, जब तक थे इक्श्नेरीमेन्टल स्टेज में हैं न्य तक यह काम जी मौजूरी लम्बरपार है उन्हीं के पुत्र दे कर दिया जाय और उनको बपुलवाबो जो जमीजन दिया जात: पानह अब भी दिया जाना रहे । में उमझना हं कि यह तरीका प्रवर्तमेग्ट के लिये उस्ता भी पड़ेगा और राजा मेंन्ट की वहन ा दिक्कते मौजूदा हालत मे रफा भी हो जायेगी।

एक बीज म पंचायतो के सिलसिले ने ओर कहना चाहता है। मैने शुरू मे यह कहा था कि जमीवारी जमीवार के लिये अब एक लाएबिलिटी (भार) है इमलिये उनदा खत्म होना जल्द से जल्द जलरी है। लेकिन इसके साथ ही नाथ रापींदार एक बकवर्ड क्लास न पाना जान उसको कम्पेन्सेशन (मुआविजा) का पूरा हक दिया जाय। उनके पाथ इनकरेजमेन्ट ओर भाईचारे की पालिमी अख्तियार करनी चाहिये और इसके साथ यह ये जरूर कहंगा कि हम अपने एन्थ्यूजियाज्य (जोश) में कोई भी ऐसी बात न करे जो काबिले एतराय हो। मैने जैसा पहले कहा कि मै डस्का हार्स, हूं और हर शर्भ जो ईमानदार है वह इसका हामी है कि गवर्नमेट जेड़ ए० एफ के जरिये सं रुपया हासिल करके जनींदारों को नक़द मुआविजा अदा करे। लेकिन मुझे पूरा शक हे कि यह कालयात्र नहीं हो तकता। में यह मानता हूं कि गवर्नमेट पूरी ईमानदारी से इस बात की के शिश में है कि जेड़ ए ए एफ में काफी रुपया वसूल है और हर जमीदार का फ़र्ज़ है कि वह इसमें पूरी मदद गवर्नमेट की करे। लेकिन मेरा स्याल यह है कि ियाय इसके कि क्रर्ज लेकर रुपया अदा किया जा सके और कोई रास्ता नकट देने का नहीं है और कोई दूसरी सूरत नहीं है। मेने इस सिलसिले में एक स्कीर कल वजाहत के माथ बयान की थी। कहा जाता है कि हुकूमत ने पंचायनों को इस यान की हिदायत दी है कि जेड़ ए ए एफ के मामले में वह गवर्नमेन्ट की मुखालिफ न करे लेकिन मैं समझता हं कि किसी अटानामस युनिट पर इस किस्म की पाबन्दी लगाना किनी सूरत से भी मुनासिब नहीं है। जिस वक्त पंचायतों के लिये एलेक्शन हुए उम वक्त हम पार्टी लाइन्स पर नहीं लड़े। उनमे कांग्रेसमैन भी है, सोशलिस्ट्स भी है, मुक्किन है कम्यू-निस्ट भी हों, इन्डिपेन्डेन्ट हों और बहुत से गिरोह के लोग हो सकते है। इसलिये अगर पार्टी की हैसियत से कोई पंचायत यह समझती है कि जेड० ए० एक० की बसूलधाबी में मदद नहीं करनी चाहिये तो उसको इसका पूरा हक है। इसलिये में अर्ज करना चाहता हुं कि चाहे कम्पेन्सेशन मिले या न मिले लेकिन एक ऐसा काम जो नाजायज है वह उन से कराना किनी रत से मुनाभिब नहीं है। मै अपने दोस्त फूर्लासह साहब की इस तजबीज से इत्तिफाक नहीं करता कि चंकि पंचायते गवर्नपेन्ट के अन्डर (मातहत)

[श्री सुस्तान आलम सां]

काम करती हैं इसलिये वे किसी भी स्कीम में गवर्नमेंट की राय के खिलाफ़ नहीं चल सकतीं, उन्हें गवर्नमेन्ट की राय के मुताबिक ही अपना काम करना होगा। मुझे अफ-सोस है और बहुत सखत अकसोस है कि में उनकी इस बात से इसिफाक नहीं करता और में समझता हूं कि सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट में इस अटानामी के जमाने में किसी अटानामस बाडो से इस बात का कहने का हक हरगिंज किसी को नहीं पहुंचता कि चंकि गवर्नमेंट को यह राय है इसिलये वह अटानामस यूनिट भी उसमें गवर्नमेंट की ताई करे। हम हर जलस को इसमें कनवर्ट करें, इसके लिये तैयार करें और उसके लिये आमादा कर सकें कि वह जेड० ए० एक० में बहुत हिम्मत से और फराखिटली से काम ले और क्ष्ये को वसूल कराए।

जनाबवाला, बिल को देखने से एक चीज और सबस में आती है कि इसमें दो वातें ऐसी और हैं जो आप दर गई हैं, नजर अंदाज हो गई हैं। एक तो है, हके आसाइश। यह इतना बड़ा हक है कि न सिर्फ बृटिश सरकार ने बिल्क इससे पहले जो हुकू मतें चलीं, उन सबने इसका पूरा ख्याल रखा। हके आताइश ऐसा है, जिस पर बहुत अगड़ें और तकरीरें हो सकती हैं। जरा सो बात पर हाईकोर्ट के परवाजे पर लिटीगेंट्स (मुक्क हमेबाज) अपमा सर मार सकते हैं और बेतहाश हपया सकी होता है। यका ६ से अगर यह हक निकल जाता है और हिज मेजेस्टी में सारे हक्क वेस्ट हो जायेंगे तो दक्का ८ से यह हक आताइश लोगों को फिर वापिस किया जाय, यह बहुत जकरो जीज है। यह बिल जय आइन्दा की जैनरेशन इस्तेमाल करेंगी तो इसके बारे में उनकी यह तमाम स्वाहिश रहेगी कि यह बजीरेमाल को हक आताइश के निकल जाने के लिये हुआ दें या बहुडुआ दें।

दूसरी चीज जो देहाती रक्त के लिये बहुत जरूरी चीज है, वह है विरयल पाउन्ड (कियस्तान) और 'कोमेशन प्राउन्ड (इसशान भूमि) की बात। यह एक ऐसा नाजुक मसला है जो कि इंसान के सेंटोमेंट से ताल्लुक रखता है। इस बिल के जिरये से कोई विरयल प्राउन्ह या कीमेशन प्राउंड जो कुछ भी हो वह पंचायतों में वेस्ट हो जांयगी। यह मैंने कई बार कहा है कि हमारी पंचाय में अभे एक तपरीमेंटल स्टेज में हैं, उनके ऊपर ऐसे इस्तिहान का बोझ नहीं डालना चाहिये कि वे इंतजाम करने में नाकामयाव हों। विरयल प्राउंड या कोमेशन प्राउंड में जित फेनलो का मुर्वी दफत होता हो, जलाया जाता हो, उनके ताल्लुक में वह हो तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा आपको इसका भी इंतजाम करना है कि बहुत सी जगहों में जहां कि कि बहुत सी जगहों में जहां कि कि बहुत सी जगहों में जहां कि कि बहुत सी उपहों के कि बहुत सी जगहों में जहां कि कि बहुत सी उपहों के कि बहुत सी उपहों कि कि बहुत सी जगहों के कि बहुत सी उपहों कि कि बहुत सी जगहों कि कि कि कि सिंटा कि कि बहुत सी जगहों कि कि सिंटा कि कि सिंटा कि कि कि सिंटा कि कि कि सिंटा कि कि कि सिंटा कि सिंटा कि कि सिंटा कि सि

जनाबवाला, जिल में जो जींदार का लगान वगैरह, या लो हल रेट, जो भी वकाया हो, उसका खात्ना जोंदारों के बाद बसूल गांबों के लिये कोई अच्छा तरीका नहीं रखा गया है। यह अच्छा तरीका न होगा कि वकाया लगान जिसका कि अदालत में दावा हो चुका हो या और सूतरे का जो बकाया हो उतकी वसूल गांवों के लिये जारेंदार, जब उसकी जानेंदारी न रहेगी और उसकी अगादनी १/५ हो रह जायगी, यह कैसे मुनकिन समसेगा कि वह उस सूरत में मुकद्देन-बाजी करे जबकि वह जानेंदारी से अलग है और वह बिरकु रही अलग रहना चाहता है। इसका यह इंतजान हो कि जो बकाया लगान उसका हो या और जो कुछ हो वह उसो तरह से वसूल किया जाय जैसे कि रेवेट्यू को बसूल यादी का तरोका है और वह सब बकाया जनींदार को दिया जाय ताकि जागेंदार को कोई साड़ा न करना पड़े। यह बहुन जकरों है और मैं इसे आनरेबिल निनिस्टर के सामने रख देना चाहता है।

एक बुनि भवी बात इस बिज के अन्दर और है, वह है सबलेटिंग की। सबलेटिंग बिल में वो सुरतों से जायज है, एक तो यह कि कुछ शनी के साथ वह शहस कर सकता है जोकिं डिसएबिल्ड परतन हो दूतरे वह जो भूनियरों का हक हासिल कर ले। डिनएबिल्ड परतंस की लिस्ट में कुछ खास लोग गिनाये गये हैं, जैसे पागल, अंशा, लंगड़ा, फीजो मुलाजिन वर्गरह, इस किस्म के लोग हैं। मेरा यह हमाल है कि वे निराम लोग होते चाहि हो। यो गर्यन नेट की एसेनिय असिवसे में हैं, खास नौर से पुलि में जो हैं, जो प्राइमरी स्पूर्ण के या दिष्ट्रकट बोई स के टीचर्स हैं। ये लोग छोड़ी छोटो जमीने रखते हैं ओर अगर दे तही दूनरी उनाह सुक्र जिम होंगे तो उनके हाथ से जमीन निरम्भ जायगी। निर्माण एह हो गरिक जनर उनकी मुक्र जिम तरही तो उनको जमीन भी निरम्भ और वे बेबारे कहीं के न रहेंगे। यह ये उनके खेती करने के लिये, अगर वह चाहें तो जमीन कहीं से मिल भी न नकेगी, प्योंशि चरित गासि कना बहुत ही मुश्किन हो जायगा। मैने यह बात बहुन जगह देखें हैं, अपने जिने से भी देखी हैं और मुझे सब बातों से पता चलता है कि इस चीज की बड़ी नाइड डिगांड (इधिन मांग) हैं कि सबलेटिंग का हक उन सबको भी मिल जाय। यह सबनेटिंग का हक उन सबको कि पहल बहुत बड़ी चीज हैं। अरे रचुबीर सहाय जीने अपना एक बयान महलेटिंग के बारेमें, उपने जिले बहायों के लिये दिया था जीकि मैने पढ़ा था और भी बहुत से दोस्त इस बीज को महसूत करते होंगे और उन्होंने इस बीज को देखा होगा कि इसके बारे में लोगों की बड़ी शांग है मी समझता हूं कि हर शहत इसको पहसूत करता है।

इसलिये फूलींसह जी ने भी इस बात को कहा है। मैने उनकी नकरीर भी अख्यारों म पढ़ी उन्होंने बनाया कि एक क्वेंच वगैरा के लिये वक्त जकरत कुछ जकर होना डाहिये। यह बिलकु रुट्टी ऐसी बीज है जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे बैकडोर से खलेंटिंग चाहते है रेंकिन में चाइता हूं कि बिलकु उक्लेंघर कट (स्व्ट) पालिनी होनी चपुहिये। या तो सबलेंटिंग जायज करार दिया जाय या किन्कुन नाग्यम । में यह भी समझता हूं कि मुक्क की और सूबे की मौनूदा हान्त को देवते हुये अबलेंटिंग का बिलकु उबंद किया जाना बहुत हार्ड (कब्दवायी) होगा। मुनिवन है कि इस कि के बनाने वालों ने जो उसल अपने नामने रखे हों उन पर इनका असर एड़ता हो लेकिन नुक्क की मच्ची जकरतों के पेन का पर उन उसलों में भी कम्प्रोनाइज करना पड़ना है। अगर मनलेंटिंग के लिये कुछ रेस्ट्रिक न्म (गार्दे वियों) के साथ इजाजन दे दी जांस्त की निहायत ही अच्छा होगा। वस्तन अगर यह इजाजत दे दी जाय कि जो लोग पूनिशर बनाये जायेगे उनको यह कम्सेटन विया जायेगा कि वे अपनी जमीन का कुछ पोर्शन (भाग) उठा तकें। मेरा ब्यान है इनसे जमींदारी एबालीशन फंड को भी कुछ इम्पीटश (प्रोत्साहन) चिल जायेगा और लोग ज्यादा ह गया दे कर मूमिधरी राइट्स हामिल करने को तैयार हो जायेंगे।

ननाबवाला, में इस पर कहना तो जगदा चाहता था मगर में यह देखता हूं कि बहुत से लोग इस पर तक़रीर करना चाहते हैं और जायद गर्जन मेंट की भी यह मंशा है कि आज ही डिस्क जन (वादिवाद) भी खत्य हो जाय इतलिये में उनके दरमियान में आबस्टेकिल (कावट) नहीं घनना चाहना। में चन्द जनरल (आज) बाते और कह कर अपनी तक़रीर को खत्म कहंगा। में एक मर्तश फिर इस बात पर जोर दूंगा कि यह बिल न कि ईस सुबे बिल्क इस मिल्क का एक हिस्टोरिक १ (ऐतिहासिक) और अहम विश् है। मुझे यह भी मालूम है कि बिहार और मद्रास ने भी ऐसे बिल बनाये हैं लेकिन वे इतनी डिटेल (ब्योरे) में नहीं रखे गये जितनी कि इसमें। इसमें ३१० वफाये हैं और हर चीज छत्त पर छोड़ दी गई है। उनको भी अगर इसमें शामिल कर लिया जाय तो १,००० दक्षायें होंगी। इसके अलावा डेट बिल इसमें नहीं है। इसके अलावा च्युनिपियेलटियां, नोटोफ इड एरियाज, टाउन एरिया, केंट्रन्मेंट बोर्ड और कुमायूं डिवीजन के बारे में अलहहा से कानून बनना बाकी है। इत पर भी मेरा यह ख्याल है कि जो कुछ हम बनायें वह जगदा से ज्यादा कम्प्रोमाइंजिंग हो। ऐसा न हो कि ठीक फारिंग न होने की वजह से हमें जल्द से जल्द तरमीम करनी पड़े। यह चीज न नो स्टेट के लिये और न पिल्क के लिये ही मुनासिव है।

जनाबवाला, मैं यह भी देखता हूं कि इस विल पर बाज तक़रीरे ऐसी हुई है जिनमें पार्टी बंदी की झलक पाई जाती हैं। जमींदार भाइयों सोशलिस्ट्स दोस्तों, और कांग्रेसी बेचेज से भी इस क़िस्म के डिस्क शन्स हुये हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस दक्त जब कि हम इस सुबे में हम

[थी सुल्तान आलम खां]

एक बहुत बड़ा रिफार्म (सुधार) करने जा रहे हैं, एक ऐसा रिफार्म जिससे कम से कम डेंद भरोड़ जनता इफोक्ट (प्रभावित) होने जा रही हैं और जो तमाम रूरल इकोनामी को इफोक्ट कर सकती है कोई गलती ने करे। ही सकता है बाज लोगों की कुछ जास राय हो लेकन नोबिलनेस और करेक्टर का यही तकाजा है कि वे मुल्क और खूबे की जरूरत की महसस करें और खंदा पेशानी से, हंस कर अपनी उस राध की बदल दें। जनाब वाला, नैने देखा कि बहुत से जिम्मेदार लोगों ने इस सिलसिले में अपनी राय बनाई और बदलीं। सुझे याद है कि जब अवालोशन कमेटी बैठी थी तो हा रि पुने के भागे नाज सोतालस्ट लीडर आचार्य नरेन्द्रदेव जी. जिनका में निहायत एहतराम करता है, उन्होंने उसमें कहा था कि १० गना मुआविजा देना चाहिये और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि परती और कल्चरेबिल वेस्टल का दो गुना की एकड मुआविजा विया जाय । उन्होंने किसी वजह से अपनी राय को बदल दिया। वरणसिंह साहच ने भी जामींदारी अबालीशन में यह कहा था कि १० गुना लगान का देना बाहिये लेकिन आज श्री चरणसिंह कहते हैं कि ८ गुना देना चाहिये। ठोक हैं और मुनासिब है अगर उन्होंने यह राध अपनी बतलायों,। इस वक्त मही अफसोत है कि हमारे श्रीमियर साहब, जिनका नाग न सिर्फ इस सुवा में बल्कि तमाम हिन्दुस्तान में मशहूर है, यहां मौजूद नहीं है वर्ना में आनरेविल वजीर लाल के साथ उनसे भी अपील करता कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी राष का बिल्कुल खुले तरीके पर इज्जीर करें और आव इस पर कैसला करने से पहिले इस पैराये में पीर करें कि वाकयो उन जो बिल इस वक्त अंजुर कर रहे हैं उससे मुलक को कहां तक नका पहुंचेगा, और हमारी करल इकोनामी कहाँ तक डिस्टर्ब (दरहथ-बरहम) नहीं होगी। हमें जमीं-वारों के साथ एक सिम्पैथी (सहानुम्ति) की पालिसी बरतना है, इसलिये कि जमींदार जसा मैंने अर्ज किया वह पीवट (धुरी) है जिनके इर्द-गिर्द खरल लोलाइटी घूमती है। में मानता हूं कि उसमें कुछ करण्शन आ गया है लेकिन अगर देखा जाय तो तकरीवन हर बाक आफ लाइफ में करण्यन (भाष्टाचार) आ गया है और इस करैण्यन की वजह से हम उसको कंडम (निन्दा) नहीं कर सकते हैं। हमें उनके पारिये वेहातों में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना है, इसलिये इस बात की बड़ी जरूरत है कि हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। एह गवनंमेंट की पालिसी अभी तक बड़ी गलत रही है कि जिसने बेसिक इयर्स में ट्रेंड नहीं किया है उसको हम ट्रेड का लाइलेंस नहीं देंगे। अगर आपने जुनियर इंटरप्राइजीज की उठने का मोका विया होता और जमींदारों को ट्रेड के लाइसेंस दिया होता तो में समझता हूं कि जितनी आज लायविलिटी (भार) आपके ऊपर है जतनी नहीं होती। वह अपने परों पर खड़े होते और वह इस काविल होते कि गवर्नमेन्ट को इस जिल में और ज्यादा काफी मदद दे सकते।

जनाबवाला, आपको इस बिल के साथ इस चीज की देखने की जरूरत है कि इस बिल से आपकी नेशनल बेल्थ (राष्ट्रीय धन) कहां तक बढ़ेगी। जहां तक हमारी नेशनल बेल्थ का ताल्लुक है, हमारी कीमी हुकूमत तीन साल से बरसरेइ क्तिवार है लेकिन हमें अभी तक नहीं मालूम है और न हमारे सामने कोई स्टैटिस्टिक्स (आंकड़े) ही हैं जिनसे हमको पता लग सके कि इस जमाने में हमारी कीमी बौलत कितनी बढ़ी है। मैंने परलों अखबार में पढ़ा है कि मिस्टर बेविंस ने कामनवल्थ की मीटिंग में एक तक़रीर में यह कहा है कि हमारे यहां की नेशनल बेल्थ पिछले तीन साल में कितनी बढ़ी है। हमें नहीं मालूम है कि हमारे यहां की नेशनल बेल्थ पिछले तीन साल में कितनी बढ़ी है और हमें यह भी नहीं मालूम है कि जमोंदारी अबालिशन के बाद नेशनल बेल्थ बढ़ेगी या घटेगी। यह प्वाइन्ट्स (बात) है जिनकी रोशनी में आपको गौर करना है। आपको यह भी देखना है कि वह जो लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट्स इस बक्त चल रहा है, जिसको आप कई बार बोहरा चुके हैं, उसमें अब कोई लूपहोल रह गया है या नहीं ओर अगर कोई लूप होल रह गया है तो उसको भी दूर कर दिया जाय। इसी के साथ जमींदारों को मुआविजा

विया जाय और इंद्यीटेटिल दिया जाग जेरा कि लापने उनमे केंद्र (बाबा) किया है। और उपको जो मुजाबिला दिया जाय वह कैश की सूरत में दिया जान नाकि पत गाप रें जपर लायिबिलिटी न रहे और वह आरकी नेशनल केय एक से में मदद दे परें। आप उन्नो बैक्सबर्ड त बनाइए। अगर आप उसको बैक्बर्ड रतार बनायेगे तो उससे मुल्क का कायदा नहीं होता । मे प्राफ़ किया जाऊं अगर मे यह अर्ज कहं ''जवार बुजुगी गिरि-ननन खला अस्तं वेजुर्गों की खता को पकड़ना भी खता है। हमारे वजीर नाल एक क्रादिल वकील है लेकिन इन बक्त वह ६ करोड़ इंसानों का फैल्ला करने जा रहे हैं। यह इनना बड़ा कान है कि इसमें हर शस्य कंफ़्यूज हो (योखे से आ) सकता है। इंसान इंसान है, वह ग़लती कर तकता है। ऐसी सूरत में में समझता हूं कि अगर कोई बुजुर्ग ग़लती करे और एक इंसान यह समझे कि वाक़यी उसकी गलती से न निर्फ उसे नुक्मान पहुंचेगा जिल्क ६ करोड़ इंसानों को नुक्सान पहुंचेगा और यह एक रेमा धटना होगा जिसको आने वाली जनरेशन्स (नस्लें) अच्छा नहीं कहेंगी, तो उस इंमान का यह फर्ज है कि वह निहायत अदव के सार्य उस बुजुर्ग का हाथ पकड़े ले और उसके यह कह दे कि आप ऐसा न की जिए। इसी तरह में यह अर्ज कहंगा कि आपने इस विल में जमोंदारों के लिय और जमींदारों के डिपेंडेंद्य के लिए काफ़ी प्राविजन नहीं रक्खा है। यह बिल जमींदारों के सरवेंन्ट्स (नौकरों) की तो विल्कुल ही इंग्नोर (नजरअन्दाज) करता है और आइन्दा उनका जमींदारों से कोई नाल्लुक भी नहीं रहेगा और अगर फिर भी उनका ताल्लुक इससे जोड़ना चाहते है तो में कहुंगा कि जाप भूमिधरों में भी दो क्लास बनाना चाहते हैं। हमने प्लेज किया है कि क्लोसलेय सोसाइटी (वर्गहीन समाज) बनायेंगे तो उसके बदले में आफ मुल्क में बैकवार्ड क्लास न बनाइए जियसे कि सूबे पर और ज्यादा लायबिलिटीज हो जार्ये। इससे हमारे सूबे का बड़ा ही नुकतान होगा। मैने कुछ लम्बी तक़रीर की है जिसमें बहुत सी बाते कही है, हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे कलमे भी निकल गये हों जो नामुनासिब हों तो उतके लिये में माफी चाहता हूं। लेकिन में साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि हर जमींदार को मिलकर जमींदारी एवालिशन बिल को कामयाब बनाने की कोशिश करनी चाहिये और गवर्नमेन्ट से इस बात की दरख्वास्त करनी चाहिये, अपील करनी चाहिए बल्कि मजबुर कर देना चाहिए कि वह जमींदारों को नकद मुआविजा दे। हो सकता है कि सर-कार के इस जमींदारी एवालिशन फंड में भी कुछ रुपया जमा हो जाय। इस फंड के हपया इकट्ठा करने में भी हर एक जमींदार को सरकार की मदद करनी चाहिये और उसका साथ देना चाहिए। लेकिन इमानदारी की अगर कोई बात हो सकती है तो मैं यही कहंगा कि ज्यादा रुपया वसूल होने की सूरत नजर नहीं आती है। उस सूरत में आप अमेरिका से क़र्ज लें या निजाम हैदराबाद से कर्ज लें और जमींदारों की नक़द मुआविजा दें जिससे वे इस रुपये को किसी कारबर में लगा सकें और अपने बाल-बंच्चों की रोटी का इन्तजाम कर सकें। अगर आप कर्जा लेगे तो किसानों को भी भिम-घरी का राइट (अधिकार) दे देंगे और इससे सोशलिस्ट पार्टी का मंह भी वन्दे हो जायगा। आप इसके जरिये जो आधा रेंट करीब ९ करोड़ के फोरगो (छोड़) कर रहे है वह भी बच जायगा, बेकार के बादरेशन (परेशानी) से बच जायेंगे और आपका एक्सटा एक्सपेंडीवर (जायद खर्चा) भी बच जाएगा। जमींदारों का प्राबलम (मसला) भी सीत्व (हल) हो जायगा और मुल्क व सूबे के ऊपर कोई लायबिलिटीज भी नहीं होंगी। हमारा सबा खुशहाल बन जायगा। इसलिये मै बहुत अदद के साथ आनरेबिल वजीर माल से यह अर्ज करूंगा कि वह एक बार फिर इस बिल पर अपनी फ्रस्त के मौके पर ठंडे दिल से गौर करें और इस बात की कोशिश करें कि जमींदार भी अपनी जमींदारी खत्म होने के बाद कायम रह सकें। जमींदारों के साथ तो आपकी पूरी सिमपैथी होनी चाहिये। आपको चाहिये कि जमींदारों को किसी सूरत से देहात का लीडर बना कर डेवलपमेंट (तरक्क़ी) के प्रोग्राम में इनीशिएटिव दिलावे। ये सब चीजे है जिनके आपको गौर करना है। वन्त है, फुरसत है और शायद इसके बाद फिर मौका

श्री सुल्तान आलम खां]

नहीं आबे। कौन जानता है कि जो नया एलेक्शन (चुनाव) होने वाला है उस एलेक्शन में क्या होगा? एलेक्शन में एक रात में पांसा पलटता है और इस हाउस में जो यह कांग्रस की हुकूमत है इसकी मुल्क के फ़ायदे के लिहाज से अभी वरसरे इक्तदार रहना जरूरी है। मुमकिन है कि मेरे इस ख्याल से कुछ लोग इख्तिलाफ़ करें लेकिन मेरे नजदीक कोई भी एसी पार्टी दूसरी नहीं है जो मुल्क को ठीक तरह से सम्भाल सके। में इसकी इमानदारी के साथ महसूस करता हूं और इस बात की समझता हूं कि कांग्रेस हकुमत का रहना अभी जरूरी हैं जबकि कम्युनिज्म हिन्दुस्तान के गेट (दरवाजे) पर आ रहा है। कामन बेल्थ कांफ़्रेंस, कोलम्बो नें भी यह कहा गया है कि जब तक एशिया. का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग (रहन-सहन का स्तर) नहीं बढ़ाया जाता है तब तक कम्यनिज्म किसी के रोके भी नहीं एक सकता है। यह सिर्फ यू० पी० के ही दायरे में महदूद नहीं है बल्कि इंटरनेशनल प्रावलम है और इसका स्कोप (दायरा) बहुत ज्यादा है। अगर आप इस बात को महसूल करते हैं कि जमींदार जमींदारी के खातमे के बाद बेदार और मफलिस इंसान न बनें, सोसाइटी के लिये लायबिलिटी न हों और उनकी वजह से सुबे के अमन व अमान को खतरा न हो तो में निहायत अदब के साथ लेकिन मेरे अल्फाज में जितना जोर हो सकता है तमाम जोर के साथ इस बात की अपील करता हूं कि आप इस बिल को एक बार फिर पढें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पीस मील लेजिस्लेशन (ट्कड़े-ट्कड़े का कान्नसाजी) बड़ी बुरी बात होती है। जो वैक्अम (रिक्त स्थान) है उस को आप कैसे भरेंगे? इसको आपको सोचना है कि जमींदारी खतम होने के बाद क्या इन्तजाम करना है ? मुझे यक्तीन है कि आप जमींदारों के साथ पूरी हमदवीं रखते हैं और किसी फैसले पर पहुँचने के पहिले इस बिल पर जरूर गीर करेंगे। में भागता हं कि जमीं वार पुराने गुनहगार हैं लेकिन कोई पुराना गुनहगार जेल काटने के बाद कैंद से निकले और उसे फिर कैंदी कहें यह मुनासिब नहीं मालूम होता। तो जामींदारी खतम हो गई। जो जामींदारी के खिलाफ शिकायत थी वह भी उसके साथ खतम हो गई। इनके माथे पर जो एक बराई का टीका लगा हुआ या वह सब खतम हो गया। अब उनके खिलाफ और ज्यादा कुछ कहना मोरलिटी (इखलाफ़) के खिलाफ़ है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा तो इसमें है कि उनके साथ अब इन्साफ का बर्ताव किया जाय ताकि सुबे के आने वाले खतरों से बच जायं। अगर हम इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ सकें तो आपका नाम रोशन रहेगा और जब यह बिल स्टैच्यूट बुक पर आएगा उसके साथ हमारी पापुलर गवर्नमेन्ट के प्रधान मंत्री और वजीरे माल जिन्होंने इसको पायलेट किया है उनका नाम अच्छी तरह से इस पर रहेगा। वरना जब वक्त गुजर जायगा तो लोग यही कहेंगे कि सुबे की एक हुकुमत थी जिन्होंने इस गलती को किया। उन्होंने ऐसा क़ानन बनाया जिससे न काश्तकारों को कोई फायदा पहुंचा और न जमींदारों को कोई नक्ता पहुंचा। इन चन्द अल्फाज के साथ में अपनी तक्दरीर की खतम करता है।

श्रो क्रमलापित तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक मेरे लायक दोस्त सुल्तान आलम खां साहब अपना भाषण कर रहे थे। यदि में गलती नहीं करता तो शायद कल और आज को मिलाकर उन्होंने १३५ मिनट अपना भाषण किया और अच्छा हुआ होता कि इसी सिलिसले में जो अब १५ मिनट बाकी है वह और जारी रखते और फिर जब आपकी कृपा से भोजन करने की छुट्टी हो गई होती उसके बाद जब २ बजे से अधिवेशन आरम्भ होता तो कदा—चित में बोलता क्योंकि १५ मिनट में शायद में उन बातों को पूरा नहीं कर सकूंगा जो कहना चाहता हूं और इसलिये बीच में छुट्टी होने से बोलने में कुछ थोड़ा सा व्याघात हो जायगा। परन्तु बदिकस्मती थी कि उन्होंने १५ मिनट पहिले हो अपना भाषण खतम कर दिया। और उनके लम्बे भाषण का बोझा तो सिर से जरूर हटा फिर भी जो काम मैंने अपने सिर पर उठाया है उसमें थोड़ी ककावट पड़ गई।

आज ५ रोज से इस बिल के ऊपर वहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, उह दर्ग अगर मोटे उसूल पर शुरू हुई होती तो शायद एक दिन में ही यह अतम हो गई होना था २, ४ घंटे और लगे होते। जमीदारी के विनाशका नामला कोई ऐसा मानला नहीं है जो हम सब के सानने या इस हाउस के भामने कोई नया भागला हो। उहा तक हमारे भाईजनिक और राजनीतिक जीवन में जर्मादारों के मिटाने का सदाल है मद अन्हें ह कि यसला आज १८, २० वर्षो से हमारे सामने हें। लायक ही ऐला कोई दूगरा मतला हो जिसके ऊपर इतना विचार किया गया हो जितना कि इस जमीदारी के विनाश के मामले पर किया जा चुका ह। इस समस्या क अन्य से १८ वर्षों ते सभा-मंचों, नंपाचार पत्रों के स्तम्भों, समितियों में, राजनीतिक मंगठनी ने, सम्से-लनों में , सदा दिचार होता रहा है और हभारे प्रान्त के आर्थिक और नागाजिक जीवन का यह एक ऐला भुख्य अंग रहा है कि इसके ऊपर हमारे प्रान्त के अच्छे अच्छे अय-जास्त्र के विशेषशों ने भी विचार किया है ओर गड़ा साहित्य तैयार किया है। इन न्या के मामने जमींदारी के मसले पर यदि मै ज्यादा भूल नहीं करता तो पिछले १०, १० वर्षों मे कई बार विचार हो पुका है। जब पिछली असम्बली के जनाने में काश्नकारी का कानून पेश था तब भी जर्मी बारी के ममले पर और उस के दूर पहलू पर विचार किया जा चुका है। इस बार भी भाल-डेढ़ साल पहिले तब काश्तकारी संशोधन कानून उहा पैस था विचार हो नुका है। जब इस अमेम्बली में यह मतला पहिले अाब या और जित समग्र जमींदारी विनाश कमेटी बनी थी तब भी इस पर विचार हो चुका है। उसके बाद फिर यह बिल आया और बिल के प्रथम वाचन पर विचार हुआ ओर अब इस पमण भी ५ रोज से बराबर विचार हो रहा है । मं देखता हूं कि जितनी बाते पहिले कही जा चुकी है वही बार-बार यहां फिर से कोहराई जा रही है और कोई न्या तर्क या नई वलील उसकी मिटाने या कायन रखने के पक्षे में पेश नहीं हुई है। इस्लिये म समझता हं कि इस बहम में कोई नई चीज नहीं है और अगर यह साधारण उसूलों पर ही जारी की गई होती तो एक दो दिन में ममाप्त हो गई होती। आज ५ रोज हो चुके हैं और सतले पर बहस जारी है तथािव मै आज आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं और थीड़े मे साधा-रण सिद्धान्तों के ही विषय में अपने विवार प्रकट करूंगा।

जहां तक बिल की धाराओं की तफतील का सवाल है स द्वितीय वाचन के अवसर पर जब धारावाहिक विचार होगा तब हो कुछ बाते कहूंगा। श्री युल्तान आलम खां साहब ने जमीदारी के मसले को बड़े जोश के साथ ओर बड़ी लियाक़त के साथ और बड़ी सरगर्मी ओर तेजी के साथ हाउस के सामने रखा है । मेरी समझ में जमींदारां की उन से अव्छा वकील शायद और कोई दूसरा मिल नहीं सकता था और मुझे इसमें भी संदेह है कि उनसे अच्छा वकील जमींदारों को कभी मिल सकेगा। उन्होंने बिल की धाराओं का काफी अध्ययन किया है और एक के बाद दूसरी तमास बिल की धाराओं पर उन्होंने विचार प्रकट किया है। उन्होंने धारा १२४, ६, १३, १७ और ना मालूम किननी धाराओं का जिन्न किया है। मैं तो समझता हूं कि जब धारावाहिक विचार होता उस समय यह सब बातें आती तो अच्छा था और इस तरह से सगय काफी बच जाता और एक दो घंटा दूसरे भाइयों को भी बोलने को निल जाता। इससे पहिले कि और बातों का जिन्न कर्छ में दो तीन बाते सरकार मे कहना चाहता विशिष्ट समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमे हं। आप की क्छ सुधार किए है और मैं देखता हूं कि उनसे यह बिल कुछ उन्नत हुआ है और विकसित हुआ है परन्तु कहीं अहीं मेरी समझ में कुछ और होने की जरूरत थी जिसकी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करता है। आपने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे काइत-कार और नवैयतें रखी हैं जिनको भूमिधरी के अधिकार पाने के लिये दस गुना लगान दे देना चाहिए। इसके साथ कुछ दूसरें तरह के जैसे अवध के परमानेन्ट टेन्योर होल्डर और बनारस कमिश्नरी के शरहमुअइयन काश्तकार है जो भूमिधरी अधिकारों को बिना [श्री का नापति तिवारी]

दश गुना दिए हुए ी पा लेगे। य समतता हूं कि यह आपने गड़ी मुनासिय बात की ह और विशिद्ध गिति ने जो निफारिश इस गंबंध में की ह वह ठीक है। तमारी क्रीन्व-इनरी का रथायी बन्धोग्स्त एक ऐतिहासिक घटना है और एक नड़ा भारी किसानों का तबका उन पिकारों का उपयोग कर रहा है जो सफड़ों वर्ष पहिले अंगेजी पामाल्य के जभाने में उन हो निले थे। उन काइतकारों को रेहन-बय का भी अधिकार है और उन को यह भी हक है कि उनके लगान में गोई इजाफ़ा नहीं होगा यानी उस लगान में कि जो लाई कार्नवालिस के जमाने में तै कर दी गई थी जि को उन्किनी बन्दे बस्त कहते ह और उसके बाद आज तक कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। आप ने भी उन्हें भिष्धर स्वीकार करके मुनासिय ही किया है। लेकिन आप की रिपोर्ट में धारा २० में इस बात का जिक है कि दवामी पट्टेवाले काश्तकार को तथा इस्तमरारी पट्टेवार को नीर-वार माना जायगा। सेरी प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में माननीय राजस्य सिंबव थोड़ा मा विवार कर लें।

में सरकार मे जर्ज करना चाहता हूं कि हमारी कमिश्नरी में ऐसे इस्तमरारी पट्टे है जिनको पटवारी कागज में जिम्न ९ और १० में लिखते हैं परन्तु वस्तुनः उन्हें वही हक मिला हुआ है जो शरहमुअइयन के काश्तकारो हमारे यहां जमींदारों ने पट्टे उस्तमरारी किए है और उन पट्टों की शर्ते वही ह जिनसे पट्टेटारों को वह हक मिले हैं, जो 'रारहमुअइयन के काश्तकार को है। उन काश्तकारों को पेड़ लगाने का हक है। मकान बनाने का हक है। उन्हें रेहन और बय करने का हक है। जमींदारों ने काफी लम्बा ओर चोड़ा नजराना लेकर उन जमीनों को बेचा है। पटवारी के कागज में यद्यपि पट्टेदार की नर्ययत जिम्न ९ में दर्ज होती रहीं पर वास्तव में जमींदार ने रुपया लेकर उन्हें शरहमुअइयन बनाया था। आज उनसे दस गुना लगान मांगा जाता है। वे दसगुना लगान देकर भूमिधर हो सकते हैं। में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे जिले में ओर किमश्नेरी में इंग सम्बन्ध में बड़ा विरोध है और क्षोभ है। काश्तकार कहते हैं कि हमने नजराना जमीन का देकर पट्टा लिखाया है ओर हक हासिल किया है। नजराने की रकम लिखी हुई है। रजिस्ट्री जुदा पट्टो में वे एक बार जमीन के दाम दे चुके। दूसरी बार फिर उसी जमीन के दाम मागे जा रहे है। में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के पट्टेदारों को भी आप उसी तरहे बिना दस गुना लगान के मुमिधर स्वीकार कर लें जिस तरह आप शरह मुअइयन के काइत-कारों को स्वीकार करने जा रहे हैं। दूसरी बात वह है जिसकी तरफ आप की सिलेक्ट कमेटी का ध्यान नहीं गया ओर आप का ध्यान भी नहीं गथा। मेरी समझ में वह एक भूल है। में आपका ध्यान उस ओर आकषित करना चाहता है। जब सन् १९४७ मे आपने कारतकारी कानुन का संशोधन किया, उस कानुन में दक्रा १७१ में जो काश्त-कार बेदलल हो गए थे उनकी जमीन वापस करने की व्यवस्था की गई है। जिग समय पूराने जमाने में कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा विधा ओर लड़ाई शुरू हुई तो हमारे देश में सत्याग्रह और सन्४२ ई०का क्रान्तिकारी आन्दोलन चला। जमींदारों ने अवसर से अनुचित लोभ उठाया ओर हमारे सूबे में हजारों एकड़ जमीन से लाखो किसान दफा १७१ में बेंदराल किये गए। यह आपका कानून जो सन् ३९ ई० मे बना या उस कानून का दुरुपयोग किया गया। उसके अर्थ का अनर्थ किया गया। लाखों किसान वेदखले किये गए। सन् ४६ ई० में जब फिर कांग्रेस मरकार बनी तो उस कानून में आपने मंशोधन किया। उस संशोधन के द्वारा किसानों को जमीन कुछ दार्तो के साथ वापस की गई। आपके सामने उस समय सबाल यह था कि जिन जमीनों से जमीदारों ने काइतकारों को बेदखल किया था उन जमीनों का बन्दोबस्त अगर जमींदारों ने दूसरे काइतकारों से नज-राना लेकर उनके साथ कर दिया हो तो वह जमीन किर पुराने काइतकार को कैसे वापस की जाय। अब यह बड़ा सवाल था कि उन बेचारे काइतकारों का नुकसान होगा जिन्होन नजराने देकर उन जमीनों को अपने नाम लिया है और काबिज है। बहुत सोचने-विचारने के बाद आपने उक्त संशोधन कानून में यह ध्यवस्था की कि जमींदारों ने जिन जमीनों का बन्दोवस्त कर दिया है वह जमीने उन काश्तकारों के पास ३ साल तक शिकमी की तरह से उनकी जोत में रहेगी ओर वे उन पर काबिज रहेंगे। ३ साल के बाद वह जमीन उन बेदखलशुदा पुराने काश्तकारों को वापन हो जायंगी, जिन जमीनों का जमीं-दारों ने कोई बन्दोबस्त नहीं किया था वह जमीने तुरन्त काश्तकारों को वापस हुई।

मै जहां तक जानता हूं मेरे जिले में ऐसी हजारों बीधे जमीन ह जो बेड खल हुई थी दफ़ा १७१ में उस्त संशोधन कानून बनने के बाद मामले लड़े गए, काश्तकारों की डिग्री हुई और यह हुआ कि दफ़ा १७१ में जो जमीन बेद खल की गई है वह वापिस कर दी जाय पुरान काश्तकारों की। लेकिन बहुत सी जमीने जिन पर शिकमी काबिज था, आपके इस क़ानून के मुताबिक गत तीन साल से उसी के क़ब्जे मे रह गई। आज जब यह क़ानून बन रहा है इसके मुताबिक पटवारी के काग्रज में जो शिकमी जिस जमीन पर है वह पांच साल तक अधिवासी रहेगा और उसके बाद वह भूजिधर हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि सन् ४६ ई० के संशोधन कानून के मुताबिक दफ़ा १७१ में जिन्होंने अपनी जमीने वापिस पाई है, लेकिन क़ब्जा नहीं कर सके, इसलिये कि उनके ऊपर शिकमी क़ाबिज है, उनका क्या होगा ? में जहां तक देखता हूं आपके इस क़ानून में इसकी कोई ब्यवस्था नहीं है। में अपने राजस्व मंत्री का घ्यान इस ओर आक्रित करना चाहता हूं कि तीन साल से जो शिकमी उस पर क़ाबिज है वह उस पर क़ाबिज रहेगा और अगर पांच साल तक अधिवासी रह कर वह भूमिधर हो जायगा तो उन पुराने काश्तकारों को जिनको जमीन वापिस मिलनी चाहिये क्या पिलेगी? इस मामले को साफ़ कर देना चाहिये।

श्री रमाशंकर लाल--वह तो असामी होगा, यह तो लिखा है।

श्री कम नापित तिवारी—शिकमी तीन साल के लिये काग्रज में दर्ज है। उसके बाद क्या स्थित होगी यह देखना होगा। भाई रामशंकर लाल जी तो मुख्तार हैं। में मुख्तार नहीं हूं। में तो एक ले मैन हूं और सीधा हिसाब जानना चाहता हूं। इस विषय में यदि क़ानून में कोई स्पष्टीकरण नहीं है तो वह हो जाना चाहिये अन्यथा कोई कहेगा असामी है, कोई कहेगा अधिवासी है।

एक तीसरी बात, जिसके बारे में कुछ मित्रं। ने यहां प्रश्न उठाया भी और भाई फूल सिंह जी ने भी कहा, पेड़ों के सम्बन्ध में है। बहुत से पेड़ काश्तकारों ने परती में लगा रक्ख है जो काश्तकारों के पेड़ है, जिनकी काश्तकार पोत देता है जमींदार की। बहुत से पेड़ काश्तकारों के खेतों के गेड़ों पर लगे हैं। उनकी हैसियत क्या होगी? अभी मैं जहां तक समझ पाया हूं, इस प्रकार परती में लगे हुए जो पेड़ है वे शायद गांव—सभा की सम्पत्ति हो जायं अथवा जमींदार की सम्पत्ति हो जायं। परती में लगे हुए इस तरह के पेड़ जिनका पोत काश्तकार देता रहा है, उनके सम्बन्ध मे यह जरूरी है कि ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाय कि जिन काश्तकारों के वे पेड़ है वे उनको मिल जायं। यह मुत्फर्रकात के काश्तकारों की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। काश्तकारों को गांवों में जितनी लकड़ी की जरूरत पड़नी रही आज तक तो वे जमींदारों से पाते रहे या अपने पेड़ों से पाने रहे। आगे भी इस तरह से परती में लगे हुए पेड़ उसको मिल जाने चाहिए। इन पेड़ों को उन से ले लेना गरीबों की संपत्ति ले लेना होगा।

(इस समग्र १ बजे भवन स्थिगित हुआ और २ बजे श्री नफ़ीसुल हतन डिप्टी, स्पीकर की अध्यक्षता में भवन को कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

डिप्टो स्पीकर-अभी कोरम पूरा नहीं है. इसिलये २-३ मिनट बाद, कोरम पूरा होने पर, कार्यवाही आरम्भ होगी।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हुआ।)

भारतीय पार्तियामेन्ट में पच्चीम रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्य में घाषणा

जिटा रिपाकर—भारतीय पालियामेट के २५ रिक्त स्थानों के लिये ३६ नामों के पत्र प्राप्त हुए हैं। इनकी घोषणा कल भवन में कर वी गई थो। जाज एक अजे तक का समय नामा की वासी के लिये निपुक्त किया गया था। इन ३६ में से १० उम्मीद—वारों ने अपने नाम वास्मि ठे लिये हैं और जो वाससी के पत्र आएँ हैं वे भी सब ठीं के पाए गए हैं। अब २६ उम्मीदवार रह गये ह और उने नाम ये हैं:—

श्री हाफिया शेल रफीउदीन लादिन, श्री लदमी धहर यादा, जोनपुर, श्री जाकिर हुसँन लां, अलीगढ़; श्रीमती सुनेता हुपलानी, मेरठ, जीपती उता नेहरू, उपलन्क, श्री सादिक-अलो, बनारस; श्री हुद-नद हिफ जर्गहनान, देहली; श्री भुनीश्यरस्त उपाध्याय, प्रताकाढ; श्री कृष्णवन्द्र शर्मा, आते; श्री पोपीना प्रति, जानपुर; श्री के० के० महावार्य, इलाहादाद; श्री आर० पू० निह, उत्तन्द्र; श्री इन्द्रिया तच्यति, हिन्तुर; श्री जिमवन नाराण्य सिह, वनारत; श्री हिन्द्रिया पास्त्री और श्री बेनीतिह, कानपुर; श्री नेमीजरण जन, जिनार; श्री कृष्णवन्द्रराय, न जोपुर; श्री वूर्यप्रपाद निश्च, देवरिण; श्री कि उपण्याति, द्वाहादा; श्री वृत्यार निह, सरठ; प्रो देवीसत्त पन्त, जनगोहा; श्री नरवेय रनानक, मगुरा; श्री वलदेव निह जार्थ, गढाति; श्री करहें प्राजा जालमीकि, बुल-स्वहर; और श्री सोहनलाठ पस्ती।

ात्र जैसी कि पिनले इत्तिला की गई ह, यह चुनाव रीडिंग रूम में कल ग्यारह और वार बजे के बीच में होगा।

श्री इन्द्रदेश त्रिपाठा--एक नाम गणत है, इसका सशोगन में करना जाहता हूं। कल भी इशारा किया गया था कि गाजीपुर के कृष्णचन्त्र राय जो लिखा है वह कृष्णानन्दराय होना चाहिए।

िटटी र्वाफर--हुणानन्व राय ही लिखा हुआ है, सही है। मेरे पढने मे गालिबन गलती थी।

मानतीय मार्वजनिक निर्माण सिचव——जनाब ने जो नाम सुनाये है उनमें एक नाम रफीउद्दीन साहत्र का है वह मुस्लिम सीट के उम्मीदयार ह। तो जनाब ने इलेक्शन होना जो तजबीज फरमाया है उसकी जरूरत तो मेरे खयाल में नहीं होगी।

ाइट्टा स्वाकर—मेने जहां तक कायवे देखे हैं, मैं यह समझता हू कि तीन जगह मुफ्लमानो के लिये महफूज कर वी गई है ओर बार जगह शिड्यूल कास्ट के लिये। लेकिन यह लाजिमी नहीं हैं कि वह तीन या चार से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, इसलिये इलेक्शन का होना तो लाजिमी हैं। यह नहीं हो सकता कि बाकी बचे हुए लोग चुने हुये घोषित कर दिये जाये।

मन १६४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल (जारी)

श्री कप्रजापति तिवार।—उपाध्यक्ष महोदय, में इस मध्याहन के अविवेशन के पूर्व इस बिल की कुछ वातो की ओर राजस्य सचिव का ध्यान आगणित कर रहा था और में उनकी सेवा में दो तीन याते निवेदन भी की थी। अब में साधारणतया इस बिल के स्वरूप की ओर दृष्टिपात करना वाहता हूं और इस बिल का समर्थन करने का प्रयास करना चाहता हूं। जो बिल इस सरकार की ओर से पेश किया गया है उसक लिये इस सरकार की और निशेष कर राजस्व मचिव की जितनी प्रशंसा की जाय यह कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश के इतिहास में और विशेष कर इस युग के इतिहास में जिसका प्रादुर्भाव देश की स्वतंत्रता के नाद हुआ है यह कवा जित इस सरकार का समसे महान प्रयास है जो सारे देश के लिये मार्ग प्रदर्शन का काम करेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक पराधीनता के बाद यदि किसी देश में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना होती है तो निश्चय ही अनिवार्यतः इसके बाद सामाजिक ओर आर्थिक

क्राति का सूत्रपात होता है। राजनीतिक पराधीनता, स्वयं कोई लक्ष्य नही हुआ करती। अगर स्वाधीनता प्राप्त की जाती है तो वह साधन बनती है, सामाजिक और आधिक स्वतंत्रता की। राजनीतिक स्वतंत्रता हम चाहते है, इसलिये कि हमारा सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन समुद्रा हो और हम अपने उद्देश्यों की मिद्धि कर सकें और वह लक्ष्य होता है जब हम सामाजिक और आधिक स्वतंत्रना प्राप्त कर ले। हम चाहते ह आज एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी व्यवस्था जिसमे मनाजका जीवन परिस्फुटित और विकसित हो सके। हमारे देश की राजनीतिक पराधीनता हमारे जीवन नार्ग को कुंठित कर रही थी और विकास के पथ का अवरोधन कर रही थी। यही कारण था कि हमे लबसे वड़ी आपक्यकना इस दान की थी कि हम अपनी राजनीतिक पराधीनता का अंत करे। स्वायीनता हमे प्राप्त दुई और इमके याद आज देश में नये युग का प्रश्वमाद हआ है। हमारे देश को यह युग एक कार्ति के दाद दूहरी कार्ति से परार्पण कब रहा है। अंग्रजी राज्य मे इस देश की जीवन एक शुन्यता और रिक्तता री पड़ा हुआ था। जब कोई विदेशी सत्ता आती है तो उपका धर्म हो जाता है कि वह जिल देश पर शापनाहड़ होती है वहां के सभाज का संगठन, आधिक संगठन प राजनीतिक संगठन और यदि नम्भव हो तो सांस्कृतिक संगठन भी इन प्रकार दा बना ले जो उसके दित के अनुकूल हो ओर विदेशी राज्यों का इतिहास इस दात का ताक्षी है। हमारे देश में यत १५० वर्षों से अंग्रेजी राज्य का एकमात्र लक्ष्य यही था कि इन रेंश की सामाजिक और आधिक संगठन की कंठित करे और जो व्यवस्था बने दह ऐसा ही हो जो उसके हित के अनुकूल हो। अगर आप अपन इतिहास पर दृष्टिपात करे तो आप यह देखेंगे कि जिस यग मे अंग्रेजी राज्य यहां पर स्थापित हुआ, वह ऐसा युग था जद दुनिया मे एक नई धारा, एक नई संस्कृति, और नया जीवन उत्पन्न हो चुका था और जिसका परिणाम था अंग्रेजों का इस देश में आगमन। इंगलैंड की औद्योगिक क्रान्ति के बाद उत्पादन के जो नये तरीके उत्पन्न हुए, उत्पादन के जो नये साधन प्राप्त हुये उनकी भित्ति पर पश्चिम में एक नया राजनीतिक और आर्थिक संगठन बना। उस राजनीतिक और आर्थिक संगठन की भिति पर एक नई संस्कृति ने जीवन ग्रहण किया। उस संस्कृति का प्रवाह था जो अंग्रेजों को यहां ले आया। औद्योगिक कान्ति के बाद पश्चिम मे जो उत्पादन की नई प्रणाली चली उससे सारा संसार एक कोने से दूसरे कोने तक प्रभावित हुआ। हिन्दुस्तान की संस्कृति बहुत पूरानी थी। अंग्रेज यहां आये और यहां आने के बाद उन्होंने इस वात की कोशिश की कि यह देश नये लहर से, नये ढंग से, समाज के नये प्रवाह से, संस्कृति की नई बारा से प्रभावित न होने पावे और यदि आप अपने इतिहास को देखें तो आप पायेंगे कि बलपूर्वक उन्होंने इस धारा का आगमन इस देश में रोका। हिन्दुस्तान में जो पुराना आर्थिक और सामाजिक संगठन था उसको चूर किया और उसकी बुनियाद पर ऐसे संगठन को खड़ा करने की कोशिश की जो उनके लिये सहायक हो। एक पराधीन देश का यह दुर्भाग्य होता है, यह उसके पाप का फल होता है कि स्वाभाविक ढंग से जो उसके विकास का मार्ग है वह कुंठित कर दिया जाए। परिणामस्वरूप हमारे देश की यह दुई का हुई कि हमारा जो कुछ था वह भी चूर हुआ और जो बाहर से लाकर हम अपना निर्माण कर सकते थे उसका मार्ग भी अवरुद्ध किया गया। इस शुन्यता, रिक्तता में पड़ा हुआ यह देश, १५० वर्षों की गुलामी के बाद जब छूटा है तो निइचये ही स्वाबीनता प्राप्ति के पश्चान वह अपने हित के अनुकूल अपने समाज और अपनी अधिक व्यवस्था का संगठन बनाने की चेष्टा करेगा और आज यदि आप अपने देश के जीवन पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि सारे देश का सामाजिक जीवन एक प्रकार की उथल-पुथल, एक प्रकार के कांति-युग से बीत रहा है और प्रसन्नता की बात यह ह कि हमारे इस प्रांत की सरकार ने उस सामाजिक कान्ति के सूत्र को अपने हाथ में ग्रहण किया है। और में समझता हूं कि यह बिल उस सूत्र के ग्रहण करने का परिचायक है और उसका बड़ा भारी प्रतीक है। दुनिया के इतिहास में सामाजिक क्रान्तियां बहुत हुई है, राजनीतिक और आर्थिक क्रान्तियां भी बहुत हुई है। हमारे देश की वही विष्लव की घारा भी बह चली

[श्री कमला। ति तियारी]

है, के तिन में समाना कि इस देश के राज भी । अध्यय ह हिन्या की राजनातिक कालियो में जिए पहार एह ने से पता जो नार अपर पति प्रशास का तथा ही सापालिक कालि और इस कारित , नेतर मा प्रधा द । स्टार दारा अर विधि कर कांग्रेसजनी हारा विना माताजिक गेर तिक किती के क्षिता में एक नवा पुष्ठ जोड़ने बाल लीना। हसरी जान तर कभी जारिया का का निर्देश कितीन होते, मानवता-सम्मत होते नहीं देशा । पानियो गा ज अ। मा हारी विभा करात्या, तस्य ओर जाति रकता और क्षिर, उर्त है च्या है भी ' म कि । परने इस देन से सानीतिक विपलव स्कृत स्था, वाधी भी मे ने रत्य म, ती रता में तो ने ती न ती न ता न न न न न न आ। ओर में हैल रहा है कि जा असे केन में सकता कर पर कार्य का मिना एक का भारी अध्यात च्चित्रार्थ होते ना राम है भी कि का कर कार में का रोग का तर के हमारे पालकी सरकार ने सारे । भागान गरा है। "नारे देश का का भागा । यादि जो सामाजिक क्रान्ति , प्रत्या । दी प्रदार्यण रूपारे सामन प्रत्ये को को परित्य । प्रकारिक को ने सामतवाती पुराती है। पानुसी, अंगर बाल असावा जय तर व्हितिसापा। है समाहजा। वह निना निसी ब्रिकार के रख एरात के दिना, किसी ब्रकार की किसा के भीर में नागा के निर्मा गया । यह एक बदीयह घटना प्रदनें जा दशे हैं जिस वा पोर एक है। प्रारं ी गराहर तेंग बनाया हवा यह चित्र हो। उस चित्र हे द्वारा पथा। अधी पंथी एक एक ऐसी प्रसाका हत होने जा सही जो कि न केवर रमारे वस के श्रांतक र भी, जो कि के सरे सामाजिए जीवन के श्रांतक की, जो कि न केवर भार तिय सरकृति के श्रांतक र भी, जो कि न जाउन पान्त के हरी के नर-नाणि के सिर पर पिशाचिनी की भांति चढ़ कर बैठो हुई थी। एक एसी प्रया का जन्त होने जा हा है, जिसका जन्म विदेशी बासन में हुना, विदेशी यागन ने जिसकी परिकाटित किया और जिसकी रक्षा भी विदेशी गासन हरता रहा, एक ऐसी प्रधा का अन इस गिर है सराहीने जासा हो। और में बरानग्रता से निवेदन अगार कि वेशी रियामार के जिल्हाना के लिहा जमीवारी के मिटाने से सरक था। इसिक्यं सरक या कि तसारे देश के देशी नरेश जनता के जीवन से दूर, करें कही करें हुए थे, जिल हा कोई सम्पर्क जनता के सामाजिक जीवन से नथा वे लोक में अप्रिय होते हुए भी आंध कार का उमभोग करते थे। उन हो होई सुदढ़ स्थितिन थी। ब्रिटिश प्रवृक्षे उनकी रक्षा करती थी। या वे आनि पूर्वक न मिटा दिये गये होते तो वे बज्याक मिटा दिवे जाते।

उनके सिटने पर उनके पक्ष में उनके िएये कोने याला कया वि को कि व्यक्ति भी न था।
परन्तु यह जमीवारी प्रथा जिस का मुख्य बुर्ग हमारे पान्त में हे जो अप्रिय और अनप्यक्त होते हुए भी जनता के जीवन से सम्बद्ध है, जिससे करों में आउमी प्रभावित है, ऐसी प्र मा हे जो हमारे आंकि और सामाजिक जीवन में अपना अभिनय करती रही हो, इस प्रथा को भिनाने के िये जो विल्णे किया गया है उसकी जितनी भी प्रशंन्सा की जाय थोज़ी है ही, साथ हो साथ गिरा गिरा विष्क वृद्धि से कोई विचार करें तो यह स्वीकार करेगा कि इस विल के प्रारा समार के सामाजिक और आधिक क्रान्तियों में हमारी प्रान्तीय सरकार का यह नया अप्याप जो ने जा रही है जो इस बात का परिचायक होगा कि सामाजिक और आधिक क्रान्तियों भी दिमा हीन ढंग से, रक्ति ही की समझता हूं कि यह बिल बास्तय में शिर श्रांसा करता है। साथ-साथ में यह भी समझता हूं कि यह बिल यास्तय में उस चीज को ले आ रहा है जिसे हमने अग्रेजी राज्य में खो दिया था। यि अपने देश के इतिहास पर दृष्टिगात करें तो आप इस बात को देखें। कि हमारे देश की संस्कृति, यामीण संस्कृति तो थी ही साथ ही साथ देश में भूम स्वामित्व हमें कुष्ठकों का रहा है। खेतिहर हमेशा ही भूमि का मालिक रहा है। हमारे यहा पुराणों में देखें, बौद्ध जातकों में देखें, उपनिषदों में देखें, स्मृतियों को भी देखें, स्वयं वेव की ऋचाओं में देखें, हमितिहर हमेशा ही स्वि को भी देखें, स्वयं वेव की ऋचाओं में देखें,

ब्राह्मण ग्रन्थों में देखें, कवियों के ग्रन्थों में देखें, सिहत्य के वाडमय मे देखे तर्वत्र एक वात ि मिलेगी कि इस देश में भूमि का स्वामित्व किसानों को प्राप्त था। ऐसी अनेक कथाये पूराणों मे है जहां राजाओं ने दान देते समय यह कहा है कि भूमि तो है प्रजा की कर जो है प्रजा का हम तो उसके हम वहीं दे सकते हैं दान में जो हमें वेतन के रूप में प्रजा से निलता है। रवीकार किया गया है इस देश में कि भूमि का मालिकाना हक, प्रशुद्ध का अधिकार भिम पर कृषकों का है और यह परिस्थिति मेरे देखने में तो मुगलों के शासन काल के अन्त तक चली है । मध्य युग मुगलों के युग तक हमारे इस देश में भूमि शास्यानित्व कृषकों का रहा है। साथ-साथ गांवों में ग्राम । संस्थाये थीं जो ग्राम्य जीदन की, एक प्रकार से समस्त सामाजिक जीवन की, सूत्र अपने हाथ में ले कर व्यवस्था चलःतीं थीं । यदि आप मेगस्पनीज के जगाने से देखें और कौटिल्य के युग से तो पौरवों और जानपदों का जहत्व इस देश में सदा से रहर है। ग्रान्य संस्थाये सान् हिक जीवन ना, प्राप्त के समस्त जीवन का उन्नयत करती थीं और भूमि पर जिसमें खेती होती रही हो उस पर नालिकाना अधिकार हमारे किसानों का रहा है। यह हमारे देश के सामाजिक कीवन को, सामाजिक व्यवस्था की भित्ति थी, बुनियाद थी जिस पर सामाजिक भी और जायिक ढांचा भी खड़ा हुआ था और इन दोनों का उत्पूलन अंग्रेजी राज्य मे हुआ। अंग्रे जी राज्य में हिन्दुस्तान का यदि सब कुछ छीन लिया गया ती साँग ही साथ इस देश के किसानों का भूभि-स्वामित्व भी छिना । यदि इस देश क: सम्मान, इसकी बुद्धि, इसकी ननुष्यता, इसका राजगीतिक प्रभुत्व, इसका अविकार, यह सब प्राठ अंग्रेजी राज्य ने छीता तो वड़ा भारी अरार्थ उसने यह भी किया कि इस देश में किसानों का भूस्वामित्व भी उसने छीना साथ-साथ हपारे देश के सामाजिक जीवन की बनियाद जो हमारी स्थानीय संस्थाये गांवों की बहतंत्रात्मक प्रजातन्त्री पंचायतें, पौरव और जानपद थे इनका भी विघ्वंस अंग्रेजी जमादे ये ही हुआ । यह तो अंग्रेजी काल के इतिहास लिखने वालों के प्रन्थों से देख लीजिये कि १८३० तक उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इस देश में गांबों में वह जनतन्त्रात्मक तं एठन कौजूद है जिनकी बुनियाद पर सारा सामाजिक जीवन ख इा हुआ था और जो गांवों में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ पूरे अधिकार का सामृहिक रूप से गांवों में उपयोग करती थीं । यह अंग्रेज इतिहासकारों के ग्रन्थों में आपको मिलेगा और धीरे-- शेरे इनका उन्मुलन, इनका विध्वंस अंग्रेजी जमाने में हुआ । मै देखना हूं कि इस बिल के द्वारा वह जो हम से छीना गया था उसको इस प्रान्त की जनता को आप पुनः प्रदान करने जा रहे हैं। आप इस बिल के द्वारा किसानों को उनका भुस्वापित्व वापिस कर रहे हैं साथ–साथ इस बिल के द्वारा आप इस देश के इस प्रांत के समस्त सामाजिक जीवन की बुनियाद उन ग्राम प्रजातन्त्रों को प्रतिष्ठित करने जा रहे है कि जिनकी भित्ति पर भारत का सर्वोदय लोकतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र धन खड़ा होने जा रहा है। यह बिल तो एक भूमिका रूप में हमारे सामने आया है। भूमिका उस यहान भारतीय प्रजातन्त्र की जिसकी प्रतिष्ठा आज से दो सप्ताह बाद इस देश में होने जा रही ह। महान भारतीय प्रजातन्त्र प्रतिष्ठित होगा और उसकी भूभिका के रूप में इस बिल को आना हमारे सामने उसकी पूर्व सूचना है और शुभ सूचना है जिसके लिये मैं इस प्रान्त की सरकार को बधाई देता हं।

जहां तक इस बिल के मौलिक सिद्धांतों का प्रश्न है, में समझता हूं कि तीन चार बातें इसकी नृख्य हैं, जिनका विरोध कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि पहिला मृख्य सिद्धांत तो यह है कि जो भूमि को जोतता बोता है और जो जिस भूमि पर काबिज है वही उसका मालिक बन बैठे। यह एक मोटा सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि भूमि को जोतने बोने वाले और राज्य के बीच जो मध्यवर्ती हैं जनका उन्मूलन हो जाय, किसी प्रकार की एजेंसी की अब आवश्यकता नहीं है। उत्पादक जनता हो और उत्पादक जनता हा सरकार का सीधा संबंध हो और बीच का मध्यवर्ती वर्ग मिट जाय। यह उसका दूसरा बहुत प्रौढ़ और स्थूल सिद्धान्त है। तीसरा सिद्धान्त यह है कि यह मध्यवर्ती वर्ग मिट जाय और उसे मिटाते हुए मुआविजा दे दिया जाय और चोथा सिद्धान्त यह है कि समस्त ग्राम्य जीवन का पुनसँगठन करने के लिगे, एक प्रकार से सनस्त सामाजिक जीवन का संगठन करने के लिगे स्थानीय

[थो 'स्टा नि सिवारो

ग्राम्य-सभाजो का पुनः प्रोतण्ठायन किया जाः, जिनके हायो में जीवन तबालन करने का जिनके जावार हो। पे चार प्रपुरा विद्वारत है कि निकके जावार पर इन बिल को ह्व-रेखा गा) हुई है और म सामता ह कि चारी ऐसे भिद्धान्त है जिनका किसी प्रकार से कोई निरोध नहीं कर सकता उँ यह समजना देवा गीर नो म्ही है। में देखता ह कि इस जिल का विरोध दो ओर से नो रहा है। वीनो दिलाओं से जिल तरफ से उसका विरोध हो रहा है वे दिलाघे ऐसी है जो परस्पर तिरोपो है, जिनका दृष्टिकोण भी परस्पर विरोधी है, पक्त दोनों ओर में इति विरोध किया ना रहा है। एहती वे हैं, जिनका प्रतिभित्ति हमारे लायक दोस्त रोपन जना पाहा है सी किया था, जिसे आप कहते ह मोशिलिस्ट पार्टी। सोशिव्स्ट पार्टी की ओर से इंग्ला बिगोध हो रहा हे ओर इसरा वर्ग है निमता पतिनिधित्व राजा ताहब जाधनपर ने एत के रोज के अपने भाषण में किया था, जिसे का जमीदार वर्ग काते है। ये दीनों दी ऐसे वर्ग ह जिनके दृष्टिके,ण परस्पर तिरोधी है । रन्तु ये दोनी इप । बच का तिरोध कर रहे े । स तो, अध्यक्ष मही-दा, नम्प्रता के साथ यह निवेदन कंपना चाहत। ह कि बहुत सीवने समजन के बाद मेरी ाक्य में यह नही आ सा कि ये दी वि तारी के छीग क्यों और किस कारण से इस िल ा निरोध कर रहे हैं। जहां तक सोतिशिट पार्टी का सम्बन्ध है उनमें थोड़ा आइचये भी होता है कि यह पार्टी इस बिल का है वे विरोध कर रही है। में तो समज नहीं पाया कि वह कोन सी त्रीज है निका विरोध किया जा रहा है। रोजन जमा साहब ने बो तीन घट भाषण किया परन्तु यह समप्त में न आया कि उन्होंने किस बात का विरोध किया। उतमे होन सी वृष्टि हैं जिसके कारण उन्हें विरोध करने की आवश्यकता पड़ी। आखिर इस बिल में है क्या दिस बिल में ऐसी बाते हैं जिन हा होना आज से वर्षों पहिले आवश्यक था। क्या है इस बिल में जिसके आप विरोधी है ? क्या आप जमींदारी को मिटाने का तिरोध हर रहे हैं ? क्या जाप किसानों को जो मालिकाना हक दिया जा रहा है उसका विरोध गर रहे है ? क्या आप बकाया लगान की डिगियों में किसानो का लेत नीलाम न होने पाने इसकी जो व्यवस्था हो रही है, सोर यह कि किसानों से बेगार न जिम जा। इसकी जो व्यास्था हो रागे है असका विरोध कर रहे हैं ? स्था आप हिमानो को अपनी भूगि पर सन प्रकार के प्रयोग करने का जो अधिकार दिया जा रहा है जसका जिलेख कर रहे हैं? क्या जाप सरकार और किसानों के बीच में जी मध्यवर्ती वर्ग रहा है, जी दूारी जीकमाई, कियानों की एपाई पर मोटा होता रहा है, उसके उन्मूलन का विरोध कर रहे हैं। इस चिल गें कता यो ऐमी बात है जिसको आप प्रमान है कि उसका विशेष करना आवश्यक है। (एक सदस्य-- अग्रेन का निरोध करना चाउते हैं) क्या आप किसानो से १० गुना लगान जने का विरोध पर रहे हैं और जमीवारों की कोई मआविजा न दिया जायइसका विरोध कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो यह पश्न हो सकता है कि जमंदारों को भुआविजा न दिया जाय लेकिन में जानता है कि जभीदारों को मुशावजा देने की बात आपने और हमने, मन ने बहुत पहिले ही रवी कार कर ली थी। हमारे रोजन जना खा गाहब ने कहा कि इन बेंबो पर बंडने से आपकी तिनात बदल गरी, निगात बदल गरी। में तो सन्त्रता हूं कि इन बेंचों पर बैठने वालो की न तो तथिगत ही नवको और न निगाह ही बदली। हमने जो बनाय सन् १९४६ में लड़ा या और जिसका पैनीफेस्टो हमारे सामने है। उसी चुनाव के मैनीफेस्टी पर हमारे सोशिलिस्ट बग भी लड़े थे और इस भवन के सदस्य थे। उसमे, उनके मंतव्य में यह लिखा हुआ है कि हम जमीं गरी प्रया भिटायेंगे। माथ ही साथ पह भी जिला हुआ है कि मुर्आवजा देकर जेमीं दारी प्रथा गिटायेंगे। अतः जय तक हम इस भवन के सदस्य है और इन बेंबो पर बैठे हुए है तब तक उती गतव्य के जनुमार काम करेंगे। जो आज इसका विरोध पर रहे हैं वे भी इसी मंतक्य के अनुगार आपे थे। हम अगने वचन की पूर्ति कर रहे है, हमारी बिंड नहीं बदली है, हमारी नीनि नहीं बदली ह, हमारा मिजाज नहीं बढ़ला है। हमने जो जनता से वायदा किया कि मध्यवर्ती वर्ग को विटारेगे, उनको पूरा कर रहे है। अपका विजाज त्रहरा होगा, आपने अपनी नीति बदली होगो, आपने अपना द्ष्टिकोंण बदला होगा ओर मैं नम्ता के लाथ निवेदन करना चाहता हं कि रोशन जना खां माहन ने अपने विवार बदले, तब कुछ बदल दिया, टोपी भी बदल दी। आदावअर्ज। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह देखता हूं कि अभी कुछ दिनों पहिले ही धार्मिक कट्टरता ओर धार्मिक उत्पाद के आधार पर चलने वाली राजनीत, जो धर्न और जाति के ऊपर दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को स्वीकार करती थी, वह राजनीति और उन राजनीति से परिपोषण पाने वाली मुस्लिम लीगिजन और मार्निजन के बीच मे बड़ी भारी खाई थी। एक धर्म और संप्रदाय को लेकर चली तो दूसरा धर्म हीन, ईव्वर होन राजनीति और सनाज नीति तथा वर्शन का समर्थक है। दोनो के बीच की खाई स्पष्ट है। पर इस गहरी खाई को कल के मुस्लिम लीगी रोशन जमां साहब ने आज के मार्किस्ट बन कर एक ही छ्लाग मे जिस प्रकार पार किया है उसे देख कर तो ऐका लगता है कि आज अगर समुद्र लांघने वाले हन्मान जी होते तो खा साहण की उद्यल-देखकर हार जान जाते क्योंकि उन्होंने समद्र के लाघने मे इतनी हिम्मत नहीं। दिखाई थी। जितनी इस खाई को लांघने में दिखाई गई। हमारी तिबदत नहीं बदली, हमारी निगाह नहीं बदली लेकिन आपकी तिबयत और आपकी निगाह जरूर बदल गई है। हमारे सोश-लिस्ट बंध यह। से चले गए। कांग्रेम से इसलिये चले गए कि कांग्रेम ने यह प्रस्ताव पेश किया था कि एक दल के अन्दर दो दल नहीं रह सकते। वह भी यही स्वीकार करके यहां आये थे कि मुआविज्ञा देकर जमीदारी समाप्त की जायं। मआदिजे के संबंध में फूर्ली मह साहब ने आंकड़ों से सब सिद्ध कर दिया है और इस प्रकार उन्होंने यह काम पुरा किया है।

में आप से कहता हूं कि उस रोज जब रोजन जनां खां साहब बोल रहे थे तो छोटे जमीं-दारों के लिए बार-वार आप कह रहे थे कि ढ़ाई सौ रुपये से कम वाले बेचारे जमींदार। अप आप मुआविजा का विरोध करते हैं, तो किसको मुआविजा न दे। ढ़ाई सौ राया से कम माला जारी देने वाले जमीदार २० लाख में से १८ या साढे १७ लाख है जिनकी हिमायत आप भी कर रहे थे। क्या ढ़ाई सौ से कम रुपया वालगुजारी देने वालों को पुआवजा न दिया जाय ? क्या उनकी हत्या की जाय ? क्या उनको भूखों मारा आपके मुआविजा की ज्यादातर रकम और लम्बी चौड़ी रकम उन्ही के पास जान वाली है, फिर आप मुआविजा में किस चीज का विरोध करते हैं। आपने अपनी नीति छोड़ दो है लेकिन हम अपनी उसी नीति पर कायम है जिसके बल पर हमने जनता से बोट प्राप्त किया और आज यहां मौजूद है। फिर मै यह भी आप से निवेदन करना चाहता हं कि जब ऑहसात्मक और रक्नेहीन ढंग से हमें एक क्रांति को चरितार्थ करना है तो उसमें किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई दुर्भाव और कोई विद्वेश रह नहीं सकता। हमने गांधी जी के द्वारा यही शिक्षा पाई है और गांधी जी ने हमें यही मार्ग बतलाया है। आज इसी मार्ग पर चल करके हम इस महान सामाजिक क्रांति को पूरा करना चाहते है । फिर हमारे सीशिलस्ट बंध किस चीज का विरोध करते हैं। अगर उन्होंने यह मांग की होती कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाय और मजदूर की तरह से किसान उस पर काम करे जैसा कि हमारे बुजुर्ग हसरत मोहानी साहब ने उस रोज अपने भाषण मे कहा था, तो बात मेरी समझ में आती। अध्यक्ष महोदय, में आप से निवेदन करता हूं कि उनकी यह हिम्मत नहीं है कि वह जनता के सामने राष्ट्रीयकरण की बात रक्ले। अभी वह यह कह कर जनता के सामने खड़े तो है कि १० गुना मत दो, हम आये गे तो तुम को मुफ्त में जमीन दे देगे। यदि वे राष्ट्रीयकरण की बात करें तो उनको भागते भी न बन पड़ेगा। इस प्रान्त के किसान राष्ट्रीयकरण के पक्षपाती नहीं है। वे मजदूर हो करके खेतों पर काम करने के लिये तैयार नहीं है। वे भूमि का स्वामित्व चाहते है। हम भूमि के राष्ट्रीय-करण में विश्वास भी नहीं करते हैं। हम स्वाभाविक मार्क्सवादी नहीं है। भूमि के राष्ट्रीयकरण की सारी लीलाये हमने रूस में देखी है। आपने यदि वह मांग की होती [श्री करा गपति तिवारी]

तो आपका निरोव मेरी सगत में आता। प्रन्तु आप कहते क्या है, जमीन का बटवारा फिर से हो। जमीन का घटवारा फिरशे फैसे हो ? दो या तीन एकड़ की जहां औसत होल्डिगज हों और ज्यादतर होल्डिंग्ज इसी तरह की हों, तो फिर से ाटरारा करने के माने यह होंगे कि बहुत सी दो दो तीन तीन एकड़ याली जापीने तो ; करके पड़ी की जायं। इस तरह १२ या १५ एकड़ की होल्डिंग्ज बनाने में नहत से आदमी पोत से जलग किये जायं। आप क्या इस बात को संभव गगमते हैं और गाप क्या ऐसा करने की राय हैते है ? केवल विरोध करने के त्रिये एक ऐसी गात कड़ा। जिएकी कोई बुलिशाद न हो कहां तक ठीक है, इस तरह की बात करा। कता तक मुना तिब है और कहां तक उचित है। में अपने सो प्रलिस्ट भाइयों से नि रेन करूगा कि उन की वह मनोवृत्ति की उनकी यह जेहनियत उनके समरत राजनीतिक और िायासी जीवन की समाप्त करने जा रही है। दह अपने राजगीत की ओर रिट्यात करें। सोरालिस्ट पार्टी स्वयं इय बाप पर विचार करे। दुर्भाग्य है इस देश का कि एक ऐसे युग में हमारे ऐसे लाय होस्त जो सोशिलिस्ट पार्टी में मोजूर है देग के निर्माण में सहायक हो सकते थे उनकी सारी मनोवृत्ति विश्वंसातमक और निरोधास्त्रक हो गई है। में निवेदा करूं आप से कि उनमे राजातिक विरोध की मनोबुत्ति पैदा हो गई है। अगर हम कोई सही चीज भी फहे तो उसकी मुखालिका करना, एकमात्र जिरोध की राजनीति आप ही चर पड़ी है। आप ही राजनीति में कीई दस नहीं हैं। और इस प्रहार की राजनीति आगके नगस्त राजनीतिक जीवन को गयाप्त कर रही है। इसी प्रकार मनोवृत्ति की लेकर आपने ट्रेंड युनियन कांग्रेन में घनने की की िक की, लेकिन उहा से निकाल दिये गए। मजदरों का पार आपके हाथ से गया। इंडियन ने तन कट्टेड पुरिधन कांग्रेप को तो आपने कांग्रेस हाई तमांड की संस्था कह कर उसता निरोध किया और गीच में ही लटके रह गए। इप प्रकार की मनोवृत्ति को लेकर नियान सम्मेलन का आपने निरोध किया और उत समय आपको नागा पहाड़ी ओर गोआ क्रांति चली आती रिखाई पड़ी। इस प्रकार की राजनीति को लेकर आप विद्यापियों के क्षेत्र से निकाले गए और इस प्रकार की राजनीति को लेकर जाप कियानों के क्षेत्र ने निकाले जा रहे है। आप बोड़ लीजिए बो चार रोज तक । आज कि मन पत्रसने लगे है कि को कि सिनों का हिने बो है। और बावजूद आपकी तमान कोशिशों के और गलत प्रचार के आज इस प्रान्त के किसान मुनिधेरी का रुपया जना करते ना रहे हैं। जनक्य उत्तर पाप क्षया कर है और बोरे-घोरे रहम आ रही है। आ इ कि प्रवारह हा करे किने में तो पनी पर हिलाई नहीं पड़ रहे हैं। ओर जा उन्होंने प्रवार किया तो सीचा कि उन्हों के प्रवार करने के जसर से मायदेषे गा हुए का विषे रहा है लेकिन अब यह असर खनन हो गगा है और उन सोज-लिस्टों की बान की कोई नहीं सुनता। तो मं नम्प्रता के जाथ गाम से हा बात को निहेदन करूं कि मभी इपहों जानते हैं कि इस जमींदारी को निटा देने से किमानों की गरीबी दूर होने वाजी नहीं है। कोन सा ऐसा खुढ़ है जो यह सगमता है कि आज जमी-बारी को निटा देने के याय कल कियान स्पर्ग में गहुंत्र पायेगा और उसकी नारी गरीबी दूरहो जाएगी। किगानों की गरीबो का कारण तो कुछ दूसराही है। ओर गह जमीदारी उसका एक अंग है। इसके मिटाने से गरीबी दूर हो ने वाली नहीं है। कि पानों की गरीबी दूर करने के दूररे रास्ते हैं। किनानों की गरीजी तब दूर होगी जब भूमि पर लहा हुआ मनुष्यों की संख्या हायोझ कम हिया जाय। अंगेजी राज्य में हमारे मुल्क के लोगों के लिये न कोई रोजगार रहा, न कोई व्यवसाय रहा, न कोई कला कीशल रहा, न कोई उद्योग रहा और न कोई दूसरा काम रहा। अंग्रेजी राज्य में इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन का सारा बोझ भूमि पर लढा है और लढा हुआ बोस ही आज हिसानों की गरीबी का कारण है। उन भी गरीबी दूर करने के लिये उस बोझ को हल्का करना पड़ेगा और उस मोझ को हका करके पुल्क को दूसरा मार्ग अपनाना होगा। जमीन कोई रवर नहीं है जो लींच कर लम्बा कर दिया और स्नेकर बांट दिया। सर बोझ को हत्का करने के

लिये हम हर जिले में डेबलपमेट योजन चलाव, ग्राम व्यवताय किया जाय, कुटीर व्यवसाय उत्पन्न किया जाय और जीवन के नये उपाय निकले िससे मुन्क को नया मार्ग मिले और लोगों को रोटी कमाने का दूपरा ढंग मिले। आज जो लोग भूमि जीत रहे हैं उस भूमि पर वहीं रह जायं और उनकी गरीबी दूर हो जाय उसके लिये तरकार प्रयत्नशील है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जमीं होरी निटाने से क्या फायदा होता? जमीं—दारी इतिलये नहीं निटाई जा रही है कि इतसे किसानों की गरीबी दूर हो जाय। यह तो इमलिए निटाई जा रही है कि उसके कारण जिमानों पर जो बोझ लदा हुआ है, किसानों के सर पर, और किसानों की रीढ़ की हड़ी जो बूर हो रही है वह दूर हो जाय। इससे कई फायदे किसानों को और है। इससे जिमानों से हरी बेगार्र लेना दक जायगा, कि गानों को मुर्गा बनाना उन्द हो जाएगा। मै जपने उहा की एक सिमाल दूं। हनारे यहां के एक जमींदार पाउब ने एक कितान के ऊपर जाया किया जान का। उन्होंने ९५/९६ पाई का बावा किया। आप एरा गीर करे कि ९५/९६ पाई दाया लगान के लिये उन्होंने कितान के ऊपर ४५ रुपये खर्वे की डिग्री धरायी। अब आप सोवें कि यह क्या बात हैं? इन चीज को मैने अवती आंटों से देखा है।

श्री प्राग नारायण—-एक बात मै आपसे कहूंगा कि यह जो उटाहरण आप दे रहे हैं तो बहुत सी बाते ऐसी हुई हों, यह ठीक हो मकता है लेकिन ऐसी कोई जियाल मेरे यहां नहीं है।

श्री कमल पित तिवारी--में आपसे यह कर्ना बाहता हूं कि जनोशरी के पिटाने से किसानों का फायदा होगा। उनकी गरीबी दूर होगी कि नहीं यह कोई नहीं समझना लेकिन किसानों का जो अधःपतन हो गया था, उनका जो सानाजिक अनघटन हुआ, उनकी जनीन छीनने के लिये बेदखली से, बाकी लगान की उगरी की दिलानी से, हरी बेगारी से, अवनी कमाई का ज्यादा हिस्सा जी दूसरों को देता था उससे उसकी जरूर रक्षा होगी। और इसके लिये ही जमीदारी की संस्था को भिटाने की अवश्यकता पड़ी है ओर एक ऐसी अनुवयोगी भूमि व्यवस्था को जो साम्। ज्यवाद की नीवको जजबूत करती है उसके मिटाने की आवश्यकता हुई। ताकि किसान स्वतन्त्रना के साथ मनुष्य जीवन का उपयोग कर तकें, वह भी लानाजिक जीवन में कुछ हिस्सा ले सके और देश के निर्माण नें उसका भो उचित हिस्सा हो। इसलिये उसको निटाने की आवश्यकता हुई। फिर आप कैसे इस चीज का विरोध करते है। से आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और खासकर सोक्रिस्ट भाइयों से यह कहना चाहना है कि आपकी रिएक्कनरी मनो-वृति हो गई है। कत की पितान हमारे सामने है। हम उसको भूले नहीं है कि पिछले जनाने ने यहां पर क्या दुआ। आज २० वर्ष हुए कि वहां पर फलेक्टिवाई जेसने ना प्रोप्राम चलाया गया था किन्तु अगर मैं गलती नहीं करता तो वहां पर ६२ प्रतिशत भी इतन क्रीनों के बाद सफ उना प्राप्त नहीं हो सकी है। इसके सिवा कौन नहीं जानता कि रूस की यह योजना खुन से सींची गई। इस योजना की पूरी करने के लिये ही ७० लाख कुपक मार डाले गए। स्वयं स्टालिन ने गलती मंजुर की थी और लिखा था कि इनफोसटाइन कितना घातक होगा अतः घीरे चलाना उचित है। सन् १९२१ ई० विद्रोह-के बाद रूप में ओर नई इक़ोनामिक पालिसी चलायी गई और उपके द्वारा राष्ट्रीयकरण भूति की बात लेनिन ने ही छोड़ दी। उसको आप देखे। आपके देश में यह एक अपूर्व अचीवमेश्ट होने जा रहा है कि जिससे हम एक अनुपम लक्ष्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं। सैकड़ों वर्षों से एक प्राचीन संस्था, एक प्राचीन मूमि-व्यवस्था आज आप के देश में समाप्त होने जा रही है जिसके अन्दर करोड़ों नर-नारियों के जीवन का प्रश्न है, करोड़ों दबे हुए, सताये हुए किसानों का प्रश्न है। आज हम उनके बोसे को सम्बद्धत करने जा रहे हैं। हम किसी को दुखी नहीं करते है। बहुन आतानी से इसकी समाप्त करना चाहते है। आप समझते हैं कि यह छोटी चीज है और फिर इसका विरोध करने की चेष्टा करते हैं।

श्री कभ गपति तियारी

आप सानते ; कि आज भारतवर्ष में ती नहीं भिष्तु सगस्त एशिया के अन्दर आजभिम व्यास्ता नो की करों की त्यन्त नान्धकता हो गई ै। की मिलाग की क्या दशा हो गाँ देवता का पान भागिक तानों। भी गाँ भूमि वत्यस्था को वे लोग कभी सलझ। नहीं सके । हगारे देश के अन्दर विदेशी राज्य ने कभी इस प्रश्न की सुप्रहाने की काँकिश नहीं की कित अब इस प्रशा की अवानों के साथ सुन्याने की की निव की जा रही है और तामका सके जिल्लामा गरते है। आपका विरोध में आही सह कहता है कि देश के लिये स्निकर माजिल नहीं होगा। में मोगिकिस्ट बन्धशों से लियेदन करना चाहता ह कि वे उस प्रक्ष पर शान दे और जिलार करें कि पान इन देश के जन्दर भीन देवयस्था को ठीक रूप से नति स्ताराण गरा तो हमारा देन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अभी शास्ति है । । अंग्रगर नहीं हो सकेगा और बहुत से स्झार जो यहा पर होने जलरो है वर गरा हो सकेगे। पा देश के जिये बहुत नहीं भारी बात है। में आप से यह निवेदा करना ह कि जिस चीज की एतने रवन गत के पाद भी रूस २० वर्ष के अन्दर भूमि व्यवस्था हो गुण्या न ग सागाई उप भूमि ज्यवस्था हो नही सरलता के साथ बडी गोन्ति और अग्निसा है साथ गुज्याने हा माहा आया है। उस भृति व्यव-स्था को । ज्याने का गढ अपूर्व अवसर हमारे और आपक सामने हैं। इतके िये व्यर्थ का विशेष करके जनता ने भूम पेदा न की जिए। केवा इतिलगे कि आपकी विरोध की नरोत्रति हो गर्दे आप उपका बिरोब करते है। पह मुनासित नही है। जहां तक उनारे जवीरार भारणी का नवाक है में उनके विरोध में क्या कहा में तो यह सपत्रता ह (ह पवि थोड़ो सी श्रृंद्ध उनके अन्तर सगतने की होगी तो वे⊦ इस बात को स्वी-कार करेंगे कि जमीवारी प्रथा के अन्त होने में ही उनका कल्याण ते।

भातनीय उपाध्यक्ष मही इय, भ एक छोटा जमीदार भी हु और में आप से निवेदन करना बाहता ह और आर के द्वारा अपनी सरकार से फेहना बाहता है कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस बिल के सिर्शिसले में और झने र को पाहे साल दो साल चलता रने ेकिन ईश्वर के नाप पर एक आर्जनिन्म निकार ने जिनके जरिए से यह जमीदारी को प्रथा यदि आज नहीं तो कल अपन्य समान्त हो जाय। ओर यह बोझ हमारे सिन से उत्तर जाय। मं आप से कहता हू कि यह प्र्या आज जगीदारों के िर पर हेर वेट है, एक दार का बोझ है ओर मूर्ग का भार है। भरे दोस्त जमीदार इस चीज को अच्छी तरह से समझते होगे। जार्ज आग के जिए सभाज म कोई स्थान है और इस प्रश्ना को निटाने में ही आपका कत्याण है। जब किसान भूगिधर होगा और माजिक जीत का होगा परती का गालिक गाय-सभा कुओ की नालाओं की आबादी की मालिक गाय-पभा होगी ओर आप को बसूली नही होगी तो आप घर से निकाल कर कहा तक भालगुजारी देंगें। प्र राव अवनी कहता ह कि कियानो से असूली न रोने पर ३ साल से अपने घर थे मालगजारी जगा करता हूं। अगर तार ऐ।। कर दे और आर्ड-नन्स निकाल यें तो भ तो आर का चिरकणी होऊगा और आप इस तरह से हम को नसलन दरनसलन बरबादी से जल्द ही बचा दीजिए। अगर कलेक्टर साहब ही वसूली कर लिया करे और अपने अहलकारों के जरिप्रे से कराते और मालगनारी जमा कर लिया करें और अगर कुछ बच जाया करे तो हमें दे दिशा करे और अगर न उचे तब भी हम बहुत प्रसन्न होगे। ओर हमारी जान इस तरह से छोउ वे। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जमीदार इसका क्यों विरोध करते हैं। यह तो एक ऐसी व्यवस्था है जो मृत हो नुकी है और उसकी केवल अन्त्रोध्टी बाकी है और उस मर्वे को दफनाना ही रह गया है और मुदे को चिपकान से क्या कल्याण आप का अब हो सकता है। यह तो युग का प्रवाह र और काल की पुकार है ओर समाज की बदली हुई व्यवस्था है और उस के बिरुद्ध कोई जा नहीं सकता है। हमारे मित्र राजा साहब जगमनपुर ने कहा था कि इस नरह में जमीतारों को बरबाद किया जा रहा है और उनसे बदला ित्या जा रहा है।

मेरे एयाल मे उनका एपाल गलत है। यह बिल जमीदारों से बुराई मान कर या कोई दुश्मनी के कारण से नहीं लाया जा रहा है और न कोई बढ़ले की भावना से ही लाया जा रहा है और न यह ख्याल ही है कि अगर जमीदारों में से किसी ने दभी कोई अत्या-चार किए है तो हम इस तरह से मा सुद ब्याज के उन ने यमुठी कर रहे है। मैं आप से कहता हूं कि यह बदली हुई व्यवस्था है समाज की, इतिहास की नई धारा और अवाह है, एक नई तरंग है सामाजिक जीवन में एक हिलोर है और यदिआप इस अनदरत ओर कालात्मा की धारो और प्रवाह को रोकने का प्रयत्न करेगे नो विध्वंस आप ही का होगा। और दुनिया की कांति के इतिहास में भी जब कोई एक शाया किक व्यवस्था सराब हो जाती है तो उसे बनाये रखने की चेट्टा कान्ति का कारण और चिन्ह हो जाती है। आज देश की स्वतन्त्रता आने के बाद एक नया दृष्टिकीण और दातादरण यहां पेदा हुआ है । अब पुराना सामाजिक संगठन दूर होगा और हनारी आप की चैंप्टा उसको रोक नहीं सकती और उस व्यवस्था का उन्नूलन, सत्यानाक्ष अवश्यमभावी है और पूर्णतः अनिवार्य है और उसका विरोध करना तो वास्तव मे अपना ही विरोध करना है ओर अपने हितों का विरोध करना है। इन दोनों विचार वालों का विरोध जिनका मैने आपसे जिक्र किया न कतई नहीं समझ सका और मैं दोनों से नम्प्रता के ताथ निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त की जनता का चाहे वह जमींदार हों या किसान सब का कहरीण इली धात से हैं कि इस बिल को शीघ पास होने दें और जन्द से जल्द इस को स्वीकार करें और देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव डालें और सब का जीवन सुली हो, सब का जीवन समुश्रत हो और प्रान्त के करोड़ों नर-नारी किसान और मजदूर इज्जत के हाथ मान-वता पूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

*श्री प्राग नाराय ग--जनाब डिंग्टी स्पीकर साहर, मेरेपहले आज दी साहबान ने अपनी स्पीचों (भाषणों) म हर छोटी सी बात को आप के सामने साफ़ कर दिया है और बतलाया है कि इस बिल में अभी और क्या-क्या होने की जरूरत है ओर उससे क्या फ़ायदा होगा।

अभी त्रिपाठी जो ने भेरे खशल में सबा घंटा लिया है ओर शायद ही कोई बात छोड़ी हो। मैं आप के भवन का कम में कम समय लेना चाहता हूं। क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि अभी बहुत से लोग इस बात के ख्वाहिशमन्द है कि वह इस बिल पर अपने ख्यालात जाहिर करें। क्यों न हो, यह तो एक ऐसी चीज के वारे में विल है कि जिस पर सुद्दों से और अमें से हमारी रोटियां चल रही है। अब वह खत्न की जा रही है। मैं तो अपने माल मन्त्री से यह प्रार्थना कहंगा कि जो वक्त इस बहस के लिये दिया गया है वह बहुत कम है। अगर एक दिन और दे तो जो लोग इसमें बोलने के लिये उत्सुक है वह भी अपने खयालात को जाहिर कर सकेंगे।

माननीय माल सचिव-अव यह बहस बजाय आज के कल खत्म होगी।

श्री प्राग न।र। या — मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर लिया। अब मैं यह कहूंगा कि हम लोगों में तो खराबियां मौजूद है। इन्हों खराबियों की वजह से यह दिन आया है। जरूर इसको तबदील किया जाय। यह ठीक ही है। आप यह देखें कि जो मुआविजा आप हम लोगों को दे रहे है वह ८० फी सदी कम करने के बाद २० फी सदी दे रहे है। आप ने यह जो ८ गुना तजवीज किया है यह भी कम नहीं है लेकिन इसमें जो चीजें आप निकाल रहे हे अगर वह भी शामिल कर दी जायें तो अच्छा है। मैंने जो स्पीचेज यहां सुनी है उसे श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी और दूसरे साहबान ने यह कहा है कि मुआविजा ४ लाख से ज्यादा न हो। बाज लोंगों का यह ख्याल

[श्री प्राग नारायण]

हैं कि मुआयिजा ही न हो। मेरे एयाल में बाजार से जो चीज खरीदते है ती हमेगा उस की कीमत अदा करके जसको लेते हैं। अगर आप किनी दुकान पर जाथे ओर किसी चीज को एठा कर बने तो क्या यह मुनाति है, क्या गहुआप को यह बीज हे जाने देगा ? हम लोग न आप का मुकाबिला करेगे और न करने के लिये तथार है। में बड़ी खुशी रे इस बात को मानता हूं कि हमारी मोजूदा सरकार जो है उसकी नीति ओर उस के प्रवालात ठीक तोर पर कार्यम रहे ओर भूने उन्मीद है कि कार्यम रहेगे। भेरी बगल में एक साहा बठे हुए ह सोक्षित्स्ट , उनको मोका नहीं मिला सोच रहे है और भाषण करेंगे। आप जो जोउं, ए० एक, रसूल कर रहे ह उत में ११ ट्जार आद नी काप कर रहे है और उस पर प्रान्त भर में हरीये एक करोड़ सांगा सर्च तुंजा ह। जड़ तक १२ करोड़ के क़रीब आप ने बसूल किया है। आप ने यह एकान िया था कि हम ३० दिपम्यर तक उस को बगूल कर लेगे। आप का जो टोर्बेट है वन पूरा हाते दिवाई की देता। हां अन आपने पह के ला किया कि अगर्ल फाल तक रूपया मिल जावगा। मेरा साभाव ह कि नापव अभी आप यह कहेंगे कि रबी की फसाव जा गी हे जुरा उनका इन्तजार धर है, तब तक गाका ले ले। भी हा तो आप लेते जायगे। भरा ख्याल है कि जितना नोका आप छे छे उतना ही गच्छा हो। म भी गह चाहता हू कि आप इसको जल्द खत्म करें। रोज २ आ। की पार्टा के लोग हर जगह यह कहें कि साह्य हम खत्म हरने जा रहे हैं, हम खत्म करने जा रहे हैं, यह तो कोई बहुत मुनासिब चीज नहीं हैं। हर जगह आगे यह देखते हैं कि आज ऐ।। हा पटा है जैया कि पुराने जमाने में होता था कि अगर मरीज मरने के करोत्र होता जा तो उपको हरी उठा देने थे। यह तो ऐसी बीज है।

अम् मुआविजे का मागला है। मुआयजे पर तो जाकी तरह से गार करी जाको देना जाहिए। इसके साथ—पाथ आप वह वेलेंगे कि जो रक्ल और कालेजेज, मन्दिर और मिस्जिव जिन पर लोगों ने अपना एपथा उमाथा है, अपनी जामवाद वाक की है उनका भी आम को इन्नजान करना बाहिए। यह जिसके मद्मे पर्नेगी। अगर पर्मित उनका इन्तजान कर दे तो बेजा नहीं है। हमं लोगों ने उन पर करणा लगापा, जागवाद उमाई, हमारे बुजुर्गों ने उनमें एपमा लगामा ताकि अमन को फायदा हो। सो पह स्टेट की जिन्मेदारी है कि उनकी देख—भाल करें। अगर रहें ऐसा नहीं करती सो क्या अन्छा नतीजा होगा? हमारे खमल से तो दिल से प्रभाव नहीं किलेगी।

इति है गाय २ आप यह देखिए कि हमारे बजुगों से यह प्रया चली आ रही त कि जो लोग उमारे यहा काम करते रहे हैं जनको माफिया दी गई है। वह माफिया द्रालिय दी गई थी कि वे काम करते थे। अभी भी ऐता चला जाता है कि जो काम भी नहीं करते हम लोग उनसे लगान नहीं लेते। तो द्राक लिये पवर्नमेण्ड को चाहिये कि उन लोगों का ख्याल रक्खे।

वूसरी चीज हैं लेगर की। आप जानते हैं कि किपी का काम उगरे मजदूर के नहीं चलता चाहे जितनों भी यह पति। करें। अभी हमारे यहा गशीनें जादा नहीं है कि हम मशीनों को लेकर पति का काम अच्छा से अच्छा श्रु कर ये। मशीनों की जब ज्यावती हो जाएगी तो यह चीज हो सकेगी। लेकिन अभी आप यह कहें कि खेत अपने आप जीतिए वरना निकलिये तो यह कहां तक ठीक हो सकता है। हमारे माल मंत्री साहब ती तुर जमोदार है, अब भूमिधर बन गए हैं। चीज वही हैं नाम बदल गया है। आवमी यही हैं।

अन में आप से एक योड़ी सी बात और अर्ज करूंगा। जहां तक मेरी इन्कार्मेशन (सूचना) है वह यह है कि हमारे यहां एक तहसीलदार साहब है। उन्होने अपने भाषण

में जो अल्काज इस्तेमाल किये हैं वे मेरे खयालात से तो मुनासिब नहीं मालूम होते। वह जरूरत से ज्यादा अपनी त्वायत्टी (भिक्तभाव) दिखला रहे हैं। हमारे मंत्री साहब मौरांवां हो आये, हमारे प्रीसियर साहब भी जहां-जहां गये उन्होंने यहबात बित्कुल साफ़ कर दी कि हम कोई जबर्दस्ती वसूली नहीं करना चाहते। किसान की खुकी की बात है कि रुपया है। लेकिन हमारे तहसीलदार साहब ने एक जुमला यह कहा कि हम जो रुपया तुम लोगों से लेंगे वह जमींदारों की कब में लगायेंगे, उनके कफ़न में लगायेंगे।

श्री रघुबीर सहाय--किसने कहा?

श्री प्रांग वाराय आप—हिनारे यहां एक तहसीलदार साहब हैं उन्होंने कहा। हमारे यहां एक एस० डी० ओ० साहब हैं मैंने उनसे भी कहा था और शायद आप पेपर (अखबार) में भी यह बात देख लेंगे। आप लोग अपना काम की जिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसी बातों नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातों से आप की नेकनामी नहीं होगी, बिक्क बदनामी होगी। बेरी तो आप से यह दरख्वास्त है कि आप इसकी तहकी कात कर लें।

माननीय माछ सचिव—क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस तहसील के तहसील-दार ने ऐसा कहा?

ंश्री प्रांग नारायण--यह पुरवा के तहसीलदार साहब हैं जो हम लोगों का ही जिलाहै। अब मैं आप से यह कहुंगा कि आप हम लोगों को जो मुआदिजा दे रहे है वह नक़द रुपये की सूरत में होगा। आप हमको नक़द रुपया दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कभी किसी के पास रुपया नहीं रहता। आप कुछ भी दें, कितना ही रुपया किसी को दें वह सब हमेशा खर्च हो जाता है। खर्चा ऐसी चीज है कि रुपये से लोग खाली हो जाते हैं। ज्यादा मुनासिब तो यह होगा कि आप ऐसी फ़ैक्ट्रीज या मिल्स खोलें कि जो मुल्क के फ़ायदे की भी हों और उसमें से हम लोगों को भी हिस्सा देकर हमको उसमें लगा दें और हम लोगों के लड़कों को भी लगा दें। हमारे मुताल्लिक़ीन भी बहुत से होंगे। उनका भी खयाल रखना जरूरी है। इस तरह से कारखाने वगैरा खोलने से बड़ी गंजा-इश हो जावेगी। हम को भी उसमें से हिस्से दे दें। अगर आप यह कहते हैं कि बांड मिल जायेंगे तो बांड तो आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा दो या डेढ़ फीसदी का सुद पदा करते हैं। उससे कोई बसर नहीं कर सकता है। हां, यह जरूर है कि सुबह से शोम तक शायद एक बक्त ला ले। महंगाई इतनी ज्यादा है कि अगर हरेक मेम्बर से दरियापत किया जाय तो आप को असली हालत महंगाई का पता चल जावेगी। या जो हमारे बहुत से लोग महकमों में तनख्वाहें पाते हैं उनको आप देखिए कि पहिली तारीख नहीं आती है और उनके ऊपर क़र्जा सवार ही रहता है। अब ऐसी महंगाई के जमाने में और भी ज्यादा मुक्तिल है। अब गवर्नमेंट ने तो ब्लैकमार्केटिंग को दूर कर-ने की कोशिश की मगर यह नहीं जाती। क्या गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है कि हम लोंगों को और छोटे-छोटे आदिमयों को पेट भर खाने को दे ? उसकी चाहिये कि ऐसा उपाय करे कि हरेक का पेट भरे कम से कम दो वक्त नहीं तो एक वक्त ही सही। ब्लैकमार्केटियर्स के लिये आप कितना ही सख्त क़ानून बनायें, उसमें कछ बेजा नहीं है। आप देखते हैं कि शक्कर भरी पड़ी है, बोरियां की बोरियां जा रही है। लेकिन जिनके पास पैसा है, जो मालदार है या जिन्होंने खूब रूपये कमाया है वे तो खरीद सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वे वेचारे नहीं खरीद सकते हैं। उनके लिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वर्गर शक्कर के चाय पी ले या किसी को अगर गुड़ दस्तयाब हो तो वह ऐसा करे कि गुड़ से ही अपना काम चलाये। अब इसके फ़ायदे या नक्सान डाक्टर लोग ही जाने कि क्या होगा।

श्री प्राग नारापण]

में तो यह समझता था, जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो गया था, कि जब उससे एमर्ज (पाहर) होगा तो बहुत इम्प्रूव्ड (मुधरी हुई) शक्ल में नजर आवेगा। अब कोई खास बात तो नजर आती नहीं। इतगी जल्दी की गई ह कि चार बैठकों में ही इस इतने बड़े जिल को खत्म कर दिया गया है। सालूम यह होता है कि यह बिल बहुत जरूरों है ओर जया कि अभी त्रिवाठी जी ने कहा था अगर लाग जमीदारों को आंडिनेस के जरिये रान्म कर दे तो ज्यादा अच्छा हो। हवारे रायाल से आप लोग बड़ी ही गल्ती कर रहे है। मुद्दा से शाम तक चारो तरफ से गालियां खाते—दाते हम लोगों। को दिन बीत जाता है। यह तो गवर्नमेन्ट का कसूर हे हमारा तो है नहीं।

शव आवने छोटे जमींतारों के पात जाश से ज्या है दें। वंश ता तील बीधा आराजी दी। उपको यह बटाई पर उठा देता था। बटाई पर उठा के गाने यह थे कि उनकी परविदा और जिन काश्तकारों को वह देता था उनके बच्चों की परविदा होती थी। यहां अन कोई सुभीता नहा दिवलाई देता है कि क्या होगा।

त्मूल्याची का तरीका आपने यह रचा है कि गाय में में किसी ते भी पकड़ कर धसूल कर लिक्षा जाय। जगर हमने अपना राया सर्व कर उाला तो आप हमारे ऊपर जो रिपया है उसको दूपरों ने क्यों कर वसूल कर महते हैं? यह कहां का इन्साफ होगा। गवनमें को चाित्ये कि कम से कम इन बातों को भी तो देखें कि तसूल करने का तरीका क्या है? आपकी गवनमें हैं और आपके हािकम और अहकामात है। आप तो बाक्षई आर्डिनेंस के जिर्ये से जो चाहें वहीं और जैसी चाहें वैसी ही हुकूमत कर रहें हैं। आप ने एक आर्डर भेज विया कि साहब, १७१ वन्द और १८१ वन्द । इस हुकम का कोई दावा नहीं है, कानून में हो तो कोई दावा करें और इसकी चारा—जूई हो और पैरवी हो लेकिन यह कुछ नहीं होता क्योंकि आपका हुक्म है तामील करेंगे। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि सह लियत के साथ बसूल होना चाहिये। ऐसा नहीं कि जो चोर है वह तो भाग जाये और जो भला आदमी है उसकी पकड़ लिया जाये और उस से सारे गाव का वसूल किया जाए।

अब आप जमीं वारी खत्म कर रहे हैं तो जब तक आप उनकी किसी सिलसिले से या किसी क़ायदें से परयरिश नहीं करते तब तक उसका क्या नतीजा होगा? अगर वह सोशलिस्ट न बनेगे तो कम्यूनिस्ट बन आयेंगे। ययोंकि वह कुछ न कुछ तो रहेंगे ही। बहरहाल सोगलिस्ट तो अच्छे नहीं मालूम होते, वे किसी को पसन्द नहीं आते मब घबड़ाते हैं कि वह न जाने क्या करे।

इंगलैन्ड की हिस्ट्री यह बात बतला रही है कि जिस बक्त वहां जमींदारों खत्म हुई थी। तो वहां क्या—क्या भयंकर शवलें पैदा हुई और जमींदारों की क्या हालत हुई थी। उसकी खड़ी लम्बी तवारीख है और पढ़े—लिखे लोग सब जानते भी हैं। जो मोजूदा सिस्टम हैं उसकी बदलने की जरूरत हैं। हर काश्तकार को जंचा करने की जरूरत हैं। यह बात हम मानते हैं कि उनकी जरूर ऊंचा किया जाये। अगर नहीं करते हैं तो दुनिया में आप तरकी नहीं कर सकते हैं। काश्तकार हमारे हाथ है। उनका पेसा हैं ओर उनकी महनत हैं जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं। जिमके बदले हमारे पास मोटर हैं निजली के पंखें हैं। यह राज कुछ उनका ही हैं। हम भूले हुए थे। हम लोगों की गल्ती थी हम मानते हैं। हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अगर हम लोग उनको अपनाते तो किसी के गलाये दाल न गलती और जमींदार समझते कि काश्तकार हमारे हैं हम उनके हैं। वहां अगर आप जायें तो देखेंगे कि अब भी आप की दाल नहीं गल सकती है। जमींदार के पास इतने गांव होते हैं उनमें तो चार, दस—पांच भले ही शाकी निकल आयें। लेकिन ऐसी बात कभी नहीं ही सकती कि जितने हमारे गांव है वहां सब हमारे शाकी हों। हम

आप से अब भी कहते हैं कि हम यहां मोजूद ह और अगर आप वहां जाकर पूंछे तो आपको भले ही एक आध शाकी मिले क्योंकि हन उनका इंजताम करते हे उनकी तकलीफों को सुनने के लिये तैयार है। अभी हनारे मित्र त्रिपाठी जी ने कहा है कि काश्तकारों के लिये कहीं न कहीं से दरस्त दिये जाये। में भी इस चीज को चाहता हूं। क्योंकि वह अब तक हम से लकड़ी मांगते थे तो हम उनको दे दिया करते थे। हम लोगों के जो बाग़ात हूं उनको कायम रखे जाये। जो गत्रै चरेदिल लैन्ड ह उनके लिये हमारे दोस्त ने आप से कहा है हुमको आप खत्म करके आयने को वादरा किया है उनको पूरा कर रहे हैं।

आयमे इलेक्शन लड़ा दोर वायदा किटा था कि हम जत्म कर देगे। आय उन घायदे को पूरा कर रहे है। लेकिन जूरा करने के पहिले आपको तह देवना चाहिये कि श्या रीज वाजिब ै ओर क्या नावाजिव । नावाजित चीज करने पर कोई भी इन आजित में नहीं रह सकता।

अब आप रिहैबिलिटेशन ग्रांट दे रहे है। मं तो उसके मार्नः यह तमजना हूं कि मोहताजी ग्रांट। पालिसी एक लग्ज है लेकिन उसके कई नानी होते ह। रिहैबिलिटेशन के भी कई जानी हो सकते ह लेकिन जे उहुत पढ़ा नहीं। जो मानी में समझता हूं वह है लोहताजी ग्रांट। आप हमको ८ गुना दे रहे है, मैं तो खुश हूंगा अगर आप इसको ७ गुना को कर दे लेकिन आप वाजिबियत पर आ जाएं।

एक सदस्य--आवको सब माफ़ कर देना चाहिए।

श्री प्राग नारायण--२००६० आप पाते ह पहिले उनको तो आप छोड़ दीजिए। मुझे ज्यादा अर्ज नहीं करना है। यह एक ऐसा बिल ह जित पर जितना बोला जाए कम होगा। आप इसको समाज और देश के सुघार के लिए ला रहे है। मुल्क के साथ हम भी है। आज आपको स्वतंत्रता मिली है मुद्दत के बाद। आप लोग जेल में गए, मारे गए, कई दिन तक खाना नहीं मिला। वह सरकार गयी। अब हमारी सरकार आई ह उसको ज्यादा से ज्यादा आराम मिलना चाहिए। रहने को सुन्दर बंगले और साल में दो-दो चार-चार मोटरें। हर प्रकार की चीजे होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ आपको हमारा भी लिहाज रखना चाहिए। हमने किस तरह से परवरिश पाई है। हमें देख कर लोगों को उलझन होती है। हसद और डाह होती है कि यह मोटर पर क्यों चढ़ता है। यह तो अपनी अपनी किस्तत है। आगे क्या होगा किसी ने नहीं देखा। आज आपका सितारा ब्लन्द है लेकिन आप के साथ हमारा भी हिस्सा है। इस मुल्क की आजादी में हमारा भी हिस्सा है। हसने भी रुपये, पैसे से आपकी मदद की थी। हां जैल नहीं गए, वह भी अगर मौक्रा मिला तो किसी दिन हो आयेगे। हम भी उधर बैठ जायेगे। आप इसे खत्म की जिए तो अपनी राय क़ायम कर लेगे कि किधर बैठे। चंदरोजा और है, इंजेक्शन पर चल रहे हैं। सब तरह के लोग दुनिया में हैं। अब इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। सिर्फ एक शेर कह कर खत्म करता हं-

> करें वह सिक्तियां हम पर, जितना उनका जी चाहे। रहेंगे उनके दर पर हम संगे अस्तां होकर।।

श्री प्रेमिरिशन खन्ना—आज हम बहुत जमाने के बाद जब हम जमीं हारी प्रथा को खत्म करने चले तो हमको अपने सामने बहुत सी अड़चने दिखाई देती है। हमारे बहुत से साथी जो जमीं दारी प्रथा को खत्म करना जरूरी समझते थे लेकिन जब हमने खत्म करने की तरफ क़दम उठाया तो उनको हम अपनी मुखालिफत मे पाते हैं। यह हमारे मुल्क की बदिक स्मती है कि हम पार्टी बंदी मे क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं यह भी भूल जाते हैं। इस देश के दूसरे प्रांतों

श्री प्रेन किशा खना]

में तमारे रापी भले ही कितने जवलगन्द जार पनजने वाले हो हो रिक्त उन्होंने भी भूमि व्यवस्था ओर कान्न माधिवे की गूरियं। को तेगा कर हनारे मर्गावंदे के र (यार पर अपना मस्वित बदल टाला, लक्तिन हपारे नार्करावादी भाइयो ने उत्तवी खूरिया पर खरा भी ध्यान न दिया और अवने डालने वाले तरोक इस्तेमाल करते गुरु कर दिए जिनको हमारे भाई त्रिपाठी ली ने 'तारा। मं तो त्रिपाठी जी से पूर्ण ए। व गहमत हूं जो हमारे मार्क्सवादी भाई सोशिल्डिम की गात करते हैं सोवियट प्रिन न के बह तोर तरे के जिनको कि एसने भूमि व्ययस्थ। बदलने के लिए िले में उस्तेमारे कि रे जनको भूल जाते हैं। क्या वे नहीं जानते ि। सोनियट यूनियन के कान्तिकारियों ने भूमि न्ययस्यों को बदलने के करोड़ों और अरबा रूपथे रार्ज किये। आठ करो उजानवर मार घाले गये। कत्ल जोर गारतगरी की इन्तिहा हो गई थी तज भी जो बुउ वह चाहते थे वह न तुआ उन हो वापस लौटना पड़ा किसानों को वास्तिगत हक्क ोना पड़े गरत तरीकों को छोड़ कर सहिलयत के तरीके अखितगार किये गर्ये जन यह सोजिलिस्ट भाई देहात में जाते हैं कोर किसानी की ज्यादा जमीन दिलाने की । त करते हैं तब किसान उनमें सवाल करते देखें गये कि द्या जमीन कोई राह ें जो गांव हर पढ़ा वो जायगी आर उनका कोई असर किसानो पर हो नही पाता। ता भेरा उनसे अनरोप है कि वे अपने तोर तरीके देखने की कोशिश करें और उनको फिर जाचने की कोश्रिक करें कि कहां उसमें गलती तो नहीं है। गवर्नमेंट को नुकसान होता ही है परन्त किसान। पर में भी उनका अंतर जायह होता जाता है। समाजवाबी भाई जा जमीदारी के साम आधाज में आबाज मिला कर भमि-व्यवस्था बिल पर मुखालिपत करते हैं तो किसानों को इसमें फर्क करना गुटिकल हो जाता है जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पिछली लटाई में जन-यद्ध का नारा लगाया था। माक्जिम के नक्ते-नजरे से चाहे वह फितने अंने स्तर की बान हो लेकिन फिरन्गी सामाराज्यवादी हकमत के साथ आयाज से आ 11 ज भिला कर जन—यद्व का जो नारा लगाया गया उसका नेतीजा क्या हुआ क्या वह समाजगावी भाइयों ने बेला नहीं क्या आखिर कम्यनिस्ट पार्टी उस नारों की बदोलत कही रसातल को पहुंच गई और हमारे राष्ट्रीय जीवन में उसका कहीं पता नहीं चलता और लोग भुबहा की नजर से देखते है क्योंकि जहिर है कि शोषण करने वाली जातिया ओर शोबित जातियों की राजनीति एक नहीं हो सकती इसी तरीके से समाजवादियों का जमीवारो के साथ मिल कर भूमि व्यवस्था की मुखालिफत करना जिनका कि नजर में कोई ज्यादा फर्क नहीं रखता और वे कहीं अपने ध्येय में आगे बढ़ा नहीं रहे है। ये अपने अगले चुनाय में कामयाब होकर आने की बात जनता से कहते हैं और जमींदारी बिला मुआविजा लत्म करने की बात कहते है। अच्छा होता कि वे आज दस गुना लगान जमा होने देते जोर जब थे ताक़त में आते तो सब वापन कर देते लेकिन हम जानते हैं कि वे तुन कर ताकत में नहीं आ सकते।

मं आप से पूछना वाहता हूं कि क्या सोथिगट यूनियन से भी उथादा अच्छी समाजवाद की योजना हमारें समाजवादी भांइयों ने बनाई हैं। आखिर सोवियट यूनियन की भी पीछे पछताना पड़ा। और वापस लौटाना ही पड़ा किसानों की समस्या बहुत पेचीदा है ही। आज सोशिल्स्ट पार्र्टी ने जो तरीका इस्तेमाल किया है वह बिल्कुल लीगी ढंग का है नतीजा जो कुछ आपके सामने हैं। आप समाजकी करण में रोड़े अटका रहे हैं। आपके तरीकों से समाजवाद के रास्ते में अड़चने पड़ रही हैं। इसके अलावा मुझे वो वातें और कहनी हैं। पहिली यह है कि बड़े—बड़े जमीदार साहबान ने गरीब काइतकारों से जमीन छीन ली और गलत तरीकों से पटवारियों से मिल कर कागजात लिखा—पढ़वा कर खुवकाइत में वर्ज करवा ली गई है। यह सब कुछ ज्यादातर १९४६ के जमीदारी प्रया थे खत्म होने के निश्चय के बाद हुआ और अक्सर इस किसम के बाक आत जमीदारों ने किये जिनकी जिम्मेदारियां और ताल्लुकात सरकार के साथ वे क्योंकि उनकों भी प्रोत्साहन मिला। में माल सचिव की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि गरीब

काश्तकार अपनी गरीबी की वजह से अदालत की चाराजोई नहीं कर सकते। उनकी कमजोरी वारसूक जमींदारों के जराये के मुकाबिले में विफल हो जाती है क्योकि उनके लिये इस कानुन में से कगाई होनी चाहिये ताँकि १९४६ ई० के बाद के तबादले काश्तकार और बड़े जमीदार के दरिमयान नाजायज समझे जायेंगे खासकर वह जो १९४६ की तजवीज के बाद के है क्योंकि ८,८-१०,१० हजार बीघे के फार्म खुदकाश्न में लिखवाकर कमजोर काश्तकारों को जबरदस्ती निकाल दिया गया है। इससे गरीब काश्तकारों के दरिमयान काफी हलचल है, काफी बदनामी का बायस हो रही है। दूमरी बात जो में आपमे किया चाहता हूं वह यह है कि एक सा लगान जमा करने का जो नियम बनाया गया है उसमें कुछ हदे तक संशोधन की जरूरत है क्योंकि गोरखपुर वगैरह की तरफ से ६५ से ७० रुपया फी एकड़ जनीन का भाव है। बनारस में ५० से ५५ तक मुजप्फरनगर और मेरठ में ६०से६५ चपत्रे फी एकड़ तक जमींन के भाव है। लेकिन मेरे हल्के में और उसके आस पाम १५ से २० रुपये फो एक इतक का भाव समझा जाता है। यह इलाका अमी का इलाका है। यहां ज्यादातर हमेशा से ही गल्ला वाहर मे आता रहा है। यह। भी किसान को दस गुना देने की बात है। जहां किसान के पास मामूली पैदावार के अलावा मुनाफा भी ज्यादा होता है वहा उनको दम गुना देना आयान है लेकिन जहां पैदावार में लागन भी मुस्किल से निकलती है बड़ां उनको दम गुना देना दूभर हो जाता है भूमिधर बनना चाहते हैं लेकिन माली मुश्किलान के सामने दिक्कतें है। होना चाहिये था जहां जमीन की कीमते ज्यादा है वहा दस गुना से ज्यादा वम्ल किया जाना चाहिये और जहा जमीन की कीमत कम है वहा कम वमूल किया जाना चाहिये। मेरे जिले और उसके आत्पास लोगो को दिक्कत सालम हुई। इमलिये ज्यादा मुनापिब होता कि शरह लगान कम कर दी जाती और उसके मुताबिक जमींदारों का मुआवजा भी कम करके उसका तवाजन गराबर कर दिया जाता है। इसिलये में समझता हूं कि इस मलले को भी इस दृष्टिकोण ने रिवाइज किया जाना चान्यि और संही तरीके पर विचार कर गरीब काइतकारों के लिये महलियत हो ऐना तरीका गवर्नगेट को अख्तियार करना चाहिये, बस मुझे यही कहना है।

श्री राजा राय शास्त्री--जनाब डिप्टी स्पीकर महोदय, मुझे इम बात की आशा थी कि विशिष्ट समिति से जो बिल इस हाउन के सामने आयेगा उममें पहले की अवेक्षा बहुत कुछ सुधार किया जायगा। यह आज्ञा हमें इसलिये बंबी थी क्योंकि जब हाउस के सामने इस बिल पर विचार हुआ तो समाजवादी विचारधारा के लोगों ने अपने विचारों को हाउस के सामने पेश किया यद्यिव इस हाउस में कांग्रेस का जबरदस्त बहुमन है फिर भी मैं इस दान की आशा करता था कि हम चाहे कितने ही अल्पमत में क्यों न हों लेकिन हमारी बातों की कुछ न कुछ सुनवाई होगी। जब विशिष्ट समिति बनाई गई तो में देखता हूं कि कांग्रेस की तरफ से जितने लोगे लिये गय उनमें से न मालूम कितन जमींदार वर्ग के होंगे, विरोधी पक्ष से मैं देखता हूं कि जमींदार वर्ग के कितने ही लोग इसमें मेम्बर बनाये गये थे, लेकिन इस हाउस में समाजवादी विचारधारा के तीन ही व्यक्ति थे किर भी इनमें से किसी को नहीं लिया गया । में उम्मीद करता था कि हालांकि हमारा उसमें कोई प्रवेश नहीं है लेकिन हमने जो विचार हाउस के सामने पेश किये हैं उनकीं कुछ न कुछ कद्र की जायगी। परन्तु विशिष्ट समिति के बाद जब वह बिल आया और उसकी रिपोर्ट मैं ने देखी तो मेरे ऊपर इस बात का असर पड़ा कि वास्तव में आज कांग्रेस का इतना बड़ा बहुमत हैं और वह यह अच्छी तरह समझती है और उसे किसी अल्पमत की परवाह नहीं हैं। वह समझती है कि अपनी तादाद के जोर से वह जो कुछ चाहेगी इस हाउस से करा लेगी और वही मैं देखता हूं। पुराने बिल और विशिष्ट समिति के बिल में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं। मैं. खैर, यह जे हर चाहता था कि चूंकि यह बहुन गम्भीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसक हमारे सूबे ओर देश पर बहुत बड़ा असर होगा इसलिये बहुन गम्भीरता के साथ इप पर विचा किया जाता, यह मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन में देखता हूँ कि हम जब कभी इस बिल घर बहरू करने को खड़े होते हैं तो इस हाउस के सामने ऐसी दलीलें पैश कर दी जाती है जिनपर वास्तव में ठंडें दिन से विचार करना बरुन कठिन बान हो जाती है। मेरी आस्त यह है कि जहां पर आंगड़ों की लड़ाई है वहां मेरा बहुत कम दखन रहता है लेकिन में सिर्फ एक चीज को इस

श्रीराजा गाम आ अ विवारभारा ने देखता हूं कि इसका हमारे देश पर गरा असर परेगा आर प्याज पर क्या प्रभा नो । यह विवार (रि. जनसाधारण के हित के चिये हु । जनसाधारण के दबाने लिये। प्रत्ये भारतीयर, चार् पाउन के अन्दर विनार तरता उ, पा हा पर पामने काम करता हं और राजनीति में भी, तो मेरा इब्टि होण यही होता है। इसलिये इतन में १० ३०।र आवश्यक बिल पर विदार हरते समय न करमूल में जा जर विदार करना ताह गह । व सार में यह बिल जो पेश किया न गा है यह के राज इस कारण से कि वर्षों से हमारे नमाज की पोजुबा व्यवस्था और वर्तमान सामाजिक दशा में मजबूर शिया है। के यह विलिये एक किया जाय और अभी लिये यह वैश म यह भी वेजता ह कि जिल्हे इंदर को लेकर पह जिल हाउन है सामने आया है वह उद्देश्य इन बिल ने पूर्णाणे महेला और अलर वर नहीं पूरा हो सहता है तो इसमे किस तरीके में स्वार किया जाय गिम्मे हम जिस उद्देश की पूर्वि करेगा चाहते ह उसकी पूर्ति कर सकें। इस निगात से जन हम उस पिए को रखते हैं तो गन पंपिति मेरी उस बात को देखने की ख्वाहिश होती है कि आया कोन स वे कारण ये जिनते जा व कार्येस सरकार की मजबूर किया कि

वह इस तरह रा बिल इस हाउस के मामने लाये ।

जनमें १४६ राज नहीं कि जब हमारा राष्ट्रीय जान्दोरान चला उसका सर्वेव से यह ध्येष रहा और बास तोर से उाप्रेस में इस तरह की विवारधारा रही कि विदेशिया सम्किकी जाजाद कराना है और इस तरा में उसकी प्रमे बड़ी लड़ाई अग्रेजा के ना। यो। दूसरी लड़ाई हमारी सामनाजाही से थी और हुए यह निवार करते थे कि तर कभी हमारे हाथ में राज सत्ता आयेगी तो हम इस सामन्तराही को शीघ से शीघ्र हटाने की फोशिश करेगे । सन १९३५ ई० में जवाहर लाल जी ने कहा या कि जगर अग्रेजों के बाद रिन्दोर तान में जपनी हु एसन कायम भी होती-ह और अगर यह मध्यवर्ती वर्ग ज्यो का त्या कायम रहता ह ता प्राज्ञानी की मलोल ही होगी। में उस समन्न यह उम्मीद करता था कि जब अंग्रेजा की गला भारतवर्ष ये चली जायेगी और यहा की हक्मत हमारे हाथ में आजावगी तो मेरे हदय में यह पूरा विवास या, पूरी आशा थी और उल्लास या कि जिस वनन उम अवने राष्ट्रीय गाँउ क नीचे ला र होंगे, काग्रेस के हाथ में शासन की की बागडोर होगी ता मधा रतीं वर्ग की कमरदूर जायगी और कारत कारो और किसाना का सिर ऊंचा हो जापगा । म यवतों वर्ग के मुकाबले में उन्हें ताकत हासिल होगी । लेकिन आजादी के बाद जब देश की राजमता की बागड़ीर कांग्रेस के हाथ में आई ओर उसके बाद की सारे देश की आर्थिक पद्धति पर जब हम विचार करते हे तो मजे भय होता हैं और मुझे प्रत्यक्ष दिखाई पडता हैं कि वास्तव में वह अपने उद्देश्यों से बहुत हट गये हैं और यह मालूम हाता है कि थो है ही दिनों में हमारी राष्ट्रीय अर्थः प्रवस्था या नेशनल ऐकोनोमी बैठ ही जायगा यही वजह थी जिसने मुझे कांग्रेस मे अलग कर दिया । में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और किसी खिसियाहट के फारणयश में समाजवाद में नहीं आया। बात केयल यह थी कि जिस सच्चाई के साथ हमने अपना आदर्श कायम किया था और जिस चीज को लेकर हम चले थे, और जो चीज हमने महसूस की थी तथा जिस ध्येय को लेकर हम चले थे, मैने देखा कि काग्रेस में रह कर उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती है। हमें आज अपने उस ध्येय की पूर्ति करना है। हम कर सकेंगे या न कर सकेंगे उसके बारे में में अभी कुछ नहीं कह सकता लेकिन में यह जानता हूं कि कांग्रेस के हाथ में इस समय ताकत है, में जानता हूं कि उनके पास शक्ति है। वे हमारी पार्टी को दबा सकते है उसका दमन कर सकते हैं लेकिन में उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो इस तरह की चीजों से निराश मुझ तो यह विश्वास है कि हमारी पार्टी को कितना ही दबाया जाय, उसका कितना वमन किया जाय लेकिन समाजवादी विचारधारा बास्तव में वस नहीं सकती। खिल्ली उडाई गई और कहा गया कि हमारी अकल में यह बात नहीं आती है कि हम इसका विरोध पयो कर रहे हैं। इसके लिये हमारी जिल्ली उड़ाई जाती है में आपसे वरख्वास्त करूंगा कि अ।प अपनी थोड़ो सो विजय थोड़ो सी हुंसी के ऊपर इनने फूले न समाइये। बनियां के इतिहास कर विलीन हो गई। जो आज कमजोर विवाई पडता है हो सकता ह कि कल वह शक्तिशाली हो ओर आप कम नोर हों। इस बिल को पेश करने का एक कारण हो सकता ह कि और वह यह कि हमारे देहात की जो आधिक व्यवस्था है वह चौपट हो चुकी है

उसको ठीक किया जाय । लेकिन में यह कहता हूं कि अगर कुछ दिन तक यही हालत और कायम रहती तो हमारे देहात के किसान भाई इस बात का इंनजार नहीं करते कि काग्रेस पार्टी कोई विल बनाय या नहीं और इस चीज को खत्म कर देते । उनकी कमर टूट चुकी हैं उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब हो चुकी ह कि वे और ज्यादा दिन तक इस चीज को बरहाइत नहीं कर मकते । हमारा अपना विश्वाम है कि अगर जमींदारी प्रथा को समान करने के लिये अगर थोड़े से समय के लिये और दिलाई की होती ए कीई जदम न उठाजा गया होना तो सारे सूबे के अन्दर किसानों का एक ऐसा बिद्रोह हो गया होना कि एक ही दम में, एक ही कान्ति में सारे सूबे की जमींदारियां खत्म हो गई होती । महात्मा गांधी ने इस बात को अच्छी नरह समझ निया था । वे अपने देश की नब्य को खूब पहिदानते थे । उन्होंने सन् १९४२ में लुई किशर से कहा था कि अगर इस वक्त कुछ न हुआ तो हिन्दुस्तान का किमतन बिना मुआवजा दिये ही अपनी जमीन पर ज्वा कर लेगा और कोई ता जत नहीं कि उसको रोक सके ।

मेरा यह विश्वास है कि कांग्रेम पार्टी इस बात को अच्छी तरह महसूस करती है कि अगर यू० प्रा० के अन्वर हमने जल्दी से कोई काम नहीं किया तो देहात के अन्वर विद्रोह मचेगे। कल एक साहव मुझको रिपोर्ट दिखा रहे थे कि ३५ लाख इस तरह के यू० पी० में काइतकार हैं जिन काइत कारों ने दूसरों की जमीन पर ब्जा कर लिया है। आप उनको दे मपासर्स कहिये या कुछ कहिये ठेकिन इससे यह बात सादित होती है कि उनके दिलों के अन्वर किननी जमीन की भूख है और वह यह खाहते हैं कि जिस तरह भी हो हमको जमीन निल्ना चाहिये। इन बान को रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि वास्तव में कांनि के आसार हमारे देश के मामने नौजूद है। में सिर्फ आपको इस वतलाना चाहता हूं कि इस हाउस में कांग्रेस की तरफ से जो विल्ल आया है उसकी बहुत कुछ पूज्य कि वी वात पर है कि वह इस बात को सहसूस करते हैं कि असंतोध इनना बढ़ गया है कि अगर उसकी रोकथाम न की गयी तो विद्रोह खड़ा हो जायेगा पृष्ठ ३५८ पर इन शब्दों में रिपोर्ट के लिखने वालों ने स्वीकार किया है :--

The age-long simmering discontent, occasionally bursting into acts of open defiance and sometimes of violence in our province and other parts of India, has reached a critical stage. Whatever for bearance and self-restraint we find in the countryside among the tenants is due to the hope that those who are running the State will undo the wrong done to them. Once that hope has gone, the tenant will be driven to desperation. The discontent may develop into revolt and our social security may be threatened by the outbreak of violence. Our scheme of Zamindari abolition contemplates payment of equitable compensation. If abolition is held over for a few years, abolition may mean expropriation without compensation and, quite possibly bloodshed and violence. In the words of Professor J. Laski, "To the threat of revolution, there is historically one answer, viz., the reforms that give hope and exhilaration to those to whom otherwise the revolutionaries make an irresistible appeal. 'One can only hope that the entire landed gentry is not blind to the writing on the wall.

(एक जमाने से भीतर ही भीतर मुलग ने वाले असंतोष ने, जिसका विस्फोट खुले विरोध और कभी हिंसात्मक कार्यों के रूप में समय—समय पर हमारे प्रान्तों और भारत के दूसरे भागों में होता रहा है, नाजुक अवस्था प्राप्त कर ली है। देहात में काश्तकारों के बीच आज हम जो भी सहनशीलता और आत्मसंयम देखते हैं उसका कारण उनकी यह आशा है कि जो लोग 'राज—काज' चला रहे हैं वे उनके प्रति किये गये अन्याय को दूर करेंगे। यदि कहीं इस आशा का अन्त हुआ तो काश्तकार धीरज खो बैठेगा। तब उसका असंतोष विद्रोह का रूप धारण कर ले सकता है, और हिंसा फैलने से हमारी सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जा सकती

[श्री राजा राम शास्त्रो]

जमीदारी-उन्मूलन की हमारी योजना में वाजिब मुआवजा देने की बात है। यदि जमीदारी का उन्मूलन कुछ वर्षों के लिये और रोक दिया जाय तो उस हालत में उन्मूलन का अर्थ बिना मुआवर्षे के जमीदार की अधिकारच्युति, (हक माठिकाना से उसका विचत किया जाना) हो सकता है, ओर बहुत संभव है कि खून-खराबी तथा हिसा भी हो। जैसा कि प्रोफेसर हैराल्ड जे ० लास्की ने कहा है इतिहास को दृष्टि में रखते हुये क्रान्ति के खतरे को दूर करने का एक ही उपाग हो सकता है। वह उपाय ऐसे सुधार करना है जिनसे उन लोगो में आज्ञा और प्रसन्नता का संचार हो सके जिनको, विपरीत अवस्था में, ऋान्तिकारियों की बाते अनिवार्य रूप से पसन्द आ जाती है। हम यही याज्ञा कर सकते हैं कि सम्चा जमीदार-वर्ग वस्तुस्थिति देखने और समजने मे असमर्थ नही है।) में समझता है कि काग्रेस सरकार ने जाने वाली काति के खतरे को देखा ओर उसको इस कानून को हाउस के मामने पेश किया। जसा मैने अभी पढकर सुनाया कि जब कोई इन्फलाय सामने जाता हो तो एक तरीका गहरूँ कि ऐसे सुवार करो कि जो भली नगी जनता इन्न लाब करना चाहती हो उमकी दशा में मुधार हो और वह इकलाब से विमल हो। दूसरा तरीका यह है कि जसा जास्की साहब ने वहा ह कि उसके दिल में जाशा पैदा कर दो और आशा इस बात की पैदा कर दो कि अब तुमारा भाग्य बदलने वाला है ताकि वह ऐसी आज्ञा से बशीभत हो फरके काति से विम्ख हो सके और यह कातिकारियों के जाल में न फरे। हमें ऐपा मालम होता है कि हमारी कार्येस की हकुम र ऐसा कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं करने जा रही है जिपन किपानों के दिरु में ऐसी भावना एदा हो कि वह कानि का मार्ग छोउ सके। मेरा अपना क्या उथह है हि काग्रेस जर्मादारी उन्म उन का ढिढोरा पीट करके उनके दिलों में इस बात की आज्ञा पैदा करना चाहती है कि हम तुम्हारे भाग्य का सही निर्णय करने जा रहे हैं। मंने पहले भी कहा था आर जान फिर बहुत। हू कि जमीबारी उन्ग उन क सबा में प देहाती में खब ढिडोरा पीडेने जिसने किसानों के बिड में आज्ञा का सचार होगा कि जली नारया मिट जायेंगी तेर जल पारे कि धना त दिन फिरेगे लेकिन अहा हिनो के नाद किसान इस बात की महसूप करें के कि का राज का ता । हम लोग तो पूरी तौर से उस बात को नएमस कर चुके है कि पुरे का पूरा तमोंदारी उन्मुखन बि ह एक घोगा बाजो को बीज ह, एक बाउ है। जिस उदेश्य को ले करके गारा गया जा रहा है यह नोज पदा नहीं होगी। उसमें अमीदारिया नहीं मिट रही है बिल्ह जगीदारिया की तादाद ब 15 जा रही है।

और आप यकीन गानियें नि वृत्त दिनों ने बाद आप देरोगे वि जिस तरह से आज के जमीदार हैं वे हिन्दुस्तान की जाने बाकी राजनीति में जो नये दनने वाले भ मिधर है, दोनों के दोनों एक साथ मिल कर गचन भेर जो देहातो में आर्थिक पद्धति पदा करने वाली है उसमें ये नये जमीदार धनी वर्ग के साथ जिल कर भूमिधर की ज्ञाक्ल में सामने आयेंगे। और जिन लोगो को आप आज जमीत नहीं दे रहे हैं, जिन य निहर मजदूरों को आप नमीन नहीं दे रहे हैं, जिन शियमी काश्तकारों को शिकमी से निकाल रहे हैं, आप देख लीजियेगा कि ये लोग एक साथ मिल कर जमीन के बटवारे के लिये आगे बढ़ेगे श्रोर यह माग करेंगे कि हमें जमीन वीजिये। हमारा भी जमीन पर हक है। अगर आप उनको जमीन नही देंगे तो वे जबरवस्ती जमीन पर व बजा करेंगे और इस तरह से देहाती में संघर्ष होगा और यही मुमिधर वर्ग काग्रेस ह हुमत की री इ बन कर रहेगा जिस तरह से कि अंग्रेज़ो ने जमीदारो को बनाया था। अंग्रेज़ा ने जमीदारो को इसलिये नहीं बनाया था कि वे उनके बड़े प्यारे थे बल्कि इसलिये कि अंग्रेजों ने सन् १८५७ में भारत की पराजित करके यहा पर बडा दमन किया था और उसमें इन्ही जमीदारी ने उनका साथ विया या। कि हो सकता है कि आइन्दा चल कर कोई ऐसा मोका आप है कि हमको इनकी मदद की आवश्यकता हो और इसी ग्याल से अपने राज्य को म नबूत करने के लिये उन्होंने इन जमीदारों को उत्पन्न किया था । और इस बात को सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन जमीदारों ने सन् १८५७ ई० से लेकर सन् ४६ तक अपने उस फर्ज को अच्छी तरह से अदा किया। अगर इतिहास को आप देखें तो मालूम होगा कि यह जमींदार वर्ग जो इस देश में पैदा किया गया था उसने अपना काम पूरा किया है। हमारा देश हिन्दुस्तान जब जब आजादी की ओर बढा, कान्ति की ओर बढा, उन्होने बरावर अंग्रेजो का साथ दिया और उनके वकादार बने रहे। यह जमीदार वर्ग हमेशा ही अंग्रेजो का गुलाम रहा। जिस हालन में आज अग्य इस बिल को पेश कर रहे हैं उसके अपर भी जरा गौर कीजिये। आज करीब-करीब १।६ हिम्से ट्रोप मे कम्युनिजन हो गया है, रूस कम्युनिस्ट हो गया है, आज सारा चीन कम्युनिस्ट हो गया है और मलाया ओर इंटोनेजिया मे कम्युनिस्ट आन्दोलन चल रहा है। आप जानते हैं कि सारे एशिया में लाल कान्ति की लहर चल रही है और इस क्रान्ति की उहर को रोकने के लिये आप इस तरह की जाने करना चाहते है। कोई नहीं जानता है कि कल हिन्दुस्तान मे इस क्रान्ति का क्या रूप होगा । हिन्दुस्तान के आइन्दा के किसान क्या करेंगे, यह कोई नहीं जानता हैं। आज कल जिस तरह कि विचारघारा चल रही हैं उसको रोकने के लिये कांग्रेस इम तरह में किसानों को घोखें में रखना चाहती है। जानते हैं कि आपके पास आर्डिनेसों की ताकत है, एम० एल० एज० की ताकत है, म्युनिसिप्रैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डो में भरे हुये कांग्रेसियों की ताकत है, अखबार आपने खरीदे हैं, बावजूद इसके आप यह समझने ह कि इससे काम आगे चलेगा नहीं और आज इसलिये इस बिल की लाने की जरूरत पड़ी है। आगे चल कर देहातों में विद्रोह शुरू होगा, उस समय के लिये आपका समर्थन करने के लिये एक वर्ग की आवश्यकना है। आज जो ये पुराने जमीदार है इनको किसान समझते है कि ये हनारे दुश्मन है। वे इन जनींदारो का कभी साथ नहीं दे सकते है। इसिलये अगर जमींदारों को अपनी बगल में लाना है तो जमींदार कह कर नही ला सकते तो अब एक बात भ मिथर वर्ग नाम देकर आत इस नये जमींदार वर्ग को किसानों के सामने पेश करना चाहते है कि ताकि भूमिधर के नाम से उनको घोखा दिया जाय। ऐमे किसान जिनके पास काफी रुपया है, जिन्होंने लडाई के जमाने में, मंहगाई के जमाने मे काफी रुपया पैदा किया है वे धनी वर्ग के साथ मिल कर भूमियर के नाम पर सामने आयेंगे। लेकिन इससे किसान घोले में नहीं आ सकता है। आज कल की दुनियां दूसरे तरीके की है। आपका तरीका तो यह है कि कहें कुछ और करे कुछ। आप चाहने हैं कि भूमिथरी की व्यवस्था हो और देहातों के अन्दर एक पूंजीपति वर्ग मजबून बने लेकिन यह न कह कर यह कहा जाता है कि हम तुम्हारे उद्धार के लिये ये बातें करतें हम जो बाते करते हैं इसकी भविष्य ही बतलायेगा कि वास्तविक बात क्या है और इस बिल को लाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आज मैं इस बिल के खिलाफ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और हमारी भविष्यवाणी सही होगी या गलत इसको तो आगे आने वाला हिन्दुस्तान का इतिहास ही बतलायेगा कि किसकी बात सही है और किसकी गलत। दूसरी बात आप यह देखिये कि हम यह महसूत करते हैं कि हमारे देश के अन्दर क्या हो रहा है।

श्री चरण सिंह—न्या में आपके जरिये से आपसे यह पूंछ सकता हूं कि किसानों को जमीन का भालिक बनाने के लिये सोक्षलिस्ट पार्टी यह मानती है या नहीं कि उसको भूमिधर बनाना चाहिये ?

श्री राजाराम शा न्त्री--इसका जवाब मै आगे दूंगा जब मै इस वात पर बहस करूंगा।

हिंदी स्पीकर--आपको सवाल का जवाब देने के लिये मजबूर नहीं किया जा रहा है आप इसका जवाब अब दे या जब आप ठीक समझे तब दे।

श्री राजाराम शास्त्री—में यह कह रहा था कि बहुत सी बातें आने वाली है। आप लोग नोट कर ले में सब का जवाब दूंगा। में यह निवेदन कर रहा था कि जब हमारे देश के अन्दर क्रान्ति की लहर आ रही है तो इन सब बातों पर गौर करने की निहायत जरूरन है। हमारे देश में ७२ ही सदी आदमी खेती पर निर्वाह करते हैं। खेती पर बोझा बढता जाता है। हम जानते हैं कि यदि भूमि की व्यवस्था नहीं की गई तो मुल्क की हालत और भी खराब हो जायगी। हालत क्या है यह रिपोर्ट में आप देखें—उसके पूरे आंकड़े रोशनजमां साहब ने आपके सामने पेश किये। उन रिगोर्ट के बारे में अपके पामने दहस नहीं करता लेकिन देखने की बात यह हैं कि मुद्दी भर लोगों के पास अधि हांश जमीन हैं और अधिकांश लोगों के पास मुद्दी भर जमीन हैं। यह विषमता ही इस बात का कारण है कि सूब के अन्दर उथल—पुथल हो। हम चाहते. हैं कि हम इस विषमता को मिटा दे। इस अशान्ति के कारण को देश से दूर कर दे। इसका एक ही नरी हा हो सकना है और वह यह है कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उससे उसको

[शो राजा राम गास्त्री]

ले और जिनके पास अमीन नहीं है उसको जमीन वे। यह मीधा सावा ो निम्पल नस्खा है जिसको निनस्टरहो नही बल्कि मामुली या आदमी धेत में काम करने ना हा, कड़वा चलाने वाला भी समझ सकता है और वह इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि जिसके पास जमीन है उससे लो और जिल्ले वास नहीं है उसको दो । लेकिन तुगारी काग्रेस गतर्न दिने इतना कमाल का नस्खा सामने रावा है कि जो अजीब है। वह बहु है कि जिसके पारा पा है जितनो जमीन हो उससे धेला भर न ली और जिमके पास धेला भर भी नहीं है उसकी एक पाई भर भी न दो। यानो िसी भी जमीदार के पास ५ हजार या १० हजार बीघा जमीन हो तो उसके लिये कार्यस सरकार ने खुला एठान कर दिगा है कि तुम्हारे पास जितना भी लूट का मार रखा है, जो तमने १८५७ ई० में विश्वास्त्रात करके कभाजा है या सन् २१ र० में या ३० में कमारा है या सन् ४२ की क्रान्ति में जनता से लटा हो । तुम्हारे पास चाहे जितना गाल हो या जितनी भी रक म तुम लट चके हो उतनी तुम्हारे पास रहेगी। जिसके पास १० हजार बीता जमीन है उससे एक बेला भर भी लेने के लिये तेपार नहीं है और ऐसे लोग जिनके पास आध बीधा, २ बोपा जमीन है उसको एक बीघा भी देने के लिये तैयार नहीं है। इस तरह की बीज है जिसके लिये कापेस सरकार ने ढिढोरा पीट रखा है कि हम सामाजिक न्याय करने जा रहे हैं। इस प्रकार ने यह रिस तरह सामाजिक न्याय का आधार होगा कि अजसके पास १० हजार बीघा जमीन है उसमे आप एक बीघा भी लेने की हिम्मत नहीं करते रें। और जिसके पास एक बीघा ह उसकी आप ओर एक बीधा देने के लिये तैयार नहीं है। यह बात हमारी समझ में नहीं आई। जब में जमीन के बं टवारे के बारे में कहंगा तब में इस पर ज्यादा कहगा लेकिन इस मोके पर तो यही कहना चाहता ह कि इसके बारे में रिपोर्ट के अन्दर किलकुल साफ ेशब्दों में यह चीज लिखी हुई है। मफा ३८९ पर यह लिखा है कि:--

"We, therefore, recommend that no limit be placed on the maximum area held in cultivation either by a landlord or a tenant. Everybody now in cultivatory possession of land, will continue to retain the whole area."

(इसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि जमीवार या हाइतकार के पास की निजी खेती के अधिकतम रक्तवें के संबंध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे में इस समय निजी खेती—वाड़ी की जमीन हैं, अपने पूरे रक्तवें पर काविज बना रहेगा)

बड़ी खुशी है कि इतने दिनों की रगड़-शगड़ के बाद शाप में थो है सी अकल आई और आपने अब यह तै कर दिया कि अब तक जिसने लूट में लूट िया वह लाए किया ले हिन' आइन्दा ३० एकड़ रो ज्यादा कोई न रख सकेगा। यह आप का कौन सा इन्साफ है कि आइन्द। को र ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकेगा लेकिन उस वक्त तफ कि जब यह कानून पास हो। रहा है उस वक्त तुक आप ने कोई रोक ही नहीं लगा र है हर शहरा चाहे जितनों जमीन हो रत राकता ह यह आप का कौन सा न्याय है, यह आप की कीन सी दलील हैं। में आप से यहता है कि आज आप जिस तरह से यह तरीका अक्तियार करते हैं कि जिस के पास जितनी अमीन है वह उसके पास ही रहे और जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं देते तो मुझको ऐसा त्याल हो रहा है कि याम्तय न आपकी इस नई भूमि व्यवस्था में भी वही असन्तोष जारी रहेगा लेकिन एक योज है जो किसान की समझ में नहीं आ सकती और बहु यह है कि अगर सारे देश की व्यवस्था शार आधिक पहाति को आप देखेंगे तो अबतक काग्रेस इसी नतीजे पर पहुंची है कि अगर परे-खों व्यवसाय है तो यह पूंजीवादियों ओर पूंजीपतियों के ही हाथ में रह भोर जाप पूंजीपितयों की हर अकार का सहयोग है रहे हैं और उनको खुश करने की कोशिश हर रहे हैं। जान उन पर दक्त कम कर रहे हैं, उनको व्यापार में तहिल्यतें वे रहे हैं। जब उनका सवाल आता है तो आप राष्ट्रीयकरण की बात को छोड़ वेते हैं और चीर बाजारी करने वाला को फुसलाने की कोशिश करते हैं। आप देश के अन्दर उन्हीं को हर प्रकार का प्रश्रय देना चाहते हैं। आप देहातों में भी जमींदारी की प्रथा की खत्म करने के बाद एक पूंजीबादी व्यवस्था नायम करना चाहते हु और कृषि व्यवस्था में भी पूंजी—व्यवस्था लाग चाहने हैं। जो अब तक कृषि से कोई सबध नहीं रखने थे उन पूर्जापितयों को भी अन आप देहान में भेजना चाहते हैं और उनको आप दावत देने हु कि बहु बहु को फार्य बनाकर और पूरोप तथा अधेरिका से मशीन मंगा कर देहातों में और बहा की व्यवस्था में दिखन है। जाय। आप अभे बाले लंगों को चाहने नैं कि वह परीबा की जर्माने परीट कर अपना काम दनावे। वैसे तो एन किसान चाहे जितना परीय क्यों न हो लेकिन बहु अपनी एक व व। जिन भी नहीं छोड़ सकता इसलिए आपने तरी गयह निकाला है कि उपकी माली हालन इननी पराव कर दी जाय कि उनके पान अगर एक एक इभी अभीन हो तो वह अपन्त होनर उनकी बेच दे और अगर उसको बेचने का हु पत्र होगातो वह अपने एक दो बीघा में ही विधटा रहेगा। लेकिन उस हालन में पैसे बाले जो जहाजन है वह क्या करेगे। वह तो उसी हालन में आपके जिरए है सरमब्ज होंगे कि जब देहात में जर्मीन भी खरीद फरोख्त को चीन यन जप्यारि। इसलिए यह साफ जाहिर है कि आपनी सरकार देहानों में एक नई पंजीवादी व्यवस्था काम्या करना चाहती है और वह तभी नायम हो मकती है कि जब आप उन परीव आदिमयों को यह हु कि दे देगे कि वह अपनी जमीनों को बेचें और असीरों को आप के परिए से पहु हु कि कि वह उन गरीदों की कमीनों को वरीदें।

बिल की दूसरी दकाओं में भी आप देखेंगे कि आप ने इम तरह की गुंज उद्य एखें हैं और ऐसा कानुन बनाया है कि अगर किसी धरीब का काम वाब हो गया तो उसकी अमीन विककर एसे लोगो के पास हो जायगी जो आपके देहातों में एक नई गुंजीवादी व्यवस्था जायम कर सकेगे। मैंने कहा कि आपका यह उद्देश्य है। पहला काम तो यह है कि यू० पी० के किसानो को पहिले लूटा जाय । जो धन-दोलत ओर पैसा किऱानो के पास है उसको लूट लिया जाय। उनको ऐसा कर दिया जाय और वह इतने गरीब हो जाये जिससे उनके पास जमीन न रह जाय। वह जब तक ग़रीब न हो जायेंगे उस वक्त तक जमीन को नही बेबेगे। पन्त जी जो स्पीचेज करते हैं उनको देख लीजिये। किसानो! तुम्हारे पास जो कुछ सोना-चांदी और जेवर घर में है सब बेच दो। भूमिधर का हक नहीं है तो जो कुछ जमीन बचे वह भी बेच लो। मतलब साफ है कि अभी जितना भी धन-दौलत सोना-चांदी उनके पास है वह सब भूमिधर दनाकर ले लिया जाय। जब भूमिधर बन जायें और चार दिन के बाद जब खाने के लाले पहुने लगे तो हमारे चरणिसह साहब के पास आयें और कहें कि साहब हम भूमिधरी भी बेचना चाहते है इसे बिकवा आय अपन पैसे वाले दोस्तां से कहे कि तुम खरीद लो। इस तरह की तजवीज की अभी हमारे सामने यह बात नही आती। इस तरह की चीजें की जा रही ह। जायगी। उन्होंने खुद यह बात कही है कि देहात में सोना-चांदी भरा हुआ है। इतना नहीं समझते कि जब हिन्दुस्तान में सोना-चांदी नहों है तो देहातों में भी नहीं है। आप दस गुना लगान लेकर कियानों को तबाह करने के लिये यह काम कर रहे है। मै आप से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गुंजीवादी व्यवस्था आप देहातों में कायम करना चाहते है उसी लिये यह बिल पेश किया है। देहातों के गरीन किसानों के यास से जमीन निकलकर बड़े आदिनियों के हाथ में जमीन जा जाय और पैसे के जोर से वह उनको खरीद लें और पूजीवादी व्यवस्था क़ायम कर सकें। क्रान्ति को रोकने के लिये पुंजीवादी दृश्वस्था क्रायम करने के लिये इन उद्देश्यो से आप हा - गमे यह बिल लाए है। यह अफलीभूत न होगा। देहातों में संघर्ष शुरू होगा। काश्तका र ओर खेतिहर अजदूर एक तरफ मोर्चा पनाकर खड़े होंने ओर दूसरी तरफ भूनियर और पुराने जमोदार होते। इतना कहना चाहता हूं कि यहां जो जमोदीर बैठे हुये हैं उन्होने तक्तरीरें कीं। मुत्रे उम्मोद यो कि उनकी जमीदारी छिन रही है वह इस िल के खिलाफ तक्करीर करेगे। हमारे न्याय पूसुफ साहब बोले । मैने चक्के ह्यी युर्ना नेरे दिल पर यह असर पड़ा गो शा भिन्नो हुई कुश्ती लड़ी जा रही है। नुझ पर उत्तर पड़ा कि वह कांग्रेनी बनने वाले है या यन चुके हैं। सोविये। जमीदारी जन्म दो रही है वह हाउस के सामने खड़े है और कांग्रेशी हुकूमत की तारीक के पुल बांध रहे है। वह आइन्दा आन की तरफ बैठने वाले हैं। उनका विरोध दिखाउटी है। वह दिल के अन्दर समझते है कि जमींदारी जिस तरह खत्म होना चाहिए उस तरह खत्म नहीं हो रही है।

[श्री राज " भारतं,

एक सदृष्य--लेकिन जर्मादारों के जगत में तो आप लोग ही बैठते ह ।

श्रा रा ताराम दार त्री—हम जानते हे कि हम वगल में बेठकर उनके कभी नहीं । सकते और यह जानते हैं कि आप दूर बेठ कर भी उन्हों के हैं। पह तो आगे आन वाली जमाना कार्यमा कि कोन कि सकी तरफ ह। है किन मेरा यह यकीन ह आर आप देख लीजिंगा कि जब नयी स्थानिया जायेगी तो जो लोग आज हमारी तरफ बैठने वाले हें वे आपकी तरफ जायेगे। पर यह भी में आपने कर देना चाहता हू कि आप में ये जा लोग ईमानवार ह, किन को जनता की कुछ चिन्ता है वे हमारा तरफ बैठगे। चन्द रोज के लिये आ। अपनी दुकान आर चला ले। कितने दिना त्रीक जार जनता को मूर्ग बना सकते ह। जभी में जायेक सामने उदाहरण देकर बताऊगा। पही उभर बैठने ताल होग हाउस के अन्दर जा परकार का मुण गान करते है उनके हाथ में जगर अल अर जाव है तो अप गारा में पर कार की घोर निन्दा करते है । यहां ऐसी बातें करते है लितन अगर आव उनके घर पर जाइये, दाकलकाका में जाइ गे तो देखिये कैसी निन्दा वे सरकार की करते है।

में आवर्त मानने या रखना चाउता हू कि इपम बो, तान नीजे बनियाद। बाते है और मेरा यह जिल्ला ह कि जगर ऐपी बनियादी जीतां को राप नहीं छ रेगे, इ की और जगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कि ।। मा हा उन मं ३ १ जीज का गस ना कि नहीं होगा। मं इस बात को पहिले लेता हूं। जैने कि मारने कहा कि जा तथ जर्मादारी को लत्म करना चारते है तो जमीन का मालिक कान बने । यह मधा प्रभवने पहिले आता है और मै जानता हु एनके हैं स्व की चाल । जसा कि कम जापति जी। ने कहा, बिल्कुल सही है। आज हमारे देश की जनता शिक्षित नहीं है हमारे किसान फंजर्रे दिव ख्याल के हैं, इसमें जगीन के ट्कर्ने में निवटे हवे है और अपनी जमीन को भानो जिन्दगी से ज्यादा प्यारो मानते हैं। चनीजा यह है कि आज यह वही वात कहना चाहते । और उसी तरह में हहना चाहते हैं जिनहीं प्रजह से वह हिमान खुश रहें ताकि अगले दिनों में उक्तों बोट ज्यादा मिल गर्क। रोज २ हमसे यह कहलाया जाता है क्यों कि हम समाजनावो है। हम उत्वित्त के जो भी साजन है, बाहे जमीन हो, कारखाने हो उत्पादन के जो गायन हु तम उनके राष्ट्रीयकरण में विक्या। फरते हुं और हम गढ़ जानते हैं कि जनता की गुनामी का, जनता की त तहीं का अगर गर्म रहा कारण आज है तो यही है कि वह जमीन, वह कारखाने और उत्पादन के जो आधन है से सारे के सारे मुद्ठी भर लागों के हाथ में रहते हैं। जो इस तरह के उत्पादन के साधन देहाता के अन्वर है, जो कल-कारखाना के रूप में शहरों में है उन पर मुद्र ही भर लोगां ने करजा कर लिया है। मेरा बिश्याम यह है कि यह जमीन प्रकृति की वेन है, किसी इन्सान ने इसे पैदा नहीं किया । किसी इन्सान को हक नहीं हो सकता कि इस तरह को जमीन पर अवनी मिल्कियत कायम करे। मं साफ कह देना चाहना हूं अर डंके की चौट पर कह देना चाहता हूं चाहे कल ही जा हर आप किसानों के बीच में यह कह दे कि जमीन की मिल्कियत के बारे में भी हम बिल्कुल राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। हम बिल्कुल साफ कह देना चाहते हैं कि अगर जमीन पर किसी का उर्क हो राकता है तो यह समूचे रामाज का ही हो राकता है। समाज ही है जो जमीन का मालिक हो मकता है। रामाज उसकी उन्नति करता है, जंगलों को काट कर समाज आगे ले जाता है, अवल में रामाज की ही जमीन होनी चाहिये।

में आज इस क्रानून को पढ़ रहा था। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इसमें जो यह बफा ६ है कि इस ऐक्ट के प्रारम्भ होने के बाद यथाशीध्य प्रान्तीय सरकार विज्ञान्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकेगी कि निहिट्ट किए जाने वाले दिनांक दे संयुक्त प्रान्त में स्थित सब आस्थान, इस्टेट्स, गृहामहिम के स्वत्वाधिकार में आ जायेगे, शेल वेस्ट इन हिज मंजेस्टी । मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि आखिर इसके यानी क्या हुए । यानी इसके सानी में यह नहीं समझ सका कि जब आप यह कहते हैं कि इस कानून को जिन्म वक्त लागू किया जावेगा तब से सारी यू० पी० की जिन्म वक्त लागू किया जावेगा तब से सारी यू० पी० की जिन्म वेस्ट करेगी। अगर ये हिज मंजेस्टी में वेस्ट करेगी तो हिज मंजेस्टी क्या बला हु ? में तो हिज मंजेस्टी के मायने यहीं समझा कि यू० पी० की जो सरकार है, हिन्दुस्तान में जो प्रजातंत्र है और हमारे यहां की जो सरकार है उसमें वेस्ट करेगी। तब आप के यह कहने के क्या मानी है कि साहब, हमारे लिये आप बार बार यह बात कहते हैं कि आप सरकार के हाथ में क्यों देना चाहते हैं ? बेचारे डेढ़ वीघा क्यों नहीं कहना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—ओर यह आप की ईमानदारी है कि यह बेईमानी का लफ्ज् इस्तेमाल करते हैं। यह कहां तक पालियामेंटरी है ?

श्री राजाराम् शास्त्री--दूसरी बात म यह अहना चाहता हूं कि जरा दफ्ता १४५ को ती आप देखिये। उसमे लिखा है कि इस ऐक्ट के निर्देशो पर उपाश्रित रहते हुए, भूगिधर को ऐसी सब भूमि पर, जिमका वह भूमिधर हों, एकान्तिक कब्जे का अधिकार होगा और उसको यह भी अधिकार होगा कि जिस प्रयोजन में चाहे उर में वह उसका उपयोग कर सके। जमीन वेस्ट तो हो जायगी हिज मैजेस्टी मे, कब्जा (पजेशन) होगा काइतकार का और वह उपयोग (यज) कर सकेगा जिस काम (पर्पज) के लिये वह चाहे। तो स्वामित्व होगा हिज मैं जेस्टी में, क़ब्जा होगा किसान में ओर वह उपयोग कर सकेगा उस जमीन का जैसा वह चाहे। तो साहब, यह क्या बात हुई ? कौनसी इसमे ऐसी खास बात है ? हम समाजवादी भी यही कहते है, और जैसा आज श्री कमलापित जी त्रिपाठी और किसी एक मेम्बर माहब ने कहा कि आप एक आंडिनेस पास कर दे ओर २४ घंटे में ऐलान कर दे जर्म दारी सबकी सब ले लेने का। क्यों साहब, जरा यह तो बतलाइयेगा इसमे कौन से फ़र्क की बात रही। हम तो इतने दिनों से चिल्लाते आ रहे हैं कि आर्डिनेंस पास हो आर २४ घंटे में एलान किया जावे कि आज से सब जमीन सरकार की ह और जिसको जो कुछ लेना हो वह पुनर्वास के लिये सरकार के यहां अर्जी दे। हम फिर वही बात दोहराते हैं। इतने दिनों की लड़ाई झगड़े के बाद आप अब यह बात कह रहे है कि आडिनेस पास करके जमीदारी जितनी जल्दी हो सके ले ली जाय। अगर यह अक्ल तीन साल पहिले आगई होती तो शायद इतनी मुसीवत न उठानी पड़ती। यह चीज आपको पहिले से करनी चाहियेथी। अगर यह चीज आपने पहिले कर दी होती तो पिछले तीन सालो में जो य० पी० के किसानों की जमींदारों की तरफ से लूट हुई वह कभी भी नहीं हो सकती थी। सारी बंजर जमीन और सारे पेड़ वगैरह जो कुछ भी थे सब लुट गये क्योंकि वे जानते थे कि जमी-दारी विनाश प्रस्ताव पास हो चुका है। इस तरह से आपने तीन सालों के लिये जमींदारों को मौक़ा दे दिया और अब आप यह कहते हैं कि साहब जल्दी से आडिनेंस पास कर दिया जाय। लेकिन में तो कहता हूं कि आपकी ओर से अभी इसमें और देर लगेगी। जहां तक हो सकेगा आप इसमें देर करेंगे । लगातार ६ माह तक यू० पी० के किसानों की लूट हो चुकेगी तब आप कहेंगे कि लो इस कानून को लो, इसको चाटों और अपनी जिन्दगी बरबाद करो।

मं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक मिल्कियत का ताल्लुक है हमारा ख्याल है कि जिप रूप में आप प्रोप्राइटरिशप देने जा रहे हैं और जब देश का उद्योगीकरण करना चाहेंगे, जब देहात में सही मानों में सहयोगी खेती या सामूहिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो उस मौक़े पर किसान विद्रोह करेंगे। आप उसक सूत्रपत करने जा एरे हैं। में आप से कहा। च:हता, हूं कि आज आयश्यकाः इस बात की है कि आप किसानों को जमीन बेचने का अधिकार न दें। आज ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है कि किसान अपनी जमीन का किसी हालत में बेंच न सकें और इस तरह की आवश्यकता को इसिल्डे महसूस करता

|भी राज राम शास्त्रा]

हू कि अगर आप जाज इस तरह को चीज करेगे तो नसी ना दिया हो ।। १ कल आप जब देहात में उद्योग करना चारेगे से क्या होगा १ कस्त्रीस्टब फामिग कर तण्फ आप करण बढाते ह तो मारे किमान विद्रो कर देगे ओर आप ह पूर पार में रूस ही त रान की नदिया ह जायेगी, जो रूप ने हिया यह जबर्द नो में करने वे लिये तथार नता ता । नकर स तरह को जबर्दस्ती की जायगो नो एमें सबक रू । से रोना है । यह क्यांतिकारी थे नोर पि नी बार उन्होंने किसानो के बल पर गदी सभाली थी। उन्हें कियान और मजदूर के नाम पर अपने निद्धान्ती की तलवार की नोंक पर पूरा घरान के लिये करा उठाना परा । लेकिन हमें तो समझदार आदमी की तरह उनसे राव है हारिए जरना है। लेकिन इएक यह माने नहीं है कि जो काम वहा जबर्दस्ती किया गया गृही हम भी करे। हम यह चाहते है कि जाज जगर किसान तैयार नही हो सकता ह तो धीरे धीरे उसे सगन्ना कर पोपोने जा के जरिये उसे एते रास्ते पर लाये कि तम ाब के हित में एक बाहित है और एक भिटित में सनका हिंत सब लोग मिन कर आगे उद्धो है। जगर आपने व्यक्तिवाद की भनोवृत्ति अही उनमे पदा कर दी तो देश का कत्याण नहीं हमें लोगा में इस तरह की भावना पंदा करनी है कि गभाज को आगे बढाने से ही व्यक्ति आगे यह गहता है और उनका स्क्रीत हा पकतो है। भ चहता है कि देहात में इस भाजना को पैदा कि ता नाम्न कि । ब कि गान एक "एय गा। में रत्ते हती। बदने एक भाय आगे बढाना चारिये। अगर आज यह तत उत्की राज्या त नहीं जायेगी तो तल जायेगो आर हमें उन्हें बताना है कि छोटे-शोटे खेतो से बुन्हारा नाम वहा चार कता ' भर ग्रम्हें एक साथ खेती उनके जार पहयोगिता प्राची काआवरंजन की भावना ठानी चाहिये। आपको को आगरेटिव सोपाइडोच है। हा जिनमे चमावारो का हाथ बहुत कम हो। अगर आप ऐपा नहीं करमें और फिर सह हारिता तथा कोआपरेशन हरेगें तो यह आपका विफल होगा । र यवि आप मजीमावी ढावे पर यह तीसा इंटिया बनायेंगे ता रूपमा वाले वहा पहुंच जा तेगे और उनके मालिक ये अमोबार होगे। ये जमीबार सारे के सारे लट्टर का कूर्ता पिस्नेंगे आर खादी की ही टोपी पहिनगें और लोगों के सामने देश भरत के रूप में आयेंगे। जैमा कि जभी पाग नारायण साहब ने कहा है कि कांग्रेग को चाहिये कि वह गावों में हम लोगों को लेउर बनाये और यकीन मानिये यह लोग लीडर बर्नेंगे और कोआ रिटिय लोसाइटीज इनके ही ग्रास जायेगी। अगर वेहात में को आपरेटिव सो पाइटीज बना ना है तो सबको बराबर एक मिलना चाहिंगे चारे कोई बी हजार रुपया दे, बाहे दल हजार रुपया दे या पाच या दल रुपया दे। अगर ऐसा होगा तो सहकारिता समितिया में किसानी भा प्रभुत्व हागा।

म काग्रे। पार्टी से इतना कहना चाहूंगा कि यह ठोक है विरोध के ित्रये, बोट लेने के लिये भिन्ने ही किताना से कह दे हम तो तुम्हे जमीन वेना चाहने हैं, हग उम्हें जगीन का मालिक बनाना चा ते हैं। मालिक शब्द बार-बार रोशन जना खा साहब ने उस्तेमाल किये थे। लेकिन आप तो स्वामित्व म्डेट को वेना चाहने हैं। वास्तव में जमीन का स्वामित्व समाज के हाथ में होना चाहिये, ज्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं होना चाहिये।

मा ना माला ना उथ--शापके जरिये से एक समाल करना चाहता है कि उपारे योग्न ने शुरू में तो यह कहा था कि इस जमीबारी एवालीशन में जमीबारों की ताबाद नहीं जारतों हैं और इस वक्त काने हैं कि भूमिनरों राइटा नहीं विव जा रहें 5, घोला दिया जा रहा है। "हाउ डज ती रिक्ताइंड को न ट स्टेडने मां"।

ा राजाराम शाप्त्रो—आप कहते हैं कि करजा तुम्हारा रहेगा, जैसे तुम वाही उसकी इस्तेमाल करों लेकिन रवामित्य रहेगा "हिन मैं। दी" के अंदर में। यह क्या गोरख— अंधा है कि नमीन का स्थामित्व तो रहेगा स्टेट में और कह रहे हैं कि ग्म स्थामित्त किसानों को दे रहे हैं। किम न को आप जमीन दे रहें हैं, उसमें आपने ओन रिश इन्तेमाल नहीं किया हैं, स्वामित्व शब्द का दरतेमाल नहीं किया हैं। आपने कहा कि कब्जा रोगा किसानों का और जिस तरह से वह वाहेगे उपयोग (युच्च) करेंगे लेकिन स्थामित्व रहेगा स्टेट का। मेरी समझ

में यह बान नहीं आती कि आप कब्ने की जान क्यों कहते हैं, यह दिक्ले अर क्यों नहीं करने कि स्वामित्व किसान का है। फिर सोदागरी आपकी कहां रहती है। दस गुना लगान केने वाले आप कीन होते हैं? जब किसान के स्विधित्व होगा उत बक्त आप दस गुना लगान नहीं ले सकते। ने आपके साथ सौदा परने के लिये तैयार हूं कि आप ओपेनली डिक्लेयर करिये (खुन्लम बुन्ना एकान को जिये) कि दिनान का जमीन पर स्वाभित्व है ओर आप दस गुना लगान नहीं लेगे। आप तो करते हैं वेईमानी की वात, थोबे छड़ी की बात। जब किसान जमीन का मालिक है तो आप कहां के ठेकेदार है उनकी कीमत मांगने याले।

लेकिन आप जानते हैं कि यह चीज नो हम तुम्हें नभी देगे जब तुन दल गुना लगान दोगे इसके मानी यह है कि किसान ज नीन का मालिक नहीं है और आए दस गुने लगान से सौदागरी कर रहे हैं। अपन ने हिप्मत है तो कहिने किसानों में कि जमींदारी खत्म हो गयी, तुम जमीन के याजिक हो, इस गुना लगान देने की जरूरन नहीं है। लेकिन आप तो सरेबाजार खड़े होकर जंत्रीन की कीनत लगाते हैं कि जो इस गुना लगान देगा वही उसका मालिक होगा। यह थोखा-धड़ी नहीं है तो क्या है ? किसान इस बात को नहीं समझ पाता तो इसके भानी यह नहीं है कि आप इस तरह की चालबाजी करके उसे फंसाने की कोशिश करें। जमींदारों से जमीन छीन कर आप बाजार में खड़े हो कर एलान कर रहे है कि जिसके पास पैसा हो वह उसे ले ले और जिसके पास पैसा नहीं है वह उसको नहीं खरीद सकता। इसमें भी कमाल की यह बात है कि जो सबसे ज्यादा गरीब है उसकी १५ गुना लगान देना पड़ेगा और उससे कम गरीब जो है उसका इस गुना लगान अदा करना है और जो बड़े-बड़े जमींदार है उनके लिये खुला एलान है कि तुम्हारे पास चाहे १० हजार बीघा जमीन हो, खुदकाइत और सीर जितनी भी हो, तुन से एक पैसा भी नहीं लेंगे। यह है कांग्रेस का बाजार। इसके बाद मुझसे आप पूछते है कि तुम जनीत का मालिक किस को समझते हो। सीधी बात यह है कि हमने ज्यादा ईमानदारी है। हम साफ कहते हैं कि जमीन का मालिक समाज है, ज्यवित नहीं हो सकते है। आप सौदागर ऐसी हालत में मैं कहता हूं कि यह बात सफाई के साथ कह दी जाय कि जमीन का मालिक समाज है। आपने ग्राम पंचायतें बनाई है। हम तो कहते हैं जमीन का इंतजाम गांव पंचायतों के हाथ में दे दीजिये। आप समझते हं

माननीय माल सचिव--जरा आहिस्ता बोलिये। समझ मे नहीं आ रहा है '

श्री राजाराम शास्त्री--बहुत ठीक बात आपने कही है। आप यह कहते है कि खेती का सारा इन्तजाम जो किया जायगा वह आने वाले भूमिधर और नये बनने वाले जमींदार ही कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि आप यह क्यों समझते हैं कि किसान एक साथ मिल कर जमीन का इन्तजाम नहीं कर सकता। जो देहात के अन्दर पंचायत पर बैठ कर. जज बनेगा' टैक्स लगायेगा और देहात का सारा इंतजाम करेगा क्या उसकी सामृहिक अक्ल में इतनी बात नहीं आ सकती कि सारे के सारे ग्राम की सामृहिक रोती किस तरह मे की जाय? हमारा यकीन है कि अगर मौका दिया जाय. शिक्षा दी जाय, अच्छी तरह से अवसर दिया जाय, तो एक दिन आयेगा जब पंचायत व्यवस्था उन्नति करेगी और इसी देहात के अन्दर शासक बन कर बैठेगी। हमारी जिन्दगी में ही यही गांव पंचायने सामृहिक रूप ने नयी चीर्जे लेकर आगे बहुँगी, यही ग्राम पंचायने अपनी मशीनरी से, अपनी अवल मे, अच्छा इन्तजाम करेंगी और इस कांग्रेस की हुकूमत से ओर उन भूमिधरों में हजारों दर्जे अच्छा इंनजाम कर के दिखला हैंगी। इस मैं भी जब कियानों और मजदूरों की हुन्मत आयी तो लोग कहते थे कि यह मिलों में काम करने याले मजदूर और यह कावडा चलाने वाले किसान क्या जाने हुरू यत करना। मैं भी कम्युनिस्टों का दुछ विरोधी रदा हं। लेकिन आज कहता. हं कि इस के किसानों और सजदूरों ने अपने यहां के जमींदारों भूनिवरों और अपने यहां के कांग्रेसियों से कहीं अच्छा इन्तजाम करके दिखला दिया। आप लोगों के कमअक्ली की यात हैं कि सारी अक्ल का ठेका आपका ही है और ग्राम पंचायते काम नहीं कर सकती है । मै तो कहता हूं कि ग्राम पंचायतों के हाथ में जमीन की मिल्कियत हो।

[श्री राजाराम शास्त्री]

भ इनी के तथ बड़े अफसोरा के साथ यह भी कहता ह कि हाउस में जब जब इस उसूल पर बहम को १८ कि हम मुआविजा देया न देया दें तो कितना दें, तो इस सिलिसिले मे बार-बार आचार्य गरेन्द्रदेव जी का नाम लिया गया। एक व्यक्ति जो इस हाउस जा मेम्बर नहीं जो जा कि तकीं का जवान नहीं दे सकता है, आप उनके नाम को क्यों शामने लाते नै ! उन्होंने पूरी चीजे जो कुछ भी पैश की है, अगर उन सबको मान लिया होता तो भी में समजता कि आप के अन्दर ईमानदारी है। मजाविता दिया जाय उसका बोज रईमो पर पड़े कि गरीबों पर पड़े, जमीन का त्यपारा किया जाय या नहीं। में कहता ह कि उनकी वाते पूरी तरह मे मान ली जाये। अगर आचार्य जी को मानते हो तो जमीन के बटवारे की भी बात मान लो। आचार्य जी ने एक मीटिंग में यह कह दिया था कि अपर हमारी बात मानते हो, अगर बराबर रात दिन हमारे नाम का माला जवा करते हो तो लो इतनी बात कर लो' जो गवाही मेने दो ह उसकी ही मान लो। उनकी गवाही जिसका आप बराबर जिक्र किया करते हो उस गवाही को भी आपने छापा नहीं है कि क्या गवाहो थी। शेर उसी की मान लीजिये। यह तथा बात है कि उनकी बात भी ने मानो और उनकी बातां को बार--बार पेश करो और उनके नाम की मालो जपते जलो? इसरो मरो प्रकीन हा गया इस बात का कि लोगों ने असमें त्या ली है कि चाहे आचार्य जी त्रद समझावे और बाहे आचार्य जी का कोई अनुवायी किनना ही समझावे ये साहब कसम खाये हैं कि किसी भी हालन में रामधने की की किश ही नहीं करेंगे और दिन रात कोसते रहेगे उन्हें, किसानों को भड़काने के लिये, देश की जनता की भड़काने क लिये उनको गुमराह करने के लिये आचार्य जी की गयाही पैश करते रहेगे। में आगरो इतना ही कहंगा कि यह चीन कोई ईमानदारी का बात नहीं है।

नुआबिने के बारे में हम लांगों को एक स्वत्य राय है और वह यह ह कि जैंगा मैने अभी अपने व्याख्यान में कहा है कि हम इस बात को कनई मानने के लिये तैयार नहीं है कि यह जनीन जनींदारों की मिलिक्यत है। चाहे तातून की निगाह से भले ही हो लेकिन न्याय की निगाह में नहीं है ओर मैं इस बात को मानने के ियं नैयार नहीं हूं कि जिं। जमीन को खुदा ने बनाया है, जिस जमीन को प्रक्रिया ने पैशा किया है ' उसमें किया इंमान का कोई स्वामित्व हो। जिस तरीके से हवा और रोशनी हैं पानी हैं यह सब बीजे कुदरत ने इंसान की बेहबूबी के लिये बनाई हैं उसी तरह से काफी बड़ी नावाद में जमीन भी उसने दी ह कि अगर इंसान अवल से काम ले तो मेरा विश्वास है कि द्वितया भर में जितते हम और आप इंसान है उनका भरण-पोषण वह कर सकती है। मै यह समशता हं कि जमींदारों को इस जात का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि बहु इस बक्त नमी रारी के खत्म होने पर मुआविजा मार्गे। पहली चीज तो यह कि इन नमीं दारों में कितने ऐरो है कि जिनके पूर्वजों ने जमींबारिया ली लेकिन कितने ऐसे हैं जिनकी मुख्त में मिली होती' अपने देश के साथ विश्यास घान की वजह से मिली होगी और कितनी ने जमीन खरीवी होगी। इसके अलावा जनका न मालूम कितना गुना रुपया ये आज तक उप जमीन से वसूल कर चुके हैं। तो आप अब थोड़ी वेर के लिये सोचिये कि क्या इनको मुआविजा पाने का कोई नैतिक अधिकार जमीन की उन्नति में उन्होंने कौन सा काम किया सिवाय किसानों को तबाह व षरबाद करने के? आज तक कोई रिकार्ड नहीं है कि इन्होंने जमीनों की उन्नति के लिये सिवाय किसानों के तबाह व बरबाद करने के कुछ किया है। इसलिये जहां तक नैतिकता का सम्बन्ध है जमींवारों को मुआविजा पार्ने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात मै नहीं कहता, जैसा मैने पिछली बार भी कहा था बाब सम्पूर्णनिन्द जी ने एक लेख लिखा या ज्ञायव जमींवारी एवालीशन के सम्बन्ध में और उन्होंने उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जहां तक नैतिकता का ताल्लुक है जमींदारों को मुआबिजा छेने का कोई अधिकार नहीं है । तो हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि आपको ऐसी कौन सी गरज इस वक्त पड़ गई जिसके लिये आपने इतनी बड़ी थैली खोल दी है ? नहीं ! नहीं ! आपने अपनी थैली नहीं खोल दी है, मैं भूल से कह रहा हूं, सरकार किसानों की जान ले रही है, उनकी चमड़ी उघेड़ कर आप पैसा बसूल कर रहे हैं और दे रहे हैं उनको जिनके पास पैसा पहिले ही काफी भरा है। ऐसी हालत में मेरी समझ मेनहीं आता कि आपके दिल में ये भाव क्यों पैदा हुये? अब आचार्यं जी की बात कही जाती है लेकिन में आपसे कहता हूं कि आचार्यं जी की वह गवाही हुई थी उस जमाने मे जब १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्दर हम लोग थे। उसके खत्म करने (एबालीशन) का हक कांग्रेस को नहीं था। जब एक इंसान चारों तरफ से जकड़ा हुआ हो और उसको कोई हक न हो कि उस कानून के बाहर जा सके, उस मौके रर वह बात कही गई थी जब हमको कोई हक नहीं था। मेरे साथी रोशनजमां जा ने उनकी रिपोर्ट आपके सामने रख दी। उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि मै कनई यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इन जमीदारों की मुआविजा लेने का कोई हक है और न हम इन गदारों को कोई मुआविजा देन के लिये तैयार है। हम इस गहारी को कोई मौका देने को तैयार नहीं है। हम समझते है कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं कि मुआविजा दिया जाय, लेकिन चूंकि १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्दर बंधे हुये हैं, उसे बदल नहीं सकते और आप मुआविजा देना ही चाहते हैं तो इस तरह से दे कि देश की बहबूदी हो और वह भी पुनर्वासन के नाम से। अगर आप चाहते हैं और यह ईमानदारी की बात है, कि इनको मुआविजा न दिया जाय तो बया यह सम्भव नहीं था कि आप कोई ऐसी तरकीब निकालते कि जिस कानून से आप बंधे हुने हैं उस कानून को ही बदल डालते। मेरी समझ में नहीं आता कि जितना और कांग्रेस याले करना चाहते है, तो उसमे १९३५ ई० का ऐक्ट अड्चन नहीं डालता, देश का बटवारा करना हो, देश के दो टुकड़े करना हो, तो उसमे १९३५ ई० का ऐक्ट खलल नहीं डालता। उसके बाद अगर पूजीपितयों को कोई रिआयत देनी है तो कोई कानुनी अध्यन नहीं पडती, अगर किसी भले आदमी की बिना किसी बात के गिरफ्तार करना हो तो कोई काननी अड्चन नहीं होती। कोई भी काम जो करना चाहते हैं उसमें कोई कानूनी अड्चन नहीं होती लेकिन जिस वक्त हजारों-करोड़ों किसानों के हित में कुछ करना होता है तो फिर १९३५ ई० के ऐक्ट की याद आती है। १९३५ ई० का ऐक्ट जाने दीजिये, उस दिन एक सदस्य ने कहा कि हिंदुस्तान का नया वियान जो बना है, जिसकी २६ जनवरी को सारे देश में दीवाली मनायी जायगी, उसमें भी यह पास कर दिया है कि अगर किमी की जमीन-जायदाद लेनी हो तो बिना मुआविजा दिये हुये नहीं ली जा सकती। तो यहां पर मजबूरी है किस बात की। आप ही तो दिल्ली की गद्दी पर भी बैठे हुये हु। अगर राजाओं को राजप्रमख बना कर बैठा सकते हैं, निजाम को गद्दी पर बैठा सकते हैं, राजा और रानी की जेब के लिये ४०-५० लाख दे सकते हैं, तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि क्या सचमुच ऐसे कानून नहीं बना सकते थ, जिसमें सदा स्टेट को यह अधिकार रहता कि अगर वह मुनासिब समझेगी तो मुआविजा देगी और अगर नहीं देना चाहेगी तो नहीं देगी। मेरा विश्वास है कि अगर हिन्दुस्तान का शासन विधान किसान और मजदूरों ने बनाया होता तो मुआविजा देने का प्रश्न कभी भी नहीं उठता। हिन्दुस्तान का शासन विधान जो दिल्ली में बना है उसको हिन्दुस्तान के १३ प्रतिशत लोगों ने बनाया है, जिसमें ज्यादा-तर ऐसे लोग है, जिनके पास धन और दौलत है। आप ऐसे शासन विधान को भले ही पास कर ले, उनकी दीवाली मना लें, लेकिन एक जमाना आयगा जब समाजवादी शासन बनेगा और इस शासन विधान को नहीं मानेगा।

माननीय माज सचित्र--आपकी आवाज फिर अर्राने लगी, समझ मे नहीं आता।

• श्री राजार। म शास्त्री—समझ में कैसे आये, समझ में तो तब आये जब आपकी नियत साफ हो। आपका कांग्रेस में बहुमत है, यू० पी० में बैठ कर यह बात कहें कि हमारे हाय बैंधे हैं इसलिये मुआविजा देना पड़ता है, यह बात गलत है। आप यहां भी बैठे हैं और दिल्ली में भी बैठे हुये हैं। जिस प्रकार यहां खैरात बंट रही है, उसी प्रकार दिल्ली में भी शीरामाराम शास्त्री [

खैरात बंट रही है, आप वहा भी पूंजीपनियों को खैरात बाट रहे हैं। इसमे आपको काननी अडचन न हो पड़नी। पनो कहता ह कि चूंकि आप पूजी रितयों की अपनी पार्टी में लिये हुये त, नेव तो या ने कि वे ही पार्टी में हु ही, इसलिये आपने ऐसी दक्षा खनाई हुं और इस दका की आड़ लेकर ऐसी बाते करते हु। आप आचार्य जी की बात करते हैं कि अतार्यार्थ जी में गवाही दी थी लेकिन अगर काग्रेस के लोग चाहते और उनकी नीवत तक होती तो उनको निवाल सहने ये ओर मुआविजे के सवालको खत्म कर सकतेथे। मैं आवको जावार्य जो हा बयात सुनाने को तैयार नतो हो। हमारी पार्टी का साफ रजान है कि जानीन में जनीदार की निलक्ष के भी निल्कात नहीं है। (एक आवाज) (समाजनादिनों की अक्ल नरकती राती हैं) अक्लमन्दी का तो पतकान है कि अगर कोई बात समझ में आ जापतो उसको पान लेगा याहिये लेकिन उनकी तो नहि ही नही है। हम कोई जानवर नहा है जिनके अनल नहो, हमने इस बात का ठे हा नही लिया है कि चाहे बुनिया बदल जाय लेकिन हा । जी बरलेंगे। कुछ लोग तो इस बात को कगम खाकर आये है कि चाहे यु० पी० तबाहु हो जाय, चाहे देश का कुछ भी क्यों न हो लेकिन अपनी अकल को नहीं बदलेंगे। आपकी अक र आकि साथ और हमारी हमारे साथ। गराम हिन्द्स्तान के जमाने में कोई राय हो सकती थी। आज हमने १९३५ ई० की दकाओं को फाड़ फेँका है, ग्रामी की अकल को बहुल दिया है। अगर हमने ऐसा किया है तो प्या गुनाह जिया है ? किन्दुस्तान आज आजाद हो गरा है और अब १९३५ ई० का का तून गर गरा है लेकिन आप कलते है कि आजाद हिन्द्रा नी नाजाद सरकार कापम हो गई, अंगरेज चले गये लेकि अंगरेजों की आपकी अक्ट नहीं गई। कल फहा गया था कि सोशिलस्ट चले गये लेकिन अपनी ओहाइ छोड़ गये। कांग्रेस की ओर एक साहब ने ओलाद जा मतलब उत्तराधिकारी तमाया। में कर्ना चाउता हूं कि अंगरेज तो चले गये लेकिन उसके गर्भ में पैदा हुई अगर कोई सरकार है तो उतकी उत्तराधिकारी यही कांग्रेस मरहार हु। अंगरेजों की ओलाद यही कांग्रस सरहार है।

न्द्रिक्टी स्पीकर--आप ज्यादा तेज बो उने हैं तो माईको होन पर गुळ सुनाई नहीं देता। श्री राजाराम शास्त्री--आपने बहुन अच्छे मो के पर कहा में बहुत मार्के की बात कह रहा था। मैंने जान-बूस कर अपने को इतनी दूर माईकोफोन से रखा है और अब ध्यान रखूंगा। कल यह कहा गया था कि सोशिलस्ट चले गये और ओलाव छोड़ गये और औलाद के मानी उत्तराधिकारी लगाये गये में। में कहना चाहता हूं कि अंगरेज उत्तराधिकारी छोड़ गये और उत्तराधिकार के माने चले गये और अपना में क्यों कहं यह आपकी ही अपनी परिभाषा है। (किसी के फिर टोकने पर) आपकी यह अक्ल अंगरेजों के कारण है। इसमें रसी भर भी मुझे कोई शिकायत नहीं। जिस गर्भ से इंसान पैदा होता है उसका असर रहा ही करता है। अगर आप कहते है कि आपकी अक्ल इतनी जल्दी बदलती है तो में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि दुनिया आज बड़ी तेजी से बदल रही है। आज कुछ नक्शा बदला है, कल कुछ और हो जायेगा। समझारी यही है कि जो जमाना हो, दुनिया जिस रफ्तार से चल रही हो, उसको देखकर हम चलें। न कि क्यमंड्र बने हुवे च्वांग-काई-शेक की तरह हो जायं। में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार परिस्थित बदले, जैसे-जैसे जमाना बदले उसके मताबिक जरा अक्ल से काम लेना सीखें और उस अक्लको बदलना सीखें। यह कसम न खार्य कि जो अक्ल ५० साल पहिले थी, जो २० साल पहिले थी, जो १० साल पहिले थी हम वही रखेंगे चाहे जमाना ही क्यों न बदल जाय। इसमें आपका भी नुक़सान है और मुल्क का भी। इमिलिये यह तानेवाजी करना अच्छी बात नहीं है। में आपको बतलाऊँगा कि यह बुरी बात नहीं है, यह तो अक्जमन्दी की बात है। अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अगर नहीं सीखते तो देश आपको सिखायेगा कि किस तरह बवला जाता है, किम तरह देश और जनता का काम किया जाता है।

फूलॉसह जो ने यह देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग यहां स्पीच देंगे तो कहीं ऐसा न हो कि देहात में आप जो करिश्में कर रहे हैं उनकी पोल खुल जाय। इसलिये फूलसिंह जी ने कहा कि यह बात समझ में नहीं आती कि इस बिंच का १० पुना लगान से क्या ताल्जुक है। अरे साहब इस बिन्न के जो स्टेटमेट आफ आब्जेक्ट्स ऐड रीजंस दिने हमे है, उसमें देखिये विलक्कल साफ जिला हुआ है, "अर्धि ह और विविध केठिनाइयो की दूर करने के लिये काइनकारों से यह फहा जायगा कि वे अपने लगान का दम गना स्वेच्छा से दे दें"। तो मैं सिर्फ इस बात पर थोड़ो देर नात करना चाहना हूं कि यह स्वेच्छा नानी बात आज कही जा रही है, सारे देश और दुनिया में, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्रीय अगर किसी बात से हैं तो इसी बात से हैं कि दसगुना के नाम पर आज परे आम देहात के किसानों की एक तरह से लूट की जा रही है और जो जो हथकंड़े काग्रेस सरकार की तरफ से कास मे लाये जा रहे हैं अगर उन तमाम हयकंडो को यह हाउन मुरेगा तो मुझे यकीन है कि आपकी खुद की आंखे खुरुगी और देश की जनता की भी आखे खुलेगी। चुंकि मैं एक विरोधी पार्टी का मेम्बर हूं इसिन्धे किसी बात को चाहे जितनी सच्चाई से कहूं लेकिन आप उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होते है। मैं बहुत ही सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि जब में कांग्रेसी हुकूमत में कोई खराबी देखता हूं तो मुझको इसिन्धे खुशी नहीं होती कि हमको एक मौका पिलना है कि हम जनता को आपके खिलाफ भड़काये बल्कि मुझको दुख होता है कि सारी जिन्दगी जिस कांग्रेस में कान किया, जिसरे आजतक देश को आगे बढ़ाने में इतना काम किया, जिसकी तरफ आज भी देश की जनना देखती है अगर उसने वहीं वह काम करना इन्ह किया जिससे हमारे देग दा भविष्य अधकार में हो, तो एक सच्चा सिपाही होने के नाते मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मै उन बुराइयों को आयके सामने इप्तलिये पेश कर दूं कि आप अपनी शक्ल ठीक तोर से देख सके। आप अपनी शक्य को ठीक तौर से नहीं देखेंगे तो निर्फ इतना ही नुकनान नहीं होगा कि कांग्रसपार्टी मरेगी बल्फि देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सिर्फ इतना ही होता कि कि काग्रेम पार्टी मरती तो कोई बात नही थी क्योंकि वहुत सी पार्टियां आयेगी और मरेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज आप जो बीज वो रहे हैं उसमें से जो पौबे निकलेगे और जो जहर पैदा होगा उससे ऐसी फिजा पैदा हो जायेगी कि देश की जनता हमेशा के लिये ऐसे शासन के खिलाफ ही जायेगी। में यह महसूस करता हं कि उबर के बठने वाले लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं है। वह पार्टी-बन्दी में इतना बेखद हो चुके है कि उनकी बुद्धि ही काम नहीं करती है और वह यह समझते हैं कि सरकार की जो हुजूरी करना ही मुख्य ध्येय बन गया है। हम देहातों में जाते हैं। हमारे सामने पटवारी आते हैं, हमारे सामने शिक्षक आते है, हमारे सामने सरपंज आते है, पंज आते है और गांव के सभापति आते है, जिनसे मेने बाते की और जिन्होंने मुझे कुछ कागज दिखलाये जिनसे यह पता चला कि किस तरह आप कांफीडेंशल सक्री लर ऑर्डर्स भेजते है औप किन-किन तरीकों से आप दस गुना लगान वसूल करते है। में सोचा करता था कि क्या करूं? कैसे पंत जी को बतलाऊं? कैसे कांग्रेस को बतलाऊं कि आपके राज्य में यह हो रहा है, लेकिन क्या करूं अखबार है तो उनके है, लेखक है तो उनके ' है और जितनी चीजे हैं सब उनकी खरीदी हुई है। आखिर सत्य को कैसे आपके सामने लाया जाय ? (एक आवाज- दिल चीर करके) मेरे दिल चीरने से अगर आपको अक्ल आती और देश की भलाई होती तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल चीर करके दिखा देता लेकिन मझे यकीन है कि अगर मैं दिल चीर करके भी दिखा दूंती भी आप उसकी कीमत को नहीं समझ सकते। मैं यह बाते आप के सामने संक्षेप में पैश करना चाहता हं कि जिन तरीकों से आज देहातों में बिलकुल स्वेच्छा से, रत्ती भर भी जिसमें इनके लिहाज से कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा रही है। पंतजी ने कहा है और इस हाउस में भी बार-बार कहा गया है। पहिली चीज तो यह कि एक जगह से नहीं, कई जगह से मेरे पास इस तरह की खबरें आई है कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता तो नहीं लेकिन नीचे के सरकारी आफिसरान जिस तरीके से आजकल अपना व्यवहार करते हैं उनके देखने से

श्री राजाराम शास्त्री]

मझे ऐसा मालूम पडता है कि कोई न कोइ गुप्त भक्यूंलर गवर्नमेट की तरफ से अपने सब डियार मेर एको निश्चित रूप से भेजा गया है। जिसकी वजह से मे देखता हं कि यू० पी ० के किसी भी जिले में जाइ ने तो हर जगह पर पाम पंत्रों के पास, प्राप सरवत्तों के पास और प्राम सभा-के सभावितयों के पास बिल्कुल एक सी भाषा में सक्यू लर हर जगह के इंसवेक्टरों ने अपने-अपने यहा के लोगों को दिया है और उनकी एक सी भाषा है। एक सा इल्जाम है, और एक सी आवाज है। किसी के ऊपर लिया है काफीडेशियल और किसी के ऊपर काफोड़ि शियल नही किला है। जब मैं सब जगह एक ही आवाज देखता ह तो मेरे दिल मे ख्याल हो ना है कि इस तरह का सक्यं लर सभी जगत गया है और यह बोखलाहट क्यो ? पहिले कागरेन को यह एतीन या कि इसके पति जनता की कितनी भिनत है, वह बड़ी अतिन एकी है, महात्ता गानी हा सिक्ता उसके उाथ में हैं, अखबार अपने हाथ में है और ज्योही पर एलान करेगी कि दन गुना लगान देकर किसान मीनवर वा जा तो फोरन एह-दो महीने के अन्दर ही करोड़ हो। उनके नवाने में जाहर गिर पहेगा, शुरू तो में इतना सहती नहीं यो क्यों कि जुण में तो ये ढिडोरा पीटते थे और भी किसी मिनिस्टर का कभी कियो शिनस्टर का अवसरों में फोटो निकलना या कि फला भिनिस्टर दस गना कपया देकर भिष्ठिय जन गर्वे गोर उनको देखकर हजारो जिलान मुसिधर जन रहे हैं, कारी पर अम्बीतरों में यह ज्वा था कि देहा के किसान जन्द्रस बना कर अपने अपने जेबो में नोट भर-भर कर खनाने की तरफ दोए रहे है। में भी सोनता था कि कोन सी ऐसी करामात हो गया जिसकी अजह में कियानों में ऐसा जोश ा खरी। पैदा हो गया। हम देहात में गर्भ तो नहा भी ए। तरह हा प्रोपेगेण्या जोरों पर थ। कि हमारे ऐपा आदमी भी उपसे प्रभावित हो गया कि जनम बलीग अने जोर का बोड लगाते हैं और पर्यो ऐसी चीख करते हैं। इसारे भैसा रे शबर मेने उपारिते इसीपार कि विकासियर में भी तो इस्ही के सह का गड़ा है। इस इसको सा राधतां से अच्छी तरह गिक है। हम इसको गा असी को असते हैं और सार उसको असते हुउँ भी हमार करर ऐसा असर पदमान है। अमिता में सिद्धान्त जनात । एक तो रात है लेकिन आप यववारों में पहें तो भाजून होगा कि इन वो भरी ने क्या नयू न हुता।

श्रा द्वारिका स्मान् मी र्ये हिन्दो स्वीतर होदयमं एत्स एल पूजना चाहता हं कि जिन मीलिल्स्टों ने अपना दय ग्रा काथा जना कर दिया है क्या उनके खिलाफ सीतिल्स्ट पार्टी कोई कार्यवाही कर रही है ? मेरे यहा थी रामनरेश सिंह ने अपना दस मुना राग जमा कर रिया है, जो आपकी पार्टी के एक अदस्य है।

श्रा राजागम शास्त्री—तो लिस्न पार्टी में काग्रंस की तरह से ताना गही नहीं है कि इस बात के कि में किनो सबस्य के जि काफ कार्य गहों करने की आवश्यकता महसूस हो। हम किसी सो शिल्स्ट कार्यकर्त्ता को दगतरह से नहीं दबाते हैं जित तरह से काग्रंस अपने सबस्तों को वबाती है। हर एक मनक्य में कुछ न कुछ कमजोरी होती है। कितने सो शिल्स्ट तो बिलकुल कमजोर निकले, वे काग्रंस में और अपनी नृक्षान चलाने के लिये और कुछ असे स्वली में मेम्बरी के लिये और कुछ जनता और किसानों के नेता बनने के लिये काग्रंस में गये। लेकिन जब इम्तहान का यक्त आता तो कितने उसमें पास हुये? बहुत से लोगों ने विश्वापधात किया। आज अगर कोई बेहात का सो शिल्स्ट कांग्रंस के जल्म के आनंक में आकर, उसके अत्याचार से इर कर, वह बेचारा गरीब देहात का मारा हुआ मो शिलम्ट क्या जमा कर दे तो मेरी समझ में नहीं आता कि उसको हम सो शिलस्ट पार्टी से क्यो निकाल वे? इस तरह से पार्टी से निकाल बाहर करने की ताना गहीं से को लिस्ट पार्टी में नहीं है। यह ताना गहीं तो काग्रंस में है। कोई बात नहीं है, आज वह दब गया तो दब गया कल उसको किर हिम्मत आयगी। हम उसकी निकालने के पक्ष में नहीं है। लेकिन में अपने बोस्तों से यह पूछता हूं कि क्यों साहब

आप जमीन—आसमान एक कर रहे है कि दस गुना लगान दो और भूमिधर बन जाओ, लेकिन क्या सब कांग्रेसी ऐसे हैं, जो १० गुना लगान देकर भूमिधर बन गये हें ? आप एलान कीजिये कि जिन्होंने नहीं दिया है उनको हम निकालने के लिये तैयार हैं।

डिप्टा स्पाकर-में माननीय मेम्बरान से दरख्वास्त करूंगा कि बीच-बीच में रोक-टोक न

करे।

श्री राजाराम शास्त्री—बात यह हें साहब ये लोग जान-बूझ कर छेड़खानी करते हैं जिससे कि में जोर से बोलुं।

डिप्टो स्पाकर--आप मेरी तरफ मुखातिब रहे और उनकी तरफ न देखे। मेरी तरफ

निगाह रखें।

श्रा राजा राम शास्त्रा-यकीन मानिये कि मेरी निगाह आपकी तरफ है, लेकिन कभी-कभी कान इधर लग जाते हैं। मे यह कह रहा था कि कौन-कौन से तरीके हैं जिनकी, स्वेच्छा से लगान वसूल करना कहा जाता हैं। कल एक साहब ने सुल्तानपुर का जिक किया कि हमारा जिला सब से आगे रहा। मै सोच रहा था कि आखिर इस जिले के साथ ही कौन सी खास बात है और में अखबार को खोज रहा था कि देखूं अखबार से कुछ मिले। यह अखबार हैं 'संघर्ष' तारी अ९ जनवरी' सका ११ पर लिखा हुआ है कि ''दसगुना लगान न देने पर जूतों की मार'' मैने इसलिये यह पड़ना शुरू किया कि लोग शुरू में हंसे। में अभी यह भी बतलाऊंगा कि आपके अखबारों में क्या लिखा जाता है इसका भी पता लगेगा। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह से जूते मारकर उससे १० गुना लगान वसूल किया गया। और उसकी पूरी चिटठी इस अखबार में छपी हैं। अगर गलत है तो मै साफ आपसे कहता हूं कि आप उस अखबार पर कान्नी कार्यवाही कर सकते हैं। उनके खिलाफ मुकद्दमा चलाये, साबित कीजिये और अदालत में जाइये। लेकिन आप वहां नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पर अदालत में जूते की मार किस तरह से पड़ी यह सब कलई खुल जायगी और आप जो यह कहते ह और बराबर प्रोयेगेन्डा करते हैं कि स्वेच्छा से लोग जमा करते हैं वह सब कलई खुल जायगी और दुनिया समझ जायगी कि असलियत क्या हैं?

एक सदस्य--क्या आप यह बतला सकते हैं कि यह मामला कहां का है?

श्रा राजि। राम शास्त्री—यह मामला अब्दुल्लापुर, थाना अमेठी, जिला सुस्तानपुर के राम—फूल के ऊपर हुआ है और उसी पर यह जूतों की मार पड़ी है।

एक सदस्य-क्या यह सोजलिस्ट है ?

श्रा राजाराम शास्त्री—पह देख लीजिये कि अगर सोशिलस्ट है तो उसके अपर जूतों की मार पड़ने दीजिये, यह हालत हैं। आपका मतलब यह हैं कि अगर कोई सोशिलस्ट ह और उस पर जूते पड़ते ह तो पड़ने दीजिए। यही मैं इन अखबारों से साबित करने जा रहा हूं। यही आपके गुप्त सरक्यूलर है कि विरोधी पार्टियों के आदिमियों को तबाह करों, उनको जूतों से मारो, उनकी जायदावें जब्त कर लो और बन्द कर दो, अगर वह दस गुना लगान जमा करने के खिलाफ अपनी जबान खोले। आप को शर्म आना चाहिए। यही डेमोकेसी हैं, यही महात्मा गांधी के मार्ग पर आप चल रहे हैं। मैं तो आप से कहता हूं कि अगर कोई सोशिलस्ट किसान ह और उसके जूते पड़ते हैं तो मुझे दुख होता है और मैं तो समझता हूं कि उसका दुख आप को चोगुना होना चाहिए। यह कोई ऐसी बात कहने का तरीका नहीं ह।

मने अभी आपको यह बतलाया कि इस तरह से सुल्तानपुर के जिले में जते मार-मार कर सब से ज्याद। वसूली हो रही ह। दूसरा नमूना यह है कि मेरे हाथ में यह "हलवल" अखबार ह। इसके सम्पादक है आप की असेम्बली के मेम्बर और कांग्रेस पार्टी के मेम्बर श्री. बृजमोहन स्टाल शास्त्री।

प्क सदस्य--वह तो आप से मिले हुए हैं।

श्रा राजा राम बाह । --वह तो आप की तरफ ही बैठते हैं, पिल्ले आप अपना घर संभालिए। एक यही, नहीं है, आप की पार्टी में कित ने ही ऐसे सच्चे ईमानदार ए कि जो यहा नहीं बोल सकते, लकिन बाहर अखबारों में बोलते हैं और म आप से कहता है ि अगर आप इसी तरह से अपनी कान लगाए रहेतो बहुत जल्द तयाह हो जायगे। अभो उन्छ दिन पिले बरेली मे आपके श्री चरण सिंह साहब गए। आप वहा भीटिंग में तकरी कर रहे थे। यह तो आप जानते ही है कि उनको तकरीर बड़ी जोरदार होती है और वह गाधी जी का नाम छिए बगेर तो खाना ही नहीं लाते हु। आप अपनी नकरार के बाद म जहने हो कि बाप लोग चाहे दस गुना लगान वैयान देयह आप की स्वेच्छा पर ह और अगर किसी भाई पर कोई सण्तो हई हो तो बतलावे। इस पर एक सज्जन खड़े हुए ओर उन्हाने ५ हा कि फला आदगी ने मेरे बाद के बाटा मारा। यह सुनकर आप के सामने वहा के कलेस्टर साहब खडे हो। गए और उन्होंने कहा कि इस। आदमी ने कुछ अपशब्द कहे थे इसोलिए उसके चाटा मारा गपा। उसी मी 📭 मे श्री बजमोहन लाल उन्होन कहा जगर इस तरह से आप बादा मार सर 13 तो यह जिटने वाले भी शास्त्री भी थे। आपको किसी दिन पीट कर रहेगे। मगर अफगोग ह कि गानी जी का नाम लेने वाले ने उस अखबार में यह नहीं ि असा कि इस पर चरण सिंह सा १४ ने। १ स्ट्रिंग्ट अजिस्ट्रेट को वया हिदायत क्या उन्होंने उनको यह उपदेश दिया कि गाउँचालों है ने हैं मारे । देशे । म यह जानना चाहता हूं कि किसी भी सरकारी अफसर की क्या पह हवा है कि वह हानन को अपने हाथ में है सरासर नाटा मारा गया ओर आप । जिस्टू ८ मी नर्ेड आप केषाः जालेटरी सेक्रेटरी क सामने चाटा मा ने का समर्थन करने करिए चटेहाते । या उस्म या न बहुत फर्क हो गया है। आप का याद होगा कि पारसा रूथा । भरन गर्को । ह ने में भ्या आदमी के एक चाटा मारा दिया था और हमने इसी हा उस म उन राजा । यो र जाया ११ जार उस म ता पर उन से इसी काग्रंस सरकार ने कम से कम माफी मगवाई थी, अंकन एक साउ की जोर हजूमत के बाद आप में यह तब्दीली पेदा हुई कि आप का एक छोटा नीचे का जफ़रार पालियामटरी हो उटरी के सामने खरो होकर कहता है कि फला जाबमों न एसे शब्द करें इसिएए नह मारा गया। 🖫 🖫 अखबार में पृष्ठ ७ पर दिप्पणी वी हुई है, उसमें िया हुआ है कि जिस में पढ़ कर मुझे ताज्जुब होता है, में कह नही सकता कि यह गए तह सही हो । इसमें लिया हुआ है, कि चरण सिंह साहत्र ने यह कहा कि जो अगार हमारे समनो पर पलता है वह हमारी नुबताचीनी करता नुं। जरा गोर वीजिये। गारेस के एम० एल० ए० अपने अखबार में यह बीज लिपते हैं। आप ने गृह उमकी वी कि जो अराबार सरकार के वमनो पर जिन्दा रहते हैं वह सरकार की न् । ता रीनी कमे कर सकते हैं। आप साफ क्यो नही कहते, बड़े अफसोस की बात है । यह कहना कि एस प ऐसा हुआ तो गय। यह भी ऐसा होगा । म आपको विश्वास विलाना चाहता हू कि म इसी साम्यवाद की हर एक बात की एवाहमख्वाह मानने के लिय तयार नहीं हूं न उसका समयन ही एयाहमरवाह करना चाहता हूं। आप रूस की बात करते हैं। अगर रस ने कोई गलत वात की है तो में उसकी मानने के लिये तैयार समाजवादी भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो में उसे कभी न मानूगा। आप का तो तरीका यह है कि कार्रेस का आदमी सब कुछ कर सकता है। दूसरी पाटी का आदमी हो तो आप उसके साथ इस तरीके से कहते हैं। रूम में जो हुआ वह उस के साथ होना हम इतने कमजोर नहीं है कि आप इस तरीके पर धमकिया वे और हम वब जाये। आप के हाथा में यह ताकत हो जो स्टालिन के हाथ में थी तो आप हमें कुचल सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हू कि यह काग्रेसी अलबार है जिससे मार पीट के नमूने मेने पश किये हैं। जुतो की मार और उसकी चिट्ठी। जजमोहन लाल शास्त्री कांग्रेसी है। जुतो की मार हुई। नरण सिंह साहब ने धमकी वी कि हमारे पैसे से पानने वाले हमारी नुकता-चीनी कैसे कर सकते हैं ? यह मनोयुत्ति हैं जिस शासन को आप तला रहे हैं। उसके नमूने देखिये। (एक आवाज--और कितने नमून है ?) जितने आपके कारो कारनामें ह उतने नमूने है। फैबाबाद में गोयल साहब का मेला हुआ। उसमें आजमगढ़ के एक साहब पहुँचे।

श्री चार्ण सिह-में पर्सनल एक्सप्लेग्दान देना चाहता हूं। जिस चीज का आप रेपरेन्स दे रहे हैं तो मेंने यह जिक करते हुये कहा था कि जहां-जहा जिस देश में हिसात्मक राजनीतिक कान्ति को गई, जैसा प्राप्त में हुआ, रूम में हुआ वहां हिन्सात्मक तरीके से हुआ। वहां प्रेस और प्लेटकार्म की लिबटी पहां रही। हमारे यहां किहिन्सात्मक स्वराज्य लिया गया और हम इकोनामिक क्रिकेट्स करना चाहते हैं। हमारे यहां दिन-रात अनर्गल वार्तालाप और किटीसिक्स होता है। हस प्रेस और प्लेटफार्म के खिलाफ ऐकान नहीं लेगे। हम जनता पर छोड़ते हैं कि वह समझ ले कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज ठीक है। हमारी सरकार कोई एकान नहीं लेगे। हम सब बाते पबलिक के गुड़ सेंस पर छोड़ते है।

श्री राजार म जान्त्री—उसदी आपने सफाई नहीं दी। मतलब यह है कि सम्मन उसी को दीलिये जो हुजूर की जी हुजूरी करे, जो आपका विरोध करे उसकी सम्मन नहीं देना चाहिये। वास्तव मंआणको जदा नो मेरी जात का यह देना चाहिये था कि आपने यह बात कही या नहीं कही।

डिटी स्पीकर--आपकी तकरीर का जबाद देने के लिये नहीं खड़े हुये थे। वह तो निर्फ पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहे थे।

श्री राजाराप द्वाश्ची—राब तीमरा तम्ना सहिब देन्तिये। अभी फैजाबाद में गोविन्द साहब का मेला हुआ। यहां पर डिन्ट्रिंग्ट मैं जिस्ट्रेंग्ट गाहब सरझा रहे थे कि भूमिधर बनने से क्या फायटा है ? बाद में उन्होंने कि सातों से पूछा कि दोलों तुम नमझ गये कि भूमिधर बनने से क्या फायदा है ? तो वहां पर एक महाशय लड़े हो गये और कहा कि मेरे समझ ने नहीं आया। उन्होंने पूछा कि तुम की हो, कितना लगान देने हो। उन्होंने कहा कि ६०-७० रुपये देता हूं। उन्होंने कहा कि बतला तो दीजिये कि क्या फायदे हैं ? में जितनी बाते कह रहा हूं अखबार की सुना रहा हूं, कहिये तो में बठ जाऊं। हां, तो यह बात बंबई के 'बिल्ज' अखबार में लिखी है, पू० पी० के 'संघर्ष' में लिखी है। सिर्फ अखबार की बात नहीं है, उस आदमी का लेख छपा है इन अखबारों में, जिसमें उसने यह बतलाया है कि किन—किन नरीकों से उसे गिरफ्तार किया गया, जल में रवला गया, हायालत में कौन—कौन तकलीफे दी गई और आठ दिनों के बाद किन-किन मूसीबतों के बाद जेल से छूटा। भला सोचिये कि जब आप यह पूछते हैं कि समझ में आया कि नहीं और जब ठोई पूछता है तो उसको आठ रोज का जेलखाना मिलता है। और आप मानते इसिल्ये नहीं है कि वह तो 'बिल्ज' में छप गया, 'संघर्ष' में छप गया।

डिट्टी रूपोत् र-आप अपनी तकरीर जल्द खत्म कर देगे या अभी और वक्त लेगे। श्री राजाराम शास्त्री-अभी तो कुछ समय और लूंगा।

हज कमेटा के निये सदस्यां के चुंनाव के सम्बन्ध में घापणा

डिप्टो रूपीकर—इसके पहिले कि हम उठे में आपको एक इत्तिला देना चाहता हूं और वह यह है कि इस सूचे की हज कमेटी की एक खाली जगह को भरने के लिये दो उम्मीदवारों की नामजवगी हुई है, श्री शुह्माद नबी साहब और श्री हसरत मुहानी साहब की। १ बजे तक नाम वापसी के लिये मुकर्रर था। इससे पहले कोई नाम वापिस नहीं हुआ। यह दोनों उम्मीदवार हैं और जैसा कि पहले एलान हो चुका हैं कल २ बजे और ४ बजे के दरमियान रीडिंग रूम में चुनाव होगा और उसमें सिर्फ मुसलमान मेम्बरान ही वोट दे सकेंगे।

अब हम उठते हैं और कल फिर असेम्बली का काम जारी रहेगा।

(इस के बाद भवन ५ बजकर १७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तृक के लिए स्थिगित हो गया)।

> कॅलासचन्द्र भटनागर, मंत्री, लेजिस्लेटिव असेम्बली, खं<mark>युक्त प्रांत</mark>्र ।

नत्थी 'क'

(बेखि ये ता० १२ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पुष्ठ ५४४ पर)
SUBORDINATE EXECUTIVE SERVICE ASSOCIATION,
UNITED PROVINCES

SCALE OF PAY

The Subordinate Executive Service (Tabsildars and Naib Tabsildars) Association, learns from press reports that the salaries of its members have been fixed as under.—

Naib Tehsildars Ru. 120-300, Tehsildars Rs. 200-450,

and that Tehsildars have been grouped together with Inspectors of various departments (with few exceptions) whose pay was 80/- to start with e.g., Eveise and Agriculture Inspectors. The revision of scale of pay of Tehsildars Rs, 160(Rs, 190 pre-1931 scale) to Rs. 200 and of Inspectors from Rs. 50 to the same level i. e., Rs. 200 is not at all based on justice and equity. Even if nature of duties are compared, it would be evident that a member of Subordinate Executive Service "combines in one the onerous duties of a chief executive officer, Magistrate, Revenue Officer, Revenue Collector and General Inspector and Supervisor of all other departments working within a Tahsil." In short the work of members of this Service consists of field work as well as judicial which is a combination of both physical and mental work and on this consideration he has been described as "The backbone of Civil Administration" not only by the Governors and the members of the Board of Revenue but by the popular Minister for Revenue, United Provinces.

The Association places on record its strong protest upon the recommendations of the Pay Committee and its decision to group the members of the Service with Inspectors of various departments. A great deal of dissatisfaction has been created on this account. Our demand is "living wage." The Association therefore requests the Government to reconsider their scales of pay and grouping and take into consideration the scales suggested by it, viz;

Naib Tahsildar Rs. 200 to 400. Tahsildars Rs. 350 to 650.

We base our demand on work alone and work in our service "implies greater apprenticeship" and hence we must be better remunerated. Our bare needs must be satisfied. We are manual as well as mental workers.

February-11, 1947.

(Sd.) P. C. BHATIA, Honorary General Secretary, 21. Mudie Square, Lucknow.

नत्थो 'ख'

(देवि रे १३ जनवरी, सन् १९५० ई० के तारांकित प्रश्न ४९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५५ पर) सरकारी डेरियों की सूची

१—डेरी डिमान्सट्रेशन फार्म, मथुरा।
२—माधुरी कुंड डेरी फार्म, मथुरा।
३—बाबूगढ़ डेरी फार्म, मेरठ।
४—हेमपुर डेरी फार्म, ने नीताल।
५—मंझरा डेरी फार्म, लखीमपुर खेरी।
६—मरारी डेरी फार्म, झांसी।
७—डेरी डिमान्सट्रेशन फार्म, भद्रुक, लखनऊ।
८—सेंट्रल डेरी फार्म, अलीगढ़।
९—एग्रीकल्चरल डेरी फार्म, कानपुर।
१०—एग्रीकल्चरल स्कूल डेरी, गांचीपुर।

१२--एगीकल्चरल स्कूल डेरी, बुलन्दशहर ।

१३--गोकुलनगरडेरी फार्म, नैनीताल।

१४--हस्तिानापुर डेरो, मेरठ (बन रही है)।

प्राइवेट डेरियों को सूची, जिन्हें सहायक अनुदान या कर्ज दिया गया है

१--बेंती के टिल ऐण्ड डेरी फार्म, प्रतापगढ़ ।

२--युनियन डेरी फार्म, कानपुर।

३--डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ।

४--श्रो के० सी० तेवाड़ी, लखनऊ (गोपाल डेरी, लखनऊ)।

५-शो राम नारायण सिंह उरई, जिला जालीन।

६—-श्रो अब्दुल मुईज खां, बस्ती ।

७--लोक सेवक संघ, बनारस।

८—–बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस ।

९--ए० एस० जाट कालेज लखोटी, बुलन्दशहर ।

१०--बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा।

११--श्री राय सोमनाथ बली, बाराबंकी।

१२--काशी गोशाला डेरी, बनारस।

वास्तिविक ओर जरूरतमन्द व्यक्तियों और संस्थाओं को डेरी की मशीनों या दूध देने वाले मवेशियों की खरीद के लिए न कि भूमि, इमारत या दूसरे वार्षिक खर्चों के लिए नक़द या वस्तुओं के रूप में सहायक अनुदान (Grants-in-aid) देने को शर्तें नीचे दी जाती है :—

१—-नस्लक्ष्मी के लिए डेरियां ऐसे ही सांड रक्लेंगी जो पशु-पालन विभागद्वारा स्वीकृत हों।

२--फार्म में किस नस्ल के मिनेशी रक्षे जाएंगे इसका फैसला पशु-पालन विभाग से परामर्श कर के किया जाएगा।

३--डेरियां अपने मवेशियों की औलाद को खरीदने का सबसे पहला हक विभाग को देगी और उन्हें विभाग के हाथ बाजर भाव के दो-तिहाई दाम पर बेचेंगी।

४—- उन्हें दूव और नस्लक्ष्मों के बारे में ठीक नरीके से रिकार्ड रखना पड़ेगा और उसका नुआइना उपयुक्त कर्मचारी साल में कम से कम दो बार कर सकेंगे। अमले के ठीक रख-रखाद

और उरी की अच्छी तरह चलाने के संबंध में विभाग द्वारा जो अविश दिए जाएंगे उनका पालन करना आवश्यक होगा।

- ५--डेरी की देख-भाग और नियन्त्रणके लिए डेयरी के प्रबन्धक (management) को एक नियत योग्यता प्राप्त ज्यक्ति रात्र। होगा और जिस किस्म का दूध पशु-पालन विभाग निर्धारित करेगा वैसा ही उन्हें बरावर देना पड़ेगा।
- ६—किसी एक उपयुक्त व्यक्तिया सस्या को अधिक से अधिक २०,००० रुपए की राज-महायता (subsidy) दी जापगी।

ये क्रचों नीचे दी हुई शतों पर दिये जायंगे :---

- (१) डेरियां नस्तकशी के लिये सिर्फ ऐसे ही साडों को रक्ष्येगी, जो पशु-पालन विभाग द्वारा स्वीकृत हों।
- (२) फार्म में रक्लो जाने वाले मविभियों को नस्ल के बारे में पश्-पालन विभाग की राय लेकर फैसला किया जायगा।
- (३) डेरियां अपने मवेशियों की ओलाद को, जो उनकी जरूरत से ज्यादा हों, खरीदने का सबसे पहला हक विभाग को देगी और उन्हें विभाग के हाथ बाजार भाव के दो-तिहाई दाम पर बेचेंगी, लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक गवेशी के लिये आ प्रक्र से अधिक ८ आना प्रतिदिन के हिसाब से दाम लिया जायगा।
- (४) उन्हें दूर्य और नस्लक्ष्मश्री काठो क सरीके ने रिकार्ड रखना होगा और इसका मुआइना उपयुक्त कर्मवारी साल में कम से कम दो बार कर सकेंगे।

अमले के ठीक रख-रखाव और डेरी को अच्छी तरह चलाने के संबंध में विभाग द्वारा जो आदेश दिये जायंगे, उनका पालन करना आवश्यक होगा।

- (५) डेरी की देख-भाल और नियन्त्रण के लिए एक नियत योग्यता प्राप्त व्यक्ति रखना होगा और जिस किस्म का दूध पशुपालन विभाग निर्धारित करेगा वैमा ही उन्हें बराबर देना पड़ेगा ।
- (६) किसी एक उपयुक्त व्यक्ति या संस्था को अधिक से अधिक २०,००० रू० की राज-सहायता (subsidy) को जायगी।
 - (७) कर्जे पर ब्याज नहीं लिया जायगा और मुनासिय जमानत पर दिया जायगा।
- (८) वे ओमत में प्रतिदिन कम ने कम ३ मन दूध पैदा करेंगी और उसे जनता की सालाई करेंगी।
- (९) बरहरनजामी या ऊपर वी हुई शर्नों में में किसी अर्त के पालन न करने पर या कर्जे की कीई किस्त अदा न करने पर देय रकम फार्म की और फार्म के मालिक की सम्पत्ति कुर्क कर के वसूल की जागनी।

नर्त्था ु'ग'

4

(देखिये १३ जनवरी सन् १९५० ई० के तारांकित प्रक्त ९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

कम- संख्या	लाइसँसदार का नाम	हथियार की किस्म व ताद	हथियार जब्त ाद करने की तारीख
8	श्री गजाधर लाल, पुत्र श्री देवी प्रसाद ब्राह्मण, मोहल्ला पंसारियान, कन्नीज	एक डी० बी० बी० एल० बन्द्रक	९-3- ४८
२	श्री भोलानाथ, पुत्र श्री बंसीयर, मोहल्ल तिवारियान, कन्नौज		8-3-86
3	श्री अलीहसन, पुत्र श्री अनवारुल हसन, ग्राम फरकापुर	एक डो० बी० एम० एलः बन्द्रक	९-३-४८
ሄ	श्री हमीद हुसेन, पुत्र श्री अब्दुल हकीम खां, कन्नोज	एक डी० बी० बी० एन० बन्दुक	२४–३–४८
ષ	श्री नवाब लां, पुत्र श्री सत्ता लां पठान, सतोरा	एक एस० बी० एम० एस वस्ट्रह	১৯–४–४ ১
Ę	(१) श्री जफर हुसेन, पुत्र श्री हिफाजत हुसेन	एक डी० बी० बी० एल० सन्दुक	८–३–४८
	(२) शेख अशफाक़ हुसेन पुत्र श्री हिफा- जत हुसेन		•• ••
	(३) श्री मोहम्मद अली अहसन, पुत्र श्री जफर हसेन कोलेमंसी	11	•• "
9	डा० हबीब उद्दीन अहमद, कन्नोज	एक एस० बी० बी० एन बन्द्रक	० २४-२-६८

नत्था 'घ'

(देखिये १२ जनवरी सन् १६५० ई० ेताराहित गहर ९२ का उत्तर पोछे पृष्ठ ५५८ पर)

कम खिया	लाइसेंसदार का नाम	हथिय।र की किस्म
१	श्री गजाघर लाल, पुत्र श्री देवी प्रसाद बह्मण,	एक डी० बी० बी० एस
	मोहल्ला पंतारियान, कन्नीज	बद्दर
२	श्री भोलानाथ, पुत्र श्री बशीयर मोहल्ला तिवारियान, कन्नोज	**
ą	श्री हमीद हुसेन, पुत्र श्री अब्दुल हकीम स्नां, फन्नी न	n
x	(१) श्री जंकर हसेन, पुत्र श्री हिकाजत हुसेन	**
	(२) शेल अशफाक हुसेन, पुत्र श्री हिफाजत हुमेन	* *
	(३) श्री मोहम्मद अली अहसान, पृत्र श्री जफर हुनेत	,

संयुक्त प्रान्तीय लेजिरलेटिव असेम्बली

गनिवार, १४ जनवरा सन् १६५० ई०

ग्रसेम्बली की बैठक ग्रसम्बली भवन, लघनऊ में ११ बजे दिन में ग्रारम्म हुई

स्पीकर--ग्रानरेविक श्री पुरुषोत्तम टास टएडन

उपस्थित सदस्यों की सूची (१६०)

अचलींसह अहदूल जे की अब्दूल मजीद अदद्रल मजीद ख्वाजा अब्दुलवाजिद, श्रीमती अब्दूल हमीद अम्मार अहमद खां अर्नेस्ट माईकेल फिलिप्स अली जर्रार जाफरी अल्क्रोट धर्मदास असग्रर अली खां अक्षयवर सिंह अत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री इन्द्रदेव त्रिगाठी इनाम हबोबुल्ला, श्रीमती उदयवीर सिंह ऐजाज रसूल, कमलापति तिवारो करीमुर्रजा खां कालीचरण टण्डन कुशलानन्द गैरोला कृपाशंकर कृटणचन्द्र कृष्ण चन्द गुप्त केशवगुप्त खुशवक्त राय खुशीराम खबसिंह गंगाधर गंगा प्रसाद

गंग महाय चोबे राजाधर प्रसाद गणेश ऋष्ग जैतली नोयान्त्रनारायण सक्येना गोपिन्द बल्लभ पन्य, माननीय श्री गोबित्र सहाय चन्द्रभानु गुन्त, माननीय श्री चन्द्र भानु शरग सिंह चरणसिंह चेतर:म छेशलाल गुन्त जगन्नाथ दास जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल जगन्नाथ सिह जगन प्रसाद रावत जगमोहन सिंह नेगी । जयपाल सिंह जयराम वर्मा जवाहिर लाल रोहतगी जहर अहमद जाकिर अलो जाहिद हसन जगल किशोर त्रिलोकी सिंह द्यालहास भगत दाऊ दयाल खना द्वारिका प्रसाद मौर्य दोन दयाल अवस्थी दीन दयालु शास्त्री दीय नारायण वर्मा

नफ़ोसुल हसन नवाजिश अली खा नवाब सिह नाजिम अली नारायण दास निसारअहमद शेरवानी, माननीय श्री पूर्ण मासी पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती प्रकाशवती सूब, श्रीमती प्रागनार।यण प्रेमिकशन खन्ना फ़लरल इस्लाम फजलूर्रहमान ला फतेहसिंह राणा फूर्लासह बवन सिंह बनारसी वास बलदेव प्रसाद बशीर अहमव बद्योर अहमद अन्सारी बावशाह गुप्त वुजमोहनलाल शास्त्री भगवती प्रसाद दुवे भगवती प्रसाद शुक्ल भगवानवीन भगवानदोन मिश्र भगवान शिह भारत सिंह याववाचार्य भोमसेन मंगला प्रसाद मस्रियादीन महफ्युरहमान महम्ब अली लां मिजाजी लाल मुक्त्वलाल अग्रवाल मुजापकर हुसैन मुनफ़त अली मुहम्मद अवील अब्बासी मुहम्मद असरार अहमद मुहम्भव इत्राहीम, माननीय श्री मुहस्मद इस्माइल मुहम्मव नबी मृहस्मद नजार मृहस्मव फ़ारूक मुहम्मव याक्ष

मुहम्मद युसुफ

मुहम्मद रजा खो महस्मद शक्र महस्मद शमीम मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी मुहम्मद शोकत अली खा मुहम्मद सुलेमान अधमी यज्ञनारायण उपाध्याय रघुनाथ यिनायक धुलेकर रघुबश नारायण सिंह रघंबीर सहाय राजकुं वार सिंह राजाराम मिश्र राजाराम शास्त्री राधाकृष्ण अग्रवाल राधामोहनसिंह रापेश्याम शर्मा रामकुमार शास्त्री रामकुपाल सिह रामचन्द्र पालीयाल रामचन्द्र सेहरा रामजी सहाय रामधर मिश्र रामधारी पाड रामनारायण राम बली मिश्र रामम्ति राम शकर गाल रागदार्ण रामस्यरप गुप्त रक्नुद्दीन स्मा रोशन जमा लां लक्ष्मी देवी, श्रीमती कतापात तुनैन लाखन वास जाटव कालबहाबुर, माननीय श्री लाल बिहारी टण्डन लोलाधर अच्छाना लुस्फ अली ला लोटन राम बंद्यीधर मिश्र विजयानन्द मिश्र विद्याधर बाजपेयी विद्यावती राठौर, श्रीमती विनय कुमार मुकर्जी विद्वनाथ प्रसाद विश्वनाथ राय

विष्णु शरण दुब्लिश बीरबल सिंह वीरेन्द्र शाह वेंकटेश नारायण तिवारी शंकर दत्त शर्मा शान्ति प्रपन्न शर्मा शिव कुमार मिश्र शिव कुमार पांडे शिव दयाल उपाध्याय शिवद।न सिंह शिवमंगल सिंह कपूर श्यामलाल वर्मा रयामसुन्दर शुक्ल श्रीचन्द सिंघल श्रीपति सहाय सज्जन देवी महनोत, श्रीमती सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री सरबत हुसैन सलीम हामिद खां

साजिदहुसेन सालिग्राम जायसवाल सिंहासन सिंह सीताराम अध्ठाना सुदामा प्रसाद सुरेन्द्र बहादूर सिंह सुल्तान आलम खां सूर्घ प्रसाद अवस्थी सईद अहमद हबीबुर्रहमान अन्सारी हबोब्रेहमान खां । हरगोविन्द पन्त हरप्रसाद सत्यप्रेमी हरप्रसाद सिंह हसन अहमद शाह हसरत मोह।नी हुकुम सिंह, माननीय श्री होतोलाल अगवाल हेदर बख्श

माननीय स्वीकर--मुझे बताया जा रहा है कि अभी सदस्यों का कोरम नहीं है, मैं दो तीन मिनट इन्तजार करता हूं।

माननीय स्वशासन सचिव (श्री आत्माराम ग विन्द खेर)—मेरा ख्याल है कि यदि घंटी बजा दी जाय तो अच्छा हो।

माननीय अन्न सचिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त) -- मेम्बर्स वोटिंग मे होंगे। (३ मिनट इन्तजार किया गरा)

मानाय स्पाका--रैकोरम पूरा न होने की वजह से इस वक्त जाता हूं फिर काम सवा ग्यारह बजे शुरू होगा।
(होरन पूरा हो जाने पर भवन की कार्यवाही सवा ग्यारह बजे आरम्भ हुई।)

प्रशीत्तर

शनिवार, १४ जनवरी, १६५० ई०

तारांकित प्रश्न

सरकार का ईस्ट अफरीका से विनौला खरीदना

*१--श्री चतुर्भुत शर्मा--क्या यह सच है कि प्रान्ती। सरकार ने सन् १९४७ ई० या इसके करीब ईस्ट अफरीका से बिनौले खरीदे थे?

माननीय शिक्षा सिचिव के सभा मन्त्री (श्रो महकू जुर्रहमान) -- जी हां।
*२--श्रो चतुर्म ज शर्मा -- यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में हैं तो क्या सरकार कृषया बतायेगी कि--

(क) कितना बिनौला खरीदा गया?

(ख) किस भाव से यह बिनौला खरीदा गया?

- (ग) आयात का कितना खर्चा हुआ ?
- (घ) क्ल कितने रुपये इसमे खर्चे हुए ?

श्री महफू जुरहमान-- (क) ९३,९४३ मन।

- (ए) १० ४० ८ आना फी मन जो बम्बई के गोद।म पर का भाव था और जिसमें वह खर्ना भी शामिल हैं जो बिनीले हो बाहर से मंगाने में हुआ।
- (ग) बिनोले को बाहर में मंगान में जो खर्चा हुआ है उसके आंकड़े अलग से नहीं मिल मके हैं।
- (ঘ) १२,२६,३४४ कर्जनमे २,२९,९४२ ४०१० आना का संबंधित (मुताल्लिका) स्वर्धा भी মাদিক ঠে।

13--धा च भूत शर्मा--जब यह बिनोला यरीवा गयाया यहां पर बिनौले का क्या भाव था और अब (इस सान्त्र) क्या भाव हे ?

थ्र। मण्कानुगतमान-- तबम्बर और विसम्बर, १९४७ ई० में बिनोले का भाव १२ ए० ५ आना से २०४० की मनतक रहा । इन माठ इनका भाव १३ ४०९ आ० से १५ ए० फ़ाँ मन तक हैं।

*४--श्री चन्भ्र त शर्मा--इस बिनोले का क्या इस्तेमा र किया गया?

श्री महक् तुर्ग :मान--विनीला लास तोर से गवर्नमेंट फैटल श्रीडिंग और डेरी फार्मों और एक निजी तीर पर पशुओं की नस्लकशी हरने वालों को दिया गया।

*५--श्री चतुर्भु ज शर्मा-- भितना बिनोला खर्च हो गया ओर अब कितना बाकी है?
श्रं। महापूज्रितान--अभी तक २४,४५९ मन बिनोला बांटा गया है ओर बाकी
६९,४९० मन बिनोला इस गतं पर नेप्लाम किया जा रहा है जि उसके नियत किये
हुए कम से कम बाम निल् जार्थ।

*६--श्री च नर्भु ज शमा--न्या यह सच है कि इस बिनोले के खराब हो जाने की आज्ञांका के कारण सरकार को इसे बेचने की सलाह दी गई है?

श्रामहफ्रज्यहमान-जो हा।

*७--आ चनभू त रार्मा-- ाया सरकार इस बिनोलें को बेचने का विचार रखती

श्री महफ्रज् हमान-- जी हां।

*८-१७--थ्रा चत्रभू जशमा--(स्थगित किये गये)।

छेन्सदाउन, गईवाल की जनता का सरकार के पास लड़ांकयों के नकुल में कक्षा ९ खोलने के लियं प्रार्थना—पत्र

*१८--श्री जगमांहन सिंह नेगां--(क) क्या सरकार के पास लेसडाउन गढ़वाल की जनता का शिक्षा सभा-सिंव और जिला शिक्षा इन्सपेक्टर के द्वारा प्रार्थना-पत्र आया है कि लेसडाउन लड़कियों की स्कूल में कक्षा ९ इस साल से खोल दिया जाय?

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रो महफूजुर्दमान--(क) जी हां।

(ख) इस वर्ष जूलाई में चार नये हाई स्कूलों के खोलने के सिलसिले में इस स्कूल की मांग पर भी विचार किया जायगा।

श्री जगमाहन सिंह नेगी--क्या सरकार के पास अड़ कियों के इस स्कूल को लोलने के लिये प्रांतीय सोरजसं बोर्ड से कोई सिकारिश आई है ? माननोय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णानन्द)—इस वक्त ठीक नहीं कहा जा सकता। बहुत सम्भव है आई हो।

श्रोमनी पूर्णिमा वन जी-गढ़वाल में लड़िक्यों के कितने हाई स्कूल है? माननीय शिक्षा सन्त्रिय-मेरा ल्याल यह है कि कोई ओर नहीं है।

श्रामती पृष्णिमा वन जी--सरकार की पुराती योजना थी कि हर जिले ने लड़ कियों का एक हाई स्कूल कम से कम होगा। इसके बारे में सरकार ने क्या प्रवस्थ किया है ?

माननोय शिक्षः सिवन-वह नीति अब भी कायम है। इपीलिये लहा गया है कि हम जुरुई में चार स्कूल खोलने जा रहे हैं, अक्षेम्बनों ने रुपया मंजूर दार दिया तो किन्हों चार जिन्हों में बार स्कूल पोल दिये जायेगे।

लेग्त डाउन से गूमखाल तक म टर सड़क वनकाना

*१९--अ: जामोइन निर्ने नेगी--का सरकार कृपा करके उतलायेगी कि लैन्स-डाउन से गूमबाल (गड़वाल जिले में) तक. जो कुर अ मीठ र दुकड़ा है मड़क बनवाने के टेन्डर लाभग दो माल पूर्व लिये जाने के जाद भी जब तक वहां मोटर वडक वयों नहीं बनाबी गबी है ?

माननाय निमाण सचिव के सभा लन्त्रों श्रीला गरुत हुमैन)—महर्क नापर हैन के शारण बनाई जा रही थी। बूंकि अद हैन का न्या जाना कर गा। है, सहः सहक की आवश्यकना बाकी नहीं रही। अनर कुछ थो। कारणों २ सन्य का बनाय जाना जरूते हुआ, तो इसका निर्माण गोन्द बार रोड प्रोताम के हूं रे केंद्र में विषय जायगा।

श्री जगम,हन सिंह नेगी--क्या सरकार इसका स्पष्ट ररेगी कि रक गये के क्या माने रु प्रयोगह स्थीत कर दिया गया है हो जिलकुल ही रक दिया गया है ?

मानतीय सावजितिक निर्माण सिचव (श्रा मृहम्मद इवार्)म) --इन वक्त तो कि हो गया है ओर इनके प्राने यह ह कि कार कुछ नहीं किया जायगा।

श्रा जगम इन सिंह नेगी--क्या यह नाक जो बर्ग तक जाती है इसकी काम इक जाने सेक्यों रोक दिया गया हैं?

माननीय सार्वजनिक निर्माण सिचिय--इान्त्रिये कि वर्श यहुंचने के लिये उस साक का बनाग जरूरी समझा था, लेकिन अब वहां पहुंचना हो नहीं है।

*२०--श्री जगमे। हन सिंह नेगा--क्या सरकार को जात है कि पौड़ी-गढ़वाल जाने के लिए उपर्युक्त ७ मील का दुक्ता न बने के कारण लगभग ४०-५० मील का चक्का काटना पड़ना है ?

श्री लागाफत हुसेन--जी नहीं पोड़ो-गढ़वाल जाने वालों को ४०-५० मील नहीं बह्किक क़रीब २६ मीड का रास्ता तै करना पड़ता है।

मरीड़ा नया वांघ पर विशेषकों की रिपोर्ट

*२१--भ्रो जगमोहन सिर्नेगी--क्या परकार कृपा करके मरोग़ नयार बांध पर विशेषज्ञां की रिपोर्ट को नकल मेज पर रक्खेगी ?

श्री लाता प्रत हुसैन--मरोड़ा नयार बांध पर विशेषज्ञों को रिपोर्ट की केवल एक हो कापी है, जिसको माननोप सदस्य निर्माण सचिव के कमरे में देख सकते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार मोटे तौर पर उन विशेषज्ञां की रिपोर्ट का वर्णन देगी कि वह इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में ? माननीय मार्यजनिक निर्माण मन्त्रिय—उ।का मजमून इस वक्त बयान करना तो मुर्माकन नहीं हे सिर्फ यह कहा जा सकता हिक बावजूद खिलाफ न होने के सुबे की नजर के देखने के काबिल हैं।

श्री जगमाहन सिंह नगी--क्या विस्टर मेबेज ने इसके बनाने के पक्ष में कोई राय दी हे?

माननीय मार्वर्जानक निर्माण मानिय-जी हो, वी है। *२२-श्री बळभद्र सिह--[माननोय सदस्य का तब मे देहान्त हो गया।]

युक्त प्रान्त में जट भी पदावाभ बढ़ाने के उपाय

*२३--श्रां व शीत्रगामश्र (अनपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि युक्त प्रान्त से का-कहा ज्ञ भी पैदाबार बढाने के लिये कौन-कोन उपाय सरकार काम में ला रही है?

• मानतीय द्वाप र्माच्यव (श्रा निस्तार स्रहमद द्वारवानी)--मानतीय सदस्य की मेज पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत कर वियागया है।

(देलिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६८० पर)

युक्तप्राम्त में चायल गृह तथा गन्ना की वार्षिक श्रौसत उपज

*२४—श्री बंशाधर भिश्र (श्रनुर्वास्थान)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त में गत ५ वर्षों में (१) चावल, (२) गेहूं और (३) गन्ना की वार्षिक औसत उपज क्या रही हैं?

माननीय र्क्कांच मांच्य -- एक विवरण-पत्र, जिसमें पूर्व ५ वर्ष की धान, गेहूं तथा गन्ना की औसत निकासी दनों में विष्याई गई हे, निम्नांकित है--

धान	गेंह्	गन्ना
१५, ३५,८८१	२६,४५,६३५	२.४१,०७,९३६
१८,३०,८२९		२,२२,२५,१४५
	२३,४८,६२६	\$\$\$0,00,98,5
•	२६,२२,८१८	२.७५,६३,९०३
२३,४६,३७९	२३,१३,०२७	२,४१,६६,११८
९४,५२,०७९	१,२२,३५,२६०	१२,२१,६३,८३५
१८,९०,४१६	२४,४७,०५२	२,४४,३२,७६७
	१५,३५,८८१ १८,३०,८२९ १७,७४,०६२ १९,६४,९२८ २३,४६,३७९ ९४,५२,०७९	१५,३५,८२१ २६,४५,६३५ १८,३०,८२९ २३,०५,१५४ १७,७४,०६२ २६,२८,६२६ १९,६४,९२८ २६,२२,८१८ २३,४६,३७९ २३,१३,०२७ ९४,५२,०७९ १,२२,३५,२६०

*२५--२८--भा बंशाधा मिश्र (मनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

खीरी जिला के हिस्टिवट मप्लाई इन्अपेक्टर के विरुद्ध श्रीभय।ग

*२९--श्री बंदीधार मिश्र (धनुपिधात)-क्या सरकार को यह मालूम है कि खीरी जिला के एक डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्स्येक्टर के खिलाफ मीमेंट की बोरियों के गायब हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग लगा था और जांच हुई थी?

माननीय प्रका समिव (श्री चन्द्रभानु गुप्त) — जी हां, सप्लाई इंसपेक्टर के विरुद्ध अभियोग यह या कि पकड़ी गई बोरियों के एखने का प्रबन्ध उसने सुचार रूप से क्यों नहीं किया ? क्योंकि बोरियां जिस व्यक्ति की सुपूर्वगी में वी गई वहां से उठ गई।

*२९--श्रो वंशोधर मिश्र(त्रनुपस्थित) -- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह जांच कब जुरू की गई थी कब खत्म हुई और उस पर कब निर्णय हुआ?

माननीय ग्रन्न सचिव--इस संबंध में जांच १३ अप्रैल, १९४९ ई० को प्रारम्भ हुई और २५ अप्रैल, १९४९ ई० को सनाप्त हुई।

साम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए सरकारी नीति तथा तरीके

*३१--श्रो गर्जाचर प्रस्'ट--स्था यह सच है कि सरकार साम्प्रदायिकता को समाप्त करने का विचार रखनी है ?

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्त्री(श्री गीविन्द सहाय)--सरकार की नीनि साम्प्रदायिकता को हुनोत्साहित करना है ।

*३२--श्री गर्जाधर प्रसाद--यदि जवाब हां में है, तो सरकार ने कीन-कीन से तरीके अपनाये हैं ?

श्री गाविन्द महाय--सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तह ये कार्रवाइयां की हैं--

१--यह आज्ञा दो गयी है कि सरकारी कागजों में आहां कहीं जाति या उपजाति किसी अलग कालम में या किसी दूसरी अगह स्वध्यक्ष्य से लिखे जाने के लिए आदेश दिए गए हैं वहां कुछ न भरा जाएगा, सिवाय उस दशा के जबिक सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए कागजात की खानापुरी करने में परिगणित जातियों के लोगों के बारे में विवरण देना जकरी हो और जबिक कान्न के अनुपार ऐसा इन्दराज करने का स्पष्टक्ष्य से आदेश हो।

आमतौर पर सरहारी कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले पत्र-व्यवहार में इस सरकार के मातहत सभी सरहारी नौकरों को सम्बोधित करने के लिए सम्मानसूचक शब्द 'मिस्टर' 'बाबू' 'पंडित' 'मोलवी' 'मिसेज' 'मुसम्मात' 'मिस' इत्यादि के स्थान पर जिनका इस्तेमाल पहले किया जाता था अब 'श्री' 'श्रीमती' 'कुमारी' शब्द का जैसा कि उपयुक्त हो, व्यवहार किया जाता है।

यह भी आदेश दिया गर्श है कि यदि परिगणित जाति का कोई व्यक्ति यह चाहें कि उसकी जाति या उपजाति उस दशः में भी सरकारी कागजात में छोड़ दी जाय या दर्ज न की जाय, जबकि उसे दर्ज करना आवश्यक हो, तो वह इस आशय की दरख्वास्त दे सकता है और उसको दरख्वास्त मान ली जानी चाहिए।

कार्यालय-स्मृति-पत्र (आफिस मेमोरेन्डम) सं० ६१६०/२--१३-४६, तारीख २४ जुलाई, १९४७ ई० सरकारी आज्ञा (जी० ओ०) सं०--ओ-१४२२/२--बी---५५-४८, ता० १४ अप्रैल, १९४८ ई० और सरकारी आज्ञा (जी० ओ०) सं० १३०३/३---१५-४९ ई० ता० ९ अप्रैल, १९४९ई० की नकलें सूचना के लिए मेज पर रख दी गयी हैं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६८२ पर)

२—सरकार के प्रस्ताव पर व्यवस्थापिका सभाओं ने यू०पी०डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ ई० और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ ई० में उपयुक्त संशोधन किए हैं जिनके द्वारा जिला बोर्डो और म्युनिसिपल बोर्डो के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली समाप्त कर दी गयी है।

३—-जहां तक नौंकरियों में नियुक्तियां करने और तरिक्कियां देने का सम्बन्ध है, सरकार ने आदेश दिया है कि--

(क) तरक्की देने के मामले में साम्प्रदायिकता को दृष्टि से किसी बात का विचार नहीं किया जायगा।

(ख) प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा सीधे भर्ती करने में योग्यता ही एकमात्र कसौटी होगी, लेकिन १० प्रतिशत खाली जगहें परिगणित जातियों के योग्य उम्मीदवारों के लिये मुरक्षित (रिजर्व) रहेंगी।

४—यह आज्ञा जारी कर री गयी ह कि चिक्त बालिंग मताधिकार के आधार पर तथार की गयी निर्वाचक सूचिया(एंटेक्टोरल रोल)म रोट देने वाली के धर्म, वर्ण या जाति के सम्बन्ध में स्चना दे को जररन नहा ह, इसिंग्ए निर्वाचक सूचियों में इनके लिए फालम नहीं होते चाहिए।

५-सरकार के प्रस्ताय पर व्यवस्थापिका नभाओ। ने रिमवल आफ सोशल जिसेबिलिटीज ऐक्ट, १९४७ ई०(सामाजिक सममयनाओं के दूर करने का ऐक्ट, १९४७ ई०)पास किया ताकि हरिजनों को समान नागिक अधिकार मिल जाय।

६--साम्प्रदायिक दृष्टिया ेग । तरीया, जिसके बनुसार कियो गाम सम्प्रदाय या जाति के लोगो का हो अभिन्या के जाती का, समक्ष्य कर दिया गया है। अब प्रान्त म जो साम्बर्गिक है। होती के बहु सबके लिए तिते ।

७-- सरकार हे जाता हो ,' कि जना नक फिर से बसाने के जिल्ल दो जाने वाली सुविधाओं का सम्बन्ध हो तोई साम्प्राधिक भद-भाग नहां किया जाना चाहिए, यदि ऐसे व्यक्ति हाल गा यिवतयों (१८२ छेरा पत्तरा) की परिभाषा के जन्तमन आते हो, चाहे । किसी भी गर्भ के जनवायी गयों ने हो।

/-- ३ग जात के िए गमी समभा प्रयत्न किए जाने । मि अफगरो की मनोवृति साम्प्रकृतिक न हो और वे जपने कर्यं भी पालन करा म पूरी तार से निज्यक्ष रहे।

९-पीपरोद उत्पादि प्रकाणित करने में जाजा इ फार्गशान उत्तरकरेट, जिला इन्फामशन अफसरा के जिला साम्प्रवायिकता के जिला प्रचार करता है।

1)३--श्री गतात्र त्रसाट-क्या मरकार यह ना बाजाने को अपा करेगी कि सरकार को अपनाय हुए तरीकों में कहा तक कामयाबी हुई '

श्रा ग बिन्: सहाय-- नतीजे सन्तीवजनक त्रा ।

श्रा गतान्तर प्रमा :-- क्या सरकार यह बत गने को हवा करेगी कि कुछ नामो के आगे और पीले जातिशूचक जो उपाधिया लगाई जाती ह उनके रोकने पर मरकार का क्या विचार हैं '

माननीय शिक्षा सिचा-सरकार इस मामले गं कोई दलल नहीं दे सकती है। हर शब्स अपने नाम के आगे जो लगाना चारे लगा सकता ह।

श्रा द्वारिक। प्रसाद मीर्थ-क्या सरकार यह बतलाने को ग्रुपा करेगे कि स्कूल और कालेजों में जो भोजन की व्यवस्था रहती है उसमें कोई जावेश ऐसा जारी किया गया है कि हरिजाों के लिये किनी प्रशार का विरोध एक साथ भोजन करने में न हो?

श्रो गाविन्द स्तिय-जहातक सरकारी सस्थाओं का ताल्युक है उनके बारे में सरकार पावन्दी लगा सकती है। लेकिन पिडण्क की संस्थाओं पर कोई कानूनी पावन्दी नहीं लगाई जा सकती है।

श्री द्वारिका प्रसान मार्थ--क्या सरकार की नोटिस में इस प्रकार की शिकायत आयी है कि जो पंचायतों के मंत्रियों या प्रधानों की दें निग की गई, उसमें भोजन की व्यवस्था में विशेष किया गया और हरिजनों को अलग रखा गया।

श्री गोविन्द सहाय-जी नहीं?

#३४-३५--श्री गन्नाधर प्रसाद--[स्थगित किये गये]।

जिला गढ़वाल के राजनीतिक पीड़िनों द्वारा सरकार के पाम ग्रार्थिक सहायता के लिये प्राथना-पत्र

*१६-श्री जगमीहन सिंह नेगी-(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिला गढ़वाल के कि--किन राजनीतिक पीड़ितों ने किस-किस आधार परऔर किन तारीखों पर सरकार के पास आर्थिक सहायता या पेंशनों की मांग के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे हैं और सरकार ने उन्हें कब-कब और कितना-कितना प्रदान किया है ?

(ख) क्या सरकार कृत्या यह भो बतलायेगी कि किस-किस की मांग अस्वीकार की गयी और किन-किन कारणों से ?

श्री गोविन्द सहाय--माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है उसका ब्बोरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६८६ पर)

श्री जगमोहन सिंह नेगी—क्या सरकार के पास इन राजनीतिक पीड़ितों का कोई आवेदन-पत्र पहुंचा है कि यह जो उनको दस और पंद्रह रुपये दिये गये हैं ये अपमान-जनक ही नहीं बल्कि इस मंहगाई के जमाने में बहुत कम रकम है।

श्रा गे। विन्द सहाय--इसके लिये नोटिस की जरूरत है। मालूम करके बता सकता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगा--यह जो लिस्ट विचाराधीन है। इस पर सरकार अपना अन्तिम निर्गय कब तक देगी?

थ्रा गविन्द् सहाय--जिनके मात्रले स्वीकार कर लिये गर्ये हैं उन पर गौर करने का सवाल नहीं उठता। जो और केसेज़ हैं उन पर जन्द से जन्द निर्णय सिया जायगा।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ये कितने वर्षों से सरकार के सम्मुख विचाराधीत हैं?

श्री ग विन्द सहाय-निरेख्याल में ऐसे केसेज बहुत कम है, जो विचाराधीन है और अगर आप फेहरिस्त देखेंगे तो मालूम होगा कि बहुत से केसेज हैं जो स्वोकार कर लिये गये हैं, लेकिन जिनके प्रार्थना-पत्र ठीक समय पर नहीं आये उन्हें तीन महीने हुये विचाराधीन लिये गये हैं।

ब्राम पंचायतों के लिए इन्सपेक्टरों को याग्यता

*३७—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के लिये होने वाले गत चुनाव में इन्सपेक्टरों की आम योग्यता कम से कम इन्टरमीडियट और राज—नीतिक पीड़ितों के लिये कम से कम मैट्रिक निर्घारित की गई थी? यदि हां, तो इन योग्यताओं के प्रभाण स्वरूप कितने लोगों के। इन्सपेक्टरी में लिया गया और उनमें कितने राजनीतिक पीड़ितों को स्थान दिया गया?

श्री माननीय स्वशासन सचिव (ग्रात्माराम गोविन्द खेर)--योग्यता के सम्बन्ध में शासकीय आदेशों के उदाहरण दिये जाते हैं--

निर्धारित योग्यता के अनुसार ४६२ नियुक्त किये गये, जिनमें १७५ राजनीतिक पीड़ित थे।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६९२ पर)

*३८—श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्यायह भी सही है कि उपरोक्त चुनाव में कुछ ऐसे भी सज्जनों को स्थान दिया गया है, जिन्होंने कम से कम निर्धारित योग्यता का भी प्रमाण नहीं पेश किया था यानी वे मैट्रिक भी पास नहीं हैं? यदि हां, तो उनका नाम पता और उनकी अधिक से अधिक योग्यता क्या है?

माननीय स्वशासन सचिव—निर्धारित योग्यता के अनुसार ही मैट्रिक फेल अथवा दर्जा ९ पास राजनीतिक पीड़ित अथवा उनके समकक्ष परीक्षोत्तीर्ण लोग लिये गये थे, जिन्हें उनको सार्वजनिक सेवाओं के अनुभव से योग्य समझा गया। माननीय सदस्य के प्रश्न से प्रकट है कि वे निम्नतम योग्यता मैट्रिक मानते हैं। ऐसी दशा में ऐसे लोगों की सुची देने का प्रश्न नहीं उठता। श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी—क्या सरकार को यह मालूम है कि राजनीतिक पीड़ित और सार्वजनिक सेवा करने वालों में बहुत से व्यक्ति ऐसे भी नियुक्त नहीं किये गये, जो मैद्रिक, एफ० ए० ओर ग्रेजुएट भी थे ?

माननीय स्वशासन साचित--मुमिकन है कि कुछ ऐसे लोग भी हों, जो मैट्रिक हों ओर न लिये गये हों क्योंकि दरख्वास्ते बहुत ज्यादा थीं।

जिला जालीन के मेजिस्ट्रंट के फैसले पर सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रालस द्वार। नुकाचीनी

ं ३९--श्री चर्नभुत शर्मा-प्या यह सच है कि जिला जालोन के मैजिस्ट्रेट के फ़ैंसले के बाद कई मुकदमों में सुपिरन्टेडेन्ट पुरिस ने नुक्ताचीनी की ?

माननीय स्वज्ञामन साचय--जी नहीं।

'लोकमत' अखवार, उर्र पर अदालत की मानहानि का मुकद्मा

'४०—श्री चतुमु त टार्मा—क्या यह सच है कि एक चितौरी चितोरा के मुकद्दे में पुलिस सुपरिन्टेडेन्ट ओर डि॰ मंजिस्ट्रेट ने 'लोकमत' अखबार, उरई पर जुडोशियल मंजिस्ट्रेट द्वारा अवालत की तोहीन (कंटेम्ट आफ कोर्ट) का मुकदमा चलाने के लिये लिखा-पढ़ी की ?

माननीय स्वशासन सांच्यव——जी नहीं, सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस ने तत्कालीन जिलाधीश क्या जुड़ीशियल मंजिस्ट्रेन्न का स्यानीय पत्र 'लोकमत' में छपे हुये लेख पर, जो पुलिस के विरुद्ध था, केवल ध्यान ही आकर्षित किया था?

*४१—-श्री चर्न मुज दामां—-क्या यह सच है कि सुपरिन्टेंडेट पुलिस और डि॰ मैजिस्ट्रेट के लिखने पर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने 'लोकमत' समाचार-पत्र के सम्पादक और मुद्रक को नोटिस उनके खिलाफ तौहीन अवालत का मुकदमा चलाने का दिया?

माननीय स्वशासन मांच्यय जी नहीं। लेल को देखकर जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने स्वयं ही उक्त पत्र के प्रकाशक तथा मुद्रक के नाम नोटिस निकाला था।

*४२--श्री स्तुरन्द्र बहादुर सिह— [स्यगित किया गया।]
मशानरी खरीदने बाले अफ्सरी व निरीक्षकों के नाम
अनुभव और विशेष देश्यतार्थे

*३४--आ ग्रोन्द्र बहादुर स्निह--क्या सरकार उन अफसरों व निरीक्षकों के नाम मय उनके अनुभव व विशेष योग्यताओं के बताने की कृपा करेगी, जिनकी जिम्मेदारी पर सरकार ने करोड़ों रुपयों की मझीनरी खरोदी हैं ?

माननीय पुलिस स्वांचय (श्री लालबहाद्र)—सरकार ने किसी विशेष अफ्रसरों की जिस्सेवारी पर मशीन नहीं खरीबी है और न खरीबती है। बिल्क जिन विभागों को मशीनों की आवश्यकता होती है वे डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज को अपनी मांग मेजते हैं और डाइरेक्टर आफ काटेज इंडस्ट्रीज जुने हुयं फर्नों से टंडर मंगवाते हैं। टंडरों के आने पर जो मशीनों वियरण से आवश्य-कर्ता मुसार अच्छी मालूम होती हैं उनको मशीनों के टंडर मांग करने वाल और यर्तनेवाले विभागों के टेंक्स अफ्रमरों की सम्मति से स्वीकार किया जाता है और वे विभाग उनके लिये कप करने का आवश्य देते हैं और उनका मूल्य चुकाते हैं। यब प्रश्न का अभिप्राय स्टोर्स पर्वेज विभाग के अफ्रसरों से हो तो उनकी एक सूची नत्यी हैं।

(बेस्तिये नत्थी 'ड' आगे पुष्ठ ६९३ पर)

स्टोर परचेज डिपाटंमेंट तथा उनके अफसरान के विशद्ध सरकारी कार्यवाही *४४--ओ सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके पास स्टोर परचेज डिपाटंसेंट व उसके अफ़सरान के खिलाफ कोई शिकायत आई थी? यदि हां. तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाडी की ? माननीय पुलिस सचिव--सरकार के पास स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफसरों के विरुद्ध एक शिकायत पिछले जून भ स में श्री रामचन्द्र नवावगंज, कानपुर की आई थी, उस पर उचित कार्यवाही की गई है।

श्री सुरेन्द्र वहादुर सिंह—न्या सरकार यह बनाने की कृपा करेगी कि वह शिकायत क्या थी और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

माननीय पुल्लिस सिचिव--जो शिकायत आई, अभी उस पर जांच खत्म नहीं हुई है। जब जांच लत्म हो जायगो तब कार्यवाही की जायगी।

*४५--श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह-नया यह सही है कि बोरों की खरीदारी में सरकार को दस-यदह लाख का नुकसान हुआ? यदि हो, तो क्यों ?

माननीय पृत्तिस सचिव-उद्योग विभाग को उनके स्टोर्स द्वारा खरीदे हुये बोरों में ऐसी कोई हानि नहीं हुई।

श्रा सुरेन्द्र बहादुर निह—न्या सरकार यह वताने की कृषा करेगी कि यदि ऐसी कोई हानि नहीं हुई तो क्या कोई हानि हुई या बिलकुल ही नहीं हुई ?

माननीय पुलिस सचित्र--जहां तक गवर्नमेट को मालूम है कोई नुकसान नहीं हुआ।

*४६--श्री सुरेन्द्र वहादुर सिंह--क्या यह सही है कि प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कन्बल खरोहने में सरकार को दस हजार रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुल्लिम सचिव--स्टोर्न परचेज विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कम्बल खरीदने में सरकार को ऐसी कोई हानि नहीं हुई ?

*४७—श्रो सुरेन्द्र वहादुर सिंह--न्या यह भी सही ह कि जूतों की खरीदारी में सरकार को बोस हजार रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

माननीय पुलिस मिचव-पह भो सहो नहीं ह कि सरकार को जूतों की खरीदारी में २०,००० ६० की हानि हुई।

श्रा सुरेन्द्र वहादुर सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगर २० हजार का नुकतान नहीं हुआ तो क्या कुछ कम नुकतान हुआ और क्या हुआ ?

माननाय पुलिस सचिव--जो हां, करोब २,१३० रु० का नुकसान हुआ।

*3८--श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह--क्या यह सही है कि स्टोर परचेब विभाग के कोई आफ़िसर हैदराबाद आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे ओर पुनः नियुक्त कियेगये ? क्या यह सही है कि उक्त महोदय पहिले स्टेनोग्राफर ये ?

माननीय पुलिस सिचव-हां, यह सही है कि स्टोर्स परचेज विभाग के एक अफ़सर श्रो सैयद फैयाज अली हैदराबाद आन्दोलन के तिलतिले में गिरफ्तार किये गये थे। परन्तु वह हाई कोर्ट से छूट गये और वे फिर अपनी जगह वापित आ गये। ये अफसर पहिले डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज के स्टेनोग्राफर थे, लेकिन १९४३ ई० में एक्सट्रा असिस्टेंट ए० डी० आई० के पद पर नियुक्त किये गये थे।

*४९--श्री सुरेन्द्र वहादुर सिंह--क्या यह सही है कि उक्त महोदय के प्रायः सभी सम्बन्धो पाकिस्तान में हैं और बहुत सी पाकिस्तानी फर्मों को जमानतें इन्होंने रिहा कर दो है ?

माननीय पुंत्तिस सिचिव—श्री सैयद फैयाज अली के कुछ चचेरे भाई व भतीजे, जो बिना उसकी मदद व उनसे अलग रहते हैं, पाकिस्तान में हैं। उनके एक छोटे भाई सैयद मकसूद अली, जो सरकारी नौकरी से पेन्यन पा गये, वह भी हाल ही में पाकिस्तान चले गये। श्री फैयाज अली का बड़ा लड़का व बड़ी लड़की भी पाकिस्तान

चले गये उनके साम्यान के लाकी लोग बीबी प्रपाच लाके या का लाकियां उनके साथ गही रक्षी हा। उत्त अकार ने ६ किस्तार क्ष्मी की जमापत िहा नहीं की है, बल्कि सरकार के आबदा रें े अमा नते रिहा की जाती है।

≺ः—आ। अरेग्रेया व स्मार—ाश यह स्थे व लि उस्त जाफिसर से अभी हाल में का भूर इ-अविश्व मा, रवी तन की सिकारिक दिस्पोल र सस्त। शरह पर मिनाम सटा के रारोड़ी को पान की पर किए उसा कर्म है। जीवक कीमत पर गवनरोड है। उसे म्बरोदन का लगान रहा है। टीइटा, तो ऐसा क्यों किया गया है

माननाथ पुल्लिस नात् । -- रोस नात ने कत्पुर जीनिशी कारपोरेशन से कोई प्रस्ताका निरंद की रण ना।

अगान दोन्द्रशास स्वराह जाने हा हत्या

९१---आ सुरस्य वटाव्यासम्बद्ध--क्या वह सह। तीः सरता असते लाल कीमत के दी बहु के अन्वरंगरीदे हुए करीज चार हो तहरा है। वेज र उँट हो ड्रेक्टर काम बार रहे, अहर ब न्या सा तो तनराप्र ने या उनी पन न रद है शिव ही, तो त्रा साधार का नेगो कि गर । हर्कर स्था गरीदे मने ?

भी मदक्त जुर, मान-- हा ३८९ र ८६रा ने, जो जगर । सर्१ ,४९ देव तह वरीदे गथ स २ १२ चाल्हालन से । १७० हर-र उस समा उन रोहा का प्रता ने चालू हारात । में जानेन नितनो नामना से फाला पूर्व विना लगवा मोस दूस्टरें जिल्लान नेक का ह और गरात्र हैनडर नहीं सरीवें गर्ये।

श्री मुन-इ बहार । मार--क्या सरहर यह बनाने का कुरा वारेगी हि ऐसे १७७ दैनटर क्यो खरीरे गरे, जिन्हे पूर्व । भेने की रनह से वे रेहार परे , ?

श्री महक्त पुरस्मान--पूर्व में (जनते हुन्हरों) है। जगरन या उत्तरी जरूरत से भी तम नकर पार है गरे वे पहाल महाचार उन्तर हिंदा। नहां यह जो खरीबे गर्ये, व निरायन अन्ती हात्ता में थे। त्कि हैकार स्वर्शने याति त्ये में जो देनूहरू का ठार 'रोनाक नण जानी हे य उपर नरे पुत्तें भा नणे विका ने, जनलिये बाज देवार जादी जराय हो गये।

क्रांप समान्यी मशीनरी खरादने के लिये दा काब हाया पश्रम दिया जाना

ं रच--श्री सुरन्द यहातु स्मिंह--(स) क्या पह सही ह कि कानपर के एक अमीर क्रम की चीक एप्रीकलचर उन्नोतिपर द्वार को लाग राय पत्रमी कृति सःबन्धी मशीनरी खरीयने क लिय बिये गरे ? यांव हां नो किस कायी से ?

(म) या यह सही है कि जिलाइन राया का हि।। ज लिये हमें चीफ साहज न बी लाख कथ्या और पेशमी देने की सिकारिश की ? याद हा, तो क्यों ?

आ। महजुर्दहमान-जी हा, सर्वश्री मुन्ता लाल एँड की० कानपुर, का उन सब दैक्टरों के मूरुव का २५ प्रति से हड़ा पे हागी दिया गया, जिनके लिये सरकार में आईर विया था। ऐसी पेशगी विया जाना स्टोर परवेज रूत्स के रूल ७ अपेन्डेक्स डी के अनुसार ठीक है।

(ख) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

र्था सुरेन्द्र बहादुर निह-क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सर्वश्री मन्ना लाल एन्ड कम्पनी के द्वारा ही सारे ट्रेक्टर क्यों मंगाये गये ?

थों महितु र हमान-सब देवहर उनके ही जरिये से नहीं संगाये गये बरिक दिल्ली की एक फर्न और भी है, जिसे २५ द्रेक्टरों का आईर दिया गया।

वकशाप के संबन्ध में टेन्डरों का विवरण

*५३--श्री मुरेन्द्र वहादुर सिंह--क्या यह सही है कि वर्कशाप इत्यादि के बनाने के लिये कुछ चुने हुए फर्मों की ऊंची शरह पर इसलिये ठेका दिया जाता है कि कम शरह के टेन्डर वाले अविश्वसनीय तथा अयोग्य हैं ? क्या सरकार एक कागज मेज पर रखने की कृपा करेगी, जिसमें गत दो वर्षों के टेन्डरों का पूरा विवरण हो ?

्रश्रो लताफत हुसैन—सार्वजनिक निर्माण विभाग के भवन तथा मार्ग उपविभाग में वर्कशाप आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरअपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सीतापुर, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस और फेजाबाद में बन रहे हैं और इनके लिये सबसे कम शरह के टेन्डर स्वीकार किये गए थे।

सरकार यह समझती है कि इस सूचना के प्राप्त करने में जितना वक्त और जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना फायदा हासिल नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र वहादुर सिंह--क्या यह सही है कि कभी-कभी कम शरह के टेन्डर देने वाले ठेकेदार अपने काम को पूरा नहीं दर पाते हैं, और इससे काम में हर्ज होता है ?

थ्रो छताफत हुसेन--बहुत कम ऐसी शिकायतें हमें मिली हैं ज्यादा तादाद ऐसे आदिमियों की नहीं है।

कृषि-रक्षा के लिए बन्दरी तथा नीलगायों के निकाले जाने की तरकीव

#५४--श्री सुरेन्द्र बहादुर सिह--क्या सरकार ने कृषि-रक्षा के लिए बन्दरों व नीलगायों के निकालने की कोई तरकीब निकाली है ?

श्री महजुक्तरहमान--जी हां, नीलगायों को मारने पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया था वह हटा दिया गया है। जिन-जिन जिलों में बन्दर फसजों को नुकसान पहुंचाते थो, वहां की जिला फूड एडवाइजरी कनेटी से आवश्यक सुझाव मांगे गये हैं।

श्रो सुरेन्द्र बहादुर सिंह—क्या सरकार को यह भालूम है कि केवल नीलगायों के मारने का प्रतिबन्य हर जारे से नीलगायों की बाधा दूर नहीं हो सकती ? क्योंकि काइनकारों के पास कोई जरिया उनके मारने का नहीं है ?

श्री मह फ़्रुजुर हमान--हर जिले में शिकारियों का नम्बर बहुत काफी है। पहल वे नी जगबों को साफ करें फिर बाद में और इन्तजाम किया जायगा।

श्री सुरेन्द्र वहादुर सिंह—ज्या सरकार यह बतलाने की कृषा करेगी कि फूड एडवाइजरी कमेटी का सुझाव आ गया या अभी तक नहीं आया है। माननीय शिक्षा सचिव—गालिबन सब जगह से अभी तक न आया होगा।

जिला जालीन के मुद्धाचार विरोधी कंमेटी की कार्यवाही

*५५--श्रो चतुर्भु ज शर्मा--जिला जालीन के भ्रष्टाचार-विरोधी (ऐंटीकरप्शन) कमेटी की बैठक पिछले साल और इस साल कितने बार हुई ?

श्रो गोविन्द सहाय—जिला जालीन के भ्रष्टाचार विरोधी (ऐन्टीकरफान) कमेटी की १९४८ ई० में ६ और १९४९ ई० में २ बैठकें हुई हैं।

*५५--श्री चतुभुं ज शर्मा-इस कमेटी के द्वारा कितने भ्रष्ट सरकारी कर्म-

चारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गया ! श्री गोविन्द सहाय—कमेटी किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करती। इसलिये सवाल नहीं उठता । *५७--श्रो चतुर्भु ज शर्मा-- क्या यह सब है हि जिला जालीत के कई पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के खिलाफ स्पट्टाचार को लिखित शिकायतें की गर्यों ?

माननीय पुलिस सचिव-जी हां।

*५८-श्री चतुर्भे ज शर्मा-नया इनकी जांच पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने की ? यदि हां, तो उनका क्या नतीजा हुआ ?

माननीय पुलिम सचिव-- उनको जांव सकिल इंसपेक्टर तथा डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने की परन्तु शिकायतें ठीक साबित नहीं हो सकी।

*५९--थ्री चतुर्भुं ज दार्मा-- वे शिकायतें कब की गई थीं और कब इनकी जांच की गई?

माननीय पुलिस सचित्र--शिकायतें १९ मई, १९४९ को की गई। जांच २२ मई को शुरू हुई और ५ तितम्बर को समाप्त हुई।

*६०--श्रो चतुर्भं ज शर्मा--(क) क्या इनकी जांच होने की सूचना शिकायत करने बालों को लिखित दी गयी?

(ख) नया जांच का नतोजा शिकायत करने वालों को बतलाया गया?

माननीय पुलिस सचित्र--(क) लिखित नहीं दो गयो परन्तु जीव शुरू होने पर उन्हें बताया गरा और उनके नाम पूछे गये जो इसमें गवाहो दे सकते थे।

(ख) माननीय तबस्य को इस सन्तन्थ में बतलाया गया।

*६१-६२--श्रो चतुर्भुज शर्मा--[स्थगित कित्रे गये।]

जिला जालीन के बारेन्द्र' 'नोकमत' तथा 'जय हिन्द' समाचार पत्रों एवं उनके प्रकाशनकर्ता के विरुद्ध कार्यवादी के वारे में पूंक्तांक

*६३--श्रो चतुर्भुं त रामां--क्या यह सच है कि कोंच से प्रकाशित होने वाले 'बोरेन्द्र' सनावार-पत्र में एक तिकाया श्रो भागीरय सिंह द्वारा छताई गयी थी ?

श्री गांविन्द सहाय--जी हां।

*६४—श्रो चतुर्भुज रामां—(क) क्या यह सच है कि इस शिकायत को झूठ समप्तकर जिला अधिकारियों द्वारा उक्त 'बोरेन्द्र' पत्र पर मुकदमा चलाने का नोटिस दिया गया?

(स) क्या यह सब है कि 'बोरेन्द्र' सम्पादक ने उत्तर दिया था कि पुलिस ने एक इसरे भागीरण सिंह से फर्जी बयान ले लिया है ?

श्रो गोविन्द सहाय-(क) जी नहीं।

(ख) जी हो।

*६५-- आरे चतुर्भेज रामी-- क्या यह तब है कि उस्त 'लोकमत' में गत १४ अप्रैल को 'पुलिस को शिहारत' नामक एक समानार छ।। या ?

श्री गोविन्द सहाय-जी हो।

*६६ - ओ चतुर्भुं ज रामी - स्या यह सच है 'कि उक्त समाचार पर सुप-रिस्टेंग्डेंग्ट पुलित ने जिला मैं जिस्ट्रेंट को लिखा कि - 'यह लेल जुड़ी शियल मैं जिस्ट्रेंट की अदालत में चलने वाले एक मामलें में अदालत के द्वारा न्याय के मार्ग को पक्षपातपूर्ण करता है?" और यह भी लिखा कि अदालत की मानहानि का मामला सम्पादक मुद्रक व प्रकाशक पर बलाया जाय?

श्रो गोविन्द सह।य-जी हां।

प्रश्नोत्तर ६२७

*६७—श्री चतुर्भु ज शर्मा—क्या यह सच है कि उक्त आग्रह पर जिला मॅजिस्ट्रेट ने अपने अधीनस्थ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट को अदालत की मानहानि का ने।टिम देने की सलाह दी?

श्रा गोविन्द सहाय-जो नही।

×६८-६९--श्रो चत्भ् ज शर्मा--[स्थगित किये गये।]

*७०—श्री चतुमुं ज रार्मा—क्या यह सच है कि काल्पो से निकलने वाले समाबार— पत्र 'जय हिन्द' ने ता० २४ मई सन् १९४९ ई० के अंत मे मुद्रक एवं प्रमारक का नाम न दे कर प्रेस ऐक्ट का उल्लंघन किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई?

श्रो गोविन्द सहाय-नही।

जिठा हमोरपूर में उन्नतिशोछ उद्योग धन्धों की नवीन योजनायें

''७१-श्री श्रीर्पात सहाय-निया सरकार ने जिला हमीरपुर में उन्नतिशी ३ उद्योग-धन्धों की कोई नवीन योजना चालू की हैं ? अगर की, तो क्या और नहीं, तो क्यो नहीं ?

मानना र पुठिस सिवय--एक शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खादी योजना ककरई, जिला हमीरपुर में चल रहा है।

बरूआ सुमेरपुर में एक शिक्षण केन्द्र ट्रेनिंग का चल रहा है और महोबा में एक ू चर्मशिक्षालय (लेंदर वरकिंग स्कूल) को सरकार अनुदान प्रदान करती है।

श्री श्रीर्पात सहाय—क्या सरकार हमीरपुर जिला के किसी ऊनी कार्यालय को सहायता करने का विचार रखती हैं?

माननाय पुलिस सचिव--सभी ऐसे ग्राम उद्योग जोकि सफलतापूर्वक चलाये जा सकते हें, उनके बारे में अगर कोई दरख्वास्त आयेगी तो उस पर गवर्नमेंट जरूर विचार करेगी।

*७२--भ्रो श्रोपति सहाय--(क) क्या यह सच है कि जिला हमोरपुर मे गोरहरी ग्राम में गौरा पःथर की खान है ?

- (ख) क्या यह भो सच है कि इस पत्थर से टो सेट, गिलास, तस्तरी, प्याले आदि सुन्दर वस्तुएं बनायी जाती है ?
- (ग) इस धन्ये को उन्नितिशोल बनाने के लिये क्या सरकार ने किसी योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां।

(ख) जी हा।

(ग) अभी सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है, पर गवर्नमेट इस प्रश्न पर विचार करेगी।

*७३--श्रा श्रीपति सहाय--क्या सरकार ने कभी नीम से तेल निकालने की योजना पर विचार किया है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रतिफल निकला ?

माननाय पुलिस सिच्य व—प्रान्त में थोड़ो मात्रा में नीम से तेल निकाला जाता है। सरकार ने नीम तेल को योजना पर जो कुछ विचार किया है उससे उस उद्योग की सफलता मे अधिक आज्ञा नहीं दिखाई दी है।

श्रो श्रोपित सहाय--वह कौन सी कठिनाई है जो सरकार के सफल होने में बाबक है?

माननीय पुलिस सचिव-कोई कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि इस काम में ज्यादा फायदे की बात नहीं दिखलाई पड़ती है इसलिये ऐसा कर लिया गया है।

७४--श्रा श्रीपति सहाय--(फ) क्या सरकार को माल्म ह कि बुन्देलखड के पहानों में लोहा निकलता ह

(ख) यहि हा, तो क्या मरकार ने उक्त छोहे को प्रात करने চी कोई योजना निकाली ह

माननाय पुलिम सचिय--(क) नही।

(ख) यह प्रश्न नही उठता।

टाउन परिया बनने बाले गावा ले कम से कम जनसर्या

'७५--श्राश्रापान महाय--क्या सरकार बनला के के कप करेगी कि वह कम से कम कितनी आगण्या वालेगाया में दाउन एरिया म्यानि करने का विधार करता ह? माननाय माशासन स्वीचार--दाउन एरिया की स्थाना कियी निश्चित जनसख्या पर निर्भर नहीं हैं इस सबर के प्रत्येक प्रराव पर गार परिस्तिन जी जान के बाद यह। दाउन एरिया की स्थापना करने का निश्चर लीता है।

जित्राह्मारपुर में चार हजार संबाध का जन नम्य। बाल गार्जा । सहसा

*७६--श्रा श्रामि स्वराय--जिला हमीरार में चार हजार से जाक जनसख्या बाले गांव किन्त और कीन-कीन ह ?

माननाय रत्रशासन म्यन्तित्र--१९४१ ई० को गणना के जामार हमीरपुर जिले में फैबर ह गांव तथा कहने होने हैं जिनको जनस या ४ हजार से आहर उनके नाम इस प्रकार है---

१—हमीरपुर (यरवा)
२—ममेरपुर (करवा)
३—विरेटा (गाय)
४—मयदहा (यस्बा)
५—महोबा (कस्बा)
६—श्रानगर (गाय)
७—कुलपहाड (तहसी २ रेडक्बार्टर)
४—गनवारी (गाय)
९—र ट (कस्बा)

श्रा श्रि । ति न्नहाय--सरकार गृलाहाण गाव में टाउन एरिया की स्थापना के बारे में क्या विचार रखती हैं? जबकि वा तहसील का हेंडक्वार्टर हे आर एक उड़ा कस्वाहें ?

माननाय स्वशासन स्म ज्ञय--इस बात पर विवार हो रहा है।

श्रा श्रोर्शन स्ट्राय -- सबदहः में टाउ। एरिशको स्युनिनियैलिटी बनाने में गवर्नमेंट का क्या विवार है जबकि वहां की आसदनी ५० हजार से उशदा है ?

माननाय स्वाासन स्वित-अभी यह मालून हुआ है कि इतना खर्वा वह बर-दारा नहीं कर सकेगा, विशाला डो म्युनिस्तैलिटो नहीं बनाया गया।

जिला हमारपुर में तेठ निकालने की योजनाप

*७७--आश्रापित सहाय--क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीरपुर में ति नहन अधिक होता है ? अगर हां, तो सरकार ने वहां तेल निकालने की घरेलू योजनायें प्रसारित करने पर विचार किया है ? अगर हां, तो क्या और नहीं, तो क्यो ? प्रश्नोत्तर ६२९

माननीय पुलिस सिचिव—हां। हमीरपुर में काफी तिल्हन होता है। इसीलिये धरेलू नेल उद्योग योजना इस वर्ष हमीरपुर में भी लगा दी गई है। वहा के बढ़ इयों को मशोधित वर्धा तेल को न्हू बनाने की शिक्षा देने का प्रबन्ध हो रहा है। इन को लड़ का एक प्रदर्शन यूनिट (डिमांस्ट्रेशन यूनिट) भी वहां भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसके बाद जिले में उन्नत प्रकार के को लड़ लगाये जायेगे जिनमें वहां के घरेलू तेल उद्योग को प्रोत्साहन मिले।

श्री श्रीपित सहाय--यह योजना कब तक चालू हो जायगी ? माननीय पुलिस सचिव--जल्द ही अशा की जाती है।

वुन्देल खरड में याल की खेती

े७८—श्रा श्रीपति सहाय—क्या सरकार को मानूम है कि बुन्देलखड में अल नाम पेड़ की जड़ से लाल रंग बनता था और उनकी खेती होते। थी?

माननीय पुलिस सचिव--हां, मालूम है।

े ७९—श्री श्रीपित सहाय—ग्या सरकार को यह भी मालूम है कि अग्रेजों ने विदेशी रंग मगाकर आल की खेनी समान्त कर दी ?

माननीय पुलिस मचिव—चूं कि आठकी जड़ से बना हुआ लाल रग अधिक महंगा पड़ता था और विदेशी रंग अर्थकाकृत सस्ता पड़ता था अतएव आल की खेती स्वतः बन्द हो गई।

*८०-भी श्रीर्पात सहाय-यदि हां, तो क्या सरकार आल की खेती को पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

माननीय पुलिस सचिव—आल कृषि को पुनर्जीवित करने की इस समय संभावना नहीं मालुम पड्ती।

जिला हमीरपुर में साकारी सांहों की संख्या

*८१--श्री श्रीयित सहाय-स्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में कुल सरकारी सांड कितने है और वे कौन-कौन गांव में है ?

श्री महफूजुरेहमान--१९१ गांत्रों की एक सूची जहां सांड़ है नत्थी है। (देखिये नत्थी 'च ' आगे पृष्ठ ६९५ पर)

*८२--श्री श्रीपित सहाय-क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने और कौन-कौन गांव के सांड बुड्ढे और बेकार हो गये हैं?

श्री महफूजुरहमान--सूचना इकट्ठी की जा रही है।

श्रोश्रोपित महाय--क्या सरकार यह बतलाने को कृपा करेगी कि यह सूचना कब तक आ जायेगी?

श्री महफूजुर्रहमान--चूंकि आगके जिले में चलने-फिरने की मुश्किलात है इस वजह से अभी कोई इत्तला मिलना मुश्किल है।

श्री श्रीपति सहाय--यह मुश्किलात कव तक दूर हो जायेगी?

श्री महफूज़र्रहमान—निवयों वग्रैरा की कुदरतन् मुहिक्ष्णात है जब वह दिक्कत दूर हो जायेगी तब कुछ हो सकेगा।

जिला हमीरपुर में उमिश्वया राठ के रास्ते में बनी रपड़ पर व्यय

*८३--श्री श्रीपित सहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में नहर बसान साख मौदहा के राठ, माइनर के कुर्रा स्केप की उमन्निया राठ के रास्ते में जो रपड़ बनी है वह कितने दिनों के लिये बनवाई गयी थी ? श्री लता कत हुसेन--ये रपड़ कई वर्षी के लिये बनाई गई है।

श्री श्रोपित सहाय—क्या सरकार को यह मालूम है कि प्रश्न का उत्तर मिलने के पश्चात् भी २४ बोरे सीमेंट खर्च नहीं हुई ?

श्री लताकत हुसेन-जवाब में बताया गया है कि सीमेंट खर्च हुई।

श्रीश्रीपति सह।य-क्या सरकार इसकी जांच करने की कृपा करेगी ?

नाननाय सर्विजनिक निर्माण सचिय-इस बात की वजह नहीं मालूम होती कि इसकी क्या जरूरत है।

श्री श्रीपति सहाय-इसिलये कि वह रपड़ फिर से ट्टने के लिये तैयार हो रही है? माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव-वह टूटने के बाद फिर से बनवाई जा चुकी है।

*८४--श्री श्रीपति सहाय--प्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उक्त रपड़ में कितना सीमेंड खर्च हुआ ओर उसका कुल एस्टिमेट कितनाथा?

श्री लताप्तत हुसेन— उसका तखमीना ४९१ रु० या जिसमें से सिर्फ ३९१ रु० खर्च हुये हैं। इस अर्च में २४ बोरा सीमेंट की कीमत भी शामिल है।

*८५--आं श्रीपति सहाय--क्या यह सच है कि वह रपड़ बनते ही तुरन्त उखड़ गयी ? यदि हो तो उसका क्या कारण है ?

श्री लता हत हुसैन—इस रपड़ के बनते समय बीहर राजबाहे के टेल से पानी कुर्रा स्केप में आ गया था जिसके कारण सूखी पःथर की नई पिंचिंग बैठ गई थी। उसी समय रपड़ उखड़वा कर दोबारा बनवाई गयो जिसकी लागत ठेकेदार की देना पड़ा।

जिला हमोरपुर की राठ तहसील में चलसी के उपयोग में लाने की नई योजना

*८६—श्री श्रीपित सहाय—क्या सरकार को मालूम है कि जिला हमीरपुर की राठ तहतील में कृषि विभाग के विशेषकों के मतानुसार अलसी उत्तम और अधिक उत्पन्न होती है?

श्री महफूजुर्रहमान--जी हां।

*८७--श्री ओपित सहाय--यि हां तो क्या सरकार ने वहां अलशी की वारितश्च या रेशे सम्बन्धी उद्योग-धंशें को श्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार को है ?

भी महफुज़ुर्रहमान—इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है, परन्तु सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

जिला हमोरपुर में नबीन पुलिस थानों की स्थापना

*८८--भी भीपति सहाय--क्या प्रान्त में पुलिस थानों के पुनः तिमाण के लियें सरकार की कोई योजना है ?

माननीय पुनिस सम्बन्ध ने हो। इन्सपेक्टर जैनरल ने इस सम्बन्ध में एक योजना सरकार को भेजी हैं जो विचाराधीन है।

*८९--थ्री श्रीपति सहाय--क्या सरकार जिला हमीरपुर में कुछ नवीन पुलिस यानों की स्थापना करने का विचार रखती है। अगर हां, तो कहां कहां?

माननीय पुलिस सिचिव—इस योजना के अनुतार हमोपुर के थानों में ३८ कान्सटेबिलों की बृद्धि होती हैं। केकिन इस जिले में इस समय नये थानों की स्थापना करने का सरागर का कोई इराबा नहीं है।

जिला हमोरपुर में राठ त्या मोडह नहनाला के रास्ता का सुधार

*९०--श्रो श्रापित सहाय--(क) क्या मरकार बतनाने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर ये राठ तथा मौदहा तहसील मे ऐसे कितने ओर कौन-नौन से गाव है, जहां जुनाई से अक्तूबर तह बराबर र स्तो में पानी भरा रहना है या दलदल पड़ जाता है?

(ख) क्या सरकार कृष्या बन येगो कि वह इनके सुपार के लिए क्या उपाय सोच रही हैं? मान नी प्रकाशना सिवय--(क) जिन रास्ता में पानी भरा रहता है या दलदल पड़ जाता है उनके नाम इस प्रकार है:--

तहसीन गठ

१--र ठ करावी सड़क के अ खिरो ४ मील।
२--राठ जरासर सड़क के आखिरी ७ मील।
३--करगवा कराकर मड़क के आखिरी ३ मील।
४--राठ उमरी सड़क के आखिरी ८ मील।
५--राठ चंड़ौत सड़क के आखिरो १० मील।
६--राठ चंनपुर सड़क के आखिरो ८ मील।
७--राठ सुदेवा सड़क के आखिरी १० मोल।

तहसाल मौदहा

१--मोदहा इटोहटा पड़ है के अ खिरी २ मोल।
२--मौदहा लेहड़ी सड़ है के आखिरी ११/२ मोल।
३--मौदहा चतरा सड़ है के आखिरी ४ मील।
४--मौदहा पाटनपुर सड़ है आखिरी ७ मील।
५--मुस्करा गहरोलो सड़ है आखिरी ६ मोल।
६--निशर सरेला सड़ है अ खिरी २१ मोल।
७--विशर जनालपुर सड़ है आखिरी ८ मील।

(ल) इन सम्बन्ध में मरहार के सामने कोई विशेष याजना अभी तक नहीं है। अलबता जिला बोर्ड हमी एपुर के राठ करगवा तथा मुम्करा गहरौली सड़कों की मरम्मत के लिये कुल २,५७,५०० ६० के अनुदान का प्रार्थना को है जिसमें से कम से कम ६४, २३० ६० तम्हाल मांगा गया है, परम्नु घनाभाव होने के कारण यह अनुदान इस साल संभव नहीं है और बोर्ड को इसे लेने का सुझाव दिया जा रहा है। प्रश्नोतर के समय के समान्त होने के कारण शेष प्रश्न अगले दिन की कार्य मुची में रख दिये गये।)

सन् १६५६ ई० का रामपुर (एष्ठिकेशन आफ लाज) ग्राडिनेंस

माननीय निश्चा मचिव—में सन् १९४९ ई० का रामपुर (उप्लिकेशन आफ लाज) आडिनेंस सन् १९४९ ई० को संख्या १३ की प्रतिलिधि मेज पर रखता हूं। सन् १९४० ई० के यूनाइटेड यालिनज मर्जेड स्टेट्स (एप्जिकेशन अप्ता

ळाज खार्डनस

माननीय शिक्षा माचित्र-मै सर् १ .० ई० के (यूनाइटेड प्राविसेन मर्न्ड स्टेट्स एष्लिकेशन आफ लाज) आर्डिनेस सन् १९५०ई० की सख्या १ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं। सन् १६३५ई॰ के सयुक्त प्रांत के मटर गाड़िया के ब्रार-कर के नियम १२ में संशाधन

मः ननाय पिरुम्म कांच्य--मं सन् १९३५ ई० के सद्वत प्रातीय मोटर गाहियों के आय-कर ऐष्ट यूनाइटेड प्राविमेज मोटर वेहिकित्म टेब्सेश्च ऐवट सन् १९३५ की वारा २१ के अन्तर्गत सन् १९३५ ई० के मयुक्त प्रात के मोटर गाड़ियों के जाए-वर नियम १२ में किये गए संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ।

†सन् १६४६ ई० का संयुक्त प्रापेय तमीं टारी-ावनाका आर भीम-व्यवस्था बिल

माननीय रूपीकर—अब माननीय माल मिच के इस प्रस्ताय पर कि सन् १९४९ हैं के समुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल पर, जैसा कि वह संयुक्त विशिष्ट मिमित द्वारा सशोधित हुआ है, विचार विधाणीय, वाद-विवाद जारी, होगा। कल श्री राजाराम शास्त्री का भावण हो रहा था। अब वह अपना भावण जारी रखेंगे।

*श्रा गानाराम शास्त्री—मानतीय स्वीकर महोदय, कल में यह कह रहा या कि यदि आप को इस व'। नृन को रफल बन ना ह तो गवनंमें द ने इस कानून म अपने स्व में बड़ी योजना यही रखी है कि किस नो गे दस एना लगन रमूल किया जाय और उसी से अमीं वारों को मुआदिजा दिया जाय, मेरा इन बारे में यह कहना है जि' र श्विप सरकार ने इस बिल में इस बात की घोषणा की है कि दस्गृना लगान देना न देना विसान की स्वेष्णा पर है, लेकिन जो तरीके मरकार को और से प्रयोग में लाए जा रहे ह वे ऐसे है कि जिनसे आप की शासन व्यवस्था चकना जूर हो रही है।

किसान नामा प्रकार की मुसीबतों में पड चुके है। सरकारी कर्मचारी इस तरह से वबे जा रहे हैं कि क़ानूनी और गैर कानूनी सब तरह की कार्रवाई वे करने छगे है । मेरा खुद ऐमा स्याल है कि ऐसी चीजो की रोक-याम न की गई तो प्रान्त के अन्दर नहीं मालूम क्या हालत पैदा ही जायगी और कितने सरकारी कर्मचारी त्याग-पत्र दे हेगे और कितनो ने त्यागपत्र दे भी दिये ह। इस चीज का आप के सामने जिक्र करके में यह बताना चाहता हूं कि आप ऐसी चें जो को छोटा न समझे अगर इस तरह की चीजे हमारे प्रान्त में की गई तो इससे हमारे प्रान्त का बहुत नुकसान होगा। कल जिस वक्त मेंने कुछ बातों का जिक किया था उस सिलसिलें में मेने इस बात का भी जिक किया था कि बहुत सी जगहो पर अधिकारियों का यह विद्वास हो गया है कि कोई भी कार्रवाई करें, ऊपर के अफसरान उनकी मदद करेंगे। बहुत से अफसरान आजकल ऐसी कर्रवाई करते है जिसके सम्बन्ध में मैने बताया था कि सुल्तानपुर बरेली तीसरे फैजाबाव और अब बाराबकी के किसानों ने भी शिकायत की है, कि किस तरीके से यह अफसरान किसानों को बुलाकर और उराकर और धमकाकर उनसे कहते हैं कि वे दस गुना लगान हैं। वे उनको पीटन की धमकी देते हैं और २० किसानों के हस्ताक्षर से मेरे पास एक पत्र आया है। एक और रिपोर्ट है कि जब २५ नवस्वर की किसानों का प्रदर्शन होने बाला या तो उस समय हम लोगों ने कानपुर में इस बात का विचार किया कि प्रदर्शन किया जाय। उस मौके पर में और किसान कार्यकर्ता "" गांव में इकद्ठा मुखे। वहां के बरोगा ने यह जानकर कि वसगुना लगान का विरोध करने के लिये किसान इकट्ठा है उनको अमानुषिक ढंग से गिरफ्तार करना शरू किया और उनकी पीटा भी और उन किसानों को हथकड़ी लगाकर कानपूर की सड़कों पर चलाया गया, जिसका वर्णन में कर नहीं स्कता। इस सम्बन्ध में मैंने कानपुर के कलेक्टर को चिट्ठी भी लिखी यी कि ऐसी हरकतों को रोकना चाहिये। में इन

रे जनवरी, सन् १९५० ६० की कार्यवाही में छपा है।

^{*}माननीय सबस्य में अपने भाषण को बुद्ध नहीं किया।

मिसालों को इसलिये पेश करना चाहता हूं कि मेरे कांग्रेसी भाई यह समझ लें कि इस तरह की हरकतों की रोकथाम नहीं की जायगी तो बहुन बुरा होगा। कई जगहों से अरे पास इस तरह की शिकायतें आई है कि सरकारी कर्मचारियों को किस तरह डराया और धमकाया जाता है और कितनी ही जगहों से मेरे पास स्कूल के टीचरों और पटवारियों की शिकायतें आई हैं। उन को दम गृना लगान बमूल करने के लिये डराया धमकाया गया। मेरे पास इस वक्त बिजनौर जिला बोर्ड के अध्यक्ष का एक छपा हुआ पत्र है। जिला बोर्ड के अध्यक्ष का एक छपा हुआ पत्र है। जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने समस्त कर्मचारियों को जिला बोर्ड के एक पर्चा छपवा के भेजा है और यह पूछा है कि उन्होंने २१-१२-४९ ई० तक जर्मोदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में किसानों को भूमिधर बनाने के लिये क्या कार्रवाई की है। जिन्होंने अधिक से अधिक रूपया जमा किया है उनको सुविधा दी जायगी। इसकी रिपोर्ट मांगी गयी है। अध्यापकों को ठीक समय पर प्रोग्राम के मुताबिक पहुंचना चाहिये। जो लोग देर से पहुंचेंगे वे अपने को मुअत्तल समशें। १५ जनवरी सन १९५० से और १६ जनवरी, १९५० को अपनो अनुगस्थित का उत्तर दे दें और उन्हें कार्य से अनुपस्थित का होना चाहिये वरन् उन के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जायगी।

क्रपया उ∉त स्थानों पर आने के समय अपनी रसीद जो ३१-१२-४९ तक रुपया जमा क्षित्रा गरा है या पटवारी की दो हुई १० गुना लगान की पिंच गो लाइये। इस नियम में आप, आपके विता, अ:पके भाई, चाचा, ताक, इत्यादि निकट सम्बन्धी रिक्तेदार सभी आते हैं। उन सब का इस गुना लगान जमा कराने की जिम्मेदारी अपकी होगी। आपने जब उनका दस गुना लगान जमा कराया हो तो उनकी भी सूबी अपने साथ लाइये । प्रोगाम दिया हुआ है कि किस-किस तारीख पर कहां-कहां आप ने रुपया जमा करके आना है। नोट दिया हुआ है कि क्या-क्या चीजें उनको भर कर लिखना हैं। उसमें नम्बर ९ यह है कि ३१-१२-४९ तक भूमियर बनने के लिये कितना रुपरा आपने जमा कराया। यदि नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नोट है कि प्रत्येक अध्यापक इसको भर कर लाने का कब्ट करे। में सिर्क यह जानना चाहता हूं कि जब यह गवर्नमेंट कहती है कि किसान के पास हप्या काफ़ी है, उसके पास सोना और चांदी भरा हुआ है, भूमियर बनने से बहुत से फ़ायदे हैं तो फिर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जाती हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से हमारे माननीय पंत जो और दूसरे मिनिस्टर सारे सूबे का दौरा करके लोगों में यह प्रचार करते फिरते हैं कि भूमिधर बनने से इतने ज्यादा फायरे हैं कि लोग अपनी खुशी से हजारों रुपये जमा कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि असलियत पर पर्दा डालने के लिये ही ऐनी बातें को जातो हैं। असलि गत बिलकुल इसके विगरीत है। असल बात यह है. कि आज जितने तरीके कोई गवर्नमेंट अपनी प्रजा को दबाने के लिये अख्तियार कर सकती है वे सब हमारी कांग्रेस सरकार आज कर रही है। जरा सोचिये कि किसी भी स्कूल के अध्यापक या गवर्नमेंट के नौ प्तर रक्खे जाते हैं, उनको तनस्वाह अगर पब्लिक के खजाने से दी जाती है, तो वह लड़कों को पड़ाने के लिये दी जाती है, इसलिये नहीं कि गवर्न-मेंट कोई भी आनी स्कीम वेश कर दे तो उसकी मनवाने का काम उनका है। सिर्फ इतना ही नहीं इसमें साफ-साफ कहा जाता है कि अगर तुम दस गुना लगान नहीं जमा करते तो आपको मुअति र कर दिया जायगा और आपके विलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्रवाई की जायगी। तो इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतें गर्वनंमेंट की तरफ से की जाती हैं।

श्री ख़ूब सिह--क्या आपकी नोटिस में कोई ऐसी भी बात आई है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने किसी को मुअत्तल किया हो?

श्री राजाराम शास्त्रो—यह कहा जाता है कि यह बात जो आप सुना रहें हैं, यह तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से की गई। वह कोई सरकारी अफसर तो है नहीं। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के

श्री राजाराम शास्त्री

तमाम कर्मचारियो को लगा दीजियं और कहियं कि ये तो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह कहा तक ठीक है। लर शब म अप के पटवारियो की सुनाना चाहता हू कि किस-किस तरीके से पटवारी तोगों को बलाकर उराया धमकाया जाता है और किस-किस तरीके से पटवारी तोगों को बलाकर उराया धमकाया जाता है और किस-किस तरीके से उनको मजबूर किया जाता है कि वे दस गुना लगान जमा कराने की क्रिश्ता कर और जो नहीं हमा करा पाने है उनको किस-किस तरीका से आप मुकत्तल करने ह और मजा देते हा। साहल मजसे इसी वयत पूछा गया ह कि बताओं किसको मअत्तर किया गरा ह, तो मैंने ता आप के सामने पर्चा गुनाया ह और इस पर जो-जो वहा पर नहीं हाजिर हथे होगे या नहीं जा पायंगे उनको क्या सजा मिलेगी तो किर मौका आयंगा म आप के मामने पेश करगा। इस बकत तो म यह कहना चाहता ह कि अगर आप अपनी तरफ से यह ऐलान कर दे कि चाहे कोई इस पर्च के मुताबिक काम करे था नहीं उसका बोई सजा नहीं मिल सकती ह और आर किसी डिस्ट्रिक्ट बाई के चेयरमन ऐगा परने हैं तो राजा उस आदमी को नहीं बिक बह चेयरमन मुअत्तल किया जायगा। इस तरह की कार्गवाई आप की जिये तो किर देखिये कि सुबे में इस तरह की हरकहाँ कि हाती है।

मुझे कल ही मालूम हुआ है कि एक गालर आपकी तरफ से जारी हुआ है कि पटवारियों के साथ क्या कायदाही की जायगी जो दस ग्ना लगान जमा कराने में स्थव नहीं करेगा। मेरे पास सर्कुलर जो अभी नहीं आया है लेकिन मुझे एक आप ही के अफसर ने बताया है, म नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन सर्कुलर गया है, जिसमें यह कहा गया कि तुम लोग इस तरह से रूपया वसूल करो और जिन कलेक्टरों और डिप्टी कलेक्टरों के नाम यह सर्कुलर गया है वे लोग उन पटवारियों को जिन्होंने एपया इकट्ठा करने में मदद नहीं की उनकों ल्ख मजा वंगे क्यांकि इसमें लिखा हुआ है कि लूब सजा दो और कारण कल ओर यतला देना। च कि पह सर्कुलर मेरे पास नहीं है इसिलयं में ज्यादा न्क्ताचीनी नहीं करना चाहता है। कभी वह सर्कुलर जब हमारे हाथ लग सकेगा तो म आप लोगा के सामने पैश करना।

म जिन अध्यापक ही गांत कह रहा था, उनके सम्बन्ध में जो कुछ मैंने कहा है आप उसकी जांच करायें और अगर वे बातें सही हो तो मुनासिय कायवाही की जाय। यह बात है पकड़ी प्राइमरी पाठशाला, दिलवारनगर महल, जिला गाजीपुर, के सहायक अध्यापक की। उनको मुअतल किया गया था। और चाजेंज उनके खिलाफ क्या थे जरा सुनियं। 10 १ आप जनता में रारकार के विरद्ध गलतफहमी फैंगतें हैं, न० २ जमीवारी उम्मूलन सम्बन्धो दसगना लगान नमा करा के विकद्ध आप लोगो को भाकातें हैं और नं० ३ जुलो मीटिंग में सरकार ही विरोधी पार्टी में शामिल होकर नेता गिरी करते हैं। अब आप जरा गोर तो की जिये कि चूकि वह ननागिरी करते हैं। वह पहिलक में जाकर अपने विचार प्रगट करते हैं सरकार के खिलाफ, ये इनने बड़े इलजाम है कि जिनके लिये उन्हें मुअत्तिल कर दिया और उसके इवर मजा यह कि हमारे माननीय मंत्री जी कहते ह

मानमाय शिक्षा समिव--यह गलती हुई उनसे कि डिसमिन नही किया और मुअलल करके ही छोड़ विया।

श्रा गाजागाम द्यास्त्री—मं करता हं कि उन्होंने डिसमिस ही नही, बल्कि फांसी पर क्यों नहीं चढ़ा दिया। जिस राज्य में, जिस सरकार में, ऐसे योग्य और इन्साफ पसन्द आदमी होंगें उसकी तो आपही अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वह सरकार कब तक कायम रह सकती है। अगर आप चाहे कि कोई भी शक्स कार्य के खिलाफ, कांगेस सरकार की नीति के जिलाफ, आवाज न उठाये, नो यह मुश्किन नहीं है। आप इसको रोक नहीं सकते। यह कैसे हो सकता है कि अगर कोई आदमी, चाहे वह सरकारी नौकर ही क्यों न हो, विरोधी

पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग में चला जावे या चुनाव में भाग ले, तो आप उमके ऊपर अभियोग लगावे और ८सको नुकसान पहुंचावे ? एक पढ़ने वाले रूड़के को जिसने सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव मे भाग लिया, आपने जुर्माना तक किया। व कहता हूं कि बुरा होगा रदि अप यह चाहें कि जितना हो सबे दमन किया जाय। दमन दुनियां में बहुतों ने किया है। आप कोई नई बात नहीं कर रहे है। लेकिन इसका नतीजा हमेगा बुरा होता है शायद अाप इस चीज को इस समय इसलिये अच्छा समझ रहे है, क्यों कि आप इस नामय सरकार है तो अ।पनो ये चीजे पसन्द आ रही है। आप ममझते है कि इन चीजो से विरोधी पार्टी दब जावेगी, ऐसा होना नामुमिकन है। मैं आपसे दावे के साथ वह सकता हूं और हमारे साननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि बहुत कम सभा दी जि मुअलल ही किया गया और फौरन ही उसकी डिसमिस क्यों नहीं कर दिया गया। जब यह खबर अखबारों में छपेगी तो जितने भी डिस्ट्वर बोर्डो के चेयरमैन होंगे वे मब इसे पढ़ेंगे और वे समझेंगे कि अब तो हमानी पीठ ठोंक दी गई है अब अगर किसी ने जरा भी कोई खिलाफ़ बान कही या कोई ऐसा काम किया तो सब तरह से हम उसनो दबा सकते है। इस नरह से वह बेचारा तो मौत के मुँह मे गया और फौरन ही डिसमिस तो उसको कर ही दिया जावेगा और जरा सुनिये, उनकी अपील कहां होगी ? अपीर वहीं उनके, हमारे माननीय मंत्री जी के पास होगी, जिन्होंने अभी अपना फरमान सुनाया ह कि राजा बहुत कम दी और इसलिये गलती की । तो। ऐसी सूरत मे तो हम तो यही कह सकते है कि ऐसी सरकार का खुदा हाफिज।

इसके बाद एक खास बात यह की जारही है और जो बहुत ही गलत है कि जहां पर ये सब तरीके अख्तयार किये जा रहे हैं वहां पर जैसा पहले भी जिन्न किया गया था, बहुत से लोग अपनी बन्दूक का लाइसेन्स रिन्यू कराना चाहते हैं। में दस पांच डिस्ट्विट्स में गया।

यह चीज १०-५ जिड़ों में जहां में गया था मेरे सामने आई कि जो लोग दस गुना लगान जरा कर देते हैं उनके लाइसेंस तो जल्द रिन्यू कर दिये जाते हैं और जो लोग दस गुना लगान जमा करने में असमर्थ होते हैं उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं किये जाते। एक सज्जन ने अपनी स्पोद में यह कहा था कि जो लोग बन्दू हों का दुरुत्योग करते हैं उनका लाइसेस हम रिन्यू नहीं करते।

पक सदस्य-इसो बिल का ताल्लुक नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री—अभी तक तो जो लोग बोल्ते रहे और सरकार के गुणों का बसान करते रहे कि रुपया वसूल हो रहा है। हमारी स्कीम इतनी बिद्ध्या है कि लोग दोड़े—दौड़े कर रुपया जमा करते हैं। तापको यह बात तो पसंद आ रही थी, लेकिन जब हमा यह बताना शुरू किया कि किन—किन हथकड़ों के साथ यह रुपया वसूल किया जा रहा है तो इससे बिल का कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बोज बहुत खतरनाक हो रही है कि जो कांग्रेस के पक्ष में हैं उनको तो आप हिथार दे रहे हैं और जो विरोध में हैं उनका हिथार छीनने है। जो बन्द कों का दुरुपयोग करते हैं उनको नहीं देते और जो सदुपयोग करते हैं उनको देते है। कांग्रेस की तरफ से जो बंदू कें इस्तेमाल होती है वह सदुपयोग में होती है और जो लोग विरोधी है वह दुरुपयोग करते हैं। मेरे पास ऐसी विद्ठ्यां आई है। अभी मेरे हाथ में एक चिद्ठिश शालक्ष्मी कांत बाराबंकी निवासी की है। इसके अतिरियत और भी कई चिद्ठियां आई है सब से अच्छा जिक्र किया गया है वह कांग्रेसी अखबार इसको कांग्रेसी नहीं कहना चाहिये क्यों कि अभी लोग एतराज कर देगें। 'हलवर्ल अखबार बरेली का है। उसके सम्पादक है श्री व जमोहन लाल शास्त्री, एम० एल० ए०। अगर में कहं कि ल इसे सकांग्रेस के लोगों को विये जाते हैं तब एतराज हो सकता है लेकिल बजमोहन लाल शास्त्री जो कि कांग्रेस के एम० एल० ए० हैं उनको तो अपनी गवर्गमें ह

श्री राजाराम जास्त्री

का बहुत ज्यादा रयाल है। वह अपने सम्वादकीय लेख में लिखते हैं कि हमें बड़े दुल के साथ लिलाना पडता है कि इस गुना लगान जमा करने में बरेली में अधिकारियों की और से वही पुराने नौकरशाही तरी हो का प्रयोग किया गया है जो तरीके बार फड बसल करने में इस्तेमाल किये जाते थे। हमारे पास काफी शिकायते इस बात की आई है कि जिन लोगो के पास बंदूको के लाइसेस है उनवी काफी परेशान किया गया। उनसे सोफ-मारु कहा गया कि याता दस गुना लगान जमा कराओ नहीं तो तुम्हारा लाइसेस पुनः जारी नहीं किया जायेगा । इस प्रकार की शिकायते हर जगह से हमारे प स आई है । यह शिकायत एक काग्रेसी एम० एल० ए० की तरफ से की गई है। उनकी पोजीशन यह है कि जब कभी में वजमोरन लाल शास्त्री जी काजित्र करता है तो इधर जो लोग बंठे हैं यह कहा करते हैं कि यह इधर बंठते तो ह ले किन ये आपके आदमी है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती ह कि कोई आदमी जो ईमानवार है वह उनकी तरफ का नहीं हो साता । वे कहते हैं पि हमारा नहीं ह । इस मनीवृत्ति के लिये में एक बात क्षाहना चाहता हू। वह जर्मनी के एक नाली लीकर का कार्रकान है जो मेरे पास है श्री गौबिल्स शहले है कि हम सब नाजियों को इस बात का विश्वास ह कि हम सही रास्ते पर है। हम किसी ऐसे आदमी को बरवाइत नहीं अर सकते जो कहता है कि वह सही रास्ते पर है। यव वह ठार तहता है तो नाजी है। यव वह नाजी नही है तो छेक नहीं काता।

ठीक बही पोतीशन आ५ कागेस की है। हर आदमी जो ईमानदार है वह काग्रेसी नहीं हैं ओर जो ठीक बात कहें वह कांगेपी नहीं हो सकता। या व्यू हमारे कागेस बाले लेते हैं। राजधादी पर बेंडे हुए अभी ४ रोज हुए है अगर इसी मनेवृत्ति का आपने प्रसार किया तो पना नहीं इस मृहक को आप कहां ले जायंगे।

इती तरह को मेरे पास शिकायनें तकाबी के सम्बन्ध में है। उस दिन हमारे माल मंत्री जी की तरफ से या दूसरें साहब की तरफ से तकाबी के सिलितिलें में जिक पिया गथा कि आप उदाहरण बतलाइयें। में आपके सामने यह एलेंगेशन्स रखता हूं अखबारों में बाते छपी हैं उनकी रिपोर्टम हमारे पास हैं।

माननीय माल स्मिय-प्याहें आफ आहंर सर । मेरे लियन दोस्त जमी-वारी एवालिशन फंड की बयुलयांकी के फिलिलें में जो ज्यादित्यों की जा रही हैं उनका जिक कल ने कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं अभी फिलनों देर करेंगे या मालूम नहीं । में यह कहना चाहता हूं कि जमींबारी एवालिशन फंड की यसूजयांकी का जो दूसरा एँउट हैं उसके मालहत होगी। इस बिल का यसूजयांकी से कोई सम्बन्ध नहीं है, इन भवन के सामने जमींबारी उन्मूलन आर भूगि व्यवस्था बिल पेश है न कि बार ऐक्ट जिलकों के से जमींबारी एवालिशन फंड बसूछ किया जा रहा है तो यह बहस कि यह ज्यादित्यों की जा रही है में तो समझता हूं कि यह जिल्कुल इरेलेंबेंट (असंगत) हैं। में हर बात का जबाब देने के लिये त्यार हूं और माका पड़ने पर जवाब बूंगा, लेकिन इप तरह की असंगत बात कहने की इजाजन रही तो इस भवन का बहुत ता अपूल्य समय खांब होगा। इसलिए जनाब की तवज्जह इस जानिब विलाना चाहता है।

श्री देशिन जमां श्रां—जनाबवाला, इस व्याइंट आफ आईर के बारे में में आएकी वह कॉलग यदि दिलाऊंगा जो मेंने सुनी श्री जिसके मुताल्लिक मेरा एक एडजनंमेंट मोशन था। यह बिल अने बाला है और इत सिल्सिले में यह बाते कही जा सकती है। मुमकिन है मैंने गलल सुना हो।

जहां तक जेडि ए एफ का साल्लुक है आप देखें कि इस बिल में वका १३५ से दका १४४ तक सिर्फ भूमिधर के बारे में जिन्द है और १० गुना लगान के बारे सन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ६३७

भें जिन्न हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि दका १३५ का हवाहा देकर इस बिल में शिंडचल २ के जरिये से इस कानून की तैयार किया जे रहा हे इसी के मानहत सरकार १० गुना लगान वसूल करेगी। शेड्यूल २ में लिखा है:——

"Amendment in the United Provinces Agricultura! Tenants (Acquisition of Privileges) Act, 1949"

[संयुक्त प्रान्तीय एग्रीकल्चरल टेनेट्स (विशेषाधिकार प्राप्ति) ऐक्ट १९४९

यह वहीं कानून है जिसके जिरये से १० गुना लगान वसूल किया जा रहा है। वह कानून इस बिल के जिरये से अमेंड किया जा रहा है। दकः १३५ से १४४ तक जमींदारी एवालिशन फंड १० गुना लगान वसूल करने के बारे में हैं। लिहाजा में नम्प्रतापूर्व क कहूँगा कि जो श्री राजाराम जी शस्त्री कह रहे हैं ठीक है। जब मेने तकरीर दी थी तो माननीय माल सचिव ने तकाबी के बारे में मिसाले मांगी थीं, श्री राजा राम जी जब उन मिसालों को बतला रहे हैं तो माननीय माल मंत्री क्यों घत्रराते हैं?

माननीय स्पीकर—इतने जोश में आप बोल गये और आक्ती आवाज इननी तेज हो गई कि साफ सुनाई नहीं पड़ा !

श्री रेश्चान जमां खां—-जनाबवाला, प्वाइंट आफ आर्डर के बारे में मुझे यह कहना है कि इस कानून की दका १३५ और शेड्यूल २ के जिरये से उस कानून को जिसका नाम यूनाइ?ड प्राविसेज एग्रीकत्वरल टेनॅं! एक्श्रीजीशन एंड प्रिविलेजेज ऐक्ट सन् १९४९ ई० है, तरमीम किया जा रहा है, इसी कानून के जिस्से से सरकार दा गुना लगान ले रही है। इस के अलावा उसके दका १४० से लेकर दका १४४ तक जमींदारी एबालिशन फंड और दस गुना लगान की वमूली के बारे में रखी गंगी है। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस और रीजन्स में भी यह कहा गया है कि हमारे मूबे के किसान स्वेच्छापूर्व के अपना दस गुना लगान जमा कर रहे हैं। लिहाजा इस बात का सीध संबंध है जमींदारी एबालिशन फंड से। चुनांवे जब में तकरीर कर रहा था और तकावी का मैंने जिक्र किया तो हमारे माननीय माल सचिव ने खुद ही मुझसे सवाल किया था, लेकिन मैंने नाम लेने से गुरेज किया था, लेकिन अब जब हमारे दोस्त शास्त्री जो इस सिलसिले में बता रहे हैं तो माननोय सचिव को बनाय घबड़ाने के खुश होना चाहिये कि उनके सवालात का जवाब दिया जा रहा है।

माननीय म्पाकर—जहां तक उस कानून का ताल्लुक है जो स्वोक र हो चुका है उसके ऊपर सवाल उठाने का अवसर नहीं है। इस बिल के बारे में जो विषय आप उठाएं उन पर में आप को कहने दूंगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा इस बात पर जोर देना कि उस विधान के अनुसार जो स्वीकृत हो चुका है क्या किया गया, मुनासिब न होगा। में आप को रोकना नहीं चाहता, इतना हो चाहता हूं कि आप इस बिल के बारे में जो इस समय पेश है या उसकी धाराओं के बारे में अपना विचार प्रगट करें।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय स्रीकर महोदय में इन बीजों का जिक सिर्फ इस लिये कर रहा था कि इस कानून के आखिर में उद्देश्य जो लिखा है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसानों से स्वेच्छा के साथ रूपा लिया जायगा और मैं यह साबित कर रहा हूं कि गवर्नमें इको इस सिल्लिले में दस बीस तरीके क्यों ईज इ करने पड़े है ? क्यों कि में यही समझता हूं कि कि जानों के पात रूपा नहीं है और गवर्नमें रूपया वसल करके साबित करना चाहती है कि उसको योजना अच्छी है, कानून अच्छा है और योजना में सफलता हो रही है। में उसको साबित करना चाहता है कि जिन तरीकों से रूपया खिच रहा है वह तरीके बहुत हो अल्जेक्शनेबल है। जो

श्रि राजाराम शास्त्री |

कानून बन नुका ग्रामपंचायत वगेरह का, इन सब चीजो मे कहा गया है कि प्रजातन्त्र होना चाहिये और इस कानून के जरिये सरकार किसानों का जीयन स्तर उठाना चाहती ह, किसानो में नबजीवन को संचार करना चाहती है, उस के व्यक्तित्व को बढाता चाहती है, तो मंयह पेश करना चाहता हू कि जिस उद्देश्य के लिये यह फानून बनाया गया है कि उन के रतर को ऊंचा करेगे, तो म यह कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप कर रहे है यह इस के उदेश्य के त्रिरोध में कर रहे हु। में कोशिश ती पूरी करूंगा कि मैं ज्यादा बात न करं, लेकिन फिर भी कुछ बातें जिन से इस बात का पता चलेगा कि कंगे स्वेच्छापूर्वकः, वसूठी की जा रही है, उस लालव को रोकता लेकिन कम जरूर करूगा। ता म तकाती के बारे में जहर हा। रहा था, रोपान लार म गुव उम बात की की निश करूंगा कि आप जिस के तारे में यह कह देशे कि हमारी तरफ से नहीं हुए उन्हीं के बारे में कहूगा। म यह कहना हूं कि हमारी सब बाता को गजन करने का केवल एक तरीका है अगर माल मंत्री की इस हाउस के सामने खड़े शेकर अपने जवाब म इस बात का ऐलान कर देगे कि यह बाने जो छोग कर रहे हैं उन्हें राजा जायगा तो मुझे संतीष हो जाएगा।

माननीय मात्र म सब-अाप बेटिए तो, भं जवाब देते वक्त कहूगा जो मुझे कहना है।

श्चा गुजा,गाम ज्ञास्त्र।-अ।प कहेगे भी तो। अगर कह दीजिए तो जिन लोगों की जान इस सुबे में खतरे में पड़ी हुई है उनकी जान तो बच जाय। आप यह ऐलान कीजिए कि इस तरह से पटवारी के जरिये से, अध्यापकों थे मातहत, इस तरह से तकावी का रुपया बस्त करके इस तरह से गन्ना सोमाइटियो के जरिये से तग करके दस गुना रुपया लेना नाजायज है और गर्ननेमेंट इन चीजों को पमन्व नहीं करती है। अंगर यह आप कह वेंगे तो फिरम आप है पास मकतमें भेजना शह कर देगा कि आपने हाउम के सामने यह ऐलान किया या और लीजिये यह फला आदमी के जाय ज्यादती की गई। इस तरह का ऐलान की जिए तो यू० पी० के रहन वालों को इसमें वुछ राहत तो मिलेगी। आअकल देखिए। आजफल जैसे गन्ना का जमाना है। किसान लाग अपना गक्षा पैवा करते ह कि वह अपना गक्ष। मिला में ले आकर बेचें और उसमें जो पसा मिरो उसके अरिये से अपना घर का कामराज पर। लेकिन आपने यह सोचा कि यही बक्त किया भाषा आपन शुरू से लेकर आधिर तक गांधी जी का नाम लिया, मिनिस्टर्श ने सबने पहिले १० गुना लगान अबा कर विया और भूमिधर बन गये, अख-बारों म फोटो नी राप गए, रोकिन जब इस तरह से भी रिपया बप्ल नहीं हुआ तब गवर्नमट ने सीचा कि इस मोके पर गन्ने की बिकी के पक्त में किसानों के पास पैसा आएगा। आपने यह एक नया तरीका निकाला है कि जहां-जहां गन्ने की सोशाइटियां है उनके जरियं मिल बालों में भिल करके अपने अफसरी को चिट्ठिया भेज करके यह नया तरीका निकाला गया है कि जिस बक्त किसान गन्ना लेकर जाता है तो जिन लोगों ने १० गुना रुपया जमा कर पिया है उनका गन्ना पहले ले लिया जाता है ओर जिन्होंने १० गुना लगान नहीं विया है उनकी नाना प्रकार से परेशान किया जाता है, उनकी कई-कई विन तक खड़ा रखा जाता है। इस तरह की चीजे की जा रही है। इस सम्बंध में हमारे पास को तीन पत्र है जिनमें यह साफ लिख। हुआ है कि जो लोग १० गुना लगान वे वेते हे उनका गन्ना पहले ले लिया जाता है और दूसरों को परेशान किया जाता है। अभी इस हाउस में आने से पहिले एक बिट्ठी मुझे बदायूं से मिली जिसमे यह साफ़ लिखा हुआ है कि जो लोग १० गुना लगान वे देते हैं उनको तो एक पर्जी वे वी जाती हैं उनका गन्ना पहले ले लिया जाता है उनको पेमेन्ट किया जाता है, पर जिन स्रोगों ने १० गुना स्रगान नहीं विया है उनको परेशान किया जाता है, उनको तंग किया जाता है और उनको कोई सहूलियत नहीं दी जाती। साथ ही साथ यह भा देखने को मिला कि जिन्होंने १० गुना लगान नहीं दिया है उनका गल्ला लेने के बाद उसकी पैमें मिलने चाहिये थे बजाय इसके कि पैसे मिले, ऐमें हथाई किये गये हैं कि उनको भूमि— धरी की पर्ची थमा दी जाती है। यह चीज ऐसी है जिसका दूर होना क इस मूबे के रहने वालों के लिये बहुत जरूरी समझता है। इस तरीके से एक आफन सी मची हुई हैं!

इसी तरीके से अभी एक खबर मुझे मिली थी जिसका मेने कल भी जिक्र किया था। अखबार का नाम सुनकर के इधर के लोग चौकन्ने हो उठते 🤈 कि साहब जो गन्ने की खेती करते हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी क्लिज को लिखी। में ट्रैन्त में हैं कि इधर कोई अलबार उनकी चिट्ठिया तक नहीं छापने को तंयार होते और वह चीज कभी ब्लिज में छपती है और कभी दूसरे जगहों में छपती है। उन्होंने यह लिखा है कि किम तरह से उन पर दबाव डाला जा रहा है और ऐसी कितनी ही नाजायज बाते की जा रही हैं जिससे आज वे परेशानी की हालत में पडते चले जा रहे है। यह ऐसा तरीका है जो बहुत नाजायज है और कहने में तो यह बात बहुत बुरी लगती है। कहने में बात बुरी लग सकती हैं और इसका सबूत भी मुझसे मांगा जाया तो मुक्किल हो सकती है। एक बहुत खतरनाक चीज यू० पी० में की जा रही । अगर पाल्क अपनी आवाज उठाये तो कैमे उठाये। अखबार ही वह जरिया हो सकता है और होता है जिसके द्वारा गवर्नमेन्ट अपना विचार रखती है आर पब्लिक भी अपना विचार प्रकट करती है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज यूर पीर के अख-बारो की आजादी कांग्रेस सरकार के हाथों में खतरे में पड़ी हुई है अरि इस चीज को दुनिया जानने न पावे कि सरकार क्या कर रही , इस वजह से बहुत मे ऐसे तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं कि जिनकी दजह से प्रेस को आजादी खतरे में । मेरा यह इल्जाम सरकार पर है कि यह सरकार नाना तरीकों से प्रेस को कंट्रोल करने की चेट्टा कर रही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों के हाथ मे इतनी ताकत दे दी टै कि उन ताक्तो की वजह मे जितने लोकल पेपर्स है उनको कंट्रोल करने की वे कोशिश करते हैं, जेसे विज्ञापन के जरिये से। इसका बहुत कडुआ तजुर्वा मुझे कानपुर में हुआ। जिस वक्त किमान मार्च हुआ वहां के डिस्टिक्ट मेजिस्ट्रेट ने समस्त अखबार वालों को बुला कर कह दिया कि देखो ५०० से ज्यादा न निकालो। आपको ताज्जुब होगा कि किसी कानपुर के अखबार ने ५०० से ५०२ नहीं लिखा। लेकिन जब इस चीज के सम्बन्ध में बहुत हाय तोबा मचाई गई तो नेशनल हेराल्ड में सही सही खबर छदी। नेशनल हेराल्ड का इस बात का खतरा मालूम हुआ कि अखबारों के एडवर्टाइजमेट एजेट डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ती बन कर काम करते हे तो उसने सही-सही खबर छाया। जब लखनऊ मे किसान मार्च हुआ तो यहां के डिस्ट्क्ट मैजिस्ट्रेट के पास इतनी हिम्मत न थी कि वह पार्यानयर और नेशनल हेराल्ड जैसे पत्रों से कुछ कह सकें और उन्होंने बड़ी आजादी के साथ मच्ची बात निकाली। यह हालत है। जैसा कि मुझे पता लगा है कि जिस निर्भीकता के माथ यह सब नेजनल हेराल्ड ने लिखा वह सरकार को पसन्द न आया। जिन्होंने बिल्टिज मे इस सम्बन्ध में लेख देखा है वे जान सकते है कि प्रेस को प्रभावित करने के लिये आज हमारी मरकार कितनी कोशिश कर रही है। कल मैने हाउस के सामने कहा था कि जिन अल्बारो को सम्मन दिये जाते है वह किस ख्याल से दिये जाते है । वह तो केवल उन्ही अवबारों को नहीं देना चाहिये जो कि गवर्नमेट की चापलुसी करे। उनके देने का उद्देश्य तो यह होता है कि पहिलक को जानकारी हो इसलिये कोई भी, जो भी उसकी राय हो हर स्वतंत्र पत्र को ऐसे विज्ञापन वगैरह गवर्नमेंट को देना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि जो कुछ थोडे अखबार गवर्नमेट की जी हुजूरी करते है उनकों तो दिया जाय और जो अपनी स्वतंत्र राय रखने हों उनको नहीं। श्री बुजमोहनलाल शास्त्री के अखबार 'हलचल' का जिक्र आया, जिसके लिये श्री चरण सिंह जी ने कहा कि तुम हमारी गवर्नमेट की आली-चना कैसे कर सकते हो। मेरा, स्पीकर महोदय, यह कहना है।

माननीय स्पीकर—आप जो ये बातें कर रहे हैं उनका इस विषय से क्या सं ध हैं? ये अनावश्यक हैं। दूसरे मौकों पर, या जब बजट पर बोलना हो, आप गवर्नमेंट की समालोचना कर सकते हैं। गवर्नमेन्ट की नेशनल हेराल्ड के सम्बन्ध में क्या नीति हैं आज वह आपकी बहस का विषय नहीं हो सकता। आप अपने विषय पर ही बोलें।

श्री राजः राम शास्त्री-बहुत अच्छा, इस चीज को मैं रोके देता हूं और दूसरी चीजें पेश करता हूं। वह दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि हमारे देहातों में जो नया प्रजातंत्रवादे कार्यम हुआ है, उसमें हमको गवर्नमेंट ने यह अधिकार दिया था कि गांव पंचायतों को चुने, उसमें वहां की जनता के प्रतिनिधियों की चुने और उसमें काम करने के लिये भेजें। इसलिये भेजें कि देहात की जनता के जो अधिकार हैं उनकी वे रक्षा करें। में आपके सामने एक नमूना पेदा करना चाहता हूं कि किस तरह से गवर्न-भेंट की तरफ से एक लिखा हुआ आईर हुआ है। कल हाउस के सामने यह बात पेश की गई कि गांव-सभा के जो समापति हैं, जो मेम्बर्स हैं, उनको इस बात का पूरा अधिकार है कि वे दस गुना लगान के संबंध में, पक्ष में या विपक्ष में, काम कर सकते हैं। में यह कहना चाहता हूं कि हाउस के सामने यह ऐलान किया गया है, लेकिन मेरे सामने एक औरीजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें गांव-सभा के मेम्बरों, गांव-सभा के सभापति, गांव-सभा के पंचों के नाम से सरपंच गांव की ओर से एक आर्डर जारी किया गया है कि सब को दस गुना लगान देना पहेंगा और १० गुना लगान न देने पर मोअत्तिल कर देने की धमकों दी गई है। जिला बोडों के अन्दर तो यहां तक नौबत आ गई है कि अगर कोई आदमी गवर्नमेंट के पक्ष का नहीं है तो उनको जिला बोडों की मिटिंग्स् में बुलाने की इजाजत नहीं दी जाती। यह चीज ऐसी है जिसके लिये कहा जा सकता है कि इसका बिल से क्या ताल्लुक है, लेकिन यह तो स्त्रिट या भावना पैदा की जा रही है। वह इसके विपरीत है और इन चीजों के रोकने की कोशिश करनी चाहिये। अब में आपके सामने कुछ डाक्यूमेन्ट पेश करना चाहता हूं। पंत जी ने भी कहा और इस बिल में भी कहा गया कि १० गुना लगा न दो या न दो यह आदमी की स्वेच्छा पर ही निर्भर है। हमारे पास पंचायत राज महाराजपुर के निरीक्षक के दस्तखती अदालत के पंचों और सरपंच थी चन्द्रपाल सिंह के नाम जो पर्चा गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अभी तक आपने १० गुना लगान जमा नहीं किया है। में माल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर रुपया देना न देना स्वैच्छा पर ही निर्मर है तो क्या किसी की यह अधिकार है कि वह किसी पंच या सरपंच का जबाब तलब कर सके। यह जवाब कित तरह तलब किया कि १० गुना क्यों नहीं विया। और अगर नहीं विया तो इस के संबंद में जब।ब तलब नहीं किया जा सकता।

एक सदस्य-इसकी वजह से कौन सी बफा नाजायज हो जाती है?

श्री र जाराम शास्त्री—कल श्री इन्द्रवेब जी त्रिपाटी ने समर्थन करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है लेकिन उन्होंके जिले गाजीपुर के जिला पंचायत अफसर प्रमुप्त के श्री त्रिवेणी पंडित को लिखते हैं कि आप १० गुना लगान जमा करने के विरोध में प्रचार करते हैं और अगर आपने ऐसा करना बन्द न किया तो आपका जवाब तलब किया जायगा। क्या यह इस बात का सबूत है कि १० गुना लगान जमा करना लोगों की स्वेच्छा पर निर्भर है। एक बात और है। जहां पर प्राम्प पंचायतों में कांग्रेस की मेजारिटी (बहुमत) है वहां कांग्रेस वाले यह कोविश करते हैं कि यह प्रस्ताब पास हो जाय कि १० गुना लगान जमा किया जाय। लेकिन जहां वे माइनिस्टी (अल्पमत) में हैं और इस प्रकार का प्रस्ताब करने की कोशिश की जाती है कि १० गुना लगान बिया जाय या पास हो जाता है तो जवाब तलब किया जाता है कि ऐसा क्यों किया गया। अगर लगान देने का प्रस्ताव पास नहीं हो सकता तो लगान वेने का प्रस्ताव पास करने की अनुमित कैसे वो जा सकती है। आप मो बीनों हाथों में लब्दू रखना चाहते हैं। यह तरीका बहुत हो गलत है। आप गांव सभाओं की क्या चाहते हैं, में पूछता हूं? क्या आप उनको सरकार की कठपुतली बनाना चाहते हैं?

र्लंग्हलापुर की गात्र-सभा के नाम नोटिस भेजवाया गया कि गाव-मभा ऐसा कोई प्रस्ताव पास न करे जिससे वर्तमान सरकार की जमीदारी उन्मूलन नीति का विशेष हो।

यह चीज तो वहा पर भेजवार्ड गई है। उससे भी बेजा बात आप देखिए कि हमारे बहुत से मत्री जी और बहुत से पालियामेटरी सेन्नेटरी वगैरा आजकल दोरा करते फिरते ह। मुक्किल यह है कि किसान जाल में फलसते नहीं ह। जहां मीटिंग होती है बहुत कम तादाद में आदमी इकट्टा होते ह और जब आदमी कम तादाद में इकट्ठा होते ह तब गाव पचायत के सरपच को बुला करके कहा जाना है कि क्या वजह है कि आदनी कम इकट्ठ हुए ह ? इस किस्म का हमारे मामने एक उदाहरण पेश है। बडहालोक मे २३ नवम्बर को श्री चरण सिंह सभा करने गये थे। वहा मुश्किल से १५ २० आदमी इकट्ठा हुए। इस पर आपने वहा के गाव-मभा के समापति को बुलाया ओर उससे यह पूछा कि इतने कम आदमी क्यो इकट्ठा हुए ह। उसने यह कहा कि हुजूर में क्या करूं। उसके बाद उससे जवाब तलब होता है, जरा देखिए। "जमीदारीं उन्मूलन की मीटिंग के समय २३ तारीख को आप अपनी अनुपस्थिति का कारण शीघ बताने की कृपा करे। वह कारण क्यों बतलायें, क्यों कि वह शासकीय कर्मचारी है। माननीय स्पीकर महोदय, म आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो गवर्नमेट के शासकीय कर्म-चारी हं उनके साथ भी गवर्नमेंट को सख्ती नहीं करना चाहिये, लेकिन अगर गवर्नमेन्ट उनके साथ सख्ती करे तो बात कुछ समझ में आ सकती है लेकिन बड़ा भारी सवाल यह आ गया है कि ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच क्या गवर्नमेन्ट के एम्प्लाइज (नोकर) है जिनको ऐसा हुक्स दिया जाता है। मै समझता हूं कि ग्राम-सभा के पंच या सरपंच सरकार के एम्प्लाइज नहीं है। वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, इस लिये उनकी सब से पहिली वफादारी उनके प्रति है जिन्होंने उनको चुना है। अगर आपने इस तरीके को अख्तियार किया तो बड़ी मुसीबत हो जायगी क्योंकि इसी तरह नम्बर धीरे-धीरे म्युनिसिपैलिटी का आ जायेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आ जायेगा और असेम्बली का आ जाएगा. और कल से हमको मजबूर किया जायेगा कि जब माल मंत्री जी आये तो सब एल० ए० को हाजिर रहेना पड़ेगा। अगर कोई एम० एल० ए० हाजिर नहीं रहेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आम पंचायतों के चुने हुए लोगों को आप कैसे मजबूर कर सकते हैं। अगर वह हाजिर नहीं होते हैं तो आप उनकों कैसे निकाल कर बाहरे कर सकते हैं। यह आपका तरीका बहुत ही खतरनाक है। बात यह है कि आप नये-नये शासक बने है, कभी राज्य जिन्दगी मे किया नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि चाहे कोई चुना हुआ प्रतिनिधि हो या और कोई हो लेकिन उसे आपका हक्म मानना पडेगा।

एक सदस्य—आप तो ग्राम पंचायत के खिलाफ है।

श्री गाजागम शास्त्री—जरा अकल की बिलहारी देखिए। में तो कह रहा हूं कि जनता के प्रतिनिधि सरकार के नौकर नहीं हो सकते, लेकिन आप कर रहे हैं कि हम प्राम पंचा—यत के खिलाफ हैं। हम प्राम पंचायत के खिलाफ नहीं है बिल्क उनके अधिकारों को जो आप छीन रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाने हैं। आपको जी हुजूरी अगर करना है तो कीजिए। हम अपने अधिकारों के लिये नो लड़ेंगे ही। अभी तक तो सरपंच, पंच और ग्राम—सभा के सभापित को ही आज्ञा दी जाती थी लेकिन एक बात में आपको और बतलाऊं जो मेरी समझ में नहीं आती हैं। तहसील इटावा, जिला इटावा के पंचायत राज इंस्पेक्टर ने बसरेहरा की ग्राम पंचायत के एक मेम्बर के नाम नोटिस जारी कर दिया है। उनका दस्तखत है और जिस पर लिखा हुआ है बुढूलाल सदस्य, ग्राम सभा बसरेहर उनके नाम से नोटिस जारी की गई है कि आप सरकारी योजना को असफल सिद्ध

[श्री राजाराम शास्त्री]

करने की कोशिश करते हैं इसलिये आप से जवाब तलब किया जाता है, क्योंकि आप सरकारी व्यक्ति हैं। यदि किसी ग्राम-सभा का मेम्बर सरकार का नौकर हो गया, यह अवल मेरी समझ में तो नहीं आती, हां धुलेकर साहब की समझ में यह बात आ रही है। वे समझते हैं कि चाहे कोई भी बात हो हमारा राज्य है। चाहे ग्राम-सभा के मेम्बर हो, ग्राम-सभा के पंच हों, ग्राम-सभा के सरपंच हों यानी जो भी हमारे राज्य में बसने वाले है वे सभी हमारे गुलाम है। यह चीज, यह फिलासफी आप हमारे सामने लगाना चाहते हैं, जिस तरह की फिलासफी को हम यहां पर चलने नहीं देंगे। और इधर के बैठने वाले एम० एल० एज० को हम समझाना चाहते हैं कि यह गवर्नमेंट स्याह या सफेद जो भी करे उसका इसलिये समर्थन न कीजिए कि वह आपकी गवर्नमेन्ट है। आप जनता के प्रतिनिधि है। जनता ने आपको चुन कर यहां पर भेजा है और जनता के अधिकारों की रक्षा करना आपका काम है। यह न कि यहां पर बैठ कर आप हर गलत काम में सरकार हिमायत करना अपना फर्ज समझे। सिर्फ इतना ही नहीं और सुनिए। अगर किसी जगह पर किन्हीं वजहों से गल्ला बसूली कम हुई है या दस गुना लगान की वसूली कम हुई ह तो उस गांव-सभा के मेग्बर पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि तुमने इसमें सरकार का साथ क्यों नहीं दिया ? तुम फलां मिनिस्टर साहब की मीटिंग में क्यों नहीं आए ? तुमने दस गुना लगान वसूली के खिलाफ प्रचार क्यों किया ? यही तक नहीं, बढ़ते-बद्दते हाथ यहां तक बढ़ गया है कि अगर किसी गांध में दस गुना लगान की वसूली नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी वहां के सभापति के ऊपर, वहां की ग्राम पंचायत के पंचों के ऊपर वी गई हैं और उन पर इल्जाम लगाया गया है कि इसके दुष्परिणामस्वरूप बहुत कम उक्त कोव आपके क्षेत्र में जमा हुआ है, इसलिये आप कारण बतलावें कि आपके खिलाफ कार्यवाही क्यों न की जावे ? आज ताकत आपके हाथ में है, जितनी चाहिये कार्यवाही कर लोजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है, और न रोकने से आप रुक ही सकते हैं। लेकिन समझ लीजिये कि आपके ये हयकंडे अधिक दिन तक नहीं चल सकते। आखिर कोई भी ताकत हो कहां तक इस तरह से चल सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति सोशिलस्ट पार्टी की मीटिंग में जावे, सोशिलस्ट पार्टी के जलूस में जावे और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गवर्नमेन्ट के पास रिपोर्ट भेज वे कि फला दाखस, फला मेम्बर, सोद्यालिस्ट पार्टी के जूलूत में चला गया था तो हम देखते हैं कि देहाती आफिसर के पास यह चिट्ठी पहुंचती है और जवाब तलब किया जाता है। विधुना के रामपाल जी, पंचायत राज के इंस्पेक्टर ग्राम पंचायत के प्रधान को लिखते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि क्या आपने सोशिलिस्ट पार्टी की रेली के समय लखनऊ नहीं गये ये? क्या आपने जेड० ए० एक० प्रस्ताव की पंचायत में रखने से इंकार नहीं किया था? माननीय स्पीकर महोदय, में आपको बतलाना चाहता हूं कि इन चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये और इन बातों की तरफ में आपका ध्यान विलाना चाहता हूं कि किन-किन तरीकों से सरकार जनता के अधिकारों को, जनता के जो चुने हुए पंच है, उनके अधिकारों को छीनती जा रही है। यह सरकार के लिये एक खतरनाक चीज है। जिस स्विरिट (भावना) से इस प्रस्ताव को पास करके इसे लागू करने की कोशिश को जा रही है कि जनता के अधिकारों का कुछ भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। आप उनके अधिकारों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी यह जम्हूरियत (प्रजातन्त्र) है, आपका यह प्रजातन्त्र है कि कोई आपकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकता है, कोई बिरोधी दल की मीटिंग में नहीं जा सकता है, कोई आवका विरोध नहीं कर सकता है तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि किस तरह की आपकी यह जम्हूरियत है। कोई जम्हूरियत इस तरह से हिन्दुस्तान में नहीं पनप सकती।

(इस समय १ वर्षे भवन स्वगित हुआ और २ वर्जे थी नकीसुलहसन, डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय डिप्टो स्पोकर महोदय! मै इस बात का जिन्न कर ·रहा था कि गवर्नमेट किन–किन तरीक़ों से इस १० ग**ना लगान के सम्बन्ध मे किसानों पर** ज्या-दितियां करती है। मैं उन सारी बातों का जित्र करना नहीं चाहता हूं, केवल आखिर में एक बात और कहूंगा और वह यह है कि जब यह तक्षावी, गन्ना, बन्द्रकों का लाइसेस, मारपीट, अखबारों में प्रोपेगेडा जब यह सब चीजे असफल हुईं तो एक सबसे दिलचस्प और अनोखा तरोका ओर अब्तियार किया गया है ओर वह यह है कि हमारे देश के किसान सीव-सादे और भोलेभाले होते हैं। उनके अन्दर धार्मिकता होती है और इस जवर्नमेंट की तरफ से या हमारे कुछ मेम्बरान को तरफ से किसानों के लिये इत धार्मिकता को भी भूमिधर बनाने ओर न बनाने के लिये इस्तेमाल किया गया। अभी कुछ रोज पहिले मैंने अखबारों में यह जब पढ़ा कि एक बस्ती के असेम्बली के मेम्बर इसलिये वहां से पदच्युत किये गय कि उन्होंने चुनाव के मोक़े पर अनुचित रीति से वोट प्राप्त करने की की शिश की और अभी कुछ दिन पहिले हमारे माननीय पन्त जो ने अपनी स्पीच में कई जगह पर यह कहा था ओर मैन पढ़ा था कि आज हमने सुबे के किसानों के लिये, उनकी भलाई के लिये यह क़ानून पेश किया है। बहुत से लीग इसका विरोध करते हैं ओर जो लोग गवर्नमेट की आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, वे भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम करते है। हमारी समझ मे यह बात न आ सकी कि गवर्नमेंट की आलोबना भारतीय संस्कृति के बिलाफ कैसे हुई। भारतीय संस्कृति को अगर में समझ सका ओर हमारे देश समझ सका ओर हमारे देश की यही संस्कृति रही है कि जब कभी शासक को तरफ से कोई ग़लत काम हो तो प्रजा का यह पूरा अधिकार रहा कि वह उसकी आलोचना करे। प्रजा के लाभ के लिये ही गवर्नमेट ने ओर राजा ने आलोचना पर सदा ध्यान हमारी रामायण में एक कथा इसी सम्बन्ध की आती है कि एक मामूली धोबी के आलोचना करने पर रामचन्द्र जी ने कितना बड़ा क़दम उठाया था। हमारे देश के अन्दर यह उदाहरण मौजूद है। प्रजा को इस बात का अधिकार रहा है कि यदि राजा ग़लत काम करता है तो उसको अपने अधिकार से वह उसके सामने रख दें। आज हमारी असेम्बली के बनाये हुए क्रायदों और क्रानून की १० गुना लगान की वसूली के सम्बन्ध में सरकारी अफसर कोई परवाह नहीं करते हैं और हमारे कांग्रेसी भाई इस तरह का सिद्धान्त जिलों में प्रचार करने के लिये अख्तियार करते हैं। हमारे एक मेम्बर तो इससे भी आगे बढ़े गये और कुछ अजीब तरीक़े १० गुपा लगान वसूल करने के सिलसिले में उन्होंने अख्तियार किये। वह यह है कि अभी मुझे यह पढ़ने को मिला कि बनारस में क्या तरीका अस्तियार किया गया ? अभी कल हमारे माननीय सदस्य कमलापित त्रिपाठी जी ने बडे जोर के साथ मुस्लिम लीग की कट्टरता की और समाजवाद को काफ़ी टोका-टिप्पणी की । कल अखबार में जो पढ़ने को मिला उससे मालुम हुआ कि जिस तहसील के आप खुद जमींदार है उसमें एक महायज्ञ किया गया और यज्ञ इसलिये किया गया कि वह भी किसानों के फायदे की चीज थी। इसलिये नहीं कि कोई वहां पर पर्व हो या कोई दान-पुष्य का काम किया जा रहा हो या जिससे परमात्मा बहुत खुश हो जायं। इस भावना से फायदा उठाने के लिये चन्दौसी तहसील के अन्दर जहां कि कमलापति जी खुद जमींदार हैं वहां पर एक सप्ताह तक यज्ञ कराया गया। यह बात नहीं कि हिन्दुओं के लिये ही उनको प्रभावित करने के लिये कराया गया हो बल्कि वहां पर निलाद शरीफ भी कराया गया ओर गवर्तमेंट की इमारत के अन्दर ही यह सब चीजें कराई गयीं। वहां पर पर्चे बांटे गये। उन पर्ची के अन्दर यह चीज कही गई थी कि यह यज्ञ शान्ति स्थापना के लिये और किसानों की भलाई के लिये किया जा रहा है और किसानों से अपील की गई थी कि इस यज्ञ में भाग लेकर अपने जीवन और अपनी आत्मा को पंवित्र बनायें ओर भूतिवर अधिकार को प्राप्त करके अपनी सन्तान को भविष्य के लिये निश्विन्त करें, भगवान् का अशोर्दाद प्राप्त करें, जित्रका अर्थ होगा कि जन्म-मरण के भिन्न-भिन्न कध्टों से मुक्ति प्रान्त करना। उसके नीचे जिला था इति शुभम्। जब यह तरीक़े किये गये, जब इस तरह की गवर्न मेंट कोशिश कर रही है। भगवान को किसानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है और किर किसानों से कहा जाता है कि तुम १० गुना लगान दो । मेरे कहने को मतलब यह है कि गवर्नमेंट जितने तरीक़े अख्तियार कर रही है इन तरीक़ों के बावजूद भी क्या आपको इस बात को सफलता िली कि जितना गवर्नमेंट को उम्मीद थी और [श्री राजाराम शास्त्री]

सरकार गयाल करती थी। गवर्नमेट ने यह ऐलान किया था कि हम तीन महीने के अन्दर १८० करोड़ रुपये बसूल कर लेगे। सरकार का यह विश्वास था कि काग्रेस का शतना असर है कि वह १८० करोड़ रुपया जल्दी ही बसूल कर लेगो।

अब आप ३ महीने की की शिश के बाद यह देख रहे ह कि आप के खजाने में कुल रपया अब तक १२ करोड़ जमा हुआ हे ओर अगर यही रपतार रही तो इस १८० करोड़ की यसूली में आप खद समझ सकते हे कि कितना जमाना लग जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के दिमाग में यह बात के से आई कि सूबे के किसान के घर में रुपया भर गया है। आप जब तक राजगही पर नहीं बंठे थे तब तक तो आप भी यही समझते थे कि किसान गरीब हु और उन के पास पंसा नहीं है लेकिन न माल्म अब किस तरीके में आप की सरकार को इलहाम हुआ या क्या हआ कि आप समझने लगे कि अब किसान के पाम रुपया हो गया है। अभी दशहरे के मोके पर श्री राजगीपालाचारी गवर्नर जनरल नं ऐलान किया था कि हिन्दुस्तान की दौलत लड़ाई के जमाने में किसान और मजदूरों के पास इकट्ठी हो गई है। म तो समझता था लड़ाई के जमाने में किसान और मजदूरों के पास इकट्ठी हो गई है। म तो समझता था लड़ाई के जमाने में आर उस के बाद अब तक सारी हिन्दुस्तान की दौलत ब्लेकमार्केट करने वालों के पास और प्जीपतियों के पास पहुंच गई है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आप समझते हैं कि हिन्दुस्तान की दौलत किसान के पास आ गई ह ।

पन्त जी ने भी अपनी कानपुर की स्पीचों में यही कहा हं कि किनानों के पास नोट भरे पड़े हं और अगर वह चाहे तो अपने छम्पर नोटों से छा सकते हैं और अपनी दूसरी स्पीच में उन्होंने कहा कि किसानों के पास इतने नोट हैं कि उनकी चूहे कुतर रहे हैं। श्री चरण सिह जी ने भी अपने एक ऑटिकिल में अयं—शास्त्र का निचोंड़ रख दिया हैं और आप ने कहा कि सूबे के देहातों में सीना—चांदी भरा पड़ा है। जब अधिकारियों के विमाग में यह चीज आ गई तब ही यह चीज झुक की गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बात नहीं है कि समाजवादियों के प्रचार का यह नतीजा है कि यह दस गुना लगान की वसूली नहीं हो रही हैं बिन्क आप को इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि किसानों के पास जितनों रकम धन-दौलत और सोना—चांदी आप समझते ह बार नव में वह उनके पास नहीं है। अगर आप की समझ में यह चीज अब भी आ जाय तो सूबे में जो तूफान आपने मचा रखा है वह बहुत कुछ खन्म हो सकता है और किर आप कोई दूसरा तरीका सोच सकते हैं कि जिससे आप को योजना भी सफल हो ओर सूबे का किसान भी सुल से रह सके।

एक मद्रम्य--आप तो समझते होंगे कि सोशलिस्ट प्रोपेगेका सफल हो रहा है?

श्री राजायाम शास्त्री—में समझता हूं और आप को बतलाना चाहता हूं कि सोशलिस्ट श्रीपेनेंडा की गंजायश भी इसीलिए हैं कि किसानों की गरीबी इतनी हैं कि उसके पास रुपया वेने के लिए नहीं हैं और इसीलिए आप को बसूली नहीं हो रही है। हां हम प्रोपेगेन्डा करते हैं और आप से भी कहते हूं कि उसके सिर पर वस गुना लगान का बोझ बालना मुनातिब नहीं हैं और आपने जुद पहिले इस बात को माना है कि उस के पास रुपया नहीं हैं और आप ने अपनी रिपोर्ट में भी यही बीख स्वीकार की है कि उसके पास रुपया वेने को नहीं है। बहुत से लोग ऐसे आर्गूमेंड पेश करते हैं कि लड़ाई के जमाने में चीजों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई और उससे किसानों की फायवा हुआ और उसी की बुनियाद में आप यह चीज करते हैं कि किसानों से रुपया बसूल किया जाय। मेरा कहने का मतलब यह है कि रिपोर्ट के प्रकाशित होते बक्त और आज की स्थिति में ऐसा कीन सा फर्क हो गया है कि जिस से आप की वह पहिली राय बवल गई। इस रिपोर्ट में आप आर्ग्नेंड का जवाब देते हुए अन्त में कहते हैं कि :—

The United Provinces Government report on marketing of wheat reveals that about 40 per cent of the cultivating policities a velocity product at least 33 per cent, have to part with practically all their wheat is powers of

their charges. It is only 27 per cent. of the cultivative population which may be presumed to be in a position to with hold the disposa of the surplus.

(उतर प्रदेशीय गेहूं मार्केटिंग को रिपोर्ट े विदित होता है कि ४० प्रतिइत में अधिक किसानों के पास बेचने के लिए गेहूं विस्कृल नहां है। इंग ६० प्रतिज्ञत में कम में कम ३३ प्रतिशत को अपने खर्च के लिए समस्त गेहूं बेचना पड़ना है। केवल २० प्रतिज्ञन किमान ऐसे है जो, अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त गेहूं को, बेचने से रोक सकते ह।)

उनके पास कुछ हो तो बचा मकें। ६० फ़ीसबी में ३३ इस तरह के आदमी ह जिनके पास अपने रोजमर्रा का खर्चा है, लेकिन कुछ बचता नहीं। ६० में २७ परमेट इन तरह के आदमी हैं जिनके पास फ़ल्ला बचता हें और जिसे वे मार्केट में बेच सकते हैं। इसके मानी यह कि लड़ाई से २७ फ़ीसबी आदियों ने फायदा उठाया है। अब मुनाफ़ा कमाने के लिये ६० में से २७ आदमी निकलते हैं। ७३ फ़ीसदी रिपोर्ट में मानते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि अब आप क्यों इस बात को स्वीकार करने लगे हे। बहुत दिन के बाद समझ आई है। "नेशनल हेराल्ड" में राम गोपाल का एक आर्टिकल निकला है जिसमें उन्होंने आज की करेन्सी और दूसरी चीजों को डिस्कस करने के बाद यह नतीजा निकाला हैं:——

Therefore even if the average cultivator wants to purchase the bhumidhari rights his poverty damps his enthusiasm. It is not the Socialish propaganda which is responsible for slowing the pace of collection. The villager still feels with the Congress and Pandit Nehru but he is helpless.

(अतः साधारण किसान भी भूमिधरी अधिकार प्राप्त करना चाहता है, किन्तु उसकी निर्धनता उसके उत्साह में बाधा डालती है। यह समाजवादियों का प्रचार नहीं है जो अर्थ संग्रह को रोक रहा है। ग्रामीण के हृदय में कांग्रेस तथा पं० नेहरू के लिए स्थान है किन्तु वह असहाय है।)

सच बात तो यह है कि जो इस आर्टिकल में कही गई है। बहुत लम्बा चौड़ा आर्टिकल लिखकर खासतौर पर श्री चरण सिंह की बात का जवाब देने के बाद यह नतीजा निकाला है और अस्ली बात तो यह है कि किसान आज कल मजबूर है। उसके पास पैसा नहीं है। वह पैसा बचा नहीं पाता और सरकार इस बात को स्वीकार ओर महसूस कर सके तब वास्तव में वह अस्ली रास्ते पर आ सकती है। नहीं तो यह मालूम पड़ता है कि जैसा डाक्टर लोहिया और आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने कहा है कि हमारी सरकार की मोजूदा स्कीम का कहीं वही हसू न हीं जैसा मुहम्मद तुगलक का नयो राजधानी बसाने की स्कीम का हुआ था। उसके दिल में यह बात आई कि दोलताबाद ने नयी राजयानी बसायी जाय। उस का तरीका यह निकाला कि सारी आबादी को हुक्म दे दिया कि दौलताबाद पहुंचा जाये। रास्ते में बहुत से लोग मर गए। किर जब लोग वहां पहुंच गए तो उनको हुक्म दिया कि दिल्ली वायस जाओ। रास्ते में बहुत लोग मर गए। हमारी सरकार की भी यही पालिसी है। किसान के पास रुपया नहीं है। आप कहते है कि देसगुना लगान दो। वसूल करने में दिक्क़ते है। स्कीम चीपट हो रही है। सरकार का लाखों करोड़ों रुपया बरबाद हो जायगा। स्कीम में विश्वास नहीं होता है। इधर सरकार सख्ती कर रही है। अध्यापकों और पटवारियों को दबा रही देहात में आंतक सा फैल गया है। वास्तव में जबरदस्ती का यह नतीजा हुआ है कि किसान घंब गरहा है। दुनिया के जितने तरीक़े रुपया वसूल करने के हो सकते हैं उन सब तरीक़ों से आप रुपया खोंचने की कोशिश करते हैं। अब यह प्रचार किया जाता है कि स्था आ रहा है। किसानों ने देना शुरू किया है। वे अब भूमिधरों के फायदों को समझे पाये है। वे आ आकर रुपया दे रहे हैं। वया यह सन्तोष की बात है कि १८० करोड़ में १२,१३ करोड़ रुपया आप वसूल कर पाये हैं। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। इतना जरूर हुआ के सरकार को यह मालूम हो गया कि १८० करोड़ स्पया किस तरीक़ से जमा हो सकेंग। । चरणसिंह साहब

श्री राजाराम शास्त्री

की स्पीच हुई। विश्वम्भर दयाल साहब की स्पीच हुई। माल मन्त्री जी और हमारे पन्त जी ने जो स्पीवें दी हैं उसमें यह कहा है कि जमींदारों के खातिमें का वस गुना लगान से कोई ताल्लुक़ नहीं हैं। दसगुना लगान वसूल हो या न हो जनींदारी खत्म होगी। मैं खयाल करता हूं कि सरकार समझ गयी है और किसान ने उनको बतलाया है कि दसगुने लगान को छोड़िए और अब जनींदारी खत्म को जाय। आप दसगुने लगान से हाथ धोड़ए। मैं आज्ञा करता हूं कि सरकार अपनी गलती को स्वीकार कर लेगी।

एक बात में और कहना चाहता हूं कि इस बिल के अन्दर, कोई चाहे जितना ही गरीब किसान क्यों न हो, आपने कोई ऐसी राहत की बात नहीं की जिससे कि उसके दिल में कोई ख़ास उल्लास पैदा हो जाय। कांग्रेस के राज्य में जो अलाभकारी जोतें हैं, जिल किसी किसान के पास एक एकड, किसी के पास एक एकड से भी कन, थोड़ी छोटो जमीने हैं और जिनको गवर्नमेंट ने अवनी रिपोर्ट में माना है और उसने यह भी गाना है कि इतनी छोटी जोतों पर जो काम करने वाले किसान है उनकी दशा वास्तव में बड़ी खराब है और किसी तरह से जिन्दा है, तो इसकी आपको नानना चाहिये कि ऐसे लोग जिनके पास इस तरह की छोटी-छोटी खेती है, जिन पर गजर नहीं चलता, किसान गरीब है उनके लिये हक़्मत यह कह देती कि हम उनके लगान को माफ़ लेकिन जिस बक्त मेंने इस रिपोर्ट को पढ़ा तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं पाई। तक आप लगान में किसी तरह की रिआयत नहीं करते तो में समझता है कि यह तो किसानों की रीढ़ तोड़ देना है। मैं कल रियोर्ट को देख रहा था और उसमें कोई भी मुझे ऐसी चीज नजर नहीं आई। क्या वजह है कि जो गरीब किसान है, जिनके पास कमती चीज है उनका लगान आप माफ़ नहीं करते। जब मैंने इस बात को रिपोर्ट में पढ़ा तो उनके तकों को सुन कर बहुत ही ज्यादा ताज्जुब हुआ। एक जगह पर रिपोर्ट में यह चीज आई ह कि हमारे देश की यहीं परम्परा रही है कि हर तरह की जितनी होत्डिंग (जीतें) है उन्हीं से लगान बसूल होता रहा है। कभी एक्जेम्बन की नीति हमारे देश में नहीं रही। हमारी तिर्फ़ यही आपसे वरख्वास्त है कि अगर हमारे देश को यही परम्परा आज तक रही है कि हर तरह की होल्डिज से रुपया बसुल किया जाय, किसी की माफ़ी न की जाय, और उसी परम्परा पर आप चलें तो यह तो कोई मुना तिब बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जबसे अपना मुल्क आजाद हुआ, अपने बेश की हुत्रुमत क्रायम हुई अगर आप मुनासिब समझते हों कि जिन किसानों पर इतना बोझा लदा हुआ है कि जिनका अतितस्व ही जतरे में है तो ऐसे मौक्रे पर अगर आप यही नीति कर दें कि जिनके पास ऐसी होल्डिंग्ज (जोतें) है हम उनका लगान माफ़ करते हैं, कोई इस तरह का अगर आप एलान करवें तो हमारा ख्याल है कि तो कुछ उनकी पता हो सकता या कि देश स्वतंत्र हआ है। इसरो चीज यह है कि आज आप जितनी मालगुजारी लेते हैं, हम देखते हैं कि जो लोग दस गुना लगान नहीं दे पार्येंगे, जो सरीब हैं उनसे आप उतना ही लगान भविष्य में भी लेते रहेंगे। हमतो तमाम बिल पर बहस करने के बाव इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो किसान जितना ही अधिक ग्ररीय है उसको कोई राहत नहीं वी गई है। अगर वह इस मौक पर आपको वस गुना पैसा नहीं वे पाता है तो जरा सोबिये कि उसकी माली हालत कैसी है। इतना कर बिया है तो आप उसको इस बिल में कौनसी चीज दे रहे हैं? आप कोई अधिकार उसको भूनिधर को तो वेते नहीं ? जमीन का बटवारा फिर से आप करते नहीं ? लगान में कोई कमी करने को आप तं यार नहीं है तो फिर उसके दिल में यह कैसे खवाल पैदा हो सकता है कि जानीबारी का खारमा हो रहा है। बास्तव में आपको इन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये और ऐसे लोगों के सम्बन्ध में भी कोई न कोई एलान आपकी तरह से होना चाहिये।

हमने यह भी वेका कि जहां तक स्नेतिहर मजबूर का सवाल है। वह बेबारा पिस रहा है। आपने इस बिल में कहा है। कि बड़े-बड़े अफसरों क्रमींबारों के लिये फलां चीज है, सीरवारों के लिये कलां चीज है, लेकिन को आदमी इस तरह के हैं कि जिनके पास कोई क्रमीन नहीं है, वे किसी तरीक़ें

से देहात में नौकरी पेशा हैं और काम करते हैं ओर वे जर्नीदारों के यहां एक तरह से गलाम हैं। उनके लिये आपने क्या रखा है ? यह भी तो जरा वनलाइये। सच पुछिये तो इस सामन्तशाही की सबसे बड़ी ज्यादती उन्हीं पर है। यही लोग जनींदारों के यहां जा-जा कर नौकरी करते हैं। उनके एास आज तक पही तरीका था कि जनींदार उनकी कुछ जमीन का टुकड़ा दे देता था और कहता था कि हमारे यहां नौकरी कर लो और इसके बदले मे तुम इस टुकड़े पर जिन्दगी बसर कर सकते हो। अब आप जर: सोचिये कि ऐसे लोगों के लिये, इस क्रानुन के बन जाने के बाद, वह चीज भी खत्म हो गई ओर वह जमीन का ट्रुड़ा भी उनसे छिन गेया। सही माने में यह होगा कि जैमा पंजीवाद चाहता है कि सर्वहारा पैदा हो, वही बात हो जायेगी । के पास कोई जमीन या जायदाद नहीं रह जावेगी, न किसी के पास पंसा ही रह जावेगा और न रती भर जमीन ही। इसी तरह से जो देहान में मजदूर है उनके पास कोई जमीन नहीं है। सच मानिये, आप कि उनके पास कोई चीज नहीं रहेगी। उनकी तादाद भी कितनी होगी? रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि कितने आदमी ऐसे होंगे। सारे हिन्दुस्तान मे खेतिहर मजदूरों को संख्या काफ़ी है और बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस बात का अन्दाजा लगाया है कि इस वक्त हिन्दुस्तान में कुछ नहीं तो कम से कम ६, ७ करोड़ की तादाद में खेतिहर मजदूरों की हमारे प्राविन्स में भी कुछ नहीं तो ७०.८० लाख के क़रीब इनकी संख्या होगी। कल में एक किताब पढ़ रहा था, उसमें तो अन्दाजा १ करोड़ के करीब का लगाया गया था। लेकिन इसी के लगभग ऐसे लोगों की तादाद आंकी जा सकती है। मेरे पास कोई आंकडे नहीं है लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि इस सूबे में खेतिहर मजदूरों को एक बड़ी तादाद है। यह तादाद कोई ऐसी छोटी नहीं है जिसकी आसानी से उपेक्षा की जा सके। वे छोटे-छोटे लोग हैं, मजदूर पेशा है और बहुत ही ग़रीब है। इस क़ानून के अन्दर उनके सम्बन्ध में कोई भी बात इसे हाउस के सामने ऐसी पेश नहीं की गई है जिससे यह समझा जा लके कि इस जमींदारी के खात्मे पर उनका भी कुछ फ़ायदा हो सकता है । 🛮 इस क़ानन के पास हो जाने के बाद आप देख लेंगे कि जमीन का बटवारा तो आप करेंगे नहीं, तो इस लैडलेस लेबर (भूमिहीन मजदूर) के अन्दर एक बड़ी ही अशान्ति पैदा हो जावेगी। इन लोगों को जमीन पाने का कोई मौक़ा तब नहीं रह जायगा और ये किसी भी हालत में शान्त नहीं रह सकते। आपकी भूमिन्यवस्था से इन लोगों की जिन्दगी का मसला हल नहीं हो सकता है और इन लोगों को कोई शान्त नहीं कर सकेगा।

इस हाउस में बैठने वाले हमारे कुछ परिगणित जातियों के सदस्यों ने, हमें इस बात को जान कर खुशी हुई, अपनी तरफ से एक नोट आफ डिसेंट (विरोध सूचक नोट) इस विशिष्ट सिमिति की रिपोर्ट में पेश किया। उन्होंने भी इस बात का काफ़ी जिक्र किया है कि खेतिहर मज़दूरों की समस्या हल नहीं की जा रही है। मैं ऐसी हालत में उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस बात की तरफ ज़रूर ध्यान देगी।

इसी तरह से शिकमी काश्तकारों की बात है। अभी तक तो यह चीज थी कि १५ गुना लगान दे कर ऐसे लोग भी भूमिघर बन सकते हैं, लेकिन ५ वर्ष के बाद। अब बड़ी भारी रिआयत की गई जब कि काफी ऐजीटेशन (अान्दोलन) हुआ। लोगों ने महसूस किया कि शिकमी के लिये पांच वर्ष तक एकना पड़ेगा तो हमारी गवर्नमेंट ने एक रहोबदल कर दिया और वह यह कि जो खास काश्तकार है अगर उसकी रजामन्दी हो तो शिकमी काश्तकार आज भी १५ गुना लगान देकर भूमिघर बन सकता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती है कि गवर्नमेंट इतनी भोली-भाली क्यों है ? गवर्नमेंट ऐसा क्यों समझतों है कि जो खास यानी आला काश्तकार है वह ऐसा क्यों कहेगा कि तुम १५ गुना लगान देकर हमारी जमीन के मालिक बन जाओ। गवर्नमेंट के लोग भी महसूस करते हैं कि खास काश्तकार कभी भी शिकमी के लिये जमीन देने के लिये रजामन्द नहीं होगा लेकिन फिर भी यह चीज बिल में रख दी गई और रख इसलिये दी कि जिससे शिकमी काश्तकारों को संतोष हो सके या वह लोग जाकर आला काश्तकार के यहां नाक रगड़ें। मेरा ख्याल तो यह है कि यह चीज महज इस बिल को सजाने की दृष्टि से रखी गई है। वर्ना इससे कोई

[शो राजाराम नाग्यो]

फापरान ो हिर्मात । सर्व १ । । विश्व के एमा और नराधा सम्बेगी।" यानी ए आका काराकार कोणाता का अभियार कन एकी और तो अकारतकार को भूभियर जनने का मोका किल्या।

त्राम त्या प्रकार पहरण से देशाह राज्य जिल्ला एकी एक है ह उन पर गोर करता हैं तो मालून तेला तक जरूम पान तार्मान है वह उन रे पान रहे और बहे--वहें फार्म्स बना सफते हैं। राज्य कि को रेन्हें र्जा जाएंगी हैं। न जब मैने रिपोर्ट की बेखा तो गालन हजा कुछ जोरही। गर्जा गेंट, छाउस म गछ बलील देती है कि समीन का बटबारा इप्लिंग गरी करते कि यह कोई रवह नहीं है लेकिन स्पोर्ट में जो कारण देते। जारा उन पर आप लोग गोर कर लंकिये। गर्जा में इस बान को मानती है कि-

"Against this We must reckon the fact that it would alouse a spirit of opposition among the substitutial cultivators, findlords and tenants and would inflict great hardship upon the landlords, whose income will, in any case, be reduced by our scheme for the abolition of simindari.

Land is a gift of nature and it seems unfair that some persons should own large areas while thous inds of other eke out a base living from small holdings. An unconomic holding is national loss, for it cannot fully occupy the minimum agricultural unit, which under the provailing technique is a pair of bullock and a plough. Redistribution of land would increase the number and the area of economic holdings and thus promote agricultural officiency."

("इसके साथ-साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे वास्तविक कृषकों में अर्थात् जमीं वारों और असामियों में विरोध की भावना उत्पन्न हो जायेगी। इससे जमी-दारों को बड़ा कब्ट होगा जिनकी आय हमारी जमीं वारी उन्मूलन योजना के कारण अवश्य हो घट नायेगी।

भूमि प्रकृति की देन हैं और यह अन्याय है कि कुछ लोगों के पास अधिक भूमि हो जब कि दूसरे हजारों लोगों के पास छोटी—छोटी जीने हों जिनमें वे खाने भर को अस पैदा कर सकें। अश्राभक्षर जोत से राष्ट्रीय हानि होती हैं क्यों कि यह एक कृषि विषयक यूनिट को अर्थात् प्रचलित परिभाषा के अनुसार, वो बंलों और एक हल को, पूरा काम नहीं दे सकती। भूमि के प्रचितरण से लाभ कर जोतों की संख्या और परिमाण बढ़ जायेगा और इस प्रकार कृषि विषयक योग्यता भी अंबी हो जायेगी।")

इतनी चीज तो तारीफ में हैं कि वास्तय में बंटवारा करने से वेश को फायदा है लेकिन क्यों नहीं करते इस पर जरा गोर की जिये। जमीन का बंटवारा करने से गयनमें हैं काफी फायदा गमझती हैं कि इसका बंटवारा ट्रोना चाहिए और नहों से खेती की समस्या हल नहीं हो मकती लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी अड़चन एक हैं और वह यह है कि जमादार इसको नापसन्द करने और इगका विरोध फरेंगे। अगर उनके विरोध करने की वजह से आप जमीन के बटवार के लिये तैयार नहीं होते तो हमारी ममझ में यह बात नहीं आती हैं। आपको लो फेसला करना चाहते हैं। जमींदार को या किसान को। अगर यह मंता है कि आप किस को खंश करना चाहते हैं। जमींदार को या किसान को। अगर यह मंता है कि आप विसी चीज को पेश करना नहीं है। जमींदार को या किसान को। अगर यह मंता है कि आप विसी चीज को पेश करना नहीं है। में इस चीज को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। मंतो यह समझता है कि जहां हजारों जमींदार नाराज होंगे वहां लाखों और करोड़ों किसान खुश भी तो होंगे। साथ ही हम यह भी महसूत करते हैं — इसमें जो परिभाषा की गयी है काइतकार की, में

कर रिपोर्ट देख रहाथा तो अब तक यह चीज समझ में आती है, दि जमीन उनकी दी जाए जो जमीन जोतता है। अगर इम तरह के लोगों के हाथ में जमीन रहे जो जीतने बोते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत से किसानों के पास जमीन रह सकती है। लेकिन मरकार महसूस करती है कि जब देहात में पूंजीवाद की व्यवस्था कायम करनी है, बडे-बडे पूजीपतियो के हाथ में बड़े-बड़े फार्स देने ह तो जो वडे-बड़े जर्मदार ह जिनके पास ५,५ और १०, १० हजार बीघा खेत हें वह उनके पास रहने दिये जाएं नाकि वह नौकरों के जरिये खेती करा सके, वह रुपया लगायेगे और रुपये के जरिये से खेती – बाडी करने की कोशिश करेगे। इसलिये कोई यह न कहदे कि खेती के अन्दर काम करने याले पंजीपति हैं यह कैसे मालिक बन सकते है। नरकार इसीलिये बड़ी खूबी के साथ तमाम दलीले देने के बाद इस नतीजे पर पहुँची कि खेती में जो पैसा लगाता है उस आदमी को भी खेती मे मिल्कियत पाने का अधिकार है। वह भी टिलर आफ दी लैंग्ड (जमीन जोतने वाला) है। चाहे खुद काम न करता हो, चाहे हल न चलाता हो, ऐसे लोगो को भी कास्त का पर्जेशन (अधिकार) दे दिया है। इसका रिजल्ट परिणाम क्या होगा? जिस तरह से रैयतवारी सिस्टम (प्रया) मे जहां जमीदार नहीं है--वम्बई को ही देखिये--वहां की तरह से ही यह तमाम प्राविजन (नियम) हमारे इस बिल में आ रहे है। इसका नतीजा यह निकलेगा कि जो खेती करने वाले हैं उनके हाथ से जमीन निकल जायगी और ऐसे लोगों के हाथ में चली जायगी जो पैसे वाले हैं। बम्बई और पंजाब में यही हुआ। दूसरी २ जगहों पर यही हुआ। आज आवश्यकता इस बात की है कि जमीन उन्हीं के पास रहे जो वास्तव में खेती करने वाले लोग है। लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि जमीन उन्ही के पास रहे जो वास्तव में खती करने वालें लोग है; लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि बिहार के पूंजीपतियों की बहुत सी पूंजी जहां शहरों में लग रही हैं वही बहुत से ऐसे पसे वालें देहातों मे भी अपनी पूंजी भेज रहे है। इस तरह से पूंजीपित ओर जमीं दारों मे एक नये तरीके की आर्थिक व्यवस्था में गठबंधन हो रहा है। धाराओं पर गौर किया तो देखा कि पैसे वाले जो है वह जमीन ले सकते हैं और जमीन पर काबिज हो सकते हैं नौकर रख कर नौकर के जरिये से खती कर सकते हैं। सारा बिल पास होने के बाद जो भूमि व्यवस्था आप कायम करेगे उसमें एक तरफ बड़े-बड़े जमींदर होंगे, जिनके पसा १० हजार बीघा तक खेत होंगे, जिनके अन्दर काम करने वाले बोमियों मजदूर होंगे, ट्रैक्टर्स चलते होगे और दूसरी तरफ साहब यह कहा जाता है कि वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकेगे। बिल में यह बात कहां ह ? आइंदा जो लोग खरीदेंगे वह ३० एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते लेकिन इस वक्त जिसके पास १० हजार एकड़ है उस पर कोई पाबन्दी नहीं हो सकती। इतने समझदार एम० एल० एक बैठे हैं उनकी समझ में यह छोटी सी बात भी नहीं आती। (एक आवाज--कितने ऐसे हैं?) में पूछता हुँ कि इस बिल में से ऐसी असमानता को क्यों नहीं मिटाते ? जो असमानता ऐसी हो कि किसी के पास दस एकड़ है और किसी के पास तीस एकड़ है, चालीसएकड़ है, जितनी असमानता कम करेंगे उतनी, में समझता है कि बात समझ में आ सकती है। लेकिन किसी के पास आधा एकड़ जमीन है और किसी के पास पांच हजार एक ड़ जमीन है, तो इस तरीक़े से काम नही चलेगा, जिस तरह से असमानता आज देहातों में हैं। एक तरफ वह किसान नजर आयेगा जो छोटे-छोटे खेतों पर काम करता होगा, जो जमीन को बेचता फिरेगा, और तबाही की जिन्हगी बसर करता होगा। दूसरी तरफ आप को वे किसान और जमींदार नजर आयेंगे जो भजदूरों से काम करवा कर रुपया कमाएंगे। इस तरीके से गरीब और अमीर की व्यवस्था तब भी देहातों में कायम रहेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। कांग्रेस की ओर से काइतकार वह लोग भी है जो पैसा लगाते हैं। हम कहते हैं कि वास्तव में जो जोते और बोवें वही काश्तकार है। अब नवाल यह आता हैं कि क्या तरीक़ा अख्तियार किया जाय जिससे देहातों के अन्दर सुधार हो नके

में समझता हूँ कि यह ठीक बात है कि देहातों में खेती के उत्पर ७२ फी सैकड़ा बोझा उनके ऊपर लदा हुआ है। कल भी मैने कहा था कि आपको देश की पूरी-पूरी आर्थिक व्यवस्था की ओर ध्यान देना पडेगा जिसमें अपको उद्योगीकरण करना पडेगा, देहातों श्री राजाराम शास्ती

में उद्योगीकरण के जाना पहेगा। आप बड़े फाम्से बनाए उसमें हुई कोई एतराज नहीं हैं। लेकिन उन बची बड़ी जोती का उन्तजाम फरने वार जो तरीका है वह व्यक्तियों के हाथ में मत सांपिते। अगर ऐसा करेंगे तो जिस तरह का रोना आज कारणानों में शेया जा रहा है नहीं रोना वहां भी रोना पहेगा हि सारी जालन भजवूर पेदा करना है, लेकिन मनाका यह थोड़े से, मटकी भर लोग जो वेशा लगाते हैं, अपने घर में रख लेते हैं। आज जान आप के हाथ मे राज्य व्यवस्था है, कानून बनाने की भना है तो हातारी दरख्वास्त है कि आप इस तरह की दायस्य। क्यों नहा करते है । अहे- "के फार्स की बना कर उनका प्रान्ध थोडे है, मह्नी भर जमीदारों के हाथ में पया देते हैं ? वह नौकरों से काम लेगे, तन् हा शोषण करंगे, और कारा पैसा अपने वाल रखेगे । मेरा अपना क्याल यह है कि जिनने लोग इस तरह के है जिनके पास बहुत जपादा जमीन है, उन जमीन को सबा छः एकट से जगाबा नहीं बढ़ने बगे, ज्यो तरह से आप अपर लिमिट (उन्चाम अविधि) भी रख वै कि तीरा एकड, नालीम एकड या पचारा एकड से ज्यादा जमीन कोई भी भूमधर नहीं रायने पायेगा। उसके बाव जिननी जमीन हो उसकी काइतकारों में बांट वीजिये। अब सवाल यह उठता है कि इतनी जमीन है नहीं कि सबको वी जा राको इसिलियों जितनों को बांट सकते हैं उनको भी न बांटी जाय। में कहता हूँ कि अगर ११ स्थान मिनिस्टरों के हैं तो ग्यारह आदिभयों को मिल पाएंगे और बाकी सब अफसोम अन्ते बंठें। पच्चीस स्थान कांस्टीटएंट अरोम्बली के थे और चार सी दरल्वास्तें आई थीं। पच्चीन को आपने वे विया और बाक़ी बेचारे नाराज हो गये। कई एक ने इस्तीफा पेश कर दिया जिनको मनाने में आप लगे हुए हैं। आपके पास जितनी चीज है, अगर हर एक को नहीं मिल सकती है तो आपकी यह बलील होती है कि चूंकि मबको नहीं मिल राकती है इमलिये किसी को नहीं दी जा सकती है। हम कहते हैं कि अगर जमीन सबको नहीं दी जा सकती है तो जितनों को दी जा सकती है उतनों को भीजिये।

बूसरी चीज देहालों के अन्वर छोटे-छोटे घंधों की लाना है। आपको देहातों के अन्वर भी वास्तव में इन्डिस्ट्रियलाइ हो । (उद्योगीकरण) करना पड़ेगा और खेती का सामाजिकी-करण करना पड़गा। हम चाहते हैं कि वेहातों में नई इन्डस्ट्रीज (धंपे) जो आप लावे वह को आपरेटिय बेनिस (सहयोग के आधार) पर हो वह किसी व्यक्ति विदोष के हाथ में न हो। जवाइण्ट स्टाक कम्पनीज की तरह से आप वहां खोलें। आप इस बात को मानें कि थानयों के हाथों में कामों के जाने की वजह से बहुत सा काम नहीं हो पाता। नई नई इंडस्ट्रीज (धंधे) खोल कर जब आप देहातों में माल बनाने का ढंग अख्तिपार करेंगे और जब आपकी नई मशोनरी वहां जाने लगेगी और वहां पर उद्योगीकरण होने लगेगा तो शहर में जो माल पैदा होगा उसकी लपत देहात में होगी और जो माल देहात में पैदा होगा उसकी मार्केटिंग (बिक्री की) व्यवस्था जब आप ठीक कर देगे वह शहरों में आन लगेगा। इसतरह से शहर और देहात दोनों में एक इसरे में सहकारिता का भाव आयेगा और इससे हुमको व आपको बल भिलेगा। इसलिये भी मार्केटिंग ब्यवस्था के लिये भी में कहता है कि इसे आप बीच के धनियों के हाथ में न छोड़िये, सौदागरों पर न छोड़िये, मुनाफ़ाकोरों के हाथों में मत बीजिय नयोंकि ये बेहातों में पैवा हुई जीजों की किशानों की खुशहाली की, तबाह करते हैं, लुटते हैं। जब आप मार्केटिंग व्यवस्था करेंगे तो बेहात का माल शहर में आयेगा और शहरों का माल वेहातों में जायगा। इस तरह से जो व्यवस्था नाप क्रायम करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। इग तमाम बहस के बाद में फिर यह संक्षेप में पेश करना चाहता हैं। जैसा कल कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आता कि सोशलिस्ट (समाजवाबी) पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बहस में इस बिल के ऊपर कहां पर फर्क है। इस-लिये में आज कहना चाहता हैं कि अगरकाप इस बिल को काफी सीर से पढ़ें तो आपको मालूम

हो जायेगा कि जो बिल हमारे साभने है इसके अन्दर कहां फ़र्क़ आता है। जैसा कहा गया है कि हम लोग इस बात के लिये लड़ रहे हैं कि गवर्नमेट ने इस क़ानून को लाने में देर लगाई है। मैने यह कहा है और मैं यह भी कहता हूँ कि यह देर करती जा रही है। इसमें गवर्नमेंट ने जो लिखा है वह यही है कि इस क़ानून के पास हो जाने के बाद भी एउ मारे यू० पी० के अन्दर एक दिन एक साथ २४ घंडे के अन्दर आगुनहीं किया जायगा और यह चीज २४ घंटे के अन्दर खत्म नहीं हो जायेगी। जिसमे यह जिखा है कि हम यथ की घ्र इसकी समाप्त कर देगे। "पथे क्रीघा" तो ऐसा गोल कट है जिसके माने कुछ भी लग सकते है। जित जिले में चाहे धीरे-धीरे कर के ला सकते हैं। इसके साथ ही गर्वनंमेट यह कहती है कि जिसके पात जिननी जनीन है उत्तक्ता कोई भी बटवारा नहीं होगा। किसी की जमीन ली नहीं जायेगी। जिसके पास ज्यादा है जमीन उससे लेकर उस ग्रेरीब को दी नहीं जायगी। जिसके पास जमीन नहीं है या कम है। सोइ जिस्ट पार्टी कहती है कि जमीन का बंटबारा हो, जिसके पास ज्यादा है उससे लो और जिनके पान नहीं है उसको दो। कांग्रेस कहती है कि ३० एकड़ को अर्स भविष्य के लिये लागू होगी, इस वक्त के लिये कोई हद बन्दी नहीं होगी। आज जिसके पास जितनी भी जमीन है चोहे ज्यादा हो वह उससे ली नहीं जायेगी और न उसके लिये कोई हदबन्दी होगी, हम चाहते हैं कि यह इर्त इसी बक्त से लागू हो जिनके पास ज्यादा जमीन है उन से जमीन ली जायं और ऊपर वालों के लिये भी एक हद बांध दी जाय। गवर्तमेंट यह कहती है कि अगर हम जमीन बांटेगे तो जमींदार नाराज हो जायेगे और वह उन्मलन की वजह से मसीवत में पड जायेगे। हमारा कहना है कि कास्तकारों को देखो, खेतिहर मेजदूरों की और देखो जिनकी आधी रीढ़ दूर चुकी है। गवर्नमें इ कहती है कि मुआविजा देना न्याय संगत है और इसके बगैर जमीदार परेकान हो जायेगा। सोश-लिस्ट पार्टी कहती हैं कि मुआविजा देना सरासर अन्याय है, जमीन प्रकृत की देन है दिसी की मिल्कियत नहीं है, हां जो ग्ररीब है उनको पुनर्वास दिया जा सकता है। गवर्नमेट कहती है कि जमींदारों को मुअ।विजा देने के लिये हम रुपया काश्तकारों से दसूल करेंगे। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि मुआविजे के लिये धनियों के ऊपर टैक्स लगाओ, धनियों से बसूल करके गरीब जमीदार को भविष्य केलिये पुनर्वास अनुदान के रूप में, सहा-यता के रूप में दो। गवर्नमेंट कहती है कि अब हम भूमिधर बना करके किसानों को क्रान्ती हक दे रहे हैं, वे जमीन बेच सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि इस तरह से बेचने के अधिकार देने से किसानों की जमीन जो है वह जमीन ऐग्रीकेल्चरिस्ट (खेती कराने वाले) के पास चली जायगी। धन से जो खरीद संकता है उसके पास चली जायगी। इसलिये इस खरीद फरोख्त की बात को रायज करना कोई जायज बात नहीं हो सकती। गवर्न-मेंट जिम तरह से पीजन्ट प्रोप्राइटरिशप (खेतिहरों का स्वामित्व) लागू करने जा रही है मैं देखता हूँ कि उससे गांवों में किसो तरह से सामृहिक भावनापैदा नहीं हो सकेगी। इसलिये में यह सोचता हूँ कि वास्तव में में देहातों में जो नई व्यवस्था क्रायम की जाय उसमें देहातों में जो पंचायतें हैं वे वहां की नीति का संचालन करें और किसानों के अन्दर इस बात की भावना लायें कि साम्हिकता अच्छी चीच है, उनमें भाई चारे की प्रवृत्ति लाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट यह समझती है कि गांव-सभा के जो पंच, सरपंच वगैरह हैं वे सब सरकारी अफसर हैं, उनको इस व्यवस्था में पूरी तरह से गवर्नमेंट का समर्थन हरना चाहिये। हम समझते हैं कि सरपंच, पंच, ग्राम सभा के प्रेसीडेंट ये सब जनता के वोट से चुने गये हैं और चुने जाते हैं। ये गवर्नमेंट के शासकीय कर्मवारी नहीं हैं इनको जनता के हित में काम करना चाहिये। गवर्नमेंट यह कहती है कि जो पैका लगावे वह किसान । हम यह कहते हैं कि जो जोते बोवे वह किसान। गवर्नमेंट यह कहती है कि भूमिधर के अलावा और जो किसान हैं उनसे जो आज लगान लिया जाता है वही लगान भविष्य में लिया जाय। हम यह कहते हैं कि किसानों से वही लगान भविष्य में लिया जाय जितनी कि आज मालगजारी है। गवर्नमेंट यह कहती है कि आला काइतकार जब रजामन्दी दे तभी शिकमी काश्तकार १५ गुना लगान जमा कर के भूमिघर बनेगा। हम यह कहते हैं कि आला काश्तकार की रजामन्दी की शर्त पेश करना यह एक तरह से आशा बंधानी है और

[श्री राजाराम शास्त्री]

वह इस तरह का हक शिक्षमी काश्तकार को नहीं देंगे। हम गवर्नमेंट के बिल में यह देखते हैं कि खेतिहर मजबूरों के लिये, जो वास्तव में बहुत बड़ी तावाद में हैं कुछ नहीं किया गया है और उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हम समझते हैं कि देहाती व्यवस्था खेतिहरमजदूर एक ऐसा मजदूर है जिसके ऊगर साम्गाज्यशाही का सारा बोझा लदा है। जिसके पास न कोई जमीन हैं और न कोई रोजो का ठिकाना। ऐसी हालत में जब हम जमींदारी की लात्मा करते हैं तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि उस किसान मजदूर का भला हो। अगर ये चोजों आप नहीं करते हैं तो मुझे संदेह रहा है कि आप किसानों के अन्दर इस आशा का संचार कर सकेंगे कि जमींदारी के लत्म होने के बाद वास्तव में देहात के किसानों की बहुत बड़ी भलाई हो सकेगी। में सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप जितनी ही आशा पैदा कर लीजिये लेकिन जो व्यवस्था आप कायन कर रहे हैं उससे कुछ न होगा। न देहात में जमीन का बंटवारा होगा और न उनकी हालत ही सुधरेगी। आपने दिया क्या है? केवल, वही जो भूनियर हैं वे अन्ती जानीन बंब सकते हैं। केवल जानीन बंबने का अधिकार दे दिया है। कियान यह समझेगा कि जमींवारी का खाटमा तो हो गया लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में वह रहेगी जिससे वास्तव में किसान कोई खुशी महसूस नहीं करता है। में वेखता हूँ कि जर्नावारी उन्मूलन के बाद जो व्यवस्था आयेगी उससे देहात की सामाजिक अवस्या में कोई अन्तर नहीं आयेगा । तारीब को अमीर खाये, ये तब भी क्रायम रहें, यही होने वाला है। ऐसी हालत में जो बिल का उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता। में उम्मीब करता है कि हनारे कांगेंस के साथी जी बात कही गई है उसे सही स्त्रिट (भावना) में लेंगे। मेरी मंशा यह सब कहते की हांगज यह नहीं थी कि आवकी बदनामी हो। हम चाहते हैं कि हनारे इंटिड कोण को समझने की कोशिश की जाय। में नहीं कहता कि जितते आईर (आवैंग) गवर्तमेंट ने विवे, जिनके उदाहरण मेंने दिये, वह गवर्नमेंट ने बदिन रती से दिये। में तो यह समझता हूँ कि हुमारे नीचे के अधिकारी वास्तव में इस तरीक से पेश आ रहे हैं कि बहुत से कायदे कानूनों को उन्होंने ताक पर रख दिया ह। उनके अन्बर यह मनोबुलि आ रही है कि हम सरकारों अफतर है, हम जितना ज्यादा लगान वसूल करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे कांगेत मिनिस्टर हमसे खुश होंगे। हमारी नोकरी बरकरार रहेगी। में समझता हूँ कि यह मनोब्सि जो उनके अन्वर पैदा हुई है वह खतरनाक है। हम चाहते हैं कि वे अधिकारी इसकी अच्छी तरह से समझ लें कि अगर वह क्रायदे कातून के विरुद्ध जाते हैं तो उनकी सौर नहीं। वे यह समझ लें कि अगर किसी ऊपर वाले की मालूम हुआ तो चाहे उन्होंने कितनी भी दस गुने लगान की वसूलवाकी की ही यह नहीं देखा जायगा कि उन्होंने कितनी बसुलयाबी की है। जब इस भावना से आप चीजों को देखेंगे तभी आपके नीचें के अफनरों को मालूम होगा कि उनकी सौरियत नहीं और तभी वे इ.स भावनी की कह कर सकते हैं। में भी यह चाहता हूं कि हमारे किसान खुशहाल हों। में भी यह चाहता हूं कि जमींदारी जल्म हो। में भी यह चाहता हूं कि वास्तव में हम जिन उद्देश्यों को लेकर चले थे वे पूरे हों। हम चाहते हैं कि सामन्तवाहो का नाव करके ऐसे तरीक़े अख्तियार किये जायं जिनकी वजह से सामग्तदाही लोग कमजोर हो और किसान शक्तिशाली हो। में समझता है कि यह बिल जिस मौहें पर हाउस के सामने आया है उस मोले पर सारे देश की निगाह हम पर लगी हुई है इस लिये में यह चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रख कर चले। मेने विछली वफ़ा भी कहा था कि जब में इस क़ानून को १८ वों सबी या १९ वीं सबी की रोशनी के सामने रख कर उस पर बहस करता हूं तो वह काफ़ी प्रगतिशील मालून होता है, काफ़ी आगे बढ़ा हुआ मालून होता है। जब में फ्रांत की राज्यकान्ति, मोरय की कान्ति को बेखता हुं और उस समय को बेखता हूं जब कि उन्होंने सामन्तशाही को ज़त्म किया था तो यह क़ानून मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप इस बात को न भूल जाइये कि जिस युग में आप इस कानून को बना रहे है उस युग

की दृष्टि से यह कानून ठीक बैठना हे या नहीं। आप यह न भूल जाइये कि इस युगधर्म मे यह कार्न आता है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो यह कोनून हमें आगे नहीं ला सकता। कले जब में चीन के बारे में सांच रहा या और यह सांच रहा था कि चीन की राष्ट्रीय सरकार, चीन के राष्ट्रवादी चांग काई क्षेत्र क्यों विफल हुये ? और इस पर भी विचार किया कि वहां पर कम्यु-निस्ट्स किस तरह से यावर (शक्ति) में आये, किस तरह से पीनित्न, गवर्नमेट (जनता की सरकार) उन्होंने कायम की । किस तरह से जनोंदार किसान, पंजीपित मजदूर, अमीर-गरीब और भूमि का मसला उन्होंने हल किया। वह किस तरह से हर चीज को किन्कस्केट (जब्त) करते हुये आगे बढ़े। लेकिन उसके अन्दर भी उन्होंने एक वर्त रखी ओर जमीन की व्यवस्था के लिये रखी रिडिस्ट्रीब्यूशन आफ लैंड (भूमि का पुनिवतरण) के लिये उन्होंने कह दिया। जब हम पूर्वी योर्य की ओर देखते हे तो हमको नाल्म होता है कि इस विषम असमानता को उन्होंने किस तरह दूर किया। जब आपके हाथ मे, जनता के हाथ मे राजसत्ता आई है तो आपको भी इस असमानता को दूर करना होगा। चीन के अन्दर समानता पर बटवारा करने का प्रोग्राम बनाया गया है। ेलेकिन जब कभी मैं इस हाउस में बोलने के लिये खड़ा होता हूं तो कहा जाता है कि जनाब जमीन रबड़ तो हे ही नहीं जो बंट सके। और हर आदमी तोते की तरह उसी की रट लगाये हुये हैं। मैं कहता हूं कि क्या प्रांत में, योरप में जनीन बंट सकती है ओर हिन्दुस्तान की जमीन नहीं बंट सकती ? अगर यहां की जनीन नहीं बंट सकती तो प्रांत, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, रूमानिया की कैसे बंग सकती है ? और चीन के कम्पुनिस्ट कैसे उसे बांट सकते है ? जब वह रबड़ ही नहीं है तो वहां वह कसे बंट सकती किसों के पास ५ हजार एकड़ जमीन है, आप यह एक नियम बना दीजिये कि किसी के पास ५ ए इ.इ. मे ज्यादा जनीन नहीं रह सकती । इममे रबड़ ओर गैर-रबड़ का क्या सवाल है ? इसमे तो मुख्य बात यह है कि जिसकी वह जमीन हे आप उसकी नाराजगी वरदास्त कर सकते है या नहीं और अगर आप नाराजगी बरदाश्त कर सकते हे तो जमीन रबड़ बन सकती है लेकिन आपके दिल मे यह ख़बाल होना चाहिये। अगर आब इसी तरह की असमानता रखेगे तो मेरा अपना खात्र है कि इस समय आपका विरोध चाहे जितना कमजोर क्यों न हो, किसान आ । के बरगलाने में नहीं आ सकता, चाहे आप ईश्वर का नाम लें या भूमिधरी बनाने की कहें। जिस तरह से आज हिन्दुस्तान के चारों ओर से कम्यूनिजम (साम्यवाद) की लहर आ रही है उस स्थिति में यदि आ ने समाज व्यवस्था को नहीं बदला ओर जनता के पक्ष में नहीं बदला तो में कहता हूं कि आप विकन होंगे। कम्यूनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) के लिये ऐसी हालत में आगे आना कठिन नहीं होगा। वह कम्यूनिस्ट पार्टी रूप या चीन के अन्दर से यहां नहीं आयेगी, बल्कि हिन्दुस्तान की सरजमीन से ही वह पैदा होगी। आपकी तरफ से जो स्पी-चेज (भाषण) दो गई है, उनके बारें मे एक उदाहरण देकर मै अपनी स्पीच (भाषण) को समाप्त करूंगा।

आपने भी इतिहास में पढ़ा हैं ओर हमने भी इतिहास में पढ़ा है कि एक थे बादशाह कैन्यूट । वह दुनिया में बहुत ही शिक्तशाली समझे जाते थे। बहुत में दरबारी उनके पास रहा करते थे और वह कहा करते थे कि जहांपनाह की ताक़त इतनी बढ़ी है कि दुनियां की कोई ताक़त उसका मुक़ाबिला नहीं कर सकती है। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठे हुये थे। समुद्र की लहरे बड़ी तेजी के साथ उधर चली आ रही थी। पहले बादशाह को डर लगा कि तूफ़ान नजदीक़ आ रहा है, कहीं बहा न ले जाय, लेकिन उनके आसपास जो दरबारी थे उन्होंने यह कहा कि हुजूर की शिक्त महान है, अगर आयं आईर दे दे तो आने वाली लहरों को पीछे हटाया जा सकता है। वह यह समझे कि इनको सलाह देनेवाले लोग उनका हित चाहने वाले हैं। उन्होंने आते हुये तूफ़ान को रोकने की कोशिश की। नतीजा वही हुआ कि वह लहरों को न रोक सके और बादशाह कैन्यूट भी समाप्त हुये और उनके दरबारी भी समाप्त हुये। तो में यह कहना चाहता हूं कि उधर के बैठनेवाले लोग रोज़मर्रा गवर्नमेट से कहते हैं कि कुछ परवाह मत करो तूफ़ान की, हम तुम्हारे पीछे खड़े हुये हैं, जनता की शिक्त हमारे साथ है। कभी-कभी अगर उधर से कुछ कमजोरी होती है तो जमींदार लोग भरोसा दे देते हूं।

श्री राजाराम शास्त्री

कि मन धनदाओ, आज नहीं तो कल २६ जनवरी को भारे जगावार और नवाब उधर बैठेंगे. तुम्हारी मदद करें भीर आने वाले तुकान को रोक देंगे। उताव हिन्दो स्पीकर, म बहुत अब में ताब करना बाहना र कि हिंदुरनान में जो मामाधिक मानि की लहर आनेवाला है उतका न हमारे दरपारी लोगे रोक सकी ह अन न वर्गतारी या न ता रोन राकते हैं। आने वाली कार्रत की रोक्षने का अगर कोई नरो हो हो हो हो है है है है महता कि वा तो गवर्गिट खाद जबले का जना पानेनेट हो जन है जिल्ला े । इन दाने से एक नाजा की डीना अगर एक चीज न पहीलों । विभागानरा माल्य होता है विजाप गास्तव में देश को अराजकता और गुना क्रांति की और होत्ये को है। आप भरो तात की न मानिये, लेकिन जो मही माधीयादी है उन्हां की और मार ही तिये, मंजर वाना की रपावज (भाराण) पहिये. क्रवलानों की स्पोचेज पढिये, बिनोबाराबे की स्पीन्य पहिये जिन्हों सही साने में कहा जा सकता है कि उनकी माथा ममता ने नटा रताया आर जो बास्तव में समझते है कि गाधी जी का एक आदर्श था जोर सी आदर्श पर हमको चलना है। में यहत अदर्श के गाप अपने उधर के बैठने वाले भाइयो से महंगा कि आप जरा जें० मी० कुमाराना ने जो कहा है उस पर गोर कीजिये। उन्होंने यह कहा है कि हमें अफ भाग है कि काज राजगद्दी पर बेठने वाले लोग गांधी जी के उसुलों को भुल गयें है, हम उस दिन का इतजार कर रहे हैं जब हम सर्वोदय में काम करने पाले, इस गवनंमेंट का विरोध करेंगे। हम चूंकि विरोधी दल के है इसलिए अगर कोई सीज पेश करते हैं तो आप कहते हैं कि हम गलत है तो आप कृपा करके कृपलानी और मशहबाला की ही बाते सुनिये। अगर आप उनकी भी नहीं सुनते हैं तो मं यही कहंगा कि जिसका सर्वनाश होने को होता है, उसकी बृद्धि नग्ट हो जाती है। चहि सारा देश कहता रहे और अख़बार वाले जिल्लाने रहें लेकिन कार्यरा वाले किसी भी हमानदार की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने यह कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो बजमोहन लाल शास्त्री को ही बात मानिये, तो यह कहा जाता है कि वह बैठे तो इधर है लेकिन उनका दिल य विमाग आपकी ही तरफ है। में तो यह कहांगा कि न आप देश के बुश्मन हुँ और न हम देश के बुश्मन है। आपने भी कुर्बानिया की है और हमने भी कुर्बानियां की है। हम कभी यह नहीं चाहते हैं कि हम सरकार की बबनाम करने के लिए सरकार की आलोबना करें क्योंकि अगर सरकार बवनाम होती तो प्रतिक्रियायादी शक्तियां शक्तिशाली होंगी। में यह भी कह बेना चाहता हूं कि एंगी प्रतिकिधावादो शक्तियों ने, चाहे हिन्दू-सभा वाले हों, चाहे मुस्लिम लीग वाले हों, चाहे जमीबार लोग हों, अगर कभी काग्रेग हुत मत के खिलाफ सर उठाया ओर विद्रोह करने की कोशिश की तो हम पूरी शक्ति से कांग्रेस सरकार की मदद करेंगे।

कांग्रेस गवनं मंट अपनं कमीं में वेश को रसातल की ओर ले जा रही है और वेश के अन्वर एक साइ कोलाजी (मनोवृत्ति) पैवा करने जा रही है कि साहब, अगर कांग्रेस सरकार गद्दी ने हट जायगी तो वेश में अराजकता फैल जायगी, और वेश का सर्वनाश हो जायगा । अगर वेश के शासक ऐसी मनोभावना जनता के अन्वर पैवा करते हैं तो आखिर में उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि आपकी मनोवृत्ति आगे नहीं चलेगी । अगर आपके अन्वर अपो-जीशन (विरोधी वल) की बातों को सुनने के लिये सहिष्णुता नहीं है तो उसका एक यही लाजिमी नतीजा होगा कि इस वेश की जनता डेमोकेटिक (प्रजातन्त्रास्मक) रास्ते को छोड़ वेगी, शाम्तिमय रास्ते को छोड़ वेगी, गांभी जो के बताये हुये सत्याग्रह के मार्ग को छोड़ वेगी और उसके बाद विहोह का रास्ता अपनायेगी जो इस वेश के लिये, हमारी सरकार के लिये, हमारे समाज के लिये, फायवे-मन्व नहीं होगा । इसलिये में समझता हूँ कि आप इस मनोवृत्ति को लेकर अगर गही पर बैठे हैं तो बास्नव में वेश का सर्वनाश होगा । आपका नारा इस बकत है, कांग्रेस नहीं तो सर्वनाश, हमारा नारा है कांग्रेस और सर्वनाश ! अगर आप बबले नहीं तो में फिर कहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जनता के अन्वर यह भावना पैवा होगी और होनी चाहिये और वह हिम्मत के साथ अपने अधिकारों की रक्षा करगी । मुझे बड़े इंस के साथ कहना पढ़ता है कि इघर के बैठने वाले

की वजह से हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने यह कहता है कि अनुशासन बहुत अच्छी चीज है लेकिन देश की तरफ भी तो ख्याल रखिये। अनुशासन के नाम पर इस तरह से तो न दिबये कि सच्ची बात भी न कह सकें। देश को और इस हाउम को यह जान कर बड़ी खुशी हुई थी और आज भी खुशी है कि कांग्रेसी सरकार जर्भी दारी का खात्मा करन जा रही है। लेकिन जब मैं इस बिल की धाराओं को पढ़ता हं तो जालून होना है कि जो व्यवस्था आगे होने जा रही है उसका परिणाम यह होगा कि देहातों के अन्दर एक तरफ तो गरीब तबका खड़ा होगा और दूसरी तरफ रईय तबका खड़ा होगा और दोनों में आपस में संघर्ष होगा जिससे कोई शान्ति नहीं हो सकेगी । अाप आज इप बिल को जरा ठंडे दिल से पढे और इस यर सोचें। आज इस बात का आप ढिडोरा पीट रहे हैं कि जमींदारी खात्मे के बाद देश के अन्दर बड़ी शान्ति पैदा हो जायगी, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमे तो देश का मर्वनाश हो जायगा। अगर आप इसको ठीक तरह से समझ बुझ कर नहीं करते है तो उसका नतीजा यह होगा कि देश में एक सामाजिक कान्ति होगी और सही माने में कान्ति होगी और मही माने में जमींदारी का उन्मुलन होगा और उस वक्त जो गवर्नमेंट बनेगी वही सही गवर्नमेंट होगी। जब तक समाज की अच्छी व्यवस्था नहीं होती तब तक जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। ऐसी हालत में मै एक बात आपसे अवस्य कहना चाहता हूं कि आप जिस स्प्रिट (भावना) में इस विल को ले रहे हैं उससे कोई गलत बात न कीजिये। जिस भावना से प्रेरित होकर आप इस बिल को पेश कर रहे हैं उस भावना को देखिये और किसानों के वास्ते, समाज के वास्ते, मुल्क के वास्ते जो कर सकते हों कीजिये। आप जानते है कि मेरे पास बोट का बल नहीं है, हमारी तादाद केवल ३ हैं। आपके पास वोट बहुत ज्यादा है, आपकी तादाद भी बहुत है। लेकिन हमारे तीन आदिमयों की आवाज केवल तीन की ही आवाज नहीं है बल्कि यह बहुत काफ़ी तादाद में जो जनता है उसकी आवाज है। आप जमींदारों को मुआविजा देने के लिये किसानों से दस गुना लगान वसूल कर रहे हैं और जितनी बातें हमने आपके सामने पेश की है उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आपके नीचे के अधिकारी जो ग़लत काम कर रहे है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन में कहता हूं कि आप मुआविजा दीजिये और जिस तरह से जो कुछ भी करना चाहें कीजिये लेकिन इस बात को याद रखें कि आप हमेशा इस कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते । आपको चाहिये कि जो कोई भी शख्स यु० पी० के अन्दर ग़ैर क़ानुनी कार्यवाही करे, चाहे वे अपने कर्मचारी ही क्यों न हों, उनकी जांच करें और ऐसे आदिमयों को सजा दें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा करते समय आप डगमगायेंगे नहीं। मैं उन कर्मचारियों को भी और सरकार को भी एक बार वार्ति ग (चेतावनी) दे देना चाहता हुं कि जो कर्मचारी जनता के साथ बुरी तरह से पेश आयेंगे, आगे आने वाली सरकार उनके साथ भी बड़ी सख्ती से पेश आयेगी और उनको अपने किये हये कर्मों के लिये सख्त से सख्त सजा देगी। मैं फिर सरकार से यह कह देना चाहता हूं कि जिस भावना को लेकर सरकार इस बिल को पेश कर रही है उसको खुब सोच-समझ कर और जनत की सारी बातों को सामने रख कर कोई क़दम उठावें जिससे जमींदारी ख़तम होने के बाद किसानों। का भी फायदा हो और इस देश का भी फ़ायदा हो।

*माननीय सार्वजिनिक निर्माण सचित्र—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस वक्त जिस वजह से खड़ा हुआ हूं वह सिर्फ इतनी है कि कुछ बातें अभी मेरे सामने इस ऐवान में जो कोशिश गवनंमेंट की तरफ से रुपया वसूल करने के मुताल्लिक हो रही है उसकी बाबत कही गई। जहां तक कि इस मजमून का ताल्लुक है इसका जवाब जनाब रेवेन्यू मिनिस्टर साहब खुद देते लेकिन चूंकि कुछ बातें मेरे जाती इल्म में है और मेरा उनसे खुद वास्ता पड़ा इसलिये मैंने यह जरूरी समझा कि मैं उन मालूमात को इस ऐवान के सामने रखूं। मेरा मक़सद किसी तकरीर का जवाब देना नहीं है मगर यह भी नहीं है कि और जो बातें मेरे स्थाल में इस

^{*}माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

| भाननीय मा जिनिक निर्माण गनिव

बर्गक मार्गार्जन जाई हा जो यहा पर जनी तह होती रर्ग है उनका में जज ने कहा आज परोज में उपाएंबान में संकेश्य कमटा का स्थि। के कार रहा ही रही है। यह स्थित उस मलेकः करोशे की है जिसने जमादारी मन्मुको क कान्न पर विचार किया। किसी तजायाजा पर ऐयान में बहस का सकसद तिक इतना तारा ह कि पलेश कमेटी ने उस कानत पर विचार करके जा कुछ तब्दोलिया कान्त म का टा उनके मुनाल्लिक जाम मुजाहिसे के जरिये से इजहारे ख्याल किया जाय कि उनम से ३६३ वाले कहा तक मौज़ ह और कहा तक माज नहीं है। लेकिन जो तकरीर पूनने की मुझर्कों इस ऐंपान में इसकांक हुआ उनस में इस नतीजे पर पहचा कि जायद आज की बुनिया म इस प्रशने बसूल को जिस पर लेजिस्हे-चर में हमेशा से अमल होता आया ह भला विया है और इस मवाहिस में इस बात का कोई इम्तियाज नहीं है कि कोई इस यक्त किस हद तक अवने आप की महदूव रखें और क्या बातें कहना बहरहाल मुबाहिसा तो जारी ह और मेरो कुठवत के अस्तियार में नही ह कि में उस मुंबाहिसे की उस दायरे के अन्दर महदूद कर द कि जिस दायरे में उसकी महदूद रहेना चाहिए। मगर मने भी अवना यह फर्ज समझा उस ऐवान का एक मेमबर होने की हैमियत से जनाब वाला के जरिये ने कि इस एवान के मेम्बर साहतान की तवज्जह इस तरफ मबज्ल कराऊ कि इस बायर के अन्दर मेम्बरान की महदूद रहना है। जमादारी की मन्तुखी के वास्ते मुवाविजा होने के सिलिंसिले में जो रुपया कि इस यक्त इस सूबे में बसूल हो रहा है उसकी बाबत १,२,१०,२०,और १०० जितनी भी शिकायत है कि गवनंमेट के मुलाजमीन किसानी पर तरह-तरह का बबाव डाल रहे हैं और नाजायज तरीके से रपया वसूल करने की कोशिश करते है यह खुलासा है उन जिकायतों का जिस पर वो घण्टे नकरीर की जाय। उसका खुलासा इतना ही निकलेगा कि अगर एक फिकरे में वह बाते कह वो जाय तब भी वह इतना हो माने रखेगी जिनना कि मेने अर्ज किया। हो सकता है कि हमारे बोस्त राजाराम ज्ञास्त्रों ने जो जिका-अवनी लक्षरीर में बयान की यह मही हो मगर में रामझना यह हू, मुमकिन यह ह कि वह मेरी बदगुमानो हो, मगर फिर भी म तो यह गमझना ह कि मेरे बोस्त जिन्होंने इस ऐवान के सामने उन शिकायतो को रखा है उन्हें खद भा उनके सही होने का यकीन नहीं है। क्यो, में ऐसा क्यो समझा ह कि उनको यकोन नहा है, इरालिये कि आज इस ऐवान में आकर इतनी देर सकरोर करने के बाद उन्हां ने जहां तह तिहायती के मुलाल्लिक इरजाव फरमाया हि गवन-मेंट उनको देखें। अगर वाक ई वह जिकायत है तो म समझता यह ह कि वह ऐशा न करते बल्क जिन बक्न वह जिहायते उनके नोटिस म आई था और जिस बक्त उन की आखो ने यह देखा ओर काना ने यह सुना था कि इस किस्म के जुल्म और ज्यावती बेंकस इत्साना के ऊपर मरहूर काग्रेल गवनंनंट की तरफ़ से ही रही है तो पकीनन उनक लिये यह वरवाजा उस वक्त भी खुला था कि जिसकी आज वह इस ऐवान में खटलटा रहे हैं । आप की चाहिये था कि आप जल्ड में जल्द इस दरवाजें की खड़बटाते और इन जिकायत का सहेबाब कराते। जैसा कि मैने अबं किया मुमकिन है कि मेरी यह बदग्मानी हो लेकिन मेरे दिल पर जो असर इस बात का पड़ा और मं समाझना यह है कि मेरे ही दिल पर नहीं पढ़ा बर्टिक जो भी लाजिकली किसी चीज को समझ सकते हैं उनके विल पर भी यही असर पड़ा होगा कि इन बातों का इस वक्त तक बिल में रखना और अब इस ऐवान में ला कर पेश करना सिकं इस घोषेंगे हैं के लिये हैं कि कांग्रेस गवर्नमें उसकी आर्गेनाई जेशन और मृत्क की तवाही सब एक ही बीज का नाम है। अगर में सही समझता हूं तो मेरे बोस्त में अवनी तकरीर में यह भी कहा है कि जहां तक इस किस्म की जिलायतों का ताहलूक है में बैलेंड करता हूं और इस ऐवान के सामने बयान देता हूं कि जब में इत तिलितिले में खुर मुलतिलक मुकामान में गया तो इस किस्म की शिकायतें की गई और मुनको बहुत सी निवाल भी वो गई और मैने भी किसी मसले और शिकायत को बगर तह-कीकात किये हुए नहीं छोड़ा और उनमें से एक की भी सही नहीं पाया। में गवर्नमेंट की जानिव से इस बात के कहने का हक रखना हूं कि हमारी गवने मेंट इस बात से गाफिल नहीं है कि किसी के तरफ्र से इस किस्म का कोई गलत अमल ही खबाह वह कांग्रेस आर्गेनाई जेशन का मेम्बर

हो और उसमें कास करता हो या गवर्तमेट का मुलाजिम हो, न होने पारे। नुजूर वाला, हम तकरीरें करते हैं और गांवों में जाते हे और हमारे मोजिल्ट भाइयों की जगाउत्तें के लोग मुर्ख टोपियां पहने हुए वहां मौजूद होते हे और में अपने देश्यत राजागर जास्त्री की खिदमत में अर्ज करना चाहता है कि एक नहीं यित्क दस, पद्मास मी इस किस्य की मुर्ख टोपियां पहने जहां मौजूद होते हैं वहां हमने डंके को चोट अपनी तकरीरों के दौरान में इस बात दो कहा है कि दस गुना लगान जमा करने के लिये कोई कस्पल्यान और किशी किस्न का कोई दबाव नहीं है। हर अल्स आजाद है और इस बात का मुख्नार है कि अगर वह चाहे तो इस भौके से फ़ायदा उठावे और अगर नहीं चाहता तो न उठावे।

मैं नहीं समझता कि हमारे इस तर्जे अमल के होते हुए कहीं यह हो सकता है कि जैसा मेरे टोस्त राजाराम जी ने कहा। अगर फिलवा के वह शिकायत सही ह तो क्यों न उसी वक्त वहां के हुक्काम की उन पर तवज्जह दिलाई गई? क्यों न उसी वक्त उन के मुतान्लिक इत्तला हासिल कर ली गई? ६ महीने इंतजार किया इस बान का कि असेम्बली की मर्जालस और बैठक हो और हम उसमें जायं तो हम अपनी तकरीर को उन मिसालों से जीनत दें। मे समझता हूं कि यह किसी ऐसे शख्स के लिये जिस के कंधों पर जिम्मेदारी नहीं रक्खी है मै मानता हूं। मेरे दोस्त राजाराम शास्त्री मोशिलिस्ट पार्टी के मेम्बर है। इस वक्त एक गैरिजिम्मेदार जमात है लेकिन खुद इस के साथ-साथ खुद उनके कंधों पर एक नमाइन्दगी का बोझ रखा हुआ है। यह बोझ हर उस शख्स के कंधों पर है जो इस ऐवान का मेम्बर है। अगर मुझको और इधर और उधर के बैठने वालों को अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास करना जरूरी है तो मैं समझता हूं कि इस एहसास से राजाराम जी भी बरी नहीं है। उन पर भी वह जिम्मेदारी आयद हैं। किसी बात को इस ऐवान के सामने रखने से पहिले हर शख्स को वाजिब है कि वह उस बात के मुत ल्लिक पूरी तहकीकात के साथ यकीन कर ले कि हकीकतन ऐसा ही है तो वह इस बात को कहने के लिये खड़े हों। वरना वह इस बात के हरगिज मुस्तहक नहीं है कि कब्ल इसके कि वह पूरी तौर से तककीकात न कर लें वह उस बात को न कहें। यह न इंसाफ की बात है और न माकूलियत की बात है कि हर बात बिला तहकीकात के यहां पर कह दी जाय। मै तो किसी की खिदमत में बेअदबी की जर-अत नहीं कर सकता। यह ऐवान और इसके मेम्बरान बड़ी इज्जत के मुस्तहक हैं। में इसको इज्जत की निगाह से देखता हूं। में इसके साथ-साथ यह कहने पर मजबूर हूं कि मेरे दोस्त ने उस तहजीब और उस एटिकेट को अपनी तकरीर मेने सामने नहीं रखा जो इस ऐवान के शोयानशान है। उन्होंने बेजा तौर की शिकायतें अपने बयान में इरशाद फरमाई और इस ऐवान के सामने पेश कीं। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जिस तरह से मेरे नोटिस में आयी हुई शिकायतें गलत साबित हुई उसी तरह से वह भी यकीनन गलत होंगी। अगर मेरे दोस्त खुद ही तकलीफ गवारा करेंगे और उनकी निस्बत तहकीकात कर लेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि उन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है। मेरा असली मकसद जिसकी वजह से मै अर्ज करने खड़ा हुआ यह था कि इस किस्म की शिकायतें जो की जाती है उनकी निस्बत मर-कार का रवेया क्या है? हुक्काम का रवेया क्या है? मैं खुद क्या करता हूं जैसा मेंने अर्ज किया। आपने तो यह किया कि जो कुछ अर्थ को मिला इह ऐवान के सामने रख दिया सही हो या गलत, इसकी आपको कोई तहकीकात न 👸 कि सही बात ही ऐवान के सामने रखें। मेरे दोस्त की उस तकरीर का खुलासा जो उन्होंने इरशाद फरमाई कम से कम उतना हिस्सा जितना मैने सुना यह यह है कि जितने चैपटर्स उस तकरीर के थे वह लगान की वसूलयाबी के मुताल्लिक शिकायतों के थे जो तेज रफ्तारी के साथ बयान की गई। उसके बाद उन्होंने कुछ तवज्जह बिल की

इसके बाद उन्होंने कुछ बिल की तरफ इशारा किया और यह फरमाया कि जमीं— दारी २४ घंटों के अन्दर खत्म हो सकती हैं। हां, सही हैं। जब मेरे दोस्त तकरीर कर [माननीय ना । जी ।क निर्माण सनिय]

नहें तता सं राष्ट्रांचा परता था कि नहीं विशेष राजनार पाना करता चलू अन्द्रों जा कि साना पान प्रतास भी जिसा पर और ता भी पमा मजाई। बहाँ ता जा कर तो गात कात भगर के उन्हें तथा पर ने की विशेष के लाने के जिस हर तो उत्ताह कि द्वानी ते जी के तिला ने ने साथ पर व व अजली इस लक्षराण के जिल्ला पान खदीन गाता अल्वो को साथ साथ पर जुनिया के अन्दर लांच नक्द घो के अल्बर की वाले नहार जाना सामा मणान अथा। जगर उसे बनिया में का लांक की कि विशेष का कि तो कि हमारे बोरन से किल्ला के देश के जाता की है।

कानत रा राही गानन है पन्त पह गा िशी है। जिस जसा । सरे दोल बनला रहें है। है दारा नारिजा शा तमी पह न । निकाला है। जिस उन्न देश होना ने बानन पास है दिया, उसरे पह होते हा परेरन, जानन-फानन पह जमादारी उन्म लन मना हो जावनी। पहले शायद, शुना यह है कि गजनमन्द आएका भी उन्म कोई आहित्ता रपतार अपनी एवं दफा है इस हालन के जन्दर दे। किश्म की कि गजनमन्द इसकी जगर किशो वजह से परिलाहन न कर सह तो उसका ऐसा तरने हा हक है। क्या हस का मनलब यह है कि गजनमेण्ट न चारा हो यह है कि हम उस काना पो बना फर और आइन्वा १० साल तक जमोतारी का बनाये रक्ष्य है कि हम इस काम का परना भानते के मृतास्तिक देनना ययीन रहा सफते हैं। स्या जिस नरीह से हमने एक काम का वरना चाहा है उसके करने में किसी हिस्स की बाजा या रकावद, किसी किस्स की कोई दिक्कत दूसरी तरफ से पेडा नहीं आएगी? उसी क लिख एक तहक्कुज ह शोर पर एक वक्षा उसके अन्दर रक्की गई है।

एक बात यह मेरे यास्त न फरमाई हिसाहब जो हम कहते हैं आर को गवर्नमेख कहती है इस कानून के मुताहिलक उत्ताव क्या फर्क है है फर्क उन्होंने यह यत्लाया था कि साहब जिनके पास जमीने जायद है उनत क्यार जिनक पास बन है उनकी दे को। में अगर राही समझा तो यही उन्हाने अपनी तकरोर म एन्याद फरमाया था। हजर बाला, यह बात बडी उन्या है, इसकी मान लेगा वाहिये हर राग्स की । मगर यह भी सीचे आप कि मेरे बोस्त को यह तजुर्या हो रहा है कि गवर्नमेण्ट जपने विमाग की यजह से उनकी इस बात को नहीं मानगी है। बया इस म्बाइ. के ऊपर कोई पीकर ओपी-नियन इकर्ठा करने की कोशिका की है? हमारे सोशलिस्ट आई भूमिधरी के ग्वये की वसुलयाबी के निलसिले में मुन्तलिफ जगही पर मन्तलिफ जलसे और तकरीरे करते है, उनसे तरह-तरह की बातें बहते हैं। खर, जो इस तरह की बाते करते हैं और इस ऐवान में अपनी तकरीरों के जिन्ये प्रोपेगेण्डा करते हैं वह बुनिया के सामने इस बात का एलान करे कि हम इस बात के हामी है कि जमीन जिन काइत कारो के पास जायब है उनके पास से लेकर उन काइतकारों को वे वो जिनके पास कि जमीन कम है। में एक इंसान की हैसियत से, इस सुबे का एक शहरी होने की हैसियत री अपने बोस्त को बाबत देता हू कि वह इस स्बे के अम्बर इस प्रोपेगेण्डा को करके एक पहिलक औपीनियन इसके फेबर में कायम कर वें और गवर्नमेन्ट से इस बात को करा गवनंमेण्य ती पब्लिक के लामने सर भूकाती है। नहीं माने तीयह गवर्नमेग्ट न माने लेकिन जुरैत नहीं है इस बात की कि उन काइतकारो के सामने यह कहे कि ऐ कम्बख्नों, तुम इतनी जमीन लिये बैठे हो और ये तुम्हारे छोटे भाई हैं जिनके पास कुछ नहीं हैं, इनका गुजारा नहीं चलता है, यह क्या नाउन्साफी है। इसलिये तुम कुछ जमीन अपने जन छोटे भाइयों को वी साकि उनका भी गुजार चले। इसके लिये पंडिलक ओपीनियन पैदा करने के लिये सोशलिस्ट नहीं खड़ा होता है। उसको कम से कम इतनी पुरंत नहीं होती हैं कि काश्तकारों के अन्वर खड़ा होकर के इस बात की राय कायम करे और यह कहें। यहां तो कह दिया। वह जो गाव में

आदमी रहता है उस बेचारे को क्या खबर कि किसी ने क्या कह दिया। वहां तो बाते बिल्कुल मुख्तिलफ किस्म को और यहां कुछ और। अगर यह फायदे की बात है और काक्तकारा का इसके अन्दर फायदा है, काक्तकारों को में, छोउ दीजिए, मुन्क का फायदा अगर इसके अन्दर है, तो क्यो नहीं वे इस काम को करते ह? कौन सो बात उनको ऐसा करने से रोकती है? मिर्फ यह बात कि यहां इम ऐवान में छड़े हो कर के किसी का किटीसिज्म कर दो, चाहे जिस तरीके से भो कर दो, और चाहे जो कुछ कह दो, यह कोई हिम्मत, बहादुरी आर जुर्रत का काम नहीं है और यह स्ट्रेट फारवडनेम नहीं है। जिसको पिन्छक की खिडमत करनी है उसे स्ट्रेटफारवर्ड होना है, उसको हिम्मत बाला होना पड़ेगा और सच्चा होना पड़ेगा वौर किसी खौफ के के चाहे उसको काक्तकार गालियां देने लगे और चाहे उसकी पार्टी उसको पसन्द करे या न करे। लेकिन सच्ची बात कहने में आपको देर नहीं करना होगा।

श्री र।जार म शामस्त्री—एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन (व्यक्तिगत स्पटीकरण) के तौर से मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि अत्यने यह जो बात कही कि मैने यह कहा कि किसानों से जमीन ले लो और जिनके पास नहीं है उनको दे दो, इसके बारे में में सिर्फ इतना ही बता देना चाहता हूं कि जिन जमींदारों के पास करोड़ों बीघा जमीन है उन की आप कोई अपर लिमिट (उच्चतम सीमा) काण्म कर दे और बाकी जमीन उनसे लेकर जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें दे दें। मैं इस चीज को चैलेंज करने की तैयार हूं कि

माननीय मार्वेजिन क निर्माण सिंचय--मुनासिंड है, जमीदार से लेकर ही तो काक्तकार को दी जा रही है। वह शख्स इम कानून को समझा नहीं जो यह कहे कि वह जमीन जो काक्तकार के पास ज्यादा है उसे लेकर काक्तकार को दे दो। तो यह और किसको दी जा रही है ? जो जमीन परती है जो काक्त में नहीं है वह जमीदार से लेकर के गांव पंचायत वो दी जा रही है कि वह उसको सेटिलमेंट (बन्दोबस्त) कराके खेती करावे।

श्री राजाराम शास्त्री--खुदकाश्त और सीर को आप कम नहीं कर रहे हैं। कहां आप ऐसा कर रहे हैं?

माननीय सार्वजिनिक निर्माण सिचिय--इस कानून में इसके मुताल्लिक लिखा हुआ है कि पंचायतों के सुपूर्व कर दी जावें और वे वक्तन-फवक्तन जरूरत के मुताबिक उनका बटधारा करती रहे।

श्री राजाराम शास्त्री -मै चाहता हूं कि आप इस बात को वतावें कि खुटकारत और सीर, जहां ज्यादा है वहां आपने जसको कम करने का क्या तरीका रखा है?

माननीय माल सचिव--जब में खड़ा हूगा तब बतला दिया जावेगा।

माननीय सार्वजनिक निर्माण सिचिव—जनाबवाला, मैने जो अर्ज किया वह यह है और मैं उस पोजीशन को फिर स्टेट करता हूं इसिलये कि उसकी निस्वत कोई गलत—फहमी न रहे, जितनो करल एरिया की जमीन है उसमें से जो काश्त की जमीन है उसके लिये तो जो कुछ है इस कानून के अन्दर लिखा हुआ है। अब वह जमीन जो और पड़ी हुई है वह भी जमींदार से निकल कर काश्तकार कम्यूनिटी के पास पहुंचेगी। वह एक काश्तकार के पास नहीं पहुंचेगी बिल्क वह काश्तकार कम्यूनिटी के पास पहुंच जायगी क्योंकि उसकी जुमला कार्यवाही उस गांव के पंचायत के हाथ में हो जायगी। इससे ज्यादा किसी और कानून में और क्या लिखा जा सकता है? आज क्या कानून में यह लिखा जाता कि नत्यू को फलां जमींदार से जमीन लेकर दी जाये या बलदेव सिंह को फलां जमींदार से जमीन लेकर दी गई। क्या यह कानून में लिखा जाता है? कानून ने इसका ढंग मुकर्रर कर दिया है। उसको मौका दे दिया गया है। उसको अपार—च्युनिटी दे दी गई है। उसके लिये एजे सी कायम कर दी गई है लिहाजा इस प्वाइंट

, पाननो । पा रंजनि इ निर्माण सचित्र

के इद्भार एक ज्यादा बहुत ते. तक जाह करने की तमरा ने । १ हो है है ही जीकि मेरे होरत । पनी तकरोर में उनके भागी का फरावार का मार्थ में मेरी राजाराम की ने जो बाल नदाई की उसके र जिल्हा है। एक राज सने यह मान उसिक्य योग को भी बज़ोड़ पर्ने झासार के कि सरम क लास पता हो उसके विभाग स यह बात राग ठी। नहीं रा

एस बात और रेजि कि मुतारि रह म हुए पर्ने धरना नाहना है। न र गा जमोदारी की मंद्ती शालाएं कहे उत्ती रद्ती का फायटा अभी गुन्ह के जिये दाना आम तीर से समन्न किया गया है और धर्माकण्ड पार्टी भी उत्तम उमार नहीं करती । और कहनी है कि जनोंबारी मणा होती लाहिये उत्त गुरु नी है लेकिन साथ ही चाहनी है कि अभी न हो। (एक आयान-कमी न ा,) मेरे दौरत इसके माहिर है। वह महा से ज्यादा जानते है लेकिन जितना प जानता ह करता है कि सींशलिस पार्टी का प्रोपेगेन्या यह है कि वह जधीदारी की मपुर्श तो चाहती है लेकिन इस वयत नहीं । और जो मृजाविज्ञा जभोदारों को तिया जाये उसके मुतालिक उनको एतराज हैं । हमारे दोस्त रोशन जमा गा स.हब ने जब अपनी पिछली तकरीर में इसके मनाहिलक कहा था तो उस बक्त भी मैंने अर्ज कर विया। आज हमारे बोस्त ने इसकी उलट करके दूसरी शक्य म पेश किया है, जिसका मतलब यह है कि मुआविजा तो दो लेकिन करो क्या ? टेक्स लगाओ। वह अल्फाज जिल पर कहा कि देखेल जगाओं वह किय पर लगेगा। यह तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन में समसना है कि देवस जो लगेगा वह काइसकार के अलावा किमी और आदमी पर लगेगा।

इसके मुनाल्लिक मं वी छोटो सी बाने अर्ज करना चाहना है। एक ती यह कि मं अपने वोस्त को वानिंग वेला हू कि अगर कभी भी अब नहीं १०,१५,५० वर्ष में हकुमत करने का इरावा है तो ऐसी गलत बान यह कभी अपनी जबान से न निकालें जो दुनिया के सर्मान्त्रमा उत्त के विलाफ हो। (एक अवाज-जिनको कभी उम्मीय न हो) यह मही हो सकता है। किसी सोमाइटो या किसी मृत्क को लो या किसी भी नेजन को ले लों लेकिन कहीं भी आपकी यान नहीं पायेंगे। एक काम के करने के वास्ते जिसमें फायवा इब्राहीम का हो या इब्रालीन की क्लास का हो जिसमे वह ताल्लुक रखता हो तो उसका बोझा किमी दूसरे पर दाल विया जाय । टॅक्सेशन के प्रिसिपल के लिलाफ, इसाफ के लिलाफ यह बीज हैं। इस ऐवान के बाहर अगर यह कहा जाय कि किसी और पर टंक्स लगा वो तो मुनने वाले जो हं वह यह समझेंगे कि भाई इन आर्थामयों की बाट न देना चाहिये, खुदा जाने कल क्या करेंगे। नावान बोस्त और वाना दुरमन इसका हमं मुकाबिला करना पहुँगा। तो यह बात दिल में लाना मनासिब नहीं है।

कहा जाला है कि काइतकारा के पास नहीं है। किसने काइसकार की मजबूर किया कि तम दी। सरकार ने ती किया नहीं। सरकार ने खला हुआ कानून बनाया है कि यह बीज तुम्हारे फायर के किये क्यों जाती है जगर इसका फायबा हासिल करना चाहते हो तो अपनी शुक्षी सं, वर्षण विस्ती जब के तम्हारे लिये यह है। मेरे दौरत जो यह बलील बेले हैं उनकी यह लक्ष्मीर तभी मीज होती जब सरकार ने काश्तकारों के ऊपर जमीबारों की मंसूल करने के लिये कोई देवस लगाया होता। किसने कहा कि देना होगा। किसी ने नहीं कहा। लाखों में अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसका बिल यह चाहे कि जो जीज मुझे इस कीमत में वी जा रही है वह मुनासिब है, उसे के लिया जाय। लेकिन उसके साथ यह कहना कि जबरवस्ती कर रहे हो, एक बात

जिसके अन्दर है नहीं थ्योरी के हिसाब से या प्रैक्टिकल के हिसाब से और दुनिया की फिजा को मुकद्दर करने के लिये मिसालें देना मेरे नजदीक कोई फेयर प्लें नहीं है। कोई माक्लियत नहीं है। से तो यह कहा है कि देना है तो दे और नहीं देना है तो न दे। मंतू बी का कानून तो बन रहा है। मुझे हुजूर, ज्यादा तकरीर करना है। मेरे दोस्त ने एक फिकरा कहा, मुमकिन है कि मैने गलत सदझ लिया हो, कि यह कानून कुछ हम को आगे नहीं ले जायगा। आगे ले जाने के बना माने मेरे दोस्त की निगाह में हैं ? किसी की निगाह में पीछे हटना भी आगे ले जाने के मतलब रखते हों। दरअसल वह तो हो पीछे जाना लेकिन वह उसको आगे जाना बतलायेगे। मै यह ममझा नहीं कि मेरे दोस्त का आगे ले जाने मे क्या मतलब है ? लेकिन अगर आगे ले जाना यह भानी रखता हो, वह यह समझते हों कि आगे ले जाने से यह मुल्क आईदा अपनी सोंसाइटो की तरककी में एक बहुत आला और अच्छे दर्जे का मुल्क हो तो में तरदीद के खोफ के वगैर पूरे यकीन के माथ इस ऐवान में अर्ज करता हूं कि इस वक्त तक दुनिया की तवारील में किसो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जानें के वास्ते इतना सच्चा कदम नहीं उठाया गया है जितन। कि यह सरकार उठा रही है।

*नाननीय प्रधान सिचव के सभा मंशी (श्री चरण सिंह)—माननीय डिप्टी इस सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करते हुये आज ६ स्पीकर साहब! दिन हो गये। बदिकस्मती से मैं श्री रोशन जमां खां की तकरीर सुनने से वंचित रह गया और खुशकिस्मती यह हुई कि शास्त्री जी के भाषण का बहुत बड़ा अंश सुन पाया हूँ। हो सकता है कि किसी बात का जवाब देने से रह जाय तो मेरा काम अकुर साहब पूरा कर देंगे। जो, हमारे दोस्त श्री राजाराम शास्त्री का तकरीर करने का ढंग है, वह मुझ पर नहीं आता, जो गर्मी, गुस्सा, गर्द व गुबार वह उठा सकते है, वह मैं नहीं उठा सकता । बहुत थोड़ी देर बोलने की कोश्चिश करूँगा, केवल एक घंटा बोलूंगा और केवल वहीं बातें इस ऐवान के सामने रखने की कोशिश करूँगा जो इस बिल से ताल्लुक रखती हैं।

आपने एक बात यह फरमायी कि इस बिल का एक उद्देश्य यह है कि जो आने वाला इन्क-लाब है उसको किसी न किसी प्रकार से रोका जाय, जिस क्रान्ति का आप स्वप्न देखते हैं, जिसको आप ऋ न्ति समझते हैं उसको यह बिल रोकेगा। यह अपका चार्ज और इल्जाम इस सरकार के ऊपर है। देखनायह है कि आपका यह इल्जाम कहां तक सही है। इसका जवाब उसमें आ जायगा जब कि मैं यह अर्ज करूँगा कि जमींदारी हम क्यों खत्म कर रहे हैं, उसके ख़त्म करने के क्या उद्देश्य है और वह सब उद्देश्य इस बिल में आया पूरे होते हैं या नहीं होते है। जमींदारी को खत्म करने के जहां बहुत से कारण हैं उनमें तीन कारण प्रधान हैं, जिनकी बाबत में अर्ज करूँगा। पहला यह है कि केवल पोल्टिकल इंडिपेंडेंस ही हो और हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार मिल जाय, इसी से पूर्ण रूप से कोई मनुष्य मुखी और स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता । इसलिये यह जरूरी है कि हर मनुष्य अपने रोजगार में भी स्वतन्त्र हो और जब तक जमींदार और काश्तकार का रिश्ता रहता है तब तक किसान अपने रोजगार में भी, खेती करने के काम में भी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं रहता। इसलिये हम जमींदारी को खत्म कर रहे है ।

दूसरी बात यह है कि जमींबार निठल्ले और निकम्मे बने हैं। करने वाले की कमाई में से कुछ हिस्सा बटा लते हैं। खुद बिना कमाये खाते हैं, और रुपये का दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग जो काम करते हैं उनकी कमाई से हिस्सा बटा लिया जाय, उनकी कमाई का अंश ले लिया जाय, और दूसरे लोगों को बिना कमाये मिल जाय, वे कमाने वालों की कमाई से हिस्सा बटा लें यह इंसाफ पर आघारित नहीं है। यह महात्मा गांघी ने बताया। इसलिये

श्री चरण सिंह रे

क्षतीवारी को काम किया जा रहा है। दूसरी बात जो मेरे लाय ह वोन्त ने फरमायी वह मैं तरलोम करता हू ओर जो रिपोर्ट में है वह भी कि जमीर कुवन्त की देन है। जमीन को रखने का केयल उसकी अधिकार है जा मेहनत करता हो। आने उसे उस प्रकार रखा कि चृक्ति कुवरत न जमीन पंवा की है, इसलियें सारें ममाज को उसका माणिक होना चाहिये। म उसकी दूसर तरोक से रख रहा ह कि चिका अमीन कुवरत ने पदा की है इसलिये उसी आदमी का रखनें का अधिकार है जा उसका सद्याग कर और उसम परिश्रम करके अपने लिये तथा अपने वेशवासियों के लिये भोजन और दूसरी नोज पदा करें।

इन तीन कारणो से हम जमीदारो लत्म कर रहे हैं और इन्हां तीन बाता से निकल आता है कि अमीदार ितमको कहते है। जमीदार के यह माने नहीं है कि जो शहस जमीन का मालिक हा। आप गालिबन यही समझ हा जमीदार के माने यह हा कि जो शरस यूनर पर हावी रहता हा पी रू उसून के मताबिक। दूसर यह कि दूसर की कमाई से हिस्सा बटा लेता हो। और तीसरे यह कि उसका उसने अधिक और जायद ममीन पर अधिकारही जिस पर यह स्वय परिश्रम नहीं करता है। इन्हीं तीर बानों ना मबदे नजर रत्यकर काग्रेग वांक्ष्य कमेटी ने विषम्बर सन् १९४३ : म जमींवारी की खत्म करते का निर्णय किया ओर जसा कि आगे चलकर एरेक्शा मनिर्फस्टो में ज्ञामित्र किया गया, और जिसकी बिना पर अगस्त सन् १९४६ ई० में इस सरकार ने प्रश्नाव पास किया। उसकी सफाई यह ह कि किसान का सीधा सबध राज्य से हा, और बीच में, मध्यवर्ती जो है, विचोलियां जा हं, उनकी निकाल दिया जाय। तो जमींदार का भतलब यह नहीं है कि जो जमोन का मालिक है बल्कि यह शक्न कि जो बठा रहता है, जो दूसरे के सहारे रहता है, दूसरो की कमाई जाता है और जिसका नाम उमसे ज्यादा खेत पर वर्ज है जिसमें यह वाकई खती करता है जिस पर उसका कोई हक नहीं है तो वेखनायह है कि हमारा जो बिल हे वह उस उद्देश्य को पूर्ति करता है या नहीं। इस मस्विदे के अन्दरहर उस शक्स को कवाह उसकी कुछ भी मोजवा ही सवत वया न हो, चाहे काइत-कारहीया जमीवारही हो या शिकमी ही, जितनी जमीन में बह हरू चलाता है वह जमीन उसके पाम रहेगी वह उससे कभी बेदावल हो नहीं सकता। जो जितनी जमीन में मेहनत करता है वह उससे अलग नहीं किया जा सकता। जो आज जमीबार कहलाते हैं लेकिन जितनी जमींन में आज यह मेहनत करता है उसका उसके पास रहने का कानूनन हक है और दुनिया उसूलों के मातहत भी लेडलाड वह नहीं, शोधक नहीं है वह उस कमाई का क्रीवण नहीं करता इसलिये उतनी जमीन उसके पाम रहने वे रहे हैं जितनी जमीन कि उसके पास है जिसका वह शोषण नहीं करता बरिक जिस पर वह मेहनत करता है और हम इसके लिये किसी तरह से भी तैयार नहीं है कि जमीन उससे छीन लें। इसलिये जहा तक उस जमीन का ताल्लुक है जो कि चाहे ५० एकड़ से ज्यावा ही क्यो न हो उसमें और काइतकारों में हम कोई फर्क नहीं करते। आपने अभी हाफिज साहब की स्पीच के बौरान में एक इन्टेरप्तान के सिलसिले में कहा था कि अगर ५० एकड़ से ज्यावा जमींगर केपास हैती ले लेना चाहिये और अगर ५० एकड़ से ज्यादा काइतकार के पास है ती उससे नहीं लेना चाहिये। यह कोई उसूल नहीं है। यह तो कोई एक्स्प्लायटेशन की, शोवण की अन्त करने का जो उद्देश्य है उसका तो यह अर्थ नहीं हो सकता कि आप जमींबारों से ज्याबा जमीन ले लेवें और किसान से न लेवें। हां, अगर आप यह कहते कि ५० एकड़ से ज्यावा चाहे काइतकारों के पास भी ही ती भी ले लेना चाहिये तो समझ में आ सकता या। लेकिन आप तो यह कहते हैं कि जमींदारों के पास अगर ५० एकड़ें से ज्यादा हो तो ले ली जावे और अगर काइतकारों के पास हो तो न लेवें। ५० एक इ से ज्यादा जमीन किसी के पास है क्वाह जमींबार हो किसान हो क्वाह उसकी कुछ ही हैसि-यत क्यों न हो हमने हर उस आवसी के पास उतनी अमीन छोड़ी है जितनी पर वह खेती करता है हरू चलाता है क्वाह उसकी हैसियत कुछ ही क्यों महो। अब इसके अलावा हमने

यह भी लिहाज नहीं किया कि इन्दराज की नवइयत क्या है, जमींदार है लेकिन सीर की जमीन दूसरों को उठा रक्खी है। बावजूद इस बात के भी हमने इसकी परवाह नहीं की। हमने सीर के काश्तकार को जिसको आज तक कभी कोई एश्योरेंस नहीं था कि हक मिल जाय उसको भी हक दिया। नवइयत क्या है, क्या दर्ज है इसकी भी इसमें परवाह नहीं है। इसके अलावा यह भी नहीं है कि जिन ३५ लाख का जिक आपने किया कि साहब जबरदस्ती जिनके नाम कागजों में दर्ज है उन्होंने इतना जुन्म किया है कि जमीने छीन लीं। जुल्म हुआ है उसको हम तसलीम करते हैं इसमें हम आपसे पीछे नहीं हैं। फिर भी ऐसे ३५ लाख आदमी नहीं हं फिर भी कई लाख आदमी ऐसे हैं जो कि जमीन में बहैसियत बगैर तसिकया लगान के दर्ज है। मैं तसलीम करता हूँ, गवर्नमेट इस बान को स्वीकार करती है लिहाजा गदर्न मेंट ने अपने उस नारे के मातहत जिसकी सन् १९३१ से यहां की कांग्रेस पार्टी ने यू० पी० में उठाया और जिमे सन् १९४६ ई० में अपने मैं निफेस्टो में कांग्रेत ने स्वीकार किया गवर्न नेंड ने यह एलान किया कि कितान उसकी कहेंगे जो कि खेत में मेहनत करता हो, उसमें हल चलाना हो, तो हनने उस नारे के मातहत जमीनें देने का विवार रखा है। उस आदमी को भी जो कि काइतकार दर्ज नहीं है लेकिन उस जमीन में ३० ज्न १९४९ ई० से पहिले विलात सिक्यालगान भी दर्ज है। में विलाखौक व तरदी द के कहना बाहना हूँ कि दुनिया में किमी भो पोन्टिकल पार्टी (राजनीतिक संस्था) ने अपन उपूर्वा को इस इमानदारी से जा कि वह बरमरे इक्तदार हुई कभी किसी कानून में नहीं निभाया जिस तरह से कि इस यू० पी० की कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट में आने के बाद निभाया।

(इत तत्रय ३ बजकर ४८ मिनट पर सभायित्यों की सूबी के सदस्य श्रो हारिका प्रसाद मौर्य, सभापति के आसन पर आसीन हुये।)

मैं वैतो बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं यह जानना चाहता हुँ अगर किसी को मालूस हो तो अगर तकरीर करने का मौका मिले तो बजरिये तकरीर के या अखबारों में तहरीर देकर, दुनियामें कभी किसी मुल्क की गवर्नमेंटने, किसी मुल्क के इतिहास सेयह मसला निकाल कर बता दें कि जिस तरह से अन्त तक जानेवाला, जिस तरह से एके उसूलें से मबनी पहिले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, पहिली दफा से आखिरी दफा तक हमारा बिल है, उस तरह का कभी किसी मुल्क की किसी गवर्नमेंट ने बनाया है और इसी तरह से एक कलम ज्यानींदारी खत्म की हो। वया माने हैं इंकलाब के? आप अक्लमंद हैं, इंकलाब होगा, रि बोल्यूबन होगा, इसलिये उसे रोकना है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन्कलाब करेगा कीन? रिवोल्युशन करेगा कौन? जहां तक किसान का ताल्लुक है, न तो किसी किसान को हमारे बिल से शिकायत है और न हो सकती है। चाहे बहैसियत मालिक दखीलकार काइतकार, मौक्सीदार काइतकार, साकितुलमिल्कियत काइतकार, दवामी वाला काश्तकार, इस्तमरारी वाला काश्तकार हो या रिआयती लगान वाला काश्तकार या माफीदार हो, यहां तक कि जो शिकमी है, उसको भी; इससे बढ़कर जिन लोगों का नाम ठेकेदारी में दर्ज है, जो सीर की जमीन उनके पास है वह तो वापिस होगी, लेकिन बिला सीर की जमीन, अगर दौरान ठेकेदारी में उन्होंने काश्त की है तो वह भी उनके पास रहेगी। इसी तरह से मुर्तहीन के पास भी। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि वह जमीन जो बिला तसिकया लगान के दर्ज है वह भी उनको मिलेगी। इस हद तक हर आदमी को जमीन दी जा चुकी है तो में समझने से कासिर हुँ, मेरी अकल के बाहर है कि आया वह कौन सा किसान रह गया है जो इन्कलाब करेगा जिसकी वजह से हम डायर कांसीक्वेंस की भविष्यवाणी करें, डरवायें, धमकायें कि यह होगा वह होगा। तो यह इसलिये जो आप कहते हैं कि रिवोल्यूशन को रोकने के लिये हम यह कह रहे हैं, यह बात बिल्कुल गलत है, प्रोपेगेंडा है, बेकार की बात है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह रिवोल्यूशनरी, ऋांन्तिकारी योजना है जो कि अपना शानी दुनिया के इतिहास में नहीं रखती। हर शहस के पास वह जमीन रहने दी जा रही है

ध्यो चरण सिह जो बार्क्ड उसके हरू के नीचे है, बिका लिहाज होनयत के, विकारिशा रकने के और बिला जिलाक नवयत के। तो ऐसी जितनी जमीने हैं वे उनके पास रहेगी। इसके अलाया जितनी गेर मजरा अमीन ह, रास्ते ह, तालाब हा, राश्हिन, आबादी जजर, बजर, दरकत, जग नात, किबस्तान, इमशान, गिलगारे, पनपट, गुध हाट, बाजार, मेला लगने के स्थान और अगर कोई विरयाही तो उसके घाट वगैरत, मेरे कहने का मा ज्यांक जितनी भी जायदाद, सम्पान, गाव के अन्दर राव के दरतेमा > की ह, वा सब की मिल्कियत मे दासफर की जा रही ह। जो किसी गाम शरस के इस्तेमाल की जमीत है यह उसके पास रहेगी, चाहे उसको कोई भो हेसियन क्यो नहां लेकिन जो नाके उस्तमाल की ह वह हम सबको वे रहे हा। मतलब यह हिक इंडिगोज नल की चीत इंडिवीज अंड गो, व्यक्ति की चीज व्यक्तियों का , और समाज की चीज हम समाज का दे रहे है। आपने फर-माया कि लेंड लेंग लेंगर की कुछ नहीं वे रहे हैं, जिन लोगा के पास जमोन नहीं । उनकी हम क्छ नहीं वे रहे ह। आया हम वे सकत थे या नहीं वे सकत यह नका म बाद में जिन्न करना। इस वक्त म यह जित्र करना चाहता ह कि लंडलेस लेगरर को उसका मकान दे रहे हैं बिला कोई उसका मुजाबिजा बिये हुये आज जिनने भी मजबूर गायो के अन्दर है वे लोग अपने मकान के मालिक हैं चाहे उनकी कच्ची ही शोपड़ी ही क्यों न हो और छोटी ही शोपधी क्या न हो थे अपने मकान के बाकायदा मालिक ह ठीक उसी तरह जितना कि जमीवार अपने महार का। जहां तक गैर मजर वा भीम रा ताल्लुक ही मजदूर, गैर-मजबुर, मारिक-गर, मालिक, गांव के जिलने भी बाजिब है वे सब हिस्सवार होते। यह बो चीजें ऐसी होगी जिनका कोई मुआबिजा नहा िया जायगा। यह तो हुई इसकी स्कीम । अब आपका कहना यह है कि सुबे की गवनं मेंट पत्तायती की यह अस्तियार दे वे कि यह मुझ्तका खेती कराये। हमारा उद्देश्ये इस कान्न से यह था कि यह जो शोषण हो रहा है बहु आगे न होने पाये और इसलिये हम इस जमीवारी की त्वतम कर रहे हैं और इसकी बानिया में दो हो तरको में ह, लीसरी को ! तरकीय नहीं हा। वह यह कि आया यहां की जमीन पर कोआपरेटिय पामिय कराई जाय या व्यक्तियत फामिय। यांव व्यक्तियत फामिय को हम ठीक समझते ह ता उसूल यही मानना परेगा कि जिसक पास जमीन हो वही खेती करें और यह दूसरे को लगान पर उस जमीन या न उठाये। आपने कोआपरेत्व फार्मिंग के बारे में फरमाया कि इस बिल में उनके मुताल्लिय कुछ भी नहीं है। उस समय ध्यान भी विलाया था लेकिन अपने अगसूनी करदो। इस बिल का आविरी अध्याय अगर कोआपरेटिव फार्मिग का अध्याय नहीं है तो क्या ह ? जहां तक को आपरेटिय फार्मिग की बात है दूर्निया भर के जिल्लान इस बात का मानते हैं, दूर्निया भर के आकरे इस बात को साबित करते ह लेकिन आपने तो फरमााया कि आर्क ने से आपको कुछ लेना महीं है आपको तो केवल आर्याडयोलाजी बतानी है। आर्याडयोलाजी के बारे में तो में केवल यही कहुँगा कि जिनके कंधी पर जिस्मेदारी है वह यह भी दल्लेंगे कि वाकई में हमारे समाज की हालत और वास्तविकता की देखते हुये कौन भी आर्याइयोलाजी यहा चल सकती है। आप तो यह नहीं देखेंगे कि यहां की स्थिति और हालत क्या है। आप तो जबरदस्ती लोगो के गले उतरना चाहते हैं चाहे वह आयंडियोलाजी किसी भूमि से पैबा हुई हो। हम परदेश की आयंडियोल की नहीं बाहते। हम तो बही आयंडियोलाकी बाहते हैं कि को हमाए वैद्या की परिस्थिति और हित का तकाजा होगा। यहां तो तिरगे झंडे की आयडियोलाजी ही चल सकेगी। महात्मा गांधी की आयब्दियोलाजी चल सकेगी। हम यहां दूसरे को आयबि-योलाजी की लावना नहीं बाहते बिना इस बात के देखे कि बाहे इस देश का हित उससे होता है या न होता हो। मैं आयंकियोलाजी के मुताल्लिक यह अर्ज कर रहा था कि वृत्या भर के आंकड़ो से यह यता लगता है कि किसी खास रकने के बाद यूनीफार्म लेड में कम होनी शुक होजाती है। बहुत से आंकड़ों के एक्सपर्ट कहते हैं कि २५, २७ या ३० के बाद कम होनी शुरू ही जाती है। किसी-किसी की राय में वह २० ही हू । कोबापर दिव फार्मिंग को, मेरी समझ में नहीं आता लोगों ने क्या जावू समझ रका है और यह कि व्यक्तिगत फामिंग में बहुत डिफी- कल्टो होती है। मेरी समझ मे जहां तक आया वह इसलिये समझ रखा है कि जितने में एक हजार चर्ले सूत पैदा करते हैं यदि उतने रुपये से एक छोटा मा कारलाना खोल दिया जाय तो ज्यादा लाभ हो सकेगा और ज्यादा मूत कत सकेगा। वे समझते है जो बात उद्योग-धंथों में लागू हो सकती है वही जमीन में भी लागू हो सकेगी और ज्यादा पैदावार वे कोआपरेटिव फार्मिंग के जरिये से कर सकेंगे। दे इस वात को नहीं ममझते है कि वह तो मेकैनिकल प्रोसेस है और ये वायलाजीकल प्रोसेम । आप किसी प्रकार भी खेती की आय को नहीं बढ़ा सकते। मैं इस विषय से माननीय स्पीकर ओर दोस्तों का अधिक समय नहीं लेना चाहता केवल इतना कह देना च हना हूँ कि यह जो लोगों का कहना है कि जितना बड़ा फार्म होगा और कोआपरेटिव फार्म होगा उननी ही ज्यादा पैदाबार होगी, मै इस बात को नहीं मानता हूँ। जितने देशों में बड़े-बड़े फार्म है उनके मुकाबिले मे उन देशों में ज्याद। पैदावार होती है जहां पर छोटे-छोटे होहिंडग्स है, यह आंकड़े वतलाते है ? यहां तक कि चीन जेसे देश में जहां हमारे यहां से छोटी-छोटी होतिंडगस है, वहां रूस, अमेरीका और आस्ट्रेलिया के सुकाबिले में फी यूनिट आफ लड ज्यादा पैदाबार होती है लेकिन में भी इस बहम को छोड़ देता हूं। और मान लेता हूँ कि मेरी राय शायद गलत हो। फिर सवाल यह कि अच्छा साहब की आगरेटित फार्मिंग होना चाहिये। मै उसके अवगुण पर नहीं जाना चाहता हूं, आगु मेट की खातिर मान लेता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है अरे होना चाहिये लेकिन क्या जबरदस्ती वह लोगों के ऊपर लाद। जाय। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वह इस का ही राम्ना हो मकना है, जो कि न हमको स्वीकार है और न आपको स्वीकार है। हनने इसमे दो किस्म के वालन्ट्री कोआपरेटिव फार्मिंग के तरीके रक्खे है। हमने इसमे यह रक्खा है कि जिस जगह कोआपरेटिव फार्मिंग छोटी होल्डिंग वाले दो-तिहाई किसान तयार हो जायेंगे तो हम एक तिहाई किसानों को समझा-बुझा करके उसके लिये तैयार करेगे। इस तरह हमको जुन-खच्चर का नज्जारा नहीं देखना पड़ेगा। हमने यह भी किया है कि जहां कोआप-रेटिव फार्मिंग हो जायेंगे वहां सरकारी प्रोत्साहन और मदद भी हम देंगे लेकिन किसानों को हम मजबूर नहीं करना चाहते हैं। जहां तक कोआपरेटिव फार्मिंग की बात है वह हमने इसमे रक्खा है। दूसरी बात यह है कि आगे एक्सप्लायटेशन न हो, उसके लिये भी हमने प्राविजन कर दिया है। इसके अलावा एक बात यह कही गयी कि आप इस कानून के जरिये रिवोत्युशन को रोक रहे हैं। रिव्योत्युशन तो आपके ही जरिये आने वाला है और कोई तो रिवोल्यूशन कर नहीं सकता है, आप ही ने रिवोल्यूशन का ठेका ले रक्खा है। दूसरी बात यह कही गयी कि यह भूमिघर जो बन रहे हैं यह जमींदार बन रहे हैं। अब मैं क्या वतलाऊं, मैं बधाई ही दे सकता हूँ आपकी इस दलील पर। आपने देखा कि जमींदार के माने हैं जो जमींदारी घारण करता हो । भूमिधर के माने हैं जो भूमि घारण करता हो, लिहाजा भूमिधर जमींदार हो गए, लेकिन हमारा भूमिधर शोषक नहीं होगा, वह जमींदार नहीं होगा जैसे कि जमींदार हम खत्म कर रहे ह जिनको आप उलहना देते हैं। आपकी दलील है कि साहब उन्हें हकूक इंतकाल दे दिया गया ह, हस्तांतरण की ताकत दे दी गयी है, इसलिये जमीन रिच आदिमयों के पास चली जायेगी। उसकी जमीन नीलाम हो सकती है, बय हो सकती है लेकिन वह ही खरीदेगा जो खेती करने के लिए तैयार हो। मान लीजिये आपकी जमीन नीलाम होती है, मै खरीदता हूँ और आपके हाथ से जमीन निकल जाती है तो इस से समाज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कहना कि भूमिघर को केवल राइट आफ ट्रांस्फर दे देने से कैपिटिलिज्मा, एक्सप्लायदेशन हे... ... जमींदारी हेगी है, आपकी जबान है, आपकी कलम है आप जो चाहें कहिये लेकिन कोई ईमानदार अपने सीने पर हाथ रख करके यह नहीं कह सकता है कि सब लेटिंग का जो प्राविजन हमने रक्खा है उसके रहते हुये किसी तरह का एक्सप्लायटेशन, कैपिटिलिज्म या लैंड ार्डिज्म फिर देश में पैदा हो सकता है। फिर यह कहा कि चन्द लोगों के पास ज्यादा जमीन है और ज्यादा लोगों के पास कम जमीन ह। यह ठीक है कि आयडियोलाजी की बात है और

श्री चरण सिह

यह उनके लिये ठीक हो सकी है जिनको केवल आर्या माना ते भग मिटाना है लेकिन क्या आप आक हे वे सकते ह। आज कल या साल भर के अन्दर कि किनने वह कम आदमी है जिनके पास ज्यादा जमीन है और सूबा के अन्दर किननी जमीन है। लेकिन नहीं और आपका कोई कमूर भी नहीं है क्यों कि लाएने क्रम वाली थी कि उसे देखेंगे ही नहीं। सब यह कहते हैं कि जमीन जी है यह अमीर आर्यास्था है हाथ में एकी जायती और वे मझी नों से खेली करेंगे। तो आपने हमने तसलीम भी किया था ए ह बार कि हमने ऐसा प्रतिबन्ध रखा है कि ३० एका से ज्याया जमीन किसी के पान आमे को नही वी जायगी। जब ३० एक इ से ज्यादा किसी को नहीं की नायगी तो जर्मान मल्टा डाई नहां हो यहना और किसी के हाथ में ज्यादा इकट्ठी भी नहीं ही सकता ह ती फिर आग की संदा हाम का सवाल ही कहा से आला है। ३० एक ए तक जमीन ए। फीमली जनने रिमास में है इन्तेर कर सकेगी। हमने इसकी भी इजाजत दे दी है कि अगर उसकी मजबूर रला का तमरत पर तो रख सकता है खास करके हारवेस्टिंग सीजन के मोके पर लो मजबूर रेखने की जरूरत पहले ही । आर यह रख सकेगा । लेकिन ३० एक इतक कि हमने एक लिमिट राजी है जिसम बिना मजबूर की सडायता के भी अगर किसी किसान को वो चार येंट्रे अवान है तो उनकी माद से वह खेती कर सकता है। चाहे उसको मजदूर मिले या न मिले। लेकिन जी बहे र फामंस है वहां पर तो ३० एकड़ की लिमिंग राखी नहीं जा समती और मशोनों के जीर वे लेती होते से वहां पर कीपिटिलिंग्स नहीं पैदा होते बाला है। लेकिन आपको कहना सक्सा या और आप ने कह डाला। जहां तक कैपिटिलिएम की प्रोत्साहन देने की बात है वह नी इस बिन के शब और प्रोविजन में नहीं है। हां आप के इमैजिनेशन में वह बोज होगी तो आपने कही। आप रिडिस्ट्रीक्न्शन की बात कहते हैं कि जमीन तक्ष्मीस कर वी आयं। ठी ह है, तक्ष्मीस कर विया जाय ती ठीक तकसीन तो वही होगा कि सब को बराबर-बराबर जमीन मिले और यही अच्छा भी होगा। वर्षोकि एक के पास १० ए हर ग्रमीन होगी और एक के पास १५ एकड़ जमीन रह गई तो फिर यहा पर भी के विकित्यक की बात या जाती है। दिन्द्राक्षा न के माने यह है कि सब जमीनों को नाप कर बराबर-बराबर है लिपत को जमीन हर ए है के पास कर की जाय। जहां तक रिकिस्ट्रीब्युशन की बात है आपने मात्रथ युरोग जोर खान के बारे में पढ लिया होगा। अगर आप का मतलब यह है कि लभी किसानों की जमीन का वागिल करके इकद्ठा करके बराबर-बराबर गज और फीले से नाप विया जाय और इतका माने की दिस्दी ब्यूक्तन होतो में समझता हूं कि आपका यह क्याल गलत है। रिकिन्द्री श्युशन के यह माने नहीं हैं और में सनसता हूं कि आप माने लगाते भी नहीं हैं। आपके हाक्टर राम मनोहर लोहिया ने फरमाया है कि हर एक किसान के पास साबे बारह एक कमीन हो और ५० एक प्रसा जमीन हो। एक बार उन्होंने ३० एक इ जमीन के लिये कहा था और बाद में २० एक इ तक आ गर्ये। आज २० एकड़ के बाव साढ़े बारह एकड़ रह गया। में यह कहता है कि २० एकड़ न सही, साढ़े बारह एकड़ ही मान लें तो हर किसान के पान नाढ़े बारह एकड कमीन होनी चाहिये में हर किसान लफ्ज कहता हूं। एक फेसिली बो-बी किसान तब रहते हैं। लेकिन आप किसान के माने परिवार कें तो यू वी के अन्वर कम से कम बाहे ज्याबा मे अगाता ७५ लाल किसान परिवार अगर ७५ लाम फेमिली को साढ़े बारह एकड़ के हिलाब से जमीन वे तो ९ करोड़ एवं इ जमीन चाहिये जिसमें ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन कल्डीवेटेंड है। और ६ करोड एकड़ जमीन जिसमें पहाड़, जंगल, शहर और वरिया भी है। यू० पी० का रकता ही ६ करोड़ एकड़ है। र करोड १३ लाख एकड़ जमीन हल के नीचे हैं जिनमें बागात भी शामिल है। तो में अपनी जाती है सियत से यह जानना चाहता हूं कि हमें यह बता विया जाय कि र करोड़ एकड़ जमीत और कहां से आ सकती है। आप हिमालय पहाड़ से या कस से ही खींच कर इतनी जमीन मगां वें तो हर किसान को साढ़े बारह एकड़ जमीन देते में हमें बड़ी लुशी होगी बहिक उससे भी आगे बढ़ कर हम बीस-बीस एकड़ जमीन हर किसान की बांटने के लिये लेवार होंगे। लेकिन आप लावें कहीं से पहिले तो ? आप लावेंगें कहा से ? आप तो किसानों को खुडा करने के लिये

यह कहते हे कि हर किसान को साढ़े बारह एकड़ जमीन कम से कम होनी चाहिये। उसके साथ-साथ शायद दो-दो गाये भी होनी चाहिये। पहिले तो दो ही गाय की बात थी लेकिन अब एक-एक होनी चाहिये।

तो में यह फहता हं कि आपको हमसे विरोध है, ठीक है विरोध रहे हमकी मुबारक है और हम इसको तसलीम करते हैं और जनतन्त्र राज्य की कामयाबी के लिये यह जरूरी है कि विरोधी पार्टी हो लेकिन वह विरोधी पार्टी किन उसूलों पर मबनी होनी चाहिये, उसका उसूल कोई तामीरी होना चास्यि ओर केवल अपोजिञ्जन की खातिर किया जाय तो उससे डिमोक्रेमी पनप नहीं सकती। यकीन मानिये कि जिस चीज को आप बचाना चाहते है उसकी यचा नहीं आप जिन त्रितियल्स को गलत समझते है, और हमारे लीडरों की नियन पर हमला करते है उससे इस देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुँचेगा। तो मैं जानना चाहंगा आप कभी भी बतला दे कि यह साढ़े बारह एकड़ का हिसाब किस तरह से मुमकिन हैं। अगर यह हिमाब ममिकन हो जाय तो हमारे माननीय पन्त जी पिक्त आदमी होगे और इधर के सब बैठने वाले दोस्त सब से पहिले अपने – अपने अमेडमेट लेकर दौड़ेंगे कि साहब इसके अन्दर यह अमेडमेट कर दिया जाय। मैं गवर्नमेट की तरफ से आपको यकीन दिलाता हं कि गवर्नमेट हर एक किसान को साढ़े बारह एकड़ देने के लिये तैयार हो जायगी। यह आपने जो रिडिस्ट्रीब्यूइन साढ़े बारह एकड़ का बनलाया यह नाम्मिकिन है। और इसके अन्दर एक बात ओर मोचने की है कि जितनी जमीन है उसकी बराबर बाटने के लिये ७५ लाख लाट पूरे हमकी चाहिये और उनके फिर टु कड़े करना पड़ेगे। उनका बराबर-बराबर टुकड़ा करने के लिये ५० वर्ष की जरूरत होगी। तोन वर्ष तो एक जिले के बन्दोवस्त करने में लग जाते हैं और सिर्फ इसमें जमीन की किस्म दोहराई जाती है उसके आधार पर सालगुजारी घटाई बढ़ाई जाती है। जब हम जमीन के बराबर-बराबर टुकड़े करने बैठेगे तो २० गणा तो स्टाफ मल्टीव्हाई करना पड़ेगा और ५० वर्ष इ तके रिडिस्ट्रेब्यूशन में लग जायंगे उस विभाजन में जिसका वड़ा भारी चर्चा है। आपका कहना यह भी है कि साहब जमीं दारों की जमीन बांट दी होती। फिर में जानना चाह गा कि जमींदारों के पास कितनी जमीन है। आप कहते हैं कि जिन जमींदारों के पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है उनसे लेकर उन लोगों को बांट दी जाय जिनके पास कम जमीन है। तो जैपा कि मैने अर्ज किया इसमें कोई सेन्स नहीं है-इसका कोई अर्थ नहीं है। यह कोई दलील नहीं है कि जिन जमीदारों के पास ज्यादा जमीन है उनसे ले ली जाय और जिन काश्तकारों के पास कम जमीन है उनको वह बांट दी जाय। मै शास्त्री जी से जानना चाहुँगा कि ऐसे कितने जमीदार है जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है। जमींदार कुल ऐसे यू० पी० के अन्दर है जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है। जमीन ९ लाख एक इं है। आम ५० एक इं उनके पास छोड़ना चाहते हैं तो इस हिसाब से साढ़े चार लाख एकड़ उनके पास छोड़ दी जायगी। बाक़ी साढ़े चार लाख एकड़ उन लोगों में तकसीम करने के लिये रह जायगी जिनके पास आप कहते है कि जमीन नहीं है। और हमारे पास जो जमीन है वह ३ करोड़ ४१ लाख एकड़ है अर्थात् काश्तकारों के पास कुल जमीन जो हमारे सूबे में है वह ४ करोड़ १३ लाख एकड़ है। इसमें से ३ करोड़ ४१ लाख एकड़ तो वह जमीन नै जो काश्तकारों के हलों के नीचे है और ७२लाख एकड़ ऐसी है जो जमींदारों की होल्डिंग (जोत) में है। तो इस रिजिस्ट्रीब्यूशन (पुनर्वितरण) के लिये जमींदारों से लेने का मतलब यह हुआ कि वह ४ लाख एकड़ जमीन ३ करोड़ ८५ लाख हो जावगी। तो इसमे कितना फायदा हुओं ? सिर्फ डेढ़ फ़ीसदी फायदा हुआ। १.३ फ़ीसदी जमीन और लोगों को मिल गई। आपने दलील में साढ़े चार लाख को बांटने का सवाल किया था। आपने जमींदारी अबालिशन रिपोर्ट में नहीं देखा उसमें यह लिखा है कि :--

Against this we must reckon the fact that it would arouse a spirit of opposition among the substantial cultivators, lendlords and tenants and would inflict great hardship up in the landlords, whose income will, in any case by reduced by our scheme for the abolition of zamindari.

श्री चरण पिह

inforce we nodertake such a measure we must as a stefully, not morely it the setient giventures but ilso ats practical mining

"(इसके साय-साथ हमको इस गांत का भी प्यान रामना पड़िया कि इसमे वास्तिकि कुल को में अर्थान् जमावारों और असामियों में पितवार का भारता उत्पाद पो जायगी। इससे जानीयारा को तहा करा होगा जिनकी आप, प्यारी जमीरारा "म् रा पोजना के कारण अवश्य ही घर जायेगी। ऐसा अर्थ करते के प्यार को उन्हें करते का ति ही नहीं आरत् कि सहस्त जपयोग का भी जनमार सर्थना है। उन्हें रेना नारिय।) '

स्वा आरको राजवींता है भानवारी का पहा तका जा है कि आप ने वह तो पह कि ति सह सह सह तो प्रवादा और अरान पह साति। हरून है। हो जिल्हें कि स्वादा और अरान पह साति। हरून है। उन्होंने कही कि स्वाद जी का वारों की बोरत है और वह ति इसा उन्हों हो ने ए हर है। उन्होंने कही कि ने हाति है में उन्हों कि साति। कि साति है कि ने अविवाद है कि ने अविवाद है कि ने अविवाद है कि ने अविवाद है कि ने कि साति है कि ने कि साति है कि सात

उसके बाव कहा गरा है कि जार जमीबारों में हा समीन के लाजिए बार्ट हाइनकारों से न लीजिए तो हम ऐता नहीं कर महते। हमारे किए जमीवार भा हमारा नामाइटो के ही आदमी है और हम उनसे कोई बुदमनी या बढ़ रा नहीं के रहे हैं बॉन्स एक मित्रान्त के मातहत हम अवनी कार्य गही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप की लगानली यही वाह रे में टोनी है कि हम कैपिडिलिस्टों (पूंजीपतियों) को मबद वे एहे हैं, किसानी की प्रिटा पर है, जमावारी की तावाव बढ़ा रहे हैं और वैश को कास्ति की और ले जा रहे हैं तो आप आजाव है आर नाहे जैता प्रोपेगेणा (प्रवार) आप करें। जहां तक युटिलिटी (उपयोग) की बात है आग देख ल कि साई ह लाल एक जमीन ७५ लाल फीमलाज (कुर्मेंबो) में बोटना है। आप हो बत गहए कि यह कैसे किया जाय और किस उसल से किया जाय। या कोई लाटरी पाली नाय और किस से लेनर एक एकड वाले को सबा ६ एकड़ बी जाय और किस तरह से यर किया जाय और किम तरह से बह तकतीन की जाय जिसमें बराबर है सियत की जानीन सब की ठी। तरह से निल जाय। अगर काम बात बन्दोबस्त वेल हर हम करेंगे तो आप सोवें कि इस काम में हमारा किता। समय नष्ट होगा और कितना राया लगेगा। हमतो एक निद्धान्त को लेकर एक गईक यवस्था कायम करने जा रहे हैं न कि यह बेखने के लिए कि किस के पास ४९ एक हैं और किसके पास ५१एक इहै। एक तो आप की दिस रिवोर्ट में बड़ान बस यही मालूम हुआ कि हमने इसमें रिजिस्ट्रीवप्तान (पुनर्वितरण) का कोई प्राविजन (प्रवन्धे) नहीं किया है। आप को ठाउँ बिल से यह सोबना चाहिए कि जिन के कन्धों पर जिन्नेवारी होती है उनकों सब बातो का खपाल करना पहला है और बेसना पड़ता है कि सौन चीख एक प्रेनिटक्ल शक्त अवितयाए कर सकती है और कीन नहीं कर सकती। हमें देखना है कि यह बीख कहां तक मुमकिन है मीर हमारा इस में कितना बेस्त और स्थ्या सक्तें होगा और उसके बाब हमारा उसके कोई सास फ्रायवा भी होता है या नहीं। इस तरह से आप सोचें कि आपको कितनी जमीन इस तरह से मिल सकती थी। हम तो सिर्फ एक उसूल के मुताबिक किसान को क्रायम रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं न कि यह कि जमीवारों से हमारी कोई बुहमती है और हमारा कोई ऐसा ध्येम है कि

उनको नुक्र भान पहुं वाया जाय। इस रिडिस्ट्रीब्यू इ.न से रुपया और वक्त जाया होता है और न किसानों का ही कोई फायदा होता है और फजूल की झंझट और परेकानी और वक्त नजाता है और देर होती है।

अब आप का कहन। यह भी है कि "नो स्माल होलींडरज" यानी छोटी ? होलींडरज (जोते) नहीं होती याहिए। लेकिन आप ने छोटी होलेंडिग्ज का कोई इलाज नहीं बतलाया। में जानना चाहुंगा कि आप के पात इसका क्या इलाज है ? म जानना चाहता है कि आपका ऐसा फहने से वया ननलब है ओर आप ही अगर इबर होते तो क्या करते? आप करते यह रिडिस्ट्रीब्यू जन ? ओर अगर करते तो बनाइए कि किस तरह में आप आप करते ? आप भी कहते है कि किसानों का लगान घटाना चाहिए और आप के सेठ दामोदर स्वरूप का भी भी यही नारा है कि लगान घटना चाहिए और क्सिन भूखों मर रहा है और वह दन गुना लगान देने के क्राबिल नहीं है। किसानों का लगान घटाने की बात सन् ३१ से ३७ तक हम भी ऋहते थे कि जब गरले का भाव सस्ना हो गा। था और एक इकोनानित डिप्रेशन था ओर उस वक्त की स्थिति हो थी कि लगान घटाने को बात की जाती थी लेकिन अगर बिना लिहाज परिस्थिति के अगर कोई बात कही जाती है तो वह ग़रुन हो जाती है। कुछ वे जे ऐसी हो सकती ह कि जो बिला लिहाज परिस्थिति के हमेशा और तमाम रोज एक सी ही रहेंगी लेकिन कुछ चीर्जे होती है जो चेंज होती रहती है ओर उनके साथ हमें अपनी पुरानी राय को दोहराना ओर बदलना पड़ता हैले हिन जो लोग यह समझने हैं हि काइनकार जो लगान देनाहै वह ज्यादा है और उसे घटना चाहिए यह ग्राहत है, नहीं घटना चाहिए, हरिग्रज नहीं । इस वक्न ऐसी कोई तजबीज नहीं है । कोई आदमी जो देहात के हालात से व.कि.क है यह नहीं कह सकता है कि काइनकार का लगान इस वक्त जयादा। है लिहाजा लगान घटाने का सवाल उठता ही नहीं। न काश्तकार का ही यह मुतालिबा है कि लगान घटाया जाय, हां इस लगान के सिलसिले में प्रोपेगेन्डा जरूर होता है। यह कहा जाता है कि भूमिधर बना रहे हैं तो उनसे तिहाई लगान लेना चाहिए या मालगुजारी लेनी चाहिए आज जब कि आम तोर पर चीप मनी (सस्ते रुखे) का जनाना है निस्वतन काश्तकार की हालत अच्छी है वैसी अच्छी हालत तो नहीं है जैसी हम देखना चाहते हैं और जैसी अच्छी हालत दूसरे देशों के काश्तकार की है। न वैसी ही है जैसी आज शहर के चन्द आदमियों की हालत है लेकिन

८२ लाख नालगुजारी देते हैं, बर्नीदार का प्राइवेट कर्ल्टीवेटेड लैड (व्यक्तिगत मजरूअ। भूमि) जो काइत कार के पास है १ करोड़ ९ लाख उसकी वाबत अबवाब है, यह ६ करोड़ ९१ लाख काया हुआ, जमींदार १ करोड़ ५ लाख कृषि आयकर देता है। यह सब मिलाकर ७ करोड़ ९६ लाख रुपया हुआ, एक पैसा काश्तकार से जो आज वह देता है हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं बल्कि यह मुमिकन है कि हम कम ले रहे हैं, यह भी कहा जाता है कि मालगुजारी केवल ली जाय और आप गरीब को नाम लेते हैं और लैंडलेस लेबरर का जिक करते हैं, लैंन्डलेस लेबरर के मुताह्लिक थोड़ा सा अर्ज कर चुका था, एक बात और अर्ज करूंगा, यह कहा जाता है कि उनको भी जमीन दी जाय। सब के लिए जमीन देना तो मुमिकन नहीं है। आज जिनके पास जमीन है वह ही नाकाफ़ी है। अगर यह फ़र्ज कर लिया जाय कि इतनी जमीन होती जो उनको भी दे दी जाती तो में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सब को जमीन से बांध देना यह देश के हित में न था। जो मुल्क मुतमब्बल है जो मुल्क तरक्कीयाफ़ता है जो देश उन्नतिशोल है बहां इन्डस्ट्री (उद्योग) पर एग्रीकल्चर (कृषि) से ज्यादा घ्यान दिया जाता है और वह देश इन्डस्ट्री को अपने यहां पनपाना चाहते हैं, दुनिया के तमाम देशों के अन्दर सब गवर्नमेंटों की यह कोशिश बराबर रही है कि इन्डस्ट्री बढ़े और खेती पेशा लोगों में कमी हो। लिहाजा जो उन्नतिशील देश है उनकी रकारों को कोशिश का यह नतीजा हुआ है कि सन् १९३९ ई० में ब्रिटेन में खेती पेशा लोगों की तादाद घट-कर ६ फ़ीसदी रह गई थी।

श्री चरण मिही

३५.६ जादमी लगे हय ह येती के अन्दर, जर्मनी में २८.८ आदमी तमें हमें हमें , इंटली म ३७७ आदमी लगे हुए हैं, कनारा में २८७ आदमी लगे हए हैं, अमेरीका म २२ फीसदी और हिन्द्रतान म ६७.२ । तो अगर आप इन राज-गहिया पर बेरे हम होते जिनकी आपको बड़ी ईर्घा लगी हुई है तो म अर्ज करना चाहता है कि उन ' फो सबी की आप तादाव घटायेंगे या बढ़ायेंगे। खेती करने के अलावा शिनारे भी आंच त्रोग : उनकी वृतिया के स्टेटिसिन्बन (आकडे यह बतलाते ., अर्थवास्त्री की रागयह है कि गैर खेती करने वांठो दी जामददी करने वाली में साढे चार गना ज्यादा होती ्मिलियों राबको कोशिय यह े कि खेती म राबसे कम आवसी लगे। नतोजा यह है कि दूसरे देशों में ज्यादातर लोग जहरा म आबाद है और गाया म नहीं आता चाहते है क्योंकि दूसरे गावों में अर्रो में आमदनी ज्यादा है। लेकिन उनको दूसरो जगहीं से अन्ने मगाना पहला ह, जैसे उगर अप, फास बगैरहा तो उनकी कोशिश यह है कि ज्यादा लोग खेती म तमें। अब हमारी यहा कोशिश यह होनी चाहिये कि ज्यावा लोग उन्होग-धर्मा में लग जाय। जब अग्रेज यहा नहीं आये ये ती ५३ की सदी आदमी यहा खेती करते ये धाका लोग दूसरे धयो में लगे हुये थे। पिछले ७५ वर्षों के अव्हर लेती करन वाला की तादाद घटती चली गयी और उद्योग-धध करने वाली की तादाद बढता चली गई। हमारे बेश म गंगा उलटी बही। हमारे देश में खेती करने वाली का तादाद बजाय ५३ फी सबी के ६७ फी सबी हो गई और दूसरे उल्लोग-धर्मा की ताबाद घट गई। तो जो शक्स वेश का हित चाहता है और केवल यिरोध करने के लिये ही विरोध नहीं करता उसका मतलबा और तकाजा यह होना चाहिये कि वेश के अव्दर इडरद्रीज कायम करें और जो लोग आज जमीन के अन्वर फसे हुय है ये लोग जब वेदा में इंडस्ट्रीज कायम हो जायंगी तो जमीन छोड कर इडस्ट्रीज मे लगेगे। उसी के लिये हम कोजिज कर रहे हैं। उसा के लिये बंध बनाये जा रहे हैं। उसी के लिये हाइडो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाये जा रहे हा, क्योंकि बिना बिजली के न ती हम खेती करने वाली की पानी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि टच्चवेल के लिये बिजली की जरूरत पड़ती है, और न हम अपने गाबो और शहरो में ही उद्योग-अंधे कायम कर सकते हैं। तो इसलिये आप चाहे किलनी ही गिलियो वें और कहे कि अखबार यह बात बत-जात है, ऐसे अखबार जिनका कोई मर्क्ल्यान नहीं है, जिनका केवल नोटिस के बल पर ही लर्च चलता है और जिनका काम केवल गाली देना है, तो वह अखबार चाहे कितना ही गाली दें, हम समझते । कि देश का हित काहे में है और अपनी आप्ते यन्त्र किये हुये जी देश के हित के काम म ।) उनम लगे हुवे हैं। आप धाहे जिलना की कि लंबलेस लेबर लंबलेस लेबर। में जानता हैं कि जापकी क्या कोशिश होगी और आपके को भाई बन्द है, जो कम्यूनिस्ट कहलाते हैं और जिनको आप बड़ी आजा भरी आंखो से देख रहे हैं कि आसाम की घाटी से आयंगे, उनकी भी यह कोशिश होगी कि लंड लेस लेबर की भड़काये। आप कहेगे कि देखी तुमकी जभीन नहीं दी । लेकिन लेडलेस लेबर हो या कोई हो, हमें अपने देशकासियों की समझ-बझ और अकल पर भरोता है और वे इस बात री बिल्कुल सहमत है और जानते हैं कि की रास्ता नेहरू, पटेल और पन्त जी बतलाते है वही रास्ता सही है और लाल मंत्रा , खून-अच्चर कराने बाला जो रास्ता है वह देश के लिये घातक तिक्क होगा और वे आपका साथ देने वाले नहीं है। आप यहां एलान करके कंट्री साइड को यह बतला रहे हैं कि पंत जी तुमकी जमीन दे सकते ये लेकिन नहीं वी। लिहाजा उठो और हमारे झंडे के नोचे आओ। लेकिन जैसा तजुर्का आपको मजदूरों में हुआ बैसाही तजुर्बी आपकी देहात में भी होगा। यह रही लंडलेस लेबर की बात।

अब सब देनेंद्र की बात जो आप कहते हैं वह एक बात आपने निराली निकाली।
यह स्कीम तो देनेंद्र ऐट बिल (स्बेच्छा से किसान) थी, जब चाहे बेबज हो सकता
था और बहुत से जो छोटे-छोटे काइतकार है और जो जमींबार कहलाते हैं
उनकी भी जमीन सब टेनेंट्स परहं। जो कानून था वह यह या कि लायबुल दृ इजेक्टमेंट

एं एनी टाइम (बेदखल बिला किमी नोटिस और जब चाहे कर मकता था।) हमने इसकी रोका और हम उसके वास्ते जमीन रहने देना चाहते हैं। लेकिन जो काइतकार असली है या कि जमीदार है, केवल इस ख्याल से कि उनका कोई फायदा नहीं है, बिल उनकी तरफ से यह मतालबा है कि हमको कानून के मुताबिक जमीन को उठाने की इजाजत थी। वह जमीन हमारे हाथ में जा रही हैं। तो यह जमीन बेदखल होनी चाहिये लेकिन पांच साल तक हम उनको मौका दे रहे हैं। जो कुछ एक आध, दो चार रुपया बीवा उनकी जायद आमदनो होती था, वह ५ साल तक कायम रहे, उसमे कोई को अण नहीं हो लाये बिल टू इजेक्टमेंट (बेदखली योग्य) थी, और वह सब चीज खन्म हो गई। इसमें खिलाफ कानून कोई चीज नहीं है। केवल ५ साल तक पीक्यूनियो एडवाटेज (आर्थिक लाभ) कुछ हद तक उनको रहेगा। अगर वह यह चीज इसके बजाय किस्त में लेना चाहे तो ऐसा कर सकते है और उसको भूमिधर बना सकते हैं। अच्छा, ता यह तो रही आपकी बात।

अब सवाल है मुआविजे का। मुआविजे के लिये आप कहते है कि साहब, नैतिक दृष्टि से नहीं देना चाहिये, मारल कोई रीजन नहीं है कि यह दिया जाय। ठीक, लेकिन में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि क्योंकि कोई मारल राइट (नैतिक अधिकार) उनको नही था उस जमीन पर अधिकार रखने का जिस पर वह खेती नही करते, इसीलिये हम जमींदारी खत्म कर रहे है। लेकिन जिस ढरें पर हमारा देश या हमारा समाज बना हुआ था, उन लोगों ने जिस दरें में अपना जीवन डाला हुआ था, उसके बारे में क्या आपका मतलब है कि हम कोई ऐसा उचित इन्तजाम न करे कि लोग अपने पैरों खड़े हो सके और उनको घर से और जमीन से बाहर निकाल कर जंगल में खड़ा कर दें? क्या आपशो इससे तसल्ली अ:पको तसल्ली हो सकती है लेकिन जिनके कंधो पर जिम्मेदारी है उनको तसल्ली नहीं होगी। उसका कारण यह है कि अगर कोई शख्स करल करता है, डाका डालता है या राहजनी करता है या और तरह-तरह के जुर्म करता है तो उसको जो रोटी देने का फर्ज स्टेट का होता है। तो हमारी सोसाइटी का जैसा ढांचा बना हुआ है उसके मुताबिक जिन लोगों ने अपना जीवन ढाला हुआ था, क्या उनको आप कार्तिल, डाक् और चोर से भी बुरा समझते हैं? डाकू को १४ साल की सजा देते हैं तो उसको भी रोटी तो जरूर देते हैं। ऐसे ही जमींदारों को जिन्होंने अपनी सब जमीन उठाई हुई थी उनको हम घर से निकाल कर बाहर खड़ा नहीं कर सकते। चाहे आप ऐसा कर सकते हो। जिन उसूलों पर हम पले है, जिन उसूलों पर यह गवर्नमेट कायम है और जिन पर हमारे ये सब इधर के (कांग्रेस बेञ्चों की ओर इशारा करते हुये) भाई पनपे है, वे उसूल ऐसे विश्वास को कोई जगह नहीं देते हैं। हम लोग ऐसा विश्वास नहीं करते है। हम जमींदारों को दुश्मन नहीं मानते। गांधी जी का उसूल यही था। उन्होने तो हमसे यही कहा था कि अंग्रेज का भी खून न बहाया जाय। वे भी हमारे भाई है। तो जमींदार तो फिर अपने ही देश के रहने बाले है। हमारे खून मे उनका खून मिला हुआ है। फिर वह हमारा भाई क्यों नहीं हो सकता है? हम उससे नफरत नहीं करते बल्कि जमींदारी से नफरत करते हैं। और जिसको हम मिटा रहे हे वह यही, जमींदारी प्रथा है। लेकिन ताकि आगे के लिये वह हमारी सोसाइटी का यूसफुल सिटीजन हो सके । इसका इन्तजाम करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसका इन्तजाम करेगे। तो इन्हीं कारणों से दुनिया भर में जहां-जहां भी जमींदारी कानून के जरिये खत्म की गई, सब जगह मुआविजा दिया गया। कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं । दुनिया भर मे ऐसा हुआ है । मै जानना चाहता हूँ और दुनिया भर में किसी भी देश की मिसाल मुझे बताई जाय, कि जिस जगह जमींदारी कानून के जरिये खत्म की गई हो वहां मुआविजान दिया गया हो। सब जगह पूरा मुआविजा दिया गया है। हम केवल माकूल और न्यायोचित मुआविजा ही दे रहे है। इस पर भी आपको ऐसी बेचैनी हो रही है।

अब आप कहते है कि साहब जबर्दस्ती छीन लीजिये, झपट लीजिये। इसका नतीजा क्या होगा? १९ लाख आदमी बहैसियत जमींदार हमारे कागजात में दर्ज है। आघे ऐसे है भो चरण सिह।

जिनके पास सेल्फ कल्टीबेटेड लंड हुं, यह रहेगे। लेकिन ८ लाख क करीब ऐसे हं जिनके पास सोर या खदराइत गुड भा नहीं हैं। एसे लोग, गय पं भिली के, ५० लाख के करीड होंगे। इन ५० छात्र आदिमियों का घर से निकाल कर बाहर खड़ा धर दिया जात, यह मुना-सित्र और ममिकिन नही है। अगर जमीवारी इस तरह से ली जा सकती है तो कारखने भी, साइतिल भो और आवता कोट भी उसी तरह से उतारा जा सकता तै। (क्छ सदस्य--टोपी कौत उतारंगा?) अब करते का माठब यह हाता कि हमारे पास जा भी सम्पत्ति है उसे छान लिया जाये। उसमें उन ह हान पा हो गये और मरना यश न करता बालरे जात होती। लियाजा देश में प्राथमता लोगो। म पानला है कि अंत में जमावार या पंजीपान मारे जायेंगे लेकिन किम कारत पर और किनने नार जायेंगे । रूप के अन्दर १२-१३ करोड आविष्णे को आवादी , तो आपकार सन जो ए है। उत्तम चार साल तक बराबर भरेल लड़ाई होती रहीथा। ह । हे यरा याना उभारे सबे में ५० जाय जाउमी मारे जाने वाले ह और सूर्यामं भा पर आग नार्येगी लोकरोहा आदमी मार जायमें और जमीवार और गर जमीवार संग मारे जायेगे। इन यह हा क्या नती हा होगा और कीन जातेगा और कोन नहीं यह कहना ती अभी बड़ा महिरु है। फर्न का जिये कि सम्पत्ति वाले परम हो जायेंगे लेकिन यन करोड़ी आवभिषों के सारप हो जाने व बाव क्यों कि तब आवसी पर भत सवार होता ह शनी खुन गरार होता है न बनता देखा जाता है और न ओरते देखो जाता है। इसमें भी जिन वक्त जार बावजाह मारा गया था तो क्या उनकी औरता और बच्चो को बहुशा गया था। यहां के जबावार अपनी जान बना धर भाग गये आप जैसे लोगो की हर की वजह से। और जाजभी वह अपनं वेश के अस्दर जा नहीं सहते। चाहते हैं कि इस तरह से छीना-सपटी करके जमीबारी जत्म की जाये। म यह कहना चाहता हैं कि इनसे देश में हाहाकार सब जायेगा। जो आदर्श और पैपाना और जो चीज हमारे ब्रममं सरदेन धरते रहे हैं और जिनहों हमारे राष्ट्र-पिता ने हमको फिर से शिवाया है और जि । की वनह ने हवारा ५ लाख वर्ष का प्राना इतिहास चन्का आता है। तहजी में एत हजार या पाय सी वर्ष में ज्याबा नहीं कला आई है। लेकिन हमारे यहां रामायण न ९ लाल वर्ष हो गये हैं और तभी से अब बना हुआ है। बांस से हम गिर गये थे लेकिन फिर से हम उठें और वही हगारे पुराने इतिहास की परम्परा चली आ रही है। वही शिद्धान्त और आवर्श हमारे समाज के हैं। हमारे यहा उवारता है। हमारी यह प्राणीमात्र के साथ वधा है मुझे संस्कृत का दलोक यात नहीं रहा है। आप जो सलवार का सिद्धान्त बाहर से लावे हैं वह देश के लिये घानक निद्ध होगा। इसके अतिरिक्त ए क बात और है जब जमीं दारी इस तरह से ली जा सकती है तो बड़े फाइनकार से छोटे काइतकार जानीन छोनेंगे। वयोंकि छोटे नाइतकार यह नहेंगे कि हमारे पास जानीन कम है। इसी तरह से आपके स्वय्त लोग कम में पहिले लोगों से यह कहा गया कि जगींवारों को मारी जब सब जमीवार नारे गये तो बड़े काइन तार कुलाक हो गये तो उनकी मारा गया और जब सब बड़े काइतकार नारे गये और बंधे में जाकर ठंडे हो गये तो भजदूरों से कहा गया कि इन काइतकारों को मारो और इस प्र हार कले किएव फार्मिय जाबब स्ती लोगों पर लाव विमा गया। इतिलये कादलकार के हित में भी यह चीज नहीं है। इस तरह से जमींबारी को छीन सपर कर केने में केवल जमींबार का मुक्ततान हो और काइतकार का फायवा हो तो यह बात भी नहीं है। इसिल ये कावतकार के हित में भी यह कीज नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात है जिसका करू में ने जिस किया था और में जानना चाहुँगा कि आपके पास इसके खिलाफ कोई मिताल हो तो जाप वें। दुनिया में जितनी सामाजिक और राजनैतिक कांति बायलॅंस से की गई तो क्या उन्होंने अपने सामने जनता का नाम अपनी जवान पर रखा। जून-अध्वर हो जाने के और गद्दी पर इक्तिवार हो जाने के बाद उन्होंने जनता के साथ विश्वा-संवात किया। जान में भी यही हुआ। एक के बाद दूसरा लीडर मारा गया। डेंदन और रोबर्टसन मारे गये। किसी ने दो साल राज्य किया और किसी ने तीन साल राज्य किया। उन आदिमयों में से जिन्होंने मिलकर वहां के बादशाह लुई को मारा था और वह सब एक दूसरे के खून के प्यासे यानी जानी दुश्मन हो गये इसके बाद आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट आया और वह खुद वहां का बादशाह बन गया। यानी इस तरह से फांम में जनतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ। इसी तरह से रूस में भे यही हुआ। लेनिन के नौ माथी थे। उसके भरने के बाद स्टैलिन आये। उनके नौ साथियों में में सात को यानी जिनोविक, रैडिक, कैनलिक ओर बखुरित वग्नैरा और ट्राटस्की भाग गया था लेकिन बाद को उसको भी मार डाला गया। में ग़ैर कम्पिनस्ट खडा तक:

उनके दिलमें पाप होता है। वह लोग अपने साथियों का विश्वास नहीं करने और उनकों यह डर रहता है कि न मालूम यह क्या कांसिपरेसी कर रहे हैं। उनके साथी यह सोचते हैं कि हमने भी अपनी जान पे लो है। स्टैलिन ही क्यों बने। हम क्यों न बने।

जो मैंने बरेली में कहा था उसी को में फिर दुहरा रहा हूँ। हमारे यहां की दो सो वर्ष की गलामी के बाद हम। रा देश आजाद हुआ और पाकिस्तान की वजह से बेहद खन खचचर हुआ। हमारे लोडर्स डिमोक्रेसी के जरीं उसूलों पर इसलिये अब भी क्रायम है कि उन्होंने नान-वायलेस के उसूलों पर ही स्वराज्य लिया है। माहात्मा जी ने कहा है कि अंग्रेज की हुकुमत दौतान की हुकूमत है लेक्नि अंग्रेज मेरा 4ित्र है। अंग्रेज और अंग्रेज की हकुमत में क्या फर्क है इसको हमें जब पढ़ते थे तो नहीं सण्झ पाते थे। अनुभव ने हमारी आंखे खोल दी हैं, जिस तरह से नान-वापलेस के उसूलों से हमने स्वराज्य लिया है उसी तरीक़े से हम सोशल और इकोनामिक रिवोल्यूशन भी करेगे। जमींदारी को हम खत्म करेगे वह हमारी घोर अब है लेकिन जमींदार हमारे मित्र है। अगर लूउ-समोट करके जमींदारी खत्म करने की जरूरत पड़ेंगी तो बाहे महाराज आप भलें ही करे लेकिन हमने तो जनतंत्र की क्रथम खाई है। इसिलये हम नहीं चाहते कि हमारे देश में डिमोक्रेसी के बजाय डिक्टें रिशय कायम हो। इसिलये हम चाहते हैं कि जमीं दारी नान-वायलेस (अहिंसा) के तरीक़े पर ही खत्म हो। इसके अतिरिक्त एक बात और है और वह यह अहिंसाबाद के मार्ग की बात है। अंग्रेजों ने इस देश पर २०० वर्षों तक राज्य किया हजारों ओर लाखों आदमी मारे गये। बराबर अत्याचार होते रहे। लेकिन जब वह छोड़ गये तो दनिया भर का इतिहास बतलाता है कि हमारे उनसे क्या ताल्लुकात रहे। जो आपको उपदेश है उसके हिसाब से अंग्रेजों से ज्यादा हमारा घोर शत्र और कोई नहीं होता। दूसरी तरफ आज हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे भाई थे पाकिस्तानी उनसे हमारे ताल्लुकात खराब हो गये। अपने देश के भाई, इस देश के निवासी और एक ही मां से पैदा हुए लेकिन उनसे ताल्लुकात खराब हो गये। काश्मीर में लड़ाई चली। अब जाकर जैसे-तैसे बन्द हुई। फिर भी गाली-गलौज हो जाती है। जवाहरलाल जी वाशिगदन गये, लंदन गये लेकिन आज तक कराची तशरीफ नहीं ले गये। वाशिगटन जाना बम्बई होकर जाते हैं, कराची से नहीं निकलते। इसका तो कारण यह कि सिद्धान्तों में फर्क है। जिस साधन से पाकिस्तान लिया वह ही भिन्न है। अंग्रेजों के भी हम खिलाफ थे, लेकिन दिल में हमारे अहिंसा भरी हुई थी जिसका नतीजा यह हुआ कि ताल्लुकात ह्यारे अच्छे यंने हुए हैं। स्वराज्य लिया गया अहिंसा के चरिये से, लेकिन पाकिस्तान लिया गया गाली-गलौज और हिंसा के जरिये, द्वेष और घृणा के बल पर। शान्ति के नाम पर मुसलमानों के हित के लिए जिन महात्मा गांधी ने अपनी जान तक देवी उनको मिस्टर जिल्ला और मुस्लिम लीगी, मुसलमानों का एनीमी नम्बर १ समझते थे। जो भाई थे वह शत्रु हो गये और जो ग़ैर ये उनसे ताल्लुकात अच्छे हो गये। कारण यह है कि अहिंसा एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिस पर वह छोड़ा जाता है वह बोस्त हो जाता है, भाई बन जाता है। अंग्रेजों पर हमने नान-वायलेंस का अस्त्र छोड़ा, उसी को यह नतीजा है कि उनसे आज भी हमारे अच्छे ताल्लुक़ात बने हुए है।

[श्री चरण तिह]

जन। दारी खत्म करने के दोनो रास्ने खले हुए हु, तल गर और क उम वे जिल्ले। तल-बार के नार में जान की नांद्रभा बहेगी और जो बनेगे वह आपम में एक दूररे को दहसन समारेंगे. रक्तो जान स्तरदे में रहेगी। हिप्र, जिहेब की भावना, किया और प्रतिकिश की भागना हुउँ। और यह रिवह पक्षश्री का समाज हो जायमा और अगर जिन तरह है इस लाम हर रहे !. उनकी साथी मान हर और उनके वाने का औरा माउ जाम करके. खाल्य हरे तो बह माई बने रहेने और घमा का प्रचार नहीं रोगा। जशदा समय में नहीं लेवा नाहवा। इसलिये हन मनायमा देना मनायिय समावेते। नाया जो स्टेड है, अरुप हरते हैं कि महात्या जो ने यह तहा था कि लुई कि तह से कि न्।शिजा नही देना चारिये। नो महात्या वा श्रोगाम कारे का गा। कार्नि का, बिद्या हु का ने बिलाफ। इस रिकारिक में बनाइसा ने क्या सा कि कार्न की लिकाफ नर्का नीस लोहिये, जेल जाना चारिये, इस्त रा देना नारिये और जनादारा माता हरती चारिये, और मार्गाज, देने का कोई प्रारंत राउठता। क्या पत्री स्थिति आतर ति र स्थिति स सहात्या ते पह शब्द कहे में ? पर रागां प्रदेशों हत्वन थे, आज आपको हत्वन हो। जगर नामाबिल हेती अगल एकेश्वान में निहाल शीनमें। केहिन बगायन हा समाल नहीं उठता। इसके अञ्चात्रपर प्रश्तिमात्री एक बाल की हैने इती लारी बाला की ली निर्देश तपान कितानी से हरिये हि ते र भरत, मतहरों से हरिये हि हरना र हरते। तमाम यह प्राप्ता जो महात्मा ने कहा था पुरा का पुरा लाजिये। इसके अवावा यह मां प्रक्रन उठना है कि रणस्नाने यह बात कही भी यो शानहो। उनशा अपना कोई लेख है नही। केवल लूई फितर ने कहाया । है। तन अगर आर्गमेंट को लातिर सारी बातें मान भी छी जार जी हि लई कि गर ने कही था, नो भहारना ने जब यह वेला हि वेग स्त्रनस्त्र होने जा रहा है, गायकत उसी बहुदे ने सान वियम्बर से न्यारह विमम्बर तह जो बैठह है। उनमें यह भा मा । । । रा विया या कि जनीतारी जल्न करी और थोड़ा बहुन जनावारी की मुनावजा जलर दी। आपके लीकर , लाव दोत्रो यालों है, आवार्य नरेन्द्रवेत उस समय कांग्रेस के ..न्यर थे। उनकी भी सम्बन्धि गाँते अन्वर थे। अगर वह उससे सहतत नहीं थे तो डिपेटिंग (विरोध सुबाह) नोटां उल सहते थे। या यही जिन वेते हि इतनी मजावरी में पर र मंशाविजा बेसे के हक में रे। आज आप क्यों कहते हैं कि मुशाबिता न वियो जाय दारिये कि कारेस छोड कर चरेगरे। यह कहने से हि मुआबिकान बिया जाय कि सान हमारी तरफ हो गामगा, क्यों कि न देने की बात उसकी अच्छी लगेगी। कार्ये । बाले कहेगे कि दो और हन कहेगे कि म बी, तो वह लाल सड़े के नीबे आ जामेंगे। लेहिन यह बात राजत है हि वह आपके मंडे के नीचे आजायंगे।

श्री सर्वजित लाल वर्मा ने जो अपना बयान विशा है उसमें उन्होंने करा ि कातून की बजह स देना चाहिये। क्राम्न तो आज भी है कि मुशाबिजा दिया जाता। आदिक रू रूप हमारे विधान का है, मुशाबिज, देने के लिये। तो पहले को जिल्ला यह करों ि विधान बदल जाय, तब देन ने प्रवार करों कि मुशाबिजा न दो। इसमें कीन तो है। निवारी है कि यह कातून होते हुए, भी कि आप किसी की जायदाद विना मुशाबिज के नहा ले सकते हैं। आप यह कहते हैं कि मुशाबिजा न दिया जाय। में यह नहीं कहता कि आप में शारी करने हैं, जीता कि कल राजाराम शास्त्रों जी ने बार—बार 'बेईमानो' लवज का इस्ते पर दिया। में तो कहता हूँ कि इमानवारी का तकाजा यह है कि पहले उस कास्टीट्यू निको बदिलये किए देनात में इंडा लेकर जाइये कि मुशाबिजा न दिया जाय। लिमाना जिन दलीलों पर उन्होंने कहा कि मुशाबिज। विया बह आज भी है।

जानीवारी अवालिशन कमेटी में कहा कि हमारे हिसाब से सौ करोड़ दारा वैद्रता है। (इस समय ४ वज कर ५० निवद पर कियी स्वीकर में युनः अध्यक्ष का गान पहण किया।)

करीब १०८ करोड़ के पहुंचता है लेकिन अग्रेरियन कमंटी के सामने कहा कि ५० करोड़ देना चाहिये। अभी तो मैने रोजन जमां की तकरीर पढ़ी उन्होंने कहा कि दिया जाय और ५० करोड़ दिया जाय। क्यों साहब ५० करोड़ क्यों दिया जाय क्या उमूल हे? ५० करोड़ भी बहुत है, २५ करोड़ भी बहुत है, १ करोड़ भी बहुत है क्या दिया जाय ५० करोड़ ही क्यों दिया जाय? मैं आप से यह कहता हूं कि आप तो यहां पर यह कहते हैं लेकिन आपके छुटभैये देहातों में फिर रहे हैं और कह रहे ह कि हम मुफ्त ही दिलवा देंगे। आपका १७ तितम्बर, १९४९ई०का एक सर्व्यूलर छपा हुआ है कि हम बिना कुछ लिये ही जिल्लवा देगे। अगले एलेक्शन में अगर आपको मार्लिकाना हक कायम करना हो तो समाजवाद को वोट दो हम बिना कुछ लिये हुए ही पाजियाना हक दे देगे। आप मालिकाना हक देगे? आप किसानों को राइट आफ ट्रांमफर तो देना नहीं चाहते ओर कहते हे कि काश्तकारों को मालिकाना हक मिलना चाहिये। यहां कहते हो कि ५० करोड़ देना चाहिये और वहां कहते हो कुछ नहीं देना चाहिये। अरे माहबं! बैठ कर अपनी पालिसी तय कर लो किसानों को भी गालम हो जाय कि क्या चाहते हो ओर आपका भी दिमाग साफ हो जाय। तो यह रही मुआविजें की बात। २५ नवम्बर सन् १९४९ ई० को श्री आचार्य नरेन्द्रदेव ने कहा कि हां, मेने यह बात कही थी कि मुआ-विजा दिया जात्र लेकिन जब स्रत ओर थी आज स्रत अर है। क्या थी स्रत जनता ने बड़ी उत्पुकता से सुना लेकिन तब क्या सुरत थीं आज क्या तबदील हुई। यह ठीक है आज स्वराज्य हो गया। यह भी ठीक है कि स्वतंत्र होने से बहुत सी बाते बदली लेकिन क्या सब बदल गई। यह कौन सी दलील है। यह सही हक कि स्वराज्य के होने से अपने हाथ में सत्ता आई है। आपके हाथ पैर बंधे थे, खुल गये, लेकिन जितनी बाते आपने उस वक्त कही थीं क्या वह सब बदल गई जो बाते आपने उस वक्त कही थी क्या वह सब गलत हो गई। क्या स्वराज्य होने से पहले दो और दो चार होते थे ओर अब दो और दो चार नहीं रहे पांच हो गये। क्या मतलब है ? स्वराज्य होने से इससे क्या सम्बन्ध ? स्वराज्य होने से पहिले आपकी समझ में कुछ देना जरूरी या लेकिन अब जरूरत नहीं रही। स्वराज्य के पहिले आप समझते थे कि जमींदारों से मुआविजा दे कर जमीन ली जाय लेकिन आज आप यह समझने लगे कि अब इनको तलवार के घाट उतार डाला जाय। बदलने में कोई बुरी बात नहीं है। स्थिति के अनुसार बदलना ठीक है लेकिन क्या हर चीज बदला करती है ? क्या कोई बुनियादी चीजे नहीं होती ? तो जहां तक कम्पे-न्सेशन देने या न देने की बात थी वह बुनियादी बात थी उसमें स्वराज्य की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता।

अब तीयरा सवाल यह है कि मुआविजा दे तो कौन दे? आप यह कहते है कि दो साहब तो अपने पास से दे दो। सरकार कैसे अपने पास से दे दे, यह तो में बाद में अर्ज करूंगा। किर भी जिक हुआ कि साहब निजाम साहब से ले लो। आप किर कहते हैं कि सेठों से लिया जाय। कितने सेठ हैं कितना लिया जाय कितने देंगे और किर सेठ जो है

म समझता है। के किसान के जारम-सम्मान के लिया के प्राप्त के किही मान के ने किसान की जेहिनयत और होती है। किसान उस को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। किर कहते हैं कि साहब, सरकार दे दे अपने पास से। क्यों साहब ! सरकार के क्या माने होते हैं? क्या सरकार के पास कोई आमदनी गैर को होती हैं? सरकार की जो भी आमदनी होती हैं वह एक-एक पैसा पिंडलक की जेब से निकलता है। अगर सरकार के पास नकद हैं तो दे देगी नहीं तो पिंडलक से ही ले कर देगी। लिहाजा जो पैसा सरकार देगी वह पास की जेब से निकलता है। अगर सरकार के पास नकद हैं तो दे देगी नहीं तो पिंडलक से ही ले कर देगी। लिहाजा जो पैसा सरकार देगी वह पांचलक की जेब से या तो आ चुका है या पांचलक की जेब से

तो चरग सिंह

आने वाला है। आप यह मुलाबा देना चाहते हैं कि सरकार जो देगी उसका बोहा पिडलिक या किसान पर नहीं पड़ेगा। आपके आचार्य जो ने क्या कहा था? आपके आचार्य जो यह न फरनाया यह था—To the large extent it has to be paid out of the rents realized from the peasantry" "(बहुत हद तक यह मुआविजा किसानों की अपनी ही जेब से आयेगा और उस लगान की शक्ल में जो कि उनको देना है।)" कहने का मतलब यह कि यह भार किसानों पर ही पड़ेगा।

भेरा बरेली का एक तज्बा है, जिसे में सुना देना चाहता है। मैंने वहां कहा था कि आचार्य जी तो खुद ही कहते हैं कि यह किसानों की जेब से आने वाला है। जब मैं अपना भाषण खत्मकर चुका तो उसके बाव एक लाल टोपी वाले खड़े हुए और उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा, में आचार्य जी से पूछ आया है। मेंने कहा कि अगर कहा हो तो आपकी सफेव टोपी और मेरी लाल टोपी। फिर भी वह कहते ही रहे कि नहीं, नहीं, मेंने आचार्यजी से पूछा, उन्होंने कहा ही नहीं। खैर! मतलब यह कि रुपया लोगों से ही आना है। में तो कहता है कि हम नहीं चाहते कि वह वस गुना लगान वें ही। उनके सामने वो रास्ते खोल विषे हैं, चाहे किस्त में दे दें, जो मौजूब लतान पर देंगे, यह किस्त बन्दों के रूप में देंगे। या अगर वह चाहें, कोई दबाब नहीं है, तो अभी जब कि उनके पास काफी पैसा है, वे वें। खेर, चाहे किसी के पास से आये। उस सुरत में सरकार जमीन की पूरी मालिक हुई, जमींदारी मिटी, अर्थीत् विचीनिये बीय में से निकल गये, कोई बेदलली की धनकी देने वाला और उसके आत्मसम्मात को ठेस पहुंचाने वाला न रहा और सीधा लगान गवर्नमेन्ट को विया। किसान पर आज का लगान कोई बोझा नहीं है, और अगर वह इस तरह से देता रहा तो कम से कम ४०,५० साल तक उसे वेता रहेगा और जब ५ साल बाद जब भाव गिर जायेंगे और यह भाव न रहेगा तो उसको बड़ा बोझ मालूम होगा। इसलिये आज उसके लिये यह मीका है कि अगर वह चाहे तो सारा गपया आज दे वे और भूमिधर बन जाय।

आप यह कह रहे हैं कि जमीन हि जमेजेस्टी में बेस्ट हो जायगी, बफा ६ पढ़ कर सुना बी, लेकिन मालिक के जो अधिकार होते हैं, फुल युजर, और राइट्स आफ ट्रांसफर (स्थानान्तरण अधिकार) और जितने भी अधिकार होते हैं, सिबाय निसयुज के, कि जमीन लगान पर उठा कर इसरे को आमदनी लाने का, इसके अलावा जितने अधिकार होते हैं दे विया। मतलब यह कि अगर मुआबिजा आगे देना पड़ता है तो खुव अपने मालिक हो जाते हैं यानी कि भूमिधर बन जाते हैं। ये दोनों चीजें उनके सामने रक्खी है और यह कला एलान है, जितने भी कांग्रेसी भाई और सरकारी कर्मवारी है वे कहते हैं कि अगर किसान की सी दफे गर्ज पड़े तो वह भू सिधर बने, हमारी हरगिज गर्ज नहीं है क्या साहब किसानों की लूट हो रही है, साहब, कैसी लूट हो रही है। अगर आपने जितनी बालें पढ़ कर सुनाई हैं उनकी खब ही तहकीकात करें। और आप ही जाकर मौके पर देखें तो आपको मालूम होगा कि ९९ प्रतिशत नहीं शत प्रतिशत बहु गलत है या वे मुगालते के साथ आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अफसरान की तारीफ़ करते हैं। अखबार वाले भी डेमोक्रेसी की जिल्ली उड़ाते हैं कि कांग्रेस लीडमं बड़ा बोल बोलते हैं। बड़े लोडमें की बड़ा तजुर्वा है, में तो अपने ही छोडे तजुर्वे की बिना पर कहता हूं कि जिस आर्डर और जिस मेहनत तथा अफाबारी के साथ उन्होंने काम किया है वह आंखें कोलने वाली है। वे इसके लिये हमारे कात-कात धन्यवाद से पात्र हैं और जनकी यह बढ़ावा देने का प्रोपेगेन्डा और यह कि जबरवस्ती हो रही है, जिल्ह्झ प्रस्ता है, बेबुनियाद है। उनका यह कहनी

बिलकुल सही नहीं कि भूमिधर बनाने में उनके वर्त्तमान अधिकारों को छीना जा रहा हैं। हम किसो के अधिकारों को नहीं छोनना चाहते, किसी के साथ हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। अगर कोई १० गुना लगान न देतो किसी को हम इसके लिये सजा देना नहीं चाहते। अगर वह १० गुना लगान नहीं देता और सीरदार ही रहता है तो इस में गवर्नमेन्ट का कोई नुकसान नहीं। उसके ऐक्सचेकर मे जो ज्यादा ही रुपया आयेगा। वह जो जमीन का सपना देखा करता था कि मै भूमि का मालिक बनुंगा उसका वह सपना पूरा हो जाता है। इस सपने के पूरे होने की खशी में उसके चेहरे पर जो सर्खी आयेगी और उस सुर्खी को छाया जो इन जन-सेवकों पर पड़ेगी तो हमारी भी तिबयत खश होगी। कहा यह जाता है कि हमारी यह स्कीम फेल हो गई। क्या मतलब ? स्कीम फेल हो गई। क्या स्कीम थी ? ७ जुलाई सन् १९४९ ई० को जब यह बिल पहले-पहल यहां पेश हुआ था उसमें किसी के १० गुना देने या न देने की वजह से एक लक्ज और एक कामा' भी इसमें बदल नही जायगा। स्कीम जैसी की तैसी ही रहेगी। माननीय पंतजी या ठाकुर साहब ने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा कि मुआवजा नकद देगे। अगर नक़द देंगे तो ही जमींदारी खत्म होगी, ऐसा कहां कहा गया था ? फिर स्कीम के फेल होने का इसमें उठता ही कहां है ? कुल यु० पी० में ७० लाख टेनेट हे जिनमें ५० लाख खुद काइत करने वाले हैं। अब इनमें से ७० लाख भी भूनिधर दन जायं तो जमींदारी खत्म होगी, ३५ लाख भू निधर बन जायं, और ३५ लाख सीरदार ही रहें तो जमींदारी खत्म होंगी और एक भी भीनधर न बने और ७० लाख ही सीरदार रहें तो भी जमी-दारी ती खत्म होगी ही और स्कीम जैसी की तैसी कायम रहेगी। अगर नक्षद रुपया हो गया तो शायद नकद दें दें अगर नकद नहीं हुआ तो नहीं देगे। स्कीम के फेल होने का तो कोई सवाल नहीं है। वह जैसी की तैसी ही रहेगी। बाज-बाज अखबारो में तो यहां तक कह दिया गया "Tuulak must return to Delhi" (तुगलक को अवस्य देहली लाट जाना चाहिए) उनका तो तिर्फ यही ख्याल है कि नकद रपया होगा तब ही जमीदारी खत्म होगी। काश्तकारों के लिये दोनों रास्ते खुले हैं, एक रास्ते में उसे कम देना पड़ेगा और वह जमीन का खुद मालिक बन जायेगा। दूसरे रास्ते में भी जमींदारी खत्म होतो है लेकिन उसे ज्यादा देना पड़ता है और इस तरह से वह मालिक सीना फुला कर घुम न सकेगा। उसे जो रास्ता पसन्द हो वह स्वीकार कर ले। स्कीम दोनों प्रकार से वैसी ही रहेगी जैसी वह थी। लाल टोपी पहिना कर और १०:२० लड़के इकट्ठे कर लिये और कहा कि वारिस हो, वारिस हो। यह हमारे देश की बद किस्मती है कि जहां कोई बात अनहोनी कही गई कि १० इकट्ठा हो गये। तालाबों पर भभूत रमा कर अगर कोई आ जाता है या बाल बढ़ा कर आ जाता है तो बहुत से गांव के आदमी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अगर एक या दो ने यह कह दिया कि इन्होंने दस दिन से लाना नहीं खाया है फिर तो कहना ही क्या। किसी लड़के ने देखा कि इसके पास तो बड़ा विमटा है उससे भी बड़ा जितना घर में मां के पास है इसी पर वह शोर मचाने लगा। गांवों में लोगों ने लाल टोपी ओढ़ ली। लोगों ने देखा कि और तो सब सफेद टोपी पहनते हैं लेकिन यह लाल टोपी है, इसमें जरूर कोई बात है। जरूर कोई बात है, वर्ना न वह समाजवादी को जानें न किसी को जानें। आपने कछ आदमी इकट्ठा कर लिये और जलूस निकाल दिया। हां यह तो कहना भूल गया कि धन्य है ऐसे नेतृत्व को जिसने यह बयान निकाल दिया कि ७० लाख टेनेंट्स का मार्च, जिसमें केवल १ लाख लखनऊ तक तशरीफ लाये। क्या इसी ही बल पर आप देश का नेतृत्व करेगे। मैं तो यह कहंगा कि देश आभागा होगा अगर वह आ को स्वीकार करेगा। इस तरह से देश को नहीं उभारना चाहिये। आपका हो जाता जिस तरह फांस में कामयाब हुआ था अगर हुकूमत जबरदस्त पोलीटिकल पार्टी के हाथ में न होती। हमारे लीडरान फांस के लीडरों कि तरह से नहीं है वे अपना सारा जीवन देश की सेवा करने में बिता चुके हैं। जितने हमारे साथी बैठे है कोई तीस साल से कोई बीस साल से देश के पीछे फकीर हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से वालं-

थी चरण भिह्

डियम मोह निनहा नाग तक अरायाना म रूपा का नता मि हता। व भी देश और जाना के सन्य प्राप्त परे हें हें भी देश की एक स्था मा नाय हों हे बार कांग्रेस के साठन गाय-पाय मा फार्य हों है । अगर हमार पीछ इतारा अवस्वस्त पोलीटिकल अर्थनाइजेशन न होना तो महाराज निम बिंग आपका अपम आपा था उसी रोज आप पत्न आ को निकाल देने। इन नलसा स्थाम हो ने केगा। स्थाप को ओर अकल के साथ जित्य करों ता मुमाहन हा कि ए हे बाता मा १६० अर्था हिंगो देश विद्या लेकिन जा स्थाप हो नैनिहता हा गाइन तहा करना अत्याप परे हो ने नकता है। मा अत्यक्त वकता हो साथ हो नैनिहता हा गाइन तहा करना अत्यक्त देश पर एक में स्थाप हो ने किता हा गाइन तहा करना अर्थ पर एक पर पर हो हो साथ अपने कांग्रेस छोड़ों और हिर इन्हों का भा नहां दिया। और हमको आप निवास वा उपदेश देने च है है। मने बहुन समय विशा अब मा पर्यानट में साथ साम रचना चाहता है।

पह स्कीम जो 'मार मन्क क'म मने पेश है, में जगा अज कर चका कि दनिया में अपना सानी नहीं रलनी। सब से बड़ी बात इस रकीम की यह है कि हर जगह जब कि केवल जनना के चने हुए नमाइन्दे ही कानन बनाते है, सियाय स्विटजर ने ह के जो एक छोटा सा मत्क है, और जहां की आबाबी हमारे एक जिले के बराबर है, हमारे यहां की ६४०,००,००० की आबादी है और जनता के मत से यह कानृत बना ह जिसकी इतिया में कोई निसाल नहीं है। जितने हमारे आन्बोलन हुए, जितने हभारे एलेक्शन हए, उन सब में इतना प्रचार ओर इतनी राजनीतिक शिक्षा कभी नहीं वी गई जितनी कि आज इस बिल के द्वारा को गई। आज जाप बिहार, मी० पी० या राजस्थान अथवा ओर किसी सबे के देहान में देविए। लेकिन प्रमा के किसानी में आपको उतनी राजनीतिक चानना नहीं रिष्ठेगी जिननी कि हमारे प्रान्त में। हगारे यहा किसाना में एक अजीव बेदारी पाई जातो ह। एक अजोब रोशनो फैल गई है ओर इस बात के लिये जरूरत ह। डेमोक्सी को कामवाब करने के विये जरूरत है कि हर शल्स अपने हक्क को गमझे। म तो नमझता ह कि कान्त जो बन रहा है, जो मीटिंग काग्रेस आर्गेनाइजेशन करती है उसमें जनता को जो राय होनी है हम फोरन उस राय के असर को लेते है और यह गवर्नमेन्ट वही करती है जो जनता चाहती है। सेलेक्ट कमेटी में वही सब कछ किया गया और आज भी जनता के लिये जो अस्छा होगा बही किया जायगा। हम रेफरेंडम करके इस बिल की बना रहे हैं। आज देश के अन्वर बेबारो है, आज देहाती के अन्वर जागति आ गई है जो जनतन्त्र को कामपात्र करने के लिये जरूरी है। यही नही हम रेफरेडम करके रुपया ले रहे हैं जब रुपया कल आवसी के पास है और वह नहीं देता उसके बाद भी किसान हमको कप्या वेते हैं और आज १७ लाल खाते वालिल कर बके हैं। तो हमारा मतलब यह है कि वे अपने हक को समझते हैं और आज उनमें एक अजीव अवेक निग (जाग ति) आ गई है। केवल यही नहीं, वे कान्त को बनवा रहे हैं और खब समझ कर अपना रेपया अबा कर रहे हैं। इससे उनका मीएल ऊचा होता है, स्टेटस भी बढता है और सेल्फ रेसर्वेत्रट (आत्म-सन्तान) भी बढ़ता है, यह मामुली चीज नहीं है। इसके अतिरिक्त हिसानों में, देहान में और पढिलक आर आफिसरों में जो एक जाई थी वह पट गई। आज आफिपर देहानी में जाते है ओर देहात की गठियां में किरते हैं। दे किसानी के घरी में जाकर बातें करते हैं, उनके बोवालों मे जाकर बातें करते है। आज किसान कलक्टर और किनिइनर से हाथ में हाथ निलाकर बात करता है। इसके अलाबा पहले आफिसर लोग शायब किसी कमीशन या किसी तहकीकात और मुआयने के मौके पर ही देहालों में जाया करते ये। आज हमारे बहुत से नाजबान आफिसर है जो देहातों के अन्दर जाते १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल ६७९

है। हमारे बहुत से नौजवान डिप्टी कलक्टर्स जो १५ साल में भी इस तजुर्बे को नहीं हासिल कर पाते वह ६ महीने के अन्दर ही हासिल कर रहे हैं। इसका मनलब यह है कि वे अपने देश की, जनता की बेहतर सेवा कर सकते हैं। तो में केवल यही कहूंगा कि हमने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बिल को बनाया है। मेरा इस गवर्नमेन्ट का और मेरे सब साथियों का ख्याल है कि हम वाकई में बड़े खुशिकम्मत है कि अंग्रेज हमारे सामने गये और आज किसानों के बन्धन कट रहे हैं और किसानों की किस्मत बनाने में हम सब लोग सहायक है।

(इसके पश्चात् सभा ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये

स्थगित हो गयी।)

कैलासचन्द्र भटनागर, मंत्री, लेजिम्लेटिव असेम्बली, संयक्त प्रान्त ।

लखनऊ, १४ जनवरी, १९५० ई०

नत्थी 'क'

(वेखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रक्त सं० २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१८ पर)

जूट की पैवावार बढ़ाने की योजना युक्त प्रांतीय सरकार ने फरवरी, १९४८ ई० में शुरू की थी। अनाज की कमी के कारण यह योजना केवल लखीमपूर (खीरी) जिले से लेकर गोरखपुर जिले तक के क्षेत्र में ही सीमित रखी गई। योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जीन (ZONGS) तथा जूट विकास—केन्द्र थे:——

क्र० सं० जो न	केन्द्र
१ लखोमपुर जोन	(१) पालिया
	(`२) झंडी
	(३)अमैपुर
	(४) धौरहरा
	(५) हसनपुर कटौली
	(६) केवल पुरवा
	(७) लोकिहा
	(८) ईसा नगर
	(९) चाहलवाला
२ सीलापुर जोन	(१०)तम्बीर
	(११) बांसुरा
	(१२) सेवता
३ जरवल रोड (बहराइच) तथा	(१३) जरबल रोड
नवाबगंज, गोंडा, जोन	(१४) बहराइ च
	(१५) नवाबगंज
	(१६) कर्नलगंज
	(१७) सहजनवां गोला बाजार
	(१८) गोरलपुर सेवा बाजार
	(१९) बार्ली बाजार मठपर रानी
	(२०)तमकोही

१९४८ ई० के वर्ष में ५,००० एकड़ से ऊपर क्षेत्र जूट की पैवाबार में लाया गया।
१९४९ के वर्ष में तराई भावर में वो केन्द्र और खोले गये (१) शिमला पास्चर
(simla pasture), जो पुनर्वासन योजना के तराई क्षेत्र में है, तथा (२) काशीपुर,
नैनीताल तथा १७,५०० एकड़ भूमि जूट की पैवाबार के अन्तर्गत लाई गई।

इस योजना में निम्नलिखित उपाय काम में लाये गये:---

- (१) जूट के बोने तथा उसके रेशे की रेटिंग (retting) तथा पेटिंग (greding) के कियारमक प्रदर्शन। इस कार्य के लिये गत वर्ष बंगाल से चार रेटर व प्रेडर (retters and greders) की सेवार्य ली गई तथा ७५,००० चपये लगभग ३०० किसानों में इस संबंध में वितरित किया गया।
- (२) बंगाल से बीज मंगाया गया तथा किसानों में सहायता कप से ३० ४० फी मन के हिसाब से बिया गया।

- (३) बाजार में बेचने के लिये मुविधाये कर दी गई है जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकें। सरकार ने दर भी नियत कर दी है।
- (४) जूट विषयक शिक्षा प्राप्त किया हुआ कर्मचारी–समुदाय हर प्रकार की टेक्निकल सलाह किसानों को दे रहा है।
- (५) घाघराघाट (जिला बहराइच) में एक जूट बीज प्रदर्शनी फार्म भी खोल दिया गया है, जहां बीज-वृद्धि तथा रेक्षा निकालने के प्रदर्शन होते हैं।

नत्थी 'ख'

(देखिए १४ जनवरी, १६५० इं० के तारांकित प्रदन सं० ३२ का उत्तर पांछे पृष्ठ ६१९ पर)

GOVERNMENT OF THE UNITED PROVINCES

No. 6160/II-13-16 ACCOUNTMENT DEPARTMENT

Dated Lucknow, July 24, 1947

OFFICE MEMORANDUM

Subject:-Communal representation in the services.

The Governor has reviewed the entire position regarding communal representation in services under the rule-making authority of the Provincial Government, and in supersession of all existing orders on the subject has decided as follows:

- (A) In the matter of promotion, communit considerations shall be entirely disregarded.
 - (ii) In the case of direct recruitment-
- (1) where selection is made by competitive tests, whether by the Public Service Commission or selection boards, the sole criterion shall be that of morit subject to a reservation of 10 per cent. of the total vacancies for candidates of Scheduled Castos, provided subject to candidates of at least the minimum qualifications are available. Where recruitment in any one year fails to produce the required number of qualified candidates of Scheduled Castes the deficiency will be made good next year, if suitable candidates are available. Sun this practice shall not be carried forward for more than one year at a time;
- (2) where selection is made otherwise than by competitive tests, the reservation for minorities shall be on the basis of population subject to reservation of 10 per cent, of the total vacancies for candidates of the Scheduled Castes, provided a sufficient number of candidates with minimum qualifications is available. In the event of sufficient candidates with even minimum qualifications not being available amongst the Scheduled Castes, the deficiency will be made good in the following year from the quota of the Hindu community in lieu of the extra vacancies given to them in the previous year from the vacancies reserved for the Scheduled Castes, if suitable candidates are available in the following year. This practice shall not be carried forward for more than one year at a time; and
- (3) in those services in which recruitment is made partly by direct recruitment and partly by promotion, and in which communal proportions are applicable, the number of candidates of the various communities selected by promotion should be taken into account in determining the number of vacancies to be reserved for each community for direct recruitment so that the total number of posts in the cadre of a service may, as far as possible, correspond to the prescribed communal proportions.

(C) The principles stated above will be applicable to rending cases of selection with the Public Service Commission and the appointing authorities where orders have not already been passed.

B. N. JHA.

Chief Secretary.

To-All Departments of the Secretariat for future guidance.

No. G260 (1)/II-13-46

COPY also forwarded for information and future guidance to-

- (1) The Secretary, Public Service Commission, United Provinces, Allahabad.
- (2) The Accountant General, United Provinces, Allahabad.
- (3) All Heads of Departments and Principal Heads of Offices, United Provinces.

By order,

V, C. SHARMA,

Deputy Secretary to Government,

United Provinces.

No. O-1422/II-E-55-1948

FROM

SHRI B. N. JHA, I.C.S.,

CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT,

United Provinces,

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND

PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

UNITED PROVINCES.

Dated Lucknow, April 14, 1948.

SIR,

I am directed to say that the Governor has decided that in Government records where provision has been made for specifying caste or sub-caste in a separate column, or otherwise, it shall, with immediate effect, be left blank except—

APPOINT

- (1) for recording the particulars of members of the Scheduled Castes in the preparation of—
 - (a) electoral rolis, or
- (b) filling up papers, for recruitment to Government service, and
 (2) where there is a specific statutory direction requiring the entry to be made.
- 2. The Governor has also been pleased to decide that henceforth ordinarily in correspondence from Government offices all Government servants under the United Provinces Government should be addressed by using the honorefices "Shri" "Shrimati" "Kumari" as may be appropriated,

instead of 'Mr", "Babu", "Pandit", "Minlyi", "Mrs", "Musimmat", "Miss", etc. in use at present. Phis does not apply to officers and other ranks of the Definer Forces, even it serving unfor the United Provinces Government, or to Hon'ble Judges of the High or Chief Court.

I have the honour to be,

SIR.

Your most obe hent servant,

B N JHA.

Onser Secretary.

No. O-14/2 (1)/II-I)-55-1948

Copy to warded for information to all Departments of the Secretariate By order.

KEHAR SINGH.

Deputy Secretary to covern cent, United Provinces,

No - 1303/111 - 15 1919

FROM

SHRI B. N. JHA,

CHIEF RECRETARY TO GOVERNMENT, UNITED PROVINCES.

To

ALL HEADS OF DEPARTMENTS AND

PRINCIPAL HEADS OF OFFICES,

United Provinces.

Dated Luckness, April 9, 1949.

Lie (ebat ministisa tron partment.

SIR. I AM directed to invite a reference to parigraph I of G. O. no O-1422'II-B 55 1948, dat d April 14 1948, ranged from the Appointment (B) Department, and of which an extract is herewith each ised, and to say that Government have of hite bein receiving representations from members of certain Schoduled Castes for changing their (8406 names charming higher descent and requesting on the ground that they should cease to be designated as members of the Scheduled Caste-, While the Government of India (Schodulod Castes) Order, 1936 was intended to afford protection to the members of certain castes among the llindus it seems unnecessary to insist on any individual being treated as a member of any particular 5 heduled Caste, if he himself denies being its member and does not desire to be so treated. I am accordingly to ask that if any su h person wants his caste or sub-caste to be emitted or not to be entered in Government records even cases in which it is still required to be entered in a cordance with the Government Order, dated April 14, 1948, referred to above, he can make an application to that effect and his request should be accepted.

Yours faithfully, B. N. JHA, Ohist Secretary. नित्थयां ६८५

No. 1303(1)/III-15-1949

Copy forwarded for information to all Departments of the Secretariat.

By order,

KEHAR SINGH,

Deputy Secretary to Government,

United Provinces.

Oppy of paragraph 1 of G.O. no. O-1422/II—B-55-1948, dated April 14, 1948, from the Chief Secretary to Givernment. Uttar Pradesh, Appointment (B) Department to all Heads of Departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

Sir, I am directed to say that the Governor has decided that in government records where provision has been made for specifying caste or subcaste in aseparate column, or otherwise, it shall, with in medate effect, be left blank, except—

- (1) for recording the paticulars of members of the Scheduled Castes in the preparation of—
 - (a) electoral rolls, or
- (b) filling up papers of recruitment to Government service, and (2) where there is a statutory direction requiring the entry to be made.

न्द्रिक ट्राक्त विश् ठ १०५१क ।क	0,	:	fr 1	•	:	:	:	:
1512 51क519 द्वार कि 51क्रिअंट	•	:	:	:	:	:	:	:
क प्राक्ष्म हे सिमाप्राष्ट्रहो	V	:	: o	:			:	;
त रुप्या ह्या नया एक मुद्दत	9	1 :	005		:	:	:	:
	U ⁹	1	:	०० है। १० वर्ष	50 00	0 PC		र वि
तिय जबकि उन्हें निया एक मुक्त निप्रदानकी गई	ۍ		वस्बर, १०,८५ है	796	057701	50 686 S	म्बर, १९४८ ई०	:
L.						्र अप्रै	₹ fin	
किस, आवार प उन्होंने प्रायंना- पत्र भेता	>>	अपने पनि के राजनीति पीड़िन होने की है।	राजनीनिक पीड़िन हो ई॰ की हैस्पियत से ि	अपने पनि के निष्क पाहिन क्षेत्रीयान्त	राजनीनिक पीड़िन ह		**	1
तिषि, जबकि उन्होंने प्राथंना- पत्र भेजा	m	१९ जुलाई १९४९ ई०	श्री भक्तदर्शन गढ्दाल ने २९ सितम्बर, १९४७ ई० को प्रार्थना पत्र भेज		इ अर्थेन, १९४९ हैं	इंश् मार्च, १९४९ ई०	२९ अष्त्वर, १९४७ ई०	:
राजनीतिक पीड़ित का नाम	œ	श्रीमती गंगीत्रीदेवी पत्नी स्वर्गीय जिवानन्व स्त्रीमा	बनारा स्वर्गीय श्री कोतवाल सिह नेमी तथा उतकी पत्नी	-	श्री मायव मित्रा	श्री ज्या नन्द भारतीय	श्री बलवत्त सिंह	श्री छेर सिंह मंबारी
# 1	•	~	Or.	No.	m	>0	3 ^	ur
	राजनीतिक तिषि, त्रविक क्षिक्त, व्याचार पर तिथि जवकि उन्हें कितना रुपया कि हैं	राजनीतिक तिबि, जबकि किस, आधार पर तिथि जबकि उन्हें कितना एपया कि हि हि पीड़ित का उन्होंने प्राबंना- उन्होंने प्रायंना- पंडान या एक मुदन प्रदान किया गया हि	राजनीतिक तिर्वि, जबकि किस, आधार पर तिथि जबकि उन्हें कितना हपया कि है है हि है हि है	राज्यीतिक तिथि, ज्रबंकि किस, आधार पर तिथि ज्रबंकि उन्हें कितना एपया कि हिंदी हिंदी प्रापंता का उन्होंने प्रापंता उन्होंने प्रापंता अधार पर तिथि ज्रबंकि उन्हें कितना एपया कि हिंदी हिंदी हिंदी प्रापंता किस, आधार पर से ना तक्ष्म प्रवान की गई मासिक एक मुद्देत हिंदी हिंदी हिंदी पर है	राजनीतिक तिष्, जबकि किस, आधार पर तिषि जबकि उन्हें कितना हपया कि हि कि कि किसना हपया कि कि किसना हपया कि कि कि कि कि कि किसना हपया कि किसना हपया कि कि कि कि कि किसना हपया कि कि कि कि किसना हपया कि कि कि कि किसना हपया कि कि कि कि कि किसना हपया कि कि कि कि कि किसना हपया कि किसना हपया कि किसना हपया कि किसना	राज्यनीतिक तिथि, जबकि किस, आधार पर तिथि जबकि उन्हें कितना हपया कि कि कि कि किस, आधार पर तिथि जबकि उन्हें कितना हपया कि कि कि कि कि किस किस किस, आधार पर तिथि जबकि उन्हें कितना हपया कि कि कि कि कि किस किस किस किस किस किस	राखलीतिक सिक्, अविक क्यायार पर सिवि अविक उन्हें कितना हुएया कि कि कि क्यायार पर सिवि अविक उन्हें कितना हुएया कि कि कि कि कि क्यायार पर सिवि अविक उन्हें कितना हुएया कि कि कि कि कि कि कि कि क्यायार कि	राक्तीतिक स्विक्तं अविक्त किस, आधार पर तिथि जवकि उन्हें कितना एका किस, किस, आधार पर तिथि जवकि उन्हें कितना एका किस, किस, आधार पर तिथि जवकि उन्हें किस

१ जून १९४९ ई०

							,		4540
िरुक राक्षिमध एरुकि क्ष	6		श्राष्त्रा-पत्र प्राष्त्रा-पत्र	मरकार! आजाओं के	अपात नहा या	*	:	***	11
1915 91 49 15 Žir fæ 91æf 89 1	. 3	or Alberta	मी गई	=	11	:	#	÷	= =
कं प्रकार विचारायोग्ह	V				•				· :
कितना हपया प्रवान किया गया मासिक एक मुक्त प्रान रक्तम	9						,	•	:
神神 神神	ns.						•	,	:
तिषि अब कि उगहे पेन्शम या एक- मुस्त रक्रम प्रवान की गई	.s-			•					:
क्ति आवार पर उन्होंने प्रायंना-पत्र में जा	>	राजनीतिक पीड़िन	होने की है सियत	 		:	8	*	अपने पति के राजनीतिक पीड़ित होने की हैसि– यत से
तिषि, जब कि उन्होंने प्रार्थमा-पत्र मेजा	MJ-	. 84% CEO			の妻のみると	:	*	:	२९ फरवरी, १९४८ हैं
तिर्वि, ज प्राचेता-		र्७ करवरी	२२ मई, १	३० अप्रैल,	१ नवम्बर, १९४७ ई०	u	2	***	२९ फरवरी
राजनीतिक पीड़ित का तिथि, जब कि उन्होंते नाम प्रार्थेगा-पत्र मेंजा	~	२० सी मवानी प्रसाद डिमरी २७ फरवरी. १९४८ई० राजनीतिक गीड़िन	२१] भी समेश्वरवत्त मं वाती, २२ मई, १९४८ ई०	स्रा मधी बासुनेव त्याची	भी मृष्टुन्तीकाल वार्ष	२४ औ अस्मिका प्रसाद	त्री कुलानच्	जी कि दत	श्रीमती प्रमा देवी पत्नी स्वर्गीय क्रुंवर सिंह मस्ताना
	-	8	4	*	nor Or	>°	2	Ch.	96

**	:	:	i	:	:	:	:	:	:	:	:	:
2	:	:	:	:	:	:	:	:	:	•	11	:
:	विचाराधीन है		=	2	66	*		** *** ** ***	**	ន ប៊	E	11
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	•	:	•	:	:	•	•	:	:	:	:	
:												
и :	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:
पिता के राजनोतिक पीड़ित होने की हेसि– यत से	राजनीतिक पीड़ित होने की हैसियत से	:	:	:	•	:	:	:		:	:	
र मई, १९४९ ई०	४ जून, १९४९ है	४ जून, १९४९ ई०	२७ मई, १९४९ ई०	सरकार को २६ मार्च, १९४९ ई० को मिला		१ नवम्बर, १९४८ ई०			:	:	:	"
भी भारत भूषण तथा भी यशोषर लाल पुत्र स्वर्गीय भी बत्तवामी लाल	था भूषपाता थाए श्री जोघ सिंह मनराख	श्री दयाराम मंदूला	श्री आदित्य राम	श्री जोर्घासह विष्ट	श्री कान्तिचन्द्र उनियाल	श्री प्रमानन्द ध्यानी	श्री नरायनदत्त महंत	श्री] तिरास	श्री सदानन्द भरद्वाज	श्री मोलादत्त चंद्रला अ	श्री थान सिंह	श्री जगत सिंह नयान
2	0	W.	9	CC.	lis.)o	3' nor	m, m,	9	2	ar or	8

६९०		लेजि	लेटिव	असेम्ब	ाली		[6.8.	जनवरी,	१९५	40
अस्योहार करनेदा कारण	٥.	ja uko	1		¥ A	:	•	:	:	:
सर-१० अप्वीकाण द्वाण करनेका अस्वीकार कारण की गई	o-*	अस्त्रीकार की गई	:	•		*	:	:	:	2
मग्दार दे धीन हे अ	V	विचारधीत ह	2		97 97	:	:	÷	11	ř.
i we	ტ				*	:	ī	:	:	:
किनमा प्रदान कि प्राप्त प्रतान	(),*		:	*	:	:	:	i	:	•
िष जब कि उन्हें पेरुन या एक- महत गका प्रतान की गई	æ*		,		*	*	•	:	:	·
दिस अधिक पर उन्होने प्रायना-ध्य भेता	N 0	जिला कांग्रेस कमेटी जारा मेन्नी गई नियि नहीं दी हुई थी	E	2	ŗ	*	=	;	:	4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
तिय तव हि उन्होंटे प्राथता-पत्र भे जा	ftv	गजतीनिक पीड़िन होने की हैमियन मे	ŗ	•	*	<i>-</i>	**	<u> </u>	44 60	
राजनीतिक पैरिहन का नाम	o•	श्री ध्यान मिह	श्री लीनानच् इबरान	की राय मिह आयं	४४ औं किशन मिह	४५ स्री संगत राम	४६ भी घनस्याम हंटबाल	श्री छगत मनी	४८ श्री जॉनन्ट सिह रवित	९ भी बलवन्त सिह रॉबत
क्रम	Sh. A	*	?÷	>	\$	*	×	*	>	%

नित्ययां ६९१

٥	श्री महेश चन्द्र	=	•	•	:	:	:	:	5	•	
0	न्नो सकदमा प्रसदि	मरकार को १० जनवर	नवरी,	=	:	•	:	:	11	:	•
ا ب	35 mm=12 misi	१९४९ ई० को मिल १६ जनवरी, १८४९	त्र के कि		:	:	:	:	•	:	:
3			લ	अपने पनि के राजनी-	राजमी-	:	:	:		:	:
m	श्रीमती चंता देवा पत्ना जितार सिंह	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	on.	तिक पीड़ित होने	म होने						
					;						

नत्थी 'घ'

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के ताराकित प्रश्न स० ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९२ पर) पनायन निरोक्षक पदों के लिये प्रकाशित शासकीय विज्ञापन का उद्धरण

- (२) योग्यता--
- (क) उम्मीदवार का हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट बोर्ड की इन्टरमीडियेट परीक्षा हिन्दी विषय के साथ अथवा सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा का उनीणं होना आवश्यक है। यदि हिन्दी भाषा इन्टरमोडियेट परीक्षा का एक विषय न रहा हो तो हाई स्कूल परीक्षा का विषय हिन्दी अवश्य होना चाहिये।
- े (ख) जिस उम्मीदवार ने निम्नानित परीक्षाओं में से एक को ओर हाई रकूल परीक्षा किंग्री विषय के साथ पास की हो या अप्रेजी भाषा को एं जिल्ल विषय के रूप में लेकर निम्ना-, कित परीक्षाओं में ने किमी एक को पास किया हो तो एं सी योग्यता प्रस्तर (२) में निर्धारित स्यूनतम योग्यता के समकक्ष मानी जावेगी:—
 - (१) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की मायमा परीक्षा ।
 - (२) काशी विद्यापीठ की शास्त्री परीक्षा ।
 - (३) गुरुकुल कांगडी को नियाविनोव परीक्षा ।
 - (४) बबीन्स संस्कृत कालेज की मध्यमा परीक्षा।
 - (११) देश सेवां में त्याग करने वाले जो उम्मोदवार शासकीय पत्र स० ओ० १२९०-११८-१००३-४०, दिनांक ५-४-४८ ई०, जिसका संक्षेप में उद्धरण नीचे विया जाता हैं, के अधीन शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं में सुविधा पाने के इच्छू कहीं उमेउममें वियेगये आदेशान्सार आवश्यक प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा ।
 - सुस्ता (१) शासकीय पत्र स० ओ० १-९०-११८-१००३-४०, विनाक ५ अप्रैल,१९४८ ई० के अनुसार हाई स्कूल परोक्षा या यक प्रात्नीय सरकार द्वारा मान्य अन्य समकक्ष परीक्षा इन्द्रश्मीबियेट परीक्षा की योग्यना के बराबर समझी आवेगी ।
 - (२) उपर्युष्त मुविधा का लाभ साधारणनः ए मे उम्मीववार के लिये मीमित रहेगा जिसने कम से कम द मास की राजा पाई हो तथा जिसके प्रमाणनर या उस जिलाधीश का जिसके कार्य-क्षेत्र में उसका निराम है, एक मर्टिफकेट इस आशय का प्रस्तृत करेगा कि उम्मीदवार ने वेश शी राजनीतिक उसति के हेतु कम से कम ६ मास की मना शेली है।

राजकीय आवेश मं० ५०२८ प० रा० बि०११४ ४८, विनोक २५ मार्च, १९४९ ई० या संचालक पंचायत राज के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के सेकेटरी की प्रेवित किया गया था, का उद्धरण

x x x

क (क) शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएँ याँव राजनीतिक पीड़ तो में से निर्भारित शिक्षा सम्बन्धी योग्यता प्राप्त योग्यता पदाकांक्षी पूरी संख्या में प्राप्त हों, तो जन-सेवा के अत्यूत्तम कार्यों, सामान्य कार्यक्षमता तथा विस्तृत अनुभव के वृष्टिकोण से अत्यन्त योग्य पदाकांक्षी चुना जा सकता है, याँव उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताय इस प्रकार के राजनीतिक पीड़ितों के लिये निर्भारित योग्यता से एक कक्षा कम है।

नत्यी (ङ)

(देखिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रश्न सं० ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९२ पर) अफसरों की सूची

 १—-श्री देवकी नन्दन सहायक—संचालक, शर्मा स्टोसं पर्चेज विभाग सं स्टोसं पर्चेज विभाग में कार्य करते रहे हैं। २—-श्री एस० फय्याज उप सहायक संचालक अली स्टोसं पर्चेज विभाग में कार्य करते रहे हैं। ३—-श्री पी० वी० कुरूप फर्नीचर विशेषज्ञ । ४—-श्री पी० वी० कुरूप फर्नीचर विशेषज्ञ । ४—-श्री जो० एन० सिंह टेक्सटाइल विशेषज्ञ । ४—-श्री जो० एन० सिंह टेक्सटाइल विशेषज्ञ । प—-श्री आर० के० चसड़ा विशेषज्ञ अग्रवाल चसड़ा विशेषज्ञ पर साल अमेरिका में रहकर वहाँ लेवर टेक्नोलोजी में एम० एस० सी० डिग्री पर कार्य करते रहे हैं। आप स्त्र पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेक्स साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। ६—-श्री एम० सी० मेटल विशेषज्ञ सक्ति विशेषज्ञ सक्ति से हुये हैं। आप लगभग डेक्स सक्तेगा पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेक्स सक्तेगा पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेक्स सक्तेगा पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेक्स साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। 	नाम	पद	योग्यता तथा विशेष अनुभव
अली स्टोर्स पर्चेज विभाग रहे हैं लीगल प्रैक्टीशनसं परीक्षा पास हैं । ३—-श्री पी० वी० कुरूप फर्नीचर विशेषज्ञ । ४—श्री जे० एन० सिंह टेक्सटाइल विशेषज्ञ । ४—-श्री जे० एन० सिंह टेक्सटाइल विशेषज्ञ । ५—-श्री आर० के० चमड़ा विशेषज्ञ विभाग में कार्य कर रहे हैं । ५—-श्री आर० के० चमड़ा विशेषज्ञ अप्रवाल विशेषज्ञ विभाग में कार्य कर रहे हैं । ५—-श्री प्रम० सी० मेटल विशेषज्ञ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं । ६—-श्री एम० सी० मेटल विशेषज्ञ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं । ६—-श्री एम० सी० मेटल विशेषज्ञ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं । ६—-श्री एम० सी० मेटल विशेषज्ञ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं । आप लगभग डेक्स साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं । आप लगभग डेक्स साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं । अप सक्तेग सक्तेग हैं । आप लगभग डेक्स साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं ।	_		की स्थापना से अधिकतर इसी विभाग
पवर्नमेंट वुड वर्किंग इत्स्टीटेंचूट बरेली के प्रिंसिपल हैं। ४—श्री जे॰ एन० सिंह टेक्सटाइल विशेषज्ञ गर्वनमेंट टेक्सटाइल इंस्टीटचूट में प्रोफेसर हैं। जापान में बुनाई की शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं। आप सन् १९४० ई० से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। ५—श्री आर॰ के॰ चमड़ा विशेषज्ञ आप २ साल अमेरिका में रहकर वहां लेटर टेक्नोलोजी में एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त किये हुये हैं। इस के पहले गर्वनमेंट हानेंस फक्टरी, कानपुर में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेढ़ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। ६—श्री एम० सी॰ मेटल विशेषज्ञ दिप्ता से एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं। आप आजकल मेटल वर्किंग, स्कूल अलीगढ़			
हैं। जापान में बुनाई की शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं। आप सन् १९४० ई० से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। ५—श्री आर० के० चमड़ा विशेषज्ञ आप २ साल अमेरिका में रहकर वहां लेटर अग्रवाल टेक्नोलोजी में एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त किये हुये हैं। इस के पहले गवर्नमेंट हार्नेस फक्टरी, कानपुर में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेढ़ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। ६—श्री एम० सी० मेटल विशेषज्ञ द्यालबाग से एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेना डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं। आप आजकल मेटल वर्षका, स्कूल अलीगढ़	३श्री पी० वी० कुरूप	फर्नीचर विशेषज्ञ]	गवर्नमेंट वुड वर्किंग इन्स्टीटचूट बरेली के
अग्रवाल टेक्नोलोजी में एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त किये हुये हैं। इस के पहले गवर्नमेंट हार्नेस फक्टरी, कानपुर में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेढ़ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर रहे हैं। ६—श्री एम० सी० मेटल विशेषज्ञ क्यालबाग से एलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेना डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं। आप आजकल मेटल वर्किंग, स्कूल अलीगढ़	४श्रो जे॰ एन० सिंह	टेक्सटाइल विशेषज्ञ	हैं। जापान में बुनाई की शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं। आप सन् १९४० ई० से
सक्सेना डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं। आप आजकल मेटल वर्किंग, स्कूल अलीगढ़	•	चमड़ा विशेषज्ञ	टेक्नोलोजी में एम० एस० सी० डिग्री प्राप्त किये हुये हैं। इस के पहले गवर्नमेंट हार्नेस फक्टरी, कानपुर में विभिन्न पदों पर कार्य करते रहे हैं। आप लगभग डेढ़ साल से उद्योग विभाग में कार्य कर
क सुपारत्टन्डट ह । क्रिय करने का आदेश देते हैं और उनका मत्य चकाते हैं। यदि प्रश्न का अभिप्राय	सक्सेना		डिप्लोमा प्राप्त किये हुये हैं। आप आजकल मेटल वकिंग, स्कूल अलीगढ़ के सुपरिन्टन्डेंट हैं।

ऋय करने का आदेश देते हैं और उनका मूल्य चुकाते हैं। यदि प्रश्न का अभिप्राय स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफसरों से हो तो उनकी एक सूची नत्थी है।

४४—सरकार के पास स्टोर्स पर्चेज विभाग के अफसरों के विरुद्ध एक शिकायत पिछले जून मास में श्री रामचन्द्र नवाबगंज, कानपुर की आई थी उस पर उचित कार्यवाही की गई ह।

४५--उद्योग विभाग को उनके स्टोर्स द्वारा खरीदे हुये बोरों में ऐसी कोई हानि नहीं हुई ।

४६—स्टोर्स पर्वेज विभाग द्वारा प्रान्तीय रक्षा दल के लिये कंबल खरीदने में सरकार को ऐसी कोई हानि नहीं हुई।

४७--यह भी सही नहीं है कि सरकार को जूतों की खरीदारी में २०,००० ६० की हानि हुई।

४८—हां, यह सही है कि स्टोर्स पर्चेज विभाग के एक अफसर श्री सैयद फय्याज अली, हैदराबाद आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे, परन्तु वह हाई कोर्ट से छूट गये और वे फिर अपनी जगह वापिस आ गये। ये अफसर पहिले डाइरेक्टर आफ काटेज इन्डस्ट्रीज के स्टेनोग्राफर थे, लेकिन १९४३ ई० में एक्सट्रा असिस्टेंट ऐ० डी० आई० के पद पर नियुक्त कर्य गर्य थे।

४९—भी संयद फय्याज अली के कुछ चचेरे भाई व भतीजे, जो बिना उनकी मदद व उनसे अलग रहते हैं, पाकिस्तान में हैं। उनके एक छोटे भाई संयद मकसूद अली, जो सरकारी नौकरी से पेन्दान पा गये, वह भी हाल ही में पाकिस्तान चले गये। श्री फय्याज अली का बड़ा लड़का ब बड़ी लड़की भी पाकिस्तान चले गये। उनके खान्दान के बाकी लोग बीबी व पांच लड़के व दो लड़कियां उनके साथ में हैं।

नत्थी 'च'

्दिलिए १४ जनवरी, १९५० ई० के तारांकित प्रक्त संख्या ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२९ पर)

हमीरपुर जिले में गांवों को, जहां सांड रहते हैं, सूची:-१-- धमोरा २--- टिकरिया ३---ऑटा ४---पदावां ५--से उरी ६--मदावा ७---मलोहन ८--मदया ९--मथाई १०--रब ११---चिली १२---सस्सर्ड १३--नकहरी १४--वेनपुर १५---विल्लख १६--गोहांड १७--कटेन्डा १८-कंथा १९--बसेला (२) २०-कोलेन्टा २१--कया २२---रोहेन्टा २३---सिकरोड़ा २४--खरना २५-गुटक्वारा २६--फैया २७-सोकदानुदा २८--कुचहचा २९--नहानद्वारा ३०--जरोखर ३१--कघोरा ३२---रावतपुरा ३३---नगरोह ३४----विरहट ३५---प्रमोद (२) ३६--बांटा ३७--बन्दोरा ३८--त्रना ३९--बरखेरा ४०—इटाली ४१--मौना ४२--बरेहरा]

४३--बंगरा ४४ --- बिलगांव ४५--रेउरा ४६--बसरोली ४७--बन्दवा ४८--भंगरोन ४९--नेवलीबाम्सा ५०-चरीबांसी ५१---लोघोपुरा ५२--ममुवा (२) ५३--इकठोरा ५४-अटगांव ५५--मंगरोठ ५६—कैथा ५७---गिरवर ५८--इटौरा ५९—बर्णान ६०—इरोघा ६१—इमरौहा ६२--बिन्दोही ६३--मदारपुर ६४--मौघा ६५—भलेसई ६६--गुरबोहा ६७--माचा ६८--वघरई इ९-खरी ७०---भौवा। ७१---नरेच ७२---रेवान ७३—खेला ७४--बेहुनी खुर्द ७५—गहटोली ७६---भुसकास ७७—इमालिया ७८---बिहुनी कलां ७९—खेई सुर्नेचद ८०--मनई ८१—पंचपेडा ८२—गुरहा ८३—चरखा ८४--भरकरो

A1	_
८५कर्गवः	१३२सिझआहा
८६परोचा	१३३महुआबन्ध
८७—सिचौली	१३४अजेने र
८८अजोही	१३५अकोयाभित्रय
८९नरायनपुर	१३६—-बजोरा
९०—कं भी	१३७—दिकरागाहपुर
९१—मुमेरपुर	१३८अतियन (२)
९२इन्मोठा (५)	१३९धरोन
९३—विद्योफन	१४०सिरहा
९४मवर्दनान	१४१कहरई
९५वेधा	१४२मकलई
९६कुकहचा	१४३बद्यवा
९७-रमोरी	१४४बघारा
९८ च्वीपुर	१४५काजी बहहौरी
९९काला	१४६—सिचौना
१००स्वासा	१४७माकरनई
१०१—करारामपुर	१४८विलवाही
१०२-लरहा	१४९—गमोसा
१०३—मलोबर	
१०४अतसर	१५०—वे जाटाकन
१०५—मनवाई जाम	१५१जरसहना
१०६—महोबा (२)	१५२—स्याबा
	१५३बन्दरा
१०७-पंचपेहरा	१५४बुस्तारा
१०८—मग प्रवारा	१५५ - जुरहट
१०९—साफन	१५६-करीकला
११०—घटनई	१५७ काशीपुर
१११भानोपुर	१५८ ककुवा
११२-रायपुर सुर्व	१५९विशेश कल्यां
११३—विनौरा	१६०महेना
११४कली पहेनी	१६१सम्बोमी
११५कुगरीरा	१६२-इम्बोरा
११६जयम्बापुर	१६३रिक्वाहा
११७—वरहात	१६४ मुक्षोरा
११८वारी	१६५स्वा
११९सलारपुर	१६६-अम्बबारा
१२०-वैनाताल गोहनपुर	१६७ बुल पहाब (४)
१२१महोबा	१६८—-भंगोल
१२२गोमा (२)	१६९अवस्थान
१२३बुमबारा	१७०दिक्तनियाँ
१२४सांसा	१७१सेलाकाल
१२५ उरबारा	१७२किंगएड़िया
१२६सेवराजुरिया	१७३सियोंबा
१२७श्रीनगर	१७४वगहरी
१२८	१७५वेश्या
१२९शीनगर जिल्लारी	१७६महरा
१६०विकवाहा	१७७मण्योकी
१३१—सियमाहा	१७८-मेचा

पी० एस० यू० बी० १४० एस० ए० १९५०--४,९९०

संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटि इस्रिम्बली

_{का} काय^९वाही

को

अनुक्रमियाका

खंड ६१

স্থ

वकाल--

प्र० वि०---१३५६ फतली में देवरिया जिले में खेती की पैदाचार एवं----से उत्पन्न स्थिति के विषय में पूछ-ताछ। खं० ६१, पृ० ४६८-४६९।

अजीज अहमद खां, श्री--

---तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्यु पर जोक संवाद। खं० ६१, पृ० २७-२८।

अध्यापको--

प्र० वि०—-कुंवर दयाशंकर,ई० एम० इंटर कालेग, बरेलो के----की वेतन म मिलने की शिकायत। खं० ६१,पृ० ५४५।

प्र० वि०—जिला बोर्डो के——के वेतन का बकाया। खं० ६१, पृ० १२–१३।

अन्तिम परोक्षा--

प्र० वि०—वैद्यों को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की———में बैठने की सुविधा। खं० ६१, पृ० ४८३।

अन्न-संग्रह-योजना--

प्र० वि०-- ---के अन्तर्गत संगृहीत गल्ले के भास। खं० ६१, पृ० ५४९।

प्र० चि॰-- ---से प्रजा में असं-तोष । खं० ६१, पृ० ५५०।

अपील---

प्र० थि०--नहर विभाग के चीफ इंजी-नियर की आज्ञा के थिरुद्ध पदच्युत व्यक्तियों द्वारा----। खं० ६१,

अफसरान--

प्र० वि०—स्टोर परचेक डिपार्टमेट तथा उसके---के विरुद्ध सरकारी कार्यद्यहो। खं० ६१, पृ० ६२२— ६२४।

अफसरों---

प्र० वि०—जिलेश में सरकारें——— के रहने का प्रवन्ध। खं० ६१, पृ० ३०७।

प्र० वि० -- मश्रीनरी खरीदने शाले ----ध निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष योग्यताएं। खं० ६१, प्० ६२२।

अफ्रीका---

प्र० थि०--सरकार का ईस्ट----से बिनौला खरीदना। खं० ६१, पृ० ६१५-६१६।

अब्दुल बाकी, श्री--

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारो रिनाशऔर भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ०५५--५९,४४३।

अब्दुल हमीद, श्री:— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

अभियोग--

प्र० चि०—चीरी जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्स्पेक्टर के चिरुद्ध——— १ खं० ६१,पृ० ६१८—६१९। अवैतिनिक विशेष अधिकारियों— प्र० वि०—पिछले वो आर्थिक वर्षों में संकेडेरियट में——की नियुपित । खं० ६१, पु० ४७५-४७७।

असन्तोष---

प्र० थि०-- जिल्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के वशुब्ध सम्बन्धो अपनियमी पर सरकारी नीति पर--- । खं० ६१, प्० ४००-४०१।

असेसरी--

प्र० वि०—पोलोभोत में सेशन्स के मुक्तदमी को सुनवाई तथा ——— को उपस्थिति। खं०६१,पू०३१०— ३१२।

का

आवर्श थाना--

प्रव विग्—गोंडा जिला के——— इटियाठीक में जुर्मों की अधिकता। खंग ६१, पृष्धर ।

आनरेरो खाद्य सलाहकार—— प्रव विक———की नियुक्ति। खंव ६१, प्रव ५४३।

आयुर्वेदिक कालेज--

अ।युर्वेदिक संस्थाओं--

प्र० वि०—एलीवेथी, हो नियोवेथी——— की सरकार द्वारा स्वोकृत उनाधियां। खं०६१,पू०४१४-४१५।

आर्डिनेस---

सन् १९४९ई०का इंडियन बार कॉसिल यू० पी० अमॅडमेंट ऍड वेलिडेशन अफ (प्रोसोडियस)---। खं० ६१,प० ३४ ।

सन् १९४९ ई० का कुनायूं एनिमल ट्रांसपोर्ट कंट्रोल अमॅबनॅट----- । खं० ६१,पू० ३४।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविसेज इंटरमी जियेश एजुकेशन (अमेंडमेंट)। खं० ६१, प्०३२८।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्रावितेज एकोमोडेशन रिक्नीजीशन (अमें डमेंट)----। खं ६१, पृ० ४२१।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविवशन---। खं० ६१, पु० ४२१।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविसेज रिक्गोजीशन आफ मोटर वेहिकित्स (इमर्जेन्सी पावसं) अमेंडमेंट ऐंड प्रोसीडिंग्स (वेलिडेशन) ----। खं० ६१, पृ० ३४।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय औषध (नियंत्रण)——। खं० ६१, पु० ३४।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कोर्ट फोस [छूट (रेमीशन)]----। खं० ६१, पृ० ३२८।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जूट की धनी वस्तुओं के नियंत्रण का----। खं० ६१, पृ० ३२८।

3

इिट्याठोक खरगपुर सड़क--प्रव विव--गौंश जिला में----को खराब हालता खंब ६१,पूर्व ५४।

इन्द्रदेख त्रिपाठा, थी--देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> भारतीय पालियामेंट में २५ रिक्त स्थानी के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पू० ५७४।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमीवारी विनादा और भूमि व्यवस्या बिला खं० ६१, पृ०४८९—४९७।

इग्स्पेक्टर— प्र० वि०—-खोरी जिला के डिस्ट्रिक्ट सम्लाई----के चिरुद्ध अभियोग। खं० ६१, पृ० ६१८-६१९।

प्र० वि०--ग्रामपंचायतीके लिए---की योग्यता। खं० ६१, पृ० ६२१-६२२।

इमारतों--प्र० धि०-- चिभिन्न जिलों में---का सरकारो काम के लिये हस्तगत करना। खं० ६१, प्० ३०७। 3

उद्योग-धंधों--

प्र० वि०—-जिला फैजाबाद के घरेलू ----के विषय में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४१०--४१४।

उपज--

प्र० वि०--युक्त प्रास्त में चावल, गेहूं तथा गन्ना की दाखिक औसत---। खं० ६१, पृ० ६१८।

उपाधियां--

प्र० वि०--ऐलोपैथी, होसियोपैथी, आयुवदिक संस्थाओं की सरकारद्वारा स्वीकृत----। खं० ६१, पृ० ४१४-४१५।

ऋ

ऋण--

प्र• वि०--सहारतपुर म्युनिसिपैलिटी द्वारा वाटर वनसं ६ ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से---की मांग। खं० ६१, पृ० ४८३।

Ų

ए जूकेशन--

प्र० वि०--बदायं में---के लिये रुपये का वितरण एडल्ट खं० ६१, प्० १४-१५।

सन् १९४९ ई०का यूनाइटेड प्राविनेज ----(अमेंडमेंट) आर्डिनेंस। खं० ६१, पृ० ३२८।

ऐ

एलोगेयो---

त्र जि॰—— —— -, होि सयोपैयी, अ। युर्वेदिक संस्थाओं को सरकार द्वारा स्वोकृत उपाधियां। खं० ६१, पृ० ४१४ – ४१५।

क

फञ्ज्यमर्स को आपरेटिच स्टोर्स--

प्रे॰ वि॰--फतेहपुर शहर में---का सरकारो बोरों तो अधिक दामों पर खरीदना। खं० ६१, पृ० ३९८-३९९।

करल--

प्र० वि०--महोली, जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, डकैती तथा ---के मामलींकी संख्या। खं०६१, पृ० ४१८।

प्र० वि०--हरदोई जिले में सन् १९४८-४९ ई० में चोरी, डकैती और---की घटनाएं। खं० ६१, पृ०३७३।

कमलापति तिचारी, श्री--

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी चिनाश और भूमि -व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५७०--५७३, ५७४---५८३।

कामश्नरों--

प्र० वि०-- --- के कार्यालयों के हेड असिस्टेटों के बारे में प्रश्न। खं० ६१, पृ० ३१३।

कमेटी--

हज---के लिये चुराव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ०६०७।

हज--- के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५६२।

कम्युनिस्ट--

प्र० वि०—हर्नोट, जिला अलीगढ़ में——-और सोशलिस्टों की गिरपतारी। खं० ६१, पृ०५५६।

कर्मचारियों--

प्र० वि०--आजमगढ़ की जजी कचहरी में---की तरक्की। खं० ६१, पृ० ५५१।

प्र० वि०--आदर्श थानों में----की नियुनित के लिये योग्यता। खं० ६१, पृ० ४१९।

प्र० वि०—पशु—पालन विभाग के—— के सम्बन्ध में पूछताछ । खं० ६१, प्० ४०७—४०८ ।

प्र० वि०—विभिन्न वर्षों में सिविल सेक्रेटेरियट में प्रत्येक विभाग के ----की संख्या। खं० ६१, पृ० ३०७। घरेलू उद्योग भयो--प्रव चिव--फिरोजाबाव के---को सरकारा सहायता। गव ६१, प्व २४--२६।

घाघरा--

प्र० दि०--गोंडा-ललनक मार्ग मे सरज् तथ(---पर पूलों की अध्ययकता। खं० ६१, प्० ५५३।

घाटों--

प्रव विव—यभुका किनार की----आवि वालः जमान के सम्बन्ध में आगरे का जनता का जिलायत । स्वव ६१, पव ४१७-४१८।

घोषणा---

कतियय समि।तयों के । उसे सदस्यों के चनाय के सम्बन्ध १ ----। या० ६१, प० ५०६ - ५०७, ५२८।

भारताय पालियामेट से २५ शिक्त स्थानी के चुनाय के सम्बन्ध से घोषणा। एक ६१, पुरु ५७४।

सन् १९४९ ई० के सपुबन आस्तीय काइतकार (विशेषाधकार उपार्जन) विशेषक (१४४) पर महामान्य गतनंर का स्वःकृति की----। स्व० ६४, प्र० ३३।

मन् १९४९ ई० के संत्रका प्रान्तीय मंदित स आफ पांडरेश आईर (संशोधन और कार्ययाहियों को वंध करने के) बिरुपर महामान्य गवर्नर-जनरल का स्याकृति का——। ग्वं० ६१, प्र ३३।

हज सबेटो के जिये सबस्यों के जुनाब के संबंध मे---। खंड ६१, पुरु ५६२, ६०७।

स्त

प्रकासन्द्रो----

प्र० वि०--गांवों में खेती को----। खं० ६१, प्० ४१०। चितुर्भुज शर्मा, श्री:--देखिये "श्रश्तोत्तर" ।

चीक इंजीनियर---

प्र० वि०--नहर निभाग के---की आत्ता के विकद्ध पदच्युत व्यक्तियों द्वारा अयोज। ण० ६१, य० ४१५।

चुनाय--

कतिपय समितियों के लिए सदस्यों के कि---के सम्बन्ध में घोषणा। खंब ६१, प्र ५०६-५०७, ५२८।

प्रविश्---पत्तायती अवालती के मरपंची ----के सम्बन्ध में झगड़े। खंब ६१, पृष्ठ ३०६।

भारतीय पालियामेट से पच्चीस रिक्त स्थानी के---- के सम्बन्ध में घोषणा। ख ६१, पुठ ५७४।

प्रविषय—भिकार पृर, विकास सर्वीभीत से पचायत के---के संबंध में किसायता एक ६१, पूर्व ८-९।

हज कमिटा के लिये सदस्यों के——— के सम्बन्ध ने घोषणा। खं० ६१, पु० ५०७।

चोरी:--

प्रवित—हरदोई जिल भे १९४८— ४९ रिं० में———, डक्तेतः और कत्ल की घटनाएं। खंब ६१, प्रवृश्री।

प्रविव — बांदा कः कोतवालः में — की रिपोर्ट। खंब ६१, पृष् ५५०।

क्

छोना जाना---

प्रविष्य -- किसानों से सार के खेतों का

ST

जगन्नाथ प्रमाद अग्रवाल, श्री---सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रात्तीय जमींवारी सिनाश और भूमि-व्यवस्था सिल। ख० ६१, पू० ३६८--३७०। जगन्नाथ बरुग सिंह, श्री--

श्री अजोज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्युपर ज्ञोक संवाद। खं० ६१, पृ० २८।

श्री गोपीनाथ श्रीवस्तिव की मृत्यु पर शोक संचाद। खं० ६१, पू० ३०।

जगमोहन सिंह नेगी, श्री--देखिये "प्रश्तोत्तर"।

जर्जाः कचहरीः—

प्र० बि०--आजमगढ़ की----मे कर्मचारियों का तरक्की। ख० ६१, पृ० ५५१।

जनाना अस्पताल---

प्र० सि०--कन्नोज ने----कः आद-इयकता। खं० ६१, पृ० ५५७।

जमशेद अले: खां, श्री--

भ(रतीय पालियासेट के रिक्त स्थानों के लिये चुनाच के सम्बन्ध मे घोषणा। खं० ६१, पृ० ५०८।

जमींदारियां--

प्र० चि०--कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन की गई ----। खं० ६१,पृ० ३०५।

जमींदारो---

प्र० वि०—-उन्मूलन ऐक्ट का कुमायूं कमिइनरी में लागू होना। खं० ६१, प्० ३२६।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय
----विनाश और मूमि-व्यवस्था
बिल। खं०६१,पृ०३२९--३७१,
४८५--५०६, ५०८--५२८,
५६२--५७३, ५७४--६०७।

जरायम पेशा⊸⊸

प्र० वि०— ———क़ानून के अन्तर्गत विभिन्न जातियां। खं ६१, पृ० ५५५।

प्र० वि०--बदायूं, एटा आदि जिलों में यादव जाति को---करार देने के विषय में सरकारी नीति। खं० ६१, प्० ४७८-४७९।

जहर से मृत्यु--

प्रविष्य -- बांदा जेल में एक कैदी की ----। खंब ६१, पृष्य ५५०-५५१। जहीरल हसनैन लारी, श्री:--

श्री अंजी:ज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की यृत्यु पर शीक संवाद। खंड ६१, पृ० २७, २८।

श्री गोपी:नाथ श्रीवास्तम की मृत्यु पर शोक संसाद। खा ६१, पृ० २९, ३०।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनादा और भूमि व्यवस्था बिल। खं ६१, प्०३५, ४१।

जांच--

प्र० वि०--बनारस के अन्यालयों और विवयाश्रमों की पुलिस द्वारा----। खं० ६१, पृ० १०-११।

जातियां---

प्र० वि०-- जरायम पेशा क़ानून के अन्तर्गत विभिन्न---। खं० ६१, प्र० ५५५।

जिलाधीश--

प्र० वि०——बलिया के----के कार्यालय के पेड अपरेटिसों के विषय मे पूछताछ । खं० ६१, पृ० २०-२१।

जिला बोर्ड--

प्र० वि०—-के अध्यापकों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की वर्षास्तरी। खं० ६१, पृ० ३९८।

जिलों——

प्र० वि०—विभिन्न---मे इमारतों का सरकारः काम के लिये हस्तगत करना। खं० ६१, पृ० ३--७।

जुए की अधिकता--

प्र० वि०--बांदा के आसपास---। खं० ६१, पृ० ५५०।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट--

प्र० वि०—-पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यू-टिंग अफसरों का——— बनाया जाना। खं० ६१, पृ० ४०३-४०४।

जुर्मानो--प्र० चि०---राजनीतिक आन्दोलन में
क्रियेगये जुर्मानों के धापसी। खं०
६१, पृ० ४१६--४१७।

जुर्मी की अधिकता--

गोंडा जिला के अल्झे थाना इटियाठोक 1----। पं० ६१, प्० ५५२।

जूट---

प्र० वि०--पुक्त अस्ति भे---कः पैदास्थार बढाने के स्वपाय। खं० ६१, पृ० ६१८।

सन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्तीय -----की जनी वस्तुओं के नियत्रण का आलेख। खं० ६१, पृ० ३२८।

भा

गगडे---

प्र० ति०—पवायती अदालतों के सरपचों के चुनाव के सम्बन्ध में ———। ख० ६१, प० ३०६।

3

टाउन एरिया कर्नचारियों -प्रव विव -- ---का नौकरी से
हटने के लिये निर्धारित आयु।
खंब ६१, पृष्ट ५४६।

टेन्डरी--

प्र० वि०--पर्गराप के सम्बन्ध में ----का तिवरण। ख० ६१, प्० ६२५।

ट्रेनिग--

प्र० वि०—-प्रान्तीय रक्षक दल के सेक्शन लीडरों कः ----। खं० ६१, प्०३९७।

द्रेक्टरी---

प्रविव -- कृषि विमाग के लिए ----को खरीद। खंब ६१, पृष्ठ ४०४ ---४०६।

प्र० वि०-- खराब--- के खरीदे जाने का कारण। खं० ६१, पृ० ६२४।

ਵ

ङक्षेतियाँ---

प्र० वि०--आगरा जिले में---की रो तथ(म। खं० ६१, पृ० ३९९-४००।

अकेती---

प्र० जि॰—हरबोई जिले मे १९४८-४९ ई॰ में चोरी,----और क़त्ल की घटनाएं। खं॰ ६१, पृ॰ ३१३। डिप्टी स्पीकर---

क्षतियय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाच के सम्बन्ध ने घोषणा । खं० दश, पृ० ५०६ –५०७।

भारताय पालिया पेट के रिक्त स्थानों के लिये चुनाद के सम्बन्ध में घोषणा। सं० ६१, पृ० ५०७— ५०८।

भारतीय पालियामेट से २५ रिक्त स्थानों के चनाव के सम्पत्य में घोषणा। खं० ६१, पृ० ५७४। लखनक ने सदस्यों के लिये परिमद्य। ख० ६१, पृ० ३७२।

सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाइटीज (सयुक्त प्रान्तीय संशोधक) बिल। ख०६१, पृ०३८।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारा विनाश और मूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५३, ५७, ६९, ४३७, ४३८–४३९, ४९४, ५०८।

सन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्त के शरणाथियों को बसाने के लिये भूमि प्रांत करने का (संशोधन) बिल। ख० ६१, पृ०ं३९–४०।

हज कमेटी के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ७७।

डेरियों--

प्र० चि०--संयुक्त प्रान्त मे---को सरकारः सहायसा। खं० ६१, पृ० ५५५।

त

तहसीलदारों--

प्र० वि०---को एक जिले में रखने की अवधि। खं० ६१, प्० ३२३।

त्यागपत्र--

प्रव विव—कानपुर म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन का——। खंव ६१, पुरु ९-१०। ध

⁻ચાને---

आदर्श - - - पे कर्नचारियों की नियुक्ति के ेत्र्य योग्यता। खं० ६१, पृ० ४१९।

प्त० चि०—-गरोली, जिला सीतापुर के आदर्श——-त्रे चोरा, डकर्ता तथा करलकेमामलीकासंख्या। खं० ६१, पु० ४१८।

द

दफा १४४--

■ प्र० वि०—स्थान, जहां १ अगस्त, १९४७ ई० से ——— लागू हैं। खं० ६१, प्० ३०६।

दिबियापुर बेला रोड---

प्र० वि०---, इटावा को पक्की करना। खं०६१, प्०३१७।

दीनदयालु अवस्था, श्रः-देखिये "प्रश्नोत्तर"।

दुसाथ जाति——

प्र० वि०— संयुक्त प्रान्त में———के लोगा खं० ६१, पृ० ५४६— ५४७।

देवनागरी लिपि--

प्र० वि०—-अदालतों तथा सरकारी दफ्तरों में---के प्रयोग का अभावा खं० ६१, पृ० ३१२।

द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्रा--देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जनींदारा विनाश और भूमि व्यव-स्था बिल। खं० ६१, पृ० ४३—— ४८, ४५७, ४८५।

> > न

नित्थयां--

४५९--४६३, ६०८--६१२। खं०६१, पु० ३७३--३९४,

नर्सेज--

यूनाइटेड प्राविसेज--ऐंड मिडवाइब्ज कौंसिल में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पू० ३२९। नवाजिशअली खां, श्री--

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम। खं० ६१, पृ० ४३०।

नहर विभाग--

प्र०वि०-- ----के मुंशियों का वेतन। खं० ६१, पृ० ५५६-५५७।

नायब तहसीलदारों--

सन् १९४५ ई० में ---- के रिक्त स्थानों का भरा जाना। खं० ६१, पृ० ५४४।

नियम--

हरिद्वार कुंभ मेला के---। खं० ६१, पु० ३४।

नियुक्ति--

प्र० वि०—आनरेरी खाद्य सलाहकार की———। खं० ६१, पु० ५४३।

प्र० वि०—प्रान्त में सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स और डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल की———। खं० ६१, पु० १७।

नियुक्तियां--

प्र० वि०--पंचायत निरीक्षकों के पदों पर----। खंड ६१, पृ० ३१८-३१९।

निर्धारित आयु--

प्र० वि॰—हाउन एरिया कर्मचारियों की नौकरी से हटने के लिये———। खं० ६१, पृ० ५४६।

निरीक्षकों--

प्र० वि०—मशोनरी खरीदने वाले अफसरों व ——के नाम, अनुभव और विशेष योग्यताएं। खं० ६१, पृ० ६२२।

निर्वाचन--

कृषि तथा पशु-पालन स्थायी समिति में स्वर्गीयं श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुए स्थान के लिये एक सदस्य के ———का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।

प्रान्तीय म्युजियम, लखनऊ की प्रबन्ध-कारिणी समिति के लिये एक सदस्य के---का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८। बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी सिमिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य के——— का प्रस्ताव। खं ६१, पृ० ३२९।

यूनाइटेड प्राविसेज नर्सेज ऐंड मिडवाइब्ज कौसिल में काम करने के लिये दो सदस्यो के———का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९। संयुक्त प्रान्तीय म्यूजियम एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यो के———का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।

निहालुद्दीन, श्री--देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> सन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल। व्य ६१, पृ० ४८-४९।

नीति--

प्र० वि०—माम्प्रदायिकता समाप्त करने के लिए सरकारी——तथा तरीके। खं० ६१, प० ६१९–६२०।

नील-गायो--

प्र० वि० — कृषि रक्षा के लिये बन्दरो तथा — के निकाले जाने की तरकीब। ख०६१, पृ० ६२५। प्र० वि० — से खेती की हानि। खं० ६१, पृ० ४० = – ४१०।

न्यु कौन्सिलर्स रेजीडेस--

प्र० वि०————, लखनऊ मे पानी की कुट्यवस्था। खं ६१, पृ०४७७— ४७८।

u

पंचायत---

प्र० वि०--- --- निरीक्षको के पदो पर नियुक्तिया। खं० ६१, पू० ३१८--३१९।

पंचायती चुनाव--

प्र० वि०—जिला बिजनौर के——— में साम्प्रदायिक अनुपात। खं० ६१, पु० ५४८।

पंचायतो---

प्र० वि०--ग्राम---के लिये इन्स-पेक्टरों की योग्यता। खं० ६१, प्० ६२१-६२२। पब्लिक कैरियर्स--

प्र० वि०—सन् १९४८-४९ में जिला इलाहाबाद मे राजनोतिक पीडितों को——के परमिट। खं० ६१, पृ० २१, २२।

परती जमीन--

प्र० वि०—-जिला देवरिया मे खेती के योग्य----। खं० ६१, पृ० ४७०। प्र० वि०—-रियासत कुंडवा, तमकोही, सलेमगढ, पडरौना मे----। खं० ६१, पृ० ४७०-४७१।

परमिट--

प्र०वि०—-राजन तिक पीडितो को मोटर ओर लारी के———। ख० ६१,•पृ० ३०८।

लखनऊ मे विशान मांडल के सदस्यों के लिये कपर्यू के—---। खं० ६१, पू० ३७२।

प्र० वि०—सन् १९४ (-४९ मे जिला इलाहाबाद मे राजनीतिक पीडितों को पब्लिक कैरियर्स के----। खं० ६१, पृ० २१-२२।

परिगणित जातियो---

प्र० वि०—प्रान्तीय सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता मे ———के लिये सुविधाये। खर्दश, पु० २३—२४।

परिगणित जाति वालो--

प्र० वि०—पी० सी० एस० मे——— के लिये जगहो की व्यवस्था। खं० ६१, प्० ३१२।

पशुओ---

प्र० वि०—कमोला, धमोला, जिला नैनीताल मे———की चोरी । खं० ६१, पृ० ४४७।

पशु—पालन——

प्र० वि०-----विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ ताछ। खं० ६१, प्० ४०७-४०८।

पशुलोक—

प्र० वि०—ऋषोकेश के निकट अवस्थित
——का आय-च्यय। खं० ६१,
पु० ४८ -४८४।

पशुवध--

प्र० वि०—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के ——सम्बन्धो उपनियमों पर सरकारी नीति पर असन्तोष । खं० ६१, पृ० ४००-४०१।

पाक्षिक रिपोर्ट--

प्र० वि०--मैजिस्ट्रेटों के मुक़हमों की ----। खं० ६१, पु० ४०४।

पानी--

प्र० वि०—न्यू क^{े,}न्सिलर्स रेजीडेंस, लखनऊ में——की कुव्यवस्था। खं० ६१, पृ० ४७७–४७८।

प्र० वि०—–शारदा केनाल से बाराबंकी जिले को अपर्याप्त———। खंड ६१, प्० ४८२–४८३।

पार्लियामेंट---

भारतीय---में २५ रिक्त स्थानों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, प्० ५७४।

पी० सी० एस०--

प्र० वि०— ——में परिगणित जाति वालों के लिये जगहों की व्यवस्था। खं० ६१, पृ० ३१२।

पुलिस---

प्र० वि०—कुमायूं डिवीजन में रेग्युलर ——के थानों में थानेदारों का निजी अथवा सरकारी व्यय पर कानूनी पुस्तकें आदि रखना। खं० ६१, प्0 ३२४।

प्र० वि०—देवरिया जिले में———के अमले में वृद्धि। खं० ६१, पृ० ४७२।

प्र० वि०—रक्षक दल और——में कशमकश। खं० ६१, पृ०९।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

पेट्रोल--

प्र० वि०—प्रान्त में——का आयात तथा वितरण। खं० ६१, पृ० १५— १७।

पेड अपरेंटिस--

प्र० वि०—बलिया के जिलाधीश के कार्यालय के——के विषय में पूछताछ। खं०६१, पृ० २०–२१।

पेशगी---

प्र० वि०—कृषि सम्बन्धी मशीनरी खरीदने के लिये दो लाख रुपया ----- दिया जाना । खं० ६१, पृ० ६२४।

प्रजा--

प्र० वि०—अन्न संग्रह योजना से———में असन्तोष। खं०६१, पृ०५४५। प्रदर्शनी—

> प्र० वि०—–बुलन्दशहर जिला——— का प्रबन्ध और उस पर खर्च। खंं ६१, पृ० ३०९–३१०।

प्रबन्ध--प्र० वि०--जिलों में सरकारी अफसरों के रहने का---। खंब ६१, प० ३०७।

प्रश्न तर

अब्दुल हमीद, श्री—-रुड़की डिवीजन में नहर गंग के शरकी रजबहा से सिचाई। खंं ६१, पु० ५४८।

इन्द्रदेव त्रिपाठी, श्री—— ग्राम पंचायतों के लिये इन्सपेक्टरों की योग्यता। खं० ६१, पृ० ६२१— ६२२।

कालीचरण टंडन, श्री—— कन्नौज के सिविल अस्पताल का प्रान्तीय— करण। खंं ६१, पृ० ५५७। कन्नौज में जनाना अस्पताल की आव—

> इयकता। खं ६१,पृ० ४४७। कन्नौज में हथियारों की जब्ती। खं०६१,पृ० ४४७-४४६।

> फर्म सामूहिक चन्दा। खं० ६१, पुठ ५५९--५६१।

> फर्रुखाबाद जिले में १९४२ ई० से १९४५ ई० तक सामूहिक जुर्माना। खं ६१, पृ० ५५८-५५९।

कुंजबिहारीलाल शिवानी, श्री—— झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली का उत्पादन तथा वितरण। खं० ६१, पृ० ३१६।

राजने तिक आन्दोलन में किये गये जुर्माने की वापसी। खं० ६१, प्०४१६।

कुशलानन्द गैरोला, श्री—— अपर गढ़वाल के हरिजनों को सहायता। खंः ६१, पु० २०। [प्रक्तोत्तर |

नई शिक्षा संस्थाओं का स्थायीकरण तथा उनकी उन्नति। रां० ६१, पृ० १९-२०।

कुपा शकर, श्री---

रक्षकदल ओर पुलिस में कशमकश। खं० ६१, पू० ९।

कृष्णचन्द्र गुग्त, श्री--

आदर्श थानों में कर्मचारियो की नियुक्ति के लिये योग्यता। खंदर,पृ० ४१९।

महोली, जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, डकेती तथा कत्ल के मामलो की संरया। खंंग ६१, पृ० ४१ – ४१९।

खुशवक्त राय, श्री--

पिछले दो आधिक वर्षों में सेक्रेटेरियट में अवैतनिक विशेष अधिकारियो की नियुक्ति। खंं ६१, पृ० ४७५—-४७७।

बिलया के जिलाधीश के कार्यालय के पेड अपरेंटिसो के विषय में पूछ -ताछ। खं० ६१, पृ० २०--२१।

सन् १९४८-४९ में जिला इलाहाबाद में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर्स के परिमट। खं० ६१, पू० २१-२२।

खुज़ीराम, श्रा--

कमोला, घमोत्रा, जित्रा नतीताल में पशुओं को चोरो। ख० ६१, पृ० ५४७।

गंगाधर, था--

प्रातीय सिविल सिवस (एम्जीक्यूटिव) प्रतियोगिता में परिगणित जातियो के लिये सुविधाये। खं० ६१, पृ० २३–२४।

गंजधधा प्रसाद, श्री---

आजमगढ़ की जजी बचेहरी में कर्म-चारियों की तरक्की। खं० ६१, पु० ५५१।

कोआपरेटिव विभाग के सुपरवाइजरो का वेतन। ख० ६१, पृ० ५५२।

प्रात सुता अर्ग नाइजरो का कोआप— रेटिव सोसाइटी के अन्तर्गत सुपर— बाइजर बनाया जाना। खं० ६१, पु० ५५१। लुर्वी, जिल्ला जालान में पडिन रामचरण के करल को नूठी खबर। खा ६१, पु० ५५१।

जिजा आजभगड के गामी ट्रिजन गुरुकुल को सम्मानी सहायता। या ६१, पृष्ट ४७९ -४८०।

जिन्हा आजमगढ में महाराजगज स्कूल के छात्र श्री बीरबल ासह पर जुर्माना। ख० ६१, पृ० २३।

शिक्षा विमाग के जिंग इस्पेक्टरों के अन्तर्गा इस्जित अध्यापकों का अनुपात। खंग ६१, पृष्ठ ४७९।

साम्प्रदायिकता समान्त करने के लिए सरकारी नीति तथा तरीक। ख॰ ६१, गृ० ६१९--६२०।

गणेतकृष्ण जात्रो, श्रः---

एँ जोवयो, हो सियोग्यो, अध्युर्वदिक सस्याओं की सरकार द्वारा स्वीकृत नयाधिया। ला० ६१, पृ० ४१४।

किमानो से सीर के खेतो का छीना जारा। खं० ६१, पृ० ४१४।

जिला फैजाबाद के घरेल् उद्योग-धंधों के विषय में यूछनाछ। खं० ६१, पु० ४१०--४१४।

चतुर्भुज शर्मा, श्री---

औद्योगिक तथा व्यापारिक अन्वेषण के लिये किसी मंस्था की स्थापना। ख० ६१, पृ० १४।

जिला जालौन के भाष्टाचार विरोधी कमेटी की कार्यवाही। ख० ६१, पु० ६२५--६२६।

जिला जाली। के मैं जिस्ट्रट के फंसले पर सुर्पाण्टेडेट युलिस द्वारा नुक्ताचीनी। खार ६१, पृष्ट ६२२।

"लंकिमत" अलबार उरई पर अदालत की मानहानि का मुक्तइमा। खंड ६१, पृ० ६२२।

सरकार का ईस्ट अफ्रोका से बिनौला खरीदना। ख० ६१, पू० ६१५− ६१६।

सीमेट और रेयान फैक्टरियो के लिए मशीनों की खरीद। खं० ६१, पु० ५४५। जगमोहन सिंह नेगी, श्री--

जिला गढ़बाल के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना—पत्र। खं० ६१, पृ० ६२०—६२१।

मरोड़ा नयार बांध पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ६१७– ६१८।

लैंसडाउन, गढ़वाल की अनता का सरकार के पास लड़िकयों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६१६-६१७।

लेंसडाउन से गुमखाल तक मोटर सड़क बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

दीनदयालु अवस्थी, श्री---

दिबियापुर-बेला रोड, इटावा को पक्की करना। खं० ६१, पृ०३१७।

दीनदयालु शास्त्री, श्री--

आनरेरो खाद्य सलाहकार की नियुक्ति। खं० ६१, पृ० ५४३।

ऋ बोकेश के निकट अवस्थित पशुलोक का आध-व्यथ। खं० ६१, पृ० ४८४-४८५।

ऋषीकेश में लाद बनाने की योजना। खं० ६१,पृ० ४८४।

एटा से कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना। खं० ६१,पु० ४८४।

वैद्यों को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की अंतिम परीक्षा में बैठने की सुविधा। खं ६१,पृ० ४८३।

सहारनपुर म्युनिसियैलिटी द्वारा वाटर वक्सं व ड्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार से ऋण की मांग। खं० ६१, पृ० ४८३।

द्वारिका प्रसाद मोर्य, श्रो—— पो० सो० एस० में परिगणित जाति वालों के लिये जगहों की व्यवस्था। खं० ६१, पू० ३१२।

> मार्केटिंग सेक्शन के काम और उस पर खर्चा। खं०६१,पु० ३।

सन् १९४७-४८ ई० की अनेक्षा सन् १९४८-४९ ई० में गल्ले की उपज। खं० ६१, पृ० ४।

निहालुद्दोत, श्री---

कमिश्नरों के कार्यालयों के हैं हेड असिस्टेंटों के बारे में प्रश्न। खं० ६१, पृ० ३१३।

प्रांत के कोआंपरेटिव डियार्टमेंट के कर्मचारियों के बारे में ब्यौरा। खं० ६१, पृ० १३।

पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमतो--

विलायत और अमेरिका के हैं विश्व-विद्यालयों में प्रांत के विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता। खं० ६१, पृ० ८।

फबरल इस्लाम, श्री--

कानपुर में गल्ला गोदाम का उद्घाटन। खंड ६१, पृ० ५६१-५६२।

टाउन एरिया कर्मचारियों को नौकरी से हटने के लिये निर्धारित आयु। खं० ६१, पृ० ५४६।

न्यू कौन्सिलर्स रेजोडेंस, लखनऊ में पानी की कुन्यवस्था। खंड ६१, पृ० ४७७-४७८।

फतेह सिंह राणा, श्री—— जिल्लेबार कृषि के औजारों का कोटा। खं० ६१, पृ० १२।

बनारसीदास, श्री--

बुलन्दशहर जिला प्रदर्शिनी का प्रबन्ध और उस पर खर्च। खं॰ ६१, पु० ३०९-३१०।

राजनीतिक पीड़ितों को मोटर और लारी के परमिट। खं० ६१, पृ० ३०८।

बलदेव प्रसाद, श्री-गोंडा जिला के आदर्श थाना इटियाठीक

में जुर्मों की अधिकता। खं० ६१, पृ०५५२।

बशीर अहमद अंसारी, श्री--

जिला बिजनौर के पंचायती चुनाव में साम्प्रदायिक अनुपात । खं० ६१, पृ० ५४८।

बादशाह गुप्त, श्री—— जिला बोर्डों के अध्यापकों के वेतन का बकाया। खं० ६१, पू० १२-१३। [प्रश्नोत्तर]

प्रान्त में सब-डिप्टी इन्सोक्टर आफ स्कूल्स ओर डिप्टी इन्सोक्टर आफ स्कूल्स को नियुक्ति। खः ६१, पृ० १७।

भगवानदोन मिश्र, श्री--

गोडा-लखनऊ मार्ग मे सरजू तथा घाघरा पर पुलो की आवश्यकता। ख० ६१, पु० ५५३।

हिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बहराइच के पशुवध सम्बन्धो उपनिधमो पर सरफारी नोति पर असन्तोष। ख० ६१, पृ० ४००-४०१।

भगवान सिह, श्री--

गढवाल जन योजनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ। ख० ६१, पू० ६--८। भिकारीपुर, जिला पोलीभीन से पचायत के चुनाव के सबध में शिकायत। खं० ६१, प्० ८-९।

भारत सिंह यादनाचार्य, श्री--

प्राप्त सुवार योजना के अन्तर्गत प्रामो का सुवार। खं० ६१, पू० ११। जरायम पेशा कानून के अन्तर्गत विभिन्न जातिया। ख० ६१, प० ५५५।

वदाय, एटा अहि जिलों ने यादन जाति को जरायम पेशा फरार देने के विषय में मरकारी नीति। खा ६१, पु० ४७८-४७९।

सउस्योका सिकारिश पर कार, लारी तथा ट्रको के लाइसेंस। ख० ६१, पु० ११--१२।

सयुक्त प्रान्त म डेरियो को सरकारी सहायता। ख० ६१, पु० ५५५।

मुकुन्दलाल अग्रवाल, थो--

पचायत निरीक्षकों के पदों पर नियुपितया। ख०६१, पृ०३१८-३१९।

पीलाभोत ने सेशस के मुझर्मों की सुनवाई तथा अतिसरों को उपस्थिति। ख०६१, प्०३१०—३१२।

मुहम्भव अवो न अब्बासी, श्री—— जिना बस्ती में लारियों का कुत्रबन्ध। खं० ६१, पृ० १८—१९।

मुहम्बद अवरार अहमद, श्री—— १ अक्नूबर, १९४८ ई० से २८ गई, १९४८ ई० तक भूख हडताल करने वाले केदियों के बारे मे ब्योगा। ख० ६१, पृ० २६।

कुछ सरकारी निभागों का डाइरेक्ट (सीधे) सामान खरादना। ख०६१, पृ० ४-५।

कृषि विभाग के लिये ट्रेक्टरों की खरीद (रा० ५१, पृ० ४०४——४०६।

कोर्ट अ। क वार्ड्स के अधीन की गई जमीदाया। ख०६१, पृ० ३०५।

गन्तः प्रसूत्रः योजना के सिलसिले में भानन य सांचवे। तथा सभा-मित्रयों के दोरे। ख० ६१, पृ० २६--२८।

जित्रा बदाय् भे बिजला के लाउ में वृद्धि। या० ६१, पूर्व ४०६—४०७।

जिलों में सरकारो अक परों के रहने का प्रजन्म। सन्दर्भ, पूर्व ३०७।

तहसीलदारों को एक जिले में रखने की अनिधा ख० ६१, पृ० ३२३।

पच(यतः अवालतो के सरपचों के चुनाव के सम्बन्ध में झगड़। ख० ६१, प० ३०६।

प्रान्त में पेट्रो रुका अध्यात तथा वितरण। स्य ६१, पृ० १५---१७।

बदायू में एक्टट एजूकेशन के लिये रुपये का वितरण। लाक ६१, पृक १४--१५।

विभिन्न जिलों में इभारतों का सरकारी काम के लिये हस्तगत करना। ख० ६१, प० ३०७।

विभिन्न वर्षों में सिविल सेकेटेरियट में प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की संख्या। ख० ६१,पृ० ३०७।

सोशल वर्कर्स को बन्दक और पिस्तौल के लाइसेसो का विधा जाना। ख० ६१, पू० ३०६।

स्थान, जहा १ अगस्त, १९४७ से दफा १४४ लागू है। ख० ६१, पृ० ३०६।

मुहम्मद ज्ञाहित फाखर, श्र.— कोअ।परेटिय सोसाइट। की सदस्यता के लिये नियम। ख० ६१, पृ०४६७। यज्ञनारायण उवाध्याय, श्री--

कुमायूं डिवीजन के पटवारियों तथा उजरती अमीनों की मासिक वेतन तथा मता। खं० ६१, पृ० ३२६।

कुनायूंडिवीजन में नयाबाद प्रोसीडिंग का काम । खं० ६१, पृ० ३२६ ।

कुमायूं डिवीजन में रैग्युलर पुलिस के थानों में थानेटारों का निजी अथवा सरकारी ट्यय पर क़ानूनी पुस्तकों आदि रखना। खं० ६१, पृ० ३२४।

गढ़वाल जिले में यात्रा लाइन पर काम करने वाले सरकारी सैनीटरी इंस्पेक्टरों तथा मेहतरों का वेतन। खं० ६१, पृ० ३२४।

चमोली तहसील के क्लर्को की महंगाई बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र। खं०६१, पु०३२५।

ज्ञमींदारी उन्मूलन ऐक्ट का कुमायूं कमिक्तरी में लागू होना। खं० ६१, पृ० ३२६।

पिछले चार वर्षों में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ में आटा तथा चावल का भाव। खं० ६१, पृ० ३२५।

बद्गीनाथ-केदारनाथ के यात्रियों को सुविधाएं। खं० ६१, पृ० ३२६-- ३२८।

बनारस के अनाथालयों और विघवाश्रमों की पुलिस द्वारा जांच। खं० ६१, पु० १०-११।

रघुवीर सहाय, श्री---

कुंबर दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के अध्यापकों को वेतन न मिलने की शिकायत। खं० ६१, पृ० ५४५।

यू० पी० तहसीलदार एसोसियेशन का तनख्वाह बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र । खं० ६१, पृ० ५४४-५४५।

सन् १९४५ ई० में नायब तहसीलदारों के रिवत स्थानों का भरा जाना। खं० ६१, प० ५४४। राधाकुष्ण अग्रवाल, श्री--

अदालतों तथा सरकारी दफ्तरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग का अभाव । खं० ६१, पृ० ३१२ ।

चालानी मुक्कद्दमों का स्वूत न मिलने के कारण स्थगित किया जाना। खं० ६१, पृ० ३१३।

मुरादाबाद, मुजपफरनगर ओर सहारन-पुर जिलों में बिजलो की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।

हरदोई जिले में १९४८-४९ ई० में चोरी, डकैती और क़त्ल की घट-नाएं। खं० ६१, पृ० ३१३।

रामचन्द्र पार्लावाल, श्री—— घरेलू उद्योग—धंथों को सरकारी सहायता। खं० ६१, पृ० २४। फीरोजाबाद के घरेलू उद्योग—धंघों को सरकारी सहायता। खं० ६१,

पु० २४--२६।

रामचन्द्र सेहरा, श्री—
यमुना किनारे की घाटों आदि वाली
जमीन के सम्बन्ध मे आगरे की
जनता की शिकायत। खं० ६१,
प० ४१७–४१८।

रामजी सहाय, श्री—— संयुक्त प्रान्त में दुसाध जाति के लोग। खं० ६१, पृ० ५४६—४५७।

रामजरण, श्री---संयुक्त प्रान्तीय स्कूलों के शिक्षकों के वेतन का क्रम। खं० ६१, पृ० ३१४--३१६।

रोशनजमां खां, श्री—— जिला देवरिया में खेती के योग्य परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०।

जिला देवरिया में गेहूं के बीज के दाम। खं० ६१, पृ० ४७०।

जिला देवरिया में बीज तथा तकावी की वसूली। खं० ६१, पृ० ४७०।

जिला देवरिया में यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड के फार्मों के बारे में पूछताछ। खं० ६१, पृ० ४७२—–४७४।

१३५६ फतली में देवरिया जिले में खेती की प्रैदावार एवं अकाल से [प्रक्तोत्तर]

उत्पन्न स्थिति के विषय में पूछ-ताउ। ख० ६१, गु० ४६८-४६९।

देवरिया जिले में पुलिम के अमले में वृद्धि। खड ६१, पृ० ४७२।

बदाय में सोशिलस्ट पार्टी के मती, श्री राधेश्याम की गिरमतारी। ख० ६१, पु० ५५६।

मकोही राज, जिला देवरिया का कोर्ट आफ वार्ड्स के प्रबन्ध में आना तथा उससे वहां की खेती तथा मजद्रों पर असर। ख० ६१, पृ० ४७१— ४७२।

रियासत कुड्या, तमकोही, सरेमगढ, पउरानाम परती जमीन। स्व०,१, प० ४७०-४७१।

हरनीट, जिला अन्धेगढ में कम्युनिस्टो जोर सोप्तिस्टो को गिरपनारी। ख० ६१, पू० ५५८।

लक्ष्मीदेवी, श्रीमनी--

आगरा जिले में डहीतपी की रोहयाम। ख० ६१, पृ० ३९९-४००।

आगरा-बाह सर्वेक्ष पर सरकार की अमें चलाने का विचार। २०० ६१, ए० ३९९।

गार्वो म खेनो की चकतन्दी। ख० ६१, पु० ४१०।

नीलगायो ते खेती की हानि। ख० ६१, पु० ४०८---४१०।

लालबिहारी ट इन, श्री--

गोडा जिला के आदर्श थाना इटियाठोक में जुर्भी की अधिकना। ख० ६१, प० ५५२।

मोर्डो जिला में इटियाठोक-व्यरगपुर सहक की वाराय हालता खं० ६१, पुरु ५५४।

गोंडा-जिल्लनऊ मार्ग से परज्तशा घाघरा परपुला को आयदयक्तरा। स्व १६१, पुरु ५५३।

वंशगोपाल, श्री--

जिला बोड के ज गायकों की हदनान ने सहानभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापका को बरम्यास्तमी। स्व० ६१, पू० ३९८। प्रान्त में गल्ला बसूली के सिलसिले में गिरफ्तारिया तथा दउ का ब्योरा। प्र०६१, पृ० ३२६।

प्रान्तीय रक्षक दल के सेवजन लीटरो की ट्रेनिंग। य० ६१, पू० ३९७।

फनेहपुर जिठे के शाला गाम में ६ अविभिन्नों में १६०० ६० वपूल करने का मामला। ख० ६१, प् ३२०-३२१।

फतेत्रपुर जिले में गल्ले की वसूली। ख० ६१, पु० ३२१।

फनेहपुर शहर में कंग्यूसमं होजाप-रेटिन स्टोर्ग का सरकारी बोरो को जिल्ला दानी पर गरीदना। स्व० ५४, प० ३९४-३९९।

रज्हा तहसील, ।जांग फी पुर ५ सर-कारी गर्जा यस्त्री की लगा पीर बाजार भागते फिक्का प्रपृत्तिया जाना। य० ५१, प्र ३२२।

सूते में कियानों स गाजा तस्ली की योजना से अगराया ख० ६१, ग० ४७४—४७५।

वशी । मश्र, श्र —

न्नानपुर म्यानिसपैलिटी के वेयरमेन का त्याग-पत्र। ख० ६१, प० ९, १०।

खीरी जिला के जिस्दृश्य सग्लाई इन्सपेक्टर के व्यक्तद अभियोग। २२० ६१, पृष्ठ ६१८—५१९।

युक्त प्रान्त में चावल, गेंहं तथा गन्ना की वार्षिक औसत उपन। ख० ६१, पु० ६१८।

युक्त प्रान्त में जूट की पैवाबार बढाने के उपाय। स० ६१, पु० ६१८।

विजयानन्व मिश्र, श्री---

नहर विभाग है ते क इजीनियर की आज्ञा के विकार पश्चिम व्यक्तियों द्वारा अपीज। स्व ६१, पू० ४१५।

श्रोचन्द मित्रल, श्री---

अजीगइ के हारित उस्मान को प्रकडी इालकर जेल भेजना। ख० ६१, पु० ४०२-४०३।

तराई भावर गवर्गमेट इस्टेट का सुधार। खं० ६१, पू० ३१९। तराई भाबर गवर्नमेंट इस्टेट के किसानों को माफी की लकड़ी और सीमेंट की चादरें दिया जाना। खं० ६१, पृ० ३२०।

पुलिस के स्पेशल प्रासीक्यूटिंग अफसरों का जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाना। खं० ६१, पृ० ४०३– ४०४।

मैजिस्ट्रेटों के मुक़ब्दमों की पाक्षिक रिपोर्ट। खं० ६१, पृ० ४०४। राजनीतिक पीड़ितों को सुविधायें। खं० ६१, पृ० ४०१–४०२।

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री--

कृषि रक्षा के लिये बन्दरों तथा नीलगायों के निकाले जाने की तरकीब। खं० ६१, पृ० ६२५।

कृषि सम्बन्धी मशीनरी खरीदने के लिये दो लाख रुपया पेशगी दिया जाना। खं० ६१, पृ० ६२४।

खराब ट्रैक्टरों के खरीदे जाने का कारण। खं० ६१, पृ० ६२४।

मशीनरी खरीदने वाले अफसरों व निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष योग्यतायें। खं॰ ६१, पृ० ६२२।

वर्कशाप के सम्बन्ध में टेन्डरों का विवरण। खंड ६१, पृ० ६२५।

स्टोर पर्चे ज डिपार्टमेंट तथा उसके अफ-सरान के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२२—–६२४।

हरगोविन्द पन्त, श्री--

जिला अल्मोड़ा में मधुमक्खी पालने के लिये सहायता। खं० ६१, पृ० ४२०-४२१।

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछताछ। खं० ६१, पु० ४०७-४०८।

सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रान्त में शहद की पैदावार। खं० ६१, पृ० ४१९-४२०।

हरप्रसाद सत्यप्रेमी, श्री— नहर विभाग के मुंशियों का वेतन। खं० ६१, पु० ५५६–५५७। शारदा कैनाल से बाराबंकी जिले की अपर्याप्त पानी। खं० ६१, पृ० ४८२-४८३।

हरप्रसाद सिंह, श्री--

अन्न संग्रह योजना के अन्तर्गत संगृहीत गल्ले के भाव। खं० ६१,पृ० ५४९।

अन्न संग्रह योजना से प्रजा में असन्तोष । खं० ६१, पृ० ५५०।

बांदा के आस पास जुये की अधिकता। खं• ६१, पृ० ५५०।

बांदा कोतवाली में चोरी की रिपोर्टे। खं• ६१, पृ० ५५०।

बांदा जेल में एक क़ैदी की जहर से मृत्यु। खं० ६१, पृ०५५०-५५१।

प्रस्ताव--

आर्कालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणो समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का——। खं० ६१, पृ० ३२८।

कृषि तथा पशु—पालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का——। खं० ६१, प्० ३२९।

जालौन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट के उपचुनाव के सम्बन्ध में 'कामरोको' ----। खं० ६१, प्० ३१, ३२।

देवरिया जिले में रबी की फसल, किसान सत्याग्रह तथा सत्याग्रही बंदियां के विषय में 'कामरोको'——। खं० ६१, पृ० ३२।

प्रान्त में चीनी के मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में 'कामरोको'---। खं० ६१, पु० ३३।

प्रान्तीय म्यूजियम्, लखनऊ की प्रबन्ध-कारिणो समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का---। खं० ६१, पृ० ३२८।

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, सांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का

[प्रस्ताव]

भूमिधरी अधिकार तथा जमीदारी उन्मू-ठन कोष एकत करने के विषय में 'कामरोको'———। छ० ६१, पृ० ३२।

यूनाइटेल प्राविशेज नर्में ए ऐन मिडवाइन्ज काशिल में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का———। ख० ६१, पृ० ३२९।

संपुक्त प्रान्तीय स्यूजियस एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्याधन का——। ख० ६१, पृ० ३२८।

प्राइमरी र तुलो के अध्यापको---

प्र० वि०—जिला बोर्ड के अध्यापकों की हउताल से महान्भूति प्रकट करने पर——की बरखास्त्रमी। य० ६१, पु० ३९८।

प्राग नारायण, श्री----

सन् १९४९ ई० का गंयुक्त प्रान्तीय जमी-दारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पु० ५८३—५८७।

प्रान्तीय रक्षक दल--

प्रव । यव----- में नेक्शन छीडरों की ट्रेनिंग। राव ५१, प्रव ३९७।

प्रान्तीय सिविल सिवस--

प्रार्थना-पत्र--

प्र० वि०—जिला गढ़वाल के राजनीतिक पीरितों द्वारा सरकार के पास आश्रिक सहायता के लिये——। खं० ६१, पृ० ६२०–६२१।

प्रव थिव--यूव पीव तहसीलदार एसोसियेशन का तनख्वाह बताने के सम्बन्ध में---। खंव ६१, पुरु ५४४-५४५।

प्र० यि० - छेन्सडाउन, भढ़वाल की जनता का गरकार के पास लड़िकयों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये - । लां० ६१, पू० ६१६- ६१७।

प्रासीक्यूटिंग अहमरो ---

प्रवे वि०--पुलिस के स्पेशल--का जुडीशिया मेजिस्ट्रेट बनागा जाना। ख० ६१, पूर्व ४०३-४०४।

प्रेम किशन खन्ना, जी--

सन् १९४९ ई० का संयुवत प्रान्तीय जमीदारी विनाश गोर भूमि व्यवस्था बिल । प्य० ६१, यृ० ५८७-५८९ ।

फ

फखरल इस्लाम, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था बिल । खं० ६१, प० ४९१, ४९७—-५०६, ५०८-५०९।

फतेह सिंह राणा, श्री—— वेखिये "प्रश्नोत्तर"।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पु० ४५५।

फुलिसह, श्री—

सन् १९४९ ई० का मंयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल । खं० ६१, प० ४४१, ४४२, ४४३, ४४३-४४४, ४४५— ४५१।

व

बनारसी दास, श्री---वेष्विये "प्रश्नोत्तर"।

बन्दरो---

प्र० वि०—कृषि रक्षा के लिये—— तथा नीलगायों के निकाले जाने की तरकीब । खं० ६१, पू० ६२५।

न्द्रक और पिस्तौल— प्र० वि०—सोशल वर्कर्स को—— के लाइसेसो का दिया जाना,। खं० ६१, पृ० ३०६।

बरग्वास्तगी---

प्र० वि०—जिला बोर्ड के अध्यापकों की तज्ञताल से सहानुभूति प्रकट करने पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की———। खं० ६१, पू० ३९८। बलदेव प्रसाद, श्री— देखिये ''प्रश्नोत्तर''।

बलभद्र सिंह --

श्री अजीज अहमद खां तथा श्री————की मृत्यु पर शोक संवाद। खं० ६१, पु० २७—२८ ।

बशीर अहमद अन्सारी, श्री— देखिये ''प्रश्नोत्तर''।

बसें---

प्र० वि०—-आगरा-वाह सड़क पर सरकार का---चलाने का विचार। खं० ६१, पृ० ३९९।

बादशाह गुप्त, श्री——
देखिये 'प्रश्तोत्तर''।

बांध--

प्र० वि०--मरोड़ा नयार---पर विशेषज्ञों की रिपोर्ट । खं० ६१, प्० ६१७-६१८।

बिजली---

प्र० वि०—झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा ———का उत्पादन तथा वितरण। खं २ ६१, पृ० ३१६।

प्र० वि०—मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों में——की सप्लाई। खं० ६१, पृ० ३१३।

प्र० वि०—जिला बदायूं में ----के लोड में वृद्धि। खं० ६१, पृ० ४०६-४०७।

बिनौला--

प्र० वि०—सरकार का ईस्ट अफ्रीका से——खरीदना। खं० ६१, पृ० ६१५–६१६।

बिल--

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय शुद्ध खाद्य---(आलेख)। ख०६१, पृ० ३७।

सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाय-टीज (संयुक्त प्रांतीय संशोधक) ----। खं० ६१, पु० ३७-३८।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (संशोधन)
----। खं० ६१, पृ० ३८--४०।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था ———। खं १६१, पृ० ३४——३७, ४०—६९, ३२९——३०१, ४२१—— ४३०, ४३१—-४५८, ४८५— ५०६, ५०८--५२८, ५६२—५७३, ५७४——६०७।

बीज तथा तकाबी--

प्र० वि०—जिला देवरिया में——की वसूली। खं० ६१, पृ० ४७०।

बोरों--

प्र० वि०—फतेहपुर शहर में कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर्स का सरकारी ——को अधिन दामों नर खरीदना। खं० ६१, पृ० ३९८-३९९।

ब्योरा---

प्र० वि०—१ अक्टूबर, सन् १९४८ ई० से २८ मई, सन् १९४९ ई० तक भूख-हड़ताल करने वाले क़ैदियों के बारे से----। खं २ ६१,पृ० २६।

भ

भगवानदीन मिश्र, श्री--देखिये 'प्रश्नोत्तर''।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ६०——६६।

भगवान सिंह, श्री——
देखिये 'प्रश्नोत्तर"।

भारत सिंह यादवाचार्य, श्री--देखिये 'प्रश्नोत्तर''।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ५२–५३।

भारतीय पालियामेंट---

———के रिक्त स्थानों के लिये चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा खं ६१, पृ० ५०७–५०८।

भूख हड़ताल--

प्र० वि०--१ अक्ट्बर मन् १९४८ ई० से २८ मई सन् १९४९ ई० तक----करने वाले कैंदियों के बारे में ज्योरा। खं० ६१, पृ० २६। भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी---

प्र० वि०—-जिला जालीन के----की कार्यवाही। खं० ६१, पु० ६२५–६२६।

Ħ

मकोही राज--

प्र० वि०——, जिला देवरिया का कोर्ट आफ वार्ड स के प्रबन्ध में आना तथा उससे वहां की खेती तथा मजदूरों पर असर। खं० ६१, पृ० ४७१–४७२।

मद्गीनरी---

प्र० वि०—कृषि सम्बन्धी——खरीदने के लिये दो लाख रुपया पेदागी दिया जाना। खं० ६१, प० ६२४।

प्र० वि०— —— लरीदने वाले अफसरो व निरीक्षको के नाम, अनुभव और विशेष यो प्रताये। लं ६१, प्० ६२२।

मशीनों की खरीद---

प्र० वि०—सीमेट और रेयान फेक्टरियों के लिये———। खं० ६१, पृ० ५४५-५४६।

महंगाई---

प्र० वि०—चमोली तहसील के क्लकों की

---वढाने के लिये जिलाधीश,
गढ़वाल का प्रार्थना-पन्न। खं० ६१,
पू० ३२४।

महमूव अली खां, श्री--

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के जुनाव के सम्बन्ध में घोषणा। खं० ६१, पृ० ४०७।

माघ मेला---

इलाहाबाद-के नियम का संशोधन। खं० ६१, पु० ३४।

मार्कें दिंग सेवदान---

प्र० वि०—के काम और उस पर लर्चा। खं० ६१, प्० ३।

मुक्तद्दमा---

प्र० वि०--- 'लोकमत' अखबार, उरई पर अवालत की मानहानि का----। खं० ६१, पू० ६२२। म्कद्दमों---

प्र० वि०——चालानी———का सबूत न मिलने के कारण स्थगित किया जाना। खंं ६१, प० ३१३।

मुकुन्दलाल अग्रवाल, श्री— वेखिये ''प्रश्नोत्तर''।

मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री—— देखिये ''प्रश्नोत्तर''।

मुहम्मद असरार अहमद, श्री--देखिये 'प्रश्नोत्तर"।

मुहम्मद जमशेद अली खां, श्री——
सन १९४९ ई० का संप्रक्त प्रान्तीय
जमीदारी विनाश और भीम व्यवस्था
बिल। पा० ६१, प० ३७१, ४२१——
४२७।

महम्मद युसुफ, श्री---

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनादा और भिम व्यवस्था बिन्छ। गां० ६१, पृ० ३६१—— ३६८।

मुहम्मव रजा खां, श्री--

सन् १९४९ र्र० का गंग्रन प्रान्तीय जमीवारी विनाश और भीम न्यवस्था बिल। खं० ६१, ए० ५३-५४।

मुहम्मव शाहिव फाणरी, श्री--वेखिये 'श्रश्नोत्तर''।

मैजिस्ट्रेट---

प्र० यि०——जिला जालीन के——— के फीसले पर सुर्पारटेंदेट पुलिस द्वारा नुक्ताचीनी। खं० ६१, पृ० ६२२।

मीजस्ट्रेटों---

प्रव वि क्षेत्र हमें की पाक्षिक रिपों। लंड ६१, पूर्व ठ०४।

मोटर वेहिकिल्स--

यू० पी०---रहत्स (नियमों) का संशोधन। खं० ६१, प० ३४। म्याजयम-

> प्रान्तीय—, लखनऊ की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सबस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२८।

संयुक्त प्रान्तीय———एडवाइजरी बोर्ड में काम करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पुँ० ३२८।

य

यज्ञ नारायण उपाध्याय, श्री--देखिये ['प्रश्नोत्तर"।

यादव जाति--

प्र० वि०—बदायं, एटा आदि जिलों में ——को जरायम पेशा करार देने के विषय में सरकारी नीति। खं० ६१, पृ० ४८४—४८९।

यू० पी० शुगर कम्पनी लिमिटेड—
प्र० वि०—जिला देवरिया मे———
के फार्मो के बारे मे पूछताछ। खं०
६१, प्० ४७२—४७४।

योग्यता--

प्र० वि०—आदर्श थानों मे कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये———। खं॰ ६१, पृ० ४१९।

प्र० वि०—ग्राम पंचायतों के लिए इन्सपेक्टरो की———। खं० ६१, प्० ६२१–६२२।

प्र० वि०—मशीनरी खरीदने वाले अफसरों व निरीक्षकों के नाम, अनुभव और विशेष———। खं० ६१, पृ० ६२२।

योजनाओ--

प्र० वि०—गढवाल ऊन——के सम्बन्ध में पूछ-ताछ। खं० ६१, प्०६-८।

₹

रक्षक दल--

प्र० वि०— ————और पुलिस में कद्ममकद्या। खं ६१, पृ० ९ ।

रघुनाथ विनायक धुलेकर, श्री— सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ४२६।

रघुवीर सहाय, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"। राजनीतिक आन्दोलन-

प्र० वि०---मे किये गये जुर्मानों की वापसी। खं०६१, पृ० ४१६-४१७।

राजनीतिक पीड़ितों--

प्र० वि०— ——को मोटर और लारियों के परिमट। खं० ६१, पृ० ३०८।

प्र० वि०-----को सुविधाये । खं० ६१, पृ० ४०१-४०२।

प्र० वि०—जिला गढ़वाल के——— द्वारा सरकार के पास आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र। खं॰ ६१, पृ० ६२०–६२१।

राजाराम शास्त्रो, श्री—
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय
जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था
बिल। खंं ६१, पृ० ५८९—
६०९।

राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर"ः

रामकुमार शास्त्री, श्री——
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय
जमींदारी विनाश और भूमि
व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ०
३५६——३६७।

रामचन्द्र पालीवाल, श्री— देखिये ''प्रश्नोत्तर" ।

रामचन्द्र सेहरा, श्री---देखिये ''प्रश्नोत्तर"।

रामजी सहाय, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

राममूर्ति, श्री— कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा । खं० ६१, पृ० ५०७।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खंं २ ६१, पृ० ४३७।

रामशंकर लाल, श्री——
सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय
जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था
विल । खं० ६१, पृ० ५१०——
५१४।

रामशरण, श्री—— देलिये ''प्रश्नोत्तर''।

रिवत स्थानो--

भारतीय पाणियामेट के — के लिये चनाय के सम्बन्ध में घोषणा। स्र ६१, प० ५०७-५०८।

रिपोर्ट---

प्र० वि०—मरोगा नप्रार बाध पर विशेषको की———। सः ६१, प्० ६१७–६१=।

रोड-

प्र० वि०—विश्वियापुर-बेला----इटावा भो पक्षी करना। ए। ६१, पृ० ३१७।

रोशनजमा खा, श्री— देशिये ''पश्नोत्तर''।

> जालोन डिरिट्रक्ट बोर्ड के प्रेसीडट के उपचुनाव के सम्बन्ध में 'कामरोको' प्रस्ताव। ख० ६१, पू० ३१।

> सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमोबारो विनाश और मीम व्यवस्या बिराग ६१, पूर्व ६६–६९, ३२९–३४५,४४४।

> > ल

लक्ष्मी देवी, श्रीमती— देखिये 'प्रश्नोत्तर''।

छाइसंस--

प्र० वि०—गदस्यों की सिफारिश पर कार, रागी तथा दूकों के———। स्य० ६१, प० ११-१२।

लाइसंसो---

प्र० वि०—सोश र पर्श्स को पन्द्र। और पिस्ती र १——का दिसा जाना। रा ५१, पर ३०६— १०७।

लागिंग--

ण । १ -- पिता सस्ती से -- म मुझारा। सा ६१, पठ १८-१९।

लाराबिहारो टइन, धी---वेलिये 'प्रश्नोत्तर''। ′ लोकमत"---

प्र० वि०-- ---अगबार, उरई

पर भदारात की मानदानि का मक्दमा राष ६१, पण ६२२।

न

व्यगोपात्र श्री--देग्यिये "प्रश्नोत्तर"।

वशीपर भिश्र, शी— देगिवे "परनोत्तर"।

वर्कशाप---

प्र० वि०— — के सम्बन्ध में उन्तरों का विवश्ण। रा० ६१, प० ६२५।

वापमी---

प्र० प्रि०--राजनीतिक जान्दो हत में किये गय जर्माना की--- । ख० ६१, ५० ४८५-१८७।

विजयानन्द मिश्र, श्रो--वेरियये "प्रश्नोत्तर"।

जिद्यविद्यालयों की जिंगया—
प्रव विव—वि जयत और जमेरिका के
विश्वविद्यालयों में प्रांत के—को
मान्यता। गंग ६१, एवं है।

मोरेन स्माह, श्री---

सन १९४९ के का सबरा प्रान्तीय जमी प्रारी जिनाश और भीम व्यवस्था बिक त्या ५१, पठ ४५१-४५५, ४५६-४५७, ४५७-४५६, ४८६-

17-1-

प्रकृतिक--प्रमाय प्रिसेन्नत के स्थारियो च प्रस्पा जमाना को भासिक ---ने से सत्ता। स्व ६१, पठ ३२६।

प्रविश्व — यह भारति से सामा ग्रह्म पर गान करने त्याच सरकारी नेत राह्नरोशासा त्या नेहतरो ना — । या ५१, पूर्व ३२४ — ३२४ ।

प्रव विक-जित्रा बाट के अध्यापको के---का बकाया। खन ६१, पुरु १२, १३। प्र० वि०—नहर विभाग के मुंशियों का ———। खं० ६१, पृ० ५५६— ५५७।

प्र० वि०—संयुक्त प्रान्तीय स्कूलों के शिक्षकों के——का ऋम। खं०६१, पृ० ३१४–३१६।

वैद्यों-

प्र० वि०—को ट्रेनिंग देकर मेडिकल कालेजों की अन्तिम परीक्षा में बैठने की सुविधा। खं० ६१, पृ० ४८३। वैयक्तिक प्रवन

उस्मान--

अलीगढ़ के हिफज----को हथकड़ी डाल कर जेल भेजना। ख० ६१, पृ० ४०२-४०३।

बोरबल सिह—

जिला आजमगढ़ में महाराजगंज स्कूल के छात्र श्री———पर जुर्माना। खं० ६१, पृ० २३।

राधेश्याम---

बबायूं में सोशिलस्ट पार्टी के मंत्री श्री——की गिरफ्तारी। खं०६१, पृ० ५५६।

श

शरकी रजबहा--

प्र० वि०—रुड़की डिवीजन में नहर गंग से——से सिंचाई। खं० ६१, प्० ५४८।

शराब--

प्र० वि०—पीलीभीत इत्यादि में----की दूकानों की बिक्री तथा नीलाम। खं० ६१, पृ० ४८०-४८२।

शहद--

प्र० वि०—सरकारी योजना के अन्तर्गत प्रान्त में——की पैदावार। खं० ६१, पृ० ४१९-४२०।

शारदा केनाल--

प्र० वि०———से बाराबंकी जिले को अपर्याप्त पानी। खं० ६१, प० ४८२-४८३।

शिकायत--

प्र० वि०—कुंवर दयाशंकर ई० एम० इन्टर कालेज, बरेली के अध्यापकों की वेतन न मिलने की ———। खं० ६१, पू० ५४५। प्र० वि०--यमुना के किनारे के घाटों आदि वालो जमीन के सम्बन्ध में आगरे को जनता की----। खं० ६१, पृ० ४१७-४१८।

शिक्षकों--

प्र० वि०--संयुक्त प्रान्तीय स्कूलों के ----के वेतन का कम। खं० ६१, प्० ३१४-३१६।

शिक्षा विभाग--

प्र० वि०————के जिला इंस्पेक्टरों के अन्तर्गत हरिजन अध्यापकों का अनुपात । खं० ६१, पृ० ४७९।

शिक्षा संस्थाओं--

प्र० वि०—नई——का स्थायीकरण तथा उनकी उन्नति। खं० ६१, पृ० १^२, २०।

शोक संवाद--

श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्युपर ———। खं०६**१,** पृ०्२७, २८।

श्री नोपीनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर ----। खं० ६१, पु० २९, ३०।

श्रीचन्द सिंघल, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

स

संशोधन--

माघ मेला के नियम का
----। खं० ६१, पृ० ३४।
यू० पी० मोटर वेहिकित्स रूल्स
(नियमों) का---। खं० ६१
पृ० ३४।

संस्था--

प्र० वि०—- औद्योगिक तथा व्यापारिक अन्वेषण के लिये किसी——-की स्थापना। खं ६१, पृ० १४।

सचिव, माननीय अन्न--

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी की प्रबन्धकारिणी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पू० ३२९।

यूनाइटेड प्राविसेज नर्सेज ऐंड मिडवाइब्ज कॉसिल में काम करने के लिय दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, प्० ३२९। [सचिव, माननीय अन्त]

सन् १९४८ ई० का संयुक्त प्रातीय शुद्ध खाद्य बिल (आलेख) । खं० ६१,पू० ३७।

सन् १९४९ ई० का कृमाय एनिमल ट्रासपोर्ट कंट्रोल अमेडमेट आर्डिनेस। ख० ६१, पू० ३४।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेड प्राविमेज एकमोडेशन रिक्बीजोशन (जमडमेंट) ऑडिनेस । स्वरु ६१, प० ४२१ ।

सन् १९४९ ई० का यूनाइटेंट प्राश्तिज | (टेम्पोरेगो) कड्रोल आफ रेस्ट एंड इनिश्चन आहिनेग। ख० ६१. पुठ ४२१।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ओषघि (नियत्रण) आज्ञिनम्। रा० ६' प० ३४।

सन् १८,८० ई० का सयक्त प्रान्तीय जृट की बनी वस्तुओं के नियत्रण का आणि सा । एक ६१,प०३२८।

संचिय, गानना गिल्य -

य्०पी० मोत्र बेहिकित्स स्तम (नियमो) का सञ्चान । स० ५१, प० ३४।

सन् १९४९ ई० का युनाइटेउ प्राविसेज रिक्वोजीशन आफ मोटर वेहिहित्स (इमजन्सी पायसं) अमेडमेट एड प्रोसीडिंग्स वेलिडेशन आडिनेस। युरु ११, पुरु ३४।

सचिव, माननीय प्रधान--

जालोन डिस्ट्रिक्ट बोई के प्रेमीडेंट के उप-जुनाब के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव। गाँ० ६१, प० २१, ३२।

थी अजीज अहमद त्या तथा श्री बलभद्र निह की मत्यु पर शोक नवाव। खं० ६१, पृ० २७।

श्री गोपीनाय श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक-संवाद। तक ६१, पर २९।

सन् १९४९ ई० का इंडियन बार कौतिल य्० पी० अमेडमेंट ऐंड बेलिडेशन आफ (प्रोसीडिंग्स) आडिनेस। खं० ६१, पू० ३४।

सन् १९४९ ई० का कोआपरेटिव सोसाय-टोज (संयुक्त प्रातीय सद्योधक) बिल । खः ६१, पृ० ३७, ३८। सन् १९४९ ई० का संयक्त प्रांत के शरणाथियों को बसाने के लिये (भूमि प्राप्त करने का) (सशोधन) बिल। ख० ६१, पृ० ३५-४०।

सन् १९४९ ई० का सयक्त प्रातीय जमीदारी विनाश और भिम व्यवस्था बिल। खं० ६१, प० ३४।

सचिव, माननीय माल--

कृषि तथा पश-पालन स्थायी समिति में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हये स्थान के जिये एक सदस्य के निर्धाचन का प्रस्ताय। य०६१, प० ३५८।

सन् १९४९ ई० का सबस्त प्रातीय कोट फीम [क्ः, (रमीजन)] आजिनेस। खं० ६१, पू० ३२८।

सन् १९४९ ई० का समस्त प्रातीय जमीरारी जिनात ॥ भीन स्ववस्था जिए। ११० ६१, प० १८, ३५-३७, ४०-४३, ४७, १५, ४३८-४३९, ४८९, ५०१, ५०९।

सम्बत पान्तीय स्माजियम एउवाइजरी बाद भ ताम एउने के लिखे दो सदस्यों के निर्वाचन का अस्ताव। स्माठ ५१, पठ २४८।

सन्तिव, माननीय शिक्षा--

प्रान्तीय स्यजियम तरानक की प्रबन्ध-कारिको समिति के िनये एक सदस्य के निर्याचन का प्रस्ताय। स० ६१, प० ३२=।

सन् १९४९ ई० का य० पी० उन्टर-मीजिएट एजूकेशन (अगेंडमेंट) आहिनेस। ११० ६१, प० ३२८।

सिचव, माननीय गार्यजीनक निर्माण—— भारतीय पालियामेट म २५ रिक्त स्थानी के चुनाय के सम्बन्ध में घोषणा । ख० ६१, पृ० ५७४।

साचिव, माननीय स्वशासन— इलाहाबाद माध मेला के नियम का संशोधन। ख० ६१, पृ० ३४।

हरिहार कुम मेला के नियम। खं० ६१. पः ३४। सड़क--

प्र० वि०—लैन्सडाउन से गुमखाल तक मोटर——बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

सदस्यता---

प्र० वि०—कोआपरेटिव सोसाइटी की ——के लिये नियम । खं० ६१, पृ० ४६७।

समिति--

आर्कालाजिकल म्यूजियम, मथुरा की प्रबन्धकारिणी ——के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पु० ३२८।

कृषि तथा पशु पालन स्थायी———में स्वर्गीय श्री बलभद्र सिंह द्वारा रिक्त हुये स्थान के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पृ० ३२९।

प्रान्तीय म्यूजियम लखनऊ की प्रबन्ध-कारिणी ———के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव। खं० ६१, पुष्ठ ३२८।

सरकारी दफ्तरों--

प्र० वि०—अदालतों तथा—— में देवनागरी लिपि के प्रयोग का अभाव। खं० ६१, पृ० ३१२।

सरकारी मोटरगाड़ियों--

प्र० वि०--एटा से कासगंज तक ----का चालू किया जाना।खं० ६१, प्० ४८४।

सरकारी सहायता-

प्र० वि०—संयुक्त प्रान्त में डेरियों को ———। खं०६१, पु० ४४४।

सरजू--

प्र० वि०—गोंडा लखनऊ मार्ग में—— तथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता। खं० ६१, पू० ५५३।

सरपंचों---

प्र० वि०—पंचायती अदालतों के ———के चुनाव के सम्बन्ध में झगड़े । खं० ६१, पृ० ३०६ ।

साजिव हुसैन, श्री--

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रांतीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बि ५०-५१ i

सामान खरीदना--

प्र० वि०—कुछ सरकारी विभागों का डाइरेक्ट (सीधे)—— । खं० ६१, पृ० ४, ५।

सामूहिक चन्दा-

प्रि॰ वि॰—फर्रुखाबाद जिले में सन् १९४०–४२ ई० तक———। खं० ६१, प्० ५५९–५६१।

सामूहिक जुर्माना--

प्र० वि०--फर्श्लाबाद जिले में सन् १९४०-४२ ई० तक---। खं० ६१, पृ० ५५८-५५९।

साम्प्रदायिक अनुपात--

प्र० वि०—जिला बिजनौर के पंचायती चुनाव में———। खं० ६१, पृ० ५४६।

साम्प्रदायिकता---

प्र० वि०—- ——समाप्त करने के लिए सरकारी नीति तथा तरीक़े। खं० ६१, पृ० ६१९-६२०।

सिविल अस्पताल--

प्र० वि०—कञ्चौज के——का प्रान्तीयकरण । खं० ६१, पू० ५५७।

सीमेंट और रेयान फैक्टरियों—

प्र० वि०— ——के लिये मशीनों की खरीद। खं० ६१, पृ० ५४५–५४६।

सीर के खेतों—

प्र० वि०—िकसानों से——का छीना जाना। खं० ६१, पृ० ४१४।

सुपरवाइजर--

सुपरवाइजरा---

प्र० वि०—कोआपरेटिव विभाग के —— का वेतन। खं० ६१, पृ० '४५२। सुपरिटेडेट पुलिस

प्र० वि०—जिला जालोन के मेजिस्ट्रेट के फेसले पर——द्वारा नुक्ताचीनी। य० ६१, पृ० ६२२।

सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री—— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सुल्तान आलम ला, श्री---

सन् १९४९ ई० का सयक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश आर भीम व्यवस्था बिल। खं० ६१, प० ४६६, ५१४-५२८, ५६४-५७०।

सुविधाये---

प्रव विव--राजनीतिक पीलितो की ---। राव ६१, प्रव ४०१-४०२।

सेन्नेटेरियट---

प्र० वि०—पिछले दो आधिक वर्षों में ——मे अवेतानक विशेष अधि-कारियों की नियुक्ति । खं० ६१, पु० ४७५-४७७।

प्र० वि०—विभिन्न वर्षी में सिविल----में प्रत्येक विभाग के कमंचारियों की संख्या । खं० ६१, पु० ३०७।

सोशल वकंशं---

प्रवित — को सन्तुक और पिस्तोल के लाइनेंसों का दिया जाना। खं० ६१, पृ० ३०६।

सोशिलस्टों--

प्र० वि०—हरनोट, जिला अलीगढ़ में कम्यूनिस्टा ओर——की गिरफ्तारी खं० ६१, पु० ५५६।

स्कल--

प्रविव — लेस डाउन, मताल की जनता का सरकार के पास ल क्षियों के ——— में कक्षा ९ योजने के लिये प्रार्थना— पत्र। यं० ६१, प्०६१६—६१७।

स्कृत्स--

प्रव विव — प्रान्त में सबर्- अटी इन्स्पेक्टर आफ — ओर डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ — की नियुक्ति। खंब ६१, पुरु १७।

स्टोर पर्वज डिपार्डमेंट--

प्र० वि० — तथा उसके अफसरान के विगद्ध सरकारी कायंवाही । खं० ६१, पृ० ६२२-६२४।

स्थानिक प्रश्न

अजीगढ---

. ----के हाफिज उस्मान को हथकड़ी डालकर जेल भेजना। खं० ६१, पु० ४०२-४०३।

अल्मोडा--

जिला---में मधुपक्यी पालने के लिये सहायता। खं० ६१, पृ० ४२०-४२१।

क्षागरा---

---- जिने में डिर्हतियों की रोक-याम। खं० ६१, प० ३९९-४००।

आगरे--

प्र० ।व०--प्रमना किनारे की घाटी जादिय ली जमीनके सम्बन्धमे---को जनता की जिकायता खं० ६१, पुरु ८१७-४१८।

आजमगढ़--

— — निगनी कचहरी में कर्मचारियों की तस्थकी। ल० ६१, पृ० ५५१।

---- जिने मंगांधी हरिजन गुरकुल को सरकारी सहायता। खं० ६१, प० ४७९-४८०।

जिला——में महाराजगज स्कूल के अत्र श्री बीरचल सिंह पर जुर्माता। खं० ६१, प्० २३।

इदिमाठोक---

गोडा जिला के आदर्श थाना--- में जमी की अधिकता। खं० ६१, पुरु ५५२।

इजाहाबाद--

----माध मेला के नियम का संशोधन। रा० ६१, पु० ३४।

सन् १९४८-४९ वे जिला---में राजनीतिक पीति को पब्लिक करियसंके परमिट। खं०६१, पृ० २१।

375---

'लोकमत' अलबार,——पर अवालत की मानहानि का मुक्तदगा। खं० ६१, प्० ६२२।

ऋषीकेश--

---के निकट अवस्थित पशुलोक का साथ व्यय १ खं० ६१, पृ० ४८४-४८५।

----में खाद बदाने की योजना। खं० ६१, प्० ४८४।

एटा--

---से कासगंज तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना। खं० ६१, पृ० ४८४।

कन्नौज---

-- -- तिविल अत्यताल दा प्रान्तीय-करण। खं० ६१, प्० ५५७।

---में जनाना अस्पताल की आवश्यकता। खं० ६१, पृ० ५५७।

----में हथियारों की जब्ती। खं० ६१, पृ० ५५७-५५८।

कमोला--

प्र० वि०———धमोला जिला नैनीताल मे पशुओं की चोरी। खं० ६१, प्०५४७।

कानपुर---

———में गल्ला गोदाम का उद्घाटन। खं० ६१, पृ० ५६१—५६२।

कासगंज--

एटा ले———तक सरकारी मोटर गाड़ियों का चालू किया जाना । खं० ६१, पु० ४८४।

कुंडवा—

रियासत----, तमकोही, सलेमगढ़ तथा पडरौना में परती जमीन। खं० ६१, पृ० ४७०-४७१।

केदारनाथ--

प्र० वि०—पिछले चार धर्षे में बद्रीनाथ तथा——में आटा तथा चावल का भाव। खं० ६१, पृ० ३२५। बद्रीताथ——के अत्रियों को सुविधाएं। खं० ६१, पृ० ३२६–३२८।

खजुहा--

----तह्सील जिला फतेहपुरमें सरकारी गल्ला वसूली की कीमत और बाजार भाव के कर्ज का बसूल किया जाना। खं० ६१, ० ३२२।

खोरी-

----जिला के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई इन्स्पेक्टर के विरुद्ध अभियोग। खं० ६१, पृ० ६१८-६१९।

गढुवाल--

अनर——के हरिजनों को सहायता। खं० ६१, पृ० २०।

———ऊन योजनाओं के सस्दन्ध में पूछ–ताछ। खं० ६१, पृ० ६–८।

जिला——के राजनीतिक पीड़ितों द्वारा सरकार के राम आर्थिक सहायता के लिये प्रार्थना—पत्र। खं० ६१, पू० ६२०—६२१।

---- जिले में यात्रा लाइन पर काम करने वाले सरकारी सैनीटरी इन्सपेक्टरों तथा मेहतरों का वेतन। खं० ६१, पृ० ३२४।

गुमखाल--

लैंसडाउन से———तक मोटर सड़क बनवाना। खं० ६१, पृ० ६१७।

गोंडा--

---जिला के आदर्श थाना इटियाठोक में जुमों की अधिकता। खं० ६१, प्० ५५२।

——में इटियाठोक खरगपुर सड़क की खराब हालत। खंब ६१, पृ० ५५४।

गोंडा-लखनऊ--

----मार्गमें सरजूतथा घाघरा पर पुलों की आवश्यकता। खं० ६१,पृ० ५५३।

चमोली--

——तहसील के क्लर्को की महंगाई बढ़ाने के लिये जिलाधीश, गढ़वाल का प्रार्थना-पत्र। खं॰ ६१, पृ० ३२५।

चुर्ली--

——जिला जालीन में पंडित रामचरण के क़त्ल की झूठी खबर। खं० ६१, पृ० ५५१। [स्थानिक प्रक्त]

जालोन--

जिला--- के भाटाचार विरोधी कमेटी की कार्यवाही। खं० ६१, पृ० ६२५-६२६।

जिला——के गोजम्ट्रेट के फेसले पर सुपरिटेडेंट प्रिंतन द्वारा न्क्ताबीनी। स्व ६१, पु० ६२२।

झांसी--

——इलेक्ट्रिक सम्ला^६ कम्पनी हारा निज्ञ*ी* का उत्पादन तथा वितरण। सं० ६१, पु० ३१३।

तमकोही--

रियासत कुँडवा,----,गलेमग३ तथा प्रशेना में परती अभीन । रां० १, प० ४७०-४७१।

तराई भावर--

—— गवनंमें इन्हेंट के किमानों को माफी कि लक्ष्मी और सीमेंट की चाउरे विषा आरा। यक दश, पूछ ३२०।

बेर्बारगा---

जिला — म खेती के योग्य परती जमीन। ख० ६१, पू० ४७०। जिला — में गेहं के बीज के दाम। रां० ६१, पु० ४७०।

प्रव विव -- जिला -- में बीज तथा तकावी की बत्तकी । रां ६१, प्रव ४७०।

जिला ———में यू० पो० झुगर कापनी लिमिटेड के फार्मी के बारे में पूछ— तारा । रा १ ६१, पू० ४७२—४७४।

धमोला--

कपो ग्र———— जिला नंनीताल में यनुतों की बोरी । खंठ ६१, पूर ५४७।

पडरोना-

रियागत कुंडवा, तमकोही, सलेमगढ़ तथा---मं परती जवीन। खं ६१, पुठ ४७०-४७१।

्पोलीभीत-

इत्यादि में शराब की दूकानों की बिकी तथा नीलाम । खं० ६१, पु० ४८०-४८२।

----मे सेशन्म के मुकदमों की सुनवाई तथा असेमरों की उपस्थिति। खं॰ ६१, पृ० ३१०-३१२।

फनेहपुर---

____ जिले में गत्ले की वसूली। खं० ६१, पू० ३२१।

——शहर में कञ्च्यार्स कोआपरेटिव स्टोर्स का सरकारी बोरों को अधिक दामों पर खरीदना। खंग् ६१, पृण ३९८-३९९।

फर्स्याबाद जिने--

---मं १९४२ ई० से १९४५ ई० तक नाम्हिक ज्याना । खं० ६१, पु० ५५/-५५९ ।

----मे नन् १९४०-४२ ई० तक सामूहित चन्दा। खं० ६१, पृ० ५५९-५५१।

फीरोजाबाद--

निक्त घरेन्द्र उपोग-धंधों को सरकारी महाग्रता । लः ६१, पु० २४-

फेजाबाद--

जिल्ला—— हे घरेलू जयोग—धंघों के विषय में पुल्ल—राष्ट्र । संब्रु ६१,पु० ४१०— ४१४ ।

ववायं——

रिजान——में बिजली के लोड में

गृति। गां० ६१, पू०४०६-४०७।

——में एइन्ट एज्रेशन के लिये

गपये का वितरण। खं० ६१,
पु० १४, १५।

——में सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री श्री राधेश्याम की गिरफ्तारी। खं० ६१, पू० ५५६।

बद्रीनाथ--

---केदारनाथ के यात्रियों को सुविधाएं। खं० ६१, पृ० ३२६-376 1

में----तथा | भिकारीपुर---पिछले चार वर्षो केदारनाथ में आटा तथा चावल का भाव। खं० ६१, प्० ३२५।

बनारस--

---- के अनाथालयों और विधवाश्रमों की पुलिस द्वारा जांच। खं० पु० १०, ११।

बरेली--

इंबरदयाशंकरई० एम० कालेज इन्टर कालेज---के अध्यापकों की वेतन न मिलने की शिकायत । खं ६१, प्० ५४५।

बलिया--

____के जिलाधीश के कार्यालय के पेड अपरेंटिस के विषय में पूछ-ताछ। खं० ६१, पू० २०, २१।

---जिला में लारियों का कुप्रबन्ध। र्खं० ६१, पृ० १८, १९।

बहराइच

डिस्ट्क्ट बोर्ड---- के पश्-बध सम्बन्धी उपनियमों पर सरकारी नीति पर असन्तोष। खं० प्० ४००-४०१।

बांदा--

----के आस-पाम जुए की अधिकता। खं २ ४१, पृ० ५५०।

---कोतवाली में चोरी की रिपोर्टे। खं ६१, प् ० ५५० ।

---- जेल में एक कैदी की जहर से मृत्यु। खं० ६१, पृ०५५०-५५१।

बाराबंकी---

शारदा कैनाल से———जिले को अपर्याप्त ६१, पु० ४८२-दानी। खं ः 8631

बिजनौर--

चुनाव ----जिला **के** पंचायती में साम्प्रदायिक तनातनी। खं० ६१, प० ५४८।

बुलन्दशहर--

———जिलाप्रदर्शिनी का प्रबन्ध और उम पर खर्च। खं० ६१, प्० ३०९, ३१०।

— जिला पीलीभीत से पंचायत के चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत। खं० ६१, पृ० ८, ९ ।

महाराजगंज--

जिला आजमगढ़ मे---स्कल के छात्र श्री बीरबर्लसिहपर हुर्माना। खं० ६१, पु० २३।

महोली--

----जिला सीतापुर के आदर्श थाने में चोरी, उकैनी नथा सन्ल के नामलों की मंख्या । एं० ६१, पु०४१८ ।

मुजप्फरनगर--

म्रादाबाद,----और महारनपुर जिलों में बिजली की मण्लाई। खं० ६१, पु० ३१३।

म्राटाबाट--

---, म्जय्फरनगर और सहारनपुर जिलों में बिजली की सप्लाई। खं० ६१, प्० ३१३।

लै सडाउन--

---गढवाल की जनता का सरकार के पास लड़ कियों के स्कूल में कक्षा ९ खोलने के लिये प्रार्थना-पत्र। खं० ६१, पृ० ६१६–६१७।

—–से गुमखाल तक मोटर सड़क बनवाना। खं २६१, पु० ६१७।

शाखा ग्राम--

फनेहपूर जिले के----में ६ आदिमयों में १,६०० रु० वसूल करने का मामला। खं ६१, पु० ३२०-3281

सलेमग इ---

रियासत कुंडवा, तमकोही----तथा पडरौना में परती जमीन। खं० ६१. पु० ४७०-४७१।

सहारनपुर---

मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और ----जिलों में बिजली की सप्लाई। खं० ६१, पु० ३१३।

[सहारनपर]

——म्युनिषिषेलिटी हारा बाटा पर्मा व प्रेनेज के लिये प्रान्तीय सरकार रोजण की माग। पंक ६१, पृष् ४८२।

मीतापर--

र्जग---मे गांव राजा के मंत्रियो का जनापा खं० ६१, प० ४१९।

हरनोट---

——जिला अलीगढ में काय्निस्टों और सोर्जालस्टो की गिरवतारी। खं० ५१, पृ० ५५६।

श्रुरिहार--

———पंभ मेला के निगम। गो० ६१, पुरु ३४।

स्वीकर, माननीय--

कतिपय समितियों के लिये सदस्यों के चनाय का कायंत्रमा। गं ६१, पूर ४२०-४३१।

जालीन डिरिन्बट गोड के प्रेसीडेंट के उप चुनाय के सम्बन्ध में 'काम-रोको' प्रस्ताव। खं० ६१, पू० ३१, ३२।

वेवांग्या जिले में ग्यों की फगल, किसान सत्याग्रह तथा मत्याग्रहों बीचयों के विषय में 'काम-रोको' प्रस्ताय। गं ६१, पूरु ३२।

प्रान्त मं चीनी के मत्य नियंत्रण के सम्बन्ध में 'काम-रोको' प्रस्ताय। यं० ६१, ५० ३३।

भूमिधरी आगिकार तथा जमीकारी तथा उन्मूलन कोच एकत्र करने के विषय में 'काम-रोको' प्रस्ताव। खं० ६१, प० ३२।

श्री अजीज अहमद खां तथा श्री बलभद्र सिंह की मृत्य पर शोक संनाद। खं: ६१, पुठ २८।

श्री गोपोनाथ श्रीवास्तव की मृत्यु पर शोक मंत्राव। खं० ६१, ए० ३०। सन् १९४९ ई० का सयुक्त प्रान्तीय जमीदारी विनाश ओर भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ० ३५–-४२१, ४३० ४८६, ४९१, ५६२।

सन् १९४९ ई० के रुडकी विश्वविद्यालय (यूनीवर्सिटी) संशोधन) बिल पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। रां ६१, पू० ३३।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काइतकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विभेयक (विल्ल) पर महामान्य गवर्नर की स्वीकृति की घोषणा। खं० ६१, पू० ३३।

सन् १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय
मेटिनेस आफ पब्लिक आईर (संशोधन
और कार्ययादियों को वंध करने के)
बिल पर महागान्य गवर्नर जनरल की
स्वीकृति की घोषणा। खं १ ६१,
पु ३३।

17

हदताल--

प्र० वि०—जिला बोर्ड के अध्यापकों की ——से सहानुभृति प्रकट करने पर प्राइमरी रक्लो के अध्यापकों की बरायास्तगी। ग्वं० ६१, पू० ३९८।

हथकड़ी---

प्र० वि०—अलीगढ के हाफिज उस्मान को——डालकर जेल भेजना। मां ६१, पृ० ४०२-४०३।

हथियारों---

प्र० वि०—कस्रोज मे——— की जब्ती। स्वं ६१, प० ५५७-५५८।

हर गोविन्त पन्त, श्री— देखिये "प्रश्नोत्तर"।

हर प्रसाद सत्यप्रेमी, श्री— देखिये "प्रक्तोत्तर"।

हर प्रसाद सिंह, श्री—

देखिये "प्रश्नोत्तर"।

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींवारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिरु । खं० ६१, पु० ४९, ६०। हरिजन--

प्र० वि०—शिक्षा विभाग के जिला इंस्पेक्टरों के अन्तर्गत——अध्यापकों का अनुपात । खं० ६१, पृ० ४७९।

हरिजनों--

प्र० वि०—अपर गढ़वाल के—— को सहायता। खंः ६१, पृ० २०।

हसरत मोहानी, श्री--

सन् १९४९ ई० का संयुक्त प्रान्तीय जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था बिल। खं० ६१, पृ०४३१, ४३४४३९-४४१, ४४२, ४४३, ४४७। ४३७, ४३७-४३८, ४३८-४३९,

हस्तगत करना--

प्र० वि०—विभिन्न जिलों में इमारतों का सरकारी काम के लिये———। खं ६१, पृ० ३०७।

होमियोपैथी--

प्र० वि०—ऐलोपैथी,———,आयुर्वेदिक संस्थाओं की सरकार द्वारा स्वीकृत उपाधियां। खं ६१, पृ० ४१४— ४१५।